

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

(INTERNATIONAL RELATIONS SINCE 1945)

डॉ० मथुरालाल शर्मा

एच. ए., बी. एड्.

पूवपूर्व प्रोफेसर (ऐमेरिटस) एवं अध्यक्ष, इतिहास विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर



कॉलेज बुक डिपो (रजिस्टर्ड)

874, त्रिपोलिया (आतिश दरवाजे के पास)

जयपुर-2 (राज.)

आभार-प्रदर्शन

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 32 वर्ष बाद भी हिन्दी भाषा में छपी सुवचिपूर्ण और श्रेष्ठ पुस्तकों को अंग्रेजी के माहोल में, उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया और यहाँ तक कि कई पुस्तकालयों में एक प्रति का भी बिक पाना टेढ़ी सीर रही। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रस्तुत पुस्तक ने अपना नाम और स्थान कमाया, यह सभी हिन्दी-प्रेमी पाठकों के लिए उत्साहवर्द्धक है।

हिन्दी भाषी पाठकों की भाँति पर 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' के नवीन संस्करण ने जो रूप धारण किया है उसमें हमें सर्वश्री डॉ. ए. अवस्थी, डॉ. आर. के. अवस्थी, डॉ. पी. एन. मसलदान, प्रो. ए. बी. लाल, डॉ. के. बी. राव, डॉ. बी. एस. बुद्धराज, डॉ. ए. पी. वर्मा, डॉ. हनुमन्त राय, डॉ. आर. एन. त्रिवेदी, डॉ. आर. सी. प्रसाद, डॉ. सुभाष काश्यप, डॉ. बी. आर. पुरोहित, डॉ. एम. डी. मिश्रा, डॉ. एल. पी. सिन्हा, डॉ. वीरवेंश्वर प्रसाद मिश्र, डॉ. बी. एन. श्रीवास्तव, डॉ. एम. एम. पुरी, डॉ. ए. डा. पन्त, डॉ. जे. एस. नेन्स, डॉ. रघुवीर सिंह, डॉ. डी. एन. पाठक, डॉ. आर. पी. श्रीवास्तव, डॉ. एन. आर. देशपाण्डे एवं अन्य मानानुभावों का सक्रिय सहयोग मिला है, हम उनके हृदय से आभारी हैं।

प्रकाशक

© PUBLISHERS

All Rights Reserved with the Publishers

Published by College Book Depot, Tripolia (Near Atish Gate), Jaipur-2

Printed at Hema Printers, Jaipur

प्रस्तावना

प्रस्तुत रचना मे महायुद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का—बदलती हुई दुनिया का—राष्ट्रों के बदलते हुए नए परिवेश का चित्रण है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र मे हुए नवीनतम परिवर्तनों और घटनाक्रमों का इसमे यथास्थान विवेचन है। विषय-वस्तु के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही घरातल स्पष्ट किए गए हैं। युद्धोत्तर विश्व के राजनीतिक मानचित्र मे क्या परिवर्तन हुए हैं; संयुक्त राष्ट्रसंघ का क्या नया स्वरूप बनता जा रहा है; अमेरिका, रूस और चीन मे परस्पर विरोध और सहयोग की जो शतरजी चालें खेली जा रही हैं; उपनिवेशवाद की क्रमशः अन्त्येष्टि किस प्रकार हुई है, एशिया और अफ्रीका के मानचित्र पर किन नए राज्यों का उदय हुआ है और इन महाद्वीपों की उल्लान और विस्फोटक समस्याएँ कौन-सी हैं, शीत-युद्ध क्रमशः शिविल होकर नए रूप मे फिर कैसे उभर आया, अफगानिस्तान मे रूसी हस्तक्षेप और ईरान-इराक युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को कितना विस्फोटक बना दिया है, तेल राजनीति क्या नए-नए गुल खिला रही है, गुट-निरपेक्षता आन्दोलन आज कितना प्रभावशाली बन गया है और विभिन्न गुट-निरपेक्ष सम्मेलनों मे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थितिज पर क्या छाप छोड़ी है, कार्टर प्रशासन के समय अमेरिकन विदेश नीति की क्या छवि रही है और नए राष्ट्रपति रीगन के समय अमेरिकन विदेश-नीति के मोड़ लेने की क्या सम्भावनाएँ हैं, सोवियत विदेश-नीति क्या नए मोड़ परिलक्षित हो रहे हैं, पर्व के पीछे तृतीय विश्वयुद्ध चल रहा है, इस पर रिचर्ड निक्सन के क्या विचार हैं, दक्षिण-पूर्व एशिया मे महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्या रूप है, भारत मे जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद नई सरकार ने विदेश-नीति को पुनः किस प्रकार साजा-सवारा और प्रभावशील बनाया है और भारत, चीन तथा पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों मे क्या नई प्रवृत्तियाँ उभरी हैं—इन सबको पुस्तक के नवीन संस्करण मे समावेश है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर एक पृथक् अध्याय है जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् की उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं और समस्याओं का उल्लेख है जो अन्य अध्यायों मे स्थान नहीं पा सकी हैं। संक्षेप मे, आज तक की सभी सम्बन्धित विषेय सामग्री के समावेश से पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाया गया है।

यह कृति कुछ 'अभाव' की पूर्ति कर सकेगी—ऐसा विश्वास है। रचना के प्रणयन मे जिन विभिन्न स्रोतों से प्रभूत सहायता ली गई है उसके प्रति आभारी हूँ। सुझावों के लिए अनुग्रहीत होऊँगा।

मधुरालाल शर्मा

अनुक्रमणिका

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सम्पन्न शान्ति सन्धिया
(Peace Settlements After World War II)

द्वितीय महायुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2), महायुद्ध के उपरान्त शान्ति निर्माण में कठिनाइयाँ (9), शान्ति प्रयास और पाँच सन्धियाँ (10), जर्मनी, आस्ट्रिया और जापान की नई व्यवस्था (13), युद्धोत्तर विश्व (15)

संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसका विधान और कार्य
(The United Nations, Its Structure and

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना (18), चार्टर की प्रस्तावना (19), प्रयोजन और सिद्धान्त (20), संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता (21), चार्टर में संशोधन की व्यवस्था (23), चार्टर की कुछ अन्य व्यवस्थाएँ (23), संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग (24), महासभा (25), सुरक्षा परिषद् (28), निषेधाधिकार की समस्या (31), धार्मिक और सामाजिक परिषद् (34), न्याय परिषद् (37), अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (39), मन्त्रिपरिषद् (41), संयुक्त राष्ट्रसंघ के राजनीतिक कार्य अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व शान्ति में भूमिका (45), संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरण और संस्थाएँ : गैर-राजनीतिक कार्य (59), संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था एक नजर में (67), संयुक्त राष्ट्रसंघ की दुर्बलताएँ (68), संघ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव (71), राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना (73), संयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन (78)

संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय

(Rise of USA and Soviet Union as Super Powers)

संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय (82), महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय (86)

निःशस्त्रीकरण
(Disarmament)

निःशस्त्रीकरण : अर्थ एवं प्रकार (92), निःशस्त्रीकरण क्या (94), द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में निःशस्त्रीकरण के प्रयास (96), निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ (106), नाटो और वारसा सन्धि : अस्त्रों की होड़ विश्व शान्ति के लिए खतरा (109)

सोवियत संघ की विदेश नीति

289

(Foreign Policy of U. S. S. R.)

स्टालिन युग (290), मोलोटोव काल (299), ख्रुशेव काल (301),
ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल (307), सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन
(330)

भारत की विदेश नीति

332

(Foreign Policy of India)

भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक आधार (332), भारतीय विदेश
नीति के आधारभूत उद्देश्य और तथ्य (333), भारत की विदेश
नीति के निर्धारक तत्त्व (335), गुट-निरपेक्षता और सह-प्रतिष्ठित्व की
नीति के प्रयोग का सर्वेक्षण (339), संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश
मन्त्री श्री बाजपेयी का नीति-सम्बन्धी भाषण (351), पाकिस्तान के
साथ भारत के सम्बन्ध (357), भारत और श्रीलंका (384), भारत
और नेपाल (387), भारत और भूटान (391), भारत और बंगला-
देश (392), भारत और चीन के सम्बन्ध (396), भारत, फ्रांस और
पुर्तगाल (406), संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के सम्बन्ध (407),
दक्षिण और मध्य अमेरिका (416), सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध
(417), भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध (429), भारत और पश्चिमी
एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका (432), भारत और अफ्रीका (434),
भारत और राष्ट्र मण्डल (438), भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ (444),
भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन (444)

चीन की विदेश नीति

448

(Foreign Policy of China)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवाद चीन के उदय के परिणाम (449),
साम्यवादी चीन की विदेश नीति के आधारभूत तत्त्व, साधन और
प्रकार (453), चीन की विदेश नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन (455), चीन
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (462), चीन और अमेरिका (462), चीन
और सोवियत संघ (467), चीन और भारत (476), पाकिस्तान
और चीन (477), चीन-अल्बानिया : बदलते रिश्ते (480), चीन-
यूगोस्लाविया : रिश्ते में नया मोड़ (482), चीन और अन्य राष्ट्र (484),
चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन (484)

ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति

....

....

486

(The British and French Foreign Policy)

ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल (486), ब्रिटेन और कोलम्बो योजना (487,

उपनिवेशवाद का अन्त और एशिया तथा अफ्रीका में नए राज्यों का उदय 15

De-Colonization and the Emergence of New States in Asia and Africa)

एशिया का जागरण : नए राज्यों का उदय, बाण्डुंग सम्मेलन (158), सन् 1955 से 1962 तक का काल . बाण्डुंग भावना का अन्त (163), सन् 1965 से 1976 तक का काल : एशियायी व्यक्तित्व को भटके (163), बंगलादेश का उदय एशिया में नव-जागरण का एक नया मोड़ (165), अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अन्त और नए राज्यों का उदय (166), एशिया और अफ्रीका के जागरण के कारण (171), एशिया तथा अफ्रीका के जागरण में समानताएँ तथा अन्तर (173), एशिया और अफ्रीका के जागरण के प्रतीक महत्त्वपूर्ण सङ्गठन और सम्मेलन (174), अफ्रीकियाई एकता को हानि पहुँचाने वाले सम्मेलन (184), अल्जीरिया का स्वाधीनता सङ्ग्राम (186), दक्षिण रोडेेशिया का सकट (188)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ और विवाद 19
(Contemporary Trends and Issues in International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ (194), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ नवीनतम विवाद और घटना-चक्र : निःशस्त्रीकरण पर ब्रिक्स् का प्रस्ताव नवम्बर 1977 (200), संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें सत्र में निःशस्त्रीकरण पर विचार और भारत की भूमिका (202), महासभा के 31वें सत्र 1976 में उपनिवेशवाद और पृथग्वासन का विरोध (203), सेशेल्स की ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति (204), अफ्रीका में बदलती शासन-प्रणाली (204), यूरोपीय आर्थिक समुदाय की 20वीं वर्षगांठ, मार्च 1977 (207), शिखर सम्मेलन सात बड़ों का मिलन, मई 1977 (208), राष्ट्रकुल सम्मेलन, जून 1977 (210), अमेरिकी शस्त्र-नीति और भारतीय उपमहाद्वीप (213), अफ्रीका : घघकता ज्वालामुखी (219), दक्षिण-पूर्वेशिया और प्रवासी भारतीय (224), लेटिन अमेरिका की अस्थिर राजनीतिक स्थितियाँ (227), पश्चिमी एशिया : शान्ति के नए प्रयास (232)

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति

(Foreign Policy of U. S. A.)

ट्रूमैन युग (235), आइज़नहॉवर युग (246), केंनेडी युग (251), जानसन युग (255), नक्सन युग (258), राष्ट्रपति फोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका (268), राष्ट्रपति कार्टर और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (275), अमेरिकी विदेश नीति का मूल्यांकन (286)

ब्रिटेन और अमेरिका (487), ब्रिटेन के फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी देशों से सम्बन्ध (489), ब्रिटेन तथा अन्य देश (490) फ्रांस की विदेश नीति : 1958 तक दुर्बल स्थिति (492), डिगॉलकालीन विदेश नीति (493), डिगॉल के बाद फ्रेंच नीति (497)

<i>Appendix A</i>	शान्ति, मित्रता और सहयोग सन्धि	499
<i>Appendix B</i>	यूरोपीय साम्यवाद और सोवियत संघ	...	502
<i>Appendix C</i>	दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान का बढ़ता प्रभाव	505
<i>Appendix D</i>	जनवरी 1977 से अब तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की झलक	508
<i>Appendix E</i>	संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री की संयुक्त घोषणा	517
<i>Appendix F</i>	प्रश्न-कोश (Question Bank)	519
<i>Appendix G</i>	ग्रन्थ-कोश (Book Bank)	531

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सम्पन्न शान्ति सन्धियाँ

(PEACE SETTLEMENT AFTER WORLD WAR II)

"अटलांटिक चार्टर, 'चार स्वतन्त्रताओं' तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के विषय में उज्ज्वल आशाएँ, विजेताओं के बगड़े एवं एशिया के विद्रोह के कारण अपूर्ण रह गईं ।"

—रूमैन

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति 1918-19 में हुई और इसके ठीक बीस वर्ष बाद द्वितीय महायुद्ध 1 सितम्बर, 1939 से प्रारम्भ हुआ जो 14 अगस्त, 1945 तक अर्थात् जापान के आत्म-समर्पण तक चलता रहा । प्रथम महायुद्ध के बाद शान्ति के जो भी प्रयत्न किए गए वे असफल सिद्ध हुए । वर्साय की सन्धि, तुष्टिकरण की नीति, हिटलर की घोर विस्तारवादी और सैन्यवादी नीति मुमोलिनी तथा जापान का साम्राज्यवादी प्रसार, शस्त्रीकरण की भयंकर प्रतियोगिता आदि ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी कि द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट होकर रहा । यह युद्ध इतना व्यापक, प्रभावकारी और प्रलयकारी था कि इसके अन्त के साथ ही विश्व इतिहास के एक युग का अन्त हो गया ।

जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण में सैनिक सघर्ष का अन्त अवश्य हो गया, किन्तु वास्तविक शान्ति की स्थापना अभी बाकी थी । युद्धोत्तर शान्ति-स्थापना का यह कार्य प्रथम महायुद्ध के उपरान्त शान्ति-स्थापना के कार्य से कहीं अधिक सरल प्रतीक होता था क्योंकि विजेता राष्ट्र महायुद्ध-काल में ही विभिन्न सम्मेलनों और वार्ताओं द्वारा शान्ति-स्थापना के मार्ग की काफी दूरी तय कर चुके थे । परन्तु वास्तव में द्वितीय महायुद्ध के बाद यह स्थिति थी नहीं । द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने के डेढ़ वर्ष बाद तक भी शान्ति-सन्धियों के प्रारूप तैयार नहीं हो सके । 10 फरवरी, 1947 तक केवल इटली, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी और फिनलैण्ड के साथ शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न की जा सकी । 'जापान' के साथ तो शान्ति-सन्धि युद्ध-समाप्ति के

2 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

लगभग साढ़े छ वर्ष बाद 28 अप्रैल, 1951 को की गई, और उस समय भी यह एक अधूरी शान्ति-सन्धि ही थी क्योंकि रूस ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रूस और जापान के बीच युद्ध-व्यवस्था की औपचारिक समाप्ति तो अक्टूबर, 1956 में हुई जब दोनों राष्ट्रों द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। आस्ट्रिया के साथ शान्ति-सन्धि युद्ध समाप्ति के लगभग 10 वर्ष बाद 27 जुलाई, 1955 को कार्यान्वित की गई और जर्मनी के साथ स्थायी शान्ति-सन्धि अभी तक सपना नहीं की जा सकी है। बर्लिन का प्रश्न शान्त होने के बावजूद आज भी जीवन्त है और जर्मनी आज भी दो भागों में विभक्त है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इसी ओर संकेत कर रही है कि यह विभाजन निश्चित भविष्य में समाप्त नहीं हो सकेगा और बहुत सम्भव है कि यह लम्बे समय के लिए स्थायी बन जाए।

स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्याय में क्रमशः निम्नलिखित बातों पर विचार करना होगा—

- (क) द्वितीय महायुद्धकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन,
- (ख) महायुद्ध के उपरान्त शान्ति-निर्माण में कठिनाइयाँ;
- (ग) शान्ति-प्राप्त और पाँच शान्ति सम्मेलन;
- (घ) युद्धोत्तर विश्व।

द्वितीय महायुद्ध कालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

अटलांटिक चार्टर

¹ (Atlantic Charter)

(अगस्त, 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अटलांटिक महासागर में एक युद्धपोत पर भेंट की और उन्होंने मित्रराष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों (War Aims) का एक अष्टसूत्री घोषणापत्र तैयार किया जिसे 'अटलांटिक चार्टर' कहा जाता है। चार्टर का उद्देश्य उस समय तक हिटलर द्वारा पराजित और उसके आक्रमण के शिकार राज्य पोलैण्ड, नावे, डेनमार्क, हॉलैण्ड, बेल्जियम, फ्रांस रूस तथा बल्कान प्रदेशों की जनता में नाज़ियों के विरुद्ध लड़ने का उत्साह पैदा करना और हिटलर द्वारा बार-बार उपस्थित की जाने वाली नवीन यूरोपीय व्यवस्था की तुलना में अपने उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना था। 14 अगस्त को चार्टर द्वारा रूजवेल्ट और चर्चिल ने घोषणा की कि—

1. उनके देश प्रादेशिक अथवा अन्य प्रकार की शक्ति वृद्धि नहीं चाहते।
2. वे ऐसा कोई भी प्रादेशिक परिवर्तन नहीं देखना चाहते जो उससे सम्बन्धित लोगों की स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट की गई इच्छाओं के अनुकूल न हो।
3. वे प्रत्येक राष्ट्र के अपनी सरकार के, जिसके अन्तर्गत वे रहेंगे, स्वरूप को चुनने के अधिकार का सम्मान करते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि जिन राज्यों की सत्ता और स्वशासन को बलपूर्वक छीन लिया गया है, वे उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए।
4. वे अपने वर्तमान कर्तव्यों का पूर्ण ध्यान रखते हुए सभी राज्यों के लिए

चाहे वे छोटे हों अथवा बड़े, विजेता हों अथवा विजित, इस बात की चेष्टा करेंगे कि उन्हें समान रूप से संसार के व्यापार एवं कच्चे माल की प्राप्ति के साधन प्राप्त हो सकें जो उनकी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हों।

5. वे सभी के लिए मजदूरी के स्तरों, आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति की दृष्टि से आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग प्राप्त कराना चाहते हैं।

6. नाजी अत्याचार को अन्तिम रूप से नष्ट करने के उपरान्त वे एक ऐसी शान्ति-स्थापना करने की इच्छा करते हैं जो सभी राष्ट्रों को अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहने के साधन प्रदान कर सकें तथा जो यह आश्वासन दे सके कि सभी देशों के मनुष्य भय तथा युद्ध से मुक्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

7. इस प्रकार की शान्ति वाह्य सागरों एवं महासागरों को निर्बाध पार करने का अधिकार प्रदान कर सकेगी।

8. उनका विश्वास है कि संसार के सभी राष्ट्रों को वास्तविक एवं आध्यात्मिक कारणों की दृष्टि से बल प्रयोग त्याग देना चाहिए क्योंकि यदि राज्य स्थल, जल अथवा वायु सम्बन्धी मैन्य शस्त्रों का प्रयोग करते रहेंगे, जो उनकी सीमाओं के बाहर आक्रमण की घमकी का काम करते हों अथवा जिनसे ऐसी सम्भावना हो, तो शान्ति स्थायी नहीं रह सकती। अतएव उनका विश्वास है कि सामान्य सुरक्षा की एक विस्तृत एवं स्थायी व्यवस्था की स्थापना के समय तक ऐसे राज्यों का निःशस्त्रीकरण आवश्यक है।

स्मरणीय है कि इस समय तक संयुक्तराज्य अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था। ऐसा तो 7 दिसम्बर, 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण के बाद ही सम्भव हुआ। अटलांटिक चार्टर की यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 6 जून, 1941 को अंग्रेजों को भेजे गए उस सन्देश के अनुसृत थी जिसमें अमेरिका का उद्देश्य चार स्वतन्त्रताओं (Four Freedoms) की प्राप्ति घोषित किया गया था। ये चार स्वतन्त्रताएँ थी—(1) भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) निजी विश्वास के अनुसार ईश्वरोपासना की स्वतन्त्रता, (3) अभाव और दरिद्रता को समाप्त कर गरीबी तथा बेकारी को दूर करना, एवं (4) निःशस्त्रीकरण द्वारा आक्रमण के भय से मुक्ति तथा निर्वन राष्ट्रों को अभयदान।

संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा

(The United Nations' Declaration)

हिटलर के विरुद्ध मुहृद संगठन और शक्ति का निर्माण करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों की यह घोषणा 1 जनवरी, 1942 को की गई। जर्मनी, इटली और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जापान के विरुद्ध संघर्ष करने वाली शक्तियों के गुट का नामकरण 'संयुक्त राष्ट्र' (United Nations) किया। इस समय तक इन राष्ट्रों की संख्या 21 हो चुकी थी। ये 21 राष्ट्र निम्नलिखित थे—अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन,

आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्वेडोर, यूनान, ग्वाटेमाला, हैटी, होण्डुरस, भारत, लक्जमबर्ग, हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड, निकारगुआ, नार्वे, पनामा, पोलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका और यूगोस्लाविया। इन सभी राष्ट्रों ने एक घोषणापत्र द्वारा अष्टनाटिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे धुरीराष्ट्रों के साथ कभी भी पृथक् सन्धि नहीं करेंगे और उनके विरुद्ध संघर्ष में अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे।

कासा ब्लाका सम्मेलन (14-24 जनवरी, 1943)

20 मई, 1942 से जनवरी 1943 तक संयुक्त राष्ट्रों के प्रत्येक सम्मेलन हुए। 14 से 24 जनवरी, 1943 तक मोरक्को के कासा ब्लाका स्थान पर चर्चिल, रूजवेल्ट तथा जनरल डिगॉल का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह घोषणा की गई कि उत्तरी अफ्रीका पर आक्रमण करने से पूर्व इटली पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया जाए।

मई-जून, 1943 में 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने खाद्य एवं कृषि सम्मेलन में लाखों विस्थापित लोगों के भोजन की समस्या पर विचार किया और इस प्रकार आगामी खाद्य एवं कृषि संगठन की नींव डाली।

मास्को सम्मेलन (19-30 अक्टूबर, 1943)

19 अक्टूबर, 1943 को मास्को में मित्रराष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जो 30 अक्टूबर तक चालू रहा। इस सम्मेलन से पहली बार युद्ध के सम्बन्ध में एक समझौता सम्पन्न हुआ। पहली बार ही मित्रराष्ट्रों ने धुरी-राष्ट्र—आस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की और चार सामान्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिए। इस सम्मेलन में संयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन और रूस सम्मिलित हुए।

सम्मेलन में तीनों सरकारों में सामञ्जस्य स्थापित करने तथा यूरोप की समस्याओं पर विचार करने के लिए लन्दन में यूरोपीय परामर्शदाता आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था भी की गई कि युद्धोपरांत आस्ट्रिया को पुन जर्मनी से पृथक् कर दिया जाएगा। इटली के बारे में यह निश्चय लिया गया कि फासिस्टवाद को जड़-मूल से समाप्त कर दिया जाए। जर्मनी के भविष्य के बारे में यह व्यवस्था की गई कि महायुद्ध के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को बंठोरे दण्ड दिया जाए।

इसी सम्मेलन में सुरक्षा और शान्ति कायम रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निश्चय हुआ। यही संगठन बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में विकसित हुआ।

वाहिंरा सम्मेलन (22-25 नवम्बर, 1943)

22-25 नवम्बर, 1943 में मित्र की राजधानी वाहिंरा में रूजवेल्ट, चर्चिल और वॉशिंग्टन बार्ड शेरर का एक सम्मेलन हुआ जिसमें दो निश्चय किए गए—

(1) जापान के विरुद्ध जल, थल और वायु सेनाओं द्वारा पूरी कार्यवाही की जाएगी,

(2) चीन को यह आश्वासन दिया गया कि सन् 1914 से तब तक जापान ने उसके जो प्रदेश अर्थात् मंचूरिया, फारमोसा तथा पेस्काडोरेज के 48 टापू बलपूर्वक छीने थे, वे सब उसे वापस दिला दिए जाएंगे, (3) 'तीनों महान् शक्तियों' को कोरिया की जनता की दासता का ध्यान है। उनका यह सकल्प है कि कोरिया को स्वतन्त्र राष्ट्र बनाया जाएगा।

काहिरा सम्मेलन में सोवियत रूस ने भाग नहीं लिया था।

तेहरान सम्मेलन (28 नवम्बर—1 दिसम्बर, 1943)

इस सम्मेलन में चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ईरान की राजधानी तेहरान में एकत्र हुए। यहाँ तीनों मित्रदेशों के सेनाध्यक्षों ने जर्मन सेनाओं के विनाश की योजनाएँ तैयार कीं। तेहरान सम्मेलन के निर्णयों को तीन भागों में विभाजित किया गया। प्रमुख निर्णय ये थे—

प्रथम भाग में जर्मनी के विरुद्ध लड़ने का दृढ़ निश्चय किया गया और अपनी विजय पर विश्वास व्यक्त किया गया।

दूसरे भाग में 'तीन बड़ों' (Big Three) ने ईरान की स्वतन्त्रता, सर्वोच्च सत्ता और प्रादेशिक अखण्डता कायम रखने की इच्छा व्यक्त की।

तृतीय भाग एक गुप्त समझौते जैसा था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मिनराष्ट्रों द्वारा दूसरा मोर्चा खोलते ही सोवियत संघ जर्मनी पर भीषण आक्रमण कर देगा।

इस सम्मेलन ने यह भी निर्णय किया कि छोटे और बड़े सभी राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा।

ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन (21 जुलाई, 1944)

संयुक्त राष्ट्रों के इस सम्मेलन में पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कॉप स्थापित करने का भी निश्चय किया गया।

डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन (अगस्त—दिसम्बर, 1944)

21 अगस्त से 7 दिसम्बर, 1944 तक संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ग्रेट-ब्रिटेन और चीन के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन के निकट डम्बर्टन ओक्स नामक स्थान पर एक अन्तर्राष्ट्रीय भावी संगठन 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' की रूपरेखा के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन के निर्णय अन्तिम नहीं थे, परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का बहुत कुछ आधार यही सम्मेलन बना। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुख्य अंगों/महासभा, सुरक्षा-परिषद्, सचिवालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सम्बन्ध में विचार किया गया और चार्टर का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। सम्मेलन में सच-सचिवालय द्वारा कार्यों को अधिक क्षमतापूर्वक सम्पन्नता के लिए एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् बनाने एवं शांति स्थापित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सहाय-सेनाओं की व्यवस्था के लिए मैनिक स्टैफ़ समिति के निर्णयों के भी सुझाव दिए गए। इस सम्मेलन में इन सत्या के सम्बन्ध में पश्चिमी राष्ट्रों और रूस के बीच कुछ मतभेद प्रकट हुए।

सम्मेलन का सर्वाधिक विवादस्पद विषय था सुरक्षा-परिपद् के सदस्यों को निषेधाधिकार (Veto Power) प्रदान करना। काफ़ी वाद-विवाद के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। यह निर्णय लिया गया कि तीनों राज्यों के शासनाध्यक्ष स्वयं इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

क्रीमिया (याल्टा) सम्मेलन (4-11 फरवरी, 1945)

महायुद्धकालीन अन्तिम महत्त्वपूर्ण सम्मेलन याल्टा नामक स्थान पर 4 फरवरी, 1945 को हुआ। यह 11 फरवरी, 1945 तक चालू रहा। इस सम्मेलन में अनेक नेताओं ने भाग लिया जिनमें रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन, ईडन, मोलोटोव मार्शल ब्रुक, एण्टोनोव, हाफकिंस, केडेगन बिंशिस्की आदि प्रमुख थे।

सुरक्षा परिपद् में मतदान की क्या पद्धति हो, इस सम्बन्ध में इस सम्मेलन में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो 'याल्टा बोटिंग फार्मूला' के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन में रूजवेल्ट और स्टालिन ने यह समझौता किया कि सुरक्षा परिपद् प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में 11 सदस्यों में से 7 के बहुमत से तथा अन्य आवश्यक विषयों में 7 स्वीकारात्मक मतों में निर्णय ले। इसमें सुरक्षा परिपद् के पाँचों सदस्य सयुक्तराज्य अमेरिका, ग्रेट-ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन की सहमति अवश्य होनी चाहिए।

इस सम्मेलन में सयुक्त राष्ट्रमंडल के अतिरिक्त यूरोप के नवीन मानचित्र तथा सुदूरपूर्व, मध्यपूर्व आदि के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श हुआ। इस सम्मेलन ने जिन समस्याओं को जन्म दिया उनका युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सम्मेलन ने जहाँ एक तरफ अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की आधारशिला रखी वहाँ दूसरी तरफ मित्रराष्ट्रों में आपसी मतभेदों को भी उत्पन्न किया।

याल्टा सम्मेलन के कुछ निर्णय उस समय गुप्त रखे गए और पूरा विवरण सन् 1955 में सयुक्तराज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया। इस सम्मेलन के महत्त्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार थे—

1. विश्व-संगठन के सम्बन्ध में 25 अप्रैल, 1945 को सान-फ्रांसिस्को (अमेरिका) में सयुक्तराष्ट्रों का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया जाए। 5 राज्यों—सयुक्तराष्ट्र अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और फ्रांस को इस संघ की सुरक्षा परिपद् का स्थायी सदस्य बनाया जाए।

2. यूरोप में नाज़ी और फासिस्ट दासता से मुक्त देशों में अटलांटिक चार्टर के अनुसार प्रजातान्त्रिक सरकारें स्थापित की जाएँ तथा आक्रमणकारी देशों द्वारा छीने हुए प्रदेश उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएँ जिनसे उन्हें छीना गया था।

3. यूरोप में शान्ति और सुरक्षा के लिए जर्मनी का निःशस्त्रीकरण किया जाए तथा उससे क्षतिपूर्ति वसूल जाए। क्षतिपूर्ति की राशि 20 अरब डॉलर निश्चित की गई और यह निर्णय हुआ कि इसका आधा भाग सोवियत संघ को दिया जाएगा।

4. पोलैण्ड की पूर्वी सीमा 'कर्जन रेखा' की कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकार किया जाए तथा पोलैण्ड में ग्याशीन स्वतन्त्र सरकार की स्थापना हो।

5. यूगोस्लाविया में यथाशीघ्र मार्शल टीटो और सुवासिच (Subasitch) के मध्य सम्पन्न समझौते के आधार पर नई सरकार की स्थापना की जाए।

6. यूरोप में युद्ध की समाप्ति के आगामी 3 महीनों में रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने तथा निचराष्ट्रो को सहयोग देने का आश्वासन दिया।

7. जापान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का वचन देने के बढने में स्टालिन ने चर्चिल और रूजवेल्ट से सुदूरपूर्व के सम्बन्ध में विशेष महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ प्राप्त कीं। इन दोनों ने बाह्य मंगोलिया में यथापूर्व स्थिति (Status-quo) स्वीकार की। सन् 1904 में जापान के आक्रमण के फलस्वरूप जापान द्वारा हस्तगत कुछ प्रदेश भी रूस को देने का निश्चय किया गया।

बाह्य मंगोलिया तथा रेल सम्बन्धी समझौते के सम्बन्ध में चीन की स्वीकृति नहीं ली गई थी, अतः यह निश्चय किया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट चीन की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और जापान की पराजय के बाद ही रूस को दी गई सुविधाओं को कार्यान्वित किया जाएगा। रूस चीन के साथ मंत्री सन्धि करेगा ताकि चीन को रूस की तरफ से किसी प्रकार का भय न रहे।

सान-फ्रांसिसको सम्मेलन (25 अप्रैल, 1945—26 जून, 1945)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर को अन्तिम रूप देने के लिए सान-फ्रांसिसको (अमेरिका) में विश्व के 50 राष्ट्रों के 850 प्रतिनिधि एक सम्मेलन में एकत्रित हुए और उन्होंने पूर्ण विचार विनिमय के बाद विश्व संगठन का एक चार्टर तैयार किया। 26 जून, 1945 को सान-फ्रांसिसको के वेटेरन मेमोरियल हाल में 50 राष्ट्रों के 850 प्रतिनिधियों ने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ। इस चार्टर में संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य सिद्धान्त और उसका विधान समाविष्ट था। ऐसा माना जाता है कि विश्व में ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सम्मेलन के अन्तिम प्रविवेशन में भाषण देते हुए कहा, “संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपने अभी हस्ताक्षर किए हैं, एक ऐसी सुदृढ़ नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।”

24 अक्तूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्रसंघ का यह चार्टर लागू हुआ। अतः यही दिन विश्व में ‘संयुक्तराष्ट्र दिवस’ के नाम से मनाया जाता है। 10 फरवरी, 1946 को लन्दन के वैंस्टमिनिस्टर हाल में संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रथम बैठक हुई। 15 फरवरी, 1946 को इस संघ का प्रथम प्रविवेशन समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय पहले लेकमबसेस (अमेरिका) में रखा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क में एक भव्य विशाल भवन तैयार किया गया जो 14 अक्तूबर, 1952 को इनकर पूरा हुआ और तब से ही संघ का कार्यालय न्यूयॉर्क में इसी भवन में है।

पोट्सडम (बर्लिन) सम्मेलन (17 जुलाई—2 अगस्त, 1945)

7 मई, 1945 को जर्मनी द्वारा बिना शर्त आत्म-समर्पण और युद्ध विराम सन्धि पर हस्ताक्षर करने के बाद यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। अब यूरोप का

नवीन मानचित्र तैयार करने तथा शत्रुराष्ट्रों के साथ की जाने वाली सन्धियों की रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से वर्लिन के निकट पोद्सडम नामक स्थान पर 'तीन बड़े' का सम्मेलन हुआ।

इस सम्मेलन में संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत संघ और ग्रेट-ब्रिटेन ने निम्नलिखित निर्णय लिए—

1. शान्ति समझौते की आवश्यक प्रारम्भिक तैयारी करने के लिए एक परिपक्व की स्थापना की जाए। इस परिपक्व का तात्कालिक एवं महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रस्तुत किए जाने के लिए इटली, रूमानिया, बल्गेरिया, हंगरी तथा फिनलैण्ड, की सन्धियाँ, प्रादेशिक प्रश्नों का निपटारा तथा जर्मनी के साथ की जाने वाली सन्धि की तैयारी हो।

2. जर्मनी को अमेरिकी, ब्रिटिश, रूसी और फ्रेंच—इन चारों अधिकार-क्षेत्रों में बांट लिया जाए। जहाँ तक सम्भव हो सम्पूर्ण जर्मनी की जनता के साथ समान व्यवहार किया जाए। जर्मनी को सैनिक शक्ति तथा शस्त्रास्त्रों से रहित कर दिया जाए तथा नाजी दल को अवैध घोषित कर वहाँ प्रजातान्त्रिक शासन की स्थापना की जाए।

3. जर्मनी की युद्ध-क्षमता को नष्ट करने के लिए शस्त्रास्त्र, गोला-बारूद के उत्पादन और हर प्रकार के वायुयानों व युद्ध पोतों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। जर्मन अर्थव्यवस्था को पुनः सगठित करने के लिए कृषि और शान्तिपूर्ण गृह-उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया जाए।

4. जर्मनी अपने औद्योगिक कल-कारखानों को समाप्त करके युद्ध की क्षति-पूर्ति करे। रूस इस क्षतिपूर्ति का भाग अपने अधीन जर्मन प्रदेश तथा अपने विदेशी सस्थानों में प्राप्त करे। अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देश जिनको क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार है, जर्मनी के पश्चिमी भाग तथा उससे सम्बन्धित विदेशी सस्थानों से क्षति-पूर्ति प्राप्त करें।

5. जर्मनी की सम्पूर्ण जल-शक्ति को ब्रिटेन अमेरिका और रूस में विभक्त कर दिया जाए तथा उसकी अधिकांश पनडुब्बियों को जल में डुबो कर नष्ट कर दिया जाए। जर्मन व्यापारिक जल-साधनों को रूस, अमेरिका और ब्रिटेन में बांट दिया जाए।

6. सम्मेलन में पोलैण्ड के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय किए गए। यह तय हुआ कि जर्मनी के साथ अन्तिम शान्ति समझौता होने तक तीन क्षेत्रों—ओडर तथा नायसी नदियों के पूर्व स्थित जर्मन विस्तृत प्रदेश, भू-पूर्व स्वाधीन नगर डोंजिंग का क्षेत्र तथा पूर्वी प्रशा के दक्षिणी प्रदेश को पोलिश-प्रशासन के अन्तर्गत रखा जाए। पोलैण्ड की अन्तरिम सरकार सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र पोलैण्ड में स्वतन्त्र चुनाव कराए।

7. इटली, हंगरी, फिनलैण्ड तथा बल्गेरिया के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि इनके साथ यथाशीघ्र शान्ति-सन्धियाँ की जाएँ और इन्हें संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया जाए।

देशों के साथ शान्ति-सन्धियाँ करने के प्रश्नों पर विचार किया गया। यह व्यवस्था की गई कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस मिलकर इटली के साथ की जाने वाली सन्धि का प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करेंगे; रूस, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा बल्कन क्षेत्रों के लिए सन्धि का प्रारूप तैयार किया जाएगा; फिनलैंड के लिए प्रारूप तैयार करने का कार्य ब्रिटेन तथा रूस करेंगे। तत्पश्चात् इन सभी प्रारूपों पर मित्रराष्ट्रों और उनके समर्थक राष्ट्रों के एक सामान्य सम्मेलन में विचार किया जाएगा। इस सम्मेलन की सिफारिशों को ध्यान में रखकर सन्धियों को अन्तिम रूप देने का कार्य विदेश-मन्त्रियों की परिषद् द्वारा होगा।

सन्धियों की विदेश-मन्त्रियों की परिषद् के निर्णय के अनुसार पेरिस में जनवरी, 1946 में शान्ति-सन्धियों के प्रारूपों को तैयार करने के लिए उप-विदेश मन्त्रियों की बैठकें प्रारम्भ हुईं। जुलाई के मध्य तक पाँच शान्ति-सन्धियों के प्रारूप तैयार कर लिए गए। पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति स्थापित करने के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन महायुद्धकाल के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पहले ही किया जा चुका था। अतः प्रारम्भिक अवरोधों के निवारण के उपरान्त पेरिस में 29 जुलाई, 1946 से 15 अक्टूबर, 1946 तक 21 राष्ट्रों का एक सामान्य सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। काफ़ी विचार-विमर्श के पश्चात् 10 फरवरी, 1947 को पेरिस में 21 संयुक्त अथवा मित्रराष्ट्रों तथा 5 पराजित राष्ट्रों द्वारा इन सन्धियों पर हस्ताक्षर कर दिए गए। शान्ति-सन्धियों के अनुममर्शन के लिए 15 सितम्बर, 1947 अन्तिम तिथि निश्चिन की गई। इस तरह यूरोप के अधिकांश भू-भाग पर शान्ति की पुनरावृत्ति सम्भव हुई। फिर भी किसी भी पराजित राष्ट्र ने शान्ति-सन्धियों को सन्तोषजनक, न्याय-संगत और अच्छा नहीं माना तथा 'सशोधन आन्दोलन' का यथाशीघ्र सूत्रपात हो गया। आस्ट्रिया, जर्मनी और जापान के साथ शान्ति-सन्धियों के बारे में पारस्परिक मतभेदों की उग्रता बनी रही और गतिरोध कायम रहा। आस्ट्रिया के साथ 15 जुलाई, 1955 को शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सोवियत रूस और उसके साथ ही पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया हस्ताक्षरकर्त्ताओं में सम्मिलित नहीं हुए। जापान के साथ अक्टूबर, 1956 में रूस द्वारा एक समझौता सम्पन्न हुआ और तब दोनों देशों के बीच युद्ध-स्थिति का अन्त हुआ।

जिन 5 शान्ति-सन्धियों पर 21 संयुक्तराष्ट्रों और 5 पराजित राष्ट्रों ने पेरिस में हस्ताक्षर किए वे निम्नलिखित थी—

इटली के साथ सन्धि (Peace Treaty with Italy)

इटली के साथ हुई सन्धि के अनुसार इटली के अधिकांश उपनिवेश उसमें ले लिए गए। इटली के जो प्रदेश से संलग्न थे, उनमें से कुछ फ्रांस को दे दिए गए। लगभग 3 हजार वर्गमील का क्षेत्र और एड्रियाटिक सागर में कुछ द्वीप इटली से लेकर यूगोस्लाविया को दे दिए गए। ग्रीस के समीप स्थित इटली के कई द्वीप ग्रीस को प्राप्त हुए। ट्रिस्ट को स्वतन्त्र प्रदेश बना दिया गया।

इटली को अफ्रीका में लीबिया, इरिट्रिया (Eritrea) और सोमालीलैंड के उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा।

इटली पर 36 करोड़ डॉलर का हर्जाना लादा गया जो सात वर्षों में भुदा किया जा सकता था। इस घन को यूनान, रूस, एबीसीनिया, अल्बानिया और यूगोस्लाविया को दिए जाने का निश्चय किया गया।

सन्धि द्वारा इटली की सैनिक शक्ति पर पर्याप्त प्रतिबन्ध लगा दिए गए। इसके अनिर्दिष्ट फ्रेंच और यूगोस्लाव सीमान्तों पर इटली की किलेबन्दी को नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार सिमली और सार्डीनिया के समुद्रतटों पर भी इटली ने जो किले बना रखे थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। परमाणु शस्त्रों, पनडुब्बियों, तारपीडों, विमानवाहक जहाजों आदि के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। इस सन्धि का कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि न केवल इटली के सम्पूर्ण औपनिवेशिक साम्राज्य का अन्त हो गया बल्कि इटली एक तृतीय श्रेणी की शक्ति रह गया।

रुमानिया के साथ सन्धि (Peace Treaty with Rumania)

रुमानिया से बेसरबिया और उत्तरी बकारिना छीन कर रूस को दे दिए गए। दोबुर्जा का प्रदेश बल्गेरिया को मिला। हंगरी से ट्रान्सिलवानिया लेकर रुमानिया को लौटा दिया गया। यह भी कहा गया कि रुमानिया हर्जाने के रूप में रूस को आठ साल में 30 करोड़ डॉलर का सामान दे। इसके अनिर्दिष्ट रुमानिया का काफी निःशस्त्रीकरण भी कर दिया गया।

बल्गेरिया के साथ सन्धि (Peace Treaty with Bulgaria)

बल्गेरिया की जनवरी, 1941 की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ। सन्धि द्वारा इसका कोई प्रदेश नहीं छीना गया अपितु प्रदेश उसे रुमानिया से दक्षिणी दोबुर्जा का प्राप्त हुआ, किन्तु उस पर इटली और रुमानिया की भांति विभिन्न सैनिक प्रतिबन्ध लगा दिए गए। यह भी निश्चित हुआ कि बल्गेरिया अपने यूनानी सीमान्त पर किसी प्रकार की स्थायी किलेबन्दी नहीं कर सकेगा और 8 वर्षों की अवधि में 45 करोड़ डॉलर यूनान को और 25 करोड़ डॉलर यूगोस्लाविया को क्षतिपूर्ति के रूप में देगा।

हंगरी के साथ सन्धि (Peace Treaty with Hungary)

हंगरी का ट्रान्सिलवानिया प्रदेश रुमानिया को और स्लोवाकिया प्रदेश चेकोस्लोवाकिया को लौटा दिया गया। हंगरी पर 20 करोड़ डॉलर का हर्जाना भी लगाया गया तथा निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी कुछ प्रावधान भी किए गए।

फिनलैण्ड के साथ सन्धि (Peace Treaty with Finland)

रूस और फिनलैण्ड के बीच सन् 1930 की सन्धि की पुष्टि कर दी गई। इस सन्धि के अनुसार रूस ने अपनी सीमा से लगे हुए फिनलैण्ड के सारे प्रदेश ले लिए थे। अब इन प्रदेशों पर रूस का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। फिनलैण्ड द्वारा 8 साल में रूस को 100 करोड़ रुपये चुकाना निश्चित किया गया। फिनलैण्ड पर सैनिक प्रतिबन्ध भी लगाए गए। क्षतिपूर्ति के रूप में फिनलैण्ड द्वारा 8 वर्षों में सोवियत संघ को 30 करोड़ डॉलर वस्तुओं के रूप में भुगतान करना निश्चित हुआ।

युद्धोत्तर शान्ति-प्रयासों के फलस्वरूप इस प्रकार पाँच शान्ति-संधियाँ सम्पन्न की गईं। इनके द्वारा पराजित राष्ट्रों को अपने आक्रमणकारी कार्यों के लिए समुचित

दण्ड मिला और विजयी राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति के रूप में धन एवं प्रवेश दिलाने का प्रबन्ध किया गया। शान्ति-सन्धियों ने यूगोस्लाविया को बल्कन प्रायद्वीप में सर्व-शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया जिसके परिणामस्वरूप वह इटली का प्रतिस्पर्धी बन गया। आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभ रूस को हुआ क्योंकि उसको पाँचों राष्ट्रों पर लगायी गई क्षतिपूर्ति का 70 प्रतिशत भाग अर्थात् 90 करोड़ डॉलर वसूल करने का अधिकार मिला। राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी पूर्वी यूरोप में रूस का अधिकार स्थापित हो गया। 29 जून, 1945 की सन्धि के अनुसार उसे चेकोस्लोवाकिया से 'सदकारपेयियन सन्धियाँ' मिली और पोलैण्ड से 16 अगस्त, 1945 की संधि द्वारा पूर्वी पोलैण्ड का एक बड़ा भाग प्राप्त हुआ। इन शान्ति-सन्धियों से पश्चिमी राष्ट्रों को आर्थिक तथा प्रादेशिक दृष्टि से किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ इसके विपरीत, भावी सम्झौतों में रूस की माँगें उत्तरोत्तर बढ़ती गई जिनके परिणामस्वरूप मित्रराष्ट्र जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ सामूहिक रूप से शान्ति-सन्धियाँ करने में असफल रहे।

इटली, हंगरी, बल्गेरिया, रूमानिया और फिनलैण्ड के साथ सम्पन्न की गई शान्ति-सन्धियाँ यद्यपि 15 सितम्बर, 1947 से अन्तिम रूप में लागू कर दी गईं तथापि इन सन्धियों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और इनके अनेक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ अथवा उनकी उपेक्षा की गई।

जर्मनी, आस्ट्रिया और जापान की नयी व्यवस्था

मुख्य पराजित शत्रु-देश जर्मनी, आस्ट्रिया और जापान में नई व्यवस्थाएँ स्थापित की गईं।

आत्म-समर्पण करते समय जर्मनी में एडमिरल डायनिट्स की अन्तर्कालीन सरकार सत्तारूढ़ थी। मित्रराष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता न देकर जर्मनी का शासन-भार स्वयं सम्भाल लेने का निश्चय किया।

जर्मनी को चार भागों में बाँट कर एक-एक भाग का शासन अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस को सौंपा गया। इस व्यवस्था के अनुसार पूर्वी जर्मनी पर रूस का, पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका का, फ्रांस से संलग्न भाग पर फ्रांस का और बेल्जियम हॉलैण्ड की सीमा से संलग्न जर्मन प्रदेशों पर इंग्लैण्ड का अधिकार हो गया। पूर्वी जर्मनी पर रूस का कब्जा हो जाने से बर्लिन के चारों ओर का प्रदेश रूसी अधिकार में आ गया। परन्तु बर्लिन को भी चार भागों में विभक्त कर अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस और रूस का पृथक्-पृथक् शासन स्थापित किया गया।

इस तरह सम्पूर्ण जर्मनी में मित्रराष्ट्रों का संयुक्त शासन स्थापित हो गया। हजनि के रूप में जर्मनी पर एक भारी रकम लाद दी गई। इस सम्बन्ध में यह निश्चय किया गया कि केवल कुछ ही मशीनें जर्मनी में रहने दी जाएँ। शेष सब मशीनें, कारखाने, युद्ध-सामग्री जहाज आदि जर्मनी से हटा कर रूस, फ्रांस, पोलैण्ड, बेल्जियम, आदि देशों में विभक्त कर दिए जाएँ।

जर्मनी में लागू की गई इस व्यवस्था का निर्णय पोट्सडम सम्मेलन में ही कर लिया गया था जो 17 जुलाई, 1945 को हुआ था। इसका उल्लेख आगे यथास्थान किया गया है। वैसे जर्मनी के प्रश्न पर इतने व्यापक मतभेद प्रकट होते रहे हैं कि प्रत्येक प्रयत्नो के बावजूद अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विधिवत् सन्धि सम्पन्न नहीं हो सकी है।

आस्ट्रिया की व्यवस्था

जर्मनी की भाँति ही आस्ट्रिया में भी सैनिक शासन की स्थापना की गई। आस्ट्रिया की राजधानी वियना को चार भागों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक भाग पर एक-एक मित्रराष्ट्र का अधिकार स्थापित हुआ। सन् 1955 के प्राग्मन तक आस्ट्रिया का प्रश्न अघोर में लटका रहा। बाद में काफी विचार-विमर्श के उपरान्त 15 जुलाई, 1955 को आस्ट्रिया के साथ आन्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर हो पाए। इस सन्धि द्वारा 12 मार्च, 1938 के बाद 17 वर्ष तक पराधीन रहने के पश्चात् आस्ट्रिया को स्वाधीनता एवं सर्वोच्च प्रभुता प्राप्त हुई। आस्ट्रिया राज्य की सन्धि पर संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ग्रेट-ब्रिटेन और आस्ट्रिया ने हस्ताक्षर किए। सन्धि द्वारा आस्ट्रिया यद्यपि एक प्रभुत्व-सम्पन्न, स्वतन्त्र और प्रजातन्त्रात्मक राज्य (A Sovereign, Independent and Democratic State) के रूप में उद्घोषित हुआ, तथापि उसके द्वारा यह वचन दिया गया कि वह जर्मनी के साथ किसी प्रकार का राजनीतिक या आर्थिक संध नहीं बनाएगा।

जापान की व्यवस्था

जुलाई-अगस्त, 1945 के पोट्सडम सम्मेलन में जापान के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ व्यापक निश्चय किए गए थे। एक निश्चय यह भी था कि जापान के सैनिक तत्वों का पूर्ण विनाश होने तक मित्रराष्ट्रों का जापानी प्रदेश पर सैनिक अधिकार बना रहेगा। इस निश्चय के अनुरूप दिसम्बर, 1945 में मास्को में संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा चीन के प्रतिनिधियों को एक मित्र-राष्ट्रीय संयुक्त परिषद् का निर्माण कर दिया गया जिसका अध्यक्ष जनरल मैकार्थर को बनाया गया। वास्तव में जापान पूर्ण रूप से अमेरिका के नियन्त्रण में आ गया क्योंकि यह अमेरिका ही था जिसने अणु बम गिराकर जापान को परास्त किया था। प्रारम्भ में जापान की भूमि पर ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेनाएँ थीं, परन्तु 1947 के बाद वहाँ केवल अमेरिकी सेना ही रह गई और जनरल मैकार्थर जापान का एक प्रकार से सर्वोच्च बन गया।

विजेता राष्ट्रों में जापान के भविष्य के बारे में गहरे मतभेद होने में एक लम्बे समय तक उसके साथ (जापान के साथ) सन्धि-वार्ता प्रारम्भ नहीं की जा सकी। अन्त में जनवरी, 1951 में अमेरिका के तत्कालीन विदेश-मन्त्री ने विभिन्न राष्ट्रों से परामर्श करने के उपरान्त सन्धि का एक प्रारूप तैयार किया जिसके अनुसार—

1. जापान की सर्वोच्च-सत्ता और प्रभुता केवल 4 बड़े और कुछ छोटे द्वीपों के एक लाख पचास हजार वर्गमील के क्षेत्र तक सीमित कर दी गई।

2. जापान ने कोरिया की स्वतन्त्रता स्वीकार की, फारमोसा और ब्यूराइल, सन्थालान टापुओं पर अपने अधिकार का परित्याग किया और प्रशान्त महासागर में बोनिन व र्यूकू टापुओं पर 2 अप्रैल, 1947 से अमेरिका की ट्रस्टीशिप स्वीकार की।

3. जापान ने चीन में अपने सब अधिकारों को छोड़ना और मित्रराष्ट्रों के युद्ध-प्रपराध न्यायालय के निर्णयों को मानना स्वीकार किया।

4. जापान ने युद्ध पूर्व के ऋणों के भुगतान का दायित्व भी स्वीकार किया। सन्धि में और भी अनेक बातें सविस्तार दी गई हैं। डलेस के प्रयत्नों से अन्त में 8 दिसम्बर, 1951 को इस प्रस्तावित जापानी सन्धि पर 48 राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। सोवियत रूस, पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया अलग रहे। जापान के साथ होने वाली यह शान्ति-सन्धि 28 अप्रैल, 1952 से क्रियान्वित हुई। अक्टूबर, 1956 में रूस और जापान के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच युद्ध-स्थिति का अन्त हो गया। फिर भी दोनों के बीच कोई औपचारिक शान्ति-सन्धि अभी तक सम्पन्न नहीं हो सकी है।

स्पष्ट है कि व्यापक भ्रम्रिम तैयारियों के बावजूद सन् 1945 के बाद शान्ति समझौते का कार्य सन् 1919 की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन सिद्ध हुआ। द्वितीय महायुद्ध के साथ ही विजेता राष्ट्रों में युद्ध के उपरान्त मतभेद अधिकधिक व्यापक और उग्रतर हो गए तथा पूर्व और पश्चिम के मध्य विश्व-शान्ति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण शीत-युद्ध का श्रीगणेश हो गया।

युद्धोत्तर विश्व (The Post-War World)

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जिस नवीन युग का सूत्रपात हुआ उसमें अनेक 'नूतन क्षितिज उभरे नवीन प्रमुख उभरे, क्षेत्र बदले, नवीन प्रवृत्तियों और सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् को नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की अनेक प्राचीन और परम्परागत मान्यताएँ नष्ट हो गईं। युद्धोत्तर युग में अनेक विरोधी प्रवृत्तियाँ एक साथ त्रियाशील हुईं और विभिन्न 'वाद' विश्व को प्रभावित करने लगे। यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की दुर्बलताओं का मान हुआ। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र राष्ट्रीय सम्प्रभुता की पवित्रता का प्रतिपादन करने लगे। ये प्रवृत्तियाँ समाप्त नहीं हुई, वरन् आज भी अस्तित्व में हैं।

यहाँ हमारा मन्तव्य द्वितीय महायुद्ध से अत्र तक के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विश्लेषण करना नहीं है वरन् महायुद्ध से तुम्हें बाद जो नया मानचित्र निर्मित हुआ, जो प्रवृत्तियाँ उभरी और विश्व जिस नई दिशा में अग्रसर हुआ उसका चित्रण मात्र करना है। युद्धोत्तर युग की इन घटनाओं, प्रवृत्तियों, नवीनताओं और विशेषताओं को संक्षेप में हम निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं—

यूरोपीय प्रभुत्व का अन्त और एशिया व अफ्रीका का जागरण—जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, युद्धोत्तर नवीन युग की पहली महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति

यह थी कि विश्व इतिहास का निर्माता यूरोप पंगु बन गया और सोता हुआ एशिया व अफ्रीका तेजी से जाग्रत होने लगा। प्राचीन काल से विश्व को अनुशासित करने वाला यूरोप (World Dominating Europe) महायुद्ध के बाद नवीन 'समस्या-प्रधान यूरोप' (Problem Europe) बन गया। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद का उन्मूलन होने लगा। यूरोपीय साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक व्यवस्था को कितना भारी आघात पहुँचा, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहाँ पहले सत्तार की जनसंख्या का लगभग 33 प्रतिशत भाग स साम्राज्यवाद के शिकरे में था वह अब 3-4 प्रतिशत से भी कम रह गया है।

सिद्धान्तों का संघर्ष—द्वितीय महायुद्ध के बाद सिद्धान्तों व आदर्शों पर बल देने की प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की एक प्रमुख विशेषता बन गई। विभिन्न सिद्धान्तों, आदर्शों और विचारधाराओं का उदय हुआ जिनमें से कुछ में साम्य था तो अधिकांश में परस्पर विरोध। ये विभिन्न विचारधाराएँ विकसित होती रही और अपनी शाखाओं-प्रशाखाओं का विस्तार करती रही। अमेरिकी उदारवाद, साम्यवाद, तटस्थतावाद, राष्ट्रवाद, अन्तर्राष्ट्रीयतावाद आदि सिद्धान्तों अथवा आदर्शों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच को प्रभावित किया और आज भी इनसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध व्यापक रूप से प्रभावित हैं।

द्वि-ध्रुवीयता का विकास और शीतयुद्ध का प्रारम्भ—युद्धोत्तर विश्व ने प्राचीन शक्ति सन्तुलन को छिन्न-भिन्न कर दिया और द्वि-ध्रुवीयता को जन्म दिया। युद्धोत्तर विश्व दो प्रमुख शक्ति-केन्द्रों या शक्ति-ध्रुवों में बँट गया—सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों ही के नेतृत्व में दो विरोधी, शक्तिशाली गुटों का निर्माण होने लगा। जहाँ महायुद्ध काल में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन आदि ने परस्पर कंधे से कंधा मिलाकर 'घुरीराष्ट्रों' (जर्मनी, जापान व इटली) के विरुद्ध संघर्ष किया था और उनके राजनीतिज्ञों तथा कूटनीतिज्ञों ने सम्मेलन और पत्र-व्यवहार आदि में एक दूसरे को सहयोग दिया था, वहाँ युद्ध के बाद इन राष्ट्रों में सहयोग के सभी आधार समाप्त हो गए। युद्ध के समय के दोस्तों में युद्ध के बाद, तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गए। शीघ्र ही इन मतभेदों ने तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य की ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि पश्चिमी और पूर्वी शिविरो के राज्यों में बारूद के गोले-गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र संघर्षों के न होते हुए भी कागज के गोले तथा अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। इसी संग्राम को 'शीत-युद्ध' (Cold War) की संज्ञा दी गई।

प्रादेशिक संगठनों का निर्माण—युद्धोपरान्त विश्व में रूस और अमेरिका दोनों ही शक्ति-केन्द्र अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक संगठनों और सन्धियों के निर्माण की ओर अग्रसर हुए। साम्यवादियों का प्रसार एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका में स्थापित पूँजीवादी राष्ट्रों के साम्राज्य और उपनिवेशों में घुन का काम कर रहा था। अतः जहाँ-कहाँ भी साम्राज्यवादी शक्तियों को चुनौती मिली, वहीं पूँजीवादी राष्ट्रों ने इस चुनौती का डटकर मुकाबला करने की चेष्टा की। फलस्वरूप

अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर अनेक ऐसी सन्धियों और संगठनों का विकास होने लगा जिनका मुख्य लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। रूस व उसके साथी राष्ट्रों में पश्चिमी शक्तियों के इन प्रयासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। इस तरह की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम यह हुआ कि एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने साम्यवादी राष्ट्रों के चारों ओर सुरक्षा-संगठनों का एक घेरा-सा डालकर साम्यवाद पर प्रकुश लगाने की चेष्टा की, दूसरी ओर रूस ने अपने व पश्चिमी राष्ट्रों के बीच के देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर अपनी सुरक्षा-व्यवस्था को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाया। पश्चिमी शक्तियों ने नाटो, सीटो, बगदाद पैंक्ट आदि का निर्माण किया तो साम्यवादी सुरक्षा संगठनों में वारसा पैंक्ट आदि सम्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त कुछ अर्द्ध-संघीय प्रादेशिक संगठनों का विकास भी होने लगा, जैसे यूरोपीय साभा बाजार।

मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व की महत्ता में वृद्धि—द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त एशिया के दो क्षेत्र मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में निरन्तर महत्त्वपूर्ण होते गए और यह स्थिति आज भी है। तेल के बहुल भण्डारों की खोज के फलस्वरूप मध्यपूर्व न केवल अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन चुका है बल्कि एक प्रधान सफ्ट-पवर् भी बन गया है। दूसरी ओर एक महत्त्वपूर्ण तटस्थ राष्ट्र के रूप में अगस्त, 1947 में स्वतन्त्र भारत के उदय ने तथा एक महान् शक्ति के रूप में लाल चीन के विकास ने सुदूरपूर्वीय क्षेत्र को विश्व के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों की श्रेणी में ला दिया है। इस क्षेत्र में चीन विशेष रूप से अमेरिका का घोर प्रतिद्वन्द्वी बन गया है।

विश्व-सरकार अथवा एक विश्व की भावना का विकास—युद्धोपरान्त युग में जिस महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति का उदय हुआ, वह अन्तर्राष्ट्रीयतावाद, एक विश्व का स्वप्न अथवा विश्व सरकार की भावना है। यह कहा जाने लगा है कि 'यदि आप विश्व में स्थायी रूप से शान्ति चाहते हैं और तृतीय विश्व-युद्ध में अणु-शक्ति के प्रकोप से मानवता की रक्षा करना चाहते हैं तो विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक विश्व-संघ का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें शान्ति और व्यवस्था का काम विश्व-सरकार को सौंप दिया जाए।' 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' की स्थापना इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम माना जा सकता है, तथापि आज भी बहुसंख्य ऐसे ही विचारकों की है जो विश्व-सरकार के विचार को व्यावहारिक मानते हैं।

निष्कर्ष रूप में सन् 1945 के बाद का विश्व विभिन्न सिद्धान्तों, रूपों, विचारों और आदर्शों की सघर्ष-स्थली बना है। प्राणविक आयुधों की भयानकता ने विश्व की महाशक्तियों को सन्तुलन और विवेक से काम लेने को बाध्य कर दिया है। साथ ही शक्ति के नए केन्द्र विकसित होते जा रहे हैं जिनसे विश्व का द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) चित्र घूमिल पड़ रहा है और विश्व बहुकेन्द्रवाद (Polycentricism) की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, इसका विधान और कार्य-प्रणाली

(THE UNITED NATIONS, ITS STRUCTURE
AND WORKING)

"संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर जिस पर आपने भी हस्ताक्षर किए हैं, एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर एक सुन्दर विश्व का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।"—राष्ट्रपति ट्रूमेन

प्रथम महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रमण्डल अस्तित्व में आया। अनेक दुर्बलताओं और महाशक्तियों के असहयोग के कारण वह अपने उद्देश्य में असफल रहा। सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और मित्रराष्ट्र एक नई प्रभावशाली विश्व-संस्था स्थापित करने की योजना बनाने लगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना

महायुद्धकाल में एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की दिशा में अनेक कदम उठाए गए जिनमें ये थे¹—

14 अगस्त, 1941—संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटेन शान्ति के आधारभूत सिद्धान्तों पर सहमत हो गए जिन्हें बाद में अटलांटिक चार्टर का नाम दिया गया।

1 जनवरी, 1942—26 राष्ट्रों ने घुरी शक्तियों को पराजित करने और अटलांटिक चार्टर को स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की। इस घोषणा में, 'संयुक्त राष्ट्रों' (United Nations) शब्दों का पहली बार प्रयोग हुआ। बाद में 21 और राष्ट्रों ने भी, घोषणा में सहमति प्रकट की।

30 अक्टूबर, 1943—मास्को घोषणा में चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका इस बात पर सहमत हो गए कि शान्ति स्थापित रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाए।

अगस्त-अक्टूबर, 1944—डम्बरटन-ओक्स सम्मेलन में, जिसमें चीन, सोवियत संघ, संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हुए थे एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के लिए प्रारम्भिक प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की गई।

अप्रैल-जून, 1945—सान-फ्रांसिस्को-सम्मेलन में 51 राष्ट्र सम्मिलित हुए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का प्रारूप तैयार किया और उसे स्वीकार किया। इस प्रारूप पर 26 जून, 1945 को हस्ताक्षर कर दिए गए। पोलैण्ड ने, जो कि सम्मेलन में उपस्थित होने में असमर्थ रहा, चार्टर पर बाद में हस्ताक्षर किए और इस प्रकार वह भी संघ के प्रारम्भिक सदस्यों (Original Members) में गिना गया।

24 अक्टूबर, 1945—चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्तराज्य अमेरिका और बहुत से दूसरे हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों ने चार्टर का अनुसमर्थन कर दिया। इस तारीख को संयुक्त राष्ट्रसंघ विधिवत् रूप से अस्तित्व में आ गया और इसलिए यह दिन (24 अक्टूबर) विश्व में 'संयुक्त राष्ट्र दिवस' (United Nations Day) के रूप में मनाया जाता है।

8 अप्रैल, 1946 को राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) ने एक प्रस्ताव पास कर अपनी समाप्ति की घोषणा कर दी। उसके उत्तरदायित्वों, कार्यक्रमों, सम्पत्ति तथा भवनों आदि को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सम्भाल लिया।

चार्टर की प्रस्तावना

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान को घोषणापत्र (Charter) कहते हैं। चार्टर की प्रस्तावना (Preamble) बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन लोगों के आदर्शों और सामान्य उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जिनकी सरकारों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का निर्माण करने के लिए कदम उठाए। यह सुन्दर प्रस्तावना इस प्रकार है¹—

- ① "संयुक्त राष्ट्रों के हम लोगों ने यह पक्का निश्चय किया है कि हम आने वाली पीढ़ियों को उस युद्ध की विभीषिकाओं से बचाएँगे जिसने हमारे जीवन-काल में ही दो बार गनुष्य मात्र पर अकथनीय दुःख डाले हैं, और
- ② कि हम मानवता के मूल अधिकारों में, मानव की गरिमा और महत्व में, और छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों के नर-नारियों के समान अधिकार में फिर प्रास्था पैदा करेंगे, और
- ③ कि हम ऐसी स्थिति पैदा करेंगे जिससे न्याय और उन दायित्वों का सम्मान कायम रहे जो सन्धियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दूसरे स्रोतों से हम पर पड़ते हैं, और
- ④ कि हम अधिक व्यापक स्वतन्त्रता द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊँचा उठाएँगे और समाज को प्रगतिशील बनाएँगे।

इन उद्देश्यों के लिए

हम सहनशील बनेंगे और अच्छे पड़ोसियों की तरह साथ मिलकर शान्ति से रहेंगे, और

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों का संगठन करेंगे, और उन नियमों का पालन करेंगे और ऐसे साधनों से काम लेंगे जिनसे इस बात का विश्वास हो जाए कि अपने सामान्य हितों की रक्षा के अलावा हथियारबन्द सेनाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और सभी लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय साधनों का प्रयोग करेंगे।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमने मिलकर प्रयत्न करने का निश्चय किया है

इसलिए हमारी सरकारें अपने प्रतिनिधियों के रूप में सान-फ्रांसिस्को नगर में एकत्र हुई हैं। इन प्रतिनिधियों ने अपने अधिकार-पत्र दिखाए जिनको ठीक और उचित रूप में पाया गया है और इन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के इस चार्टर को स्वीकार कर लिया है और इसके आधार पर वे अब एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि की स्थापना करते हैं जिसका नाम 'संयुक्त राष्ट्रसंधि' होगा।"

प्रयोजन और सिद्धान्त

चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्रसंधि के प्रयोजनों (Purposes) का और अनुच्छेद 2 में सिद्धान्तों (Principles) का उल्लेख किया गया है।

(क) संयुक्त राष्ट्रसंधि के प्रयोजन (Purposes) संक्षेप में ये हैं—

1. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करना और सामूहिक तथा प्रभावपूर्ण प्रयत्नों में आने वाले खतरों का उन्मूलन करना, शान्ति भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना तथा न्याय और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों के आधार पर शान्तिपूर्ण साधनों से उन अन्तर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं को सुलभाना जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो।

2. सब राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना।

3. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और बिना किसी भेद-भाव के मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्मान को प्रोत्साहन देना।

4. संयुक्त राष्ट्रसंधि को एक ऐसा केन्द्र बनाना जहाँ इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के अलग-अलग प्रयासों में सामञ्जस्य स्थापित किया जा सके।

(ख) उपर्युक्त प्रयोजनों को पूरा करने के लिए संधि और उसके सदस्य जो भी काम करें, उनमें इन सिद्धान्तों (Principles) का ध्यान रखा जाना आवश्यक है—

1. संयुक्त राष्ट्रसंधि का आधार सब सदस्यों की सम्प्रभुता की समानता (Sovereign Equality) का सिद्धान्त है।

2. सभी सदस्य अपने उन दायित्वों को ईमानदारी के साथ निभाएंगे जो उन्होंने चार्टर द्वारा अंगीकार किए हैं।

3. सभी सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण साधनों से इस प्रकार तय करेंगे कि विश्व की सुरक्षा, शान्ति और न्याय खतरे में न पड़ें।

4. सभी सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में किसी राज्य की अखण्डता तथा राजनीतिक स्वाधीनता के विरुद्ध न तो बलकी देगे और न बल-प्रयोग करेंगे। वे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो संयुक्त-राष्ट्रों के प्रयोजन से मेल न खाता हो।

5. सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ को ऐसी हर कार्यवाही में सब तरह की सहायता देंगे जो चार्टर के अनुसार हो। वे ऐसे किसी भी राज्य की सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ रोकथाम की कोई कार्यवाही कर रहा हो।

6. संघ इस बात का विश्वास दिलाएगा कि जो राज्य इसके सदस्य नहीं हैं वे भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए इन्हीं सिद्धान्तों का पालन करेंगे।

7. चार्टर में जो कुछ कहा गया है उससे संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी भी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का अधिकारी नहीं होगा।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयोजन और सिद्धान्त वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग के महान् आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यदि सदस्य-राज्य ईमानदारी से इनका अनुसरण करें तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत् विनाशकारी सघर्षों से बच जाए और विश्व के सभी देश सुख तथा समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने लगे। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सदस्य-राष्ट्र चार्टर की भावना का पालन नहीं करते, बल्कि चार्टर की धाराओं का प्रयोग इस ढंग से करते हैं कि उनके राजनीतिक स्वार्थों को पूर्ति हो। सिद्धान्त रूप में चार्टर के शब्दों में विश्वास व्यक्त किया जाता है लेकिन व्यवहार में चार्टर की भावना का उल्लंघन होता है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ इतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सका है जितना होना चाहिए था। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यह विश्व-संस्था वास्तव में पूरी तरह महाशक्तियों के हाथ का खिलौना बन गई है जिसमें छोटे राष्ट्रों की कोई परवाह नहीं की जाती। फिर भी इस बात से कुछ सन्तोष होता है कि भूतपूर्व राष्ट्रसंघ की तुलना में संयुक्त राष्ट्रसंघ अभी तक काफी सफल रहा है और इस सन्स्था के सदस्य-राष्ट्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई है। मानवता के लिए वह दिन सौभाग्य का सूचक होगा जब संयुक्त राष्ट्रसंघ सही अर्थों में सभी राष्ट्रों के हितों की ईमानदारी से रक्षा करेगा और बड़े राष्ट्र अपनी अड़बेबाजी की राजनीति में इस सन्स्था को दूषित करना छोड़ देंगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता

चार्टर में तीन से लेकर छह तक सदस्यता सम्बन्धी अनुच्छेद हैं। संघ की सदस्यता दो प्रकार की है। कुछ देश प्रारम्भिक सदस्य हैं और कुछ को बाद में सदस्यता प्रदान की गई। प्रारम्भिक सदस्य (Original Members) वे 51 राज्य हैं जिन्होंने सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था और चार्टर को स्वीकार किया था। दूसरे सदस्य वे हैं जिन्होंने संघ में बाद में प्रवेश किया। संघ की सदस्यता उन सभी राज्यों के लिए खुली है जो शान्तिप्रिय हों और चार्टर में विश्वास करते हों। अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्य बनाने के लिए अनिवार्य शर्तें ये हैं—(1) वह

शान्तिप्रिय राज्य हो, (2) चार्टर द्वारा प्रस्ताविन कर्तव्यों को स्वीकार करता हो, (3) संध के निर्णय के अनुसार उन कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ हो, एवं (4) संध के निर्णयानुसार उन कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा रखता हो। सदस्य बनना तभी सम्भव है जब महासभा का दो-तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद् की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। सुरक्षा परिषद् के वर्तमान पन्द्रह में से नौ सदस्यों का बहुमत तथा स्थायी सदस्यों का निर्णयात्मक मत इसके पक्ष में होना चाहिए। महासभा में निर्णय लेने से पूर्व सुरक्षा परिषद् की स्वीकृति आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सदस्यता की दृष्टि से आज एक विश्वव्यापी संगठन बन चुका है। 1945 में इसके प्रारम्भिक सदस्य केवल 51 थे जबकि सितम्बर 1974 में इसकी कुल सदस्य संख्या 138 और 1975 के मध्य तक 140 हो गई। 1977 के अन्त में इसकी सदस्य संख्या 148 थी। नए सदस्य राज्यों में बंगलादेश, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी, बहामा, वियतनाम आदि उल्लेखनीय हैं। दोनों जर्मन राष्ट्रों के संध की सदस्यता प्रदान करना एक क्रांतिकारी घटना थी क्योंकि आधिकारिक रूप में इसे द्वितीय महायुद्ध का अंग माना जा सकता है। 1 मई, 1975 को वियतनाम युद्ध समाप्त हो जाने से और राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा दक्षिण वियतनाम में सत्ता सम्भाल लेने से इस बात की सम्भावना प्रबल हो गई है कि सम्पूर्ण वियतनाम एक ही भण्डे के नीचे आ जाएगा और एक राष्ट्र के रूप में संयुक्तराष्ट्र संध में प्रवेश करेगा। सितम्बर, 1977 में विश्व समुदाय ने साम्यवादी वियतनाम गणतन्त्र को अपनी विरादरी में शामिल कर लिया। वह विश्व-संस्था का 148वाँ सदस्य था। स्विट्जरलैण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है लेकिन वह स्वेच्छा से सदस्य नहीं बना है। वैसे, संध के कार्य-कलापों में वह पूरी तरह सहयोग करता है। उसका आचरण ऐसा है जैसे वह संध का ईमानदार सदस्य हो। साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ में महाशक्तियों के आपसी तनाव का एक बड़ा कारण रहा था। यह शीतयुद्ध का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। लेकिन 26 अक्टूबर, 1971 को ताइवान को निष्कासित कर उसके स्थान पर साम्यवादी चीन को संध का सदस्य बनाकर शीतयुद्ध की एक विकट समस्या को सुलझा दिया गया। लगभग 70 करोड़ की जनसंख्या वाले राष्ट्र को सदस्यता प्रदान कर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सच्चे अर्थों में एक सार्वभौमिक संगठन का रूप ले लिया है।

चार्टर में किसी राष्ट्र की सदस्यता समाप्त करने की भी व्यवस्था है। ऐसे किसी सदस्य-राज्य को जो चार्टर के मिद्धान्तों का लगातार उल्लंघन करे, चार्टर के छठी धारा के अन्तर्गत संध से निष्कासित किया जा सकता है। यह सुरक्षा परिषद् की अनुशंसा पर महासभा के निर्णय से होता है।

चार्टर में सदस्यता के निलम्बन की भी व्यवस्था है। ऐसे किसी भी सदस्य-राज्य को, जिस पर निरोधात्मक या दण्डात्मक कार्यवाही की गई हो, निलम्बित किया जा सकता है। लेकिन उपर्युक्त समझे जाने पर उसे पुनः सदस्यता प्रदान की जा सकती है। इन दोनों ही बातों के लिए सुरक्षा परिषद् की सिफारिश आवश्यक है। निलम्बन महासभा के निर्णय से होता है।

चार्टर में संघ की सदस्यता परित्याग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सदस्य-राज्य सम्प्रभु होते हैं अतः वे सदस्यता जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। अपनी सार्वभौमिकता के इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए इण्डोनेशिया ने जनवरी, 1965 में संघ से पृथक् होने की सूचना दी थी। सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान ने भी संघ छोड़ने की धमकी दी थी, पर वह ऐसा साहस नहीं कर सका। इण्डोनेशिया में जब नई सरकार का निर्माण हुआ तो उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता पुनः प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की और 28 दिसम्बर, 1966 को उसे फिर से संघ में शामिल कर लिया गया।

चार्टर में संशोधन की व्यवस्था

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में संशोधन की व्यवस्था अध्याय 18 में अनुच्छेद 108 और 109 के अन्तर्गत दी गई है। यह अनुच्छेद इस प्रकार हैं—

अनुच्छेद 108—वर्तमान चार्टर में जो भी संशोधन होवे वे राष्ट्रसंघ के सब सदस्यों पर तभी लागू हों सकेंगे जब उनको महासभा दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार कर ले और सुरक्षा परिषद् के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई बहुमत से उनकी पुष्टि कर दें।

अनुच्छेद 109—1. जब कभी चार्टर के पुनरावलोकन की बात हो तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलन किया जा सकता है जिसकी तारीख, समय और स्थान महासभा दो-तिहाई बहुमत से और सुरक्षा परिषद् अपने किन्हीं सात सदस्यों के मत से तय करेगी। उस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ के हर सदस्य का एक वोट रहेगा।

2. यदि सम्मेलन में वर्तमान चार्टर का कोई परिवर्तन दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह तभी लागू हो सकेगा जब सुरक्षा परिषद् के सदस्य अपनी-अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार दो-तिहाई बहुमत से उनकी पुष्टि कर दें।

3. चार्टर के क्रियान्वयन के बाद महासभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन के पहले अगर ऐसा सम्मेलन नहीं होता तो ऐसा सम्मेलन करने का प्रस्ताव महासभा के उसी अधिवेशन के एजेण्डा पर रखा जाएगा और अगर महासभा में बहुमत से और सुरक्षा परिषद् में किन्हीं सात सदस्यों के मत से यह स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा सम्मेलन बुलाया जा सकेगा।

चार्टर की कुछ अन्य व्यवस्थाएँ

संघ के चार्टर की कुछ अन्य उल्लेखनीय व्यवस्थाएँ ये हैं—

पुस्त सन्धियों और पुस्त राजनयिक प्रणाली के विरुद्ध व्यवस्था—इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 102 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है कि संघ के सदस्य जो सन्धियाँ या अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करेंगे (चार्टर के लागू होने के बाद) उन्हें यथाशीघ्र संघ के सचिवालय में पंजीकृत कराया जाएगा और उसके बाद सचिवालय उन्हें यथाशीघ्र

प्रकाशित करेगा। जिन सन्धियों और समझौतों को पजीकृत नहीं किया गया उनकी शर्तों को दुहाई संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी अंग के समक्ष नहीं दी जा सकेगी।

चार्टर के दायित्वों को प्राथमिकता—इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 103 में उल्लेख है कि—“यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी सदस्य के वर्तमान चार्टर के दायित्व किसी दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के दायित्व के विरुद्ध पड़ते हों, तो उस स्थिति में वर्तमान चार्टर के दायित्वों को माना जाएगा।”

सदस्यों के आवश्यक कानूनी अधिकार, विशेषाधिकार आदि की व्यवस्था—अनुच्छेद 104 और 105 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में मुख्य व्यवस्थाएँ ये हैं—

(क) संघ को अपने हर सदस्य-देश में अपने कार्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे।

(ख) संघ को अपने हर सदस्य-देश में अपने प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(ग) उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों के प्रतिनिधियों और संघ के अधिकारियों को संघ के कार्यों को स्वतन्त्र रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त होंगी।

भाषाएँ—अनुच्छेद 111 के अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषाएँ चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, अंग्रेजी और स्पेनी होंगी। अधिकांश काम अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में होता है।

भाषा—संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा राष्ट्रसंघ की भाँति ही सदस्य-राज्यों के चन्दे पर आधारित है। विभिन्न सदस्य एक निश्चित अनुदान सूची के अनुसार संघ के वार्षिक बजट में वार्षिक चन्दे के रूप में अपना अनुदान देते हैं। अनुदान की राशि राष्ट्र की देय शक्ति के अनुपात में निर्धारित की गई है। उदाहरणार्थ 1947 में निर्धारित राशि के अनुसार अमेरिका संघ के बजट का 39.9 प्रतिशत, ब्रिटेन 11.84 प्रतिशत, रूस 7.40 प्रतिशत, फ्रांस 6 प्रतिशत, चीन 6 प्रतिशत, भारत 3.95 प्रतिशत अनुदान देते थे। सदस्य-राज्य अपने अनुदान में नियमित नहीं रहे हैं और उनकी टालमटोल की नीति के कारण कई अवसरों पर संघ को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंग

चार्टर के अनुच्छेद सात में संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंगों (Organs) का उल्लेख है। तदनुसार प्रमुख अंग छ हैं—

1. महासभा (General Assembly)
2. सुरक्षा परिषद् (Security Council)
3. आर्थिक और सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council)
4. न्यास परिषद् (Trusteeship Council)
5. न्याय का अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
6. सचिवालय (Secretariat)

चार्टर के अनुसार आवश्यकतानुसार अन्य सहायक अंग भी स्थापित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 8 में उल्लेख है कि "संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने प्रमुख या सह अंगों में समानता की दशा में किसी भी हैसियत से काम करने के लिए किम्वं नर-नारी की पात्रता पर कोई पाबन्दी नहीं लगाएगा।"

महासभा (The General Assembly)

चार्टर के अध्याय चार में अनुच्छेद 9 से 22 तक महासभा की रचना, तथा शक्तियों से सम्बन्धित हैं। महासभा को सच की व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है, तथापि इसके प्रभाव वाष्पकारी नहीं हैं। सच के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य-राज्य को महासभा में पाँच प्रतिनिधि तथा वैकल्पिक प्रतिनिधि (Alternative Delegates) भेजने का अधिकार है, उसका मत एक ही होता है। महासभा का एक अध्यक्ष और सात उपाध्यक्ष हैं। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति चुनती है।

महासभा का अधिवेशन

महासभा का अधिवेशन बर्ष में एक बार होना अनिवार्य है, सुरक्षा परिषद या सच के सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर महासचिव द्वारा विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसे विशेष अधिवेशन कई अवसरों पर बुलाए जा चुके हैं—फिनलैंड की समस्या पर 28 अप्रैल से 15 मई, 1947 और 16 अप्रैल से 14 मई, 1948 तक; मध्यपूर्व की स्थिति पर 1 से 10 नवम्बर, 1956 हंगरी की स्थिति पर 4 से 10 नवम्बर, 1956 तक; लेबनान की समस्या पर 21 अगस्त, 1958 तक; कांगो की समस्या पर 17 से 20 मितम्बर 1960 विशेष अधिवेशन बुलाए गए थे। जून, 1967 में अरब इजरायल संघर्ष पर विचारों के लिए भी महासभा का विशेष अधिवेशन हुआ था। सन् 19६७ भारत-पाक युद्ध के समय भी महासभा का विशेष अधिवेशन आयोजित किया था।

महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से साधारण प्रश्नों के निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। उस सदस्य को, सच का पूरा चन्दा न दिया हो, मतधिकार से वंचित किया जा सकता है।

महासभा की समितियाँ

महासभा का कार्य मुख्यतः सात समितियों में विभक्त है। प्रत्येक समिति अपना एक प्रतिनिधि भेज सकती है। ये सात समितियाँ हैं—(1) राजनयिक और सुरक्षा समिति, (2) आर्थिक तथा वित्तीय समिति, (3) सामाजिक-सांस्कृतिक समिति, (4) न्याय समिति, (5) प्रशासकीय एवं बजट समिति, (6) कानूनी समिति, एवं (7) विशेष राजनीतिक समिति।¹ इनके अतिरिक्त

1 Political and Security Committee, Economic and Financial Committee, Social, Humanitarian and Cultural Committee, Trusteeship Committee, Administrative and Budgetary Committee, Special Political Committee

24 प्रक्रियात्मक (Procedural) समितियाँ भी होती हैं जैसे सामान्य समिति जो उक्त समितियों की कार्यवाहियों में सम्बन्ध स्थापित करती हैं एवं प्रमाण-पत्र प्रवृत्ति (Credential Committee) जो प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्रों की जाँच करता है।

सभा में संयोग एवं समूह

महासभा एक सदस्यीय निकाय की भाँति है क्योंकि वहाँ एक प्रकार की रूपरेखा दलीय व्यवस्था (Embryonic Party System) प्रभावी रहती है। सदस्य-राज्य निरन्तर एक दूसरे से मिलते हैं। उनमें पदों के पीछे और खुले रूप में भ्रम समस्याओं और प्रश्नों पर निरन्तर परामर्श होता रहता है। महासभा में दो के समूह (Groups), संयोग अथवा गठबन्धन (Coalitions), गुट (Blocks) निरन्तर सक्रिय रहते हैं। आलोचकों के अनुसार इन संयोगों, समूहों और गुटों गतिविधियों के फलस्वरूप महासभा द्वारा किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुँचने की शक्ति कम हो जाती है। यह आरोप यद्यपि एक हद तक सही है, तथापि हमें यह भूलना चाहिए कि महासभा कोई दार्शनिकों या वैज्ञानिकों का निवाय नहीं है न ही न्याय की खोज करने वाला कोई न्यायिक संस्थान ही है। यह तो एक नीतिक निकाय (Political Body) है जो विभिन्न समस्याओं का सम्भावित गान खोजने का प्रयास करता है और देखाता है कि किस प्रकार समस्या के गान में सदस्यों का बहुमत प्राप्त किया जाए।

महासभा के प्रस्तावों में राज्यों के प्रायः निम्नलिखित चार वर्गों का उल्लेख है—(1) लेटिन अमेरिकी राज्य (Latin American States), (2) अफ्रीकी एशियाई राज्य (African and Asian States), (3) पूर्वी यूरोप के राज्य (Eastern European States), (4) पश्चिमी यूरोप एवं दूसरे राज्य (Western European and Other States)। राज्यों के इन वर्गों के अलग-अलग अथवा एक से मिलकर समय-समय पर विभिन्न समूह (Groups) विकसित होने रहते हैं।

सभा के कार्य और उसकी शक्तियाँ

मोटे रूप में महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के क्षेत्र में निहित सभी प्रश्नों पर विचार कर सकती है। इसके प्रमुख कार्यों और शक्तियों का उल्लेख संक्षेप में अनुसार किया जा सकता है—

प्रथम, शान्ति और सुरक्षा कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नों के अनुसार सिफारिशें करना। इसमें निःशस्त्रीकरण और शस्त्रों के नियमन सिफारिशें भी सम्मिलित हैं।

दूसरे, शान्ति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार-करना तथा तत्सम्बन्धी सिफारिशें करना, बशर्ते कि उन पर तब सुरक्षा परिषद् वाद न चल रहा हो।

तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय वातान के विकास¹⁰ संहिताकरण, मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतन्त्रताओं की प्राप्ति तथा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में आवश्यक अध्ययन प्रेरित करना तथा इन सब बातों के विकास के लिए समुचित अभिशप्ता करना ।

चौथे, सुरक्षा परिषद् और संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंगों से रिपोर्ट बनाना और उन पर विचार करना ।

पाँचवें, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्राप्ति पहुँचाने वाले किसी मामले के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए सिफारिशें करना ।

छठे, न्याय-परिषद् के माध्यम से न्याय-गमभीतो के अनुनाशन का निरोध करना ।

सातवें, सुरक्षा परिषद् के दस अस्थाई सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के 27 सदस्यों और न्याय-परिषद् के निर्वाचित होने वाले सदस्यों को चुनने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों के निर्वाचन में सुरक्षा परिषद् की सिफारिशों पर महासचिव की नियुक्ति करना ।

आठवें, संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट पर विचार करना और उसे स्वीकार कर राष्ट्रों के लिए चन्दे की राशि नियत करना और विशिष्ट अभिकरणों के बजटों जांच करना ।

शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव

3 नवम्बर, 1950 के 'शान्ति के लिए एकता' (Uniting for Peace) प्रस्ताव पारित होने के बाद से महासभा की शक्तियों में उत्प्रेषणीय वृद्धि हो गई । इस प्रस्ताव के अनुसार—शान्ति को खतरा, शान्ति भंग अथवा आक्रमण के भय सम्बन्ध में स्थायी सदस्यों के एकमत न होने के कारण यदि सुरक्षा-परिषद् अपने क संचालन में असफल रहे, तो महासभा तुरन्त ही उस मामले पर विचार कर सकती है और सामूहिक कार्यवाही के लिए उचित सिफारिशें कर सकती है । शान्ति-होने तथा आक्रमण होने की दशा में शक्ति-प्रयोग की सिफारिश कर सकती है ता अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रहे । प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा परिषद् सदस्यों के साधारण मत से अथवा सभ के सदस्यों के बहुमत से 24 घण्टे का नोटिस देकर महासभा का सकटकालीन अधिवेशन बुला सकती है ।

'शान्ति के लिए एकता प्रस्ताव' ने महासभा की स्थिति को काफी महत्त्व बना दिया है । इस बात की आशंका घट गई है कि महाशक्तियाँ बार-बार निषेधाधिकार के प्रयोग से सुरक्षा परिषद् को एवढम निष्क्रिय बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहेगी । नवम्बर, 1956 को मिस्र पर इजरायल, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण होने पर महासभा के अधिवेशन ने इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करते सफलतापूर्वक शान्ति स्थापित की थी ।

सभा के महत्त्व में वृद्धि के कारण

महासभा निरन्तर प्रभावशाली होती जा रही है और उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसके कुछ विशेष कारण ये हैं—

1. सभ के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य हैं, अतः यह एक प्रभावशाली जनिक सम्मेलन है।

2. निषेधाधिकार के दुरुपयोग के फलस्वरूप सुरक्षा परिषद् की स्थिति पहले जमान लाभकारी नहीं रही है और राज्य विश्व-जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए महासभा को अधिक उपयुक्त स्थान समझते हैं।

3. 'शान्ति के लिए एकता-प्रस्ताव' ने महासभा की शक्ति-वृद्धि में बहुत योगदान है।

4. आपात्कालीन सेना की नियुक्ति से भी महासभा की शक्ति और महत्ता वृद्धि हुई है।

5. सुरक्षा परिषद् के साथ साथ महासभा को भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और शांति के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार के समुचित प्रयोग महासभा के प्रभाव में वृद्धि की है।

6. महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार इसे सभ के अंगों की अपेक्षा कुछ अधिक अच्छी स्थिति प्रदान करता है।

अपने अधिकारों के समुचित प्रयोग के फलस्वरूप महासभा ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान में अनेक सफलपूर्ण अवसरों पर स्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सुरक्षा परिषद् (Security Council)

101 व कार्यप्रणाली

सुरक्षा परिषद् 'संयुक्त राष्ट्रसंघ की कुंजी' (Key-organ of the U. N.) है। इसकी रचना सभ के कार्यकारी और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में की गई तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा का मुख्य दायित्व इसी पर है। चार्टर की मूल विधियाँ के अनुसार परिषद् में पहले 11 सदस्य थे—5 स्थायी और 6 अस्थायी, जिनमें 15 अक्टूबर, 1965 में चार्टर में एक संशोधन के अनुसार सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है—5 स्थायी और 10 अस्थायी। स्थायी सदस्य हैं—अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। परिषद् द्वारा निर्णयों के न्यूनतम आवश्यक मतों की संख्या भी बढ़ाकर 7 से 9 कर दी गई है। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अवधि की समाप्ति पर कोई भी सदस्य तुरन्त पुनः चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

परिषद् का सेशन इस प्रकार का है कि वे लगातार काम कर सकें। इसलिए यह मुख्यालय पर परिषद् के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधि हर समय रहना आवश्यक है। कार्यविधि के नियमों के अनुसार परिषद् की बैठकों के बीच 14 दिन से अधिक

का अन्तर नहीं होना चाहिए। परिषद् मुख्यालय के अलावा इच्छानुसार अन्य अपनी बैठक कर सकती है। अपने कार्यों के समुचित निर्वहण के लिए वह महा-अगो की स्थापना भी कर सकती है। परिषद् की दो स्थायी समितियाँ (Standing Committees) हैं—(क) विशेषज्ञ समिति, जो कार्यविधि की नियमावली का देखती है, एवं (ख) नवीन सदस्यों के प्रवेश का काम देखने वाली समिति। इस अतिरिक्त परिषद् समय-समय पर तदर्थ समितियों और आयोगों की नियुक्ति भी कर रही है। सैनिक आवश्यकताओं, शस्त्रों के नियन्त्रण आदि पर स्वतन्त्र परामर्श सहायता के लिए एक सैन्य स्टाफ समिति (Military Staff Committee) भी है। परिषद् के अधीन एक निःशस्त्रीकरण आयोग भी है जिसकी स्थापना जनवरी, 1948 में की गई थी।

परिषद् का सभापतित्व परिषद् के सदस्यों में से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के नाम के क्रम से प्रतिमास बदलता रहता है। परिषद् के प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को एक मत प्राप्त होता है। परिषद् के निर्णय दो प्रकार के होते हैं—सुरक्षा परिषद् के कार्य और अधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना की दृष्टि से सुरक्षा परिषद् व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। चार्टर के अनुच्छेद 24 में स्पष्ट उल्लिखित है अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का प्रधान उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद् का है। उसे यह देखना है कि संघ की ओर से प्रत्येक कार्यवाही जल्दी और प्रभावपूर्ण ढंग से हो। अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों का कर्तव्य है कि वे चाहे अनुसार सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को मानें और उन पर अमल करें। सुरक्षा परिषद् को अधिकार व शक्तियों का उल्लेख चार्टर के 6, 7, 8 और 12वें अध्याय में किया गया है। इन अध्यायों के अनुसार शान्ति व सुरक्षा की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से परिषद् की शक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

प्रथम, अनुच्छेद 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित रखना है। परिषद् उन विवादों और परिस्थितियों तत्काल विचार करती है जो शान्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हो अथवा प्रकार की सम्भावना हो गई हो। सुरक्षा परिषद् अपने कर्तव्यों को संघ के प्रयोग और सिद्धान्तों के अनुसार ही पूरा करती है। अनुच्छेद 24 में ही यह व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद् महासभा के विचार के लिए वार्षिक रिपोर्टें या जरूर पड़ने पर विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

दूसरे, सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करती है। चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 तक विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे से सम्बन्धित हैं।

तीसरे, सुरक्षा परिषद् शान्ति के लिए खतरनाक, शान्ति भंग और आक्रमणकारी देशों के बारे में कार्यवाही करती है। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 39 से 51 आवश्यक व्यवस्थाएँ दी गई हैं। सुरक्षा परिषद् ही यह निर्णय करती है कि को-

जो शान्ति को खतरे में डालने वाली, शान्ति भंग करने वाली और आक्रामक हो जा सकती है। वह तिकारिश करती है अथवा यह तय करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय और सुरक्षा कायम रखने अथवा उसे फिर से स्थापित करने के लिए इनमें से जो कार्यवाहियाँ करें—(क) ऐसी कार्यवाहियाँ जिनमें हथियारबन्द सेना का ग न हो। परिपद सभ के सदस्यों से पूर्ण या आंशिक रूप से आधिक सम्बन्ध रखने की माँग कर सकती है। इस कार्यवाही के अनुसार समुद्र, वायु, डाक, रेडियो और यातायात के अन्य साधनों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं या तीव्रता सम्बन्ध तोड़े जा सकते हैं। (ख) यदि सुरक्षा परिपद इस कार्यवाही को पूर्ण ममके तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखने या पुनः स्थापित करने के लिए जल थल और वायु सेनाओं का प्रयोग कर सकती है। इस कार्यवाही में अन्तर्राष्ट्रीय के सदस्य देशों की जल, थल वायु सेना विरोध प्रदर्शन कर सकती है, डाल सकती है या कोई अन्य कार्यवाही कर सकती है।

चौथे, अनुच्छेद 43 के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के सभी सदस्य-राज्य बचनबद्ध हैं कि "सुरक्षा पद के माँगने पर और विशेष सम्झौते या सम्झौतों के अनुसार वे अपनी सशस्त्र सहायता तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करेंगे जिनमें मार्ग-अधिकार भी शामिल हैं।"

पाँचवें अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा-परिपद हथियारबन्द या सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की योजनाएँ सैनिक स्टाँक समिति (Military Staff Committee) की सलाह और सहायता से तैयार करेंगी। अनुच्छेद 47 में उल्लेख है कि सुरक्षा परिपद के उपयोग के लिए जो सशस्त्र सेनाएँ दी जाएँगी उनका युद्ध-विधि निर्देशन सैनिक स्टाँक समिति के हाथ में रहेगा और यह समिति सुरक्षा पद के अधीन रहेगी। परिपद द्वारा प्रेषित किए जाने पर सैनिक स्टाँक समिति को प्रादेशिक उप-समितियाँ भी बना सकती है। अनुच्छेद 47 ही व्यवस्था देता है सैनिक स्टाँक समिति का काम सुरक्षा परिपद को इन प्रश्नों पर सलाह और सहायता देना होगा—(i) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा परिपद की सैनिक आवश्यकताएँ, (ii) उसके अधीन सेनाओं का प्रयोग और उनकी कमान, (iii) शस्त्रों नियंत्रण, और (iv) सम्भावित निःशस्त्रीकरण। सैनिक स्टाँक समिति के सदस्य सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्यों के मुख्य सैनिक अधिकारी (Chief of Staff) या के प्रतिनिधि होंगे।

छठे, अनुच्छेद 48 के अनुसार सुरक्षा परिपद के निर्णयों पर जो कार्यवाही जाएगी परिपद के निर्णय के अनुसार सभ के सब सदस्यों को या उनमें से कुछेक करनी होगी। अनुच्छेद 49 की व्यवस्था के अनुसार सुरक्षा परिपद जो भी कार्यवाही निश्चित करेगी उसको पूरा करने में संयुक्तराष्ट्र के सब सदस्य सामूहिक में एक दूसरे को सहयोग देंगे।

सातवाँ, अनुच्छेद 51 में उल्लेख है कि—'यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी

सदस्य पर कोई सशस्त्र आक्रमण होता है तो वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आक्रमण करने का अधिकारी होगा। चार्टर के अनुसार उस पर उस समय (जब कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा) जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए स्वयं कोई कार्यवाही न करे। सदस्य राज्य आक्रमण के लिए जो भी कार्य करेगा, उसकी सूचना तुरन्त ही सुरक्षा परिषद् को देगे, पर चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना या पुनर्स्थापना के लिए जब कभी और जो कार्य कोई स्थापना आवश्यक समझे कर सकती है।"

हासचिव

आठवें, जब सुरक्षा परिषद् किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर दे। हो उस समय हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष आगे समस्याएँ उठ नही हो। ऐसी स्थिति में उस राष्ट्र को, चाहे वह सच का सदस्य हो या नहीं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सुरक्षा परिषद् से परामर्श करा है। यह अधिकार होगा। (अनुच्छेद 50)

राष्ट्रसंघ

नवें, स्थानीय विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद् प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है। इसके अति प्रादेशिक संगठन या अभिकरण अपने क्षेत्रों में शान्ति और सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई उठाते हैं, उनकी सूचना उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा परिषद् को देनी पड़ती है। अतः हमें, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने और वे दायित्व ग्रहण किया है, उसे निभाने का भार भी सुरक्षा परिषद् पर ही है। सरासरी प्रदेशों को किसी भी राष्ट्र के संरक्षण में देने समय संरक्षण सम्बन्धी शर्तें मु। इसे परिषद् द्वारा ही तय की जाती हैं। वही इन शर्तों में संशोधन कर सकती है। वह ऐसे कुछ क्षेत्रों सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षण में होता तो इन क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए सुरक्षा परिषद् आवश्यक कार्यवाही कर सकती है।

कार

सुरक्षा परिषद् को प्रेषणाकृत कुछ कम महत्वपूर्ण शक्तियाँ भी दी हैं जिनमें से अधिकांश का प्रयोग वह महासभा के साथ मिलकर करती है। ये अतः निर्वाचनार्थक (Elective), प्रारम्भिक (Initiatory) और निरीक्षणार्थक (Sic n visory) हैं। निर्माताओं द्वारा परिषद् को ये कार्य इस दृष्टि से सौंपे गए। भी महाशक्तियों महत्वपूर्ण संगठनात्मक मामलों पर अपना कुछ नियंत्रण रख सार महासचिव द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के व्यापारिक के चुनाव में भी परिषद् का मुख्य हाथ रहता है।

निषेधाधिकार की समस्या (Problem of Veto-Power)

चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा-परिषद् की मतदान-प्रणाली का उत्तर जिसमें प्रस्ताव अथवा संशोधन (Substantive) मामलों में परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक मत आवश्यक है। इन 5 स्थायी सदस्यों में

कोई भी सदस्य अपनी असहमति प्रकट करे अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान तो प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं सम्भवा जाता। चार्टर में परिपक्व पर साधारण और धारण कार्यविधि में अन्तर करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। अतः जब यह उठता है कि अमुक मामला साधारण माना जाए या प्रक्रियात्मक (Procedural) या असाधारण (Substantive), तब दोहरे निषेधाधिकार (Double Veto) योग्य होता है, अर्थात् पहले तो निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को धारण विषय बनने से रोका जाता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव के दायित्वों (obligations) के विरोध में पुनः मतदान होता है।

आलोचकों का आरोप है कि निषेधाधिकार की व्यवस्था के कारण सुरक्षा अपने सामूहिक सुरक्षा के दायित्व में असफल हो गई है। ग्रानोल्ड फोर्स्टर के तुर, "निषेधाधिकार का अतक सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी या के रक्त में ही पक्षाघात है। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर (arter) किसी भी समय उसकी दन्त-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर उसके एजिन निक मक्ता हो।"

प्राधिकार के विपक्ष में तर्क

1. पाँच महात् राष्ट्रो को निषेधाधिकार प्रदान कर सभी सदस्यों के समानता की मयुक्त राष्ट्रसंघीय मिद्धान्त की उपेक्षा की गई है। निषेधाधिकार छोटे रों पर जबरदस्ती लादा गया। उन्हें मयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर के निषेधाधिकार छेद को महाशक्तियों के दबाव के कारण स्वीकार करना पड़ा था। न्यूजीलैण्ड एक प्रतिनिधि के अनुसार, "पाँचों महात् शक्तियों ने मान-फ्रांसिसको में प्राधिकार पर दल दिया, अन्य शक्तियों को विवश होकर उसे स्वीकार करना। निषेधाधिकार की तुलना ऐसी शादी से की जा सकती है जो बन्दूक की नोक की गई हो।"

2. निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा-परिपक्व शान्ति एवं सुरक्षा की व्यवस्था अपने दायित्वों का समुचित रूप से पातन करने में असमर्थ हो गई है। यह तत् अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान में सबसे अधिक बाधक है। तत्थ के एक भूतपूर्व महासचिव ट्रिग्वेली ने स्पष्ट कहा था कि "विश्व-मस्थान्वधिकार के कारण नपु सक है। यह महाशक्तियों के सघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त र है।"

3. निषेधाधिकार पक्षपोषक राज्यों (Client States) की एक सुली शीतिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। यह सम्भव है कि प्रत्येक स्थायी सदस्य मित्रराष्ट्रों को निषेधाधिकार द्वारा संरक्षण प्रदान करे। इस प्रकार यह भय होना स्वाभाविक है कि मयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य स्थायी सदस्यों के नेतृत्व में गुटों में विभक्त हो जाएँगे। यह भय निराधार नहीं है क्योंकि अमेरिका और के नेतृत्व में दो शक्तिशाली गुट पहले ही अस्तित्व में आ चुके हैं। लाल चीन स्वेच में प्रवेश और सुरक्षा परिपक्व में स्थायी सदस्यता प्राप्त होने से वह भी अपने में एक तीसरे गुट की स्थापना कर लेगा।

4. निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद् में जो गतिरोध उत्पन्न होते हैं, उनसे विश्व-राज्यों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में आस्था बुरी तरह डगमगई है।

5. निषेधाधिकार के दुरुपयोग के कारण कई स्वतन्त्र राष्ट्र अनेक तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य न बन सके और आज भी कुछ राष्ट्रों का सघ में प्रवेश अटका हुआ है। निषेधाधिकार का दुरुपयोग इस रूप में भी सम्भव है कि कोई स्थायी सदस्य किसी सदस्य को हटाए जाने या निलम्बित होने से रोक दे, महासचिव व नियुक्ति को पट्टाई में डाल दे तथा चार्टर में उपयोगी सशोधन को ठुकरा दे।

आलोचकों का आरोप है कि निषेधाधिकार द्वारा महाशक्तियों को संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था पर आधिपत्य प्राप्त हो गया है। हम कैंसन के अनुसार, "महाशक्ति का यह अधिकार अन्य सभी सदस्यों पर कानूनी प्रभुसत्ता स्थापित करता है। य उनके निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का सूचक है। इसके कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में वास्तविक और बाँझनीय निर्णय नहीं हो पाते।"

निषेधाधिकार के पक्ष में तर्क

1. निषेधाधिकार की आलोचनाओं में वजन है, तथापि कुछ व्यावहारिक तथ्यों की उपेक्षा करना अनुचित है। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सफल तभी मिल सकती है जब उसे विश्व की महाशक्तियों का सहयोग प्राप्त हो और महाशक्तियाँ किसी भी ऐसी सत्ता में भाग नहीं लेना चाहेंगी जिसमें अन्य देश केवल अपने बहुमत से उन्हें कोई कार्य करने प्रथमा न करने के लिए बाध्य करें। इस रोकने का एक मात्र उपाय निषेधाधिकार ही है। ए. ई. स्टीवेंस ने ठीक ही कहा है कि "महत्व के नियम का जन्म अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से होता है। यदि 5 महान् राज्य किसी मामले पर राजी नहीं होते तो उनमें से किसी विरुद्ध शक्ति का प्रयोग एक बड़े युद्ध को प्रागन्वित करना होगा। निषेधाधिकार की स्थापना इसी सम्भावना से बचने के लिए हुई थी।"

2. निषेधाधिकार असहमतिसूचक लक्षण है न कि इसका कारण। अतः निषेध-व्यवस्था के समाप्त कर देने से महाशक्तियों के मतभेद दूर नहीं होंगे और ही इससे कोई बड़ा लाभ होगा। यदि निषेधाधिकार की व्यवस्था न भी होती तो भी सुरक्षा परिषद् में गत्यावरोध उत्पन्न करने की दूसरी युक्तियाँ निकाल ली जाती और उनका भी उतना ही दुरुपयोग किया जाता जितना वर्तमान निषेधाधिकार व्यवस्था का किया जा रहा है। महाशक्तियों की असहमति की उपेक्षा करने की व्यवस्था स्पष्ट परिणाम वही होगी जो राष्ट्रसंघ के सम्बन्ध में हो चुका है अर्थात् कुछ सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे देंगे और तब संयुक्त राष्ट्रसंघ की भी वही स्थिति हो जाएगी जो भूतपूर्व विश्व-संस्था की हुई थी।

3. यह कहना अनिश्चितपूर्ण है कि निषेधाधिकार के प्रयोग के फलस्वरूप सुरक्षा परिषद् का काम ठप्प हो गया है। अब तक का अनुभव अधिकांशतः यह सिद्ध करता है कि निषेध-शक्ति के प्रयोग के कारण कोई अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय लेने

अधिक वाधा नहीं पहुँची है। जिन निर्णयों में यह वाचक बना है, उनके न लेने भी विषय-शान्ति को किसी प्रकार का खतरा नहीं पहुँचा है। इसके विपरीत कई निषेधाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्तिपूर्ण उपायों से सुलझाने में सहायक हैं। जब कश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन व अमेरिका ने खुलकर किस्तान का समर्थन किया और निर्लज्जतापूर्वक न्याय को गला घोंटा तब सोवियत के निषेधाधिकार के प्रयोग ने स्थिति को सम्भालने और न्याय की रक्षा करने में सहायता प्रदान की थी।

4. वास्तव में निषेधाधिकार सभ के विभिन्न पक्षों में गन्तुवन कायम रखने सहायक सिद्ध हुआ है। यदि निषेध-व्यवस्था न होती तो समुक्त राष्ट्रमण पूरी रह एक गुट विशेष का शास्त्र बन जाता जिसे अपनी मनमानी करने की पूरी छुट मिल जाती।

5. निषेधाधिकार को अनेक स्वस्थ परम्पराओं के बिकान और व्यावहारिक दमों ने पुनर्पिछा कुछ कम प्रभावगाली बना दिया है। शान्ति के लिए एकता का स्ताव पारित होने के बाद से अब न तो यह अधिकार कोई नया अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष रान्न करता है और न उसे आगे बढ़ाना है। इसके होने हुए भी महामणा द्वारा निक कामें सम्पादित किए जाने हैं। शान्ति निरीक्षण आयोग, सामूहिक उपाय मिति पादि की स्थापना द्वारा महामणा ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को निषेध के ण्यभाव से मुक्त कराने का कारणर प्रदान किया है।

निष्कर्ष रूप में, उपयोगी यह होगा कि कई सदस्यता और शान्तिपूर्ण ममभीकों सम्बन्ध में तो निषेधाधिकार समाप्त होना चाहिए, परन्तु शान्ति भग और आक्रमण की स्थिति में सैनिक कार्यवाही के लिए इस अधिकार का प्रयोग बनाए रखना चाहिए, अन्यथा अनेक गम्भीर और गवीन समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। निषेधाधिकार के प्रयोग की समस्या के सम्बन्ध में गुडरीव एवं हेम्बरो का मूल्यांकन उचित ही है। उन्होंने लिखा है—“राष्ट्रों में जो ममभीता नहीं हो रहा है उसके कारण निषेधाधिकार का प्रयोग हो रहा है। उसके लिए किसी उत्तरदायी ठहराया जाए, यह निर्णय करना कठिन है। वास्तव में यह एक राजनीतिक प्रश्न है। रूस ने इस अधिकार का अधिकतर प्रयोग किया है। परन्तु उसका तर्क है कि विरोधी बहुमत से बचने के लिए ही वह इस अधिकार का प्रयोग करता है। यह स्वीकार करना चाहिए कि महा शक्तिशाली की सर्वसम्मति और उनकी समान प्रभुता का ही यह अर्थ है कि उनमें मनभेद और सह-सम्मति सम्भव है। स्थायी सदस्यों में जो आगा से अधिक मतभेद रहे हैं, उनका मूल कारण नीतियों सम्बन्धी मनभेद है जिनमें शान्ति-गन्धियों के मत में बाधा डाली है तथा क्षतिप्रेस्त देशों के मुद्दोत्तर पुनर्विकास को अवरुद्ध किया है।

आर्थिक और सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council)

चाटर् के अध्याय 10 में अनुच्छेद 61 से 72 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् से सम्बन्धित हैं। यह परिषद् विश्व में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक

एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्य करती है। अपने सहायक अंगों द्वारा यह मा जीवन के व्यापक क्षेत्रों का अध्ययन करती है और उस आधार पर कार्यवाही की सिफारिशें करती है।

संगठन और मतदान

आर्थिक एवं सामाजिक परिपद में पहले महासभा द्वारा चुने हुए संयुक्त राष्ट्रसभ के 18 सदस्य होते थे किन्तु सन् 1965 में चार्टर में एक संशोधन फलस्वरूप अब 27 सदस्य होते हैं। इनमें से 9 सदस्य प्रति तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं अर्थात् एक तिहाई सदस्य हर तीसरे वर्ष पदत्याग कर देते हैं। पद-निवृत्त सदस्य तुरन्त पुनः चुनाव में खड़े हो सकते हैं। परिपद में प्रत्येक सदस्य-राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। इसमें न तो किसी राष्ट्र को निवेद्याधिकार प्राप्त है और न ही स्थायी सदस्यता। महासभा अपनी इच्छानुसार किसी भी सदस्य-राज्य को इस परिपद में चुन सकती है। सन् 1965 के संशोधन के अनुसार जो 9 सीटों की वृद्धि हुई, उनके वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की गई है—सात सीटें अफ्रीकी-एशियाई देशों को, एक लेटिन अमेरिकी देशों को तथा एक पश्चिमी यूरोप के देशों को।

आर्थिक एवं सामाजिक परिपद के सभी निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। परिपद के हर सदस्य का एक मत होता है। किसी गैर-मदस्य राज्य को भी, यदि वह परिपद में प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित है, विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है, पर उसे मतदान का अधिकार नहीं होता।

क्रियाविधि एवं सहायक अंग

परिपद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देने के लिए और अपने कार्यों की पूर्ति के लिए आयोगों तथा समितियों की स्थापना करती है। अभी तक घनेक कार्यकारी आयोगों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें उल्लेखनीय ये हैं—यातायात तथा संचार आयोग, परिणाम आयोग, जनसंख्या आयोग, सामाजिक आयोग, मानव अधिकार आयोग, नारी-अधिकार आयोग, मादक पदार्थ आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-व्यापार आयोग। आयोगों के सदस्य परिपद द्वारा चुने जाते हैं। मादक पदार्थ आयोग के प्रतिनिधि सीधे उनकी सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। परिपद ने एक उप-आयोग भी स्थापित किया है जिसका मुख्य कार्य भेद-भाव की रोकथाम करना है। इसी प्रकार एक अल्पसंख्यक सुरक्षा सम्बन्धी आयोग है। तीन प्रादेशिक आयोग भी स्थापित किए गए हैं—यूरोपीय आर्थिक आयोग, एशिया एवं सुदूर-पूर्व आर्थिक आयोग तथा लेटिन अमेरिकी आयोग। परिपद की कुछ विशेष सत्ताएँ भी हैं—उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि (U N International Children Emergency Fund) जिसका उद्देश्य बाल कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों में सहायता देना है। स्थायी केन्द्रीय अफीम बोर्ड भी परिपद की एक विशेष सत्ता है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिपद अपनी क्रियाविधि के निम्न स्वयं निर्माण

नी है। अपना अध्यक्ष चुनने की विधि भी वह स्वयं निश्चिन्त करती है। परिषद् प्रधिवेशन आवश्यकतानुसार अपने नियमों के अनुसार होते हैं। इन नियमों के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी है कि परिषद् सदस्यों के बहुमत की प्रार्थना पर परिषद् अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

समितियाँ

अपने कार्यों में सहायता के लिए परिषद् स्थायी समितियाँ गठित करती है जिनमें से मुख्य ये हैं—प्राविधिक सहायता समिति, अन्तर्राष्ट्रीय सस्था चार्तालाप समिति, गैर-सरकारी संगठन परामर्श व्यवस्था समिति, कार्य सूची समिति और बैठकों कार्यक्रमों की आन्तरिक समिति। इन समितियों में प्राविधिक सहायता समिति से अधिक महत्वपूर्ण है।

परिषद् की शक्तियाँ

चार्टर के अनुच्छेद 62 से 66 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के कार्यों एवं क्षेत्रों का उल्लेख है। तदनुसार इसके प्रमुख कार्य और अधिकार निम्नलिखित हैं—

प्रथम, यह परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी मामलों का अध्ययन करती है। इन मामलों पर वह अपनी रिपोर्टें तैयार करती है और महासभा, संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों तथा विशिष्ट संस्थाओं से सिफारिशें कर सकती है। परिषद् मानव अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाने अथवा उनके अनुपालन के लिए भी सिफारिशें कर सकती है।

दूसरे, परिषद् अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मामलों के सम्बन्ध में महासभा प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों के प्राख्य तैयार कर सकती है। सच के नियमों के अनुसार अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों पर वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करा सकती है।

तीसरे, परिषद् उन विशिष्ट समस्याओं के साथ, जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग से सम्बन्धित हो, समझौते कर सकती है। वह उन शर्तों की भी निश्चित करती है जिनके आधार पर सस्था का संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बन्ध स्थापित होता हो। इन समझौतों पर महासभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। परिषद् विशेष कार्य करने वाली संस्थाओं से परामर्श करके या उनसे अपनी सिफारिशें करके उनकी कार्यवाहियों में तालमेल बंठाती है। यह इन संस्थाओं से विधिवत् रिपोर्टें प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा सकती है। इन रिपोर्टों पर परिषद् के जो विचार होते हैं उन्हें वह महासभा तक पहुँचाती है।

आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के लक्ष्य बहुत ऊँचे आदर्शों से परिपूर्ण हैं। यह सत्तार से गरीबी और हीनता को मिटाकर एक स्वस्थ और सुन्दर विश्व के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में विवादों को मिटाने का प्रयत्न करके यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित देती है। पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास के लिए परिषद् ने अनेक आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता-योजनाएँ संचालित की हैं। परिषद् की प्राविधिक सहायता समिति

का मुख्य उद्देश्य ही मानव जाति को कष्ट और दरिद्रता से छुटकारा दिलाना है। यह अर्द्ध-विकसित देशों को विशेषज्ञ भेजती है और उन्हें मशीनों, उपकरणों आदि की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देती है। यह भवनों, सड़कों, बन्दरगाहों आदि के विकास में और उद्योग तथा कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सहयोग देती है। परिषद् ने जो प्राविधिक सहायता बोर्ड (Technical Assistance Board) स्थापित किया है वह महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

परिषद् का मुख्य लक्ष्य मानव-अधिकारों को प्रोत्साहन देना है और इस दायित्व की पूर्ति के लिए परिषद् द्वारा विभिन्न आयोग स्थापित किए गए हैं। परिषद् के एक आयोग की सिफारिश पर ही महासभा ने 10 सितम्बर, 1948 को मानव-अधिकारों का घोषणा-पत्र (Declaration of Human Rights) स्वीकार किया था जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का विस्तार से उल्लेख है। इन मानव अधिकारों का महत्व प्रकट करने के लिए ही प्रतिवर्ष 10 सितम्बर को 'मानव-अधिकार दिवस' मनाया जाता है। परिषद् ने शरणार्थियों तथा राज्यहीन व्यक्तियों के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं तथा ट्रेड यूनियनों के अधिकारों-दासता और वेगार की स्थिति का अध्ययन किया है। स्त्रियों की स्थिति की सूचना एवं व्यावसायिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रायोग स्थापित किया है और इन विषयों में विभिन्न समझौतों के प्रारूप तैयार किए हैं।

जैसा कि कहा जा चुका है, विभिन्न विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् का उत्तरदायित्व है। अभी तक जिन प्रमुख समस्याओं के साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ का सम्बन्ध है, वे हैं—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, विश्व डाक संघ, अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार व्यवस्था संघ एवं विश्व श्रुतु विज्ञान संगठन।

न्यास परिषद् (Trusteeship Council)

चार्टर के अध्याय 12 में अनुच्छेद 75 से 85 तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था (International Trusteeship System) का और अध्याय 13 में अनुच्छेद 86 से 91 तक न्यास परिषद् की रचना, शक्तियों, क्रिया-विधियों आदि का उल्लेख है। पहले राष्ट्रसंघ में सरक्षण-व्यवस्था (Mandate System) थी और अब इसके स्थान पर इससे बहुत कुछ मिलती जुलती न्यास व्यवस्था अपनाई गई है जिसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि विश्व में अनेक पिछड़े हुए तथा अविकसित प्रदेश हैं जिनका विकास तभी सम्भव है जब सम्य और उन्नत देश उन्हें सहयोग प्रदान करें। अतः उन्नत देशों का यह कर्तव्य है कि वे स्वयं को न्यासी (Trustee) समझकर अविकसित प्रदेशों के हितों की देख-भाल करें तथा उनके विकास में हर सम्भव सहयोग दें। राष्ट्रसंघ की सरक्षण-व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि से पीड़ित प्रदेशों के लिए

हि, वहाँ संयुक्त राष्ट्रमण की न्याम पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के लिए है। न्याम पद्धति के मूल उद्देश्य हैं—
(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा में वृद्धि करना, (ख) न्याम प्रदेशों के निवासियों का स्वशासन की दिशा में विकास करना (ग) मानव-अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं का प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन देना तथा यह भाव जाग्रत करना कि समार का सभी लोग ग्रन्थोन्नाश्रित हैं, एवं (घ) सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक मामलों में संयुक्त राष्ट्रमण के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना।

न्यास पद्धति के अन्तर्गत समाविष्ट प्रदेश दो भागों में विभाजित हैं—
अस्वशासित प्रदेश (Non-Self Governing Territories), एवं न्यास या सरक्षित प्रदेश (Trust Territories)। प्रथम प्रकार के अस्वशासित प्रदेश में वे पराधीन प्रदेश तथा उपनिवेश हैं जो सरक्षित प्रदेश न बने हों। ये ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी देशों के साम्राज्याधीन प्रदेश हैं। दूसरे प्रकार के अर्थात् न्यास प्रदेश वे हैं जो न्याम-समझौते द्वारा, जो सम्बन्धित राज्यों के मध्य होने हैं और जिन पर महासभा की स्वीकृति अनिवार्य है, न्यास प्रदेश बना दिए जाते हैं।

कुछ वर्ष पूर्व न्यास पद्धति के अन्तर्गत न्यूगिनी, रुआण्डाउरुण्डी, फ्रैंच कैमरून, फ्रैंच टोगोलैण्ड, पश्चिमी समोआ, टोंगानिका, ब्रिटिश कैमरून, पोरु, प्रशान्त महासागर द्वीप, सुमालीलैण्ड, टोगोलैण्ड नामक ११ देश थे जिनमें से बाद में केवल दो प्रदेश ही न्याम प्रदेश रह गए—न्यूगिनी तथा पपुआ, परन्तु सन् १९७५ में ये भी स्वतन्त्र हो गए।

संगठन एवं कार्य-प्रणाली

न्यास परिषद् का कार्य मार्च, १९४७ से आरम्भ हुआ था। इस परिषद् में सभ के निम्नलिखित सदस्य शामिल हो सकते हैं—

(i) सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य, चाहे वे न्याम प्रदेश पर प्रशासन करते हैं अथवा नहीं।

(ii) संयुक्त राष्ट्रमण के वे सदस्य जो न्याम-क्षेत्र का प्रशासन करते हों।

(iii) महासभा द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित उनसे सदस्य जिनसे न्याम परिषद् में न्याम-प्रदेशों पर शासन करने वाले और न करने वाले सदस्यों की समस्या को समान करने के लिए आवश्यक हो।

परिषद् के सदस्य का एक मन होता है। इसके निर्णय परिषद् में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं। न्याम-परिषद् अपनी कार्यविधि के नियम 'स्वयं' बनाती है। अपने अध्यक्ष चुनने की विधि भी वह स्वयं निर्धारित करती है। न्याम परिषद् की बैठके नियमानुसार की जाती हैं। सदस्यों की प्रार्थना पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। यह परिषद् आवश्यकतानुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् और अन्य संस्थाओं से सहायता ले सकती है।

कार्य एवं अधिकार

न्यास-परिषद् महासभा से आदेश प्राप्त करती है और न्यास-प्रदेशों के शासन की देख-रेख करती है। प्रशासी अधिकारी अपने प्रतिवेदन प्रतिवर्ष न्यास परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिन पर आवश्यक विचार-विमर्श करने के उपरान्त परिषद्, महासभा और सुरक्षा-परिषद् को विभिन्न प्रकार की सिफारिशें भेजती है। न्यास-परिषद् की सिफारिशें इस प्रकार की होती हैं जैसे, मूल निवासियों को सरकार के विभिन्न अंगों में स्थान दिलाना, उनके वेतन एवं जीवन-स्तर को उन्नत करना, चिकित्सा तथा अधिक लाभप्रद स्वास्थ्य सेवाएँ मुलभ कराना, दण्ड-पद्धति में सुधार, सामाजिक कुरीतियों का अन्त कर मूल निवासियों की कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देना। न्यास परिषद् ने न्यास-क्षेत्रों में होने वाला अणु विस्फोटों पर भी विचार दिया था।

न्यास-परिषद् का दूसरा मुख्य कार्य न्यास-प्रदेश के निवासियों के लिखित एवं मौखिक आवेदन पत्रों पर विचार करना है। यह परिषद् का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से परिषद् और न्यास-प्रदेशों की जनता में सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाता है।

न्यास-परिषद् का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य समय-मसम पर न्यास-प्रदेशों की निरीक्षण मण्डल (Visiting Missions) भेजना है। इन मण्डलों के माध्यम से पराधीन प्रदेशों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखा जाता है। इनको परिषद् की आँख और कान कहा गया है। ये न्यास प्रदेशों के आर्थिक विकास, शिक्षा-प्रसार, श्रम-व्यवस्था, सामाजिक-सुधार, भूमि-सुधार आदि से सम्बन्धित नीतियों का अध्ययन करने हैं और सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देते हैं। पिछड़े हुए प्रदेशों की जटिल समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने में इन निरीक्षक मण्डलों से बहुत सहायता मिली है।

न्यास-परिषद् महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ही करती है तथापि अपने कार्य को तत्परता से सम्पन्न करने अथवा किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए समय-समय पर अपने कई समितियाँ स्थापित की हैं जैसे शिक्षा समिति, ग्रामीण विकास समिति एवं प्रशासी सच समिति। महासभा की चौथी समिति और स्वयं महासभा ने न्यास-पद्धति के विज्ञान में काफी हाथ बंटाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

(The International Court of Justice)

यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग है। यह वही पुराना अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे राष्ट्रसंघ ने सन् 1901 में हेग में स्थापित किया था। नवीन न्यायालय अपने पूर्ववर्ती न्यायालय की अपेक्षा कई प्रकार से दोष-मुक्त है।

संगठन

इस न्यायालय में केवल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव सुरक्षा-परिषद् एवं महासभा द्वारा 9 वर्षों के लिए किया जाता है और कार्यविधि की समाप्ति के बाद जो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। एक राज्य से दो न्यायाधीश नहीं लिए जा

सकते। न्यायाधीश की पदच्युति भी हो सकती है जबकि वह सदस्यों की सर्वसम्मति से आवश्यक शर्तों को भंग करने का दोषी पाया जाए।

न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के प्रतिरिक्त अन्य अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। यदि न्यायालय में किसी ऐसे राज्य का मामला विचारणीय हो जिसका 15 न्यायाधीशों में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह मामले की सुनवाई के समय अस्थायी न्यायाधीश के रूप में अपना एक कानूनी विशेषज्ञ नियुक्त करा सकता है। यह न्यायाधीश मामले की सुनवाई समाप्त होने ही पद से हट जाता है। उससे मामले के सम्बन्ध में कानूनी राय ली जाती है, किन्तु निर्णय में उसका कोई हाथ नहीं रहता। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर समापति का निर्णायक मत मान्य होता है। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

न्यायिक निर्णय का निष्पादन

संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयों को क्रियान्वित कराने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को स्वीकार करेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा-परिपद का आश्रय ले सकता है। सुरक्षा-परिपद जैसा आवश्यक समझे वैसे मिफारिश अथवा कार्यवाही करेगी। न्यायालय के निर्णय यद्यपि सर्वसम्मति से लिए जाते हैं फिर भी मतभेद की अवस्था में प्रत्येक न्यायाधीश अपना पृथक् विचार निर्णय-पत्र के साथ सलग्न कर सकता है।

न्यायालय के निर्णयों को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही निश्चित करते समय सुरक्षा-परिपद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इनमें से पाँच स्थायी सदस्य होने चाहिए। क्रियान्विति के उपायों की धारा 41 तथा 42 में प्रावधान है। प्रथम के अनुसार सुरक्षा-परिपद सैनिक-बल को छोड़कर ऐसे उपायों का प्रयोग कर सकती है जिनमें आर्थिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, डाक, रेडियो, यातायात के साधन तथा राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद शामिल हैं। यदि ये उपाय असफल हो जाए तो धारा 42 के अनुसार सुरक्षा-परिपद, जल, स्थल और वायु सेना द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

क्षेत्राधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार तथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Voluntary Jurisdiction) के अन्तर्गत न्यायालय अपनी सविधि (Statute) की धारा 36 के अनुसार उन सभी मामलों पर विचार करेगा

सकता है जिनसे सम्बन्धित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। केवल राज्य ही न्यायालय के विचारणीय पक्ष हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं।

अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Obligatory Jurisdiction) को वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार (Optional Compulsory Jurisdiction) भी कहा जाता है जिसके अनुसार राज्य स्वयं घोषणा द्वारा अग्रंकित क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है—सन्धि की धारणा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से सम्बन्धित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन सुझा जाए तथा किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम। घोषणा करते समय राज्य कोई भी शर्त लगा सकता है। कभी-कभी तो ऐसी शर्तों के कारण यह घोषणा व्यावहारिक रूप में निरर्थक बन जाती है; तथापि, शर्तें होते हुए भी वैकल्पिक धारा अनिवार्य न्यायिक निर्णय की सर्वाधिक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा-परिषद् किसी भी कानूनी प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श मांग सकती। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार-क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना-पत्र में सम्बन्धित प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज संलग्न होते हैं जो उस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है और सिद्धान्त रूप में सुरक्षा-परिषद्, महासभा या अन्य संस्था इसकी अवहेलना कर सकती है, पर व्यवहार में ऐसा करना सर्वथा कठिन होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण विवादों के समाधान में सहयोग दिया है। उदाहरण के लिए मोरक्को का मामला, एंग्लो-ईरानी मामला, भारतीय प्रदेशों से पुर्तगाल को मार्ग देने का विवाद, कोफू-चेनल विवाद, एंग्लो-नार्वेजियन मछलीग्राह विवाद आदि को लिया जा सकता है। न्यायालय के कार्य-मंचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा उपस्थित की है। राज्यों की अवहेलना तथा उनके असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण यह अधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली नहीं बन सका है।

सचिवालय (Secretariat)

संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के सम्पादन के लिए एक सचिवालय की स्थापना की गई है। चार्टर के अध्याय 15 में अनुच्छेद 97 से 101 तक सचिवालय से सम्बन्धित हैं। यह सचिवालय सामान्यतः राष्ट्रसंघ (लीग) के सचिवालय का प्रतिरूप है।

संगठन एवं विभाग

सचिवालय में एक महासचिव और वे कर्मचारी सम्मिलित होते हैं जो सघ के कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक हो। महासचिव सचिवालय की सहायता से अपने सब कार्य करता है। महासचिव की नियुक्ति मुख्य परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। वही सब का प्रमुख अभिशासक अधिकारी है। सघ के पदाधिकारियों या कर्मचारियों की नियुक्ति महासचिव महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार करता है। कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा-शर्तों को निर्धारित करने में सबसे अधिक ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि वे कुशल और ईमानदार हो। महामचिव यह भी ध्यान रखता है कि भर्ती अधिक से अधिक विस्तृत भौगोलिक आधार पर हो। अनुच्छेद 101 में यह व्यवस्था है कि प्रायिक और सामाजिक परिषद् तथा ग्योप परिषद् को स्थायी रूप में यथोचित कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे और सघ के अन्य अंगों को भी आवश्यकतानुसार कर्मचारी दिए जाएंगे। ये सभी कर्मचारी सचिवालय का ही एक अंग होंगे।

महामचिव और उनके कर्मचारी केवल संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति निष्ठावान् होते हैं। अनुच्छेद 100 में स्पष्ट उल्लेख है कि "अपने कर्तव्यों की पूर्ति में महासचिव और कर्मचारी किसी राज्य से या सघ के बाहर किसी अन्य अधिकारी से परामर्श नहीं माँगेगे और न प्राप्त करेंगे। वे अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारी हैं और केवल सघ के प्रति उत्तरदायी हैं।"

संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रत्येक सदस्य वचनबद्ध है कि वह महामचिव और उनके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकार करेगा। प्रत्येक सदस्य-राज्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह महासचिव और कर्मचारियों के दायित्वों के निर्वाह में किसी प्रकार का प्रभाव डालने की चेष्टा नहीं करेगा।

सचिवालय, प्रशासनिक और अन्य कार्यों की दृष्टि से, अनेक विभागों में विभक्त है। इसके प्रमुख विभाग हैं—प्रायिक विषय सम्बन्धी विभाग, सामाजिक कार्य सम्बन्धी विभाग, न्याय तथा अस्वशासित क्षेत्रों से सूचना सम्बन्धी विभाग, सम्मेलन एवं सामान्य मेवाएँ, प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवाएँ तथा वैधानिक या कानूनी विभाग। महासचिव की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी सहायक और एक टेक्नीकल सहायता प्रशासक भी होता है। टेक्नीकल सहायता प्रशासन एक महासचालक की देख-रेख में कार्य करता है। 1 जनवरी, 1955 से महासचिव का कार्यभार कम करने के लिए 7 अवर सचिवों को भी नियुक्ति की गई है। महासचिव के कार्यालय से अनेक कार्यालय सम्बन्धित हैं, जैसे महासचिव का कार्यकारी सचिव वैधिक विषयों का कार्यालय, नियन्त्रक कार्यालय, सेवावर्ग कार्यालय तथा विशेष राजनीतिक कार्य सम्बन्धी उपसचिव का कार्यालय। सचिवालय के प्रशासी और कर्मचारी वर्ग में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, दुभाषिए, अनुवादक पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रशासक, सम्पादक, वित्तीय अधिकारी, विधिवेत्ता, फोटोग्राफर सेवीवर्ग के अधिकारी तथा विशेषज्ञ, मरकारो और संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए विदेश सेना अधिकारी आदि सम्मिलित होते हैं।

सचिवालय-कार्यालय एवं कार्य

सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूयार्क तथा जेनेवा में है, किन्तु क्षेत्रीय सेवाओं, प्रादेशिक आयोगों तथा मन्त्रालयों के लिए इनके कर्मचारी विश्व के कई भागों में वितरित रहते हैं। सचिवालय बहुत महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। यह संघ के अभिकारणों के अधिवेशनों के लिए सेवाएँ प्रदान करता है। यह इन अधिवेशनों में भाग लेने के लिए प्रार्थना करता है तथा पृष्ठभूमि तैयार करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय अनिश्चित संघ के अन्य अंगों के लिए सचिवालय सम्बन्धी सेवाएँ प्रदान करता है। कार्यकारिणी की भाँति कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यवाही को ध्यान में रखकर यह प्रत्येक साधन द्वारा हर प्रकार की सूचना एकत्रित करता है।

महासचिव की स्थिति और कार्य

संयुक्त राष्ट्रसंघ (लीग) के महासचिव की तुलना में संयुक्त राष्ट्रसंघ का महासचिव अधिक अधिकारसम्पन्न और प्रभावशाली व्यक्ति है। उसे कुछ ऐसे अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं जिनका पुराने राष्ट्रसंघ में सर्वथा अभाव था। चार्टर के अनुसार महासचिव के निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य हैं—

1. अनुच्छेद 99 के अनुसार यदि महासचिव समझे कि किसी मामले से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो सकता है तो वह सुरक्षा परिषद् का ध्यान उस मामले की ओर आकर्षित कर सकता है। यह महासचिव का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अधिकार है। ऐसा कोई अधिकार राष्ट्रसंघ के महासचिव को नहीं था। इस अधिकार के बल पर ही संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत रुचि लेकर विश्व-शान्ति कायम रखने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योग देते रहे हैं।

2. अनुच्छेद 98 में प्रावधान है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख अभिशासी अधिकारी की हैसियत में महासचिव महासभा में सुरक्षा परिषद् में, आर्थिक और सामाजिक परिषद् में तथा न्याय परिषद् की बैठकों में कार्य करेगा। इसके अलावा वह उन कार्यों को भी पूरा करेगा जो ये अंग उसे सौंप दें।

3. महासचिव संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यों के विषय में महासभा के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

4. संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का भार महासचिव पर ही होता है।

महासचिव की स्थिति वास्तव में बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसकी वास्तविक शक्तियाँ अनुच्छेद 99 में केंद्रित हैं। स्टीफन वेदल के अनुसार इस अनुच्छेद के अन्तर्गत महासचिव को सात महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं¹—

(1) किसी भी विवाद या स्थिति को सुरक्षा परिषद् की प्रस्थायी कार्यसूची में रखना,

- (2) राजनीतिक निर्णय लेना,
- (3) सुरक्षा परिषद् के सामने उन प्राथमिक और सामाजिक घटनाओं को रखना जिनके राजनीतिक परिणाम निकलने की सम्भावना हो,
- (4) अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पूर्व आवश्यक पूछताछ या खोजबीन करना,
- (5) यह निश्चय करना कि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्या सुरक्षा परिषद् के सामने प्रस्तुत की जाए एवं परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व औपचारिक रूप से वार्तालाप करना,
- (6) अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक घोषणा करना या सुभाव रखना, या सुरक्षा परिषद् के विचारार्थ प्रारूप-प्रस्ताव प्रस्तुत करना, तथा
- (7) सुरक्षा परिषद् के मंच से विश्व-लोकमत को सम्बोधित करते हुए शान्ति के लिए प्रयत्न करना।

महासचिव को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के महान् अवसर प्राप्त होते हैं। वह निरन्तर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों के सम्पर्क में रहना है, अतः उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों को प्रभावित कर सकता है। महासचिव सार्वजनिक वक्तव्य देकर भी विश्व-जनमत को प्रभावित कर सकता है। महासचिव की रिपोर्टें, जो महासभा में प्रस्तुत की जाती हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के सन्देशों के समान प्रभावशाली होती हैं। अपनी रिपोर्टों में वह इस तरह की सिफारिश भी कर सकता है कि संगठन को कौनसी नीति या कार्यक्रम अपनाना चाहिए। फिर भी, अन्तिम रूप में सदस्यों का सहयोग ही वह कुंजी है जो महासचिव को असफल या मफल बना सकती है। महासचिव हिटलर, नेपोलियन, लिंकन या लॉयड जॉर्ज नहीं बन सकता। विश्व-संस्था के सदस्यों के विश्वास और सहयोग के अनुपात में ही उसकी शक्ति घट-बढ़ सकती है। महासचिव एक निष्पक्ष अधिकारी समझा जाता है। वह एक अन्तर्राष्ट्रीय असेनिक सेवक और विश्व-संस्था का प्रवक्ता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अब तक के महासचिव

संयुक्त राष्ट्रसंघ में अब तक महासचिव के पद पर चार व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है—ट्रिग्वेली, डॉग हेमरशोल्ड, ऊ-याण्ट तथा कुर्त वाल्डहीम। 1 फरवरी, 1946 को नार्वे के ट्रिग्वेली 5 वर्ष के लिए महासचिव पद पर नियुक्त किए गए। 1 नवम्बर, 1950 को उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 10 नवम्बर, 1952 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 10 अप्रैल 1953 को स्वीडन के डॉग हेमरशोल्ड को महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 26 सितम्बर, 1957 को उन्हें 10 अप्रैल, 1957 से शुरू होने वाले 5 वर्ष के लिए पुनः महासचिव पद प्रदान किया गया, लेकिन कोंगो में शान्ति-सन्धियान में 18 सितम्बर,

1961 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब बर्मा के ऊ-थाण्ट को कार्य-वाहक महासचिव नियुक्त किया गया और फिर उनकी निवृत्ति 5 वर्ष के पूरे कार्यकाल के लिए कर दी गई। अक्टूबर, 1966 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, किन्तु उन्हें पुनः सर्वसम्मति से महासचिव चुन लिया गया। वर्तमान महासचिव आस्ट्रिया के डॉ. कुर्त वाल्दहीम हैं जो 1 जनवरी, 1972 से कार्य कर रहे हैं। 21 सितम्बर से 21 दिसम्बर, 1976 तक संयुक्त राष्ट्र महासभा का 31वाँ नियमित सत्र न्यूयार्क में हुआ था और सुरक्षा परिषद् की सर्वसम्मति सिफारिश पर महासभा में डॉ. वाल्दहीम को अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के राजनीतिक कार्य

अथवा

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व-शान्ति में भूमिका

संयुक्त राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है। संघ के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन उसके राजनीतिक कार्यकलाप ही सामान्यतः अधिक प्रकाश में आते हैं। विश्व-जनमत राजनीतिक कार्यों के आधार पर ही संघ की सफलता-असफलता का मूल्यांकन करता है। अब तक संघ के सामने कई अन्तर्राष्ट्रीय विवाद उपस्थित हुए हैं जिनको सुलझाने में कभी उसे सफलता मिली है और कभी निराशा। यहाँ हम कुछ प्रमुख राजनीतिक विवादों का उल्लेख करेंगे और देखेंगे कि संघ उनको निपटाने में कहाँ तक सफल हुआ है।

1. रूस-ईरान विवाद—संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत यह प्रथम विवाद था। ईरान के एक प्रान्त आइजरेजान में सोवियत फौजें प्रवेश कर गई थी। 19 जनवरी, 1946 को ईरान ने सुरक्षा-परिषद् में शिकायत की। रूस पर ईरान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया और ईरानी प्रान्त में रूसी सेनाओं की उपस्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा बताया गया। सुरक्षा-परिषद् में पश्चिमी गुट के राज्यों ने ईरान का समर्थन किया। जवाब में रूसी प्रतिनिधि ने परिषद् से प्रार्थना की कि यूनान में उपस्थित ब्रिटिश सैनिकों को निकालने के लिए कार्यवाही की जाए। अमेरिका और सोवियत रूस अपने भीत-गुट्ट को संयुक्त राष्ट्रसंघ में घसीट लाए। रूस ने इसी विवाद में अपने प्रथम वीटो का प्रयोग किया। परिषद् ने रूस से आग्रह किया कि वह 6 मई, 1947 तक ईरान से अपनी सेनाएँ हटा ले। बाद में मामला दोनों देशों की प्रत्यक्ष बार्ता द्वारा सुलझ गया। 21 मई, 1946 को दोनों देशों की राजधानियों ने घोषणा की कि सोवियत सेनाएँ 9 मई को ही ईरान छोड़ी कर चुकी हैं।

ईरानी संकट को सुलझाने में सुरक्षा-परिषद् का यद्यपि विशेष हाथ नहीं रहा, तथापि परिषद् में हुई बहसों ने रूस के विरुद्ध प्रबल जनमत जाग्रत कर दिया और रूस ने अपनी सेनाएँ ईरानी भूमि से हटा लेना ही उचित समझा। यह सिद्ध हो गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकमत को प्रदर्शित करने वाला एक अत्यन्त उपयोगी मंच है।

2. यूनान विवाद—पहले 3 जनवरी, 1946 को रूस ने सुरक्षा-परिषद् से गिरावट की कि महायुद्ध की समाप्ति के बाद भी ब्रिटिश सेनाएँ यूनानी भूमि पर जमी हुई हैं और यूनान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप एवं अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पैदा कर रही हैं। परिषद् में विचार-विमर्श के समय यूनानी प्रतिनिधि ने कहा कि यूनानी जनता अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति अनिवार्य समझती है। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि सुरक्षा-परिषद् ने मामले की सुनवाई समाप्त करने का निश्चय कर लिया। दिसम्बर, 1946 में यूनान ने परिषद् से शिकायत की कि पड़ोसी साम्यवादी देश छापामारों को सहायता दे रहे हैं और यूनान में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। परिषद् द्वारा नियुक्त आयोग ने मई, 1947 में इस शिकायत की पुष्टि की। परिषद् ने जब आगे जाँच-पड़ताल करने का प्रयत्न किया तो सोवियत रूस ने वीटो का प्रयोग कर दिया। इसके बाद महासभा ने जाँच-पड़ताल के लिए आयोग नियुक्त किया जिसे प्रत्वानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया ने अपनी सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अन्त में तीन मुख्य कारणों से यूनानी समस्या का समाधान हो गया—

- (i) महासभा द्वारा नियुक्त आयोग की उपस्थिति में साम्यवादी देश छापामारों को पूरी सहायता नहीं दे सके।
- (ii) टोटो-स्टालिन-विवाद के कारण यूनानी छापामारों को यूगोस्लाविया की सहायता बन्द हो गई।
- (iii) संयुक्त राष्ट्रसंघ के निरीक्षण में अमेरिका द्वारा यूनान को पूर्ण आधिकारिक सैनिक सहायता प्राप्त हुई।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामयिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप से दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश साम्यवादी नियन्त्रण में जाने से बच गया।

3. बर्लिन की समस्या—मार्च 1945 को पोर्ट्सडैम सम्मेलन के अनुसार बर्लिन नगर रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के नियन्त्रण में विभक्त कर दिया गया था। पश्चिमी बर्लिन मित्रराष्ट्रों के नियन्त्रण में और पूर्वी बर्लिन रूस के नियन्त्रण में रहा। पोर्ट्सडैम सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि दोनों जर्मनी की आर्थिक एकता कायम रखी जाएगी, लेकिन चारों देश इस निर्णय का पालन न कर सके। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नई मुद्रा प्रचलित करने से रुबल होकर रूस ने 1 मार्च, 1948 को पश्चिमी बर्लिन के जल और स्थल मार्ग बन्द कर दिए। इस नाकेबन्दी का प्रत्युत्तर पश्चिमी राष्ट्रों ने हवाई मार्ग का अधिनाधिक प्रयोग करके दिया।

23 सितम्बर, 1947 को सुरक्षा-परिषद् में रूसी नाकेबन्दी के विरुद्ध शिकायत की गई और इस कार्यवाही को शान्ति के लिए धातक बताया गया। भण्डा महाशक्तियों के बीच था, अतः सुरक्षा परिषद् समस्या पर विचार करने के अतिरिक्त और कुछ भी कर सकने में असमर्थ थी। इस बीच चारों महाशक्तियों के बीच अनौपचारिक रूप से समस्या के समाधान की बातचीत चालू रही और 4 मई, 1949 को फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् को सूचित किया कि बर्लिन समस्या पर रूस से उनका समझौता हो गया है।

यद्यपि समस्या का हल महाशक्तियों के पारस्परिक समझौते से हुआ, तथापि संयुक्त राष्ट्रसंघ ने विचार-विमर्श, पत्र व्यवहार और सम्पर्क आदि के रूप में दोनों पक्षों को परस्पर मिलाने के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी पृष्ठभूमि तैयार की और स्थान तथा सुविधाएँ उपलब्ध करायीं।

4. कोरिया संकट—इस गम्भीर संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ को पहली बार सैनिक कार्यवाही का सहारा लेना पड़ा। जून, 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर भीषण सैनिक आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद् ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। जुलाई, 1950 में लगभग 16 राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेना एकत्र की गई जिसने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। उत्तरी कोरिया के समर्थन में चीन भी युद्ध में कूद पड़ा। एक ओर तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की सैनिक कार्यवाही जारी रही और दूसरी ओर संघ ने शान्तिपूर्ण समझौते के प्रयास भी चालू रखे। अन्त में जुलाई, 1953 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से कोरिया का युद्ध विश्व-युद्ध बनने से रुक गया। ए. ई. स्टीवेंसन के शब्दों में—‘संयुक्त राष्ट्रसंघ की इस प्रथम महान् सामूहिक सैनिक कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया कि यह संगठन शक्ति और शान्ति दोनों रूप से काम करने में सक्षम है।’ वास्तव में संयुक्तराज्य अमेरिका की प्रबल सैनिक शक्ति के बल पर ही संच कोरिया युद्ध में सफल हो सका।

5. फिलिस्तीन विभाजन की समस्या—प्रथम महायुद्ध के बाद यह प्रदेश ब्रिटेन को सुरक्षित प्रदेश (Mandate) के रूप में प्राप्त हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त फरवरी, 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि उसके लिए इस मेडेट के शासन-प्रबन्ध को चलाना सम्भव नहीं है। अप्रैल, 1947 में ब्रिटेन ने यह समस्या महासभा के सामने प्रस्तुत की। महासभा द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने अगस्त, 1947 में सिफारिश की कि फिलिस्तीन को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए—एक भाग में अरब राज्य की स्थापना हो और दूसरे में यहूदी राज्य की। महासभा ने सिफारिश स्वीकार कर ली। लेकिन फिलिस्तीन-विभाजन के प्रश्न पर अरबों और यहूदियों में सघर्ष आरम्भ हो गया। दोनों पक्षों में प्रभावी युद्ध-विराम के सभी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयास विफल हो गए। 14 मई, 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में अपना शासन हटा लिया (जिसकी घोषणा 15 मई को की गई) और यहूदियों ने फिलिस्तीन में इजरायल-राज्य की घोषणा कर दी। इस पर ईराक, लेबनान, ट्रांसजोर्डन आदि अरब राष्ट्रों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। अरब-राष्ट्र इजरायल के प्रत्याक्रमण की नहीं भेल सके। 11 जून, 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधि बर्नाडोट के प्रयत्नों से दोनों पक्षों में चार सप्ताह के लिए युद्ध-विराम हो गया, किन्तु उपद्रव चालू रहे और 17 सितम्बर को बर्नाडोट भी गोली के शिकार हुए। सुरक्षा-परिषद् ने अब डॉ. राफ़ जे. बुंच को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। 29 दिसम्बर को तीसरी बार युद्ध-विराम स्थापित हुआ। इसके बाद महासभा ने एक ‘संयुक्त राष्ट्र समझौता आयोग’ (U. N. Conciliation Commission) नियुक्त

किया जिमने अनेक गम्भीर प्रश्नों का समाधान किया और इजरायल व पड़ोसी राज्यों में सीमा सम्बन्धी सन्धिर्षा सम्पन्न हुई।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों में फिलिस्तीन के विभाजन की समस्या के समाधान स्वरूप इजरायल और अरब राष्ट्रों में सन्धिर्षा हो गई, तथापि इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अक्टूबर, 1956 में मिस्र और इजरायल में पुनः युद्ध छिड़ा तथा हमी हस्तक्षेप व संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयासों से शान्ति स्थापित हुई। इसके बाद सन् 1967 और फिर सन् 1973 में अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच भीषण युद्ध हुआ किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रयत्नों से अस्थायी तौर पर शान्ति स्थापित हो गई।

6. इण्डोनेशिया विवाद—द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इण्डोनेशिया पर हॉलैण्ड का अधिकार था। युद्धकाल में उस पर जापान ने अधिकार स्थापित कर लिया। जापान की पराजय के बाद इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादियों ने अपने यहाँ एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी। इसके फलस्वरूप हॉलैण्ड और इण्डोनेशिया में युद्ध छिड़ गया। मामला सुरक्षा परिषद् में आया। परिषद् द्वारा नियुक्त 'सद्भाव समिति' (Good Offices Committee) के प्रयत्नों से अगस्त, 1947 में दोनों पक्षों में युद्ध बन्द हो गया और स्थायी सन्धि-वार्ता आरम्भ हो गई। लेकिन दिसम्बर, 1948 में हॉलैण्ड ने इण्डोनेशियाई गणराज्य के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ दिया तथा इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिषद् ने इस कार्यवाही का विरोध कर हॉलैण्ड से कहा कि इण्डोनेशिया में एक सर्वोच्च सत्ता-सम्पन्न सघातमक गणराज्य की स्थापना की जाए जिसे उच्च सरकार एक जुलाई, 1949 तक सम्प्रमुता हस्तान्तरित कर दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सद्भाव समिति' को 'इण्डोनेशिया आयोग' में परिवर्तित कर दिया गया।

काफी विचार-विमर्श और दबाव के बाद हॉलैण्ड ने इण्डोनेशियाई राजधानी से अपनी सेनाएँ वापस बुलाई और यह घोषणा की कि 30 दिसम्बर, 1949 तक इण्डोनेशिया-गणराज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तान्तरित कर दी जाएगी। बाद में 27 दिसम्बर, 1949 को ही इण्डोनेशिया को एक स्वतन्त्र सम्प्रभु गणराज्य मान लिया गया और 28 दिसम्बर, 1950 को उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्रदान कर दी गई। इण्डोनेशियाई विवाद को हल करने में इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

7. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न—दक्षिण अफ्रीका की सरकार 'काले-गोरे' में भेद-भाव के लिए बहुत समय से बदनाम है। सन् 1946 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने यह प्रश्न उपस्थित कर दिया और दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर मानवीय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत की शिकायत पर यह सफाई दी कि यह उसका घरेलू मामला है और संयुक्त राष्ट्रसंघ को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महासभा ने दक्षिण अफ्रीका की आपत्ति को अमान्य ठहराते हुए भारतीय

प्रस्ताव पारित कर दिया। किन्तु दक्षिण अफ्रीका ने इस प्रस्ताव की कोई परवाह नहीं की और जाति-भेद की अपनी अमानवीय नीति चालू रखी। सन् 1949 में यह प्रश्न पुनः महासभा में उठाया गया जिसने एक प्रस्ताव द्वारा सिफारिश की कि भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका एक बोलमेल सम्मेलन द्वारा समस्या का समाधान करें। सम्मेलन में दक्षिण-अफ्रीका की जिद के कारण कोई निर्णय न हो सका। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में अब तक यह प्रश्न बराबर उठाया जाता रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अपना रवैया नहीं बदला है। महासभा में प्रस्ताव पारित होते हैं, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वस्तव में इस प्रकार के मानवीय व्यवहार की समस्या को न सुलझा पाना संयुक्त राष्ट्रसंघ की बहुत बड़ी विफलता है।

8 कश्मीर समस्या—15 अगस्त, 1947 को भारत उपमहाद्वीप में दो स्वतन्त्र राष्ट्र-भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता देने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की कि देशी राज्य अपनी इच्छानुसार अपनी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं और चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। कश्मीर भी इसी तरह का एक देशी राज्य था। इस राज्य ने स्वतन्त्र रहने का निर्णय किया।

पाकिस्तान की नीयत कश्मीर को जबरदस्ती अपने साथ मिलाने की थी। अतः 22 अक्टूबर, 1947 को उसने उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त के कबाइलियों द्वारा कश्मीर पर हमला करवा दिया। पाकिस्तान की नियमित सेना के एक बड़े भाग ने भी इस आक्रमण में भाग लिया। राजधानी श्रीनगर का पतन सन्निकट होने पर कश्मीर के महाराजा ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत सरकार से कश्मीर को भारत में शामिल कर अविलम्ब सैनिक सहायता देने का अनुरोध किया। महाराजा ने प्रवेश पत्रक (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात् भारतीय सेनाएँ कश्मीर की रक्षा के लिए भेज दी गईं। कश्मीर में पाकिस्तान का नग्न आक्रमण जारी रहा और 1 जुलाई, 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद् में शिकायत की कि इस आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रमण स्वयं भारत पर आक्रमण है। भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरू ने घोषणा की कि कश्मीर का भारत में स्थायी विलय वहाँ जनमत संग्रह (Plebiscite) के आधार पर होगा।

सुरक्षा परिषद् में दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप होते रहे। 20 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद् ने एक मध्यस्थता आयोग (Mediation Commission) नियुक्त किया जिसे युद्धबन्दी और जनमत-संग्रह का कठिन काम सौंपा गया। आयोग के प्रयत्न से युद्ध-विराम हो गया और छे कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। आयोग ने जनमत संग्रह कराने के लिए दोनों देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जिन्हें पाकिस्तान ने भंग कर दिया। कश्मीर में परिस्थितियाँ तेजी से बदलती गईं और भारत व पाकिस्तान में समझौता कराने के संयुक्त राष्ट्रसंघीय

प्रयास सफलता प्राप्त न कर सके। पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों का खुला समर्थन मिलता रहा और उनके हाथों में खेलते हुए सुरक्षा परिषद् भारत के साथ अन्याय करती रही। सन् 1954 में कश्मीर सविधान सभा ने कश्मीर के भारत में विलय का विधिवत् अनुमोदन कर दिया। सन् 1956 में राज्य के लिए एक नया सविधान स्वीकार किया गया जिसके द्वारा कश्मीर प्रत्येक दृष्टि से भारत का वैध प्रग बन गया। इस तरह कश्मीर समस्या का स्वरूप विनशुल बदल गया और जनमत-संग्रह का कोई मूल्य नहीं रह गया। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल हो जाने और कश्मीर को वलपूर्वक लेने की चालें खेलने के कारण जनमत-संग्रह की बात बहुत पहले ही निरर्थक हो चुकी थी।

पाकिस्तान पाश्चात्य राष्ट्रों के समर्थन के बल पर बार-बार कश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाता रहा, लेकिन भारत के दृढ़ रवैये और न्याय का पक्ष देते हुए सौविध्यत रूस द्वारा निषेधाधिकार प्रयोग के कारण उसके कुटिल उद्देश्य पूरे न हो सके।

कश्मीर का मामला आज भी सुरक्षा परिषद् की विषय-सूची में है। दुर्भाग्यवश विश्व की गुटबन्दी के कारण सुरक्षा परिषद् अभी तक इस विवाद को हल नहीं कर सकी है। सुरक्षा परिषद् में पश्चिमी शक्तियों का बहुमत है, अतः पाकिस्तान परिषद् के फैसले को अपने पक्ष में कराने का कोई मौका नहीं चूकता। किन्तु मितम्बर, 1965 और दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्धों के बाद अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान भी यह समझ गया है कि परिषद् के माध्यम से भारत पर कोई भी निर्णय थोपने की बात सोचना व्यर्थ होगा।

वास्तव में संयुक्त राष्ट्रमण्डल के लिए कश्मीर का विवाद राहू के समान सिद्ध हुआ। यद्यपि वह इस प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों को शान्त कर मरा है तथापि पश्चिमी शक्तियों के हाथों में खेलन हुए उसने जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है उससे इस महान् समस्या के गौरव को आघात ही पहुँचा है। न्याय और निष्पक्षता का तकाजा यही है कि संयुक्त राष्ट्रमण्डल आन्तमक पाकिस्तान की सेनाओं को कश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करे।

9 स्वेज नहर विवाद—सन् 1869 में निर्मित स्वेज नहर का संचालन एक स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकांश शेयर थे। समझौते के अनुसार इसकी रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी सेना रखती थी। नवम्बर, 1950 में मिस्र की सरकार ने यह माँग की कि ब्रिटिश सेना स्वेज नहर क्षेत्र से हट जाए। ब्रिटेन द्वारा यह माँग ठुकरा देने पर दोनों पक्षों के सम्बन्ध बटु हो गए। मिस्र में राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकड़ा और अन्त में जुलाई, 1954 में एक नए समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन को स्वेज नहर क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी पड़ी। इस समय मिस्र में वर्नल नासिर का शासन था। उपर्युक्त समझौते के बाद भी मिस्र और ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ और 26 जुलाई, 1956 को नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा मिस्र

स्थित स्वेज नहर कम्पनी की सम्पत्ति जव्त कर ली। 26 सितम्बर को ब्रिटेन और फ्रांस ने यह सम्पूर्ण विवाद सुरक्षा परिषद् के समक्ष रखा। 13 अक्टूबर, 1956 को परिषद् ने समस्या के हल के लिए एक प्रस्ताव के रूप में 6 सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जिसमें स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण का भी सुझाव दिया गया, लेकिन सोवियत वीटो से यह प्रस्ताव रद्द हो गया।

आपत्ती तनाव इतना बढ़ गया कि 26 अक्टूबर, 1956 को ब्रिटेन और फ्रांस की प्रेरणा पर इजरायल ने स्वेज नहर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इसके दो दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इजरायल के साथ युद्ध में जुड़ पड़े। सुरक्षा परिषद् में युद्ध-बन्दी का प्रस्ताव फ्रांस और ब्रिटेन के वीटो के कारण पास न हो सका। संघ के जीवन में यह घोर संकट का समय था जब सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य स्वयं संघ के चार्टर का उल्लंघन कर संघ के एक सदस्य-राज्य पर आक्रमण कर रहे थे। 2 नवम्बर, 1956 को महासभा के एक विशेष अधिवेशन ने अमेरिका का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस की सैनिक कार्यवाही की निन्दा करते हुए अविलम्ब युद्ध बन्द करने पर जोर दिया गया। 4 नवम्बर को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि महासचिव श्री डॉग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक आभातकालीन सेना तैयार करे जो मिस्र में युद्ध-बन्दी का कार्य करे। 10 राष्ट्रों ने मिलकर 6 हजार सैनिक जुटाये जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के नीले और श्वेत ध्वज के नीचे एकत्र हुए। 5 नवम्बर को सोवियत संघ ने ब्रिटेन और फ्रांस को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक निश्चित समय में मिस्र पर आक्रमण बन्द नहीं किया गया तो सोवियत संघ नवीनतम शस्त्रों के साथ इस संकट में हस्तक्षेप करेगा। इस चेतावनी से तृतीय महायुद्ध की सम्भावना दिखाई देने लगी और ब्रिटेन और फ्रांस ने भयभीत होकर युद्ध बन्द कर दिया। 7 नवम्बर, 1956 को महासभा ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस व इजरायल की भेनाएँ मिस्र से हट जाएँ तथा स्वेज नहर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप युद्ध पूरी तरह बन्द हो गया और 15 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्रसंघीय आभातकालीन सेना का पहला दस्ता मिस्र पहुँच गया। मिस्र न संघ की सेनाओं को तभी प्रवेश की आज्ञा दी जब मिस्र की प्रभुसत्ता को हानि न पहुँचाने का वचन दे दिया गया। अप्रैल, 1957 में स्वेज नहर से जहाजों का आना-जाना पुनः आरम्भ हो गया।

मिस्र में युद्ध बन्द कराने और विदेशी सेनाओं को हटाने में संयुक्त राष्ट्रसंघ को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और स्वेज पर ब्रिटेन व फ्रांस के पुनः आधिपत्य के सपने चूर-चूर हो गए।

10. काँगो समस्या—संघ की सबसे कठिन परीक्षा काँगो में हुई और सौभाग्यवश इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। जुलाई, 1960 में काँगो में भीषण गृह-युद्ध छिड़ गया जिसे भड़काने में बेल्जियम का मुख्य पङ्कज था। काँगो सरकार की प्रार्थना पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सेनाओं ने पहुँचकर काँगो और बेल्जियम के बीच होने वाले संघर्ष को तो समाप्त कर दिया, लेकिन काँगोई प्रान्तों के गृह-युद्ध की

स्थिति तेजी से बिगड़ती गई। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक ओर तो सैनिक उपायो द्वारा कांगो का विघटन रोका तथा दूसरी ओर समझौतावादी नीति भी अपनाई। सितम्बर, 1962 में महासचिव हेमरशोल्ड कांगो के सघर्षरत नेताओं से बातचीत करने के लिए स्वयं कांगो गए और वही मार्ग में एक वायु-दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नए महासचिव ऊथार्ट ने अपने प्रयत्न जारी रखे। अन्त में, विरोधी प्रान्त कटगा ने अपने घुटने टेक दिए और जनवरी 1963 में कांगो में शान्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ का शान्ति स्थापना का कार्य कांगो के एकीकरण के साथ समाप्त हुआ।

11 यमन की समस्या—19 सितम्बर, 1962 को यमन के शासक इमाम अहमद की मृत्यु हो गई। 26 सितम्बर को एक क्रान्ति द्वारा यमन में राजतन्त्र की समाप्ति कर दी गई और क्रान्तिकारी परिषद् ने वहाँ गणराज्य की स्थापना की। दूसरी ओर राजतन्त्रवादियों को अपने पक्ष में कर शहजादा हुसैन ने सऊदी अरब में जिद्दा नामक स्थान पर यमन की निर्वासित सरकार की स्थापना की। दोनों यमनी सरकारें एक-दूसरे को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक और सामरिक नीतियाँ अपनाती रही। अक्टूबर के समाप्त होते-होते राजतन्त्रवादियों और गणतन्त्रवादियों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। सऊदी अरब और जोर्डन ने राजतन्त्रवादियों की सहायता की और मिस्र ने गणतन्त्रवादियों की। गृह युद्ध को व्यापक बनाने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने हस्तक्षेप किया। मार्च, 1963 में संघ की ओर से राल्फ बुच ने प्रत्यक्ष भेट द्वारा दोनों पक्षों को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि वे अपने-अपने सैनिकों को वापस बुला लें और समस्या का शान्तिपूर्ण हल खोजें। संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाद के पभावपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप जर्न-जर्न वाह्य शक्तियों ने यमन से अपनी सेनाएँ हटा ली और यमन में शान्ति स्थापित हो गई।

12 साइप्रस की समस्या—13 अगस्त, 1960 को साइप्रस ब्रिटिश अधिकार से मुक्त होकर स्वतन्त्र गणराज्य बन गया। साइप्रस का जो संविधान बनाया गया उसमें वहाँ के बहुसंख्यक यूनानियों और अल्पसंख्यक तुर्कों के बीच सामंजस्य और शान्ति कायम रखने की व्यवस्था की गई। स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति मकारियोस ने संविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तावित किया जिससे दोनों जातियों के मध्य सन्तुलन और सामंजस्य समाप्त हो जाना। फलस्वरूप दोनों जातियों में राजनीतिक संघर्ष और गृह-युद्ध आरम्भ हो गया। समस्या पर यूनान, टर्की और साइप्रस के बीच इजलैण्ड में शान्ति-सम्मेलन शुरू हुआ। ब्रिटेन ने साइप्रस में नाटो सेनाएँ भेजने का चक्कर रचा। राष्ट्रपति मकारियोस ने दिसम्बर, 1963 में सारा मामला सुरक्षा परिषद् के सामने प्रस्तुत कर संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक भेजने और स्थिति सम्भालने के लिए संघ के हस्तक्षेप की माँग की। लम्बे विचार-विमर्श के बाद मार्च, 1964 में साइप्रस में शान्ति-स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना भेजने का निर्णय किया गया। शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना साइप्रस पहुँच गई जिसने वहाँ कानून और व्यवस्था स्थापित रखने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद इस आपात्कालीन सेना की अवधि बढ़ाई जाती रही।

13. डोमिनिकन गणराज्य विवाद—लेटिन अमेरिका के इस छोटे से राज्य में अप्रैल, 1965 में गृह-युद्ध छिड़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पक्ष की सरकार को बचाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया। वहाना यह लिया गया कि डोमिनिकन गणराज्य को साम्यवादियों में बचाने के लिए यह कार्यवाही की गई है। रूस ने सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करे। अन्त में परिषद द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया कि दोनों युद्धरत पक्ष युद्ध-विराम करें और महासचिव डोमिनिकन गणराज्य में आवश्यक जान-पड़ताल के लिए प्रतिनिधि भेजें। अमेरिकी राज्यों के सगठन ने भी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए। अन्त में अमेरिकी राज्यों के सगठन और संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रयासों से 4 माह के गृह-युद्ध के उपरान्त 31 अगस्त, 1965 को दोनों पक्षों में समझौते के फलस्वरूप शान्ति स्थापित हो गई। महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में खुले शब्दों में कहा कि डोमिनिकन गणराज्य में युद्धबन्दी कराने में सच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

14. अरब-इजरायल संघर्ष—सन् 1956 के अरब-इजरायल युद्ध-विराम के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की अन्तर्राष्ट्रीय सेना गाजा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गई थी ताकि इजरायल-अरबों में पुनः संघर्ष न छिड़ जाए लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता गया। सन् 1967 में ओरो से युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई। मई में राष्ट्रपति नासिर के ज़िद करने पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के सैनिक हटा लिए गए। अब संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सेनाएँ आमने-सामने हो गई। एक-दूसरे की कार्यवाहियों से स्थिति बिगड़ गई और 5 जून को एकाएक इजरायल ने अरबों पर विनाशकारी आक्रमण कर दिया। जोर्डन, सीरिया, मिस्र, ईराक आदि 10 करोड़ वाली जनसंख्या के देश छोटे से इजरायल के आक्रमण का सामना न कर सके। केवल 5 दिन की लड़ाई में ही अरब राष्ट्रों की सामरिक क्षमता का विनाश हो गया। इस बीच सुरक्षा परिषद युद्ध-विराम के लिए पूरे प्रयास करती रही। 7 जून को परिषद ने यह प्रादेशात्मक प्रस्ताव पारित किया कि सभी युद्धरत देश युद्ध बन्द कर दें। चूँकि अरब राष्ट्र युद्ध-क्षमता खो चुके थे और इजरायल सामरिक उद्देश्यों को पूरा कर चुका था, अतः 8 जून को इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध-विराम हो गया और 10 जून तक सभी अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच पूरी तरह युद्ध बन्द हो गया। संयुक्त अरब गणराज्य स्वेज तट पर संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक रखने के लिए सहमत हो गया। 16 जुलाई से स्वेज नगर क्षेत्र में सच के पर्यवेक्षकों की देख-रेख में युद्ध-विराम लागू हो गया। किन्तु फिर भी पूर्ण शान्ति स्थापित न हो सकी और आज भी इस क्षेत्र में दोनों पक्षों में सैनिक झड़पें होती रहती हैं। पारस्परिक तनाव पुनः विस्फोटक स्थिति में पहुँचता जा रहा है और स्थायी शान्ति तो कोसों दूर दिखायी देती है। अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच बार-बार युद्ध-विराम कराने में सच की सफलता अवश्य मिली है, लेकिन इसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र में शान्ति अभी सम्भव हो

संकेती जब विश्व की महाशक्तियाँ बीच में पड़ कर रुचिपूर्वक कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगी।

15. भारत-पाक सघर्ष, 1965—कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने सन् 1965 में पुनः युद्ध का आश्रय लिया। अगस्त, 1965 में हजारों पाकिस्तानी हमलावर छिपकर युद्ध विराम रेखा पार कर कश्मीर के भारतीय प्रदेश में प्रवेश कर गए। भारत ने जब इस घुसपैठी आक्रमण को असफल कर दिया तो मितम्बर, 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान की एक पूरी पैदल ब्रिगेड और 70 टैंक कश्मीर पर चढ़ आए। विवश होकर भारत को भी अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध खुलकर लड़ाई छेड़ देनी पड़ी। 22 दिन के प्रमासान युद्ध में पाकिस्तान पर करारी मार पड़ी और आखिर सयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रयासों से 23 सितम्बर, 1965 को प्रातः 3½ बजे भारत-पाक युद्ध-विराम हो गया तथा पाकिस्तान की रही सही नाज नष्ट होने से बच गई।

सयुक्त राष्ट्रसंघ प्रारम्भ से अन्त तक युद्ध-विराम के प्रयत्न करता रहा। स्वयं महासचिव ने दिल्ली और कराँची पहुँच कर थी शास्त्री और अग्रुव से सम्पर्क स्थापित किया। महामन्त्रि ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद् को बताया कि यदि पाकिस्तान सहमत हो तो भारत बिना शर्त युद्ध बन्द करने को प्रस्तुत है, किन्तु पाकिस्तान ने युद्ध-विराम प्रस्ताव को प्रत्यक्षत ठुकरा दिया। महामन्त्रि ने माँग की कि परिषद् दोनों पक्षों को अविलम्ब युद्ध बन्द करने का आदेश दे और युद्ध बन्द न होने पर आवश्यक कार्यवाही करे। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि परिषद् पहले यह निश्चित करे कि आक्रामक कौन है। भारत ने यह भी कह दिया कि सयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। पाकिस्तान ने पहले कश्मीर में घुसपैठी आक्रमण शुरू किया और बाद में विविध आक्रमण कर दिया। अन्त में काफी ऊहापोह के बाद परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि भारत और पाकिस्तान 22 सितम्बर को दोपहर से युद्ध बन्द कर दें और युद्ध-विराम लागू होने के बाद अपनी सेनाओं को 5 अगस्त, 1965 की स्थिति में लौटा लें। पाकिस्तान द्वारा सहमति की सूचना देने पर युद्ध 23 सितम्बर, 1965 को प्रातः 3½ बजे बन्द हो गया।

सुरक्षा परिषद् का 22 मितम्बर का प्रस्ताव भारत के साथ अन्याय था। इसमें दोनों देशों को युद्ध बन्द करने का आदेश दिया गया था जबकि यह आदेश केवल आक्रमणकारी पाकिस्तान को ही दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने ही परिषद् के युद्धबन्दी के पहले वाले प्रस्ताव को ठुकराया था। आक्रामक और आक्रान्त दोनों के साथ एक-सा व्यवहार करना न्यायसंगत नहीं था। भारत ने केवल यही सोचकर इसे स्वीकार कर लिया कि उसकी शान्तिप्रियता पर कोई अगुली न उठा सके।

16. चेकोस्लोवाकिया का संकट—21 अगस्त, 1968 को सोवियत संघ तथा वारसा-सन्धि के अन्य साम्यवादी देशों ने चेकोस्लोवाकिया में सैनिक कार्यवाही

कर हंगरी की घटनाओं को एक बार फिर ताजा कर दिया। रूसी पक्ष की इस सैनिक कार्यवाही के कई कारण थे। मूल कारण यह घोषित किया गया कि चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादी शासन की प्रतिक्रियावादी तत्वों से रक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। तुरन्त ही इस मसले को सुरक्षा परिषद् में उठाया गया। परिषद् के 7 सदस्य-राष्ट्रों की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें रूसी कार्यवाही को एक स्वतन्त्र और प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्र पर आक्रमण की सजा देकर उसकी निन्दा की गई तथा यह मांग की गई कि रूस और वारसा राष्ट्रों की सेनाएँ शीघ्र ही चेकोस्लोवाकिया से वापस चली जाएँ। कई कारणों से यह प्रस्ताव व्यर्थ मिट्टी हुआ। स्वयं चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बाद में सितम्बर में महासभा के अधिवेशन में इस विवाद को पुनः उठाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन इस बार भी कोई परिणाम नहीं निकला। वास्तव में चेकोस्लोवाकिया-संकट के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक मूकदर्शक से अधिक नहीं निभायी।

17. साम्यवादी चीन का संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश—महासभा ने सन् 1971 के अधिवेशन में लगभग 22 वर्षों से विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के साम्यवादी चीन की सदस्यता से सम्बन्धित एक बहुत ही जटिल प्रश्न का समाधान कर दिया गया। 26 अक्टूबर, 1971 को साम्यवादी चीन को संघ की सदस्यता प्रदान करने और ताइवान (राष्ट्रवादी चीन) को वहाँ से निष्कासित करने सम्बन्धी प्रस्तावित 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिए जाने से संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में वस्तुतः एक नए युग का सुरुवात हुआ।

18. बंगलादेश की समस्या—पाकिस्तान ने अपने ही एक भाग पूर्वी बंगाल की स्वायत्तता की मांग को कुचलने के लिए सन् 1970-71 में बर्बर दमन चक्र चलाया जिसके फलस्वरूप मार्च, 1971 में पूर्वी बंगाल की जनता ने एक स्वतन्त्र देश के रूप में अपनी स्थापना की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने बंगलादेश के जन-प्रान्दोलन को कुचलने के लिए अमानुषिक ढंग से सैनिक शक्ति का प्रयोग किया, जिसके कारण लगभग एक करोड़ लोग भागकर शरणार्थियों के रूप में भारत आ गए। भारत ने तथा अन्य देशों के साथ स्वयं बंगलादेश के प्रतिनिधि मण्डल ने इस समस्या की गम्भीरता की ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन अमेरिका के पाक-समर्थक और बंगलादेश विरोधी रवैये के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ इस समस्या को सुलझाने और बंगलादेश में पाकिस्तान द्वारा मानवीय अधिकारों के हनन को रोकवाने में कोई विशेष सहायता नहीं कर सका। पाकिस्तान का भीषण अत्याचार और हत्याकाण्ड चालू रहा तथा विश्व-संस्था उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। बाद में भारत के सहयोग से बंगलादेश का मुक्ति-संग्राम सफल हुआ और एक गणप्रभु राज्य के रूप में वह संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य भी बन गया।

19. भारत-पाक संघर्ष, 1971—इस संघर्ष के समय भी संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अमेरिका और उसके विद्वन्मग्न राष्ट्रों के प्रभाव में आकर पुनः बड़ा पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया। भारत के इस अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि असली विवाद

पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच है तथा इसे भारत-पाक विवाद के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए ।

सुरक्षा परिपद् में अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि भारत तथा पाकिस्तान युद्ध-विराम करें और तुरन्त अपनी-अपनी सेनाएँ पीछे हटा लें । अन्य राष्ट्रों द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए जिनमें से एक में युद्ध विराम कर सेनाएँ वापस हटाने की बात थी । चीना प्रस्ताव रूस द्वारा पेश किया गया जिसमें कहा गया था कि पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक हल निकाला जाए जिससे स्वाभाविक रूप से अन्त में संधि समाप्त हो सकेगा । अमेरिका के प्रस्ताव पर रूसी वीटो के प्रयोग से भारत के समक्ष उपस्थित एक भारी सकट टल गया । 24 घण्टे में ही परिपद् की दूसरी बैठक में पुनः युद्ध-विराम तथा दोनों पक्षों के सैनिकों के लौट जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे रूस ने पुनः वीटो कर दिया । चीन ने अपने असफल प्रस्ताव में भारत पर आक्रमण करने का आरोप लगाया । सुरक्षा परिपद् में असफल होने पर विवाद महासभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों के प्रभाव से युद्ध-विराम तथा सेनाओं की वापसी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया । भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी युद्ध-विराम तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन और वहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं की वापसी की बात को नहीं माना जाता । 14 दिसम्बर को परिपद् की तीसरी बैठक में अमेरिका के पहले जैसे ही प्रस्ताव पर रूस ने तीसरी बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया । परिपद् का अगला अधिवेशन बुलाए जाने और कोई अन्य प्रपच किए जाने से पूर्व ही भारत ने एक पक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दी (16 दिसम्बर) । भारत का उद्देश्य बंगलादेश गणतन्त्र को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्ति दिलाना था । यह उद्देश्य पूरा होने ही उसने युद्धबन्दी का आदेश दे दिया और युद्ध में बुरी तरह पिट रहे पाकिस्तान ने युद्ध बन्द कर देने में ही अपनी कुशलता समझी ।

20. अरब-इजरायल युद्ध, 1973—अक्तूबर, 1973 में चीना अरब-इजरायल युद्ध प्रारम्भ हो गया, लेकिन महाशक्तियों की उदासीनता के कारण सुरक्षा परिपद् में तत्काल सारी स्थिति पर विचार नहीं हो सका । रूस ने इसलिए रुचि नहीं ली कि युद्ध के प्रारम्भ में अरबों की विजय हो रही थी । अमेरिका द्वारा रुचि लेने का कारण था कि वह उस अवसर की प्रतीक्षा में था जब इजरायल सम्भल कर जवाबी हमले द्वारा अपना पक्ष मजबूत कर लेता । इसी बीच संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव वाल्डहीम ने सुझाव रखा कि युद्धरत राष्ट्रों में अविलम्ब युद्ध बन्द करने की अपील की जाए । 7 अक्तूबर को सुरक्षा परिपद् की गुप्त बैठक में इस सुझाव पर विचार हुआ, लेकिन रूस और चीन के विरोध के कारण कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सका । अधिकांश सदस्यों का विचार था कि ऐसी किसी भी अपील से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक उसके साथ ही यह मान भी न की जाए कि इजरायली सेनाएँ मन् 1967 की युद्ध-पूर्व की विराम रेखा तक लौट जाएँ । 9 अक्तूबर को अमेरिका ने सुरक्षा परिपद् की बैठक बुलाने की पहल की ।

अपने प्रस्ताव में उतने माँग रखी कि इजरायल, मिस्र और सीरिया से युद्ध बन्द करने और युद्ध की पूर्व स्थिति तक अपनी-अपनी सेनाएँ लौटा लेने की अपील की जाए। यह प्रस्ताव अरब देशों के हित में नहीं था। अतः रूस ने प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसे किसी भी प्रस्ताव को 'वीटो' कर देगा। परिषद् की प्रथम बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और 12 अक्टूबर की दूसरी बैठक में भी इस प्रश्न पर कोई सहमति न हो सकी कि किस प्रकार युद्ध बन्द कराया जाए। जब युद्ध की स्थिति अत्यधिक विस्फोटक हो गई तो 22 अक्तूबर को रूस और अमेरिका ने संयुक्त रूप से सुरक्षा परिषद् में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सुरक्षा परिषद् यह माँग करती है कि युद्धरत पक्ष तुरन्त युद्ध बन्द कर दें और जो जिस जगह है वही इस प्रस्ताव की स्वीकृति के 12 घण्टे के अन्दर सारी कायदाही रोक दें; युद्धबन्दी के तुरन्त बाद सुरक्षा परिषद् के सन् 1967 के 242वें प्रस्ताव को पूर्णरूप से लागू किया जाए एवं सम्बन्धित पक्ष व्यापेचित तथा स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए समझौता-वार्ता आरम्भ कर दें। परिषद् के प्रस्ताव को इजरायल और मिस्र ने 22 अक्तूबर की शाम को 7 बजे स्वीकार कर लिया, लेकिन सीरिया ने इसे स्वीकार नहीं किया, अतः गोलन पहाड़ियों पर युद्ध जारी रहा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि रूस का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने की सम्भावना दिखायी देने लगी। 26 अक्तूबर को अमेरिका ने भी विश्व भर में अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दे दिया। 27 अक्तूबर को सुरक्षा परिषद् की बैठक में युद्ध-विराम की निगरानी के लिए और उसके उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आपात् सेना के गठन पर विचार-विमर्श हुआ और परिषद् ने भारत के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महासचिव ने कहा कि आपात् सेना में 7 हजार व्यक्ति होंगे। एक सैनिक टुकड़ी अविलम्ब ही मिस्र में युद्ध-विराम का उल्लंघन रोकने के लिए तैनात कर दी गई। इसके बाद पश्चिमी एशिया की विस्फोटक स्थिति में कुछ सुधार हुआ। समझौता-वार्ता चालू रही और तब अग्त में 11 नवम्बर, 1973 को इजरायल और मिस्र के बीच एक 6 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका से पुनः यह स्पष्ट हो गया कि वह महाशक्तियों के हाथ का खिलौना है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक गतिविधियों के इस विवेचन से स्पष्ट है कि यह ने विवादों का समाधान करने में अपनी जागरूकता दिखायी है लेकिन वह महाशक्तियों की अडगोवाजी का शिकार रहा है। कश्मीर के प्रश्न, वियतनाम के वर्ण, दक्षिण प्रफ्रीका की रंग-भेद नीति, निःशस्त्रीकरण, अणुशक्ति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध, पश्चिमी एशिया के सकट के स्थायी समाधान आदि में संघ की विफलता का ही मुँह देना पड़ा है। फिर भी उनमें से कुछ समस्याओं को अधिक विस्फोटक बनने से रोकने की दिशा में संघ के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। अनेक अवसरों पर संघ के सामयिक हस्तक्षेप के कारण ही स्थिति विस्फोटक होने से रुकी है। यद्यपि संघ विश्व-शान्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूर्ण सन्तोषजनक सिद्ध नहीं हुआ है

तथानि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में शान्ति स्थापना के इतने अनेक बार सफल प्रयत्न किए हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विविष्ट अभिकरण और संस्थाएँ : गैर-राजनीतिक कार्य

विश्व में शान्ति कायम रखना तथा राष्ट्रों के बीच उत्पन्न राजनीतिक विवादों को सुलझाना संयुक्त राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन चार्टर ने संघ पर कुछ गैर-राजनीतिक कार्यों का दायित्व भी डाला है, जिनका उद्देश्य मानव-समाज के भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहयोग देना है। चार्टर में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग पर विशेष बल दिया गया है। अनुच्छेद 55 में व्यवस्था है कि—

“बौद्धिक समानाधिकार और स्वाधीनता के आधार पर राष्ट्रों के बीच शान्ति और मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तथा जनहित और स्थिरता की जो स्थितियाँ आवश्यक हैं उनको पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ नीचे लिखी बातों को प्रोत्साहन देगा—

- (क) रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना, सबके लिए काम की व्यवस्था करना आर्थिक और सामाजिक उन्नति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करना।
- (ख) अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और तत्सम्बन्धी समस्याओं का सुलझाना तथा संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना।
- (ग) जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेद किए बिना सबके लिए मानव-अधिकारों और मूल स्वतन्त्रताओं के प्रति सर्वत्र सम्मान और उनका पालन कराना।”

इन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ अपनी स्थापना के समय से ही प्रयत्नशील है। इन कार्यों का सम्पादन संघ कई विविष्ट अभिकरणों और संस्थाओं की सहायता से करता है। जिन अभिकरणों और संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सम्बन्ध है, उन्हें कार्यों की दृष्टि से चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है—आर्थिक, संचार, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी।

आर्थिक संगठन

आर्थिक कार्यों के लिए जिन चार मुख्य संस्थाओं का निर्माण किया गया वे हैं—(क) अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन (I. L. O.), (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन (F. A. O.), (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.), एवं (घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I. F. C.)।

(क) अन्तर्राष्ट्रीय धन संगठन—यह एक पुराना अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना प्रथम महायुद्ध के बाद हुई थी और जो राष्ट्रसंघ (लीग) के साथ सम्बद्ध था। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। इस संगठन

के सिद्धान्त हैं—(i) श्रम वस्तु नहीं है, (ii) गरीबी समृद्धि के लिए खतरनाक है, (iii) मानव-प्रगति के लिए सगठन तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता परनावश्यक है, एवं (iv) अभाव और दरिद्रता के विरुद्ध प्रत्येक देश को पूरे उत्साह के साथ मुड़ करना चाहिए। इन सिद्धान्तों की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो कार्यक्रम अपनाया है वह मोटे रूप में इस प्रकार है—श्रमिकों को जीवन-निर्वाह और पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक तथा पूरी मजदूरी प्राप्त हो, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कामों का विस्तार हो, श्रमिकों के लिए पर्याप्त भोजन और आवास की व्यवस्था हो, श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार प्राप्त हो, उन्हें अवसरों की पूरी समानता प्राप्त हो, एवं उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की सुचारु व्यवस्था हो। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा श्रमिकों का जीवन-स्तर सुधारने और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। सगठन के तीन प्रमुख अंग हैं—(क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (International Labour Conference), (ख) प्रशासनिक निकाय (Governing Body), एवं (ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय (International Labour Office)।

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन—संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत सन् 1945 में महायुद्ध के बाद स्थापित यह प्रथम सगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य एवं कृषि की दशाओं को उन्नत करना है। पौष्टिक खुराक प्राप्त हो, रहन-महन का स्तर ऊँचा उठे, फ़ाँसों, जंगलों तथा मछली उद्योग वाले क्षेत्रों में सभी तरह के खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हो तथा इनका समुचित वितरण हो—इन बातों के लिए यह सगठन प्रयत्नशील रहता है। इसने विश्व के विभिन्न भागों में भूमि और जल के मूल साधनों के विकास में योग दिया है और नवीन प्रकार के पौधों की बदला-बदली को प्रोत्साहन दिया है। विश्व के देशों में इसने कृषि के उन्नत तरीकों का प्रचार किया है, मवेशियों के रोग-निवारण के लिए कार्य किया है और इस दिशा में विभिन्न राष्ट्रों को तकनीकी सहायता दी है। खाद्य और कृषि की प्रत्येक समस्या पर इस सगठन की तकनीकी सहायता और परामर्श महत्वपूर्ण रहे हैं। यह प्रतिवर्ष विश्व-खाद्यान्नों का निरीक्षण करता है। भारत में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में इस सगठन ने बहुत सहायता की है।

खाद्य एवं कृषि सगठन के मुख्य अंगों में एक सम्मेलन, एक परिषद् और डायरेक्टर जनरल तथा उसका स्टाफ सम्मिलित है। सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य-राज्य का एक-एक प्रतिनिधि होता है। सम्मेलन ही खाद्य और कृषि सगठन की नीति का निर्धारण करता है और बजट स्वीकार करता है। सम्मेलन के अधिवेशन की समाप्ति और आरम्भ की प्रवधि में परिषद् काम करती है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष—इसकी स्थापना 27 दिसम्बर, 1945 को हुई जबकि इसके कोष का 80 प्रतिशत भाग विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जमा करा दिया। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य लक्ष्य हैं—विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहन

देना, सदस्यों के बीच व्यवस्थित विनिमय-व्यवस्था की स्थापना करना प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय तथा मन्दी की स्थिति को दूर करना, सदस्यों के बीच चानू लेन-देन में मुग्तान की बहुपक्षीय प्रणाली की स्थापना में सहायता करना, विश्व-व्यापार की प्रगति में अवरोधक विदेशी विनिमय के प्रतिबन्धों को समाप्त करना, सदस्यों के लिए कोष के साधन उलब्ध कराना और इस तरह उनमें विश्वास की भावना जगाना आदि। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबन्ध-कार्यालय उस देश में होता है जो सबसे अधिक नियतांश प्रदान करता है। वर्तमान समय में यह कार्यालय संयुक्तराज्य अमेरिका में है। इस कोष की शाखाएँ किसी भी सदस्य-देश में खोली जा सकती हैं। मुद्रा कोष के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। इसने विभिन्न देशों को समय-समय पर ऋण देकर उनके मुग्तान की बकाया के स्थायी असन्तुलन को दूर किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में इसका भारी योग रहा है। इसने सदस्य-देशों को मुग्तान की बकाया के दीर्घकालीन असन्तुलन को दूर करने में भी सहायता दी है। कोष आर्थिक और मौद्रिक विषय पर सदस्य-देशों को उपयोगी परामर्श देता है। यह अपने सदस्यों को विश्व की आर्थिक स्थिति के परिवर्तन की सूचनाएँ नियमित रूप से देता रहता है। कोष अपने विशेषज्ञों की सेवाएँ प्रदान करता ही है, कभी-कभी बाहरी विशेषज्ञों को भी सदस्य-देशों की सहायतार्थ भेजता है। ये विशेषज्ञ सदस्य देशों के आर्थिक परामर्शदाताओं का कार्य करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबन्ध एक गवर्नर-मण्डल (Board of Governors), कार्यकारी सचालक मण्डल (Board of Executive Directors) और प्रबन्ध सचालकों (Managing Directors) तथा अन्य स्टाफ की सहायता से किया जाता है।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम—इसकी स्थापना जुलाई सन् 1956 में की गई और 20 फरवरी, 1957 से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के एक विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। इसका कोष अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कोष से बिल्कुल पृथक् है। निगम का मूल उद्देश्य विश्व बैंक के एक पूरक के रूप में उत्पादनशील निजी उद्यम के विकास को (विशेषकर अर्द्ध-विकसित देशों में) प्रोत्साहन देना है। निगम के चार्टर में धारा 1 में इसके इन उद्देश्यों का उल्लेख है।

1. निजी उद्योगों के विकास, सुधार और विस्तार को बढ़ावा देना तथा इसके लिए बिना सरकार की गारण्टी के सदस्य-देशों में स्थित निजी उद्योगों में विनियोग करना।

2. विनियोग के अवसरों, देशों और विदेशी निजी पूंजी तथा अनुभवों की व्यवस्थापन को परस्पर सम्बद्ध करना और उनमें समन्वय स्थापित करना।

3. सदस्य-राष्ट्रों में घरेलू और निजी विदेशी पूंजी को उत्पादनशील विनियोगों में प्रवाहित कर विकास में सहायक परिस्थितियों को उत्पन्न करना हो।

सारंश में निगम का उद्देश्य निजी उद्योगों के साथ मिलकर बिना सम्बन्धित

सरकार की गारण्टी के उनमें पूँजी का विनियोग करना है। यह केवल निजी क्षेत्र के उद्योगों में ही विनियोग कर सकता है, सरकारी योजनाओं और सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों में नहीं। भारत इस निगम का प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है और निगम की पूँजी में भारत ने जो गुगतान किया है उसके आधार पर भारत का निगम में चौथा स्थान है। निगम की सदस्यता केवल उन्हीं देशों को प्राप्त हो सकती है जो विश्व-बैंक के सदस्य हैं। सदस्यता ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। निगम के प्रबन्ध के लिए एक गवर्नर-मण्डल होता है। दिन-प्रतिदिन के कार्य-संचालन के लिए एक संचालक बोर्ड होता है। विश्व-बैंक का मध्यस्थ नियम के संचालक-बोर्ड का पदेन चेयरमैन होता है।

(ड) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक—ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना का भी निर्णय किया गया। यह संस्था, जिसे विश्व बैंक (World Bank) भी कहते हैं, मुद्रा कोष की एक पूरक संस्था के रूप में 27 दिसम्बर, 1945 को स्थापित हुई, किन्तु 25 जून, 1946 से इसने अपना कार्य प्रारम्भ किया। मुद्रा कोष और विश्व बैंक 'स्थायित्व एवं विकास' के उद्देश्यों पर आधारित हैं। मुद्रा कोष स्थायित्व पर अधिक बल देता है और विश्व बैंक 'विकास' पर। इसके मुख्य उद्देश्य हैं—सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास, व्यक्तिगत विदेशी विनियोगों को प्रोत्साहन, दीर्घकालीन सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, अधिक आवश्यक उत्पादन के कार्यों को प्राथमिकता, शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना। प्रत्येक राष्ट्र, जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, विश्व बैंक का भी स्वतः ही सदस्य बन जाता है। इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं की सदस्यता साथ-साथ चलती है और एक की सदस्यता त्याग देने पर दूसरे की सदस्यता भी सामान्यतः समाप्त हो जाती है। मुद्रा कोष की सदस्यता समाप्त हो जाने पर कोई देश विश्व बैंक का सदस्य तभी बना रह सकता है जब उसे बैंक के 75 प्रतिशत मतों का समर्थन प्राप्त हो। प्रारम्भ में बैंक की अधिकृत पूँजी 10,000 मिलियन डॉलर थी जिसमें समय-समय पर वृद्धि होती रही है। 31 दिसम्बर, 1970 से इसे 24 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 27 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। बैंक की पूँजी में अमेरिका का भाग (6,350 मिलियन डॉलर) सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे पर पश्चिमी जर्मनी, चौथे पर फ्रांस और पाँचवें पर भारत (900 मिलियन डॉलर) है।

विश्व बैंक का संगठन भी मुद्रा कोष के संगठन की भाँति है। बैंक के संगठन में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रशासनिक संचालन बोर्ड, सलाहकार समिति और ऋण समिति विशेष महत्वपूर्ण हैं। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—सदस्य-देशों को ऋण देना (अधिकारिता ऋण अल्पविकसित देशों में बिजली, उद्योग, परिवहन आदि के विकास के लिए ही दिए गए हैं); निजी विनियोजकों को गारण्टी देकर उनकी पूँजी अन्य देशों को दिलाना; सदस्य-देशों को तकनीकी सहायता और प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्श देना; सदस्य-देशों के अधिकारियों के लिए वित्त, मुद्रा-व्यवस्था, कर-प्रणाली,

औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संगठन आदि विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना; अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएँ सुलभाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना; आदि। उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब की नदियों के जल-विभाजन सम्बन्धी विवाद का निपटारा सन् 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से ही हुआ था। विश्व बैंक ने अब तक जो कार्य किए हैं उनसे संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित रखने के उद्देश्य में महायत्ना मिली है। बैंक के विकास-कृतियों की सहायता से भौंपडियो तक प्रकाश पहुँचा है, नए-नए कल-कारखानों का निर्माण हुआ है, सूखे क्षेत्रों को पानी मिला है यातायात और सन्देशवाहनों का प्रसार हुआ है तथा रेगिस्तान नखलिस्तान में परिणत हुए हैं।

संचार सम्बन्धी संगठन

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट संचार अभिकरणों में ये महत्वपूर्ण हैं—अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (I.C.A.O.), विश्व डाक संघ (W. P. U.), अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ (I. T. U.), विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन (W. M. O.), और अन्तर-सरकारी जहाजरानी परामर्श संगठन। अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रमुख उद्देश्य हैं—अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सम्बन्धी प्रतिमान और विनियम निश्चित करना, उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करना, अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन विधियों और समझौतों के प्रारूप तैयार करना, आदि। विश्व डाक संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं—सदस्य-देशों में डाक सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करना, डाक सम्बन्धी कठिनाइयों का निवारण करना, एक देश से दूसरे देश को डाक भेजने की दर आदि निश्चित करना। अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं—तार, टेलीफोन और रेडियो सम्बन्धी सेवाओं का प्रसार और विकास, सर्वसाधारण को कम से कम दर पर इनकी सेवाएँ सुलभ करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों आदि का निर्माण, दूर-संचार (टेली-कम्प्युनिकेशन) के व्यवहार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और प्राविधिक सुविधाओं में वृद्धि करना। विश्व ऋतु-विज्ञान संगठन के उद्देश्य हैं—ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी जाँच-पड़ताल अथवा ऋतु-विज्ञान के बारे में भूगर्भ सम्बन्धी जाँच-पड़ताल के लिए केन्द्र स्थापित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, ऋतु-विज्ञान सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्रों की स्थापना और उनका उचित संचालन करना, ऋतु-सम्बन्धी ज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान के लिए व्यवस्था करना, ऋतु-विज्ञान के बारे में खोज और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, आदि। अन्तर-सरकारी जहाजरानी परामर्श संगठन का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय जहाजरानी सेवाओं को सरल और गतिमान बनाना है। यह सागरों पर सुरक्षा और अन्य प्राविधिक मामलों के लिए सरकारों के बीच सहयोग की व्यवस्था करता है, सरकारों के अनावश्यक प्रतिबन्धों और भेद-भाव को दूर करने में सहायता करता है। यह संगठन जहाजरानी के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ के किसी अंग या विशेष अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मामलों पर विचार करता है।

सांस्कृतिक संगठन : यूनेस्को

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरणों में 'यूनेस्को' अर्थात् संयुक्तराष्ट्रीय

शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization—UNESCO) का अपना विशेष महत्व है। 4 नवम्बर, 1946 को इस संस्था का जन्म हुआ। इसके तीन प्रमुख भाग हैं—सामान्य सभा (General Conference), कार्यकारी मण्डल (Executive Board) एवं सचिवालय (Secretariat)। संयुक्त राष्ट्रसंघ के लगभग सभी सदस्य यूनेस्को के भी सदस्य हैं। यूनेस्को का लक्ष्य शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देकर शांति और सुरक्षा में योगदान करना है। यह संस्था बिना किसी भेद-भाव के चार्टर में निहित मानव-अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं को क्रियाशील बनाने में सहायक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसंघ के विशिष्ट अभिकरणों में सबसे अधिक सफलता यूनेस्को को ही प्राप्त हुई है। यूनेस्को के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

1. यूनेस्को का प्रथम कार्य है शिक्षा। इसमें तीन बातें सम्मिलित हैं—शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति और शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इस कार्यक्रम में साक्षरता के प्रसार और आधारभूत शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। मौलिक शिक्षा का अभिप्राय सामुदायिक विकास की उस शिक्षा से है जो जन-साधारण को उनके स्वास्थ्य, भोजन, फसलों और जीवन-स्तर को सुधारने के लिए दी जाती है। यूनेस्को ने जन-शिक्षा (Mass Education) पर बहुत बल दिया है। इसका यह एक पवित्र ध्येय है कि सभी लोगों के लिए नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसीलिए यह संस्था विभिन्न देशों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष योजनाओं को सहायता देती है।

2. यूनेस्को का कार्य है विज्ञान का विकास। इसने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान पर बहुत ध्यान दिया है। यूनेस्को ने क्षेत्रीय-विज्ञान-सहयोग केन्द्र स्थापित किए हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य है रेगिस्तानी प्रदेशों को उपजाऊ बनाने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के कार्यों में सामञ्जस्य लाना। प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में यह संस्था वैज्ञानिकों के सभा-सम्मेलनों का आयोजन करती है, वैज्ञानिक संगठनों को सहायता देती है और अनुसन्धान, प्रकाशन तथा वैज्ञानिक शिक्षा का कार्य करती है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसके मुख्य कार्य हैं—अन्तर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण और महाशता, विचार-गोष्ठियों का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय तनावों सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन, आदि। यूनेस्को ने विभिन्न भाषाओं में जातिवाद के विरुद्ध साहित्य प्रकाशित कराया है जिससे यह सिद्ध हो गया है कि एक जाति को दूसरी जाति से उच्च मानने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

3. यूनेस्को का तीसरा कार्य संस्कृति सम्बन्धी है। यह संस्था मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है। उदाहरणार्थ, जब आस्वान बांध के निर्माण के फलस्वरूप नूबिया के प्राचीन स्मारकों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया था तो उनकी रक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था। भारत, कोलम्बिया, नाइजीरिया आदि में सांस्कृतिक

पुस्तकालय खोलने की योजनाओं में यूनेस्को का भारी योगदान रहा है। इनमें सबसे प्राचीन दिल्ली का सार्वजनिक पुस्तकालय है। यूनेस्को ने मानव जाति का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रकाशित किया है। यह सामूहिक ज्ञान के प्रचार के लिए प्रयत्नशील है। फ़िल्म, प्रेस, रेडियो आदि के द्वारा इस कार्यक्रम की पूर्ति की जाती है। यूनेस्को के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसन्धान, सभा-सम्मेलनों और विचार गोष्ठियों के आयोजन होते हैं। यह विविध प्रकार का साहित्य भी प्रकाशित करता है।

4. यूनेस्को का चौथा कार्य है व्यक्ति-व्यक्तिमय और जन-सम्पर्क। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इस तरह विश्व के दूरस्थ देशों के वैज्ञानिकों और विद्वानों का पारस्परिक सम्पर्क हो जाता है। यूनेस्को ने जन-सम्पर्क के साधनों—प्रेस, रेडियो, फ़िल्म, टेलीविजन आदि के विस्तार के लिए काफी प्रयत्न किए हैं।

5 यूनेस्को और भी अनेक कार्य करता है। यह विभिन्न देशों के शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता पहुँचाता है। इस कार्य के लिए यह विश्व के देशों की जन-कल्याणकारी सत्ताओं से धन-संग्रह करता है। अपने विशेषज्ञों द्वारा यह सगठन विभिन्न देशों को उपयुक्त परामर्शों द्वारा लाभ पहुँचाता है। सितम्बर, 1952 में स्वीडन की गई 'यूनिवर्सल कापीराइट कन्वेंशन' यूनेस्को की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। इस सम्मति द्वारा यूनेस्को ने लेखकों और कलाकारों के हितों के संरक्षण में विशेष योग दिया है।

यूनेस्को ने अपने उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सगठनों घषवा सत्ताओं की स्थापना की है जिनमें से मुख्य हैं—अन्तर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान (International Theatre Institute), अन्तर्राष्ट्रीय संगीत परिषद् (International Music Council), दर्शन और मानवतावादी अध्ययन की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् (International Council of Philosophy & Humanistic Studies), अन्तर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय सघ (International Sociological Association), अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान सघ (International Political Science Association), एव तुलनात्मक विधि की अन्तर्राष्ट्रीय समिति (International Committee of Comparative Law)।

यूनेस्को विश्व में शान्ति की स्थापना और मानवतावाद के निर्माण में वास्तव में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह सत्ता प्राधुनिक पीढ़ी के लिए गौरवपूर्ण है, किन्तु यह आवश्यक है कि एशिया और अफ्रीका की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और सांस्कृतिक निधियों पर यह सत्ता विशेष ध्यान दे।

स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सगठन

संयुक्त राष्ट्रसंघ से सम्बद्ध स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सगठनों में विशेष महत्त्वपूर्ण ये हैं—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय अगुशक्ति एजेंसी—इसकी स्थापना 29 जुलाई, 1956 को हुई। संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ इसके कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव महासभा द्वारा नवम्बर, 1956

मे और एजेंसी की जनरल कान्फ्रेंस द्वारा अक्टूबर, 1957 में स्वीकार किया गया। इस अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी (International Atomic Agency) के मुख्य उद्देश्य हैं—विश्व की शान्ति-व्यवस्था और सम्पन्नता में अणुशक्ति के योगदान को बढ़ावा देना, अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग को हर प्रकार से प्रोत्साहन देना तथा यह देखना कि उसके द्वारा दी जाने वाली सहायता का अनैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन—7 अप्रैल, 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (W. H. O.) की स्थापना हुई, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल विश्व भर में 'स्वास्थ्य दिवस' के रूप में मनाया जाता है। इस संगठन की सदस्यता सभी राष्ट्रों के लिए खुली है। इसके प्रमुख अंग हैं—सभा (Assembly), कार्यकारी बोर्ड (Executive Board), एवं सचिवालय (Secretariat)। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत स्थापित इस संगठन का उद्देश्य ससार को रोगों से मुक्त कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन अनेक कार्य करता है जैसे—(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों का मंचालन, (2) महामारियों और रोगों के उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, (3) स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसन्धान, (4) बीमारियों के अन्तर्राष्ट्रीय नामों के निदान सम्बन्धी कार्यों में एकरूपता की स्थापना, (5) प्राकृतिक छोटी को रोकने का प्रबन्ध, (6) मानसिक स्वास्थ्य-मुधार को प्रोत्साहन, (7) आहार, पोषण, स्वच्छता, (8) निवास और काम करने की दशाओं में सुधार, (9) स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र में प्रशामनिक और सामाजिक विधियों का अध्ययन, आदि। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीके लगाने और औषधियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। संगठन विश्व भर के राष्ट्रों को हैजा, चेचक आदि सक्षामक रोगों की सूचना देता है। इस प्रकार की सूचनाएँ संगठन की ओर से प्रायः रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती हैं। रोगों के प्रसार को रोकने के कार्य में सभी सरकारें सहयोग देती हैं। संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों से इन्फ्लूएन्जा, पोलियो, मेलिटिस आदि रोगों पर विशेष शोध-कार्य कराया जा रहा है। संगठन तकनीकी बुलेटिन और अन्य साहित्य प्रकाशित कर ससार भर के देशों को वितरित करना है। यह संगठन अणु-शक्ति के उपयोग के स्वास्थ्यजनक पहलुओं से भी निकट सम्पर्क रखता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात्कालीन कोष—बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए महासभा द्वारा 11 सितम्बर, 1946 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात् कोष (U. N. International Children Emergency Fund) की स्थापना की गई। यह तथा आर्थिक और सामाजिक परिपक्व की देखरेख में काम करती है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं—ससार भर के (विशेषकर अशुभिन देशों के) बच्चों की हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना; भूकम्प, बाढ़ आदि के समय प्रसूतिनाथों और शिशुओं की सहायता करना; प्रसूति-ग्रहों और शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना करना, शिशु-आहार की व्यवस्था करना आदि। इस बालकोष की

सहायता से भारत के विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों में 100 से भी अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें घातु-विद्या (नर्सिंग) की शिक्षा दी जाती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था का अभिप्राय उनके स्थायी अंगों, विशिष्ट अभिकरणों, सम्मेलनों और कोषों से है जिनका विवेचन किया जा चुका है। स्टीवेन रोजन एवं वाल्टर जोस ने संयुक्त राष्ट्रमधीय व्यवस्था को इस प्रकार दर्शाया है—

संयुक्त राष्ट्रसंघ की व्यवस्था एक नजर में
(United Nations System at a Glance)

स्थायी अंग ¹ (Permanent Organs)	विशिष्ट अभिकरण ² (Specialised Agencies)	सम्मेलन और कोष ³ (Conferences and Funds)
1. महासभा	1. विश्व स्वास्थ्य सगठन	1. व्यापार एवं विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
2. सुरक्षा परिषद्	2. खाद्य एवं कृषि सगठन	2. बाल-कोष
3. न्यास परिषद्	3. अन्तर-मरकारी जहाजरानी परामर्श सगठन	3. संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट कोष
4. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्	4. अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ	4. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष
5. सचिवालय	5. विश्व डाक संघ	5. पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक
6. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय	6. अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ	
	7. विश्व ऋतु-विज्ञान सगठन	
	8. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन	
	9. संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सगठन (यूनेस्को)	
	10. अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति आयोग	

1. Permanent Organs : General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, Economic and Social Council, Secretariat, International Court of Justice
2. Specialised Agencies : World Health Organization, Food and Agricultural Organization, Intergovernmental Maritime Consultative Organization, International Civil Aviation Organization, Universal Postal Union, International Telecommunications Union, World Meteorological Organization, International Labour Organization, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), International Atomic Energy Commission
3. Conferences and Funds : United Nations Conference on Trade and Development, Children's Fund, United Nations Special Fund, International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development.

संयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन

सफलताएँ—संयुक्त राष्ट्रसंघ के अव्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ राजनीतिक और गैर-राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में संघ की उपलब्धियाँ महान् रही हैं वहाँ संघ को कुछ गम्भीर असफलताएँ भी सहनी पड़ी हैं। संघ ने अनेक राजनीतिक विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाया है। कई अवसरों पर इसमें युद्ध के विस्तार को प्रभावशाली ढंग से रोका है। ऐसे भी अवसर आए हैं जब इसने विवादों की उग्रता को कम कर पारस्परिक वार्ता का वातावरण पैदा किया है। संघ की इन सफलताओं को देख कर ही हमें पण्डित नेहरू के ये शब्द आज भी स्मरण हो आते हैं कि—“संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कई बार विश्व में बार-बार उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है, अतः इसके बिना हम प्राधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते।” संघ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोकने में वस्तुतः एक सुरक्षा आवरण (Safety Valve) का काम करता रहा है। डॉ. राल्फ बुचे के शब्दों में संघ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि “वह राष्ट्रों को बातचीत करने में व्यस्त रखता है। वे जितनी देर तक बातचीत करें उतना ही अधिक अच्छा है क्योंकि उतने समय तक युद्ध की सम्भावनाएँ टली रहती हैं।”

संयुक्त राष्ट्रसंघ को उपनिवेशवाद के उन्मूलन में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इण्डोनेशिया, मोरक्को ट्यूनिशिया, अल्जीरिया आदि की स्वतन्त्र कराने में संघ के प्रयत्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। संघ की सुरक्षण व्यवस्था ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में वृद्धि की है और विश्व के अनेक प्रदेशों के निवासियों में स्वशासन की योग्यता विकसित करने में सहायता पहुँचाई है। कुछ वर्ष पूर्व संघ की न्यास पद्धति के अन्तर्गत 11 देश थे जो अब स्वतन्त्र राज्यों के रूप में विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित हैं। संघ अफ्रीका में बचे हुए साम्राज्यवादी उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के लिए सतत् प्रयत्नशील रहा है।

गैर-राजनीतिक कार्यों में संघ की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण और सकल रही है। इसकी विभिन्न संस्थाओं से विश्व के विभिन्न राष्ट्रों और समाजों को भारी लाभ पहुँचा है। श्रम संगठन ने श्रमिकों की दशा को उन्नत करने और खाद्य तथा कृषि संगठन ने अन्न का उत्पादन बढ़ाकर भूकाल को नियन्त्रित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बीमारियों के प्रतिरोध में और यूनेस्को ने मानव के सांस्कृतिक विकास में बहुत सहायता पहुँचाई है। संघ के गैर-राजनीतिक कार्यों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक राज्याध्यक्ष के ये शब्द निश्चय ही सही हैं कि—“संयुक्त राष्ट्रसंघ में निःशस्त्रीकरण और राजनीतिक कार्यों का खरगोश तो अभी भपकी ही ले रही है जबकि उसकी विशेष संस्थाओं की तकनीकी सहायता और सहयोग का कलुषा अपनी धीमी चाल से बहुत धीरे बढ़ गया है।” विश्व में मुद्रा मन्त्रियों प्रस्थिरता एवं अभाव तथा ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक, अन्य कच्चे माल और औद्योगिक वस्तुओं के ऊँचे मूल्यों के कारण विशेष रूप से विकासशील देशों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के समाधान के लिए तन् 1975 में संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों से निरन्तर सन्धि प्रयास होते रहे हैं। सितम्बर, 1975 के पहले पखवारे में सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र महासभा का सातवाँ विशेष अधिवेशन एक ही वर्ष में होने वाला दूसरा विशेष अधिवेशन था जो एकमात्र विकास एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की समस्याओं के निमित्त सम्पन्न हुआ था।

असफलताएँ — सफलताओं के साथ असफलताओं का सम्बन्ध रहना स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्रसंघ बहुत से महत्वपूर्ण विवादों को सुलझाने में असफल रहा है। जिन विवादों में महाशक्तियों के हित टकराते रहे हैं उनको सुलझाने में इसकी असफलता एक दुखभरी कहानी है। कुछ विवादों में इस विश्व-संस्था का रवैया बहुत ही पक्षपातपूर्ण और न्याय को ठेस पहुँचाने वाला रहा है, जैसा कि कश्मीर विवाद और बंगलादेश में (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान पर) पाक-दमन के सन्दर्भ में। निःशस्त्रीकरण की दिशा में भी संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से कोई ठोस प्रगति नहीं हो पायी है। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद से ही जर्मनी के साथ शान्ति-सन्धि और उसके एकीकरण का प्रश्न, पश्चिमी एशिया में तनाव दूर करने की समस्या, कोरिया के एकीकरण का प्रश्न आदि विश्व-शान्ति के लिए खतरे के सकेत के रूप में रहे हैं। उनके समाधान में संघ कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। संघ को इस महत्वपूर्ण उद्देश्य में भी निराशा ही हाथ लगी है कि वह विश्व के राष्ट्रों में परस्पर विश्वास का वातावरण विकसित कर युद्ध की सम्भावना को समाप्त करदे। पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को दूर करने में संघ को ठोस रूप से कुछ भी सफलता हाथ नहीं लगी है। प्रवश्य ही संघ एक ऐसे राजनीतिक रंगमंच की भूमिका तो निभा रहा है जहाँ विरोधी राष्ट्र बैठकर समस्याओं पर वाद-विवाद कर सकें। बातचीत के ऐसे माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी मात्रा में परस्पर सहयोगी रुख पनपता है। संघ में राष्ट्रों के बीच जो टकराव होता है और जिस रूप में बड़े राष्ट्र अपने दाव-पेचों से संघ के वातावरण को विपात बनाते हैं, उसे देखकर ही कुछ वर्ष पूर्व संघ के भूतपूर्व महासचिव ऊयाँट ने कहा था कि—“संघ अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में बहुत कम प्रगति कर पाया है और इसका मुख्य कारण यह है कि वह महाशक्तियों का सहयोग-स्थल बनने के बजाय उनके परस्पर विरोधी स्वार्थों में संघर्ष का अखाड़ा बन गया है।”

कुल मिलाकर संघ की सफलताओं और गौरव का पलड़ा भारी है। संघ विश्व-जनमत का प्रतिनिधि है, अतः नैतिक दबाव का शक्तिशाली साधन है और आक्रामक देशों के पड़वन्धों का पर्दाफाश करने का उपयुक्त स्थान है। अपनी कमजोरियों के बावजूद संघ विश्व में विभिन्नताओं में एकता का सुन्दर प्रतीक है। अपने कार्यों के कारण वह विश्व-शान्ति और समृद्धि के लिए एक अनिवार्य संगठन बन चुका है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की समाप्ति या असफलता का अर्थ होगा—महाविनाश की परिस्थितियों का मूलपात।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की समस्याएँ और दुर्बलताएँ

संयुक्त राष्ट्रसंघ की अनेक सांविधानिक, संवैधानिक और व्यावहारिक दुर्बलताएँ

हैं। इन दुर्बलताओं ने इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की शक्ति पर बुरा प्रभाव डाला है और यह महान् संस्था आशाओं के अनुरूप सफल सिद्ध नहीं हुई है। अतः यह देखना उचित होगा कि संघ किन विशिष्ट समस्याओं और दुर्बलताओं का शिकार है और उन्हें दूर करके किस प्रकार इसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है। हमें इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना होगा कि यह संस्था विश्व के राष्ट्रों का ऐच्छिक संगठन है, यह उनके सहयोग का साधन है और इसकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर है कि सदस्य-राष्ट्र इसे कहां तक सहयोग देते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ की असफलताओं के मूल में असली बात यह भी है कि इसके इजन् की बनावट भी कुछ दोषपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक इजीनियरों में इस इजन् को चलाने की इच्छा और कौशल अधिक दोषपूर्ण है। इजन् की बनावट के दोषों को दूर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इजन् का प्रभावशाली ढंग उपयोग तभी सम्भव है जब इंजीनियर भी उसे अच्छी तरह चलाने के इच्छुक हो और इजन् की कुशलता में प्रतिक्षण वृद्धि देखना चाहते हों।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जिन समस्याओं और दुर्बलताओं का शिकार रहा है और है, वे निम्नानुसार हैं—

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ लम्बे समय तक सार्वदेशिक संगठन नहीं बन सका क्योंकि 80 करोड़ जनसंख्या वाला साम्यवादी चीन 26 अक्टूबर, 1971 से पहले इसका सदस्य नहीं बन पाया। दोनो जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी) भी 19 सितम्बर 1973 को संघ के सदस्य बन पाए। चीन और दोनो जर्मनी तथा विपतनाम के प्रवेश से संयुक्त राष्ट्रसंघ यथार्थ रूप में हाल ही में एक सार्वभौमिक या विश्वव्यापी संगठन बन सका है। चूंकि लम्बे समय तक संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन, जर्मनी आदि राष्ट्रों को प्रवेश नहीं मिला, अतः विश्व-शान्ति और सुरक्षा कायम रखने में संघ के प्रयत्न उतने प्रभावकारी नहीं हो सके जितने होने चाहिए थे। कारण भी स्पष्ट है कि संघ से बाहर रहने वाले देशों की मनोवृत्ति स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति कायम रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त रखने की होती है। इस बात का संघ की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

2. संघ सिद्धान्तिक विरोधाभास का शिकार है। एक ओर राज्यों के समानाधिकार और समान प्रभुता की बात कही गई है तो अनेक स्थलों पर चार्टर में राज्यों की सम्प्रभु-प्रममानता के सह-प्रस्तित्व का प्रतिपादन है। उदाहरणार्थ सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यों की स्थिति प्रसामान्य रूप से विशेषाधिकार-सम्पन्न है। चार्टर में लक्ष्यों और सिद्धान्तों के गीत गाए गए हैं, पर कहीं भी न्याय, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान, राष्ट्रीय आत्म निर्णय जैसे सिद्धान्तों की व्याख्या नहीं की गई है।

3. घरेलू क्षेत्राधिकार की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है और यह भी उल्लेख नहीं है कि 'घरेलू क्षेत्र' का निश्चय कौन करेगा। इस बारे में महासभा के निर्णय वस्तुस्थिति के आधार पर न होकर प्रायः गुटबन्दी के आधार पर होते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में 'घरेलू क्षेत्राधिकार' और हस्तक्षेप की विशिष्ट धारणा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ में यह विशुद्ध राजनीतिक विषय बना हुआ है।

4. संयुक्त राष्ट्रसंघ 'यथास्थिति सम्बन्धी अस्पष्टता' के कारण भी कुछ कम प्रभावशाली रहा है। वास्तव में जर्मनी, कोरिया, पूर्वी यूरोप, वियतनाम आदि सभी प्रस्थापित व्यवस्थाओं के परिणाम हैं और यथास्थिति कायम रखने के बारे में संघ के सदस्यों में बहुत अस्पष्टता है जिसके फलस्वरूप प्रभावशाली और निश्चित कार्यवाही करने की दृष्टि से संघ प्रायः अस्थिर रहा है।

5. संघ के बाद-विवाद और निर्णय अधिकांशतः पक्षपातपूर्ण अथवा महा-शक्तियों के अपने हितों से प्रभावित रहे हैं। अधिकांश समस्याएँ शक्ति-राजनीति द्वारा तय की जाती हैं। पश्चिमी गुट के बहुमत को विफल करने के लिए इस अपने निषेधाधिकार का व्यापक प्रयोग करता है। स्वयं महासचिव यह स्वीकार करते रहे हैं कि गुटबन्दी और बड़े राष्ट्रों के संघर्ष ने विश्व-संस्था को पंगु बना दिया है।

6. संघ निषेधाधिकार के दुरुपयोग का मंच बना हुआ है। स्थायी सदस्य किसी भी उचित किन्तु अपने विरोधी दावे को विशेषाधिकार के प्रयोग से ग्रमान्य ठहरा देते हैं। यह विचित्र स्थिति है कि कोई एक महाशक्ति शेष सदस्यों की इच्छाओं को निरस्त कर दे, यहाँ तक कि महासभा की इच्छा को भी विफल कर दे। पर यह भी स्वीकार करना होगा कि कुछ मामलों में इस निषेधाधिकार की व्यवस्था से ही न्याय की रक्षा हो सकी है, जैसे कश्मीर तथा भारत-पाक संघर्षों के मामले में।

7. महासभा विश्व-जनमन का प्रतिनिधित्व करते हुए भी उसके निर्णय का प्रतिनिधित्व नहीं करती। वस्तुतः 'शान्ति के लिए एकता का प्रस्ताव' पारित किए जाने के बाद भी व्यवहार में महासभा आज भी अपनी उपयोगिता में बहुत कुछ क्षा परिपद् पर ग्रथित है। यदि महासभा किसी कार्य की सिफारिश दो-तिहाई बहुमत से भी करे तो परिपद् उसे अपने विवेक के आधार पर अस्वीकार कर सकती है। यह एक गम्भीर सांविधानिक विरूपता है कि एक ही समय संघ के दो अग्र-भिन्न-भिन्न राय प्रकट कर सकते हैं। शक्ति-वितरण में महाशक्तियों की मनमानी को कायम रखने की व्यवस्था के फलस्वरूप संघ में सुरक्षा परिपद् द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय सन्कार' की स्थिति बनी हुई है।

8. संघ के पास अपने निर्णयों को लागू कराने की स्वयं की शक्ति नहीं है। उसके पास 'काटने के दाँत' नहीं हैं। अपनी निजी सेना न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने पर वह सदस्य-राष्ट्रों की सैनिक सहायता पर निर्भर रहता है। यह सदस्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वह सैनिक सहायता दें या न दें।

9. संघ के निर्णयों का महत्त्व सिफारिशों से अधिक नहीं है। सदस्य-राज्यों को छूट है कि वे उन्हें स्वीकार करें या न करें। एक बड़ी दुर्बलता यह है कि महासचिव की शक्तियों का अभी तक समुचित रूप से निश्चय नहीं किया जा सका है, अतः परिपद् द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही करना कई बार महासचिव के लिए कठिन हो जाता है।

10. चार्टर में अभी कुछ ही समय पूर्व तक आत्मरक्षा और आक्रमण के बीच

भेद स्पष्ट नहीं किया गया था : यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था कि किसी देश द्वारा किए जाने वाले किम प्रकार के कार्य आक्रमण माने जाएंगे। चार्टर के अनुसार आक्रमण का अर्थ 'शक्ति का भ्रवैधानिक प्रयोग' है, किन्तु 'शक्ति का भ्रवैधानिक प्रयोग' क्या है, यह प्रश्न विवादास्पद बना रहा है। सीभाग्यवश अब लगभग 31 वर्षों के परिश्रम के बाद 15 दिसम्बर, 1974 को लगभग 350 शब्दों में 'आक्रमण' की परिभाषा कर दी गई है।¹

11. महासभा की कार्यविधि भी दोषपूर्ण है। सभा के सम्मुख विचारणीय

1. "आक्रमण की परिभाषा के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि आक्रमण एक देश द्वारा दूसरे देश की प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता या राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध सशस्त्र-सेना या किसी अन्य तरीके का प्रयोग है जो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र के अनुरूप नहीं है।

दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र का उल्लंघन कर एक देश द्वारा दूसरे देश पर पहले सशस्त्र सेना का प्रयोग आक्रमण की कार्यवाही का प्रारम्भिक प्रमाण होगा, यद्यपि सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के अनुरूप यह निश्चित कर सकती है कि आक्रमण हुआ है।

तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है कि युद्ध की घोषणा किए बिना भी एक देश द्वारा दूसरे देश पर सशस्त्र आक्रमण, दूसरे देश की भूमि पर कब्जा करना चाहे यह अस्थायी हो क्यों न हो, बमबारी, बन्दरगाहों तटों की नौबन्दी भी आक्रमण है। एक देश की सशस्त्र सेना द्वारा दूसरे देश की भूमि, मनुष्य, वायु सेना, नौसेना और विमानों के बंदे पर धाका बोलना भी आक्रमण है। समझौते की अवधि के बाद दूसरे देश की भूमि पर जमे रहना भी आक्रमण कहलाता है। अपनी भूमि का किसी तीसरे देश के विरुद्ध प्रयोग करने की अनुमति देना या किसी दूसरे देश की ओर से किसी अन्य देश पर सशस्त्र कार्यवाही के लिए सशस्त्र व्यक्ति व भाड़े के सैनिक भेजना भी आक्रमण है।

चौथे अनुच्छेद के अनुसार सुरक्षा परिषद् भी यह तय कर सकती है कि घोषणा-पत्र के अन्तर्गत किन-किन कार्यवाहियों को आक्रमण की सूझा दी जा सकती है।

पाँचवें अनुच्छेद के अन्तर्गत आक्रमण आक्रमण ही होगा। इसमें इन बात पर कोई विचार नहीं होगा कि राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कारणों से दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

आक्रमण युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के प्रति एक अपराध है। आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व बढ़ जाता है।

आक्रमण के परिणामस्वरूप प्राप्त क्षेत्र या कोई अन्य सुविधा बानूनी नहीं मानी जाएगी।

छठे अनुच्छेद में कहा गया है कि इन परिभाषा का अर्थ यह नहीं होगा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र में वृद्धि या कमी की जा सकती है।

सातवें अनुच्छेद में आत्म-निर्णय, स्वाधीनता और स्वतन्त्रता के अधिकार के लिए युद्ध आक्रमण की परिभाषा में नहीं आएगा।

आठवें अनुच्छेद में उल्लेख है कि आक्रमण की परिभाषा सम्बन्धी आठों अनुच्छेद एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।"

विधियों की सख्या पहले ही बहुत अधिक रहती है और इस पर भी लम्बे-लम्बे भाषणों द्वारा सभा का अधिकांश समय नष्ट कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त समितियों में एक बार प्रस्तुत प्रस्तावों को भी कभी-कभी पुनः सभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस पुनरावृत्ति से लाभ कम होता है, समय की हानि अधिक होती है।

12 महासभा के अधिवेशनों में राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिज्ञ उपस्थित रहने की परवाह नहीं करते और साधारण प्रतिनिधियों के उपस्थित रहने से सभा की कार्यवाही अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाती।

13 सभ के बाहर की गई सैनिक सन्धियों के कारण भी इसका महत्त्व कुछ कम हो गया है। क्विंसीराइट के अनुसार, “क्षेत्रीय सुरक्षा गुटों के अनियन्त्रित विकास के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती।”

14. यह भी विडम्बना है कि सदस्यगण महासभा और सुरक्षा परिषद् को प्रचार-संस्था के रूप में प्रयोग करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक हथकण्डों द्वारा विश्व-जनमत को अनुचित रूप से अपने पक्ष में तैयार करना होता है। नार्मन बंटविच और अड्रूय मार्टिन के इन शब्दों में वजन है कि “महासभा और सुरक्षा परिषद् का प्रयोग विवादों को सुलझाने के लिए नहीं, अपितु उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है।”

सभ को शक्तिशाली बनाने के सुझाव (Suggestions to Strengthen the U. N. O.)

नवीन और परिवर्तित परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि प्रथम तो संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में आवश्यक संशोधन किया जाए और द्वितीय, इस प्रकार के विभिन्न उपाय किए जाएं जिनसे यह विश्व-संस्था अधिक शक्तिशाली बन सके। पहले उन सुझावों का उल्लेख किया जाएगा जो चार्टर में संशोधन के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं और तत्पश्चात् अन्य सुझावों का।

(क) चार्टर में संशोधन अथवा पुनर्निरीक्षण—महाशक्तियों के बीच पारस्परिक सहमति न होने से चार्टर में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं हो सका है। यह आशंका की जाती है कि संशोधन से वर्तमान-शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाएगा और संशोधन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मतभेद प्रखर रूप से उभर आएंगे। तथापि समय-समय पर संशोधन सम्बन्धी अनेक सुझाव दिए जाते रहे हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं—

1. महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तन किया जाना चाहिए। एक देश के 5 सदस्य और एक वोट के स्थान पर सदस्य तथा वोट जनसंख्या के अनुपात से होने चाहिए ताकि महासभा के निर्णय अधिकतम जनसंख्या के हितों के आधार पर हो।

2. सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद् की सिफारिश की शर्तें हटा देनी चाहिए अथवा उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से नए सदस्यों को

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान करे। केवल महासभा को इस प्रकार सदस्यता प्रदान करने का अधिकार दिए जाने से सदस्यता के प्रश्न पर राजनीतिक सीदेबाजी की वर्तमान कटु स्थिति समाप्त हो जाएगी।

4. सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों का प्रावधान हटा देना चाहिए ताकि शक्ति-सन्तुलन परिषदीय शक्तियों के पक्ष में न रहे। परिषद् को सन्तुलित और निष्पक्ष बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के भारत जैसे महत्त्वपूर्ण सदस्यों को भी इसमें समान आधार पर स्थान प्राप्त हो। यदि स्थायी सदस्यता कायम रखने का ही निश्चय हो तो उनकी सदस्य-संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

5. 'घरेलू क्षेत्र' की व्यवस्था में समुचित सन्तुलन किया जाना चाहिए। यह सुझाव भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में जो बातें घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं उनका सहिताकरण कर दिया जाए तथा उनके अतिरिक्त जो विषय शेष रहे उन पर शान्ति एवं सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रसंघ जो कार्यवाही उचित समझे स्वतन्त्रपूर्वक करे।

6. यह सुझाव दिया जाता है कि महासभा को द्वि-सदनात्मक रूप दिया जाए एक 'मानवता का सदन हो' और दूसरा 'राष्ट्रीय सदन'। मानवता-सदन का संगठन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में हो तथा राष्ट्रीय सदन का गठन राज्यों की समानता के आधार पर हो और उसमें प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र को प्रतिनिधित्व दिया जाए। सभी साधारण विषयों का निर्णय दोनों सदनों द्वारा किया जाए, लेकिन मनभेद की स्थिति में वह निर्णय उस रूप में मान्य समझा जाए जिस रूप में मानवता-सदन पुनः तीन-चौथाई मतों से पारित करदे। साथ ही शान्ति और सुरक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णय मानवता-सदन द्वारा लिया जाए। इस बात के निर्णय का दायित्व कि कौन-से विषय महत्त्वपूर्ण हैं, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपा जाए।

7. सुरक्षा परिषद् की बैठकें हमेशा न होकर कुछ निश्चित अवधियों में ही हो ताकि सम्बन्धित देशों के प्रधान मन्त्री या विदेश मन्त्री उसमें भाग ले सकें। यह सुझाव विशेष स्वागत योग्य नहीं है क्योंकि सुरक्षा परिषद् यदि एक सतत कार्यशील अंग न रहा तो शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होने पर अथवा अन्य किसी महत्त्वपूर्ण मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की वर्तमान में जो कुछ भी क्षमता है उसे आघात पहुँचेगा।

8. अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद् में मतदान की व्यवस्था में 'प्रक्रिया सम्बन्धी विषय' तथा 'अन्य सभी विषय' शब्द इतने अनिश्चित और अस्पष्ट हैं कि इससे निषेधाधिकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अतः यह उपयुक्त है कि इन शब्दों को अधिक स्पष्ट किया जाए।

9. प्रादेशिक संगठन सम्बन्धी धाराओं में ऐसा संशोधन होना चाहिए जिससे सैनिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन न मिल सके।

10. शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी

निर्णय राष्ट्रों पर बाध्यकारी माने जाएँ, किन्तु यह भी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए कि निर्णय राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हो।

(ख) अन्य सुझाव—जो अन्य सुझाव समय-समय पर दिए गए हैं उनमें से ये उल्लेखनीय हैं—

1. सदस्य-राज्य अधिक स्वामिभक्ति और कल्पनात्मक रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करें। विशेषकर महाशक्तियाँ संधि के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रहे और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सैद्धान्तिक शिथिलता न दिखाएँ।

2. महासभा, सुरक्षा परिषद् तथा अन्य अगों का प्रचार-संस्था के रूप में उपयोग न किया जाए। इस सम्बन्ध में एक तो सदस्य-राज्य स्वयं पर नियन्त्रण रखें और दूसरे आवश्यक सांविधानिक व्यवस्थाएँ करने का भी प्रयास किया जाए।

3. महासभा के अधिवेशन अल्पकालीन हो जिनमें सदस्य-राष्ट्रों के प्रधानमंत्री अथवा विदेश मंत्री सम्मिलित हो। मन्त्रि-मण्डलीय स्तर के प्रतिनिधि अपने-अपने देशों की नीति निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अतः वे महासभा की कार्यवाही को अधिक प्रभावशाली और निर्णयकारी बनाने में सक्षम हो सकते हैं।

4. चार्टर की व्याख्या करने समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। सुरक्षा परिषद् की शक्तियों के मूल्य पर यदि महासभा, जो विश्व जनमत की प्रतिनिधि है, कोई कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले, तो इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य लक्ष्य तो समस्या का समाधान करना है न कि वैधानिक अवरोध उत्पन्न कर समस्या को उलझाना।

5. संधि के वर्तमान यन्त्र को विस्तृत बना देना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार नवीन संस्थाओं का निर्माण किया जा सके।

6. जो क्षेत्र राष्ट्रीय सम्प्रभुता के अधीन नहीं हैं वहाँ पर प्रशामकीय सत्ता स्थापित हो जानी चाहिए, जैसे बाह्य अन्तरिक्ष।

7. संधि की आय का कोई स्वतन्त्र स्रोत होना चाहिए। उचित होगा कि वह विकास-कर, सेवा-कर, यात्री-कर आदि लगाए और विश्व-बैंक की आय तथा बाह्य अन्तरिक्ष शुल्क आदि द्वारा अपनी आय में वृद्धि करे।

१. राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ की तुलना

संयुक्त राष्ट्रसंघ को राष्ट्रसंघ का एक अगला कदम (One Step Further to League of Nations) कहा जाता है। अतः देखना चाहिए कि दोनों विश्व-संस्थाओं में क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का संगठन राष्ट्रसंघ की तुलना में कितना श्रेष्ठ है।

समानताएँ

1. दोनों ही संस्थाओं का जन्म महायुद्धों के फलस्वरूप हुआ। दोनों ही को उत्तराधिकार में युद्ध-व्यस्त विश्व की जटिल राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ प्राप्त हुईं।

2. दोनों ही संस्थाओं की स्थापना सम्प्रभु राष्ट्रों के ऐच्छिक संगठनों के रूप में हुई। दूसरे शब्दों में ही संस्थाओं ने सदस्य-राज्यों की सम्प्रभुता का आदर करना स्वीकार किया। दोनों ही ने सिद्धान्त रूप में प्रत्येक देश के मत को बराबर का महत्त्व देने की बात को मान्यता दी।

3. मूल रूप से दोनों ही संस्थाओं की स्थापना के समय विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों को सघ में स्थान दिया। जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो सदस्यों की संख्या विजेता राष्ट्रों तक ही सीमित रखी गई और संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय 51 राष्ट्रों तक।

4. राष्ट्रसंघ के ढाँचे में ही कुछ सुधार कर संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अपना लिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा, सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय राष्ट्रसंघ की असेम्बली, परिषद्, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय के प्रतिरूप हैं। गैर-राजनीतिक कार्यों के सम्बन्ध में भी राष्ट्रसंघ की भाँति संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न सहायक अंग भी विश्व की गरीबी, बीमारी, भुखमरी, अशिक्षा, अज्ञान आदि से मुक्ति दिलाना और राष्ट्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक विकास करना चाहते हैं। दोनों ही संगठनों में परिषद् के अध्यक्ष पद को परामर्शा के क्रम से रखने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रसंघ की तरह संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी विवादों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय पारस्परिक वार्तालाप द्वारा समझौता माना गया है।

5. राष्ट्रसंघ की भाँति ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रकृति भी ऐसी है कि सदस्यों के सक्रिय सहयोग के बिना यह सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता।

6. राष्ट्रसंघ की भाँति ही संयुक्त राष्ट्रसंघ का क्षेत्राधिकार भी व्यक्तियों पर न होकर राज्यों पर है।

7. राष्ट्रसंघ को राज्यों या उनके नागरिकों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं था और संयुक्त राष्ट्रसंघ को भी नहीं है। राष्ट्रसंघ की भाँति संयुक्त राष्ट्रसंघ का काम भी सदस्य-राज्यों के चन्दे पर निर्भर है।

अन्तर

दोनों संस्थाओं में यद्यपि अनेक समानताएँ हैं, तथापि कई महत्त्वपूर्ण अन्तर भी हैं। ये अन्तर संयुक्त राष्ट्रसंघ को राष्ट्रसंघ से अधिक प्रभावशाली, सशक्ति और अधिकार-सम्पन्न सिद्ध करते हैं। इन अन्तरों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ राष्ट्रसंघ का अगला चरण है, दोनों संगठनों के सचिवालयों, व्यवहारों और व्यवस्थाओं में प्रमुख अन्तर प्रकटित हैं—

1. राष्ट्रसंघ की स्थापना प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के बाद पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में की गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने से पहले ही हो गया। इसकी स्थापना के लिए बार्ताएँ युद्धकालीन राष्ट्रीय सम्मेलनों में ही आरम्भ हो गई और 26 जून, 1945 को सानफ्रांसिस्को सम्मेलन में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर हो गए जबकि महायुद्ध अगस्त, 1945 में समाप्त हुआ।

2. राष्ट्रसंघ की प्रसविधा (Covenant) बर्साय-सन्धि तथा अन्य शान्ति-सन्धियों का अभिन्न अंग था जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के अधिकार पत्र (Charter) का स्वतन्त्र अस्तित्व है—यह किसी शान्ति-सन्धि का अंग नहीं है। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य शान्ति-सन्धियों द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को कायम रखना था, संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ ऐसी कोई बात जुड़ी हुई नहीं है।

3. संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य-संख्या राष्ट्रसंघ की सदस्य-मर्यादा से बहुत अधिक है। आज 149 देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्य हैं, राष्ट्रसंघ ऐसा सार्वभौमिक रूप कभी प्राप्त नहीं कर सका। राष्ट्रसंघ को सभी विश्व-शक्तियों का वंसा विश्वास प्राप्त नहीं हो सका था जैसा आज संयुक्त राष्ट्रसंघ को प्राप्त है। राष्ट्रसंघ में तत्कालीन 5 महाशक्तियों में से 2 ही स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित रहनी थी जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ में द्वितीय महायुद्धोत्तर तीनों महाशक्तियाँ सम्मिलित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका कभी भी राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना और इसमें रूस के प्रवेश करते ही जापान तथा जर्मनी इससे वृथक् हो गए। अतः विश्व के महान् शक्तिशाली राष्ट्रों का जैसा प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रसंघ में है वंसा राष्ट्रसंघ में कभी नहीं रहा।

4 दोनों संस्थाओं के विधानों के प्राकार में भी अन्तर हैं। राष्ट्रसंघ की प्रवृद्धि में केवल 26 धाराएँ थी जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में 111 धाराएँ हैं।

5 सगठनात्मक दृष्टि से भी कई अन्तर है। राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग केवल तीन थे—असेम्बली, परिषद् और सचिवालय, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रमुख अंग छ हैं—महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद्, न्याय परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् बिल्कुल नवीन संस्था है जिससे स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पर केवल राजनीतिक कार्यों का दायित्व ही नहीं है बल्कि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक कार्यों पर भी विशेष बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में मानव-व्यक्तित्व के विकास और व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण के महत्त्व को समझा गया। इन गैर-राजनीतिक कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत कई विशिष्ट संस्थाएँ हैं जिनका पुराने राष्ट्रसंघ में अभाव था।

6 वर्तमान सभा की महासभा में निर्णय 2/3 मत से लिए जाते हैं और ये निर्णय सदस्य-देशों पर बाध्यकारी रूप से लागू नहीं होते बल्कि मिफारिश के रूप में होते हैं। दूसरी ओर पुरानी सभा की असेम्बली की सभा में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे और इनका पालन करना सदस्यों के लिए अनिवार्य था। इस दृष्टि से यह कहना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा राष्ट्रसंघ की सभा से निर्वल है।

7. संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में महासभा और सुरक्षा परिषद् के कार्यों का राष्ट्रसंघ की सभा और परिषद् की अपेक्षा अधिक स्पष्ट विभाजन है। सुरक्षा परिषद् का कार्य क्षेत्र राष्ट्रसंघ की परिषद् की अपेक्षा सीमित होते हुए भी अधिक स्पष्ट

है। उसके निर्णयों का पालन सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। इस तरह सुरक्षा परिषद् पुरानी परिषद् की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। उसके पास वास्तविक शक्ति है। उसके संयोजन और व्यवहार के नियमों ने उसे परिषद् की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था बना दिया है।

8. सुरक्षा परिषद् एक स्थायी संस्था है और 14 दिन में इसकी एक बैठक अवश्य होती है। राष्ट्रसंघ की परिषद् (कौमिल) की बैठकें वर्ष भर में केवल तीन ही होती थीं। इसके प्रतिरिक्त जहाँ संकटकाल में सुरक्षा परिषद् की आवश्यक बैठक तुरन्त बुलायी जा सकती है वहाँ राष्ट्रसंघ की परिषद् इस दृष्टि से निर्वल और पिछड़ी हुई थी।

9 राष्ट्रसंघ की सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने की व्यवस्था का आशय था कि उसके सभी सदस्य-राज्यों को निषेधाधिकार (Veto Power) प्राप्त था। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ में केवल सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों को ही निषेधाधिकार प्रदान किया गया है।

10 राष्ट्रसंघ आक्रमण होने पर ही उसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही कर सकता था जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ युद्ध छिड़ने पर ही नहीं बल्कि शान्ति भंग होने या आक्रमण होने की सम्भावना पर भी अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है।

11. राष्ट्रसंघ में शान्ति भंग करने वाले देश के विरुद्ध मुख्य रूप से आर्थिक प्रतिबन्धों की व्यवस्था थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास आर्थिक प्रतिबन्धों की शक्ति तो है ही, अपितु विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद् जल, थल और वायु सेना द्वारा सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है। वह अपने सदस्यों से सेनाओं की माँग करती है और सैनिक योजना को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने के लिए उसके पास एक सैनिक स्टॉक समिति भी है। राष्ट्रसंघ इस सम्बन्ध में असहाय था। उसके पास संकट में प्रयोग की जा सकने वाली इस प्रकार की कोई सेना नहीं थी। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की 43वीं धारा के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् को आवश्यकता पड़ने पर अन्तर्राष्ट्रीय सेना संगठित करने का भी अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग पिछले वर्षों में कई बार किया जा चुका है। राष्ट्रसंघ इस दृष्टि से एकदम अप्रगम था।

12 आक्रमण रोकने की कार्यवाही के सम्बन्ध में दोनों संस्थाओं में एक ओर भी बड़ा अन्तर देखने को मिलता है। राष्ट्रसंघ में ऐसी कार्यवाही करने के लिए सदस्य बाध्य नहीं थे। राष्ट्रसंघ के विधान की 16वीं धारा के अनुसार सच के सदस्य यह निर्णय करते थे कि किसी सदस्य-देश ने राष्ट्रसंघ में विधान के दायित्वों का उल्लंघन किया है या नहीं तथा उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की जाए या नहीं। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में शान्ति भंग की दिशा का निश्चय करने और सैनिक कार्यवाही करने का निर्णय लेने का दायित्व सच के सभी सदस्यों का न होकर सुरक्षा परिषद् का है। सुरक्षा परिषद् के निर्णयों का पालन सदस्यों की इच्छा पर निर्भर नहीं है बल्कि आवश्यक है। शान्ति के लिए एकता के प्रस्ताव में महासभा को भी अधिकार प्रदान किया है कि सुरक्षा परिषद् में यदि निषेधाधिकार

के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो वह शान्ति स्थापित करने के लिए सैनिक कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रसंघ के विधान में नहीं थी।

13. शान्ति और युद्ध की स्थिति में राष्ट्रसंघ अपनी ओर से कोई पहल नहीं कर सकता था। किसी सदस्य द्वारा मामला प्रस्तुत करने पर ही उन पर विचार सम्भव था। लेकिन वर्तमान विश्व-स्थिति में इस कमजोरी को दूर कर दिया गया है। चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् और महासभा दोनों इस दिशा में पहल करने में समर्थ हैं। महासचिव पर भी इस सम्बन्ध में विशेष दायित्व है। सन् 1973 के अरब-इजरायल युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में जब महाशक्तियों ने या किसी अन्य राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद् में मामला नहीं उठाया तो महासचिव ने सुझाव रखा कि युद्धरत राष्ट्रों से लड़ाई अविलम्ब बन्द करने की अपील की जाए। इसके बाद सुरक्षा परिषद् सक्रिय हो गई।

14. संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्याय-व्यवस्था (Trusteeship System) राष्ट्रसंघ की सरक्षण व्यवस्था (Mandate System) से बहुत भिन्न और श्रेष्ठ है।

15. संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्य संघ के प्रधान कार्यालय में अपना एक स्थायी प्रतिनिधि अवश्य रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त विचार-विमर्श सम्भव हो सके। राष्ट्रसंघ के विधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी।

16. संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में शान्ति-रक्षा के लिए प्रादेशिक संगठन (Regional Organizations) बनाने की अनुमति दी गई है, जबकि राष्ट्रसंघ के विधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी।

17. राष्ट्रसंघ के विधान में 'आत्मरक्षा' के अधिकार के सम्बन्ध में कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं बही गई थी, यद्यपि अनुच्छेद 157 में इसका गोलमाल संकेत था। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुच्छेद 51 में संघ द्वारा कार्यवाही करने से पूर्व आक्रमण का शिकार बने राज्य को 'आत्मरक्षा' का अधिकार स्पष्ट शब्दों में दिया गया है।

18. संयुक्त राष्ट्रसंघ का महासचिव राष्ट्रसंघ के महासचिव से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वह एक बहुत ही प्रभावशाली 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ' होता है।

19. घरेलू अधिकार-क्षेत्र (Domestic Jurisdiction) के सम्बन्ध में भी दोनों संस्थाओं में मौलिक अन्तर था। संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस बारे में राष्ट्रसंघ की अपेक्षा अधिक व्यापक व्यवस्था है। राष्ट्रसंघ में इस बात के निर्धारण का भार सदस्य-राज्यों पर नहीं, बल्कि परिषद् पर डाला गया था कि कौनसी बात घरेलू मामले के अन्तर्गत आएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में यह निश्चय नहीं किया गया है कि घरेलू क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य को निर्णय की स्वतन्त्रता प्राप्त है। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रसंघ का कार्यक्षेत्र और प्रभाव सङ्कुचित हो गया है।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का संगठन राष्ट्रसंघ के संगठन से अनेक अंशों में अधिक उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली है। प्रो. ईग्लटन (Eagleton) का कहना सत्य है कि "यद्यपि दोनों व्यवस्थाओं के स्वरूप और साधारण कार्यों में एकरूपता दिखाई देती है, तथापि इनके बीच जो मौलिक अन्तर हैं उनको देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ मान्यता और प्रकृति में राष्ट्रसंघ से पर्याप्त भिन्न है।"¹ एक बात और भी है और वह यह कि संयुक्त राष्ट्रसंघ एक निर्दोष सस्था नहीं है। इसमें प्रत्येक त्रुटियाँ हैं जिनका सुधार होने पर यह सस्था और भी अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली बन सकती है। अभी यह अन्तराष्ट्रीय कानून को यथेष्ट नैतिक और मौलिक समर्थन प्रदान करने में असमर्थ है। इसके पास ऐसी ठोस सैनिक शक्ति का अभाव है जिसके बल पर वह सभी राष्ट्रों से अन्तराष्ट्रीय कानून का पालन करवा सके। आशा है कि विश्व के राजनीतिज्ञ उपर्युक्त समय पर इन त्रुटियों का परिमार्जन करने में समर्थ हो सकेंगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का बदलता हुआ रूप : विकासशील देशों की आवाज बुलन्द

संयुक्त राष्ट्रसंघ का बदलता हुआ रूप आशा की नई किशो को उजागर कर रहा है। इस विश्व सस्था पर लगभग 20 वर्ष से संयुक्तराज्य अमेरिका छाया हुआ था, पर अब उसकी मनमानी का अन्त हो रहा है। शोषित और पीड़ित एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देश अब अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक मंच के प्रभावशाली अभिनेता बनते जा रहे हैं। वह दिन समाप्त हो चला है जब अमेरिका और उसके पिछलग्गू राष्ट्र विश्व सस्था को अपनी 'बपीती' मानकर चलते थे। सघ के 29वें, 30वें और 31वें अधिवेशनो में उसकी बदलती हुई तस्वीर स्पष्ट हुई है।

सितम्बर-दिसम्बर, 1974 के महासभा के 29वें अधिवेशन में पश्चिमी एशिया, फिलिस्तीनी समस्या, कम्बोडिया, दक्षिणी एशिया को परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित करने की पाकिस्तान की माँग आदि पर महासभा ने खुलकर विचार किया और बहुमत के आधार पर निर्णय लिए। महासभा के निर्णयों ने उन राष्ट्रों में खलबली पैदा कर दी जो अब तक संयुक्त राष्ट्रसंघ को अपनी 'बपीती' समझकर उस पर अपने निर्णय थोपते आ रहे थे। विशेष रूप से अमेरिका तो बहुत ही चौंकाया और उसने यह घमकी दी कि यदि इसी प्रकार बहुमत के आधार पर एक पक्षीय प्रस्ताव पारित किए जाते रहे तो वह सघ को दिया जाने वाला अपना अनुदान बन्द कर देगा। जब महासभा ने फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के नेता यासिर अराफत को अधिवेशन में भागण देने की अनुमति दी और दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि मण्डल को अधिवेशन से चले जाने का निर्देश दिया तो अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल के नेता जान स्काली के धर्म का बाँध टूट गया। उन्होंने कहा कि तीसरी दुनियाँ के देश अपने

1 Engleton : "Covenant of the League of Nations and the Charter of U. N. : Points of Difference" —Dept. of State Bulletin, August 19, 1945.

बहुमत का गलन प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अमेरिका की घमकी और आरोप की विकासशील देशों पर बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। इन देशों के प्रतिनिधियों ने अमेरिका के इस आरोप का खण्डन किया कि महासभा 'बहुमत की निरकुशता की शिकार है।' श्रीलंका के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका उस बिगड़े हुए बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है जो जीत की आशा न होने पर मैदान छोड़ देता है। इस सरी बहस का कोई निश्चित परिणाम तो सामने नहीं आया, लेकिन यह बात स्पष्ट हो गई कि संयुक्त राष्ट्रमंडल का रूप अब वैसा नहीं है, जैसा 30 वर्ष पूर्व उसकी स्थापना के समय था या कुछ ही वर्ष पूर्व चीन के सदस्य बनने के समय था। अब उस पर अमेरिका का स्वामित्व नहीं रहा। यद्यपि वास्तविक शक्ति सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों में निहित है जो यदि चाहे तो अपने निपेधाधिकार द्वारा बहुमत के निर्णयों को प्रभावहीन बना सकते हैं, तथापि इस बात की सम्भावनाएँ प्रबल हो उठी हैं कि विकासशील देश अपनी सत्ता का लाभ उठाकर अपनी आवाज बुलन्द करेंगे और पूँजीवादी तथा साम्यवादी देशों के पारस्परिक मतभेदों का लाभ उठाकर अपने दृष्टिकोण की सार्थकता सिद्ध कर दिखाएँगे। विकासशील देश अब संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयों को प्रभावित करने की स्थिति में आ गए हैं।

सितम्बर से दिसम्बर, 1975 तक महासभा का तीसरा नियमित अधिवेशन हुआ जिसमें विकासशील देशों से सम्बन्धित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रश्न उठे। भारत ने सदा की भाँति ही इसकी कार्यवाही में सक्रिय भूमिका निभायी। इस अधिवेशन में केप बर्दे, कोमरोन, मोजाम्बिक, पापुआ न्यूगिनी, साओ तोम तथा प्रिंसिप और सुरीनाम को नए सदस्यों के रूप में प्रवेश मिला। इससे संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 144 हो गई। इससे पहले, दोनों वियतनामों को प्रवेश दिलाने के प्रयास सुरक्षा परिषद् में विशेषाधिकार के प्रयोग से विफल कर दिए गए थे। तदुपरान्त महानभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा सुरक्षा परिषद् से अनुरोध किया गया कि दोनों वियतनामों के सदस्यता-आवेदनो पर शीघ्र और अनुकूल दृष्टिकोण से पुनर्विचार किया जाए। भारत ने इस प्रस्ताव का सहप्रवर्तन किया था। दक्षिण कोरिया के सदस्यता-आवेदन पर विचार नहीं हो सका क्योंकि इसे सुरक्षा परिषद् की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का 31वाँ मंत्र 21 सितम्बर से 21 दिसम्बर, 1976 तक न्यूयार्क में हुआ। इसके वाद-विवाद और प्रस्तावों में प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विधिक एवं अन्य मसलों पर विचार हुआ। भारत ने इन विचार-विमर्शों में सक्रिय भाग लिया। इस सत्र के प्रारम्भ होने से प्रारम्भ होने से पूर्व विश्व निकाय की सदस्यता 144 थी जो बढ़कर 147 हो गई इसमें सशस्त्र, अगोला और पश्चिम समोआ इन तीन नए सदस्यों को शामिल किया गया था। वियतनाम समाजवादी गणराज्य के सुरक्षा परिषद् में शामिल किए जाने पर एक बार फिर निपेधाधिकार का प्रयोग हुआ। वाद में गुट-निरपेक्ष देशों की

पहल पर महासभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें वियतनाम समाजवादी गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिलाने और संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 4 का हृदता से पालन करते हुए इस मामले पर सुरक्षा परिषद् द्वारा अनुकूल विचार करने की सकारिश की गई। भारत ने इस प्रस्ताव का सहसमर्थन किया। इस सत्र में राष्ट्र मण्डलीय सचिवालय को प्रेक्षक के रूप में आने की अनुमति दी गई। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा का 32वाँ अधिवेशन 20 सितम्बर, 1977 को विश्व संस्था में दो नए सदस्यों के प्रवेश के साथ आरम्भ हुआ। ये नए सदस्य हैं—वियतनाम और ज़िबूती। इनकी सदस्यता के प्रश्न पर विचार भारत सहित 100 सदस्यों द्वारा रखे गए प्रस्ताव के आधार पर किया गया। इनके प्रवेश के साथ ही विश्व संस्था की सदस्य संख्या 149 हो गई।



संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्तियों के रूप में उदय

(RISE OF U. S. A. AND U. S. S. R. AS
SUPER POWER)

“इस दस्तावेज में जो युनियादी सिद्धान्त निरूपित किए गए हैं वे उन उत्तरदायित्वों के लिए बाधक साबित नहीं होंगे जो अमेरिका और सोवियत संघ अन्य देशों के बारे में पहले अंगीकार कर चुके हैं।”

—संयुक्त घोषणा, मास्को शिखर वार्ता, 1972

जर्मनी और जापान की पराजय के साथ ही द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति हुई। 7 मई, 1945 को यूरोप में जर्मनी ने और 14 अगस्त, 1945 को एशिया में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार लगभग छः वर्ष तक चलने वाले मानव इतिहास के एक सबसे अधिक क्रूर, भयानक और विनाशकारी युद्ध का अन्त हुआ जिसने विश्व के लगभग प्रत्येक राष्ट्र, यहाँ तक कि प्रत्येक परिवार को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया था।

द्वितीय महायुद्ध इतना व्यापक और प्रभावकारी था कि इसके अन्त के साथ ही विश्व-इतिहास के एक युग का अन्त हो गया। एक नूतन युग का सूत्रपात हुआ जिसमें अनेक राज्य उभरे, नई महाशक्तियों का उदय हुआ, प्रभुत्व-क्षेत्र बढ़े, नई प्रवृत्तियों और नए सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में नई समस्याएँ उत्पन्न हुई। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक यूरोप विश्व-इतिहास का निर्माता था। सन् 1492 में कोलम्बस द्वारा नई दुनिया अर्थात् अमेरिका की खोज से लेकर सन् 1939 तक के युग को विश्व-इतिहास का यूरोपीय युग कहा जाता है। लेकिन महायुद्ध ने इस यूरोपीय युग का अन्त कर दिया। महायुद्ध ने यूरोप की आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक सभी दृष्टियों से पगु बना दिया। महायुद्ध के बाद का यूरोप

एक 'समस्या-प्रधान यूरोप' (A Problem Europe) बन गया। जर्मनी और इटली नष्ट हो गए तथा ब्रिटेन और फ्रांस तृतीय श्रेणी के राष्ट्र बन गए। विश्व-नेतृत्व यूरोप के हाथों से निकल कर संयुक्तराज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के हाथों में भा गया। महायुद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब संसार में दो ही महाशक्तियाँ रह गई हैं—संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये दोनों ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उदित हुए और युद्धोत्तर विश्व तेजी से इनके प्रभाव-क्षेत्रों में बँटने लगा। दोनों राष्ट्र मानव-चिन्तन की दो प्रबल विचारधाराओं के प्रतीक बन गए। सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का प्रतिनिधि बना तो संयुक्तराज्य अमेरिका लोकतन्त्रवादी आकांक्षाओं का पक्षधर बन गया। दो भिन्न प्रकट हुए—संयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी शिविर।

संयुक्त राज्य अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय

द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका के उदय को एक 'महाशक्ति' (Super Power) के रूप में समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम—यह भी देखें कि द्वितीय महायुद्ध से पहले तक संयुक्तराज्य अमेरिका की क्या स्थिति थी, क्या शक्ति-नीति थी।

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व अमेरिका

संयुक्तराज्य अमेरिका महायुद्ध के पूर्व से ही एक समृद्ध और शक्तिसम्पन्न देश था, लेकिन उसे 'महाशक्ति' का वह स्तर प्राप्त नहीं था जो युद्धोत्तरकाल में प्राप्त हुआ। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक वह यथासम्भव पृथक्तावादी नीति का अनुसरण करता रहा। राष्ट्रपति जैफरसन ने सन् 1801 में इस नीति को इन शब्दों में स्पष्ट किया था—“शान्तिपूर्ण व्यापार सबके-साथ, भ्रष्ट पैदा करने वाली सन्धियाँ किसी के साथ नहीं।” इसका आशय यही था कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करेगा, लेकिन यूरोपीय राजनीति के जाल में नहीं फँसेगा। सन् 1823 में अमेरिका की विदेश नीति में सुप्रसिद्ध 'मुनरो सिद्धान्त'—(Monroe Doctrine) का प्रवेश हुआ। राष्ट्रपति मुनरो ने एक ओर तो यह कहा कि अमेरिका यूरोपीय विवादों से पृथक् रहेगा, लेकिन दूसरी ओर यूरोपीय राज्यों को यह चेतावनी भी दी कि वे अमेरिका महाद्वीप में साम्राज्यवादी चेष्टाओं से दूर रहे। यदि अमेरिकी गोलाढ' में हस्तक्षेप किया गया तो इसे संयुक्तराज्य अमेरिका अग्रणीपूर्ण कार्यवाही समझेगा। दूसरे शब्दों में, मुनरो सिद्धान्त का अर्थ था—‘तुम पृथक् रहो, हम भी पृथक् रहेंगे।’ प्रथम महायुद्ध तक मुनरो सिद्धान्त और पृथक्तावादी नीति का मेल भली-भाँति चलता रहा। लेकिन महायुद्ध आरम्भ हो जाने पर अमेरिका के लिए इस परम्परागत नीति पर चलते रहना सम्भव नहीं रहा। आरम्भ में तटस्थ रहने के बाद अमेरिका भी मित्रराष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ा। इससे मित्रराष्ट्रों की शक्ति में भारी वृद्धि हो गई और विजयी जर्मनी पराजित जर्मनी में बदल गया।

प्रथम महायुद्ध समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति विल्सन ने अपने देश को

अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के मार्ग पर चलाना चाहा, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। सीनेट के विरोध के कारण अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य तक नहीं बन सका। इस प्रकार अमेरिका में पृथक्तावादी नीति का पुनरोदय हुआ। सन् 1920 से 1932 तक अमेरिका के राजनीतिक जितन पर रिपब्लिकन दल छाया रहा और पृथक्तावाद (Isolationism) का बोलवाला रहा। इस नीति के अनुसरण के कारण अमेरिका को विश्व में 'महाशक्ति' का स्तर प्राप्त नहीं हो सकता था। मार्च, 1937 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका पृथक्तावाद से अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ओर मुड़ने लगा। फिर भी अमेरिका चाहता यही था कि मित्रराष्ट्रों के साथ सहानुभूति रखते हुए भी यूरोप के मामलों से मयासाध्य पृथक् रहे। सन् 1937 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक भाषण दिया जिसे अमेरिकी विदेश नीति में परिवर्तन का द्योतक कहा जाता है। शिकागो में दिया गया यह भाषण 'क्वारेन्टीन वक्वन्ता' (Quarantine Speech) के नाम से विख्यात है। इस भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने अन्तर्गतत्वा ग्रहस्तक्षेप और तटस्थता की नीति से हटने का निश्चय कर लिया है और शान्तिप्रिय राष्ट्रों के साथ सहयोग कर जर्मनी, जापान, इटली जैसे उग्र राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही का समर्थन किया है। अब अमेरिका यूरोप की राजनीति में रुचि लेने लगा। अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से उदासीन नहीं रहना चाहता। वह एक सबल और सुदृढ़ देश के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है।

द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका

द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट होने पर अमेरिका में इस प्रश्न पर गम्भीर मतभेद रहा कि वह युद्ध में सम्मिलित हो या नहीं। लेकिन जब 7 दिसम्बर, 1941 को जापान ने पर्लेहार्बर के अमेरिकी नौ-सैनिक इन्डो पर बम बर्षा कर दी तो 8 दिसम्बर को ही अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार अब 'पुरानी दुनिया' तक सीमित युद्ध 'नई दुनिया' में भी प्रवेश कर गया और अमेरिका जैसा सबल तथा साधन-सम्पन्न राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस आदि मित्रराष्ट्रों के पक्ष में मैदान में आ गया। महायुद्धकाल में अमेरिका ने अपनी महान् सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे शत्रुराष्ट्रों (जर्मनी, जापान, इटली आदि) की पराजय निश्चित हो गई। युद्ध के दौरान अमेरिका ने मित्रराष्ट्रों के पक्ष में अपने सैनिक भी भेजे, उन्हें शस्त्रास्त्र भी दिए और उनके लिए डॉलर की पैलियाँ भी खोल दी। इस सैनिक और आर्थिक सहायता ने अमेरिका का सिक्का जमा दिया और एक 'महाशक्ति' के रूप में उदय होने का उसका मार्ग प्रणस्त हो गया।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका एक 'महाशक्ति' के रूप में

द्वितीय महायुद्ध संयुक्तराज्य अमेरिका के लिए प्रच्छन्न रूप में एक वरदान सिद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध ने अमेरिका को एक शून्यी राष्ट्र से शून्यदाता राष्ट्र का रूप दिया था और द्वितीय महायुद्ध ने अधिकांश विश्व को उसके आर्थिक प्रभुत्व से आच्छादित

कर दिया। कारण स्पष्ट था कि महायुद्ध में अमेरिका को उस घोर विनाश का सामना नहीं करना पड़ा जिसका अन्य मित्र और शत्रु राष्ट्रों को करना पड़ा था। जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस आदि सभी राष्ट्र भयंकर बमबर्षा के शिकार हुए थे और ब्रिटेन को छोड़कर इन सभी देशों की भूमि पर रक्तरेजित युद्ध हुए थे। सोभाग्यवश अमेरिका ही इस दुर्दशा से बचा रहा। न उसकी भूमि पर युद्ध लड़ा गया और न उसे दूसरे देशों के समान क्रूर बमबर्षा का शिकार होना पड़ा। इसीलिए, जहाँ युद्धकाल में दूसरे देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से अस्त-व्यस्त हो गए, वहाँ अमेरिका की आर्थिक मजबूती पर कोई आंच नहीं आई। युद्ध के बाद यूरोप का चित्र 'दर्दनाक' था, सैनिक दृष्टि से यूरोप के राष्ट्र अत्यधिक दुर्बल थे, आर्थिक दृष्टि से वे लगभग मृत के मुँह में थे, वहाँ अमेरिका इन सब कठिनाइयों और दुर्दशाओं से बचा हुआ था। सैनिक दृष्टि से भी वह अत्यधिक सबल था और आर्थिक दृष्टि से भी। इसीलिए उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई और अब वह सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों ही दृष्टियों से पूँजीवादी जगत् का नेता बन गया। युद्धकाल में उसका उत्पादन गिरने के बजाय बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत और कृषि उत्पादन में लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अणु बम का रहस्य भी उसके पास था, जापान पर अणु बम गिराकर वह अपनी महान् विनाशक क्षमता का परिचय दे चुका था। अतः स्वभावतः युद्ध से पीड़ित और ध्वस्त राष्ट्र उसके भण्डे के पीछे थे। खड़े हुए और उन्होंने उसका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। जिस लोकतन्त्रवादी जगत् का नेतृत्व पहले ब्रिटेन के हाथों में था वह अब संयुक्तराज्य अमेरिका के हाथों में आ गया। प्रत्येक देश उसकी सहायता पाने के लिए लालायित था।

28 अक्टूबर, 1945 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश नीति के जिन बारह सूत्रों (Twelve Point) की घोषणा की उनसे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका अब 'नेतृत्व' से पीछे नहीं हटना चाहता, 'महाशक्ति' की अपनी भूमिका निभाने के लिए वह इन बारह सूत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित सूत्र अमेरिका की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप में प्रकट करते थे—

- (क) अमेरिका चाहता है कि जिन देशों से सर्वोत्तम प्रभुसत्ता के अधिकार बलपूर्वक छीने गए थे, वे उन्हें वापस लिए जाने चाहिए।
- (ख) अमेरिका किसी मित्र देश में जनता की महमति के बिना किए गए, किसी प्रादेशिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा।
- (ग) अमेरिका देखेगा कि स्वशासन के योग्य देशों को विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने शासन का स्वरूप चुनने में स्वाधीनता मिले।
- (घ) अमेरिका अपने साथियों के साथ सहयोग करते हुए पराजित देशों में शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना के लक्ष्य पर चलेगा।
- (ङ) अमेरिका ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देगा जो विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश पर बलपूर्वक थोपी गई हो।
- (च) विश्व में कच्चे माल की प्राप्ति और व्यापार में सब देशों की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

- (छ) अमेरिका विश्व में विचार अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतन्त्रता की वृद्धि का प्रयत्न करेगा।
- (ज) विश्व में दरिद्रता दूर करने और जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए सब देशों में पूर्ण आर्थिक सहयोग होना चाहिए।

ये नीति-बिन्दु अमेरिका की महत्वाकांक्षा के प्रतीक थे जिनमें अमेरिका मानो यह कह रहा था कि उसने दुनिया को बचाने, सुधारने तथा दुनिया में अपनी सरकारें स्थापित कराने का ठेका ले लिया है। इन उद्देश्यों में अमेरिका के 'डॉलर साम्राज्यवाद' की गूँज थी। अमेरिका अब पृथक्तावादी नीति से बिलकुल हट चुका था अर्थात् यह नीति अमेरिका के लिए अब मृत हो चुकी थी। अमेरिका ने अब राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक हस्तक्षेप की नीति पर चलना शुरू कर दिया था। उसको चुनौती देने वाला एकमात्र राष्ट्र सोवियत संघ था। अतः अमेरिका के नीति-निर्माताओं और प्रशासकों ने यह निश्चय कर लिया कि उनका देश प्रत्येक स्तर पर सोवियत संघ के प्रभाव और साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। इसे 'अवरोध की नीति' (Policy of Containment) की सज्ञा दी गई। इसके फलस्वरूप मार्शल योजना का निर्माण हुआ जिस पर अप्रैल, 1948 में अमेरिकी कांग्रेस ने स्वीकृति की मोहर लगा दी। इस योजना का उद्देश्य युद्ध द्वारा घबस्त यूरोप का पुनरुद्धार कर उसे साम्यवाद से बचाना था। इस योजना के अन्तर्गत चार वर्ष (1947-1951) में अमेरिका ने यूरोप को लगभग 11 मिलियन डॉलर की सहायता दी। इस नीति के दो स्पष्ट परिणाम दृष्टिगोचर हुए—एक ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक पतन और साम्यवादी आधिपत्य से बच गया तथा दूसरी ओर अमेरिका पश्चिमी जगत् का सर्वमान्य नेता बन गया।

'महाशक्ति' के रूप में अमेरिका के इरादे तब और भी स्पष्ट हो गए जब जनवरी, 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने प्रसिद्ध 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Points Programme) की घोषणा की। ट्रूमैन ने यह स्पष्ट कर दिया कि संयुक्तराज्य अमेरिका ने विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है, आक्रमण के विरुद्ध स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्रों को मुहृद बनाने का निश्चय किया है और अल्पविकसित देशों के उत्थान के लिए पुन प्राविधिक सहायता देने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम के मूल में अमेरिका के राष्ट्रीय हित निहित थे। यह चार सूत्री कार्यक्रम 'शीत-युद्ध' का एक अस्त्र था, अर्द्ध-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने की एक कूटनीतिक चाल थी। चार सूत्री कार्यक्रम के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश नीति का कार्य विश्व-व्यापी हो गया। अब यह निश्चय किया गया कि "जहाँ कहीं शान्ति भंग करने वाली प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमण की कार्यवाही होगी, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए सकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा।"

आर्थिक क्षेत्र में तो अमेरिका ने अपना नेतृत्व स्थापित कर ही लिया, सैनिक क्षेत्र में भी उसने स्वयं को पूरी तरह एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए

अनेक कदम उठाए। अन्य देशों के साथ सैनिक सन्धियों और पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम की नीति आरम्भ की गई जिसके फलस्वरूप अप्रैल, 1948 में नाटो (NATO) की स्थापना हुई। इस सन्धि-संगठन द्वारा संयुक्तराज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप के साथ सैनिक गठबन्धन में बंध गया। साम्यवादी जगत् के लिए यह एक चेतावनी थी कि वह नाटो के सदस्य-देशों पर आक्रमण करने का साहस न करे। इस सन्धि ने यूरोपीय देशों को एक सुरक्षा-आवरण प्रदान किया ताकि वे अपने आर्थिक और सैनिक विकास कार्यक्रम तैयार कर सकें। इस सन्धि द्वारा अमेरिका ने यह दायित्व सम्भाल लिया कि वह साम्यवाद विरोधी किसी भी युद्ध के लिए सदैव तैयार रहेगा। 'नाटो फार्मूला' का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। नाटो-सदस्यों को सैनिक सहायता दी गई, सदस्य-देशों में सैनिक अड्डे स्थापित किए गए तथा विभिन्न देशों के साथ मैत्री-सन्धियाँ क्रियान्वित की गईं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी अमेरिका ने सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाना आरम्भ कर दिया। वह सुरक्षा परिषद् में रूस विरोधी सदस्यों का समुदाय बन गया और संयुक्त राष्ट्रसंघ 'महाशक्तियों के दाव-पेच का अखाड़ा' बन गया। जब सन् 1946 में सुरक्षा परिषद् में यूनान सम्बन्धी विवाद प्रस्तुत हुआ तो अमेरिका और रूस तथा उनके साथी राष्ट्र 'शीत-युद्ध' की विश्व सत्था में घसीट लाए। संयुक्त राष्ट्रसंघ पर अमेरिका का प्रभाव व्याप्त हो गया और संघ के निरीक्षण में वस्तुतः अमेरिका द्वारा ही यूनान को आर्थिक और सैनिक सहायता दी गई। जब सन् 1950 में कोरिया का गृहयुद्ध छिड़ा तो मुख्य रूप से अमेरिका के प्रयत्नों से ही सुरक्षा परिषद् ने उत्तर कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर सैनिक हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। जुलाई, 1950 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के भण्डे के नीचे जिन 16 राष्ट्रों की संयुक्त सैनिक कमान की स्थापना हुई उसका सेनापति अमेरिका के जनरल मैकआर्थर को बनाया गया। अमेरिका की प्रबल सैनिक शक्ति के कारण ही संयुक्त राष्ट्रसंघ कोरिया-युद्ध में सफल हो सका। वास्तव में सारा युद्ध अमेरिका ने लड़ा, केवल उस पर 'लिबल' संयुक्त राष्ट्रसंघ का लगा था।

इस प्रकार आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक सभी स्तरों पर अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर आया। चहुँमुखी प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र निरन्तर विस्तृत होता गया और वह 'मुक्त विश्व' (Free World) का एकछत्र नेता बन गया। आज भी अमेरिका विश्व की महाशक्ति नम्बर एक बना हुआ है।

महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय

द्वितीय महायुद्ध से क्षतिग्रस्त और अस्त-व्यस्त विश्व में केवल एक ही देश ऐसा बचा जो संयुक्तराज्य अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम था, और यह देश था सोवियत संघ। यूरोपीय महाद्वीप पर सोवियत संघ ही एक ऐसा राष्ट्र था जो युद्ध-कालीन महान् क्षतियों के बावजूद शक्तिशाली था। यद्यपि महायुद्ध के कारण लगभग 2½ करोड़ रूसी गृहहीन हो गए थे, लाखों रूसी सैनिकों और नागरिकों की प्राणों से हाथ धोना पड़ा था और लगभग 8 लाख वर्ष मील रूसी प्रदेश 'राख का ढेर' बन

गया था, तथापि ये सभी बलिदान और संकट रूस के लिए 'वरदान' सिद्ध हुआ। ऐसी अनेक बातें रूस के अनुकूल पड़ीं जिनके कारण उसका प्रादेशिक विस्तार हुआ, उसके राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव में वृद्धि हुई और वह विश्व की दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। द्वितीय महायुद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में रूस के उदय को भी आवश्यक पृष्ठभूमि में देखना उपयुक्त होगा।

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व रूस

सन् 1917 की महान् बोलशेविक क्रान्ति ने रूस में जारशाही का अन्त कर साम्यवादी शासन की स्थापना की। साम्यवादी रूस ने स्वयं को युद्ध से पृथक् कर लिया। पश्चिमी पूँजीवादी राष्ट्रों ने रूस की नई शासन-व्यवस्था को समाप्त कर देने का चक्रव्यूह रचा और रूस में सैनिक हस्तक्षेप भी किया, लेकिन ये सारे प्रयत्न निष्फल हुए। सन् 1921 के समाप्त होते-होते साम्यवादी सरकार ने अपने पर पूरी तरह जमा लिए। इसके बाद सन् 1921 से 1934 तक रूस ने 'रक्षात्मक पार्यवय' (Defensive Isolation) की नीति का अनुसरण किया। इस काल में रूस ने आत्म-रक्षा की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के साथ सन्धियाँ सम्पन्न की, उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए और दूसरे देशों में साम्यवादी प्रचार करना कम कर दिया। वह सामान्यतया पश्चिमी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहा और राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी उमने ग्रहण नहीं की। रूस ने पूँजीवादी राज्यों से समझौता करने की नीति का अनुसरण किया, किन्तु साथ ही अन्य देशों में साम्यवादी क्रान्ति फैलाने का प्रयत्न भी करता रहा। अतः पश्चिमी राज्य रूस को अविश्वास और सन्देह की दृष्टि से देखते रहे। अमेरिका ने सन् 1933 में रूस को मान्यता प्रदान की। दोनों देशों के बीच एक सन्धि हुई जिसमें दोनों ने एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा का और विरोधी प्रचार करने वाले दलों के दमन का वचन दिया। यह सन्धि रूस के लिए बहुत हितकर थी क्योंकि इसके बाद ही रूस की साम्यवादी सरकार को सत्तार की सभी बड़ी शक्तियों ने मान्यता प्रदान कर दी। सन् 1934 में रूस राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया। अनेक देशों के साथ उसकी सन्धियाँ हुईं। सन् 1936 तक रूस एक विशाल शक्तिमत्त देश गिना जाने लगा। इस प्रकार रूस के लिए एक महाशक्ति बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। रूस को जर्मनी की ओर से आशंका थी, अतः सन् 1939 में उसने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया। यह समझौता पश्चिमी देशों को आश्चर्यचकित कर देने वाला था क्योंकि वे तो जर्मनी को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस समय रूस का सारा कूटनीतिक खेल एक बहुत ही कुशल और मेधावी खिलाड़ी जैसा था जो यह भलीभाँति जानता था कि पश्चिमी देश विश्वासघात कर रहे हैं और जर्मनी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए रूस भीतर ही भीतर रचय को शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर सैनिक तैयारियाँ भी करता रहा।

द्वितीय महायुद्ध काल में रूस

सितम्बर, 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। रूस आरम्भ में तटस्थ रहा,

लेकिन जून, 1941 में जर्मन-प्राक्रमण होने पर वह पूरी शक्ति के साथ युद्ध में कूद पड़ा। युद्धकाल में अनेक उतार-चढ़ाव आए, लेकिन रूसी सेनाओं ने अपनी युद्ध-कला दृढ़ता और धीरता का सिक्का जमा लिया। भारी क्षति सहने के बावजूद रूस का एक विजयी राष्ट्र के रूप में उदय हुआ और ये रूसी सेनाएँ ही थी जिन्होंने सबसे पहले बर्लिन के सिर पर चोट की। जब जर्मन-राजधानी बर्लिन पर मित्रराष्ट्रों का अधिकार हुआ तो बर्लिन चार भागों में विभाजित हुआ जिनमें एक भाग पर रूस का कब्जा रहा। युद्धकाल में जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए तथा मित्रराष्ट्रों के साथ रूस के जो सम्झौते हुए उनमें रूस ने अपने हितों की पूरी तरह रक्षा की। युद्धकाल में ही उसने अपनी प्रादेशिक सीमाओं का भी विस्तार कर लिया।

रूस के पक्ष में महायुद्ध के परिणाम और 'महाशक्ति' के रूप में रूस का उदय

महायुद्ध में बलिदान और सकट रूस के लिए 'वरदान' सिद्ध हुए। महायुद्ध के परिणामों और महायुद्ध के बाद अपनाई गई नीतियों के कारण रूस अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में 'महाशक्ति' के रूप में प्रतिष्ठित हो गया।

(क) युद्धकाल में सीमाओं का विस्तार—महायुद्धकाल में ही रूस ने अपनी सीमाओं का पश्चिम में विस्तार कर लिया और पूर्वी केन्द्रीय यूरोप को अपने नियन्त्रण में ले लिया। वास्तव में महायुद्ध में रूस स्पष्ट और निश्चित ऐतिहासिक लक्ष्यों को लेकर अग्रसर हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से वह तीन दिशाओं में विस्तार का आकांक्षी था—पश्चिम की ओर यूरोप में, दक्षिण की ओर पूर्वी भूमध्यसागर के निकटवर्ती प्रदेश में तथा पूर्व में प्रशान्त सागर की ओर। इस प्रादेशिक विस्तार के अतिरिक्त रूस यह भी चाहता था कि पड़ोसी यूरोपीय देशों पर भी उसका प्रभाव जम जाए। महायुद्ध ने रूस को इन ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर दिया। सन् 1918 में रूस को जितने भू-भाग की हानि हुई थी उसे उसने पुनः प्राप्त कर लिया। रूस ने अपनी सीमा में (इतिहास में पहली बार) सभी रूसी आबादी वाले क्षेत्रों को सम्मिलित किया, पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया और मुद्रपूर्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाए रखी। अवश्य ही पूर्वी भूमध्यसागर के सम्बन्ध में रूस अपने ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका।

(ख) पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार—महायुद्धकाल में पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों की सत्ता सेना ने जर्मन दासता से मुक्ति दिलायी थी और इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने जर्मनी के विरुद्ध आपामार सत्रों का नेतृत्व किया था। युद्धोपरांत इन देशों में राजनीतिक सत्ता भी साम्यवादियों के हाथ में आयी और सोवियत रूस के लिए इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व विस्तार का मार्ग सरल हो गया। युद्ध के उपरान्त सन् 1948 तक की तीन वर्ष की अल्पावधि में ही यूरोप के सात देश पूरी तरह 'लाल' बन गए। फरवरी, 1945 के याह्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने 'विमुक्त यूरोप सम्बन्धी घोषणा' (Declaration on Liberated Europe) पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्टालिन ने याह्टा-भावना को ठुकराते हुए

पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का विस्तार कर दिया। उसने सन् 1947 और सन् 1948 की सन्धियों द्वारा फिनलैंड को भी अपने नियन्त्रण में ले लिया। फिनलैंड की स्वतन्त्रता तो कायम रही, लेकिन उसे यह बचन देना पड़ा कि वह रूस विरोधी विदेश नीति नहीं अपनाएगा। स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करायी और इस प्रकार सोवियत राष्ट्रीय सुरक्षा-शक्ति को सुदृढ़ बनाया। इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के विकास के लिए भी समझौते किए गए। सन् 1947 की 'मोलोटोव योजना' में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उनके औद्योगीकरण पर दल दिया गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी के साथ व्यापारिक सन्धियाँ की गईं। पूर्वी यूरोप के देशों के साथ आर्थिक सहयोग को घनिष्ठ बनाने के लिए सन् 1949 में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् (Council for Economic Mutual Assistance—Com. Con) स्थापित की गई। यह 'कौम कौन' पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम' (European Recovery Programme—E.R.P.) की एक प्रकार से जवाबी कार्यवाही थी। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सैनिक सन्धियाँ भी कीं। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया के साथ तो सैनिक सन्धियाँ युद्धकाल में ही की जा चुकी थीं। इसके बाद मार्च, 1946 से अप्रैल, 1949 तक 17 द्वि-पक्षीय सन्धियाँ की गईं। आगे चतुर्भुज, 1955 में इन देशों ने वारसा-संघट्ट पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार सोवियत संघ के साथ ये देश और भी अधिक दृढ़ता से बंध गए।

रूस का प्रादेशिक प्रभुत्व-विस्तार वस्तुतः आश्चर्यजनक था। सन् 1939 में रूस ने अपने क्षेत्र में लगभग 27 करोड़ 40 लाख वर्गमील की वृद्धि कर ली और साथ ही लगभग 36 करोड़ वर्गमील क्षेत्र के सात राज्य मास्को समर्थक बन गए। इन देशों के अतिरिक्त अधिभूत पूर्वी जर्मनी भी रूसी संरक्षण में ही था और वहाँ समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित शासन-प्रणाली कायम की जा चुकी थी।

(ग) आन्तरिक क्षेत्र में सुदृढ़ता—जिसी भी देश की आन्तरिक शक्ति उसे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत सहायक होती है। द्वितीय महायुद्धकाल में यद्यपि रूस को भारी भटके लगे, रूसी जन-धन की भयावह हानि हुई, तथापि रूस में साम्यवादी शासन-व्यवस्था की नींव कमजोर नहीं हुई। विपुल सकटों को झेलकर भी रूस विजयी हुआ, अतः आन्तरिक क्षेत्र में स्टालिन का और उसके शासन का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। सैनिक गुट का प्रभाव समाप्त हो गया और साम्यवादी दल में जो अर्वाच्यनीय तत्त्व थे वे भी स्टालिन का लोहा मानने लगे।

(घ) विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार—जिस स्टालिन ने प्रथम महायुद्ध के बाद ट्रॉट्स्की के विश्व-क्रान्ति के विचार का विरोध किया था, वही द्वितीय महायुद्ध के बाद इस नीति का प्रचल पोषक बन गया। साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में रूस ने विभिन्न उपायों का सहारा लिया। यूनान के गृह-युद्ध में यूनानी साम्यवादियों को पड़ोसी साम्यवादी देशों के माध्यम से सहायता

पहुँचायी गई। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) के विश्वव्यापी क्रान्ति-कारी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सन् 1947 में विभिन्न देशों की साम्यवादी पार्टियों के नेताओं ने बेलग्रेड में 'कॉमिन्फार्म' की स्थापना की। इसका उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था। स्टालिन चाहता था कि पूर्व और पश्चिम में रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक राज्यों की सरकारें स्थापित हो और पुराने युजुंफ्रा साम्राज्य नष्ट हों। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर स्टालिन ने विश्व-समस्याओं के समाधान में समझौतावादी नीति न अपनाता ही उचित समझा। वह प्रडोमेवाजी की नीति पर चलकर शान्ति-व्यवस्था को टालना चाहता था ताकि संसार की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल हो जाए।

(ड) लौह-भावरण की नीति—स्टालिन को भय था कि यदि पाश्चात्य लोकतन्त्र के जीवाणु सोवियत संघ में प्रवेश कर गए तो वह साम्यवादी शासन के लिए एक अशुभ बात होगी। इसीलिए उसने लौह-भावरण (Iron Curtain) की नीति अपनायी ताकि रूस को सभी प्रकार के पश्चिमी प्रभावों से प्रवृत्ता रखा जा सके। महायुद्ध के तुरन्त बाद संयुक्तराज्य अमेरिका और पश्चिमी राज्यों ने साम्यवाद के विरुद्ध जोर-शोर से जहरीला प्रचार शुरू कर दिया। साम्यवादी देशों के इंदे-गिंदे अज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए जिनके नाम 'आजाद हंगरी रेडियो', 'आजाद पोलैण्ड रेडियो' आदि रहे गए। किन्तु स्टालिन भी पूरा 'घाय' था। उसने विभिन्न प्रतिबन्ध लगाकर साम्यवादी जगत् के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि साम्यवाद-विरोधी प्रचार प्रवेश न कर सके। स्टालिन ने रूस और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को गैर-साम्यवादी देशों के सम्पर्क से पृथक् रखने का निश्चय कर लिया था। कठोर कानूनों द्वारा सन् 1945 से ही रूसियों का बाह्य जगत् के साथ सम्पर्क रोक दिया गया। उदाहरणार्थ, एक कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि युद्ध के समय रूस में आए हुए विदेशी सैनिकों के साथ जिन रूसी स्त्रियों ने विवाह किया था वे अपने पतियों के पास विदेश नहीं जा सकेंगी। एक अन्य कानून द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहों पर रोक लगा दी गई। विदेशी राजदूतों और पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी बहुत कठोरता का व्यवहार किया गया। विदेशों में स्थित सोवियत राजदूतों पर भी कठोर अनुशासनात्मक प्रतिबन्ध लगाए गए।

(च) 'शान्तिवादी आन्दोलन' की कूटनीति—सोवियत रूस के पक्ष में एशिया और प्रशिया का समर्थन प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने युद्ध के कुछ ही समय बाद 'शान्ति आन्दोलन' (Peace Offensive) आरम्भ किया। पूँजीवादी पश्चिम को 'युद्ध-तोलुप' (War-monger) कहा गया। सन् 1950 में स्टॉकहोम की विश्व-शान्ति समिति द्वारा आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाने की अपील पर उचित समय पर लगभग 50 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त कराए गए। इस शान्ति आन्दोलन ने एशिया और प्रशिया की विशाल जनसंख्या को बहुत प्रभावित किया।

वे साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे तथा सोवियत संघ को पश्चिम की तुलना में अधिक शान्तिप्रिय और साम्राज्य विरोधी मानने लगे। साम्यवादियों ने इस आन्दोलन में सब देशों के मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों से सहयोग माँगा। जहाजी श्रमिकों में यह प्रचार किया गया कि अमेरिका से शस्त्रास्त्रों को लाने वाले जहाजों से माल न उतारा जाए और हड़ताल कर दी जाए। प्रचार की दृष्टि से शान्तिवादी आन्दोलन को प्रारम्भ में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि स्टालिन अपने अनुदार दृष्टिकोण के कारण इस आन्दोलन से रुस को अधिक लाभान्वित नहीं कर सका, तथापि विश्व के देशों में रुसी शक्ति और रुसी क्षमता की चर्चा होने लगी। पश्चिमी देश भी यह समझ गए कि यदि पूँजीवादी गुट में अमेरिका जैसी महाशक्ति है तो, साम्यवादी गुट में रुस जैसी महाशक्ति है जो अमेरिका को टक्कर देने में सक्षम है।

(घ) रुस द्वारा विनाश के घावों को धो डालना—रुस ने महायुद्ध के फोड़ों की थोड़े ही समय में आश्चर्यजनक रूप से मलहम-पट्टी कर ली। रुसी नागरिकों में आत्म-विश्वास का अभूतपूर्व प्रादुर्भाव हुआ। रुस ने समाजवादी पद्धति के कारण, द्रुत गति से अपना पुनर्निर्माण कर लिया और नाजी आक्रमण की कड़वी स्मृतियों को मिटा डाला। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी रुसी सेना में कोई विशेष कमी नहीं की गई, इसके विपरीत आधुनिकतम शस्त्रास्त्र बनाने पर विशाल धनराशि व्यय की गई।

(ज) अणु-शक्ति पर अमेरिका के एकछत्र स्वामित्व को भंग करना—सैनिक स्तर पर सच्चे अर्थों में एक महाशक्ति बनने के लिए यह आवश्यक था कि रुस भी अमेरिका के समान अणु-शक्ति का स्वामी बनता। रुस ने इस दिशा में प्राणपण से चेष्टा की और अगस्त, 1953 में अपना प्रथम आणविक विस्फोट किया। इससे रुस की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए तथा उसे संयुक्तराज्य अमेरिका का वास्तविक प्रतिद्वन्द्वी माना जाने लगा। रुस ने अल्पकाल में ही विभिन्न प्रकार के अणु-आयुधों और अणु-बमों का निर्माण कर अमेरिका के लिए गम्भीर चुनौती प्रस्तुत कर दी।

(झ) नाटो के जवाब में वारसा-पैक्ट—पश्चिमी राष्ट्रों और अमेरिका के सैन्य-संगठनों के जवाब में रुस ने भी ऐसे संगठनों की स्थापना की। सन् 1955 में वारसा-पैक्ट की स्थापना कर नाटो की ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। विभिन्न राष्ट्रों के साथ सैनिक सन्धियों की भी गई।

इस प्रकार द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में दो महाशक्तियों का उदय हुआ—संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व में शक्ति के दो प्रमुख केन्द्र उभर कर सामने आए और लगभग सन् 1954-55 तक विश्व में दृढ़ द्वि-ध्रुवीयता (Tight Bipolarity) का बोलबाला रहा। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे की जबरदस्त प्रतियोगी बन गईं और दोनों ही के नेतृत्व में दो विरोधी गुटों का निर्माण होता गया। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा विशेषकर यूरोप में बहुत तीव्र रही जिससे न केवल शीत-युद्ध में तीव्रता आई बल्कि प्रतिद्वन्द्वी सन्धियों और अनेक सैनिक गुटों का निर्माण भी तेजी से हुआ। सन् 1955 के प्रारम्भ में स्थिति यह थी कि जहाँ विश्व-शान्ति और

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता केवल 59 सम्प्रभु राज्यों तक सीमित थी वहाँ अमेरिका और ब्रिटेन एक ओर तथा रूस और अन्य राष्ट्र दूसरी ओर लगभग 60 से भी अधिक राज्यों के साथ बँधे थे।¹ सन् 1955 के मध्य द्वि-ध्रुवीयता शिथिल होने लगी और घारा बहुकेन्द्रवाद (Polycentricism) की ओर बहने लगी। आज यद्यपि शक्ति के अनेक केन्द्र, कम से कम चार या पाँच उभर आए हैं फिर भी महाशक्तियों के रूप में वस्तुतः अमेरिका और रूस की ही गणना की जाती है। निकट भविष्य में साम्यवादी चीन और भारत भी महाशक्तियों का दर्जा पा सकेंगे, इसकी सम्भावनाएँ प्रबल हैं।



निःशस्त्रीकरण की समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी विश्व-शान्ति की। आज के आणविक युग में तो यह समस्या हमारे जीवन-मरण की समस्या बन गई है। शस्त्रास्त्रों के इस भयावह सक्त के बावजूद शस्त्रीकरण की होड़ इसीलिए जारी है कि आज राष्ट्रो में सम्बन्ध पारस्परिक अविश्वास और दूसरे राष्ट्रो के इरादों के बारे में निरन्तर भय से ओत प्रोत हैं। निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की उन समस्याओं में से हैं जो निरन्तर विचार-विमर्श के बावजूद गम्भीरतम रूप धारण किए हुए हैं। अनवरत प्रयासों के बावजूद शस्त्रीकरण की होड़ तेजी से जारी है।

निःशस्त्रीकरण : अर्थ एवं प्रकार

अमेरिका की इस्टीमेटेड फोर डिफेंस अनालिसिस (वाशिंगटन डी. सी.) ने निःशस्त्रीकरण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है—

“कोई भी एक योजना, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निःशस्त्रीकरण के किसी भी एक पहलू—जैसे सरया, प्रकार, शस्त्रों की योजना-प्रणाली, उसका नियन्त्रण, उनकी सहायता के लिए पूरक यन्त्रों का निर्माण, प्रयोग व वितरण, गुप्त सूचनाएँ एकत्र करने के समन्त्र, सेना का सत्यात्मक स्वरूप, आदि को नियमित करने से संबंधित हो, निःशस्त्रीकरण की श्रेणी में आती है।”

सामान्य अर्थ में निःशस्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शस्त्रों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त कर देना है। प्रो. मॉर्गेन्थो के अनुसार “निःशस्त्रीकरण से आशय शस्त्रों की होड़ समाप्त करने के लिए अथवा शस्त्रों को कम या समाप्त कर देने से है।”

निःशस्त्रीकरण सामान्य (General), स्थानीय (Local), मात्रात्मक (Quantitative), गुणात्मक (Qualitative) कैसा भी हो सकता है। सामान्य निःशस्त्रीकरण में लगभग सभी राष्ट्र सम्मिलित होते हैं जैसे सन् 1932 का विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। स्थानीय निःशस्त्रीकरण में कुछ ही राष्ट्र भाग लेते तथा प्रभावित होते हैं। मात्रात्मक निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य सभी प्रकार के शस्त्रों पर

नियन्त्रण से है जबकि गुणात्मक निःशस्त्रीकरण के अनुसार किन्हीं विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम प्रचारा समाप्त करने की तिकारिण की जाती है। जब हम पूर्ण निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने से होता है।

निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम को कतिपय क्षेत्रों में 'शस्त्र-नियन्त्रण' (Arms Control) कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। यह माना जाता है कि निःशस्त्रीकरण के अनुसार तो राष्ट्रों के पास शस्त्र होने ही नहीं चाहिए, किन्तु पूर्ण निःशस्त्रीकरण कोई नहीं चाहता क्योंकि आन्तरिक व्यवस्था, अप्रत्याशित बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए कुछ शस्त्र सैन्य-बल अपेक्षित है। अतः समस्या 'शस्त्र-नियन्त्रण' (Arms Control) की है, पूर्ण निःशस्त्रीकरण की नहीं। वेजले डब्ल्यू पोस्वार (Wesley W Posvar) ने अपने लेख 'The New Meaning of Arms Control' में लिखा है कि "निःशस्त्रीकरण का अभिप्राय सेनाओं और शस्त्रों को घटा देना या समाप्त कर देना है जबकि शस्त्र-नियन्त्रण में वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य युद्ध के सम्भावित और विनाशकारी परिणामों को रोकना (विशेषकर आणविक युद्ध के परिणामों को) है। इसमें सेनाओं तथा शस्त्रों को घटाने या न घटाने का विवेक महत्त्व नहीं है।"

अधिकांश अमेरिकी लेखकों और राजनीतिक विचारकों ने निःशस्त्रीकरण के स्थान पर 'शस्त्र-नियन्त्रण' शब्द का प्रयोग किया है। सोवियत रूस तथा उसके सहयोगी निःशस्त्रीकरण पर ही नहीं बल्कि पूर्ण निःशस्त्रीकरण पर जोर देते हैं। निरपेक्ष दृष्टि से देखने पर शस्त्र-नियन्त्रण ही अधिक सार्थक और व्यावहारिक प्रतीत होता है जबकि निःशस्त्रीकरण एक ऐसा आदर्श दिखाई देता है जो सोचने, कहने और विवाद करने के लिए भले ही ठीक हो, पर व्यवहार में दुष्प्राप्य है।

निःशस्त्रीकरण अपने आप में समस्या का समाधान न होकर एक माध्यम मात्र है जो सभी सार्थक हो सकता है जब वह उद्देश्यपूर्ण तथा योजनाबद्ध हो। शस्त्रीकरण का निषेध अथवा कमी करने के लिए अविश्वास, प्रतिस्पर्धा, शोषण, आदि के विपरीत अच्छे विकल्प ढूँढने होंगे और राष्ट्रीय हित की परिभाषा अधिक विचारपूर्ण ढंग से करनी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए शान्ति-पूर्ण उपायों की सम्भावनाएँ मजबूत मन से खोजनी होंगी अन्यथा मात्र शस्त्रों में कुछ कमी कर देने से निःशस्त्रीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हार्बर्ड विश्वविद्यालय के प्रो. रॉयट्स कोवी के इस अभिमत से सहमत होना कठिन है कि कोई भी निःशस्त्रीकरण-योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक राष्ट्रों को यह विश्वास न हो जाए कि उनके राष्ट्रीय हित और सुरक्षा निरापद है। इस आश्वासन का एक तरीका, जो सम्भवतः काफी प्रभावशाली होगा, अधिक से अधिक राज्यों को शस्त्र-नियन्त्रण योजनाओं से सम्बद्ध करना है। यद्यपि शस्त्रास्त्रों की बढ़ती हुई विनाशकता स्वयं अपने आप में उन शस्त्रों के प्रयोग को सीमित कर देती है, तथापि प्रयोग की सम्भावना का निषेध नहीं किया जा सकता और आज के आणविक अस्त्रों के प्रयोग का अर्थ है 'महाविनाश'।

निःशस्त्रीकरण : क्यों ?

शान्ति-स्थापना के लिए

अपने सामान्य और सार रूप में निःशस्त्रीकरण की धारणा में विश्व-शान्ति और सुरक्षा की आशाएँ निहित हैं। शस्त्रास्त्र एक राष्ट्र की विदेश-नीति को सैनिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिसमें युद्ध और संघर्ष की सम्भावनाएँ सदा जीवित, जाग्रत और प्रबल रहती हैं। श्री कोहन के अनुसार, "निःशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के भय और मतभेद को कम करके शान्तिपूर्ण समझौतों की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है।"

निःशस्त्रीकरण और शान्ति के सम्बन्ध में विचार-मतेष्व नहीं पाया जाता। हैडले बुल का तर्क है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता और तनावपूर्ण स्थितियाँ ही युद्ध के वास्तविक कारण हैं क्योंकि इनसे ही शस्त्रास्त्रों की भीषण प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है जिसका अन्तिम परिणाम युद्ध और विनाश होता है। प्रो. झूमैन के अनुसार संघर्ष की आशंका ही शस्त्रीकरण की होड़ को जन्म देती है और युद्ध की सम्भावना से शस्त्रों में वृद्धि होती है। यह मानना कि शस्त्रों के कारण युद्ध होते हैं गाड़ी को घोड़े के आगे खड़ा करना है। कुछ विद्वानों का मन है कि शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा से अनिवार्यतः युद्ध नहीं होने और यह भी आवश्यक नहीं है कि निःशस्त्रीकरण से अवश्यम्भावी रूप में शान्ति और सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी। मूल समस्या तो अन्तर्राष्ट्रीय मद्भावना की है। बिजली राइट का मत एकदम विपरीत है। उनका विचार है निःशस्त्रीकरण को शान्ति तथा सुरक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं माना जा सकता। निःशस्त्रीकरण से तो युद्ध के बार-बार होने की सम्भावना (Frequency) बढ़ जाती है। शस्त्रास्त्रों के अभाव में राज्य दूसरे राज्यों के आक्रामक कार्यों और इरादों का मुकाबला नहीं कर पाते। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध मुख्यतः इसीलिए हुए थे कि बड़े राष्ट्रों ने निःशस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास किया था।

स्पष्ट है निःशस्त्रीकरण का विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की अत्यन्त जटिल और विवादास्पद समस्या है पर मतभेदों के बावजूद इस तथ्य को नहीं ठुकराया जा सकता कि निःशस्त्रीकरण समय की माँग है और इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्वास के नए द्वार खोले जा सकते हैं। यदि हम अपने व्यवहार में शान्ति के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण अपना लें तो निःशस्त्रीकरण के प्रयास बड़ी सीमा तक सफल हो सकते हैं।

आर्थिक कल्याण और पुनर्निर्माण के लिए

निःशस्त्रीकरण के पक्ष में यह आर्थिक तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि शस्त्रों की दौड़ के स्थान पर 'शान्ति के लिए दौड़' शुरू होने पर मानव-समाज की समृद्धि का मार्ग अधिक प्रशस्त होगा तथा विश्व के औद्योगीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नूतन युग का सूत्रपात होगा। संयुक्त राष्ट्रमण्डल के एक अध्ययन के अनुसार सेना पर होने वाला सस्तर का कुल व्यय सन् 1971 तक 18700 सरब डालर (140250

लाख रुपये) तक पहुँच गया था। सन् 1961 से 1971 के बीच दस वर्षों में सरकार का रक्षा-व्यय 500 खरब डालर (3750 खरब रुपये) से बढ़कर 2000 खरब डालर (15000 खरब रुपये) वार्षिक हो गया जो विश्व की कुल राष्ट्रीय आय का साढ़े छ प्रतिशत था। पश्चिमी एशिया में सन् 1974 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन 845 डालर था और सेवा पर प्रति व्यक्ति खर्च 135 डालर। सन् 1975 के वित्तीय वर्ष में अकेले अमेरिका ने 71 देशों को 9.5 मिलियन डालर के अस्त्र-शस्त्र बेचे। जरा कल्पना कीजिए कि यदि इस विपुल धनराशि का अनुपयोग विश्व की पीड़ित और अभावग्रस्त जनता के लिए किया जाता तो मानवता का कितना भला होता।

कतिपय क्षेत्रों में कहा जाता है कि निःशस्त्रीकरण के फलस्वरूप मन्दी का दौर शुरू होगा जिसके भीषण परिणाम लोगों को भुगतने पड़ेंगे, साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी प्रवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार की भ्रांशकाओं में अधिक वजन नहीं है। निःशस्त्रीकरण के फलस्वरूप जो रचनात्मक वातावरण पनपेगा, उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की क्षमताएँ प्रवरुद्ध नहीं होंगी। इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि के इतने विशाल स्रोत खुल जाएँगे जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अवश्य ही हमें 'शस्त्रीकृत अर्थव्यवस्था' को 'निःशस्त्रीकृत अर्थव्यवस्था' में परिवर्तित करने की समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा।¹

समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए

निःशस्त्रीकरण से विश्व-राज्य के निर्माण की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी, महायुद्ध का सम्भावित खतरा टल जाएगा तथा राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का मार्ग प्रशस्त होगा। शीत-युद्ध का ज्वर कम होगा, आतंक के वादल छूटेंगे और राष्ट्रों के विवाद बड़ी सीमा तक गोलमेगोल सम्मेलनों में तय होने लगेंगे।

नैतिक वातावरण के निर्माण के लिए

निःशस्त्रीकरण नैतिक रूप से भी आवश्यक है क्योंकि 'किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अन्य राष्ट्रों की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य तथा जीवन को रेडियो सक्रिय धूल तथा सामरिक तैयारी द्वारा अनेक खतरों में डाले।' सैद्धान्तिक रूप से नैतिक आधार पर निःशस्त्रीकरण का प्रतिपादन उचित है, लेकिन यथार्थवादी राष्ट्रीय राजनीति में इसका विशेष प्रभाव नहीं होता। उदाहरण के लिए, भारत जैसे शान्तिप्रिय राष्ट्र के प्रति चीन और पाकिस्तान के खड़े को देखते हुए इकतरफा निःशस्त्रीकरण का कोई भी कदम उठाना देश के लिए आत्मघातक होगा।

आणविक संकट से बचने के लिए

आज के युग में आणविक युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग निःशस्त्रीकरण अथवा शस्त्रों पर प्रभावशाली नियन्त्रण ही है। खतरनाक शस्त्रों पर

रोक लगाने तथा उन्हें सीमित कर देने से चाहे आक्रमण रोके न जा सकें, किन्तु उनको कम, मर्यादित और अपेक्षाकृत कम विध्वंसक बनाया जा सकेगा। निःशस्त्रीकरण के फलस्वरूप प्रथम तो कोई भी राष्ट्र तुरन्त एवं व्यवस्थित रूप से युद्ध छेड़ने में असमर्थ हो जाएगा और दूसरे, राष्ट्रों के मध्य द्वेषपूर्ण सम्बन्धों में कमी हो जाने से राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक समायोजन के अनुकूल वातावरण बन जाएगा। नाभिकीय तथा आणविक शस्त्रास्त्र ही आज राष्ट्रों के मनो को आतंकित किए हुए हैं। दूसरी ओर यह तर्क भी दिया जाता है कि आज महाशक्तियों की नाभिकीय एवं आणविक शक्ति ने आतंक का जो मन्तुलन स्थापित किया हुआ है उसी से विश्व में शान्ति कायम है, अन्यथा तृतीय महायुद्ध कभी का छिड़ गया होता। इस तर्क में वजन है तथापि यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध की निरन्तर सम्भावनाओं और आशंकाओं से बचने का मार्ग निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण का है, शस्त्रीकरण का नहीं।

निष्कर्ष रूप में, आधुनिक परिस्थितियों ने विश्व के राष्ट्रों के लिए निःशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाना श्रेयस्पर है। युद्ध और शान्ति का चक्र न कभी मिटा है और न कभी सम्भव मिट सकेगा, मतः प्रयत्न इसी दिशा में होना चाहिए कि युद्ध की विनाशक-शक्ति घट जाए। इस दृष्टि से नाभिकीय तथा आणविक हथियारों के भावी निर्माण पर ईमानदारी से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और इस प्रकार के उपलब्ध हथियारों को विनष्ट कर देना चाहिए। यह कार्य जोर-जबर्दस्ती न होकर स्वेच्छा से होना चाहिए और इसके लिए सभी राष्ट्रों को ईमानदारी से परस्पर सहयोग करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों पर शोध करने वाली समिति ने सन् 1960 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि—“चूंकि महा परमाणु-युद्ध सम्पूर्ण विश्व के लिए विनाशकारी होगा, अतः जब महाशक्तियाँ पारस्परिक प्रविश्वास व प्रतिस्पर्धा को भुलाकर परमाणु-शक्ति के उत्पादन, परमाणु-अस्त्रों के निर्माण, नियन्त्रण एवं वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं प्रतिबन्ध के लिए सहयोग करने को तैयार होंगे। परमाणु-अस्त्रों के परीक्षणों पर नियन्त्रण लगाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।”

द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में निःशस्त्रीकरण के प्रयास

द्वितीय महायुद्ध के बाद के निःशस्त्रीकरण-प्रयासों को हम मोटे रूप में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—प्रथम भाग के अन्तर्गत उस समय तक की चर्चाएँ सम्मिलित की जा सकती हैं जब केवल अमेरिका ही अणु-बम का स्वामी था, द्वितीय भाग का आरम्भ तब से माना जा सकता है जब सोवियत संघ ने भी अणु-बम का निर्माण कर लिया। निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही युटो में विरोधी दृष्टिकोण मिलता है और इस दिशा में विज्ञान वाले प्रयासों का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ भी है तथा निजी चर्चाएँ भी। द्वितीय महायुद्ध के बाद

निःशस्त्रीकरण की दिशा में जो भी प्रयास हुए हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों में व्यक्त करना उपयुक्त होगा—

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था

संघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण को महासभा और सुरक्षा परिषद् दोनों की ही कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 11, 26 एवं 47 में तत्सम्बन्धी व्यवस्थाएँ हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने प्रारम्भ से ही निःशस्त्रीकरण की समस्या पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया था। जनवरी, 1946 में संघ द्वारा अणु-शक्ति आयोग (Atomic Energy Commission) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जिसके अन्तर्गत राष्ट्र परमाणु-शक्ति के उत्पादन को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में रखने तथा अणु-शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने की सहमत हो सकें तथा आणविक अस्त्रों के प्रयोग व उत्पादन पर पूरा नियन्त्रण लगाया जा सके। अणु-शक्ति आयोग को वांछित सफलता नहीं मिली। अतः दिसम्बर, 1946 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका आशय था कि अणु-शक्ति आयोग अपने कार्य में तेजी लाए और सुरक्षा परिषद् शीघ्रतापूर्वक अस्त्रों के घटाने तथा उनका नियमन करने की व्यावहारिक योजनाएँ बनाए। शीघ्र द्विपरिषद् द्वारा 'परम्परागत शस्त्र आयोग' (The Commission for Conventional Armaments) गठित किया गया जिसका कार्य केवल परम्परागत शस्त्रों की सीमित एवं नियमित करने सम्बन्धी प्रस्ताव रखना ही था, अणु-शस्त्रों और विनाश के व्यापक साधनों से इसका सम्बन्ध नहीं था।

दोनों आयोगों की स्थापना भी हो गई, महाशक्तियों द्वारा विभिन्न प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए लेकिन सभी प्रयासों का परिणाम कुल मिलाकर शून्य रहा। शान्ति की दिशा में बढ़ने के बजाय इन प्रयासों ने शीतयुद्ध को प्रोत्साहन दिया। अमेरिका ने एक अन्तर्राष्ट्रीय आणविक विकास-संस्था के निर्माण का सुझाव रखा जो परमाणु-शक्ति के उत्पादन से सम्बन्धित कच्चे माप पर भी नियन्त्रण लगाए। सोवियत रूस ने सुझाव दिया कि वर्तमान परमाणु अस्त्रों को नष्ट कर दिया जाए और उत्पादनात् सुझावों को कार्यान्वित किया जाए। महाशक्तियों के पारस्परिक विरोधी दृष्टिकोण के फलस्वरूप निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी।

सन् 1947 से 1954 तक कई छुट-पुट प्रयास हुए। सन् 1954 के प्रारम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति एजेंसी (International Atomic Energy Agency) अस्तित्व में आई जिसने एक पंचराष्ट्रीय उप-समिति की स्थापना की। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और रूस इसके सदस्य थे। अनेकों बैठकों के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकला। स्थिति यह रही कि एक पक्ष की ओर से निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव आते और दूसरे पक्ष द्वारा ठुकरा दिए जाते।

जेनेवा-सम्मेलन, 1955 से 1960 तक

जुलाई, 1955 में जेनेवा में रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रान्स का सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन होवर ने 'खुली आकाश योजना' (Open Skies Plan) प्रस्तावित की। इसका आशय था कि अमेरिका और रूस दोनों ही अपने सैनिक बजट उत्पादन, वर्तमान शक्ति एवं उसके विकास की सम्भावनाओं के बारे में एक दूसरे को सूचना दें तथा परस्पर जाँच एवं निरीक्षण के लिए सहमत हों। एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाए। सोवियत प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने अमेरिकी योजना को अस्वीकार करते हुए अपना यह प्रस्ताव रखा कि निःशस्त्रीकरण को क्रियान्वित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण-अभिकरण की स्थापना की जाए और उसे निरीक्षण का कार्य सौंपा जाए, सभी देशों से विदेशी सैनिक गृह्यो को समाप्त कर दिया जाए, आणविक-शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए और परम्परागत शस्त्रों में निश्चित कटौती की जाए।

जेनेवा-सम्मेलन असफल रहा। दिसम्बर, 1955 में भारत ने अणु-शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग की और शस्त्रों से सम्बन्धित एक अल्पकालीन सन्धि का भी सुझाव दिया, किन्तु अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया। जून, 1956 में संयुक्त राष्ट्रसंघीय निःशस्त्रीकरण आयोग की उप-समिति की बैठक में रूस ने त्रिसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया—(1) दो वर्षों के लिए आणविक परीक्षण बन्द कर दिए जाएँ, (2) इस प्रतिबन्ध को लागू करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग बँठाया जाए, एवं (3) आयोग महिन रूस अमेरिका और ब्रिटेन प्रशान्त महासागर में नियन्त्रण चौकियाँ स्थापित करें। रूसी प्रस्ताव पश्चिमी राष्ट्रों को मान्य नहीं हुए। लन्दन-सम्मेलन की असफलता धोपित कर दी गई।

नवम्बर, 1957 में निःशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार किया गया। अभी तक पश्चिमी राष्ट्रों को रूसी वैज्ञानिक परीक्षणों की गोपनीयता से चिन्ता थी और वे जाँच तथा निरीक्षण पर जोर दे रहे थे, लेकिन अगस्त, 1957 में रूस ने अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों (ICBM) के सफल परीक्षण की घोषणा कर और अक्टूबर, 1957 में एक कृत्रिम उपग्रह (Sputnik) छोड़कर पश्चिमी जगत् को स्तब्ध कर दिया।

दोनों पक्षों की ओर से निःशस्त्रीकरण-प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और अस्वीकृत करने का क्रम जारी रहा। फरवरी, 1958 में रूसी प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने एक योजना प्रस्तावित की जिसके मुख्य पहलू ये थे—(1) अणु-बम परीक्षण बन्द किए जाएँ, (2) अमेरिका रूस व ब्रिटेन आणविक शस्त्रों का परिचालन कर दें, (3) जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं को घटाया जाए, (4) नाटो तथा वारसा पैक्ट के देशों में अनाक्रमण समझौता हो, एवं (5) आक्रामक आक्रमण रोके जाएँ। यह योजना निष्फल हुई। मार्च, 1958 के लगभग पोलैंड के विदेश मंत्री ने 'रापाकी योजना' (Rapaki Plan) प्रस्तुत की जिसमें यूरोप की

सुरक्षा और शान्ति हेतु पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणु-विहीन क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया। यह प्रस्ताव भी निष्फल रहा। मार्च, 1958 में सुप्रीम सोवियत के एक प्रस्ताव में कहा गया कि सोवियत सभ इस आशा से सभी प्रकार के आणविक परीक्षण बन्द कर रहा है कि अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे, किन्तु यदि दूसरे देशों द्वारा आणविक परीक्षण बन्द न किए गए तो वह अपने परीक्षण पुनः प्रारम्भ कर देगा। अमेरिका द्वारा उत्तर दिया गया कि यदि उसे रूसी परीक्षणों के बन्द होने का निश्चय हो गया तो वह भी अपने परीक्षण बन्द करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा। अक्टूबर, 1958 में जेनेवा-सम्मेलन में निःशस्त्रीकरण पर अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, पर कोई उपयोगी समझौता नहीं हो सका।

सन् 1959 में रूसी प्रधान मंत्री ख्रुश्चेव ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में पूर्ण निःशस्त्रीकरण का एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि चार वर्ष की अवधि में सभी राज्य पूर्ण निःशस्त्रीकरण करें ताकि किसी राज्य के पास युद्ध करने का कोई साधन न रह जाए। साथ ही उन्होंने एक आंशिक निःशस्त्रीकरण की योजना भी प्रस्तावित की जिसमें कहा गया कि नाटो-सदस्यों तथा पश्चिमी राज्यों के साथ वारमा पेंवट के सदस्यों की अनाक्रमण सन्धि सम्पन्न हो, एक राज्य का दूसरे राज्य पर आकस्मिक आक्रमण रोकने के बारे में समझौता हो, मध्य यूरोप में अणु-प्रायुध-विहीन क्षेत्र कायम किया जाए आदि। रूसी प्रस्ताव का सब देशों ने स्वागत किया, लेकिन पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसे उपहास का विषय बना दिया गया और इस प्रकार गतिरोध बना रहा। सन् 1960 में भी जेनेवा-सम्मेलन हुआ, पर प्रसफल रहा। जुलाई, 1960 से 1973 तक

जून, 1960 में दस राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भग हो जाने के कुछ ही माह बाद सोवियत रूस ने 50 मेगाटन शक्ति के अणु-बम का परीक्षण किया। नवम्बर, 1961 में महासभा ने यह भारतीय प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि आणविक परीक्षणों पर जब तक कोई समझौता न हो जाए तब तक इनको बन्द हो रखा जाए। एक अन्य प्रस्ताव में महासभा ने कहा कि यदि किसी देश द्वारा अणु-शस्त्री का प्रयोग किया गया तो इसे घाटेर का उत्प्लवन माना जाएगा। मार्च, 1962 में विदेश-मन्त्रियों के सम्मेलन को निःशस्त्रीकरण-प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी समय जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन हुआ जिसमें भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि आणविक परीक्षणों का पता लगाने के लिए तटस्थ राष्ट्रों के स्टेशन कायम किए जाएं। रूसने प्रस्ताव रखा कि दोनों ही पक्ष सहमत हो जाएं कि दूसरे देशों की भूमि में तीन महान् आणविक शक्तियाँ आणविक-अणु कायम नहीं करेंगी। सम्मेलन में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों का महत्व केवल कागजी रहा।

कैंडी और ख्रुश्चेव के प्रयत्नों से निःशस्त्रीकरण-वार्ता में कुछ प्रगति हुई और मास्को में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने 15 जुलाई, 1963 को 'सीमित परमाणु-प्रतिबन्ध-सन्धि' पर हस्ताक्षर किए। 10 अक्टूबर, 1963 से सन्धि लागू

हुई। उस समय तक लगभग 100 राष्ट्र इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। सन्धि के अन्तर्गत तीनो देशो ने स्वीकार किया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत बाह्य अन्तरिक्ष, प्रादेशिक तथा महायुद्ध या वायुमण्डल में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। सन्धि प्रमोदित अवधि के लिए की गई तथापि हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को अधिकार दिया गया कि वे उस समय स्वयं को इस सन्धि की बाध्यताओं से मुक्त रक्त रख सकते हैं जब वह समझें कि सन्धि से सम्बन्धित कोई ऐसी अमामान्य घटना घटी है जिससे सम्बन्धित देश का सर्वोच्च हित सवट में पड़ गया है। सन्धि में अन्य सदस्यों को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था भी की गई वशर्ते कि वे इसकी मौलिक धाराओं से सहमन हो। इस सन्धि में भूमिगत परीक्षणों पर प्रतिबन्ध की बात नहीं की गई। इसका मुख्य कारण यह था कि भूमिगत परीक्षणों की जाँच के लिए घटना-स्थल पर जाना अनिवार्य होता है जिनसे राज्य की प्रादेशिक मार्वाभौमिकता का उल्लघन होता है।

परमाणु-परीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि ने खुले तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बान-बौत का स्वस्थ वातावरण तैयार किया। पर मार्च, 1964 में जेनेवा-निःशस्त्रीकरण सम्मेलन का कोई सुपरिणाम नहीं निकला। कुछ ही दिनों बाद चीन ने अपने प्रथम अणु-बम का परीक्षण कर सन् 1963 के जेनेवा-समझौते की उपेक्षा की। नवम्बर, 1964 में महासभा ने एक प्रस्ताव में निःशस्त्रीकरण-प्रायोग से आग्रह किया कि परमाणु धातुधो के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई समझौता अवश्य होना चाहिए। जुलाई, 1965 में जेनेवा में निःशस्त्रीकरण-प्रायोग की बैठक पुन बुलाई गई, लेकिन धातुधो को नियन्त्रित करने के उपायो पर इतने मौलिक मतभेद थे कि कोई फल नहीं निकला।

निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयासों का क्रम चलता रहा और तब एक उल्लेखनीय सफलता मिली जबकि रूस व अमेरिका के बीच सन् 1968 की परमाणु-अस्त्र प्रसार-निरोध सन्धि (The Non-Proliferation Treaty, 1968) हुई, अन्य राज्य, विशेषकर यूरोप के राज्य, इससे आवश्यक नहीं थे। सन्धि का मसविदा बड़ा लम्बा-चोड़ा था। सारांशतः उसकी मूल धारें ये थी—(1) परमाणु-अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र, परमाणु-अस्त्र-विहीन राष्ट्रों को परमाणु-अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, (2) हस्ताक्षरकर्त्ता परमाणु-अस्त्र-विहीन राष्ट्र परमाणु-अस्त्र बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, (3) हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को असैनिक कार्यों के लिए परमाणु-शक्ति का विकास करने की पूरी छूट रहेगी।

अनेक राष्ट्रों की आपत्तियों के बावजूद जून, 1968 में संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा ने सन्धि पर अपनी स्वीकृति दे दी। यद्यपि इस समझौते से यह स्पष्ट हो गया कि महाशक्तियाँ परस्पर सहयोग करें तो सभी गम्भीर समस्याओं को सुलझ सकती हैं तथापि इस सन्धि का बहुत से राष्ट्रों ने स्वागत नहीं किया। सन्धि की सबसे बड़ी कमी यह है कि एक ओर तो यह प्रतिबन्ध है कि जो राष्ट्र परमाणु-बम नहीं बना पाए हैं वे भविष्य में भी इस ओर कदम नहीं उठाएँगे और दूसरी ओर

उन्हें परमाणु आक्रमण से बचने के लिए आश्वामन दिया है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रणु-प्रायुधों से उनकी सहायता की जाएगी जिसका निर्णय सुरक्षा परिषद् करेगी। स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद् महाशक्तियों के हाथ का खिलौना है। फिर इस आशवासन का तब कोई महत्त्व नहीं रह जाता जब सुरक्षा परिषद् के किसी भी न्यायी सदस्य को किसी प्रस्ताव के वीटो करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने 'आक्रमण' शब्द की व्याख्या नहीं की है। अतः यह भ्रम बने रहने की सम्भावना है कि परिषद् किस हालत में किसको आक्रमणकारी समझेगी। भारत ने सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए। कारण स्पष्ट है कि उसे परमाणु-अस्त्र-सम्पन्न चीन से भारी खतरा है और सन्धि इस खतरे को दूर नहीं कर सकती।

सन् 1968 में परमाणु-अस्त्र विरोधी सन्धि के उपरान्त सन् 1972 के प्रारम्भिक चरण तक निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की जा सकी। सामरिक-प्रश्न-परिशीलन वार्ता के दौर चले, संयुक्त राष्ट्रसंघ निःशस्त्रीकरण समिति ने सभी देशों द्वारा जीवाणु अस्त्र-भण्डारों को नष्ट कर देने सम्बन्धी प्रारम्भ तैयार किया, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम निराशाजनक रहे। मई, 1972 के अन्तिम सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने मास्को की यात्रा की और दोनों देशों के बीच 'रूस-अमेरिका परमाणु परिशीलन सन्धि, 1972' सम्पन्न हुई। इस ऐतिहासिक सन्धि में दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करते हुए आत्म-विश्वास पर आधारित एक नया सन्तुलन कायम किया। इस पंचवर्षीय सन्धि में, जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल प्रमाणित होने पर किसी भी पक्ष द्वारा 6 मास के नोटिस पर रद्द की जा सकती है, स्वीकार किया गया है कि—(1) नए अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा, (2) कोई भी पक्ष हल्के या पुराने किस्म के भू-प्रक्षेपास्त्र-स्थलों को सुधार कर भारी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के लिए योजना नहीं बनाएगा, (3) दोनों पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों और प्रक्षेपास्त्रयुक्त आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण नहीं करेंगे, यद्यपि निर्माणाधीन पनडुब्बियों का कार्य पूरा करने की छूट रहेगी, (4) सन्धि की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आक्रामक प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों का आधुनिकीकरण करने अथवा स्थानांतरण अस्त्र बनाने का अधिकार दोनों देशों को प्राप्त होगा, एवं (5) सन्धि के अनुपालन की जाँच के लिए हर एक राष्ट्र केवल वही विधियाँ अपनाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।

वास्तव में इस सन्धि से भी निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। श्रीमती गाँधी की टिप्पणी थी कि अस्त्र-परिशीलन अपने आप में सही नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में शान्ति-स्थापना की दिशा में इससे कोई उपयोग नहीं मिलता। श्रीमती गाँधी ने यह भी कहा कि रूस और अमेरिका दोनों को यह आशवासन देना चाहिए कि परमाणु-अस्त्रों का उपयोग परमाणु अस्त्र-विहीन देशों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सन्धि इतनी आशिक है कि

परमाणु-अस्त्रों पर खर्च होने वाली राशि में कमी आने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण द्वारा उन्हें बेहतर या अधिक घातक बनाने की प्रतियोगिता कायम रहेगी।

मास्को में परमाणु परिसीमन सन्धि के सम्पन्न होने के बाद सन् 1973 के मध्य तक निःशस्त्रीकरण और अणु-शक्ति के परिसीमन के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी, इसके विपरीत निःशस्त्रीकरण-प्रयासों को ठेस पहुँची। मार्च, 1973 के समाचार-पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ कि चीन ने द्रव ईंधन से चालित एक ऐसा दूरगामी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र तैयार किया है जो सोवियत रूस के सबसे बड़े प्रक्षेपास्त्र से भी बड़ा है। चीन के नए महाप्रक्षेपास्त्र पर अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों द्वारा भी चिन्ता व्यक्त की गई। 27 जून, 1973 को चीन ने एक और परमाणु-विस्फोट किया जो 2 मेगाटन टी. एन टी शक्ति का था। विशेषज्ञों ने स्पष्ट मत प्रकट किया कि आणविक आयुध और प्रक्षेपास्त्र विकास की दिशा में चीन की प्रगति अन्य सभी देशों से तेज रही है।

1974-76 में परमाणु अस्त्र परिसीमन की दिशा में प्रगति

सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 27 जून से 3 जुलाई, 1974 तक तीसरी शिखर-वार्ता हुई जिसमें परमाणु अस्त्र परिसीमन पर कोई व्यापक समझौता तो नहीं हो सका, किन्तु भूमिगत परीक्षण पर प्रतिबन्ध तथा कुछ प्रक्षेपास्त्रों के परिसीमन आदि के बारे में समझौते हुए। 3 जुलाई, 1974 को जो दस वर्षों का आणविक आयुध-परिसीमन-समझौता हुआ उसे 31 मार्च, 1976 से लागू किया जाना निश्चिन किया गया। समझौते के अनुसार दोनों देशों ने 150 किलो टन से अधिक के भूमिगत आणविक परीक्षणों को रोकने तथा अपने प्रक्षेपास्त्रों पर नए सीमा लगाने का निश्चय किया। यह तय किया गया कि आन्तिमपूर्ण कार्यों के लिए किए गए विस्फोट इस आंशिक प्रतिबन्ध-व्यवस्था की परिधि में नहीं आएँगे। नवीन समझौते के अन्तर्गत दोनों पक्ष अपनी-अपनी प्रक्षेपास्त्र-व्यवस्था को 3 अक्टूबर 1977 से 2 अक्टूबर, 1978 के बीच एक बार तथा उसके उपरान्त पाँच वर्षों में एक बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेंगे। यह कार्य परस्पर सूचना के आदान-प्रदान के बाद ही किया जा सकेगा।¹

सन् 1974 में भूमिगत परमाणु-परीक्षण करने के बारे में जो उपर्युक्त समझौता हुआ उसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि वायुमण्डल को दूषित होने से बचाने और रेडियोधर्मिता के खतरे से बचने के लिए अब सभी परमाणु-परीक्षण भूमि के नीचे किए जाएँगे। लेकिन परमाणु-परीक्षण के खतरे से दुनिया को बचा के लिए इतनी ही सन्धि काफी नहीं थी, अतः जून, 1976 में एक नई धारा जोड़कर इस सन्धि को अधिक लाभकारी बना दिया गया। परमाणु-परीक्षण स्थल व जानकारी कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को देना नहीं चाहता था जिसका मतलब था

कि यह पता लगाना कठिन था कि परीक्षण शान्तिपूर्ण कार्य के लिए हुआ है या परमाणु अस्त्र बनाने के लिए। अतः यह बात स्वागत योग्य थी कि स्थल का निरीक्षण करने पर दोनों देश सहमत हो गए।

1977 में हथियारों की होड़ पुनः शुरू

जुलाई, 1977 के दिनमान में प्रकाशित समाचारों के अनुसार सन् 1977 में महाशक्तियों में हथियारों की होड़ एक बार फिर शुरू हो गई है। अमेरिका ने बी-1 बमवर्षक न बनाने का निर्णय तो लिया है साथ ही यह निर्णय भी किया है कि वह 'क्रूज' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करेगा। इससे पहले उसने न्यूट्रान बम का परीक्षण भी किया था। अमेरिका का उद्देश्य शायद सोवियत संघ को यह जतलाना था कि परमाणु अस्त्रों के क्षेत्रों में वह श्रेष्ठ स्थिति में है और साथ ही अपनी शक्तों पर सामरिक अस्त्र के प्रसार पर रोक लगाने सम्बन्धी वार्ता (साल्ट) में अपने तर्कों को प्राथमिकता देना था। लेकिन सोवियत संघ ने इन नए हथियारों की आलोचना करते हुए कहा है कि यह कंसे सम्भव है कि एक तरफ तो आप शान्ति और मानवाधिकारों के प्रति प्रेम जतलाएँ और दूसरी ओर नए हथियारों का निर्माण कर सारी मानवता को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दें। यह सब काम अमेरिका ही कर सकता है। छवी टिप्पणीकारों की मान्यता है कि सभी विश्लेषणकर्ता अनुभव करते हैं कि ऐसे नए हथियारों के निर्माण से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जटिलताएँ ही पैदा होंगी तथा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सामरिक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी वार्ता में गतिरोध उत्पन्न होगा।

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने पिछले 20 वर्षों के अनुसंधान के बाद हाल में एक नए बम का परीक्षण किया है। अमेरिका का यह नया अस्त्र है न्यूट्रान बम जो भवनों और सैनिक सस्थानों को हानि पहुँचाए बिना अपने लक्ष्य पर जाकर मनुष्यों तथा अन्य जीवों का विनाश कर सकता है। विस्फोट के बाद यह बम विकिरण छोड़ता है जो जीवों के सैलों में प्रवेश कर उन्हें अस्त-व्यस्त कर देता है जिसके कारण जीव जन्तु मर जाते हैं। इसकी एक विशेषता यह भी है कि लक्ष्य के आस-पास के सीमित क्षेत्र में ही इसका प्रभाव पड़ता है। इनके नर संहार को सैनिक ठिकानों तक ही सीमित रखा जा सकता है और हिरोशिमा तथा नागासाकी जैसे विस्फोट की कोई सम्भावना नहीं है। सन् 1952 में सोवियत संघ ने भी इसी प्रकार के बम के निर्माण के लिए प्रयोग किए थे किन्तु वह इस होड़ में अमेरिका से पिछड़ गया है। अमेरिका ने न केवल इसका परीक्षण कर लिया है बल्कि उसके विकास की योजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श के बाद अमेरिकी सेनेट ने 42 के मुकाबले 43 मतों से इस योजना पर होने वाले धन की भी स्वीकृति दे दी है।

निःशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाइयाँ

1. महाशक्तियाँ अपने शस्त्रास्त्रों के आधुनिकीकरण का मोह छोड़ने को तैयार नहीं हैं; अतः स्वाभाविक है कि देश के आधुनिकतम आयुधों के जवाब में दूसरा देश उससे भी बढ़कर आयुध बनाने की सोचता है और इस तरह जो भी निःशस्त्रीकरण-

समझीते होते हैं वे बहुत ही भौतिक और व्यवहार में प्रभाव-शून्य होते हैं। उदाहरणार्थ, जून-जुलाई, 1974 के शिखर-सम्मेलन में रूस और अमेरिका के बीच प्रभावी सामरिक अस्त्र-परिसीमन-समझौता न हो पाने के राजनीतिक क्षेत्रों में दो प्रमुख कारण बताए गए हैं—(क) हाल में अमेरिका के लक्ष्य भेदकर स्वतः लौट आने वाले एम. आई. आर. बी. प्रक्षेपास्त्रों के बारे में यह तथ्य सामने आया है कि प्रथम आक्रमण की स्थिति में ये प्रक्षेपास्त्र शत्रु के ठिकानों को उतनी क्षति नहीं पहुँचा पाएँगे जितनी उनसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि उनके आपस में टकराकर नष्ट हो जाने की अधिक सम्भावना है। प्रेक्षकों का मत है कि यह ज्ञात हो जाने के बाद अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग अधिक बड़े और ठिकाने पर सही मार करने वाले अस्त्रों के निर्माण के लिए सरकार पर दबाव डालेगा। हो सकता है कि इस स्थिति के कारण निक्सन ने सामरिक अस्त्र परिसीमन जैसा समझौता टालने का भी प्रयास किया हो। (ख) दूसरे कारण का सम्बन्ध सोवियत सघ से था। यह तो सन् 1972 में समझौते के समय ही स्पष्ट हो गया था कि जब तक दोनों महाशक्तियाँ आक्रमण और प्रतिरक्षा, दोनों ही दृष्टियों से परमाणु-अस्त्रों में समान स्तर पर नहीं पहुँच जाती, तब तक उनके बीच सामरिक-अस्त्र-परिसीमन सम्बन्धी पूर्ण समझौता नहीं हो सकेगा। आशा थी कि सोवियत सघ शीघ्र ही प्रक्षेपास्त्रों में अमेरिका के बराबर न सही, उसके निकट तो पहुँच ही जाएगा, किन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में अभी वह अमेरिका से पीछे है—न केवल इसलिए कि उसके विश्वभर में सैनिक अड़्डे न होने के कारण वह अमेरिका की समता नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास अमेरिका से कम परमाणु अस्त्र हैं।

इन परिस्थितियों में सामरिक अस्त्र-परिसीमन के बारे में किसी व्यापक समझौते की अपेक्षा कैसे की जा सकती है ?

2 कूटनीतिक और सैनिक क्षेत्रों में अमेरिका की परमाणु-शक्ति सोवियत सघ से बहुत अधिक आँकी जाती है और प्रक्षेपास्त्रों के बारे में लगभग तीन गुनी अधिक। फिर भी वह नए परमाणु-प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील है और अपने प्रयत्नों का औचित्य सिद्ध करने के लिए वह समय-समय पर सोवियत सघ की परमाणु-शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता रहा है। सन् 1960 में अपने चुनाव अभियान में जॉन एफ. केंनेडी ने यही किया। उसके बाद अमेरिका ने जब एम. आई. आर. बी. प्रक्षेपास्त्र-प्रणाली पर कार्य शुरू किया, तब भी यह कहा गया कि सोवियत सघ ने तालीन और गासोश नामक प्रतिरक्षात्मक प्रक्षेपास्त्र-प्रणालियों का विकास कर लिया है, अतः अमेरिका के लिए एम. आई. आर. बी. प्रणाली अनिवार्य हो गई है। लेकिन जब एम.आई.आर.बी. प्रणाली पर जोरों से काम होने लगा तो अमेरिका ने यह स्वीकार किया कि सोवियत सघ की उक्त प्रतिरक्षा व्यवस्था से उसे कोई खतरा नहीं है। फिर भी प्रक्षेपास्त्र निर्माण के व्यापक कार्यक्रम का औचित्य सिद्ध करने के लिए अगले कुछ वर्षों में या सन् 1980 के बाद सोवियत सघ द्वारा प्राप्य परमाणु क्षमता का तर्क दिया जा रहा है। यह एक ऐसा बहाना है जिसके रहते अस्त्र

दौड़ रोकने की बात नहीं की जा सकती क्योंकि इससे न तो अमेरिका के त्रिडेंट पनडुब्बियाँ और बी-1 बमवर्षक बनाने के कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही प्रतिरक्षा-व्यवस्था को उत्तरोत्तर सुदृढ़ करने का सोवियत संध का कार्यक्रम प्रभावित होगा। यह स्थिति सामरिक अस्त्र-परिसीमन-समझौते की सम्भावनाओं के प्रतिकूल है। उसके लिए तो आवश्यक है कि अमेरिका यह तथ्य स्वीकार कर ले कि वह परमाणु-प्रक्षेपास्त्रों में सोवियत संध से आगे है और इस दृष्टि से सोवियत संध को इस क्षेत्र में कुछ सुविधा प्रदान करे ताकि वह उसके समकक्ष आ सके।

3. अणु-शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों का निर्धारण अनेक आन्तरिक एवं बाह्य तत्वों में प्रभावित होता है। एक देश पहले अपने राष्ट्रीय हितों पर दृष्टि-पात करता है तथा बाद में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व हित को देखता है। इसी आधार पर फ्रांस ने परीक्षण-प्रतिरोध-सन्धि का समर्थन नहीं किया। दो या अधिक राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध आज इतने अस्थिर हैं कि कल का मित्र आज का शत्रु बन सकता है। इन परिस्थितियों में अणु-आयुधों के रहने से आक्रमणकारी पर प्रतिबन्ध लग जाता है और वह तुरन्त युद्ध छेड़ने का साहस नहीं कर पाता क्योंकि दूसरे देश की शक्ति उसका भी विनाश कर सकती है। अस्थिर सम्बन्धों का भय तथा इनमें निहित खतरे और प्रचोभन की भावनाएँ शस्त्रों को सीमित करने के मार्ग में बाधक बन जाती हैं। आजकल सैनिक तकनीक का इतना विकास हो चुका है कि निःशस्त्रीकरण के नाम पर किसी को भी धोखा दिया जा सकता है। शक्तिशाली शस्त्रों को गुप्त रखकर तथा ऊपरी सेना घटाकर निःशस्त्रीकरण का दिखावा किया जा सकता है। जब तक यह भय दोनों पक्षों के मन में रहेगा तब तक निःशस्त्रीकरण का भविष्य उज्ज्वल नहीं है।

4. राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निःशस्त्रीकरण की ज़िम्मेदारी की जाँच के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बनायी जाए। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतन्त्रता पर जो अकुल लगता है उसे मानने को कोई तैयार नहीं होता। यही कारण है कि निःशस्त्रीकरण योजना की सफलता से पूर्व विश्व-सरकार की स्थापना का, मुद्दा दिया जाता है।

5. निःशस्त्रीकरण के कारण एक देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। शस्त्रों के निर्माण पर व्यय होने वाली भारी राशि या अस्त्र-निर्माण बन्द कर देने पर रचनात्मक कार्यों में कैसे उपयोग किया जाएगा, उससे अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त होने से कैसे बचाया जाएगा आदि प्रांजकाएँ उठती हैं तथा यह आशा भी रहती है कि इसे अर्द्ध-विकसित देशों के विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भी सम्भव है कि निःशस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों का भय एवं आशा वास्तविक है। इस आशा एवं भय का पश्चिम के सम्पन्न समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी अनुमान का विषय है।

6 निःशस्त्रीकरण करते समय देशों के शस्त्रों का जो अनुपात निर्धारित किया जाता है उसके कारण देशों के बीच मन-मुटाव व अविश्वास की भावना पैदा होती है। शस्त्रों की सीमा-निर्धारण के समय प्रत्येक देश को दूसरे देश के प्रति यह शका रहती है कि शायद वह अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा विरोधी पक्ष की शक्ति घटाने का प्रयत्न कर रहा है। तकनीकी रूप से यह बड़ा कठिन काम है कि एक देश की सैनिक आवश्यकता का पता लगाया जाए तथा उसी अनुपात में उसकी सैनिक शक्ति को घटाया जाए। जॉन फॉर्स्टर डलेस के मतानुसार इसी समस्या के कारण अमेरिका द्वारा निःशस्त्रीकरण की योजनाओं का समर्थन सच्चे दिल से नहीं किया जा सका। इस समस्या के समाधान के लिए दो सुभाव प्रस्तुत किए जाते हैं—
(1) पूर्ण रूप से निःशस्त्रीकरण कर दिया जाए, (2) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस-शक्ति द्वारा देशों को सामूहिक सुरक्षा की गारण्टी दी जाए। किन्तु ये सुभाव भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक पहले शस्त्रों को कम न किया जाए, इसलिए अनुपात की समस्या मूल है।

7. यह कहा जाता है कि अविश्वासपूर्ण बनावरण में निःशस्त्रीकरण और शस्त्रों का नियन्त्रण तथा अन्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। यदि देशों में पारस्परिक विश्वास रहे तो शस्त्रों की आवश्यकता ही न रहे और निःशस्त्रीकरण की समस्या भी उत्पन्न न हो। पूर्ण अविश्वास की स्थिति अराजकता एवं तानाशाही में से एक को स्थापित कर देगी। यह भाशा की जाती है कि निःशस्त्रीकरण की समस्या के समाधान के बाद दोनों गुटों में विश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है। अविश्वास के कारण कोई समझौता नहीं हो पाता; होता भी है तो सच्चे रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाता।

8 एक समस्या यह सामने आती है कि पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निःशस्त्रीकरण किया जाए। ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधक हैं और एक का समाधान हो जाने पर दूसरे का समाधान सुगम है। यह सोचा जाता है कि शस्त्र भण्डों का कारण है और इनको घटाने से अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और सन्तुष्टि बढ़ेगी। किन्तु यह प्रयास एक पक्षीय होगा। होना यह चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास एवं प्रतिद्वन्द्विता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास किया जाए। मडरियाणा के शब्दों में, 'शस्त्रीकरण की समस्या का समाधान इस समस्या के अन्दर ही नहीं खोजा जा सकता, किन्तु इसके बाहर ही खोजा जा सकता है।' यथार्थ में निःशस्त्रीकरण की समस्या निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है, यह वास्तव में विश्व-समुदाय के संगठन की समस्या है।

वास्तव में निःशस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कार्य तब तक नहीं हो सकता जब तक महाशक्तियों में मौलिक मतभेद बने रहेंगे। निःशस्त्रीकरण में बाधित सफलता न मिलने का एक कारण यह भी है कि 'माणविक क्लब' (The Nuclear Club) की सदस्यता बहुत सीमित है। अभी तक अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और

चीन की आणविक शस्त्रास्त्रों के क्षेत्र में खिसाड़ी हैं, लेकिन जब विश्व के अन्य देशों भी मंदान में उतर आएंगे और जरा-सी टकराहट पर अणु-युद्ध का खतरा सजीव हो उठेगा तो महाशक्तियाँ सम्भवतः बाध्य हो जाएँगी कि वे निःशस्त्रीकरण (विशेषकर अणु-प्रस्त्रों के क्षेत्र में) की दिशा में गम्भीर प्रयास करें। अभी तक इस ओर जो भी कदम उठाए गए हैं अथवा समय-समय पर जो सन्धियाँ की गई हैं वे प्रदर्शनात्मक और प्रचारात्मक ही अधिक हैं, अन्यथा महाशक्तियों का यह प्रयास जारी है कि अभिनव सामरिक अणु-शस्त्रों की खोज की जाए और वर्तमान शस्त्रों की विनाशक शक्ति बढ़ाई जाए।

द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों तथा सोवियत रूस ने कन्धे से कन्धा भिड़ाकर धुरीराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया था, पर इस एकना के बावजूद दोनों पक्षों में एक-दूसरे के प्रति सन्देह के बीज विद्यमान थे। युद्ध के बाद सन्देह के बीजों ने वृक्ष का रूप धारण कर लिया। युद्ध-काल का सहयोग असहयोग में बदल गया। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के पूँजीवादी गुट तथा सोवियत रूस और उसके साथी देशों के साम्यवादी गुट के बीच तनाव और मतभेद इतने बढ़ गए कि वे एक-दूसरे पर कठोर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। इस प्रकार महायुद्ध के बाद शीत-युद्ध शुरू हुआ जिसमें अस्त्रों के स्थान पर वाष्वाणु का प्रयोग हुआ।

शीतयुद्ध का अर्थ

महायुद्ध के उपरान्त सशस्त्र सैनिक संघर्ष तो शान्त हो गया, बारूद ने गोले-गोली बन्द हो गए, लेकिन बटु शब्दों, आरोपो-प्रत्यारोपो, एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार और कूटनीतिक दाँव-पेच आदि का युद्ध आरम्भ हो गया। इसी सग्राम को 'शीतयुद्ध' (Cold War) की संज्ञा दी गई। पिछले दो-तीन वर्षों से और विशेषकर सन् 1974-75 में अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में सुधार के कारण शीतयुद्ध बहुत कुछ शिथिल पड़ चुका है, लेकिन विश्व इस बात को नहीं भूल सकता कि पिछले वर्षों में शीतयुद्ध ने कई बार भीषण संकटों को जन्म दिया, यहाँ तक कि महाशक्तियों के बीच सशस्त्र युद्ध तक की नीवत आ गई थी।

शीतयुद्ध में दोनों पक्ष आपस में शान्तिकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित रखते हुए भी शत्रु-भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक-दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह एक कूटनीतिक युद्ध है जो अत्यन्त-उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध के अन्तर्गत आ सकता है। शीतयुद्ध में दोनों पक्ष अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धान्तिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रचार-अस्त्र का उपयोग, जामूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, सैनिक गुटबन्दीयों और प्रादेशिक संगठनों का

निर्माण, शस्त्रीकरण आदि शीतयुद्ध के महत्वपूर्ण अंग हैं। स्वर्गीय नेहरू के शब्दों में यह 'दिमागों में युद्ध के विचारों को प्रथम देने वाला युद्ध है जिसका उद्देश्य शत्रुओं को प्रकला कर देना और मित्रों को जीतना होता है।'

शीतयुद्ध के कारण

शीतयुद्ध का आधार तो महायुद्ध-काल में ही धन चुका था, पर महायुद्ध के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत संघ में उग्र मतभेद हो जाने से इन दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व में दो गुटों का कूटनीतिक युद्ध शुरू हो गया। अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिनसे शीतयुद्ध का तंजी से प्रसार होता गया। यहाँ हम प्रारम्भिक कुछ वर्षों में शीतयुद्ध के पनपने के कारणों का उल्लेख करेंगे जिसमें 'पश्चिम' के 'पूर्व' के विरुद्ध तथा 'पूर्व' के 'पश्चिम' के विरुद्ध आरोप सम्मिलित हैं।

(क) पश्चिम के पूर्व के विरुद्ध आरोप

अमेरिका के नेतृत्व में पश्चात्य शक्तियों ने सोवियत रूस पर अनेक आरोप लगाए। उनमें मुख्य इस प्रकार थे—

1. रूस द्वारा याल्टा सम्मेलनों की अवहेलना—ब्रिटेन और अमेरिका की रूस के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिकायत यह थी कि उसने याल्टा-सम्मेलनों का पूर्ण उल्लंघन किया। फरवरी, 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने कुछ सम्मेलन किए थे, उदाहरणार्थ जर्मनी को चार 'आधिपत्य क्षेत्रों' (Occupation Zones) में विभाजित करना, पोलैण्ड में सोवियत संघ द्वारा सुरक्षित 'लुबलिन सरकार' और पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षित 'लंदन सरकार' के स्थान पर स्वतन्त्र चुनावों द्वारा प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना, नए पोलैण्ड से उसके पूर्व में स्थित रूसी भाषा-भाषी प्रदेश का कर्जन-रेखा के आधार पर पृथक्करण, यद्यपि पश्चिम में उसे मुद्रावज के रूप में कुछ जर्मन-भूमि दिए जाने का प्रावधान था। सोवियत रूस द्वारा यह भी वचन दिया गया था कि वह 'बाल्ट मंगोलिया' में 'पूर्व-स्थिति' (Status-quo), दक्षिणी सलातिन तथा कुराईल द्वीपों पर स्वामित्व, दारें का अन्तर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Dairen), पोर्ट आर्थर में एक रूसी नौसैनिक बन्दे की स्थापना तथा एक चीनी-रूसी कम्पनी द्वारा मन्चूरियन रेलवे के संयुक्त-संचालन की शर्तों के साथ जर्मनी के आत्म-समर्पण के दो तीन महीने बाद जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा। स्टालिन ने यह भी कहा था कि वह चीन की 'राष्ट्रवादी' सरकार को ही वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

लेकिन रूस द्वारा याल्टा-सम्मेलनों की उपेक्षा की गई। उसने अनेक ऐसी कार्यवाहियों की जिनसे यह स्पष्ट हो गया कि रूसी दृष्टिकोण में याल्टा-सम्मेलनों रही कागजों के डेर के अलावा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए,

(1) रूस ने पोलैण्ड में स्वतन्त्र चुनावों पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक सरकार की स्थापना करने के बजाय पोलिश जनता पर अपनी संरक्षित 'लुबलिन-सरकार' (Lublin Government) को ज़ाबने का प्रयत्न किया।

(ii) रूस ने केवल लुबनिन सरकार को ही पोलिश जनता पर नहीं लादा बल्कि देश के अन्य प्रजातान्त्रिक दलों को गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने पोलैण्ड में प्रवेश करना चाहा तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

(iii) हंगरी, बल्गेरिया, रूमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी रूस द्वारा युद्ध-विराम समझौते तथा गाल्टा व पोदुसडम सन्धियों का उल्लंघन किया गया। रूस ने इन सभी देशों में प्रजातन्त्र की पुनर्स्थापना में मित्रराष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया और रूस-समर्थक सरकारें स्थापित कर दी।

(iv) जर्मनी द्वारा आत्म-समर्पण किए जाने से पूर्व ही रूसी फौजों ने यूनान के उत्तर में अधिकांश पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी यूरोप पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया और जनता पर साम्यवादी सरकारें थोप दीं। कुछ ही वर्षों में यूनान और बाल्टिक सागर के बीच सुदृढ़ श्रमिक-तानाशाही राज्य स्थापित हो गए।

(v) सोवियत रूस की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उससे द्वारा मित्रराष्ट्रों को साइबेरिया में अड़्डों की सुविधा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति सन्देह को बढ़ाया।

(vi) मचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने मई 1946 के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रवेश तक नहीं करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश सम्बन्धी सभी सुविधाएँ प्रदान की और उनको सम्पूर्ण युद्ध-सामग्री सौंप दी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी।

2. रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना—युद्ध के उपरान्त एंग्लो-अमेरिकी फौजें तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, लेकिन रूसी फौजें उत्तरी ईरान में स्थित रही। यद्यपि विश्व जनमत और विश्व-संस्था के दबाव से बाद में रूसी सेनाएँ ईरान से हटा ली गई, तथापि पश्चिमी राष्ट्रों का रूसी नीयत पर सन्देह और भी दृढ़ हो गया।

3. टर्की पर रूसी दबाव—युद्ध के तुरन्त बाद रूस ने टर्की से कुछ भू-प्रदेश एवं वास्फोरस में सैनिक अड़्डे निर्मित करने के अधिकार की माँग की। उसके बढ़ते हुए हस्तक्षेप के उत्तर में अमेरिका ने चेनावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद् में लाया जाएगा।

4. अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान—युद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही प्रमुख सोवियत-पत्रों में अमेरिका के प्रति कटु आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने लगे। इस 'प्रचार अभियान' से अमेरिका के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में तीव्र विक्षोभ व्याप्त हो गया।

5. रूस द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना—युद्धोपरान्त क्षतिपूर्ति-प्रावधान का अनुचित लाभ उठाते हुए रूस ने जर्मन-उद्योगों को छिन्न-भिन्न कर मूल्यवान मशीनों का रूस में स्थानान्तरण करना शुरू कर दिया। रूस के इस कार्य से पहले से ही अस्त-व्यस्त जर्मन आर्थिक व्यवस्था पर और अधिक बोझ पड़ा। ब्रिटेन और अमेरिका में रूस की इस कार्यवाही से काफी विक्षोभ फैल गया और उन्हें विवश होकर जर्मन-व्यवस्था की सहायतायें पर्याप्त धन व्यय करना पड़ा।

6. जर्मनी सम्बन्धी समझौते के गम्भीर उल्लंघन—रूस ने जर्मनी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के और भी अनेक गम्भीर उल्लंघन किए, जैसे (क) रूस ने अपने अधीनस्थ जर्मन क्षेत्र के हजारों लोगों को बंदी बना कर रूस भेज दिया या वन्दी-शिबिरो में डाल दिया, (ख) पूर्वी जर्मनी की जनता को पश्चिमी जर्मनी की जनता से एकदम पृथक् कर दिया, (ग) अप्रैल, 1946 में जर्मन समाजवादी दल को बसपूर्वक साम्यवादी दल में संयुक्त कर दिया गया, (घ) जर्मनी को एक पृथक् आर्थिक इकाई के रूप में मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था को ठुकरा कर रूस ने स्पष्ट कह दिया कि प्रत्येक क्षेत्र अपना व्यापार स्वयं करेगा, एवं (च) रूस ने सोडर-नीति रेखा को जर्मन-पोलिश-सीमा के रूप में मान कर लुबलिन सरकार को यह अनुमति प्रदान कर दी कि वह उस भूमि पर अधिकार करके वहाँ वैसे जर्मन नागरिकों की निष्कासित कर दे।

7. बर्लिन की नाकेबन्दी—जून, 1948 में, लन्दन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए रूस ने बर्लिन की नाकेबन्दी की और पश्चिमी बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल-सड़क और जल-यातायात बन्द कर दिया। यही नहीं, रूस ने हजारों जर्मन युद्ध-बन्दिनों और नागरिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

8. निषेधाधिकार का बार-बार प्रयोग—सोवियत रूस ने अपने निषेधाधिकार के अनियन्त्रित प्रयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के मार्ग में बाधाएँ डालना प्रारम्भ कर दिया। निषेधाधिकार के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपनायी।

9. रूस द्वारा शान्ति-व्यवस्था में बिघ्न—शान्ति-व्यवस्था की पुनर्स्थापना में रूस द्वारा इतनी बाधा डाली गई और इतनी अनुचित तथा व्यापक मांगें प्रस्तुत की गईं कि शान्ति समस्याएँ मुलभूत के स्थान पर उलभने लगी तथा नए विवाद उत्पन्न होने लगे।

10. अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियाँ—रूस ने अन्य देशों में ही नहीं, अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन किया। सन् 1945 के प्रारम्भ में 'स्ट्रैटेजिक सर्विस' के अधिकारियों को पता चला कि उनकी संस्था के बहुत से गुप्त दस्तावेज साम्यवादी संरक्षण में चलने वाले 'अमेरेगिया' नामक मासिक-पत्र के सम्पादन के हाथ लग गए हैं। सन् 1946 में 'कनाडियन शाही आयोग' की रिपोर्ट ने यह प्रमाणित कर दिया कि कनाडा का साम्यवादी दल 'सोवियत संघ की एक मुजा' है। अब अमेरिकी सरकार साम्यवादियों के प्रति पूरी तरह सशक्त हो गई और सम्पूर्ण अमेरिकी राष्ट्र तथा अन्य पश्चिमी शक्तियों में रूस के प्रति घृणा की उत्कट भावना व्याप्त हो गई।

पश्चिमी राज्यों और अमेरिका ने उपर्युक्त तथा अन्य आरोप लगाते हुए सोवियत संघ के प्रति पूर्ण अविश्वास व्यक्त कर दिया। यह कहा जाने लगा कि हमें तानाशाही के एक रवल्प के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना

चाहिए। ब्रिटिश प्रधान मंत्री चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन की उपस्थिति में 5 मार्च, 1946 को अपनी सुप्रसिद्ध 'फुल्टन वक्त्रता' में साम्यवाद के विरोध की एक नई नीति का सकेत दिया। इस भाषण में चर्चिल ने यूरोप पर सोवियत 'लोहे-आवरण' (Iron Curtain) की निन्दा की तथा 'स्वतन्त्रता की दीपशिखा प्रज्ज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए' एक अंग्लो-अमेरिकी गठबन्धन की मांग की। सन् 1946 के अप्रैल मास के बाद से ही दोनों पक्षों (पश्चिमी व पूर्वी गुट) ने अपने मतभेदों को खुलेप्राय उगतना शुरू कर दिया। 12 मार्च, 1947 को यूनानी गृहयुद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस से यूनान एवं टर्की को 400 मिलियन डॉलर की सहायता देने का अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने विख्यात 'ट्रूमैन सिद्धान्त' (Truman Doctrine) का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत उन्होंने उन सभी स्वतन्त्र देशों को सहायता देने की नीति पर बल दिया जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों अथवा बाह्य-शक्तियों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के प्रयत्नों का विरोध कर रहे थे। 5 जून, 1947 को 'मार्शल योजना' की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य यूरोप की प्रस्त-अस्त आर्थिक दशा को सुधारना था। जहाँ पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों ने इस योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया वहीं रूस ने इसे अपने लिए गम्भीर चुनौती समझा। 3 जुलाई, 1947 को ब्रिटेन और फ्रांस ने यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान की समस्या पर विचार करने के लिए पेरिस में 22 देशों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें प्रारम्भ में तो पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया ने भाग लेने की स्वीकृति दे दी, परन्तु बाद में सोवियत रूस के विरोध के कारण इस निमन्त्रण को ठुकरा दिया। एटली (Attlee) के शब्दों में—“जब पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया ने मार्शल सहायता के विचार को स्वीकार कर लिया तब पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के एकीकरण की उसकी (वेबिन की) आशाएँ बढ गईं। परन्तु क्रैमलिन के आदेश पर इन स्वीकृतियों के परावर्तन ने इस आशा को समाप्त कर दिया। वस्तुतः यह 'शीत-युद्ध' की एक घोषणा थी।”

(ख) पूर्व (रूस) के पश्चिम के विरुद्ध आरोप

पश्चिमी राज्यों द्वारा रूस के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए, उनसे यह नहीं समझना चाहिए कि शीत-युद्ध के नाटक का एकमात्र खलनायक सोवियत रूस ही था। सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्रों ने अपने आरोपों में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि युद्धोत्तर काल के तनाव और अशांति का सम्पूर्ण दोष पश्चिमी राष्ट्रों का है।

(1) युद्धकाल में पश्चिम द्वारा 'द्वितीय मोर्चा' खोले जाने में देरी—रूस की पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध एक सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि जर्मनी द्वारा पूरी तरह से दबे रहने की स्थिति में स्टॉलिन ने मित्रराष्ट्रों से बार-बार अनुरोध किया था कि पश्चिमी यूरोप में जर्मनी में विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोला जाए ताकि सोवियत रूस पर किए जाने वाले जर्मन आक्रमण में कमी आ सके, परन्तु पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा रूसी सुभाव को यह कहकर प्रस्वीकार कर दिया गया कि उनका तैयारी अभी अधूरी

है। दूसरा मोर्चा खोलने जाने में पर्याप्त विलम्ब किए जाने का परिणाम यह हुआ कि सोवियत रूस को जर्मनी के हाथों जन-धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। बैली (Bailey) के शब्दों में, "इससे क्रैमलिन में यह सन्देह जड़ पड़ा कि पश्चिमी राष्ट्र, जो युद्धोत्तर काल में एक शक्तिशाली सोवियत संघ के उदयान की सम्भावना से भयभीत हैं, युद्ध के अखाड़े में कूदने में पूर्व रूस को पूर्णतया 'आहत तथा शक्तिहीन' होते देखना चाहते हैं।"

(ii) पश्चिमी देशों की फासिस्ट देशों से सांठगांठ—रूस ने इस बात पर बहुत धोम प्रकट किया कि सैनिक व्यावहारिकता की भाँव में अमेरिका ने इटली और फ्रांस के फासिस्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित किया और फिनलैण्ड द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने तथा लेनिनग्राड पर आक्रमण करने के काफी समय बाद तक वाशिगटन ने उनसे अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किए।

(iii) युद्धकाल में पश्चिम द्वारा अर्पणित सहायता—सोवियत संघ ने यह आरोप लगाया कि युद्धकाल में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो सैनिक सहायता सोवियत रूस को दी, वह रूस द्वारा उत्पन्न की गई युद्ध सामग्री का केवल 4 प्रतिशत था। वास्तव में मित्रराष्ट्रों की आन्तरिक अभिलाषा यह थी कि रूस जर्मनी के साथ संघर्ष में विलकुल परत हो जाए।

(iv) अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रूस से गुप्त रखना—अमेरिका ने अणुबम के आविष्कार को सोवियत रूप से सर्वथा गुप्त रखा जबकि ब्रिटेन और कनाडा को इस बात का पता था। स्टॉलिन ने अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने की परस्पर विश्वासघात माना।

(v) सोवियत संघ की 'लैण्ड-लीज' सहायता बन्द किया जाना—अमेरिका द्वारा 'लैण्ड-लीज अधिनियम' (Land Lease Act) के अन्तर्गत सोवियत संघ को जो आंशिक सहायता दी जा रही थी, उससे बड़ा (रूस) पहले से ही असन्तुष्ट था, क्योंकि सहायता एकदम ना-काफी थी। किन्तु यूरोप में विजय के उपरान्त राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जब यह आंशिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी तो सोवियत रूस भड़क उठा।

(vi) सोवियत विरोधी प्रचार अभियान—रूस पश्चिमी राष्ट्रों से इसलिए भी बहुत असन्तुष्ट था कि युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं में निरन्तर सोवियत-विरोधी साहित्य का प्रचार करती रही। पश्चिमी प्रेस खुले आम साम्यवादी देश के प्रति घृणा-प्रचार में सलग्न हो गए और साम्यवादी खतरे का खूब बढ़ा-चढ़ा कर प्रचार किया गया।

(vii) 5 मार्च, 1946 की चर्चिल की विख्यात 'फुल्टन वक्तव्य' ने सोवियत रूस को एकदम चौंका दिया। इसमें यह स्पष्ट निर्देश था कि 'हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए।"

(viii) 'पश्चिम' के प्रति, विशेषकर समुक्तराज्य अमेरिका के विरुद्ध रूसी सन्देह उक्त बहुत अधिक बढ़ गया जब 20 सितम्बर, 1945 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने

भूतपूर्व उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए. वेलेस को केवल इस अपराध के लिए दयागपत्र देने को कहा कि उसने 12 सितम्बर को न्यूयॉर्क में अपने एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ तथा अमेरिका के बीच मैत्री-स्थापना की अपील की थी। इसके कुछ ही माह बाद राज्य-मन्त्रि डॉन एचीसन ने 10 फरवरी, 1947 को सीनेट के सम्मुख स्पष्ट रूप से घोषणा की कि "रूस की विदेश नीति आक्रामक तथा विस्तारवादी है।" इसके बाद ही साम्यवाद के विरोध के नाम पर और सोवियत-विस्तार को रोकने के उद्देश्य से 'ट्रूमैन सिद्धान्त', 'मार्शल योजना' आदि का सूत्रपात हुआ। सोवियत संघ ने इन सब कार्यवाहियों को अपने अस्तित्व के लिए एक चुनौती माना। 25 अक्टूबर को मार्शल योजना के जवाब में यूरोप के नौ साम्यवादी देशों का कोमिनफार्म स्थापित किया गया। अब दान-दान पर झगडा होने लगा और एक-दूसरे के विरुद्ध गाली-गलौज और आरोपो-प्रत्यारोपो की घुम्राधार बर्पा होने लगी।

इस विवरण से सुस्पष्ट है कि युद्धोत्तर काल में 'पूर्व' और 'पश्चिम' के बीच एक गहरी खाई बन चुकी थी और सन् 1917 की सोवियत क्रान्ति से द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक के इतिहास में वैमनस्य का अच्छी तरह बीजारोपण हो चुका था।

1947 से 1953 तक शीतयुद्ध

सन् 1945 से 1953 तक पश्चिमी देशों और रूस में संयुक्तराष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर अणुशक्ति के नियन्त्रण व नियमीकरण; निःशस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति सन्धियों; जर्मनी, बर्लिन, यूरोप की सुरक्षा-समस्याओं, एशिया एवं अफ्रीका के अल्पविकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद-विवाद तथा कूटनीतिक संघर्ष चालू रहा। रूस द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर, 1947 में यूरोप में नौ साम्यवादी देशों के 'कोमिनफार्म' (Cominform or Communist Information Bureau) की स्थापना के बाद में शीतयुद्ध की उग्रता बढ़ती गई। रूस ने पूर्वी यूरोप पर अपने नियन्त्रण को और भी अधिक कठोर बना दिया। शक्ति के दो गुट या शिविर बन गए और उनमें अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों के विस्तार के लिए जी-तोड़ स्पर्धा होने लगी। रूसी दबाव के कारण फिनलैंड को मार्शल सहायता का प्रस्ताव अस्वीकार करना पड़ा। परन्तु एक साम्यवादी देश यूगोस्लाविया ने ही अपने नेता मार्शल टीटो के नेतृत्व में स्टालिन के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। मार्शल टीटो का यह कार्य 'शीत-युद्ध' की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जहाँ इसने एक तरफ गैर-साम्यवादी देशों को नवीन दान प्रदान दिया, वहाँ दूसरी तरफ रूस के दृष्टिकोण को और भी अधिक कठोर बना दिया।

बर्लिन की नाकेबन्दी, दो जर्मनियों का उदय—सन् 1948 में रूस ने बर्लिन की नाकेबन्दी करके नया सफट उत्पन्न कर दिया। इस घटना ने 'शीतयुद्ध' को एक नया मोड़ दिया। बर्लिन के घेरे के समय ही दोनों पक्षों को शक्ति परीक्षण का सर्वप्रथम वास्तविक अवसर मिला और शीतयुद्ध में इस बार अमेरिका का रुख पहली

बार अत्यधिक कठोर दिखाई दिया। यद्यपि रूस की बर्लिन-नाकेबन्दी अरफन सिद्ध हुई और मई, 1948 में इस नाकेबन्दी को समाप्त कर दिया गया, तथापि इस घटना का एक गम्भीर परिणाम यह हुआ कि अब सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमेरिका तरह-तरह के सैनिक-संगठनों की स्थापना की दिशा में सक्रिय हो गया। दूसरी ओर पहले से ही क्षतविक्षत जर्मनी 'शीतयुद्ध' का एक प्रधान केन्द्र बना रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनो पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इस तरह 21 सितम्बर, 1949 को 'संघीय-जर्मन-गणराज्य' (Federal Republic of Germany) अथवा 'पश्चिमी जर्मनी' का उदय हुआ। मित्रराष्ट्रों अर्थात् उपर्युक्त तीनों शक्तियों में इन कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर, 1949 को जर्मनी के रूढ़ी क्षेत्र में 'जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य' (German Democratic Republic) अथवा 'पूर्वी जर्मनी' की स्थापना कर दी गई। इस तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दो जर्मन राष्ट्र अस्तित्व में आए और उनके एकीकरण का प्रश्न शीतयुद्ध को बल प्रदान करने लगा।

नाटो की स्थापना, साम्यवादी चीन का उदय, आदि घटनाएँ—रूस के कठोर हल और साम्यवाद के प्रसार की नीति का उत्तर पश्चिमी शक्तियों ने 4 अप्रैल, 1949 को 'नाटो' (NATO) की स्थापना के रूप में दिया। शीतयुद्ध का क्षेत्र केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा। एशिया भी इसकी लपेट में आ गया। रूस ने टर्की और ईरान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, परन्तु पाश्चात्य शक्तियों की सहायता से ये दोनों देश रूसी दबाव का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे। 1 अक्टूबर, 1949 को पेरिस में साम्यवादी गणराज्य स्थापित हो जाने से 'शीतयुद्ध' में अत्यधिक गर्मी आ गई। साम्यवादियों की इस विजय ने रूस के उत्साह में आशातीत वृद्धि कर दी। संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद् का एक स्थायी सदस्य था। परन्तु जब क्यांगकाई शेक की राष्ट्रवादी सरकार फारमोसा को पलायन कर गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद् में अपना स्थान पाने की माँग की। पश्चिमी गुट यह नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद् में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए। परिषद् के 5 स्थायी सदस्यों में से 2 साम्यवादी हो जाने के भय से संयुक्तराज्य अमेरिका ने चीन की नई सरकार को मान्यता नहीं दी और साम्यवादी प्रतिनिधि के संघ में स्थान ग्रहण का घोर विरोध किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता की माँग को इस प्रकार ठुकरा दिए जाने का रूस द्वारा तीव्र विरोध किया गया और एक बार तो उसने परिषद् की बैठकों तक का बहिष्कार कर दिया। वास्तव में साम्यवादी चीन की संघ में सदस्यता के प्रश्न पर शीतयुद्ध में बटुता और गम्भीर वंमनस्थ का समावेश हुआ तथा आगामी वर्षों में शीतयुद्ध की भीषणता और पारस्परिक मतभेदों की तीव्रता में हर प्रकार से वृद्धि हुई। अक्टूबर, 1971 में जनवादी चीन विश्व-संस्था का सदस्य बन सका और सुरक्षा परिषद् में ताइवान की जगह उसे स्थायी सदस्यता प्राप्त हुई। ताइवान का विश्व-संस्था से यह निष्कासन सर्वथा अप्रत्याशित था।

कोरिया का युद्ध—बर्लिन-प्रश्न पर और संयुक्त राष्ट्रसंघ में साम्यवादी चीन के प्रवेश की समस्या पर शीतयुद्ध की तीव्रता अभी कम न हो पायी थी कि जून, 1950 में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया जिससे 'शीत-युद्ध' ने कुछ समय के लिए 'उष्ण अथवा सशस्त्र युद्ध' का रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्ष में यह युद्ध दो कोरियाई क्षेत्रों में था, परन्तु वास्तव में यह दोनों शक्ति-गुटों के नेताओं हूँ एव अमेरिका में ठन गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उसके ऋण्डे के नीचे अनेक देशों की, विशेषतः अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की। परन्तु किसी भी पक्ष को निर्णयात्मक विजय प्राप्त न हो सकी और 8 जून, 1953 को अन्ततः कोरिया में युद्ध विराम हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और हूँ की सरकारों ने युद्धबन्दी का स्वागत किया, किन्तु दिलों में विद्रोह की आग घबकती रही। फलतः शीतयुद्ध जारी रहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कोरिया युद्ध शीतयुद्ध की ही एक महत्वपूर्ण घटना थी। चेस्टर बाउल्स (Chester Bowles) के शब्दों में, "कोरिया-युद्ध ने ही हूँ और चीनी नीतियों को एक घरेलू में एकता प्रदान की।" चीन के लिए सोवियत सहायता की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई और चीन और पश्चिमी राज्यों के सम्बन्ध और भी अमैत्रीपूर्ण हो गए।

जापान के साथ मित्रदेशों की शान्ति-सन्धि, 1951—जिस समय कोरिया-युद्ध चल रहा था, तभी मितम्बर, 1951 में अमेरिका और कई अन्य देशों ने जापान के साथ एक शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर किए। हूँ को यह बात बुरी लगी और उसने इस एकपक्षीय कार्यवाही की खुल कर आलोचना की।

सन् 1953 से 1958 तक का शीतयुद्ध

मार्च, 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शीतयुद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आया। स्टालिन पश्चिम के प्रति उग्रवादी और कठोर नीति का समर्थक था। उसका दृष्टिकोण सन् 1953 के प्रारम्भ तक शीतयुद्ध का एक प्रधान कारण बना रहा। सर एलबरी गैसकोप्पे के अनुसार, 'सन् 1947 के बाद यद्यपि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रखे, तथापि वह इतना अग्रगण्य और दुःसाध्य हो गया कि उसके साथ कार्य करना कठिन हो गया। जो भी सुझाव प्रस्तुत किए जाते वह उनको अस्वीकार कर देता था।' स्टालिन के बाद के उत्तराधिकारी, विशेषतः ख्रुश्चेव ने समझौतावादी नीति को अपनाने की कोशिश की, अमेरिका के नेतृत्व में भी एक परिवर्तन आया और शीतयुद्ध के उन्नायक राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहावर ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अगस्त, 1953 में सोवियत संघ का प्रथम आणविक परीक्षण हुआ और दोनों को हथियारों के क्षेत्र में विद्यमान खाई को धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी।

परन्तु शीतयुद्ध की यह शिथिलता एकदम अल्पकालिक ही सिद्ध हुई क्योंकि हूँ के विदेश मंत्री मोलोटोव और अमेरिका के विदेश सचिव टेलस दोनों ही शीत-युद्ध के बाँके पट्टेबाज थे। एक तरफ तो हिन्द-चीन के प्रश्न पर शीतयुद्ध में पुनः तेजी

प्राची क्योंकि फ्रेंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाले युद्ध में दोनों ही गुटों ने अलग अलग पक्षों का जोरदार समर्थन किया और दूसरी तरफ अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समझौतों तथा सैन्य संगठनों की स्थापना करने की नीति अपना कर शीतयुद्ध को बढ़ावा दिया। अमेरिका ने नाटो, सीटो और दगदाद पैक्ट स्थापित किए और इनके जवाब में रूस ने वारसा पैक्ट की स्थापना की। वास्तव में दोनों ही पक्षों ने अपनी-अपनी कार्यवाहियों से एक दूसरे के प्रति सन्देहों को दृढ़ बनाया तथा अपनी प्रत्येक कार्यवाही ने शीतयुद्ध को कुछ-न-कुछ देशों के अनाक्रमण प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो मार्च, 1954 में जब रूसी विदेश मंत्री मोलोटोव ने रूस के उत्तर अटलांटिक सन्धि में सम्मिलित होने के लिए तत्परता दिखायी तो नाटो देशों ने इसका विरोध किया। जनवरी, 1956 में रूसी प्रधान मंत्री बुल्गानिन ने राष्ट्रपति आइजनहॉवर के सम्मुख एक रूसी-अमेरिकी मंत्री सन्धि का प्रस्ताव रखा, परन्तु वह भी फनीभूत नहीं हुआ। ऐसे प्रस्ताव समय-मसम पर किए जाते रहे, किन्तु पारस्परिक मतभेद और गन्देह इतने गहरे थे कि कोई सफाया प्राप्त न हो सकी। समुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व आदि सभी क्षेत्रों में पूर्व और पश्चिम का सघर्ष जारी रहा। जापान और जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण ने दोनों ही गुटों में काफी तनाव उत्पन्न कर दिया। जर्मनी के भविष्य और बर्लिन के स्तर पर भी मतभेद कायम रहे। अणुशक्ति के निर्माण और नियन्त्रण पर कोई समझौता न हो सका। सभार के सबसे प्रमुख प्रश्न 'निःशस्त्रीकरण' पर दोनों ही गुटों में तीव्र मतभेद रहा—प्रस्ताव व प्रति-प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते रहे, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक प्रश्न पर शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि में दोनों गुटों के दृष्टिकोण निर्धारित होने लगे।

सन् 1956 में हंगरी के प्रश्न ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शीतयुद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की। पश्चिमी देशों ने रूसी कार्यवाही की तीव्र निन्दा की और जघन रूस ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप सन् 1956 में मिस्र पर होने वाले एंग्लो-फ्रेंच-इजरायल आक्रमण की तीव्र भर्त्सना की। जून, 1957 में 'आइजनहॉवर-सिद्धान्त' की घोषणा की गई जिसके अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार कौजें भेजने तथा सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार दिया। 'आइजनहॉवर-सिद्धान्त' की घोषणा के बाद मध्यपूर्व में 'शीतयुद्ध' में और अधिक गर्मी आ गई। रूस ने पश्चिमी एशिया के लिए इस सिद्धान्त को एकदम अनुचित बताया तो अमेरिका और इंग्लैंड ने उस क्षेत्र में रूसी धुतरेठ व तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की निन्दा की। तत्पर्य यह है कि सन् 1955 से सन् 1958 तक पश्चिमी एशिया शीतयुद्ध का अखाड़ा बना रहा। उस क्षेत्र के सामरिक महत्व और तेल-कूपी पर प्रभुता कायम रखने के लिए दोनों पक्षों में कूटनीतिक सघर्ष जारी रहा। फारस के तेल-विवाद, स्वेज नहर के सफाई, लेबनान में अमेरिकी सेनाएँ उतारने, ईरान की आगति आदि प्रवसरो पर दोनों ही पक्ष ताल ठोक कर एक दूसरे के विरुद्ध मंदान में डट गए। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो शीतयुद्ध में प्रभावित न रही हो।

सन् 1958 से 1975 तक शीतयुद्ध की स्थिति

इस समय के शीतयुद्ध के इतिहास को निम्न रूप में अध्ययन करना सुविधाजनक होगा—

ख़ुश्चेव की अमेरिकी यात्रा तथा यू-2 विमान काण्ड—सन् 1959 में कुछ कारणों से शीतयुद्ध में कुछ शिथिलता आई। दोनों में बढ़ते हुए तनाव में कमी लाने के लिए ख़ुश्चेव ने 15 सितम्बर से 28 सितम्बर, 1959 तक अमेरिका की यात्रा की। संयुक्त बक्तव्य में कहा गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्याय शान्तिपूर्ण उपायो तथा पारस्परिक वार्तालाप द्वारा किया जाना चाहिए।

शीतयुद्ध के तनाव को कम करने और आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए चार बड़े देशों (संयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस) के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरम्भ से पूर्व ही 1 मई, 1960 को यू-2 विमान काण्ड हो गया जिसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि कर अन्ततः शिखर सम्मेलन को असफल बना दिया। बात तब बहुत बढ़ गई जब राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियाँ बहुत गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी प्राकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जामूसी कार्यवाहियाँ करता है और आगे भी करता रहेगा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसका निषेध नहीं है। इस घोषणा से ख़ुश्चेव आग-बबूला हो गया। उसने ऐसी जामूसी उड्डानों को राष्ट्रीय अपमान बताते हुए इन्हें भविष्य में बन्द करने की माँग की और साथ ही यह धमकी दी कि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना से यदि युद्ध छिड़ गया तो उसका दायित्व संयुक्तराज्य अमेरिका पर होगा। यू-2 विमान-काण्ड ने शीतयुद्ध में जो तूफान खड़ा किया, उससे रूस ने प्रचुर लाभ उठाया। ख़ुश्चेव ने यह सिद्ध करने में कोई बसर नहीं छोड़ी कि रूस शान्ति का सबसे बड़ा प्रेमी और अमेरिका इसका सबसे बड़ा शत्रु है तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के लिए वही एकमात्र उत्तरदायी है।

रूसी चेतावनी के फलस्वरूप अब अमेरिकी अड्डों की अनुमति देने वाले देश यह अनुभव करने लगे कि यू-2 विमानों को अपने देश में उतरने देना भयंकर खतरों को मोल लेना था।

पेरिस शिखर सम्मेलन—यू-2 विमान काण्ड की घटना से 16 मई, 1960 में होने वाले शिखर सम्मेलन की असफलता साफ दिखाई देने लगी। लेकिन 11 मई को सुप्रीम सोवियत में अपने एक भाषण में ख़ुश्चेव ने सम्मेलन की सफलता के प्रति आशा का संचार किया। ख़ुश्चेव ने कहा, “संयुक्तराज्य अमेरिका के इस उत्तेजनपूर्ण कार्य से हमें अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं लानी चाहिए। पेरिस में यू-2 का विषय नहीं उठाया जाएगा।”

किन्तु जब पेरिस में शिखर-सम्मेलन शुरू हुआ तो ख़ुश्चेव ने यू-2 का प्रश्न उठाते हुए अमेरिकी जामूसी कार्यवाही की तीव्र निन्दा की। ख़ुश्चेव ने बड़े ही

नाटकीय ढंग से माँग की कि अमेरिका को अपने जामूसी काम की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए माफी माँगनी चाहिए, भविष्य में ऐसे उत्तेजक कार्य बन्द करने चाहिए और इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। ख्रुश्चेव ने शीतयुद्ध को तब पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया जब उसने डिगॉल और मैकमिलन से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने हाथ बढ़ाया तो ख्रुश्चेव ने इँकार कर दिया। इतना ही नहीं, ख्रुश्चेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दिए गए रूसी यात्रा के निमन्त्रण को वापस ले लिया और कहा कि राष्ट्रपति महोदय को अब रूस आने की आवश्यकता नहीं है।

रूसी नेता के इस रुख से शिखर-सम्मेलन असफल हो गया। आइजनहॉवर के आश्वासन और डिगॉल व मैकमिलन के गतिरोध को दूर करने के प्रयत्न सम्मेलन को भंग होने से न बचा सके। सम्मेलन के दूसरे सत्र में ख्रुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया, अतः सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर देनी पड़ी।

कैनेडी का अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित होना और क्यूबा-काण्ड—ख्रुश्चेव ने पेरिस शिखर-सम्मेलन को असफल बनाने के बाद अपने विभिन्न भाषणों में आश्वासन दिया कि रूस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा। 8 नवम्बर, 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीनेटर जॉन फिट्ज़जैरल्ड कैनेडी की सफलता के बाद शीतयुद्ध में कमी की आशा की जाने लगी। ख्रुश्चेव ने कैनेडी को अपनी बधाई में और कैनेडी ने ख्रुश्चेव को दिए गए प्रत्युत्तर में बड़े आशावादी शब्दों का प्रयोग किया।

दोनों नेताओं की आशाओं और उनके आश्वासनों का कुछ समय तक प्रभाव रहा और शीतयुद्ध में कुछ नरमी आई, लेकिन सन् 1962 में क्यूबा के संकट ने पुनः एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। क्यूबा के प्रश्न पर विश्व युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो गई। सीमाश्रयण कैनेडी और ख्रुश्चेव की बुद्धिमत्ता के कारण यह संकट टल गया। सोवियत रूस ने क्यूबा के सशस्त्र क्षेत्र से हट जाने का निर्णय करके बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया।

शीतयुद्ध में शिथिलता—क्यूबा-संकट के बाद ख्रुश्चेव और कैनेडी दोनों ही नेता निःशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति के लिए प्रयास करने लगे। अतः शीतयुद्ध में काफी समय तक उवाल नहीं आया। 5 अगस्त, 1963 को रूस, अमेरिका और इंग्लैण्ड ने मास्को में आणविक परीक्षणों पर रोक सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर किए और बाद में चीन, फ्रांस आदि कुछ राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के सौ से अधिक राष्ट्रों ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिए। शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया। सन् 1955 की आस्ट्रिया की शान्ति-सन्धि के बाद पूर्व और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समझौता था।

ख्रुश्चेव और कैनेडी के प्रयत्नों से शीतयुद्ध में शिथिलता आई और यह आशा की जाने लगी कि दोनों नेता पारस्परिक विश्वास और शान्ति के बीज बो देंगे, पर दुर्भाग्यवश 22 नवम्बर, 1963 को कैनेडी एक हत्यारे की गोली के शिकार बने और 15 अक्तूबर, 1964 को ख्रुश्चेव अपदस्थ हो गए।

कनेडी की मृत्यु के बाद लिण्डन बी. जॉनसन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला। दूसरी ओर छुश्चेव के पतन के बाद अक्टूबर, 1964 में रूस का नेतृत्व कोसिगिन और ब्रेझ्नेव के हाथों में आया। दोनों पक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में विश्वास प्रकट किया। कुछ असें तक शीतयुद्ध में रुका, लेकिन बाद में वियतनाम युद्ध की तीव्रता और अरब-इजरायल सघर्ष के फलस्वरूप शीतयुद्ध पुनः भड़क उठा।

वियतनाम युद्ध, भारत-पाक संघर्ष, अरब-इजरायल सघर्ष और शीतयुद्ध—सन् 1964 में ही शीतयुद्ध के तीव्र होने के आसार प्रकट होने लगे थे। रूस ने कांगो आदि में समुक्त राष्ट्रमण्डल के शान्ति-स्थानना सम्बन्धी कार्यों के व्यय सम्बन्धी अपने प्रश्न की अदायगी से इन्कार कर दिया। अमेरिका ने मांग की कि यदि रूस अपना प्रश्न अदा नहीं करता तो चाटेंर के उन्नीसवें अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे महासभा में मनाधिकार से वंचित कर दिया जाए। इस घटना में शीतयुद्ध फिर भड़क उठा।

वियतनाम युद्ध की तीव्रता ने शीतयुद्ध को और बढ़ावा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम के प्रति अत्यन्त उग्र और आक्रामक नीति का अनुसरण किया। अमेरिकी वायुयान उत्तरी वियतनाम की सीमाओं में घुसकर बम वर्षा करने लगे। सोवियत रूस ने इन आक्रामक कार्रवाहियों का कड़ा विरोध किया और शीतयुद्ध की लहर पहले से अधिक तेज हो गई।

सितम्बर, 1965 में कश्मीर के प्रश्न पर भारत-पाक सघर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि की। पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध अपना कूटनीतिक युद्ध छेड़ने में कोई कसर नहीं रखी पर स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री की दृढ़ता और स्पष्टता के सामने वे सफल नहीं हो सके।

जून, 1967 में अरब-इजरायल सघर्ष के समय शीतयुद्ध ने सशस्त्र सघर्ष का रूप धारण कर लिया। सोवियत सघर्ष ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह इजरायल को आक्रामक कार्रवाहों के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उधर अमेरिका ने इस सघर्ष के लिए सोवियत कूटनीति को दोषी ठहराया। पश्चिमी एशिया के संकट के प्रश्न पर दोनों गुटों में इतना वाक्ययुद्ध चला कि उनके आपस में टकराने का संकट पैदा हो गया। दोनों के जहाजी बेड़े भूमध्य सागर में चक्कर काटने लगे। अरब और इजरायल नेताओं द्वारा भी जबरदस्त कूटनीतिक एवं वाक्ययुद्ध छिड़ गया। यही शीतयुद्ध अरब-इजरायल सशस्त्र युद्ध में परिणत हो गया जिसकी समाप्ति समुक्त राष्ट्रसंघीय हस्तक्षेप और अरब-राष्ट्रों की आक्रामक पराजय में हुई।

अरब-इजरायल सघर्ष के समय सुरक्षा परिषद् की प्रत्येक बैठक में शीतयुद्ध का दृश्य देखने को मिलता था। अमेरिका और सोवियत सघर्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते थे और एक दूसरे को पश्चिम एशिया के संकट के लिए उत्तरदायी ठहराते थे। अरब राष्ट्रों की पराजय के बाद सोवियत सघर्ष के प्रति अरबों में सन्देह और अविश्वास व्याप्त हो गया क्योंकि उसने युद्ध में अरबों को कोई सत्रिय और प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी थी जबकि इजरायल को अमेरिका व ब्रिटेन दोनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता प्राप्त हुई थी। इन वातावरण में देखते हुए रूस ने अरब

जगत् में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यह माँग की कि अरब इजरायल संघर्ष का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में पेश किया जाए। 18 जून, 1967 को जब महासभा में प्रश्न पर विचार होने लगा तो स्वयं रूसी प्रधान मंत्री ने कार्यवाही में भाग लिया। कोसिगिन ने महासभा में उपस्थित होकर स्वयं एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो अरब भावनाओं का प्रति निधित्व करता था, लेकिन पश्चिमी गुट उसको मनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः 19 जून की बैठक में सोवियत प्रतिनिधि-मण्डल ने महासभा से बहिर्गमन कर अरबों की सहानुभूति जीती। सोवियत प्रधान मंत्री ने अमेरिकी प्रशासन पर कस-नस कर प्रहार किए। अरब-इजरायल संघर्ष के सन्दर्भ में इस प्रकार शीतयुद्ध आकाश छूने लगा।

ग्लासबरो का शिखर-सम्मेलन—सोवियत प्रधान मंत्री कोसिगिन ने, जो महासभा के अधिवेशन में आए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन से ग्लासबरो में भेंट की ताकि शीतयुद्ध की गर्मी कुछ शान्त हो सके। मुख्य रूप से यह शिखर-सम्मेलन ग्लासबरो में 23 जून से 26 जून, 1967 तक चला। इसमें वियतनाम और पश्चिमी एशिया पर विचार-विमर्श किया गया। निःशस्त्रीकरण एवं परमाणु शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक प्रश्न भी छूने नहीं रहे। दोनों नेताओं का यह शिखर-सम्मेलन चीन द्वारा हाइड्रोजन बम के परीक्षण के प्रभाव से व्याप्त था। दोनों ही नेता इन बातों की भली-भाँति समझते थे कि अणुशक्ति से सम्पन्न चीन विश्व के दोनों ही गुटों के लिए खतरा हो सकता है।

ग्लासबरो में कोई रोवेबाजी नहीं हो सकी, लेकिन इस सम्मेलन के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में अवश्य कमी आई। पश्चिमी एशिया के संकट के सम्बन्ध में दोनों महाशक्तियों के बीच सहमति के क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस शिखर-सम्मेलन के बाद दोनों ही महाशक्तियाँ कुछ अधिक समयित भाषा का प्रयोग करने लगी।

वियतनाम युद्ध में शिथिलता और शीतयुद्ध में कमी—सन् 1967-68 में वियतनाम का प्रश्न शीतयुद्ध को भड़काता रहा। अमेरिकी नीति के विरुद्ध विश्व जनमत में ही नहीं बल्कि स्वयं अमेरिकियों में भी गम्भीर प्रतिक्रिया हुई। अतः बाध्य होकर राष्ट्रपति जॉनसन ने एक ओर तो उत्तरी वियतनाम पर बमबारी रोकने की घोषणा की और दूसरी ओर आत्मग्लानि से पीड़ित होकर राष्ट्रपति पद के लिए पुनः उम्मीदवार न होने का निश्चय व्यक्त किया। इसके फलस्वरूप धीरे-धीरे वियतनाम युद्ध शिथिल होता गया और शीतयुद्ध ठण्डा पड़ता गया।

मार्च, 1969 का बर्लिन संकट और शीतयुद्ध—शीतयुद्ध में पुनः गर्मी तब आई जब पश्चिमी जर्मनी ने निश्चय किया कि 5 मार्च, 1969 को फेडरल जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बर्लिन में सम्पन्न किया जाए। पूर्वी जर्मन सरकार ने इस निश्चय का विरोध करते हुए कहा कि पश्चिमी बर्लिन अभी तक सन् 1945 के पोट्सडम सम्झौते के अधीन है, अतः पश्चिमी बर्लिन की सरकार को इस तरह का समारोह कर उसे केवल पश्चिमी जर्मनी का एक भाग सिद्ध करने का कोई अधिकार

नहीं है। पूर्वी जर्मनी ने आरोप लगाया कि पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव बर्लिन में कराने का निर्णय पूर्वी जर्मनी के दावे के खण्डन के लिए किया गया है।

पूर्वी जर्मनी ने केवल मौखिक विरोध ही नहीं किया बरन् पश्चिमी बर्लिन जाने वाले मार्गों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला निर्वाचक-मण्डल बर्लिन न पहुँच सके। किन्तु पश्चिमी जर्मनी भी इस बात पर तुल गया कि राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बर्लिन में ही किया जाएगा। अतः वायुयानों द्वारा (हवाई यातायात प्रतिबन्ध से मुक्त था) निर्वाचक-मण्डल अपने दल-बल सहित पश्चिमी बर्लिन पहुँचा। पश्चिमी जर्मनी को इस सम्पूर्ण कार्यवाही में पश्चिमी राष्ट्रों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। यद्यपि पूर्वी जर्मनी ने, जो रुम समर्पित है, तीव्र विरोध प्रकट किया और स्वयं रुम ने भी पश्चिमी जर्मनी को इस स्थिति से बचाने की चेतावनी दी तथापि राष्ट्रपति का चुनाव-कार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया इस प्रश्न पर सोवियत सघ ने कोई बड़ा पूर्व-पश्चिम संकट खड़ा नहीं किया क्योंकि इसमें उमका कोई उद्देश्य सिद्ध होने वाला नहीं था बल्कि इसका दो बातों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था—प्रक्षेपास्त्रों के दारे में रुम द्वारा प्रभावित वार्ता पर तथा नए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के साथ सोवियत सघ के नियंत्र सम्मेलन की योजना पर।

मास्को बोन सम्मेलन, 1970 तथा शीतयुद्ध में कभी—द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही जर्मन समस्या अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेषकर महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध का प्रमुख कारण बनी हुई थी। पश्चिमी जर्मनी और सोवियत सघ के सामान्य सम्बन्धों का विकास न होने से शीतयुद्ध को समय-समय पर प्रोत्साहन मिलता रहता था। सोभाग्यवश 12 अगस्त 1970 को दोनों ओर से लम्बे प्रयासों के उपरान्त मास्को में सघीय जर्मनी के विली ब्रांट और सोवियत सघ के कोसिगिन ने एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे युद्धोत्तर यूरोपीय इतिहास का एक प्रवर्तन-बिन्दु माना जाता है। इस सम्मेलन से शीतयुद्ध का एक प्रमुख कारण निश्चित रूप से कमजोर पड़ गया। सन्धि की मुख्य बात यह थी कि दोनों पक्षों ने वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न करने का निर्णय किया। सन्धि पर हस्ताक्षर के दिन ही सघीय जर्मन सरकार ने सोवियत विदेश मन्त्रालय को एक पत्र भेजकर यह स्पष्ट किया कि स्वतन्त्र आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर जर्मनी का एकीकरण सघीय सरकार का सर्वोपरि राजनीतिक लक्ष्य है।

मास्को-बोन सन्धि के बाद यह प्राशा व्यक्त की जाने लगी कि अब यूरोप में युद्ध नहीं होगा, नाटो तथा वारसा सन्धि जैसे सैन्य संगठन शिथिल पड़ जाएंगे और पूर्व तथा पश्चिम में सुरक्षा की भावना में वृद्धि होगी। इस सन्धि की विशेषता दो बातों में थी—प्रथम, सोवियत सघ और पश्चिमी जर्मनी ने एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति प्रयोग का निषेध किया और द्वितीय, पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी की सीमाओं सहित यूरोप की वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं को दोनों देशों ने स्वीकार किया। सन्धि से पूर्व तक मुख्य तनाव जर्मनी के वर्तमान स्वरूप तथा युद्धोत्तर राष्ट्रीय सीमाओं के प्रश्न पर

हो था। अतः जब सन्धि द्वारा वर्तमान सीमाओं को मान्यता मिल गई तो तनाव का एक मुख्य कारण समाप्त-सा हो गया।

वर्लिन समझौता, 1971 तथा शीतयुद्ध के एक और कारण में स्थितता— मास्को-बोन सन्धि के उपरान्त 3 नवम्बर, 1971 को अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रान्स के बीच लगभग 18 महीने की बातचीत के बाद, वर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते द्वारा पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में तनाव-पूर्ण स्थिति समाप्त हो गई। यह निर्णय किया गया कि पश्चिमी वर्लिन के लोगों को पूर्वी वर्लिन तथा पूर्वी जर्मनी जाने की अनुमति प्राप्त होगी। इस समझौते से पूर्व पश्चिम वर्लिनवासियों को पूर्वी वर्लिन तथा पूर्वी जर्मनी में अपने सम्बन्धियों तथा मित्रों से मिलने जाने पर प्रतिबन्ध था। सोवियत संघ कुछ विशेष सुविधाएँ देने को भी तैयार हो गया। वास्तव में इस समझौते के सम्पन्न होने पर ही उन अनाक्रमण सन्धियों की सम्पुष्टि निर्भर थी जो पश्चिमी जर्मनी ने रूस और पोलैण्ड के साथ की थी।

पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता, 1972—सितम्बर, 1971 का वर्लिन समझौता पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच सामान्य सम्बन्ध कायम करने की आधारभूमि बन गया। 8 नवम्बर, 1972 को पश्चिमी जर्मनी को राजधानी बोन में दोनो जर्मन-राज्यों के बीच एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें दोनो राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर विभिन्न मानवीय क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का आश्वासन दिया और जर्मन समस्या के समाधान के लिए बल-प्रयोग के उपायों को सदैव के लिए तिलांजलि दी। इस सन्धि के फलस्वरूप दोनों जर्मन-राज्यों के पिछले लगभग 23 वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण सम्बन्धों की समाप्ति हो गई। यह एक ऐतिहासिक सन्धि थी जिसने दोनो जर्मन-राज्यों की शत्रुता को समाप्त कर शीतयुद्ध के प्रमुख कारण और यूरोपीय शान्ति के लिए एक स्थायी खतरे को दूर कर दिया।

कोरिया का समझौता, 1972 और सहयोग-वृद्धि का आयोग, 1973— एशिया में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के तनावपूर्ण सम्बन्धों ने भूतकाल में शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था। सन् 1972 में दोनों राज्यों के बीच सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए और 4 जुलाई, 1972 को एक समझौता हुआ जिसमें दोनो ने वचन दिया कि वे एक दूसरे को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। इसके पूर्व अगस्त, 1971 में दोनो कोरिया की रेडक्रॉस सोसाइटी की एक बैठक में यह तय किया गया कि कोरिया-युद्ध के दौरान जो लगभग 1 करोड़ रिश्तेदार, मित्र आदि बिछुड़ गए थे उनकी मददला-बदली की जाए। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के एकीकरण सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के समाधान के विषय में प्रगति हुई और एक समन्वय समिति गठित की गई। जुलाई, 1973 में दोनों के बीच पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए समन्वय समिति ने अनेक मुझाव दिए।

यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, जुलाई, 1973—एक पूर्व निश्चय के अनुसार यूरोप

के 35 राज्यों के विदेश-मन्त्रियों का एक सम्मेलन 3 से 5 जुलाई, 1973 तक हेलसिंकी में हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को दूरकर शीतयुद्ध को समाप्त करना और यूरोप के देशों में सुरक्षा की नई भावना को जन्म देना था। कई दृष्टियों से यह एक ऐतिहासिक सम्मेलन था और राजनीतिक क्षेत्र में कहा गया कि—(i) यूरोपीय महाद्वीप में यह अपनी किस्म का अनूठा सम्मेलन है। (ii) इससे बड़े छोटे राष्ट्रों में सन्तुलन स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। (iii) इस सम्मेलन में बड़ी शक्तियों के हितों का सम्मान और छोटे राष्ट्रों के हितों और राष्ट्रीय गरिमा के बीच एक विशेष प्रकार का तालमेल बँटाने का वातावरण उत्पन्न होगा।¹ संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव डॉ. कुर्क वाल्डहीम ने कहा कि इस सम्मेलन से यूरोप में एक नवीन विचारधारा और स्वरूप का निर्माण होगा जिससे नए प्रकार के शक्ति-सन्तुलन कायम होंगे। यूरोप में इस सम्मेलन से एक नवीन आशा का संचार होगा और राष्ट्र एक दूसरे के अधिक निकट आएँगे,² सम्मेलन में रुस की ओर से एक लम्बा दस्तावेज पेश किया गया जिसमें यह माँग की गई कि सभी यूरोपीय देशों के लोगों को खुलकर एक दूसरे से मिलना और विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए तथा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करने की चेष्टा न करे। इससे यूरोप अधिक मजबूत और सम्पन्न होगा तथा उसमें अधिक सुरक्षा की भावना पैदा होगी।³ हेलसिंकी सम्मेलन ने तनाव-विन्दुओं को मिथिल कर शीतयुद्ध के प्रभाव को और भी कम किया। यूरोपीय राज्यों का भ्रमता शिखर सम्मेलन दिसम्बर, 1973 में होने वाला था, किन्तु चौथे अरब-इजरायल युद्ध और तेल संकट के कारण वह भविष्य के लिए टटा गया।

महान् राष्ट्रों के सम्बन्धों में परिवर्तन और तनाव क्षेत्रों में कमी—सन् 1972 के बाद से ही रुस और अमेरिका के शीर्षस्थ नेता एक दूसरे से मिलते रहे हैं और चीन तथा अमेरिका में भी मेल-मिलाप बढ़ा है। नवम्बर, 1974 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड ने भी ग्लाडोवोस्तक में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव से भेंट की। इन कूटनीतिक यात्राओं और सम्पर्क-सूत्रों के विस्तार के फलस्वरूप और रुस के सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है और चीन तथा अमेरिका के सम्बन्ध भी उत्तरोत्तर अच्छे बन रहे हैं, अतः शीतयुद्ध लगभग ठण्डा पड़ चुका है। बीच-बीच में तनाव पैदा होते हैं लेकिन 'मयम और बार्ता की कूटनीति' शीतयुद्ध के पैर नहीं जमने देती।

कम्बोडियाई युद्ध की समाप्ति, अप्रैल 1975—कम्बोडिया का गृहयुद्ध शीतयुद्ध का एक बड़ा कारण बना हुआ था। इस युद्ध में बड़ी शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से निपट थीं। संयुक्तराज्य अमेरिका लोन-नोल सरकार की पीठ पर था और उसे भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र दे रहा था। विरोधी खमेर सेना को मार्क्सवादी राष्ट्री—विशेषकर चीन से सहायता प्राप्त होती थी। राजकुमार सिहानुक ने लम्बे अर्से से चीन में शरण ले रखी थी। सौभाग्यवश 18 अप्रैल, 1975 को सिहानुक-सेनाओं (प्रथम खमेर सेना)

की विजय के साथ कम्बोडियाई युद्ध का अन्त हो गया और तनाव का एव, अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र समाप्त या शिथिल हो गया ।

वियतनाम-युद्ध का अन्त, 30 अप्रैल, 1975—सन् 1975 का वर्ष एक तरह से समूचे विश्व के लिए शुभ था । कम्बोडियाई युद्ध के कुछ ही दिनों बाद 30 अप्रैल, 1975 को वियतनाम का ऐतिहासिक युद्ध भी समाप्त हो गया । संयुक्तराज्य अमेरिका की कठपुतली सँगोन सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया । अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार ने सम्पूर्ण दक्षिण वियतनाम का नियन्त्रण सम्भाल लिया । वियतनाम का युद्ध बहुत ही विस्फोटक था जिससे कई बार महायुद्ध तक का खतरा उत्पन्न हो गया था । राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे और उत्तर वियतनाम की पीठ पर रुम और चीन थे तथा दक्षिण वियतनाम की कठपुतली थियू सरकार के पीछे संयुक्तराज्य अमेरिका था । अमेरिका तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग ले रहा था लाखों की सख्या में अमेरिकी सैनिक वियतनाम में उपस्थित थे । 14 वर्ष के लम्बे युद्ध ने 30 अप्रैल, 1975 को प्रकाशित दिनमान के समाचारों के अनुसार 56 हजार 550 अमेरिकियों की जानें गईं और 150 अरब डॉलर खर्च हुए । घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 3,03,682 थी और लापता सैनिकों की संख्या 2949 । ये तो सरकारी आँकड़े हैं, अथवा अमेरिकी जन-घन की हानि कहीं अधिक हुई होगी । यदि अमेरिका वियतनाम युद्ध में सक्रिय सैनिक हस्तक्षेप न करता और राजनीतिक ढंग से सम्मानजनक समझौता करने की ईमानदारी दिखाता तो वियतनाम युद्ध कभी का समाप्त हो गया होता और अमेरिका को उस लज्जाजनक रूप में वियतनाम से न हटना पड़ता जिस रूप में वह 30 अप्रैल, 1975 के आस-पास हटा । वियतनाम के स्वतन्त्रता-मेनानियों की विजय विश्व के स्वाधीनता-आन्दोलनों के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी । वियतनाम युद्ध कितना भयानक था, इसका अनुमान इन्हीं आँकड़ों से लगाया जा सकता है कि "इस युद्ध में लगभग 10 लाख लोगों की जानें गईं, द्वितीय विश्वयुद्ध से दुगुने खम बरसाए गए, यही नहीं नापाम बमों को असेनिक ठिकानों पर भी खुला इस्तेमाल किया गया ।" (दिनमान 11 मई, 1975)

पश्चिमी एशिया शान्ति की ओर—पश्चिमी एशिया में अरब-इजरायल संघर्ष लगभग 27 वर्ष से शीतयुद्ध और सशस्त्र युद्ध का कारण बना हुआ था । लेकिन सन् 1975 के मध्य से ही पश्चिमी एशिया में शान्ति के आसार अधिक प्रबल हो गए हैं । 4 सितम्बर, 1975 को अमेरिका, मिस्र और इजरायल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ । समझौते में तय किया गया कि सिनाई पर्वतमाला के दरों (गिदी और मितला) और उनके इर्दगिर्द आठ निगरानी चौकियाँ होंगी—एक चौकी पर इजरायल का पूर्ण नियन्त्रण रहेगा और एक पर मिस्र का । अन्य छः चौकियों पर 200 अमेरिकी तकनीकी कर्मचारी रहेंगे । इन चौकियों में कुछ पूर्ण स्वचालित भी हो सकती हैं । ये निगरानी चौकियाँ किसी भी पक्ष की ओर से किए जाने वाले आक्रमण की पूर्व सूचना देने का काम करेंगी । प्रबुद्धी तेल क्षेत्र मिस्र की अधिक मार में आ जाएगा । इस तेल क्षेत्र से इजरायल को अपनी जरूरत का 55 प्रतिशत तेल

प्राप्त होता था, किन्तु आयात में कोई व्यवधान पड़ने की स्थिति में अमेरिका ने उसकी आवश्यकता पूर्ति करने की गारंटी दी। मिस्स ने अमेरिका में यह वायदा किया कि वह इजराइल को जाने वाले टैंकरो को रोकने के लिए साल सागर की नाकेबन्दी नहीं करेगा।¹ यह भी निश्चय किया गया कि अब इजराइल का माल किसी तीसरे देश के जहाज में निःशुल्क स्वेज नहर से भेजा जा सकेगा। इजराइल के लिए यह एक महत्वपूर्ण सुविधा थी जिसे पिछले 27 वर्षों में अरबों से चार लड़ाइयाँ लड़ने के बाद भी वह प्राप्त नहीं कर पाया था। समझौते की प्रमुख धारा यह थी कि नए गलियारे (बफर क्षेत्र) में मिस्स, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त राष्ट्र की शान्ति-रक्षण सेनाओं के बीच सहयोग की व्यवस्था रहेगी। यह सहयोग जितना ही अधिक होगा, मिस्स और इजराइल के बीच टकराव की सम्भावना उतनी ही कम होगी।²

10 अक्टूबर, 1975 को मिस्स और इजराइल के अधिकारियों ने उपर्युक्त समझौते को विधिवत् कार्यान्वित करने और पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण समझौता किया। यद्यपि इस समझौते से पश्चिमी एशिया में शान्ति का वातावरण बन गया तथापि स्थायी शान्ति एक प्रश्न चिह्न बनी रही। महाशक्तियों के माध्यम से समझौता वातावरण चालू रही।³ जुलाई-अगस्त 1977 में पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिए एक बार फिर सक्रिय प्रयास हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वैस ने पश्चिमी एशिया की यात्रा करके मिस्स, सीरिया, जोर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और इजराइल के नेताओं से बातचीत की। मिस्स के राष्ट्रपति अनवर सादात ने स्पष्ट रूप से कहा कि पश्चिमी एशिया में शान्ति सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव न० 242 का अनुमरण करने से हो सकती है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इजराइली सेनाएँ 1967 के अरबों के अधिकृत इलाकों को खाली कर दें। सादात ने आश्वासन दिया कि ऐसा हो जाने पर इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी जाएगी। अपनी सद्भावना जतलाने के लिए अनवर सादात ने घोषणा की कि मिस्स में रहने वाले सभी यहूदियों को मिस्स का नागरिक माना जाएगा, उन्हें विस्थापित नहीं कहा जाएगा। साइरस वैस की यात्रा से पश्चिमी एशिया में स्थायी शान्ति की सम्भावना को बल मिला। इसका एक स्पष्ट प्रमाण तब मिला जब 15 नवम्बर 1977, को इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाशेम बेगिन ने मिस्स के राष्ट्रपति अनवर सादात को इजराइल की यात्रा करने के लिए अमेरिकी राजदूत द्वारा लिखित निमन्त्रण भेजा। श्री बेगिन ने जोर्डन, सीरिया और लेबनान के नेताओं को सादात के बाद इजराइल आने का निमन्त्रण दिया। राष्ट्रपति सादात 19 नवम्बर को जब इजराइल पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। यह दुर्भाग्य की बात थी कि मिस्सी राष्ट्रपति की इजराइल यात्रा के विरोध में सीरिया में मिस्स से अपने राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद की घोषणा कर वहाँ से अपने सभी देशवासियों को स्वदेश लौटने की अपील की।

1-2. दिनमान 7 नवम्बर, 1975, पृष्ठ 34.

3. दिनमान 19 अक्टूबर, 1975, पृष्ठ 32.

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जिस शीतयुद्ध का विकास हुआ वह सन् 1962 में वयूबा काण्ड के बाद शिथिल पड़ने लगा। स्वर्गीय कनेडी और ख्रुश्चेव द्वारा शीतयुद्ध को समाप्त करने की दिशा में कार्य प्रारम्भ किया ही गया था कि 22 नवम्बर, 1963 को कनेडी की हत्या कर दी गई और 15 अक्तूबर, 1964 को ख्रुश्चेव को पदच्युत कर दिया गया। दोनों नेताओं के उत्तराधिकारियों ने यद्यपि उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करने का आश्वासन दिया, तथापि दोनों गुटों के बीच शीतयुद्ध किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों जैसे हिन्द-चीन, पश्चिमी एशिया, आदि में तनाव बढ़ने से शीतयुद्ध अधिक उग्र हो जाता और तनाव शिथिल होने पर शिथिल पड़ जाता। प्रारम्भ में जब शीतयुद्ध मुख्यतया अमेरिका और रूस के बीच चलता था तो इसका स्वरूप द्विपक्षीय (Bipolar) होता था, किन्तु बाद में सन् 1969 में रूस-चीन-सीमान्त सपर्ण के कारण इसका स्वरूप त्रिपक्षीय (Tripolar) हो गया। यह शीतयुद्ध सातवें दशक के अन्त तक किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहा और सम्पूर्ण विश्व के वातावरण को विपात कर रहा। आठवें दशक के प्रारम्भ से शीतयुद्ध के कारण एक-एक करके तेजी से समाप्त होते गए। निःशस्त्रीकरण सम्झौता को बल मिला तथा सन् 1971 का बर्लिन सम्झौता और फिर सन् 1972 का पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच सम्झौता सम्पन्न हुआ। सन् 1972 में कोरिया सम्झौता हुआ। सन् 1972 के बाद से ही महाशक्तियों के सम्बन्धों में परिवर्तन के फलस्वरूप तनाव शिथिल होता गया। केवल हिन्द-चीन और पश्चिमी एशिया के सकट के कारण तनाव क्षेत्र उभरते रहे, लेकिन 'सयम और वार्ता की कूटनीति' ने शीतयुद्ध के पैर नहीं जमने दिए। सन् 1975 के मध्य तक कम्बोडियायी, वियतनामी और अरब-इजराइली संघर्ष का अन्त हो गया और इस तरह विश्व ने शीतयुद्ध से मुक्ति की साँस ली। जिस तरह का अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बनता जा रहा है उससे यही आशा बलवती होती है कि निकट भविष्य में शीतयुद्ध पुनः नहीं भड़केगा—शीतयुद्ध का युग अब समाप्त हो चुका है।

शीतयुद्ध में शिथिलता के कारण

शीतयुद्ध के इतिहास के इस विवेचन से स्पष्ट है कि काफी उतार-चढ़ाव के बाद पिछले कुछ वर्षों से शीतयुद्ध की उग्रता निरन्तर घटती गई है। इसके मूल में जो मुख्य कारण रहे हैं वे ये हैं—

1. दोनों महाशक्तियाँ यह अनुभव करती जा रही हैं कि सैनिक शक्ति के बल पर समस्या का निदान बहुत कठिन और व्यय-साध्य है। वियतनाम के युद्ध ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को घुटने टिका दिए, युद्ध से उसके सैनिकों का ही विनाश नहीं हुआ बल्कि उसका अर्थ-तन्त्र भी संकट में पड़ गया उसका व्यापार-सन्तुलन बिगड़ गया और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार में डॉलर की साख तक खतरे में पड़ गई।

2. दोनों महाशक्तियों को यह आशंका भी सताने लगी है कि शीतयुद्ध कभी

भी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे तृतीय महायुद्ध का विस्फोट हो जाए। यूना के महान् संकट के बाद से ही महाशक्तियों की यह नीति स्पष्ट दिखायी देने लगी है कि वे परस्पर संघर्ष की हर स्थिति से बचती हैं।

3. पूँजीवादी और साम्यवादी शिविरो में अब सैद्धान्तिक संघर्ष उतना तीव्र नहीं रहा है जितना पहले था। अमेरिका के मित्रराष्ट्र शीतयुद्ध की राजनीति से भलग होकर साम्यवादी देशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने लगे हैं और अमेरिका भी अब इसी नीति पर उतर आया है। पूँजीवादी शिविर ने साम्यवादी देशों के साथ प्रचुर व्यापार करने का मार्ग खुला रखने के लिए यह उद्युक्त समझा है कि शीतयुद्ध को यथामाध्य प्रोत्साहन न दिया जाए।

4. गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की सख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और गुट-निरपेक्षता की नीति ने शीतयुद्ध की उग्रता कम करने की महती भूमिका निभायी है।

5. सन्तुल्य राष्ट्रमण्डल में अब महाशक्तियों का प्रभाव वैसा नहीं रहा है जैसा पहले था। अमेरिशियायी राष्ट्रों की सख्या बढ गई है, 'तृतीय विश्व' की आवाज को अब पहले की तरह दबाया जाना सरल नहीं रहा है। इस स्थिति ने शीतयुद्ध की उग्रता को कम किया है।

6. सोवियत संघ द्वारा स्टालिनवादी उग्र नीति का परित्याग कर निरन्तर सह-अस्तित्व की नीति पर बल देने से शीतयुद्ध काफी शिथिल हुआ है। अमेरिकी नवतन्त्र ने भी सोवियत मंत्री और सोवियत नीति का महत्त्व समझकर सहयोगी रुख अपनाया है। दोनों ही गुटों में इस विचारधारा ने बल पकड़ा है कि परम्पर मतभेद होने के बावजूद दोनों गुटों के सम्बन्ध शान्तिपूर्ण रह सकते हैं।

7. पिछले कुछ वर्षों से बड़े राष्ट्रों के नेताओं में सम्पर्क बढ़ा है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन को यह श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने सोवियत रुख और चीन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। उनकी पहल से एक ओर रूस तथा अमेरिका और दूसरी ओर चीन तथा अमेरिका के जो गिहर-सम्बन्ध हुए उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वानावरण के सुधार में वांछी सहयोग मिला।

8. शीतयुद्ध की उग्रता कम करने में भारत की भूमिका भी विशेष महत्त्वपूर्ण रही है। जटिल परिस्थितियों के बावजूद भारत गुट-निरपेक्षता की नीति पर दृढ़ रहा है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तनावों के कम होने में सहायता मिली।

9. मास्को-बोन समझौता, बर्लिन समझौता, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच समझौता, कोरिया समझौता, कम्बोडियाई और वियतनामी युद्ध की समाप्ति आदि घटनाओं ने यह आशा उत्पन्न कर दी है कि विश्व शीतयुद्ध के भँवर में निकल चुका है और शान्ति तथा सह-अस्तित्व की शक्तियाँ प्रबल हो रही हैं।

वास्तव में महान् राष्ट्रों के सम्बन्धों में पिछले वर्षों में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, उन्हीं के फलस्वरूप अनेक समस्याओं का निदान हो सका है और तनाव के क्षेत्र समाप्त तथा कम हुए हैं। विश्व का कल्याण इसी में है कि महाशक्तियाँ अन्य देशों में हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दें, पारस्परिक

सम्बन्धों को मधुर बनाएँ और प्रत्येक समस्या का समाधान शस्त्र-बल के बजाय पारस्परिक बातों द्वारा करें।

शीतयुद्ध और देतात (Cold War and Detente)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों के अनुसार देतात¹ अथवा सोवियत अमेरिकी मंत्री एब्रहम सहयोग का प्रारम्भ कैंनेडी-ख्रुश्चेव के समय से हुआ। उनके अकस्मात् सत्ता से हटने के कारण कुछ समय तक मंत्री और सहयोग का मार्ग अवरुद्ध हो गया, किन्तु निक्सन और ब्रेज्नेव ने सहयोग के सूत्रों का पुनः विकास किया जिससे अमेरिका के विदेश-सचिव डॉ. कीसिजर की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। यद्यपि निक्सन के पद त्याग के बाद फोर्ड भी रुस के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं, तथापि दोनों महाशक्तियों के बीच मैत्री और सहयोग के विकास की गति उतनी तीव्र नहीं है जितनी निक्सन के समय थी।

देतात (सोवियत-अमेरिकी मंत्री एब्रहम सहयोग) के प्रारम्भ के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी माने जाते हैं—

प्रथम, अणुबम के रहस्य पर अमेरिका का एकाधिकार समाप्त हो जाने के कारण रुस और अमेरिका के बीच अस्त्र-शस्त्र की दृष्टि से एक सन्तुलन-सा पैदा हो गया। इसके फलस्वरूप भूतपूर्व अमेरिकी विदेश सचिव डलेस की वह नीति उपयोगी नहीं रही जिससे साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सशस्त्र संघर्ष पर बल दिया जाता था। बर्लिन की घेराबन्दी, कोरिया का युद्ध, वयूबा वाण्ड आदि ने स्पष्ट कर दिया कि महाशक्तियों के बीच 'सहयोग' की आवश्यकता है, 'टकराहट' की नहीं।

द्वितीय रुस की आर्थिक आवश्यकताओं ने उसे अमेरिका की मैत्री प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। साम्यवादी क्रान्ति के पाँच दशक बाद भी सोवियत जनता उत्पादन के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही थी जिससे वे उच्च जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो। अमेरिका के पास यह उन्नत तकनीकी ज्ञान था लेकिन रुस इसका भागीदार तभी बन सकता था जब वह अमेरिका के प्रति संघर्ष के बजाय सहप्रस्थित्व की नीति अपनाता। अतः स्टालिनोत्तर युग में सोवियत नेताओं ने पूँजीवाद के साथ सहप्रस्थित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और इस तरह दोनों महाशक्तियों में सहयोग का द्वार खुल गया।

तृतीय, साम्यवादी चीन के साथ संघर्ष उत्पन्न होने के कारण सोवियत संघ के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह चीन के मुकाबले में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए पश्चिमी देशों और मुख्यतः अमेरिका से शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे।

चतुर्थ, भारत की भूमिका भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रही। एक ओर तो रुस ने समझ लिया कि चीन के विरुद्ध अपनी स्थिति सुदृढ़ कायम रखने में भारत की

1. 'देतात' एक फ्रेंच शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है—धनाप वीचिल्य। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में इसका अर्थ रुस-अमेरिका तनाव में कमी और उनमें बढ़ती हुई मित्रता तथा सहयोग की भावनाओं से लगाया जाता है।

मंत्री मूल्यवान है और दूसरी ओर अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों ने समझ लिया कि रूस-भारत मैत्री अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर प्रभावशाली गुल खिला सकती है। भारत को इस केन्द्रीय स्थिति के कारण महाशक्तियों में सहयोग के सूत्रों को प्रोत्साहन मिला। भारतीय नेताओं ने सदैव इस बात का प्रयत्न किया कि शीतयुद्ध के कारण समाप्त हो और विश्व के बड़े राष्ट्रों के बीच सहयोग का वातावरण स्थापित हो।

पचम, अमेरिका वियतनाम के युद्ध से थक चुका था। वह वियतनामी युद्ध के दलदल से सम्मानपूर्वक सोवियत सघ के सहयोग से ही निकल सकता था।

उपयुक्त कारणों से यह स्वाभाविक था कि दोनों महाशक्तियाँ परस्पर तनाव और सघर्ष के मार्ग का परित्याग कर मैत्री और सहयोग का मार्ग अपनाएँ।

देतांत का शीतयुद्ध पर प्रभाव

देतांत अर्थात् रूस-अमेरिकी सहयोग का शीतयुद्ध पर निर्णायक प्रभाव पड़ना अवश्यम्भावी था। दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव ही शीतयुद्ध की जड़ था और जब दोनों महाशक्तियों ने यह नीति अपना ली कि वे क्रमशः सहयोग के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो शीतयुद्ध भी अपनी साँसें गिनने लगा। देतांत का प्रारम्भ तो कनेडी एड्रियेच के कार्यकाल में ही हो चुका था, लेकिन इसे वास्तविक ठोसरूप निक्सन-ब्रेझ्नेव-काल में मिला। इसकी प्रथम वास्तविक अभिव्यक्ति तब हुई जब मई, 1972 में निक्सन शिखर वार्ता के लिए मास्को गए और वहाँ उन्होंने आशा व्यक्त की कि—“इस शिखर-वार्ता से शान्तिपूर्ण सहयोग एक वास्तविकता बन जाएगा और दोनों देश विश्व की समस्त जनता की सुख समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम कर सकेंगे।” मई, 1972 की इस शिखर-वार्ता के फलस्वरूप रूस और अमेरिका के बीच एक के बाद एक विभिन्न समझौतों का मार्ग प्रशस्त हो गया। निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी समझौते भी सम्पन्न हुए और आर्थिक समझौते भी। देतांत के विकास का दूसरा चरण जून, 1973 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव की वाशिंगटन यात्रा से प्रारम्भ हुआ। इस शिखर-वार्ता में दोनों देशों के बीच समुद्र-विज्ञान सहित अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग तथा मौखिक आदान-प्रदान सम्बन्धी कई समझौते सम्पन्न हुए। इस शिखर-वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का विकास करना था, वन दोनों नेताओं ने यह निश्चय किया कि इस क्षेत्र में रूस और अमेरिका को परस्पर माभीदार बनाना चाहिए। निक्सन और ब्रेझ्नेव की इन यात्राओं के फलस्वरूप दोनों महाशक्तियों के बीच जो सहयोगपूर्ण समझौते हुए उनसे कारण “शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया और विश्व-शान्ति का वातावरण सुहृद हो गया।”

अगस्त, 1974 में देतांत के प्रतिपादक निक्सन को वाटरगेट काण्ड ने कारण राष्ट्रपति-पद से हटाना पड़ा और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति जगत् में देतांत ने भविष्य के प्रति आशांका व्यक्त की जाने लगी, लेकिन नए राष्ट्रपति फोर्ड ने देतांत को सुहृद करने का आश्वासन दिया और प्रमाण स्वरूप देतान्त के एक प्रमुख निर्माता

निम्नतम प्रशासन के विदेश सचिव डॉ. कीसिजर को अपने प्रशासन में भी उसी पद पर पुनः नियुक्त किया। फोर्ड-ब्रेज्नेव काल में देतांत का क्रमशः विकास होता रहा। फोर्ड और ब्रेज्नेव के बीच नवम्बर, 1974 में सामरिक अस्त्र-परिसीमन के लिए समझौते के दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए बातचीत हुई और दोनों ही पक्षों ने अपनी अणुशस्त्र की दौड़ पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना स्वीकार किया। शीतयुद्ध के विरुद्ध विकसित देतान्त की इस भावना को जनवरी, 1975 में तब कुछ ठेस लगी जब अमेरिकी कांग्रेस ने दोनों महाशक्तियों के बीच सम्पन्न व्यापारिक समझौते को यहूदियों को सोवियत संघ से बहिर्गमन की स्वतन्त्रता दिए जाने की शर्त के साथ जोड़ दिया और सोवियत संघ ने उसे प्रस्वीकृत कर दिया। तथापि यह कोई स्थायी घबरोह नहीं था, दोनों देशों ने बीच सहयोग के सूत्र विकसित होते रहे और सामरिक महत्त्व के शस्त्रास्त्रों के परिसीमन की सन्धि (Strategic Arms Limitation Treaty) और यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन की तैयारियाँ चालू रही।

20 जनवरी, 1977 को डेमोक्रेटिक पार्टी के 53 वर्षीय जेम्स अर्ल (जिम्मी) कार्टर ने अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ग्रहण की। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में यह आशा की गई कि कार्टर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति को बढ़ावा देगे तथा साम्यवादी और पूँजीवादी सहप्रतिस्ति के बल प्रदान करेंगे। कार्टर-प्रशासन का 1978 के प्रारम्भ तक का इतिहास यही संकेत देता है कि महाशक्तियों के परस्पर सहयोग तथा सहभावना को बल मिला है तथा वेतात-भावना का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। विभिन्न समस्याओं पर रूस और अमेरिका के मतभेदों की उद्गता कम हुई है और दोनों महाशक्तियाँ यह अधिक अच्छी तरह समझने लगी हैं कि 'सहयोग और शान्ति की विजय' में ही मानव सभ्यता का सुनहरा भविष्य सुरक्षित है।

यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन और हेलसिंकी भावना का निर्माण

फिनलैण्ड की राजधानी हेलसिंकी में 30 जुलाई से 1 अगस्त, 1975 तक यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन बुलाने की मांग सबसे पहले सोवियत संघ द्वारा सन् 1966 में ब्रुडोपेस्ट साम्यवादी सम्मेलन की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यूरोप का जो नया राजनीतिक मानचित्र बना था और जो नए सीमान्त स्थापित हुए थे तथा जिनकी अस्वीकृति और परिवर्तन के प्रयासों से पुनः तनाव और संघर्ष उत्पन्न होने की सम्भावना थी, उन्हें स्थायित्व प्रदान किया जाए और इस तरह तनाव तथा संघर्ष के एक बड़े कारण को समाप्त किया जाए।

हेलसिंकी सम्मेलन में अल्बानिया को छोड़कर अमेरिका, सोवियत संघ और कनाडा सहित पश्चिमी तथा पूर्वी यूरोप के सभी राष्ट्रों ने भाग लिया। भाग लेने वाले देशों की कुल संख्या 35 थी। सम्मेलन में 30 हजार शब्दों का एक घोषणा-पत्र भाग लेने वाले राष्ट्रों के हस्ताक्षरों से 'स्वीकृत' हुआ जिसे फिनलैण्ड के राजकीय अभिलेखागार में 18 मीटर की गहराई में चमड़े की एक हरी जिल्द में बांधकर

सुरक्षित रख दिया गया है और इसकी प्रतिलिपियाँ ही देखने को उपलब्ध हुई हैं। इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक अपवाद स्वरूप इस मूल प्रति को देखने की विशेष अनुमति न दी जाए। यह घोषणा-पत्र एक वानूनी दस्तावेज होने के बजाय वस्तुतः आचरण की एक नैतिक संहिता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह द्वितीय महायुद्ध और उसके तनावपूर्ण शीतयुद्ध के कुपरिणामों को समाप्त करने वाला और उसके स्थान पर सदस्य-राष्ट्रों में सुरक्षा और सहयोग की भावना को जन्म देने वाला है तथा समुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव कुर्त वाल्डहीम के अनुसार व्यावहारिक समझौते का प्रतीक है। इस सम्मेलन द्वारा स्वीकृत घोषणापत्र के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं—राज्यों की प्रभुमत्ता को एक दूसरे के द्वारा स्वीकृति प्रदान होना, बल-प्रयोग से बचे रहने का मकल्प, राष्ट्रों के बीच समस्त विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान, सीमाओं की अखण्डता का सम्मान, मानव और मूलभूत अधिकारों के प्रति आदर, राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, आदि। सम्मेलन इस रूप में ऐतिहासिक था कि इसमें भाग लेने के लिए 35 यूरोपीय अमेरिकी देशों के राजाध्यक्ष और शीर्ष नेता पहुँचे और वे मोटे तौर पर इस बात के लिए चिन्तित रहे कि 'नरमी' (देतात) में कहीं कमी और यूरोप की आज की स्थिति में कोई गिरावट न आने पाए। मार्शल टीटो ने कहा कि सुरक्षा और सहयोग एक नए अन्तर्राष्ट्रीय आधिक स्वरूप के बिना अघूर रहेगे। उन्होंने 'नरमी' (देतात) का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तटस्थ और विकासशील राष्ट्रों पर उनकी स्वतन्त्र नीतियों के कारण नए दबाव डाले जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शक्ति-के नाम पर हथियारों की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

यूरोपीय सुरक्षा-सम्मेलन की सफलता से इस बात की पुनः पुष्टि हो गई कि मतभेदों और अवरोधों के बावजूद सोवियत संघ और अमेरिका सहअस्तित्व, शान्ति और सहकार की दिशा में प्रगति करना चाहते हैं।

सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति-राजनीति (Ideological Conflict Vs Power Politics)

अब हमें 'शीतयुद्ध' के एक दूसरे पहलू पर भी कुछ विचार करना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है कि 'शीतयुद्ध' एक सैद्धान्तिक संघर्ष (Ideological Conflict) है जिसमें दो विरोधी जीवन-पद्धतियाँ (उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद) सर्वोच्चता के लिए संघर्षरत हैं। इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि शक्ति-राजनीति के इस युग में सोवियत संघ और समुक्तराज्य अमेरिका के बीच जो एक विशेष प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता है, वह बहुत कुछ सैद्धान्तिक है। इसके पीछे एक गहन सामाजिक दर्शन है जो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का एक मुख्य कारण बन गया है। समुक्तराज्य अमेरिका सोवियत प्रणाली को एक अन्तर्राष्ट्रीय पड़्यन्त्र मानता है जिसका उद्देश्य अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर अथवा अपना

प्रभाव डालकर साम्यवाद का प्रसार करना है। दूसरी ओर सोवियत संघ पश्चिमी देशों की प्रणालियों को शोषण, आक्रमण हीन उपायों द्वारा स्वार्थ-लाभ तथा संगठित लूट-खसोट पर आधारित मानता है। दोनों देशों और उनके विद्यमान राष्ट्रों के दृष्टिकोण परस्पर इस तरह विरोधी हैं कि उनका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ा है और सर्वत्र रूस व अमेरिका का वैचारिक सघर्ष प्रवेश कर गया है। यह वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक सघर्ष आज विश्व राजनीति का एक आधार बन चुका है और इसी सघर्ष को जारी रखने एवं इसमें सफलता प्राप्त करने के प्रत्येक सम्भव उपाय सोचे जा रहे हैं।

वैसे तो इस सैद्धान्तिक सघर्ष का उदय प्रधानतः सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद ही हो गया था, किन्तु द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में इसने चिन्ताजनक और भीषण रूप धारण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों राष्ट्रों के बीच तनावों में वृद्धि होती गई और विश्व की समस्याओं के प्रति विरोधी नीतियाँ परस्पर टकराने लगी। साम्यवाद को सीमित रखने के लिए अमेरिका ने विभिन्न कदम उठाए। ट्रूमैन सिद्धान्त का प्रतिपादन, मार्शल-योजना जैसे कार्यक्रमों की पूर्ति, सैनिक एवं प्रादेशिक संगठनों की स्थापना आदि बातों से यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने साम्यवाद के विरुद्ध कमर कस ली है। दूसरी ओर साम्यवाद ने पूँजीवादी घेरों को नोडकर साम्यवाद के प्रसार का सकल ले लिया। इसका अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि द्वितीय महायुद्ध के बाद 'श्रीतयुद्ध' का दानव समग्र संसार को घसने लगा। स्थिति यह बन गई कि सैद्धान्तिक सघर्ष में विजय पाने और श्रीतयुद्ध को कायम रखने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सैनिक सभी प्रकार के उपाय काम में लाए जाने लगे। लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसे भी कार्य हो रहे हैं जिनमें सघर्ष विरोधाभास है। सघुत्तराज्य अमेरिका लोकतन्त्र की साम्यवाद से रक्षा नाम पर विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता देता है ताकि वहाँ की स्थिति सुदृढ़ रहे और साम्यवाद के प्रसार का अवसर न मिले। लेकिन यह आर्थिक सहायता उन्हीं देशों को प्राप्त होती है जो सोवियत संघ के विरोधी हैं या उनको जिनकी स्थिति अब अच्छी नहीं है और जहाँ लोकतन्त्र के प्रति आस्था मिटती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। उदारवाद को महत्त्व न दिया जाकर विचारों की विभिन्नता को घृणा से देखा जाता है। स्वतन्त्र विचारों के लिए आदर न होने से विश्व में अविश्वास की राजनीति को बल मिला है।

दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति इतने सशक्त हैं कि अपनी व्यवस्था के रक्षार्थ उन्होंने गुप्तचरों का एक विश्व-व्यापी जाल बिछा रखा है। सैद्धान्तिक सघर्ष में और एक-दूसरे के दर्शन से अपने दर्शन को अथवा अपने रहन-सहन को श्रेष्ठतर सिद्ध करने के लिए प्रचार के सभी साधन अपनाए जाते हैं। प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर अधिकसित देशों की मित्रता खरीदी जाती है, सामरिक सामग्री पर नियन्त्रण किया जाता है और दुर्बल देशों के अर्थतन्त्र को नियन्त्रित किया जाता है। इतना ही

नहीं, अन्य देशों में जो राजसत्ता के लिए सघर्ष होते हैं उनमें किसी दल विशेष का पक्ष लेकर सैद्धान्तिक सघर्ष को बढ़ाया जाता है।

इस तरह वर्तमान शीतयुद्ध का एक सर्वोपरि आधार सैद्धान्तिक या वैचारिक सघर्ष (Ideological Conflict) ही है। आर्नोल्ड टॉयनबी ने शीतयुद्ध को एक सैद्धान्तिक सघर्ष मानते हुए विश्व-राजनीति की 'द्वि-ध्रुवी' व्याख्या की है। टॉयनबी के अनुसार वर्तमान समय में विश्व-राजनीति में केवल दो सिद्धान्त और केवल दो शक्तियाँ हैं—उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद और संयुक्तराज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस। यह कहा जाता है कि सत्तार के अन्य राज्यों के पास इसके प्रतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प नहीं है कि इन दो महाशक्तियों में से एक-न-एक का साथ दें। मार्शल टीटो का सोवियत सघ के विरुद्ध विद्रोह अथवा भारत पर असह्यतावाद किसी भी ऐच्छिक विकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु महाशक्तियों द्वारा चयनित विकल्प (Choice Allowed) का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात इसी से स्पष्ट है कि यदि रूस और अमेरिका में कभी अन्तिम सघर्ष का अवसर उपस्थित हो जाए तो यूगोस्लाविया अथवा भारत के पास सिवाय इसके कोई प्रभावी विकल्प नहीं रहेगा कि वे दोनों में से किसी एक पक्ष का साथ दें।

यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि स्वयं पश्चिमी शक्तियाँ और साम्यवादी देश भी शीतयुद्ध के एक सैद्धान्तिक सघर्ष होने का दावा करते हैं। पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसे एक सैद्धान्तिक सघर्ष मानने का स्पष्टतम प्रमाण 5 मार्च, 1946 को चर्चिल की विख्यात 'फुल्टन वक्तृता' है जिसमें उन्होंने यूरोप के द्वार-द्वार सोवियत 'लोह आवरण' (Iron Curtain) की निन्दा करते हुए सोवियत खतरे से ईसाई सभ्यता की रक्षा करने तथा साम्यवादी निरकुशता द्वारा गुलाम बनाए गए लोगों को स्वतन्त्र कराने के लिए एक एंग्लो-अमेरिकी मंत्री सन्धि पर दल दिया था। शीतयुद्ध एक सैद्धान्तिक सघर्ष है, इस सम्बन्ध में रूसी दावे की पुष्टि उस घोषणा-पत्र के निम्नलिखित अंशों द्वारा की जा सकती है जो 5 अक्टूबर, 1947 को रूस सहित 18 प्रमुख साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मास्को तथा वारसा में एक साथ प्रसारित किया गया था—

“..... दो विरोधी राजनीतिक विचारधाराएँ उजागर हो गई हैं। एक और सोवियत सघ तथा अन्य लोकतन्त्रीय राज्यों का उद्देश्य साम्राज्यवाद का विनाश करना तथा लोकतन्त्र को मजबूत बनाना है। दूसरी ओर इंग्लैंड तथा अमेरिका का उद्देश्य साम्राज्यवाद को मजबूत बनाना तथा लोकतन्त्र का गला घोटना है। चूँकि सोवियत सघ तथा लोकतान्त्रिक देश विश्व-प्रभुत्व एवं लोकतन्त्रीय आन्दोलनों के दमन की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक हैं इसलिए इंग्लैंड तथा अमेरिका के खूनी साम्राज्यवादियों ने सोवियत सघ तथा नए लोकतन्त्र के प्रतीक अन्य देशों के विरुद्ध एक अभियान प्रारम्भ कर दिया है।..... इन परिस्थितियों में साम्राज्यवाद-विरोधी लोकतन्त्रीय समुदाय के लिए संगठित होना तथा साम्राज्यवादी समुदाय की

प्रमुख शक्तियों के विरुद्ध अपनी नीति निश्चित करने हेतु एक सामान्य मञ्च (Common Platform) का निर्माण करना आवश्यक है।”

निष्कर्ष यही निकलता है कि शीतयुद्ध को एक सैद्धान्तिक संघर्ष की संज्ञा दिया जाना गतत नहीं है, पर यह कहना अवश्य भ्रामक है कि यह केवल एक सैद्धान्तिक संघर्ष है। शीतयुद्ध और सैद्धान्तिक संघर्ष पर्यायवाची नहीं हैं बल्कि सैद्धान्तिक संघर्ष शीतयुद्ध के एक प्रधान कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। नेतृत्व की होड़, प्रभाव-विस्तार की होड़, शक्ति-प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएँ प्रादि अनेक अन्य तत्त्व भी हैं जो शीतयुद्ध भड़काते हैं।

गुट-निरपेक्षता

(NON-ALIGNMENT)

‘यदि हम अपने आपको किसी एक गुट के साथ संयुक्त कर लेते हैं तो शायद एक प्रकार से यह अच्छा कदम सिद्ध होगा, लेकिन हमें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। इससे हम दुनिया में अपना प्रभाव काम में नहीं ला सकेंगे।’ — जवाहरलाल नेहरू

गुट-निरपेक्षता अथवा असलग्नता की नीति को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप देने का श्रेय भारत को है। स्वतन्त्र भारत ने अपनी विदेश नीति का इसे आधार-स्तम्भ बनाया और कठोर वाचाओं के बावजूद इस नीति को आगे बढ़ाया। धीरे-धीरे गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होती गई। सन् 1961 में बेलग्रेड के गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 25 देश सम्मिलित हुए थे जबकि सन् 1973 में अल्जीरिया में सम्पन्न शिखर सम्मेलन में 76 देशों ने भाग लिया। वर्तमान प्रवृत्ति यही है कि जो भी राष्ट्र गुलामी की वेडियों से मुक्त होकर स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्रों के रूप में उदित हो रहे हैं वे अधिकांशतः गुट-निरपेक्ष नीति को ही अपनाना श्रेयस्कर समझते हैं। सबसे ताजा उदाहरण अप्रैल, 1975 में बम्बोडिया में लोननोल सरकार के पलायन के उपरान्त विजयी सिद्धान्तिक सरकार की घोषणा है जिसमें बम्बोडिया के लिए गुट-निरपेक्षता की नीति की स्वीकार किया गया है। भारत विश्व के सभी गुट-निरपेक्ष देशों की ‘आशा’ है और विश्व-पटल पर भारत की आवाज का आज पहले से अधिक महत्व है। महाशक्तियाँ चाहे गुट-निरपेक्षता की नीति में हृदय से विश्वास न करती हो, लेकिन प्रकट रूप में इस नीति के प्रति वे सम्मान प्रदर्शन करती हैं। साम्यवादी चीन, जो विस्तारवादी और सैनिकान्धनी नीति का अनुसरण कर रहा है, स्वयं को ‘गुट-निरपेक्ष कहलाता है’ अत्यधिक पसन्द करता है। पाकिस्तान जैसे देश के लिए गुट-निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखता, फिर भी वह गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्रवेश का प्रयत्न करता रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि गुट-निरपेक्षता की नीति आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपनी जड़ जमाकर एक ‘वास्तविकता’ बन गई है।

गुट-निरपेक्षता का अर्थ और उसके तत्त्व

गुट-निरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति-गुटों से तटस्थ या अलग रहते हुए अपनी स्वतन्त्र निर्णय-नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार न्याय का समर्थन करना। इसका अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में 'तटस्थता' (Neutrality) नहीं है। गुट-निरपेक्ष देश विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन नहीं रहते बल्कि एक ऐसी स्पष्ट और रचनात्मक नीति का अनुसरण करते हैं जो विश्व-शान्ति की स्थापना में सहायक हो। भारत सरकार के एक प्रकाशन के अनुसार—“गुट-निरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतन्त्र नीति-नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य-प्रनीचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ जुड़कर उचित-अनुचित का विचार किए बिना आंख मूंदकर पीछे-पीछे चलना गुट-निरपेक्षता नहीं है।” ‘तटस्थता’ और ‘गुट-निरपेक्षता’ पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। इनमें यह समानता तो है कि दोनों के अन्तर्गत शीतयुद्ध के समय संघर्ष से पृथक् रह जाता है, लेकिन आधारभूत अन्तर यह है कि जहाँ वास्तविक युद्ध छिड़ने पर एक तटस्थ राष्ट्र युद्ध से पृथक् रहता है वहीं गुट-निरपेक्ष देश युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से उलझ सकता है। न्याय का समर्थन करते हुए उसकी विदेश नीति सकारात्मक रूप में संचालित होती है। स्विट्जरलैण्ड एक ‘तटस्थ’ देश है जबकि भारत एक ‘गुट-निरपेक्ष’ देश है। गुट-निरपेक्षता के अप्रदूत स्व. नेहरू ने कहा था—“मैं ‘तटस्थ’ शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्धकाल में होता है। शान्ति-काल में भी इससे एक प्रकार युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है।” जॉर्ज लिस्का ने लिखा है कि—“किसी विवाद के सन्दर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत है, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किन्तु असंलग्नता या गुट-निरपेक्षता का अर्थ है सही ओर गलत में भेद करना तथा सदैव सही नीति का समर्थन करना।”¹

गुट-निरपेक्षता कोई निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं है। यह एक सक्रिय और स्वतन्त्र सिद्धान्त है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अन्तर्राष्ट्रीय घटना-चक्र से अन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। गुट-निरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी देश के साथ तनिक गुटबन्दी में सम्मिलित न होना, पश्चिमी या पूर्वी गुट के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न ढँचना, किसी भी प्रकार की आक्रामक सन्धि से अलग रहना, शीतयुद्ध से पृथक् रहना, राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। सन् 1961 में गुट-निरपेक्षता के तीन कार्य-धारों नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके पाँच आधार अथवा तत्त्व स्वीकार किए थे—

- (1) सदस्य-देश स्वतन्त्र नीति पर चलता हो;
- (2) सदस्य-देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो;

(3) सदस्य-देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो;

(4) सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो; एवं

(5) सदस्य-देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो।

गुट-निरपेक्षता की जो तीव्र भारत ने सन् 1946-47 में रखी वह समय के साथ और भी अधिक दृढ़ बन चुकी है। स्व. नेहरू के ये शब्द आज भी इस नीति के सन्दर्भ में सजीव हैं—

“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय की घमकी दी जाती हो, अथवा जहाँ आक्रमण होता हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।”

पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाकर बंगला देश के उदय में भारत ने जो ऐतिहासिक भूमिका अदा की वह स्व. नेहरू के उपर्युक्त शब्दों की पुष्टि करती है। इससे मिट्ट होना है कि गुट-निरपेक्षता का अर्थ ‘थोथा शान्तिवाद’ नहीं है। यह निर्भयता और साहस की नीति है, कायरता की नहीं।

गुट-निरपेक्षता का विकास : प्रोत्साहन देने वाले कारक

गुट-निरपेक्षता की नीति सैद्धान्तिक रूप में तो बहुत पहले से विद्यमान थी लेकिन इसे व्यावहारिक और साकार रूप मिला भारत के स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय होने पर। इसके बाद कुछ और भी राष्ट्रों ने गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाया। इनमें प्रमुख थे—इण्डोनेशिया, यूगोस्लाविया तथा संयुक्त अरब गणराज्य लेकिन छठे और सातवें दशक में एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतन्त्र हुए जिनमें से अधिकांश ने गुट-निरपेक्षता को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया और आग बिबब के बहुसंख्यक देश इस नीति का समर्थन करते हैं तथा इसे मान्यता देने हैं जब सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 25 देश सम्मिलित हुए। सन् 1964 के काहिरा शिखर सम्मेलन में 74 गुट निरपेक्ष देशों ने भाग लिया; सन् 1970 के लुसाका सम्मेलन में यह संख्या 54 पहुँच गई और सन् 1973 में अल्जीरिया में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का जो सम्मेलन हुआ उसमें 76 सदस्य-देशों ने भाग लिया।

गुट-निरपेक्षता की इस लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण ये हैं—

1. राष्ट्रवाद की भावना—नवोदित राष्ट्रों के नेता गुट-निरपेक्षता के समर्थकों में राष्ट्रवाद का आश्रय लेते रहते हैं। फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट-ब्रिटेन का इतिहास भी बताता है कि ये देश राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही तटस्थता की नीति को प्रभावित हुए।

2. उपनिवेशवाद का विरोध—नवोदित अफ्रीकियाई राष्ट्रों में यह भाव विद्यमान रहा है कि बड़े राष्ट्रों के साथ सैनिक सन्धिपत्रों में बँध जाने पर वे फिर से उनके दबाव में आ जाएँगे। उपनिवेशवाद का बड़ा फल खाने के बाद अब नवोदित देश य

समझने लगे हैं कि गुटों से निरपेक्ष रहकर ही वे अपने आत्म-सम्मान की रक्षा कर सकते हैं।

3. दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की इच्छा—नवोदित राज्यों को अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए उन्नत राष्ट्रों से आर्थिक और प्राविधिक सहायता की आवश्यकता रहती है। गुट-निरपेक्षता की नीति प्रपनाकर ये देश पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही गुटों से सहायता लेने में सफल होते हैं। फलस्वरूप गुट-निरपेक्षता की नीति अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। यही एक ऐसी नीति है जिस पर चलकर बिना शर्त सहायता ली जा सकती है।

4. जातीय एवं सांस्कृतिक पहलू—गुट-निरपेक्षता की नीति का एक जातीय और सांस्कृतिक पहलू भी है इस नीति के समर्थक मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के वे देश हैं जिनका यूरोपीय राष्ट्रों ने आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया। ये देश अश्वेत हैं और उनमें जातीय तथा सांस्कृतिक समानताएँ हैं। सांस्कृतिक एकता की कड़ियाँ यद्यपि मजबूत नहीं हैं, तथापि इस बारे में सभी एकमत हैं कि वे किसी भी बड़ी शक्ति के अधीन न रहे।

5. शान्तिपूर्ण विकास की इच्छा—गुटीय प्रतिस्पर्धा नवोदित राष्ट्रों के लिए हानिकारक है। शान्तिपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि गुटों से पृथक् रहने की नीति का अनुसरण किया जाए।

गुट-निरपेक्षता की अभिव्यक्ति : विभिन्न सम्मेलन

गुट-निरपेक्ष देशों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती गई और इस नीति की अभिव्यक्ति समय-समय पर होने वाले विभिन्न सम्मेलनों में हुई है। गुट-निरपेक्ष देश कभी शिखर-सम्मेलनों का आयोजन करते हैं तो कभी विदेशमन्त्रियों के सम्मेलन का। इससे चार मुख्य लाभ होते हैं—(1) गुट-निरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है (2) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर गुट-निरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण की स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति होती है, (3) गुट-निरपेक्ष देशों में पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि होती है, एवं (4) विश्व के राजनीतिक रगमंच पर गुट-निरपेक्ष देशों की आवाज को बल मिलता है।

अभी तक गुट-निरपेक्ष देशों के जो महत्वपूर्ण सम्मेलन और विदेशमन्त्री-सम्मेलन हुए हैं वे संक्षिप्त में निम्नलिखित हैं—

प्रथम शिखर सम्मेलन (बेलग्रेड), 1961

सितम्बर, 1961 में बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 25 देश सम्मिलित हुए। सम्मेलन के मुख्य विचार-दिन्दु ये थे—

1. महाशक्तियों से अनुरोध किया गया कि वे शीतयुद्ध की उग्रता कम करें, आपसी बातचीत द्वारा समस्याओं के हल खोजें और निःशस्त्रीकरण के लिए सक्रिय रूप से प्रयाग करें।

2. विश्व में शान्ति-स्थापना के लिए सभी देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करने पर बल दिया गया।

3. विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी देशों को अपने ढंग से शासन-संचालन की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए और किसी के घरेलू मामलों में विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

4. दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की निन्दा की गई।

5. विश्व में सैनिक अड़ों को समाप्त करने की अपील की गई।

6. सभी विचारधाराओं के सह-अस्तित्व को विश्व-शान्ति के लिए आवश्यक माना गया। यह भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयों को पूरी मान्यता दी जानी चाहिए।

बेलग्रैंड सम्मेलन में कुछ मतभेद भी उभरे। इण्डोनेशिया के डॉ. सुकार्णो ने उपनिवेशवाद को समकालीन विश्व की बुराइयों की जड़ बतलाया जबकि पण्डित नेहरू ने विश्व-शान्ति की स्थापना को मुख्य स्थान दिया।

द्वितीय शिखर सम्मेलन (काहिरा), 1964

अप्रैल, 1964 में काहिरा में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 47 देशों ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त 11 देशों के पर्यवेक्षक भी सम्मिलित हुए। सम्मेलन का उद्देश्य गुट-निरपेक्ष क्षेत्र को विस्तृत करना और इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना था।

सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री स्वर्गीय शास्त्री ने विश्व-शान्ति की स्थापना के लिए एक पाँच-सूत्री प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो इन प्रश्नों से सम्बन्धित था—(i) अणु निशस्त्रीकरण; (ii) सीमा-विवादों का शान्तिपूर्वक हल, (iii) विदेशी प्रभुत्व, आक्रमण एवं तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से मुक्ति, (iv) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक विकास, एवं (v) संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यक्रम का समर्थन। भारत ने राष्ट्रों के लिए आचार-संहिता सम्बन्धी एक 10 सूत्री योजना भी प्रस्तुत की। सोवियत संघ ने सम्मेलन के घोषणापत्र की बहुत सराहना की और उसे शान्तिवादी तथा सह-अस्तित्व के विचारों के अनुकूल बताया।

तृतीय शिखर सम्मेलन (लुसाका), 1970

सितम्बर, 1970 में गुट-निरपेक्ष देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में हुआ जिसमें 54 देशों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 9 पर्यवेक्षक सम्मिलित हुए। सम्मेलन के मुख्य विचार-विन्दु ये थे—

1. सम्मेलन ने विश्व के सम्पन्न और निर्धन देशों की खाई को ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आर्थिक तथा सुरक्षात्मक आवश्यकताओं पर बल दिया।

2. पुराने उपनिवेशवाद के साथ-साथ नव-उपनिवेशवाद की भी आलोचना की गई।

3. सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष दलों का स्थायी संगठन बनाने और उसका कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे गुट-निरपेक्षता की भावना को ठेस पहुँचने की सम्भावना थी। भारत के कड़े विरोध के कारण ऐसा संगठन नहीं बन पाया।

जार्जटाउन सम्मेलन, अगस्त 1972

गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का एक चार दिवसीय सम्मेलन जार्जटाउन में हुआ। एक घोषणा का प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरान्त सम्मेलन समाप्त हो गया। इस घोषणा में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं—

1. गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास पर दल दिया गया।

2. हिन्द-चीन, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में संघर्षों पर चिन्ता प्रकट की गई।

3. यह स्पष्ट किया गया कि संयुक्तराष्ट्र महासभा की हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र रखने की घोषणा पर अमल किया जाए।

4. दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार की योजना का प्रारंभिक स्थित कम्बोडिया की सिहानुक सरकार के पांच सूत्री प्रस्ताव का समर्थन किया गया। यह माँग की गई कि अमेरिकी फौजों को वियतनाम से शीघ्र वापस चला जाना चाहिए।

सम्मेलन में भारत सहित 58 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन की आर्थिक समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों को आत्म-निर्भरता पर जोर देना चाहिए। इस बात पर भी बल दिया गया कि सदस्य देश द्वि-पक्षीय व्यापार में यथासम्भव राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करें।

सम्मेलन के अन्तिम अधिवेशन में पारित एक प्रस्ताव में अमेरिका की आक्रमणकारी नीति और हिन्द-चीन में युद्ध विस्तार की कड़े शब्दों में निन्दा की गई।

चतुर्थ शिखर सम्मेलन (अल्जीरिया), 1973

सितम्बर, 1973 में 4 से 8 तारीख तक गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का अल्जीरिया में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 76 देशों ने भाग लिया। यह गुट-निरपेक्ष देशों का अब तक का सबसे बड़ा शिखर-सम्मेलन था। सम्मेलन के मुख्य विचार-विन्दु इस प्रकार थे—

1. लीबिया और अल्जीरिया के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया कि गुट-निरपेक्षता की एक नई परिभाषा की जाए और गुट-निरपेक्ष देशों के लिए नया विधान बनाया जाए।

2. इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति नहीं मिल सकी कि सम्मेलन के लिए एक स्थायी सचिवालय का निर्माण किया जाए। यही तय किया गया कि वर्तमान प्रबन्ध-व्यवस्था चालू रखी जाए।

3. घोषणापत्र में सुझाव दिया गया कि तटस्थ राष्ट्र कम्बोडिया के राजकुमार सिहानुक की निर्वासित सरकार को मान्यता दें। यह भी कहा गया कि मिस्र सीरिया और जोर्डन को उन क्षेत्रों की मुक्ति के लिए राजनयिक सहयोग दिया जाए जो इजराइल ने अपने अधिकार में कर लिए हैं। वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को भी राजनयिक सहयोग देने की सिफारिश की गई।

4. फिडेल कास्ट्रो ने घोषणा की कि क्यूबा इजराइल से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ रहा है।

5. अफ्रीकी मुक्ति-ग्रान्दोलनों को सहयोग दिए जाने का प्रश्न सम्मेलन में कई बार उठाया गया।

6. फिडेल कास्ट्रो ने रूस को गुट-निरपेक्ष देशों का समर्थक बताया जबकि लेटिन अमेरिकी देशों, विशेषकर आजील पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि वे अमेरिकी साम्राज्यवाद को प्रथम दे रहे हैं।

7. भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने कहा कि कुछ बड़े देशों द्वारा दुनिया पर प्रभुत्व जमाए रखने के प्रयत्नों का प्रतिरोध किया जाना चाहिए।

8. सम्मेलन में बड़े राष्ट्रों की चर्चा और आलोचना हुई, पर चीन का उल्लेख नहीं हुआ। प्रेक्षकों ने यह महसूस किया कि शिखर-सम्मेलन में पश्चिमी देशों से अधिक दिलचस्पी रूस और चीन ने ली।

9. बड़े राष्ट्रों (एस-अमेरिका) के बीच सम्बन्ध-सुधार का स्वागत किया गया, किन्तु यह भी कहा गया कि सम्बन्ध-सुधार से होने वाले लाभ सभी राष्ट्रों में समान रूप से बँटने चाहिए। दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सम्बन्ध-सुधार के परिणाम बड़े राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों के घोषण के नए रूपों में विकसित नहीं होने चाहिए।¹

अल्जीरिया सम्मेलन, 1974

अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरिया में 17 गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का तीन दिवसीय सम्मेलन (20 से 22 मार्च, 1974) सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में निम्न बानों पर विचार हुआ—

1. हिन्द महासागर में अमेरिका द्वारा डिपानो गार्सिया को नौ-सैनिक भड़का बनाने के निश्चय की आलोचना की गई।

2. तेल-उत्पादक देशों से अपील की गई कि वे विकासशील देशों के प्रति नरम रवैया अपनाएँ। तेल के भावों में वृद्धि पर विन्ता व्यक्त की गई।

3. गुयाना, श्रीलंका, नेपाल और लाइबेरिया का एक अध्ययन-गुट बनाया गया जिसे तेल-उत्पादक देशों के संगठन के साथ परस्पर सहयोग और तालमेल द्वारा समस्याओं को मुलभूत के लिए विचार-विमर्श करने का कार्य सौंपा गया।

4. सम्मेलन ने एक अन्तर्संस्कारी गुट का भी गठन किया जिसकी यह दायित्व सौंपा गया कि वह विभिन्न देशों में होने वाले कच्चे माल का जायजा ले और बड़े देशों के साथ कच्चे माल के बारे में समझौता करने की दिशा में अपनी राय दे।²

1. दिनमान, 16 सितम्बर 1973, पृष्ठ 31-32.

2. दिनमान, 31 मार्च 1974, पृष्ठ 28-29.

मार्च, 1975 में हवाना सम्मेलन

मार्च, 1975 में 17 गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हवाना में हुआ। सम्मेलन की विजति में कई अन्तर्राष्ट्रीय मामले सामने आए—

1. हिन्द महासागर में ब्रिटेन और अमेरिका की उपस्थिति की निन्दा की गई। इस बात पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई कि इस क्षेत्र के विदेशी अड्डों पर सैनिक शक्ति बढ़ायी जा रही है और महाशक्तियाँ इस क्षेत्र में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर रही हैं। महाशक्तियों के इस रवैये को हिन्दमहासागरीय क्षेत्र के राज्यों की स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय अखण्डता पर आघात माना गया। डियानो गार्सिया में सैनिक गतिविधि के बढ़ने पर विशेष चिन्ता प्रकट की गई।

2. संयुक्त राष्ट्रमण्ड के उस प्रस्ताव का समर्थन किया गया जिसमें हिन्दमहासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाने का समर्थन किया गया था।

3. भारतीय विदेशमन्त्री श्री चहल्लाण ने अपने भाषण में अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया कि वह इस क्षेत्र के अपने मित्रों को विनाशकारी हथियार देकर प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बना रहा है।

4. अन्य राजनीतिक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श हुआ, जैसे तनाय में गिरियलता, पश्चिमी एशिया में उपनिवेशों की समाप्ति, हिन्द-चीन तथा साइप्रस। विदेशमन्त्रियों की समन्वय समिति (या ब्यूरो) द्वारा फिलिस्तीन के प्रश्न पर अलग से एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें इस आवश्यकता का हृदय से समर्थन किया गया कि गुट-निरपेक्ष देश इस विषय से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुपालन में तथा गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों तथा उद्देश्यों के अनुसार फिलिस्तीन में न्यायसंगत तथा स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों में खुलकर तथा ठोस योगदान करें।

5. बैठक के सम्मुख आर्थिक क्षेत्र के प्रमुख प्रश्नों में एक महत्त्व का प्रश्न था—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट से प्रत्यक्ष गम्भीर रूप से प्रभावित देशों की जटिल समस्या। अन्तिम घोषणा के आर्थिक खण्ड में ब्यूरो ने दूसरी बातों के अलावा अपने इस विश्वास की पुनः पुष्टि की कि विश्व की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि समस्त समार इसके लिए ऐसे पारस्परिक सहयोग से कार्य करें जो नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी घोषणा और कार्यक्रम के अनुसार सभी देशों की समानता और सम्मान पर आधारित हो। साथ ही ब्यूरो ने राज्यों के आर्थिक अधिकार और दायित्व सम्बन्धी चार्टर को क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के क्षेत्र में नूतन युग की स्थापना की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

अगस्त, 1975 में लीमा सम्मेलन

गुट निरपेक्ष देशों से विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन 25 से 30 अगस्त, 1975 तक लीमा (पीरू) में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन ने 'परस्पर सहायता एवं एकता का लीमा कार्यक्रम' शीर्षक एक घोषणा प्रस्तावित की। घोषणा के आर्थिक खण्ड में

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की एकता एवं बन्धुत्व को सुदृढ़ बनाने की एक योजना भी शामिल है। इसमें दो भागों में 'विकासशील देशों के बीच सहयोग तथा विकसित देशों में सहयोग' सम्बन्धी एक क्रियात्मक योजना भी है। सम्मेलन में विशिष्ट राजनीतिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर भी प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इस सम्मेलन में 82 सदस्य देशों तथा कई पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कुछ गुटबद्ध देशों ने भी इसमें पर्यवेक्षक तथा अतिथि के रूप में भाग लेने में रुचि प्रदर्शित की। महान् शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में किए गए सैनिक समझौतों में सम्बद्ध तथा अपने क्षेत्र में विदेशी सैनिक अड्डे रखने वाले देशों को गुट-निरपेक्ष सम्मेलनों में नहीं बुलाया जाता था। अतः विचार-विमर्श के बाद उन देशों को, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि सीमा में भेज दिए थे विशेष तौर से अतिथि के रूप में इस शर्त पर आमन्त्रित कर दिया गया कि प्रमस्त, 1976 में कोलम्बो में होने वाले गुट-निरपेक्ष सम्मेलन से पहले तथा बाद में इस पूरे प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाएगा।

सम्मेलन में राजनीतिक प्रश्नों के अन्तर्गत मध्यपूर्व तथा फिलिस्तीन, माइप्रम, इण्डोचीन और हिन्द महासागर के बारे में विचार-विमर्श हुआ। इन प्रश्नों पर गुट-निरपेक्ष देशों के पहले दृष्टिकोण को पुनः दोहराया गया। इण्डोचीन के पुनर्निर्माण में सहयोग के लिए गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा एक स्वैच्छिक एकता निधि स्थापित करने का निर्णय किया गया। सम्मेलन ने हिन्दमहासागर पर एक अलग से प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें इस विषय से सम्बन्धित समुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को दोहराया गया।

वैश्व में आर्थिक प्रश्नों पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक कोष की स्थापना का अनुमोदन किया। कोष की सदस्यता के लिए समान चन्द 5,00,000 डॉलर निश्चित किया गया। चन्दे की सम्पूर्ण राशि को निधि की स्थापना के बाद अतिरिक्त स्वैच्छिक चन्दे द्वारा पूरा किया जाएगा। ज्यों ही 40 देश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर तथा उसका अनुममर्थन कर देते निधि अस्तित्व में आ जाएगी। भारत ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।

सम्मेलन ने कच्चे माल तथा विकासशील देशों द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादनों के सुरक्षित भण्डार की वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष निधि की स्थापना के सम्बन्ध में अन्तर्संरकारी विशेषज्ञ दल को समझौते का अन्तिम प्रारूप तैयार करने के लिए अधिकृत किया।

सामूहिक संचार साधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए गुट-निरपेक्ष देशों की प्रेम-एजेंसियों का एक निकाय स्थापित करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों से परामर्श करने के बाद भारत ने एक प्रस्ताव रखा जिसे सम्मेलन ने स्वीकृत कर लिया। गुट-निरपेक्ष देशों का मन्त्रिमण्डलीय स्तर का सम्मेलन, दिल्ली, जुलाई 1976

दिल्ली में 8 से 13 जुलाई को आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों का मन्त्रिमण्डलीय

स्तर का सम्मेलन इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था कि उसमें ऐसी समाचार एजेंसी पुंज के गठन पर विचार-विमर्श हुआ तो इन देशों की वास्तविक आवश्यकताओं व उपलब्धियों को केन्द्र-बिन्दु मानकर समाचारों का एकत्रण और आदान-प्रदान करेगा। उसके माध्यम से न केवल पश्चिमी देशों की समाचार एजेंसियों पर आश्रित रहने की स्थिति समाप्त होगी, बल्कि एक तटस्थ और पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टि से कार्य करने के परिणामस्वरूप इन देशों का वास्तविक स्वरूप भी दुनिया की दृष्टि में उजागर किया जा सकेगा।

साठ गुट-निरपेक्ष देशों के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। अध्यक्षता केन्द्रीय सूचना राज्यमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने की। श्रीमती गांधी ने अपने भाषण में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच समाचारों के सीधे आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल दिया और समाचार एजेंसी-पुंज के गठन को एक अच्छा प्रारम्भ माना। श्रीमती गांधी ने कहा “हमारा अतीत एक तरह का रहा है, हमारा वर्तमान एक तरह का है और भविष्य भी समान है, शीतयुद्ध के तनाव में कमी आ जाने के कारण गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का उद्देश्य लक्ष्य नहीं हुआ है।” यह सर्वाधिक सशक्त अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है। दोनों के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों ने प्रेरक भूमिका निभायी। हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रवृत्ति उलटने न पावे। हममें परस्परिक विश्वास गहरा होना चाहिए और गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए। शान्ति को शस्त्रास्त्रों के भण्डार बनाने से खतरा है, लेकिन आर्थिक असमानताएँ भी शान्ति को खतरे में डाल रही हैं। अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित करने की जरूरत है।

श्रीमती गांधी ने गुट-निरपेक्ष देशों और उनके भूतपूर्व शासकों के बीच के असमान सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध की भी चर्चा की—“वे ही देश औद्योगिक साधन-सामान तथा तकनीकी जानकारी देने के मुख्य स्रोत रहे— उनके अपने पूर्वाग्रह रहे जिसके कारण हमारी छवि को विरूप करके प्रस्तुत किया गया। इसी कारण हमारे लोग उनके उपनिवेशवाद के आसानी के साथ शिकार हो गए।” श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेजी या फ्रांसीसी भाषा के अध्ययन के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की तकीर्णता की भावना नहीं है। प्रश्न उन पश्चिमी देशों के समाचार एजेंसियों और प्रकाशन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत तथ्य को निर्वाच्य स्वीकार करने का है। हमें एक दूसरे को गीधे जानना चाहिए। एक दूसरे के सम्पर्क में रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के विचारों को उनके मूल रूप में जान सकें। शक्तिशाली राष्ट्रों के सूचना-माध्यमों के पीछे एक सायास उद्देश्य भूतपूर्व उपनिवेशों यानी नव-स्वतन्त्र देशों की जनता, उसके नेता और उसकी सरकार की बदनाम करना रहा है। जब हमारे बारे में कोई गलत चीज कही जाती है तब हम यह जान सकते हैं कि क्या गलत और क्या सही है। लेकिन दूसरे के बारे में कोई गलत रपट आती है तब हम तत्काल उसकी तथ्यात्मकता की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। हम अफ्रीकी घटनाओं के बारे में अफ्रीका के लोगों से ही सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को भारत

की घटनाओं के बारे में भारतीय व्याख्या पाने की स्थिति में होना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के प्रमुख कवियों, उपन्यासकारों, पत्रकारों और इतिहासकारों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं जबकि हम यूरोप और अमेरिका के छोटे से छोटे लेखक से भी परिचित हैं।

(दिनमान 18-24 जुलाई, 1976)

कोलम्बो में पाँचवाँ निगुंट शिखर सम्मेलन¹ (16-19 अगस्त, 1976)

गुट-निरपेक्ष देशों का पाँचवाँ ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन श्रीलंका का राजधानी कोलम्बो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती मिरिमाओ भण्डारनायके के इस आह्वान के साथ प्रारम्भ हुआ—

“मानव इतिहास में हम ऐसा अध्याय जोड़ें जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के हथकण्डों को प्रभावहीन कर दे।”

श्रीमती भण्डारनायके सम्मेलन की अध्यक्षता निर्वाचन हुई। सम्मेलन की सम्पूर्ण कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिन्दु ये थे—

“1. श्रीमती भण्डारनायके ने निगुंट आन्दोलन को संयुक्तराष्ट्र में ‘बहुमत के आनक’ की सजा दिए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि निगुंट आन्दोलन न कभी ऐसा रहा है, न उसका ऐसा इरादा है और न ही भविष्य में वह ऐसा रूप लेना चाहता है। उन्होंने घोषणा की—गुट-निरपेक्ष देशों का संघर्ष किसी भी राष्ट्र अथवा समुदाय के विरुद्ध न होकर अन्याय, असमानता तथा हस्तक्षेप और शोषण के विरुद्ध है। शान्ति सब देशों का अधिकार है, इसलिए इसका दायित्व भी सब पर होना चाहिए।

2 भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा—सम्मेलन को अधिक न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का संदेश प्रसारित करना चाहिए। भारतीय नीति की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने सदैव अपनी कयनी और करनी में स्वतन्त्रता, न्याय, समता तथा सहयोग का पक्ष लिया है। अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी अपने विचारों और सिद्धान्तों पर भारत सदैव दृढ़ रहा है। भारत ने उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया है और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ढाले गए सभी राजनीतिक और आर्थिक दबाव का प्रतिरोध किया है। उन्होंने कहा कि मानवता की अन्तर्राष्ट्रियता के रूप में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अब तक की उपलब्धियाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण रही हैं, फिर भी हमें व्यापक परिवेश में सोचना है और विघटनकारी प्रवृत्तियों से दूर रहना है। उन्होंने कहा—यह सर्वथा उचित ही है कि एशिया, जिसने विदेशी शासन-काल में यंत्रणा भोगी है, गुट-निरपेक्षता की भावना अंगीकार करने वालों में अग्रणी है। श्रीमती गांधी ने सदस्य-देशों से एकजुट होकर शान्ति की रक्षा, पक्ति सुदृढ़ करने की अपील की।

3. संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव डॉ. कुतुबुद्दीन खान ने कोलम्बो पहुँचने पर कहा—गुट-निरपेक्ष देशों का कोलम्बो सम्मेलन राष्ट्रसंघ के कार्य और विश्व-शान्ति तथा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

4. श्रीमती भण्डारनायक ने निगुंट देशों की नई अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए आह्वान किया और इसकी कुछ रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि निगुंट राष्ट्रों को (1) एक नई मुद्रा का प्रचलन करना चाहिए जिसकी पुश्त पर विकासशील देशों की अपरिमित आर्थिक शक्ति हो, और साथ ही (2) तीसरी दुनिया के लिए एक व्यापारिक बैंक स्थापित करना चाहिए। श्रीमती भण्डारनायक ने कहा कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति के सघर्ष में हमें अपने निज की वित्तीय और मौद्रिक प्रणालियों का गठन करना चाहिए। विकासशील देश विकसित देशों की मुद्रा को अपने सुरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में रखते हैं जिससे उनकी मुद्राओं की शक्ति और दृढ़ता प्राप्त होती है। यदि निगुंट राष्ट्र अपनी निज की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रचलन करें और अपनी सुरक्षित मुद्रानिधियों से विकसित देशों की मुद्राओं को धीरे-धीरे निकाल दें तो वे विकसित देशों की आर्थिक शक्ति का मुकाबला कर सकेंगे। श्रीमती भण्डारनायक का दूसरा सुझाव यह था कि तेल, ताँबा, डॉल्माइट और यूरेनियम आदि महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए उत्पादक एगोसिएशन स्थापित की जाएँ ताकि विकासशील देश इन वस्तुओं के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। यदि निगुंट देशों की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और व्यापारिक बैंक स्वतन्त्र रूप से स्थापित हो जाए तो लन्दन, पेरिस, जूरिख और न्यूयॉर्क का आज वित्तीय दृष्टि से जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है वह नहीं रह पाएगा। संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास आयोग के अग्र तक के सम्मेलनों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मन्त्रणाओं से यह स्पष्ट है कि विकसित देशों से विकासशील देश कुछ आशा नहीं कर सकते। इसलिए विकासशील देश स्वयं ही परस्पर सहयोग से अपने आर्थिक उद्धार के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि सभी निगुंट देशों की आर्थिक शक्ति संगठित हो जाए तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और विकसित देशों की पराधीनता से उन्हें मुक्ति मिल सकती है।

5. निगुंट देशों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत आर्थिक घोषणापत्र में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया। मेजबान देश श्रीलंका द्वारा तैयार किए गए इस घोषणापत्र के प्रारूप में भारत के कई महत्वपूर्ण सुझावों का समावेश हुआ। घोषणा-पत्र की मुख्य बातें ये थी—

(क) गुट-निरपेक्ष देश अनुभव करते हैं कि वर्तमान आर्थिक-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन तथा पुनर्गठन किए बिना सारी दुनिया, खासकर विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं का समाधान असम्भव है। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में अक्षमता विश्व की मण्डियों के हाल के सकटों से स्पष्ट है। समूचा विश्व-समुदाय आज एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की खोज करने पर विवश हुआ है जो सामान्य श्रम, सार्वभौम समानता, परस्पर-निर्भरता, समान हितों और सहयोग पर आधारित हो।

(ख) बहु-उद्देश्यीय नियमों की नीति तथा आचरण की भर्त्सना करते हुए

कहा गया कि ये निगम अपने निजी लाभ के लिए विकासशील देशों के साधनों का शोषण कर उनकी अर्थव्यवस्था को विवृत करते हैं तथा इन देशों की सार्वभौमिकता और आराम-निर्यात के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये निगम बहुधा धूसर देने और भ्रष्टाचार के अन्य कुत्सित तरीके अपनाते हैं तथा विकासशील देशों को औद्योगिक देशों के अधीन बनाते हैं।

(ग) यदि बड़ी सैनिक शक्तियाँ निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करें तथा अपने साधनों का एक बड़ा भाग विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में व्यय करें तो विकासशील देशों की काफी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यदि ऐसा किया गया तो निकट भविष्य में ही विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की खाई पाटी जा सकती है।

(घ) घोषणापत्र में विकसित देशों से विश्वव्यापी स्तर पर परस्पर-निर्भरता के सिद्धान्त में अपनी आस्था प्रकट करने तथा ऐसे कदम उठाने की अपील की गई जिससे वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को बल मिले और अंततः नई आर्थिक व्यवस्था विकसित हो।

6 सम्मेलन द्वारा स्वीकृत राजनीतिक घोषणापत्र में तनाव 'शैथिल्य' शब्द को कोई स्थान न देकर सभी देशों के लिए स्थायी शान्ति की स्थापना के सन्दर्भ में 'अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी' वाक्यांश का प्रयोग किया गया। भारत की राय को प्रमुख स्थान दिया गया। राजनीतिक घोषणापत्र में गुट-निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के न्याययुक्त समाधान के लिए प्रभावी भूमिका अदा करने का सकल्प व्यक्त किया।

7 सम्मेलन में पिछले 15 वर्षों में हुए परिवर्तनों की समीक्षा की गई तथा वर्तमानकालीन गुट-निरपेक्षता की भूमिका को मूल्यांकन के लिए समीचीन माना गया। सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सार्थकता तथा विश्व सदर्भ में इसकी उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका के कारण इन देशों का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वे गुट-निरपेक्षता के मूलस्वरूप के संरक्षण के लिए सतत् जागरूक रहे तथा इसके सिद्धान्तों और नीतियों में अपनी अटूट आस्था रखते हुए इस आन्दोलन की एकजुटता तथा अखण्डता की रक्षा के लिए इसके निर्णयों का आदर करें। सम्मेलन में कहा गया कि अनेक गुट-निरपेक्ष देशों पर कई तरह के दबाव डाले जा रहे हैं, उन पर खुले तौर पर आक्रमण किया गया है अथवा उन्हें धमकियाँ दी गई हैं। इस प्रकार गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से सम्बद्ध सभी देशों के विरुद्ध नियोजित ढंग से निन्दा, डराने व धमकाने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वे अपनी सगठित तथा स्वतन्त्र भूमिका न निभा सकें। सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच घनिष्ठ एकता का आह्वान किया तथा इसे समय की अपरिहार्य आवश्यकता बताया। इसके अनतिरिक्त गुट-निरपेक्ष देशों को समूचे विश्व की प्रगतिशील तथा शान्तिप्रिय शक्तियों के साथ अपना सहयोग जारी रखने पर जोर दिया गया क्योंकि यही एक मार्ग है जिससे वे साम्राज्यवाद का मुकाबला कर सकते हैं।

8. निगुंट देशों की यह परम्परा रही है कि उनके सम्मेलन में राष्ट्रों के छोटे-मोटे आपसी मामले नहीं उठाए जाते, परन्तु बंगलादेश ने इस परम्परा को ताक पर रखकर इस सम्मेलन में गंगा के पानी के बँटवारे का सवाल उठाया और भारत पर अनेक अनुचित आक्षेप किए। भारत शान्तिपूर्वक वार्ता द्वारा सब समस्याओं को निबटाने की नीति में आस्था रखता है और बंगलादेश के साथ भी वह इसी नीति का अनुसरण कर रहा है, परन्तु बंगलादेश के नेना या तो प्रकरण भारत का विरोध कर अपने आपकी प्रकाश में लाने और सस्ती प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं या पाकिस्तान अथवा कोई अन्य देश बंगलादेश के कान्धे पर रख कर बन्दूक चला रहा है ताकि निगुंट देशों की एकता और सगठन में दरार डाली जा सके। इसलिए श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने सम्मेलन में द्विपक्षीय मामले न उठाने पर जोर दिया क्योंकि इससे सामुदायिक उद्देश्य दृष्टि से शोभन हो सकते हैं। निगुंट देश यदि एकता और सगठन की सुदृढ़ता कायम नहीं रख सकेंगे तो उनकी सामूहिक शक्ति कमजोर होगी और उनके बड़ी शक्तियों की कठपुतली बन जाने की आशंका बढ़ जाएगी।

9 भूटान नरेश जिग्मे दोरजी वांग्चुक ने गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र के सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने के भारत के प्रयास की सराहना की।

कोलम्बो के इस पाँचवें निगुंट शिखर सम्मेलन में विश्व के चार महाद्वीपों के 40 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। मालदीव को निगुंट राष्ट्र सगठन का पूर्ण सदस्य बना लिया गया। इस प्रकार यह देश सगठन का 86वाँ सदस्य देश बना। निगुंट शिखर सम्मेलन ने विदेश मन्त्री सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार 18 उपाध्यक्षों का चुनाव किया। विदेश मन्त्री सम्मेलन ने उपाध्यक्षों की संख्या 14 से बढ़ाकर 18 करने का प्रस्ताव किया था। श्रीलंका के मेडिस को सम्मेलन का महासचिव चुना गया। यह पाँचवाँ शिखर सम्मेलन 19 अगस्त को राजनीतिक और आर्थिक घोषणापत्र स्वीकार करने के बाद समाप्त हो गया। शिखर-सम्मेलन ने निगुंट देशों का जो आर्थिक कार्यक्रम स्वीकार किया है उसमें अपील की गई कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 'एकताकोष' स्थापित कर 1976 के अन्त तक उसको शुरू कर दिया जाए। सम्मेलन के 25 सदस्यीय ब्यूरो में भारत, श्रीलंका, ईरान, क्रीरिया, फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा तथा इण्डोनेशिया आम सहमति के आधार पर सदस्य चुन लिए गए। अफगानिस्तान और बंगलादेश ब्यूरो में स्थान पाने के लिए अपने दावों पर प्रडे रहे और तब यह निर्णय किया गया कि तीन वर्ष के कार्यकाल में शुरू के डेढ़ वर्ष बंगलादेश और शेष डेढ़ वर्ष अफगानिस्तान 'सदस्यता' ग्रहण करेंगे।

श्रीलंका में आयोजित निगुंट देशों का पाँचवाँ सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जल विभाजक की तरह उभर कर सामने आया। दूसरे महायुद्ध के बाद शीतयुद्ध ने जोर पकड़ा तब अनेक नव-स्वाधीन देशों ने सामरिक सन्धियों की महाशक्तियों की

आर्थिक और राजनीतिक चालवाजी का अंग माना और तीसरी शक्ति—निगुंट आन्दोलन को जन्म दिया। इसमें भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया प्रमुख थे। अब शीतयुद्ध काफी ठण्डा पड़ चुका है और 'देतों' (तनाव रहित या तनाव में बर्फी की स्थिति) का रूप ग्रहण करता जा रहा है। यूरोप में हेलमिकी सम्मेलन एशिया में विघटनात्मक से अमेरिका की वापसी, चीन अमेरिका सवाद, रूस अमेरिका व्यापार का आरम्भ आदि इसके प्रतीक हैं। मगर इससे विकास के अवसरों पर उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई है, हालाँकि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निगुंट देश अपने सकल और साधनों के बल पर अन्वेषणात्मान कुछ आगे बढ़े हैं। ये देश वर्षों से एक दूसरे के निकट आने और उन्नत देशों की चौधराहट के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयत्न करते रहे हैं जिसको कई अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अभिव्यक्ति मिलती रही है। समुक्त राष्ट्रसंघ में तीसरी दुनिया के देशों की संख्या में वृद्धि पश्चिम के सामन्ती अर्थशास्त्र और विदेशी महायत्ना पर आधारित विकासवाद के खोखलेपन की प्रतीति, पश्चिमी देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका और रोडेजिया में अल्पमत गोरी सरकारों का बेहया समर्थन, चीले और अगोलो में खुला हस्तक्षेप, इन तथा ऐसी ही बातों ने निगुंट देशों को विश्वास करा दिया कि जब तक कि वे एकजुट नहीं होंगे तब तक वे उद्योग-प्रधान देशों के पिछलगू ही बने रहेंगे। यह प्रतीति नई नहीं है—संयुक्तराष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, संयुक्तराष्ट्र महामभा, समुद्री कानून सम्मेलन आदि कई जगह पिछले देशों ने अपने अधिकारों को आग्रहपूर्वक घोषित किया है। कोलम्बो सम्मेलन इसी श्रुतता का इसी मोर्चेबन्दी की दिशा में एक निर्णायक बिन्दु माना जाएगा।

यह सम्मेलन ऐतिहासिक इसलिए था कि निगुंट आन्दोलन के इतिहास में पहली बार अपने अधिकारों की लड़ाई को प्रमुखता देने हुए पारस्परिक मतभेदों को गौण स्थान दिया गया, जिससे विश्व राजनीति में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो सके क्योंकि यही उनकी बुनियादी आवश्यकता है। इसी की तार्किक परिणति यह है कि निगुंट आन्दोलन को माफ़े का मोर्चा माना गया और नेतृत्व में साभेदारी के पुराने सिद्धान्त को ज्यादा खुले दिल से स्वीकार किया गया।

गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भारत की भूमिका—गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं ने वक्तव्य दिए और उनके वक्तव्यों में कोई बुनियादी अन्तर्विरोध नहीं रहा। आरम्भ में गुट-निरपेक्ष देशों के ब्यूरो में भारत को स्थान दिए जाने का बंगलादेश ने विरोध किया, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली। भारत और श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिष्ठा का इसमें बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि श्रीमती गांधी के भाषण पर देर तक तालियाँ बजती रहीं और प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी से मिलने के लिए अनेक देशों के प्रधानमंत्री तथा विदेशमंत्री आए। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत ने पिछले दस वर्षों में श्रीमती गांधी के नेतृत्व में न केवल एक स्वतन्त्र विदेश नीति पर दृढ़ता से अमल किया बल्कि देश में सर्वतोमुखी प्रगति का करिश्मा कर दिखाया। अभी कुछ वर्ष पहले तक भारत को एक पिछड़ा हुआ देश मान कर उसका उपहास किया जाता था

लेकिन शान्तिपूर्ण प्रयोगों के लिए परमाणु विस्फोट कर और अन्तरिक्ष में अपना उपग्रह भेजकर भारत ने अन्तर्विधि के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर दिया। बंगलादेश की लड़ाई में विजय प्राप्त कर और बाद में शिमला सम्मेलित के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधार कर भारत ने अपनी आन्तरिक शक्ति और सुभक्क का अनुपम परिचय दिया। इसके गुट-निरपेक्ष देशों के बीच श्रीमती इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता व प्रतिष्ठा का बढ़ जाना स्वाभाविक था।

गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गांधी ने अपना भाषण जवाहरलाल नेहरू को उद्घृत करते हुए आरम्भ किया। श्रीमती गांधी ने कहा कि सन् 1947 में एशियायी देशों के नेता पहली बार अपनी एकता व्यक्त करने के लिए नई दिल्ली में एकत्र हुए थे। उस समय पं. जवाहरलाल ने हमसे कहा था कि हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और उन सब के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं।

श्रीमती गांधी ने कहा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बीच वाडुग सम्मेलन में घोंप गए थे और उसी जड़ें वेलग्रेड में फूटीं। वेलग्रेड से काहिरा, लुसाका और अल्जीरस होता हुआ गुट-निरपेक्षता का आन्दोलन जिस मार्ग से मुजरा वह एक शानदार मार्ग था। वर्तमान सम्मेलन गुट-निरपेक्षता के विश्व-दृष्टिकोण का परिचायक है।

गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में सम्मिलित नए देशों का स्वागत करने के बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि गुट-निरपेक्षता की धारणा हमारे देश में बहुत पहले अर्थात् हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान स्थापित हुई थी। हमारे देश में इस धारणा का विकास शीतयुद्ध के प्रसार और गुटों के निर्माण से काफी पहले हो चुका था। शीतयुद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या उसके उत्तराधिकार के विषय में यही बात कही जा सकती है। औपनिवेशिक प्रशासन समाप्त हो चुके हैं, मगर क्या उनके नतीजे भी समाप्त हो चुके हैं। हम में से अनेक देशों पर भी बाहरी दबाव हैं।

हिन्द महासागर के विषय में श्रीमती गांधी ने कहा कि हिन्द महासागर के आसपास के सभी देश जो इसे शान्ति का क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं इस क्षेत्र में सैनिक अड़्डों की स्थापना और समुद्री प्रतियोगिता के कारण अशान्त हैं।

महाशक्तियों के बीच तनाव रहित स्थिति की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हेलसिंकी सम्मेलित का स्वागत करते हैं। वर्तमान तनावरहित स्थिति भौगोलिक दृष्टि से सीमित तो है ही अपने प्रयोजन में भी सीमित है, इसे और भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा ससार के अन्य भागों में इसका विस्तार होना चाहिए। आखिरकार यूरोप तनावरहित कैसे बना रह सकता है जबकि ससार के अन्य भागों में निरुपेक्ष लड़ाइयाँ और प्रतियोगी घुसपैठ जारी है। तनावरहितता में गुट-निरपेक्ष देशों तथा अन्य देशों के प्रति आदर भी शामिल होना चाहिए।

गुट-निरपेक्ष देशों की सरकारों का तन्ना उलट कर तनावरहितता सहप्रस्थित्व का आनन्द नहीं ले सकती, न यह सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिए गर्भार प्रयत्न किए बिना ज्ञानि का दौर शुरू कर सकती है। तनावरहितता की परिणति सश्रिय सहप्रस्थित्व तथा सहयोग में होनी चाहिए जिसमें गुट-निरपेक्ष तथा प्रभाव-क्षेत्र अप्रामाणिक हो जाएं।

श्रीमती गांधी ने कहा कि विश्व की नई आर्थिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तम राष्ट्रों का दृष्टिकोण प्रतिकूल रहा है। हमें खुद स्वयं को आर्थिक दृष्टि में मजबूत बनाने के लिए आपसी सहयोग करना होगा। हमारे सामने चुनौतियाँ और अवसर हैं। चुनौती यह है कि तमाम जबरदस्त दवावों के बावजूद अपनी बुनियादी एकता को बनाए रखें और अपने सिद्धान्तों पर डटे रहें। अवसर यह है कि सम्मिलित शक्ति और समुक्त इच्छा से हम सबके लिए ज्ञान्ति और स्वाधीनता प्राप्त करें।
(दिनमान, अगस्त-सितम्बर, 1976)

गुट-निरपेक्षता का बदलता हुआ रूप

समय के साथ गुट-निरपेक्षता का रूप निखरता जा रहा है अधिक वास्तविक होता जा रहा है। प्रारम्भ में इसकी नीति आवश्यकता से अधिक आदर्शवादी थी, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं ने गुट-निरपेक्ष देशों को यह अनुभव करा दिया कि इस नीति को अधिक यथार्थवादी बनाया जाए और राष्ट्रीय हित के तत्त्व को प्रधानता दी जाए। भारत ने इस नीति को परिष्कृत करने तथा इसके विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत ही इस नीति का प्रवर्तक था। स्वर्गीय नेहरू ने इसे आदर्शवादी जामा पहनाया था। नेहरू मानवतावाद में ओजप्रोन महापुरुष थे और राजनीति की नैतिक घरातल पर प्रतिष्ठित करने में सत्रमें आगे रहने थे। उनका नैतिकतावाद इनका उच्च था कि है कई बार राष्ट्रीय हित की अनजाने ही उपेक्षा कर बैठते थे। चीन के आक्रमण ने नेहरू के आदर्शवाद को गहरा घक्का पहुँचाया और उन्होंने अपने ही जीवनकाल में गुट-निरपेक्षता की नीति को यथार्थवादी जामा पहनाना शुरू कर दिया। उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री के समय गुट-निरपेक्षता की नीति पहले से अधिक सश्रिय और यथार्थवादी हो गई। इसमें तुष्टिकरण का जो आवश्यकता से अधिक गुट मिला हुआ था वह शास्त्री के समय कम हो गया। तत्पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में गुट-निरपेक्षता की नीति ने वास्तविक निगार पाया। श्रीमती गांधी ने यह मिड कर दिया कि किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक सन्धि में बँधे बिना भी एक राष्ट्र कूटनीतिक उपायों तथा नैतिक-सैनिक मंत्री-सन्धियों के बल पर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है। श्रीमती गांधी पूरी तरह गुट-निरपेक्ष रहते हुए भी इस जैसी महाशक्ति की प्रगाढ़ मंत्री अर्जित करने में सफल हुई और इसीलिए सन् 1971 की भारत-पाक-मैत्री-मन्त्रि गुट-निरपेक्ष नीति के नए दृष्टिकोण की परिचायक है। इस सन्धि द्वारा गिना नैतिक गुटों में शामिल हुए भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की गई है।

हाल ही के वर्षों में गुट-निरपेक्षता की नीति में पारस्परिक आर्थिक सहयोग के तत्त्व पर विशेष बल दिया जाने लगा है। काहिरा में हुए द्वितीय शिखर-सम्मेलन में गुट-निरपेक्ष देशों के पारस्परिक आर्थिक विकास और सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया और तब से यह पहलू अधिक विकसित हुआ है। विरयात कूटनीतिज्ञ और समुक्तराज्य अमेरिका में भारत के राजदूत टी. एन. कोल के अनुसार—“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीतिक पहलू की अपेक्षा आर्थिक पहलू पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिए जाने से गुट-निरपेक्षता की धारणा की सार्थकता सिद्ध हुई है।”

गुट-निरपेक्षता का परस्पर विरोधी स्वरूप भी अस्तित्व में है जिसका स्पष्ट उदाहरण पश्चिमी एशिया में दृष्टिगोचर होता है। समुक्त अरब-गणराज्य सीरिया आदि अरब-राष्ट्र इजराइल के साथ सैनिक संघर्ष से विवश होकर सोवियत संघ के साथ इस तरह बंध गए हैं कि गुट-निरपेक्षता सम्बन्हास्पद बन गई है। फिर भी अरब-राष्ट्र इस बात के प्रति सचेष्ट हैं कि उनकी राजनीतिक प्रभुता पर आघात न आए। दूसरे शब्दों में पश्चिमी एशिया का यह क्षेत्र एक तरह से सचेत और सावधान गुटबन्दी का अखाड़ा बन गया है।

वर्तमान परिस्थितियों में गुट-निरपेक्षता का महत्त्व

आज के युग में गुट-निरपेक्षता का महत्त्व सुगन्धत. इन कारणों से स्पष्ट है—

1. गुट-निरपेक्ष नीति अपनाते वाले राष्ट्रों की सख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।
2. समुक्त राष्ट्रसंघ में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज आज अधिक सबल है।
3. गुट-निरपेक्ष जगत् को विश्व की दो महाशक्तियों के बीच सन्तुलनकारी शक्ति के रूप में मान्यता मिल चुकी है। पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही गुट गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। उनमें इन देशों को आर्थिक और प्रादेशिक सहायता देने की होड़ भी लगी हुई है। दोनों ही महाशक्तियाँ भूतनीतिक समर्थन देकर अधिकाधिक गुट-निरपेक्ष देशों को अपने पक्ष में करने को उत्सुक हैं।
4. आज के आणविक युग की माँग है सहस्रस्तित्व। गुट-निरपेक्षता की नीति इस सहस्रस्तित्व की धारणा को बल प्रदान करती है। यह 'जी प्रो और जीने दो' के सिद्धान्त में विश्वास करती है।
5. गुट-निरपेक्षता की नीति सस्वीकरण को हतोत्साहित करती है। इसका विशेष बल आर्थिक समृद्धि और शान्तिपूर्ण विकास पर है तथा यह गैर-सैनिक उपलब्धियों को महत्त्व देता है।
6. गुट-निरपेक्षता हर प्रकार के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरोधी है। यह रचनात्मक राष्ट्रवाद और राष्ट्रों के स्वतन्त्र अस्तित्व की समर्थक है।

7. गुट-निरपेक्षता समुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के सिद्धान्तों को बल प्रदान करती है तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के उपायों का समर्थन करती है।

8. गुट-निरपेक्षता रग-भेद और जातिवाद में विश्वास नहीं करती। इसका नारा है विश्व-वन्धुत्व।

9. इसकी नीति सैनिक गुटों और सैनिक सन्धियों का तिरस्कार करते हुए राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि करने वाली है। इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है।

10. गुट-निरपेक्षता की नीति लचीली है तथा इसमें समय के अनुरूप ढलने की क्षमता है। इस प्रकार यह सतत विकासशील है। यह निर्भीकता और साहस की नीति है जो न्याय की रक्षा के लिए तलवार उठाने की भी प्रेरणा देती है।

आज मानव-जाति आणविक शस्त्रास्त्रों के बारूदी ढेर पर बैठी हुई है और जरासी भी चिनगारी के विस्फोट से इस ढेर का महाविनाश हो सकता है। इस खतरे से बचने का एक ही उपाय है कि सहप्रस्तित्व और गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया जाए।



(8) ✓

7

उपनिवेशवाद का अन्त और एशिया तथा अफ्रीका में नये राज्यों का उदय

(DE-COLONIZATION AND THE EMERGENCE OF NEW STATES IN ASIA AND AFRICA)

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका का जागरण द्वितीय महायुद्ध के बाद की एक सर्वाधिक आन्तरिकारी घटना है जिसने अन्तर्राष्ट्रीय जगत् के राजनीतिक मानचित्र की ही काया पलट कर दी है। विश्व के इन तीनों ही क्षेत्रों के अधिकांश राज्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार थे; पर समय ने करवट ली, पराधीनता से मुक्त होने के लिए संघर्षों का सूत्रपात हुआ, जागरण की लहर फैलती गई और आज ये तीनों ही क्षेत्र (एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका) बहुते-कुछ स्वतन्त्रता की साँम ले रहे हैं। एशिया और अफ्रीका तो लगभग उपनिवेशवाद से मुक्त हो चुके हैं और जो एक-दो प्रतिशत भूभाग आज भी उपनिवेशवाद के शिकार है, उनके भी निकट भविष्य में ही मुक्त हो जाने की पूर्ण आशा है। लेटिन अमेरिका ने भी करवट बदली है, न्यूना जैसे राष्ट्रों ने अमेरिका के उपनिवेशवादी प्रभुत्व और डॉलर साम्राज्यवाद को चुनौती दे दी है। फिर भी अनेक राज्य चाहकर भी अभी स्वयं को अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र से मुक्त नहीं कर सकते हैं। कहने को तो वे स्वतन्त्र राज्य हैं, लेकिन उनकी स्थिति गुलाम या परतन्त्र राज्यों जैसी ही है। यह स्थिति भी उपनिवेशवाद का ही एक रूप है। किन्तु जैसा वातावरण बन चुका है, जिन नई शक्तियों का उदय हो रहा है, उससे यह स्पष्ट दिखायी देता है कि लेटिन अमेरिका 'पूर्णतः स्वतन्त्र' होकर रहेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ की सरक्षित व्यवस्था (Trusteeship System) के अधीन जो सरक्षित प्रदेश थे वे भी अब स्वतन्त्र होकर नए सम्प्रभु राज्यों का रूप ग्रहण कर चुके हैं। उपनिवेशवाद का वस्तुतः अब जनाजा निकल चुका है और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या सन् 1975 तक 140 थी और अब 149 हो गई है। जहाँ पहले समार की जनसंख्या का लगभग 33 प्रतिशत भाग उपनिवेशवाद के शिकार में था वहाँ अब दो प्रतिशत भी नहीं रहा है।

एशिया में उपनिवेशवाद का अन्त और नए राज्यों का उदय

एशिया महाद्वीप का परिचय

एशिया पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में भूमध्य सागर तक तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिन्द महासागर के मध्य बसा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या वाला यह महाद्वीप सभी प्रकार के घसों, सस्य-पौधों और भाषाओं का घर है। यहाँ खनिज-पदार्थों की प्रचुरता है और विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु पायी जाती है। राजनीतिक दृष्टि में एशिया को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है और उनमें निम्नलिखित राष्ट्र सम्मिलित किए जाते हैं—

- 1 दक्षिण एशिया — भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंका
- 2 दक्षिण-पूर्वी एशिया — बर्मा, इण्डोनेशिया, हिन्द-चीन, मलयेशिया, फिलीपाइन्स, पाइलैण्ड आदि
- 3 पूर्वी एशिया — चीन, हांगकांग तथा जापान
- 4 पश्चिमी एशिया — अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, सीरिया, सऊदी अरब, मिस्र, लेबनान, इजरायल, ट्रांसजोर्डन, टर्की, साइप्रस आदि।

दक्षिण-पूर्वी एशिया में कुछ विद्वान् भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश को सम्मिलित करते हैं जबकि अन्य विद्वान् इन देशों को 'दक्षिण एशिया' नामक पृथक भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी एशिया' को पारश्चात्य इतिहासकारों ने मध्यपूर्व (Middle East) की संज्ञा प्रदान की है। वास्तव में 'मध्यपूर्व' यूरोपीय राष्ट्रों और विद्वानों द्वारा की गई एक प्रकार की राजनीतिक अभिव्यक्ति है।

एशिया का जागरण : नए राज्यों का उदय,
वाण्डुग सम्मेलन (1947-1955)

औद्योगिक क्रान्ति ने यूरोप को तेजी से प्रभावित किया, लेकिन एशिया अपनी प्राचीन प्रथाओं और संस्थाओं में मग्न रहा। इसके फलस्वरूप यूरोप तो मध्यकालीन अवस्था पार कर आधुनिक अवस्था में पहुँच गया और निरन्तर प्रगति करता गया, लेकिन एशिया अत्यधिक पिछड़ा रहा। इसका एक गम्भीर राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी राज्यों ने एशिया में अपने पैर जमाकर उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। जापान, फ्राइलैण्ड, ईरान, नेपाल और चीन को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण एशिया पश्चिमी राष्ट्रों के स्वामित्व में आ गया। अंग्रेज भारत, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर और हांगकांग में जम गए, फ्रांसीसियों ने हिन्द-चीन में डेरा जमाया, डचों ने ईस्ट इण्डोनेसिया में पैर रोप दिया; रूसियों ने चीन के आसन्न प्रान्त सहित साइबेरिया के बाह्य मंगोलिया में और स्पेनिस लोगों ने (बाद में अमेरिकियों ने) फिलीपाइन्स में अपने घड़ों जमा लिए, यहाँ तक कि पुर्तगाल जैसे छोटे से राज्य ने भी अपने उपनिवेश कायम कर लिए। वे देश भी, जो प्रकट रूप में स्वतन्त्र थे,

व्यावहारिक दृष्टि से विदेशी राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके।

प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रीयता की प्रथम लहर—एशिया के राष्ट्रों पर आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पश्चिम का प्रभुत्व छा गया, लेकिन पश्चिम के सम्पर्क और पश्चिमी साहित्य के प्रवेश के कारण शनैः-शनैः एशियावासियों में नव चेतना का उदय हुआ। प्रबुद्ध एशियावासी यह समझ गए कि विषम आर्थिक कठिनाइयों, आर्थिक शोषण और लज्जाजनक जीवन से एशिया के देश तभी मुक्ति पा सकते जब वे राजनीतिक दासता के जुए को उतार फेंके। प्रथम महायुद्ध ने भी एशियायी देशों के जागरण को गतिशील बनाया। इस सारी स्थिति को चित्रित करते हुए ज़ुर्मेन ने लिखा है—

“इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के नए बुद्धिजीवियों ने पार्श्वस्थ देशों के विज्ञान, युद्धकला और राजनीतिक कुशलता और निपुणता का ज्योंही एक अंश प्राप्त किया त्योंही उनमें ऐसे नेतागण भी पैदा हो गए जो यह माँग करने लगे कि उन्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चिन करने का अधिकार मिलना चाहिए।”¹

महायुद्ध के बाद एशियावासी ‘आत्म-निर्णय’ की माँग करने लगे। ‘भारत भारतीयों के लिए’ ‘चीन चीनियों के लिए’ आदि नारे बुलन्द होने लगे। विदेशी शासन से मुक्ति के लिए एशियायी देशों में जो उत्कट अभिलाषा जाग्रत हुई उसने एक दीर्घकालीन स्वतन्त्रता-प्रान्दोलन और संघर्ष का रूप धारण कर लिया। एशिया के पराधीन राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार की माँग करने लगे। एशिया तेजी से जागरण के पथ पर बढ़ता गया और द्वितीय महायुद्ध से उसके निश्चय को अत्यधिक बल मिला।

द्वितीय महायुद्ध द्वारा राष्ट्रीयता की लहर को बल प्रदान किया—द्वितीय महायुद्ध ने एशिया महाद्वीप को अपने लक्ष्य-प्राप्ति की दिशा में अग्रसर किया। एशियायी राष्ट्रों ने महायुद्ध में पश्चिमी शक्तियों का साथ दिया था जिसके बदले में उन्हें आश्वासन मिला कि उनकी पराधीनता की डेड़ियाँ काट दी जाएँगी। इसमें एशियावासियों में नई चेतना तथा नई शक्ति का संचार हुआ। इसके प्रतिरिक्त महायुद्ध ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता और प्रजेयता की भावना को नष्ट कर दिया जिसमें उपनिवेशों की जनता में एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। एशियावासी यह महसूस करने लगे कि साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने का मार्ग कठिन भले ही हो, असम्भव नहीं है। महायुद्ध में विजय पाने के बाद जब पश्चिमी साम्राज्यवादी देश अपने बवनों को झूट गए तो एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता-प्रान्दोलन अधिक तीव्र हो गया। ये महाद्वीप अब यह सहन करने को तैयार नहीं थे कि साम्राज्यवाद की पुरानी व्यवस्था ज्यों की त्यों कायम रहे। उपनिवेशवादी ताकतों ने स्वाधीनता-सेनानियों को फिर आश्वासन की भीठी गोतिराँ खिनाकर शान्त करना चाहा, लेकिन

श्रव जनता में यह भावना घर कर चुकी थी कि उनके वचनों पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। महायुद्ध से थके और जर्जरित पश्चिमी साम्राज्यवादी राष्ट्रों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे अफ्रीशियायी राष्ट्रीय आन्दोलनों को दबाए रख सकें, अतः शीघ्र ही दोनों महाद्वीपों में नए सम्प्रभु राज्यों के उदय का सिलसिला शुरू हो गया।

सन् 1947 से 1955 तक का युग : नए राज्यों का उदय : एशियायी व्यक्तित्व का विकास—सन् 1919 के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में साम्राज्यवाद की जो पराजय शुरू हुई वह सन् 1945 के पश्चात् अन्तिम पराजय के रूप लेने लगी तथा साम्राज्यवाद के पैर उखड़ने लगे। 15 अगस्त, 1947 के स्वतन्त्र भारत का उदय हुआ और साथ ही पाकिस्तान नामक एक नए मुस्लिम राज्य का भी निर्माण हुआ। भारत-विभाजन की कीमत पर पाकिस्तान का उदय इतिहास की एक दुःखद क्रूर और अन्यायपूर्ण घटना थी, किन्तु भारतीयों ने इस महान् बलिदान को भी सहन किया और अपनी परम्परागत उदारता का परिचय दिया। 4 जनवरी, 1948 को बर्मा ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की और 'बर्मी-सघ' अस्तित्व में आया। फरवरी, 1948 में, लगभग 133 वर्षों की अंग्रेजी अधीनता के बाद, थैलैंड ने स्वाधीनता की साँस ली। इसके बाद में 1 अक्टूबर, 1949 के साम्यवादी चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई जो भारत की आजादी के बाद दूसरी महान् शान्तिकारी घटना थी। 27 दिसम्बर, 1949 को इण्डोनेशिया एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में प्रकट हुआ और 9 नवम्बर, 1953 को कम्बोडिया स्वयं को एक पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया। 21 जुलाई, 1954 को जेनेवा सम्मेलन के अन्तर्गत लाओस राज्य की पूर्ण स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान की गई इस प्रकार सन् 1955 के आरम्भ तक एशिया के अनेक देशों ने स्वतन्त्रता के सू के दर्शन कर लिए। जून 31 अगस्त, 1957 को मलाया ने औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली तो द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त स्वतन्त्रता का सूर्योदय देखने वाला वह एशिया का 11वाँ देश था।

एशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार के साथ यह भावना भी बल पकड़ती गई कि कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्हें पारस्परिक एकता, संगठन और सहयोग का परिचय देना होगा। इस प्रकार की एकता की नवीन चेतना की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मार्च, 1947 में हुई। इस समय 'विश्व मामलों की भारतीय परिषद्' (Indian Council of World Affairs) के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित एक गैर-सरकारी 'एशियायी मंत्री सम्मेलन' (Asian Relations Conference) हुआ। इस सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव पारित हुए और महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए तथा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए एक 'एशियायी मंत्री संगठन' (Asia Relations Organisation) की स्थापना की गई—

(1) एशियायी समस्याओं और सम्बन्धों के महाद्वीपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के अध्ययन और ज्ञान को प्रोत्साहित करना,

(ii) एशियायी राष्ट्रों तथा विश्व के दूसरे राष्ट्रों के बीच मंत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना, एवं

(iii) एशियायी जनता की प्रगति और हितों में वृद्धि करना ।

सम्मेलन में शामिल होने वाले 28 एशियायी देशों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्वागत भाषण में कहा—

“जब प्राधुनिक युग का इतिहास लिखा जाएगा तब यह घटना एशिया के अतीत को उसके भविष्य से अलग करने वाले सीमा-चिह्न के रूप में याद की जाएगी ।” एशिया के नव-जागरण पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आगे कहा—“परिस्थितियाँ बदल रही हैं और एशिया को अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया है । एशिया के देश अब दूसरों के हाथों के मोहरे नहीं बनेंगे, विश्व के मामलों में उनकी स्वतन्त्र नीतियों का होना निश्चित है ।”

एशियायी एकता तब एक कदम और आगे बढ़ी जब जनवरी, 1949 में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसने औपनिवेशिक स्थिति पर विचार किया । इसमें मुख्य रूप से इण्डोनेशिया में डच सरकार द्वारा की गई सैनिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ । एशियायी व्यक्तित्व का विकास होता गया । मई, 1950 में किलोवाइस ने बोर्नो नामक स्थान पर एशियावासियों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग पर विचार करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया । अप्रैल, 1954 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा और इण्डोनेशिया के प्रधानमंत्री हिन्द-चीन सहित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए परस्पर मिले । दिसम्बर में पाँचों प्रधानमंत्री बोगार में एकत्र हुए और वहाँ एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों का एक वृहद्-सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका में नव-जागरण की तहर का सर्वोत्तम रूप से बाण्डुंग सम्मेलन में प्रकट हुआ । भारत, बर्मा और इण्डोनेशिया द्वारा इस महान् अफ्रो-एशियायी सम्मेलन का आयोजन किया गया जो 18 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1955 तक चला । इस सम्मेलन में भारत सहित 29 राष्ट्र सम्मिलित हुए । पहली बार साम्यवादी चीन ने भी गैर-साम्यवादी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श में भाग लिया । सम्मेलन की समाप्ति पर सम्पूर्ण सत्तार को विश्वास हो गया कि सोया हुआ एशिया और अफ्रीका अब जाग उठा है । इस सम्मेलन में पण्डित नेहरू का शान्ति-सन्देश नवीन उत्साह के साथ सुना गया ।

बाण्डुंग सम्मेलन में अणु बम पर प्रतिबन्ध, रंगभेद की नीति की निन्दा, साम्राज्यवाद का विरोध और विनाश तथा अफ्रो-एशियायी देशों में सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए । इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया कि ‘स्वतंत्रता’ का वास्तविक अभिप्राय क्या है । काफी विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वास्तविक स्वतन्त्रता वही है जिसमें इन तत्वों का समावेश हो—(1) विदेशी प्रभाव से मुक्ति तथा पूर्ण लोकतन्त्रीय स्वशासन, (2) जाति,

समुदाय, रंग आदि के भेद भाव रहित मानव-प्रतिष्ठा को मान्यता, (3) तीव्र आर्थिक समृद्धि जिसका लाभ अधिक से अधिक जनता को प्राप्त हो, एवं (4) मुड का उन्मूलन और सद्भावना का प्रसार ।

वाण्डुंग सम्मेलन का विशेष महत्त्व इस बात में था कि विश्व में सभी देशों के पारस्परिक व्यवहार हेतु 10 सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया । ये सिद्धान्त भारत, चीन द्वारा प्रतिपादित पंचशील के सिद्धान्तों का ही विस्तृत रूप थे । ये सिद्धान्त थे—

- (i) मौलिक मानवीय अधिकारों के प्रति सम्मान की धारणा;
- (ii) संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान की भावना;
- (iii) सब नस्लों तथा छोटे-बड़े सभी राष्ट्रों की समानता में विश्वास;
- (iv) दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना;
- (v) संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुसार प्रत्येक देश को अकेले या सामूहिक रूप से आत्मरक्षा का अधिकार;
- (vi) महाशक्तियों की विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निमित्त व्यवस्थाओं से पृथक् रहना तथा दूसरे देशों पर अनुचित दबाव न डालना;
- (vii) आक्रामक कार्य न करना और आक्रमण की घमस्त्रियाँ न देना;
- (viii) सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण उपायों से समाधान करना;
- (ix) पारस्परिक हितों की वृद्धि, एवं
- (x) न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान ।

वाण्डुंग सम्मेलन की उस समय बड़ी प्रशंसा की गई । इसे एक अभूतपूर्व सम्मेलन माना गया और लघु संयुक्त राष्ट्रसंघ की मंजा दी गई । वॉरेंट नामक विद्वान् ने अपनी पुस्तक 'साम्यवादी चीन और एशिया' में इस सम्मेलन के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे—

“वाण्डुंग सम्मेलन एशिया और अफ्रीका के पुनरोत्थान का प्रतीक था । यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें एशिया और अफ्रीका के पश्चिमी महाशक्तियों के प्रभाव से मुक्त प्रमुख नेता बैठक में सम्मिलित हुए थे जो इस बात का ज्वलन्त उदाहरण था कि विश्व के मामलों में अब एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का भी प्रभाव बढ़ रहा है ।”

अन्त में वाण्डुंग सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि—

“हम अफ्रीकावासी एक ही प्रकार के अत्याचार से पीड़ित रहे हैं और हमारे लक्ष्य भी समान हैं । हम अफ्रीका और एशियावासी सर्वत्र एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते रहे हैं । एशिया और अफ्रीका के हम लोग उन्निवेशवाद की लूट और अत्याचारों के शिकार रहे हैं और इसके कारण गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति में रहने के लिए बाध्य किए गए हैं । हमारी आवाज बलात् दबाई गई है । हमारी महत्त्वाकांक्षाओं को कुचला गया है और हमारा भाग्य दूसरों की दया पर निर्भर रहा है । अतएव हम दासता के विरुद्ध विद्रोह करने के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है ।”

सन् 1955 से 1962 तक का काल : वाण्डुंग भावना का अन्त

वाण्डुंग सम्मेलन ने इस आशा का संचार किया कि अफ्रीका और एशिया के राष्ट्र 10 सिद्धान्तों के अनुसार आपसी सम्बन्धों की स्थापना कर परस्पर एकता और सहयोग का विकास करेंगे, लेकिन 'वाण्डुंग भावना' कुछ ही समय तक जीवित रही। एक ओर तो एशिया में नए स्वतन्त्र राज्य अस्तित्व में आते गए और दूसरी ओर साम्यवादी चीन अनुचित दबाव 'फूट डालो और काम निकासो', विस्तारवाद आदि की नीति पर चलकर एशियायी राज्यों की एकता और सद्भावना को खण्डित करने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में यह समझा जाने लगा था कि भारत और चीन मिलकर एशियायी व्यक्तित्व को नया रूप देने में सफल होंगे, लेकिन चीन की कुटिल और विश्वासघाती नीति ने एशिया के हितों को भारी आघात पहुँचाया। चीन ने 'वाण्डुंग भावना' को ठुकरा दिया तथा विस्तारवाद की सुनियोजित नीति का अनुसरण किया। अपने महान् मित्र-देश भारत की भूमि तक पर भी चीन अपनी कुदृष्टि डालने से बाज नहीं आया। वह अन्य अफ्रीका-एशियायी देशों पर भी दबाव डालने का प्रयत्न करने लगा। चीन ने 'जान-बूझकर सीमा-विवाद' खड़ा कर नवम्बर, 1962 में अचानक ही भारत पर विशाल पैमाने पर आक्रमण कर दिया। यह एक मित्र-देश की पीठ में छुरा भोकने जैसी बात थी। चीन का कदम पंचशील का और वाण्डुंग सम्मेलन के 10 सिद्धान्तों का खुला और शर्मनाक तिरस्कार था। भारत ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण का मुकाबला किया, किन्तु आकस्मिक हमले का लाभ उठाने में चीन सफल रहा। विश्व के अधिकांश युद्धों का इतिहास बताता है कि आक्रमणकारी आकस्मिक हमले का लाभ प्रायः उठा लेता है और उसे इस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है जब संधी लम्बा चले और आक्रमणकारी देश को पराजित कर दिया जाए या कोई सम्मानजनक समझौता हो जाए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों, सैनिक कारणों, कुटनीतिक दबावों आदि के कारण एशिया के इन दो सबसे बड़े देशों के बीच युद्ध लम्बा चलना असम्भव नहीं था। यही भारत सम्मिलने की स्थिति में आया, चीन ने एकरफा युद्ध-विराम की घोषणा कर दी और शान्तिवादी भारत ने तत्कालीन परिस्थितियों में थोड़ी सी भूमि के लिए युद्ध को लम्बा खींचना उपयुक्त नहीं समझा। चीन वपों से अपनी सैनिक योजना को कार्यान्वित कर रहा था तथा आक्रमण की तैयारी में सलग्न था। दूसरी ओर भारत को चीनी हमले की किंचित मात्र भी आशा नहीं थी। अतः भारत की सैनिक और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को जबरदस्त आघात पहुँचा, पर दूसरी ओर चीनी हमले ने भारत को सचेत कर दिया और बाद के वपों का इतिहास साक्षी है कि भारत किसी भी आक्रमण का मुँहोड़ उत्तर देने में समर्थ हो गया। चीन की अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में सर्वत्र निन्दा हुई, लेकिन चीनी नेता हिटलरवादी आचरण से विश्व-शान्ति के लिए सतारा उत्पन्न करते रहे।

सन् 1965 से मई, 1976 तक का काल :

एशियायी व्यक्तित्व को भटके

सामन्तवादी चीन ने आक्रमण, सहयोग और विश्वासघात की जिस नीति

का सूत्रपात किया था उससे पाकिस्तान जैसे देश को प्रोत्साहन मिला। यह स्पष्ट दिखाई दिया कि दोनों देशों ने परस्पर गठजोड़ कर एशिया की एकता को भंग कर और शान्तिवादी शक्तियों को निराश करने का बीड़ा उठा लिया था। सन् 1965 में इण्डोनेशिया में हस्तक्षेप कर चीन ने साम्यवादी शान्ति कराने का असफल प्रयत्न किया। सन् 1965 में ही पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया पर उसने यह समझने की गलती की कि सन् 1965 का भारत सन् 1962 का भारत नहीं था। इस भूल का दण्ड उसे भोगना पड़ा। पाकिस्तान को घुरी तरह पराजित कर भारत ने अपनी खोई हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बहुत कुछ वापस पा लिया। चीन के साथ भी सीमाओं पर कुछ सैनिक भड़पे हुईं, लेकिन भारत की बदलती हुई सैनिक शक्ति का उसे परिचय मिल गया। 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने पुनः भारत के हवाई अड्डों पर आक्रान्त ही भीषण हवाई आक्रमण कर दिया किन्तु, मात्र 14 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान विघटित हो गया। युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर 16 दिसम्बर, 1971 को लगभग एक लाख पाक सैनिकों द्वारा आत्म-समर्पण करने पर पाक सेना के ले जनरल ए. ए. के. नियाजी ने आत्म-समर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पश्चिमी मोर्चे पर भी पाकिस्तान की लगभग 1400 वर्गमील भूमि पर अधिकार कर लिया गया। 17 दिसम्बर को भारत ने एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा कर दो और पाकिस्तान ने ईश्वर की 'अन्यवाद' दिया। नवोदित बंगलादेश के प्रति पाकिस्तान का द्वेषपूर्ण रवैया फिर भी जारी रहा, यद्यपि कालान्तर में उसे वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। फरवरी, 1974 में पाकिस्तान ने बंगलादेश को बिना जर्न मान्यता प्रदान की और बदले में बंगलादेश ने भी पाकिस्तान को मान्यता देकर अपनी सदाशयता का परिचय दिया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद नव स्वतन्त्रता प्राप्त एशियायी देशों में जिस महयोग का प्रारम्भिक वर्षों में विकास हुआ, वह कालान्तर में बिगड़ने लगा। एशियायी देशों के दृष्टिकोणों में एकस्यता के बजाय विभिन्नता के (वहिक यूँ कहिए कि वैमनस्य के) दर्शन होते लगे जिसके फलस्वरूप स्थान-स्थान पर तनाव तथा सैनिक संघर्ष उठ खड़े हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध मधुर नहीं हैं भारत और चीन में वैमनस्य है, बंगलादेश के प्रति चीन और पाकिस्तान के मन साफ नहीं हैं। पश्चिमी एशिया में तो न केवल अरब देश ही पारस्परिक फूट के शिकार हैं बल्कि इजरायल के साथ भी वे संघर्ष में उलझे हुए हैं। कई बार भय नक युद्धों का विस्फोट हो चुका है और कोई नहीं कह सकता कि पुरः किम छए युद्ध भड्क उठे। दक्षिण पूर्वी एशिया में हिन्द-चीन अशान्त है। यद्यपि वर्षों से चला आ रहा वियतनाम युद्ध राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की विजय के साथ 30 अप्रैल, 1975 को समाप्त हो गया तथापि विनाश के घाव भरना अभी बाकी है। यदि उत्तर और दक्षिण वियतनाम के एकीकरण का दौर चला तो कोई नहीं कह सकता कि स्थिति क्या बन पाएगी। अप्रैल, 1975 में ही पिछले पाँच वर्षों से चले आ रहे कम्बोडिया युद्ध का भी यद्यपि अन्त हो गया, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय

राजनीति की उलझने कम्बोडिया को अभी भी अशान्त बनाए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि एशिया महाद्वीप में चारों ओर अशान्ति के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं, एशियायी व्यक्तित्व में दरारे हैं तथा सघर्ष के मादल बराबर मण्डरा रहे हैं। यद्यपि एशिया की आवाज बुलन्द है, अब संयुक्त राष्ट्रसंघ में एशियायी देशों की आवाज को ठुकराना महाशक्तियों के लिए पहले की तरह सुगम नहीं है, फिर भी एशिया तब तक पूरी तरह नहीं उठ सकता जब तक एशिया के राष्ट्र परस्पर सहयोग नहीं करते। समय-समय पर होने वाले सम्मेलनों में एशिया के देश सहयोग की शक्तियों को बढावा देते हैं, लेकिन विघटन की शक्तियाँ भी कम प्रबल नहीं हैं। यह आशा की जानी चाहिए कि एशिया के राष्ट्र सदबुद्धि से काम लेकर एशिया महाद्वीप को वही प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे जो यूरोपीय महाद्वीप को प्राप्त है।

बंगलादेश का उदय : एशिया में नव-जागरण का एक नया मोड़

आज का बंगलादेश दिसम्बर, 1971 में एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य के रूप में उदय से पहले, पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने अपने ही इस पूर्वी भाग की दशा उपनिवेश से भी बदतर बना रखी थी। इस प्रदेश का घोर आर्थिक शोषण तो पाकिस्तान प्रारम्भ से ही कर रहा था, लेकिन 25 मार्च, 1971 की वह रात बड़ी भयावह और काली थी जब तत्कालीन पाकिस्तानी सैनिक शासकों ने पूर्वी बंगाल की अपनी 7.5 करोड़ जनता पर हत्याकाण्ड और नृशंस अत्याचार का अभियान शुरू कर दिया। इनने जुल्म दाएँ गए थे कि इतिहास में दूँदने पर भी शायद ऐसे उदाहरण नहीं मिल सकें। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचारों को देख कर शायद हिटलर को भी 'दूसरी दुनिया में' पछतावा हो रहा होगा कि वह अत्याचारों में पाकिस्तान से मात खा गया। पाकिस्तानी सैनिक शासन के हाथों लगभग 10 लाख व्यक्तियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और एक करोड़ से भी अधिक लोगों को अपना घरबार छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इतिहास में किसी सैनिक सङ्गठन द्वारा इतने बड़े पैमाने पर निरपराध नागरिकों की हत्या करने और एक देश की जनता द्वारा मजबूर होकर इतनी बड़ी संख्या में घरबार छोड़ने का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। भारत ने मानवता के आधार पर शरणार्थियों की हर प्रकार से सहायता की और पूर्वी बंगाल के स्वाधीनता सघर्ष का समर्थन किया। जब 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को नीचा दिखाया और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तथा पूर्वी बंगाल की मुक्ति-बाहिनी की संयुक्त कमान ने पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए। 16 दिसम्बर, 1971 को ढाका में लगभग 1 लाख पाक सेनाओं के आत्म-समर्पण के साथ ही दुनिया के नक्शे पर बंगलादेश (पूर्वी बंगाल या पूर्वी पाकिस्तान) गणराज्य स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वैसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में इस नए राष्ट्रों का अस्तित्व तो तभी व्यावहारिक बन चुका था जब 6 दिसम्बर, 1971 को भारत ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी।

बंगलादेश का उदय वस्तुतः एशिया में एक नव जागरण का सूचक था जो

सन्देश देना है कि अत्याचार, हिंसा और बर्बरता से लोहा लेना मानव का जन्म-सिद्ध अधिकार है और किसी भी देश की उत्पीड़न तथा शोषित जनता को यह मार्ग अपनाना चाहिए। बंगलादेश के उदय ने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को दफना दिया। 14 अगस्त, 1947 को जिस घृणा और रक्तपात के बीच पाकिस्तान का जन्म हुआ उसी नफरत और रक्तपात के साथ पाकिस्तान खण्डित हो गया। एक पीढ़ी में ही यह सिद्ध हो गया कि मजहब कभी भी राष्ट्रीयता का मुख्य आधार नहीं बन सकता। अंग्रेजों ने भी द्विराष्ट्र सिद्धान्त को समर्थन इसलिए दिया था कि वे भारत में अपनी प्रभाव जमाए रखना चाहते थे, लेकिन उनकी कुटिल नीति सफल न हो सकी। भारत पर प्रभाव जमाने की बात तो दूर रही, बंगलादेश के उदय ने ऐसे भ्रामक और नापाक सिद्धान्तों की घण्टियाँ उड़ाकर अंग्रेजी और पाकिस्तानी इरादों को मिट्टी में मिला दिया।

उदय के बाद बंगलादेश ने अपनी जनता को लोकतान्त्रिक संविधान दिया। 16 दिसम्बर, 1972 से बंगलादेश में नया संविधान लागू कर दिया गया। इसके तुरन्त बाद ही मार्च, 1973 में संविधान के अन्तर्गत नए चुनावों की घोषणा कर दी गई। निष्पक्ष निर्वाचनों में शेख मुजीब की आवासी लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 22 फरवरी, 1974 को परिस्थितियों से बाध्य होकर पाकिस्तान ने बंगलादेश को मान्यता प्रदान की और 18 सितम्बर, 1974 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी बंगलादेश को प्राप्त हो गई। साम्यवादी चीन के अडिगल रवैये और उसके द्वारा चीन के प्रयोग की आशंका से ही बंगलादेश का संघ में प्रवेश इतने समय तक रुका रहा था। भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्तर पर बंगलादेश को अपना समर्थन और सहयोग दिया और आज दोनों देश मैत्री में आवद्ध हैं। तथापि शेख मुजीब की हत्या के बाद 1975-1976 में बंगलादेश में जो बानाबुरण बना है वह शोचनीय है। बंगलादेश में भारत विरोधी तत्त्व फिर उठा रहे हैं और बंगलादेश की नई सरकार का यह वर्तमान है कि वह उस देश के प्रति अपनी मैत्री का निर्वाह करे जिम्मे उमके स्वतन्त्रता संग्राम को सफल बनाने में अभूतपूर्व सहायता की थी और अपने जवानों का बलिदान दिया था।

अफ्रीका में उपनिवेशवाद का अन्त और नए राज्यों का उदय अफ्रीका महाद्वीप का परिचय

अफ्रीका लगभग 11,5,00,000 वर्गमील क्षेत्रफल वाला एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह आकार, लम्बाई और अन्य कई अर्थों में दक्षिण अमेरिका के समान है। उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश निवासी गोरे हैं और शेष अफ्रीका के मूल निवासी काले हैं लेकिन दोनों के बीच एकता और प्रेम की भावनाएँ विकसित होती रही हैं। अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका से बहुत सी बातों में समानता रखता है। ब्रून एव मैमटे (Brunn & Mamatey) के अनुसार—

“दोनों अपने उत्तर में एक विशाल भू-खण्ड से एक तट भूदमरूमध्य द्वारा जुड़े हुए हैं, जो मानव-निर्मित नहरों द्वारा विभाजित है। दोनों लगभग त्रिकोणाकार

हैं जो दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़े हुए एक पूर्ण कोण बनाते हैं। दोनों बीच में विषुवद-रेखीय प्रदेशों की तरह बरसाती जंगलों और बड़ी नदियों से भरपूर हैं—अफ्रीका की कांगो नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी एक जैसी है। जनसंख्या का घनत्व लगभग एव-सा है, जिसमें एक वर्गमील क्षेत्र में सिर्फ 20 व्यक्ति रहते हैं। दोनों साधन-सम्पन्न हैं। खनिज, पेट्रोल और जलशक्ति इतनी है कि उनके विकास के लिए सिर्फ पूंजी की आवश्यकता है। दोनों ने जनसंख्या की वृद्धि की दर 10वीं और जीवन-स्तर निम्नकोटि का है। दोनों यूरोपीय उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं और दोनों ने सघर्ष द्वारा आजादी प्राप्त की है। दक्षिण अमेरिका के लोगों ने स्वयं की स्पेनिश और पुर्तगाली शासन के शिकारों से 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही मुक्त कर लिया था। अफ्रीका की जनता 19वीं शताब्दी में अनेकों यूरोपीय शक्तियों की साम्राज्य-लिप्सा का शिकार थी, किन्तु उन्होंने 20वीं शताब्दी के मध्य में तेजी से स्वतन्त्रता प्राप्त की।¹¹

सन् 1870 के बाद से ही यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका में उपनिवेशों की स्थापना की होड़ लग गई। सन् 1870 के बाद केवल 20 वर्ष की अल्पावधि में ही यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका के लगभग 9/10 भाग को परस्पर विभाजित कर लिया। सन् 1880 में उनके पास 1 लाख वर्ग मील प्रदेश था जो 10 वर्ष बाद बढ़ कर 6 लाख वर्गमील हो गया। इस प्रकार 19वीं सदी के अन्तिम चरण के समाप्त होते-होते समूचा अफ्रीका महाद्वीप यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश बन गया। प्रथम महायुद्ध से पूर्व केवल एबीसीनिया ही स्वतन्त्र राज्य रह गया था किन्तु सन् 1936 में इसकी स्वतन्त्रता भी इटली द्वारा समाप्त कर दी गई, हालाँकि द्वितीय महायुद्ध में यह राष्ट्र पुनः स्वतन्त्र हो गया। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ तो सम्पूर्ण अफ्रीका में केवल एबीसीनिया, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीकी संघ और मिस्र ही स्वतन्त्र या अर्द्ध-स्वतन्त्र राज्य थे। अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के मध्य इस प्रकार विभाजित था—

क्र.सं.	नाम	क्षेत्रफल (वर्गमील)	1961 के अनुसार जनसंख्या
1	फ्रांसीसी अफ्रीका	40,22,150	4,41,52,600
2	ब्रिटिश अफ्रीका	20,25,719	6,24,33,645
3	बेल्जियम अफ्रीका	9,24,300	1,20,00,000
4	पुर्तगाल अफ्रीका	7,78,000	95,00,000
5	स्पेनिश अफ्रीका	1,34,260	14,95,000

द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतन्त्रता की लहर (1945-1974)

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका, जिसे कभी अन्ध-महाद्वीप (Dark-Continent) कहा जाता था, कुछ ही वर्षों में स्वतन्त्रता के प्रकाश से प्रालोकित हो उठा। जिसे

तेजी से यूरोप के राष्ट्रों ने अफ्रीका में अपने साम्राज्य का निर्माण किया था, उससे भी कई गुना अधिक तेजी से अफ्रीका में उनके साम्राज्य का अन्त हो गया। 20 वर्ष के अल्पकाल में ही अफ्रीका के 90 प्रतिशत देश स्वतन्त्र हो गए। जाति, भाषा, इतिहास, परम्परा, धर्म आदि की विभिन्नताओं के बावजूद अफ्रीका में राष्ट्रवाद ने प्रगडाई ली। यह एक विलक्षण घटना थी। इस राष्ट्रवाद के उदय और विकास मूल में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण निहित थे—

1. यूरोप की गोरी जातियाँ अफ्रीका के अश्वेत लोगों को स्वयं से निम्न कोटि का मानती थी। इस सिद्धान्त की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद की मुख्य प्रेरणा 'जातीय समानता' के सिद्धान्त से मिली, पाश्चात्य सम्पर्क और पाश्चात्य साहित्य के प्रवेश ने भी अफ्रीका के प्रबुद्ध लोगों में राष्ट्रवाद की ज्योति जपाने में सहायता की।

2. द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की स्वाधीनता के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों में भी स्वाधीनता की लहर फैल गई। एशिया के राष्ट्र तेजी से स्वतन्त्र होने गए। स्वतन्त्रता की यह लहर अफ्रीका महाद्वीप से जा टकराई और इस महाद्वीप के करोड़ों लोग स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए घातुर हो उठे।

3. महायुद्धकाल के स्वतन्त्रता-प्रेमी प्रमेरिकियों के सम्पर्क ने भी अफ्रीका-वासियों में स्वतन्त्रता की आकांक्षा पैदा की। राष्ट्रसंघ और संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध से भी अफ्रीका के राष्ट्रीय जागरण की बल मिला।

4. अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी अफ्रीका के देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता दी। महायुद्ध ने उपनिवेशवादी शक्तियों को अत्यन्त दुर्बल बना दिया। फ्रांस, ब्रिटेन आदि राष्ट्र इतने कमजोर हो गए कि उनमें अपने उपनिवेशों के स्वाधीनता आन्दोलनों का दमन करने की शक्ति नहीं रही। जब एशिया के उपनिवेश तेजी से उनके चंगुन से मुक्त होने लगे तो अफ्रीकी राष्ट्रवादियों में भी प्रबल आत्म-विश्वास जाग्रत हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका महाद्वीप में एक एक करके स्वतन्त्रता की तीन उत्तरोत्तर ज्वरदंश लहरें आईं। महायुद्ध की समाप्ति पर अफ्रीका में केवल 4 राज्य स्वतन्त्र थे—एवीमीनिया, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीकी संघ और मिस्र। यह 130 लाख वर्ग मील का क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का केवल 11% था और इसकी 28 करोड़ की आबादी अफ्रीका की कुल जनसंख्या का 26% थी। इसके बाद स्वतन्त्रता की पहली लहर आई। इस लहर ने केवल अल्जीरिया को छोड़ कर मरबो द्वारा आवासित शेष उत्तरी अफ्रीका से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का सफाया कर दिया। इस पहली लहर द्वारा स्वतन्त्र होने वाले राष्ट्रों में सन् 1951 में स्वतन्त्र होने वाला सीरिया और सन् 1956 में स्वाधीनता प्राप्त करने वाले मूडान, मोरक्को तथा ट्यूनीशिया थे। स्वतन्त्रता की दूसरी लहर ने काले अर्थात् नीग्रो लोगों द्वारा आवासित अफ्रीका को प्रभावित किया। सन् 1957 में ब्रिटेन द्वारा

घाना को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और सन् 1958 में गिनी पंचम फ्रेंच गणराज्य से पृथक् हो गया। सन् 1959 तक अफ्रीका में ग्यारह राज्य स्वाधीन हो गए, किन्तु अभी तक सहारा के दक्षिण का और जम्बेसी नदी के उत्तर का मध्य अफ्रीका पराधीन था। सन् 1960 में स्वतन्त्रता की तीसरी जबर्दस्त लहर ने इस क्षेत्र के अधिकांश गुलाम देशों को आजाद कर दिया। यह वर्ष अफ्रीका के स्वतन्त्रता का वर्ष कहा जाता है जिसमें 17 देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। इसके बाद एक-एक करके अफ्रीका के शेष देश भी स्वतन्त्र होते गए और आज केवल इनेगिने प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप स्वतन्त्र हो चुका है। जो देश स्वतन्त्र हुए वे ये थे—

क्र. सं.	नाम देश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	स्वतन्त्र होने की तिथि
1.	लाइबेरिया	अमेरिका	1847
2.	इथोपिया	—	1941
3.	लीबिया	—	24 नवम्बर 1951
4.	इरिट्रिया	इटली	सितम्बर 1952
5.	सूडान	ब्रिटेन	जनवरी 1956
6.	मोरक्को	फ्रांस	मार्च 1956
7.	ट्यूनीशिया	फ्रांस	मार्च 1956
8.	घाना	ब्रिटेन	मार्च 1957
9.	गिनी	फ्रांस	अक्तूबर 1958
10.	संयुक्त अरब गणराज्य	—	1959
11.	कैमरून	फ्रांस	जनवरी 1960
12.	मोरक्को (कुछ अंग)	स्पेन	मार्च 1960
13.	टोगो	फ्रांस	अप्रैल 1960
14.	मालीयस	फ्रांस	जुलाई 1960
15.	कांगोली गणराज्य	बेल्जियम	जुलाई 1960
16.	सोमालिया	ब्रिटेन व इटली	जुलाई 1960
17.	मालायासो गणराज्य	फ्रांस	जुलाई 1960
18.	छाव	फ्रांस	अगस्त 1960
19.	नाइजर	फ्रांस	अगस्त 1960
20.	आइवरी कोस्ट	फ्रांस	अगस्त 1960
21.	वीरुडार्ड गणराज्य	फ्रांस	अगस्त 1960
22.	सेनेग	फ्रांस	अगस्त 1960
23.	होमी	फ्रांस	अगस्त 1960
24.	कांगो गणराज्य	—	अगस्त 1960
25.	मध्यवर्ती अफ्रीका	—	अगस्त 1960
26.	नाइजीरिया	ब्रिटेन	अक्तूबर 1960
27.	मालिनेरिया	फ्रांस	नवम्बर 1960
28.	सिमरालिमोन	फ्रांस	अप्रैल 1961
29.	रूंडा-उरुंडी	बेल्जियम	जुलाई 1962
30.	अङ्जीरिया	फ्रांस	नवम्बर 1962

क्र. स.	नाम प्रदेश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	स्वतन्त्र होने की तिथि
31.	सुगाँडा	ब्रिटेन	अक्तूबर 1962
32.	तगानिक्वा	ब्रिटेन	दिसम्बर 1962
33.	बेनिया	ब्रिटेन	दिसम्बर 1963
34.	बजीबार	ब्रिटेन	दिसम्बर 1963
35.	न्यामालेण्ड (मलावा)	ब्रिटेन	1964
36.	जेम्बिया (उत्तरी रोडेसिया)	ब्रिटेन	1964
37.	जैम्बिया	ब्रिटेन	1965
38.	ब्रिटिश गिबाना		
	(नया नाम गुआना)	ब्रिटेन	मई 1966
39.	बोत्सवाना (बेचुआनलैण्ड)	ब्रिटेन	सितम्बर 1966
40.	सेसीयो (बसुवोलैण्ड)	ब्रिटेन	अक्तूबर 1966
41.	बारबाडोस	ब्रिटेन	नवम्बर 1966
42.	बारिबास	ब्रिटेन	मार्च 1968
43.	ब्रिटाइ	ब्रिटेन	फरवरी 1974
44.	गिनी बिस्सऊ	पुर्तगाल	सितम्बर 1974
45.	मोजाम्बिक	पुर्तगाल	जून 1975
46.	बेपवर्दे	पुर्तगाल	जुलाई 1975
47.	बोम्बोरी द्वीप समूह	पुर्तगाल	जुलाई 1975
48.	अंगोला	पुर्तगाल	नवम्बर 1975
49.	सेशेल्स	ब्रिटेन	जून 1976

अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक परम्पराएँ आरम्भ से ही अधिनायकवादी और सर्वसत्तावादी रही हैं। औपनिवेशिक युग आरम्भ होने से पहले अफ्रीका महाद्वीप में एकतन्त्रात्मक शासन का बोलबाला था। कबीलों के सरदार स्वच्छाचारी ढंग से शासन करते थे। औपनिवेशिक युग के दौरान भी इस स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। अफ्रीका के लोग साम्राज्यवादी शक्तियों के निरंकुश शासन से पीड़ित रहे। अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में स्वस्थ लोकतन्त्रीय परम्पराओं का विकास नहीं हो सका, किन्तु अब स्वतन्त्रता के इस युग में अनेक अफ्रीकी देशों में—विशेषकर भू-पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में, मसदीय लोकतन्त्र की स्थापना की गई है। यद्यपि उदात्त लोकतन्त्र अभी अधिक सफल नहीं हुआ है, तथापि अफ्रीका धीरे-धीरे लोकतान्त्रिक परम्पराओं और संस्थाओं के विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। कुछ देशों में लोकतन्त्र की काफी प्रगति हुई है तो कुछ देशों में निर्वाचित एकतन्त्र की स्थापना बर्ग गई है।

अफ्रीका में साम्यवाद का प्रभाव अभी तक विशेष उग्र नहीं हो पाया है। अफ्रीकी देशों के प्रति सोवियत संघ और चीन के दृष्टिकोण भिन्न रहे हैं। सोवियत संघ ने अफ्रीकावासियों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में नैतिक और कूटनीतिक समर्थन दिया है जबकि चीन की नीति अफ्रीकी देशों पर दबाव डालने और उन्हें

अपनी शक्ति से आतंकित करने की रही है। यद्यपि दोनों ही देश चाहते हैं कि अफ्रीका में साम्यवाद का प्रसार हो, तथापि दोनों के उद्योग भिन्न-भिन्न हैं। दोनों ही देशों के नेता अफ्रीका के विभिन्न देशों के बारे में चिन्ता करते रहे हैं।

राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर भी अफ्रीका के सामने एक बड़ी समस्या अपनी इस स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने की है। महाशक्तियाँ और कुछ अन्य बड़े देश अफ्रीका के पिछड़े देशों को अपने प्रभाव में लाने की उत्सुक हैं। आर्थिक दृष्टि में अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ है, यद्यपि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से यह एक समृद्ध है। अफ्रीका के देश चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र उन्हें आर्थिक और प्राविधिक सहायता दें ताकि वे अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सकें, लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि उनकी सम्प्रभुता और स्वतन्त्रता पर कोई आंच न आए। अब यह सम्भव नहीं है कि अफ्रीकी देश पारम्परिक औद्योगिक उत्पादन के लिए बाजार बन कर रह जाएँ।

एशियाई राज्यों की तरह ही अफ्रीकी राज्यों में पारस्परिक फूट के शिकार हैं। विभिन्न राज्यों में पारस्परिक झगड़ों का दोलन जारी है, कई बार सैनिक झड़पें भी होती हैं। सैनिक अन्तिम होना भी एक आग बान है। पृथक्तावादी आन्दोलन भी जब तब जोर पकड़ते हैं। शिक्षा, सम्यता और वित्तन में पिछड़े हुए होने के कारण अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवाद अभी इतना प्रभावशाली नहीं हो सके है जितना एशिया महाद्वीप में। ये सब बातें अफ्रीका महाद्वीप की एकता के लिए हानिकारक हैं और इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर अफ्रीका का इतना शक्तिशाली चित्र अभी नहीं उभर सका है जितना उभरना चाहिए था। भविष्य में अफ्रीका के कुछ देशों में साम्यवादी आन्दोलन के जोर पकड़ जाने और स्थिति विस्फोटक बन जाने की सम्भावना से भी डकार नहीं किया जा सकता। अफ्रीका के कई देशों जैसे काहिरा, अदिस अबाबा, प्रोटेरिया, किमोनरोविया आदि में साम्यवादियों के कूटनीतिक झड़पें हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, फामोसी पश्चिमी अफ्रीका में स्थानीय साम्यवादी दलों का प्रभाव है। वैसे अफ्रीका के नेताओं में से बहुत कम ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं।

एशिया और अफ्रीका के जागरण के कारण

एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में जागरण की जो लहर उठी और विकसित हुई उसके कारण निम्नलिखित हैं—

1. द्वितीय महायुद्ध ने यूरोप के राष्ट्रों को आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक दृष्टि से निर्वल बना दिया था। यूरोप स्वयं 'समस्या-प्रधान' (Problem Europe) महाद्वीप बन गया। जर्मनी और इटली नष्ट हो गए, ब्रिटेन और फ्रांस तीसरी श्रेणी के राष्ट्र बन गए। इस प्रकार ये उपनिवेशवादी शक्तियाँ इस योग्य नहीं रही कि अपने विशाल साम्राज्य का भार सम्भाल सकें।

2. महायुद्ध में गरीबी जातियों को गहरी पराजयों का सामना करना पड़ा। अतः एशिया और अफ्रीका के लोगों के दिलों में यह बात बैठ गई कि गरीबी जातियों

‘अजेय’ नहीं है। इस अनुभूति ने उनमें नव-जीवन का संचार किया जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्र होते गए।

3. महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ। उसने दोहरी नीति अपनाई—एक ओर तो ब्रिटेन, फ्रांस आदि उपनिवेशवादी शक्तियों को प्रार्थना दीया और दूसरी ओर एशियाई देशों के मन में यह बात भी बैठाती चाही कि अमेरिका उनके स्वाधीनता-संग्राम का समर्थक एवं उपनिवेशवाद का विरोधी है। अमेरिका ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रकट रूप में विरोध नहीं किया था वरन् वह कोशिश की थी कि इन महाद्वीपों के जागरण का अमेरिकी हितों में प्रयोग किया जाए, अतः परिणाम यह निकला कि अफ्रो-एशियायी राष्ट्रवाद जोर पकड़ गया।

4. अफार एशिया के बावजूद सोवियत संघ भी महायुद्ध के बाद दूसरी महाशक्ति के रूप में उभरा। रूस ने एशिया और अफ्रीका के देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपने स्वाधीनता-आन्दोलनों को प्रेरणा दी। एक महाशक्ति का कूटनीतिक और नैतिक समर्थन पाकर महाद्वीपों के राष्ट्रीय आन्दोलन सफलता की ओर बढ़े।

5. महायुद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बंट गया—पूँजीवादी और साम्यवादी। दोनों गुटों ने एशिया और अफ्रीका के पिछड़े राष्ट्रों को आर्थिक और प्राविधिक तथा समर्थित सैनिक सहायता देना शुरू किया। दोनों ने ही यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वे एशिया और अफ्रीका के हित-चिन्तक हैं। इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम यह हुआ कि अफ्रो-एशियाई राष्ट्र अपने राजनीतिक और सामरिक महत्त्व को अधिक अच्छी तरह समझने लगे। उनका साहस बढ़ गया और राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रसार हुआ।

6. संयुक्त राष्ट्रसंघ में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाई गई और विश्व-जनमत एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों के पक्ष में हो गया। न्याय-परिषद् ने दूस्त्री राष्ट्रों पर संरक्षित प्रदेशों में सार्वभौमिक सुधारों के लिए दबाव डाला और एक निर्धारित समय में उन्हें स्वतन्त्र कराने का कार्यक्रम तैयार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि न्याय-संस्था के अन्तर्गत आज कोई प्रदेश नहीं है जबकि मई 1945 में 11 प्रदेश थे।

7. आवागमन और संचार के वैज्ञानिक साधनों के फलस्वरूप दुनिया जिस तरह से सिकुड़कर छोटी हो गई उससे भी एशिया और अफ्रीका के आन्दोलन गतिमान हुए। विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं में सम्पर्क बढ़ा तथा स्वाधीनता आन्दोलनों को सकल बनाने के लिए नीतियों का निर्धारण हुआ। दोनों महाद्वीपों के देश इस बात से अच्छी तरह परिचित हो गए कि यूरोपीय राष्ट्रों तथा अमेरिका की तुलना में वे आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से कितने पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार की अनुभूति ने अफ्रीका और एशियावासियों को अपनी उन्नति के लिए प्रेरित किया। जो राष्ट्र स्वतन्त्र होते गए वे इस बात के लिए कटिबद्ध हो गए कि वे शीघ्रान्वित स्वावलम्बी बनने लगे किन्तु फिर से साम्राज्यवाद के शिकवे में न फँस सकें।

8. अल्जीरिया के सफल स्वाधीनता संग्राम ने अफ्रीका महाद्वीप में एक नई ज्योति जगाई।

एशिया और अफ्रीका का जागरण वास्तव में उस उभरते हुए राष्ट्रवाद का ही दूसरा नाम है जो इन महाद्वीपों के छोटे-बड़े राष्ट्रों की विभिन्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों और मान्यताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्रों और विशेषताओं के बीच टकराव तथा आदान-प्रदान के फलस्वरूप विकसित हुआ है।

एशिया तथा अफ्रीका के जागरण में समानताएँ तथा अन्तर

समानताएँ

1. दोनों ही महाद्वीप जाग उठे हैं, गुलामी से लगभग मुक्त हैं तथा हर प्रकार के साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद के विरोधी हैं।

2. सदियों तक परतन्त्र रहने के कारण दोनों महाद्वीप आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं। दोनों में ही अशिक्षा का बोलबाला है तथा राजनीतिक चेतना अपरिपक्व है।

3. महाशक्तियाँ दोनों ही महाद्वीपों के अनेक राज्यों की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक बमजोरियों का लाभ उठाकर अपने 'आर्थिक उपनिवेशवाद' के लिए प्रयत्नशील हैं। अमेरिका अपने 'डॉलर साम्राज्यवाद' का प्रसार चाहता है तो रूस भी अपने आर्थिक प्रभावक्षेत्र के विस्तार का इच्छुक है, लेकिन अमेरिका की तुलना में रूस की नीति कम उग्र है।

4. महाशक्तियों की हस्तक्षेप-नीति ने दोनों ही महाद्वीपों में सपर्ष के अनेक विस्फोटक केन्द्रों की स्थापना कर दी है।

5. दोनों महाद्वीपों में अधिकांश राज्यों का नेतृत्व पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नेताओं के हाथों में है। ये नेता अपने देशों की पाश्चात्य व्यवस्थाओं के अनुकूल ढालना चाहते हैं। अनेक देशों की जनता गरीबी की चक्की में पिस रही है, लेकिन उन देशों का नेतृत्व वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है।

6. दोनों ही महाद्वीपों के देश राष्ट्रवाद की लहर से प्रोतप्रोत हैं, पर साथ ही साम्यवाद के प्रसार से भी आशंकित हैं।

7. अपने आर्थिक और प्राविधिक विकास के लिए दोनों ही महाद्वीप परभुतापेक्षी हैं, अतः सहायता देने वाली शक्तियों की सहायता प्राप्त देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने के प्रबल गुलम होने रहे हैं।

8. सैनिक क्रान्तियाँ दोनों ही महाद्वीपों में होनी रहती हैं, तथापि लोकतन्त्रीय परम्पराओं और संस्थाओं का विकास होता जा रहा है।

अन्तर

1. एशिया का राष्ट्रवाद अफ्रीकी राष्ट्रवाद की तुलना में अधिक परिपक्व है।

2. एशिया में भारत, चीन, जापान, बर्मा जैसे विशालकाय और उन्नत देशों का अस्तित्व है जबकि अफ्रीका में छोटे-छोटे राष्ट्रों की भरमार है। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत् पर जितना प्रभाव एशिया का है उतना अफ्रीका का नहीं।

3. एशिया में अफ्रीकी राष्ट्रों की तुलना में शिक्षा का अधिक प्रसार है।

4. एशिया में लोकतन्त्र जितना प्राये बढ चुका है, अफ्रीका में अपेक्षाकृत बहुत कम बढ पाया है। जहाँ भारत एशिया में लोकतन्त्र का गढ़ है वहाँ अफ्रीका में ऐसा कोई देश नहीं है।

5. अफ्रीकी राष्ट्रवाद उग्र है जबकि एशियायी राष्ट्रवाद सामान्यतः शान्तिपूर्ण उपायों में विश्वास करता है। अपवाद की बात अलग है।

6. एशियायी में यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने सुस्पाई रूप से बसने की नीति अपनाई थी जबकि अफ्रीका में यूरोपीय जानियों स्पाई रूप से बस गईं। अतः एशिया की तुलना में अफ्रीका में अधिक जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गईं जो आज भी अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रही हैं।

7. रंगभेद और कबीलावाद की समस्याएं एशिया की अपेक्षा अफ्रीका में निरन्तर अधिक गम्भीर रही हैं।

8. अफ्रीकी नेता, अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर एशियायी नेताओं की तुलना में प्रायः अधिक उग्र रहे हैं। इसने एफ्रो-एशियायी एकता आन्दोलन को बड़ा आघात पहुँचा है।

9. एशिया की तुलना में अफ्रीका में साम्यवाद का प्रभाव उग्र रूप में नहीं हो पाया है। एशिया में चीन दुनिया का सबसे बड़ा साम्यवादी देश है।

10. एशिया की तुलना में अफ्रीका के देश आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं।

एशिया और अफ्रीका के जागरण के प्रतीक महत्त्वपूर्ण संगठन और सम्मेलन

द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में चेतना की जो लहर उठी उसके फलस्वरूप इन महाद्वीपों के विभिन्न राष्ट्रों ने पारस्परिक सम्पर्क का महत्त्व समझा। अतः समय-समय पर अफ्रोएशियायी देशों के सम्मेलन हुए जिन्होंने राष्ट्रीयता का प्रसार किया और उपनिवेशवाद की जड़ें खोखली कर दी। जागरण के मन्देशवाहक इन महत्त्वपूर्ण सम्मेलनों पर दृष्टिपात करना उचित होगा।¹

प्रथम एशियायी सम्मेलन, 1947

भारत के प्रधान मन्त्री स्वर्गीय प. नेहरू की प्रेरणा से इण्डियन कौंसिल ऑफ वल्थे अफेयर्स ने मार्च अप्रैल 1947 में एशियायी देशों के एक गैर-सरकारी सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें 28 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सदस्यों ने एशियायी देशों की राजनीतिक स्वतन्त्रता, उनके आर्थिक विकास, रंगभेद आदि की विभिन्न समस्याओं पर विचार किया। इस बात पर सभी सदस्य-राज्य सहमत थे कि एशियायी देश आपस में मिलकर ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

1. सदस्य या गृह-निरपेक्ष देशों के जो सम्मेलन हुए (जैसे काहिरा सम्मेलन 1964, युबाबा सम्मेलन 1970, अल्जीरिया सम्मेलन 1973, आदि) उनका विवरण 'गृह-निरपेक्षता' अध्याय में दिया गया है।

एशियायी सम्मेलन, 1949

भारत सरकार के आमन्त्रण पर दिल्ली में 20 से 30 जून, 1949 तक एशियायी देशों का द्वितीय सम्मेलन हुआ। इसका मूल उद्देश्य इण्डोनेशिया पर डच आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करना था। इस सम्मेलन में डच कार्यवाही की कठोर शर्तों में निन्दा की गई। डच आक्रमण को असफल बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए तथा सुरक्षा परिषद्, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड का सहयोग प्राप्त कर हॉर्नैण्ड के प्रति कठोर नीति अपनाने का निश्चय किया गया।

वाष्डुंग सम्मेलन, 1955

इण्डोनेशिया के नगर वाष्डुंग में 18 अप्रैल से 27 अप्रैल, 1954 तक एशिया और अफ्रीका के 29 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिस पर पूर्व पृष्ठों में प्रकाश डाला जा चुका है। इस सम्मेलन ने अफ्रो-एशियायी राष्ट्रों में एक नया आत्मविश्वास जाग्रत किया। राज्यों के आपसी व्यवहार के दस सिद्धान्त निर्धारित किए गए जो पचशील का ही विस्तारमात्र थे। सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याओं के प्रति एशिया और अफ्रीका का समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

मोंशी सम्मेलन, 1963

फरवरी, 1963 में मोंशी (टांगानिका) में अफ्रोशियायी एकता सम्मेलन हुआ। इसमें—(i) ब्रिटेन से अपील की गई कि वासुतोलैण्ड, वेसुआनालैण्ड तथा स्वाजीलैण्ड को तुरन्त बिना शर्त स्वतन्त्रता प्रदान कर दे; (ii) राष्ट्रों से अपील की गई कि उपनिवेशवादी अस्तित्वों के दमन में पीड़ित लोगों को राजनीतिक शरण दी जाए; (iii) इजरायल की इस बात के लिए निन्दा की गई कि वह एक नया उपनिवेशवादी अड्डा बनता जा रहा है; (iv) यह स्वीकार किया गया कि चीन को फारमोसा को मुक्त करने का अधिकार है; (v) सभी राष्ट्रों से अपील की गई कि पुर्तगाल के विरुद्ध आर्थिक और कूटनीतिक बहिष्कार लागू कराएँ और अगोला तथा मौजाम्बिक के स्वतन्त्रता आन्दोलनों को सहायता दे; (vi) दक्षिण रोडेशिया के लोगों को उनके मुक्ति-संग्राम में सहयोग देने की अपील की गई; (vii) ब्रिटेन से अमेरिका से आक्रामक कार्यवाहियाँ बन्द करने की अपील की गई; (viii) ब्रिटेन को सुझाव दिया गया कि वह सन् 1963 के अन्त तक जजीबार को स्वतन्त्र कर दे; एवं (ix) यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ अमेरिकी साम्राज्यवाद का साधन न बने और इसका पुनर्गठन इस तरह किया जाए कि इसमें एशिया और अफ्रीका को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

अदिस अबाबा सम्मेलन, 1963

मई, 1963 में इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में 32 राष्ट्रों का अफ्रीकी सम्मेलन हुआ। इसमें संयुक्त अफ्रीका की स्थापना पर विचार किया गया। अफ्रीकी राष्ट्रों के एक स्वाधीन विधायक की स्थापना और सभी राज्यों के विदेश-मन्त्रियों की एक मन्त्रि-परिषद् की स्थापना पर विचार हुआ। इन निश्चयों के

अनुसार कार्य भी हुआ। सचिवालय का नाम 'अफ्रीकी एकता संगठन' रखा गया। अफ्रीकी राज्यों के बीच होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक आयोग भी स्थापित किया गया। अफ्रीका के पराधीन देशों को औपनिवेशिक दासता से मुक्त करने और दक्षिण अफ्रीका की अश्वेत जनता को रंगभेद नीति के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए एक मुक्ति-मेला और मुक्ति-कोष की स्थापना पर विचार हुआ। यह निर्णय लिया गया कि दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल के विरुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक बहिष्कार की नीति अपनाई जाए। सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसमें अफ्रीकी एकता का एक घोषणापत्र स्वीकार किया गया जिसमें समूचे अफ्रीका महाद्वीप को दासता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की गई। इसके लिए 9 अफ्रीकी देशों—टॉगानिका अल्जीरिया, इथियोपिया, संयुक्त-अरब-अमिराज्य, युगाण्डा, कांगो, गिनी, सेनेगल नेवा, नाइजीरिया को मिलाकर एक स्वाधीनता समिति (Liberation Committee) की स्थापना हुई। इसका प्रधान कार्यालय दारेस्तलाम में रखा गया।

अफ्रेशियायी एकता सम्मेलन, 1972

जनवरी, 1972 में काहिरा में अफ्रेशियायी एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें 69 देशों के प्रतिनिधि-मण्डलों ने भाग लिया। सम्मेलन पाकिस्तानी प्रतिनिधि-मण्डल के विरोधी रवैये के बावजूद भारत और बंगलादेश के ग्वायोचित पत्र में विभाजित हुआ। लीबिया के प्रस्ताव अन्वय मुस्लिम राज्यों ने नवोदित बंगलादेश का समर्थन किया और भारतीय उपमहाखण्ड की वास्तविकता को स्वीकार किया। सम्मेलन में बंगलादेश के प्रतिनिधि-मण्डल को भी आमन्त्रित किया गया जो इस बात का प्रमाण था कि एशिया और अफ्रीका के बहुसंख्यक देशों ने उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। पश्चिम एशिया, हिन्द-चीन और अफ्रीका के मुक्ति-आन्दोलनों के बारे में भी खुलकर विचार-विमर्श हुआ। अफ्रेशियायी देशों का एक माभा वाजार बनाने की भी पेशकश की गई।

अफ्रीकी एकता संगठन

25 मई 1962 को 30 अफ्रीकी देशों ने प्रसिद्ध प्रस्ताव सम्मेलन में 'अफ्रीकी एकता संगठन' की स्थापना के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। वही इस संगठन का मुख्यालय है। संगठन का प्रधान उद्देश्य है—अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग की वृद्धि, उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा सदस्य-देशों की स्वाधीनता की रक्षा के लिए काम करना। समय-समय पर सदस्य देशों के विदेश-मन्त्रियों के अधिवेशन होने हैं। जिल्लर अधिवेशन भी होते हैं। इनके माध्यम से संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और अफ्रीकी देशों के बीच उत्पन्न मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

पान-अफ्रीकावाद

अखिल अफ्रीकी आन्तर्ग आन्दोलन अथवा पान-अफ्रीकावाद (Pan-Africanism) दस महाद्वीप के एकीकरण का एक बहुत प्राचीन आन्दोलन है। इस

आन्दोलन का ध्येय 'संयुक्तराज्य अफ्रीका' की स्थापना है। सबसे पहले सन् 1900 में लन्दन में पान-अफ्रीकी सम्मेलन हुआ और तब से समय समय पर ये सम्मेलन होते रहे हैं जिनमें अफ्रीका को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने सम्बन्धी निर्णय लिए गए हैं। घाना के स्वतन्त्र होने पर अफ्रीका में जब यह सम्मेलन हुआ (इसके पहले यह आन्दोलन अफ्रीका के बाहर ही था) तो इसके मुख्य उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया। ये उद्देश्य, संकेत रूप में, इस प्रकार हैं—

1. अफ्रीका के सभी देशों के एक सघ का निर्माण जाए। क्षेत्रीय आधार पर भी सघ बनाए जा सकते हैं, जैसे—उत्तर अफ्रीका सघ, पश्चिम अफ्रीका सघ, केन्द्रीय अफ्रीका सघ, दक्षिण अफ्रीका सघ, आदि।

2. उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेदवाद का विरोध किया जाए।

3. अहिंसात्मक साधनों और तटस्थ नीति को प्रोत्साहन दिया जाए।

पहले पान-अफ्रीकी सम्मेलनों में अफ्रीकी देशों की स्वतन्त्रता पर अधिक बल दिया जाता था, पर अब अफ्रीका महाद्वीप लगभग स्वतन्त्र हो चुका है, अतः सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 'अफ्रीकी व्यक्तित्व' की कल्पना को साकार करना है। किन्तु इस लक्ष्य की पूर्ति सुगम नहीं है क्योंकि अफ्रीका के देश प्रायसी फूट के शिकार हैं। इस महाद्वीप में विभिन्न भाषाओं, सस्कृतियों, परम्पराओं और धार्मिक विचारों का पोषण होता है। अफ्रीका के देशों में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, शिक्षा की दृष्टि से अधिकांश देश काफी पिछड़े हुए हैं, एवं अधिकांश अफ्रीकी राज्यों के नेता उग्र तथा अस्थिर प्रकृति के हैं।

अरब लीग

अरब लीग अरबों की राष्ट्रीय जागृति की प्रतीक है। इसकी स्थापना सन् 1945 में मिस्र, जोर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, ईराक और यमन के बीच एक सम्झौते के फलस्वरूप हुई। बाद में लीबिया, सूडान, मोरक्को आदि अनेक अरब देश इसमें सम्मिलित हो गए। लीग का मुख्य उद्देश्य अरब-देशों में एकता और सहयोग का प्रसार करना है, लेकिन अरबों की प्रायसी फूट के कारण अभी तक इस दिशा में उत्साहजनक प्रगति नहीं हो सकी है।

विश्व-राजनीति में तेल-उत्पादक अरब-देशों का महत्त्व बढ़ने के साथ-साथ उसके एकमात्र राजनीतिक संगठन के रूप में अरब लीग का महत्त्व भी काफी बढ़ गया है। अक्टूबर, 1974 में अरब लीग के सम्मेलन में अरब देशों के राष्ट्रपतियों की स्वागत में बैठक हुई जिसमें फिलिस्तीन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को फिलिस्तीनियों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई।

कंपाला सम्मेलन, जुलाई-अगस्त, 1975

अफ्रीकी एकता संगठन का 12वाँ सम्मेलन 28 जुलाई से 1 अगस्त, 1975 तक युगाण्डा की राजधानी कंपाला में हुआ। जैसा पहले से ही संकेत मिल गया था, यह सम्मेलन अफ्रीकी एकता के बीच विद्यमान दरारों को व्यक्त करने वाला सिद्ध हुआ। संगठन के सदस्य-देशों की संख्या 45 है जबकि उसमें युगाण्डा सहित

20 देशों ने ही भाग लिया। अफ्रीकी एकता के दृढ़ रतम्भ तांजानिया के राष्ट्रपति जुलियस न्येरेरे, जाम्बिया के जेनेथ काउंडा, [नदस्वाधीन मोजाम्बिक के राष्ट्रपति समोरा माबेल और बोत्स्वाना के प्रधानमंत्री सर सेरेत्से खामा जैसे महत्त्वपूर्ण नेता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। सम्मेलन का बहिष्कार करने के पीछे तांजानिया का प्रबल तर्क यह था कि चूंकि सम्मेलन युगाण्डा में हो रहा है, अतः उसमें भाग लेने का अर्थ होगा कि सन् 1971 में सत्ता हथियाने के बाद राष्ट्रपति ईदी अमीन ने हजारों अफ्रीकियों की जो हत्या की, संगठन के सदस्य उसका समर्थन करते हैं। इस आरोप में बचन था और सम्भवतः इसीलिए संगठन के अधिपत्यक सदस्य सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए।¹

काफ़ी विवाद के बाद युगाण्डा के राष्ट्रपति ईदी अमीन सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार उनकी महत्वाकांक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन अफ्रीकी एकता संगठन को इससे भारी ठेस पहुँची। इजरायल के विरोध के सम्बन्ध में भी संगठन में एकता नहीं हो पायी। मिश्र ने प्रस्ताव किया कि जब तक इजरायल अरब भूमि खाली नहीं करता तब तक के लिए उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से 'वंचित' कर दिया जाना चाहिए। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे ने अपने प्रस्ताव में माँग की कि इजरायल को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से तुरन्त अलग कर दिया जाए। सम्मेलन ने दोनों ही प्रस्तावों पर विचार किया और सदस्य-देशों में काफ़ी मतभेद उभर कर सामने आया। अन्त में मिश्र के प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए इस प्रस्ताव का प्रस्ताव पारित किया गया कि इजरायल पर दबाव बढ़ाना चाहिए और यदि वह अरब भूमि वापस न करे तो अन्ततः उसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है। फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे को बड़ा क्षोभ हुआ और उसके नेताओं ने सम्मेलन समाप्त होने के बाद मिश्र पर आरोप लगाया कि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का मिश्र ने 'असम्मानजनक बचाव' किया है और 'मुट्टी भर सिनाय के बदले इजरायल का पक्ष लिया है।

सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया के प्रश्न पर भी विचार किया गया और कहा गया कि जब तक वहाँ वहुमत का शासन स्थापित न हो जाए तब तक अफ्रीकी एकता संगठन को वहाँ के राष्ट्रवादियों के स्वाधीनता सपने का समर्थन करते रहना चाहिए। अंगोला के गृहयुद्ध पर भी सम्मेलन में विचार किया गया और उसमें उलझे हुए विभिन्न पक्षों से तुरन्त युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया।

इस बार सम्मेलन में विघ्न पड़ा। सम्मेलन के दूसरे दिन ही नाइजीरिया में रक्तहीन सैनिक क्रांति हो गई जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति गोवोन को सत्ताव्युत होना पड़ा। इससे न केवल राष्ट्रपति गोवोन ने सम्मेलन में आने भाग लेना बंद कर दिया बल्कि 5 अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी अगले दिन (30 जुलाई) अपने-अपने देश को लौट गए। ये ये राष्ट्रपति अब्दुल अहिदजो (कंपहन), अनवर सादात (मिश्र) सेयनी बूचे (नाइजर), उमर बोगो (गैबोन) और गारियेन ग्योमानी (कांगो)।

सम्मेलन में संगठन सम्बन्धी कई प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं हो सका। अफ्रीका के विभिन्न भागों में चालू मुक्ति सघर्षों के संचालन के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के बारे में सम्मेलन में विचार किया गया लेकिन सर्वेसमय न होने के कारण सम्मेलन अपनी मुक्ति-समिति को आगामी फरवरी में अदिस-अबाबा में होने वाले सम्मेलन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देकर समाप्त हो गया।¹

अदिस-अबाबा का विशेष सम्मेलन (जनवरी, 1976)

ग्रीर अंगोला का गृहयुद्ध

11 नवम्बर, 1975 को पुर्तगाली साम्राज्यवाद से मुक्ति पाते ही अंगोला में पहले से ही प्रारम्भ गृहयुद्ध में तीव्रता आ गई और कुछ ही घंटों में तीनो प्रमुख दलों—‘अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन’ (एम. पी. एल. ए.), अंगोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (एफ. एन. एल. ए.) और अंगोला पूर्व स्वाधीनता सघ (यूनीटा) ने अंगोला के विभिन्न भागों में अपनी स्वतन्त्र सरकारों की घोषणा कर दी।² अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन ने सम्पूर्ण अंगोला पर अपनी प्रभुसत्ता घोषित करते हुए अपने अध्यक्ष अगस्टीनो नेतो का देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। देश के आन्तरिक क्षेत्रों में नोवो लिसबुआ में दूसरे राजनीतिक दल अंगोला पूर्ण स्वाधीनता सघ (यूनीटा) ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और शहर का नाम कुम्बांघो रख दिया। इसके जवाब में तीसरे राजनीतिक दल ‘अंगोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे’ (एफ. एन. एल. ए.) ने अंगोला के ‘लोकप्रिय प्रजातान्त्रिक गणराज्य’ की घोषणा कर दी।

इन तीनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सरकारों की घोषणा करने के बाद एक दूसरे पर आक्रमण-प्रत्याक्रमण शुरू कर दिए। लेकिन अनेक अफ्रीकी देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों और सोवियत सघ से मान्यता प्राप्त होने तथा सैनिक और अन्य सहायता मिलने के कारण अंगोला की राजधानी लुआंडा स्थित अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन की सरकार का पलड़ा अन्य दोनों दलों की सरकारों से भारी हो गया। राजधानी में अगस्टीनो नेतो की सरकार को उन सभी अफ्रीकी देशों ने मान्यता दे दी जो कभी पुर्तगाली शासन में थे।

अंगोला के गृहयुद्ध में महाशक्तियों का हस्तक्षेप चिन्ताजनक बात थी। अमेरिका ने अंगोला पर दूसरी सरकार का आधिपत्य स्थापित होने का हौवा खड़ा कर अंगोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सरकार को सैनिक सहायता देना शुरू कर दिया और इस-विरोधी होने के कारण चीन ने भी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सरकार का समर्थन करते हुए उसे सैनिक सहायता प्रदान की। इस तरह स्वतन्त्रता प्राप्त करते ही अंगोला महाशक्तियों की स्वार्थ-नीति और गृहयुद्ध का शिकार हो गया।

गृहयुद्ध को रोकने और अंगोला में पुनः एकता स्थापित करने के लिए

1. द हिन्दुस्तान टाइम्स, 3 अगस्त, 1975, पृष्ठ 1.

2. दिनमान, 23 नवम्बर, 1975, पृष्ठ 31.

अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा 10 जनवरी, 1976 को इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में एक विशेष शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन उसमें अन्तिम रूप से समस्या का ऐसा कोई समाधान नहीं ढूँढा जा सका जो सभी पक्षों को मान्य होता। 46 अफ्रीकी राष्ट्रों के इस संगठन की बैठक में अनेक राजाध्यक्षों तथा प्रधान मन्त्रियों ने भाग लिया। इसके अलावा अंगोला के तीनों मुक्ति संगठनों के प्रतिनिधि भी बैठक में मौजूद थे। वैसे तो इस अभूतपूर्व बैठक का प्रमुख उद्देश्य गृहयुद्ध और विदेशी हस्तक्षेप से जस्त अंगोला में शान्ति स्थापित करने के उपाय ढूँढना था, किन्तु इसके साथ एक महत्वपूर्ण समस्या यह भी थी कि अफ्रीकी एकता संगठन अंगोला में विभिन्न मुक्ति आन्दोलनों द्वारा स्थापित सरकारों में से किस सरकार को मान्यता दे। 46 में से 22 देश अगस्टीनो नेतृ की सरकार (लुपींडा स्थित अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन की सरकार) को मान्यता दे चुके थे और चाहते थे कि अगस्टीनो के नेतृत्व में चल रहे एकता और शान्ति-प्रभियान को हर सम्भव सहायता दी जाए। इसके विपरीत अन्य 22 राजाध्यक्षों का मत था कि तुरन्त युद्ध-विराम के माध्यम से तीनों दलों की सभी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त एक राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापित की जाए। छेप दो देशों इथियोपिया और युगाण्डा ने अधिकृत रूप से अपनी कोई राय जाहिर नहीं की।¹ राजाध्यक्षों में विद्यमान बुनियादी मन-भेदों के कारण किसी तरह का निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो सका, क्योंकि निर्णय होने की हालत में अफ्रीकी एकता संगठन के विघटन का खतरा था। अतः सम्मेलन में इस समस्या पर छह महीने बाद पुनः विचार करने का निश्चय किया गया। प्रतिनिधियों का विचार था कि तब तक स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी और तब उस पर निर्णय लेना आसान होगा।

पश्चिम अफ्रीकी और अन्य देशों से मान्यता प्राप्त तथा सोवियत समर्थन और सहायता से लंबे अंगोला जनमुक्ति आन्दोलन की सरकार की स्थिति निरन्तर सुदृढ़ होती गई और अंगोला राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की सरकार जिसे अमेरिका और चीन का समर्थन प्राप्त था, पराजय के कगार पर पहुँच गई। फरवरी, 1976 में युगाण्डा में जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन राष्ट्रपति अगस्टीनो नेते ने किया। उन्होंने घोषणा की कि हमारा मथ्यें तब तक चलता रहेगा जब तक अंगोला पूर्णतया स्वतन्त्र और एक नहीं हो जाता।

एशियन शिखर सम्मेलन (फरवरी, 1976)

इण्डोनेशिया के बाली द्वीप में पिछले दिनों (23-24 फरवरी) दक्षिण पूर्व-एशियाई राष्ट्रों के मध्य (एशियन) का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। यह शिखर सम्मेलन आठ वर्ष में पहली बार हुआ था। इसका उद्घाटन इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने किया। पाँच देशों—इण्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलिपीन में यद्यपि कई तरह के विवाद विद्यमान थे और उन्हें सम्मेलन में

भी उठाया गया लेकिन बातचीत मंत्री और सहयोगपूर्ण वातावरण में हुई। कई प्रकार के अभाव अभियोग लगाए गए, लेकिन अन्ततः पाँच देशों में इस बात पर सहमति हो गई कि 'भूली ताँहि बिसार दे आगे की सुधि ले' के आधार पर भावी सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाना चाहिए।¹ उल्लेखनीय है कि एशियान का गठन नौ साल पहले हुआ था। इस नौ साल में इन देशों के सम्मेलन तो होते रहे लेकिन सहमति का अवसर शायद ही कभी आया हो।

अवसर यह सुनने में आता था कि पाँच देशों का यह 'एशियान' यूरोप के नौ देशों के यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे साभा बाजार ही कहते हैं, के अनुरूप समान मण्डी के गठन के लिए प्रयास करेगा। सम्मेलन में इस मुद्दे पर बहस जरूर हुई लेकिन अपने भाषण में राष्ट्रपति सुहर्त ने इस बात पर जोर दिया कि हमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि हमारा उद्देश्य सैनिक गुट की स्थापना नहीं है (इशारा शायद नाटो और वारसा की ओर था) किन्तु हम लोग यह जरूर चाहते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखण्डता कायम रहे ताकि हम लोग किसी भी तरह के आर्थिक खतरे का सामना शान्तिपूर्वक और दृढ़ता के साथ कर सकें। विघटन नाम युद्ध समाप्त होने के बाद जिस तरह के नए राजनीतिक समीकरण दक्षिण पूर्वी एशिया में बने थे उनके प्रति भी सचेत रहने पर जोर दिया गया।²

इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि एक संयुक्त सन्धि थी जिसका उद्देश्य परस्पर सहयोग और मंत्री को बढ़ावा देना था। आर्थिक क्षेत्रों में दो कार्यक्रम स्वीकार किए गए—पेट्रो-रसायन, इस्पात, रबड़, पोटैश और टिन प्लेट में बड़े पैमाने पर संयुक्त औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना और व्यापार में एशियान देशों को प्राथमिकता देना। हालाँकि साभा बाजारनुमा मण्डी के गठन की बात अवश्य उठी, लेकिन नेताओं ने महसूस किया कि यह रूप धीरे-धीरे देना चाहिए।³

मंत्री और सहयोग के जिस समझौते पर एशियान के पाँच नेताओं ने हस्ताक्षर किए उसमें बीस अनुच्छेद हैं। पहले अनुच्छेद में कहा गया गया है कि हमें निरन्तर शान्ति, सहयोग और मंत्री का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए ताकि हमारे देश के लोगों में अखण्डता, एकता और परस्पर प्रेम की भावना बलवती रहे। हम लोगों को एक दूसरे की स्वाधीनता, अनुसूता, क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करना चाहिए। हर देश को अपनी आन्तरिक स्थिति और आन्तरिक समस्याओं से निपटने का अधिकार है और दूसरे देशों को उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अपितु किसी भी बाह्य जोर जबरदस्ती की घटना की निन्दा करनी चाहिए और आपस में प्रभावकारी सहयोग कायम रखना चाहिए।⁴

1. दिनमान, 14-20 मार्च, 1976, पृष्ठ 38.

2-4. वही, पृष्ठ 38.

एशियान सम्मेलन : अगस्त, 1977¹

अगस्त, 1977 में ब्वालालम्पुर में एशियान देशों का शिखर सम्मेलन हिन्द-चीन देशों के साथ और अधिक सद्भाव तथा सहयोग बढ़ाने की अपील के साथ समाप्त हुआ। सम्मेलन में दक्षिणपूर्व एशियाई देशों की हालाँकि बटु आलोचना की गई, तथापि अन्ततः एशियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के साथ अधिकारधिक सहयोग समूचे एशियाई क्षेत्र के हित में है। इंडोनेशिया और फिलिपीन के राष्ट्रपतियों तथा मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के प्रधानमन्त्रियों के हस्ताक्षर से दो दिन के सम्मेलन की समाप्ति के बाद समुक्त विज्ञप्ति प्रसारित की गई जिसमें कहा गया कि पारस्परिक हितों की रक्षा तथा शान्ति के लिए एशियान क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बहुत आवश्यक है।

सम्मेलन में भाग लेने वाले पाँच देशों ने अपना संकल्प दोहराया कि हम समूचे दक्षिणपूर्व एशिया को शान्ति, स्वतन्त्रता और स्थिरता का एक क्षेत्र बनाएँगे। एशियान देशों ने सन् 1971 में यह प्रतिज्ञा की थी। एशियान की बड़े राष्ट्री में केवल अमेरिका का ही समर्थन प्राप्त है। सोवियत संघ का विचार है कि एशियान गुट अमेरिका के सहयोग से एक सैनिक गुट बन जाएगा। शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले सोवियत संघ के एक प्रमुख समाचार ने एशियान सम्मेलन के आयोजन की कड़ी आलोचना की थी। उधर चीन के समाचार-पत्रों में इस सम्मेलन के समाचार तो छपे लेकिन चीनी समाचार-पत्रों ने सम्मेलन पर कोई टिप्पणी नहीं की।

एशियान के पाँच देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस प्रश्न पर थाईलैंड और फिलिपीन के समर्थन से सिंगापुर ने सुझाव रखा था कि व्यापार में रियायतें देने की एक योजना के सम्बन्ध में पाँचों देशों का एक आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में समुक्त विज्ञप्ति में केवल इतना ही उल्लेख किया गया कि योजना पर अगले वर्ष पहली जनवरी तक कोई निर्णय लिया जाएगा। स्पष्ट है आर्थिक सहयोग के बारे में सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका।

समुक्त विज्ञप्ति में संकेत दिया गया कि एशियान के नेता ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमन्त्रियों से निकट भविष्य में जब भेंट करेंगे तो इसी बात पर जोर देंगे कि एशियान के देशों के तैयार और अर्द्धतैयार माल की खपत ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड में अधिकाधिक होनी चाहिए। यह अनुरोध भी किया जाएगा कि एशियान देशों की निर्यात आय को स्थिर बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। यही भाग एशियान देश अन्य विकसित देशों से करने वाले हैं। इस सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भी सन् 1977 के शुरू में परामर्श हुआ था।

आर्थिक स्थिति के संदर्भ में सम्मेलन में इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई कि विकासशील देशों में सरक्षण प्राप्त करने की भावना बढ रही है, जो इन देशों के लोगों के लिए हितकर नहीं है। विकासशील देशों से अनुरोध किया गया कि वे सरक्षण प्राप्त करने की भावना का जल्दी से जल्दी त्याग करें और आत्मनिर्भरता के अपने प्रयत्न जारी रखें।

शिखर सम्मेलन से पहले क्वालालम्पुर में ही एशियान के विदेशमन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें दक्षिणपूर्व और दक्षिणपश्चिम एशिया के देशों से स्वतन्त्रता और तटस्थता का क्षेत्र बनाने का अनुरोध किया गया। मिलजुल कर काम करने के अपने दृढ़ निश्चय को दोहराते हुए पाँचों देशों के विदेशमन्त्रियों ने आशा व्यक्त की कि तटस्थता और स्वतन्त्रता का क्षेत्र स्थापित करने के कार्य में एशिया के सभी देश अपना योगदान करेंगे। विदेशमन्त्रियों का यह सम्मेलन शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए हुआ था।

दो दिन के शिखर सम्मेलन के पहले दिन फिलिपीन के राष्ट्रपति श्री फार्दिनाद मारकोस की इस घोषणा से काफी सद्भावनापूर्ण वातावरण बना कि मलेशिया के पूर्व स्थित सबाह पर वह अपने अधिकार का दावा छोड़ रहे हैं। फिलिपीन यह मामला संयुक्त राष्ट्र तक ले गया था जिसके कारण फिलिपीन और मलेशिया के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सबाह ने अलग रहने के लिए पृथक्तावादी आन्दोलन भी संचालित किया था। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शासनाध्यक्षों के भाषणों से स्पष्ट पता चल रहा था कि पाँचों देशों में राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर अभी भी मतभेद है। शायद इसीलिए पाँचों देशों में आर्थिक क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर कोई सहमति नहीं हो सकी। लेकिन मलेशिया के प्रधानमन्त्री दातुक हुसेन ने यही दावा किया कि पाँचों देशों में पिछले 10 वर्षों से चली आ रही गुटबन्दी समाप्त हो गई है और अब वे एक समूह के रूप में उभर कर सामने आए हैं। थाईलैंड के प्रधानमन्त्री डॉक्टर थानिया क्रविसेन ने विरोधी रवैया अपनाने के लिए वियतनाम की कटु आलोचना की। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि वियतनाम एशियान देशों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र के देशों से वह अलग-अलग समझौते करना चाहता है। एशियान के प्रति वियतनाम का विरोध सर्वविदित है। फिलिपीन के राष्ट्रपति मारकोस का स्वर कुछ भिन्न था। वह वियतनाम के प्रति शान्तिपूर्ण रवैया अपना रहे थे। उनका कहना था हमें अपने व्यवहार से एशियान के प्रति वियतनाम की सभी आशकाएँ दूर कर देनी चाहिए।

आर्थिक प्रश्नों पर मिंगापुर के प्रधानमन्त्री श्री ली क्वान यू ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पाँचों देशों के वित्तमन्त्री आर्थिक समस्याओं पर मतभेद दूर करने में असफल रहे हैं। एशियान के पाँचों देशों ने फरवरी, 1976 की अपनी बैठक में जिस संयुक्त औद्योगिक योजना पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था वह अब तक लागू नहीं किया जा सका। उनका यह भी कहना था कि

“पाँचों देशों के बीच व्यापार में रियायतें देने की योजना कुछ वस्तुओं तक सीमित है। इस मामले में भी हम आगे नहीं बढ़ सके।”

एशियान देश पिछले काफी समय से जापान, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाजारों में अपनी वस्तुओं की सपत की माँग करते रहे हैं। जापान की मण्डियों में ये देश अपने माल की अधिकाधिक सपत चाहते हैं क्योंकि एशियान देशों से कच्चा माल सबसे अधिक जापान को ही निर्यात होता है। इसके अतिरिक्त एशियान देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय से भी व्यापार सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करने को उत्सुक है।

आर्थिक प्रश्नों के अलावा एशियान देशों की कुछ राजनीतिक समस्याएँ भी हैं। वियतनाम से हटने के बाद अमेरिका की एशियान देशों में रुचि बढ़ना स्वाभाविक है। राष्ट्रपति कार्टर दक्षिण कोरिया से अपनी सेनाएँ हटाकर एशियान देशों के प्रति अपने रवैये का प्रमाण पहले ही दे चुके हैं। एशियान देशों में जापान की दिलचस्पी भी काफी बढ़ी है, पर यह स्पष्ट है कि एशियान देश अपने यहाँ किसी भी बड़े देश की सैनिक उपस्थिति नहीं चाहते। सम्मेलन से कुछ दिनों पूर्व ही फिलिपीन के राष्ट्रपति मारकोम ने कहा था कि जापान को एशियान देशों के साथ सहयोग के बारे में युद्ध से पहले जैसी स्थिति की बात नहीं सोचनी चाहिए। चाहे जो भी हो एशियान देशों के इस शिखर सम्मेलन से हिन्द-चीन के क्षेत्र में सहयोग और सद्भाव का एक नया युग शुरू हो सकता है। इण्डोनेशिया के विदेशमन्त्री श्री आदम मलिक ने कहा था कि एशियान सीटों की तरह का कोई सैनिक संगठन नहीं है यह तो इस क्षेत्र के देशों में एकता और सहयोग वृद्धि का एक माध्यम है। थाईलैंड चाहता है कि एशियान देश इस क्षेत्र में कम्युनिज्म का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएँ, लेकिन सभ्यतः अन्य देश इस विचार को अधिक पसन्द नहीं करते।

अन्य सम्मेलन

अफ्रिकियाई जागरण और एकता को सुदृढ़ करने वाले अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन थे—वेलेग्रेड सम्मेलन (1961), काहिरा सम्मेलन (1964), नई दिल्ली सम्मेलन (1966), लुमाबा सम्मेलन (1970), जार्ज टाउन सम्मेलन (1972), ग्रहजीरिया सम्मेलन (1973), अल्जीरिया सम्मेलन (1974), हवाना सम्मेलन (1975), कोलम्बो सम्मेलन (1976)। ये सभी सम्मेलन गुट-निरपेक्षता के समर्थक थे और इतना विस्तृत विवेचन गुट-निरपेक्षता सम्बन्धी अध्यापन में किया जा चुका है।

अफ्रिकियाई एकता को हानि पहुँचाने वाले कुछ सम्मेलन

एशिया और अफ्रीका के कुछ ऐसे सम्मेलन भी हुए हैं जिनमें अफ्रिकियाई एकता को लाभ पहुँचाने की अपेक्षा हानि अधिक हुई है और आपसी फूट को प्रोत्साहन मिला है। इन सम्मेलनों पर भी एक दृष्टि डालना उपयुक्त होगा—

जुद्धा सम्मेलन, 1972

मार्च, 1972 में 31 एशियाई विदेश इस्लामी मन्त्रियों का यह पाँच दिवसीय सम्मेलन सऊदी अरब की राजधानी जद्दा में हुआ। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध

विषय बमन किया लेकिन उसे निराश होना पड़ा। पाकिस्तान ने मांग की कि सम्मेलन की विज्ञप्ति में बंगलादेश का उल्लेख न कर 'एक पाकिस्तान' की बात कही जाए, लेकिन सऊदी अरब के शूह फैज़ल (जिन्की मार्च, 1975 में हत्या कर दी गई) ने स्पष्ट कह दिया कि बंगलादेश एक 'वास्तविकता' है और इसके सन्दर्भ में ही बात की जानी चाहिए। सम्मेलन में बंगलादेश को मान्यता देने की बात भी उठी, किन्तु लीबिया, जोर्डन, इण्डोनेशिया और मलेशिया इसके पक्ष में नहीं थे। वास्तव में यह एक खेदजनक बात थी कि इस्लामी सम्मेलन में बंगलादेश के मुसलमानों के हितों की उपेक्षा की गई। इस्लामी देशों ने बंगलादेश के अपने ही जाति-भाइयों को 'काफिर' समझा और पाकिस्तान के अत्याचारों पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत-रूसी मैत्री पर भी पाकिस्तानी प्रतिनिधि तथा कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया।

इस्लामी सम्मेलन का एक उद्देश्य एक नए गुट का निर्माण भी था ताकि समय-समय पर इस गुट के सदस्य मिलकर आपसी हितों पर विचार कर सकें। सम्मेलन में इस बात को मुस्लिम हितों के विरुद्ध समझा गया कि मुस्लिम जगत् में यहूदियों और साम्यवादियों का प्रवेश हो। सम्मेलन में यमन और ईराक शामिल नहीं हुए।

कुल मिलाकर यह सम्मेलन एशियायी एकता में दरारें डालने वाला सिद्ध हुआ। स्वयं मुस्लिम देशों के हितों की भी सम्मेलन की कार्यवाही से हानि अधिक पहुँची, लाभ कम हुआ।

इस्लामी शिखर सम्मेलन, 1974

पाकिस्तान में एक इस्लामी शिखर सम्मेलन 22 फरवरी से 24 फरवरी, 1974 तक लाहौर में हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अध्यक्षता की। सम्मेलन में 36 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि-मण्डल सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन को यद्यपि 'अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी राज्य सम्मेलन' की सजा दी गई तथापि न तो इसका स्वरूप ही अन्तर्राष्ट्रीय था और न इसमें शामिल होने वाले सभी राज्य इस्लामी थे। टर्की, इण्डोनेशिया आदि देशों को भी इसमें आमन्त्रित किया गया था जिन्होंने स्वयं को विधिवत् इस्लामी राज्य घोषित नहीं किया है। यदि सम्मेलन का उद्देश्य धार्मिक था तो भारत सहित उन देशों को आमन्त्रित क्यों नहीं किया गया जहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में अनेक राज्यों में मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं, किन्तु लाहौर के इस सम्मेलन में केवल 13 अफ्रीकी देश ही शामिल हुए थे। इस प्रकार यह सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप के भी सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था।

वास्तव में लाहौर के इस्लामी सम्मेलन का स्वरूप राजनीतिक ही अधिक था। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि सम्मेलन में भारत के सात करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो। उसे भय था कि ऐसा होने पर इस्लामी राज्यों का मुखिया बनने का उसका स्वप्न पूरा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान का दृष्टिकोण ऐसा था मानो मुस्लिम देशों का अस्तित्व पाकिस्तान के अस्तित्व के साथ जुड़ा हो।

सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए और सुभाव दिए गए, वे संकेत रूप में इस प्रकार थे—(i) दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए—एक में यरूशलेम से इजरायली सैनिकों की तुरन्त वापसी की माँग की गई, दूसरे में कहा गया कि इस्लामी देश मिस्र, सीरिया तथा जोर्डन के फिलिस्तीनियों को बंध स्थान दिलाने का प्रयास कर इजरायल द्वारा हथियाए गए लोगों की वापसी के लिए पूरी सहायता करें। (ii) पश्चिमी एशिया तथा तेल प्रावि विषयों पर भी प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मिस्र के राष्ट्रपति अन्वर सादात और अल्जीरिया के राष्ट्रपति वुमैदीएन का यह सुभाव महत्वपूर्ण था कि इस्लामी सम्मेलन की तेल-विहीन विकासशील देशों के लिए सहायता की रकम निर्धारित कर देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि तेल के वर्तमान भावों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। (iii) लीबिया के राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी ने एक तीन स्तरीय पद्धति का सुभाव दिया—प्रौद्योगिक राष्ट्र वर्तमान भावों से तेल खरीदें, जबकि तीसरी दुनिया और इस्लामी देशों को उनके आकार और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रियायती दाय पर तेल दिया जाए। (iv) उगाण्डा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने सुभाव दिया कि ईराक और ईरान में सामान्य सम्बन्ध कायम करने के लिए इस्लामी देशों का एक सद्भावना आयोग दोनों देशों को भेजा जाए। (v) ईदी अमीन ने मुस्लिम देशों से यह भी अनुरोध किया कि वे इजरायल, रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका के विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की आज्ञा न दें।

लाहौर के इस्लामी शिखर-सम्मेलन से तीन बातें भली प्रकार स्पष्ट हो गईं—

(1) पाकिस्तान का भारत-विरोधी रवैया और भारतीय मुसलमानों को 'काफिर' समझना, (2) मुस्लिम देशों की आपसी फूट और एशिया तथा अफ्रीका के अनेक मुस्लिम देशों का इस्लामी सम्मेलन में भाग न लेना, एवं (3) अनेक राष्ट्रीय आचरण जो अफ्रीकियों के एकता में फूट डालने वाला था।

अल्जीरिया का स्वाधीनता संग्राम

अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया ने फ्रांस के विरुद्ध जो लम्बा स्वाधीनता संग्राम किया वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि—(1) अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद का सबसे निरंकुश और दर्दनाक पहलू अल्जीरिया में देखने को मिला, (2) अल्जीरिया का संघर्ष दुनिया के अन्य देशों के स्वाधीनता-संग्रामों के लिए एक उदाहरण बन गया, एवं (3) इस संग्राम ने पुनः इस बात की पुष्टि कर दी कि श्वेत जातियों से टक्कर लेकर उन्हें नाकाम चने चबाए जा सकते हैं।

अल्जीरिया पर फ्रांस का अधिकार सन् 1830 में स्थापित हुआ था। फ्रांसिसियों ने यहाँ बसकर अल्जीरिया का हर प्रकार से शोषण किया। अल्जीरिया-वासियों के प्रत्येक विरोध का फ्रांस सदैव कठोरतापूर्वक दमन करता रहा। उन्हें

शान्त करने के लिए कालान्तर में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार भी प्रदान किया गया, लेकिन अल्जीरियावासी सन्तुष्ट नहीं हुए। 1 जुलाई, 1951 को उन्होंने एक राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया जो 'राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चा' (Front of National Liberation—F. N. L.) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोर्चे ने 1 नवम्बर, 1954 को स्वाधीनता सघर्ष आरम्भ किया जो लगभग सात वर्ष तक चला। इस युद्ध में लगभग 4,00,000 व्यक्तियों की जानें गईं। इनमें से लगभग 2,00,000 अर्सेनिक अल्जीरियाई मुसलमान, 1,60,000 स्वतन्त्र अल्जीरियाई सरकार के सैनिक, 18,000 फ्रांसीसी सैनिक तथा 2,000 गोरे अल्जीरियाई निवासी थे। अल्जीरियाई राष्ट्रवादी इस सत्त्वा को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि फ्रांसीसी सेनाओं ने कम से कम दस लाख अल्जीरियाइयों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध-बन्दी के जो भी प्रयास हुए, व्यर्थ गए। फ्रांस के दुराग्रह के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी युद्ध-विराम के लिए कुछ नहीं किया जा सका। जून, 1958 में जनरल डिगॉल बिस्तृत अधिकारों सहित फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति बने। उन्होंने फ्रांस की जनता को यह वचन दिया कि वे अल्जीरिया की समस्या को शीघ्र निपटा देंगे।

सितम्बर, 1959 में फरहत अब्बास के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चे ने काहिरा में एक ममानान्तर सरकार की स्थापना की जिसे चीन द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई। परिस्थितियों से बाध्य होकर 4 नवम्बर, 1960 को जनरल डिगॉल ने अल्जीरिया को स्वतन्त्रता देने की घोषणा की। उन्होंने 'अल्जीरिया, अल्जीरियावालों के लिए' के प्रश्न पर जनमत कराने का प्रस्ताव रखा, किन्तु फरहत अब्बास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा कर अपने अनुयायियों को मतदान में भाग न लेने का आदेश दिया। फिर भी 8 जनवरी, 1961 को जनमत-संग्रह हुआ और फ्रांस तथा अल्जीरिया दोनों में विशाल बहुमत ने डिगॉल की अल्जीरिया सम्बन्धी नीति का समर्थन किया गया। 27 मार्च, 1961 को फ्रांस और अल्जीरिया द्वारा शान्ति-वार्ता में भाग लेने की सहमति की घोषणा की गई, किन्तु अगले ही माह अप्रैल, 1961 में इस आगामी शान्ति-वार्ता के विरुद्ध जनरल सालाँ और अन्य जनरलों के नेतृत्व में फ्रेंच सैनिकों ने अल्जीरिया में विद्रोह कर दिया। डिगॉल ने विद्रोहियों के खिलाफ तेजी से कठोर कार्यवाही की। जनरल सालाँ पलायन कर गया और उसने एक गुप्त सेना (OAS) की स्थापना कर ली।

20 मई, 1961 को फ्रांस और अल्जीरिया में शान्ति-वार्ता आरम्भ हुई और तुरन्त ही भग भो हो गई। शान्ति-वार्ता की आँख मिचोनी चलती रही। जनवरी, 1962 में ओ. ए. एस. आतंकवादियों ने अल्जीरिया भर में मुसलमानों पर आक्रमण किया, मुसलमानों ने भी जवाबी हमले किए और दोनों पक्षों के मैकडो व्यक्ति मारे गए। फरवरी, 1962 में शान्ति-वार्ता में प्रगति हुई और अन्त में 18 मार्च, 1962 को युद्ध-बन्दी के बाद दोनों पक्षों (अल्जीरिया और फ्रांस) के बीच समझौते की घोषणा की गई। 1 जुलाई, 1962 को अल्जीरिया स्वतन्त्र हो गया और इस तरह एक महान् स्वतन्त्रता संग्राम का अन्त हुआ। 20 सितम्बर, 1962 को अल्जीरिया

के एक दलीय चुनावों में बेनवेला गुट की विजय हुई। विरोधी गुट बेनवेला का था। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि गृह-युद्ध की धासका होने लगी, लेकिन अन्त में दोनों नेताओं में समझौता हो गया।

दक्षिण रोडेशिया का संकट

जम्बेजी नदी तथा उत्तरी ट्रांसवाल के मध्य स्थित दक्षिण रोडेशिया अफ्रीका का एक देश है। इस देश का क्षेत्रफल 390 हजार वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 60 लाख है। इसमें 40 लाख से अधिक अफ्रीकी हैं, लगभग 2 लाख यूरोपीय हैं और शेष अन्य। दक्षिणी रोडेशिया का, जिसकी राजधानी सेलिसबरी है, मूल विवाद यह है कि यहाँ की गोरी सरकार बहुसंख्यक अफ्रीकियों को देश के शासन में सांभोदार नहीं बनाना चाहती और राष्ट्रवादी अफ्रीकी इस बात के लिए निरन्तर सघर्ष कर रहे हैं कि दक्षिण रोडेशिया का शासन अफ्रीकियों के हाथ में हो तथा गोरी की प्रभुसत्ता का अन्त हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—सन् 1953 में ब्रिटेन ने उत्तरी रोडेशिया (जिसका शासन उसने सन् 1924 में अपने हाथ में लिया था) दक्षिणी रोडेशिया और न्यासालैण्ड (रोडेशिया का पड़ोसी देश जिस पर ब्रिटेन ने सन् 1891 में अधिकार किया था) को मिला कर 'मध्य अफ्रीका सघ' (Central African Federation) की स्थापना की। उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैण्ड की जनता ने सघ का विरोध किया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इस सघ में अफ्रीकी लोगों की बहुलता थी, लेकिन निर्वाचन-योग्यता इस प्रकार की थी कोई अफ्रीकी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता था। अन्त अफ्रीकियों में असन्तोष बढ़ता गया और धीरे-धीरे राष्ट्रवाद की लहर इतनी प्रबल हो गई कि ब्रिटेन अधिक समय तक जनता की उपेक्षा नहीं कर सका तथा सन् 1963 में अफ्रीका सघ भंग हो गया। न्यासालैण्ड और उत्तरी रोडेशिया स्वतन्त्र हो गए। आजादी के बाद उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया कहलाने लगा और न्यासालैण्ड का नाम मलावी रखा गया। दक्षिणी रोडेशिया अब भी ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन रहा और इयान स्मिथ वहाँ के नए प्रधानमन्त्री बने।

दक्षिण रोडेशिया की गोरी सरकार द्वारा स्वतन्त्रता की एकपक्षीय घोषणा—प्रधानमन्त्री इयान स्मिथ ने ब्रिटेन को घमकी दी कि वह दक्षिणी रोडेशिया को स्वतन्त्र कर दे अन्यथा दक्षिण रोडेशिया की सरकार अपनी ओर से स्वतन्त्रता की घोषणा कर देगी। ब्रिटेन ने कहा कि स्वतन्त्रता तभी दी जा सकती है जब (1) सब अफ्रीकी लोगों को मताधिकार प्राप्त हो, एवं (2) गोरे लोगों के लिए सुरक्षित विशेष प्रदेशों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। स्मिथ सरकार ने ब्रिटिश शर्तों को अमान्य ठहरा कर 11 नवम्बर, 1965 को दक्षिण रोडेशिया की एरूपक्षीय स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी जिससे रोडेशिया सम्बन्धी महान् सांविधानिक संकट उत्पन्न हो गया। इयान स्मिथ ने कहा कि समुत्तराज्य अमेरिका के प्रारम्भिक तेरह उपनिवेश अठारहवीं शताब्दी में ब्रिटेन के अधीन थे और उन्होंने भी विद्रोह करके अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की थी। दक्षिण रोडेशिया भी उन्हीं का अनुसरण कर रहा

है। पर इयान स्मिथ यह भूल गए कि जहाँ अमेरिका में बहुसंख्यक-प्रल्पसंख्यक का कोई प्रश्न नहीं था वहाँ दक्षिणी रोडेेशिया का मुख्य प्रश्न ही यह था कि क्या प्रल्पसंख्यक गोरो को बहुसंख्यक अफ्रीकियों पर शासन करने का अधिकार है। अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में यही सन्देह व्यक्त किया गया कि यह सारा काण्ड ब्रिटेन की गुप्त सहानुभूति के कारण ही सम्भव हो सका था और इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए कोई सैनिक कार्यवाही नहीं की।

असफल शान्ति वार्ताएँ और संघर्ष का दौर (सन् 1965-नवम्बर 1977)—
दक्षिण रोडेेशिया की कार्यवाही के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश गवर्नर ने स्मिथ सरकार को पदच्युत कर दिया और ब्रिटेन ने दक्षिण रोडेेशिया से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध भंग कर दिए तथा आर्थिक प्रतिबन्ध भी लगाए। नवम्बर, 1965 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा स्मिथ सरकार के कार्य की निन्दा की गई और सदस्य-राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे उसे न तो मान्यता दें और न ही उसके साथ व्यापार करें। आर्थिक प्रतिबन्धों और कूटनीतिक उपायों का स्मिथ सरकार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजनीतिक क्षेत्रों में यह स्पष्ट विचार था कि ब्रिटेन की गुप्त सहानुभूति दक्षिण रोडेेशिया की गोरी सरकार के साथ है। नवम्बर, 1967 में महासभा ने शक्ति प्रयोग करने पर दल दिया, किन्तु ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं की। मई, 1968 में सुरक्षा परिषद ने दक्षिण रोडेेशिया के विरुद्ध पूर्ण आर्थिक नाकेबन्दी का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका क्योंकि गुप्त रूप से स्मिथ सरकार को सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त होती रही।

नवम्बर, 1969 में दक्षिण रोडेेशिया की संसद ने (जिस पर गोरो का प्रभाव छाया हुआ था) एक विधेयक पास कर इयान स्मिथ सरकार का गोरा शासन स्थायी बना देने की व्यवस्था कर दी। ब्रिटेन और स्मिथ सरकार के बीच बातचीत के अनेक दौर चले किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। वस्तुतः ब्रिटेन दक्षिण रोडेेशिया की गोरी सरकार के विरुद्ध कोई भी कठोर कदम उठाने को प्रस्तुत नहीं था और न सब भी है। नवम्बर, 1971 में ब्रिटिश विदेशमन्त्री डगलस ह्यूम और रोडेेशियायी प्रधानमन्त्री स्मिथ के बीच एक समझौता हुआ जिसके द्वारा अफ्रीकी जनता के हितों पर भारी कुठाराघात किया गया। इस समझौते से स्मिथ सरकार के दबने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अफ्रीकी बहुमत का शासन स्थापित करने का उल्लेख समझौते में किया गया, लेकिन इस बारे में कोई निश्चित तिथि निश्चित नहीं की गई। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार यह अवधि 30 से 50 वर्ष तक की हो सकती थी। और भी अनेक ऐसे निर्णय किए गए जो स्मिथ सरकार के पक्ष में थे। ब्रिटिश कम्पनियों को रोडेेशिया के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गई ताकि आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण पिछले वर्षों का घाटा पूरा हो सके। यह लज्जाजनक समझौता इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटेन किस प्रकार स्मिथ सरकार के हितों की रक्षा के लिए तत्पर था। समझौते पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी किसी भी बात की उपेक्षा कर दी गई। अवश्य ही इस सम्बन्ध में जनमत जानने

के लिए 'वियर्स आयोग' गठित किया गया। सम्भवतः यही प्राणा की गई थी कि वियर्स आयोग ऐसी रिपोर्ट देगा जो समझौते के लागू होने के पक्ष में होगी लेकिन जब 207 पृष्ठों की रिपोर्ट में यह कहा गया कि रोडेशिया के बहुसंख्यक अफ्रीकी समझौते प्रस्ताव से असहमत हैं और इसका समर्थन रोडेशिया के केवल लगभग दार्द सात गोरे लोगो ने ही किया है, तो मायता बिगड़ गया। इयान स्मिथ ने तुरन्त ही रेडियो-प्रसारण में वियर्स-रिपोर्ट को गैरकानूनी ठहरा दिया और घोषणा कर दी कि नवम्बर, 1971 के समझौते के आधार पर अब कोई बातचीत नहीं की जा सकती। इस प्रकार एक निष्पक्ष रिपोर्ट को ठुकरा दिया गया और ब्रिटेन की मिलीभगत से रोडेशिया पर स्मिथ का शासन बना रहा।

दक्षिणी रोडेशिया के अफ्रीकी राष्ट्रवादियों का असन्तोष बढ़ता गया और उग्रवादी तत्त्व सघर्ष के लिए उतावू हो गए। छापामार युद्ध शुरू हो गया। सन् 1974 के अन्त में स्मिथ सरकार अफ्रीकी राष्ट्रवादी छापामारों के साथ युद्ध-विराम करके बातचीत करने के लिए तैयार हुई। 11 दिसम्बर, 1974 को लुसाका में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार कुछ अश्वेन नेताओं को मुक्त किया गया। बातचीत में चार अफ्रीकी संगठनों ने भाग लिया—अफ्रीकी नेशनल कौंसिल (एक मात्र ऐसा संगठन जिसे स्मिथ सरकार ने गैरकानूनी नहीं माना था), जिवावे अफ्रीकी पौपुल्स यूनियन (जापु), जिवावे मुक्ति मोर्चा (फेलिमो), जिवावे अफ्रीकन नेशनल यूनियन (जानो)। लुसाका समझौते के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि रोडेशियाई प्रधानमन्त्री स्मिथ वक्त का तकाजा पहचान कर सांविधानिक बातचीत या तर्क सगत-समझौते के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। मार्च, 1975 में रोडेशिया के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता रेचर्ड सियोल की गिरफ्तारी पर स्मिथ ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी अत्यन्त गंभीर सरकार फिलहाल रोडेशिया-समस्या के किसी समाधान के पक्ष में नहीं है। स्मिथ की हठधर्मी ने राष्ट्रवादी अफ्रीकी नेताओं को गंभीर सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध और तेज करने के लिए विवश कर दिया। “वास्तव में स्मिथ सरकार ने सोचा था कि लुसाका वार्ता का लाभ उठा कर देश में छापामार गतिविधियों पर काबू पाया जा सकता है। इयान स्मिथ ने अपने कूटनीतिक दावपेंच के अन्तर्गत एक तरफ तो राजनीतिक वन्दियों की रिहाई शुरू की और दूसरी तरफ अश्वेन बहुमत का शासन स्थापित करने के बारे में भ्रामक वक्तव्यों का सिलसिला जारी रखा। लुसाका वार्ता में युद्धविराम के लिए जिन शर्तों की घोषणा की गई थी उन्हें स्वीकार करने के बावजूद सरकार ने उनका अन्वयन किया।”¹

29 अप्रैल से 6 मई, 1975 तक जर्मका की राजधानी किंसटन में 33 देशों के नेताओं का राष्ट्रकुल सम्मेलन हुआ। सम्मेलन पर एशियायी, अफ्रीकी और कैरिबियायी देशों का प्रभाव रहा। जिस मुद्दे को लेकर अधिक तीव्र बहस हुई वह

था—दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद का। अफ्रीकी देशों ने दक्षिण अफ्रीकी बस्तियों और रोडेशिया से गिराफाही समाप्त करने की को आवाज उठाई उसकी गूँज सारे सम्मेलन में सुनाई दी। डॉ. केनेथ काउडा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका को गिरे शासकों का धृष्टपोषण नहीं करना चाहिए। यह घोषित किया गया कि जब शान्तिपूर्ण प्रयास असफल हो जाते हैं तो स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हथियारों को उठाना जरूरी हो जाता है।

किंगस्टन के राष्ट्रकुल सम्मेलन के निर्णय के बाद रोडेशिया में घटना-क्रम ने तेजी पकड़ी। रोडेशिया के राष्ट्रवादी नेता जोशुआ मोकोमो ने प्रधानमंत्री इयान स्मिथ के साथ सांविधानिक बातचीत की सम्भावना से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बातचीत ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रवादी स्वाधीनता सेनानियों के बीच होनी चाहिए क्योंकि कानूनी रूप से रोडेशिया अभी भी ब्रिटिश उपनिवेश है। श्री मोकोमो ने आरोप लगाया कि इयान स्मिथ की सरकार शान्तिपूर्वक अफ्रीकियों को सत्ता सौंपना नहीं चाहती। इयान स्मिथ का रवैया भी अधिकाधिक कड़ा होता गया। दिसम्बर, 1975 में इयान स्मिथ ने श्री मोकोमो से बातचीत का सुझाव तो स्वीकार कर लिया लेकिन उन्होंने रोडेशिया के लिए बहुमत शासन सिद्धान्त रूप में भी स्वीकार नहीं किया। बातचीत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। उधर नवम्बर, 1975 में संयुक्तराष्ट्र महासभा के इस प्रस्ताव से भी रोडेशिया के राष्ट्रवादियों के हाथ मजबूत हो गए कि बहुमत अफ्रीकी शासन का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर ही रोडेशिया की स्वतन्त्रता के लिए बातचीत होनी चाहिए। महासभा के प्रस्ताव में कहा गया कि अफ्रीकी राष्ट्रीय परिषद् से बातचीत किए बिना रोडेशिया की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता क्योंकि यही सच्चा रोडेशिया की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। महासभा ने ब्रिटेन से यह अनुरोध किया कि रोडेशिया में इयान स्मिथ की गैर-कानूनी सरकार को किसी भी हालत में और कभी भी ब्रिटेन से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। महासभा ने अफ्रीकी जनता की स्वाधीनता की माँग का पूर्ण समर्थन किया और अफ्रीकी राष्ट्रीय परिषद् से कहा कि वह स्वाधीनता के लिए अपना आन्दोलन चालू रखे।

अफ्रीकी राष्ट्रीय परिषद् (ए एन सी) के एक गुट के नेता जोशुआ मोकोमो और रोडेशिया अल्पसंख्यक गिरे सरकार के हठी प्रधानमंत्री इयान स्मिथ के बीच सांविधानिक समझौते के लिए हुई बातचीत की विफलता, रोडेशिया के समाधान के लिए इयान स्मिथ द्वारा ब्रितानी प्रस्ताव की अस्वीकृति, लुसाका में तनजानिया, बोत्स्वाना, मोजाम्बिक और जाम्बिया के राष्ट्रपतियों की विफल वार्ता, रोडेशिया में कूबा और सोवियत सघ के हस्तक्षेप के विरुद्ध अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी कीमिंगर की चेतावनी आदि मार्च, 1976 के अन्तिम सप्ताह की कुछ ऐसी घटनाएँ थी जिनसे रोडेशिया की समस्या और अधिक जटिल हो गई। इनसे यह संकेत भी मिला कि जहाँ इयान स्मिथ अफ्रीकी राष्ट्रीय परिषद् में फूट डालकर अपना उल्लू सीधा करने की किराक में है वहाँ अमेरिका और उसके साथी स्मिथ पर उतना ही दबाव डालना

चाहते हैं जिससे कि दक्षिणी अफ्रीका में उनके हित सुरक्षित रहें। बहुसंख्यक काले लोगों को न्याय दिलाने की उनकी सद्बुद्धि का उनके रवैये में कोई सबूत नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अफ्रीकी राष्ट्रवादियों के सम्मुख एक ही उपाय शेष था कि वे अपना सशस्त्र संघर्ष तीव्र करें और जानिवासी गोरे स्मिथ से प्रथम तक बातचीत द्वारा प्राप्त नहीं कर सकें वह बलात् प्राप्ति करें।

रोडे़शिया समस्या के समाधान में गतिरोध कायम रहा। सन् 1977 के प्रारम्भ में ब्रिटिश प्रतिनिधि ईवोर रिचर्ड ने निरन्तर एक महीने तक अफ्रीकी नेताओं, रोडे़शियाई राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं तथा रोडे़शिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ से बातचीत की पर स्मिथ के दुराग्रही रवैये के कारण वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकल सका, तथापि लन्दन लौटकर रिचर्ड ने घोषणा व्यक्त की कि रोडे़शिया में बहुसंख्यक कालो का शासन शीघ्र स्थापित होगा और अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका की सहायता से वह इयान स्मिथ पर सभ्यता के लिए दबाव डालेगा। रिचर्ड ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि रोडे़शिया के सम्बन्ध में जब तक कोई स्वाधीन सभ्यता नहीं हो जाता तब तक वहाँ कालो का शासन स्थापित किया जाएगा। जो सरकार स्थापित की जाएगी उसमें कालो और गोरो दोनों के प्रतिनिधि होंगे। परन्तु इसका मुल्यमा रोडे़शिया स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त होगा। उसी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन किया जाएगा जो देश की प्रतिरक्षा तथा कानून और व्यवस्था को अन्तरिम सरकार के सहयोग से चलाएगी। कालो और गोरो में भेद करने वाली भूमि सम्बन्धी तथा अन्य कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। रिचर्ड की यह योजना अफ्रीका के 5 देशों और रोडे़शियाई राष्ट्रीय मोर्चे की स्वीकार थी। अमेरिका के विदेशमन्त्री साइरस वैंस ने रोडे़शिया अल्पमत गोरी सरकार को यह चेतावनी दी कि जब तक वह बहुसंख्यक कालो को सत्ता की रोह में प्रवृत्त डालती रहेगी, अमेरिका से उसे किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। अमेरिका ने ब्रिटिश प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया जिसके अनुसार दो वर्षों तक अस्थायी सरकार को ब्रिटेन की देख-रेख में काम करना था।

रोडे़शिया की स्थिति दिनोदिन तनावपूर्ण होती गई और इयान स्मिथ ने एक सवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी गोरी अल्पसंख्यक सरकार जब तक चाहेगी तब तक शासन में बनी रहेगी। अगस्त, 1977 के चुनावों में अपने अपने हथकण्डों से भारी विजय प्राप्त की। सन् 1974 के चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी 66 सदस्यीय ससद् में सभी 50 यूरोपीय स्थानों पर उनके रोडे़शिया फ्रंट ने कब्जा कर लिया। गोरो की मतदाता सूची में 86,000 मतदाता थे जिनमें से 80 प्रतिशत से भी अधिक ने मतदान में भाग लेकर इयान स्मिथ की स्थिति सुदृढ़ कर दी। दूसरी ओर कालो के 7 500 मतदाताओं में से केवल 25 प्रतिशत ने ही मतदान में भाग लिया। चुनाव में विजय के बाद स्मिथ की मुख्य चाल यह है कि कालो की एकता भंग कर दें। स्मिथ के हठी रवैये से ब्रिटेन और अमेरिका के उस शान्ति प्रस्ताव (सितम्बर, 1977) को आघात ही पहुँचा है जिसकी मुख्य धाराएँ हैं—

‘इयान स्मिथ ब्रिटेन द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि को सत्ता का हस्तान्तरण कर दे। यह अन्तरिम प्रशासन होगा (ब्रिटेन के भूतपूर्व सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल कारवेर के नाम की भी घोषणा कर दी है), स्मिथ अपनी गोरी सेना भंग कर दे और राष्ट्रीय छापामार स्वयं को निःशस्त्र कर लें। इन दोनों ही सेनाओं के भंग किए जाने के बाद रोडेशिया के कानून और व्यवस्था का दायित्व संयुक्तराष्ट्र की सेना को सौंपा जाए। यह सेना रोडेशिया में चुनाव होने तक रहगी। यह भी प्रस्ताव है कि चुनाव एक व्यक्ति एक मत के अनुसार हों और यह कार्य नए संविधान के अन्तर्गत अगले वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में गोरों की सुरक्षा की गारण्टी का प्रावधान है। इस नव-स्वाधीन रोडेशिया में अल्पमत गोरों की सुरक्षा के लिए एक अरब डॉलर की निधि की व्यवस्था होगी। यह धन प्राथिक विकास पर व्यय होगा। साथ ही जो गोरें रोडेशिया छोड़कर जाना चाहें उन्हें निश्चित मुआवजा दिया जाएगा।’

end

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ और विवाद

(CONTEMPORARY TRENDS AND ISSUES IN INTERNATIONAL POLITICS)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में समकालीन प्रवृत्तियाँ

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर जिस युग का सूत्रपात हुआ उसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार-क्षेत्र के अनेक 'नूतन सिनिज' उभरे हैं, प्रभुत्व-क्षेत्र बदल गए हैं नवीन प्रवृत्तियों और मिथ्यान्तों का प्रादुर्भाव हुआ है, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् को नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विदेश नीतियों के स्वरूप बदलते जा रहे हैं—संशोधन में विश्व राजनीति का ताना-बाना महान् परिवर्तनों के दौर से गुजर चुका है और गुजरता जा रहा है। पहले हम कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रवर्तन करेंगे—

1 युद्ध के भय की तीव्रता—द्वितीय महायुद्ध के अन्त में आणविक हथियारों के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने की दिशा में एक नए तत्त्व का समावेश कर दिया है। वह तत्त्व है—युद्ध के भय की तीव्रता (Intensification of fear of war)। आज आणविक शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों में प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने की आवश्यकता अत्यन्त किमी भी समय से अधिक अनुभव की जा रही है। यह समझा जाने लगा है कि ऐसा कोई भी युद्ध समूची अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक भयावह चुनौती है।

2. राज्य-व्यवस्था का विश्वव्यापी बनना—राज्य-व्यवस्था पूर्णरूप से विश्व-व्यापी बन चुकी है। आज विश्व का लगभग प्रत्येक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का सदस्य है और इस बात का व्यवस्था के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि दो सर्वोच्च महाशक्तियाँ एक-दूसरे पर विश्व-प्रभुत्व के प्रयत्नों का आरोप लगाती हैं, तथापि यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी एक शक्ति द्वारा विश्व-साम्राज्य का यह भय धारण न होकर काल्पनिक है।

3. क्षेत्रीय प्रभुत्व की चुनौती में उभार—आधुनिक परिस्थितियों में विश्व-साम्राज्य का भय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए कोई वास्तविक

चुनौती नहीं रह गया है। हाँ, क्षेत्रीय साम्राज्य का भय अवश्य विद्यमान है और अनेक राज्यों की नीतियों को सक्रिय बनाए हुए है। यही कारण है कि आज के युग में क्षेत्रीय युद्ध (Regional Wars) सामान्य बन गए हैं। राज्यों में क्षेत्रीय हितों के लिए युद्ध होते रहते हैं। विलियम कोपलिन के अनुसार समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए महाशक्तियों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है—

- (क) जिन क्षेत्रों में उनके अपने हित हैं, वहाँ वे स्वयं स्थायित्व कायम रखने का प्रयत्न करते हैं।
- (ख) कुछ क्षेत्रों में वे सघर्ष और क्षेत्रीय साम्राज्य को रोकने में परस्पर सहयोग करते हैं।
- (ग) कुछ क्षेत्रों में वे विरोधी पक्षों को समर्थन देकर एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं। उदाहरणार्थ, पश्चिमी एशिया में संयुक्तराज्य अमेरिका इजरायल का पृष्ठ-पोषण करता है तो सोवियत संघ अरब राष्ट्रों का।

4. सुरक्षा संगठनों की तकनीक का विकास—वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में यह भी एक सामान्य बात हो गई है कि महाशक्तियाँ युद्ध छिड़ने से पहले ही वृद्धा क्षेत्रीय मामलों में उलझ जाती हैं। द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में 'क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों' (Regional Security Organisations) की तकनीक का विकास हुआ है जो बहुत कुछ क्षेत्रीय गठबन्धनों जैसी दिखाई देती है। संयुक्तराज्य अमेरिका ने नाटो केन्द्रीय सन्धि संगठन, अमेरिकी राज्य-संगठन, एंजुस परिषद् जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों की स्थापना की है तो दूसरी ओर सोवियत संघ ने पारसा पैक्ट का गठन किया है।

5. क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेपवादी नीति—महाशक्तियाँ गृहयुद्धों में भाग लेकर भी क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करती रही हैं। रूस और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियों ने गृहयुद्धों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किए हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ महाशक्तियों ने महसूस किया कि किसी एक महाशक्ति का वहाँ अपना विशिष्ट हित है, हस्तक्षेप एकपक्षीय रहा है। उदाहरणार्थ, पश्चिमी गोलार्द्ध के किसी भी राज्य में घरेलू अव्यवस्था की दशा में अकेले संयुक्तराज्य अमेरिका का हस्तक्षेप सामान्यतः पर्याप्त समझा जाता रहा है। पूर्वी यूरोपीय राज्यों में सोवियत संघ के विशेष हित हैं, अतः इन राज्यों में घरेलू अव्यवस्था के प्रति वह विशेष रूप से चौकन्ना रहता है। सम्भवतः दोनों महाशक्तियों में इस बात पर सहमति हो गई है कि अपने-अपने हित-क्षेत्रों में यदि घरेलू राजनीतिक अस्थिरता की चुनौती प्रस्तुत हो तो प्रकली महाशक्ति उस चुनौती से निवृत्त ले चाहे दिखाने के लिए दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के विरुद्ध वक्तव्य दें। इस प्रकार जहाँ पश्चिमी गोलार्द्ध अकेले संयुक्तराज्य अमेरिका के लिए छोड़ दिया गया है वहाँ पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के लिए छूट है।

6. विश्वव्यापी चौकसी की व्यवस्था—क्षेत्रीय साम्राज्यों को रोकने के लिए

संयुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ने विश्वव्यापी चौकसी की व्यवस्था (Universal Surveillance) अपनायी है। महाशक्तियाँ इस बात पर दृष्टि रखती हैं कि क्षेत्र-विशेष में किसी महाशक्ति द्वारा चुनौती प्रस्तुत की गई है या किसी अन्य राज्य द्वारा। जब चुनौती किसी महाशक्ति की ओर से नहीं आती तो दोनों ही महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से घबरा पड़ें के पीछे की नूतनीति से प्रायः परस्पर सहयोग करती हैं। जहाँ चुनौती दोनों में से किसी एक महाशक्ति द्वारा प्रस्तुत होती है, वहाँ प्रायः अवरोध (Deadlock) की स्थिति पैदा हो जाती है। वीतन, विघननाम आदि के सन्दर्भ में इस प्रकार की अवरोधपूर्ण स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं। अन्य राज्यों द्वारा क्षेत्रीय प्रभुत्व के प्रयत्नों को रोकने में रूस-अमेरिकी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक महत्वपूर्ण सत्यात्मक आधार-स्थल का काम किया है। दोनों महाशक्तियों ने किसी युद्ध-विराम को लागू करने के लिए कई बार महासचिव के मद्-प्रयासों का स्वागत किया है। साइप्रस, मध्य-पूर्व और भारत-पाक संघर्षों में ऐसा हो चुका है।

7. निःशस्त्रीकरण एक अधिक संघटन प्रतिमान की दिशा में—समकालीन विश्व में दो महायुद्धों के बीच की अवधि की तुलना में निःशस्त्रीकरण ने एक अधिक संघटन प्रतिमान (A more moderate pattern) का अनुसरण किया है। द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में इस पर अधिक बल दिया जाने लगा है। अधिकांश समकालीन निर्णायकता निःशस्त्रीकरण का एक ऐसा साधन या उपाय मानने लगे हैं जो युद्ध के खतरे को कम करता है। महाशक्तियों ने अपनी रणनीतियों और व्यूह-रचनाओं के उग्र बनाने की नीति का अनुसरण किया है, लेकिन प्रत्यक्षतः एक दूसरे से संपर्क की स्थिति को सर्व्व टाळा है। यह स्थिति वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रखने में सहायक हुई है।

8. विवाद-क्षेत्रों का विभाजन—उन विवाद-क्षेत्रों की समस्या और विविधता बढ़ती जा रही है जिन पर राज्य परस्पर सौदेबाजी करते हैं। पुरातन युग में राजा मुख्यतः उस क्षेत्र के नियन्त्रण पर सौदेबाजी करते थे जो उनकी भौगोलिक सुरक्षा में सम्बन्धित होता था, किन्तु आधुनिक राज्य एक दूसरे से व्यापक और विविध विवाद क्षेत्रों पर सौदेबाजी करते हैं जिनमें से अनेक का प्रादेशिक नियन्त्रण जैसे प्रश्नों को कोई सम्बन्ध नहीं होता। उदाहरणार्थ, राज्यों के बीच अन्तर्संस्कारी सगठनों का निर्माण और एतिवर्तिन, आर्थिक विकास की नीतियाँ, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि में समाधान आदि प्रश्नों पर सौदेबाजी होती है, यहाँ तक कि कुछ राज्यों की प्रान्तरिक सामाजिक नीतियों (जैसे दक्षिण अफ्रीका में रणभेद नीति) पर भी राज्यों के मध्य सौदेबाजी होती है। उन प्रश्न प्रादेशिक नियन्त्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित हैं उन पर सौदेबाजी की स्थितियाँ अधिक पचीदा बन जाती हैं। उदाहरणार्थ गुटनीति के सम्बन्ध में को समझना केवल किन्हीं प्रादेशिक लक्ष्यों के सम्बन्ध में ही नहीं किया जाता या कि समझौते का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होना कि एक राज्य या राज्यों के गु

विशेष के विरुद्ध सुरक्षा की जानी है, बल्कि उस समझौते में और भी व्यापक हित-प्रश्न सम्मिलित होते हैं। नाटो सीटो, वारसा पैक्ट आदि संगठन केवल प्रादेशिक नियन्त्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्नों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ऐसी प्रतिबद्धताओं में बंधे हुए हैं जिनसे अनेक प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं जैसे विदेशी सेनाओं की तैनाती, प्रशासकीय कर्मचारियों की नियुक्ति, आधार स्थलों की स्थिति, संगठन-सदस्यों के समर्थकों का आवंटन, आदि। राष्ट्रीय सुरक्षा की राजनीति से अस्त्र-नियन्त्रण और निःशस्त्रीकरण जैसा विवाद-क्षेत्र या मसला उत्पन्न होता है और आज 20वीं शताब्दी की विदेश-नीति में यह मामला अधिक अधिकाधिक विवादास्पद बनता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास से भी विवाद-क्षेत्रों की सख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, इन संगठनों की राजनीति के प्रश्न, जिनमें सांविधानिक परिवर्तन, पदाधिकारियों के चुनाव, बजट सम्बन्धी आवंटन, संगठनों में राज्यों की स्थिति आदि शामिल हैं, राज्यों की विदेशनीति के नए विवाद-क्षेत्र बन गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकारों, साम्यवाद बनाम पूँजीवाद, उपनिवेशवाद बनाम उपनिवेशवाद-विरोधी आदि समस्याओं पर मौखिक संधयों का रगमच प्रदान करते हैं।

9. विचारधाराओं का परिवर्तित रूप—वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं का कठोर स्वरूप सजीला होता जा रहा है तथा परिवर्तित हो रहा है। इसके अनेक पक्ष हैं। एक ओर साम्यवाद तथा पूँजीवाद—इन दो परम्परागत और परस्पर विरोधी विचारधाराओं में संधयें शिथिल पड़ रहा है और रूस तथा अमेरिका सहप्रतिस्पर्धियों की बात करने लगे हैं, तो दूसरी ओर एक ही विचारधारा के बीच विभाजन की खाई चौड़ी हो रही है और चीन तथा रूस एक दूसरे को शत्रुता की दृष्टि से देख रहे हैं।

10. बहुकेन्द्रवाद की ओर प्रवृत्ति—वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् बहुकेन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर उन्मुख है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) का अर्थ है विश्व का दो शक्ति-गुटों या केन्द्रों में विभाजन हो जाना और बहुकेन्द्रवाद का अर्थ है शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हो जाना। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त समुक्तराज्य अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व में दो शक्ति-गुटों का तेशी से उदय हुआ, परन्तु 1960 के आने-आते यह द्वि-ध्रुवीयता शिथिल पड़ने लगी और विश्व जनें-शनें बहुकेन्द्रवाद की ओर अग्रसर होने लगा। सबसे पहले द्वि-ध्रुवीयता को राष्ट्रीयता ने चुनौती दी। एशिया और अफ्रीका के नवजागरण के फलस्वरूप दोनों गुटों से पृथक् रहने की नीतियों को अपनाने से द्विकेंद्रित व्यवस्था और अधिक शिथिल हो गई। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने अदा की। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण द्वारा स्वयं को पुनः शक्ति-सम्पन्न बनाकर यह निश्चय किया कि अब वे अमेरिका के पिछलग्गू बनकर नहीं रहेंगे। विशेषकर फ्रांस ने स्वर्गीय जनरल डिगॉल के नेतृत्व में विश्व की द्विध्रुवीय व्यवस्था को विशेष आघात पहुँचाया। इस

व्यवस्था को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में इस बात से भी आघात पहुँचा कि अणु आयुधों का एकाधिकार अमेरिका और रूस के पास में बिसरने लगा तथा ब्रिटेन फ्रांस और चीन भी अणुशक्ति सम्पन्न बन गए। नवोदित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रूपरेखा यद्यपि अभी सुस्पष्ट और मुनिश्चित नहीं है, तथापि दो शक्ति गुटों के स्थान पर अधिक शक्तिकेन्द्रों का स्पष्ट रूप से उदय हुआ है। अब विश्व की दो महाशक्तियों, रूस और अमेरिका के लिए एशिया में भारत और चीन की उपेक्षा करना सम्भव नहीं है।

वस्तुतः वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहुकेन्द्रीय है जिसमें केवल पूँजीवादी, साम्यवादी और तटस्थतावादी गुट ही नहीं हैं बल्कि अन्य राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्रसंघ भी सम्मिलित हैं। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि उचित अवसर पर कमजोर से कमजोर राष्ट्र की आवाज भी अपनी महत्त्व रखती है। मध्यपूर्व में इजराइल और संयुक्त अरब गणराज्य भी शक्ति के ऐसे केन्द्र हैं जो अपने रवंगे में परिवर्तन द्वारा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और महाशक्तियों के पारस्परिक संबंधों को भ्रूणभोर सकते हैं। शक्ति-सन्तुलन की ऐतिहासिक परम्परा का आज विशेष महत्त्व नहीं रह गया है और सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था की बात अव्यावहारिक प्रतीत होने लगी है।

11 विभिन्न देशों के स्तरों में परिवर्तन—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आज यूरोपीय देशों की राजनीति ही नहीं रह गई है। एशिया और अफ्रीका का नवजागरण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नए महत्त्व, नए सम्बन्ध और नए प्रभाव का सूचक है। आज अफ्रीकाई राष्ट्रों का भाग्य साम्राज्यवादी राष्ट्रों के माथ बँधा हुआ नहीं है, अब वे अपनी स्वतन्त्र विदेश-नीति का प्रयोग करने में लगे हैं और संयुक्त राष्ट्रसंघ में उनकी आवाज की उपेक्षा करना किसी भी महाशक्ति के लिए सुगम नहीं है। इन राष्ट्रों के निर्लुप्तों का आधुनिक राजनीति पर भारी प्रभाव पड़ना है। भारत और चीन नई महाशक्तियों के रूप में उदित हो रहे हैं और अपने सिद्धान्तों के अनुरूप विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। भारत एशिया में लोकतन्त्र का गढ़ है तो चीन प्रादेशिक विस्तारवादी, सैन्यवादी तथा कुटिल राजनीति का खिलाडी है जो विश्व की सभी लोकतान्त्रिक महाशक्तियों के लिए चुनौती है। पाकिस्तान सैनिक तानाशाही के अधीन अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर विखण्डित हो चुका है।

12 विश्व-संस्था के प्रति परिवर्तित रव—विश्व-संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति संसार के राष्ट्रों का दृष्टिकोण आज उतना उत्साहप्रद नहीं है जितना इस संस्था की स्थापना के समय अव्येक्षित था। अधिकांश राष्ट्र इसके सिद्धान्तों के प्रति समुचित रूप में निष्ठावान नहीं हैं और सुरक्षा-परिपद महाशक्तियों के हाथों का खिलौना बन गई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने सफलता या तो उन मामलों में प्राप्ति की है जिनमें महाशक्तियों से इसे पूर्ण सहयोग मिला अथवा उन छोटे और कम महत्त्व के विवादों में जिनसे महाशक्तियाँ प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं थी और जिनमें उनके हितों की

टकराहट नहीं थी। अतः अब अधिकांश देशों में यह दृष्टिकोण बल पकड़ने लगा है कि समुक्त राष्ट्रसंघ ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। समुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति सद्भावना और सक्रिय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रों का उदासीन रख अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में चिन्ता का विषय है।

13. मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व की विशिष्ट स्थिति—महायुद्ध के उपरान्त एशिया के दो प्रदेश मध्यपूर्व और सुदूरपूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में निरन्तर विशेष महत्त्व प्राप्त करते गए और आज भी ये विश्व का प्रधान सकटस्थल बने हुए हैं। मध्यपूर्व तेल के वृहत् भण्डारों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का आकर्षक केन्द्र है तो भारत और साल चीन के उदय ने सुदूरपूर्व को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रदेशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। वास्तव में आज एशिया विश्व-राजनीति का तूफानी केन्द्र बन चुका है।

14. साम्राज्यवाद का बदलता हुआ स्वरूप—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नई विस्फोटक प्रवृत्ति यह है कि साम्राज्यवाद के नए परिवेश में उभरने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रादेशिक साम्राज्यवाद तो पनोन्मुख है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद पैर पसारने के लिए प्रयत्नशील है। अफ्रीका इस नए साम्राज्यवाद का विशेष स्थल है, लेकिन अफ्रीकी जनता अब जाग उठी है और विभिन्न प्रकार से साम्राज्यवादों के विरुद्ध मोर्चा ले रही है। उस सघर्ष ने जहाँ एक ओर जन-ग्रान्दोलनों का रूप ले लिया है, वही दूसरी ओर बुद्धिजीवियों का ग्रान्दोलन भी इस मुक्ति-सघर्ष को तीव्र और स्थायी बनाने के लिए गृष्ठभूमि तैयार कर रहा है और बौद्धिक तथा वैचारिक स्तर पर नई दुनिया का सूत्रपात कर रहा है। यह एक शुभ लक्षण है।

15. गुट-निरपेक्ष देशों की उत्तरोत्तर बढ़ती भूमिका—गुट-निरपेक्षता ग्रान्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इतना प्रभावी होता जा रहा है कि महाशक्तियों और विश्व के पूँजीवादी तथा साम्यवादी शिविरों द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता। सन् 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन के बाद गुट-निरपेक्षता ग्रान्दोलन को उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। विश्व-शान्ति कायम रखने और विश्वयुद्ध तथा स्थानीय सघर्ष रोकने में गुट-निरपेक्षता ने सैद्धान्तिक एवं स्थानीय सहयोग प्रदान किया है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जातिवाद के विरुद्ध सघर्ष में यह निरन्तर प्रथिम पक्ति में रहा है। इसने विश्व के प्रमुख आर्थिक प्रश्नों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और न्याय एवं समानता के स्तर पर आधारित नव-आर्थिक समाज की स्थापना में रचनात्मक योग दिया है। गुट-निरपेक्ष देशों की निरन्तर बढ़ती हुई सक्षम गुट-निरपेक्षता की लोकप्रियता का प्रमाण है। सितम्बर, 1961 के बेलग्रेड गुट-निरपेक्ष प्रथम शिखर सम्मेलन में केवल 25 देशों ने भाग लिया था, सन् 1973 के अल्जीरिया सम्मेलन में 76 देशों ने भाग लिया और अगस्त, 1976 के कोलम्बो सम्मेलन में मालदीव निर्गुट राष्ट्र संगठन का 86वाँ सदस्य-देश

बनार। कोलम्बो निर्गुंट शिलर सम्मेलन में यह बात स्पष्ट हो गई कि गुट-निरपेक्ष देश जिन्हीं भी दबावों के आगे नहीं झुकेंगे।

16 सम्प्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि—द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त उन्निवेश-वाद के लोग के कारण सम्प्रभु राज्यों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जहाँ सन् 1955 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों की संख्या केवल 51 थी, वहाँ अब यह 149 है। सम्प्रभु राज्यों की संख्या में इस अभूतपूर्व वृद्धि के फलस्वरूप विश्व-राजनीति का स्वरूप बहुत कुछ रूपान्तरित हो गया है और विभिन्न राज्यों के स्तरों तथा स्थितियों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अफ्रिकियाई राष्ट्रों की आवाज विश्व संस्था में आज अधिक प्रभावी है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ नवीनतम विवाद और घटना-चक्र

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्र एक अविराम प्रवाहमान सरिता की भाँति है जिसमें नित नए परिवर्तनों के छोटे-मोटे बुलबुले उठते-गिरते रहते हैं, परिवर्तनों की लहरें हिलोरें मारती रहती हैं। कुछ परिवर्तन अपेक्षाकृत शान्त प्रकृति के होते हैं तो कुछ काफी उग्र और विस्फोटक। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पहलुओं, महाशक्तियों की विदेश-नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघ, निःशस्त्रीकरण, शीतयुद्ध आदि के विस्तार से उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है। यहाँ हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अन्य उल्लेखनीय पहलुओं, अभिनव घटना-चक्रों तथा दृष्टि-कोणों को प्रस्तुत करेंगे।

निःशस्त्रीकरण पर ब्रेझ्नेव का प्रस्ताव, नवम्बर 1977

महायुद्धोत्तर युग में निःशस्त्रीकरण की दिशा में महाशक्तियों की ओर से जो प्रस्ताव-प्रतिप्रस्ताव किए जाते रहे हैं उनमें सोवियत संघ के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री लियोनिद ब्रेझ्नेव का नवम्बर, 1977 का प्रस्ताव न केवल नवीनतम वरन् बहुत ही महत्वपूर्ण है।

‘सोवियत भवतुवर-क्रान्ति की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्रैमलिन में आयोजित एक रैली को सम्बोधित करते हुए 2 नवम्बर को श्री ब्रेझ्नेव ने यह प्रस्ताव किया कि सभी देश एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत परमाणु अस्त्रों का निर्माण एक साथ रोक दें। उन्होंने यह आग्रह भी किया है कि एक निश्चित अवधि के लिए न केवल सभी प्रकार के परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए बल्कि साथ ही शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किए जाने वाले परमाणु विस्फोटों को भी स्थगित कर दिया जाए। अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को महत्त्वपूर्ण बनाते हुए श्री ब्रेझ्नेव ने कहा कि आज की सबसे बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता यह है कि उस शस्त्रास्त्र होड़ को रोका जाए जिसने सारे समार को अपनी चपेट में ले लिया है। सैनिक संघर्षों को क्रमशः कम करने हेतु हम शस्त्रास्त्र होड़ को कम करने के पक्ष में हैं और इस प्रक्रिया को आरम्भ करना चाहते हैं। हम पहले तो परमाणु युद्ध की सम्भावनाओं को कम करना चाहते हैं और अन्तः उन्हें समाप्त करना चाहते हैं। परमाणु युद्ध मानव-जाति का सबसे प्रबल शत्रु है।

“श्री ब्रेझ्नेव ने परमाणु युद्ध के संकट से मानव-जाति की मुक्ति के लिए यह सुझाव दिया है कि जिन देशों के पास परमाणु अस्त्रों के भण्डार हैं वे उसमें धीरे-धीरे कटौती करें और अन्त में उसे बिलकुल समाप्त कर दें। उनकी मान्यता है कि विश्व के देश दीर्घकाल से परमाणु अस्त्रों पर जिम प्रतिबन्ध की अपेक्षा कर रहे हैं, परमाणु परीक्षणों का स्थगन उसकी भूमिका होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन कामों के हो जाने पर उन अनेक समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान दिया जा सकेगा जिनका सामना मानव-जाति को करना पड़ रहा है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, कच्चे माल और ऊर्जा के स्रोतों को जुटाना, एशियायी, अफ्रीकी, लातीनी अमेरिकी देशों के पिछड़ेपन को दूर करना आदि महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जिनका समाधान नितान्त आवश्यक है।”

सोवियत राष्ट्रपति के इस प्रस्ताव से कुछ दिन पहले ही जापान ने आग्रह किया था कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाए क्योंकि शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए और सैनिक उद्देश्यों से किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों में भेद करना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। जिन देशों के पास आज परमाणु अस्त्र नहीं हैं वे भी शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए विस्फोट कर अन्ततः परमाणु अस्त्र निर्माण की क्षमता अर्जित कर सकते हैं। अतएव मनी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध के अभाव में परमाणु अस्त्र निरोध मन्त्रि मार्थक नहीं बन पाएगी। जापान का यह तर्क उचित था। परमाणु शक्ति सम्पन्न होने की छूट देकर किसी देश से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि आवश्यकता होने पर भी वह अपनी उस शक्ति का उपयोग सैनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं करेगा। जापान की इस माँग के सम्बन्ध में भी ब्रेझ्नेव का हाल का प्रस्ताव बहुत कुछ मार्थक है। परमाणु विस्फोटों का स्थगन अन्ततः पूर्ण प्रतिबन्ध का स्वर ले सकता है, बशर्ते कि सम्बद्ध देश नेकमीयती का परिचय दें।

स्वाभाविक ही था कि ब्रेझ्नेव के प्रस्ताव पर अमेरिका अपनी प्रतिक्रिया तत्काल व्यक्त करता। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने उसी दिन रात को विश्व यहूवी काँग्रेस को सम्बोधित करते हुए ब्रेझ्नेव के प्रस्ताव का यह कहकर स्वागत किया कि “हमें आशा है कि शीघ्र ही हम परमाणु-परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाने में सफल होंगे जिससे पृथ्वी पर से इस (परमाणु शक्ति) का खतरा निभूँल दिया जा सकेगा।” हमारे प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई ने भी ब्रेझ्नेव के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत किया है।

ब्रेझ्नेव का प्रस्ताव अच्छा और व्यावहारिक है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में उसे क्रियान्वित करना निश्चय ही कठिन है। प्रस्ताव की सफलता के लिए जरूरी है कि वे सभी देश उसको क्रियान्वित करने के लिए बिना शर्त सहमत हो जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं तथा वे भी जो परमाणु शक्ति सम्पन्न हैं यद्यपि फिलहाल उनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं। इसका अर्थ यह होगा कि परमाणु अस्त्रों ने जिन्हें आज सर्वशक्तिवान् बना रखा है उनके और जो उनके समकक्ष पहुँचने के लिए प्रयत्नरत हैं

उन देशों के बीच वर्तमान शक्ति सन्तुलन रहेगा। यह स्थिति कम से कम वह देश तो स्वीकार नहीं करेंगे जो बड़ा की शक्ति में बैठने के लिए निरन्तर परमाणु परीक्षण करते रहे हैं तथा कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि दोनों बड़े राष्ट्र दूसरी की सहमति की बिना किए बिना इस दिशा में पहल करें। प्रश्न यह है कि क्या वे इसके लिए तैयार होंगे ?

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें सत्र में निःशस्त्रीकरण पर विचार और भारत की भूमिका¹

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें सत्र 1976 की कार्यमूची में निःशस्त्रीकरण, अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के बारे में कुल 20 मंजूरियाँ जिन पर 23 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें से भारत ने 6 प्रस्तावों की सहप्रवर्तित किया और ये सभी पारित हुए, इनमें से चार तो विना मतदान के पारित हो गए। भारत ने दो अन्य प्रस्तावों में मत दिया, 4 में अनुपस्थित रहा और 1 के (दक्षिण एशिया में अणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र की स्थापना के प्रश्न पर पाकिस्तान द्वारा प्रवर्तित) विरोध में मत दिया। तीन अन्य प्रस्ताव बिना किसी मतदान के पारित हो गए।

निःशस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में 31वें सत्र की हुई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना थी। कॉलम्बो शिखर सम्मेलन की सिफारिशों के अनुशीलन में भारत सहित अन्य गुट-निरपेक्ष देशों में एक प्रस्ताव सहप्रवर्तित किया जो पारित हुआ। इसके अनुसार निःशस्त्रीकरण पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का मई-जून, 1978 में विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया।

दक्षिण एशिया में अणु-शस्त्र-मुक्त क्षेत्र की स्थापना के प्रश्न पर पाकिस्तान ने पुनः एक प्रस्ताव सदन में रखा। भारत ने इस सत्र में कोई प्रस्ताव सदन में नहीं रखा क्योंकि इस विषय पर दिए गए अनेक वक्तव्यों में इसकी स्थिति पहले ही काफी स्पष्ट हो चुकी थी जिनसे विरोध का संकेत मिला था। 29 और 30वें सत्र में पाकिस्तान के प्रस्तावों के विरुद्ध भारत ने अपनी तरफ से वैकल्पिक प्रस्ताव रखे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित किया। यथार्थ में 29वें सत्र में भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रस्तावों पर मतदान हुआ। भारत के प्रस्ताव के पक्ष में पाकिस्तान के प्रस्ताव की अपेक्षा अधिक मत पड़े थे। फिर भी पाकिस्तान के प्रस्ताव की अस्वीकृति को दोहराने के लिए भारत ने पाकिस्तानी प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। कुल मिलाकर पाकिस्तानी प्रस्ताव के बारे में भारत की स्थिति यह थी कि दक्षिण एशिया में अणु शस्त्रमुक्त क्षेत्र की स्थापना करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक एशिया और पैसिफिक में अणु शस्त्र विद्यमान है क्योंकि दक्षिण एशिया इसका अभिन्न अंग है।

परम्परागत निःशस्त्रीकरण के बारे में भारत ने अपना वही मत दोहराया कि परम्परागत शस्त्रों पर व्यापक निदमन होना चाहिए, उस पर आगे एवं सम्पूर्ण

निःशस्त्रीकरण के सन्दर्भ में विनष्ट होना चाहिए और सर्वोच्च प्राथमिकता अशु शस्त्रों तथा बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले अन्य हथियारों की समाप्ति के प्रश्न को दी जानी चाहिए। इस स्थिति के अनुरूप भारत इस प्रस्ताव पर होने वाले विचार-विमर्श पर स्थगन लाने में सफल हुआ जिसमें परम्परागत हथियारों के उत्पादन, उन्नत बनाने और संचय करने पर रोक लगाए बिना केवल उनके अन्तर्राष्ट्रीय हस्तान्तरण पर नियन्त्रण लगाने का प्रस्ताव था और साथ ही इसमें अशु निःशस्त्रीकरण एवं बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले सभी हथियार सम्बन्धी लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता भी नहीं दी गई थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 31वें सत्र में निःशस्त्रीकरण के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं में कोई ठोस प्रगति नहीं देखी गई और अनेक समस्याओं, विशेषकर व्यापक अशु अस्त्र परीक्षा प्रतिबन्ध के निष्कर्ष एवं प्राथमिकता के आधार पर रासायनिक हथियारों पर प्रतिबन्ध, आगे विचार-विनिमय के लिए सी सी डी को तैयार किए गए।

महासभा के 31वें सत्र 1976 में उपनिवेशवाद और पृथग्वासन का विरोध

महासभा का जा 31वाँ नियमित सत्र 21 सितम्बर से 21 दिसम्बर, 1976 तक न्यूयार्क में हुआ जहाँ दक्षिण सरकार की पृथग्वासन नीतियों और जिम्बाब्वे के गैर-कानूनी राज्य की कटु आलोचना हुई। पृथग्वासन के महत्त्व पर विशेष प्रकाश डालने के लिए इस पर विद्यमान वर्षों की तरह विशेष राजनीतिक समिति के बजाय पूर्ण सत्र में विचार-विमर्श किया गया। इस वाद-विवाद में 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और मात्र पृथग्वासन पर 11 प्रस्ताव पारित किए गए जिनमें से 8 भारत ने सह-प्रस्तावित किए। महासभा ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका के पीड़ित लोगों के सशस्त्र युद्ध का समर्थन किया। इसने प्रिटोरिया राज्य को अवैध घोषित किया और दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए सभी साधनों से युद्ध करने के अधिकार की पुनः पुष्टि की। इसके अलावा महासभा ने दक्षिण अफ्रीका के स्वतन्त्रता सचर्य में भाग लेने के कारण बन्दी बनाए गए सभी लोगों को तत्काल मुक्त करने की माँग की और सुरक्षा परिषद से प्रिटोरिया राज्य के खिलाफ शस्त्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की पुनः माँग की। एक दूसरे प्रस्ताव में प्रिटोरिया शासन के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग की निन्दा की गई क्योंकि इसे दक्षिण अफ्रीका के पीड़ित लोगों के विरुद्ध विद्रोहपूर्ण कार्यवाही माना गया और शासन के साथ सहयोग करने वाले सभी देशों और विदेशी आर्थिक हित कायम रखने वालों की भर्त्सना की। इजराइल की भर्त्सना करते हुए एक प्रस्ताव 'दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के साथ सहयोग बढ़ाने सम्बन्धी' स्वीकृत किया गया। महासभा ने विशेष समिति को पृथग्वासन के विरुद्ध सन् 1977 में अफ्रीका (घाना) में एक विश्व सम्मेलन गठित करने का अधिकार दिया जिसका कार्य सरकारों, विशेषीकृत अभिकरणों तथा अन्य संगठनों द्वारा अपनाए जाने योग्य साधनों की सूची तैयार कर एक कार्यक्रम तैयार करना था। इसने बिना किसी विरोध के एक निर्णय को

भी स्वीकृति प्रदान की जिम्मा उद्देश्य खेलकूद में पृथग्वासन के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय-समवाय तैयार करने के लिए प्राप्त समिति गठित करना और दक्षिण अफ्रीका के लिए समुक्त राष्ट्र ट्रस्ट निधि में, जो भेद-भावपूर्ण कानून से पीड़ित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करती है, उदारता से अंशदान देने की अपील करना था। इसके अलावा महामन्त्री ने ट्रांसफेर्ड—दक्षिण अफ्रीका का एक वलुस्तान (गृहविहीन) की स्वतन्त्रता की घोषणा की प्रस्वीकृत किया और उसे सर्वेध पोषित किया। वलुस्तानों की स्थापना की अर्हता की गई और इन्हे पृथग्वासन की मुहब्ब बनाने की एक चाल बताया गया जो गोरे अल्प लोगों का शासन कायम रखने और दक्षिण अफ्रीका के अल्लस्तान्तरणीय अधिकारों को छीनने के लिए चली गई थी। सरकारों को 'तथा-कथित स्वतन्त्र ट्रांसफेर्ड' के किमी भी रूप को मान्यता नहीं देने और उनके माथ मा अन्य किमी वलुस्तान के साथ सभी प्रकार के सम्बन्धों में पृथक् रहने को कहा गया।

भारत ने उपनिवेशवाद और पृथग्वासन में सम्बन्धित विषयों पर, जैसा कि इन विषयों पर भारत का मत सर्व-विदित है, मद्दासना के दिवार-विमर्शों में सक्रिय भाग लिया। भारत उपनिवेशवाद की समाप्ति (24वीं समिति) के लिए समुक्त राष्ट्र की विशेष समिति, पृथग्वासन पर विशेष समिति और नामविद्या परिषद् का सदस्य बना रहा।

सेशेल्स की ब्रिटिश साम्राज्यवाद में मुक्ति

28 जून को आधी रात को सेशेल्स द्वीपसमूह 160 वर्षों के ब्रितानी आधिपत्य में मुक्त हो गया। सेशेल्स के सबसे बड़े द्वीप माहे (जहाँ सेशेल्स की कुल आबादी का 90 प्रतिशत भाग बसा हुआ है) में राजधानी विकटोरिया के राष्ट्रीय स्टेडियम में सेशेल्स की लगभग समूची जनसंख्या (65 हजार) इस ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुई। रानी एलिजाबेथ के प्रतिनिधि ग्लोस्टर के ड्यूक ने सेशेल्स के 36 वर्षीय राष्ट्रपति जेम्स पचम को नए सत्रिधान के कागजात सौंप कर स्वतन्त्रता समारोह को अन्तिम रूप दिया। सेशेल्स जो अब राष्ट्रमण्डल का 35वाँ सदस्य है, के नए राष्ट्रपति ने अपने भाषण में गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाने का वचन दिया। जेम्स पचम ने कहा कि हमारा देश एक अशान्त दुनिया में अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में सारी दुनिया को मेरा यह सन्देश है कि हमारे तट सुरक्षा की दृष्टि से कितने ही बमजोड़ बगों न हो तथा हमारी आर्थिक स्थिति अभी भले ही ठीक न हो पर संयुक्त सेशेल्स को कभी पराजित नहीं किया जा सकेगा।

श्रीमती इन्दिरागांधी ने स्व-स्वतन्त्र राष्ट्र के नेताओं और जनता को अपने बधाई सन्देश में कहा कि 'भारत और सेशेल्स के अनेक ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा समान स्मृतियाँ हैं। हिन्दमहासागर के द्वीप-गिर्दों के सभी देश अपने क्षेत्र को शान्ति का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे।'

अफ्रीका में बदलती शासन-प्रणाली

एशिया और अफ्रीका महाद्वीप राजनीति और प्रशासन के प्रयोग में अस्थिर रहे

हैं। अफ्रीका आज भी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। जनवरी के दिनमान में अफ्रीका में बदलती शासन-प्रणालियों का सक्षिप्त विवरण दिया गया है जो हमें अफ्रीका की राजनीतिक और शासनिक स्थिति का अच्छा आभास देता है—

4 दिसम्बर, 1976 को मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र द्वारा राजशाही की घोषणा से केवल अफ्रीकी देशों में ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी पर्याप्त प्रतिक्रिया हुई है। इस घोषणा के अनुसार जून वेदेल बोकासा देश के सम्राट् होगे। सम्राट् बनने से पूर्व बोकासा देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री थे। सन् 1972 में उन्होंने देश के आजीवन राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। अब वह बोकासा से सत्ताहीन महमद बोकासा हो गए हैं। लोकतन्त्र में देश को राजशाही की ओर ले जाने का निर्णय पिछले दिनों सत्ताकण्ड मंसोन (काले घफ़ीरी आन्दोलन पार्टी) ने किया था। अभी तक अफ्रीकी देशों में उगांडा के ईदी अमीन को महत्वाकांक्षी माना जाता रहा है लेकिन बोकासा उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बधाई देने वाले लोगों में सबसे पहले व्यक्ति अमीन ही थे।

मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र पर कभी फ्रांसीसियों का अधिकार था। पिछले दिनों अफ्रीका की एकमात्र राजशाही इथियोपिया का अन्त हुआ था। अफ्रीकी देशों ने तब इस परिवर्तन को सही दिशा माना था, हालांकि जिस तरह से सम्राट् हेले सिलासी को सत्ता से हटाया गया था उस तरीके को अच्छा नहीं माना गया था, किन्तु हर देश की अपनी व्यवस्थाएँ और स्थापनाएँ होती हैं। उनके अनुसार ही वहाँ का शासनतन्त्र संचालित होता है। जहाँ तक अफ्रीकी देशों का प्रश्न है यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि प्राजाद होने के बाद इन देशों में लोकतन्त्र और बहुत हद तक ससदीय लोकतन्त्र की परम्पराएँ ही शुरू में कायम होती रही हैं। धीरे-धीरे एक कच्चीले और दूसरे कच्चीले में जब मतभेद बढ़ते चले जाते हैं तो नाते टूटने लगते हैं और इससे शासनतन्त्र की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है। अतः इन देशों में सैनिक क्रान्तियाँ और अस्थिरता कोई अनहोनी बात नहीं है।

जागरूक नेता—कुछ नेता जो अधिक जागरूक, सतर्क और चौकस थे, उन्होंने या तो देश में एकदलीय शासन प्रणाली कायम की या संविधान को अपने हितों के अनुरूप ढाल कर आजीवन राष्ट्रपति या राज्यध्यक्ष का पद प्राप्त कर लिया। लेकिन एक राज्याध्यक्ष द्वारा अपने आपको सम्राट् घोषित करने का कदम मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र ने ही उठाया है। इस तरह के भी अवसर आए हैं कि स्वयं को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने वाले नेताओं को केवल सत्ता से ही नहीं हटाया गया बल्कि उनका अन्त बड़े कठिन दौर में और अपने देश से बाहर हुआ। इसका उदाहरण घाना के राज्याध्यक्ष डॉ. क्वामे एक्रूमा हैं। नाइजीरिया से पहले बिफ्रा के अलगाव के प्रश्न पर पर्याप्त रक्तपात हुआ। इस दौर से पहले और इस दौर के बाद भी वहाँ राजनीतिक अस्थिरता कायम रही। पहले प्रधानमंत्री तफावा बालेवा की हत्या हुई, उसके बाद कर्नेल गोबोन जब सत्ता में आए तो जनरल ईरोसी की हत्या हुई।

गोवोन विग्रफा लड़ाई तो लड़ गए लेकिन बाद में जब उनकी जड़ मजबूत होने लगी तो जिस सैनिक शासन के बल पर वह सत्ता में आए थे उसी सैनिक बल ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। उगांडा के डॉ. मिल्टन ओबोटे को भी अपने विषय में कम भ्रम नहीं था। लेकिन उन्होंने के सेनाध्यक्ष जनरल ईदी अमीन ने उनकी अनुपस्थिति में सत्ता हथिया ली। उगांडा में भी स्वाधीनता के बाद राजशाही थी, लेकिन जब सन् 1966 में मिल्टन ओबोटे ने एडवर्ड मुतेसा से सत्ता छीनी तो उन्होंने राजशाही समाप्त कर दी। अफ्रीकी देशों में यदि कहीं स्थिरता दिखायी दे रही है तो वे देश हैं—जाम्बिया, जहाँ के राष्ट्रपति केनेथ काउंडा (24 अक्टूबर, 1964 से राष्ट्रपति) हैं, तांज़ानिया, जहाँ के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे (26 अप्रैल, 1964 से राष्ट्रपति) हैं और केन्या, जहाँ जोमो केन्याटा (12 दिसम्बर, 1964 से राष्ट्रपति) सत्ता में हैं। वंसे रक्तपात के दौर से जेयरे भी गुजरा है, लेकिन सन् 1966 से राष्ट्रपति मोयुनु के हाथ में निरन्तर शासन की वागडोर है। सन् 1970 में वह सात वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे। दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया दो ऐसे देश हैं जहाँ गोरानाही है। निस्सन्देह गोरानाही का अन्त करने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन उसकी समाप्ति बब होगी कह पाना कठिन है। स्थिरता के नाम पर मॉरिशस में भी 12 मार्च, 1968 से राजनीतिक स्थिरता है। वहाँ पर समझौते सरकार है, लेकिन 20 दिसम्बर, 1976 को जो चुनाव हुए हैं सम्भवतः वे राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं।

आसपास—मध्य अफ्रीका गणतन्त्र का क्षेत्रफल 6,25,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 2,080,000 (1970 का आँकड़ा) है। राजधानी बांगुई है जिसकी जनसंख्या 3,01,793 है। 13 अगस्त, 1960 को मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र को स्वाधीनता प्राप्त हुई। अफ्रीका के चार फ्रांसीसी राज्यों में मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र भी एक राज्य था। जनवरी, 1959 के अन्त्य तीन अफ्रीकी फ्रांसीसी राज्यों के साथ मिल कर आर्थिक और तकनीकी सघ का गठन हुआ। 20 सितम्बर, 1960 को मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया। पहले राष्ट्रपति डेविड डाका थे। जनवरी, 1960 में अपने चुनाव के बाद उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को भग कर दिया। जनवरी, 1965 में उनका पुनर्निर्वाचन हुआ। चुनाव मैदान में तब वह केवल एकमात्र उम्मीदवार थे। उस समय मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र चीनी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बना हुआ था। जनवरी, 1966 को मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र के सेनाध्यक्ष कर्नल जीन बेडेल बोकासा ने राष्ट्रपति डाका को सत्ताच्युत कर दिया। राष्ट्रपति बोकासा ने चीन से सभी तरह के राजनयिक सम्बन्ध-विच्छेद कर दिए। 8 मार्च, 1972 को वह देश के आजीवन राष्ट्रपति बन गए।

फ्रांस का प्रभाव—मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है। तब इसका नाम उबांगी शारी था। यह गिनी की खाड़ी के 350 मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र चैंड, सूडान, कांगो, जेयरे और कैमरून से घिरा हुआ है। इन देशों से घिरा होने के कारण यहाँ पर विस्थापितों की संख्या भी

काफी है—लगभग दोस हजार सूडान के और दो हजार कांगो के निवासी भी यहाँ रहते हैं। यहाँ की सरकारी भाषा फ्रांसीसी है लेकिन बांडा, मवाका जाँदे तथा माँदजीया बापा कबीलों के लोग माँगो बोली बोलते हैं। मध्य अफ्रीकी गणतन्त्र की प्रायः का मुख्य स्रोत होरा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की 20वीं वर्षगांठ, मार्च 1977

यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 25 मार्च को रोग मे अपनी 20वीं वर्षगांठ मनायी। इस अवसर पर सभी नौ सदस्य-देशों के प्रतिनिधियों ने समुदाय की गतिविधियों के लेखे-जोखे के अलावा समुक्त यूरोप की परिवर्तन पर भी विचार-विमर्श किया। ऐसी आशा की गई थी कि रोम सम्मेलन मे कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे समुदाय की गतिविधियों को एक नई दिशा मिलेगी, जिनसे समुदाय के देशों के पारस्परिक सम्बन्ध तो धनिष्ठ होंगे ही, अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे भी बड़ ठोस और प्रभावी आर्थिक-राजनीतिक भूमिका निभा सकेगा। किन्तु जो विज्ञप्ति प्रचारित की गई उसमे नया कुछ भी नहीं था, पुरानी नीतियों और आश्वासनों को ही दोहराया गया। समुक्त यूरोप की परिकल्पना को कोई मूर्तरूप देना तो दूर रहा, सदस्य-देश कोई ऐसा प्रमाण देने मे भी विफल रहे जिससे यह आश्वासन मिलता कि उनकी एकता अभग है। सच तो यह है कि 20 वर्ष पहले की रोग सन्धि के लक्ष्य की पूर्ति की सम्भावना तो पहले से कम दिखायी पड़ी।

समुदाय के सदस्य देशों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता ने रहते उनके नेताओं से किसी ठोस निर्णय की आशा भी नहीं की जा सकती थी। यदि यूरोपीय आर्थिक समुदाय को प्रभावी बनाना है तो यह आवश्यक है कि सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसी समुक्त यूरोपीय नीतियाँ तैयार करें जिनका पालन करने के लिए सभी सरकारें बाध्य हों और यदि समुदाय मन्त्रि-परिषद् किसी समझौते पर पहुँचने में विफल हो तो इस दशा मे न्यायालय में अपील करने का प्रावधान हो। रोम सम्मेलन में इस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं किया गया। जापान से व्यापार सम्बन्ध, इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन, कच्चे माल की उपलब्धि आदि पर भी समुदाय के दृष्टिकोण में कोई गवीनता नहीं है।

25 मार्च, 1957 की रोम-सन्धि का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि पश्चिमी यूरोप के सभी देशों को साम्राज्य बाजार में बराबर का अधिकार मिले। 20 वर्ष बीत जाने पर भी इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। आर्थिक समुदाय की गतिविधियों में अपना बर्तस्व बनाए रखने का प्रयास समुदाय के बड़े सदस्य-देश निरन्तर करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। रोम सम्मेलन में चार बड़ों—ब्रिटेन फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और इटली—ने छोटे सदस्य-देशों की बात प्रायः अनगुनी कर अपने इरादों को अभिभक्ति दी। वर्तमान में स्थिति यह है कि एक यूरोप के समर्थक तो बहुत हैं, किन्तु ऐसे यूरोप का नेतृत्व किसके हाथ में हो इसके लिए उनमें प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। जब तक यह स्थिति रहेगी, समुक्त यूरोप की स्थापना की दिशा में समुदाय कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकेगा।

शिखर सम्मेलन : सात बड़ों का मिलन, मई, 1977

7 और 8 मई, 1977 को लन्दन में सात गैर-कम्युनिस्ट देशों का शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। यह सम्मेलन कई तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है। पट्टली द्वार अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने अपने देश से बाहर जाकर किसी सम्मेलन में भाग लिया था। पट्टली द्वार ही कार्टर और पश्चिम जर्मनी के चांसलर हेल्मुट श्मिड्ट में बातचीत हुई थी। यूरोप में ही (जिनेवा) में कार्टर ने तीरिया के राष्ट्रपति हाकिम असद से लम्बी वार्ता की थी और पश्चिमी एशिया की समस्या का जायजा लिया था। कार्टरों मुस्कान की पूरे सम्मेलन में चर्चा रही। राजनीतिक टिप्पणीकारों का विचार है कि कार्टर की उपस्थिति से सम्मेलन में एक नई तरह की ताजगी थी जो पहले बहुत कम देखने सुनने को मिलती थी। शायद यही कारण था कि इस आर्थिक शिखर सम्मेलन में जो नियुक्त किए गए उन पर औद्योगिक और विकासशील देशों में अधिक तीखी प्रतिनिधिता नहीं हुई। जो विकासशील देश अधिक प्रसन्न भी नहीं थे।

इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य-देश थे—अमेरिका (जिम्मी कार्टर), ब्रिटेन (जेम्स केलेहन), पश्चिमी जर्मनी (हेल्मुट श्मिड्ट), फ्रांस (जिस्कार द एस्ते) जापान (फुकुदा), कनाडा (पियरे बूदो) और इटली (ग्रिन्डोनी)। इन देशों के नेताओं ने स्थिति का अवलोकन करते हुए महसूस किया कि सन् 1975 की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में अनाधिक गुंथार है। हुआ है यद्यपि किसी न किसी प्रकार के गम्भीर मामले हर देश के सामने रहे हैं। इस समय सबसे प्रमुख मुद्दा मुद्रा-स्फीति की दर को कम कर रोजगार के नए क्षेत्रों को ढूँढना था। मुद्रा-स्फीति पर नियन्त्रण का अभिप्राय बेरोजगारी को कम करना तो है लेकिन इससे उसका समूल विनाश नहीं हो पाएगा। यह बात भी अनुभव की गई कि सन् 1974 में तेल की मूल्यवृद्धि से पश्चिमी देशों की अर्थ-व्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था वह किसी न किसी रूप में अभी तक बना हुआ है और यही कारण है कि फालतू और कमी वाले देशों में तालमेल की बहुत आवश्यकता है। यह आवश्यकता है कि विभिन्न देशों की वृद्धि और स्थिरता के लक्ष्यों में परस्पर समन्वय बैठाया जाए।

मुख्य फैसले—ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स केलेहन ने आर्थिक शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों का हवाला देते हुए कहा—मुद्रा-स्फीति में कटौती के प्रयास और अधिक रोजगार की स्थितियाँ पैदा करना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राक्षय में अतिरिक्त माघन जुटाना ताकि सदस्य-देशों की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने की दिशा में कार्य किया जा सके; बहुपक्षीय व्यापार समझौते द्वारा व्यापार में वृद्धि करना, ऐसा होने से कुछ देशों के प्रति जो 'सरलात्मक रवैया' प्रभावित होता रहा है उसे समाप्त किया जा सकेगा। ऊर्जा के संरक्षण में निश्चित प्रयास तथा ऊर्जा के नए स्रोतों को विकसित करना, परमाणु ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक अध्ययन करना, लेकिन इस बात का स्थान रखा जाएगा कि परमाणु-हथियारों के उत्पादन की होड़ न लग जाए, विकासशील देशों को सहायता देने के लिए हर सम्भव प्रयास करना, एक अरब

डॉलर की एक विशेष निधि की स्थापना की गई है ताकि प्रतिनिधन देशों की सहायता की जाए और वे अपने ऋण के ब्याज का भुगतान कर सकें। इसके साथ ही इन गरीब देशों के उत्पादों जैसे काफी, टिन आदि की नियमित मुहैया करने के लिए समझौते भी शामिल हैं। इन समझौतों को कार्यरूप देने के लिए इन गरीब देशों की वित्तीय सहायता के लिए भी एक निधि की स्थापना करने का फैसला किया गया है। इस बात की भी कोशिश की जाएगी कि इन उत्पादनों के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय को नियमित करने की व्यवस्था की जाए।

ऊर्जा के सम्बन्ध में भी उपयोगी कदम उठाए गए। परमाणु प्रसार के सबूत को कम करते हुए परमाणु ऊर्जा की वृद्धि पर भी जोर दिया गया। इस परमाणु ऊर्जा के विकास का अर्थ गरीब देशों की सहायता करना है। सम्मेलन में यह भी महसूस किया गया कि सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ सहयोग करने के प्रयास किए जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों की तरह समाजवादी देशों का भी एक व्यापार समुदाय है जिसे 'कामिकान' कहा जाता है। 'कामिकान' के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी जोर देने की बात उठायी गई जिसे सभी देशों ने स्वीकार किया। इनके अलावा सात देशों के बीच अनुभव तथा नवीन तकनीकों का आदान-प्रदान किया जाएगा। युवा वर्ग को अधिक नुविद्याएँ प्रदान की जाएंगी। राष्ट्रपति कार्टर की मानवाधिकार सम्बन्धी नीतियों को मोटे तौर पर पुष्टि की गई।

मतभेद भी—प्रमुख मुद्दों की सहमति के बावजूद इन देशों के नेताओं में असहमति के पट भी दिखाई दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति जिस्कार द एस्तें ने कहा कि देशक गरीब और विकासशील देशों की सहायता के लिए विशेष निधि की स्थापना सम्बन्धी फैसले पर सहमति हो चुकी है लेकिन इससे इन देशों का काम भना होगा। सन् 1975 में उत्तर-दक्षिण के देशों में जो सवाद चल रहा है, यदि इस वर्ष के अन्त तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुँचता तो अमीर और गरीब देशों के बीच नेवल शका की परते ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि परस्पर मतभेदों की खाई भी चौड़ी होती चली जाएगी और इसमें गरीब देशों को एक 'मनोवैज्ञानिक भटका' लगेगा।

परमाणु अस्त्रों पर विचार—इस तरह का मतभेद परमाणु अस्त्रों के निर्माण और उनकी बिक्री के बारे में भी था। एक तरफ तो परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने की बातें की जाती हैं दूसरी ओर उनके निर्माण की गति में वृद्धि हो रही है। कार्टर-प्रशासन के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और रूस में जो 'साहट' बार्नि हुई है उसे सफल नहीं कहा जा सकता। इससे दोनों देशों के बीच 'दिल' के सम्बन्धों को भी आघात पहुँचा है। अमेरिका की मानवाधिकार की परिभाषा से सोवियत संघ क्रुद्ध हुआ है। इससे पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच जिस निकटता की बात की जाती रही है उसमें भी दरारें पड़ सकती हैं। यह तो सर्वविदित है कि पश्चिम जर्मनी द्वारा ब्राजील को परमाणु संपन्न दिया जाना अमेरिका को स्वीकार नहीं। इस विषय पर दोनों देशों में बहसुनी हो चुकी है। माना जाता है कि जब जिम्मी कार्टर ने हेलम्प्ट शिमिट के सामने यह मुद्दा रखा तो शिमिट ने कहा कि पुराने समझौते तोड़ने से

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी साख गिरेगी। केवल परमाणु समझौता ही नहीं टूटेगा बल्कि बहुत से ऐसे व्यापारिक अनुबन्ध भी टूट सकने हैं जो कई वर्ष पहले केवल जर्मनी और ब्राजील के बीच ही नहीं अन्य देशों के साथ भी हुए हैं। किन्तु इस बात पर सहमति थी कि परमाणु ऊर्जा के बिनाशकारी तरीकों पर रोक लगाने के लिए सभी देश मिलकर प्रयत्न करेंगे। फ्रान्स द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सयंत्र की जानकारी दिए जाने का भी हवाला दिया गया। इस समझौते को रद्द कराने के लिए भी अमेरिका के दबाव की आलोचना की गई। राष्ट्रपति कार्टर ने कहा कि निस्संदेह सभी देश परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के इच्छुक हैं लेकिन यह मसला बहुत ही जटिल होता जा रहा है। लिहाजा शिखर सम्मेलन ने एक समिति का गठन किया जो परमाणु प्रौद्योगिकी के सुरक्षात्मक प्रयोग के तरीकों का अध्ययन करेगी। इसका उद्देश्य आणविक क्षमताओं के प्रसार पर नियन्त्रण करना है, लेकिन उनके रक्षण आदि के रूप में या शान्तिपूर्ण प्रयामों के लिए प्रयोग करने वाले देशों को इन तकनीक से वंचित करना नहीं है। यदि कहीं किसी मुद्दे पर मतभेद था तो यही एक मुद्दा था।

बंसे नाटो की भूमिका के बारे में भी फ्रान्स और अमेरिका के तर्कों में सामंजस्य नहीं बैठा। कार्टर नाटो देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाने के इच्छुक हैं जबकि द एस्तें तटस्थता का खंबा ही अपनाए रखना चाहते हैं। नाटो के जिन 20 देशों के नेताओं ने लन्दन में विचार-विमर्श किया उनमें द एस्तें उपस्थित नहीं थे। कार्टर ने कहा कि यदि नाटो देशों को सैनिक रूप में शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तो वे सोवियत संघ की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लन्दन में इन वार्ताओं के बाद कार्टर ने जिनेवा में मोरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद से वार्ता की तो अन्य नेता अपने-अपने देशों को लौट गए। कार्टर ने अगद में वार्ता के बाद पश्चिमी एशिया की समस्या सुलभाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनियों को पृथक् राज्य दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा अनुमान है कि पश्चिमी एशिया के मामले पर जिनेवा में जो वार्ता होगी तब फिलिस्तीनियों की इस माँग पर विचार होगा।

(दिनमान, मई, 1977)

राष्ट्रकुल सम्मेलन, जून, 1977

सात जून से पन्द्रह जून 1977 तक राष्ट्रकुल देशों का 21वाँ शिखर सम्मेलन लन्दन में हुआ। 36 सदस्य-देशों में से 34 देशों ने इसमें भाग लिया—उगाडा और सेशेल्स उपस्थित नहीं हुए। उगाडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन की नीतियों के कारण उन्हें इस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, या यो कहिए कि उनका निरन्तर विरोध हुआ और सेशेल्स में जेम्स माशेम का तटता पलट जाने पर लन्दन में रहने हुए भी वह सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए। यह परामर्श उन्हें मारिमाग के प्रधानमन्त्री सर शिवसागर रामगुलाम ने दिया। वर्तमान राष्ट्रकुल सम्मेलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा कि जब 34 देशों के प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति लन्दन पहुँचे तो ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की सत्ता की रजत जयन्ती मना रहा था।

उद्घाटन भाषण—इस सम्मेलन में आकर्षण का मुख्य केन्द्र प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई थे। ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री जेम्स केलेहन के बाद वरिष्ठ सदस्य होने के कारण जाँविया के राष्ट्रपति केनेथ काउडा ने अपना भाषण दिया और उसके बाद मोरारजी देसाई को पहले दिन अपना भाषण देने का अवसर प्रदान किया गया। इस सम्मेलन में सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर खुल कर विचार हुआ। कभी-कभी गरमागरमी भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर वातावरण सद्भावना पूर्ण रहा। लंकास्टर हाउस में हुए इस सम्मेलन के अपने उद्घाटन भाषण में जेम्स केलेहन ने कहा कि अमीर और गरीब देशों के बीच व्याप्त खाई, दक्षिण अफ्रीका में फैलते हुए सघर्ष आदि समस्याओं का सामूहिक बुद्धिमत्ता द्वारा समाधान करना है। उन्होंने पेरिस में सम्पन्न उत्तर-दक्षिण सवाद का भी उल्लेख किया जिसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते थे। हम हमेशा यह तो कहते हैं कि हमें परस्पर-निर्भर रहना चाहिए, किन्तु अमीरों और गरीबों के बीच खाई और दूरी बराबर बढ़ती जा रही है। सवार की 65 करोड़ जनसंख्या नितात गरीबी में अपना जीवन बिताती है, उसकी वार्षिक आय 50 पाउंड प्रति व्यक्ति भी नहीं है। निस्संदेह यह हमारे युग और हमारे नेतृत्व को बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रकुल के विभिन्न भागों से सम्बन्ध रखने वाले हम सभी देशों को नितात गरीबी का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के साथ मिल बैठ कर उनके उद्धार की दिशा में कार्य करना है। ब्रितानी प्रधानमन्त्री ने सभी तरह के जातिगत भेदभावों की निन्दा करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में बहुसंख्यक लोगों के शासन की स्थापना सम्बन्धी समस्याओं का समाधान ढूँढना चाहिए। ब्रिटेन घोषणा करता है कि रोडेशिया और नामीबिया की समस्या का समाधान शीघ्र हो जाएगा। वास्तव में सारी अन्तर्राष्ट्रीय मानव शक्तियाँ इन देशों में बहुसंख्यक शासन स्थापना के लिए वचनबद्ध हैं। केलेहन के बाद केनेथ काउडा ने महारानी एलिजाबेथ की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यों और प्रयासों द्वारा इसे ब्रितानी राष्ट्रकुल के स्थान पर जन-राष्ट्रकुल का रूप दे दिया है।

दार्शनिक दृष्टिकोण—काउडा के बाद मोरारजी देसाई जब बोलने को खड़े हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूँज उठा। उन्होंने सभी समस्याओं को मिलजुल कर सुलझाने पर जोर देते हुए कहा कि समय के साथ और बढ़ती हुई उम्र के कारण उन्होंने दार्शनिक रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। अब तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि हम अपनी समस्याओं को सामान्य समस्याएँ समझ कर उनका हल ढूँढ़ें। ऐसा करने पर ही हम किसी परिणाम पर पहुँच सकेँगे वरना हमारी समस्याएँ बढ़ती चली जाएँगी। राष्ट्रकुल को संयुक्त राष्ट्र का 'लघु रूप' बताते हुए उन्होंने कहा कि कालांतर में यह संस्था वैचारिक मंच स्थापित करेगी जिसमें ससार के सभी विचारों को प्रतिबिम्बित किया जाएगा। विचारों के इस तरह बनने और उन पर विचार होने से ही हमें शक्ति मिलेगी और हम लोगों में एकता और भाईचारे की भावना विकसित होगी। श्री देसाई ने राष्ट्रकुल की भूमिका की पर्चा करते हुए कहा

कि विश्वयुद्ध के बाद चौकसी और सतर्कता का वातावरण बना था। उसमें हमारी सम्पत्ता में कुछ दरारें दिखने लगी थीं, हमें उन दरारों को भरना है ताकि विश्व को गरीबी और विनाश से बचाया जा सके। आज अमीर और गरीब मिलकर रहते हैं। उनमें गरीबी और अमीरी की समस्या नहीं, समस्या मानवता की है। मानवता को इस समस्या को हम अपनी लगन और ईमानदारी से सुलझा सकते हैं। हमें जातिवाद, नस्लवाद, धर्म आदि के अवरोधों और बधनी को तोड़कर एक ऐसे सप्तार का निर्माण करना चाहिए जहाँ परस्पर विश्वास और आस्था की भावना विकसित हो। ऐसा होने से हम उन्नति कर पाएँगे, नहीं तो चुनौती और विनाश के आतंक में हम अपना समय नष्ट कर देंगे। इसके लिए आज की सरकार और प्रशासन में अधिक खुलापन और उद्देश्यपूर्ण और-तरीका होना चाहिए। हमें अपने कार्यों को उचित ठहराते हुए लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। यह सब काम शान्ति से ही सम्भव है और निस्संदेह देर से इसमें हमें सफलता मिलेगी।

रामफल की कार्यसूची—प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के इस भाषण का इतना प्रभाव पड़ा कि अगले सभी वक्तव्यों ने उन्हीं के भाषण से उद्धरण दिए। अफ्रीकी समस्या को सुलझाने के लिए मोरारजी देसाई के भाषण का सहारा लिया गया तो अमीर और गरीब देशों के बीच व्याप्त खाई को पाटने के लिए भी श्री देसाई के विचारों की सराहना की गई। राष्ट्रकुल के महासचिव श्रीधर रामफल ने सदस्य-देशों के प्रति सम्मेलन की कार्यसूची प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन को कुछ गम्भीर और आवश्यक विषयों पर विचार विमर्श करना है। राष्ट्रकुल इस सकट कालीन विश्व में शान्ति ला सकता है। इस तरह की आशा कुछ समय पहले पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्त की थी।

परस्पर सम्बन्धों पर वार्ता—प्रधानमन्त्री श्री देसाई ने बंगलादेश के राष्ट्रपति जियाउर्रहमान से फरक्का तथा अन्य परस्पर समस्याओं पर दो बार वार्ता की। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमन्त्री पियरे ट्रूडो से भी प्रधानमन्त्री ने बातचीत की तथा परमाणु परीक्षण से उत्पन्न भारत और कनाडा में जो तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो गया था उस पर भी दोनों प्रधानमन्त्रियों ने विचार-विमर्श किया। इस बात की आशा हो चली है कि एक बार फिर भारत और कनाडा में सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे। आस्ट्रेलिया के प्रधानमन्त्री माल्कम फ्रैंजर से भी श्री देसाई ने बातचीत की। श्री देसाई का प्रस्ताव था कि एशियाई और यूरोपीय समुदायों को मिल बैठकर अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूँढना चाहिए। अन्य एशियाई देशों की तरह आस्ट्रेलिया को भी अपने कृषिजन्य उत्पादनों को यूरोपीय और विशेष तौर पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को खपाने में कठिनाई अनुभव हो रही है। इसके लिए उन्हें किसी विकल्प की खोज करनी होगी। मोरारजी देसाई ने सिंगापुर, मलेशिया और जर्मका के नेताओं से भी वार्ता की।

नाइजीरिया का आक्रोश—नाइजीरिया के विदेशमन्त्री प्रिमेडियर जे. एन. गार्वा ने एक वक्तव्य प्रसारित करके कहा कि रोडेसिया में एक ही तरीके से बहुसंख्यक

लोगों का शासन स्थापित हो सकता है और वह तरीका है सशस्त्र संघर्ष का। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन रोडेशिया को शान्तिपूर्ण ढंग से सत्ता हस्तान्तरण के लिए सहमत नहीं कर पा रहा है। उसकी इस असमर्थता के कारण रोडेशियाई क्षेत्रों में घुटन की भावना पैदा हो रही है। पिछले बारह वर्षों से ब्रिटेन निरन्तर प्रयत्न कर रहा है लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। विंगेडियर गार्वा ने यह घमकी भी दी कि यदि ब्रिटेन अपने वचन को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह राष्ट्रकुल की सदस्यता त्याग देगा। पिछले बारह वर्षों में इथान स्मिथ की सरकार राष्ट्रकुल की अन्तरात्मा को कचोट रही है और आखिर धैर्य की भी कोई सीमा होती है। बारह साल तक इस राष्ट्रकुल सम्मेलन ने प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अतः अब सशस्त्र संघर्ष के अनिर्दिष्ट और कोई विकल्प नहीं रह जाता। कैसे पिस रहे हैं उन्हें राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और अल्पसंख्यक गोरे उनकी इस स्थिति का उपहास करते हैं। इस तरह की स्थिति को हम राष्ट्रकुल-सदस्य-देश विश्व-शान्ति के लिए खतरा मानते हैं।

अन्य विषय—सिप्रस और बेलीज के बारे में भी चर्चा हुई। सम्मेलन में बताया गया कि बेलीज स्वाधीन होने के लिए तैयार नहीं। बेलीज ब्रितानी उपनिवेश है। बारबादोस के प्रधानमंत्री जे. एम. जी. आदम्स ने कहा कि बेलीज को तब तक स्वाधीनता प्रदान नहीं की जानी चाहिए जब तक उसका पड़ोसी देश ग्वाटेमाला उस पर अपना क्षेत्रीय दावा नहीं छोड़ देता। इसके अलावा यदि स्वाधीनता प्रदान करनी पड़े तो बेलीज को ग्वाटेमाला से होने वाले सम्भावित आक्रमण की दिशा में पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस मसले तथा ऐसे ही अन्य अनेक मसलों पर बाद में ब्रिटेन से बाहर अनौपचारिक तौर पर भी बातचीत हुई।

सिप्रस के राष्ट्रपति मकारियोस ने सिप्रस की स्थिति का ब्योरा देते हुए कहा कि तुर्क और यूनानी सिप्रियो में सरकारी स्तर पर बातचीत तो हुई है लेकिन अभी किसी परिणाम पर पहुँचा नहीं जा सका है। दो वर्ष पूर्व किंग्स्टन सम्मेलन में इस भूमध्यसागरीय द्वीप के बारे में जो आठ सदस्यीय समिति गठित की गई थी उसकी रपट भी सम्मेलन में पेश की गई। इस रपट पर भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से विचार-विमर्श हुआ।

इस सम्मेलन में दो देश प्रनुपस्थित रहे—सेशेल्स और उगांडा। सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मांशेम को एक वार्न्ति में सत्ताच्युत कर दिया गया और उनके स्थान पर एल्बर्ट रेने ने सत्ता सम्भाली लेकिन न रेने और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने लन्दन सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। जेम्स मांशेम लन्दन में मौजूद थे। सत्ता उलटने की घटना पहले भी हो चुकी है। आज से छह वर्ष पूर्व जब सिंगापुर में राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिल्टन ओबोटे गए थे तो ईदी अमीन ने उगांडा में उनका तख्ता पलट दिया था।

(दिनमान, जून, 1977)

अमेरिकी शस्त्र-नीति और भारतीय उपमहाद्वीप

रिटायर्ड कर्नल प्रार. रामाराव ने नवम्बर, 1977 के दिनमान में प्रकाशित

अपने लेख में इस बात का ऐतिहासिक और तार्किक वर्णन दिया है कि अमेरिका की शस्त्र-नीति किस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप की शान्ति को भंग करती रही है और इस प्रकार की नीति से निःशस्त्रीकरण के प्रयासों को कितना आघात पहुँचा है। वर्तमान कार्टर प्रशासन भारत के प्रति मंत्रीपूर्ण है और आशा की जानी चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिका अपनी शस्त्र-नीति के इतिहास को अब नहीं दुहराएगा। कर्नल रामाराव का मूल्यांकन इस प्रकार है—

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के दिनों में एक तकनीकी या सैनिक दृष्टि से उन्नत देश द्वारा शस्त्रास्त्र के इच्छुक देशों को उसकी आपूर्ति या इकार निश्चित रूप से इस तथ्य पर आधारित रहा है कि शस्त्रों की पूर्ति करने वाले देश की विदेश-नीति के उद्देश्य क्या हैं। इस मामले में निस्सन्देह महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण भी काम करता है, लेकिन जहाँ तक बड़ी शक्तियों का सम्बन्ध है शस्त्र आपूर्ति सम्बन्धी निर्णय अन्ततः विदेश-नीति के उद्देश्यों से नियन्त्रित होते रहे हैं। अमेरिका के एक भूतपूर्व प्रतिरक्षा मन्त्री क्लार्क क्लीफोर्ड ने सदन की विदेशी मामलों की समिति के समक्ष गवाही देते हुए यह घोषणा की थी कि सैनिक साज-सामान की विक्री का कार्यक्रम विदेश नीति के एक ठोस यन्त्र के रूप में ही जारी रखा जाएगा। विदेश उपमन्त्री पॉलवार्न ने इस विषय को कुछ अधिक स्पष्ट करते हुए कहा था—“हमारा काम है सैनिक साज-सामान की विक्री और सैनिक अनुदान कार्यक्रम के माध्यम से अमेरिका की विदेश-नीति को कार्यान्वित करना। हमारा मन्तव्य केवल हथियार देने के उद्देश्य से हथियारों को बेचना या देना नहीं है।”

सैनिक साजसामान के विक्रेता के रूप में अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश है। अमेरिका द्वारा भेजे जाने वाले कुल साज-सामान का एक बहुत छोटा अंश सैनिक सहायता के रूप में दिया जाता है, शेष के सम्बन्ध में विदेश-नीति के मुद्दे ही मुख्य कारक होते हैं। यह विदेश-नीति ही इस बात का फलदायी करती है कि एक खास देश को कितनी मात्रा में और किस किस प्रकार के हथियार दिए जाएँ।

भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में हाल में घटित घटनाओं के सन्दर्भ में इस उपमहाद्वीप को हथियार देने की नीति अत्यधिक रुचि का विषय होना चाहिए, भारत के लिए तो यह विशेष रूप से चिन्तनीय और महत्वपूर्ण है।

इस सदी के छठवें दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति ब्राइनहावर प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पाकिस्तान से सैनिक अड्डे बनाने की कुछ सुविधाएँ प्राप्त की जाएँ जिससे रूस और चीन की घटनाओं पर दृष्टि रखी जा सके। दूसरे उद्देश्यों में पाकिस्तान में अपने सैनिक सलाहकार रखकर वहाँ के प्रशासकों को अपने प्रभाव में लाना था। अमेरिका के साथ समझौता करने के पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य अमेरिका से प्रभावशाली सैनिक, राजनीतिक और आर्थिक सहायता प्राप्त करना था ताकि वह भारत से एक शक्तिशाली देश की हैसियत में बातचीत कर सके।

यद्यपि अमेरिका ने पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण की प्रक्रिया को पसंद नहीं किया, तथापि यह निश्चित है कि वह यह चाहता था कि भारत यदि कश्मीर का पूरा भाग नहीं तो कुछ पाकिस्तान को अवश्य दे दें। सन् 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के बाद जब सन् 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब अमेरिका के नीति नियोजकों के मन में दक्षिण एशिया के प्रश्न पर इसलिए चिन्ता हो गई, क्योंकि आक्रमण से वस्तु भारत के लिए रूस के अधिक निकट पहुँचने की सम्भावना बढ़ गई थी। इस स्थिति के कारण उपमहाद्वीप सम्बन्धी अमेरिकी नीति की पुनः समीक्षा हुई। इस समय तब अमेरिका के लिए पाकिस्तान के इस्तेमाल का महत्व काफी कम हो गया था। कारण यह था कि अमेरिका ने उपग्रह तकनीक में काफी प्रगति कर ली थी और वह पेशावर को प्रहड़ा बनाए बिना भी अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकता था। इसके अलावा अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो दिलचस्पी थी उसके महत्वपूर्ण परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह उपमहाद्वीप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था यद्यपि इसके बावजूद उसने दक्षिण एशिया को युद्ध और अशान्ति से मुक्त रखना चाहा। इसी तर्क के आधार पर उसने सन् 1965 में भारत और पाकिस्तान को हथियार देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस प्रतिबन्ध का वास्तव में भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भारत ने उसके पहले के वर्षों में अमेरिका से हथियार लिए ही नहीं थे। लेकिन अमेरिका की यह नीति उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हुई क्योंकि इसके कारण उसे विधिवत् यह कहने का अवसर मिल गया कि अमेरिकी स्रोतों से संचार सम्बन्धी उपकरण भी भारत को नहीं मिल सकेंगे। इस निर्णय के पीछे निश्चित रूप से यह तथ्य भी था कि अमेरिका ने आक्रान्ता को भारत के समक्ष रख दिया। निश्चय ही अमेरिका ने वास्तविक स्थितियों पर अर्थात् पाकिस्तान के आक्रामक होने की दृष्टि से समस्या पर विचार नहीं किया।

पाकिस्तानी दृष्टिकोण से अमेरिका का यह निर्णय उसके लिए बहुत ही हानिकारक था क्योंकि उस निर्णय के अनुसार आधुनिक हथियारों की आपूर्ति का स्रोत समाप्त हो गया, इसके साथ ही समाप्त हो गया खुला राजनीतिक समर्थन। जो भी हो, पाकिस्तान के तत्कालीन विदेशमंत्री भुट्टो ने राष्ट्रपति अय्यूब द्वारा उन्हें मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित किए जाने के बाद से ही, पाकिस्तान को अमेरिका से विलग न कर चीन और रूस से निकटता का सम्बन्ध बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। उठवें दशक के मध्य में मुहम्मद यूसुफ बोहर चीन गए थे और वहाँ पर चाऊ-एन-लाई से एक प्रकार का समझौता हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि यदि पाकिस्तान कोई भी भारत विरोधी रवैया अपनाता है तो उसमें उसे चीन का समर्थन प्राप्त होगा। पाकिस्तान को रूस के कुछ अधिक निवृत्त ने जाने के पीछे भुट्टो का उद्देश्य हथियारों की प्राप्ति के अलावा रूस को भारत का पूर्ण समर्थन करने से रोकना था।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्री भुट्टो को इन दोनों ही मामलों में सफलता मिली। उनके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान को रूस से 225 टी-एन 4/55

किस्म के टैंक और पदाति सेना तथा तोपखाने में प्रयुक्त होने वाला साजसामान मिला। इसी समय चीन ने भी काफी बड़ी मात्रा में पाकिस्तान को सैनिक साजसामान दिया, जैसे टैंक, तोप और बन्दूकें, बमबर्षक हवाई जहाज, निगरानी करने वाली तेज रफ्तार की नावें और पदाति सेना के दो तीन डिवीजन बनाने के लिए पूरा साजसामान। यह स्थिति ठीक मन् 1965 के बाद की थी। सन् 1968-69 तक पहुँचते-पहुँचते उसने सैनिक साजसामान की अपनी मारी क्षतिपूर्ति कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान के शासकों ने अमेरिका से और अधिक हथियारों की माँग की ताकि उसके साथ-साथ पाकिस्तान की स्वतः राजनीतिक समर्थन भी मिल सके। अमेरिका में डेमोक्रेटिक दल का प्रशासन समाप्त हो चुका था और उसकी जगह पाकिस्तान के समर्थन तथा भारत के प्रति अपने दुराग्रहपूर्ण रव्ये के लिए विख्यात रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति पद सम्भाल लिया था। इसके साथ ही उसूरी की घटनाओं को लेकर चीन और रूस के बीच बढ़ते हुए सघर्ष ने राष्ट्रपति निक्सन को यह अवसर प्रदान किया कि वह चीन के साथ निकट सम्बन्ध बढ़ाने के लिए कुछ ठोस बरदम उठाए। इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को भी अपनी भूमिका निभानी थी और प्रपवाद स्वरूप निक्सन ने हथियारों पर प्रतिबन्ध के पुराने निर्णय के बावजूद पाकिस्तान को बन्दूकों और टैंकों के रिसाले के अतिरिक्त पदाति के लिए तीन सौ गाड़ियाँ और एक स्क्वेड्रन के लिए बमबार हवाई जहाज दिए। पाकिस्तान को यह साजसामान मुद्रिन मूल्य के 15 प्रतिशत पर ही दिया जाने वाला था जिसे अमेरिकी सेना ने पुराना, पिछड़ा हुआ या रद्दी मानकर अपने उपयोग के लिए अयोग्य ठहरा दिया था यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों की दृष्टि से ये हथियार और साजसामान बहुत आधुनिक और प्रभाव-शाली थे।

सन् 1971 की घटनाएँ अब इतिहास बन चुकी हैं। उसके बाद के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप को सैनिक हथियार और साजसामान देने की अमेरिकी नीति में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसने अलग-अलग मामलों के आधार पर पाकिस्तान को हथियार देने या न देने का निर्णय किया। यह निर्णय भी किया गया कि ये हथियार सैनिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत न दिए जाकर नकद बेचे जाएँगे। सिद्धान्त रूप में भारत को हथियार देने का आधार भी यही होगा, हालाँकि वास्तव में अमेरिका भारत को उच्च तकनीक वाले मारक प्रभाव के हथियार नहीं देगा।

इस काल में पश्चिमी एशिया के कुछ देशों के अलावा पाकिस्तान को हथियार देने वालों में चीन एक प्रमुख देश रहा है। इन आपूर्तियों का पाकिस्तान ने कई कारणों से स्वागत किया। इनके कारण हथियार देने वाले देशों को राजनीतिक समर्थन देने की पाकिस्तान की दिलचस्पी बनी रही। इसी के कारण पाकिस्तान को अपने पड़ोसी से समझौते की बातचीत में अपनी स्थिति को श्रेष्ठ साबित करने का अवसर मिलता रहा। भूटो को देश की आन्तरिक स्थिति को स्थायित्व देने में सहायता मिली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन हथियारों को प्राप्त करने में चीन के सम्बन्ध में नकद भुगतान का भार नहीं था। इसका एक कारण यह भी

था कि चीन हमेशा यह कहता रहा कि वह हथियारों का व्यापारी नहीं है अतः मित्रों और सहयोगियों को जो भी हथियार दे रहा है वे उपहार स्वरूप हैं। दूसरी तरफ कुछ पश्चिम एशियाई देशों ने अपने यहाँ से 47/48 टैंक, एक 86 सेंवर जैट हवाई जहाज तथा दूसरे उपकरण पाकिस्तान को दिए। ये चीजें उन्हें पहले उत्पादक देशों से मिली थी लेकिन जब उन्हें अपनी सेनाओं के लिए अधिक आधुनिक टैंक और हवाई जहाज प्राप्त हो गए तो उन्होंने पुराना माल ऋण मूल्य पर पाकिस्तान को दे दिया।

अक्टूबर, 1973 को योम किप्पूर युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आ गया। तेल की कीमतों में चौगुनी वृद्धि हो जाने के कारण पश्चिम के औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था को प्राथमिक झटका लगा था। लेकिन इससे सम्भलने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे प्रभाव-शाली उपाय ढूँढ निकाले जिससे तेल की बढ़ी हुई कीमत के कारण खर्च किए हुए डॉलर दूसरे माध्यमों से वापस आ जाएँ। इस तरीके में बड़े पैमाने पर हथियारों की बिक्री शामिल थी। इस प्रकार पश्चिम एशियाई देशों को सन् 1973-74 में लगभग तीन अरब डॉलर मूल्य के जो हथियार प्रदान किए गए, उनका सन् 1976-77 में मूल्य घाठ घरब से भी ऊपर पहुँच गया। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे दूसरे पश्चिम यूरोपीय देशों ने भी उसी प्रनुपात में पश्चिम एशियाई देशों को हथियारों की बिक्री बढ़ा दी। तकनीकी रूप से उन्नत इन देशों के हथियार अत्यन्त आधुनिक थे। कुछ मामलों में तो ये हथियार उन्होंने अपनी सेनाओं तक में सामान्य उपयोग के लिए नहीं दिए थे।

कई पश्चिम एशियाई देशों ने, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का आयात किया था, अपने यहाँ पाकिस्तानियों को परामर्शदाता या तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया ताकि वे इन नए हथियारों का रख-रखाव कर सकें और उनके यहाँ के तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण आदि में सहायता दे सकें। इन देशों में नए और उन्नत किस्म के आधुनिक हथियारों के आ जाने के बाद पुराने किस्म के जो हथियार निरर्थक और अनुपयोज्य ठहरा दिए गए थे वे पाकिस्तान को दे दिए गए।

इसी के साथ एक प्रमुख पश्चिम एशियाई देश ने आधुनिक ईंधन तय्यार लगाने तथा आधुनिक हवाई जहाज खरीदने के लिए पाकिस्तान को बहुत उदार शर्तों पर ऋण दिया। इस प्रकार अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति पर जो रोक लगाई थी उसका पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरे माध्यमों से पाकिस्तान में हथियारों का आना जारी रहा और वह भी पहले की तुलना में ज्यादा तेज रफ्तार के साथ। इस प्रकार 1966 और 1972 के बीच पाकिस्तान को चीन से 270 टी-59 टैंक, 154 मिग, 19 बमबार लड़ाकू हवाई-जहाज, 4 आई एल-28 बमबार प्राप्त हुए। रूस ने उसे 225, टी-55 किस्म के टैंक देने के बावजूद पर 170 टैंक और कुछ भारी किस्म के हेलिकॉप्टर प्रदान किए। इटली से उसे एम-47 किस्म के मरम्मत किए गए 100 टैंक, फ्रांस से 70 मिराज-315 बमबार लड़ाकू जहाज, पश्चिमी जर्मनी और ईरान से 90 एफ-86 हवाई जहाज उपलब्ध

हुए। 1974 में स्वीडन से उसे 47 एम. एफ-2, ईरान से 40 एफ-5 और गुर्दान से 7 एफ-5 हवाई जहाज मिले। विश्वास किया जाता है कि 1974 के बाद चीन ने उसे 250 टी-59 टैंक, 70 मिंग, 19 हवाई जहाज और 18 तेज गति वाली निगगनी नावें और मशीन बनाने का कारखाना खोलने के उपकरण दिए। कुछ लोगों का कहना है कि टैंकों की संख्या 500 है। अमेरिका ने 300 एम-113 किस्म के सैनिक वाहन दिए। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 1970-71 में ही इसकी मांग की थी जिसे न केवल अमेरिका ने स्वीकार कर लिया था बल्कि उसका भुगतान भी ले लिया था। इसी के साथ-साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 विध्वंसक तथा संचार और पूर्ण चेतावनी वाले उपकरण भी दिए।

फोर्ड-कीसिंगर प्रशासन के अन्तिम दौर में कीसिंगर ने यह कोशिश की थी कि श्री मुट्टो 110 ए-7 किस्म के आक्रमण कोसैयर हवाई जहाज लेना इस शर्त पर स्वीकार कर लें कि आणुविक ईंधन बनाने के लिए प्राप्त से सम्बन्ध लेने के समझौते को रद्द कर दें। मुट्टो ने यह शर्त स्वीकार कर ली थी, लेकिन इसके पहले कीसिंगर मुट्टो पर और दबाव डाल सके, फोर्ड प्रशासन समाप्त हो गया और कार्टर ने राष्ट्रपति पद सम्भाल लिया। श्री कार्टर न केवल आणुविक हथियारों के प्रसार के घोर विरोधी हैं, बल्कि वह तीसरी दुनिया के देशों में अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति के भी विरुद्ध हैं। अतः पाकिस्तान को प्रस्तावित आक्रामक हवाई जहाज देने की योजना रद्द कर दी गई। श्री कार्टर ने इसके सम्भावित दुष्परिणामों को अच्छी तरह महसूस कर लिया था।

पाकिस्तान को ए-7 आक्रामक हवाई जहाज देने के प्रस्तावित निर्णय को स्वीकृति न देने की घोषणा के तुरन्त बाद ही अमेरिका स्थित पाकिस्तान समर्थकों ने अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी। 1970 और 1972 में प्रायः एक तर्क दिया जाता था कि पाकिस्तान मित्रविहीन है, उसका भयभीत होना वास्तविक है। उसकी सेना के पास जो हथियार हैं वे अब बेकार हो चुके हैं और वे पर्याप्त भी नहीं हैं। उसकी आन्तरिक स्थिरता कायम रखने और एकता की सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिका को प्रतिवार्य रूप से अस्त्र-शस्त्र देने चाहिए। राष्ट्रपति कार्टर की घोषणा के तुरन्त बाद अमेरिका के बुद्धिजीवियों और कुछ अन्य लोगों की सहायता से उन्होंने पुनः यही तर्क प्रस्तुत किया। इन तर्कों की इन रण में भी पुष्टि की गई कि पाकिस्तान के पास उसकी आवश्यकता से कम शस्त्रास्त्र हैं और उसकी शक्ति पहले की अपेक्षा घटी हो चुकी है। यही तर्क अभी हाल में अमेरिका के एक विद्वान् प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफेन कोहेन द्वारा भी दिया गया था। किन्तु यह तर्क वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि स्वयं जुल्फिकार अली भुट्टो के ही अनुसार पाकिस्तान की सेना न केवल 1971 की तुलना में अधिक शक्तिशाली है बल्कि उसकी प्रतिबद्धताएँ भी पहले की अपेक्षा कम हैं। इसके अलावा अब पाकिस्तान का शस्त्र उद्योग काफी विनियमित हो चुका है और वह अब काफी हद तक आत्मनिर्भर है। चीनो टैंकों और हवाई जहाजों की मरम्मत की सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं और इस रूप में पाकिस्तान सैन्य उपकरणों के

उत्तम उपयोग में सक्षम है। पाकिस्तान के अमेरिकी समर्थकों ने ए-7 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू जहाजों की आपूर्ति का आग्रह नहीं किया था बल्कि इससे कम शक्ति के ए-4 और एफ-5 हवाई जहाज देने की बात कही थी। ये हवाई जहाज अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम में प्रयुक्त किए गए थे और वे भी बहुत प्रभावकारी माने जाते हैं। यदि ये हवाई जहाज पर्याप्त संख्या में पाकिस्तान को दिए जाते हैं तो पाकिस्तानी वायु सेना पूरे वायु क्षेत्र पर अपनी वरिष्ठता चाहे स्थापित न कर सके, इच्छित वायु क्षेत्रों पर तो निश्चित रूप से हावी हो सकती है।

अमेरिका की सैनिक लॉदी पाकिस्तान की सैनिक शक्ति की स्थिति के खराब होने और उसके कारण उसके कमजोर होने का जो तर्क देती है, वह भी निराधार है। इसका स्पष्ट प्रमाण जनरल जिया-उल-हक का हाल में ही दिया गया वह धक्कथप है जो उन्होंने पाकिस्तान की घटनाओं के सम्बन्ध में श्री जगन्नीवनराम द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के उत्तर में दिया था। जनरल जिया-उल-हक ने लाहौर के एक समाचार-पत्र को दी गई एक मॅटदास्ती में यह स्वीकार किया था कि भारतीय नेताओं का यह भय वास्तविक है कि पिछले वर्षों में दोगो देशों के बीच युद्ध का कारण उस समय का पाकिस्तान का सैनिक प्रशासन था और आज का पाकिस्तान का सैनिक प्रशासन भी वैसे ही रह सकेगा। जिया-उल-हक के कथन में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि पाकिस्तानी सेना को देश की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिक शस्त्रास्त्र की वास्तविक आवश्यकता है।

अपनी आन्तरिक सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चय ही पाकिस्तान को शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है, न कि बड़े पैमाने पर आधुनिक किस्म के आक्रामक हवाई जहाजों, हवा के मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों, टैंकों, और इलेक्ट्रॉनिक युद्धास्त्रों से चलाए जाने वाले बमों की।

कुछ अमेरिकी बुद्धिजीवियों का पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र देने का तर्क राष्ट्रपति कार्टर की इस नीति के विरुद्ध भी है कि तीसरी दुनिया में पारस्परिक किस्म के खर्चीले शस्त्रास्त्र की आपूर्ति को नियन्त्रित किया जाना चाहिए। उन बुद्धिजीवियों का तर्क यदि सकारात्मक होता है तो उसके परिणामस्वरूप भारत के लिए खतरा बढ़ जाएगा जो अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की प्रगति में सलग्न है। इसके कारण पाकिस्तान के भीतर भी तनाव पैदा होगा और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा।

अफ्रीका : घघकता ज्वालामुखी

महाशक्तियों को अपना शीतयुद्ध जारी रखने के लिए कोई न कोई ठिकाना चाहिए तनावपूर्ण यूरोप, तबाह वियतनाम, दिग्भ्रमित पश्चिमी एशिया, अस्थिर लातीनी अमेरिका, विशुब्ध हिन्द महासागर, अविश्वासप्रस्त भारतीय उपमहाद्वीप आदि उनके शीतयुद्ध के ही तो परिणाम हैं जिसे वे सारे सतार को अपने बीच बाँटने के लिए लड़ रहे हैं। महाशक्तियों—अमेरिका, सोवियत संघ और चीन का प्रबल ताजा लक्ष्य है अफ्रीका जहाँ के देश स्वाधीनता के नवविहान के साथ ही औपनिवेशिक शासकों

के कुचक में फँसकर आपसी झगड़ों में उलझ गए थे—फिर चाहे वह अल्जीरिया की समस्या रही हो या काँगो की, नाइजीरिया का गृहयुद्ध रहा हो या अंगोला का दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच का संघर्ष रहा हो या रोडेशिया का, सर्वत्र इन बड़ों ने और इनके कुछ पिछलग्गुओं ने गमं तबे पर अपनी रोटी सेकी और उगाड़ा, इथियोपिया, सोमालिया आदि में राज भी वे यही कर रहे हैं।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया को छोड़कर शेष अफ्रीकी देशों में अमेरिका और उसके मित्र-देशों की पकड़ ढीली पड़ गई है, किन्तु यह भी एक तथ्य है कि इस नई स्थिति से साम्यवादी गुट ने लाभ उठाने में कोई श्रुण नहीं की। सोवियत संघ और चीन ने, जहाँ जिसको सुविधा मिली अफ्रीकी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने का अथक प्रयास किया।

चीन ने 1162 मील लम्बे उन दुहरे रेलमार्ग (जो तानजाम रेलमार्ग के नाम से जाना जाता है) का निर्माण किया जिसका बनाना पश्चिम के विशेषज्ञों के अनुसार 'असम्भव' था और विश्व बैंक, अमेरिका, ब्रिटेन आदि सब की ओर से निराश होकर कैनेथ वाउण्टा (जाम्बिया) और जुलियम न्येरेरे (तनजानिया) ने चीन का दामन पकड़ा। चीन ने उन्हें निराश नहीं किया। घन और जन की सहायता देकर उसने जाम्बिया की समुद्र तट तक अपना तौबा पट्टंचाने के लिए यह वैकल्पिक मार्ग दिया।

चीन ने मात्र छह वर्षों के (1970 में काम आरम्भ हुआ और 14 जुलाई, 1976 को यह रेलमार्ग जाम्बिया की और तनजानिया की जनता को समर्पित कर दिया गया) अल्प समय में ही असम्भव को सम्भव कर दिया और जिस अफ्रीका में उसके पाँच जमाने की दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं थी वहाँ कुण्डली मार कर बैठ गया।

इस सफलता के बाद चीन अन्य दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के लिए अफ्रीका में एक प्रबल चुनौती बन कर उभरा और अब ये तीनों देश अफ्रीकी लोगों के मन पर उनकी भूमि, वन्दरगाहों, प्राकृतिक सम्पदा और उनके होने वाले मुनाफों पर अपना-अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं।

अफ्रीका में सोवियत संघ का हस्तक्षेप चीन से बहुत पहले शुरू हो गया था। सोमालिया से उसका सम्बन्ध कोई 17 वर्ष पहले स्थापित हुआ था और राज भी उनके बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है। मिस्र, सूडान और दक्षिण यमन से भी उसके अच्छे सम्बन्ध रहे हैं। सन् 1971 में मिस्र से उसके सम्बन्ध प्रबल्य तनावपूर्ण हो गए थे किन्तु अब फिर सुधार आरम्भ हो गया है जिसका बहुत कुछ श्रेय मुद्दान के राष्ट्रपति कर्नल नुमेरी और जेरे के राष्ट्रपति मोडुबू को है।

इनके प्रयास से ही हाल में दोनों देशों के बीच सम्पर्क स्थापित हुआ। मिस्र के उपप्रधानमन्त्री और विदेशमन्त्री इस्माइल फाहमी जून के दूसरे सप्ताह में सोवियत संघ की यात्रा पर गए और निकट भविष्य में सोवियत विदेशमन्त्री ग्रोमिको काहिरा की यात्रा करने वाले हैं।

पिछले वर्षों में अफ्रीका में सोवियत सघ के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई है। क्यूबा के माध्यम से उसने अंगोला में सशस्त्र हस्तक्षेप द्वारा जो सफलता प्राप्त की उससे उसका हौसला बड़ा है। हाल में क्यूबा के किडेल कास्त्रो ने उगाण्डा को एक सैनिक मिशन भेजकर स्वेच्छाचारी ईदी अमोन की सरकार से भी सम्बन्ध स्थापित करने की पेशकश की है। बताया जाता है कि कास्त्रो के इस प्रयास के पीछे सोवियत सघ का हाथ है। सोवियत सघ द्वारा इथियोपिया के शासक ले. कर्नेल मेगिस्तू हैले मरियम का समर्थन किया जाना भी एक चौकाने वाली घटना है क्योंकि इथियोपिया के सम्बन्ध उन सभी देशों के साथ तनावपूर्ण है जो सोवियत सघ के मित्र हैं या जिन्हें मित्र बनाने के लिए वह प्रयास कर रहा है। इनमें प्रमुख हैं सोमालिया, मिस्र, सूडान और उगाण्डा।

जहाँ तक अमेरिका का सम्बन्ध है कुछ वर्ष पहले तक वह स्वयं को अफ्रीका का भाग्यविधाता मानता था क्योंकि प्रायः सारा अफ्रीका किसी समय उसके मित्र-देशों ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के अधीन था और स्वाधीन होने के बाद भी अपने औपनिवेशिक शासकों पर अफ्रीकी देशों की निर्भरता कायम रही। सन् 1973 में अंगोला की स्वाधीनता और तदुपरान्त वहाँ छिड़ने वाले गृहयुद्ध में क्यूबा और सोवियत सघ की निर्णायक भूमिका ने अमेरिका का अफ्रीका के प्रति मोहभंग कर दिया और वहाँ सोवियत सघ और चीन के प्रभाव विस्तार को रोकने के लिए नए सिरे से सोचने पर विवश हुआ।

अफ्रीका के प्रति नई विंता अमेरिका में ही पैदा नहीं हुई, सोवियत सघ और चीन ने भी अपनी व्यूह रचना को नए आयाम दिए। उगाण्डा और इथियोपिया से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने की सोवियत सघ की आकांक्षा स्पष्ट है, उसने हाल में चीन के प्रभाव वाले तनज़ानिया से भी मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया है। इससे चीन का सतर्क होना स्वाभाविक ही है क्योंकि वह अब भी सोवियत सघ को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। नव चीन समाचार समिति ने पिछले दिनों यह आरोप लगाया था कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में लिब्रेरिये में हुए अफ्रीकी एकता सगठन के 14वें अधिवेशन के बाद से दोनों महाशक्तियों का, विशेषकर सोवियत सघ का अफ्रीका में हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। उसके अनुसार अफ्रीका की स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए सोवियत सघ की ओर से गम्भीर खतरा है। नवचीन समाचार समिति के इस आरोप में यह ध्वनि निकलती है कि अफ्रीका में सोवियत सघ के प्रभाव को रोकने के लिए चीन द्वारा अमेरिकी नीति का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष समर्थन किया जा सकता है।

अफ्रीकी जनमत की उपेक्षा करके सोवियत सघ और क्यूबा जिस प्रकार उगाण्डा, लीबिया और इथियोपिया से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं उससे जहाँ विश्व का ध्यान पश्चिमी एशिया से हट कर अफ्रीका की घटनाओं पर केन्द्रित हुआ है, वहाँ उससे यह संकेत भी मिल रहा है कि आने वाले दिनों में महाशक्तियों के बीच एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो सकती है कि इनमें शत्रु-मित्र की पहचान करना कठिन हो जाएगा—कहीं चीन और अमेरिका मिलकर सोवियत सघ का

प्रतिरोध करते देखे जाएँ को कही अमेरिका और सोवियत संघ, चीन के विरुद्ध खड़े दिखाई देंगे ।

पूर्वी अफ्रीका में इसके कुछ प्रमाण खोजे जा सकते हैं । सोमालिया के मार्क्स्वादी शासन की 17 वर्ष पुरानी मंत्री के बावजूद इस वर्ष फरवरी में सोवियत संघ ने इथियोपिया के नव सैनिक नेता ले फर्नल मेगिस्तू को समर्थन देने का फैसला किया जिसका अमेरिका से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और जिसके कारण उसकी अपने पड़ोसी सोमालिया, मिस्र और सूडान से कभी नहीं पटी । सोवियत संघ की इस नीति का एक स्वाभाविक परिणाम यह सामने आया है कि जहाँ एक ओर चीन से प्रोत्साहन पा कर सऊदी अरब, सूडान, यमन, अरब गणराज्य और मिस्र ने इथियोपिया के विरुद्ध 'पवित्र गठबन्धन' किया जबकि दूसरी ओर के गठबन्धन में सोवियत संघ, क्यूबा, लीबिया, इथियोपिया और एक हद तक इजरायल भी शामिल है । इन विपक्ष गठबन्धनों के पीछे मात्र यह सिद्धान्त है कि अपने शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है ।

इन गठबन्धनों ने सोवियत संघ के दो विश्वस्त मित्र, दक्षिणी यमन और सोमालिया को दिग्भ्रमिन् कर रखा है । इथियोपिया से उनके सम्बन्ध कभी अच्छे नहीं रहे । सोमालिया और इथियोपिया तो आज भी सीमा-विवाद में उलझे हुए हैं । सोमालिया स्वयं को इथियोपिया का समर्थन करने की स्थिति में नहीं पाता और न ही आर्थिक कारणों से वह फिलहाल सोवियत संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने की स्थिति में है ।

जहाँ तक सोवियत संघ का प्रश्न है उसने अपने इरादे इस वर्ष के शुरू में स्पष्ट कर दिए हैं । वह सोमालिया की विवशता को जानता है और इसलिए वह इथियोपिया से, जो फरवरी, 1974 से उत्तरोत्तर अमेरिका के विरुद्ध होता जा रहा है और 25 अप्रैल को अमेरिकी अर्सेनिक कर्मचारियों को निष्कासित करके जिसने अमेरिका से अपने 30 वर्ष पुराने सम्बन्ध तोड़न का विचार व्यक्त कर दिया है, मित्रता स्थापित करने में कोई चतुरा नहीं मानता है । लालसागर पर प्रभुत्व स्थापित करने और हिन्द महासागर में अमेरिकी प्रभाव की काट के लिए इथियोपिया की मित्रता को वह अधिक उपयोगी मानता है । सोमालिया के बेरबेरा बंदरगाह में उसे जो नौसैनिक सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं अगर उनसे उसे हाथ धोना भी पड़ा तो इथियोपिया के मस्मावा और अस्ताव बंदरगाहों से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी । सम्भवतः यही कारण था कि 4 मार्च को मस्वावा में ले. कर्नेल मेगिस्तू का भव्य स्वागत किया गया और इथियोपिया को क्यूबा के माध्यम से भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र प्रदान किए गए । इसी सन्दर्भ में जिबूती और अस्मारा में जो क्रमशः इथियोपिया के एकाई और इस्सास तथा इरीट्रिया प्रदेशों की राजधानियाँ हैं, जिबूती गत 27 जून को स्वाधीन हो गया और अस्मारा पर इन दिनों सरकार विरोधी गुट का नियंत्रण है उसकी दिलचस्पी भी सहज ही समझ में आने वाली है ।

सोवियत संघ के इथियोपिया प्रेम के बावजूद ऐसा लगता है कि सोमालिया

पश्चिमी गुट में शामिल हो जाएगा। उसे अपने सघर्ष में सूझाने, मिस्र और सऊदी अरब की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त है जिसका कारण इथियोपिया से इन देशों के सम्बन्ध मधुर न होना है। वह इनका दामन भी पकड़ सकता था, परन्तु मिस्र और सोवियत संघ के बीच सम्बन्ध सुधरने के बाद की स्थिति क्या होगी, यह भी वह जानता है। वह यह भी जानता है कि सोवियत सहायता से उसने अपनी आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को जो रूप दिया है उसे रातों रात बदला नहीं जा सकता, इसलिए सम्भावना यही है कि फिलहाल वह धैर्य से काम लेगा।

किन्तु इससे अफ्रीका एक व्यापक सफट से उतर नहीं सकता। वस्तुस्थिति यह है कि अफ्रीकी एक दोमुँहा ज्वालामुखी बना हुआ है—उसका एक मुँह रोडेजिया, दक्षिण अफ्रीका है जहाँ काले अफ्रीकियों और उनके अल्पसंख्यक गोरे शासकों के बीच का सघर्ष कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है दूसरा मुँह पूर्वी अफ्रीका है जहाँ किसी भी पक्ष की मामूली सी भूल से विस्फोट हो सकता है।

पूर्वी अफ्रीका में वर्तमान स्थिति की गम्भीरता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि भूमध्य-सागर से लेकर हिन्द महासागर तक का और लालसागर से केन्या की उत्तरी सीमाओं तक का सारा क्षेत्र इन दिनों सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। अन्य 'क्षेत्रीय' सघर्षों की तुलना में यद्यपि सैनिक और सैनिक साज-सामान इस क्षेत्र में कहीं कम है तथा कूटनीतिक गतिविधियों भी पश्चिमी एशिया अथवा वियतनाम जितनी नहीं हैं, तथापि स्थिति की गम्भीरता से कोई इकार नहीं कर सकता। सोमालिया के एक बुद्धिजीवी ने एक पश्चिमी पत्रकार से स्थिति की गम्भीरता को उजागर करते हुए कहा था कि "एक बात निश्चित है कि आने वाले महीनों में इस क्षेत्र में हजारों लोग मौत का शिकार बनेंगे।"

स्थिति की इस गम्भीरता के पीछे तीन मुख्य कारण हैं—(1) हिन्द महासागर और लालसागर की सीमाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण का सामरिक प्रश्न जिसमें होकर यूरोप 90 प्रतिशत तेल आयात करता है (2) 2,80,00,000 की जनसंख्या वाले देश इथियोपिया में परम्परावादी क्रान्ति की सफलता या असफलता का सैद्धान्तिक प्रश्न। इसे उदार और 'उग्र' तत्त्वों के बीच का सघर्ष भी कहा जा सकता है। तीन अन्य अफ्रीकी देशों जेसरे, अंगोला और पश्चिमी सहारा में भी सघर्ष का प्रायः यही रूप है और (3) औपनिवेशिक शासन समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रावादी शक्तियों के पुनरेकीकरण का राजनीतिक प्रश्न।

महाशक्तियाँ एक-दूसरे से इन्हीं मुद्दों के चारों ओर अपने प्रभाव-विस्तार की लड़ाई लड़ती रही हैं। हाल में स्थिति में कोई परिवर्तन आया है तो वह यह कि सोवियत संघ ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उसके राष्ट्रीय हितों से मेल नहीं खाते। इथियोपिया को उनकी समर्थन और उगाँड़ा से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने के उसके प्रयास का इस सदर्भ में उल्लेख किया जाता है। प्रश्न उठता है कि सोवियत

सम ऐसा क्यों कर रहा है। एक सम्भावित कारण यह बताया जा रहा है कि पश्चिमेशिया में उसकी भूमिका को सऊदी अरब के घन और मुस्लिम भूमिका ने पहले ही बहुत नगण्य बना दिया था, अब मुस्लिम इरीट्रिया और मुस्लिम सोमालिया को गहायता देकर उसने सोवियत संघ के लिए एक नयी चुनौती पैदा कर दी है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सोवियत संघ को इथियोपिया को शह देनी पड़ी हो तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। किन्तु अमेरिका और चीन उसके इरादे पूरे होने देंगे ऐसा नहीं लगता। उनकी सद्दा किसी भी एक देश को केन्द्र बना कर सारे अफ्रीका को युद्ध में भोक सकती है। (दिनमान, जुलाई 1977)

दक्षिण-पूर्वेशिया और प्रवासी भारतीय

एशिया, अफ्रीका, कॅरेबियन द्वीपसमूह का शायद ही कोई देश ऐसा होगा कि जहाँ भारतीय मूल के लोग न रहते हों। इन भारतीयों के पूर्वज कई दशक पहले या तो ले जाकर बसाए गए थे या काम और व्यापार की खोज में वे स्वयं इन देशों में पहुँच गए थे। आरम्भ में इन भारतीयों के सामने जो कठिनाइयाँ आईं वे थी—भाषा, मस्कृति या सामाजिक आचार व्यवहार की। कालान्तर में इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया। इसके बाद अन्य कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न होनी शुरू हुईं। ऐसी समस्याओं में स्थानीय लोगों के साथ सम्बन्ध की भावना, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की माँग, आदि थी। इन तरह की माँगों के कारण कई बार कटुता भी पैदा हो गई और तनाव अधिक हो जाने से मरवारी स्तर पर हम प्रश्न को उठाया भी जाता रहा।

यह बात सही है और विदेशी सरकारें स्वीकार भी करती हैं कि भारतीयों ने उनके देश के आर्थिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब कई देशों में दशा यह हो गई है कि वहाँ रहने वाले भारतीयों को अपने देश के बारे में उतना ही ज्ञान है जितना कि उन देश के नागरिकों को है। वहाँ पर जन्मे व्यक्ति का जिस तरह अपने देश के प्रति भावात्मक प्रेम होना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने इन देशों की नागरिकता स्वीकार कर ली है तो बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं होंगे। ऐसे लोगों की समस्या पिछले दिनों श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के सम्बन्ध में पैदा हुई थी। इस समस्या का निदान पहले शास्त्री भंडारनायक समझौते के माध्यम से हुआ। बाद में श्रीमती तिरिमाप्पो भंडारनायक ने श्रीमती इन्दिरा गांधी से बात-चीत द्वारा समझौता कर इस मामले को हल करने का प्रयास किया। काफी हद तक यह समस्या हल हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ पिछले दिनों श्रीलंका में उत्पन्न हुईं उनसे लगता है कि इस समस्या की जड़ अभी भी काफी गहरी हैं। जहाँ तक अन्य देशों का सम्बन्ध है उनमें भारतीयों की स्थिति को उस तरह का खतरा नहीं है। थाईलैंड में पिछले तीन वर्षों में सरकारें बदली हैं लेकिन भारतीयों के व्यापार या उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों पर किसी प्रकार का अक्रुश नहीं लगाया गया। उन्हे वर्तमान शासन की भी सद्भावना प्राप्त है। बर्मा में पिछले दिनों जब

विदेश मन्त्री गए थे तो वहाँ के भारतीयों के साथ बातचीत में उन्होंने देखा कि भारतीयों की स्थिति सुखद है और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को सराहा ही जाता है।

राजदूत सम्मेलन—श्रीलंका की इन घटनाओं के बावजूद दक्षिण पूर्व एशिया तथा अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों की आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसके अलावा उन देशों की अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाने में भी प्रवासी भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका भूषा की है। यही कारण है कि समय-समय पर इन लोगों को उन देशों में रह कर वहाँ की स्थितियों में घुलमिल जाने की सलाह दी जाती रही है। पिछले दिनों दिल्ली में राजदूतों के सम्मेलन (23 से 26 अगस्त, 1977) में प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई, विदेश मन्त्री प्रतल बिहारी वाजपेयी, गृह मन्त्री चरणसिंह, प्रतिरक्षा मन्त्री जगजीवनराम आदि ने बदली हुई परिस्थितियों में अपने व्यवहार और कार्य शैली में परिवर्तन का परामर्श दिया था। प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा कि हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में शान्ति स्थापना है। इसी से गुट निरपेक्षता की शुरुआत होती है जो न तो नकारात्मक है और न ही निष्क्रिय। यह तटस्थ भी नहीं है बल्कि शान्ति स्थापित करने की दिशा में निश्चित प्रयास है। प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में नशाबन्दी का उल्लेख करते हुए राजदूतों से तत्सम्बन्धी आचरण का आग्रह किया। विदेश मन्त्री प्रतल बिहारी वाजपेयी ने राजदूतों को स्पष्ट और मुक्त विचारों के आदान-प्रदान की सलाह देते हुए कहा कि बदली हुई परिस्थितियों से हमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों तथा वहाँ की सरकारों को अवगत कराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का सम्मेलन औपचारिक सम्मेलन नहीं होना चाहिए बल्कि यह कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा की दिशा में उपयोगी मंच होना चाहिए। विदेश मन्त्री के एक और भाषण का भी उल्लेख किया गया जिसमें उन्होंने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के पारपत्रों का रग चाहे जैसा भी हो वे भारत माता के पुत्र और पुत्रियाँ हैं और हम उन्हें पराया नहीं समझते। वे कही भी रहें उनका दिन हमारे साथ है और भारत माता के आँखों में उन्हें हमेशा स्थान मिलेगा।

परिवर्तन—निःसन्देह यह बहुत बड़ा नीति परिवर्तन है। आज से तीस वर्ष पहले तक उन लोगों को जिन्होंने विदेशों की नागरिकता स्वीकार कर ली थी, सलाह दी जाती थी कि उन्हें किसी बात के लिए भारत की ओर नहीं देखना चाहिए। उनसे यह भी कहा जाता था कि वे तब मन से उसी देश की सेवा करें जिसे उन्होंने अपना लिया है। जिनके पास विदेशी पारपत्र हैं उन्हें विदेशी ही माना जाता था। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सोलह राजदूतों के सम्मेलन में शायद पहली बार उन्होंने सभी भारतीय मूल के लोगों के लिए इस तरह के उद्गार सुने। यही कारण है कि राजदूतों ने अपनी समस्याएँ प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके पास यथोचित साहित्य नहीं है, प्रचार सामग्री की अधिक सुविधाएँ नहीं हैं तथा लोगों से

निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए उनके स्रोत और साधन तय्यार हैं। विदेश मन्त्री ने इन सभी अभावों की पूर्ति का आश्वासन दिया।

जहाँ तक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का सम्बन्ध है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इण्डोनेशिया, फिलिपीन आदि में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग पन्द्रह लाख है। इनमें से लगभग पाँच लाख केवल मलेशिया में रहते हैं। मलेशिया में भारतीयों के अतिरिक्त अन्य जातियाँ हैं—चीनी और मलय। एक समय मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर के जालान तुन पेराक की शतप्रतिशत दूकानें भारतीयों की थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इस क्षेत्र में चीनियों का दखल और प्रभाव बढ़ गया है। यही दशा सिंगापुर व थाईलैंड में भी है। पहले इण्डोनेशिया में भी चीनियों का बोलचाल था लेकिन मुक्त के पतन के बाद चीनियों की अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है।

प्रवासी भारतीयों का दायित्व—वास्तव में भारतीय इन देशों में अमिकों के रूप में गए थे, अतः स्थानीय लोगों से जिस तरह के सम्मान की अपेक्षा वे करते हैं वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एक समय था जब मलेशिया के रवड बागानों में भारतीयों का दखल रहता था किन्तु अब नहीं है। अब तो केवल सांस्कृतिक सम्बन्धों के माध्यम से ही वहाँ पर भारतीयों की सापेक्ष है। जब मोरारजी देसाई ने इस मुद्दे पर जोर दिया तो उनके दिमाग में शायद यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारतीय संस्कृति द्वारा वहाँ के रहने वाले भारतीय वर्तमान सरकार के प्रति अधिक सद्भावना और आदर की स्थितियाँ तैयार कर सकते हैं। निःसन्देह आपात्कालीन स्थिति में यहाँ रहने वाले भारतीयों ने आपात्कालीन स्थिति के विरोध में काफी काम किया था। न केवल वहाँ से साहित्य ही प्रकाशित होना रहा बल्कि आपात्कालीन स्थिति-विरोधियों की सहायता भी की गई। जो लोग इन देशों में गए उनको हर तरह से सहायता प्राप्त हुई।

योगदान—इसके अतिरिक्त इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को पिछले दिनों भारत में घन भेजने और उनको सपनों में लगाने का आश्वासन दिया गया था। इस क्षेत्र में काफी लोग पहले आए भी थे। वर्तमान सरकार निःसन्देह जहाँ इस तरह के प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर जोर दे सकती है, वहाँ रहते हुए सरकारी तन्त्र में भी भारत सरकार के प्रति सद्भावना का वातावरण पैदा कर सकती है। इनके अतिरिक्त भारत में जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन प्रतिनिधि मण्डलों में वार्षिक प्रतिनिधि मण्डल भी सम्मिलित है। विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रकाश के दिनों में सामान्यतः पर्याप्त स्थानों पर ही एकत्र होकर अति और भारत की समस्याओं पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यदि भारत से जाने वाले सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल इन लोगों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी समस्याएँ भारत तक पहुँचाएँ तो निःसन्देह सरकार और भारतीय मूल के लोगों में संपर्क की कमी की जो शिकायत की जाती है वह दूर हो जाएगी। राजदूत सम्मेलन में भी इसी बात पर जोर दिया गया था।

(दिवमान, सितम्बर 1977)

लेटिन अमेरिका की अस्थिर राजनीतिक स्थितियाँ

लेटिन अमेरिका महाद्वीप को अस्थिरता का महाद्वीप माना जाता है। पन्चवीस देशों के इस महाद्वीप में शायद दो-चार देश ही ऐसे होंगे जहाँ पिछले एक दशक में स्थिर सरकारें काम कर रही हों अथवा जहाँ निर्वाचित सरकारें अपनी पूरी अवधि तक सत्तास्थ रही हों। यदि हम लेटिन अमेरिका के नक्शे पर दृष्टिपात करें तो जो प्रमुख देश सामने आते हैं वे क्यूबा, मेक्सिको, कैंरेबियन द्वीपमगूह में सूरिनाम, गयाना या एक दो देश और। क्यूबा की स्थिर स्थिति का कारण प्रधानमंत्री फिडेल कास्त्रो का रुतबा, दवादवा और बलिशानी व्यक्तित्व के प्रभाव वहाँ का राजनीतिक ढाँचा भी है। वहाँ के लोगो ने भी अपने घाप को समाजवादी ढाँचे में ढाल लिया है। जहाँ तक मेक्सिको का प्रश्न है वहाँ यदाकदा प्रदर्शन या हड़तालें तो हुई हैं लेकिन पिछली लगभग आधी शताब्दी से हर छह साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाच होता रहा है। सूरिनाम और गयाना में भी अभी तक चुनाव निश्चित समय पर हुए हैं।

विभिन्न स्थितियाँ—लेकिन स्थिरता के बजाय लेटिन अमेरिकी देशों में अस्थिरता के समाचार ही अधिक सुनने में आते हैं। वास्तव में लेटिन अमेरिका के देशों का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प है। उपनिवेश की जकड़ से छूटने के बाद इन देशों में सामान्य लोकतन्त्रीय सरकारें ही अस्तित्व में आती रही हैं, लेकिन ये सरकारें साल दो साल या तीन साल तक ही कायम रह पाती है, उसके बाद सैनिक क्रांति हो जाती है। सैनिक क्रांति का प्रभाव भी दो चार साल तक ही रहा। फिर लोकतन्त्र को बहाल करने का नारा लगने लगता है, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, ससर्दें अस्तित्व में आती हैं तथा नए सविधान बनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देश में लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई है, तथापि तीन वर्ष बाद पहले जैसी गतिविधियाँ और एक बार फिर अस्थिरता। कुल मिलाकर लेटिन अमेरिकी देशों की ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। जब तक राजनीतिक अस्थिरता रहेगी उस देश की अर्थव्यवस्था घोंट रहेगी। जब तक अर्थव्यवस्था डाँचाडोल रहेगी वहाँ के लोगों का जीवन-स्तर निश्चित रूप से अस्त-व्यस्त रहेगा। जब तक ग्राम लोगों का जीवन-स्तर अच्छा नहीं होगा गरीबी और पिछड़ेपन की स्थिति बनी रहेगी। इस समय लेटिन अमेरिकी देशों में मेक्सिको, वेनेजुएला, ब्राजील जैसे कुछ देश ही हैं जहाँ की अर्थ-व्यवस्था को अधिक जर्जर कोटि में नहीं रखा जा सकता। क्यूबा की अर्थव्यवस्था दूसरे ढंग की है यह सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जब फिडेल कास्त्रो ने इस ढंग का आर्थिक निर्माण शुरू किया तो वे चाहते थे कि क्यूबा की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव लेटिन अमेरिका के कुछ अन्य देशों पर भी पड़े। उस समय उन्हें दो व्यक्ति समान विचारों के मिल गए थे—चे ग्वेवारा और रेजिम देवू। वे ग्वेवारा ने बोलिविया के जंगलों में रहकर छापामार युद्ध द्वारा वहाँ की सरकार को गिराने की कोशिश की। इन गतिविधियों से सरकारें परेशान जरूर हुई थी लेकिन अपनी छापामार गतिविधियों द्वारा वे उनका पतन नहीं करवा सके। बोलिविया की सरकार का अन्त करते-करते स्वयं ग्वेवारा का अन्त बोलिविया के जंगलों में हो गया।

यूया की बात और है—जहाँ तक साम्यवादी विचारधारा का प्रश्न है, चीले में भी जब साल्वादोर आयेजे (जुलाई, 1971 से 11 सितम्बर, 1973) की सरकार बनी थी तो उसका स्वागत करने वाले सबसे पहले व्यक्ति फिडेल कास्त्रो ही थे। लेटिन अमेरिका में समान विचारों का एक और व्यक्ति उन्हे मिल गया। इस बीच दोनों देशों में व्यापार तथा सद्भावना की वृद्धि हुई। इस बात के भी समाचार प्राप्त होने लगे कि इन दो नेताओं का प्रभाव लेटिन अमेरिका के अन्य देशों पर भी पड़ेगा क्योंकि लेटिन अमेरिका के सभी देशों में कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, आवश्यकता केवल उन्हे संगठित नेतृत्व प्रदान करने की है। लेकिन क्रान्ति के इस महाद्वीप की बलिबेदी पर डॉ. आयेजे भी चढ़ा दिए गए। उसके बाद जनरल बीनीचेत की सरकार सत्ता में आई। अभी तक वहाँ अस्थिरता और राजनीतिक रिक्तता की स्थिति बनी हुई है। कहा जाता है कि चीले में वामपंथी तो दूर कोई बुद्धिजीवी भी खुलकर अपना परिचय नहीं देता, काफी बड़ी संख्या में उनका सफाया कर दिया गया है। जहाँ इस तरह का अतन्त्रपूर्ण शासन चलेगा वहाँ के लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ कैसी होंगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इन तरह की तथा हर साल दो साल में शासन परिवर्तन की स्थिति में लोगों की कितनी भलाई हो सकती है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

गए, आए, फिर गए—लेटिन अमेरिकी कुछ देशों की स्थितियों का जायजा लेना उचित होगा। अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और दूसरे स्थान पर आता है आर्जेंटीना (क्षेत्रफल 10,72,067, जनसंख्या 2,50,50,000—राजधानी ब्युनस आयर्स)। आर्जेंटीना में स्थिति काफी अस्थिर रही है। पहले लोकतन्त्र, फिर सैनिकवाद, फिर लोकतन्त्र और सैनिक क्रान्ति से लोकतन्त्र की समाप्ति। मई 1946 में हुआ पेराने का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हुआ। वह एक सैनिक अधिकारी थे। लोकतन्त्र के बाद उन्होंने अधिनायकवादी सरकार की स्थापना की। उन्होंने शुरू में श्रमिकों को कुछ सुविधाएँ देकर अपने समर्थकों की संख्या तो काफी बढ़ा ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभिव्यक्ति, समाचारपत्रों, धार्मिक स्कूलों आदि पर प्रतिबन्ध लगा कर लोगों की नाराजगी भी मोल ले ली। देश ऋणग्रस्त हो गया। लोगों में क्रोध और आशङ्का का माहौल बनपने लगा और 16 सितम्बर, 1955 को एक सशस्त्र क्रान्ति में पेराने को सत्ता से हटा दिया गया। वह देश छोड़कर स्पेन चले गए। सैनिक जुता ने अस्थायी सरकार का गठन किया। उसने नागरिक स्वतन्त्रता बहाल की। पेरानेवादी पार्टी को भग कर दिया गया और एक ऐसा समय आया जब पेराने का नामोनिशान भी नहीं बचा। 22 फरवरी, 1958 को 12 वर्ष बाद चुनाव हुए। डॉ. फ्रांदिजी राष्ट्रपति चुने गए। लोगों ने समझा कि देश में लोकतन्त्र बहाल हो गया है। लेकिन सैनिकों के विभिन्न गुटों की हरकत फिर शुरू हुई और 29 मार्च, 1962 को एक सैनिक क्रान्ति में चुनाव द्वारा निर्वाचित डॉ. फ्रांदिजी को पदच्युत कर दिया गया। एक बार फिर चुनाव हुए और चुनाव के बाद फिर सैनिक क्रान्ति का दौर शुरू हुआ। अन्ततः मार्च, 1971 में जनरल लागुटे राष्ट्रपति बने। उन्होंने

नागरिक सरकार बहाल करने का प्रादेश प्रसारित किया। इस बीच पेरोनवादी तत्त्वों का गठन हो गया। मार्च, 1973 में पुनः चुनाव हुए तथा पेरोन समर्थक डॉ. हैक्टर कैंपोरा राष्ट्रपति बने। 13 जुलाई, 1973 को कैंपोरा ने त्यागपत्र दे दिया। 77 वर्षीय पेरोन स्वदेश लौट आए थे। उसी वर्ष 23 सितम्बर को वह राष्ट्रपति चुने गए और उनकी तीसरी पत्नी मारिया अस्तेशा पेरोन उपराष्ट्रपति। 1 जुलाई, 1974 को पेरोन की मृत्यु हो गई। श्रीमती पेरोन राष्ट्रपति बनी। लेटिन अमेरिकी देशों में वह पहली महिला राष्ट्रपति थी। उनके सत्ता में आने के बाद पेरोन समर्थक दो गुटों वामपंथी और दक्षिणपंथी में विभाजित हो गए। हिंसा और आतंकवाद का चक्र आरम्भ हो गया और अन्ततः श्रीमती पेरोन को सत्ता से हटा दिया गया। जनरल बिदेला सत्तारूढ़ हुए। श्रीमती पेरोन इस समय जेल में हैं।

चे का असफल अभियान—ग्राहेंतीना की यह राजनीतिक कहानी लेटिन अमेरिका के अन्य बहुत से देशों की भी कहानी है। चिले, पेरामुग, उरुग्वे, पेरू में भी इसी तरह की स्थिति रही है। जब क्यूबा में फिडेल कास्त्रो सत्तारूढ़ हुए थे तो उनके सहयोगी चे ग्वेवारा ने बोलिविया को अपना निशाना बनाया। वहाँ भी वह क्यूबा जैसी राजनीतिक स्थिति पैदा करना चाहते थे। बोलिविया एक समय स्पेन के अधीन था। 6 अगस्त, 1825 को उसे स्वाधीनता प्राप्त हुई। सन् 1967 को बोलिविया (क्षेत्रफल : 4,24,162 वर्गमील, जनसंख्या 54,70,000, राजधानी सक्की) का 16वाँ संविधान बना जिसमें कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया, खानों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया और कृषि सम्बन्धी सुधार किए गए। डॉ. विक्टर पाज 31 मई, 1964 को तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उस समय तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बोलिविया में भी स्थिरता पा रही है, लेकिन 4 नवम्बर को एक सैनिक क्रांति में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। सैनिक और गैर-सैनिक कम्युनिस्ट विरोधी सेनाओं ने कर्नल हुगो बार्जेर के नेतृत्व में सत्ता सम्भाली। उसके बाद हिंसा की कई घटनाएँ पड़ी। ब्राजील से मिलकर उन्होंने इस्पात, सीमेंट और प्रेट्रा-रासायनिक संयंत्रों के निर्माण सम्बन्धी अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किए। लेकिन लोगों का विरोध बढ़ने लगा क्योंकि अधिक समय तक एक शासन को न तो सैनिक और न ही गैर-सैनिक तत्त्व दर्शाएँ कर सकते थे। अतः सन् 1974 में बार्जेर ने अपने मन्त्रि-मण्डल से गैर-सैनिक सदस्यों को बर्खास्त कर दिया। राजनीतिक पाटियो और मजदूर सचों पर प्रतिबन्ध लगा और सन् 1980 तक चुनाव स्थगित कर दिए गए। लेटिन अमेरिका में यह दूसरी तरह की शासन-व्यवस्था है।

प्रस्थिरता तो यहाँ भी है—जहाँ तक क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रश्न है ब्राजीली लेटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है (क्षेत्रफल : 32,85,472 वर्गमील, जनसंख्या : 10,76,61,000, राजधानी ब्राजीलिया) ब्राजील में सन् 1930 में सैनिक शासन था। मेलुलियो वरगास को सन् 1933 तक कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नए संविधान के अनुसार सन् 1945 में वह राष्ट्रपति बने और 1950 में उनका

पुनःनिर्वाचन हुआ लेकिन सन् 1954 में सेना के दबाव के कारण उन्हें अवकाश प्राप्त करना पड़ा। सन् 1954 से 1960 तक कई राष्ट्रपति आए और गए—सैनिक और असैनिक दोनों, लेकिन विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर जिन व्यक्तियों ने सफलता प्राप्त की वह वे जोशियों गोलाटे। वह भी तीन साल तक सत्ता में रहे। सन् 1967 में जनरल कास्टेलो ब्लांको राष्ट्रपति चुना गया। सन् 1967 में नए संविधान का निर्माण हुआ जिसमें संसद के अधिकार कम कर राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ा दिए गए। राष्ट्रपति ब्लांको ने अपने एक विश्वस्त सैनिक अधिकारी को सेना ईसित्वा को अपना उत्तराधिकारी चुना। सन् 1969 में राष्ट्रपति सित्वा की मृत्यु हो गई। सैनिक नेताओं ने जनरल मेडीसी को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन सेना के आपसी गुटों में मनभेद पैदा हो गया और मेडीसी को अपने पद में हटाना पड़ा। उनके स्थान पर जनरल गोजेल नए राष्ट्रपति बने। बाद में सन् 1974 में ममद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों ने उन्हें अपना विधिवत् राष्ट्रपति चुन लिया। इस चुनाव के बाद बड़ी अस्थिरता का वातावरण छा गया जिसके कारण सन् 1980 तक चुनाव स्थगित कर दिए गए।

भूकम्प की छपेट में—इन प्रमुख देशों के अलावा कुछ और लेटिन अमेरिकी देश हैं। निकारगुआ (क्षेत्रफल 57,183 वर्गमील, जनसंख्या 2,080,000 और राजधानी मानागुआ) में प्राकृतिक आपदाओं के अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी रही है। 23 दिसम्बर, 1972 के भयंकर भूकम्प में 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हुई और वो लाख लोग बेघरवार हो गए। संविधान वहाँ तीन बार बदला जा चुका है। सन् 1967 में जनरल सोमोजा देबएले राष्ट्रपति चुने गए। सन् 1972 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और तीन सदस्यीय 'राष्ट्रीय जुता' का गठन किया गया। लेकिन पिछले दिनों वेह (क्षेत्रफल 496,222 वर्गमील, जनसंख्या 15,380,000 राजधानी लीमा) में सैनिक योजना की जो रूपरेखा प्रचारित की गई उससे यह बात समझ में आती है कि जिस तरह प्राकृतिक अस्थिरता से यह देश अस्थिर रहता है, राजनीतिक अस्थिरता भी उसको कम परेशान नहीं करती। 31 मई, 1970 के भूकम्प में लगभग पचास हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 3 अक्टूबर, 1967 को यहाँ भी एक सैनिक नास्ति हुई। राष्ट्रपति टेरी की जनरलहुमान अवलारेदो ने सत्ता से हटा दिया।

लेटिन जातिवाद—नि सदेह लेटिन अमेरिकी देशों के बारे में जो तस्वीर उभरती है उससे पता चलता है कि अधिकतर देशों में दक्षिणपंथी सैनिक सरकारें हैं। वामपंथ की लहर सीमित है, लगभग हर देश में कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं लेकिन हर देश में उनका चरित्र भिन्न-भिन्न है। बावजूद सैनिक उथल-पुथल के लेटिन अमेरिका में जातिवाद कम नहीं है। सैनिक स्तर तक या निचले स्तर तक यहाँ के मूल निवासियों की काफी संख्या है, किन्तु सरकार के विपरी भी महत्वपूर्ण अधिकारी पद पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जाता। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ काले और इण्डियन मूल निवासी बिखरे पड़े हैं, जैसे ब्राहूतीना, चीले, ऊरुवे, पैरागुए की कुल 4 करोड़ 20

लाख की जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत ही कालों और इन मूलनिवासियों का है। लेकिन कुछ वेनेजुएला, कोलोम्बिया, इक्वाडोर और पेरू जैसे देश भी हैं जहाँ मिश्रित स्पानीश या कालों की संख्या ज्यादा है। बोलिविया में इण्डियन मूल के लोगों को दबा कर रखा जाता है। जहाँ तक ब्राजील का प्रश्न है, करीब 11 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ 20 लाख गोरे हैं, 20 प्रतिशत काले और शेष काले-गोरे इण्डियन मिश्रित हैं। गयाना और सूरीनाम को छोड़कर किसी भी देश में काले व्यक्ति को काबोना स्तर का मन्त्री नहीं बनाया गया है, ब्राजील में भी नहीं। सेना में अधिकारी वर्ग की बागडोर तो गोरों के हाथ में है जबकि सैनिक काले या इण्डियन हैं।

आर्थिक मंदी का दौर—इस तरह की अस्थिर स्थिति का ही कारण है कि लेटिन अमेरिका में अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। मुद्रा स्फीति की दर भी अधिक है। ब्राजील में मुद्रा-स्फीति की दर 45 प्रतिशत है। ब्राजील के राष्ट्रपति ग्जेल ने घोषणा की थी कि सन् 1976 में सरकारी खर्च में साढ़े तीन अरब डॉलर की कमी की जाएगी, लेकिन वह केवल घोषणा ही रही। ब्राजील के बजट का 80 प्रतिशत खर्च तेल खरीदने में ही किया जाता है। विदेशी कंपनियाँ यहाँ काफी सक्रिय हैं और इस देश में उनका प्रभाव और दबदबा दिनो-दिन बढ़ता जा रहा है। ब्राजील ने अपने कृषि कार्यक्रम को विकसित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है, तथापि उसके कॉफी के निर्यात में कमी आई है। ब्राजील की कॉफी निर्यात प्रसिद्ध है। ब्राजील के अलावा मेक्सिको को भी राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर देश माना जाता रहा है। पिछले वर्ष दिसम्बर में मुद्रा प्रचलन में किए बिना ही 'पैसे' की कीमत घाटी कर दी। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था डावांढोल हो गई है। नए राष्ट्रपति जोस लोपेज पोर्तिलो के समक्ष जो आर्थिक संकट पैदा हो गया है उसका प्रभाव आर्थिक तथा सामाजिक सुधार कार्यों पर बहुत पड़ेगा। अमेरिका और मेक्सिको में अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध हैं। पिछले वर्ष अमेरिका में आर्थिक मंदी की स्थिति थी, तो भी मेक्सिको बढ़ती हुई परिस्थितियों में अमेरिका के साथ व्यापारिक सन्तुलन कायम नहीं रख सका। आर्जेन्टीना की सरकार ने आयात करने में जो उदारवादी रवैया अपनाया था उसका शिकार वहाँ के वर्तमान शासन रहे है। श्रीमती पेरों की सरकार के सत्ता से हट जाने के बाद वहाँ विदेशी पूँजी भी कम लग रही है। जो मजदूर सच मजदूरी में वृद्धि की माँग करते थे उनकी मजदूरी पहले जैसी ही है जबकि कीमते आसमान छू रही हैं। इससे देश में पर्याप्त असन्तोष है। लगभग ऐसी ही स्थिति चीले में है। वेनेजुएला और इक्वाडोर के अतिरिक्त इन देशों में तेल की कमी है। इनके बजट का अधिकतर पैसा तेल के आयात पर खर्च होता है। वेनेजुएला ने पिछले दिनों अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, अतः राष्ट्रपति कारदोस पेरेज तेल से होने वाली आय का प्रयोग अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए करना चाहते हैं। जहाँ पिछले वर्ष ब्राजील की कॉफी के निर्यात में मंदी रही, वहाँ कोलोम्बिया की कॉफी के निर्यात में वृद्धि हुई। अतः उरा देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ। इन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों के होते हुए भी बहुउद्देश्यीय

निगमों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय और गैर-सरकारी साहूकार लेटिन अमेरिकी देशों की सहायता के लिए अक्सर तैयार रहते हैं। इस सहायता के उपलक्ष में वे कुछ उनसे अपेक्षा भी करेंगे और जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो तनाव और अस्थिरता का वैसा ही वातावरण पैदा हो जाता है जिसे पिछले साल सी. आई. ए. की गतिविधियों के प्रश्न पर लेटिन अमेरिका के कई देशों में पैदा हो गया था।
(दिनभान, फरवरी, 1977)

पश्चिमी एशिया : शान्ति के नए प्रयास (दिसम्बर 1977 तक)

2 जनवरी, 1973 के अरब-इजराइल युद्ध ने यह तथ्य पुनः स्पष्ट कर दिया था कि पश्चिमी एशिया का मामला तलवार से हल न होकर शान्ति वार्ताओं से ही हल हो सकता है। अमेरिका के भूतपूर्व विदेशमन्त्री कीसिंगर की कूटनीति ने इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच समझौते का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मिस्त्र के राष्ट्रपति सादात ने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दे दी और इजराइल ने सिनाई क्षेत्र से हट जाने की बात स्वीकार ली। सीरिया, लीबिया और अन्य अरब देश सादात से अप्रसन्न हो गए लेकिन मिस्त्री राष्ट्रपति ने अपने शान्ति प्रयत्नों को चालू रखा। सन् 1977 पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापना की दिशा में विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। राष्ट्रपति सादात की मान्यता है कि इजराइल अपनी घरेलू स्थितियों के कारण शान्ति-स्थापना का इच्छुक है। सन् 1977 के अन्तिम महीनों में इजराइली और मिस्त्री नेताओं ने एक-दूसरे के प्रति सद्भावना पूर्ण वक्तव्य प्रकाशित किए और इजराइली प्रधानमन्त्री बेगिन ने तो एक कदम आगे बढ़कर सादात को रस्मी तौर पर यरुशलम आने का निमन्त्रण भी भेज दिया। सादात के अलावा बेगिन ने सीरिया के राष्ट्रपति सारकिश को भी निमन्त्रण-पत्र भेजे। बेगिन ने अपने निमन्त्रण-पत्र में कहा कि राष्ट्रपति सादात जब और जिस दिन चाहें यरुशलम आकर इजराइली ससद् (नेसेट) को सम्बोधित कर सकते हैं। सादात की प्रतिक्रिया थी कि वह इजराइल ससद् के 120 सदस्यों से वातचीत कर पश्चिमी एशिया के बारे में उन्हें अपने दृष्टिकोण से परिचित करना चाहते हैं। बेगिन ने कहा कि इजराइल की कोई शक्ति नहीं है, वह केवल यह चाहता है कि सम्मेलन में सुलकर वातचीत हो ताकि पश्चिमी एशिया में वास्तविक शान्ति स्थापित हो सके। सादात ने इजराइली ससद् (नेसेट) को सम्बोधित करने पर सहमत होते हुए सवाददाताओं को स्पष्ट किया कि यदि इजराइल सन् 1969 में हस्तगत अरब क्षेत्रों को वापस कर दे और एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की गारंटी दे दे तो सभी अरब देश उसके साथ समझौता करने को तैयार हैं। इजराइली प्रधानमन्त्री बेगिन ने मिस्त्रियों को पट्टी वार अपील करते हुए कहा, आप हमारे पड़ोसी हैं और हमेशा ही पट्टीबी रहेंगे। वास्तव में शाह फारूक ने सन् 1948 में मिस्त्र को इजराइल के खिलाफ युद्ध में भोका था। नि सन्देह युद्धों ने समस्याओं का समाधान नहीं होता। उसने बाद उन्होंने मिस्त्रियों को याद दिलाया कि हम लोगों ने ब्रिटेन से देश को मुक्त कराया और स्वाधीनता की नींव रखी। यद्यपि बेगिन ने सादात को जून, 1967 से पहले की स्थिति को लौट आना

असम्भव बताया, तथापि यह सुभाव दिया कि जिनेवा शान्ति सम्मेलन में यह अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी तरह की शान्ति वार्ता से पूर्व हमें अपनी शर्तें नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सादात मरुसलम आने को तैयार हैं तो मैं काहिरा किसी भी समय आ सकता हूँ। हमारा उद्देश्य पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करना है।”

अरब राष्ट्रों की अप्रसन्नता की परवाह न करते हुए मिस्त्र के राष्ट्रपति अमर सादात ने इजराइल जाने का फैसला कर लिया। 29 वर्ष की घोर शत्रुता और युद्ध की ताक पर रखकर 20 नवम्बर, 1977 को उन्होंने इजराइली संसद से पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापित करने में सहायता का अनुरोध किया। इजराइली संसद में भाषण देते हुए सादात ने कहा—“उनकी यात्रा से विश्व के अनेक नेता क्रुद्ध हो गए हैं लेकिन मैं पूरी दृढ़ता के साथ आपके पास आया हूँ ताकि हम शान्ति के नए रिश्ते तथा खुदा की इन धरती पर सभी के लिए शान्ति स्थापित कर सकें।” सादात ने घोषणा कि “हमने विश्व के सभी लोगों के लिए दिल खोल दिए हैं जिससे यह समझा जा सके कि हम ग्याय और शान्ति चाहने वाले लोग हैं।” सादात ने इजराइल संसद से आगे कहा, “हम मिस्त्रवासी और मुसलमान यरशलम को कितना महत्व देते हैं और उसे कितना पवित्र मानते हैं इस बारे में आपको कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।” उन्होंने फिलिस्तीन समस्या के सम्बन्ध में कहा कि कोई भी इस बात में इंकार नहीं कर सकता कि यही सारी समस्या की जड़ है। कोई व्यक्ति इजराइल में प्रचारित नारों को स्वीकार और फिलिस्तीन लोगों के अस्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा—“फिलिस्तीनी लोगों के बिना कोई शान्ति कायम नहीं हो सकती। इस पहलू की उपेक्षा करना अथवा टालना भारी गलती होगी।”

राष्ट्रपति सादात ने इजराइली संसद में अपना एक शान्ति-प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें निम्नलिखित बातें थी—

- (1) फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को मान्यता। इन अधिकारों में अपना देश कायम करने का भी अधिकार शामिल है।
- (2) सभी देशों को अपनी सीमाओं के अन्तर्गत शान्ति से रहने का अधिकार।
- (3) सभी देशों में संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र के आधार पर सम्बन्धों की स्थापना।
- (4) पश्चिमी एशिया में युद्ध स्थिति की समाप्ति।

मिस्त्र के जानकार सूत्रों ने कहा है कि “इजराइल और उसके तीन प्रमुख पड़ोसी अरब देशों (मिस्त्र, सीरिया और जोर्डन) के बीच राजनीतिक समझौता हो जाने के तीन महीने बाद मित्र युद्ध स्थिति समाप्त करने के लिए सहमत हो सकता है।”

“मेरा विचार है कि संयुक्तराज्य अमेरिका के लिए यह उचित नहीं होगा कि यह पश्चिमी यूरोप में नाटो से अपनी सेनाएँ हटा ले। इसके विपरीत मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें सोवियत संघ और वारसा पैक्ट के उसके साथियों के साथ सैन्य शक्ति में पारस्परिक और सन्तुलित कर्मा पर विचार-विमर्श करना चाहिए।”

—राष्ट्रपति फोर्ड

संयुक्तराज्य अमेरिका को विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न देश माना जाता है। सोवियत संघ के साथ उसकी मुख्य प्रतिस्पर्धा है। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व-नेतृत्व की आकांक्षी हैं। पूँजीवादी शिविर में अमेरिका सर्वोपरि है और साम्यवादी गुट में सोवियत संघ, तथापि हाल ही के वर्षों में अपने ही गुटों में उनके नेतृत्व को चुनौती दी जाने लगी है।

प्रथम महायुद्ध के बाद संयुक्तराज्य अमेरिका अपनी परम्परागत पृथक्तावादी नीति पर लौट आया था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के कुछ वर्ष पूर्व से ही यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका, बदली हुई परिस्थितियों में, विश्व-राजनीति से तटस्थ नहीं रह सकता। द्वितीय महायुद्ध में अमेरिका ने मित्रराष्ट्रों को आर्थिक और सैनिक दोनों रूपों में भरपूर सहायता दी—अमेरिका के पूरे उत्साह के साथ महायुद्ध में उतर आने के फलस्वरूप अधिनायकवादी शक्तियों (जर्मनी, इटली और जापान) की पराजय अवश्यम्भावी हो गई। महायुद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रकट हुआ और विश्व-राजनीति में खुलकर भाग लेने लगा। उसने पृथक्तावादी नीति को पूर्णरूप से त्याग दिया। इस नीति पर लौटना अब सम्भव भी नहीं था क्योंकि साम्यवादी रुस एक महान् शक्ति के रूप में अपने प्रभाव-विस्तार के लिए कीटवद्ध था। जर्मन के अनुसार—

“प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका आसानी से पार्यक्रमवादी नीति का अनुसरण कर सकता था क्योंकि घुरीराष्ट्रों की पराजय के बाद यूरोप और एशिया में एक नया शक्ति सन्तुलन स्थापित हो गया था किन्तु द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अमेरिका के लिए पृथक्तावादी नीति का अनुसरण करना सम्भव नहीं था क्योंकि नाज़ी राष्ट्रों के त्रि-भुट की हार के बाद यूरोप और एशियायी देशों पर साम्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था।”

संयुक्तराज्य अमेरिका की विदेश नीति का

काल-विभाजन

द्वितीय महायुद्धोत्तरकालीन अमेरिकी विदेश नीति को समय-समय पर नया रूप दिया जाता रहा है। प्रत्येक नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में विदेश-नीति को कुछ नया मोड़ मिला है, एक नयी दृष्टि प्राप्त हुई है। सामान्यतः द्वितीय महायुद्ध के बाद की अमेरिकी विदेश-नीति को इन चरणों या कालों में विभाजित किया जाता है—

- (1) सहयोग और अनुकूलता की नीति का काल (मगस्त, 1945 में मगस्त, 1946);
- (2) आर्थिक सहायता द्वारा साम्यवाद के प्रसार को अवरुद्ध करने की नीति का काल (मगस्त, 1946 से जून, 1950);
- (3) खुले सघर्ष और सैनिक सन्धियों की नीति का काल (जून, 1950 से जुलाई, 1953);
- (4) नवीन दृष्टिकोण का काल (जुलाई, 1953 से जनवरी, 1961); एवं
- (5) सह-अस्तित्व की नीति का काल (जनवरी, 1961 से आज तक)

युद्धोत्तर युग में अभी तक अमेरिका की बागडोर छः राष्ट्रपतियों के हाथ में ही है—ट्रूमैन, आइज़नहाउर, केंनेडी, लिण्डन बी. जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, रॉनाल्ड फोर्ड। प्रत्येक राष्ट्रपति ने अमेरिका का विदेश-नीति के आधारभूत तत्वों रक्षा करते हुए अपने कार्यकाल में समयानुकूल परिवर्तन किए और अधिक उचित यही होगा कि हम इन राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के अनुसार अमेरिका विदेश-नीति की विवेचना करते चलें।

ट्रूमैन-युग (1945-1952)

द्वितीय महायुद्ध के बाद सन् 1952 तक के अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकी विदेश-नीति की जो आधारभूत नीतियाँ रखी वे आज भी मार्गदर्शक बनी हुई हैं। भावी राष्ट्रपतियों ने समय के अनुसार अपनी विदेश-नीतियों को नए मोड़ दिए, लेकिन ट्रूमैनकालीन तथ्य आज भी सजीव हैं। साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने का जो दृढ़ निश्चय राष्ट्रपति ट्रूमैन ने व्यक्त किया था, वही निश्चय भावी राष्ट्रपतियों ने किया और साम्यवाद पर अकुश रखने के लिए नए-नए कदम उठाए। विश्व-राजनीति में अमेरिकी नेतृत्व को सर्वोच्चता देने का जो प्रयत्न ट्रूमैन ने किया, वही प्रयत्न भावी राष्ट्रपति भी करते रहे हैं। ट्रूमैन-काल में अमेरिका यह

मानकर चला कि सोवियत संघ उसका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी है और अमेरिका का भावी इतिहास भी यही बताता है कि बहुत कुछ सोवियत संघ को प्रमुख लक्ष्य मानकर ही अमेरिका की विदेश-नीति संचालित होती रही है।

राष्ट्रपति ट्रूमैन का व्यक्तित्व विशेष आकर्षक नहीं था, परन्तु वह ईमानदार कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, उदार और साहसी था। जाति अथवा धर्म-विभेद की भावनाएँ उसे छू तक नहीं गई थी। साहित्य में उसकी इतनी गहरी पेंट थी कि कभी-कभी वह प्रकाण्ड विद्वानों को भी चकित कर देता था। वह इतना निर्भीक राष्ट्रपति था कि बड़े से बड़े अधिवासियों को पद से हटाने में तनिक भी सकोच नहीं करता था। उसने गृह और विदेश-नीति के क्षेत्र में वह सकल्प और कठोर निष्ठा का परिचय दिया।

ट्रूमैन के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश-नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ

ट्रूमैन-युग में अमेरिकी विदेश-नीति में जिन प्रवृत्तियों अथवा तत्वों पर जोर दिया गया उन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

1. अमेरिका विश्व-राजनीति में खुलकर भाग लेने लगा। यूरोप तो उसकी दिलचस्पी का प्रधान केन्द्र बना ही, विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिका की महत्वाकांक्षा स्पष्ट हो गई। एक महाशक्ति के रूप में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए अमेरिका ने एक के बाद एक अनेक कदम उठाए।

2. महायुद्ध के बाद अगस्त, 1946 के आस-पास तक ट्रूमैन ने 'सहयोग और अनुकूलता की नीति' (Policy of Co-operation and Accommodation) का अनुसरण किया। अमेरिकी विदेश-नीति के निर्माता यह मानकर चले कि युद्ध-काल में मित्रराष्ट्रों में जो सहयोग था वह युद्ध के बाद भी कायम रहेगा। 'सहयोग और अनुकूलता की नीति' के इस काल को 'मधु-रात्रि काल' (The Honey-Moon Period) भी कहते हैं।

3. अमेरिका का यह प्रयत्न रहा कि तनाव का क्षेत्र समाप्त करने के लिए महायुद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ शीघ्र से शीघ्र शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न की जाएँ।

4. सोवियत संघ के साथ सहयोग की नीति असफल होते देखकर ट्रूमैन ने अगस्त, 1946 में अमेरिकी विदेश नीति को एक नई दिशा प्रदान की। ऐसी नीति के अनुसरण का निश्चय किया गया जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप में तुरन्त 'अवरुद्ध' कर दिया जाए। चूँकि यह पिछली नीति को त्यागकर एक नई दिशा की ओर मुड़ने का निश्चय था, अतः अगस्त, 1946 से जून, 1950 तक की अवधि को 'नवीन दिशान्तरण काल' (Period of New Departure) कहा जाता है। इस युग में साम्यवाद के कठोरतापूर्वक अवरोधन की नीति अपनाई गई, अतः इसे 'अवरोधन नीति का काल' (Period of the Policy of Containment) भी कहते हैं। फिर भी राष्ट्रपति ट्रूमैन और उपराष्ट्रपति हैनरी वॉलास का यह मत रहा कि अमेरिका और सोवियत संघ का मूल हित इसी बात में है कि शान्ति कायम रही जाए ताकि विश्व के सभी देश पुनर्निर्माण-कार्यों में सफल हो। यह

विचार व्यक्त किया गया कि सोवियत सघ भयभीत है और पश्चिमी आक्रमण के विरुद्ध आश्वासन चाहता है।

5. ज्यों-ज्यों संधि निरन्तर शक्तिशाली होता गया स्टालिन अधिकाधिक उग्र होता गया। तब सन् 1950 में अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के अवरोधन का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस नीति के अनुसार 'नाटो' (NATO) की स्थापना की गई। इसे 'अवरोधन रणनीति' (The Strategy of Containment) की संज्ञा दी गई। ज्यों-ज्यों साम्यवाद का खतरा बढ़ता गया, अमेरिका सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों के निर्माण की ओर उन्मुख होता गया। सन् 1950 में ही उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तर कोरिया की पीठ पर साम्यवादी शक्तियाँ थी। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का पक्ष लेकर इस साम्यवादी आक्रमण को विफल कर देने का सफल किया और समुक्त राष्ट्रसंघ की सेनाओं के रूप में अमेरिकी सेनाएँ युद्ध-क्षेत्र में कूद पड़ी। कोरिया का युद्ध जून, 1950 से जुलाई, 1953 तक चला और इस अवधि को अमेरिकी विदेश-नीति के इतिहास में 'खुले संघर्ष का काल' (Period of Open Conflict) कहा जाता है।

6. ट्रूमैन-युग में अमेरिका की यह स्पष्ट नीति थी कि वह अणु शक्ति का एकलव्र स्वामी बना रहे। अणु-शक्ति के नियन्त्रण की योजनाएँ भी बनाई गईं।

संरक्षण रूप में ट्रूमैन-युग में विदेश-नीति के मुख्य चरण ये रहे—'सहयोग और अनुकूलता की नीति', 'अवरोधन नीति', 'सैनिक सन्धियों की नीति' और 'खुले संघर्ष का काल'।

सहयोग और अनुकूलता की नीति (अगस्त, 1945—अगस्त, 1946)

प्रारम्भ में अमेरिका ने यह सोचा कि मित्रराष्ट्रों का युद्धकालीन सहयोग शान्तिकाल में भी बना रहेगा, अतः राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 'सहयोग और अनुकूलता की नीति' (Policy of Co-operation and Accommodation) का अनुसरण किया। अमेरिका ने चाहा कि युद्धकालीन विनाश के चिह्नों को शीघ्रातिशीघ्र मिटा दिया जाए, पराजित राष्ट्रों के साथ शान्ति-सन्धियाँ सम्पन्न की जाएँ और चारों ओर शान्ति का वातावरण उत्पन्न किया जाए। अमेरिका ने यह भी चाहा कि किसी देश को प्रादेशिक अखण्डता को भंग न किया जाए और कोई भी विदेश-शक्ति किसी देश में बलपूर्वक किसी सरकार को न थोपे। अमेरिका ने युद्धोत्तरकालीन सभी समस्याओं का निदान मिल-जुलकर करने का निश्चय किया। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अमेरिका ने सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ किए। प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है और अमेरिका की विदेश-नीति भी इसी लक्ष्य से संचालित हुई कि सोवियत सघ की तुलना में अमेरिका के प्रभाव-क्षेत्र का निरन्तर विस्तार होता जाए।

'बारह सूत्री' उद्देश्यों की घोषणा, 1945—सहयोग और अनुकूलता की नीति की व्याख्या करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 28 अक्टूबर, 1945 को 'बारह

मूत्री' (Twelve Points) उद्देश्यों की घोषणा की। ये उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार थे—

1. अमेरिका प्रादेशिक विस्तार नहीं चाहता, वह किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा।

2. अमेरिका का मत है कि जिन देशों से सर्वोच्च प्रभुता के अधिकार बलपूर्वक छीन गए थे, वे उन्हें वापस किए जाने चाहिए।

3. अमेरिका किसी मित्रदेश में जनता की स्वतन्त्र सहमति के अभाव में किए गए किसी प्रादेशिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेगा।

4. अमेरिका का यह विश्वास है कि स्वशासन में समर्थ देशों को बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने शासन का स्वयं निर्धारित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह सिद्धान्त यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी गोलार्द्ध में समान रूप से लागू होता है।

5. अमेरिका का लक्ष्य अपने साधियों के साथ सहयोग करते हुए पराजित देशों में शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रीय शासन की स्थापना करना है।

6. अमेरिका विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश में बलपूर्वक थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं देगा।

7. सब देशों को अनक देशों में से होकर गुजरने वाली नदियों तथा समुद्रों में आवागमन की निर्बाध स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

8. विश्व में कच्चे माल की प्राप्ति तथा व्यापार में सब देशों की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

9. अमेरिका का मत है कि पश्चिमी गोलार्द्ध के राज्यों को दम गोलार्द्ध के बाहर की किसी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना पड़ोसियों की भाँति अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

10. अमेरिका चाहता है कि समूच विश्व में दरिद्रता और अभाव को दूर करने तथा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सब देशों में पूर्ण आर्थिक सहयोग हो।

11. अमेरिका विश्व में विचार-अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतन्त्रता के विस्तार के लिए प्रयत्न करेगा।

12. अमेरिका का दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों में शान्ति स्थापित रखने के लिए ऐसे सयुक्त राष्ट्रमण्डल की आवश्यकता है जिसके सदस्य शान्ति-प्रेमी हों और शान्ति-स्थापना के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्यवाही करने के लिए भी तैयार हों।

सैनिक सत्या में कमी—विश्व-शान्ति के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों की सत्या में कमी करना शुरू कर दिया। लगभग दो वर्ष के अन्तर्गत ही 1 करोड़ 20 लाख सैनिकों की सत्या से घटाकर 15 लाख कर दी गई। अमेरिका की आशा थी कि रूस भी सहयोग करेगा और अनुकूल

उत्तर देगा। लेकिन यह आशा गलत सिद्ध हुई। अमेरिका तत्कालीन विश्व-राजनीति के दो महत्त्वपूर्ण-पहलुओं को समझने में—भूल कर बंठा—प्रथम, सोवियत संघ की आक्रमणकारी चालें; एवं द्वितीय, एशिया महाद्वीप में क्रान्ति।

सोवियत संघ से उप्र मतभेद और सहयोगपूर्ण नीति का परित्याग—कुछ ही समय में मभी क्षेत्रों में यह प्रकट हो गया कि रूस और अमेरिका परस्पर-विरोधी हैं और विश्व की हर समस्या पर दोनों में उप्र मतभेद हैं। दोनों शक्तियों में किसी प्रकार का समझौता और सहयोग सम्भव नहीं है। विशेषतः पाँच क्षेत्रों में सोवियत-अमेरिकी मतभेद अत्यधिक उप्र हो गए—

- (i) जर्मनी के समीकरण का प्रश्न,
- (ii) पोतुण्ड में रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन में दिए गए वचनों के उल्लंघन की अमेरिकी शिकायत,
- (iii) इटली, हंगरी, रूमानिया, बल्गेरिया तथा फिनलैंड के साथ शान्ति-सन्धियों का प्रश्न,
- (iv) संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसमें रूस द्वारा नियेचाधिकार के प्रयोग का प्रश्न, तथा
- (v) ईरान, टर्की और यूनान में रूसी महत्वाकांक्षाओं का प्रश्न।

इन उप्र मतभेदों और अन्य असहमतियों के कारण दोनों शक्ति गुटों में 'शीतयुद्ध' आरम्भ हो गया। रूसी असहयोग से अमेरिका के आशावादी नेताओं की वहा आघात पहुँचा। एशिया महाद्वीप में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक क्रान्ति हो रही थी और रूस ने एशियायी देशों के मुक्ति-आन्दोलनों को समर्थन देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। रूसी चालों से बाध्य होकर अमेरिका के विदेश-नीति निर्माताओं ने अगस्त, 1946 के लगभग सहयोग और अनुकूलता की नीति का परित्याग कर दिया।

अवरोध की नीति (अगस्त, 1946—जून, 1950)

सन् 1946 के मध्य तक रूस की ओर से अमेरिका निराश होता जा रहा था और राष्ट्रपति ट्रूमैन के मुख्य परामर्शदाता एवरिल हैरीमैन तथा विदेश-विभाग के रूसी विशेषज्ञ जार्ज केनन ने रूस के साथ सहयोग की नीति में स्पष्ट रूप से सन्देह प्रकट किया। उनका विचार था कि "मास्को सहयोग और समझौते की नीति को दुर्बलता का लक्षण समझता है। वह केवल शक्ति की ही परवाह करता है, अतः उसने विरुद्ध हड़ता की नीति पर चसना चाहिए।"

अब अमेरिका ने यह निश्चय कर लिया कि साम्यवादी प्रसार को अविलम्ब 'प्रयत्न' किया जाए। इस निश्चय के साथ ही 'अवरोध नीति' (Policy of Containment) पर अमल किया जाने लगा। अमेरिका के आशावादी नेताओं का अब भी विश्वास था कि सोवियत संघ भयभीत है और केवल पश्चिमी आक्रमण के विरुद्ध आशवासन चाहता है। यदि उसे यह विश्वास दिला दिया जाए तो वह सहयोग करने लगेगा। लेकिन प्रधानता इस विचार की थी कि रूस पर विश्वास नहीं किया

जा सकता। गोपनीयता, अस्पष्टता, सन्देहशीलता, कथनी और करनी में भेद घीसा-घड़ी घादि सोवियत नीति के प्रधान लक्षण थे। अमेरिकी सरकार पर यह भी दबाव पड़ा कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए वह साम्यवाद के विरुद्ध सैद्धान्तिक सघर्ष भी छेड़ दे। उस समय रूस दुनिया भर के देशों में 'साम्यवादी घर्म' का जोर-शोर से प्रचार करने में लगा हुआ था। अमेरिकी विदेश-विभाग इस बात से भी चिन्तित हो गया कि चीन और पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का प्रसार अमेरिका की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा हो सकता था।

‘अवरोधन’ की अमेरिकी विदेश-नीति के मुख्य तथ्य ये थे—

ट्रूमैन सिद्धान्त—मध्य-पूर्वी क्षेत्र में यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी बनने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने इन्हे आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। इसी नीति को ‘ट्रूमैन-सिद्धान्त’ (Truman Doctrine) कहा जाता है। महायुद्ध के बाद चारों ओर आर्थिक संकट की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गईं। मुसलमान, टर्की और ईरान में साम्यवादी आन्दोलन ने विशेष जोर पकड़ लिया। यह आशंका पैदा हो गई कि यदि तुरन्त ही इन देशों की आर्थिक सहायता न की गई तो वे साम्यवाद के प्रभाव में चले जाएंगे। अतः मार्च, 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कांग्रेस (अमेरिका की संसद) से अपील की कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए यूनान और टर्की के लिए आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। यूनान को 25 करोड़ डॉलर और टर्की को 15 करोड़ डॉलर देने की सिफारिश की गई। कांग्रेस ने विधेयक को स्वीकार कर लिया और 22 मई, 1948 को उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। ट्रूमैन-सिद्धान्त के अन्तर्गत प्राप्त विपुल आर्थिक सहायता के बल पर सन् 1950 के अन्त तक यूनान और टर्की ने साम्यवादी दबाव से सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली।

वास्तव में ट्रूमैन-सिद्धान्त ने अमेरिकी विदेश-नीति के इतिहास में एक असाधारण कीर्तिमान की स्थापना की। इस नीति ने घोषणा की कि “जहाँ कहीं भी शान्ति भंग करने वाला प्रयत्न या परोक्ष आक्रामक कार्यवाही होगी, उसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने का भरसक प्रयत्न करेगा।” ट्रूमैन-सिद्धान्त के फलस्वरूप अमेरिकी विदेश-नीति का कार्यक्षेत्र विश्व-व्यापी हो गया। इस सिद्धान्त ने अमेरिका की विदेश-नीति में मौलिक परिवर्तनों का सूत्रपात किया तथा उसे विकास की एक नई दिशा प्रदान की। माइकेल डोनेलन के शब्दों में, “ट्रूमैन-सिद्धान्त निश्चय ही सम्पूर्ण स्वतन्त्र विश्व के लिए मूनरो-सिद्धान्त था। इसने पुराने सिद्धान्त को नई परिस्थितियों के साथ आवश्यकतानुसार समायोजित कर दिया और पश्चिमी गोलार्द्ध की सीमाओं का विस्तार स्वतन्त्र-विश्व की सीमाओं तक कर दिया।”¹ ट्रूमैन सिद्धान्त निम्नलिखित दृष्टियों से अत्यधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ—

1. इसने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब पृथक्तावादी नीति का परित्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की समस्याओं के प्रति सक्रिय हो गया है।

1. Michael Donelan : The Ideas of American Foreign Policy, p 749.

2. यह रूस को उसकी विस्तारवादी चेष्टाओं के विरुद्ध एक चेतावनी थी, उसके साथ शीतयुद्ध की घोषणा थी और मास्को के प्रति सहयोगपूर्ण नीति का परित्याग था।

3. यह सिद्धान्त 'अवरोधन' नीति के विकास का प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था।

4. यह 'मुनरो-सिद्धान्त' का व्यापक रूप था जिसने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका पूर्वी और पश्चिमी गोलार्द्ध में स्वतन्त्रता की आकांक्षी जनता को उसके स्वाधीनता संघर्ष का समर्थन करेगा।

5. यह सिद्धान्त इस तथ्य की स्वीकृति थी कि भूमध्यसागर और मध्यपूर्व में उत्पन्न हुई 'शक्ति शून्यता' का रूस द्वारा लाभ उठाए जाने से पूर्व अमेरिका लाभ उठाने का इच्छुक है।

6. इस सिद्धान्त का मूल उद्देश्य बल्कान प्रायद्वीप में रूसी प्रसार को रोकने के लिए और साथ ही रूस को घेरने के लिए यूनान और टर्की को महत्वपूर्ण सैनिक अड्डे के रूप में सुरक्षित रखना तथा मध्यपूर्व के विशाल तेल भण्डारों को अपने अधिकार में रखना था।

7. यह सिद्धान्त रूस के प्रति अमेरिकी विरोध की स्थूल अभिव्यक्ति था।

ट्रूमैन-सिद्धान्त को विभिन्न क्षेत्रों से कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका की आर्थिक और सामरिक सहायता देने की नीति को साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का एक नवीन रूप बताया गया। इस सिद्धान्त का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा न होकर पश्चिमी एशिया के तेल भण्डारों को रूसी प्रभाव से अछूत रखना था। ट्रूमैन-सिद्धान्त से संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति को आघात पहुँचा क्योंकि यूनान और टर्की को संघ के माध्यम से सहायता न दी जाकर वृषक् रूप से दी गई। स्वयं अमेरिकियों की दृष्टि में ट्रूमैन-सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का ही विकसित रूप था।

युद्धोपरान्त की प्रारम्भिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के फलस्वरूप अब यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी विदेश-नीति का मौलिक उद्देश्य साम्यवाद और सोवियत प्रसार को रोकना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपनी विदेशी नीति में तीन बातों को स्थान दिया—प्रथम, आर्थिक; द्वितीय, राजनीतिक एवं तृतीय सैनिक। आर्थिक तत्त्व के अन्तर्गत आर्थिक सहायता और आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम अपनाए गए। राजनीतिक तत्त्व को सम्पादित करने के लिए पश्चिमी यूरोपीय राय की स्थापना की दिशा में कार्यवाही की गई और सैनिक तत्त्व के अन्तर्गत सैनिक अंगठनों की स्थापना पर बल दिया जाने लगा।

मार्शल योजना (Marshall Plan)—'अवरोधन की नीति' (Policy of Containment) का दूसरा चरण 'मार्शल योजना' थी। इस योजना के अन्तर्गत युद्ध से ध्वस्त यूरोप को सहायता देने की बात कोई सर्वथा नई नहीं थी। द्वितीय महायुद्ध काल में वह उधार पट्टा-कार्यक्रम (Lend Lease Programme) के अन्तर्गत तथा सन् 1945 में इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 'संयुक्त राष्ट्र सहायता और

पुनर्वास प्रशासन' (UNRRA.) के माध्यम से यूरोप को आर्थिक सहायता देता रहा था ।

अमेरिका के विदेश मन्त्री मार्शल ने मास्को के शान्ति-सम्मेलनो में देखा कि इसी दूर बात में अडमेबाजी की नीति अपना कर शान्ति-सन्धियों में विलम्ब कर रहे हैं । मार्शल शीघ्र ही समझ गया कि रूसियों के सन्धि चर्चा में देर लगाने का परिणाम यूरोप में कानियों द्वारा साम्यवाद की स्थापना हो जाना है ताकि फिर समझौते करने में बठिनाई न हो । अतः 26 अप्रैल, 1947 को वाशिंगटन लौटने पर मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि यदि अविलम्ब यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयास न किए गए तो वह साम्यवादी हो जाएगा । अपने सहकारियों के साथ परामर्श करने के उपरान्त राष्ट्रपति ट्रूमैन ने भी इस प्रकार की सहायता देने का निश्चय कर लिया और तब 5 जून, 1947 को विदेश-मन्त्री मार्शल ने हावर्ड विश्वविद्यालय में अपने सुप्रसिद्ध भाषण में कहा—

‘हमारी नीति किसी देश या सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है । यह भूल, दरिद्रता, निराशा और अव्यवस्था के विरुद्ध है । इसका उद्देश्य विश्व में एक ऐसी अव्यवस्था का पुनरुत्थान करना है जिससे स्वतन्त्र सस्याधो की विकसित करने वाली राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकें । संयुक्तराज्य अमेरिका की सरकार द्वारा यूरोप को सहायता दिए जाने से पहले यह आवश्यक है कि यूरोपीय देशों की इस सहायता की आवश्यकताओं के विषय में समझौता हो जाए । इस सरकार के लिए न तो यह अच्छा होगा और न प्रभावशाली कि यूरोप को अपने पैरों पर खड़ा करने वाले आर्थिक कार्यक्रमों का निर्माण करें । यह यूरोपीयों का कार्य है । इसकी पहलू यूरोप से होनी चाहिए । हमारा कार्य सहायता देना है ।’

मार्शल ने अपने भाषण में साम्यवादी और गैर-साम्यवादी देशों में कोई भेद नहीं किया, बल्कि प्रकट रूप में यही कहा कि उनके देश की नीति किसी देश अथवा सिद्धान्त विशेष से संपर्क की नहीं, बल्कि भूल, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था का सामना करने की है । परिणामस्वरूप सोवियत संघ को भी पुनर्निर्माण के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमन्त्रित किया गया । परन्तु मास्को और उसके साथी राज्यों ने इस प्रस्ताव को अमेरिकी साम्राज्यवाद की एक नई चाल, बताकर ठुकरा दिया ।

पश्चिमी देशों के राष्ट्रो ने मार्शल योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया । ब्रिटेन और फ्रांस की पहल पर जुलाई, 1947 में पेरिस में 16 यूरोपीय देशों (इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रामेटेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, लक्जमबर्ग, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, पुर्तगाल, नीदरलैण्ड और टर्की) के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ । इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति (Committee of European Economic Co-operation) की स्थापना की गई और यूरोपीय पुनरुद्धार का चार वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया ।

यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति ने संयुक्तराज्य अमेरिका को एक रिपोर्ट

समर्पित की जिसमें कहा गया कि अमेरिका यदि 1.3 बिलियन डॉलर धन राशि खर्च करने को तैयार हो तो सन् 1951 तक एक आत्मनिर्भर यूरोपीय धर्म-व्यवस्था (Economy) की स्थापना की जा सकती है। यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिसम्बर, 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कांग्रेस के समक्ष 'मार्शल योजना' में सम्बाधित धन्य का अनुमान प्रस्तुत किया जिसमें सत्रा चार वर्ष की अवधि के लिए 17 अरब डॉलर और 15 महीनों के लिए 6 अरब 80 करोड़ डॉलर के धन्य का अनुमान लगाया गया। इस प्रस्ताव के उद्देश्य (Motive) की व्याख्या करते हुए ट्रूमैन ने कहा—“मेरा प्रस्ताव यह है कि अमेरिका उन 16 राज्यों को, जो उसी की तरह स्वतन्त्र सत्ताओं की सुरक्षा एवं राष्ट्रों के बीच स्थायी शान्ति के लिए हठ संकल्प है, उनके पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता देकर विश्व-शान्ति एवं अपनी सुरक्षा में योगदान करें।”

‘मार्शल योजना’ को, जो अधिकृत रूप में ‘यूरोपीय राहत कार्यक्रम (European Relief Programme)’ के नाम से जानी गई, कांग्रेस ने पास कर दिया। 3 अप्रैल, 1948 को कांग्रेस ने ‘विदेशी सहायता अधिनियम’ पारित कर मार्शल योजना को मूर्त रूप प्रदान किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए ‘यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन’ (Organization for European Economic Co-operation) की स्थापना की गई।

‘मार्शल योजना’ से रूस और पश्चिम का विरोध पहले की अपेक्षा और भी अधिक उग्र हो गया। इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (1947-1951) में अमेरिका ने यूरोप को लगभग 11 मिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना के बल पर एक ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक पतन और साम्यवादी आधिपत्य से बच गया तथा दूसरी ओर संयुक्तराज्य अमेरिका पश्चात्य जगत् का सर्वमान्य नेता बन गया। अमेरिका ने यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देते हुए यह शर्त लगाई कि वे अपनी सरकारों में साम्यवादी तत्त्वों का उन्मूलन करेंगे। सन् 1946-47 तक फ्रांसीसी सरकार में साम्यवादी थे, परन्तु सन् 1946 में जब ब्लुन फ्राम के लिए ऋण उपलब्ध करने हेतु बांशिगटन गया तो उस पर यह दबाव डाला गया कि इसे शान्त करने के लिए फ्रेंच सरकार से साम्यवादियों का निष्कासन आवश्यक है। इसी प्रकार इटली में मार्शल सहायता देने वाली सरकार को कम्युनिस्ट से साम्यवादियों को निष्कासन पड़ा।

‘मार्शल योजना’ एक प्रकार से ट्रूमैन-सिद्धान्त का ही विकसित रूप थी जिसने ट्रूमैन सिद्धान्त में प्रतिपादित ‘अवरोधन-नीति’ को तीन प्रकार से आगे बढ़ाया—

- (i) जहाँ ट्रूमैन-सिद्धान्त में अलग-अलग राज्यों की सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ मार्शल योजना में यूरोप को समग्र रूप से सहायता देने की व्यवस्था की गई।
- (ii) मार्शल योजना ने ‘अवरोध की नीति’ में आर्थिक तत्त्वों के महत्त्व को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया।

(iii) इसके द्वारा पहली बार अमेरिकी आर्थिक सहायता को एक सहयोगी एव योजनाबद्ध रूप दिया गया ।

मार्शल योजना का प्रत्युत्तर रूस ने सितम्बर, 1947 में 'कोमिनफोर्म' को स्थापना के रूप में दिया ।

आर्थिक स्तर पर साम्यवाद के अवरोध की नीति के अनुसार अमेरिका ने जर्मन अर्थ-व्यवस्था को भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया । सन् 1948 में पश्चिमी शक्तियों द्वारा जर्मनी के अपने क्षेत्रों में कुछ मुद्रा सम्बन्धी सुधार किए गए, जिनके विरोध में रूस द्वारा बर्लिन की 'कुत्थात नाकेबन्दी' की गई जो मन्तव्य असफल सिद्ध हुई । पश्चिमी शक्तियों के मुद्रा-सुधारों और बर्लिन-संकट पर उनकी दृढ़ता ने जर्मन जनता को आश्वस्त किया कि पश्चिमी शक्तियाँ उनके हितों को रक्षा करने के लिए उत्सुक और समर्थ हैं ।

चार-सूत्री कार्यक्रम (Four Point Programme)—मार्शल योजना का उद्देश्य केवल यूरोप की आर्थिक अस्त-व्यस्तता को पुन सुधारना था, लेकिन चीन में साम्यवादियों की महान् विजय से अमेरिकी और अन्य पश्चिमी राजनेता इस बात से चिन्तित हो गए कि विश्व के अल्पविकसित देश साम्यवादी प्रसार के उत्तम क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं । अतः राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ऐसे प्रदेशों में साम्यवादी प्रसार के अवरोध के लिए, अमेरिकी विदेश-नीति के 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा करते हुए 20 जनवरी, 1949 को कहा कि—“आगामी वर्षों में शान्ति और स्वतन्त्रता के कार्यक्रम में चार प्रधान बातों पर बल दिया जाएगा—

- (i) संयुक्त राष्ट्रमण्डल का पूर्ण समर्थन
- (ii) विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के कार्य करते रहना,
- (iii) आक्रमण के विरुद्ध स्वतन्त्रता-प्रेमी राष्ट्रों को सुदृढ़ बनाना, एवं
- (iv) अल्पविकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक (Technical) सहायता देना ।”

कांग्रेस ने सन् 1950 के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम (Act for International Development) द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया । रिचर्ड स्टीबिंस (Richard P. Stebbins) के शब्दों में, “यह कानून अमेरिकी विदेश-नीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था ।” इस योजना द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी क्योंकि अर्द्ध-विकसित देशों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक थीं तथा इसके द्वारा अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की साधना होती थी । हालाँकि द्वारा चार-सूत्री कार्यक्रम को शीतयुद्ध का ही अस्व माना गया । कहा गया कि यह अर्द्ध-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा उनमें आवश्यक रणनीति का सामान प्राप्त करने का एक तरीका है ।

नाटो : अवरोध की रणनीति (NATO : The Strategy of Containment)—राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर के साथ संयुक्तराज्य अमेरिका ने संनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के अवरोध का प्रयत्न किया । हमने हमारे देशों के

साथ सैनिक सन्धियों और पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम (Mutual Defence Assistance Programme) का तरीका अपनाया जो अमेरिकी विदेश-नीति में एक नवीन प्रयोग था। सैनिक अवरोध की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका द्वारा नाटो का संगठन किया गया और 4 अप्रैल, 1949 को संयुक्तराज्य, कनाडा, इटली, आइसलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क और पुर्तगाल के बीच यह प्रथम सैनिक सन्धि सम्पन्न हो गई। यह उत्तरी अटलांटिक सन्धि अनेक तरह से एक 'नया परिवर्तन' (Innovation) थी। यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति अमेरिका ने स्वयं को वचनबद्ध किया। इसी के साथ यूरोपीय देशों की रणशक्ति बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया।

संयुक्तराज्य अमेरिका को तेजी से सैनिक सन्धियों के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उत्तरदायी एक और महत्वपूर्ण घटना यह थी कि सोवियत रूस ने सन् 1949 में ही एटम बम (Atom Bomb) के रहस्यों को खोज निकाला था जिन्हें संयुक्तराज्य अमेरिका ने सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा था। रूस की इस खोज से संयुक्त राज्य अमेरिका के अणुशक्ति पर एकाधिकार (Monopoly) का अन्त हो गया और उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया।

खुले संघर्ष का काल (जून 1950-जुलाई 1953)

साम्यवाद का खतरा ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, संयुक्तराज्य अमेरिका महत्वपूर्ण सैनिक सन्धियों और प्रतिरक्षा संगठनों की ओर उन्मुख होता गया। जून, 1950 में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत अमेरिकी सेनाओं ने ही लगभग पूर्ण युद्ध लड़ा, अमेरिकी विदेश-नीति में सैनिक शक्ति का महत्व द्विगुणित हो गया। स्लीचर (Schleicher) के शब्दों में, "अमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुने से भी अधिक हो गया, यूरोप को दिए जाने वाले सहयोग की अपेक्षा सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने लगा तथा मार्शल योजना की मदें 'सुरक्षा समर्थन की मद' बन गई।"

कोरिया युद्ध जून 1950 से जुलाई 1953 तक चालू रहा। यह अवधि शीतयुद्ध के स्थान पर खुले संघर्ष अथवा सक्रिय युद्ध की थी, इसलिए अमेरिकी युद्धोत्तर विदेश-नीति के इतिहास में यह एक प्रकार का 'खुले संघर्ष का काल' (Period of Open Conflict) रहा। इस अवधि में अवरोध-नीति के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष महत्त्व देते हुए 30 अप्रैल, 1951 को अमेरिका ने फ्लिपिन्स के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता किया, 1 सितम्बर, 1951 को ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड के साथ एजस समझौता किया और दसरी तरह 8 सितम्बर, 1951 को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा-सन्धि की।

स्पष्ट है कि अमेरिकी प्रशासन में सैनिक शक्ति के उपयोग एवं सैनिक तथा प्रतिरक्षा समझौतों के महत्त्व की विचारधारा बलवती हुई। इस तरह अमेरिका अपनी विदेश-नीति में अब आर्थिक और सैनिक दोनों ही तत्वों को प्रधानता देने लगा। ये दोनों ही तत्व आज भी अमेरिकी विदेश-नीति के प्रधान अंग बने हुए हैं।

आइजनहाॅवर-युग (1953-1960)

जनवरी सन् 1953 में 24 वर्षों में प्रथम बार एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में जनरल आइजनहाॅवर ने ह्वाइट हाउस में प्रवेश किया। इसके पूर्व ही मार्च 1953 में सोवियत अधिनायक स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी। आइजनहाॅवर-काल में सोवियत नेतृत्व में भी दो परिवर्तन हुए—स्टालिन के तुरन्त बाद मोलेकोव इस का प्रधानमन्त्री बना और फरवरी सन् 1955 में उनके पतन के बाद ख्रुश्चेव-युग (1955-1964) प्रारम्भ हुआ।

आइजनहाॅवर-काल में अमेरिकी विदेश-नीति के मुख्य बिन्दु

आइजनहाॅवर-युग में अमेरिकी विदेश-नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए, केवल कुछ सामयिक परिवर्तन किए गए और ट्रूमैन-सिद्धान्त की भाँति ही मध्यपूर्व के लिए 'आइजनहाॅवर-सिद्धान्त' प्रतिपादित किया गया। आइजनहाॅवर-काल में अमेरिकी विदेश-नीति का स्वरूप निम्नानुसार रहा—

1. यथासम्भव युद्ध का बहिष्कार किया गया। आइजनहाॅवर के समय में ही जुलाई सन् 1953 में कोरिया-युद्ध समाप्त हुआ।

2. दूसरे देशों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई, लेकिन वही दुर्बलता प्रकट नहीं की गई। आइजनहाॅवर के समय अमेरिका ने कहीं भी तुष्टिकरण की नीति (Policy of Appeasement) नहीं अपनाई।

3. साम्यवाद को प्रसार को सीमित या समाप्त करने के लिए अधिक और सैनिक सहायता की नीति जारी रखी गई। मंत्रीपूर्ण सैनिक सन्धिषो की नीति भी चालू रही।

4. अमेरिकी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया गया, लेकिन विश्व के देशों को यह आश्वासन दिया गया कि अमेरिका अपनी सैन्य-शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विश्व के उत्पादन और लाभपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई।

6. यूरोपीय एकता को प्रोत्साहन दिया गया और पश्चिमी मोलाद्ध के देशों के साथ अधिकाधिक सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया।

7. संयुक्तराष्ट्रसंघ का समर्थन करते रहने और इसका साम्यवाद के विरुद्ध एक साधन के रूप में प्रयोग में लाने की नीति अपनाई गई।

आइजनहाॅवर युग की विदेश-नीति की मुख्य घटनाएँ

साम्यवाद के साथ शक्ति-परीक्षण, कोरिया-युद्ध की समाप्ति—सन् 1949 में सोवियत संघ द्वारा अणुबम के रहस्य को खोज निकालने और अमेरिका के आणविक एकाधिकार को समाप्त करने के वाद से ही संयुक्तराज्य अमेरिका में विशेष चिन्ता व्याप्त हो गई थी। इसीलिए वह निश्चय किया गया था कि इसके पहले कि सोवियत संघ अधिक शक्तिशाली हो जाए, उसको युद्ध में फँसाकर कमजोर बना दिया

जाए तथा उसकी सामरिक शक्ति का विनाश कर दिया जाए। यह 'प्रतिकारात्मक युद्ध' (Preventive War) की भावना थी। जून सन् 1950 में छिड़ने वाला कोरियाई युद्ध इसी नीति का परिणाम था। लेकिन जब युद्ध में अमेरिका की प्रतिष्ठा तक पर घाति माने लगी तो अमेरिका का जनमत विक्षुब्ध हो गया। आइजनहावर ने राष्ट्रपति-पद के चुनावों में जनता को बचन दिया कि वह कोरियाई युद्ध को समाप्त कर देगे। राष्ट्रपति बनते ही आइजनहावर ने एक ओर तो पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने की ओर दूसरी ओर समझौते के द्वार खुले रखने की नीति अपनाई। जुलाई, 1953 में कोरिया में युद्ध-विराम हो गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि साम्यवादी-विश्व से खुली टक्कर में निर्णायक विजय प्राप्त करना अमेरिका के लिए असम्भव है।

पश्चिमी यूरोप के एकीकरण, अणुशक्ति पर नियन्त्रण आदि के प्रयत्न—मई सन् 1953 में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका का शिखर-सम्मेलन हुआ। पश्चिमी-यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्न किए गए। सन् 1954 में इतने अधिक सम्मेलन हुए कि विदेश-सचिव जान फोस्टर डलेस को यात्री राज्य-सचिव की सजा दी जाने लगी। पश्चिमी यूरोप को एकीकृत करने के प्रयत्नों के फलस्वरूप इसी वर्ष पश्चिमी यूरोपीय संघ (Western European Union) की स्थापना की गई और जर्मनी को नाटो का सदस्य बना लिया गया। सोवियत संघ द्वारा सन् 1953 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लेने के बाद दिसम्बर सन् 1953 में आइजनहावर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में अणु-शक्ति पर नियन्त्रण और उसका शान्ति के प्रयोग का प्रस्ताव रखा।

साम्यवाद के अवरोध के लिए सीटो तथा बगदाद-पैक्ट की स्थापना—सन् 1954 में साम्यवादी चीन की सहायता से साम्यवादी छारामारो द्वारा हिन्द चीन में गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गई। फलस्वरूप जुलाई में हिन्द चीन, फ्रांस, साम्यवादी चीन, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने जेनेवा सम्मेलन में हिन्द चीन को विभाजित करने का निर्णय किया। इसके उत्तरी भाग में वियतमिन्ह (बाद में उत्तर वियतनाम) का साम्यवादी राज्य स्थापित किया गया और दक्षिणी भाग को लाओस, कम्बोडिया और दक्षिण वियतनाम के तीन गैर-साम्यवादी राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इस घटना-चक्र ने संयुक्तराज्य अमेरिका को साम्यवादी चीनी प्रसार को अवरोध करने के लिए दृढ़ सकल्प बना दिया। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने सितम्बर सन् 1954 में थाईलैण्ड फिलिपाइस पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के साथ 'दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक सुरक्षा सन्धि' पर हस्ताक्षर कर सीटो (SEATO) की स्थापना की।

इसी प्रकार पश्चिमी एशिया के देशों की साम्यवाद में रक्षा के लिए सन् 1955 में बगदाद समझौते (Bagdad Pact) का मूनवात हुआ। इस सैनिक सन्धि में अमेरिका सहित ब्रिटेन, टर्की, ईरान, पाकिस्तान आदि सम्मिलित हुए।

मध्य-पूर्व और आइजनहावर सिद्धान्त—पश्चिमी एशिया तथा मध्य-पूर्व में

वगदाद-पैकट की स्थापना साम्यवाद के विरुद्ध विशेष प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई, पर शीघ्र ही अमेरिका को इस दिशा में अग्रसर होने का एक और सुअवसर मिल गया। जब सन् 1956 में स्वेज-नहर के प्रश्न पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने उन्हें स्पष्ट परामर्श दिया कि वे अपना मिस्र पर आक्रमण समाप्त कर दें। उबन रुस ने भी चेतावनी दी। परिस्थितियों से बाध्य होकर आक्रमणकारियों को स्वेज से हटाना पड़ा और मध्यपूर्व में अमेरिका के लिए सहानुभूति बढ़ गई। इस समय स्थिति यह थी कि ब्रिटेन और फ्रांस के हट जाने से मध्य-पूर्व में 'शक्ति शून्यता' पैदा हो गई थी और भय था कि रुस अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। अतः अमेरिका ने इस 'शक्ति-शून्यता' को भरना चाहा और इस क्षेत्र में साम्यवादियों का प्रसार रोकने के लिए 'आइजनहॉवर-सिद्धान्त' (Eisenhower Doctrine) प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धान्त की घोषणा 5 जनवरी, 1957 को राष्ट्रपति आइजनहॉवर द्वारा कांग्रेस को भेजे गए एक संदेश में की गई। इस घोषणा के आधार पर बन कानून पर राष्ट्रपति ने 9 मार्च, 1958 को हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए अपने विवेक से सैनिक भेजने और सैनिक कार्यवाही करने का व्यापक अधिकार मिल गया। कांग्रेस ने आइजनहॉवर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता के इच्छुक मध्यपूर्वी देशों की सहायता के लिए 200 मिलियन डॉलर की विशाल धनराशि स्वीकृत की।

आइजनहॉवर-सिद्धान्त के प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाएँ हुईं। जोर्डन, लेबनान, ईराक, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि ने इसका स्वागत किया जबकि मिस्र, सीरिया आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बतताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अरब राष्ट्रवाद को कुचलने और इजरायल को अरबों पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। सोवियत संघ ने इसे विदेशी हस्तक्षेप और एकदम की सला दी। वास्तव में आइजनहॉवर सिद्धान्त ट्रूमैन सिद्धान्त का ही एक विकसित रूप था जिसमें सहायता का क्षेत्र आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार का था। ट्रूमैन सिद्धान्त की भाँति यह भी अमेरिका के 'नवीन साम्राज्यवाद' का सूत्र था।

आइजनहॉवर-सिद्धान्त की घोषणा के बाद शीघ्र ही अमेरिका के सामने ऐसे अवसर उपस्थित हुए जब उसे इस सिद्धान्त के प्रयोग का अवसर प्राप्त हुआ। लेबनान और जोर्डन में इस सिद्धान्त का प्रयोग हुआ, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से यह अधिक सफल नहीं हो सका। सर्वप्रथम सन् 1958 में लेबनान के राष्ट्रपति ने अपने विरुद्ध विद्रोह के दमन के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता की माँग की। सुरक्षा-परिषद् में शिकायत की गई कि सीरिया और मिस्र विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं। जुलाई में अमेरिकी सेनाएँ लेबनान में उतर गईं। अगस्त 1948 में संयुक्तराष्ट्र-महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा माँग की गई कि अमेरिका लेबनान में अपनी सेनाएँ वापस बुला ले, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से साफ इकार कर दिया। लेबनान में गृह-युद्ध जारी रहा और विद्रोही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने में सफल हुए। नई

सरकार की मांग पर अमेरिका को 26 अक्टूबर, 1958 को सेवनान खाली कर देना पड़ा। जुलाई, 1958 में ईराकी त्रान्ति से जोर्डन के शाह को आशंका हुई कि कहीं जोर्डन में भी सैनिक विद्रोह न हो जाए, प्रतः ब्रिटेन और अमेरिका से सैनिक सहायता मांगी गई। ब्रिटेन ने अपनी सेनाएँ जोर्डन भेजी तो अमेरिका ने शाह हुसैन को 75 लाख डॉलर की नई आर्थिक सहायता प्रदान की। पर दोनों ही कार्यवाहियाँ अप्रभावी रही क्योंकि संयुक्तराष्ट्र महासभा के अगस्त 1958 के प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटेन को अपनी सेनाएँ जोर्डन से वापस बुलानी पड़ी। ब्रिटिश सहायता से 'आइजनहॉवर सिद्धान्त' का जो सैनिक प्रयोग जोर्डन में किया गया वह निष्फल रहा।

वास्तव में 'आइजनहॉवर सिद्धान्त' को मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव को रोकने में सफलता नहीं मिली, इसके विपरीत लेबनान और जोर्डन में सैनिक हस्तक्षेप के फलस्वरूप मास्को के प्रभाव-क्षेत्र में वृद्धि हुई। 'आइजनहॉवर सिद्धान्त' से संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचा। यह सिद्धान्त विश्व-संस्था को निर्वल बनाने वाला सिद्ध हुआ। यह क्षोभ की बात थी कि राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने मध्यपूर्व में नवीन राष्ट्रीयता के जागरण की उपेक्षा की। इज्राइल के विरुद्ध अरबों के तीव्र विरोध ने भी इसकी सफलता के मार्ग में बाधा उपस्थित की। व्यावहारिक दृष्टि से आइजनहॉवर सिद्धान्त को मामूली सफलता प्राप्त हो सकी।

शीतयुद्ध में शिथिलता (1959-60)—आइजनहॉवर सिद्धान्त के कारण शीतयुद्ध तीव्र हो गया, लेकिन सितम्बर, 1959 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर सोवियत प्रधानमन्त्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की, तो वातावरण में सुधार हुआ। दोनों नेताओं ने यह निर्णय लिया कि पारस्परिक मतभेदों के प्रश्नों पर वार्ता के लिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सन् 1960 के अन्त-काल में रूस की यात्रा का निमन्त्रण भी स्वीकार किया।

शिखर सम्मेलन की सफलता—काफी विचार-विमर्श के बाद 16 मई, 1960 को प्रस्तावित शिखर-सम्मेलन होना निश्चय हुआ। दुर्भाग्यवश सम्मेलन के पूर्व ही मुख्य रूप से दो अवशकुन हो गए—

(i) जर्मनी से सम्बन्धित विवाद, एवं (ii) यू-2 विमान काण्ड।

(1) पहला अवशकुन जर्मनी के सम्बन्ध में हुआ। 14 जनवरी, 1960 को पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर फ्रीडेनर ने आरोप लगाया कि रूसी बॉलिन पर हमला कर रहे हैं तथा शिखर-सम्मेलन का मुख्य विषय जर्मनी के स्थान पर निःशस्त्रीकरण का प्रश्न होना चाहिए। ख्रुश्चेव ने घमकी दी कि "यदि पूर्व और पश्चिम की वार्ता से बॉलिन की स्थिति में कोई परिवर्तन न हुआ तो वह पूर्वी जर्मनी से पृथक् सन्धि कर लेगा और पोलैण्ड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ उसकी सीमा का निर्धारण कर देगा।"

फरवरी, 1960 में रूस ने बॉलिन में एक नया सकट पैदा कर दिया। पूर्वी जर्मनी में विद्यमान पश्चिमी देशों के सैनिक मिशनों को दिए जाने वाले वीसा पूर्वी

जर्मन सरकार के नाम से जारी कर दिए गए जबकि अब तक ये पूर्वी जर्मनी के सोवियत अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि हम इस प्रकार पश्चिमी देशों से पूर्वी जर्मनी की सरकार को 'वास्तविक मान्यता' (De facto Recognition) दिलवाना चाहता था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स के दृढ़ विरोध के पश्चात् ग्रन्थ में 14 मार्च, 1960 को सोवियत हम इस बात पर सहमत हो गया कि पश्चिमी देशों के सैनिक अधिकारियों को पूर्वी जर्मनी की यात्रा के लिए जो बीमा दिए जाएंगे उन पर सोवियत अधिकार-क्षेत्र (Zone of Soviet Occupation) अस्ति रहेगा।

इसके बाद फिर तनाव पैदा हुआ। 16 मार्च को पश्चिमी जर्मन-बान्स्तर में घोषणा की कि 16 मई को शिखर सम्मेलन होने से पहले ही पश्चिमी बर्लिन में हम बात पर जनमत संग्रह लिया जाए कि लोग बर्लिन में क्या स्थिति बनाए रखने के पक्ष में हैं अथवा नहीं। इसके विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि इन प्रकार का जनमत संग्रह बर्लिन के दोनों भागों में होना चाहिए।

स्पष्ट ही ऐसे बानावरण में दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति सन्देह पूर्वापेक्षा अधिक बढ़ गया जिसका कुपभाव शिखर-सम्मेलन पर पड़ा।

(ii) शिखर-सम्मेलन के मार्ग में दूसरा मड़ने बड़ा अपशकुन यू-2 विमान-बाण्ड हुआ। 5 मई, 1960 को सोवियत प्रधानमन्त्री ने रोषपूर्ण शब्दों में घोषणा की कि हम के हवाई अड्डों की जासूसी करने हुए एक यू-2 अमेरिकी विमान को 1 मई, 1960 को रॉकेट द्वारा नीचे गिरा दिया गया है। हम ने अमेरिका पर बटु-प्रहार किए और बाद में राष्ट्रपति आइजनहॉवर की इस घोषणा ने आश में धी का काम किया कि "अमेरिका की जासूसी उड़ानें ग्याय-सगत हैं और परलंतावर पुनरावृत्ति रोकने के लिए उड़ानें आवश्यक हैं।" सोवियत हम ने आइजनहॉवर के इस चुनौती भरे शब्दों की अपना राष्ट्रीय अपमान समझा।

यू-2 विमान बाण्ड से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुँच गया और शिखर सम्मेलन की सफलता की आशा घूमिल हो गई, लेकिन कृश्चेव की इन घोषणाओं से फिर भी आशा बनी रही कि "अन्तर्राष्ट्रीय दबाव हम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए और शिखर सम्मेलन में यू-2 का विषय नहीं उठाया जाएगा।"

लेकिन जब 16 मई को शिखर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो सोवियत प्रधानमन्त्री ने प्रधानक ही यू-2 बाण्ड के लिए अमेरिका की निन्दा करते हुए निम्नलिखित मर्मि वेष कर दी—

- (क) अमेरिका को अपने उद्योगात्मक कार्य की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए क्षमा माँगनी चाहिए, इस कार्य को बन्द करना चाहिए, और इस बाण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए।
- (ख) यदि ऐसा नहीं किया जाता तो हम की दृष्टि में शिखर सम्मेलन में अमेरिका के साथ बातचीत करना व्यर्थ है और वह इसमें भाग नहीं ले सकता।

ख्रूशचेव ने यह भी कहा कि सम्मेलन को 6 या 8 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों के बाद जनवरी, 1961 में यह आयोजित हो सके। आइजनहाउवर द्वारा जासूसी उड़ानों को भविष्य में स्थगित कर देने के प्रस्तावनों के बावजूद ख्रूशचेव अपनी मांग पर मड़े रहे। 17 मई को सम्मेलन आरम्भ होने पर ख्रूशचेव जब नहीं आए तो यह घोषणा कर दी गई कि "ख्रूशचेव द्वारा अपनाए गए रुख के कारण शिखर सम्मेलन आरम्भ करना सम्भव नहीं है।"

कैनेडी-युग (1960-1963)

नवम्बर 1960 में सीनेटर जॉन एफ. कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कैनेडी एक विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति थे। एक इतिहासकार के शब्दों में, "कैनेडी में लिकन का राजनीतिक बोध, थियोडोर हजवेल्ड का चुम्बकीय आकर्षण और चमत्कारी तेज, एड्रू जैक्सन का ठण्डा रोप, विल्सन का पंना विवेक तथा वार्फुल्ड और फ्रैंकलिन हजवेल्ड का नीति-कौशल सब एक ही साथ विद्यमान थे।" कई दिशाओं में कैनेडी इनसे भी बढ़कर थे। व्यापक ज्ञान, विचारों की सुस्पष्टता, गहरी पठ, अदृशवाद और त्रियावाद का सुन्दर समतुलन उनकी अपनी ही विशेषताएँ थी। उनके सकल्यों की दृढ़ता और उनकी कार्य-पद्धति लोगों को चकित कर देती थी। उनकी बाणी में ओज, उनके विचारों में साहस, उद्देश्यों में बल और भाषणों में आकर्षण था। राष्ट्रपति पद पर कैनेडी की विजय डेमोक्रेटिक दल की विजय थी।

कैनेडी-युग में अमेरिकी विदेश-नीति को नया मोड़

कैनेडी ने कुछ दृष्टियों से अमेरिका की विदेश-नीति को नया मोड़ दिया, नई गति दी। विदेश-नीति के पुराने तत्त्व भी कैनेडी-युग में अधिक प्राणवान बन गए। मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन चाहे न हुए हो, किन्तु कैनेडी के समय वे इतने सजीव बन गए कि ऐसा लगने लगा मानो विदेश-नीति में एक नई जान आ गई हो। कैनेडी-युग की अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य बिन्दु ये थे—

1. समझौते और वार्ताओं द्वारा पूर्व और पश्चिम के मतभेदों को कम किया जाए पर साथ ही साम्यवादो खतरे के विरुद्ध साहस और दृढ़ता की नीति अपनाई जाए।

2. विश्व में साम्यवाद के अतिरिक्त गरीबी और अन्य तानाशाहियाँ भी शत्रु हैं। विश्व की परेशानियों का कारण केवल साम्यवाद ही नहीं है और अमेरिका को साम्यवाद का मुकाबला करने के साथ-साथ विश्व के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को और भी ध्यान देना चाहिए।

3. विश्व में डॉलर का मूल्य सुरक्षित रखा जाए तथा इसकी साख में कमी न होने दी जाए।

4. ऐसे प्रयत्न बरबरा किए जाएँ कि महाशक्तियाँ एक दूसरे के निकट आएँ तथा एक दूसरे को समझें। महाशक्तियाँ अपने पारस्परिक सम्बन्धों को अधिक समय तक ढीला और बटु नहीं रख सकती।

5. दोनों गुटों के बीच असह्यता और गलन-फहमी के कारण अनेक संकट पैदा हो जाने हैं हिन्तु विचारों के स्पष्ट आदान-प्रदान द्वारा इन्हें मिटाया जा सकता है।

6. साम्यवाद को सीमित करने के लिए पूरे विश्व को यहाँ तक कि लोह-दीवार के भग्दर के प्रदेशों को भी राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र बनाया जाए।

7. पूर्ण दृढ़ता और साहस की नीति का अनुसरण करते हुए तथा साम्यवादी छल-प्रपञ्च के प्रति सचेत रहते हुए यथा-साध्य सहप्रस्तित्व की प्रणाली पर बल दिया जाए।

कैनेडी-युग में विदेश-नीति सम्बन्धी मुख्य घटनाएँ

कैनेडी शासन-काल में अमेरिकी विदेश-नीति का विश्लेषण निम्नलिखित सन्दर्भों में किया जाना उपयुक्त होगा—

मानव-अधिकार और कैनेडी—कैनेडी ने मानव-अधिकारों के प्रति दृढ़ निष्ठा व्यक्त की और इसे अमेरिकी विदेश-नीति की प्रेरक शक्ति बताया। 20 नवम्बर, 1963 को उन्होंने नागरिक अधिकारों के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्रसभ में विचार-विमर्श किया और घोषणा प्रकट की कि अमेरिका सहित विश्व के सभी राष्ट्र वर्ण-भेद, जाति-भेद आदि को मिटाकर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान सुरक्षा प्रदान करेंगे।

शान्ति और सह-प्रस्तित्व में विश्वास—10 जून, 1963 को अपने भाषण में कैनेडी ने विश्व-शान्ति को सबसे महत्वपूर्ण विषय बतलाने हुए घोषणा की कि यह शान्ति विश्व पर अमेरिकी शास्त्रास्त्रों से थोपी हुई अमेरिकी शान्ति नहीं होगी बल्कि यह ऐसी शान्ति होगी जिससे पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य बने और राष्ट्रों तथा व्यक्तियों को विकास का प्रबलर उपलब्ध हो। कैनेडी ने शान्ति और निःशस्त्रीकरण के प्रति स्वोक्ति दृष्टिकोण की भर्त्सना नहीं की, बल्कि शान्ति की दिशा में रुस के सम्भावित प्रभावों को उभारा। कैनेडी में सहप्रस्तित्व की हादिक और उत्कट भावना थी।

पुराने मित्रों के प्रति वफादारी—रूसो-साम्यवादी व्यवस्था के प्रति सहप्रस्तित्व का नारा बुलन्द करने के साथ ही कैनेडी ने 'वफादार मित्रों के प्रति निष्ठा' रखने का भी वचन दिया और उसे निभाया भी। उन्होंने नाटो (NATO) का आर्थिक और राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए तथा जर्मनी के प्रश्न पर भुक्ने से इकार कर दिया। जून, 1961 में जब एड्रुचेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पुण्य सन्धि पर हस्ताक्षर करने की घमकी दी और कहा कि इससे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान के लिए पश्चिमी बर्लिन में जाने के अधिकार समाप्त हो जाएँगे, तो कैनेडी ने सोवियत घमकी का जवाब विवेकपूर्ण अस्वीकृति में दिया। उनके नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने रुस को स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि रुस की एकपक्षीय कार्यवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। अमेरिका और

उसके मित्रराष्ट्रों की इस दृढ़ता का परिणाम यह हुआ कि रूस ने अपनी धमकी को कार्यान्वित नहीं किया।

क्यूबा संकट और कनेडी—राष्ट्रपति कनेडी के कार्यकाल में क्यूबा के संकट ने केवल अमेरिकी राष्ट्र को ही नहीं बल्कि सारे विश्व को हिला दिया। इस घटना में कनेडी की विदेश-नीति की दृढ़ता स्पष्ट रूप से उजागर हुई। क्यूबा लम्बे समय तक अमेरिका का समर्थक था, लेकिन जून, 1959 में फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में हुई एक क्रान्ति के बाद वह रूस-समर्थक बन गया। 3 सितम्बर, 1962 को इस रूसी घोषणा ने भावी संकट का संकेत दिया कि वह क्यूबा को साम्राज्यवादियों से रक्षा के लिए शस्त्रास्त्रों की पूर्ण सहायता देगा। उबर राष्ट्रपति कनेडी ने कहा कि रूस ने क्यूबा को प्रक्षेपास्त्रों, पनडुब्बियों तथा रॉकेट आदि से सज्जित किया है जिनसे अमेरिका की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। 7 सितम्बर को अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को डेढ़ लाख रिजर्व सैनिकों को आवश्यकता पडने पर सैनिक सेवा के लिए बुला लेने का अधिकार दिया। 16 सितम्बर, 1962 को कनेडी ने क्यूबा की हवाई जाँच-पड़ताल के आदेश दिए जिनसे पुष्टि हो गई कि वहाँ प्रक्षेपास्त्रों का भारी संग्रह हो रहा है। 22 अक्टूबर को कनेडी ने अपने चेतावनी-पूर्ण भाषण में स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की विदेश-नीति में सुरक्षा का तत्त्व कितना प्रबल है और भंडो तथा सहयोग का आकांक्षी अमेरिका किम हद तक सैनिक कार्यवाही का धातय ले सकता है। 23 अक्टूबर को कनेडी ने क्यूबा की नाकेबन्दी की घोषणा कर दी। यह आदेश हम को स्पष्ट चेतावनी थी कि उसके शस्त्रास्त्रों से सज्जित जहाज क्यूबा नहीं पहुँच सकते, अन्यथा युद्ध होगा।

इस घोर संकट के समय सोवियत प्रधानमन्त्री ख्रुश्चेव ने भी बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। 23 अक्टूबर को ही ख्रुश्चेव द्वारा घोषणा की गई कि रूस क्यूबा से अपने प्रक्षेपास्त्र वापस भंगाने की आशा दे रहा है और वह उस द्वीप पर स्थित सभी प्रक्षेपास्त्र अड्डों को संयुक्त राष्ट्रसंघ की देखरेख में समाप्त करने को सहमत है। सोवियत प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा कि रूस भविष्य में इस प्रकार की सामग्री क्यूबा न भेजने का भी आश्वासन देता है। राष्ट्रपति कनेडी ने ख्रुश्चेव की घोषणा का तुरन्त उत्तर दिया—“यह एक सच्चे नेता सरीखा निर्णय है।”

कनेडी की दृढ़ता और सत्परता तथा ख्रुश्चेव के विवेक और संयम के फलस्वरूप क्यूबा संकट से उत्पन्न अणुयुद्ध की आशंका टल गई। क्यूबा के अन्तर्राष्ट्रीय संकट के बहुत व्यापक परिणाम हुए—(1) हम-चीन के सैद्धांतिक मतभेद बढ़ गए। चीन ने आरोप लगाया कि रूस अमेरिका से डर कर पीछे हटा है। (2) क्यूबा-संकट ने भारत पर चीन के आक्रमण को प्रेरित किया। चीन ने सोचा कि अमेरिका और हम संघर्ष में उलझे, भारत को पश्चिम से सहायता नहीं मिल सकेगी और चीन भारत के बड़े भू-भाग पर कब्जा कर लेगा, (3) क्यूबा-संकट के निवारण के फलस्वरूप पश्चिम से भारत को तेजी से सहायता मिली तथा गुट निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को बल मिला।

अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि, 1963—कैनेडी और ख्रुश्चेव के विवेक से दोनों देशों का विरोध कम हुआ और सन् 1963 में अणुपरीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि ने मास्को तथा वाशिंगटन के बीच सीहार्दपूर्ण वातावरण की सृष्टि की। कैनेडी ने निश्चयीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। इस सम्बन्ध में अमेरिका की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए—(1) सभी राष्ट्र परीक्षणों पर प्रतिबन्ध की सन्धि पर हस्ताक्षर करें। प्रतिबन्ध लगाने की बातें शुरू करने के लिए आम निश्चयीकरण होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है और न करनी चाहिए, (2) प्रमाणांशों में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन बन्द किया जाए और इन समय बिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, उन्हें इन विस्फोटक पदार्थों को हस्तान्तरण न किया जाए, (3) उन राष्ट्रों की परमाणु-अस्त्रों पर नियन्त्रण हस्तान्तरित करने से रोका जाए जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं, (4) परमाणु-अस्त्रों को अन्तरिक्ष में नए युद्ध-क्षेत्रों के बीज बोने से रोका जाए, (5) इस समय तक जो परमाणु-अस्त्र बन चुके हैं उन्हें धीरे-धीरे नष्ट कर दिया जाए और उनमें लगी सामग्रियों को शान्तिपूर्ण कार्यों में प्रयुक्त किया जाए, (6) परमाणु-अस्त्रों को ले जाने वाले सार्वजनिक सड़कों के वाहनों के उत्पादन और असीमित परीक्षण पर रोक लगायी जाए व धीरे-धीरे उन्हें भी नष्ट कर दिया जाए।

काफ़ी प्रयत्न के बाद अन्त में 25 जुलाई, 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के बीच एक परमाणु-परीक्षण प्रतिबन्ध-सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए जिस पर बाद में फ्रांस और चीन को छोड़कर, विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने भी हस्ताक्षर कर दिए। सन्धि में कुछ ही दिवस पूर्व 15 अप्रैल, 1963 को अमेरिका और रूस के बीच सीवा टेल्फोन और रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U. S. Soviet Hot Line Agreement) हुआ जिसका उद्देश्य क्यूबा जैसे संकटों के समय दोनों देशों में सीवा सम्पर्क स्थापित कर गलती या प्राकृतिक घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निवारण करना था।

लेटिन अमेरिका और कैनेडी—कैनेडी ने लेटिन अमेरिका के प्रति उदार और मैत्रीपूर्ण नीति अपनायी। कैनेडी से पहले 'अमेरिकी राज्यों के संगठन' (O.A.S.) द्वारा सैनिक तथा कूटनीतिक सहयोग पर अधिक बल दिया जाता था पर कैनेडी ने आर्थिक सहयोग पर अधिक बल देना शुरू किया। मार्च, 1961 में उन्होंने अमेरिकी नए राज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों के समक्ष 'प्रगति के लिए मैत्री' (Alliance for Progress) का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार अन्य स्वतन्त्र देशों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तिगत पूंजीपतियों ने मिलकर संयुक्तराज्य अमेरिक के लेटिन अमेरिका के आर्थिक विकास एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए 20 हजार मिलियन डॉलर की सहायता तथा ऋण देने की पेशकश की। अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति कैनेडी ने पश्चिमी गोलार्द्ध के राष्ट्रों के प्रति एवं विशेष प्रियज्ञा की कि "वे संयुक्तराज्य अमेरिका के अच्छे शब्दों को 'प्रगति के लिए मैत्री' के रूप में अच्छे कामों में परिणत करेंगे जिससे स्वतन्त्र लोगो तथा स्वतन्त्र सरकारों का निर्धनता की जज़ीरें तोड़ फँकने में सहायता दी जा सके।"

कैनेडी ने दक्षिणी अमेरिका के देशों के प्रति सहायता की नीति अपनायी जिसका अच्छा परिणाम निकला। दक्षिणी अमेरिका के देश प्रल्पकाल में ही आर्थिक और सामाजिक विकास के पथ पर अग्रसर होने लगे।

भारत-पाकिस्तान तथा कैनेडी—कैनेडी ने भारत के प्रति सहानुभूति और सदाशयता की नीति अपनायी, यद्यपि 'दबाव डालने और अमेरिका के पक्ष में लाने' की नीति का परित्याग नहीं किया गया। भारत-भूमि पर उपनिवेशवाद के अन्तिम चिह्न पुर्तगाली बस्तियों को जब भारत द्वारा मुक्त कराया गया तो अमेरिका प्रशामन की वही उपनिवेशवादी प्रतिभियां हुईं। न केवल सुरक्षा परिषद् में भारत के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाया गया बल्कि अमेरिकी प्रशामन ने भारत की आर्थिक सहायता भी रोक दी। भारत के विरुद्ध कश्मीर के प्रश्न का उपयोग करने का भी प्रयत्न किया गया। जब विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक द्वारा मध्यस्थता के सुझाव को भारत ने स्वीकार नहीं किया तो कैनेडी ने थोड़े दिनों के लिए भारत की आर्थिक सहायता स्थगित कर अपना रोप प्रकट किया। इस प्रकार मौलिक रूप से कैनेडी प्रशासन भी भारत को अमेरिकी विदेश-नीति का दास बनाने की नीति पर चलता रहा। फिर भी कैनेडी का रुख भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तुलना में भारत के प्रति अधिक उदार रहा। सन् 1962 में चीनी आक्रमण के समय बिना शर्त भारत को अदिलम्ब सैनिक सहायता भेजकर कैनेडी ने भारत में अमेरिकी विरोधी भावना को बहुत कुछ शान्त कर दिया।

कैनेडी और वियतनाम—कैनेडी को दक्षिण वियतनाम के विरुद्ध वियतनाम की सफलता सहन नहीं हुई और उन्होंने दक्षिण वियतनामी सरकार की सहायता करने का निश्चय किया। सन् 1961 में दक्षिण वियतनाम में केवल 700 के लगभग अमेरिकी सैनिक थे जिन्हें सन् 1963 में बढ़ाकर 16 500 कर दिया गया। घन और अस्त्र-शस्त्रों से भी दक्षिण वियतनाम की दिग्गज सरकार की सहायता की गई। कैनेडी की विदेश-नीति में यह नया मोड़ था और शीघ्र ही वह समय आ गया जब दक्षिण वियतनाम का युद्ध वास्तव में अमेरिका का युद्ध बन गया।

जॉनसन पुन (1964-1968)

22 नवम्बर, 1963 को राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला और बाद में सन् 1964 के निर्वाचन में विजय प्राप्त कर पुनः राष्ट्रपति पद पर प्राप्ति हुए। राष्ट्रपति पद-ग्रहण करने के तुरन्त बाद जॉनसन ने घोषणा की कि विदेश-नीति के क्षेत्र में वे दिग्गज राष्ट्रपति कैनेडी की नीति का अनुसरण करेंगे और अमेरिकी विदेश-नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

जॉनसन की घोषणा प्रारम्भ में तो बहुत-कुछ यथार्थ-सी प्रतीत हुई थी, किन्तु बाद में इसकी यथार्थता प्रमथन करने लगी। जॉनसन ने एक ओर तो शीत-युद्ध

विस्तार रोकने का दिखावा किया और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उग्र और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया।

जर्मन एकीकरण और बर्लिन सम्बन्धी प्रश्न—जर्मनी और बर्लिन के प्रश्न पर युद्ध के बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गम्भीर मतभेद चले आ रहे थे। जॉनसन के प्रशासन-काल में भी अमेरिका की नीति लगभग पहले जैसी ही रही। अमेरिका का कहना था कि जर्मनी के दोनो भागों और बर्लिन में स्वतन्त्र मतदान द्वारा विधान-निर्मात्री सभा की स्थापना की जाए और यह सभा एक केन्द्रीय जर्मन सरकार की स्थापना करे जो विजेता-शक्तियों के साथ सन्धि करे जिससे पोलैण्ड एवं हंगरी द्वारा हथियाये गए प्रदेशों का अन्तिम बँटवारा हो। इसके विपरीत सोवियत दृष्टिकोण भी पहले के समान ही था कि पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी को एक प्रभुत्वान्मय राज्य स्वीकार कर लें और फिर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनो गणराज्य अपने एकीकरण के लिए परस्पर प्रत्यक्ष वार्ता करें। दोनो ही पक्षों की ओर से जर्मन एकीकरण के लिए रचनात्मक कदम उठाए जाने की अपेक्षा कूटनीतिक दाव-पेचों से उलझे हुए सुझाव पेश किए जाते रहे।

साम्यवादी चीन को मान्यता का प्रश्न—जॉनसन ने भी साम्यवादी चीन को मान्यता देने से इन्कार कर दिया। वह यह मानत रहे कि जिम लाल चीन ने आज तक हिंसा और युद्ध का आश्रय लिया है संयुक्त-राष्ट्रसंघ से युद्ध किया है, तिब्बत की स्वतन्त्रता का अपहरण किया है और जो अमेरिका के विनाश की बात करता है, उसे संघ में प्रवेश के योग्य एक शान्तिप्रिय राष्ट्र नहीं माना जा सकता तथा अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता।

निःशस्त्रीकरण का प्रश्न—जॉनसन के शासन काल में आर्थिक परमाणु-परीक्षण रोकने की सन्धि के पश्चात् निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न अवश्य किए गए। परमाणु-शस्त्रों के प्रसार के निषेध के लिए काफी विचार-विमर्श के बाद एक सन्धि का प्रारूप भी तैयार किया गया जो उनके शासन काल की एक उपलब्धि है।

यूरोपीय सुरक्षा का प्रश्न—यूरोपीय सुरक्षा की दृष्टि से भी जॉनसन के शासन काल में अमेरिकी विदेश-नीति को काफी हानि उठानी पड़ी। जनरल डिगान के नेतृत्व में फ्राम अमेरिका के प्रभाव से निरुल गया जिसके फलस्वरूप विवश होकर अमेरिका को नाटो का मुख्यालय पेरिस से हटाकर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स स्थानान्तरित करना पड़ा।

वियतनाम का प्रश्न—जॉनसन के शासन काल में वियतनाम-युद्ध को अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और अन्तर-वियतनाम पर अधिकाधिक उग्र एवं विनाशकारी दमबर्पा की गई। मार्च, 1968 तक जॉनसन-प्रशासन वियतनाम-समस्या पर झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। सन् 1968 के आरम्भ से ही जब उत्तर वियतनामी सेना तथा वियतनामी छापामारों के हाथों अमेरिकी सेना को अपमानजनक पराजय सहनी पड़ी और अमेरिका सहित विश्व के विभिन्न भागों में

युद्ध का तीव्र विरोध होने लगा, तो 31 मार्च, 1968 को जॉनसन ने राष्ट्र के नाम अपने एक सन्देश में यह नाटकीय घोषणा की कि वियतनाम में शान्ति-वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तर वियतनाम पर आंशिक रूप से बमबारी बन्द कर देने के आदेश दिए गए हैं और आगामी चुनावों में वह राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशी नहीं बनेंगे। यद्यपि इस घोषणा से शान्ति-स्थापना के लिए हगोई की शर्तें पूरी नहीं हुईं, तथापि इससे राजनीतिक वातावरण में एक निश्चित परिवर्तन आया।

लेटिन अमेरिका सम्बन्धी नीति—जॉनसन प्रशासन लेटिन अमेरिका के सदस्यों में 'प्रगति के लिए मैत्री' (Alliance for Agreement) कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने में असफल रहा। उसकी मौलिक नीति यही रही कि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों की भौगोलिक दूरी का लाभ उठाकर लेटिन अमेरिका को हर तरह से अमेरिकी प्रभाव-क्षेत्र में रखा जाए। स्वर्गीय कनेडी वयूवा से चोट खाकर वह नहीं चाहते थे कि लेटिन अमेरिका में साम्यवाद पनपे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जॉनसन ने उदार नीति छोड़कर कठोर रवैया अपनाया। लेटिन अमेरिका के प्रति उनकी नीति 'कथनी और करनी' में भिन्न रही।

कोरिया और प्यूलो-शान्ठ—तोपनोका की अमेरिकी कूटनीति की असफलता का पहला जीता-जागता प्रमाण जॉनसन-प्रशासन-काल में मिला। राष्ट्रपति जॉनसन ने 'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी' की नीति को न केवल जारी रखा बल्कि उसका कार्यक्षेत्र और भी बढ़ा दिया तथा इस नीति ने शीघ्र ही एक ऐसा सकट पैदा कर दिया जिसमें अमेरिका को बहुत अपमानित होना पड़ा। अमेरिका के एक जासूसी पोत प्यूलो (Pueblo) को 23 जनवरी, 1968 को उत्तरी कोरिया ने अधिकारियों व कर्मचारियों सहित अपनी प्रादेशिक जल-सीमा में पकड़ लिया जिसके अन्त में अमेरिका को लिखित क्षमा-याचना करनी पड़ी। जॉनसन ने उत्तरी कोरिया को भयभीत करने के लिए विशाल पैमाने पर सैनिक तैयारियाँ कीं, मामले को सुरक्षा-परिपद् में उठाने का संकेत दिया, भीषण परिणामों की चेतावनी दी लेकिन उत्तरी कोरिया नहीं झुका। लाज बचाने के लिए मास्को की सलाह पर अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क ने कूटनीतिक भाषा में अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि "प्यूलो जासूसी पोत भूल से उत्तरी कोरिया के प्रादेशिक जल में भटक गया था।" इस स्वीकारोक्ति से पूर्व अमेरिकी सरकार का यही कहना था कि प्यूलो सूचना सग्रह का सहायक पोत था जिसे जापान सागर में समुद्र तट से 25 मील दूर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पकड़ा गया। अमेरिका की स्वीकारोक्ति के बाद उत्तरी कोरिया ने प्यूलो को छोड़ दिया।

पश्चिम एशिया का सकट—जून, 1967 के अरब-इजरायल संघर्ष में जॉनसन प्रशासन ने पूर्णतः अरब-विरोधी रुख अपनाया। जॉनसन-प्रशासन की यह नीति पश्चिम एशिया के संकट को अधिक तीव्र करने में सहायक हुई। तत्पश्चात् छिड़ने पर भी अमेरिका ने इस बात से अपनी अनभिज्ञता प्रकट की कि आक्रमणकारी कौन है। सुरक्षा-परिपद् में अमेरिका द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि अरब क्षेत्रों से

इजरायली सेना की वापसी सशर्त हो। अमेरिका को सोविपत रुस का यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ कि इजरायल अरब क्षेत्रों से वापस हटे और इजरायली आक्रमण की निन्दा की जाए।

अरब-इजरायल संघर्ष में जॉनसन प्रशासन ने जो नीति अपनायी, वह स्वयं अमेरिकी हितों के भी अनुकूल नहीं थी। अमेरिका ने अरब राज्यों की नाराजगी मोल ले ली। अरब देशों ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिए और अपने देश में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को अविलम्ब वापस चले जाने के आदेश दे दिए। किन्तु इन सब विरोधों के बावजूद जॉनसन प्रशासन के अरब विरोधी रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इतना ही नहीं 25 नवम्बर, 1968 को अमेरिका ने इजरायल को अमेरिकी हथियार बेचने का निर्णय ले लिया। जॉनसन प्रशासन का प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रोत्साहन इजरायल को प्राप्त होना रहा।

भारत-विरोधी रवैया—राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत के प्रति उम उदार रवैये को समाप्त कर दिया जो स्वर्गीय कर्नेडी ने अपनाया था। सन् 1964 में तत्कालीन रक्षामन्त्री चट्टाण जब अमेरिका गए तो उन्हें कहा गया कि भारत को अपनी सुरक्षा-शक्ति अवश्य ही बढ़ानी चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास की कीमत पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए। भारत को तो यह सीख दी गई जबकि पाकिस्तान को सिर से पैर तक शस्त्र-सज्जित किया जाता रहा। सब तर्कों का सार यह था कि अमेरिका भारत को उन्नत किम्प के इवाई जहाज नहीं देना चाहता था। राष्ट्रपति जॉनसन ने विषयनाम पर अमेरिकी वमवारी सम्बन्धी भारत की आलोचना सहन नहीं की और प्रधानमन्त्री शास्त्री की अमेरिकी यात्रा स्थगित कर दी। पाकिस्तान ने कच्छ के रन में और फिर सन् 1965 के युद्ध में भारत के विरुद्ध अमेरिकी हथियारों का प्रयोग किया, लेकिन जॉनसन प्रशासन का वरदहस्त पाकिस्तान के सिर पर रहा। सन् 1968 में भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता नगण्य हो गई। अमेरिका के भारत विरोधी रवैये से क्षुब्ध होकर ही धनूचर, 1968 में संयुक्तराष्ट्र अधिवेशन के लिए न्यूयॉर्क पहुँच कर भी श्रीमती गाँधी वाशिगटन गए बिना ही दिल्ली चली गईं क्योंकि उनके शब्दों में “वहाँ जान में कोई सार्थकता नहीं थी।”

कुल मिला कर यह कहना चाहिए कि जॉनसन शासनकाल में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण न सिर्फ अमेरिका को काफी हानि हुई बल्कि उसे अपनी लोकप्रियता से भी हाथ धोना पड़ा। इस तथ्य को बाद में स्वयं जॉनसन ने भी स्वीकार किया।

निक्सन युग

(1969-अगस्त, 1974)

20 जनवरी, 1969 को रिचार्ड निक्सन संयुक्तराज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने विश्व शान्ति की स्थापना के लिए दुनिया के हर राष्ट्र के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि जहाँ भी शान्ति अस्वायी है वहाँ वे उसे स्थायी बनाने का प्रयत्न करेंगे। निक्सन

का कार्यकाल अमेरिका के इतिहास में 'क्रान्तिकारी' माना जाएगा क्योंकि उन्होंने साम्यवादी जगत् के प्रति अमेरिका की नीति को एक नयी दिशा प्रदान की थी तथा और भी अनेक दृष्टियों से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अमेरिकी विदेश-नीति को मुखर बनाया। सुदीर्घ-कालान्तर से चला आ रहा विषयनाम युद्ध उन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुआ (यद्यपि कालान्तर में यह पुनः भड़क उठा) और महाशक्ति रूस के साथ निःशस्त्रीकरण वार्ताओं में काफी प्रगति हुई। पूँजीवादी और साम्यवादी जगत् में 'सह-अस्तित्व' की सम्भावनाओं की जितना अधिक बल निक्सन के कार्यकाल में मिला उतना पहले कभी नहीं मिला था। कुछ दृष्टियों से निक्सन की विदेशी-नीति 'स्वतन्त्रताक विन्दुओं' को स्पर्श करने लगी, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि निक्सन ने अमेरिका को 'बहुमूल्य सेवाएँ' अर्पित की। दुर्भाग्यवश निक्सन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रणमंच पर 'ईमानदार राजनेता' के रूप में नहीं उभर सके और अपने ही देश में 'वाटरगेट' ने उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। संयुक्तराज्य अमेरिका के सम्पूर्ण इतिहास में निक्सन पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें इस तरह अपमानजनक रूप से पद-त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा था और आने वाले राष्ट्रपति को उन्हें क्षमादान देना पड़ा था। निक्सन युग में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संयुक्तराज्य अमेरिका की गरिबिधि तथा विदेश-नीति के मुख्य विचार-विन्दु इस प्रकार हैं—

यूरोप की सद्भावना यात्रा

राष्ट्रपति बनने के लगभग छ सप्ताह बाद ही निक्सन ने यूरोप की सद्भावना यात्रा की जिसका उद्देश्य एक 'नए यूरोप' को खोज करना था। निक्सन यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ विषयनाम, पश्चिमी एशिया आदि समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान करना चाहते थे तथा अमेरिका के दृष्टिकोण को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। निक्सन की यात्रा पर यूरोप में कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया गया। फ्रांस में तीव्र विरोध हुआ तो पश्चिमी जर्मनी अणु-प्रसार-निरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। यपनी यूरोपीय यात्रा में बेल्जियम को छोड़कर हर जगह राष्ट्रपति निक्सन को अमेरिका-विरोधी नारों की शूँज सुनाई दी। निक्सन समझ गए कि जीतयुद्ध में पश्चिमी यूरोप अब संयुक्तराज्य अमेरिका को अपना पूरा समर्थन नहीं देगा।

उत्तरी कोरिया में अमेरिकी जासूस

'अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारों' का पृष्ठपोषण निक्सन-प्रशासन ने भी किया जिसके फलस्वरूप अप्रैल, 1969 में 'न्यूब्लो जामूसी काण्ड' से भी अधिक भयंकर जामूसी घटना घटी। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका के एक जामूसी विमान ई. सी. 121 को मार गिराया। अमेरिका का कहना था कि जहाज उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ, जब कि उत्तरी कोरिया का आरोप था कि विमान उसकी सीमा में प्रवेश कर जामूसी कर रहा था। कुछ समय बाद ही निक्सन-प्रशासन ने दम्भपूर्वक घोषणा की कि दक्षिणी कोरिया तथा प्रशान्त महासागर में अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए और उत्तरी कोरिया की सैनिक तैयारियों से अवगत रहने के लिए अमेरिका

इस प्रकार की जामूसी कायंवाही भविष्य में भी जारी रहेगा। 'चोरी और सीनाचोरी' का यह एक अच्छा उदाहरण था।

जर्मन-समझौते की दिशा में अमेरिकी नीति

निकसन ने जर्मनी के एकीकरण की समस्या पर यद्यपि वही रुख अपनाया जो जॉनसन ने अपनाया था तथापि 3 सितम्बर, 1971 को चतुर्शक्ति बर्लिन समझौता (The Four Power Berlin Settlement) सम्पन्न हो गया जिससे बर्लिन-समस्या का एक उत्साहवर्द्धक समाधान निकल आया। यह समझौता मुख्यतः इसीलिए हो सका कि सोवियत रुम बढ़ती हुई चीनी-अमेरिकी मैत्री से प्रभावित था कि कहीं इसका लाभ उठाकर चीन उस पर अपना दबाव बढ़ाने का प्रयत्न कर युद्ध का सफ्ट पैदा न कर दे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के बीच सम्पन्न हुए इस समझौते के अनुसार पश्चिमी तथा पूर्वी बर्लिन के बीच आवागमन की पूरी स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई और यह निश्चय किया गया कि इस क्षेत्र में विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाएगा। सोवियत संघ को पश्चिमी बर्लिन में राजनयिक प्रतिनिधित्व दिया गया जिसके अनुसार उसने वहाँ अपना महावाणिज्य दूतावास खोला। समझौते में यह भी घोषणा की गई कि पश्चिमी-बर्लिन पश्चिमी जर्मनी का मूल भाग नहीं है, दोनों क्षेत्रों के बीच सम्बन्धों को विकसित किया जाएगा। समझौते पर अमेरिका के तत्कालीन विदेशमन्त्री रोजर्स की टिप्पणी थी—

“हम एक कदम आगे बढ़े हैं इससे यूरोप में शान्ति-भरक्षा की सम्भावना बढ़ गई है।” यदि परिस्थितियों पर विचार किया जाए तो बर्लिन-समस्या का समाधान अमेरिकी विदेश नीति की सफलता का उतना द्योतक नहीं था जितना सोवियत संघ की अपनी पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षित करने की चिन्ता से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा का। जर्मन समस्याओं पर महाशक्तियों ने जो सहयोगपूर्ण रुख अपनाया उसका एक शुभ परिणाम यह निकला कि समुक्त-राष्ट्रसंघ में दोनों जर्मनियों (पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी) में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया और दोनों राज्यों को विश्व-सत्ता की सदस्यता भी प्राप्त हो गई।

निकसन-प्रशासन और वियतनाम

राष्ट्रपति निकसन ने प्रारम्भ में बमबर्षा सीमित कर समयान्तर से अमेरिकी सैनिकों को काफी बड़ी संख्या में स्वदेश वापस बुला लिया; किन्तु साथ ही वियतनाम में अमेरिकी तकनीकी सामरिक शक्ति को इस ढंग से कायम रखा कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर हावी न हो सके। पर कुछ ही समय बाद निकसन का रुख अविनाशिक बढा हो गया और दिसम्बर 1971 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर व्यापक हवाई आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। निकसन की नीति यह थी कि एक ओर समझौता बार्ता के लिए द्वार खुले रहे जाएँ और दूसरी ओर सैनिक शक्ति से उत्तर वियतनाम को समझौता करने के लिए विवश किया जाए। वियतनाम उत्तरी अमेरिकी हवाई हमलों ने आगे नहीं झुका और 26 अप्रैल, 1972 को निकसन ने घोषणा की—‘हम पराजित नहीं होंगे और न ही हम अपने मित्रों को साम्यवादो

प्राक्रमण के सशक्त घुटने टेकने देंगे।¹⁷ उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई भी अमेरिकी हवाई हमले के घेरे में घा गई। संघर्ष और वार्ता का दौर चसता रहा और अखिर 27 जनवरी, 1973 को वियतनाम में युद्धबन्दी-समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। पर युद्ध विराम के उत्सर्जन की घटनाएँ चालू रही और जुलाई-अगस्त, 1974 में तो कुछ गम्भीर झड़पों में दोनों पक्षों के काफी सैनिक भी हताहत हुए। निक्सन-प्रशासन द्वारा दक्षिणी वियतनाम को प्रचुर आर्थिक सहायता जूी जाती रही, लेकिन वह अपनी सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं कर सका। वियतनाम युद्ध-विराम स्थायी नहीं रह सका और निक्सन के जाने के कुछ ही माह बाद युद्ध पुनः भड़क उठा।

भूमध्यसागर में अमेरिकी नीति

सन् 1967 के अरब-इजरायल संघर्ष के बाद से ही भूमध्यसागर में सोवियत नौशक्ति के विस्तार के फलस्वरूप अमेरिकी नौसेना भी इस दिशा में सक्रिय हो गई और आज भूमध्यसागर इन दोनों बड़ी शक्तियों के नौसैनिक विस्तार की आकांक्षा का केन्द्र बना हुआ है। नाटो के सदस्य-देश भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत हद तक इस क्षेत्र से संबद्ध हैं। भूमध्यसागर में अमेरिकी हित बहुत व्यापक हैं। इजरायल के पृष्ठ-पोषण के लिए भी अमेरिका भूमध्यसागर में अपनी नौ-शक्ति के विकास को आवश्यक मानता है। अगस्त, 1970 में अमेरिका और स्पेन के बीच एक सैनिक समझौता हुआ जिसका उद्देश्य अमेरिकी छोटे बड़े की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाना था। भूमध्यसागर में अमेरिकी और यूरोपीय हितों में कोई समानता नहीं है; लेकिन सोवियत संघ की चुनौती अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए समान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भूमध्यसागर के प्रति अमेरिका अपनी नीति निर्धारित करता है। यदि उत्तरी एटलांटिक-संघ-समूह कमिी हद तक अपनी भूमिका निभाने के लिए संयार है, तो भूमध्यसागर में अमेरिकी बेड़े की सहायता की उस हर हालत में आवश्यकता होगी।

निक्सन और पश्चिमी एशिया

पश्चिमी-एशिया-संकट पर निक्सन प्रशासन का रवैया अरब-विरोधी और इजरायल-समर्थक रहा। जनवरी, 1972 में अमेरिका ने इजरायल को बहुचर्चित फंटेम विमान पुनः देने का भी निर्णय ले लिया और यह भी ठीक उस समय जब इजरायल स्वयं को समझौते के लिए तैयार कर रहा था। अमेरिका की यह कार्यवाही पश्चिमी एशिया की समस्या को और भी जटिल बनाने वाली थी। अक्टूबर, 1973 में अरब-इजरायल-युद्ध में इजरायल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ तथा दोनों महाशक्तियों—अमेरिका और रूस की जबरदस्त कूटनीतिक सरगर्मी से युद्ध-विराम सम्भव हुआ। इसके बाद डॉ. कीसिंगर स्थायी समझौता कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास करते रहे, पर अगस्त, 1974 में निक्सन के पतन के कारण वाञ्छित-परिणाम न निकल सके।

इजरायल के समान ही ईरान को भी अधिकाधिक युद्ध-सामग्री से सैत करने

की नीति अपनाई गई। ईरान को अरबों खपों के हथियार देने के मूल में 'ईरान-पाकिस्तान घुरी' को शक्तिशाली और स्थिर बनाना था। ईरान के माध्यम से अमेरिकी शस्त्रास्त्रों का भंडार पाकिस्तान पहुँचना एक बड़ा जटिल और बहुद्देशीय कूटनीतिक खेल था। वाशिंगटन-पिण्डी-पेरिंग घुरी के समान ही वाशिंगटन-तेहरान-पिण्डी घुरी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बिस्फोटक स्थिति पैदा करने वाली चालें थीं। न केवल विपुल सैन्य सामग्री बल्कि अमेरिकी सैनिक-असैनिक प्रशिक्षक भी मई, 1973 से ही अधिकाधिक संख्या में तेहरान पहुँचने लगे। इस दिशा में अमेरिकी विदेश-नीति के लक्ष्यों पर 27 मई, 1973 के दिनपत्र की यह सम्पादकीय टिप्पणी उल्लेखनीय है—

'अपनी इजरायल नीति के कारण तेल-उत्पादक अरब-देशों में दाल न गलती देख कर अमेरिका ने ईरान के राजाशाह पहलवी को इस क्षेत्र में अपने हितों का पोषक बनाने का फैसला किया है। यद्यपि अमेरिका की प्रमुख हचि ईरान और फारस की खाड़ी के देशों में खनिज तेल का प्रवाह खुला रखने में है, तथापि उसका इतना ही महत्वपूर्ण राजनीतिक लक्ष्य भी है—प्रान्तरिक मतभेदों से त्रस्त पाकिस्तान के लिए गैरमान्यवादी स्थानीय सरकारों की तलाश के साथ-साथ भारत और सोवियत संघ से राजनैतिक आर्थिक प्रभाव का विकल्प पैदा करना। अमेरिकी शस्त्रास्त्र पर आधारित ईरान की सामरिक शक्ति अरब-विरोधी भी होगी क्योंकि ईरान की ईराक से परम्परागत शत्रुता चली आ रही है। इसी तरह अमेरिका ने ईरान को अपना कृपा-भाजन बनाकर इस क्षेत्र में रुम के भारी होते पलट्टे की फिलहाल हलका साबित कर दिया है। इस स्थिति के दूरगामी परिणाम काफी दिलचस्प साबित होंगे।'

नक्सन की युद्धपोत-राजनीति

युद्धपोत अथवा तोपनों की अमेरिकी कूटनीति की असफलता का प्रमाण उत्तरी कोरिया में 'प्यूल्गो-काण्ड' के मिलसिले में मिल चुका था। लेकिन इससे कीर्ति शिक्षा न लेते हुए राष्ट्रपति नक्सन ने अमेरिकी युद्धपोत राजनय का खेल फिर खेला और भारत-पाक युद्ध के समय दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के समर्थन के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना सातवाँ बेड़ा भेज दिया और बहाना यह बनाया कि ढाका में स्थित 15 अमेरिकियों को जिन्होंने सम्भवतः स्वेच्छा से ढाका में रहने का निर्णय लिया था निकालना है। यह समझ में न आनेवाली बात थी कि इन्ने-गिने अमेरिकियों को ढाका से निकालने के लिए शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े की क्या आवश्यकता थी जिसमें अमेरिका का एकमात्र परमाणु शक्तिचालित विमानवाही (एण्टर-प्राइज) भी शामिल था।

स्वतन्त्र बंगलादेश के दमन में पाकिस्तान को समर्थन देने और पाक-चीन गठबन्धन के साथ स्वयं को भी पूरी तरह जोड़ने के सम्बन्ध में ही राष्ट्रपति नक्सन ने सम्भवतः भारत के विरुद्ध अपनी युद्धपोत की राजनीति खेली ताकि मनोवैज्ञानिक रूप से भारत भयभीत होकर बंगलादेश से अपनी सेनाएँ हटा ले अथवा पाकिस्तान के साथ अमेरिकी योजनाओं के अनुरूप तुरन्त युद्ध-विराम स्वीकार कर ले और इस प्रकार पाकिस्तान का विभाजन बच जाय।

निकसन और चीन

राजनीति में न कोई स्थायी मित्र होता है और न कोई स्थायी शत्रु। जिस साम्यवादी चीन को अमेरिका अपना शत्रु नम्बर एक मानता था उसी के प्रति मैत्री के हाथ बड़ाकर राष्ट्रपति निकसन ने अमेरिकी कूटनीति को एक क्रान्तिकारी मोड़ दिया, इसमें सन्देह नहीं। अप्रैल, 1971 में अमेरिका के टेविल टैनिस खिलाड़ियों का चीन पहुँचना कोई सामान्य मनोरंजन का विषय नहीं था बल्कि राजनयिक क्षेत्रों में यह एक गम्भीर बात थी। इस घटना से जिस 'विंग-पांग राजनय' का सूत्रपात हुआ, उससे अन्त में जाकर यह सम्भावना प्रकट होगई कि दीर्घकालीन दो शत्रु देशों के बीच परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क और सहयोग का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति निकसन ने अत्यन्त साहसी कदम उठाकर चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में पहल की और विश्व-राजनीति में यह सम्भावना पैदा कर दी कि अमेरिका और चीन मित्र बनकर के विश्व शक्ति-सन्तुलन में एक अभूतपूर्व क्रांति ला देंगे।

राष्ट्रपति निकसन ने प्रारम्भ में ऐसे कई कदम उठाये जिससे यह आभास मिला कि अमेरिका दक्षिण-पूर्वी एशिया से किसी न किसी प्रकार छुटकारा पाना चाहता है, विपतनाम युद्ध से सम्मानपूर्ण पलायन चाहता है और इसके लिए वह चीन के सहयोग का आकांक्षी है। चीन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति निकसन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये—

(1) "अमेरिकी पर्यटकों को चीन निर्मित वस्तुएँ खरीदने की इजाजत दी गई।"

(2) अमेरिकी व्यापारिक सस्थानों की अधीनस्थ व्यापार सस्थाओं को जनवादी चीन के साथ प्रसारिक वस्तुओं में व्यापार करने की अनुमति दी गई। इससे पहले न केवल अमेरिकी व्यापारी बल्कि विदेशों में काम करने वाले उनके आश्रित व्यापारी भी ऐसा नहीं कर सकते थे।

(3) अमेरिका में निर्मित या अमेरिकी सस्थाओं द्वारा साइंस प्राप्त वस्तुओं विशेषकर मशीनों के पुर्जे इत्यादि चीन को भेजे जाने की अनुमति दे दी गई। अमेरिकी तेल कम्पनियों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे गरसाम्यवादी देशों के यानों को चीन के बन्दरगाहों तक जाने के लिए तेल बेचें बशर्ते कि इन जलयानों में किसी प्रकार की युद्ध सामग्री न हो।"

एकपक्षीय सुविधाओं द्वारा निकसन-प्रशासन ने चीन के साथ पहली किश्त में व्यापारिक सम्बन्ध और दूसरी किश्त में राजनीतिक तथा मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने की नीति अपनायी। राष्ट्रपति निकसन का यह कदम विवेकपूर्ण ही था क्योंकि एशिया में अपना बोक हल्का करने और साथ ही चीन के साथ प्रत्यक्ष मुठभेड़ की सम्भावना कम करने के लिए अमेरिका के लिए चीन को अपने निकट लाना आवश्यक था।

निकसन प्रशासन ने चीन की ओर मित्रता का जो हाथ बढ़ाया उसके फलस्वरूप संयुक्त-राष्ट्रसंघ में चीन की सदस्यता का मार्ग कुछ सुगम हो गया क्योंकि अनेक देशों

पर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा कि अब लाल चीन की राष्ट्रसंघ की सदस्यता के मार्ग में रोड़े घटकाना लाभप्रद नहीं है। अक्टूबर, 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन (ताइवान) को संयुक्त-राष्ट्रसंघ से निष्कासित कर उसके स्थान पर जनवादी चीन (कम्युनिस्ट चीन) को सदस्य बनाने का अल्बानिया का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया। 26 अक्टूबर, 1971 का महासभा का यह निर्णय अमेरिका की विदेश-नीति और राजनय की पहली बड़ी हार थी और चीन के अध्यक्ष माओत्से तुंग की कारिकारी राजनय की पहली बड़ी जीत थी। इस घटना से राष्ट्रपति निक्सन स्तब्ध रह गये। फिर भी चीन और अमेरिका की ओर से ऐसे कोई प्रयास नहीं किये गये जिससे राष्ट्रपति निक्सन की सम्भावित यात्रा लटवाई में पड़ जाये।

अमेरिका और चीन दोनों ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में एक-दूसरे के निवृत्त होने की नीति अपनाई थी जिसका ज्वलन प्रमाण बंगलादेश के मुक्ति-प्रान्दोलन और भारत-पाक संघर्ष के समय मिला। मानवता और लोकतन्त्र के विरुद्ध इससे बड़ी दुश्मि-सन्धि और क्या हो सकती थी कि स्वार्थ में अग्र्य होकर अमेरिका और चीन ने अपने बर-भाव मुलाते हुए संयुक्त-राष्ट्रसंघ में और इसके बाहर पाकिस्तान का खुला समर्थन किया—कूटनीतिक स्तर पर भी और सामरिक सहायता देकर भी। दोनों ही देशों ने बंगला देश में पाक सेना द्वारा किये गये जाति-संहार को न केवल चुपचाप देखा बल्कि माहिवा सरकार को प्रोत्साहित भी किया।

मार्च, 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने पेरिग-यात्रा की। इस पर लघुभण सवा करोड़ खर्चा हुआ। अपनी सात दिवसीय चीन-यात्रा के दौरान राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की मित्रता प्राप्त करने के लिए उसे दो रियायतें दी, लेकिन बदले में कुछ लेने की विशेष परवाह नहीं की। निक्सन-चाऊ का पहला शिकार ताइवान बना जिसे अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती का दम्भ था। अपने चीन-प्रवास काल में निक्सन ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि यदि चीनी नेता अमेरिका में सहयोग करेंगे तो वह ताइवान की समस्या के हल में रकावट नहीं डालेगा। ताइवान को चीन का एक हिस्सा मान कर ताइवान स्थित अमेरिकी सेनाओं और सैनिक अड्डों को धीरे-धीरे हटाने की इच्छा व्यक्त कर ताइवान समस्या को चीनी स्वयं मुलुंभाएँ कहकर निक्सन ने चीन के प्रति अपनी भावी नीति स्पष्ट कर दी। संयुक्त विज्ञप्ति से यह प्रकट था कि हिन्द-चीन, कोरिया और वियतनाम के प्रश्न पर दोनों देशों में मतभेद बने रहे। अगर कहीं दोनों में पूरा मतसंघ देखने को मिला तो वह था भारतीय उपमहाद्वीप के प्रश्न पर। विज्ञप्ति में "न केवल भारत और पाकिस्तान को समान पलड़ों में रखते हुए उनसे कश्मीर में अपनी-अपनी सेनाओं को युद्ध-विराम रेखा तक लौट आने का आग्रह किया गया बल्कि भारत के प्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की भी धृष्टता की गई।" चीन ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रात्य-निर्णय के अधिकार का भी समर्थन किया। मतसंघ का एक मुद्दा यह भी रहा कि दोनों ही देशों ने बंगलादेश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, मानो इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार का विश्व-शांति और

मानवता से कोई सम्बन्ध नहीं था। राष्ट्रपति निक्सन की चीन-यात्रा की सफलता का समस्त मूल्यमूल्य तो भविष्य में ही किया जा सकेगा, हाँ, यह अवश्य हुआ कि लगभग 23 वर्ष पुराने बैर-भाव के बावजूद दोनों देशों के बीच सवाद और सम्पर्क के सूत्र कायम हो गए।

प्रश्न उठता है कि लगभग 23 वर्षों से सम्पूर्ण विश्व में चीन के विरुद्ध मोर्चाबन्दी करने वाले अमेरिकी प्रशासन के मन में चीन से मैत्री की भावना क्यों प्रबल हुई और चीन भी उसकी तरफ क्यों झुका और आज भी यही प्रवृत्ति क्यों विकासमान है ? कारण स्पष्ट हैं—

1. सोवियत संघ के बढ़ते हुए सैनिक और राजनीतिक प्रभाव ने अमेरिका को विवश किया है कि चीन को अपने पक्ष में करे।

2. चीन और सोवियत संघ के सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों से काफी तनावपूर्ण हो गए हैं, अतः अमेरिका ने यह उचित समझा है कि रूस से निबटने के लिए चीन को मोहुरा बनाया जाए। चीन भी रूस के साथ अपनी प्रतिद्वन्द्विता में अमेरिका के सहयोग का आकांक्षी है।

3. अमेरिका दक्षिण-पूर्व एशिया से स्वयं हटकर वहाँ चीन की उपस्थिति के अधिक पक्ष में है। कम से कम चीन और अमेरिका दोनों ही इस बात पर तो सहमत हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया से अमेरिका के हटने के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति सोवियत संघ द्वारा नहीं होनी चाहिए।

4. चीन को यह विश्वास हो रहा है कि पूर्वो एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति अस्थायी है जबकि जापान शक्तिशाली होकर वहाँ स्थाई रूप से छा जाने की कोशिश कर रहा है। इस सम्दर्भ में अमेरिका ही सन्तुलन कायम रख कर सोवियत संघ के मुकाबले पूर्वो एशिया में चीन की सैनिक उपस्थिति की सम्भावनाओं को बढ़ा कर सकता है। चीन को अपने पक्ष में रखकर अमेरिका दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनकर भारत पर अपनी दबाव-नीति जारी रख सकता है।

5. संयुक्तराज्य अमेरिका के व्यापारिक विशेषज्ञ इस बात पर दबाव डालते रहे हैं कि 70 करोड़ की आबादी के किसी देश को अमेरिकी व्यापार के प्रभाव-क्षेत्र से अलग रखना अमेरिकी हित में नहीं। यह भावना तब से जोर पकड़ गई जब से यह आभास मिलने लगा कि चीन अमेरिकी माल खरीदने के लिए उत्सुक है।

साम्प्रदायी विश्व के साथ सह-अस्तित्व की जिस नीति को कैंनेडी-प्रशासन ने बल प्रदान किया था उसे बहुत कुछ आगे बढ़ाने का श्रेय राष्ट्रपति निक्सन ने प्राप्त किया। निक्सन ने मई, 1972 में मास्को की यात्रा की। 22 मई, 1972 को वे दल-बल सहित मास्को पहुँचे। निक्सन की यह 6 दिवसीय मास्को यात्रा ऐतिहासिक थी क्योंकि सन् 1945 में माल्टा सम्मेलन के बाद दोनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली भेंट थी।

रूसी नेताओं के साथ वार्ता के उपरान्त जो 'संयुक्त घोषणा' प्रकाशित हुई उसमें दोनों देशों ने 'शान्तिपूर्ण सम्बन्ध' विकसित करने की आवश्यकता पर बल

दिया। यह कहा गया कि सकट से बचने और परमाणु युद्ध से दूर रहने का भरमक प्रयत्न किया जाएगा। सहमति का एक मुद्दा यह था कि संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा-परिषद् के दोनो सदस्य (रूस तथा अमेरिका) और अन्य स्थायी सदस्य ऐसी स्थितियों उत्पन्न करेंगे कि सभी देश शांति और सुरक्षा से रह सके और उनके आन्तरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप न हो सकें। दोनो देश इस बात पर भी सहमत थे कि वे आपसी हितों के मामले पर विचार विनिमय की परम्परा आगे बढ़ाएंगे और अस्त्र-परिमीनत्व की नई सम्भावनाएँ जोजेंगे तथा यह सब 'अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा-दृष्टि' से किया जाएगा। दोनो देशों ने घोषणा की कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी विशेष अधिकार का न वे स्वयं कोई दावा करते हैं और न किसी अन्य देश को ऐसा करने देंगे, क्योंकि दोनो ही देश सभी राज्यों की प्रमुखता को समानता का स्तर प्रदान करते हैं। कुन मिलाकर संयुक्त विज्ञप्ति में यही ध्वनित हुआ कि एक ओर सिद्धान्तवादिता है तथा दूसरी ओर पहले से ओड़ी गई जिम्मेदारियों की मजबूरी की उत्पत्ति है तथा विज्ञप्ति की आधार संहिता केवल महाशक्तियों के पारस्परिक उपयोग के लिए है, अन्य सभी छोटे-बड़े देशों के न्यायसंगत हित दवाए जाने योग्य हैं।

भास्को यात्रा के दौरान रूस और अमेरिका के बीच अस्त्र-परिमीनत्व की एक ऐतिहासिक सन्धि हुई। इस पचवर्षीय सन्धि में, जो राष्ट्रीय हितों के प्रतिबल सिद्ध होने पर किसी भी पक्ष द्वारा 6 महीने के नोटिस पर रद्द की जा सकती है, स्वीकार किया गया कि—

1. "इस वर्ष की पहली जुलाई के बाद नए अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण नहीं किया जाएगा।

2. कोई भी पक्ष हल्के या पुराने हिस्स के भू-प्रक्षेपास्त्र-स्थलों को सुधार कर भारी अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग के योग्य नहीं बनाएगा।

3. दोनो पक्ष पनडुब्बियों के प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों तथा प्रक्षेपास्त्रयुक्त आधुनिक पनडुब्बियाँ नहीं बनाएँगे, हालाँकि निर्माणाधीन पनडुब्बियों का काम पूरा करने की छूट रहेगी।

4. इस अन्तरिम सन्धि की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए दोनो देशों को आवासीय प्रक्षेपास्त्रों और प्रक्षेपकों का आधुनिकीकरण करने अथवा स्थापनापत्र अस्त्र बनाने का अधिकार रहेगा।

5. सन्धि के परिपालन की जाँच के लिए हर राष्ट्र केवल वही विधिगाँ अपनाएगा जो अन्तर्राष्ट्रीय वानुस के मान्य मिद्दान्तों के अनुरूप हो। दोनो पक्षों ने स्वीकार किया कि वे अस्त्र-अस्त्र निर्माण को गुप्त रखने के लिए जानबूझ कर ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं करेंगे जिनसे सन्धि की भावना को ठेस पहुँचे। दूसरे देश को निगरानी रखने में बठिनाई हो।"

दोनों देशों के बीच अन्तरिक्ष-अभियान-सहयोग-सन्धि भी हुई जिसमें निश्चय किया गया कि दोनो देशों के उडनदस्ते एवं साथ आकाश-विहार करेंगे और देश जाफकारी का आदान-प्रदान करेंगे। एक अन्य सैनिक सन्धि के अनुसार अमेरिका ने रूस की बढी हुई नौसैनिक शक्ति को स्वीकार किया।

जून, 1973 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव ने अमेरिका-यात्रा की और दोनों देशों में कुछ सन्धियाँ हुईं। एक सन्धि में दोनों देशों ने सवल्य किया कि उनमें से कोई भी परमाणु-युद्ध नहीं करेगा। एक दूसरी सन्धि परमाणु-अस्त्र-शस्त्र की सीमा और परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग से सम्बन्धित थी। निःशस्त्रीकरण की दिशा में यह एक नए दौर का प्रादुर्भाव थी कि दोनों देशों ने सिद्धान्त रूप में सन् 1974 तक परमाणु-आयुधों के निर्माण पर रोक लगाने और परमाणु-शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने का निश्चय किया। दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध तब और घनिष्ठ हुए जब 27 जून, 1974 को राष्ट्रपति निक्सन मास्को यात्रा पर गए और 3 जुलाई, 1974 को प्रतिप्रक्षेपास्त्र प्रणालियों तथा आक्रामक-परमाणु अस्त्रों की और सीमित करने तथा भूमिगत परीक्षाओं पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस शिखर-वार्ता में ही 29 जून को दोनों देशों में एक महत्वपूर्ण 10 वर्षीय व्यापार समझौता हुआ जिसे सन् 1972 के व्यापार-समझौते का पूरक बताया गया। सन् 1972 के व्यापार-समझौते पर अमेरिकी कांग्रेस ने यह निर्णय किया था कि जब तक यहूदियों के विस्थापन के बारे में सोवियत सघ उदार नहीं होता तब तक समझौते की पुष्टि नहीं की जाएगी। सोवियत प्रवक्ता ने कहा कि सोवियत-अमेरिकी व्यापार का तथाकथित गहरी समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में निक्सन तीन मुख्य उद्देश्य लेकर सोवियत सघ की यात्रा पर निकले थे—(1) विश्व की दो महान् शक्तियों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करना, (2) विश्व के कुछ भागों में उनके बीच सघर्ष की सम्भावनाओं को कम करना, एवं (3) परमाणु-अस्त्र परिसीमन के क्षेत्र में कुछ प्रगति करना। कम से कम पहला उद्देश्य प्राप्त करने में वह बहुत कुछ सफल हुए। शेष दोनों उद्देश्यों की दिशा में भी उत्साहवर्द्धक प्रगति हुई। शिखर-वार्ता में पश्चिमी एशिया, भारत के परमाणु परीक्षण, यूरोप में सेनाओं में कटौती, यूरोपीय सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी निक्सन और ब्रेझ्नेव के बीच विचार-विमर्श हुआ, किन्तु इसके निष्कर्षों को गोपनीय रखा गया।¹

भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश के प्रति निक्सन का रवैया. भाग 2

निक्सन-प्रशासन-काल में अमेरिका का भारत-विरोधी रवैया विशेष उग्र रहा और निक्सन ने समय बीगो देशों के बीच सम्बन्ध जितने कटु रहे, पहले उतने कभी नहीं रहे थे। निक्सन ने भारत की न केवल आर्थिक सहायता ही रोकी, बल्कि सैनिक साज-सामान देना भी बन्द कर दिया और हर प्रकार भारत के प्रति अग्रेसरी प्रवृत्ति की। बंगलादेश के मुक्ति-प्रान्दोलन को कुचलने में तत्कालीन याहिया सरकार को अमेरिका और चीन का जो प्रोत्साहन मिला वह लोकतन्त्र के नाम पर कलक था। भारत-पाक युद्ध छिड़ने पर और चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सहायता दिए जाने पर निक्सन-प्रशासन ने भारत की न केवल किसी प्रकार की सहायता ही देने में

असमर्थता प्रकट की बल्कि बंगाल की खाड़ी में अपना शक्तिशाली नौ-बेड़ा भेज कर भारत को प्रभावित करने की भी कोशिश की। अगस्त, 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के पद-स्थाप तक ऐसी कोई उज्ज्वल आशा नहीं बन बन सकी कि निफ्ट भविष्य में भारत-अमेरिका सम्बन्धी में ठोस सुधार हो सकेंगे।

राष्ट्रपति फोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका (अगस्त 1974-जनवरी 1977)

'महाबली निक्सन को वाटरगेट बाण्ड ले डूबा और 9 अगस्त, 1974 को उनके औपचारिक पद-स्थाप के बाद उसी दिन उपराष्ट्रपति जेरोल्ड फोर्ड ने अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नए राष्ट्रपति ने कहा कि वे इस सकल्प के साथ राष्ट्रपति-पद ग्रहण कर रहे हैं कि अमेरिका और विश्व के लिए जो कल्याणकारी होगा वही करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शान्ति के लिए निक्सन-प्रशासन ने अब तक जो कुछ किया वे भी उसी मार्ग का अनुसरण करेंगे। अमेरिका के इतिहास में 61 वर्षीय फोर्ड दूसरे राष्ट्रपति थे जो इस पद पर निर्वाचित न हो सके। अगस्त, 1974 में राष्ट्रपति पद सम्भालने के बाद में जनवरी, 1977 में जिम्मी कार्टर के पदाह्व होने तक उनके राष्ट्रपतित्व काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर अमेरिका की भूमिका को अग्रविक्रित बिन्दुओं में रखा जा सकता है—

पश्चिम-एशिया

अरब-इजराइल समस्या के समाधान के लिए अमेरिका के विदेश-मन्त्री डॉ. कीसिंगर ने अपने कूटनीतिज्ञ प्रयास जारी रखे। मार्च, 1975 तक ये प्रयत्न निराशाजनक रूप से असफल रहे और फोर्ड प्रशासन ने स्वीकार किया कि इजरायल और मिस्र के मतभेद ऐसी स्थिति में पहुँच गए थे कि उन्हें दूर करना सम्भव नहीं था। फिर भी अमेरिका के शान्ति-प्रयास जारी रहे और अन्ततः 4 सितम्बर, 1975 को डॉ. कीसिंगर मिस्र और इजरायल के बीच एक अन्तरिम समझौता कराने में सफल हुआ। समझौते की मुख्य बातें ये थी—

1. सिनाई पर्वतमाला के दरों और उनके आस-पास 8 निगरानी चौकियाँ होंगी—एक चौकी पर इजरायल का पूर्ण नियन्त्रण होगा और एक पर मिस्र का। शेष 6 चौकियों पर अमेरिकी तकनीकी कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये निगरानी चौकियाँ किसी भी पक्ष की ओर से किए जाने वाले आक्रमण की पूर्व सूचना देने का काम करेंगी।

2. अदुहदी तेल क्षेत्र जिसमें इजरायल को अपनी आवश्यकता का 55 प्रतिशत तेल प्राप्त होता था मिस्र के अधिकार में आ जाएगा। इजरायल अब पूरी तरह तेल के आयात पर निर्भर रहेगा लेकिन इस आयात में कोई व्यवधान पड़ने पर अमेरिका उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। मिस्र ने वचन दिया कि वह इजरायल को जाने वाले टैंकरो को रोकने के लिए लालसागर की नावेचन्दी नहीं करेगा।

1. हिन्दुस्तान 24 मार्च 1975, सप्ताहकीय पृष्ठ 4.
2. हिन्दुस्तान 7 सितम्बर 1975, पृष्ठ 33.

3. इजरायल का माल किसी भी तीसरे देश के जहाज में स्वेज नहर में होकर निःशुल्क भेजा जा सकेगा। इजरायल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा थी जिसे पिछले 27 वर्षों में अरबों से चार युद्ध करने के उपरान्त भी वह अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया था।

4. नए गतिधारे (बफर क्षेत्र) में मिस्र, अमेरिका, इजरायल और संयुक्त राष्ट्र की शान्तिरक्षक सेनाओं के बीच सहयोग की व्यवस्था होगी।

उपरोक्त अन्तरिम समझौते पर मिस्र और इजरायल ने संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि की साक्षी में हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने समझौते के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर-समारोह का बहिष्कार किया। सोवियत संघ के विरोध का मुख्य मुद्दा सिनाय में नियन्त्रण चौकियों पर अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रावधान था। रूस की दृष्टि में यह व्यवस्था 'एक नया जटिल तत्त्व' थी। राजनीतिक क्षेत्रों में सिनाय समझौते को अमेरिकी कूटनीति की विजय माना गया। 10 अक्टूबर, 1975 को मिस्र और इजरायल के अधिकारियों ने 4 सितम्बर के समझौते को विधिवत् कार्यान्वित करने और पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना की दिशा में एक पूर्ण समझौता किया। तदनुसार यह निश्चय किया गया कि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इस समझौते के अनुमोदन के बाद "सिनाई से जो मिस्री और इजरायली हटेंगे उनकी जगह अमेरिकी सैनिकों की सात चौकियाँ स्थापित की जाएँगी। ये चौकियाँ, जिन्हें पूर्व सूचना-केन्द्र का नाम दिया गया है, तनाव की दिशा में एक दूगरे देश को सावधान करेंगी।" यह पूर्ण समझौता हो जाने से इजरायल ने रास मूबार नामक तेलकूपों को मिस्री हितों को देखने वाले अमेरिकी प्रतिनिधियों को हस्तान्तरित कर दिया। इस समझौते के फलस्वरूप वह मतभेद भी बहुत कुछ समाप्त हो गया जो अमेरिकी और अरब पक्षों के बीच पैदा हो गया था। 2 नवम्बर, 1975 को अमेरिका द्वारा मिस्र को नाभिकीय भट्टी देने का निश्चय किया। 30 नवम्बर को मास्को में संयुक्त विज्ञप्ति में यह निश्चय प्रकट किया गया कि पश्चिमी एशिया में स्थायी शान्ति के लिए इजरायली सेना को सभी अधिकृत क्षेत्रों को खाली करना होगा। 5 मार्च, 1976 को अमेरिका ने इजरायल से आग्रह किया कि उसे पूरा सिनाई क्षेत्र खाली कर देने पर सहमत हो जाना चाहिए। अमेरिका व मिस्र के गुप्तते हुए सम्बन्धों में एक नई कड़ी तब और जुड़ गई जब 15 मार्च, 1976 को मिस्र के राष्ट्रपति सादात द्वारा सोवियत संघ से मंत्री-सन्धि रद्द कर दी गई। 27 मई, 1976 को सीरिया और इजरायल गोलन पहाड़ियों पर संयुक्तराष्ट्र सेनाएँ 6 महीने और रखने पर सहमत हो गए। 30 मई को मिस्र का अमेरिका से 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की सहायता का समझौता हुआ। फोर्ड प्रशासन में अमेरिका और मिस्र के सम्बन्धों में सुधार जारी रहा।

वियतनाम

वियतनाम में फोर्ड प्रशासन निक्सन के पद-चिह्नों पर चलता रहा। सन् 1975 का नया वर्ष वियतनामी जनता के लिए अशुभ संदेश लेकर आया और

युद्ध पुनः तेजी से मड़क उठा। अप्रैल के आरम्भ में यह लगभग स्पष्ट हो गया कि दक्षिण वियतनाम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के हाथों में चला जाएगा। 11 अप्रैल, 1975 को फोर्ड ने अपने एक विशेष सन्देश में कांग्रेस से दक्षिण वियतनाम के लिए एक अरब डॉलर की सहायता का प्रस्ताव रखा, पर कांग्रेस ने राष्ट्रपति की इस माँग को अव्यावहारिक ठहराया।¹ आतिर 30 अप्रैल, 1975 को अमेरिका समर्पित दक्षिण वियतनामी सरकार ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार कई पीढ़ियों से चला आ रहा वियतनाम का ऐतिहासिक युद्ध समाप्त हो गया। जन-यन के भारी बलिदान के बावजूद अमेरिका को वियतनाम से हटना पड़ा। यह महापुद्गोत्तर इतिहास में अमेरिकी विदेश-नीति की सबसे गहरी और लज्जाजनक पराजय थी। वियतनाम के प्रति अमेरिका का आक्रोश मिटा नहीं और अगस्त, 1975 में उसने सुरक्षा परिषद् में निलेवाधिकार का प्रयोग कर उत्तर वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश में बाधा उत्पन्न की।² अमेरिका का निलेवाधिकार प्रयुक्त करता अप्रत्याशित नहीं था। अमेरिकी प्रतिनिधि ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि सुरक्षा परिषद् दक्षिणी कोरिया को संयुक्त राष्ट्र-संघ का सदस्य बनाने के लिए सहमत होगी तभी अमेरिका दोनों वियतनामों की सदस्यता का समर्थन करेगा। लेकिन सुरक्षा परिषद् ने उससे पहले ही दक्षिणी कोरिया के आवेदनपत्र पर विचार करने में इन्कार कर दिया था। अमेरिका ने अपनी कायेंगाही के समय में यह तर्क दिया था कि यह चुनौती आधार पर सावभौमिकता के सिद्धान्त के विरुद्ध है। अमेरिकी राजदूत डेनियल पैट्रिक मोनिहान ने अपने नपतुने भाषण में कहा, 'हमें उस चुनौती सावभौमिकता से कुछ लेना-देना नहीं है जो व्यवहार में केवल उन्हीं नए सदस्यों को प्रवेश दिनांकी है जो अधिनायकवादी राज्यों को स्वीकार्य होते हैं।' उन्होंने कहा कि दक्षिणी कोरिया को यह अधिकार भी नहीं दिया गया कि उनमें मामले पर विचार हो। 1 नवम्बर, 1976 को सुरक्षा-परिषद् में यह प्रश्न पुनः प्रस्तुत हुआ कि वियतनाम गणतन्त्र को संयुक्त राष्ट्रसंघ का 146वाँ सदस्य बना लिया जाए। सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया, किन्तु अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में यह वियतनाम को संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश के लिए समर्थन देने को तैयार नहीं है। हिन्द-चीन पर साम्यवादियों का पूर्ण अधिकार हो जाने के बाद फोर्ड प्रशासन अमेरिका की एक विशेष उपसक्ति यह मानी जाएगी कि वह हनोई और वाणिगटन के बीच किसी न किसी स्तर पर सम्बन्ध बनाए रखने में सफल रहा। पाकिस्तान को हथियार

भारत के प्रति फोर्ड प्रशासन का रवैया निवसन-प्रशासन में भी एक कदम आगे बढ़ा-विशेष रूप से तब जब फरवरी 1975 में अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान को हथियार देने पर 10 वर्ष से लगी पाबन्दी को हटाने के अपने निर्णय की सूचना

1. दिनमान 20 अप्रैल 1975, पृष्ठ 30.

2. दिनमान 24 अगस्त 1975, पृष्ठ 32.

औपचारिक रूप से भारत सरकार को दे दी। अमेरिका सरकार ने अपने निर्णय को इस आधार पर उचित ठहराने की कोशिश की कि भारत में गत वर्ष अणु-विस्फोट किया था और अमेरिका की इस क्षेत्र में शक्ति-सन्तुलन बनाए रखने में गहरी रुचि है। राष्ट्रपति फोर्ड इस तथ्य को भला बैठे कि मुख्यतः अमेरिकी हथियारों ने ही पाकिस्तान को भारत से बार-बार युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है।

अमेरिका के इस कदम की भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और भारतीय विदेश मंत्री ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा भी स्थगित कर दी। 13 अप्रैल, 1975 को रक्षा-मंत्री स्वर्णसिंह ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि पाकिस्तान 'अन्तर्राष्ट्रीय पङ्ख' का शिकार हो गया है तथा उसे भारी मात्रा में दिए जा रहे अमेरिकी हथियार स्वयं उसी के लिए खतरा है।¹

इन व्यवधानों के बावजूद भारत सरकार का यह प्रयत्न रहा कि अमेरिका के साथ सम्बन्ध सुधारे जाएँ। अतः "एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए भारत-अमेरिका के बीच वार्ता और आदान-प्रदान का कार्यक्रम सन् 1975 में जारी रहा। आम तौर पर यह अनुभव किया गया कि समस्याओं के बावजूद दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय हित के स्तर पर कोई विवाद नहीं है। अक्टूबर, 1975 में भारत के विदेश-मंत्री ने अमेरिका की यात्रा की। भारत सरकार ने अमेरिका को स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को उन्नत अमेरिकी हथियार मिलने से शिमला समझौते के अन्तर्गत सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है और इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ बड़ सकती है। सितम्बर, 1976 में श्री केवलसिंह अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। अक्टूबर, 1976 अमेरिका में राष्ट्रीय चुनावों की सरगमी का महीना रहा और 3 नवम्बर, 1976 को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जिम्मी कार्टर रिपब्लिकन राष्ट्रपति फोर्ड को हराकर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति चुने गए। भारतीय राजदूत केवलसिंह ने भारत सरकार के सस्थानों तथा अमेरिका स्थित प्रतिष्ठानों को सलाह दी कि वे नए प्रशासन की स्थापना के बाद अमेरिका से व्यापारिक तथा अन्य सम्बन्ध मजबूत बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में नया प्रशासन पुराने प्रशासन से भिन्न होना और हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि नए प्रशासन के साथ हम अपने सम्बन्ध अधिक मजबूत बनाएँ। श्री केवलसिंह ने कहा कि अमेरिका में, जहाँ कुछ दिनों पूर्व भारत विरोधी रूप बना हुआ था, आज स्थिति बदल रही है। अब भारत की प्रगति की वहाँ भी सराहना की जा रही है। आर्थिक क्षेत्र में हुई प्रगति को सामान्यतया स्वीकार किया गया है।

कम्बोडिया

अमेरिका वियतनाम में भी पिटा और कम्बोडिया में भी। 18 अप्रैल, 1975 को समाचार प्रकाशित हुए—“कम्बोडिया युद्ध का अन्त—मेर सेना का नोमपेन्ह पर कब्जा और सरकार का समर्थन, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्री

माने।" वस्तुतः कम्बोडिया में भी अमेरिका को किसी प्रकार अपनी इज्जत बचाने की ही चिन्ता रही और वह पराजित सरकार को गुमराह करने वाले प्राश्वासन देता रहा। अमेरिका की नीति जो भी रही हो, यह प्रसन्नता की बात थी कि पिछले पाँच वर्ष से 70 लाख कम्बोडिया नागरिकों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर देने वाला तथा अग्रणीत लोगों की बलि लेने वाला युद्ध समाप्त हो गया।

अमेरिका-रूस : सुघरते सम्बन्धों का मूल्यांकन

सन् 1972 (22 से 30 मई) में रिचर्ड निक्सन ने सोवियत संघ की पहली यात्रा कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नयी दिशा प्रदान की थी। उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति फोर्ड ने भी इस यात्रा-कूटनीति को जारी रखा और रूस के साथ सम्बन्ध सुधार के प्रयत्न चालू रहे। 23-24 नवम्बर, 1974 को फोर्ड की सोवियत नेता ब्रेझ्नेव से पहली भेंट ब्लाडीवोस्टक में हुई। इस शिखर-बातों के दौरान सामरिक अस्त्र-परिसीमन के लिए समझौते के एक दूसरे चरण की हुर्रेला तैयार की गई और डॉ. कीसिंगर ने कहा कि जून, 1975 में ब्रेझ्नेव की अमेरिका-यात्रा के समय प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएँगे। नया समझौता सन् 1977 में प्रथम समझौते की (जो 1972 में हुआ था) प्रवधि समाप्त होने पर लागू होगा और सन् 1985 तक क्रियान्वित रहेगा। राष्ट्रपति फोर्ड ने कहा—“हमने अस्त्र-दौड़ पर रोक लगायी है जिसने कारण सोवियत संघ को अपने नियोजित कार्यक्रम में कटौती करनी होगी और यह कटौती अमेरिकी कार्यक्रम से कुछ अधिक ही होगी।”

सोवियत-संघ और अमेरिका के अधिकारियों में विभिन्न स्तरों पर बातचीत का सिलसिला चलता रहा—कभी मास्को से और कभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन-स्थलों पर। जुलाई-अगस्त, 1975 में हैगसिटी सम्मेलन को मफल बनाने में रूस और अमेरिका ने एव-दुमरे का दृष्टिकोण समझने की कोशिश की। जुलाई, 1975 में अन्तरिक्ष-यात्रियों का मिलन वास्तव में रूस और अमेरिका के मध्य बढ़ती हुई सहभावना का परिचायक था। इस सफल संयुक्त परियोजना से परस्पर मैत्री की भावना हठ हुई और यह आशा की जाने लगी कि दो महाशक्तियों के बढ़ते हुए सहयोग से विश्व-राजनीति में व्याप्त तनाव कम होगा। 9 अप्रैल, 1976 को अमेरिका और सोवियत संघ आणविक परीक्षणों का निरीक्षण करने पर सहमत हो गए और 13 मई, 1976 को शान्ति के लिए परमाणु विस्फोट के आकार आदि पर दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ। दोनों महाशक्तियों के अधिक सम्बन्ध भी उत्तरोत्तर सुघरते गए। सन् 1976 के मध्य तक उनके बीच व्यापार में चार सौ प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि आई थी।

अमेरिका-चीन सम्बन्ध : बदलते पहलू

निक्सन ने चीन की ओर अमेरिकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और फोर्ड ने भी अगस्त 1974 में सत्ताह्व होने ही अगले माह नवम्बर 1974 में विदेश मंत्री डॉ. कॉमिंगर को पुनः चीन यात्रा पर भेजा था। यह उनकी सातवीं पीकिंग यात्रा

थी। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका और चीन के सम्बन्ध ठण्डे हो चले हैं। वास्तव में चीन को यह अच्छा नहीं लगा कि अमेरिका रूस के अधिक निकट आये। फोर्ड-ब्रेज्नेव वार्ता के लिए ब्लाडीवोस्टक के चुनाव से चीन की भावनाओं को विशेष ठेस पहुँची क्योंकि यह स्थान कभी चीन का भाग था। चीन ने सोचा कि उसे चिढ़ाने के लिए ब्लाडीवोस्टक को वार्ता-स्थल चुना गया है। चीन के आक्रोश का एक कारण यह भी था कि अमेरिका ने ताइवान के प्रश्न पर शर्माई-समझौते पर अमल नहीं किया जो साल भर पहले डॉ. कीमिंगर की छठी यात्रा के समय दोनों पक्षों के बीच हुआ था। चीन के नये विदेश मन्त्री चियापो कुमानहुआ ने भूतपूर्व राष्ट्रपति निक्सन की सराहना की और कहा कि उन्होंने चीन-अमेरिका सम्बन्ध सुधारने में भारी योग दिया था। इस सराहना के माध्यम से चीनी नेताओं ने राष्ट्रपति फोर्ड को जता दिया कि अब अमेरिका की ओर से चीन को कुछ अनिश्चितता महसूस होने लगी है। चार-दिन के प्रवास के बाद कीमिंगर खाली हाथ लौट आये।

डॉ. कीमिंगर की आठवीं चीन यात्रा (19-23 अक्टूबर, 1975) के दौरान भी चीन के नेताओं ने बड़े ठण्डे दिल से अमेरिकी विदेश मन्त्री का स्वागत किया। राजनीतिक क्षेत्रों में यहाँ तक आशंका व्यक्त की गयी कि सम्भवतः राष्ट्रपति फोर्ड की चीन यात्रा छटायो में पड़ जायेगी। अध्यक्ष मापो ने भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की प्रशंसा की और उनसे पुनः मिलने की इच्छा प्रकट करके यह संकेत दिया कि चीन को फोर्ड आचार-विचार पसन्द नहीं हैं। मापो और अन्य चीनी नेता तो यह चाहते थे कि निक्सन ने चीन-अमेरिका सम्बन्ध की प्रक्रिया जहाँ पर छोड़ी थी फोर्ड वहाँ से उसे आगे बढ़ाये। लेकिन फोर्ड के सामने नई परिस्थितियाँ थी और वे निक्सन का अनुकरण नहीं कर सकते थे। डॉ. कीमिंगर के फीके स्वागत के बावजूद राष्ट्रपति फोर्ड ने दिसम्बर 1975 में चीन की यात्रा की। वह 1 से 4 दिसम्बर तक राजधानी पीकिंग में रहकर इण्डोनेशिया और फिलिपीन होते हुए स्वदेश लौट गये। फोर्ड की चीन-यात्रा फीकी रही। यात्रा की समाप्ति पर कोई सयुक्त वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। चीनी नेताओं ने इसे विवेकशील गोपनीयता को 'एक नई शैली' की संज्ञा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के फीके स्वागत के बावजूद चीन-अमेरिका में वार्ता दूटने की नीव नही आयी। फरवरी, 1976 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन की यात्रा की जहाँ उन्हें राज्याध्यक्ष जैसा सम्मान दिया गया। रिचर्ड निक्सन के इस सम्मान द्वारा चीनी नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड को यह संकेत दे दिया कि 'चीन को फोर्ड नहीं निक्सन चाहिए'। 15 मई, 1976 को अमेरिका ने ताइवान की प्रेरणा चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का निश्चय व्यक्त किया।

अमेरिका और जापान

राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 18 नवम्बर, 1974 को फोर्ड की पहली

विदेश यात्रा जापान की राजधानी टोकियो की थी। फोर्ड के पहुँचने से पहले ही टोकियो की सड़कों पर फोर्ड विरोधी नारे लगने लगे और वामपंथी युवकों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। जब निमन प्राये थे तो भी ऐसा ही हुआ था। जापान में वस्तुतः अमेरिका-विरोधी भावना बहुत उग्र है। फोर्ड का स्वागत कड़ी सुरक्षा के अन्तर्गत किया गया। उनकी प्रणवानी के लिए हवाई अड्डे पर न तो सम्राट ही आये और न प्रधानमंत्री ही। जापान को इस बात से गहरा आक्रोश है कि एक तो ओकोनावा द्वीप बहुत विलम्ब से और भारी ढील दृष्टि के बाद लौटाया गया और दूसरे चीन की ओर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पहले अमेरिका ने जापान को विश्वास में नहीं लिया। जापानी प्रधानमंत्री तानाका और फोर्ड के बीच बातों में जापान ने अमेरिका से अनाज की माँग की जो अमेरिका ने स्वीकार कर ली। कीसिंगर ने, जो फोर्ड के साथ थे, अपनी पान मूची योजना प्रस्तुत की जिसमें सभी औद्योगिक राष्ट्रों से अपील की गयी थी कि वे मिलकर प्रतिदिन 30 लाख बैरल तेल की खपत कम करें ताकि तेल-मकड़ को पार किया जा सके। अमेरिका-जापान की सन् 1960 की सुरक्षा-संधि को दोनों देशों के बीच मंत्री-सम्बन्धों के लिए पुनः महत्वपूर्ण बताया गया।

टोकियो की यात्रा के बाद राष्ट्रपति फोर्ड दक्षिणी कोरिया की यात्रा पर गये और फिर वहाँ से इलाडीबोस्टन में रुमी नेनाओ से मिले।

लेटिन अमेरिका वयूबा के प्रति नीति परिवर्तन

कोस्टारिका की राजधानी सान जोस में 29 जुलाई, 1975 को काफी रात गये अमेरिकी राष्ट्रों के 21 सदस्यीय संगठन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि पिछले 11 सालों से वयूबा के विरुद्ध जो सामूहिक राजनयिक और व्यापारिक प्रतिवन्ध लगा रहे थे उन्हें अब समाप्त कर दिया जायेगा। अमेरिका समेत 16 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रत्येक अमेरिकी राज्य वयूबा के साथ अपने व्यापारिक और राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र है। उल्लेखनीय है कि विधिवत तौर पर यह प्रस्ताव पारित होने के पहले कई देशों ने वयूबा के साथ एकतरफा सम्बन्ध स्थापित कर भी लिये थे। इन देशों का दबाव अमेरिका पर इतना बढ़ गया कि अमेरिकी-राष्ट्र-संगठन में फूट की स्थिति दृष्टिगोचर होने लगी। कई सदस्यों ने अमेरिकी प्रशासन में अनुरोध किया कि वह वयूबा के विरुद्ध अव्यवस्थित नीतियों को अपनाता छोड़ दे। कई क्षेत्रों में यह प्रस्ताव अमेरिकी नीतियों की पराजय समझा गया।

राष्ट्रपति केनेडी ने वयूबा को अन्य देशों में वृष्ण करने का प्रयास किया था। लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। वयूबा न केवल लेटिन अमेरिकी देशों में ही नहीं, बल्कि तीसरी दुनिया के देशों में भी सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया और गुटनिरपेक्ष देशों का वह एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाने लगा। वयूबा की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने प्रशासन पर दबाव डाला कि समय या गया है जब वयूबा के साथ सम्बन्ध सुधारे जायें। वयूबा

के साथ सम्बन्ध सुधारने का दौर निवमन-काल से ही शुरू हो गया था और फोर्ड के सत्ता में आने के बाद उन पर दबाव और बढ़ गया।

सन् 1974 में फ्रांस के राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आये। अक्टूबर 1973 में अरब इजराइल-युद्ध के बाद अरब-देशों द्वारा तेल का मूल्य बढ़ाकर तेल आपूर्ति नियंत्रित करने से विश्व में जब तेल-संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने तेल का उपयोग करने वाले देशों को संयुक्त कार्रवाई द्वारा उसका सामना करने की जो योजना बनायी, फ्रांस के राष्ट्रपति जार्ज पोम्पिडू ने उससे फ्रांस को पृथक् रखा। अप्रैल 1974 में पोम्पिडू की मृत्यु के बाद गिस्टार्ड गिस्तांग राष्ट्रपति चुने गये। उन्होंने भी अरब देशों पर संयुक्त रूप से दबाव डालने के बजाय द्विपक्षीय आधार पर सहयोग की नीति अपनायी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री फोर्ड के साथ गिस्तांग की मेट के बाद फ्रांस ने भी तेल उपभोक्ता देशों के साथ सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी। गिस्तांग 20 मई, 1974 को फ्रांस के नये राष्ट्रपति चुने गये तथा बाद में जैक्स चिराक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। फ्रांस ने अरब इजरायल युद्धकाल से पश्चिमी एशिया के देशों द्वारा शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जो अगस्त 1974 में उठा लिया गया।

राष्ट्रपति कार्टर और अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

30 जनवरी, 1977 को डेमोक्रेटिक पार्टी के 53 वर्षीय जेम्स अर्ल (जिम्मी) कार्टर (जन्म 1 अक्टूबर, 1924, प्लेन, जार्जिया) ने अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रूप में जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वॉरेन बर्जर से शपथ ग्रहण की, तो उनकी आँखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी जो अमेरिका के भविष्य का संदेश दे रही थी। कार्टर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा—

“हम सब को मिल कर परस्पर एकता और विश्वास की एक नई राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात करना है। आप लोगों की शक्ति मेरी कमजोरियों को बल प्रदान करेगी। आप लोगों की बुद्धिमत्ता मेरी गलतियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। हम सबको एक साथ मिल कर सीखना है, एक साथ मिल कर हँसना है, एक साथ मिल कर काम करना है और एक साथ मिल कर प्रार्थना करनी है। मुझे विश्वास है कि हमको अन्ततः विजय प्राप्त होगी। हमें एक बार फिर अपने देश में पूर्ण विश्वास की भावना जाग्रत करनी है। हमारा यह भी विश्वास है कि अमेरिका पहले से अच्छा होगा और पहले से हम वही अधिक शक्तिशाली होंगे। मानवाधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पूर्ण होनी चाहिए। हमारे कानून निष्पक्ष होने चाहिए। शक्तिशाली कमजोर का गला न दबाए इस बात का ख्याल रखते हुए हमें मानवीय गरिमा में वृद्धि करनी चाहिए। विदेशों में हमारा देश तभी शक्तिशाली होगा यदि हम अपने घर में शक्तिशाली होंगे। हम जानते हैं कि अपनी स्वाधीनता और अपनी लोकतन्त्रीय पद्धति एवं मूल्यों का इस धरती पर ही हम प्रमाण दे सकते हैं। विदेशों में हमें इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे हमारे घर के आगामों और नियमों का उल्लंघन होना हो। हम एक शक्तिशाली

राष्ट्र की शक्ति को बनाए रखेंगे। हम अपनी शक्ति को केवल सघर्ष युद्ध के क्षेत्र में ही उजागर नहीं करेंगे बल्कि गरीबी, अज्ञानता और अत्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। हम अपने गौरवपूर्ण आदर्शों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं लेकिन हमारे आदर्शों का तात्पर्य हमारी कमजोरी नहीं है। हम स्वाधीन हैं अतः हम अन्य राष्ट्रों की स्वाधीनता की भावना के विरुद्ध नहीं हो सकते।”

“आज दुनिया अस्त्रों की दौड़ में लगी हुई है। अपनी शक्ति को वह अस्त्रों के पैमाने से नापती है। हम अपनी ओर से विश्व में अस्त्रों को सीमित करने के प्रयास की प्रतिज्ञा करते हैं। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इस वर्ष के अन्त तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तथा इस घरेली से सभी परमाणु अस्त्रों की समाप्ति कर देंगे। हम सभी देशों और लोगों से इस प्रयाम में सहयोग का अनुरोध करते हैं। इसकी सफलता का अर्थ जीवन है, मृत्यु नहीं। मेरा विश्वास है कि सत्तार के राष्ट्र यह कहने पाए जाएंगे कि हमने एक ऐसे शान्तिपूर्ण वातावरण की मृष्टि की है जो युद्ध के अस्त्रों पर आधारित न होकर अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर आधारित है जो हमारे बहुमूल्य मूल्यों को प्रतिबिम्बित करती है।”¹

दिसम्बर, 1977 तक वाटर प्रशासन का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रवैया क्या रहा इसे हम निम्नलिखित शीर्षकों में व्यक्त कर सकते हैं—

नए रिश्तों की शुरुआत

20 जनवरी, 1977 को सत्ता सम्भालने के बाद राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने चुनाव अभियान में किए गए वादों पर अमल शुरू कर दिया। पहले उन्होंने वियतनाम के युद्ध में जबरन लामबन्दी का विरोध करने वाले लोगों को क्षमादान सम्बन्धी आदेश प्रसारित किया। उपराष्ट्रपति वाल्टर मांडेल को 23 जनवरी से 31 जनवरी तक सात देशों की यात्रा पर भेजा और समुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि एड्ज़ू यंग को 3 फरवरी से 12 फरवरी की ताँजानिया तथा नाइजीरिया की दस दिवसीय यात्रा पर भेजा।

यंग का आश्वासन—एड्ज़ू यंग ने ताँजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे को अमेरिका के राष्ट्रपति की सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा कि हम अमेरिकी अपने प्रभाव और शक्ति के प्रयोग से दक्षिण अफ्रीका भर में बहुमूल्यक और बहुजातीय शासन की सम्भावनाओं पर विचार कर सकते हैं। दरअसल दक्षिण अफ्रीका व समस्याओं का समाधान अफ्रीकियों द्वारा स्वयं होना चाहिए, हम लोग तो केवल सहायता कर सकते हैं। इस सहायता में हमें रक्तपात और विनाश के विकल्प स्थापन पर स्थायी शान्ति का विकल्प ढूँढना चाहिए। यंग ने इन अफ्रीकी नेताओं को विश्वास दिलाया कि वह वापरर्ड सशोधन में परिवर्तन करा कर रोडेशिया-त्रोम का आयात बंद करने की सिफारिश करेंगे। एड्ज़ू यंग की इस यात्रा से अफ्रीका में अमेरिका प्रशासन के प्रति एक नई तस्वीर स्थापित होगी।

मॉडेल की बातचीत—उपराष्ट्रपति वाल्टर मॉडेल ने बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान की नौ दिवसीय यात्रा में इन देशों से पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में वार्ता की। साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय और नैटो के अमेरिका के साथ सम्बन्धों का जायजा लिया। वॉशिंगटन वापसी पर उन्होंने कहा कि वह आश्चर्य हो कर स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने इटली की जर्जर अर्थव्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिलाया और नैटो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम जर्मनी के नेताओं से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों पर वार्ता तथा ब्राजील को परमाणु जानकारी देने के बारे में विशेष विचार हुआ।

पश्चिम एशिया और कार्टर प्रशासन

कार्टर प्रशासन ने पश्चिम एशिया की समस्या के निदान के लिए पूर्वापेक्षा अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। कार्टर के पदारूढ होने के बाद से ही अरब नेता समस्या के हल के लिए अमेरिका की ओर ताकने लगे थे। वैसे भी अरब देशों की ओर विशेषकर मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को अमेरिका और उसके नेताओं पर बहुत भरोसा है। उनकी मान्यता है कि यदि पश्चिमी एशिया में स्थिति सामान्य हो सकती है और शत्रुतापूर्ण वातावरण की समाप्ति हो सकती है तो वह केवल अमेरिकियों की मध्यस्थता से ही सम्भव है।

सन् 1977 के प्रारम्भिक चरण में पश्चिमी एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तनावपूर्ण वातावरण को छोड़ कर मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेल्मुट शिम्मेरूट से स्पष्ट कहा कि पश्चिमी एशिया के मामले पर जिनेवा में होने वाले सम्मेलन में फिलिस्तीनियों का अवश्य भाग लेना चाहिए। समस्या मुख्यतया उन्हीं की है और उनके प्रतिनिधियों को मुनना सभी के लिए उपयोगी रहेगा। राष्ट्रपति सादात ने सन् 1977 का वर्ष पश्चिमी एशिया के लिए निर्णायक माना। उन्होंने इस बात की भी आशा व्यक्त की कि काफी समय से स्थगित जिनेवा सम्मेलन जल्दी आरम्भ होगा।

जब सादात अमेरिका पहुँचे तो पहले विदेश मंत्री साइरस वैंस और उसके बाद प्रतिरक्षा मंत्री केरलड ब्राउन ने उन्हें कुछ उसी प्रकार का आश्वासन दिलाया। अनवर सादात ने राष्ट्रपति कार्टर को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी कि जब तक फिलिस्तीनियों का पृथक् राज्य नहीं बना जाता तब तक अरब-इजराइल संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। यह काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। इसके भलाया सादात ने अमेरिकी हथियारों की खरीद के बारे में भी वार्ता की। राष्ट्रपति सादात और राष्ट्रपति कार्टर ने सन् 1977 के उत्तरार्द्ध में जिनेवा सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रयास करने की बात दोहरायी। सादात को कार्टर की नीयत पर संदेह न होना स्वाभाविक था। कार्टर प्रशासन द्वारा इजरायल को दसवर्षक ऋचने की कार्यवाही रद्द करना और विदेश मंत्री साइरस वैंस को पश्चिमी एशिया की तथ्यावेषण का उत्तरदायित्व सौंपना, ये दो ऐसी घटनाएँ थी जिन्हें सादात समस्या के समाधान के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति की ईमानदारी का प्रमाण मान सकते थे।

सादात के अमेरिका-याना के बाद ही पश्चिमी एशिया की राजनीति में तेजी से नए मोड़ आए। इजरायल में मोशे बेगिन के नेतृत्व में लिक्वुड ग्रीर नेशनल रिक्लीजियेस पार्टी ने सत्ता ग्रहण की तो मिस्र के विदेश मंत्री इस्माइल पाहमी ने सोवियत सघ की यात्रा की। मिस्र और इजराइल के नेता पश्चिमी एशिया की राजनीति को एक नई दिशा देने के प्रयत्न में लगे रहे। उपर अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने इजरायल के नए शासकों को स्पष्ट रूप से बता दिया कि अरबों की हथियारों हुई भूमि उन्हें लौटानी होगी।

अक्तूबर, 1977 में अमेरिका, सोवियत सघ, अरब देश और इजरायल के बीच एक अनीपचारिक सम्मेलन हुआ जिसमें उस गतिरोध को समाप्त कर दिया जो पिछले एक दशों से जिनेवा सम्मेलन बुलाने में बाधक बना हुआ था। सम्मेलन के अनुसार इजरायल इस बात पर सहमत हो गया कि अरब देशों के प्रतिनिधि मण्डल में फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो सकता है—यानी मिस्र, सीरिया, जोर्डन, लेबनान और फिलिस्तीन का एक समुक्त प्रतिनिधि मण्डल भविष्य में होने वाले जिनेवा सम्मेलन में अरब पक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि अब तक इजरायल इस बात पर अड़ा हुआ था कि वह ऐसे किसी सम्मेलन में भाग नहीं लेगा जिसमें फिलिस्तीनी प्रतिनिधि उपस्थित होंगे।

अमेरिका और विशेष कर राष्ट्रपति कार्टर ने विश्वास रखते हुए मिस्री राष्ट्रपति सादात ने पश्चिमी एशिया में शान्ति की स्थापना के लिए इजरायल की यात्रा का निर्णय ले लिया। 19 नवम्बर, 1977 को सादात जब यरूशलम पहुँचे तो 29 साल पूर्व अस्तित्व में आए इजरायल भ्रान्त बाने वह प्रथम अरब नेता थे। जब इजरायली प्रधानमंत्री मोशे बेगिन से उन्होंने हाथ के ऊपर हाथ रख कर मिलाया तो एक टिप्पणीकार बरबस कह उठा— मैं दोनों को देख रहा हूँ लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है कि क्या वास्तविकता है, क्या यह मिलन सम्भव है।" राष्ट्रपति सादात ने 20 नवम्बर को इजरायली ससद् (नेसेट) को सम्बोधित किया और पश्चिमी एशिया में शान्ति के लिए कुछ उदार शर्तें रखी। सादात ने इजरायली संसद्-सदस्यों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि फिलिस्तीन राज्य की स्थापना से उन्हें डरना नहीं चाहिए। वस्तुतः, उनके अस्तित्व में आने से उसे तो दुनिया से सहायता की आवश्यकता होगी। अमेरिका ने भी फिलिस्तीनी राज्य की वास्तविकता को मान्यता प्रदान की है। सादात ने यह भी कहा कि वह बिना मिन बैठ कर अपनी समस्याएँ सुलझा लेंगे तो इसमें हम छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं खुने दिनाग से यहाँ प्राया हूँ। इसके साथ ही उन्होंने इजरायल के अस्तित्व को मान्यता देने की भी घोषणा की, लेकिन उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया कि वह इजरायल के साथ एकतरफा सम्मेलन करना चाहते थे। यह बात सही है कि इजरायल के अधिकार में मिस्र का अधिक क्षेत्र है और सीरिया का उससे कम,

लेकिन अनवर सादत ने यह स्पष्ट कर दिया कि मिस्र के अलावा सीरिया और जोर्डन से भी समझौता किया जाना चाहिए।¹

अमेरिका और वियतनाम

जिम्मी कार्टर के राष्ट्रपतित्वकाल के प्रारम्भिक कुछ महीनों में ही वियतनाम के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक बन गया। अप्रैल-मई, 1977 में पेरिस वार्ता का दौर चला। जो बात-चीत वियतनाम और अमेरिका के बीच हुई उसमें अमेरिका के रिचर्ड होलब्रुक ने विश्वास दिलाया कि अमेरिका अब वियतनाम के समुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने में बाधा न डालेगा। पिछली चार बार अमेरिका ने समुक्त राष्ट्रसंघ में अपने निजेषाधिकार का प्रयोग कर वियतनाम को विश्व-संस्था का सदस्य नहीं बनने दिया। अमेरिका प्रकेला ही इस बात पर वियतनाम का विरोध कर रहा था। पेरिस-वार्ता में अमेरिका ने वियतनाम में अपने दूतावास स्थापित करने की बात उठायी। वियतनाम ने दो मुख्य बातों पर जोर दिया। पहली, अमेरिका सन् 1973 के अमेरिका-वियतनाम समझौते की 29वीं धारा के अनुसार युद्ध में आहत देश के पुनर्निर्माण में आर्थिक सहायता दे और दूसरी, अमेरिका वियतनाम के साथ व्यापार करने पर लगाए गए सब प्रतिबन्धों को तुरन्त हटा ले। पेरिस बातचीत के दौरान यह प्रश्न उठा कि कौन-सी बात पहले तय की जाए—अमेरिका द्वारा एक दूसरे के देश में दूतावास स्थापित करने की बात पहले रखी गई जबकि वियतनाम में अमेरिका द्वारा की गई क्षति को पूरा करने के लिए अमेरिका की वियतनाम को आर्थिक सहायता तथा वियतनाम के साथ व्यापार करने पर लगाए गए प्रतिबन्धों को उठाने, की मांग वियतनाम ने पहले की। जहाँ तक युद्ध में लापता अमेरिकी सैनिकों का प्रश्न था वियतनाम का कहना था कि मृतकों के शव ढूँढना, उनका पता लगाना तथा उनको अमेरिका भेजना वह अपना कर्तव्य समझता है। इस सम्बन्ध में वियतनाम अब तक बम वर्षा द्वारा गिराए गए अमेरिकी विमानों के 23 चालकी तथा सैनिकों की अस्थियाँ व जब अमेरिकी प्रतिनिधियों को वापस ले जाने के लिए सौंप चुका है। वियतनाम ने संगीत पर कब्जा करने के बाद वहाँ शेष सब अमेरिकियों को भी वापस अपने देश लौट जाने दिया था। वियतनाम ने युद्ध-क्षति को पूरा करने के अमेरिका द्वारा मजूर प्रस्ताव को कार्यान्वित करने पर सबसे अधिक जोर दिया।

20 मिनस्वर 1977 को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 32वाँ अधिवेशन विश्व-संस्था में दो नए सदस्यों के प्रवेश साथ प्रारम्भ हुआ। ये सदस्य थे—वियतनाम और जिबूती। वियतनाम का रास्ता ठीक दो महीने पहले 20 जुलाई को सुरक्षा परिषद् की बैठक में ही साफ हो गया था जबकि भारत द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र में वियतनाम के प्रवेश की अनुमति दी थी।

कार्टर प्रशासन और रोडेशिया की समस्या

रोडेशिया की समस्या के प्रति कार्टर-प्रशासन ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इसका प्रमाण सन् 1977 के प्रारम्भ में रोडेशिया की अल्पमत गौरी सरकार को अमेरिकी विदेश मन्त्री साइरस वैंस द्वारा दो गई नेतावनी से मिलता है। वैंस ने इयान स्मिथ की सरकार को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि जब तक वह बहुसंख्यक कालो की सत्ता के राह में प्रबलन डालती रहेगी, अमेरिका से उसे किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। उन्होंने इयान स्मिथ द्वारा कालो को सत्ता हस्तांतरण का ब्रिटिश प्रस्ताव रद्द करने के निर्णय को घातक बताया और कहा कि इसका प्रभाव दक्षिण अफ्रीका पर भी बड़े पैमाने पर पड़ेगा। अमेरिका ने ब्रिटिश प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया जिसमें दो वर्षों तक प्रस्थायी सरकार ब्रिटेन की देखरेख में काम करेगी। रोडेशिया वार्ता में राष्ट्रवादी आन्दोलन के सभी नेताओं को शामिल किया जाना चाहिए, तथाकथित आन्तरिक मामला कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। वैंस के अलावा यूरोपीय प्रायिक समुदाय के विदेश मन्त्रियों ने भी इयान स्मिथ द्वारा ब्रिटिश प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया।

अमेरिका और पनामा : पनामा को पनामा मिल गयी

3 नवम्बर 1903 तक पनामा दक्षिण अमरीका के कोलम्बिया राज्य का एक प्रांत था। 3 नवम्बर 1903 को पनामा निवासियों ने विद्रोह कर दिया और स्वतन्त्र पनामा राज्य की स्थापना की। स्वतन्त्र होने में अमरीका ने उसकी सहायता की। 13 नवम्बर को अमरीका ने पनामा राज्य को मान्यता दे दी। इसके बाद धीरे-धीरे बहुत से राष्ट्रों ने इसे मान्यता दे दी। सन् 1914 में कोलम्बिया ने भी उसे एक पृथक् राष्ट्र मान लिया। पनामा गणराज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 31890 वर्गमील है और उसकी जनसंख्या 10 लाख के लगभग है। इसके बीचो बीच जाने वाली नहर देश को दो भागों में विभाजित करती है तथा दोनों ओर के प्रशांत और अटलांतिक महासागरों को मिलाती है। नहर क्षेत्र की घाटादी 60 हजार के लगभग है। इनमें 38000 लोग अमरीकी हैं। नहर के कारण इस राज्य के निवासियों में अनेक जातियों के लोग आकर बस गए हैं। यह नहर सन् 1914 में बन कर तैयार हुई थी और उसे 15 अगस्त 1914 को व्यापारिक कार्यों के लिए चालू कर दिया गया था। इससे पूर्व जहाजों को दक्षिण अमरीका का कई हजार मील का जो चक्कर लगा कर दूसरी ओर जाना पड़ता था, वह बच गया। पनामा नहर के दोनों ओर पाँच-पाँच मील चौड़ा और अटलांतिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ क्षेत्र सन् 1904 से अमरीकी सरकार के अधिकार में है। इस क्षेत्र का प्रशासन नहर-क्षेत्र सरकार और नहर का संचालन पनामा नहर कम्पनी के हाथों में है। इस नहर कम्पनी की स्थापना 1 जुलाई 1914 को हुई थी। अमरीकी नौसेना के मन्त्री के हाथों ही नहर कम्पनी के सारे शेयर रहते हैं।¹ 11 अगस्त 1977 को 1. हिल्बुस्तान दिनांक 25 अगस्त, 1977—पी के हरिवंश का लेख पनामा पर अमेरिकी नियन्त्रण।

अमेरिका ने पनामा के साथ एक नये समझौते की घोषणा की जिसके अनुसार, समझौता लागू होते ही, पनामा नहर क्षेत्र पर से अमेरिकी सैनिक दबाए धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा और 31 दिसम्बर 1999 तक यह समूचा क्षेत्र पूरी तरह पनामा के नियन्त्रण में आ जायगा। सन्धि के द्वारा पनामा ने यह स्वीकार कर लिया है कि नहर क्षेत्र पर अमेरिका का नियन्त्रण समाप्त होते ही नहर की रक्षा के लिए पनामा अमेरिका की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। परन्तु बताया जाता है कि इस प्रकार की भूमिका सन्धि की कोई धारा नहीं है, इसके लिए अमेरिका से प्रलग ही समझौता किया जायेगा। सन्धि में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नहर की तटस्थता को कायम रखा जायेगा और सभी राष्ट्रों के जहाज उसमें आ जा सकेंगे। वर्तमान सन्धि 1903 की सन्धि का स्थान ले लेगी। 1903 की सन्धि ने ही अमेरिका को नहर और उसके सीमा-क्षेत्र के नियन्त्रण का अधिकार हमेशा के लिए दे दिया था।¹

पनामा के मामले में सबसे बड़ी उलझन पनामा की आर्थिक मांग को पूरा करना था। पनामा की मांग थी कि उसे 46 करोड़ डॉलर का मुआवजा दिया जाय। यह मुआवजा सन् 1903 से आज तक का होगा और आज से इस शताब्दी के अन्त तक, जबकि नहर को पूर्णतः पनामा को दे दिया जाएगा, 15 करोड़ रुपए वार्षिक की पूर्ति की जाए। अगस्त 1977 के नये समझौते के अनुसार सन् 2000 तक पनामा को 4 से 5 करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष तक मुआवजे के रूप में दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका पनामा को आर्थिक सहायता के रूप में कोई 30 करोड़ डॉलर और सैनिक सहायता के रूप में 5 करोड़ डॉलर देगा।

पनामा समझौते से यद्यपि पनामा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी पर अमेरिका का नियन्त्रण 2000 तक बना रहेगा। इतने में क्या हो जाय, कौन कह सकता है।

भारत के प्रति कार्टर का दृष्टिकोण

अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कार्टर का कहना है कि भारत-अमेरिका सम्बन्धों को बे रचनात्मक रूप देना चाहते हैं। श्री कार्टर ने भारत के नये राजदूत श्री नानी पालकीवाला द्वारा अपना परिचय-पत्र पेश किये जाने के अवसर पर भाषण करते हुए कहा कि शायद भारत तथा अमेरिका बहुत समय से एक-दूसरे को पूर्ण निर्धारित दृष्टिकोण से देखते रहे हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ने बदलती परिस्थितियों तथा बदलते सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच सम्बन्ध विकसित करने पर बल दिया। अपनी ओर से श्री पालकीवाला ने भी दोनों देशों के सम्बन्ध 'घनिष्ठ बनाने के लिए अनुकूल वातावरण की ओर ध्यान आकषिप्त किया।

नये राजदूत के परिचय-पत्र पेश करने के अवसर पर ऐसी भावनाओं का प्रदर्शन स्वाभाविक है। वैसे भी भारत में जनता पार्टी की स्थापना के बाद अमेरिका से सम्बन्ध सुधारने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने की सम्भावनाएँ उजागर हुई हैं, इससे कोई

इन्कार नहीं कर सकता। जनता पार्टी की विजय का मुख्य कारण आपात स्थिति रही है। नई सरकार ने अनेक बार प्राने आलोचकों की आलोचनाओं का उत्तर देते हुए इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कुछ ही महीनों के प्रन्दर जनता पार्टी न लोकतन्त्र को पुनः स्थापित कर दिया है, प्रेस की स्वतन्त्रता कर दी गई है तथा मानव अधिकारों के मूल्यों को पुनर्स्थापना की गई है। अमरीका प्रेस की स्वतन्त्रता, अमरीका में ही नहीं बल्कि इस में भी मानव अधिकारों के हनन पर चिन्तित है। इसमें कितनी राजनीति है और कितनी वास्तविक चिन्ता है, यह अलग विवाद का विषय है। किन्तु इतना स्पष्ट है कि जनता पार्टी जिन आदर्शों को पुनर्स्थापना के दावे कर रही है वे अमरीका को भी सदा प्रिय रहे हैं। ऐसी स्थिति में निस्संदेह भारत तथा अमरीका के सम्बन्धों में सुधार के अनुकूल वातावरण पैदा हुआ है।

किन्तु भारत की स्वतन्त्रता के वाद अमरीका के साथ सम्बन्धों में विगाड़ के लिए कांग्रेस सरकार की नीति बाधक रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। आगत स्थिति तो 1975 में आरम्भ हुई और 19 महीनों तक ही रही। किन्तु भारत और अमरीका के सम्बन्ध तब भी मधुर नहीं थे जब प० नेहरू की लोकतन्त्र में आस्था तथा मानवीय मूल्यों में विश्वास अपने-प्राप में एक मिसाल है। नेहरूजी का मानवीय दृष्टिकोण तथा लोकतन्त्रीय मान्यताएँ भी अमरीका को भारत की नेजनीयती का विश्वास नहीं दिला पायीं। स्पष्टतः उस समय अमरीकी नेताओं का विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उसके साथ नहीं है, वह उनके विरुद्ध है। कुछ ही वर्ष पूर्व राष्ट्रपति निसन के शासनकाल तक भारत के प्रति अमरीका का यही रुख रहा। यह किसी व्यक्तिविशेष की नीति होने के बजाय पूरे प्रशासन का सुविचारित दृष्टिकोण था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत तथा अमरीका के बीच सही अर्थों में रचनात्मक सहयोग के लिए दृष्टिकोण में सुनिपासी परिवर्तन की आवश्यकता है।

भारत तथा अमरीका विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में अमरीकी जनता तथा प्रशासन की सहानुभूति स्पष्टतः स्वातन्त्र्य सेनानियों के साथ थी। फिर भी सन् 1947 में भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद दोनों राष्ट्र एक-दूसरे से दूर हटते गये। यह एक ग़ूर सत्य के रूप में तब प्रकट हुआ जब सन् 1971 में भारत-बंगला देश संघर्ष के समय अमरीका ने भारत के विरुद्ध बंगाल की खाड़ी में अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा।

किन्तु समय और परिस्थितियों के साथ अमरीकी दृष्टिकोण में कुछ हद तक परिवर्तन आया है। विश्वास किया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति कार्टर भारत तथा अमेरिका के बीच दीर्घकालीन सहयोग की माधारशिला रखेंगे। जहाँ तक भारत का प्रश्न है यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अमेरिका जैसे समृद्ध तथा सबल राष्ट्र के साथ सहयोग उसके लिए हितकर होगा।

कार्टर की शान्तिप्रियता

अमेरिका के कार्टर प्रशासन ने निश्चय किया है कि ईरान अमेरिका से जो 250 एफ-18 एल लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है, वे उसे न बेचे जाएँ। इससे पूर्व कार्टर-प्रशासन पाकिस्तान को 110 ए-7 लड़ाकू विमान बेचने से भी इन्कार कर चुका है। ये दोनों कदम श्री कार्टर के इस कथित संकल्प के अनुकूल हैं कि अमेरिका ससार का प्रमुख हथियारो का मोदागर नहीं बनना चाहता और यह सगार के किसी भी भाग में शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करेगा। जहाँ तक पाकिस्तान को ए-7 विमान न देने के निर्णय का प्रश्न है, भारत के तो यह सर्वथा अनुकूल है और भारत में उसका स्वागत होगा स्वाभाविक है। पिछले लगभग दो दशक से भारत और अमेरिका के बीच सम्बन्धों में पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी हथियारों की प्राप्ति के प्रश्न पर ही तनाव आता रहा है। बगला देश के मुक्ति-संघर्ष के समय हुए भारत-पाक युद्ध के दौरान श्री निक्सन की पाकिस्तान की ओर झुकाव की स्पष्ट घोषित नीति के फलस्वरूप उसके बाद से तो दोनों देशों के सम्बन्ध काफी बिगड़े रहे हैं और तब से अमेरिका ने भारत को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी। श्री कार्टर से पूर्व अमेरिकी प्रशासन एक तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने और दूसरे भारतीय उपमहाद्वीप में तथाकथित शक्ति सन्तुलन कायम रखने के नाम पर पाकिस्तान को उसकी प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं से कहीं अधिक हथियार देता रहा है। इसका परिणाम भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव का निरन्तर जारी रहना ही नहीं था, बल्कि दोनों की शक्ति शस्त्रास्त्र खरीदने में लगी रहने से उनका विकास और आर्थिक उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि पूँजी और उत्पादन आर्थिक विकास में लगने के बजाय शस्त्रास्त्र प्रतिस्पर्द्धाओं में लगने रहेंगे। इसलिए श्री कार्टर की शान्तिप्रियता की यह नीति, जिसकी भलक पाकिस्तान और ईरान सम्बन्धी उपयुक्त निर्णयों से मिलती है, विश्व शान्ति पर अनुकूल प्रभाव डालेगी और इससे भारत के साथ अमेरिका के सम्बन्ध भी और अधिक सुधरेंगे।

कार्टर प्रशासन और चीन : बदलते समीकरण

कार्टर-प्रशासन चीन के साथ अमेरिका के सम्बन्ध सुधारने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है। दशों दिशा में पहल करते हुए 22 से 27 अगस्त 1977 तक अमेरिकी विदेशमन्त्री साइरस वैंस ने चीन की यात्रा की थी। पर यह यात्रा दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधारने में सहायक नहीं हुई। ताइवान सम्बन्धी मतभेद के कारण अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय सहयोग के अन्य मुद्दों पर भी मतंकेय नहीं हो सका। अमेरिकी विदेशमन्त्री ताइवान से सम्बन्ध तोड़ने को तैयार नहीं हुए और चीन उसके बिना मित्रता का प्रदर्शन करने के लिए भी भला क्यों तैयार होता? परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर को यह कहने का अवसर मिला कि चीन को पूर्ण मान्यता देने में अभी वर्षों लगेंगे।

श्री वैंस की यात्रा की समाप्ति पर कोई संयुक्त वित्ति प्रसारित नहीं की गई फिर भी ऐसा वातावरण दिखाई देने लगा कि दोनों पक्ष अन्ततः ताइवान पर

समझौता कर लेंगे। किन्तु लगभग दो सप्ताह बाद 6 सितम्बर को चीन के उप-प्रधानमन्त्री तेङ्ग सिआओ पिङ ने ऐसोसिएटेड प्रेस को दी गई एक भेंट वार्ता में ऐसा प्रभाव पैदा करने का दोष अमेरिका पर मढ़ते हुए कहा कि "अमेरिका अपने पहले वापदे से मुकर गया है जिसके कारण चीन और अमेरिका के कूटनीतिक सम्बन्धों को सामान्य बनाने के प्रयास को घक्का लगा।" उनके अनुसार बातचीत के दौरान श्री वैंस ने जो कुछ कहा वह भूतपूर्व राष्ट्रपति फोर्ड और भूतपूर्व विदेशमन्त्री डॉ कीसिंगर के प्रस्तावों के ठीक विपरीत था। श्री तेङ्ग ने कहा कि दिसम्बर, 1975 में अपनी चीन यात्रा के समय तत्कालीन राष्ट्रपति फोर्ड ने यह वचन दिया था कि यदि वह पुनः निर्वाचित हो गए तो वह ताइवान से सम्बन्ध विच्छेद कर चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करेंगे। श्री तेङ्ग के अनुसार तब अमेरिका ने सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए तीन कार्य करने का आश्वासन दिया था—(i) ताइवान से अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ना, (ii) अमेरिका-ताइवान सुरक्षा सन्धि रद्द करना, और (iii) ताइवान स्थित 12,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना। किन्तु श्री तेङ्ग के अनुसार श्री वैंस ने यह कहा कि अमेरिका चीन के साथ तो पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार है किन्तु वह ताइवान में एक राजनयिक सम्पत्ति कार्यालय भी स्थापित करना चाहता है। श्री तेङ्ग ने इस प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि इससे अमेरिका और ताइवान के बीच राजनयिक सम्बन्ध कायम रहेगा। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है और उसे अमेरिका से अपने सम्बन्धों का मुख्य प्राधार मानकर चल रहा है। माओ के समय में चीन की यही नीति रही और अब सत्ता बदलने पर भी उसकी यही नीति है। सच तो यह है कि चीन में सत्ता परिवर्तन का प्रभाव अभी तक उसकी विदेश नीति में स्पष्ट परिलक्षित नहीं हुआ है। भारत के साथ उसके सम्बन्धों को देखते हुए भी ऐसा ही आभास मिलता है।

विदेश-मन्त्री वैंस की चीन यात्रा के परिणामों से अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर को कोई निराशा नहीं हुई है। चीन के प्रति अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए उन्होंने चीनको विभिन्न किस्मों के हथियारों तथा विद्युत-प्राणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने का निश्चय किया है। अब तक ये हथियार आश तोर पर निर्यात नहीं किए जाते थे। दोनों कम्युनिस्ट दिग्गज-सोवियत सघ और चीन कतिपय सूक्ष्म उपकरणों के क्षेत्र में अमेरिकी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने तथा प्रौद्योगिकी तैयार माल प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। सोवियत सघ आश तोर पर तकनीकी जानकारी प्राप्त करने को ही उत्सुक है परन्तु चीन इस आशा के साथ तैयार माल भी प्राप्त करना चाहता है ताकि उसके प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ उस माल से उसके निर्माण की तकनीक जान सकें।

कार्टर-प्रशासन सोवियत सघ : कार्टर की नैतिकता की राजनीति कार्टर-प्रशासन सोवियत सघ के साथ अपने देश के उत्तरोत्तर सम्बन्ध सुधार के लिए सचेष्ट है। कार्टर मानवाधिकार का पृष्ठपोषण कर रहे हैं और नैतिकता

की राजनीति से लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और साम्यवादी देशों को प्रभावित करना चाहते हैं। सोवियत लेखक सलारोप्र के मानवाधिकारों की वकालत सम्बन्धी पत्र के प्रश्न पर सोवियत संघ और अमेरिका में सन् 1977 के प्रथम चरण में कुछ तनाव भी उत्पन्न हो गया था। सोवियत प्रचार माध्यमों ने यह आरोप लगाया था कि कार्टर अन्य देशों में जिन मानवाधिकारों की वकालत कर रहे हैं उनका हनन स्वयं अमेरिका में बड़े पैमाने पर हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति कार्टर की अपनी कार्य-शैली है—अमेरिकी विदेश नीति में कीसिमर युग समाप्त हो गया है और नया प्रशासन अपना नया मार्ग निर्धारित कर रहा है। राष्ट्रपति कार्टर की नैतिकता की राजनीति से सबसे अधिक साम्यवादी देश प्रभावित होंगे। बताया जाता है कि श्री सलारोप्र को श्री कार्टर द्वारा लिखे पत्र को प्रसारित किए जाने के बाद से सोवियत संघ में किसी असन्तुष्ट व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया गया। कार्टर से मिलने वाले रोमानिया के एक वरिष्ठ राजनेता ने भी राष्ट्रपति कार्टर को यह विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार विपक्ष के प्रति उतनी प्रगुदार नहीं है जितनी वह समझते हैं। सोवियत संघ के प्रति कार्टर-प्रशासन की नई नीति का मूलाधार यह बताया जाता है कि अमेरिकी जनमत को सोवियत संघ पर विश्वास नहीं है और वह वहाँ हो रहे दमन पर अमेरिकी चुप्पी को नापसंद करता है। राष्ट्रपति कार्टर का विचार है कि अमेरिकी जनमत का समर्थन मिलने पर ही वह सोवियत संघ से अपनी शर्तों पर समझौता करने में सफल हो सकते हैं। वह चाहते हैं कि अगले दशक में दोनों महाशक्तियों के परमाणु-घरानों में भारी कटौती हो और सोवियत संघ तथा पश्चिमी गुट के देशों के बीच नए आर्थिक सम्बन्ध विकसित हों।

यह एक कारण हो सकता है कि सोवियत विरोधी अमेरिकी जनता का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति कार्टर ने सोवियत संघ के असन्तुष्टों की ओर से बोलना शुरू किया है किन्तु इससे भी व्यापक और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि ऐसा करके वह सोवियत संघ पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। असन्तुष्टों के प्रति यदि सोवियत सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो अमेरिका में सोवियत विरोध और बढ़ेगा और उस दशा में सोवियत संघ के विरुद्ध कुछ प्रतिबन्धात्मक कदम उठाने में राष्ट्रपति कार्टर को कोई कठिनाई नहीं होगी। ये प्रतिबन्धात्मक कदम क्या हो सकते हैं इसका संकेत भी उन्होंने इथियोपिया, आर्जेंटीना और ऊर्ग्वे को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती को घोषणा करके दे दिया है।

सोवियत संघ समेत सभी साम्यवादी देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और एक मात्र इस मुद्दे को लेकर अमेरिका उन पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका के पास विश्व के अत्याधुनिक प्रौद्योगिक उपकरण हैं जिनकी साम्यवादी देशों में भारी माँग है। राष्ट्रपति कार्टर इसे दबाव का साधन बनाना चाहते हैं। साम्यवादी देश अपने असन्तुष्ट लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और विदेश में अमेरिका के विरुद्ध मोर्चा न खोलें, तभी उन्हें अमेरिका से प्रौद्योगिक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं। श्री कार्टर की नैतिकता की

राजनीति का यही मूल स्वर जान पड़ता है। सोवियत संघ तथा अन्य साम्यवादी देशों पर दबाव डालने के लिए साम्यवादी देशों को दिए जाने वाले अमेरिकी ऋणों में कटौती करने का कदम भी यह देर सवेरे उठा सकते हैं और अपने इस अभियान में अपने यूरोपीय मित्रों और जापान को भी सम्मिलित कर सकते हैं, यद्यपि ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि सोवियत संघ को उधार माल देकर पश्चिमी देश येन केन प्रकारेण अपने बेरोजगारी के बोझ को हल्का बनाए रहे हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि कार्टर प्रशासन ऐसा सभी प्रकार के सम्झौतों के मार्ग तब तक के लिए बन्द कर देना चाहता है जब तक सोवियत संघ उसकी नैतिकता की राजनीति से सहमत न हो जाए।

निरचय ही राष्ट्रपति कार्टर ने अपने कार्यकाल के कुछ ही महीनों में हस्त-चल रहा था कि वह परमाणु अस्त्रों में अग्रता प्राप्त कर लेगा और अपने यहाँ के असन्तुष्टों का अमेरिका की अग्रसरता के बिना दमन कर सरेगा। उसे याशा थी कि इस सबके बावजूद वह अमेरिका के आर्थिक सहयोग से लाभान्वित होता रहेगा। अब कार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु-अस्त्रों के बारे में वह उचित समानता चाहेंगे और अमेरिका से आर्थिक सहयोग स्थगित रखने के लिए सोवियत संघ को पर मे और बाहर अपना आचरण बदलना होगा। कार्टर की इस नीति ने सोवियत संघ को दुविधा में डाल दिया है।

कार्टर की इच्छा रूस अमेरिका सम्बन्धों को जो भी मोड़ देने की हो, इस तनातनी के वातावरण में ज्वलहात हथियारों की होड़ एक बार फिर शुरू हो गई है। अमेरिका ने बी-1 बमवर्षक न बनाने का निर्णय तो लिया है, साथ ही यह फैसला भी किया है कि वह 'कूज' प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करेगा। इससे पहले उसने न्यूट्रान बम का परीक्षण भी किया था। अमेरिका का उद्देश्य सोवियत संघ को शायद यह जतलाना है कि परमाणु अस्त्रों के क्षेत्र में वह ज्यादा मज्दूरी स्थिति में है। साथ ही वह अपनी शक्तों पर सामरिक अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने सम्बन्धी बातों (स्टाट) में अपने तर्कों को भी प्राथमिकता देना चाहता है। लेकिन सोवियत संघ ने इन नए हथियारों की आलोचना करते हुए कहा कि यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक तरफ तो माघ शान्ति और मानवाधिकारों के प्रति प्रेम बगलाएँ और दूसरी ओर नए हथियारों का निर्माण कर सारी मानवता को विनाश के बगार पर लाकर खड़ा करें। यह सब काम अमेरिका ही कर सकता है। रूसी टिप्पणीकारों का विचार है कि सभी विश्लेषणकर्त्ता अनुभव करते हैं कि ऐसे नए हथियारों के निर्माण से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जटिलता ही पैदा होगी तथा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सामरिक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी बातों में गतिरोध उत्पन्न होगा।

अमेरिकी विदेश-नीति का मूल्यांकन
(Evaluation of American Foreign Policy)

युद्धोत्तरकालीन अमेरिकी विदेश-नीति के विश्लेषण से यही स्पष्ट होता है

कि घोषणाओं के अलावा वास्तव में वह कभी भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी नहीं रहा है और यदि कभी उसने ऐसा किया भी है तो राष्ट्रीय स्वार्थों से प्रेरित होकर ही। सत्य तो यह है कि आर्थिक और सैनिक सहायता द्वारा अमेरिका ने अपना एक अदृश्य साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा की है जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हुआ है। लेटिन अमेरिका और पूर्वी एशिया उसके साम्राज्य-विस्तार के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। उसने विश्व के देशों में अपने अनेक सैनिक अड्डे स्थापित कर रखे हैं तथा अनेक देशों के साथ असमान आर्थिक और सैनिक समझौते किए हैं। अरब-इजरायल संघर्ष के माध्यम से उसने पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाले अपार तेल-भण्डारों पर अपना नियन्त्रण रखने की चेष्टा की है। ट्रूमैन सिद्धान्त, माइजनेहॉवर सिद्धान्त, आदि इस उद्देश्य की पूर्ति के ही साधन रहे हैं। पूर्वी एशिया में भी उसने कुछ समय पूर्व तक पद-दलित शासक ज़ांग-काई-शेक को चीन के शासक के रूप में मान्यता दे रखी थी। वह वियतनाम और कम्बोडिया में कठपुतली सरकारों का संचालन करता रहा है तथा पश्चिमी एशिया में इजरायल को अपनी हठधर्म पर बड़े रहने में सहायता दे रहा है। यूरोप में वह भूतपूर्व फासिस्टों और नाज़ियों का समर्थन कर रहा है। उसके इन सब कार्यों के फलस्वरूप विश्व-शान्ति की कड़ियाँ मजबूत होने के बजाय विश्व-युद्ध का तनावपूर्ण वातावरण ही विकसित होता जा रहा है।

पिछले बीस वर्षों में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी सैन्य-शक्ति के रूप में सामने आया है। उसके पास सबसे बड़ा सशस्त्र सैनिक दस्ता है, चीन से भी बड़ा जो कि सभार का सबसे घना बसा देश है। उसकी सैनिक सहाय अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रूस से भी अधिक है। 42 से भी अधिक देशों के साथ उसके सैनिक समझौते हैं और 33 देशों में 2,000 से अधिक स्थानों पर सैनिक अड्डे हैं। पिछले बीस वर्षों में उसने अपने राष्ट्रीय राजस्व का आधे से अधिक भाग इन सैनिक समझौतों पर व्यय किया है। अपने इन दायित्वों को निभाने में अगर वह प्रबल संकोच करता है तो यूरोप या सुदूर-पूर्व से वह हटता है तो उसके रक्षित स्थान की पूर्ति करने को दो भ्रजगर तैयार पड़े हैं—रूस और चीन। यह बात अमेरिका को सहन नहीं।

अमेरिकी विदेश-नीति के अध्येता को ऐसा लगेगा मानो नैतिकता और विश्व-शान्ति के लिए क्या आवश्यक है इसका निर्णय करने का ठेका केवल अमेरिका ने ही ले लिया है। एशिया में तो अमेरिकी विदेश-नीति बड़ी-बड़ी गलतियों की शृंखला के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में अमेरिका ने एशिया को पश्चात्य उपनिवेशिक शक्तियों के चश्मे से ही देखने का प्रयत्न किया है और अफ़ेक्षियायी देशों के प्रति राजनीति के निर्धारण में पुरानी दकियानूसी नीति का प्रयोग कर रहा है। निरूपन-प्रशासन ने जो कुछ किया, फोर्ड-प्रशासन भी उनी सीक पर चला। 20 जनवरी, 1977 को राष्ट्रपति पद जिम्मे काटेंर ने सम्भाला और तब से अमेरिका की नीति कुछ यथार्थवादी और उदार बनी है। नए राष्ट्रपति की अपनी कार्य-शैली है। काटेंर-प्रशासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में अमेरिकी शक्ति पर

पुनर्विचार किया है और भारत के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया है। कार्टर-प्रशासन यह समझने लगा है कि एशिया में भारत लोकतन्त्र का गढ़ है और भारतीय हितों की कीमत पर अमेरिका को अपनी सकीर्ण नीतियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्टर ने मानवाधिकार पर बल दिया है और अपनी नैतिकता की राजनीति को विश्व में प्रभावी बनाना चाहते हैं। पश्चिमी एशिया में शान्ति-स्थापना की दृष्टि से कार्टर-प्रशासन की भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण रही है। रोडेशिया की समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश प्रस्ताव को समर्थन देकर अमेरिका ने इपान स्मिथ की अल्पमत गरीबी सरकार को एक व्यावहारिक चुनौती दी है। कार्टर-प्रशासन चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने को प्रयत्नशील है और विश्व-शान्ति को स्वर्गीय राष्ट्रपति नैनेडी की भाँति ही प्राथमिकता दे रहा है। यह आशा की जानी चाहिए कि कार्टर के राष्ट्रपतित्व में अमेरिकी विदेश-नीति नई दिशाएँ ग्रहण करेगी और अमेरिका की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वैसे राष्ट्रपति बदल जाने से किसी राष्ट्र के बुनियादी हितों में परिवर्तन नहीं होता और प्रत्येक राष्ट्रपति का प्रथम लक्ष्य इन हितों की रक्षा करना होता है, तथापि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए भी नीतियों में परिवर्तन की व्यापक सम्भावनाएँ रहती हैं। राष्ट्रपति कार्टर के मामले में विदेश-नीति के सन्दर्भ में मुख्य समस्या होगी रूस और चीन के साथ सम्बन्ध। राष्ट्रपति निक्मन तथा राष्ट्रपति फोर्ड के विदेशमन्त्री डॉ. हेनरी किस्सिजर ने चीन को रूस के निकट नहीं आने देने की सदा कोशिश की थी।

सोवियत संघ की विदेश नीति

(FOREIGN POLICY OF U. S. S. R)

“रूस की नीति अपरिवर्तनीय है..... उसके साधनों, उसकी धारों तथा कूटनीति में परिवर्तन आ सकता है, परन्तु उसकी नीति का मार्ग-दर्शक गृह-विविध-प्रभुता, एक अविफल और ध्रुव सत्य है।” —कार्ल मार्क्स

सन् 1917 की बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप वर्तमान साम्यवादी रूस अस्तित्व में आया। रूस के नए शासन ने अपने देश को महायुद्ध से पृथक् कर लिया। दो महायुद्धों के बीच की अवधि में रूस उत्तरोत्तर शक्तिशाली होता गया। द्वितीय महायुद्ध कालीन घोर विनाश के बावजूद अन्न में सोवियत रूस ने महान् राजनीतिक और प्रादेशिक लाभ अर्जित किए। महायुद्ध के उपरान्त संयुक्तराज्य अमेरिका की टक्कर का यदि कोई देश था तो वह सोवियत संघ ही था, किन्तु आणविक शक्ति पर एकाधिकार के कारण रूस की अवहेलना करना अमेरिका के लिए आसान था। यह स्थिति कुछ ही वर्ष बाद पलट गई क्योंकि रूस भी अणु शक्ति का स्वामी बन गया। महायुद्ध के बाद लगभग तीन दशकों के उपरान्त आज स्थिति यह है कि अमेरिका और रूस दोनों लगभग समान टक्कर की महाशक्तियाँ हैं। घन-सम्पन्नता में अमेरिका अग्रणी है, सैनिक दृष्टि से भी कुछ राष्ट्र अमेरिका को उच्चतर समझते हैं, लेकिन यह कहना वस्तुतः कठिन है कि सोवियत शक्ति अमेरिका की तुलना में कहाँ तक कम है। दोनों ही महाशक्तियाँ एक-दूसरे के सम्पूर्ण विनाश में समर्थ हैं और इसलिए विगत कुछ वर्षों से दोनों सह-अस्तित्व की दिशा में अग्रसर हुए हैं। चीन और भारत दो महान् सन्तुलनकारी शक्तियाँ हैं जिनमें चीन अमेरिका के पक्ष में झुकता जा रहा है और भारत तथा रूस घनिष्ठ मित्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ की विदेश-नीति को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है—

(क) उग्रवादी नीति का स्टालिन युग (1945-1953)

(ख) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का स्टालिनोत्तर युग (1953 से अब तक)—मोर्लैकोव काल (1953-54), ख्रुश्चेव काल (1954-64), ब्रेझ्नेव-कोसिगिन काल (1964-77)।

स्टालिन युग (1945-1953)

महायुद्ध-काल में स्टालिन ने मित्र-राष्ट्रों को पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन महायुद्ध के बाद पश्चिम के प्रति शकानु होकर उसने अत्यन्त उग्र हुई विदेश-नीति अपनाई। स्टालिन ने शीतयुद्ध को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। पामर एवं पॉकट के शब्दों में, "युद्धोत्तर सोवियत नीति कम से कम 8 वर्षों अर्थात् 1953 तक पश्चिम के प्रति शत्रुता, असहयोग और अलगाव की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तिपू, सोवियत प्रभाव-क्षेत्र के हटोकरणा तथा सामान्य हृद्यमिता की विशेषताओं से युक्त रही थी।"¹ जिन प्रमुख कारणों से स्टालिन ने उपवादी नीति अपनाई, वे ये थे—

1. महायुद्ध-काल में ही पश्चिमी राष्ट्रों ने सोवियत साम्यवाद के विरुद्ध विपला प्रचार शुरू कर दिया था।

2. पश्चिमी देशों ने रुस को सैनिक सहायता बहुत कम दी। स्टालिन के मन में यह बात बैठ गई कि पश्चिमी राष्ट्र वास्तव में यह चाहते थे कि रुस जर्मनी के साथ संधि में बिलकुल कमजोर हो जाए।

3. अमेरिका ने अणु-बम के आविष्कार को सोवियत रुस से गुप्त रखा और स्टालिन ने इसे विश्वासपात माना।

4. युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सोवियत-संघ को 'लैंड-लीज एक्ट' के अन्तर्गत दी जानेवाली आर्थिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी।

5. युद्ध के बाद अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी राष्ट्रों ने जो नीति अपनाई उससे चहूँ प्रतीत हुआ कि वे सोवियत रुस के विरुद्ध पद्धत रच रहे हैं।

6. युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ की स्थिति सामरिक और अन्य दृष्टियों से बहुत अच्छी थी। रुसी सेनाएँ मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर अधिकार जमाए बैठी थी। पश्चिमी यूरोप आर्थिक सकट में था और साम्यवाद के प्रसार के लिए वहाँ अच्छी सम्भावनाएँ थी। एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध असन्तोष का सागर उमड़ रहा था। अतः स्टालिन ने सोचा कि चारों ओर स्थितियाँ ऐसी हैं कि साम्यवाद अपने पैर जमा सकता है। यदि पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई तो रुस लूट-खसोट और जोर-जबरदस्ती द्वारा राजनीतिक और प्रादेशिक लाभ उठाने से पश्चित रह जाएगा।

इन अनुकूल परिस्थितियों में स्टालिन ने यही उपयुक्त समझा कि पश्चिम पर आरोप लगाए जाएँ, पुरानी बातों को भुंदा जाए, शीतयुद्ध को तीव्र कर पश्चिम के प्रस्तावों के प्रति अडिगपेशाबी की नीति में अचिन्ताधिक लाभ उठाया जाए। 6 नवम्बर, 1947 को तत्कालीन रुसी विदेशमन्त्री मोलोटोव ने कहा—“हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें सब सड़कें साम्यवाद की ओर जाने वाली हैं।”

स्टालिनकालीन विदेश-नीति के मुख्य तत्त्व या विशेषताएँ

स्टालिन युग में सोवियत विदेश-नीति के निम्नलिखित तत्त्व थे—

1. पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव का विस्तार किया जाए।

2. विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार किया जाए।

3. पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति विरोधी रुख अपना कर शीतयुद्ध को तीव्र बनाकर अधिकाधिक राजनीतिक लाभ नठाया जाए।

4. लीह-आदरस की नीति को अपनाकर ऐसी व्यवस्था की जाए कि साम्यवादी जगत् में पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार प्रवेश न कर सके।

5. एशिया, अफ्रीका आदि में उपनिवेशवाद का विरोध किया जाए और शान्तिवादी आन्दोलन छेड़ दिया जाए।

6. संयुक्त राष्ट्रसंघ को शीतयुद्ध का मंच बना दिया जाए, तथा वहाँ बाधा उपस्थित कर राजनीतिक हितों की रक्षा की जाए। गुरक्षा-परिपद में वीटो के प्रयोग से पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्तावों को निरस्त किया जाए।

सोवियत विदेश-नीति के इन तत्त्वों से ऐसा प्रतीत होता है मानो स्टालिन ने ही अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को गन्दा बनाया और पश्चिमी देशों के न्यायपूर्ण रुख को ठुकराया, पर वास्तव में बात ऐसी नहीं थी। स्टालिन के सामने रूसी हित तो सर्वोपरि थे ही, पश्चिमी देशों का रुख भी इस प्रकार का रहा कि स्टालिन को उन पर विश्वास नहीं हुआ। स्टालिन की जगह यदि किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होता तो वह भी तत्कालीन परिस्थितियों में पश्चिमी देशों के साथ सहयोग न कर पाता। विजय के नशे में फूले हुए अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों ने निरन्तर सोवियत रुम को दबाए रखने की नीति अपनाई तथा साम्यवाद के विनाश की चाले खेली। बाध्य होकर सोवियत संघ ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। स्टालिन अपने शासनकाल में सदैव बठोर और निर्मम रहा था, अतः उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह पश्चिमी देशों के प्रति उदार होगा।

1. पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार—द्वितीय महायुद्ध ने रूस को पूर्वी यूरोप में अपनी प्रभुता के विस्तार के स्वप्न की पूर्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। महायुद्धकाल में पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों को लाल सेना ने जर्मन दासता से मुक्ति दिलाई थी और इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने जर्मनी के विरुद्ध छापामार संघर्षों का नेतृत्व किया था। युद्धोपरान्त इन देशों में राजनीतिक सत्ता भी साम्यवादियों के हाथ में आई और सोवियत रूस के लिए इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व-विस्तार का मार्ग सरल हो गया। युद्ध के उपरान्त सन् 1948 तक की तीन वर्ष की अत्यावधि में ही यूरोप के सात देश पूरी तरह 'लाल' बन गए। फरवरी, 1945 के याल्टा सम्मेलन में रुजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने 'मुक्त यूरोप सम्बन्धी घोषणा' (Declaration of the Liberated Europe) पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्टालिन ने याल्टा भावना को कठोरतापूर्वक कुचल डाला और पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व का विस्तार कर लिया। वह फिनलैंड को भी आधीन करने से नहीं चूका।

सन् 1947 में उसने फिनलैण्ड के साथ शान्ति-सन्धि की और अप्रैल 1948 में मैत्री सन्धि। इन सन्धियों द्वारा स्टालिन ने फिनलैण्ड की स्वतन्त्रता तो स्वीकार की, लेकिन फिनलैण्ड से यह वचन ले लिया कि वह रुम विरोधी विदेश-नीति नहीं अपनाएगा। स्टालिन ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना कर सोवियत राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में सफलता प्राप्त की। इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्धों के विकास के लिए समझौते किए गए। सन् 1947 की 'मोलोटोव योजना' में इन देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए औद्योगीकरण पर बल दिया गया। जनवादी गणतन्त्रों की स्थापना अथवा दूसरे शब्दों में साम्यवादी शासन-भत्ता की स्थापना के फलस्वरूप इन देशों का पश्चिम के साथ व्यापार भी पुनर्विस्तार नगण्य रह गया।

6 मार्च, 1941 को रूस और पोलैण्ड के बीच तथा 12 जुलाई, 1947 को चेकोस्लोवाकिया के साथ व्यापारिक सन्धि सम्पन्न हुई। चेकोस्लोवाकिया के साथ ही सन् 1948 में एक अन्य समझौता हुआ जिसमें रूस ने उसे ऋण के रूप में एक बड़ी राशि देना स्वीकार किया। सन् 1948 में हंगरी के साथ भी दो व्यापारिक सन्धियाँ की गईं। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच आर्थिक सहयोग को अधिकधिक घनिष्ठ बनाने के लिए सन् 1949 में 'पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद्' (Council for Economic Mutual Assistance : Com. Con.) की स्थापना की गई। इस 'कोम कोन' को पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम' (European Recovery Programme : E.R.P.) का प्रत्युत्तर कहा जा सकता है।

राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव स्थापित होने का आघात तो पश्चिमी शक्तियों को लगा ही था, आर्थिक क्षेत्र में भी रूस के व्यापक प्रभुत्व से पश्चिमी देशों और रूस के तनावों में वृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप परम्परा से पश्चिमी देशों को साठान एव वच्चे माल का निर्यात करता था। पश्चिम के कुछ देश तो अपनी प्रत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के लिए पूर्वी यूरोप पर आश्रित थे। सोवियत नीति का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि पश्चिमी देशों में सोवियत संघ और पूर्वी-यूरोप के साम्यवादी शासन-तन्त्रों के प्रति पूर्ण कटुता उत्पन्न हो गई। स्टालिन की नीति ने शीतयुद्ध को तेज कर दिया।

सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मैत्री और पारस्परिक सहायता की अनेक सैनिक सन्धियाँ भी हुईं। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा यूगोस्लाविया के साथ तो सैनिक सन्धियाँ युद्धकाल में ही की जा चुकी थी। इसके बाद 18 मार्च, 1946 से 16 अप्रैल, 1949 तक 17 द्विपक्षीय सन्धियाँ (Bilateral Treaties) की गईं। इन सन्धियों को सम्भावितः जर्मन आक्रमणों को रोकने के लिए किया गया। बाद में 14 मई 1955 को इन देशों ने वारसा पॅक्ट पर हस्ताक्षर कर सोवियत संघ के साथ स्वयं को और भी घनिष्ठ मैत्री में आवद्ध कर लिया।

2 विश्व में साम्यवादी शान्ति का प्रसार—द्वितीय महायुद्ध के बाद मास्को

ने साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार की नीति का अनुसरण आरम्भ कर दिया। साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ द्वारा सभी प्रकार के उपायों का सहारा लिया गया। यूनान के गृहयुद्ध में यूनानी साम्यवादियों को पड़ोसी साम्यवादी देशों—प्रतुवानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया द्वारा सहायता पहुँचायी गई। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) के विश्वव्यापी क्रान्ति के कार्यों को प्रतिरुद्ध करने के लिए सन् 1947 में वारसा में एकत्रित यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, रूमानिया, हंगरी, पोलैण्ड, रूस, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और इटली की साम्यवादी पार्टियों के नेताओं ने 'वेलग्रेड में साम्यवादी सूचना संस्थान' या कोमिनफोर्म (Communist Information Bureau: Cominform) की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि "संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा विध्वना युद्ध विश्व मण्डलों में प्रतियोगिता की समाप्ति के लिए लड़ा गया था, किन्तु रूस ने यह युद्ध यूरोप में लोकतन्त्र के पुनर्निर्माण और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए लड़ा था।" कोमिनफोर्म का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद रूस ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे पूर्व और पश्चिम में रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक राज्यों की सरकारें स्थापित हो, पुराने बुर्जुआ साम्राज्यों का विनाश हो और इस साम्यवादी विचारधारा के आधार पर नवीन सोवियत साम्राज्य का निर्माण हो। अपने इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टालिन ने युद्धोत्तर विश्व समस्याओं के समाधान में शीघ्रता नहीं की। वह मङ्गोलिया द्वारा शान्ति-व्यवस्था में विनम्र करना चाहता था ताकि संसार की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल बन जाय।

3. टर्की, ईरान, यूनान और यूगोस्लाविया पर सोवियत दबाव—स्टालिन काल में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्बन्धों में जहाँ हर प्रकार से सफलता का पलड़ा रूस के पक्ष में भारी रहा, वहाँ रूस को टर्की, ईरान, यूनान और यूगोस्लाविया के सम्बन्ध में निश्चित असफलताओं का सामना करना पड़ा। सोवियत दबाव की नीति अन्ततोगत्वा सफल न हो सकी।

(क) टर्की—पूर्वी यूरोप के देशों को अनुगामी बनाकर रूस पश्चिम से होने वाले सम्भावित आक्रमणों के प्रति तों सुरक्षित हो गया, लेकिन रूस के विरुद्ध युद्ध करने का दूसरा पुराना मार्ग अभी खुला था और वह मार्गपूर्वी भूमध्यसागर तथा फारस की खाड़ी के निकटवर्ती देशों—यूनान, टर्की और ईरान से होकर था। दक्षिण से होने वाले आक्रमण के विरुद्ध सोवियत सुरक्षा की मुख्य समस्या बोसफोरस और डार्डनेलीज जलडमरूमध्य पर नियन्त्रण की थी। सोवियत नेताओं ने द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ होते ही इस समस्या पर विचार किया और समय के साथ अपनी योजना को व्यावहारिक रूप देना शुरू कर दिया। युद्ध-काल में रूस ने जलडमरूमध्य की संयुक्त सुरक्षा के लिए टर्की से सैनिक भेजने की अनुमति चाही, लेकिन ब्रिटेन

और फ्रांस को अपनी पीठ पर देल कर टर्की ने सोवियत मांग ठुकरा दी। अग्रेषित फरवरी 1945 में टर्की ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर मित्रराष्ट्रों का साथ दिया, लेकिन 'देरी से अग्रगण्य' गये इन रण के कारण यह सोवियत दबाव से मुक्त नहीं रह सका। इसी समाचार-पत्रों ने टर्की के विरुद्ध अपना अभिमान छोड़ा लेकिन टर्की दबाव में नहीं आया—क्योंकि एक तो ब्रिटेन और फ्रांस का उसे समर्थन प्राप्त था और दूसरे टर्की में साम्यवादी दल के रूप में 'पंचमार्गी' मौजूद नहीं थे जो रूस के पक्ष में टर्की सरकार पर दबाव डालते। युद्ध के उपरान्त जब 'शीत-युद्ध' प्रारम्भ हुआ तो परिपक्वी राष्ट्रों ने इच्छा से टर्की का समर्थन किया। अक्टूबर 1946 में सोवियत-टर्की समझौता-वार्ता नग्न हो गई, पर टर्की इसी दबाव को सहन कर गया।

(ख) ईरान—यहाँ भी सोवियत नीति असफल रही। सन् 1941 में रूस और ब्रिटेन की संयुक्त सेना ने ईरान पर अधिकार कर लिया था। युद्ध-काल में रूस ने अपने अधिकृत प्रदेश में एक गुप्त साम्यवादी दल 'तुदेह दल' को प्रोत्साहित किया जिसने ईरानी अजरबैजान को जो इसी अजरबैजान के निकट था, वृषककरण के लिए आन्दोलन किया। युद्धोपरान्त सन् 1946 के प्रारम्भ में अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने ईरान छोटी कर दिया, लेकिन सोवियत सेना डटी रही। मामला सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत हुआ लेकिन प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा 24 मार्च, 1946 को एक समझौता हुआ जिसमें रूस ने उत्तरी ईरान में तेल सम्बन्धी सुविधा प्राप्त कर अपने सैनिकों को ईरान से हटाना स्वीकार कर लिया। सोवियत सेना के लौट आने के बाद ईरानी सैनिकों ने अजरबैजान-प्रदेश में प्रवेश किया और वृषकलावादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद ही ईरान की ससद् ने सोवियत रूस को दो गई तेल-सम्बन्धी सुविधा को स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया। रूस ने ईरान के विरुद्ध प्रचार-अभिधान छोड़ा और ईरान में इसी हस्तक्षेप का खतरा पैदा हो गया; लेकिन अमेरिका ने, जो 'ट्रूमैन सिद्धान्त' के अनुसार पहले से ही यूनान और टर्की को सैनिक तथा आर्थिक सहायता दे रहा था, ईरान को 2 करोड़ 50 लाख डॉलर की सैनिक सहायता और ईरानी सेना को सशस्त्र करने के लिए सैनिक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का वचन दिया जिसके फलस्वरूप ईरान में रूस हस्तक्षेप का संकट टल गया।

(ग) यूनान—यहाँ भी साम्यवादी शासन की स्थापना के इसी प्रयत्न असफल रहे। सन् 1944 में बर्लिन और स्टालिन ने मास्को में यह स्वीकार किया था कि यूनान ब्रिटिश प्रभाव-क्षेत्र में रहेगा, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र-राष्ट्रों का सहयोग बिखर गया। सम्भवतः इसी स्वीकृति से भई, 1946 में साम्यवादियों ने पूरी शक्ति से शूट-युद्ध छेड़ दिया और ब्रिटिश सरकार ने, जो यूनान-सरकार को निरन्तर सहायता दे रही थी, अमेरिका को सूचित किया कि वह यूनान को और अधिक सहायता देने में असमर्थ है और अमेरिका ने 'ट्रूमैन सिद्धान्त' के अन्तर्गत यूनान को सहायता देने का निश्चय किया। पर सहायता से पूर्व ही अमेरिका का एक सैनिक प्रतिनिधि मण्डल यूनान पहुँच गया ताकि यूनानी सेना की

सहायता की जा सके। "साम्यवादियों ने एथेंस की सरकार को अमेरिकी साम्राज्य की कठपुतली कहकर निन्दा की और जनरल मार्को वेफ़ीकेड के नेतृत्व में अस्थायी मुक्त यूनान सरकार ने शक्ति अर्जित करली, लेकिन धीरे-धीरे एथेंस सरकार ने अमेरिकी सरकार की सहायता से अपनी सेना को सुसंगठित कर लिया और अक्टूबर, 1949 में साम्यवादी आन्दोलन समाप्त हो गया।"

(घ) यूगोस्लाविया—सबसे अधिक घातक असफलता रूस को यूगोस्लाविया के मामले में प्राप्त हुई, क्योंकि कुछ समय तक रूसी गुट में बने रहने के बाद यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो ने रूस के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और जून, 1948 में यूगोस्लाविया रूसी गुट से पृथक् हो गया। स्टालिन ने मार्शल टीटो पर हर प्रकार से दबाव डालने की कोशिश की, किन्तु वह टीटो को अपने नियंत्रण में नहीं ला सका। टीटो को यह बिल्कुल पसन्द नहीं था कि यूगोस्लाविया स्थित लाल सेना यूगोस्लाविया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, अतः उसने सोवियत नागरिक और सैनिक भ्रष्टाचारों पर कड़ी निगरानी रखते हुए स्टालिन से स्पष्ट शब्दों में माँग की कि रूसी फौजें यूगोस्लाविया क्षेत्र से हटा ली जाएँ।

स्टालिन और टीटो के मतभेद बढ़ते गए। फलस्वरूप 28 जून, 1948 को कोमिनफोर्म (Communist Information Bureau : Cominform) ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी पर यह आरोप लगाकर उसे अपनी सदस्यता से वंचित कर दिया कि उसकी नीतियाँ मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं। प्रस्ताव में कुछ और भी आरोप लगाए गए। 29 जून को यूगोस्लाव नेताओं ने कोमिनफोर्म द्वारा लगाए गए आरोपों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के बीच शीतयुद्ध की स्थिति पैदा हो गई जो स्टालिन की मृत्युपर्यन्त (मार्च, 1953) चालू रही। वास्तव में स्टालिन ने टीटो को अपने समकक्ष मानने से इन्कार कर दिया और उसके प्रति पूर्ण विरोध की नीति अपनाई।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के 'भाईचारे' के विरुद्ध किए गए टीटो के इस विद्रोह का पश्चिमी देशों ने स्वभावतः नुक्त कंठ से स्वागत किया। इस विद्रोह को 'सोवियत साम्राज्यवाद के विरुद्ध पूर्वी यूरोप के विद्रोह का सूचक' समझा गया। जुलाई, 1948 में संयुक्तराज्य अमेरिका ने यूगोस्लाविया की 6 करोड़ डॉलर की सम्पत्ति उसे लौटा दी। यूगोस्लाविया ने भी अमेरिका को 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का भुगतान दिया। अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी इसी तरह के सद्भावनापूर्ण और लेनदेन की भावना के समझौते किए गए। मार्शल टीटो ने सोवियत रूस से क्षुब्ध होकर पूर्वी यूरोप के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अपेक्षा पश्चिमी देशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया, किन्तु यह सदैव ध्यान रखा कि उनका राष्ट्र पूर्णतः सोवियत या पश्चिमी प्रभाव से मुक्त एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहे।

4. पश्चिम का विरोध और शीतयुद्ध की उपरता—सोवियत रूस द्वारा पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना के प्रयत्नों और पश्चिमी शक्तियों

द्वारा रूसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेष्टाओं के कारण सोवियत संघ और पश्चिम की 'विचित्र मैत्री' का अन्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्षों के अन्दर ही दोनों युद्धों में उग्र शीतयुद्ध प्रारम्भ हो गया। पराजित राज्यों के साथ सन्धिओं की शर्तों, इटली के उपनिवेशों तथा राष्ट्रसंघ के भेड़ेंटे वाले प्रदेशों का विभाजन, जर्मनी का निःशस्त्रीकरण और एकीकरण, पश्चिमी देशों तथा रूस के लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों में मौलिक अन्तर, क्षतिपूर्ति, मध्यपूर्व में प्रभुत्व के लिए तीव्र प्रतियोगिता आदि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में शीतयुद्ध की तीव्रता बढ़ी। पश्चिमी राष्ट्र कोमिनफ़ोरम की गतिविधियों और स्टालिन की हठधर्मी से आशंकित हो गए। उर्वर सोवियत संघ का यह विश्वास दृढ़ होता गया कि पश्चिमी राष्ट्र उसके उन्मूलन का पडयन्त्र रच रहे हैं। रूस की दृष्टि में ट्रूमैन-सिद्धान्त, मार्शल योजना, बर्लिन के घेरे के समय की गई हवाई सहायता, जापान व जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण, शूमेन एव प्लेबन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि कार्य अनुतापूर्ण थे।

स्टालिन ने अपनी नीति को शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व का जामा पहनाया, परन्तु उसकी कार्यवाहियों से यह स्पष्ट हो गया कि 'शान्तिपूर्ण सहप्रस्तित्व' की नीति से उसका अभिप्राय केवल इतना था कि दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध नहीं होना चाहिए। एक प्रचारात्मक वाग्युद्ध और कोरिया जैसे स्थानीय युद्धों को वह इन नीतियों के विरुद्ध नहीं समझता था। स्टालिन की इस नीति का एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों में तनाव बढ़ता चला गया।

5. लोह आवरण की नीति—महायुद्ध के उपरान्त स्टालिन ने 'लोह आवरण' (Iron Curtain) की नीति अपनायी ताकि साम्यवादी जगत् को सभी प्रकार के वास्तविक प्रभावों से मुक्त रखा जा सके। अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्रराष्ट्रों ने साम्यवादी देशों के आसपास अज्ञात रेडियो स्टेशन स्थापित करके साम्यवाद के विरुद्ध जहरीला प्रचार शुरू कर दिया। इन रेडियो स्टेशनों के नाम 'फ़्रीज्ड हंगरी रेडियो', 'फ़्रीज्ड पोलैण्ड रेडियो' आदि रहे गए। स्टालिन समझ गया कि पश्चिमी देश साम्यवादी व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहते हैं, अतः उसने पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों और रूस के चारों ओर कठोर प्रतिबन्धों की ऐसी व्यवस्था की कि उनके भीतर अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार न पहुँच सके। स्टालिन ने निर्णय कर लिया कि वह रूस एवं पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत् को गैर-साम्यवादी देशों के सम्पर्क से वृथक् रखेगा। सन् 1945 से ही ऐसे कानून बनाए जाने लगे जिनसे बाह्य जगत् के साथ रूसियों का सम्पर्क रुक जाए। एक कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि युद्ध के समय रूस में आए हुए विदेशी सैनिकों के साथ जिन रूसी स्त्रियों ने विवाह किया था वे अपने पतियों के साथ विदेश नहीं जा सकेंगी। एक अन्य कानून द्वारा विदेशियों के साथ सोवियत नागरिकों के विवाहों को निषिद्ध ठहरा दिया गया। विदेशी राजदूतों तथा पत्र-प्रतिनिधियों के साथ भी बहुत कठोरता का व्यवहार किया गया। विदेशों में स्थित सोवियत राजदूतों

पर कठोर अनुशासनात्मक प्रतिबन्ध लगाए गए तथा इसी प्रेस पर भी कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया ।

6. अफ्रीका तथा एशिया के प्रति सोवियत नीति एवं शान्ति आन्दोलन— अफ्रीका एवं एशिया के प्रति स्टालिन की नीति विवेकपूर्ण किन्तु अनुदार थी । उसने मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव में वृद्धि करने की चेष्टा की और दक्षिणी कोरिया को साम्यवादी बनाने के लिए कोरिया युद्ध की प्रेरणा दी । यद्यपि स्टालिन कम साम्राज्यवादी नहीं था, तथापि उसने एशिया और अफ्रीका में पराधीन राष्ट्रों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का समर्थन किया और साम्राज्यवाद की निन्दा की । पश्चिमी राष्ट्रों का दृष्टिकोण यह रहा कि एशिया और अफ्रीका की जनता को यह महसूस हुआ कि ये राष्ट्र अत्यन्त रूप से उपनिवेशवाद का समर्थन कर रहे हैं ।

साम्राज्यवाद विरोधी नीति के साथ ही सोवियत सघ ने 'शान्ति-आन्दोलन' (Peace Offensive) आरम्भ किया और पश्चिम को युद्ध-लोकपुत्र (War Monger) कह कर बदनाम करने की चेष्टा की । स्टालिन का 'शान्ति आन्दोलन' एक चातुर्य-पूर्ण और सफल चाल सिद्ध हुई । सोवियत सघ की प्रेरणा पर सन् 1950 में स्टॉट्टोम में विश्व-शान्ति सम्मेलन की बैठक हुई जिसमें आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाने की अपील की गई । अपील में कहा गया—

"हम इस बात की माँग करते हैं कि मानव-जाति के सामूहिक उन्मूलन और प्रातक के अस्त्र के रूप में आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । हम वह माँग करते हैं कि इस पर कठोर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित किया जाए । हम उस सरकार को युद्ध-प्रपराधी समझेंगे जो किसी देश के विरुद्ध इस अस्त्र का प्रयोग करने में पहल करेगी ।"

प्रचार की दृष्टि से यह आन्दोलन बहुत सफल और लोकप्रिय सिद्ध हुआ । अपील पर कुछ समय में ही लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए । शान्ति आन्दोलन ने एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या को बहुत प्रभावित किया । वे साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए तथा सोवियत रूस को पश्चिम की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और उपनिवेशवाद-विरोधी मानने लगे ।

7. संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति सोवियत नीति— स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत सघ ने संयुक्त-राष्ट्रसंघ के निर्माण में सक्रिय भाग लिया । संयुक्त-राष्ट्रसंघ इसी विश्वास पर आधारित था (और है) कि महाशक्तियाँ, विशेषतः सोवियत सघ और संयुक्तराज्य अमेरिका सहयोगपूर्वक कार्य करते हुए, मघ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक बनेंगी; परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा पूरी न हो सकी । अपने जन्म के कुछ ही समय उपरान्त संघ शीतयुद्ध का प्रधान अखाड़ा बन गया । लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर सघ के मंच पर उपस्थित हुए । सघ में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का रुष्ट बहुमत था और सोवियत रूस ने स्वयं को एक स्थायी एवं निरन्तर अल्पमत में पाया । ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निरुण्यों को रोकने के लिए उसके पास इसके प्रतिरिक्त

बोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद् में अपने निषेधाधिकार का दृढता से प्रयोग करे। कोरिया युद्ध के समय अन्तराल के लिए रुस ने समुक्त राष्ट्रसंघ की बैठकों का बहिष्कार कर दिया लेकिन वह बहिष्कार उसके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हुआ, क्योंकि इस बहिष्कार के कारण ही समुक्त राष्ट्रीय सेनाएँ दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेजी जा सकी। इस घटना से रुस ने समझ लिया कि समुक्त राष्ट्रसंघ से बाहर रहकर प्रयत्न करने की अपेक्षा वह समुक्त-राष्ट्रसंघ की कार्यवाहियों में भाग लेकर तथा परिषद् की बैठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रों के दुरादों को अधिक अच्छी तरह विफल कर सकता है। इस अनुभूति के बाद फिर कभी रुस ने ने संघ की बैठकों का बहिष्कार नहीं किया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद् में अपने निषेधाधिकार के प्रयोग से पश्चिम के अनेक अग्राय-पूर्ण प्रस्तावों को, जिनमें कश्मीर-प्रस्ताव भी शामिल है, धरास्तायी किया।

स्टालिन की विदेश-नीति का मूल्यांकन

यद्यपि स्टालिन ने पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभुत्व की स्थापना द्वारा रुसी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर लिया, परन्तु उसकी हठधर्मी की नीति सोवियत संघ के लिए कुल मिलाकर अलाभकारी हो सिद्ध हुई। स्टालिन की आक्रामक नीति से पश्चिमी शक्तियाँ सशक्त हो गईं और उन्होंने बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को रोकने तथा साम्यवाद के प्रसार को प्रतिरुद्ध करने के लिए अनेक उपाय किए। टूटू पैन् सिद्धान्त, मागेल योजना, डकक, ब्रुसेल्स सन्धियाँ, नाटो पैक्ट, पश्चिमी यूरोप की एकता के लिए निर्मित विभिन्न संगठन आदि स्टालिन की कठोर नीति का करारा जवाब था। सन् 1945-47 तक यूरोप की स्थिति स्टालिन के लिए अत्यन्त अनुकूल थी, लेकिन सन् 1953 तक यह स्थिति बदल गई। सन् 1949 में चीन में साम्यवादी विजय तथा सन् 1950 में कोरिया-युद्ध के प्रारम्भ ने पश्चिमी शक्तियों को कोरिया, जापान, फारमोसा और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए चिन्तित कर दिया। मध्यपूर्व में टर्की और यूनान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत रुस को वैसे ही बदनामी हाथ लगी जैसी बाद में आइजनाहॉवर-सिद्धान्त के प्रयोग से अमेरिका को। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। अपनी हठधर्मी के कारण वह इन राष्ट्रों की दोनों शक्ति गुटों के प्रभाव से बचने की इच्छा और नीति को नहीं समझ सका। वह उन्हें साम्यवाद का शत्रु मानने लगा। इससे उसने एक बड़ी सीमा तक इन राष्ट्रों का समर्थन हो दिया। तटस्थ देशों के प्रति स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया। उदाहरणार्थ भारत को उनकी तटस्थता के कारण ही स्टालिन रुस-विरोधी समझता रहा था। इसीलिए स्टालिन-काल के रुसी विश्वकोष में भारत के स्वाधीनता संग्राम को और महात्मा गांधी को पूँजीवाद का समर्थक बताया गया था।

स्टालिन की उपवादी कठोर नीति ने स्वयं साम्यवादी गुट में भी काफी शोक उत्पन्न कर दिया। जब यूगोस्लाविया में मार्शल टोटो ने सोवियत संघ का

अन्धीनुकरण करने में इंकार कर दिया तो स्टालिन के शिकंजे से निकलने के लिए अन्य साम्यवादी देशों में भी राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को अधिक समर्थन मिलने लगा। इसकी अभिव्यक्ति बाद में सन् 1956-57 में पोलैंड तथा हंगरी के उपद्रवों में हुई। स्टालिन की 'लोह आवरण' की नीति से अन्य देशों में रुस के प्रति सन्देह और अविश्वास की धारणाओं को बल मिला। जार्ज एफ. केनन (George F. Kennen) का मत है कि सन् 1952 तक सोवियत नीति 'अनुर्वर' हो गई थी और सन् 1953 में स्टालिन के उत्तराधिकारियों के लिए उसमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया।

कुछ लोग स्टालिन की विदेश-नीति में रूढ़िवाद (Conservatism) की भूलक पाते हैं। उनके मतानुसार वह पश्चिम पर शक्ति के बल पर हावी नहीं होना चाहता था, बल्कि उसने पश्चिमी शक्ति एवं सम्पत्ति को गिराने तथा अपने साम्राज्य को शक्ति एवं स्थायित्व देने के प्रयास किए। अधिराज्यों में व्याप्त असन्तोष के प्रति वह सजग था, तो भी उसने सोवियत शक्ति के विस्तार के प्रत्येक अवसर का लान उठाया। सन् 1953 का वर्ष पश्चिमी विचारकों द्वारा भीभाष्यशाली माना जाता है जब स्टालिन इस संसार से विदा हो गया। कहा जाता है कि स्टालिन ने रुस जैसे पिछड़े व अविकसित देश को दुनिया की महान् औद्योगिक एवं सैनिक शक्ति बना दिया तथा चंगेजखाँ और तैमूरलंग जैसा साम्राज्य स्थापित कर दिया।

शान्तिपूर्ण प्रतिगोचिता का स्टालिनोत्तर युग : मोर्तेंकोव काल (1953-54)

स्टालिन की मृत्यु से पूर्व ही सोवियत विदेश-नीति में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किन्तु बाद में उसकी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह फिर से विकासोन्मुखी बनी। स्टालिन के बाद तीन मुख्य बातों ने सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि की। पहला विकास यह था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य में स्थायित्व आ गया। दूसरे, सोवियत संघ की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति तेजी के साथ बढ़ने लगी। तीसरे रुस के दक्षिणी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लगा, मध्य-पूर्व, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश उसके प्रभाव क्षेत्र बन गए। विश्व का सन्तुलन एक प्रकार में साम्यवाद की ओर झुक गया। स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य में वृद्धि नहीं हुई सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी उत्तम हो गई जितनी पहले कभी नहीं थी। स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन चुनौतियों का सामना करना था, वे थी—सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप में सोवियत शासन के स्थायित्व पर पश्चात्प स्वीकृति प्राप्त करना तथा जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक सोवियत सुरक्षा को खतरे में न डालते हुए देश की शक्ति का विस्तार करना। साम्राज्य की रक्षा करना उसे प्राप्त करने से अधिक कठिन होता है, इसीलिए उन्होंने अधिराज्यों को स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की, आर्थिक सम्बन्धों को कम शोषणयुक्त बनाया तथा जीवन स्तर के आधुनिक विकास को प्रोत्साहन दिया। स्टालिन के बाद सोवियत रुस को बर्लिन-समस्या का सामना करना पड़ा, साम्यवादी चीन के साथ इसका सैद्धान्तिक विवाद बढ़ा, मार्शल टीटो

के साथ मतभेदों में उतार-चढ़ाव आया, पोलैण्ड और हंगरी में क्रान्तिप्राप्त हुई तथा एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों में क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं संचय हुए और इन सबके कारण सोवियत संघ की विदेश नीति की गति काफी तेज हो गई।

स्टालिन की उग्रतावादी कठोर विदेश-नीति के जो परिणाम निकले और पाश्चात्य देशों एवं तटस्थ देशों में उसकी जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, उनके फलस्वरूप अब सोवियत नीति का एक नवीन दिशा में उन्मुख होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य था। इसलिए स्टालिन के गविलम्ब उत्तराधिकारी मोर्लैकोव ने दिवंगत नेता के अन्त्येष्टि-संस्कार में ही घोषणा की कि—“लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूँजीपति देशों में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व स्थापित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा।” मोर्लैकोव का यह आश्वासन इस बात का संकेत था कि स्टालिन के उत्तराधिकारी पश्चिमी एवं गैर-साम्यवादी देशों के प्रति उग्रता और कठोरता में कमी लाना चाहते थे। इसके तुरन्त बाद ही 15 मार्च, 1953 को सुपीम सोवियत में सोवियत प्रधानमंत्री ने कहा—“अब सोवियत विदेश-नीति का संचालन व्यापार की वृद्धि और शान्ति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किया जाएगा। कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे शान्तिपूर्वक हल न किया जा सकता हो। यह सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।” सोवियत रुम की नीति में परिवर्तन का संकेत देने वाली इन विभिन्न घोषणाओं के कारण अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में रुस के विरुद्ध प्रचार में कमी आई। इसी के परिणामस्वरूप अब तक पश्चिम के विरुद्ध घाग बरसाने वाले रूसी विदेश मंत्री विशिस्की ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा की बैठक में भाषण देते हुए पश्चिम को निमन्त्रण दिया कि “आप मित्रता की सुरंग में आये रास्ते तक आये बढ़कर हमसे मिलें।” इसके साथ ही पश्चिमी देशों के विरुद्ध रुम द्वारा किए जाने वाले विरोधी प्रचार की उग्रता में भी कमी आ गई।

रुम की नई विदेश नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही प्राप्त होने प्रारम्भ हो गए। अक्टूबर 1952 से चालू कोरियाई युद्ध का गतिरोध खत्म हो गया और 10 अप्रैल 1953 को पानमुनजोन में रुम एवं घायल युद्धबन्धियों के बारे में समझौता होने पर युद्ध भी समाप्त हो गया। रुस द्वारा टर्की और जर्मनी के प्रति उदार नीति अपनाई गई। 15 मई 1955 को आस्ट्रिया के सम्बन्ध में शान्ति-सन्धि हो गई। फिनलैण्ड के वैमिक घुड़े सोवियत सैनिकों द्वारा खाली कर दिए गए, सोवियत सेना में 1 लाख 80 हजार सैनिकों की कमी की गई। सन् 1954 में जेनेवा-सम्मेलन द्वारा हिन्डूबोन की समस्या, नए शान्तिपूर्ण हल स्थापना तथा सोवियत संघ ने यूनायटेड नेशन्स के साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किए। यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर कर उसे पुनः साम्यवादी परिवार में लाने की चेष्टा की गई। 29 अप्रैल 1953 को मोर्लैकोव ने यूगोस्लाव प्रतिनिधि से कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत की प्रारंभ 1953 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः कायम हो गए, इसके उपरान्त सोवियत

नेताओं ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी के साथ भी अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को दूर करने के प्रयत्न किए।

मोर्लैकोव के नेतृत्व में सोवियत रूस की लीह-आवरण की नीति में भी शिथिलता आई। बाह्य दुनिया से सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि सोवियत संघ लोहे की दीवार में बन्द न समझा जाए। स्टालिन विश्व को दो विरोधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसकी शक्ति-सन्तुलन की प्रक्रिया माना गया और अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ-राष्ट्रों की सद्भावना प्राप्त करने की चेष्टा की गई।

छ श्चेव-काल (1955-64)

इस समय सोवियत संघ में अन्दर ही अन्दर नेतृत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। मोर्लैकोव इस संघर्ष में पराजित हुए और 8 फरवरी, 1955 को उन्हें प्रधान-मन्त्री पद त्यागना पड़ा। अब मार्शल बुल्गानिन नए सोवियत प्रधानमन्त्री बने तथा छ श्चेव पार्टी के महासचिव नियुक्त हुए।

सन् 1955 से 1963 तक की सोवियत विदेश नीति का युग छ श्चेव युग कहलाता है क्योंकि फरवरी, 1955 से मार्च, 1958 तक के बुल्गानिन के प्रधान-मन्त्रित्व काल में भी वास्तविक प्रभाव एक प्रकार से छ श्चेव का ही था। इस युग में सोवियत विदेश-नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

छ श्चेवकालीन विदेश-नीति की मुख्य प्रवृत्तियाँ

(1) लीह आवरण की नीति उत्तरोत्तर शिथिल होती गई तथा 'यात्रा-कूटनीति' का महत्व बढ़ता गया।

(2) पश्चिम के प्रति उग्र नीति का शनैः-शनैः परित्याग किया जाने लगा। सोवियत नेता शान्तिपूर्ण सह-मस्तित्व की ओर अग्रसर हुए। विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा पर शीतयुद्ध का परित्याग नहीं किया गया। अनुकूल परिस्थितियों में शीतयुद्ध को उभार कर राजनीतिक और प्रचारात्मक लाभों को प्राप्त करने के प्रयत्न चलते रहे।

(3) अल्पविकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई गई। इसमें उत्तरोत्तर विकास होता चला गया।

(4) सोवियत प्रभाव-विस्तार की उरकठा रखते हुए भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को तीव्र कर दिया गया। सोवियत नीति यह रही कि एशिया और अफ्रीका की जनता की अधिकाधिक सहानुभूति प्राप्त कर इन महाद्वीपों में साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। सोवियत शक्ति और प्रभाव-विस्तार के मुख्य आकर्षण केन्द्र तीन क्षेत्र रहे—एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका।

(5) घण्टे घण्टे में अमेरिका से समानता तथा उसके प्राप्ति निकल जाने के प्रयत्न अनवरत चलते रहे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी रणनीति रची गई।

यह उपयुक्त होगा कि रूशनेव-युग में सोवियत विदेश नीति के मुख्य पहलुओं का विस्तार से विवेचन किया जाए और देखा जाए कि इस नीति का व्यवहार में क्रियान्वयन किस प्रकार हुआ।

1. लोह आवरण में शिथिलता, यात्राओं की कटनीति—इस युग में सोवियत लोह आवरण की नीति में पर्याप्त शिथिलता आई और 'यात्रा-कूटनीति' का महत्त्व बढ़ा। सोवियत संघ के विभिन्न सांस्कृतिक तथा ससदीय शिष्टमण्डल विदेशों में जाने लगे और विदेशों के ऐसे ही शिष्टमण्डल साम्यवादी देशों में आमन्त्रित किए जाने लगे। स्टालिन बाह्य देशों के साथ सम्पर्क का घोर विरोधी था और सम्भवतः केवल एक बार तेहरान सम्मेलन के समय अपने देश में बाहर गया था अन्यथा युद्ध सम्मेलनों में ही उसकी चर्चिल और रूजवेल्ट से भेंट हुई थी। लेकिन अब रूशचेव, बुल्गानिन आदि उच्चतम स्तर के सोवियत नेता दूसरे देशों की सद्भावना और मैत्री अर्जित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राएँ करने लगे और उन देशों के नेताओं को अपने यहाँ आमन्त्रित करने लगे।

जून, 1955 में भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू सोवियत रूस द्वारा आमन्त्रित किए गए और नवम्बर, 1955 में रूशनेव तथा बुल्गानिन ने भारत-यात्रा की। इससे दोनों देशों में सद्भाव और मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत नेताओं की भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रति स्टालिनकाल से जो सन्देह बना हुआ था वह दूर हो गया। अप्रैल, 1956 में दोनों नेता ग्रेट ब्रिटेन गए। 1959 के आरम्भ में प्रथम सोवियत उप-प्रधानमंत्री मिर्कोयान ने 15 दिन तक अपने घोर विरोधी समझे जाने वाले अमेरिका की यात्रा की और 17 जनवरी को राष्ट्रपति धाइजनहॉवर द्वारा अमेरिका में सन् 1954 में मोर्लेकोव के बाद पहली बार हार्डट हाउस में किसी रूसी राजनीतिज्ञ का स्वागत हुआ। सोवियत उप-प्रधानमंत्री ने दोनों देशों में व्यापार-वृद्धि को आवश्यक बताया और इस बात पर बल दिया कि 'शीतयुद्ध' (Cold-War) का स्थान 'शान्तिपूर्ण-प्रतियोगिता' (Peaceful Competition) को लेना चाहिए। स्वदेश वापस लौटने पर मिर्कोयान ने 31 जनवरी, 1959 को सोवियत साम्यवादी पार्टी के 21वें अधिवेशन में मास्को में कहा कि उन्होंने अमेरिकी राजनीतिज्ञों और नेताओं के साथ जो भी वार्तालाप किया उसमें उन्हें कहीं सोवियत साम्यवाद के 'निरोध' (Containment), 'पीछे धकेलने' (Roll Back) तथा 'साम्यवाद की दासता से मुक्ति' (Liberation) की कोई चर्चा नहीं सुनाई दी। मिर्कोयान द्वारा अमेरिका की अपनी यात्रा से उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिए जाने बाद सितम्बर 1959 में सोवियत प्रधानमंत्री रूशचेव ने अमेरिका की यात्रा की। फरवरी-मार्च, 1960 में रूशचेव ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों—भारत, बर्मा, इण्डोनेशिया, अफगानिस्तान आदि की यात्रा की।

सोवियत नेताओं द्वारा लोह-आवरण शिथिल किए जाने और विश्व के विभिन्न देशों की यात्रा करने से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चिन्न रूप से कमी हुई और दोनों विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति अपने अधिक शंकायु न रहे जितने स्टालिनकाल में थे।

मपनी यात्राओं में रूसी नेताओं ने शासनाध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन आयोजित करने पर बार बार बल दिया। ऐसा एक सम्मेलन जुलाई, 1953 में जेनेवा में हुआ जिसमें हिन्दचीन की समस्या को महत्व दिया गया। दूसरा सम्मेलन मई, 1960 में हुआ जो दुर्भाग्यवश यू-2 विमानकाण्ड से उत्पन्न बातावरण का शिकार बनकर असफल हो गया।

2. शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान की नीति—स्टालिन की मृत्यु के बाद शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का शुभारम्भ मोलेकोव के प्रधानमन्त्रित्व-काल में ही हो चुका था, किन्तु इसमें निखार खूशचेव तथा इसके परवर्ती युग में आया। फरवरी, 1956 में रूसी साम्यवादी दल की 20वीं कांग्रेस ने स्टालिन तथा उसकी नीतियों की कटु आलोचना की तथा इसके और साम्यवादी देशों से युद्ध की अनिवार्यता के लेनिन-सिद्धान्त को सशोधित कर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की सोवियत नीति का आधार बनाया।

खूशचेव की प्रेरणा से उनके समय जो विदेश नीति अंगीकृत की गई उसकी 5 प्रमुख विशेषताएँ थी—

प्रथम, जहाँ स्टालिन के शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का अर्थ केवल युद्ध का न होना मात्र था, वहाँ खूशचेव ने इसका अर्थ यह माना कि सभी गैरसाम्यवादी राष्ट्र, विशेषकर एशिया और अफ्रीका के तटस्थ राष्ट्र, सोवियत संघ के शत्रु नहीं हैं।

दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया।

तीसरे, यात्राओं की कूटनीतिक स्वीकार की गई और यह माना गया कि दूसरे देशों से अच्छे सम्बन्धों की स्थापना करने के लिए सोवियत नेताओं को अन्य देशों की यात्राएँ करनी चाहिएँ तथा लोह-प्रावरण को शिथिल कर साम्यवादी एवं गैरसाम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए।

चौथे, सोवियत संघ द्वारा विश्व के अल्प-विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता अनुभव की गई।

पाँचवें पश्चिमी शक्तियों को साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी बना कर उनकी निन्दा करते हुए भी उनके साथ खुले मध्य की नीति का परित्याग किया गया।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नवीन सोवियत नीति के अनुसार गैर-साम्यवादी देशों को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है—(1) समुत्तराज्य अमेरिका, (2) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी देश, एवं (3) तटस्थ देश, जैसे—भारत, इण्डोनेशिया, बर्मा, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, अफगानिस्तान व स्विट्जरलैंड। दूसरे शब्दों में, पहले रूस दुनिया में दो रंग के रूप देखता था—लाल और सफेद। अब वह इसमें लाल, पीले, नीले, हरे विभिन्न प्रकार के फूल देखने लगा। पहले उसकी नीति लाल रंग के फूलों के सिवा सब तरह के फूलों के समूलोन्मूलन की थी, अब वह सबके साथ-साथ रहने के 'शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व' की बात करने लगा।

12 अक्टूबर, 1954 को सोवियत संघ और चीनी सरकारों की एक संयुक्त घोषणा

में स्पष्ट कहा गया कि वे समस्त देशों के साथ पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर मंत्री-सम्बन्ध कायम करना चाहते हैं।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत रूसी विदेश नीति में एक निश्चित लचीलापन (Flexibility) आया। इण्टरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी के मुख्य सम्पादक डब्ल्यू आर. हर्स्ट (W. R. Hearst) को एक इण्टरव्यू में स्ट्रुचेव ने स्पष्ट किया था कि यदि संयुक्तराज्य अमेरिका का शासक वर्ग इस असन्धिव्य तथ्य को स्वीकार कर ले कि विश्व में एक समाजवादी जगत् का अस्तित्व है जो अपने आदर्शों के अनुरूप उन्नति के मार्ग पर प्रगसर है एवं इस समाजवादी दुनिया के प्रतिरिक्त एक पूंजीवादी दुनिया भी है तो वह (सोवियत रूस) इन दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व की सम्भावनाओं को स्वीकार कर लेगा। अपने इसी इण्टरव्यू में स्ट्रुचेव ने दृढ़ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि रूस इस बात को किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकता कि ससार के प्रत्येक देश पर संयुक्तराज्य अमेरिका हावी होने की चेष्टा करे।

स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान और सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को मानन के सोवियत रूस ने निश्चित प्रमाण भी प्रस्तुत किए। उदाहरणार्थ, जुलाई, 1953 को कोरिया युद्ध की समाप्ति में रूसी सहयोग प्राप्त हुआ, जनवरी-फरवरी, 1954 में चार बड़ों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसके निश्चय के अनुसार ब्रिसेल में जो जेनेवा सम्मेलन हुआ उसमें नियतनाम की समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। 15 मई, 1955 को वास्ट्रिया के साथ शान्ति स्थापित हुई। जुलाई, 1955 में चार बड़ों का शिखर-सम्मेलन हुआ जो सन् 1945 के पोर्टस्डाम सम्मेलन के बाद चार बड़ों की पहली बैठक थी। इसमें हिन्दचीन के प्रश्न का शान्तिपूर्ण समाधान हुआ। इसी बीच 15 जून, 1954 को सोवियत संघ ने कालेसागर के प्रदेश में टर्कों के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक मांगों का परित्याग करने की घोषणा की।

सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव की नियुक्ति पर अपने पहले के दुराग्रही रवैये को छोड़कर डाग हैमरशोल्ट को महासचिव के रूप में स्वीकार कर लिया। 11 जुलाई, 1955 में भारत के प्रपत्नों और रूस के समर्थन से साम्यवादी चीन ने 11 बन्दी अमेरिकी विमान चालकों को रिहा कर दिया। रूस द्वारा अनुराई गई इस सहयोगपूर्ण और उदार नीति का संयुक्त राष्ट्रसंघ पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। रूसी सहयोग से वह अब अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य करने लगा। नवम्बर-दिसम्बर, 1955 में एक तरफ सोवियत रूस ने और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एवं संयुक्तराज्य अमेरिका ने यह निश्चय किया कि एक दूसरे के द्वारा प्रस्तावित राज्यों को संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने के प्रस्तावों का विरोध नहीं करेंगे। इस निश्चय के परिणामस्वरूप 8 दिसम्बर, 1955 को 18 राज्यों को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान की गई। सोवियत नेताओं ने दूसरे देशों की सद्भावना यात्राएँ करना आरम्भ किया। 18 अप्रैल, 1956 को कोमिनफोर्म को भंग कर दिया गया। जुलाई-अगस्त,

1963 में अगु-परीक्षण-प्रतिबन्ध-सन्धि सम्पन्न की गई जिसे सन् 1922 की वाशिंगटन सन्धियों के पश्चात् निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों की दिशा में प्रथम सफलता कहा जा सकता है। अगस्त में ही मास्को और वाशिंगटन के मध्य सीधा टेलिफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U. S. Soviet Hot Line Agreement) सम्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य यह था कि किसी भी सकटकालीन स्थिति में दोनों राष्ट्रों के अध्यक्ष एक-दूसरे से सीधी वार्ता द्वारा विश्व को आणविक युद्ध का शिकार होने से बचा सकेंगे।

रुझवेव काल में 'पूर्व' और 'पश्चिम' के सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार हुआ, किन्तु राजनीतिक शत्रु के रूप में दोनों की स्थिति यथापूर्व रही और कूटनीतिक दावेपेचों द्वारा अपना-अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने में दोनों ही पक्ष अग्रसर रहे। मूल अन्तर केवल यही रहा कि स्टालिनशाही उप्रवादी नीति का स्थान चानुर्मूर्ण और गहन कूटनीतिक उदार नीति ने ले लिया जिसमें प्रत्येक अनुकूल अवसर से लाभ उठाने की चेष्टा जारी रही। मौके बेमौके ऐसे अवसर उपस्थित होते रहे और ऐसी घटनाएँ घटी जिनमें समय-समय पर शीतयुद्ध में तेजी आई और दोनों पक्षों में कटुता व्याप्त हुई। उदाहरणार्थ 1955 में स्वेज नहर और हजरी के प्रश्न पर दोनों गुटों में अत्यधिक उपना उत्पन्न हो गई। मई, 1960 में यू-2 विमान की घटना ने शीतयुद्ध में ज्वार ला दिया और सन् 1962 में क्यूबा के सकट ने दोनों महाशक्तियों को सघर्ष के इन्ने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के बिस्फोट की सम्भावना से विश्व की सम्पूर्ण शान्तिप्रिय जनता आशंकित हो उठी। फिर भी इससे इकार नहीं किया जा सकता कि सकट के प्रत्येक अवसर को टालने में ग्युनाधिक रूप से दोनों ही पक्षों ने विवेक और धैर्य का परिचय दिया तथा रस्मी को इतना नहीं खिंचने दिया कि वह टूट जाए।

3. अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता—मोल्लोकोव और रुझवेव युग में सोवियत संघ ने भी अल्प-विकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता देने की नीति अपनाई जो आज तक सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनी हुई है। समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सन् 1948 में ही ट्रूमैन सिद्धान्त और मार्शल योजना के अन्तर्गत अल्प-विकसित देशों के लिए आर्थिक सहायता का कार्यक्रम चालू था ताकि उन देशों के बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोका जा सके। इसके प्रत्युत्तर में स्टालिनोत्तर युग में सोवियत रूस ने अल्पविकसित देशों को विकसित करने की अपेक्षा उनमें साम्यवाद के प्रचार और तोड़-फोड़ के सिद्धान्त को अपनाया था। परन्तु स्टालिनोत्तर युग में नवीन नीति का आरम्भ हुआ जिसके अनुसार रूस द्वारा अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर बल दिया जाने लगा। इसके परिणाम-स्वरूप जनवरी, 1954 से जनवरी, 1963 तक दोनों ही देशों द्वारा अल्पविकसित एवं अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की एक प्रतियोगिता-सी प्रारम्भ हो गई।

अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति, अपनाने के साथ

सोवियत रूस ने उत्पादन और सैनिक शक्ति में रबर्ष की पश्चिमी देशों से श्रेष्ठतर निम्न करने का पूर्ण प्रयास किया। ह्यूश्चेव का स्पष्ट मत था कि, “प्रथम सबसे महत्वपूर्ण समस्या पूँजीवाद को पराजित करना है। जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के द्वारा अधिक पैदा करेगा वह विजयी होगा।” इस नीति के कठनस्वरूप रूप के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। सैनिक शक्ति में भी सोवियत तम तेजो से आगे बढ़ा। सन् 1957 में स्पूतनिक और सन् 1961 में 50 मेगावाट बल का निर्माण कर वह रॉकेट तथा प्राणविक शस्त्रों की दौड़ में संयुक्तराज्य से भी आगे निकल गया।

4. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध—ह्यूश्चेव ने एशिया और अफ्रीका के देशों तथा असतमन विश्व (Uncommitted World) की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद-विरोधी प्रचार को और भी तीव्र कर दिया। संयुक्त राष्ट्रमण्डल और अन्यत्र वह साम्राज्यवादी शक्तियों की तीव्र निन्दा करने लगा और उपनिवेशों तथा गुलाम राष्ट्रों की स्वतन्त्र बनाने के मनी प्रस्तावों और आन्दोलनों को पूर्ण समर्थन प्रदान करने लगा। हमी नेनापो की भावना थी कि इस नीति से उन्हें दोहरा लाभ मिलता है। पहला तो यह कि उसे एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवाद से पीड़ित जनता की सहानुभूति प्राप्त होती है और दूसरे, साम्राज्यवाद के विघटन से हम के प्रबल एवं कट्टर शत्रु पूँजीवादी पश्चिम की प्रमुखा क्षीण होती है।

वास्तव में स्टालिन की मृत्यु के बाद ही विशेषकर ह्यूश्चेव के प्रभाव में आने के उपरान्त से एशिया और अफ्रीका के अल्पविकसित या अविश्वसित देशों और उपनिवेशों के प्रति सोवियत नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित थे—

- (i) भूतपूर्व उपनिवेशी प्रथवा प्रद्व-उपनिवेशी देशों के सन्देह एवं राष्ट्रीय सम्मान का अच्युत प्रकार से ध्यान रखना हुए इनके प्रति पूरी तरह मित्रता एवं सौहार्द प्रदर्शित करना,
- (ii) इन देशों के पश्चिम के साथ घनीय के कटु सम्बन्धों का लाभ उठाकर इन्हें पश्चिम से विमुख करना,
- (iii) न केवल उपनिवेशवाद विरोधी बल्कि आनिवाद विरोधी प्रवृत्तियों का भी उभारना;
- (iv) राजनीतिक तटस्थता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना,
- (v) औद्योगीकरण द्वारा उनकी अपनी अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने की महत्त्वाकांक्षा को बल देना, हो मवे तो सोवियत एवं पारस्परिक व्यापारों के सम्बन्धों की ओर उनकी झुकाना;
- (vi) उनके पश्चिम के साथ प्रत्येक सम्भावित विवाद को उरसाना;
- (vii) विदेशी पूँजी या सहायता को उनकी स्वतन्त्रता एवं सम्मान के बिना बढा कर सन्देह की भावना उरसाना,
- (viii) उनकी भाँगों के सामन सोवियत रुम के दुन औद्योगीकरण के आदर्शों के रूप में प्रस्तुत करना ताकि ह्यानीय लोग यह समझ सकें कि केवल साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उन्नतियों को साकार कर सकता है।

सोवियत संघ के शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार के मुख्य प्राकृतिक केन्द्र तीन हैं—अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका। शिपिलोव (Shepilov) ने पूर्व के सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रों के समाप्त प्रायः उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को सहायुभूति तथा सम्मान प्रदान करती है। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा आत्म-निर्णय प्रत्येक देश की जनता (People) का अभिन्न अधिकार है।

ख़रुश्चेव का पतन, उसकी नीति का मूल्यांकन

ख़रुश्चेव के समय सोवियत नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह जिन नई दिशाओं की ओर उन्मुख हुई उसका विवेचन किया जा चुका है। ख़रुश्चेव ने सोवियत नीति को जो मोड़ दिया वह उसके पतन के बाद भी जारी रहा। बाद में सोवियत नेताओं की नीति ख़रुश्चेववादी ही रही। प्रधानमन्त्री कोसीगिन एवं राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव ने इस की इस सह-अस्तित्व एवं शान्तिवादी नीति को गति प्रदान की। गत वर्षों के इतिहास से इस भाषा का संचार हुआ है कि सोवियत रूस अपनी उदार नीति पर आसन्न रहेगा।

थोड़े ही और उन्हीं के समान कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उदारवाद इस की अल्पवालीन नीति है अर्थात् उनकी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्टालिन के समय के शुद्ध-आन्दोलनों में अनेक बड़े नेताओं की जो पदावगति होती थी, वह आज भी होती है। इस के मामले में विशेष रूप से सिद्धहस्त अनेक पाश्चात्य कूटनीतिज्ञों की मान्यता है कि रूसी विदेश-नीति का प्रमुख ध्येय पूँजीवादी समाज का उन्मूलन है जिसमें शायद ही कोई मूल परिवर्तन आए। पर आज का इस तो व्यवहार में स्वयं की सह-प्रस्तित्व का सच्चा समर्थक सिद्ध कर रहा है और अनेक मतलों पर पश्चिमी राष्ट्री तथा अमेरिका की अपेक्षा अधिक शान्तिवादी होने का परिचय दे रहा है।

ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल

(1964-1977)

ख़रुश्चेव के पतन के बाद अक्टूबर, 1964 में सोवियत संघ का नेतृत्व ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के हाथों में आया। यह आशका व्यक्त की गई कि नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा और सोवियत नीति में पुनः प्रतिगामी परिवर्तन आएगा। लेकिन नए सोवियत नेताओं ने ख़रुश्चेववादी नीति अपनाते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त पर चलने का आश्वासन दिया और उसे निभाया भी। ब्रेझ्नेव-कोसीगिन ने सोवियत कूटनीति को कुछ नई दिशाएँ भी प्रदान की हैं। वर्तमान जटिल और परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत विदेश-नीति का मुख्य लक्ष्य साम्यवादी चीन और संयुक्तराज्य अमेरिका के दोहरे खतरे का मुकाबला करते हुए साम्यवादी जगत में रूसी नेतृत्व और विश्व में सोवियत प्रतिष्ठा को कायम रखना है। चीन-अमेरिका-यूरो के सफल मुकाबले के लिए भारत की मैत्री के महत्त्व को हाल ही के वर्षों में सोवियत नेता भली-भाँति याद चुके हैं और पाकिस्तान-भारत

सम्बन्धों में वर्तमान सोवियत विदेश-नीति का बहुत-कुछ इसीलिए पुनर्मूल्यांकन हुआ है।

सह-अस्तित्व और यात्रा-कूटनीति—रूस के नए नेतृत्व ने शूश्चेव्स्कीय यात्राओं की कूटनीति जारी रखी है। अक्टूबर, 1966 में सोवियत विदेशमन्त्री ग्रोमिको ने राष्ट्रपति जॉनसन से मिलकर निःशस्त्रीकरण और वियतनाम के प्रश्न पर बातों की। जून, 1967 में अमेरिका और रूस के सर्वोच्च नेताओं का विश्व सम्मेलन हुआ तथा पश्चिमी एशिया के संकट पर सयुक्तराष्ट्र-महासभा के अधिवेशन में भाग लेने के लिए रूसी प्रधानमन्त्री कोसीगिन स्वयं उपस्थित हुए। ग्लासबरो में जॉनसन और कोसीगिन ने विभिन्न समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके बाद भी यही क्रम चालू रहा और सोवियत नेताओं ने भारत-पाकिस्तान, अमेरिका तथा अरब प्रदेशों की यात्राएँ की। इन यात्राओं में सोवियत नेता विश्व के राष्ट्रों के मध्य सोवियत विदेश-नीति के विवादग्रस्त पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या दे सके जिससे सह-अस्तित्व और समस्याओं के शान्तिपूर्ण निदान का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

ताशकन्द : सोवियत कूटनीति में नया मोड़—मिर्तम्बर, 1965 में भारत-पाक सघर्ष का अन्त कराने में उल्लेखनीय प्रयास करने के उपरान्त दोनों देशों के बीच विवाद सुलभाने के लिए मध्यस्थता कर रूस ने अपनी विदेश-नीति के नए पैतरे से समूचे राजनीतिक विश्व को स्तब्ध कर दिया। सोवियत संघ ने इससे पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को कभी स्वीकार नहीं किया था। जनवरी, 1966 में 'ताशकन्द वाता' को सफल बनाने में सोवियत कूटनीति अत्यन्त सक्षम रही जिसके फलस्वरूप 10 जनवरी, 1966 को रात्रि के लगभग 9 बजे तालियों की गटगडाहट के बीच तत्कालीन पाक राष्ट्रपति अयूब खान और भारतीय प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत प्रधानमन्त्री कोसीगिन की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे 'ताशकन्द घोषणा' (Tashkent-Declaration) कहा गया। इस समझौते के कारण उस समय कश्मीर-विवाद ठण्डा पड़ गया, भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध सामान्य होने लगे तथा यह निश्चय हुआ कि दोनों पक्षों की सेनाएँ उन स्थानों पर लौट आईं जहाँ वे अगस्त, 1965 में युद्ध प्रारम्भ होने से पहले थीं। सभी मतभेदों पर बातचीत चालू रखने का निर्णय किया गया।¹ सोवियत राजनय की इस सफलता के मूल में प्रमुख कारण थे—(i) भारत और पाकिस्तान को एक निष्पक्ष वातावरण में समझौता-वार्ता के लिए क्रियाशील करना (ii) समझौता कराने के प्रश्न को सोवियत रूस द्वारा अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना, (iii) सोवियत रूस की भौगोलिक स्थिति और एशिया में शान्ति व्यवस्था रखने में उनकी रुचि, एवं (iv) पाकिस्तान को चीन-अमेरिकी मुठ में आने से रोकने की प्रबल रुची उत्पन्न।

पाकिस्तान के प्रति तभीन दृष्टिकोण किन्तु शीघ्र ही भूत सुधार—ताशकन्द समझौते के मूल में सोवियत संघ की भारत और पाकिस्तान के प्रति बदलती दृ

नीति के बीज छिपे थे—यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। रुस के नये नेतृत्व का रुख ताशकन्द समझौते के उपरान्त कुछ वर्षों तक भारत के प्रति उनना मैत्रीपूर्ण नहीं रहा जितना ख़ुश्नेव के समय था। कश्मीर के प्रश्न पर भी सोवियत रुस में पाकिस्तान के पक्ष में कुछ तरफ़ी आयी। जुलाई, 1968 में रुस ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का जो निर्णय किया वह भारत की मित्रता और आशाओं पर एक करारी चोट थी। सोवियत रविये ने भारत को इस बात के लिए विवश किया कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता।” फिर भी भारत का रुख सहनशीलता और ‘प्रतीक्षा करो और देखो’ का रहा। उपर सोवियत नेता पाकिस्तान की दुरगो चालों से क्षुब्ध हो गये। उनकी यह धारणा बनी कि अमेरिका, चीन और रुस तीनों में से पाकिस्तान किसी का भी विश्वसनीय मित्र नहीं हो सकता। जो हथियार दे, वही उसका मित्र है। पाकिस्तान ने ताशकन्द समझौते के जो गम्भीर उल्लंघन किये उनसे भी पाकिस्तान की ईमानदारी में सोवियत नेताओं का विश्वास टूट गया। दूसरी ओर भारत की गम्भीरता और दृढ़ता ने तथा रुस के प्रति अपरिवर्तित दृष्टिकोण ने सोवियत नेताओं को यह अनुभव करा दिया कि रुस के लिए अमेरिकी और चीनी खतरे के विरुद्ध भारत जैसे शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र के हाथों में कितनी सन्तुलनकारी शक्ति है। जब बंगलादेश (उस समय पूर्वी पाकिस्तान) की घटनाएँ घटी तो इसी सहानुभूति भारत और बंगला देश के न्यायपूर्ण पक्ष की ओर रही।

भारत और सोवियत-विदेश नीति—स्टालिन ने, जो कठोर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का समर्थक था, भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को ‘निर्बल तथा अवसरवादी नीति’ का ही प्रतिरूप समझा। भारत के पश्चिमी देशों के साथ सहयोग स्थापित करने के प्रयत्नों की सोवियत रुस में आलोचना हुई, लेकिन सन् 1949 के अन्त तक भारत और रुस के सम्बन्धों में सुधार होने लगा। मास्को में भारतीय राजदूत डॉ॰ राधाकृष्णन् के सद्प्रभावों से दिल्ली-मास्को के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास में बहुत सहायता मिली।

इस बढ़ती हुई मैत्री को जून 1950 में कोरिया-युद्ध छिड़ने पर झटका लगा। भारत न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में था, अतः उसने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने में कोई हिचक नहीं दिखायी। इससे सोवियत संघ में भारत के प्रति रोष पैदा हो गया, किन्तु जब कोरिया-समस्या के आगामी चरण में भारत ने सयुक्त-राष्ट्रसंघीय सेनाओं को 38वीं प्रलाप रेखा पार करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के विरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिन को विश्वास हो गया कि भारत की निर्णय-शक्ति स्वतन्त्र है, वह परिचयों के दबाव से प्रेरित नहीं है। दोनों देश इसलिए भी एक-दूसरे के निकट प्राये कि तिनम्बर, 1951 में भारत ने जापानी शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सन्धि जापान को साम्राज्यवादी शिक्षे में जकड़ने की एक चाल थी।

मोर्लेकोव और फिर बुन्गानिन-ख़ुश्नेव काल में भारत और रुस के सम्बन्ध

अधिक घनिष्ठ रहे। सन् 1954 में रुस ने 'पक्शील' के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जून, 1955 में वी नैहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की तथा रूस्वियों को अपने सह-अस्तित्व की विचारपारा से अत्यधिक प्रभावित किया। सन् 1955-56 में बुल्गारिन और ख्रुश्चेव ने भारत की यात्रा की। उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण समान थे। कश्मीर विवाद पर सोवियत संघ भारत को खुला समर्थन देता रहा और सुरक्षा-परिषद् में भारत विरोधी पश्चिमी राष्ट्रों के प्रस्ताव पर 'वोटो' का प्रयोग करता रहा। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में भी दोनों देशों के दृष्टिकोण में समानता रही।

अक्टूबर, 1962 में चीनी आक्रमण के प्रारम्भ में रूसी रुस भारत के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन धीरे-धीरे भारत पर चीनी आक्रमण के सम्बन्धों में सोवियत दृष्टिकोण बदलने लगा और दिसम्बर, 1962 में तो सुग्रीम सोवियत के नामने श्री ख्रुश्चेव ने भारत पर चीनी आक्रमण की खुली निन्दा तक की। सन् 1963 में चीन द्वारा बोलम्बो प्रस्ताव ठूँटा देने पर भी रुस ने चीन की कटु आलोचना की। रुस द्वारा भारत को मिग विमान दिये गये और रूसी सहयोग से मिग-विमान का कारखाना भी भारत में स्थापित किया गया।

26 अक्टूबर, 1964 को ख्रुश्चेव के पत्र के पश्चात् रुस में ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के नये मतभेद का उदय हुआ जो भाव भी सत्ताह्व है। वाद के कुछ वर्षों में भारत की रुस का वैसा समर्थन प्राप्त नहीं हो सका जैसा ख्रुश्चेव ने दिया था। जितम्बर, 1965 में भारत-पाक संधि के समय सोवियत नेतृत्व की नीति किसी न किसी प्रकार संधि को शांति करने की रही और रुस ने पाकिस्तान के कार्यों का पक्ष के समान विरोध नहीं किया।

लाशकन्द समझौते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में थोड़ा-सा तनाव सब आया जब रुस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का निश्चय किया। सोवियत कूटनीति की यह 'नयी दिशा' भारत के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली थी। सोभाग्रवश रुस को अपने 'दिशा-भ्रम' का जोर ही ग्रहण हो गया और भारत-रुस सम्बन्धों में उत्तरोत्तर विकास होता रहा। बंगलादेश के सम्बन्ध में रुस का रुझान भारत-समर्थक था। सन् 1971 में पाकिस्तान ने बंगलादेश के जन-प्रान्दोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं रखी और रुस ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि वह नरमहार समाप्त कर समस्या के राजनीतिक हल के पक्ष में बंगलादेश के सकट काल में पेरिंग विण्डी-वांशिगटन घुरी के निर्माण की सम्भावनाओं और उससे उत्पन्न खतरे को देखकर भारत ने 9 अगस्त, 1971 को सोवियत संघ के साथ मैत्री-सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इस तरह भारत और सोवियत संघ चीन-अमेरिकी सम्बन्धों से भविष्य में उत्पन्न होने वाले परिणामों का सामना करने के लिए और अधिक निश्चिन्त हो गये। इस सन्धि द्वारा केवल भारत ही लाभान्वित नहीं हुआ अपितु सोवियत संघ भी एशिया में एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया और यह उसकी वर्तमान विदेश नीति की एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है।

इस सन्धि की सबसे बड़ी बात इस निश्चय में है कि यदि कोई तीसरा देश दोनों में से किसी एक पर आक्रमण करता है तो वे उसके प्रतिकार के लिए एक दूसरे से परामर्श करेंगे। इसका सीधा अभिप्राय यह अवश्य ही नहीं है कि उनमें से एक आक्रमणकारी पर आक्रमण कर देगा, परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह प्रयत्नशून्य है। जब आक्रमण होगा तो आक्रमण के प्रतिकार का उपाय सोचा जायगा। इसका अर्थ सैनिक सहायता भी हो सकता है। सहायता का कोई अन्य स्वरूप भी हो सकता है। लक्ष्य आक्रमण के निराकरण का है। यदि यह पूर्ण हो जाता है तो शान्ति के लिए और क्या अभीष्ट है।

दिसम्बर 1971 के भारत-पाक युद्ध तथा बंगलादेश के उदय के समय यह पुनः स्पष्ट हो गया कि भारत की स्वतन्त्र निर्णय शक्ति पर किसी भी अंकुश अथवा संदेह की कल्पना करना भ्रामक है तथा सोवियत रूस भारत का सच्चा हितैषी और सक्कट में काम करने वाला मित्र है। गुरला-गरिपद् ने भी रूस ने पाकिस्तान और उसके 'बड़े प्राक्ता' अमेरिका के मनसूबों पर पानी फेर दिया। युद्ध के दौरान उसने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी विदेशी ताकत हस्तक्षेप करने का दुस्साहस न करे। इतना ही नहीं, जब अमेरिका का सातवाँ बेड़ा 'रहस्यमय दरादे' से बंगाल की खाड़ी की ओर चल पड़ा तो रूस ने भी हिन्द महासागर में अपने युद्धपोत इस दृष्टि से तैयार कर दिये कि भारत के विरुद्ध अमेरिका द्वारा नौ-सैनिक कार्यवाही करने पर उसका उचित उत्तर दिया जाय। रूसी महयोग के फनस्वरूप अमेरिका और चीन को यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया कि भारत-सोवियत मैत्री सन्धि कोरी कागजी कार्यवाही नहीं है बरन् एक सच्ची सन्धि है। सन् 1972, 1973 एवं अगले वर्षों में इस मैत्री-सन्धि की वर्षगांठें मनाकर दो महान् राष्ट्र एक दूसरे के और भी निकट आये हैं।

भारत और सोवियत संघ की मैत्री नवम्बर 1973 में ब्रेझ्नेव की भारत यात्रा से और अधिक पुष्ट हुई। ब्रेझ्नेव ने भारत की सिद्धान्तनिष्ठ नीतियों की सराहना की और राजनीतिक क्षेत्रों में स्पष्ट मत व्यक्त किया गया कि सोवियत नेता की इस यात्रा से एशियायी देशों के शान्ति और सुरक्षा के लिए सामूहिक सघर्ष के प्रयासों को और बल मिला है। ब्रेझ्नेव की इस यात्रा से स्पष्ट हो गया कि भारत-सोवियत संघ मैत्री 'दो देशों की परस्पर-सन्धि' के दावरे से बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सहयोग के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और आर्थिक तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं के क्षेत्र में तेज अधिकाधिक रूस पर निर्भर करने लगा है। रूसी नेता की चार-दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के दौरान 30 दिसम्बर, 1973 को भारत और सोवियत संघ के बीच एक 15 वर्षीय आर्थिक और व्यापारिक समझौता हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि सोवियत संघ भारत को आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए भारी उद्योगों व विकास-कार्यक्रमों के लिए विशाल सहायता देगा। समझौते के अन्तर्गत यह निश्चय प्रकट किया गया कि सन् 1980 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को डेढ़ गुना या दुगुना बढ़ा दिया जायगा और इसके

लिए दोनों देश आवश्यक कदम उठायेगे। 30 नवम्बर को अन्तर्गत वापस आने देश लौट गये। विमान से रवाना होने के बाद उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को विमान पर से सन्देश भेजा कि "हमारी दानवीत एशिया और समूचे विश्व की स्थिति पर ठोस प्रभाव डालेगी तथा दोनों देशों के बीच मैत्री-सम्बन्ध अधिक विकसित तथा सुदृढ़ करने के लिए जोरदार प्रेरणा का काम करेगी।" 1 दोनों देशों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। जब फरवरी 1975 में पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार प्रदान करने को घोषणा की गई तो रूस ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की और इसे भारतीय उपमहाद्वीप की शान्ति के लिए घातक बताया।

भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता, सूझ-बूझ और परस्पर लाभकारी सहयोग के सम्बन्ध निरन्तर निवसित और सुदृढ़ होते गये। मास्को में दोनों देशों के बीच नवम्बर 1975 में विदेश कार्यालयों के बीच नियमित द्विपक्षीय वार्षिक परामर्श हुआ तथा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर पारस्परिक हित की दृष्टि से लाभकारी आदान प्रदान हुआ। सर्वोच्च सोवियत की सर्वोच्च परिषद् के उपाध्यक्ष एस बी नियाजवकोव के नेतृत्व में एक सोवियत ससदीय प्रतिनिधि मंडल ने 10 से 17 अप्रैल 1975 तक भारत की यात्रा की। दीर्घकालीन व्यापार समझौता वार्ता के सम्बन्ध में भारत के वाणिज्य मंत्री धी चटोपाध्याय नवम्बर 1975 में मास्को गये। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी भारत को उल्लेखनीय सोवियत सहयोग मिला। अप्रैल 1975 में सोवियत रॉकेट की सहायता से भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह (आर्यभट्ट) सोवियत संघ से छोड़ा गया। यह उस समझौते के अन्तर्गत था जो दोनों देशों के बीच मई 1972 में हुआ था। कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष खोज के पर्यवेक्षण सम्बन्धी पारस्परिक सहयोग के कार्यक्रम पर दोनों देशों के बीच नवम्बर 1975 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जनवरी 1976 में दोनों देशों ने 1976 व 77 दो वर्षों के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये जिसका विषय—कृषि एवं जल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग था। 1976 व 80 की अवधि के लिए अप्रैल 1976 में एक नया व्यापार-समझौता हुआ जिससे भारत में परम्परागत निर्यात वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्यात का मार्ग भी खुल गया जिनका सम्बन्ध आधुनिक मशीन और उपकरण-निर्माण से है। इसे भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जायगा क्योंकि अभियान्त्रिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को सोवियत संघ जैसे विकसित देश और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में मान्यता प्राप्त हुई है।

भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्रीपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी सहयोग के सम्बन्धों में अनेक उच्चस्तरीय यात्राओं के विनिमय तथा महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर के माध्यम से और भी प्रगति हुई। इनमें व्यापार, व्यापारिक नीतिबद्धन और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम समझौते शामिल हैं। उच्चस्तरीय यात्राओं के

माध्यम से भी निकट सम्बन्धों को कायम रखा गया। इन यात्राओं में जून 1976 में प्रधानमंत्री और मंगोलियाई लोक गणराज्य की यात्रा के अवसर पर विदेश मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा भी सम्मिलित है। अप्रैल 1977 में सरकार के नये नेताओं से विचार-विनिमय के लिए सोवियत विदेश मंत्री श्री ग्रोमिको भारत आये। इस यात्रा से अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा आपसी हित के मामलों पर विचार-विनिमय करने का अवसर मिला। इस यात्रा के दौरान अधिक एव तकनीकी सहयोग, व्यापार एव दूरसंचार सम्बन्धों की स्थापना से सम्बन्धित तीन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनसे दोनों देशों के बीच सहयोग वृद्धि की और भी सम्भावना है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा, खेल-कूद और पर्यटन के क्षेत्र में अपने सम्बन्धों को और भी सुदृढ़ बनाने और विकसित करने की इच्छा व्यक्त की। बातचीत के दौरान अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में दोनों देशों के समान विचार पाये गये। अक्टूबर 1977 में प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने रूस की यात्रा की। काग्रेस शासन के दौरान भारत तथा रूस के बीच जो विशेष सम्बन्ध विकसित हुए थे, जनता-पार्टी की नयी सरकार ने उन्हें प्रागे बढ़ाया है। श्री देसाई की यात्रा का मूल उद्देश्य दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाना था जिसमें उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त हुई। श्री देसाई की इस यात्रा के बाद यह अधिक स्पष्ट हो गया कि दोनों देश अपने पारस्परिक हितों को ध्यान में रखते हुए परम्परागत मैत्री-सम्बन्धों का निर्वाह करते रहेगे।

पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों के प्रति सोवियत नीति—रूस पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत् पर अपना समुक्त प्रभाव बनाये रखने के पक्ष में है ताकि वहाँ में पश्चिमी यूरोपीय राजनीति में प्रभावपूर्ण ढंग से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः पूर्वी यूरोपीय देशों में पनप रही सोवियत विरोधी प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए उसने वारसा पेंकट की पहली की अपेक्षा और अधिक कठोर तथा शक्तिशाली बना लिया है। सन् 1968 में चेकोस्लोवाकिया में रूस विरोधी विद्रोह को कुचलने में उसके तथा अन्य वारसा पेंकट के देशों द्वारा निर्वाह की गई भूमिका से यह स्पष्ट है। सोवियत नेताओं का कहना है कि रूस और उसके साथियों का सैनिक हस्तक्षेप चेकोस्लोवाकिया में साम्यवाद के विरुद्ध की जाने वाली क्रान्ति को विकल बनाने के लिए आवश्यक था।

अस्तित्व ने सन् 1967 से ही चेकोस्लोवाकिया में उदारवादी प्रवृत्ति और पकड़ने लगी थी और जनवरी, 1968 में दुश्चेक के नेतृत्व में चेकोस्लोवाकियाई साम्यवादी दल ने समाजवादी लोकतन्त्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर, उदारवाद के पक्ष में बहुत से सुधार प्रस्तावित किये थे। जब चेकोस्लोवाकिया के नेताओं ने रूसी अप्रमत्तता की कोई परवाह नहीं की तो 21 अगस्त, 1968 की राति को सोवियत रूस तथा वारसा पेंकट के चार अन्य देशों—पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और बल्गेरिया की शक्तिशाली सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर कुछ ही घण्टों में राजधानी प्राग सहित अन्य बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया। अन्त में काफी विचार-विमर्श के बाद मास्को में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता

हुआ जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चेकोस्लोवाकिया सरकार ने बचन दिया कि वह चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी। सितम्बर, 1968 के मध्य तक प्राग से सोवियत सेनाएँ वापस लौट गईं। अप्रैल, 1969 में कुबचेक के नेतृत्व का अन्त हो गया और सोवियत रुस समर्थक सरकार की स्थापना हुई। आक्रमण की कटु स्मृतियाँ धीरे-धीरे घुमिल पड़ गई और आज दोनो देशों के सम्बन्ध सामान्य हैं। अल्बानिया अवश्य चीन के प्रभाव में है, किन्तु रूमानिया में रुस ने अपनी स्थिति पुनः सम्भाल ली है। पोलैण्ड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, बल्गेरिया आदि देशों के साथ रुस के सम्बन्ध यथावत हैं।

यद्यपि साम्यवादी शिविर में स्वैच्छिक एकता का तो अभाव ही रहा है तथापि 1977 का वर्ष इस दृष्टि से नयी आशाओं का संचार करता है। निश्चय ही सन् 1977 की राजनीतिक दुनिया सन् 1948 से भिन्न है। पिछले तीस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय राजनय में कई समीकरण बने और बिगड़े हैं, उनमें कई उतार-चढ़ाव आये हैं और महाशक्तियों ने सीधे मशरूम लघ्वर्यों को टालने के लिए 'शीतयुद्ध' और फिर 'वैता' की कूटनीति अपनायी है। स्वाभाविक था कि इस दोरे में कम्युनिस्ट देश भी अपने पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करते और शायद पुनर्विचार का ही यह परिणाम है कि कम्युनिस्ट गुट में आपसी विवादों का अन्त करने की चिन्ता उत्पन्न हुई है। इसलिए यह कोई सयोग नहीं है कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो एक सम्मेलन अंतराल के बाद अगस्त 1977 की 16 तारीख को आठ दिन की राजकीय यात्रा पर सोवियत संघ गये और वहाँ से उत्तर कोरिया होते हुए 30 अगस्त को पहली बार चीन पहुँचे। अवश्य ही यह एक सयोग है कि जिन मार्शल टीटो ने अठारह वर्ष पूर्व सन् 1949 में सोवियत संघ से सम्बन्ध विच्छेद कर कम्युनिस्ट गुट में स्वतन्त्र नीति अपनाने की बुनियाद रखी थी वही टीटो अब कम से कम तीन शिविरों में विभक्त कम्युनिस्ट जगत् की एकता की मुहिम पर निकले।

साम्यवादी आन्दोलन को मजठित करने अवकाश कम से कम उसे और विघटन से रोकने की भूमिका में मार्शल टीटो कम्युनिस्ट जगत् में अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। सोवियत संघ उनसे सबाद स्थापित करने की पहल भी कर चुका था। इस सबाद की शुरु वरने का अवसर जुदाया कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के सम्मेलन ने, जो 28 जून, 1976 को बर्लिन में हुआ था। उस सम्मेलन के अवसर पर ब्रेझ्नेव और टीटो के बीच 'पेची बात' हुई थी। इस बात का परिणाम भी इस ही सामने आया। यूगोस्लाविया के टीटोवाद-विरोधी लगभग 130 सोवियत समर्थकों को टीटो सरकार द्वारा दण्डित किये जाने के बावजूद श्री ब्रेझ्नेव 15 नवम्बर, 1976 को श्री टीटो से बातचीत करने बेलग्रेड पहुँचे। सोवियत संघ सन् 1975 से ही यूगोस्लाविया से नौसेना के लिए बन्दरगाह की तथा कुछ अन्य सुविधाएँ देने का प्रयत्न कर रहा था। ब्रेझ्नेव ने सितम्बर 1977 की अपनी बेलग्रेड यात्रा के अवसर पर दिये गये इस आश्वासन को दोहराया कि सोवियत संघ यूगोस्लाविया

की स्वाधीनता का आदर करता रहेगा और यात्रा के बाद जारी की गयी वितर्कित में दोनों देशों के बीच 'स्वच्छ सहयोग' की बात प्रकट की गयी। सोवियत संघ ने एक तरह से समाजवाद का प्रपना मार्ग अपने आप तय करने के यूगोस्लाविया के मार्ग को भी मान्यता दे दी।

16-24 अगस्त 1977 के अपने मास्को प्रवास के समय मार्शल टीटो ने सोवियत नेताओं से पारस्परिक सम्बन्ध और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों देशों की इस शिखर वार्ता में समूचे विश्व की गहरी रुचि थी। स्वागत समारोहों तथा प्रीतिभोज के अवसर पर सोवियत नेता श्री ब्रेझ्नेव ने विश्व में मित्रता और मदभाव का वातावरण स्थापित करने के साथ-साथ सभी प्रकार के आक्रमणों और शीतयुद्ध चालू रखने के प्रयत्नों की कड़े जब्दों में निन्दा की। श्री ब्रेझ्नेव का कहना था कि आज के विश्व में क्रान्तिकारी और प्रगतिशील आन्दोलनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समाजवादी देशों और गुटनिरपेक्ष देशों को आज सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य साम्राज्यवादियों का भुकावला करना और शान्तिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा विश्व में शान्ति स्थापित करना है। श्री ब्रेझ्नेव का यह भी कथन था कि कुछ साम्राज्यवादी देशों ने समाजवादी देशों के विरुद्ध अपना प्रचार तेज कर दिया है। इस प्रचार का उद्देश्य दुनिया में तनाव कायम रखना है। ये साम्राज्यवादी देश चाहते हैं कि विश्व के दो शिबिरो में परस्पर विश्वास न बढे और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में तनाव बना रहे। श्री ब्रेझ्नेव ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री कार्टर के इस बक्तव्य का भी उल्लेख किया कि अमेरिका सोवियत संघ से अपने सम्बन्ध घनिष्ठ बनाना चाहता है। श्री ब्रेझ्नेव का कहना था कि अमेरिका की ओर से पहले भी इस प्रकार के प्रयत्न होने रहे हैं लेकिन इन विचारों को जब तक कार्यरूप में परिणत न किया जाये तब तक इनका कोई अर्थ नहीं है। हम चाहते हैं कि अमेरिका सोवियत-संघ की समस्याओं के समान समाधान के लिए सहमत हो। जहाँ तक यूगोस्लाविया का सम्बन्ध है हमारे सम्बन्ध परस्पर विश्वास, स्वतन्त्रता तथा समानता के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया समान लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टियाँ केवल समाजवाद को समर्पित हैं। दोनों देशों की पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है। सोवियत नेता का यह भी कहना था कि यूरोपीय सुरक्षा, पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका में जातिभेद के विरुद्ध संघर्ष जैसे प्रश्नों पर यूगोस्लाविया और सोवियत संघ का दृष्टिकोण समान है।

पश्चिमी सूत्रों के अनुसार यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो की कम्युनिस्ट देशों की यह यात्रा विश्व कम्युनिस्ट शिखर सम्मेलन की तैयारी के सम्बन्ध में थी। मार्शल टीटो विश्व के कम्युनिस्ट आन्दोलन को विघटन से बचाने के लिए चीन और सोवियत नेताओं से गम्भीर विचार विमर्श करने के पक्ष में है। इस समय दुनिया का साम्यवादी आन्दोलन तीन भागों में बँट गया है—सोवियत साम्यवाद मार्क्सवादी साम्यवाद, और यूरोपीय साम्यवाद। सोवियत संघ पिछले कई

वर्षों से विश्व साम्यवादी सम्मेलन के लिए प्रयत्नशील रहा है, लेकिन दुनिया की साम्यवादी पार्टियों में मतभेद इतने उग्र थे कि वे इस प्रकार के सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हुए। काफी समय से दुनिया की साम्यवादी पार्टियों की धारणा बनी हुई है कि किसी भी साम्यवादी विश्व सम्मेलन को सोवियत प्रभुत्व से नहीं बचाया जा सकता। इसी आशंका को दूर करने के लिए यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टोटो काफी समय से प्रयत्नशील हैं। द्वाय यूरोपीय साम्यवाद विपक्ष नयी प्रवृत्तियों से सोवियत सघ काफ़ी चिंतित रहा है क्योंकि अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व सोवियत सघ ही करता रहा है। अभी कुछ समय पहले यूरोपीय साम्यवादी नेताओं का सम्मेलन पूर्वी बर्लिन में हुआ था जिसमें इस आशय के निबन्ध पढ़े गये थे कि हर देश को अपने-अपने ढंग का साम्यवाद लाने का अधिकार है। इन प्रवृत्तियों से चिन्तित होकर सोवियत सघ ने साम्यवादी जगत् में तनाव कम करने के अभियान का मूकपात किया। मार्शल टोटो ने इसमें स्वयं को अग्रणी रूप में प्रतिष्ठित किया है। सोवियत सघ और यूगोस्लाविया की वर्तमान वार्ता तथा अन्य प्रमुख देशों से मार्शल टोटो के इस परामर्श के क्या परिणाम निकलेंगे यह कहना तो अभी कठिन है, परन्तु सोवियत सघ का सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लेना कि हर देश को अपने-अपने ढंग का साम्यवाद लाने का पूर्ण अधिकार है, साम्यवादी इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है।¹

लेटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के सम्बन्ध में सोवियत नीति—वर्तमान समय में सोवियत सघ ने अपना ध्यान यूरोप और एशिया की ओर केन्द्रित रखा है। लेटिन अमेरिका और अफ्रीका के सम्बन्ध में उसकी विदेश नीति विशेष सक्रिय नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं—प्रथम, लेटिन अमेरिका और अफ्रीका भौगोलिक दृष्टि से सोवियत सघ से बहुत दूर हैं। द्वितीय, इन क्षेत्रों में स्थित चाँगे, जूआ, घाना, मूडान आदि देशों में उसे यह कठु प्रनुभव हो गया है कि साम्यवाद का स्वागत करने के लिए लेटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं।

सोवियत रूस के अमेरिका तथा पश्चिमी गुट से सम्बन्ध—सोवियत-अमेरिकी सम्बन्धों का इतिहास मुख्यतः तनाव और सघर्ष का इतिहास रहा है जिसमें कुछ समय से सहयोग के बीज अंकुरित हो रहे हैं। रूसी नेताओं का यह विश्वास बनपा है कि अमेरिका और तापी राष्ट्रों में सोवियत सघ को कोई तात्कालिक सैनिक या राजनैतिक खतरा नहीं है। अमेरिका के साथ उलझने और शीतयुद्ध को पुनः तीव्र करने के अवसर आये हैं, लेकिन सोवियत नेताओं ने, स्टालिन के समान, स्थिति का बिगड़ने का प्रयास नहीं किया है। उत्तरी कोरिया में जाँसून और निकसन प्रशासन के समय हुए अमेरिकी जासूमी कांडों के समय भी सोवियत रूस न मध्य ही प्रदर्शित किया और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे युद्ध का खतरा बढ़े अथवा शीतयुद्ध

का प्रसार हो। विघटनात्मक-समस्या पर भी रूस का यही रुख रहा कि वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जाय। उत्तर विघटनात्मक को विशाल सैनिक सहायता देते हुए भी रूसी नेताओं ने ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं किया जिससे अमेरिका के साथ समझौता-वार्ता के द्वार बन्द हो जायें। सन् 1972 में लम्बे गतिरोध के उपरान्त, विघटनात्मक समस्या पर जो पेरिस वार्ता हुई वह बहुत कुछ सोवियत राष्ट्रपति श्री पोंदरेगनी की हनोई यात्रा और अमेरिका तथा रूस की मास्को-शिखर-वार्ता का परिणाम थी और अन्त में विघटनात्मक में युद्ध-विराम में भी सोवियत कूटनीति का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। दोनों देशों के नेताओं द्वारा सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के फलस्वरूप ही सितम्बर, 1971 में 'बर्लिन समझौता' सम्पन्न हो सका। रूस-अमेरिकी सम्बन्धों और उपर्युक्त विशिष्ट समस्याओं पर दोनों देशों के बीच हुए समझौतों आदि पर अमेरिकी विदेश नीति के सम्दर्भ में विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि पश्चिमी एशिया का संकट, जर्मनी की समस्या, निःशस्त्रीकरण का प्रश्न, परमाणु शक्ति का विस्तार आदि सभी पहलुओं पर दोनों पक्षों की ओर से अनुकूल वातावरण बनाने की चेष्टा की जा रही है। सद्य वर्तमान की इस कूटनीति से यही संकेत मिलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सह-अस्तित्व की खडनी हुई भावना के हाथों सुरक्षित है। तनाव के केन्द्र खड़े होते हैं, जैसे दिसम्बर 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान हिन्दमहासागर में अमेरिका और रूसी जहाजों बेड़ों की हलचल से उत्पन्न हुए थे, लेकिन दोनों पक्ष दूरदर्शिता से काम लेकर स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचाने का प्रयास करते हैं। यह विश्व-शान्ति की दिशा में एक शुभ संकेत है।

महाशक्तियों के बीच शीर्षस्थ नेताओं के सम्पर्क में तनाव-बिन्दुओं को शिथिल बनाया है और सह-अस्तित्व के आधारों को विस्तृत किया है। इससे निःशस्त्रीकरण के प्रयामों को भी बल मिला है। 22 मई, 1972 को भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन की मास्को-यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की सोवियत सभ में यह पहली यात्रा थी और इन प्रथम यात्रा के दौरान ही तीनों देशों के बीच कई महत्त्वपूर्ण सन्धियों पर हस्ताक्षर हुए। 23 मई को शिखर-वार्ता में कैनर तथा हृदय रोगों और वायु तथा जल-दूषण के विरुद्ध सघर्ष में सहयोग के लिए दो समझौते हुए और 24 मई को वाह्य अन्तरिक्ष की खोज तथा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग सम्बन्धी दो अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 26 मई को दोनों देशों के बीच 'युद्धिक शस्त्रास्त्र परिसीमन सन्धि' (Strategic Arms Limitation Treaty—SALT) सम्पन्न हुई जिसमें दोनों महाशक्तियों ने एक-दूसरे की शक्ति के सामने झुकते हुए भय मिश्रित आराम विश्वास का एक नया सन्तुलन स्थापित किया। इन सभी सन्धियों का विस्तृत विवेचन संयुक्त-राज्य अमेरिका की विदेश नीति से सम्बन्धित ग्रन्थों में किया जा चुका है। निकसन की यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति गहरी

आस्था व्यक्त करते हुए घोषित किया गया कि सैनिक संघर्ष को टालने के लिए दोनों देश महाशक्ति प्रयत्न करते रहेंगे।

मतभेदों के बावजूद 1972 के वर्ष में दोनों देशों के सम्बन्धों में और अधिक सुधार हुआ। अगस्त, 1972 में सोवियत संघ ने भारी माना में गेहूँ खरीदने के लिए अमेरिका से एक शीर्षकांसीत समझौता किया और 18 अक्टूबर, 1972 को दोनों देशों के बीच हुई एक व्यापारिक सन्धि में रूस ने सहमति व्यक्त की कि द्वितीय महायुद्ध के समय उसने अमेरिका से जो उधार-पट्टा-ऋण लिया था उस राशि को वह चुका देगा। इस सन्धि के बाद हुई एक अन्य सन्धि में यह तय हुआ कि अगले तीन वर्षों में दोनों देशों के आपसी व्यापार में तीन गुना वृद्धि करदी जायगी। ये दोनों व्यापारिक सन्धियाँ इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण थी कि द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध नगण्य थे।

अगले ही वर्ष 18 जून, 1973 को सोवियत साम्यवादी पार्टी के महामन्त्रि ब्रेझ्नेव ने अमेरिका की नौ दिवसीय यात्रा की। हवाई अड्डे पर स्वागत करते हुए निक्मन के कहे कि सैद्धान्तिक मतभेदों और सामाजिक प्रणालियों में अन्तर के बावजूद दोनों देश सामान्य सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। उरत में सोवियत नेता ने कहा कि सोवियत-अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार किसी भी रूप में किसी तीसरे देश के हितों के विरुद्ध नहीं हैं। ब्रेझ्नेव की अमेरिकी यात्रा के समय भी दोनों देशों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। सिद्धान्तन, यह स्वीकार कर लिया गया कि सन् 1974 तक दोनों महाशक्तियों परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर स्थायी रोक लगा देंगी तथा परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पूर्वक काम करेंगी। व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया जिसके कारण अन्य क्षेत्रों में भी परस्पर सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करने का निश्चय किया गया। दोनों देशों के बीच अनिश्चिन्त काल के लिए एक सन्धि भी हुई जिसका उद्देश्य परमाणु युद्ध को रोकना था। सन्धि के अन्तर्गत दोनों पक्षों की ओर से यह सरलप किया गया कि उनमें से कोई भी परमाणु युद्ध नहीं करेगा परस्पर एक-दूसरे को अथवा माथी देशों या अन्य देशों को न तो घमकी देगा और न ही बल प्रयोग करेगा। दोनों देशों ने युद्ध की स्थिति उत्पन्न न होने देने और परमाणु युद्ध भड़क उठने जैसी कार्यवाही न करने का भी संकल्प किया। इन संकल्पों की मायता तो समय की कसौटी पर ही परखी जा सकेगी, लेकिन दोनों महाशक्तियों के शीर्षस्थ नेताओं की इस वार्ता की सज्जे बड़ी उपलब्धि यह थी कि 'युद्ध से नहीं बल्कि आन्तरिक सहयोग से दोनों को लाभ हो सकता है' के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। अगस्त, 1973 में दोनों देशों के बीच पुनः एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सन् 1975 में दोनों देशों द्वारा समुक्त अन्तरिक्ष उड़ानों का कार्यक्रम चालू करने का निश्चय किया गया। आपसी तनाव कम करने और सम्पर्क व सहयोग-सूत्र जारी रखने के लिए 27 जून, 1974 को राष्ट्रपति निक्मन ने पुनः सोवियत संघ की यात्रा की और इस अवसर पर भी दोनों देशों के बीच कुछ समझौते

सम्पन्न हुए। अमेरिका की विदेश नीति के सन्दर्भ में इन सम्मेलनों का विवेचन किया गया है। नवम्बर, 1975 के ब्वाडीवोस्टक में फोर्ड-ब्रेझ्नेव शिखर वार्ता हुई। जुलाई, 1975 में अपोलो-सोयुज समुक्त अन्तरिक्ष कार्यक्रम में दोनों ने सहयोग किया। 1977 की समाप्ति तक दोनों देश सम्बन्ध-सुधार की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील हैं तथापि सम्बन्धों में उतनी सौहार्दता नहीं है जितनी निवसन और फोर्ड प्रशासन के दौरान रही थी।

यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों के साथ भी सोवियत रूस ने सपर्क और सहयोग-सूत्र विकसित करने के प्रयत्न जारी रखे। जून, 1973 में वाशिंगटन से स्वदेश लौटते हुए ब्रेझ्नेव फ्रांस में राष्ट्रपति पोम्पिडू से मिले। फ्रांस ने सोवियत नेता को यह अहंमाम करा दिया कि रक्षा-सेनाओं में कटौती और यूरोप के भविष्य के बारे में वियना के आगामी सम्मेलन में भाग लेने के विषय में भी फ्रांस ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखायी, तथापि दोनों शीर्षस्थ नेताओं के मिलने से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावनाओं को बल मिला। दोनों देशों के सम्बन्ध सुधरते गये और 24 अक्टूबर से 18 अक्तूबर, 1975 तक फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार द एस्नैं ने सोवियत संघ की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा से दोनों देशों के दृष्टिकोणों में अधिक निकटता आयी। वास्तव में फ्रांस और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। इस दोस्ती को मजबूत करने का श्रेय निश्चित तौर पर जनरल डिगॉल को है। जब पश्चिमी यूरोपीय देशों से फ्रांस कुछ अलग गढ़ गया था प्रत्यत् जब फ्रांस ने पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों की अधिक परवाह करनी छोड़ दी थी तब हम और फ्रांस एक-दूसरे के अधिक निकट आये थे। इस बढ़ती हुई निकटता की वजह से ही अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया था। फ्रांस और रूस दोनों देशों के नेताओं ने विश्व की समस्याओं को सुलझाने में गतिशील रवैया अपनाने का संकल्प लिया। वैसे 15 अक्टूबर को मास्को में रूसी नेता ब्रेझ्नेव ने यह बात स्पष्ट कर दी कि पश्चिम के साथ हमारी सैद्धान्तिक लड़ाई बनी रहेगी लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर वे ऐसी नीति अपनानाएंगे जिससे विश्व के सभी देशों में अलगाव के स्थान पर सहयोग की भावना विकसित हो।

जून 1977 में सोवियत साम्यवादी पार्टी के महासचिव ब्रेझ्नेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद भी सभाल लिया। राष्ट्रपति बनने के बाद ब्रेझ्नेव ने सबसे पहली यात्रा पेरिस की की। फ्रांस के राष्ट्रपति वालेरी जिस्कार द एस्नैं से दोनों देशों के सम्बन्धों पर विस्तार से बातचीत हुई। वास्तव में फ्रांस रूस में मित्रता की जड़ें ग्यारह वर्ष पूर्व जनरल डिगॉल ने मजबूत की थी। यही वजह है कि फ्रांस को रूस यूरोप में एक महत्त्वपूर्ण मित्र और भागीदार मानता है। डिगॉल द्वारा रूस की ओर झुकने का कारण अमेरिका से अनुरक्त थी। नाटो के सम्बन्ध में फ्रांस और अमेरिका के दृष्टिकोण में मतभेद वैधानिक नहीं हैं लेकिन उस तरह की सम्भावना भी नहीं है जो जॉन फेंगेडी के समय थी। इसके अतिरिक्त अमेरिका के नये राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा मानवाधिकार की परिभाषा के प्रश्न पर दोनों देश निकट आने के

बजाम दूर हुए हैं। काटें ने रूस के दो प्रसन्तुष्ट साहित्यकारों को जो पत्र लिखे तथा रूस में मानवाधिकारों के उल्लंघनों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिये उससे भी दोनों देशों के बीच खाई चौड़ी हुई है। परमाणु अस्त्रों के विस्तार पर रोक लगाने सम्बन्धी वार्ता में जिसे 'साहट' भी कहते हैं। अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधि मण्डलों में उस तरह की सद्भावना दिखायी नहीं दी जो रिवरडे निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के प्रशासन काल में रूसी और अमेरिकी नेताओं के बीच रही थी। राजनीतिक प्रेक्षकों की यह भी मान्यता है कि देना की जड़ें भी कमजोर हुई हैं। अमेरिका और रूस के सम्बन्धों में जो दुराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी है उसको देखते हुए ब्रेझ्नेव ने एक बार फिर फ्रांस के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की।

फ्रांस के अलावा पश्चिम जर्मनी के साथ भी रूस के सम्बन्ध सुधरे हैं। वास्तव में पश्चिम जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर (प्रधानमंत्री) विलि ब्रॉट ने पूर्वी और पश्चिमी देशों में सद्भावना की जो शुरुआत की थी यह उसका प्रतिफल है। इस दिशा में लियोनिद ब्रेझ्नेव का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि फ्रांस के अलावा पश्चिम जर्मनी के साथ वह अपने सम्बन्धों को अच्छे और महत्त्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन रूसी नेता की इन पश्चिमी देशों के राजनेताओं से इतनी शिकायत नहीं जितनी साम्यवादी पार्टी से है। यूरोप में साम्यवादी पार्टियों का जिस तरह विकास हो रहा है। उससे सोवियत नेता अधिक खुश नहीं हैं। स्पेन, इटली और फ्रांस की साम्यवादी पार्टियों ने सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी से अलग रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। इससे सोवियत संघ हीनता का अनुभव करता है। शायद यही कारण था कि पेरिस में होने हुए भी ब्रेझ्नेव फ्रांसीसी साम्यवादी पार्टी के नेता जार्ज मार्श से नहीं मिले। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। शायद इन नेताओं की आकांक्षा है कि यदि सोवियत संघ पश्चिमी देशों के प्रति उदार नीति अपना रहा है तो इस तरह की नीतियां अपनाने का अवसर हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया आदि देशों को भी दिया जाना चाहिए।

रूस और बंगलादेश—बंगलादेश के प्रति रूस की आरम्भ से ही सहानुभूति रही। बंगलादेश के मुक्ति-संघर्ष के लिए रूस ने अपना नैतिक और राजनीतिक समर्थन दिया और एक स्वाधीन गणराज्य के रूप में बंगलादेश का उदय होते ही उसे मान्यता प्रदान की। यही नहीं, रूस ने बंगलादेश के आर्थिक पुनर्निर्माण में रुचि लेकर पारस्परिक आयात-निर्यात सम्बन्धी समझौता भी सम्पन्न किया। मार्च, 1972 में शेख मुजीब ने सोवियत संघ की यात्रा के समय रूसी नेताओं से महत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता भी हुआ जिसके अन्तर्गत रूस ने बंगलादेश को 3 अरब 33 करोड़ रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया। रूस ने यह आश्वासन भी दिया कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ में बंगलादेश को प्रवेश दिलाने का पूरा प्रयत्न करेगा।

विश्व संस्था में बंगलादेश के प्रश्न पर जो संधर्ष हुआ उसमें रूस ने बंगलादेश को पूर्ण समर्थन दिया था।

रूस और जापान—द्वितीय महायुद्ध के शत्रु इन दोनों राष्ट्रों में विगत कुछ वर्षों से परस्पर निकट आने की उत्सुकता होती जा रही है। जापान के कुछ राजनीतिक क्षेत्रों का तर्क है कि रूस के साथ आर्थिक सहयोग न बढ़ाया जाए अन्यथा चीन की नाराजगी बढ़ेगी जिससे जापान के लिए कुछ अन्य आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी, लेकिन अधिसूक्ष्म राजनीतिक क्षेत्र का विश्वास है कि सोवियत संघ के साथ आर्थिक सहयोग जापान के हित में है। इससे जापान की स्थिति काफी सुहृद होगी और चीन जापान से सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न करेगा।

रूस और भूमध्यसागर—पश्चिमी एशिया पर अपना प्रभाव जमाने के लिए रूस प्रारम्भ से ही भूमध्यसागर में प्रवेश का इच्छुक रहा है और जून, 1967 के अरब-इज़रायल-संधर्ष के बाद से सोवियत संघ के नौसैनिक बेड़े को इस सागर में अपने विस्तार के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा अवसर सुलभ हो गए हैं। रूसी प्रयत्न यह है कि इस क्षेत्र में उसके समर्थक देश भूमध्यसागर में अमेरिका की उपस्थिति समाप्त करने की नीतियाँ अपनाएँ। सोवियत संघ चाहता है कि वह भूमध्यसागर के तटवर्ती देशों की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पूर्वी यूरोप के देशों जैसी ही बनादे ताकि इन देशों के साथ मास्को के सम्बन्ध पूर्वी यूरोप के देशों जैसे हो जाएँ। भूमध्यसागर में अधिकाधिक प्रवेश से सोवियत संघ ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काफी वृद्धि कर ली है और यदि इस क्षेत्र की उप्रति के बारे में कोई योजना सामने आए तो सोवियत संघ का इसमें महत्वपूर्ण स्थान होगा।

सोवियत रूस और एशियायी सुरक्षा तथा एशिया में रूसी लक्ष्य—एशिया में अपने प्रभाव-क्षेत्र के विस्तार के लिए सोवियत कूटनीति ने हाल ही के कुछ वर्षों में 'ब्रेक्नेववाद' का सहारा लिया है। यह विचार सन् 1969 में सोवियत नेता थो ब्रेक्नेव ने रखा था जिसमें अस्पष्ट रूप से एशियायी देशों के लिए एक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। सन् 1972 में इस योजना को पुनः प्रस्तुत किया गया और अकगान-प्रधानमन्त्री के स्वागत पर बोलते हुए कोसीगिन ने कहा—'एशिया की सुरक्षा का सही उपाय सैनिक गुट नहीं है और न ही कुछ राष्ट्रों द्वारा दूसरे का विरोध करना, बल्कि यह उपाय देशों के बीच अच्छे पड़ोसी का वातावरण पैदा करना है।' पर साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि शान्ति स्थापित करने का सोवियत संघ का तरीका सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा—'सोवियत विदेश-नीति को सबसे महत्वपूर्ण दिशा राष्ट्रों की आजादी और स्वशासन का अतिक्रमण करने वाले साम्राज्यवादियों को पराजित करने के लिए युद्ध और संघर्ष स्थलों को समाप्त करना है।' इस व्याख्या से यह धारणा होता है कि रूसी नेताओं का सुरक्षा सिद्धान्त एक नया 'पंचशील' होने के बावजूद सैनिक हस्तक्षेप या सैनिक समाधान से रहित नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि ब्रेक्नेव अथवा कोसीगिन ने एशियायी सुरक्षा की इस योजना को यहीं तक सीमित रखा, लेकिन उनके सलाहकारों और प्रतिनिधियों ने योजना को स्पष्टतः पश्चिम-विरोधी रंग दिया। सोवियत

प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य प्रो. गफरोव ने इस सुरक्षा-योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिन्द-महासागर चारों ओर से साम्राज्यवादियों के सैनिक अड्डों से घिरा हुआ है, अतः सभी शांति-प्रिय देशों की सामरिक सुरक्षा आवश्यक है। नवम्बर 1973 में अपनी भारत-यात्रा के समय ब्रेज्नेव ने पुनः एशियायी सामूहिक सुरक्षा योजना पर चर्चा की। भारत ने अभी इस योजना के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना साकार रूप ले सकेगी।

एशियायी देशों के प्रति सोवियत मंत्री और सहयोग स्वागत योग्य है तथापि एशिया के देशों को इस का सही सदर्पारामर्श प्रेषित है कि वे किसी भी प्रकार की सैनिक गुटबन्दी में न उलझे। हाल ही के कुछ वर्षों में एशिया में नए शक्ति-सन्तुलनों का विकास हुआ है। ब्रेज्नेव सिद्धान्त में एशियायी सुरक्षा-व्यवस्था तो निहित है, पर साथ ही इसके लक्ष्य अमेरिका और चीन भी हैं। पुनश्च, रूस हिन्दमहासागर पर अपने प्रभाव का आकांक्षी है। 15 सितम्बर, 1970 के 'लन्दन टाइम्स' ने इस क्षेत्र में रूसी लक्ष्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा था—“हिन्दमहासागर में रूसी नौसेना की मौजूदगी का मुख्य कारण पश्चिमी स्वार्थों को चुनौती देना नहीं बल्कि चीन के विरुद्ध भारत को समर्थन देना और सामान्यतः एशिया तथा अफ्रीका में चीनी प्रभाव को रोकना है।” रूस इस तथ्य से परिचित है कि हिन्दमहासागर पर त्रिमन्त्र नियन्त्रण हो जाएगा उसी का प्रभाव प्रशान्त महासागर पर भी शीघ्र ही पड़ने लगेगा। एशिया में अपने पैर गंजवूत करने के लिए हिन्दमहासागर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ-साथ रूस ने दक्षिण-पूर्व के देशों के साथ भी अपने सम्बन्ध तेजी से सुधार लिए हैं।

वियतनाम के प्रति सोवियत नीति—30 अप्रैल, 1975 को वियतनाम-युद्ध की समाप्ति और वहाँ से अमेरिका के पलायन के बाद वियतनाम की संपूर्ण कहानी समाप्त हो चुकी है। दक्षिण और उत्तर वियतनाम के संपर्क में साम्यवादी शक्तियाँ उत्तरी वियतनाम की पीठ पर रही थी। सोवियत रूस ने वियतनाम का भरपूर सैन्य-सामग्री पहुँचाई। अनुमानतः उत्तर वियतनाम को दी जाने वाली सैन्य-सहायता में रूस का भाग 80 प्रतिशत और चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों का लगभग 20 प्रतिशत था। उत्तर वियतनाम को लगभग 10 अरब डॉलर की सहायता रूस और चीन से मिली जो दक्षिण वियतनाम को अमेरिका से मिलने वाली सहायता की तुलना में काफी कम थी। सोवियत नीति वियतनाम-संपर्क के शान्तिपूर्ण समाधान की थी और सन् 1972 में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने अपनी हवाई यात्रा में उत्तर वियतनामी नेताओं को इस बात के लिए सहमत किया कि वे शान्ति-वार्ता का द्वार खुला रहें। रूस-अमेरिका के समझौताबारी एवं और वियतनाम के सम्बन्धित पक्षों के विवेक के फलस्वरूप जनवरी 1973 में युद्ध-विराम हुआ और ऐतिहासिक वेरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन जनवरी, 1976 में वेरिम समझौता भंग हो गया तथा वियतनाम-युद्ध पुनः भड़क उठा। अन्त में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की अन्तिम विजय के साथ ही वियतनाम-युद्ध समाप्त हो गया। सोवियत भूमिकाओं की इस दृष्टि से सराहना की जाएगी कि अमेरिका के समान सोवियत सैनिकों ने उत्तर

वियतनाम की ओर से युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया और इस प्रकार वियतनाम-युद्ध के विस्तार को सीमित रखा।

सोवियत रूस और अरब जगत्—पश्चिमी एशिया से ब्रिटेन के हटने के बाद से ही यह क्षेत्र रूस और अमेरिका के प्रभाव-विस्तार का बड़का दानता जा रहा है। रूसी नीति अरब राष्ट्रों को कूटनीतिक, आर्थिक और सैनिक सहयोग देने की रही है जबकि अमेरिका इजरायल को हर प्रकार की सहायता देता आया है। सन् 1948 के फिलिस्तीनी संघर्ष में रूस ने इजरायल का समर्थन करते हुए अरब-आक्रमण की निन्दा की थी लेकिन इसके बाद रूस ने अनुभव किया कि मध्यपूर्व के अरब राष्ट्रों के लिए रूसी सहयोग के द्वार खुल गए और बाद के सभी अरब इजरायल संघर्षों में रूस अरबों के पक्ष में रहा। सन् 1967 के युद्ध में अरबों की घोर पराजय हुई और वे इस बात पर क्रुद्ध थे कि अरब देशों को सोवियत संघ का वाञ्छित सैनिक समर्थन नहीं मिल सका। अतः अरबों को प्रसन्न करने के लिए ही जून, 1967 में सोवियत राष्ट्रपति ने स्वयं काहिरा पहुँच कर संयुक्त अरब गणराज्य को आधुनिकतम शस्त्रास्त्र देने का आश्वासन दिया। सितम्बर, 1967 में रूस ने एक शान्ति-योजना प्रस्तावित की जो इजरायल ने स्वीकार नहीं की। 28 मई, 1971 को मिस्र और रूस के बीच एक 15 वर्षीय मंत्री-सन्धि सम्पन्न हुई, लेकिन सन् 1972 में दोनों देशों के सम्बन्धों में तनाव घा गया और जुलाई में राष्ट्रपति सादात ने रूसी सैनिक विशेषज्ञों को मिस्र छोड़ देने का आदेश देकर रूस की आघात पहुँचाया। मिस्र का आरोप था कि रूस ने उसे अति-आधुनिक हथियार नहीं दिए। विगाड का यह दौर अधिक नहीं चला और जब अक्टूबर, 1976 में चौथा अरब-इजरायल युद्ध हुआ तो अरबों ने रूसी शस्त्रास्त्रों की सहायता से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्ति कर ली।

युद्ध-विराम के बाद अमेरिका तथा सोवियत रूस के प्रयास से 21 दिसम्बर, 1973 को जेनेवा में पहली बार अरब-इजरायल शान्ति वार्ता आरम्भ हुई। सीरिया ने इसमें भाग नहीं लिया। मिस्र तथा इजरायल के बीच स्वेज क्षेत्र से सेना पीछे हटाने पर समझौता हो जाने के बाद सीरिया तथा इजरायल के बीच गोलन क्षेत्र में भी सेना को पृथक् करा दिया गया। सन् 1974 में सोवियत रूस तथा अमेरिका की ओर से समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए लगातार प्रयत्न किए जाते रहे। इस बीच अरब देशों ने तेल का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर तेल के लिए अरब देशों पर निर्भर रहने वाले अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इस नए राजनीतिक अस्त्र के प्रयोग से यूरोप के देशों ने इजरायल के समर्थन में ढील दिखाई और वे अरब देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने को उत्सुक दिखाई देने लगे। अरब-इजरायल समस्या के समाधान में अमेरिका रूस से बाजी मार ले गया और अनेक अरब नेता उत्पादक देशों ने सन् 1974 में अमेरिका पर से तेल सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठा लेने का निश्चय कर लिया। अमेरिकी विदेश-नीति के अध्याय में बताया जा चुका है कि सितम्बर, 1975 में अमेरिका, अरब और इजरायल के बीच एक अन्तरिम समझौता कराने में सफल हुआ। मिस्र पर प्रभाव के सन्दर्भ में रूसी कूटनीति अन्ततोगत्वा अमेरिकी कूटनीति के समक्ष

परास्त हो गई लगती है जिसका सबसे उच्चतम प्रमाण यह है कि 14 मार्च, 1976 को मिस्र के राष्ट्रपति अन्नवर सादात ने सोवियत संघ से अपनी पाँच वर्षीय मैत्री-सन्धि को भंग कर दी। सादात की इस कार्यवाही से विश्व के राजनीतिक क्षेत्रों में कई तरह की प्रतिक्रिया हुई। सोवियत संघ ने मिस्र की इस कार्यवाही की प्रालोचना की जबकि अमेरिका, इजरायल, चीन आदि देशों में इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। सादात की इस कार्यवाही से निश्चित रूप से रुस के हितों को ठेस पहुँची है। क्या इस सन्धि के भंग होने का प्रभाव अरब जगत् के अन्य देशों पर भी पड़ेगा—यह तो बतलाना पड़ेगा लेकिन मिस्र के विदेशमन्त्रियों ने यह जरूर कहा है कि मैत्री-सन्धि में हथियारों के फालतू पुर्जों देने की जो पारा दर्ज थी उन पर असर न होने के कारण ही इस मैत्री सन्धि को भंग किया गया है।¹ राष्ट्रपति सादात ने मिस्र की 360 सदस्यीय समूह में अपने नीति उद्देश्यों वक्तव्य में कहा कि “यह सोवियत संघ के विल्टो-चूहे सेल से लय आकर पाँच परब टॉनर के जूए की पुनः व्यवस्था में भी अभिक्रम रहा था। अब स्थिति यह है कि हमारे 18 महीनों में सोवियत सैनिक साजसामान मिस्र के लिए कबाड़ बन कर रद्द हो गए। जब उन्हें सन्धि के अनुसार फालतू पुर्जें नहीं मिलते हैं तो इस सन्धि का उनके लिए कायम के एक टुकड़े से अधिक महत्व नहीं है और कायम के इस टुकड़े को हम अपने पास नहीं रखना चाहते।”²

मिस्र और सोवियत संघ के इस सन्धि-विच्छेद का प्रभाव अन्य अरब देशों पर कम के प्रतिकूल नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ रुस की घनिष्ठ मित्रता बनो रही है। रुस के अरब दोस्तों में इराक, लीबिया, सीरिया आदि प्रमुख हैं। लीबिया और मिस्र में घनबल है और यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि 14 मार्च 1976 को तो मिस्र सोवियत संघ-समझौता भंग हुआ और उसके पहले 7 मार्च को ही सोवियत संघ ने लीबिया को 25 मिल-25 लड़ानू विमान देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा सोवियत संघ ने लीबिया को प्रतिस्पर्धन अवसरों प्रदान करने के सम्बन्ध में भी समझौता किया। सीरिया और सोवियत संघ की मैत्री भी काफी सुदृढ़ हुई है। जोर्डन भी जिस प्रकार सोवियत संघ के निकट आया उसमें अमेरिका की साकुपता बड़ी। जोर्डन में सन् 1976 के प्रारम्भ में रुस-निर्मित सैन्य विमानक्षेत्र प्रक्षेपास्त्र जार्डन लगाए गए—यह दोनों देशों की बढती हुई मैत्री का प्रमाण है। इसके अलावा जितिल्लीवी छापाकारों को सभी आप्रानिक हथियारों से न केवल रुस लेंस करता है बल्कि उनके लिए अन्य कई प्रशिक्षण केंद्र भी अरबों की भूमि या सोवियत संघ में स्थित हैं। कुवैत का भुकाव भी रुस की ओर ही रहा है। 7 मार्च 1976 को कुवैत में भी रुस से हथियार लेने के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोमालिया में भी रुसी प्रभाव बढ़ रहा है और वहाँ पर रुसी शासन स्थापित किए जाने की भी चर्चा है। अल्जीरिया में भी रुस के प्रति रुचि बढी है। अतहादपर में रुस की सहायता से एक इस्लामिक सरकार का लया गया है।

सन् 1977 में रुस और मिस्र के सम्बन्धों में सुधार के लक्ष्य दिए हैं। समय

की आवश्यकता महसूस करने हुए मिस्र और सोवियत संघ ने अपने बिगड़े हुए सम्बन्धों में सुधार लाने की दिशा में काम करना शुरू किया है। मिस्र के विदेशमन्त्री इस्माइल फाहमी ने मास्को की तीन दिन की (9 से 11 जून, 1977) राजकीय यात्रा की। अपनी इस यात्रा के समय दोनों विदेशमन्त्रियों ने बीती ताहि बिसार दे को आधार बना कर बातचीत की। यद्यपि कोई ठोस और रचनात्मक आधार स्थापित नहीं हो सका, तथापि इस तरह के सकेत जरूर मिलते हैं कि तीन वर्षों बाद दोनों देशों का यह मिलन व्यर्थ तथा प्रभावहीन नहीं रहा है। रूसी नेता शायद यह मानते हैं कि मिस्र और सोवियत संघ में गलतफहमी बढ़ाने में निकोलाई पोदगर्नो ने भूमिका निभाई थी और अब परिवर्तित हुए सन्दर्भों में उस प्रतीतिकर स्थिति को सद्भावना और नैत्री में बदलना चाहते हैं। आज भी मिस्र के पास उसके प्रस्थ भण्डारों में काफी बड़ी सख्या में रूसी विमान और सैनिक साज समान भरा पड़ा है। पुराने और अतिग्रस्त हथियारों की मरम्मत के लिए इस मिस्र की सहायता कर सकता है। तीन वर्ष पहले उसने जो अति-आधुनिक हथियार चाहे थे उनकी पूर्ण या आंशिक पूर्ति भी कर सकता है। मिस्र में मुद्रास्फीति की स्थिति है अतः रूसी नेताओं ने उसकी आर्थिक सहायता का भी इस्माइल फाहमी को विश्वास दिलाया। रूसी नेताओं ने उसकी सहायता से बने इस्पात कारखाने के लिए पाँच लाख से सात लाख टन प्रति वर्ष कोयला देने की बात भी मान ली है। राष्ट्रपति ब्रेझ्नेव ने इस्माइल फाहमी को स्पष्ट तौर पर यह विश्वास दिलाया कि वह रूस-मिस्र सम्बन्धों में पूरी तरह से सुधार करने के लिए तैयार है। निस्संदेह आज से सात साल पूर्व की सद्भावना दोनों देशों में उत्पन्न नहीं हो पायी है लेकिन उस तरह की कटुता भी नहीं है जो तीन वर्ष पहले उत्पन्न हो गई थी। मिस्र और सोवियत संघ को निकट लाने में जेयरे के राष्ट्रपति मोबुतु और सूडान के राष्ट्रपति नुमेरी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

मिस्र के राष्ट्रपति अन्वर सादात के अनुसार रूसी नेताओं और विदेशमन्त्री इस्माइल फाहमी की बातचीत को सफल नहीं माना जा सकता। उन्होंने एक लेवनाली पत्र को बताया कि हमारी तीन मुख्य मांगें थी। अतिरिक्त पुर्जों की मांग, ऋण का पुनर्निर्धारण तथा नए आधुनिक हथियारों की सप्लाई। इन तीनों ही मुद्दों पर रूस ने किसी प्रकार की प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की। रूसी नेताओं ने केवल मुस्करा कर यही कहा कि इस दिशा में नए सिरे से सोच विचार किया जाएगा। रूस और मिस्र में परस्पर सशय की जो शुरुआत तीन वर्ष पहले हुई उसको इतनी जल्दी सद्भावना में बदल देना कठिन दिखाई देता है। राष्ट्रपति सादात ने यह बात भी साफ तौर पर कही थी कि बड़ी शक्तिशाली अरब और अफ्रीकी देशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न ही वह चाहते हैं कि जेयरे जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो। रूस इथियोपिया और लीबिया को जिस तरह हथियारों से लैस कर रहा है उससे अरब राष्ट्र सशक्त हैं। यही कारण है कि वे बार-बार यह कहते हैं कि लाल सागर केवल अरबों के लिए ही सुरक्षित होना चाहिए। अरबों का तो यहाँ तक मानना है कि लीबिया और मिस्र तथा लीबिया और सूडान की सीमाओं पर कूबा के सैनिक तैनात

हैं। ऐसा क्यों? राष्ट्रपति सादात ने तो यहाँ तक सन्देह व्यक्त किया है कि रुस तथा उसके समर्थक देश मिस्र को अपने पड़ोसी देशों से पृथक् कर देना चाहते हैं। हम की इस तरह की धारणा के बीछे अमेरिका की पश्चिमी एशिया सम्बन्धी नीति है। परन्तु यह भी मानते हैं कि पश्चिमी एशिया की समस्या का 90 प्रतिशत समाधान केवल अमेरिका ही कर सकता है। राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने फिलीस्तीनीयों के लिए पृथक् राज्य की माँग का समर्थन किया है।

रुस-टर्की मैत्री का शुभारम्भ—सन् 1975 का वर्ष सोवियत मघ और टर्की के सम्बन्धों में मैत्री और सहयोग के स्वरूप का नया अध्याय जोड़ने के साथ समाप्त हुआ। वर्ष के अन्तिम दिनों में सोवियत प्रधानमंत्री कोसीगिन लगभग 10 वर्ष के अन्तराल के बाद पुनः टर्की गए और उन्होंने चार दिन (26 से 29 दिसम्बर, 1975) के अकारा-प्रवास काल में दोनों देशों की मित्रता का शिलान्यास किया। 28 दिसम्बर, 1975 को सोवियत प्रधानमंत्री ने टर्की के भूमध्यसागरीय बन्दरगाह मिस्त्रिया में सोवियत महाप्रता से निर्मित इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया। अकारा-प्रवास काल में कोसीगिन ने तुर्की के प्रधानमंत्री सुलेमान दमिरेल तथा अन्य प्रमुख नेताओं से विस्तृत विचार-विमर्श किया। उनकी यात्रा की समाप्ति पर जो संयुक्त बक्तव्य प्रसारित किया गया वह इस तथ्य का खोजक है कि कोसीगिन ने अपनी बी वर्ष पहले की तुर्की यात्रा के दौरान दोनों देश के सम्बन्ध सुधारने की दिशा में जो पहल की थी उसमें अन्ततः उन्हें सफलता मिली। संयुक्त बक्तव्य में कहा गया, "दोनों पक्ष तुर्की और सोवियत मघ के बीच मैत्री और सहयोग सम्बन्धी एक राजनीतिक दस्तावेज तैयार करने पर सहमत हो गए हैं। इस दस्तावेज पर निबट अभिप्रेम से होन वाली एक उच्चस्तरीय बैठक में हस्ताक्षर किए जाएंगे।"¹ संयुक्त बक्तव्य में यह नहीं बताया गया कि प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेज के मुद्दे क्या होंगे।

रुस के साथ मैत्री के शुभारम्भ से यह धर्म नहीं लेना चाहिए कि टर्की और अमेरिका के बीच मैत्री सम्बन्ध भीके पड़ गए हैं। 26 मार्च, 1976 को वाशिंगटन में टर्की और अमेरिका के बीच एक चार वर्षीय सैनिक समझौता हुआ (जो अमेरिकी कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त होने पर लागू होगा) जिसका मुख्य मुद्दा यह है कि इस वर्ष के अन्त तक टर्की अपने यहाँ स्थित अमेरिका के उन 26 हवाई अड्डों और गुप्तकर्मियों को फिर खोल देगा जिन्हें उसने पिछले वर्ष जुलाई में अमेरिका से भगवा हो जाने पर बन्द कर दिया था। बदले में अमेरिका उसे अगले चार वर्ष में एक अरब डॉलर में भी अधिक की सैनिक सहायता देगा। साथ ही, अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक से भी उसे भारी मात्रा में ऋण मिलेगा। रुस के साथ बढ़ने हुए सम्बन्धों से टर्की की नाटो की सदस्यता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नाटो और अमेरिका की प्रतिरक्षा की व्यवस्था के लिए टर्की का आवश्यक महत्त्व है और

इसीलिए अमेरिका किसी भी मूल्य पर टर्की को सोवियत गुट में न जाने देने के लिए कटिबद्ध है।

पश्चिमी जर्मनी के साथ समझौता—शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का उपयोग करते हुए सोवियत रूस ने पश्चिमी जर्मनी के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार किया है यूरोप में तनाव कम करने की दिशा में पश्चिमी जर्मनी के चांसलर श्री विली ब्रांट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामान्य सम्बन्ध बनाने की आकांक्षा से ही 12 अगस्त, 1970 को मास्को में विली ब्रांट तथा कोसीगिन ने एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे 'मास्को-बोन सन्धि' कहा जाता है। युद्धोत्तरकाल में सोवियत कूटनीति की यह सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इस सन्धि से सोवियत संघ को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि बोन ने जर्मनी की वर्तमान सीमाओं को मान्यता प्रदान कर दी जिसका स्पष्ट आशय है कि बोन सरकार ने पहली बार पोलैंड तथा पूर्वी जर्मनी की ओडरनिसी नदी सीमा को स्वीकार कर लिया है तथा यह भी माना है कि युद्ध पूर्व के जर्मनी के वे क्षेत्र जो ओडरनिसी नदियों के पूर्व में थे—पोलैंड के अथ हैं, लेकिन ओडरनिसी सीमा रेखा को मान्यता देने का यह अर्थ नहीं है कि पश्चिमी जर्मनी ने पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता दे दी है। इस सन्धि में निहित अर्थ यही है कि पश्चिमी जर्मनी ने जर्मनी के पूर्वी भाग पर एक अलग सरकार के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। पश्चिमी जर्मनी के साथ यह समझौता यूरोप में एक आम समझौते और शान्ति का आधार बन सकता है। यूरोप में शान्ति होने पर ही सोवियत रूस अपनी शक्ति को चीन के विरुद्ध लगा सकेगा।

शान्ति की दिशा में तब एक कदम और आगे बढ़ा गया जब 3 सितम्बर, 1971 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते का वर्णन अमेरिकी विदेश-नीति के सन्दर्भ में किया जा चुका है। समझौते की कुछ सामान्य धाराओं से यह स्पष्ट है कि बर्लिन के कानूनी स्तर और चारों राष्ट्रों की स्थिति पर इस समझौते की शर्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य व्यावहारिक धाराएँ इन बातों से सम्बन्धित हैं—(1) बर्लिन तक और बर्लिन से अतिरिक्त यातायात, (2) सशस्त्र जर्मनी के साथ पश्चिमी बर्लिन के सम्बन्ध, (3) बर्लिन के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र तथा पूर्वी जर्मनी के साथ संचार-सम्बन्ध, एवं (4) बर्लिन का विदेशों में प्रतिनिधित्व। बर्लिन में प्रवेश के प्रश्न पर चारों राष्ट्रों ने तय किया है कि पूर्वी जर्मनी के मार्ग से यातायात बे-रोकटोक होगा और यह यातायात सीधे सामान्य ढंग से होता रहेगा। अभी तक बर्लिन यातायात में पूर्वी जर्मन अधिकारियों द्वारा बाधा डाली जाती थी जिससे गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाते थे। अगस्त, 1961 में बर्लिन दीवार बन जाने के बाद से ही पूर्वी जर्मन अधिकारियों ने पश्चिम बर्लिनवासियों पर नगर के पूर्वी भाग में अपने सम्बन्धियों और मित्रों से मिलने पर प्रतिबन्ध लगा रखे थे।

रूस-अफ्रीका : बदलते समीकरण

सन् 1977 के प्रथम चरण में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलाई

पोदगर्नी ने अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण देशों की यात्रा की। अपनी 12 दिवसीय यात्रा में पोदगर्नी ने तांजानिया, जाम्बिया, मोजाम्बिक और सोमालिया के नेताओं से परस्पर सम्बन्धों तथा अफ्रीकी समस्याओं पर वार्ता की। इस यात्रा का उद्देश्य अफ्रीका के इन महत्वपूर्ण देशों को रूस द्वारा आर्थिक, सामरिक सभी तरह की सहायता का आश्वासन था। रूस के किसी बड़े नेता की यह पहली अफ्रीकी-यात्रा थी। इसीलिए इस यात्रा का विश्व की बड़ी शक्तियों ने ही नहीं, विकासशील देशों ने भी बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। पोदगर्नी ने अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों से सम्बन्धित कुछ नेताओं से भी बातचीत की जैसे जिबाब्वे अफ्रीकी सच के (जापू) जोशुआ म्कोमो, दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी सगठन (स्वापो) के अध्यक्ष साम नूजोमा और दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ए. एन. सी.—एस. ए.) के अध्यक्ष बलाइवर टाबो। इन नेताओं से पोदगर्नी की सुसाका में बातचीत हुई। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि सोवियत सच दक्षिण अफ्रीका के उपनिवेशवाद और जातिवाद के के इस आखिरी 'घट्टे' को हमेशा के लिए मिटा देता अपना महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व मानता और समझता है। सोवियत जनता भविष्य में दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति के लिए सघर्षरत लोगों को अपना स्थायी समर्थन प्रदान करेगी। उन्होंने इस समाचार को निराधार बताया कि उनकी इच्छा किसी भी अफ्रीकी देश में किसी प्रकार का सैनिक अड्डा स्थापित करने की है। रूसी सहायता का अर्थ दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है।

अफ्रीका महाद्वीप के देशों में सभी बड़ी शक्तियाँ चीन, अमेरिका और सोवियत सच अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा अपने प्रतिनिधि एड्रू यंग को अफ्रीकी देशों की यात्रा पर भेजने का उद्देश्य कालो का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना था। उसके बाद वेपर्ड विधेयक में सशोधन कर उन्होंने अपने आश्वासन को विश्वास का रूप दे दिया। इस कानून के स्वीकृत होने से अमेरिका रोडेशिया से क्रोम और क्रोम उत्पाद नहीं खरीदेगा। निकोलाइ पोदगर्नी ने इन देशों को यंग जैसा विश्वास तो दिलाया ही रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रीय मोर्चों को भी धन और शस्त्र दोनों को देने का वायदा किया। सोवियत नेताओं की मान्यता है कि पश्चिमी देश रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीका में बहुसरयक कालो को सत्ता सौंपने के प्रयास में ईमानदारी का रवैया नहीं अपना रहे हैं। अगर ऐसा होता तो जिनेबा सम्मेलन के कुछ न कुछ परिणाम प्रवश्य निकलते। अमेरिका के प्रभाव को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से रूसी नेता के भावसंवादी देशों को अपनी रस्ते का पूरा यकीन दिलाना चाहते हैं। उन्होंने इथियोपिया और सोमालिया को इस तरह का विश्वास दिलाया है। सम्भवतः सोवियत सच के आग्रह पर ही फिडेल कास्त्रो ने सोमालिया की यात्रा की थी। शायद यही कारण है कि बरबरा स्विट सोमालिया में रूसी साज-सामान जैसे एक हवाई अड्डा, एक शुष्क बंदरगाह, ईंधन टैंक, संचार-केन्द्र तथा अस्त्र भण्डार आदि अधिक हैं। अन्य कई देशों में रूसियों को

‘सुविधाएँ’ तो अवश्य प्राप्त हैं लेकिन अमेरिका की भाँति उनके प्रड्डे नहीं हैं। अंगोला में युद्ध का समर्थन करने के लिए रूस ने कोनाकरी, गिनी और पोर्टो-नोमर (कांगो) बंदरगाहों का प्रयोग किया था। जब उगांडा में ईदी अमीन ने अमेरिकियों के प्रति जेहाद छेड़ा था तो अमेरिका ने मोबासा और केन्या स्थित अपने अड्डों को सतर्क कर दिया था। उगांडा को रूस का मित्र माना जाता है। कुछ प्रेक्षकों का यह भी मत है कि रूसी सक्रियता का कारण अफ्रीकी बंदरगाहों में अमेरिकी और पश्चिमी देशों के अर्सेनिक वेडो पर दृष्टि रखना है। लेकिन इस तरह के विचार को उन्नीसवीं सदी की विचारधारा माना जाता है। आज तो किसी एक देश का दूसरे देशों के जहाजों से टकरावका अर्थ युद्ध है। यही कारण है कि आज कोई देश इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते। आजकल आर्थिक व सामरिक सहायता तथा लम्बी अवधि के समझौतों द्वारा बड़ी शक्तियाँ छोटे तथा गरीब और विकासशील देशों में अपना प्रभाव स्थापित रखना चाहती हैं।

राष्ट्रपति पोदगर्नी ने तांजानिया की राजधानी दारेस्सलाम से अपनी चार दिवसीय यात्रा (23 मार्च से 26 मार्च, 1977) शुरू की। उन्होंने राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे को यह स्पष्ट रूप से कहा कि सोवियत संघ किसी तरह की रियायतें, सैनिक प्रड्डे और विशेषाधिकार न तो किसी अफ्रीकी देश में और न ही अन्य कहीं चाहता है। इस तरह की अपवाह पश्चिमी देशों की ‘शरारत’ है। हम समान सहयोग के आधार पर मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य निजी स्वार्थ नहीं बल्कि पूरी मानव स्वामीयता और शान्ति स्थापना का प्रयास है। सोवियत संघ और तांजानिया साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समान हितों की दिशा में प्रयास करने के लिए संकल्पित है। तांजानिया ने कभी चीन से बहुत अच्छे सम्बन्ध थे और चीन ने उसे 35 करोड़ 80 लाख डॉलर की सहायता दी थी जबकि रूस और अमेरिका से कुल 20 करोड़ डॉलर की सहायता मिली। बहुचर्चित तान-जा रेल भी चीन की सहायता से बन रही है। इस बात की भी चर्चा है कि पोदगर्नी की यात्रा ढाई वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन रूस द्वारा दीर्घकालीन मैत्री समझौते पर जोर और न्येरेरे की इकारी की वजह से यह सम्भव नहीं हो सकी। पोदगर्नी की इस यात्रा काल में तांजानिया क्रान्तिकारी पार्टी के क्षेत्रीय सचिव अन्दुल पर सुलेमान का यह वक्तव्य महत्वपूर्ण था—“अफ्रीका यह सोच रहा है कि समाजवादी सत्ता से सहयोग के बिना न तो साम्राज्यवाद का प्रभावकारी प्रतिरोध किया जा सकता है और न ही आर्थिक विकास सम्भव है।”

तांजानिया के बाद पोदगर्नी की जांबिया की राजधानी लुसाका की यात्रा (26 से 29 मार्च, 1977) भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी। दोनों नेनामों में परस्पर मैत्री और सहयोग का जायजा लेते हुए जांबिया द्वारा अफ्रीका में घटा की जाने वाली भूमिका की प्रशंसा की। डॉ. कैनेथ काउडा ने नवम्बर, 1974 में रूस की यात्रा की थी। दोनों देशों में आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक समझौते के प्रसार

पर भी जोर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण रोडेशिया की नस्ली अमानवीय नीतियों की मर्त्सना करते हुए कहा गया कि जब तक अफ्रीकी बहुसंख्यकों को सत्ता नहीं सौंपी जाती तब तक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और मानवीय सुरक्षा को खतरा बना रहेगा। दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया को स्वतन्त्रता देने तथा स्मिथ से बिना शर्त कालो को सत्ता सौंपे जाने की माँग की। नामीबिया के बारे में समुक्त राष्ट्र के फैसले की पूरी तरह से लागू करने की माँग की गई। जब तक दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में बहुसंख्यक कासो का शासन नहीं होगा तब तक अंगोला, बोत्स्वाना, मोजांबिक तथा जाम्बिया जैसे पड़ोसी देशों में हमेशा खतरा बना रहेगा। दोनों देशों ने घोषणा की कि इन भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ न्यायपूर्ण संघर्ष में सभी देशों को राष्ट्रीय आन्दोलनों को सहयोग देना चाहिए। इसके साथ ही स्पष्टवादी काउडा अंगोला के गृहयुद्ध में सोवियत संघ और अंगोला के हस्तक्षेप पर भी अपना रोष व्यक्त किए बिना नहीं रहे। आज स्थिति यह है कि अंगोला रूसी फ्लू भार से दबा जा रहा है। रूस ने अंगोला को 30 करोड़ डॉलर की सहायता दी और इस समय अंगोला में लगभग 13,000 कूचाई सैनिक और तकनीकी अधिकारी हैं।

मोजांबिक के राष्ट्रपति और फ्रंटिस्मो पार्टी के नेता समोरा माशेल से भी पोदगर्नी ने परस्पर और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर वार्ता की। मोजांबिक के साथ 15 वर्षीय मैत्री-समझौता भी किया गया है। अफ्रीका के वर्तमान राजनीतिक दौर में मोजांबिक ने जो स्थिति प्राप्त कर ली है उसका भी जायजा लिया गया। पोदगर्नी ने अपने भाषणों में मोजांबिक द्वारा अपनाए जाने वाले वैज्ञानिक समाजवाद का भी उल्लेख किया। आरम्भ में मोजांबिक का झुकाव चीन के प्रति था लेकिन आज वह सोवियत संघ की निरन्तर मित्रता की ओर हाथ बढ़ाता जा रहा है। मोजांबिक में रोडेशिया के लगभग आठ हजार छापामारों का झुंडा है जिसे सोवियत संघ का समर्थन मिल रहा है।

सोवियत विदेश नीति का मूल्यांकन (Evaluation of Soviet Foreign Policy)

युद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की जटिलताओं में सोवियत विदेश नीति अभी तक जितनी सफल और प्रभावकारी रही है, उतनी अमेरिकी विदेश नीति नहीं। पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप आदि सभी क्षेत्रों में सोवियत रूस ने अपना प्रभाव बढ़ाया है और अमेरिका तथा उसके साथी राष्ट्रों की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया है। महायुद्ध के बाद तीन वर्षों में ही सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप को 'साल' बना देने में सफलता प्राप्त की। पश्चिमी एशिया में अरब जगत पर सोवियत रूस प्राथमिकता का दाय से छा गया और भारत तो उसका प्रगाढ़ मित्र है। भारत के साथ रूसी मैत्री की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रूस ने भारत की गुट-निरपेक्षता को पूरा सम्मान देते हुए उनकी मित्रता स्वीकार की है। भूमध्यसागर और हिन्दमहासागर में सोवियत नी-शक्ति का प्रभावी वर्चस्व है। जापान के साथ भी रूस के सम्बन्ध मधुर बनते जा रहे हैं और दोनों पक्षों में

आर्थिक सहयोग की नींव पर राजनीतिक सम्बन्धों का महल खड़ा किया जाने लगा है। पश्चिमी जर्मनी से सम्मिलित करके भी रूस ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की है। फ्रांस गत कुछ वर्षों से रूस के पक्ष में जितना झुका है वह स्थिति अमेरिकी गुट की अपेक्षा रूस के लिए अधिक उत्साहवर्द्धक है। अमेरिका के अतिरिक्त केवल चीन ही रूसी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अमेरिका और रूस में पक्षों के पीछे परस्पर सहयोग और सह-अस्तित्व की जो गुप्त बातें चल रही हैं उनसे अधिकतर यही अनुमान है कि निकट भविष्य में चीन रूस के साथ प्रतिद्वन्द्विता त्याग कर पुनः सहयोग की नीति का अनुसरण करने लगेगा। भारत जिस शक्तिशाली रूप में उभरा है उससे भी चीन की मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा, इस सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

सोवियत संघ के शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के नारे पर अनेक राजनीतिक क्षेत्रों में सन्देह प्रकट किया जाता है, लेकिन यदि हम अमेरिका के रवैये को देखें तो शायद रूस से भी अधिक सन्देह उस पर किया जाता चाहिए। बंगलादेश के लोकतान्त्रिक जन-प्रान्दोलन को कुचलने में अमेरिका ने जो लज्जाजनक भूमिका अदा की, वह अमेरिकी लोकतन्त्र के नाम पर कलक है। भारत के न्यायोचित पक्ष का सला छोड़ने और युद्ध-विपक्षी पाकिस्तानी तानाशाहों को हथियारों से लैस करने में भी अमेरिका की भूमिका निन्दनीय रही है। फिर आज का युग प्राणविक अस्त्रों का युग है जिसमें युद्ध की दशा में परमाणु-अस्त्र न विजेता की लाज रखेंगे न विजित की। अतः सह-अस्तित्व का विकल्प सह-विनाश हो रह गया है और शायद कोई भी महाशक्ति इस मार्ग को अपनाना पसन्द नहीं करेगी। यही कारण है कि चीनी प्रजगर, जो युद्ध की फूँकारें मारता था, अब युद्ध और शान्ति की मिश्रित फूँकारें छोड़ने लगा है।

“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होता हो वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।”
—जवाहरलाल नेहरू

भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र हुआ, किन्तु भारत की विदेश-नीति का सूत्रपात 2 सितम्बर, 1946 से माना जा सकता है जबकि एक ‘अन्तरिम सरकार’ का निर्माण हो गया और यह समझा जाने लगा कि भारत वास्तव में अपनी विदेश-नीति का अनुसरण करने में स्वतन्त्र है।

भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक आधार

मार्च, 1950 में लोकसभा में भाषण देते हुए पण्डित नेहरू ने कहा था—
“यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम विदेश-नीति के क्षेत्र में एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे अतीत के इतिहास से और हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित है। इसका विकास उन सिद्धान्तों के प्रतुसार हुआ है जिनकी घोषणा अतीत में हम समय-समय पर करते रहे हैं।”

भारतीय विदेश-नीति का निर्धारण तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से ही नहीं हुआ बल्कि इसके निर्माण में भारतीय प्राचीन-प्रणाली की प्राचीन परम्परा और स्वाधीनता सपना के उच्च आदर्शों का भी ध्यान रखा गया। भारतीय चिन्तन और दर्शन में सदैव भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों को स्वीकार किया गया है और सहिष्णुता उसका स्वभाव रहा है, अतः जब भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट-निरपेक्षता और विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के तरीकों को सर्वोपरि महत्त्व दिया तो इसका कारण भारत की यही परम्परा थी। भारतीय विदेश-नीति में उपनिवेशवाद, जातिवाद, फासिज्म आदि का विरोध सन्निहित है, उसे भी स्वाधीनता संघर्ष काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनेक प्रस्तावों द्वारा स्पष्ट कर चुकी थी। इस प्रकार यह दावा करना सर्वथा उपयुक्त है कि भारत की विदेश नीति कोई

प्राकृतिक उपज नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक आधार हैं। पामर एवं पर्सिंस के शब्दों में “भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कई शताब्दियों में विकसित सम्प्रदायों के मूल में छिपी हैं और इसमें चिन्तन-शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आन्दोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुँच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्त्व के गांधीवादी सिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग रहा है।”¹

भारतीय विदेश-नीति के आधारभूत उद्देश्य और लक्ष्य

भारत की विदेश-नीति के आधारभूत उद्देश्य सरल और स्पष्ट हैं। भारत सरकार के एक प्रकाशन ‘स्वतन्त्र भारत के बढ़ते कदम’ के अनुसार इन उद्देश्यों में स्वतन्त्रता की प्राप्ति में अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये उद्देश्य हैं—

प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना और उसे प्रोत्साहन देना।

द्वितीय, सभी पराधीन देशों की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देना क्योंकि भारत की दृष्टि से उपनिवेशवाद केवल मूल मानव अधिकारों का उत्खनन ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का सतत् कारण भी है।

तृतीय, जातिवाद का विरोध और ऐसे साम्यवादी समाज के विकास का समर्थन जिसमें रंग, जाति और वर्ग के किसी भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो।

चतुर्थ, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समझौते द्वारा समाधान।

पंचम, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और सम्पूर्ण मानवता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्रसंघ को सक्रिय सहयोग देना।

पामर एवं पर्सिंस ने भारतीय विदेश नीति के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार गिनाये हैं²—

- (1) जातीय भेदभाव और साम्राज्यवाद का प्रबल विरोध;
- (2) साम्यवाद अथवा शक्ति-राजनीति की अपेक्षा राष्ट्रो के आधारभूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास पर बल;
- (3) एशियायी देशों की उपेक्षा न करने और उन पर बलात् कुछ न धोपने पर धारणा;
- (4) स्वतन्त्रता अथवा असंलग्नता की नीति पर बल;
- (5) संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास;
- (6) शीतयुद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से बचना; एवं
- (7) अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने वाले और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की सम्भावनाएँ बढ़ाने वाले प्रयत्नों में आस्था।

भारत की विदेश-नीति के उपर्युक्त उद्देश्यों और लक्ष्यों में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी नीतियों से राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि महत्त्व देता है और विदेश नीति की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी इस बात में है कि वह राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में कहां तक सफल हुई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 30 वर्षों में, घोर कठिनाइयों के बावजूद, भारत की विदेश नीति ने राष्ट्रीय हितों का पोषण और सबर्द्धन किया है। इजरायल के विरुद्ध अरब राष्ट्रों का समर्थन, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में रूसी दमन-चक्र के विरोध में शिथिलता, अमेरिका की तुलना में सोवियत संघ को प्राथमिकता, आदि कुछ बातों के कारण भारतीय विदेश-नीति में विरोधाभास का आरोप लगाया जाता है। लेकिन गम्भीरता से सोचने पर विदित होगा कि भारत ने प्रत्येक अवसर पर गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का अनुपालन किया है। भारत ने सदैव न्याय का पक्ष लिया है और इस दृष्टि से ही अपना समर्थन और विरोध प्रकट किया है। यदि कभी कुछ विरोधाभास या व्यक्तिक्रम दिखायी भी दिया है तो उसके मूल में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहा है। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किसी देश की विदेश-नीति को कठोरता का जामा नहीं पहनाया जा सकता। यदि राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए विदेश-नीति में सामयिक मोड़ दिए जाते हैं तो यह सर्वथा युक्तिसंगत है। पर ये सामयिक हेरफेर विदेश-नीति के आधारभूत उद्देश्यों और तत्त्वों को नष्ट नहीं करते। भारत सन् 1947 में गुट-निरपेक्ष देश था और आज भी गुट-निरपेक्ष है। भारत ने सन् 1947 में सह-अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया था और वर्तमान में भी वह सह-अस्तित्व का प्रवल समर्थक है। इसी प्रकार भारत ने सदैव जातिवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद आदि का विरोध किया है। समुक्त राष्ट्रमण्डल में भारत ने जो प्रस्ताव रखी हैं और संघ के कार्यों में जो सहयोग दिया है वह अपने आप में एक उदाहरण है। किसी भी देश की विदेश-नीति का मूल्यांकन करते समय स्वर्गीय श्री नेहरू के ये शब्द, जो उन्होंने 4 दिसम्बर, 1947 को संविधान-सभा में कहे थे, सदैव ध्यान में रखने होये—

‘आप चाहे कोई भी नीति अपनायें, विदेश-नीति का निर्धारण करने की कला राष्ट्रीय हित के सम्पादन में ही निहित है। हम अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सहयोग और स्वतन्त्रता की चाहे कितनी ही बातें करें और उनका कंसा ही अर्थ लगायें, किन्तु अन्ततोगत्वा एक सरकार अपने राष्ट्र की भलाई के लिए ही कार्य करती है और कोई भी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो उसके राष्ट्र के लिए अहितकर हो। अतः सरकार का स्वरूप चाहे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी अथवा समाजवादी, उसका विदेश मन्त्री मूलतः राष्ट्रीय हित में ही सोचना है।’

पुनश्च, पैडसफोर्ड एंव लिंकन के शब्दों में—

“विदेश नीतियों का निर्माण मूढम सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होता, वरन् ये राष्ट्रीय हितों के क्रियात्मक विचारों का परिणाम होती हैं।”

भारत की विदेश-नीति के मौलिक तत्व आज भी वही हैं जो पहले थे।

अन्तर केवल इतना ही आया है कि नेहरू युग में आदर्शवाद पर अधिक बल रहा, यद्यपि अपने जीवन की संघ्ना में नेहरू भी यथार्थवाद को महत्त्व देने लगे, शास्त्री युग में यथार्थवाद को अधिक महत्त्व देकर तुष्टिकरण की नीति के दुर्बल चिह्नों को मिटाया जाने लगा और तत्पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की विदेश-नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुन्दर सन्तुलन दृष्टिगोचर हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को श्रीमती गांधी ने अन्धरी तरह समझा और देश की विदेश-नीति के आदर्शवादी सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए उसे पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक, दृढ़ और आत्मविश्वासपूर्ण बनाया। पहले बंगला देश के सन्दर्भ में, फिर पाकिस्तान के प्रति और साथ ही रूस एवं अमेरिका जैसी महाशक्तियों के प्रति श्रीमती गांधी ने विदेश-नीति का कुशल संचालन किया। भारत ने उपनिवेशवाद और जातिभेद का विरोध किया और गुट-निरपेक्षता तथा सह-प्रतिस्तर के आन्दोलन को पूर्वापेक्षा सबल बनाया।

मार्च, 1977 में कांग्रेस शासन के पतन के साथ ही जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। प्रधानमन्त्री पद श्री मोरारजी देसाई ने और विदेशमन्त्री पद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्भाला। विदेश-नीति के सन्दर्भ में नई सरकार ने अपना स्पष्ट और सुदृढ़ विचार व्यक्त किया कि भारत सक्रिय गुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलता रहेगा। 4 अप्रैल, 1977 को राष्ट्र के नाम सन्देश प्रसारित करते हुए प्रधान-मन्त्री श्री देसाई ने कहा—

‘हम पूरे दिल से शान्ति कायम रखने में विश्वास रखते हैं, शान्ति के नारे में नहीं। हम शान्ति को ऐसा साधन मानते हैं जो हम सबके लिए कल्याणकारी है और जिससे इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सकती है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि शान्ति हम तभी रख सकते हैं जब हम बिना किसी डर या पक्षपात के या किसी का धुरा सोचे बिना, गुट-निरपेक्षता के सही रास्ते पर चलें। दुनिया की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को मिलकर और आपसी सहयोग से हल करने का सिद्धान्त ही हमारी विदेश-नीति का निर्देशक सिद्धान्त होगा। दुनिया के शेष भागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सहयोग की भावना रखकर हम इस मार्ग का अनुसरण करेंगे और दुराग्रह नहीं रखेंगे। आने वाले समय में बढ़ते हुए आर्थिक और मानवीय सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीतिक सम्बन्धों की जगह लेंगे। हम इस विकास में अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब हम खुद आर्थिक दृष्टि से मजबूत हों।’¹

भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्त्व

भारत की विदेश नीति के भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, वैचारिक आदि तत्त्वों पर विस्तृत विवेचन अपेक्षित है—

भौगोलिक तत्त्व

भारत एक सुविशाल देश है जिसकी लगभग 3500 मील लम्बी समुद्री सीमा और 8200 मील लम्बी स्थल सीमा है। समुद्री सीमा का तीन दृष्टियों से विशेष

महत्व है—प्रथम, हिन्द महासागर पर अधिकार रखने वाली शक्तियाँ भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, द्वितीय, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार हिन्दमहासागर द्वारा होता है; एवं तृतीय, विशाल समुद्र तट की रक्षा के लिए अनिवार्य है कि भारत शक्तिशाली नौ-शक्ति का विकास करे। भारत की स्थल सीमाएँ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और बर्मा से मिलती हैं। हिमालय प्रब देश की सुरक्षा का विश्वसनीय प्रहरी नहीं रहा है, चीन के आक्रमण ने भारत की आँखें खोल दी हैं।

अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत की विदेश नीति का निर्धारण निम्नलिखित हितों को ध्यान में रखकर हुआ है—(1) जिन सीमावर्ती एवं अन्य देशों से देश की सुरक्षा को भय हो, उनके साथ तटस्थता अथवा मित्रता का व्यवहार। ये देश हैं—ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, हिन्द-चीन, साम्यवादी चीन आदि। (2) मध्यपूर्व, बर्मा, डच, ईस्ट इण्डोज आदि से तेल की प्राप्ति। (3) सीमावर्ती राज्यों में बसने वाले भारतीयों का कल्याण और भारतीय व्यापार का विस्तार। (4) हिन्दमहासागर में भारत की सुरक्षा और व्यापार के आधारभूत समुद्री तथा हवाई मार्गों की सुरक्षा। (5) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा प्रमुतासम्बन्ध राष्ट्रों के मामलों में अपने देश के इतिहास, हित और संस्कृति के अनुरूप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना।

आर्थिक एवं सैनिक तत्त्व

सदियों की गुलामी में भारत का आर्थिक शोषण होता रहा, अतः स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद देश की विदेश-नीति के निर्धारण में आर्थिक और सैनिक तत्त्वों का विशेष महत्व रहना स्वाभाविक था और आज भी है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से अधिक स्पष्ट हो जाएगी—

(i) भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनायी ताकि विश्व शान्ति का प्रोत्साहन देते हुए वह दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहे।

(ii) भारत के नीति-निर्माताओं ने यह भली प्रकार समझ लिया कि उनके देश विश्व के पूँजीवादी और साम्यवादी शक्तियों के बीच सन्तुलनकारी भूमिका निभाकर दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अतः भारत ने यही नीति अपनायी कि किसी भी पक्ष के साथ सैनिक-सन्धि में न बंधा जाए, किसी भी गुट में साथ ऐसी सन्धि न की जाए जिससे देश की गुट-निरपेक्षता और सम्प्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। भारत ने विदेशों से जो भी आर्थिक और प्राविधिक सहायता प्राप्त की व राजनीतिक शर्तों से मुक्त रही।

(iii) नवोदित भारत सैनिक दृष्टि से निर्बल था, अतः विदेश नीति के निर्धारकों ने यह उपयुक्त समझा कि दोनों गुटों की सहानुभूति अर्जित की जाए। यह तभी सम्भव था जब गुट निरपेक्षता और सह-प्रतिष्ठित्व की नीति अपनायी जाती।

(iv) भारत जैसे सुविशाल और महान् देश के लिए यह स्वाभाविक था कि

वह ऐसी विदेश नीति का अनुसरण करता जिससे उसकी स्वयं की निर्णय-शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ सके ।

जिन आर्थिक और सैनिक तत्त्वों ने सन् 1947 में भारत की विदेश-नीति के निर्धारण में योग दिया वे तत्त्व आज भी उतने ही सजीव हैं । सन् 1978 का भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से सन् 1947 के मुकाबले कहीं अधिक सबल है, लेकिन गुट-निरपेक्षता और शान्ति की नीति भयंकर कठिनाइयों में भी भारत के लिए इतनी हितकारी सिद्ध हुई है कि उसके परित्याग का कोई प्रश्न नहीं उठता । पाकिस्तान अपने जन्मकाल से ही सैनिक गुटों से प्रतिबद्ध रहा है लेकिन इस नीति के परिणाम उसके लिए दुःखदायी सिद्ध हुए हैं । यह चीन, अमेरिका जैसे राष्ट्रों के हाथ लगभग बिक चुका है तथा उनके शिकजे से निकलना उसके लिए यदि असम्भव नहीं तो अति कठिन अवश्य है । विश्व के अनेक दूसरे देशों का इतिहास भी साक्षी है कि गुटों के साथ बँधकर उन्होंने अपनी राजनीतिक सम्प्रभुता के साथ खिलवाड़ की है । एक गुट-निरपेक्ष देश के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर भारत की जो आवाज है वह सैनिक सन्धियों और गुटों में आवद्ध अधिकांश देशों की आवाज से कहीं अधिक बलशाली और प्रभावकारी है ।

ऐतिहासिक परम्पराएँ

अतीत से ही भारत सहिष्णु और शान्तिप्रिय देश रहा है । इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी किसी देश पर राजनीतिक प्रभाव लादने या उसकी प्रादेशिक प्रवृत्तियों को भंग करने की चेष्टा नहीं की । यह ऐतिहासिक परम्परा भारत की विदेश-नीति का महत्त्वपूर्ण निर्माणक तत्त्व है । स्वाधीन भारत के तीन दशक पूरे हो गये हैं और इस सम्पूर्ण अवधि में भारत ने सभी देशों के साथ समानता और मित्रता की नीति निभायी है । पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक आक्रमण किए किन्तु फिर भी भारत की नीति उसके साथ मंत्री और मह-अस्तित्व की रही है । प्रत्येक युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया, किन्तु फिर भी उस पर अपनी शर्तें नहीं लादी । सन् 1965 के युद्ध में पाकिस्तान का जो भू-भाग छीन लिया गया था वह ताशकन्द के समझौते द्वारा लौटा दिया गया । सन् 1971 में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी, लेकिन शिमला समझौते द्वारा भारत ने समस्त हस्तगत भूमि पुनः पाकिस्तान को सौंप दी, यहाँ तक कि अनेक रियायतें और सुविधाएँ देकर भी पाकिस्तान की मित्रता की आकांक्षा की । इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि पाकिस्तान भारत की तुष्टिकरण की नीति को, शान्तिपूर्ण और सह-अस्तित्व की विचारधारा को उसकी दुर्बलता का चिह्न मानता है । पाकिस्तान के मृतपूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली बुट्टो भारत को युद्ध की घमकियाँ देते रहे हैं, भारत से हजार वर्ष बढ़ने की बात करते रहे हैं, फिर भी भारत भड़काने में नहीं आता, पाकिस्तान के प्रति एक बड़े भाई जैसा आचरण करता है । लेकिन यदि सिर पर ही आ पड़ी तो अब की बार, जैसा कि हमारे नेता चेतावनी दे चुके हैं, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वह हमेशा के लिए याद रखेगा । साम्यवादी चीन भी भारत के प्रति

घोर शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाता है। सन् 1962 में अचानक विशाल पैमाने पर आक्रमण कर चीन ने एक मिच की पोठ में छुरा भोंका और भारत की कुछ भूमि हृदय ली। उस समय भारत सैनिक दृष्टि से सबल नहीं था, लेकिन वह किसी भी आक्रमण का मुँह तोड़ उत्तर देने में सक्षम है तथापि शान्तिवादी भारत ने यह कभी प्रयत्न नहीं किया कि सैनिक शक्ति के बल पर अपनी भूमि वापस प्राप्त की जाए। यह बात भारत की दुर्बलता का चिह्न नहीं है बल्कि एक महान देश की सहनशीलता का प्रमाण है।

वैचारिक तत्त्व

सहिष्णुता, उदारता आदि तत्त्वों को ऐतिहासिक परम्परा के साथ वैचारिक तत्त्वों में भी रखा जा सकता है। इनके अनिरीक भारत की विदेश-नीति गांधीवाद से काफी प्रभावित है। इस पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी कम नहीं है। समाजवादी शिविर के प्रति भारत की सहानुभूति बहुत कुछ मार्क्सवादो प्रभाव का परिणाम मानी जा सकती है। गुट-नीति के क्षेत्र में भी भारत ने समाजवादी दलों के समाज की स्थापना का लक्ष्य सामने रखा है। पश्चिम के उदारवाद का भी भारत की विदेश-नीति पर काफी प्रभाव है। हमारी विदेश-नीति के कर्णधार स्वर्गीय श्री नेहरू पाश्चात्य लोकतन्त्रीय परम्पराओं से बहुत प्रभावित थे। वे पश्चिमी लोकतन्त्रवाद और साम्यवाद दोनों की अग्रच्छाइयों को पसन्द करते थे और उनकी बुराइयों से बचना चाहते थे। इस प्रकार की समन्वयकारी विचारधारा ने गुट-निरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रीय संघर्ष

भारत के स्वाधीनता संघर्ष ने विदेश-नीति के निर्धारण में उत्प्रेरणीय योग दिया क्योंकि—(i) इसके कारण भारत में महाशक्तियों के संघर्ष का मोहरा बनने से बचने का विचार उत्पन्न हुआ; (ii) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष रहते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की भावना जाग्रत हुई; (iii) हर प्रकार के उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंग-भेद का विरोध करने का अद्भुत साहस उत्पन्न हुआ; एवं (iv) स्वाधीनता-ग्रान्दोलनों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई।

वैयक्तिक तत्त्व

भारत की विदेश-नीति पर वैयक्तिक तत्त्वों का, विशेषकर पण्डित नेहरू का व्यापक प्रभाव रहा है। प. नेहरू साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी तथा विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान के समर्थक थे। वे मैत्री, सहयोग और सह-अस्तित्व के शोषक थे, लेकिन अन्त्यायपूर्ण आक्रमण को रोकने के लिए शक्ति के प्रयोग को भी उतना ही महत्व देते थे। महाशक्तियों के संघर्ष में भारत के लिए वे असंलग्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते थे। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होंने भारत की विदेश-नीति का निर्माण किया। इसका वर्तमान स्वरूप पण्डित नेहरू के विचारों का ही प्रतीक है। पण्डित नेहरू के अनिरीक डॉ. रामाकृष्णन, कृष्णमेनन, पण्डित के नाम भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में सम्मिलित किए जाते हैं

जिन्होंने भारत की विदेश-नीति को प्रभावित किया। साम्यवादी चीन के प्रति भारत की प्रारम्भिक नीति के निर्धारण में सरदार पण्डितजी का विशेष हाथ रहा था। उनके गलत मूल्यांकन के कारण ही तिब्बत और चीन के बारे में भारत की विदेश-नीति पथ-भ्रष्ट हो गई तथा चीन पर अन्धविश्वास कर बैठी। पण्डितजी चीन में भारत के राजदूत थे और उनकी रिपोर्टों के आधार पर पण्डित नेहरू चीन के प्रति भारत की नीति का निर्धारण करते रहे। सन् 1962 के चीनी आक्रमण ने सभी की आँखें खोल दी और उसके पश्चात् विदेश-नीति यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुई। स्वर्गीय शास्त्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में भारत की विदेश-नीति में अधिक निखार आया और आज सन् 1978 में प्रधानमंत्री श्री देसाई और विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपने मौलिक तत्वों को पूर्ववत् कायम रखते हुए, यह पिछले किसी भी समय की तुलना में अधिक व्यापहारिक है। भारत की शान्ति-प्रियता, सहिष्णुता, मैत्री और सहयोग की भावना आज भी उतनी ही बलवती है, अतः अभी पहले थी, केवल अन्तर यह आया है कि भारत इस बात को समझ चुका है कि केवल शान्ति के नारों से काम नहीं चल सकता, शत्रु-राष्ट्रों से रक्षा के लिए भारत को एक शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र भी बनना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की आवाज अभी बुलन्द रह सकेगी जब सैनिक दृष्टि से भी वह सुदृढ़ हो। भारत की किसी प्रकार की आक्रामक या विस्तारवादी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आत्म-रक्षा के लिए सैनिक सुदृढ़ता अनिवार्य है।

राष्ट्रीय हित

विदेश-नीति का निर्माण सूक्ष्म सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होता। यह राष्ट्रीय हितों के व्यापक विचारों का परिणाम होता है। भारत की विदेश-नीति में राष्ट्रीय हित को सदैव सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है और दिया जाता रहेगा। राष्ट्रीय हित समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, अतः भारत की विदेश-नीति में कभी जड़ता नहीं पाई है। भारत ने किसी साम्राज्य का आकांक्षी है, न उसे अपने किसी उपनिवेश की रक्षा करनी है। भारत ने न अन्तर्राष्ट्रीय मानसंबाध-माओवाद की शान्ति का बोझ उठाया है और न ही किसी विचारधारा अथवा शासन-प्रणाली के विरोध में कोई सैनिक संगठन स्थापित किया है। भारत का राष्ट्रीय हित तो इस बात में निहित है कि राष्ट्र की एकता, अखण्डता और स्वतन्त्रता की रक्षा की जाए, देश में लोकतन्त्र को सुदृढ़ बनाया जाए, देश के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए और पड़ोसी एवं अन्य राष्ट्रों के साथ यथासम्भव मैत्री का विकास किया जाए। भारत ने स्वाधीनता के अपने लगभग 30 वर्षों में इन्हीं लक्ष्यों की साधना की है। बाह्य आक्रमण से रक्षा करना राष्ट्र के अस्तित्व की पहली शर्त है और इतिहास साक्षी है कि भारत ने देश पर आए हर संकट का मुहताब जवाब दिया है।

गुट-निरपेक्षता और सह-प्रस्तित्व की नीति के प्रयोग का सर्वेक्षण (1947—1977)

सन् 1947 में जब भारत का स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, उस समय

अन्तर्राष्ट्रीय रणमंच पर दो विरोधी शक्तियाँ विद्यमान थी। अपनी परम्परा के अनुसृत भारत ने सभी शक्ति-गुटो से तटस्थ या पृथक् रहने और किसी का पिछलग्गू न बनने का निर्णय किया। प. नेहरू ने कहा था—“जहाँ तक सम्भव हो, हम उन शक्ति-गुटो से अलग रहना चाहते हैं जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं।”

किन्तु गुटो से पृथक् रहने की नीति का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थता कदापि नहीं है। निश्चित रूप से इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हम सत्तार की घटनाओं से उदासीन रह कर तमाशा देखते रहेंगे और दुनिया से कटे रहेंगे। इसका मतलब है ऐसी स्पष्ट, क्रियारमक तथा रचनात्मक नीति अपनाना जिससे सत्तार में शान्ति स्थापना को बल मिले। वास्तव में सामूहिक सुरक्षा इसी पर निर्भर है। वस्तुतः गुट-निरपेक्षता का प्रर्थ है अपनी स्वतन्त्र रीति-नीति का अनुसरण। गुटो से अलग रहने से हर प्रश्न के धींचित्य-प्रगोचित्य को देखा जा सकता है। किसी गुट के साथ मिलकर, उचित-अनुचित का खाल किए बिना उनका अन्धानुकरण करना होता है।

गुट-निरपेक्षता की नीति पर कायरता का आरोप निराधार है। जो नीति स्वतन्त्रता, न्याय और मानव मूल्यों का अपमान न सह सकती हो, अन्ध्याय के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग से भी पीछे न हटती हो, हर कीमत पर राष्ट्रीय हित की रक्षा करने में समर्थ हो, उसे कायरता की मजा नहीं दी जा सकती। गुट-निरपेक्षता ने सम्बन्ध में पण्डित नेहरू के ये शब्द आज भी सजीव हैं—

“जहाँ स्वतन्त्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहाँ आक्रमण होना हो, वहाँ न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न ही तटस्थ रहेंगे।”

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही भारत ने जिस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभायी है, पाकिस्तान और सैनिक उपनिवेशवाद का विरोध किया है, जातिवाद और रंगभेद से लोहा लिया है, मुक्ति-प्रान्दोलनों को समर्थन दिया है, विश्व-मस्या के मंच से एशिया और अफ्रीका की आवाज को बुलन्द किया है, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त कर उसे स्वाधीन राष्ट्र के रूप में उदय होने में ऐतिहासिक भूमिका बढ़ा दी है, उन सबसे यही सिद्ध होता है कि गुट-निरपेक्षता निर्भीकता की नीति है, साहस और आत्म विश्वास की नीति है, नैतिक मूल्यों की रक्षा करने हुए राष्ट्रीय हितों का पोषण करने की नीति है। गुट-निरपेक्षता और सह-प्रगतिस्त्व की नीति शान्तिवाद में विश्वास करती है, लेकिन अन्ध्याय और आक्रमण के विरुद्ध तलवार उठाने में भी संकोच नहीं करती। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से कुछ प्रमुख घटनावशों के प्रति भारत का जो रुख रहा उससे गुट-निरपेक्षता की नीति के कार्यान्वयन पर भली प्रकार प्रकाश पड़ सकेगा।

प्रारम्भिक अवस्था (1947-1950)—स्वाधीनता प्राप्ति के तुरन्त बाद

के कुछ वर्षों में भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति अस्पष्ट-सी रही। अन्तर्राष्ट्रीय मायनों में भारत का भुकाव पश्चिमी देशों की ओर रहा। इसके कई कारण थे—प्रथम, सुरक्षा के मामले में भारत पूरी तरह पश्चिमी गुट पर आश्रित था; द्वितीय, भारतीय शिक्षित वर्ग की सहानुभूति ब्रिटेन और उसके साथी राष्ट्रों के साथ थी; तृतीय, भारत के तत्कालीन व्यापारिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी देशों के साथ थे और देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए सहायता मुख्यतः ब्रिटेन और अमेरिका से ही प्राप्त हो सकती थी; चतुर्थ, सोवियत संघ का कण्ठधार स्टालिन था जो उग्र और दुराग्रही था और भारत के नेता आश्वस्त नहीं थे कि भारत-रूस सहयोग का विकास हो सकेगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में सन् 1947 से 1950 तक भारत का भुकाव अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रति रहा। इसके समर्थन में कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। विभाजित जर्मनी में एक को (पश्चिमी जर्मनी को) जो पश्चिमी-गुट से सम्बन्धित था कूटनीतिक मान्यता प्रदान की गई जबकि पूर्वी जर्मनी को मान्यता नहीं दी गई। भारत का यह तर्क बजनदार नहीं था कि पूर्वी जर्मनी को यदि मान्यता दी जाती तो इसका अर्थ जर्मनी के विभाजन को स्वीकार कर लेना होता। कोरिया-युद्ध के प्रारम्भ में भी भारत का रुख कुछ पक्षपातपूर्ण सा रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाति भारत ने भी तुरन्त उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया जबकि वस्तु-स्थिति यह थी कि पश्चिमी देश आज तक अपने कथन के समर्थन में पूर्ण विश्वसनीय प्रमाण नहीं दे सके हैं। यह बहुत सम्भव है कि आक्रामक दक्षिणी कोरिया रहा हो। भारत का निर्णय कोण्डारी की रिपोर्ट पर आधारित था और यह रिपोर्ट उसके व्यक्तिगत विचारों से अत्यधिक प्रभावित थी।¹

कोरिया-युद्ध में थाव की भूमिका—भारत ने उत्तर कोरिया को आक्रामक घोषित करने में जल्दबाजी दिखायी, लेकिन कुल मिलाकर कोरिया-युद्ध के समय उसे दुनिया के सामने अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति प्रदर्शित करने का पहला अवसर मिला। भारत ने उस समय युद्ध-वन्धियों को लौटाने के लिए तटस्थ राष्ट्रों के प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और एक अति कठिन कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक पूरा कर दिखाया।

गुट-निरपेक्षता की नीति में निखार, रूस के साथ सम्बन्धों में सुधार का प्रारम्भ—कोरिया-युद्ध के बाद से ही भारत की विदेश-नीति में अधिक निखार आने लगा। सोवियत संघ की तुलना में पश्चिमी देशों की ओर अधिक भुकाव की प्रवृत्ति कम होने लगी। सन् 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में कुछ उदार तत्वों का समावेश हुआ और भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को सोवियत नेता कुछ अधिक विश्वास और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध शक्तिशाली बनाने की नीति पर अमल शुरू कर दिया।

सन् 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक सैनिक सन्धि हुई जिसके अन्तर्गत भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्रास्त्र देने का निर्णय किया गया। गोआ-समस्या के प्रति अमेरिका का रुबंया भी भारतीय जनमत को विक्षुब्ध करने वाला था। विदेश सचिव जॉन फॉस्टर डलेस ने सार्वजनिक रूप से गोआ में पुर्तगाल की उपनिवेशवादी सरकार का समर्थन किया। अमेरिका और उसके साथी पश्चिमी राष्ट्रों की वास्तविक सहानुभूति भारत के प्रति नहीं रही। भारतीय नेताओं ने इस स्थिति का मूल्यांकन किया और समझ लिया कि देश के लिए यही हितकर है कि भारत गुट-निरपेक्षता की नीति पर धारुड रहे। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत सघ के प्रति उदासीन रहना भारत के लिए अहितकर था। सोवियत सघ ने गोआ के प्रश्न पर भारत का समर्थन किया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक सम्बन्धों में भी वृद्धि हुई। भारत को सोवियत सघ से ठोस प्राथिक सहायता भी प्राप्त होने लगी। इस तरह पश्चिम पर भारत की निर्भरता कम होती गई। दोनों गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त होते रहना भारत की गुट-निरपेक्ष नीति की सफलता की छोक थी। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू को सोवियत सघ जाने और सोवियत नेता ख्रुश्चेव की भारत-यात्रा से भी इस और भारत के बीच सहयोग में वृद्धि हुई।

हिन्द-चीन का संकट—भारत की गुट-निरपेक्ष नीति की उपयोगिता को प्रदर्शित करने का एक ठोस प्रवसर हिन्द-चीन सघर्ष के समय (फ्रांस और हिन्द-चीनी देशभक्तों में) मिला। यद्यपि भारत जेनेवा कॉन्फ्रेंस का सदस्य नहीं था, किन्तु शान्ति के लिए जो समझौता हुआ उसमें उसने महत्वपूर्ण योगदान किया। सन् 1954 के जेनेवा समझौते को कार्यान्वित कराने में भारत का पूर्ण सहयोग रहा। हिन्द-चीन-विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए भारत ने एक छः सूत्री योजना प्रस्तुत की। जेनेवा समझौते का पालन कराने के लिए जो अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग बना उसका भारत चेयरमैन बनाया गया।

पंचशील—गुट-निरपेक्षता की नीति द्वारा शान्ति-क्षेत्र-विस्तार के भारत के सकल्प का चरम उरकर्ष सन् 1954 में हुआ, जब उसने सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्त की घोषणा की। श्री नेहरू ने कहा—“गरम या ठण्डा चाहे जैसा युद्ध हो, इसका विकल्प शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व ही है।” 29 अप्रैल, 1954 को भारत और चीन के तिब्बत-क्षेत्र के बीच व्यापार और आवागमन आदि के बारे में भारत-चीन समझौते द्वारा इस विचार को प्रतिष्ठा मिली और इसे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई। इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धान्तों का समावेश किया गया जो आगे चलकर ‘पंचशील’ के नाम से विख्यात हुए। ये हैं—एक दूसरे की क्षेत्रीय अखण्डता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान; अनाक्रमण; एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना; समानता तथा एक दूसरे के हित का ध्यान और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व। इन सिद्धान्तों के बारे में श्री नेहरू के ये शब्द आज भी तजीब हैं—“मैं समझता हूँ कि यदि इन सिद्धान्तों को सभी देश स्वीकार कर ले तो आज की दुनिया की बहुत-सी मुसीबतें शावद काही हर तरह दूर हो जाएँगी।”

अप्रैल, 1955 में वाण्डुंग सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धान्तों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। वाण्डुंग सम्मेलन के बाद विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धान्तों को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की।

पंचशील के सिद्धान्तों की श्रेष्ठता से कोई इंकार नहीं कर सकता। प्रथम तीन सिद्धान्त घोषित करते हैं कि सभी राष्ट्रों को एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्चता का सम्मान करते हुए परस्पर आक्रमण और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चौथे सिद्धान्त का आशय है कि प्रत्येक राष्ट्र को छोटे-बड़े सभी राज्यों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए पारस्परिक हितों को आगे बढ़ाना चाहिए। पाँचवाँ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धान्त तो आधुनिक जटिल अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की माँग है। सह-अस्तित्व को ठुकराने का विकल्प केवल सहविनाश ही हो सकता है। विभिन्न पद्धति वाले राष्ट्रों में शान्तिपूर्ण और रचनात्मक प्रतियोगिता चल सकती है, विनाशक प्रतियोगिता नहीं।

पंचशील के सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए निःसन्देह आदर्श भूमिका का निर्माण करते हैं, पर इनका मूल्य सभी ही जब विश्व के राष्ट्र इनमें व्यावहारिक आस्था रखें। एक राष्ट्र तो इनका पालन करे और दूसरा राष्ट्र इन्हें ठुकराए तो बात नहीं बन सकती। भारत पर पाकिस्तान और चीन के आक्रमण यह सिद्ध कर चुके हैं कि केवल शब्द-जाल से ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना नहीं की जा सकती। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी सिद्धान्त का यदि कोई पालन न करे तो इसमें सिद्धान्त का दोष नहीं है। यह तो अपनी दृष्टि पर है कि हम किसी आदर्श की रक्षा करें या उसे ठुकरा दें। पंचशील के सिद्धान्त पारस्परिक विश्वास के सिद्धान्त हैं और यदि पारस्परिक विश्वास की भजना ही किसी को पसन्द न हो तो क्या किया जा सकता है।

यदि भारत-भूमि पर आक्रमण होता है, भारत की अखण्डता पर आघात होता है, भारत की प्रभुता में हानि पहुँचाई जाती है, भारत की मंत्री-भावना को कमजोरी का चिह्न समझा जाता है तो पंचशील के सिद्धान्त यह नहीं कहते कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सन्नद्ध न हो। पंचशील के सिद्धान्त वे आदर्श हैं जिन्हें व्यावहारिक जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। इनसे हमें नैतिक शक्ति मिलती है और नैतिकता के बल पर हम न्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं। पाकिस्तान के आक्रमणों का मुँह तीव्र उत्तर देकर भारत ने जहाँ अपने मान-सम्मान की रक्षा की है, वहाँ पहले ताश्कन्द समझौते और फिर शिमला समझौते द्वारा अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा कर उसने पंचशील के सिद्धान्तों में आस्था भी प्रदर्शित की है।

हंगरी की घटना, 1955 तथा स्वेज संकट, 1956—इन दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में भारत की भूमिका में उसकी गुट-निरपेक्षता की पुष्टि की। सन् 1955 में हंगरी में सोवियत संघ के हस्तक्षेप पर भारत ने नैतिक विरोध प्रकट कर यह सिद्ध कर दिया कि वह अपने स्वतन्त्र निर्णय में किसी गुट से प्रभावित नहीं है।

दस घटना से दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ तनाव अवश्य पैदा हो गया, लेकिन यह अल्पकालिक ही रहा क्योंकि सोवियत संघ इस बात को समझ गया कि भारत का कार्य अर्धवैपरीत्य नहीं था। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास में कोई विशेष उलझन पैदा नहीं हुई और दोनों के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ता चला गया।

सन् 1956 में स्वेडन पर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल के आक्रमण की सत्कार-भर में भारी प्रक्रिया हुई। भारत सरकार ने एंग्लो-फ्रेंच आक्रमण की तीव्र आलोचना की और आक्रमण को समाप्त करने तथा मित्र से आक्रमणकारी सेना को हटाने के मामले में सोवियत संघ के साथ पूर्ण सहयोग किया। इस संकट के समाधान में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। अन्त में जो समझौता हुआ उसमें वही सिद्धान्त था जो भारत ने सुझाए थे।

चीन का आक्रमण, 1962—नवम्बर, 1962 में भारत पर चीन का विश्वासघाती आक्रमण हुआ और गुट-निरपेक्षता की नीति की अग्नि-परीक्षा हुई। अधिकांश क्षेत्रों में यह माँग की जाने लगी कि गुट-निरपेक्षता की नीति प्रसफल हो चुकी है, अतः इसका यथाशीघ्र परित्याग होना चाहिए। लेकिन प्रधानमन्त्री नेहरू ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति पर घाट नहीं रहेगा। आक्रामक आक्रमण के कारण भारत को कुछ गम्भीर सैनिक पराजयों का सामना करना पड़ा। भारत की अपील पर अमेरिका तथा ब्रिटेन से काफी मात्रा में सैनिक सामग्री प्राप्त की गई। विरोधियों ने आरोप लगाया कि भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति अन्वयावहारिक है क्योंकि एक ओर तो भारत साम्यवादी गुट के प्रमुख सदस्य चीन के साथ युद्धरत है और दूसरी ओर उसका सामना करने के लिए अमेरिकी गुट से सैनिक सहायता ले रहा है। पण्डित नेहरू विरोधियों के सामने परास्त नहीं हुए। चीन का आक्रमण उनके लिए एक गहरा आघात था, लेकिन उन्होंने गुट-निरपेक्षता की नीति में दृढ़ विश्वास प्रकट किया। उनका सबल तर्क यह था कि आक्रमणकारी का मुकबला करने के लिए भारत ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली है, उसके साथ किसी प्रकार की राजनीतिक या अन्य शर्त नहीं है। किसी बन्धनमुक्त सहायता लेने का अभिप्राय गुट-निरपेक्षता की नीति से दूर हटना नहीं कहा जा सकता। पण्डित नेहरू ने यह भी कहा कि यदि इस नीति का परित्याग कर दिया गया तो भारत और चीन का सीमा-संघर्ष शीतयुद्ध का एक अंग बन जाएगा और भारत-चीन विवाद का कोई शान्तिपूर्ण समाधान नहीं निकल सकेगा। उन्होंने प्रायः कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि गुटों की नीति कभी भी सही रूप में फलदायक नहीं हो सकी है। अमेरिका के समर्थन के बावजूद न तो कोरिया और जर्मनी का एकीकरण हो सका है और न ही पाकिस्तान को काश्मीर मिल सका है। इसलिए यह आशा करना निरी मूर्खता होगी कि यदि भारत पाश्चात्य राष्ट्रों के गुट में या साम्यवादी गुट में मिल गया तो इसे उसके छोटे हुए अन्तर्गत वापस मिल जाएँगे। भारत सरकार की ओर से एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि देश अपनी रक्षा के

लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा, परन्तु गुट-निरपेक्षता की नीति का परित्याग नहीं करेगा।

पाकिस्तान का आक्रमण, 1965—सितम्बर, 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में गुट-निरपेक्षता की नीति की शक्ति एक बार फिर सही सिद्ध हुई। पाकिस्तान सीएटो और मैटो जैसे शक्तिशाली सैनिक गुटों का सदस्य होने पर भी किसी से कोई प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नहीं कर सका। टर्की और ईरान ने उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन तो दिया, किन्तु अन्य राज्यों के विरोध के कारण पाकिस्तान की सहायतार्थ स्वयं नहीं आये। इस युद्ध से पाक दृष्टिकोण के बारे में यह गिढ़ हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुटों में सम्मिलित होने की नीति गलत है। बात यही तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक समुक्तराज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर अधिक प्रतिबन्ध लगा दिए और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बन्द नहीं कर देंगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी। स्पष्ट ही अमेरिका ने अपनी इस घोषणा द्वारा एक साथी-राज्य और गुट-निरपेक्ष राज्य को एक ही कोटि में रखा। जब गुटों में सम्मिलित होने से पाकिस्तान को भी लाभ नहीं पहुँच सका तो फिर भारत को लाभ पहुँचने की क्या आशा की जा सकती थी। वास्तव में यह गुट-निरपेक्षता की नीति का ही परिणाम था कि संकट की अवस्था में भारत को अनेक क्षेत्रों से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ और युद्ध के समय उसकी कूटनीतिक स्थिति किसी तरह कमजोर नहीं हुई। सुरक्षा परिषद में युद्ध पर बहस के दौरान भी सोवियत संघ से उसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। भारत-पाक युद्ध ने असलगतः की नीति की श्रेष्ठता को फिर सिद्ध कर दिया।

वास्तव में 27 मई, 1964 को भारत के महान् नेता श्री नेहरू की मृत्यु के बाद यह आशंका व्यक्त की गई थी कि भारत गुट-निरपेक्षता की नीति पर नहीं चल पाएगा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री शास्त्री ने इस प्रकार की आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया। न केवल युद्ध-काल में बल्कि युद्ध के बाद भी ताण्डव समझौते के माध्यम से गुट-निरपेक्षता की नीति की पुष्टि हुई। समझौते से भारत को काफी हानि हुई तथापि वह भारत की गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति का परिचायक था। श्री शास्त्री अपने अल्प प्रधानमन्त्रित्व काल में किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं आए। उन्होंने अपने देश की स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान की।

श्रीमती गांधी के नेतृत्व में गुट-निरपेक्षता की नीति (1966-मार्च, 1977)—जनवरी, 1966 में श्री शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद पण्डित नेहरू की इकलौती पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने प्रधानमन्त्री पद संभाला और उनके नेतृत्व में भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति और भी सशक्त रूप में निखरी। श्रीमती गांधी ने गुट-निरपेक्षता की नीति के आधारभूत सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार उसे बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों में सफलतापूर्वक मंचालित किया।

विभिन्न दवावों के बावजूद श्रीमती गांधी किसी भी महाशक्ति प्रववा गुट-विशेष में प्रभाव से दूर रही। आवश्यकतानुसार उन्होंने पश्चिमी राष्ट्रों की भी आलोचना की और सोवियत संघ की भी। अमेरिका की प्रसन्नता के बावजूद वियननाम में भारत ने अपनी पूर्ववर्ती नीति जारी रखी तो चेकोस्लोवाकिया की घटना पर भारत सभी कार्यवाही के विरुद्ध अपना गहरा खोम प्रकट करने से नहीं चूा।

प्रारम्भ में ही अमेरिका ने श्रीमती गांधी के प्रति दबाव की नीति अपनायी, लेकिन वह उन्हें अपनी घमकियों में नहीं ला सका। वगलादेश के सन्दर्भ में श्रीमती गांधी ने अमेरिका को कूटनीतिक पराजय दी तो दूसरी ओर रूस के मंत्रीपूर्ण रूप का स्वागत किया। रूस के साथ अगस्त, 1971 में मंत्री-मन्त्रि की गई, लेकिन गुट-निरपेक्षता और स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति पर धांच नहीं आने दी। सन्धि की धारा 4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सोवियत संघ भारत की गुट-निरपेक्ष नीति को स्वीकार करना है और उसे विश्व-शान्ति के लिए उपयोगी मानता है। सन्धि के मभी अनुच्छेदों की शब्दावली शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की विचारधारा को पुष्ट करने वाली, सैनिक गठबन्धनों का विरोध करने वाली तथा विवादों को 'पारस्परिक सम्मान और सम्बुद्ध दारा द्वि-पक्षीय ढंग से' निरादने की समर्थक है। सन्धि सम्पन्न होने के उपरान्त अभी तक दोनों पक्षों की ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो गुट-निरपेक्षता के विपरीत हो या किसी भी रूप में सैनिक गठबन्धन को समर्थन देनी हो। दिसम्बर, 1971 में वगलादेश के प्रश्न पर जो भारत-पाक युद्ध हुआ उसने गुट निरपेक्षता की नीति को पुनः सही सिद्ध कर दिया, पाकिस्तान को हथियार देन वाले पाकिस्तान को प्रंगूठा दिखा गए और देखते-देखते पाकिस्तान अपने एक भू-खण्ड को अपनी ही भूमिका से जो बंठा।

उत्तर-विपक्षनाम के साथ जनवरी, 1972 में दोरय सम्मन्धों की घोषणा कर श्रीमती गांधी ने अपनी स्वतन्त्र नीति का परिचय दिया। अक्टूबर, 1973 में चौथा अरब इजरायल युद्ध छिड़ने पर भारत का स्पष्ट मत रहा कि तनाव का मूल कारण इजरायल का अधिग्रहण रव था। चूंकि अरबों का प्रसन्नोप विस्फोटक गोमा रव पट्टेच चुका था, अतः युद्ध के दायित्व के लिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। भारत का दृष्टिकोण यह था कि इजरायल अरब क्षेत्र से हट जाए, इजरायल को प्रभुत्वसम्पन्न देश के रूप में जीवित रहने का अधिकार प्राप्त हो और फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों का समुचित समाधान खोजा जाए। भारत का यह दृष्टिकोण सन्तुलित और निष्पक्ष था और पहले ही की भांति गुट-निरपेक्ष नीति के अनुरूप था। युद्ध के बाद अरबों ने अपने 'तेल-प्रत्य' का प्रयोग कर विश्व के देशों के लिए विशेष-कर प्रल्प-विकसित राष्ट्रों के लिए—सकट उत्पन्न कर दिया। भारत के प्रति भी कोई रियायत नहीं की गई। एक मित्रदेश के प्रति इस प्रकार के व्यवहार से भारतीय लोकमत काफी क्षुब्ध हो गया, किन्तु फिर भी भारत अरबों को अपना कूटनीतिक समर्थन देता रहा। अप्रैल, 1975 में कम्बोडियाई और वियननामी युद्ध की समाप्ति और वहाँ से अमेरिका की लज्जाजनक पराजय ने भारत के इस मत

को पुष्टि की कि बड़े राष्ट्रों को दूसरे देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यदि छोटे देश गुट-निरपेक्ष नीति का अनुसरण करें तो दस प्रकार के हस्तक्षेप से बहुत कुछ बचा जा सकता है। पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य करने के लिए सन् 1976 में भारत ने जो पहल की वह इस नीति के प्रयोग का पुनः स्पष्ट प्रमाण था। 24 मई, 1976 को ससद् में विदेश मन्त्रालय के कार्यों पर बहम के समय ग्राम तीर से स्वीकार किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः कायम करने तथा चीन के साथ राजनयिक सम्बन्धों का दर्जा बढ़ाने के निर्णय भारत की विदेश नीति की प्रभावशाली उपलब्धि है। जुलाई, 1976 में भारत-पाक के बीच विधिवत् राजदूत स्तर पर सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए और 20 सितम्बर, 1976 को जनवादी चीन गणराज्य के राजदूत श्री चेन चाऊ मुवान ने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत कर दिया।

वास्तव में 1976 का सम्पूर्ण वर्ष भारत की गुट-निरपेक्ष नीति के जयघोष के साथ समाप्त हुआ। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय की 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अर्थों का उल्लेख उपयुक्त होगा—

“तनाव से अपेक्षाकृत मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, समीक्षाधीन वर्ष में भारत अपने पड़ोसियों, विकासशील विश्व तथा विकसित देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में अपनी ओर से कुछ उद्देश्यपूर्ण कदम उठा सका। बहुत दिनों से चली आ रही कुछ समस्याओं का निराकरण हुआ और कुछ को बड़ने से रोका गया। भारत के रचनात्मक रवये की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा प्रशंसा की गई और शान्ति स्थापित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में इसे ठोस सहयोग माना गया। अमुरक्षा अथवा शका की भावना मन में लाए बिना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भारत ने कई अवसरों पर अपनी ओर से पहल की; जो वह एक तो अपनी अर्थ-व्यवस्था की गतिशीलता और लचीलेपन के कारण और दूसरे स्वातंत्र्योत्तर दशान्वियों में शिल्प विज्ञान और वैज्ञानिक आन्तरिक-संरचना के कारण ही कर सका। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों के बाद मार्च, 1977 में सरकार में शान्तिपूर्ण परिवर्तन हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा और इससे मुझ लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं पर आधारित हमारी हडता और स्थिरता की एक तस्वीर उजागर हुई।”

“मतभेदों के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने तनाव-शैथिल्य की भावना में अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के विभिन्न पक्षों की दृष्टि से भारत ने शान्ति, स्वतन्त्रता और सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यह स्वीकार करते हुए कि तनाव-शैथिल्य किमी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और इसका विस्तार ससार के सभी भागों में होना चाहिए, भारत ने हिन्दमहासागर में विदेशी सैनिक उपस्थिति और अड्डों की स्थापना का विरोध किया। उसने इस नीति का समर्थन किया कि हिन्दमहासागर शान्ति-क्षेत्र रहना चाहिए जैसा कि अफ्रीकाई सदस्यों राज्य चाहते हैं और जैसा कि

संयुक्तराष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह हथियारों की होड़ रोकने को और सार्वभौम निरस्त्रीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग न किए जाने को अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने की दिशा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम मानता है। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय के बीच अहस्तक्षेप, समानता और शान्तिपूर्ण सह-प्रस्तित्व के माध्यम पर सहकारितापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाने चाहिए।”

“अपने सभी पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सामान्य और अच्छे बनाने के प्रयत्नों द्वारा भारत ने स्वयं अपने क्षेत्र में तनाव-शैथिल्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से बहुत से मामले सुलझाये गए। श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके आधार पर उसके साथ मिलने वाली समुद्री सीमा अंकित कर दी गई। मालदीव और भारत के बीच की समुद्री सीमा के परिशीलन के लिए मालदीव के साथ एक समझौता सम्पन्न हुआ। अफगानिस्तान और नेपाल के साथ सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहे। अफगानिस्तान और नेपाल के साथ मन्त्री और अधिकारी-स्तर पर यात्राओं के विनिमय में और इन यात्राओं के दौरान जो बातचीत हुई उसमें समझ बूझ और सद्भावना की भावना का परिचय मिला। चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य करने की दिशा में पहल की गई और राजदूत के स्तर पर उस देश के साथ राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किए गए। पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्धों में जो परिवर्तन आया वह भी इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण बात थी। मई 1972 के शिमला-समझौते में सामान्यीकरण के लिए जो कदम उठाने की बात सोची गई थी और जो किसी न किसी कारण स्थगित होती जा रही थी, वह इस वर्ष के मध्य में एक ही राजनयिक बैठक में निश्चित कर दी गई और इसमें दोनों देशों ने पूर्ण सहयोग दिया। जुलाई, 1976 में दोनों देशों के बीच राजदूत स्तर पर पुनः सम्बन्ध स्थापित हुए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रेल-सम्पर्क भी पुनः स्थापित हुआ और निजी व्यापार भी फिर से चालू हो गया। बंगला देश के साथ भी भारत अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने और उन्हें सुधारने की दिशा में प्रयत्न करता रहा तथा आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में उसे कुछ हद तक सफलता भी मिली।”

“अपने निकटतम पड़ोसियों के अतिरिक्त भारत दक्षिण-पूर्वी एशिया और पश्चिमी-एशिया के देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए निरन्तर कार्य करता रहा। इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा के सम्बन्ध में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। विदेश जनमन्त्री ने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपीन्स के साथ अपने मंत्री सम्बन्धों को सुदृढ़ करने तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से इन देशों की यात्रा की। ‘एसीयन’ के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के लिए इस क्षेत्र के देशों के प्रयास का भारत ने स्वागत किया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया को शान्ति, स्वतन्त्रता और तटस्थता का क्षेत्र बनाने के संकल्प का समर्थन दिया।

लाप्रोस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से निकटतर आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं के द्वार खुले। भारत ने विषयनाम के दोनों क्षेत्रों के एकीकरण का स्वागत किया और विषयनाम के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के लिए अपना समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री के विशेष दूत की यात्राओं से तथा विषयनाम के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुत से क्षेत्रों में अधिक सहयोग के द्वार खुले। पूर्वी एशिया में भारत-जापान व्यापार सहयोग समिति और दोनों देशों के मन्त्रालयों के अधिकारियों की सलाहकार समिति की बैठकों के माध्यम से जापान के साथ निकट व्यापारिक और राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए। कोरिया गणराज्य तथा कोरियाई लोक गणराज्य के साथ सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहे। जहाँ तक पश्चिमी एशिया का प्रश्न है, भारत ने अरबों के पक्ष के प्रति अपना समर्थन पुनः व्यक्त किया तथा इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ निकटतर सम्बन्धों के लिए कार्य किया। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि अरबों के जो प्रदेश इजरायल के गैर-कानूनी अधिकार में हैं उन प्रदेशों में यदि इजरायल वापस हट जाए और फिलिस्तीनी लोगों को उनके वैध अधिकार पुनः प्रदान कर दिए जाएँ तो अरब-इजरायल समस्या का एक स्थायी और न्यायोचित समाधान निकल सकता है। भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्धों में वृद्धि हुई। माल और तथ्यों के आदान-प्रदान के प्रतिरिक्त भारत ने इस क्षेत्र के लिए तकनीकी और प्रदर्शक-कुशल जनशक्ति की आपूर्ति बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दी जो अरब देशों के साथ भारतीय सहयोग की एक विशेष बात है। इस क्षेत्र के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की एक नई विशेषता यह थी कि भारत ने सामग्री और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर इस क्षेत्र के औद्योगीकरण में अत्यधिक योगदान दिया।”

“अफ्रीका में तजानिया और जाम्बिया के साथ व्यापक पैमाने पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग किया गया। अन्तर्सरकारी सहयोग के अन्तर्गत हजारों भारतीय विशेषज्ञों को चुनकर इन देशों के आन्तरिक संरचना के विकास की विभिन्न शाखाओं में नियोजित किया गया। अफ्रीका में पुर्तगाल के अवीनस्थ जो उपनिवेश थे उनकी स्वतन्त्रता के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जात का ध्यान जिम्बाबवे के मुक्ति-संघर्ष पर केन्द्रित हुआ। प्रभावी बहुसंख्यक-शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सघर्षरत जिम्बाबवे के लोगों को सभी सम्भव सहायता देने के आने बचने को भारत ने पुनः दोहराया। इसी प्रकार भारत ने दक्षिणी अफ्रीकी सरकार द्वारा नासिबिया पर निरन्तर गैर-कानूनी अधिकार की निन्दा की और कहा कि ‘स्वापो’ के नेतृत्व में आवादी के लिए वैध संघर्ष करने वाले नासिबियाई लोगों का समर्थन करेगा। दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथक्वासन के विरुद्ध संघर्ष में भारत के योगदान की सराहना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में जातीय पृथक्वासन विरोधी समिति ने एक विशेष बैठक बुलायी जो एक अमाधारण सद्भावनापूर्ण बात थी।”

“समीक्षाधीन अवधि में भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों के बीच वर्तमान सहयोग के लिए वाणिज्यिक, प्रौद्योगिक और

आर्थिक सम्बन्ध और अधिक विकसित हुए। राजनीतिक क्षेत्र में उच्च स्तर पर यात्राओं के विनिमय के माध्यम से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहे गए। अप्रैल, 1977 में जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री की यात्रा से उस देश के साथ बेहतर सम्बन्ध और सहयोग की सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर हुईं।"

"समुक्तराज्य अमेरिका के साथ सहयोग विकसित करने के तरीके और उपाय खोजने के लिए विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत उम देश के साथ भारत के सम्बन्धों की दिशा में एक विशेष बात थी। अमेरिका ने मुक्त और निष्पक्ष चुनावों के परिणामस्वरूप लोकतन्त्रात्मक उपायों से सरकार में शान्तिपूर्ण परिवर्तन की सराहना की और उत्तम सम्बन्धों का परिचय दिया। भारत की आशा है कि समानता, सद्भाव और पारस्परिक लाभ के आधार पर समुक्तराज्य के साथ निष्ठा सम्बन्धों का विकास हो सकेगा। गुट-निरपेक्ष समूह के सदस्य के रूप में दक्षिण और मध्य अमेरिका के कई देशों के साथ भारत के सम्बन्धों के सहयोग की अधिक सम्भावनाएँ दृष्टिगोचर हुईं। भारत ने कई द्विपक्षीय सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए तथा इस क्षेत्र के देशों के साथ अपना सहयोग बढ़ाने के लिए यात्राओं के विनिमय के माध्यम से अपने सम्बन्ध विकसित किए।"

"गरीब और अमीर देशों के बीच की असमानता के कारण विश्व समुदाय के समक्ष जो आर्थिक चुनौतियाँ हैं उनकी ओर भारत का ध्यान निरन्तर केन्द्रित रहा। बाहरी दबाव का मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक है कि विकासशील देशों में आत्मनिर्भरता और परस्पर सहयोग हो और इसके लिए यह जरूरी है कि ससार के अर्थतन्त्र की निर्यातात्मक प्रक्रिया में कुछ पुनर्वितरण करने के प्रयास किए जाएँ।"

"जुलाई, 1976 में नई दिल्ली में प्रेस एजेंसी पूल के सम्बन्ध में गुट निरपेक्ष देशों के मन्त्रि-स्तर सम्मेलन में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जिसमें गुट-निरपेक्ष देशों की प्रेस एजेंसियों का एक पूल बनाने की मियारिश की गई। कोलम्बो शिखर-सम्मेलन में भारत ने गुट-निरपेक्षता की अपेक्षा और गुट-निरपेक्ष देशों के बीच एकता और सहयोग के महत्त्व पर बल दिया।"

श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता की नीति (मार्च-दिसम्बर, 1977)—प्रधानमंत्री श्री देसाई ने अपनी सरकार द्वारा गुट-निरपेक्षता और सह-अस्तित्व की नीति का अनुसरण करते रहने की घोषणा की। कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जा रहा था कि नई सरकार सामयिक समस्याओं पर तटस्थ राष्ट्रों के दृष्टिबिन्दु के प्रति निष्ठापूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखेगी, गुट-निरपेक्षता की नीति पर पहले की भाँति न चलकर अमेरिका परत हो जाएगी, आदि। लेकिन प्रधानमंत्री श्री देसाई और विदेश मंत्री श्री वाजपेयी ने इन भ्रान्तियों को दूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भारत की विदेश-नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा। अप्रैल, 1977 में नई दिल्ली में 25 राष्ट्रों के तटस्थ सम्मेलन में नई सरकार की घोषणा की जाँच हुई। 25 सदस्यों के व्यूरो को सम्बोधित करते हुए

श्री देसाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुट-निरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा बन गई है। भारत के लिए यह राष्ट्रीय मूल्य की बात है और भारत सच्चे प्रथम में गुट-निरपेक्ष रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कोलम्बो शिखर-सम्मेलन के निर्णय को ठोस और समन्वित ढंग में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गुट-निरपेक्ष देशों के समक्ष आज चुनौती इस बात की है कि अपनी सामूहिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उनमें कितनी प्रबल शक्ति है, कितनी समन्वय-शक्ति है, कितनी आपस में बांट लेने की शक्ति है और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो सामूहिक प्रयास और आत्म-विश्वास के माध्यम से इन्हें प्राप्त कर लेने के लिए कितना श्वास करने की शक्ति है। भारत का यह विश्वास है कि विकासशील देशों को पारस्परिक सहयोग तथा आत्मविश्वास के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि पारस्परिक लाभ पर आधारित न्यायोचित अन्यायश्रयता विकसित की जाए जिसमें ऐसी नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक व्यवस्था के द्वार खुले जिसमें समय शान्ति और समृद्धि पर आधारित अधिक और राजनीतिक स्थिरता की नींव रखी जा सके।”

नई सरकार के नेतृत्व में सन् 1977 की समाप्ति तक यह बात निःसंदिग्ध रूप में स्पष्ट हो गई है कि भारत गुट-निरपेक्षता की नीति पर दृढ़ है। विश्व के समक्ष निगुट नीति की अनिवार्यता में कोई संदेह नहीं रहा है। निगुट नीति पर चलते हुए ही अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों में तेजी से सुधार हो रहा है और जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर की भारत-यात्रा की सम्भावना है। अक्टूबर, 1977 में प्रधानमंत्री श्री देसाई ने सोवियत संघ की यात्रा की थी और दोनों देशों ने शान्ति, विकास और सहयोग के लिए गुट-निरपेक्ष-नीति को अपना सुदृढ़ समर्थन दिया था। विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अक्टूबर, 1977 में संयुक्तराष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से स्पष्ट किया था। श्री वाजपेयी के भाषण में नई सरकार के दृष्टिकोण और भारतीय विदेश-नीति की सापेक्षता का सबल स्पष्टीकरण हुआ।

संयुक्तराष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री श्री वाजपेयी का नीति-सम्बन्धी भाषण

न्यूयार्क में 4 अक्टूबर, 1977 को संयुक्तराष्ट्र महासभा को सम्बोधित करते हुए विदेशमन्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा—

“भारतवर्ष में हाल ही में एक ऐतिहासिक और अहिंसात्मक क्रान्ति हुई। गत मार्च में हुए चुनावों में भारतीय जनता ने मानव की दुर्दम्य आत्मशक्ति का परिचय दिया और एक स्वतन्त्र और उन्मुक्त समाज में अपनी आस्था की पुष्टि की। उन्होंने लोकतन्त्र को नष्ट करने के तामसी तथा निरकुश शक्तियों के घूर्ततापूर्ण प्रयत्नों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। सारे देश की 60 करोड़ जनता के लिए मार्च की यह क्रान्ति स्पष्टतया दूरगामी महत्त्व की है, साथ ही समस्त संसार के स्वतन्त्रता प्रेमी लोगों के लिए भी यह उसनी महत्वपूर्ण है।

“हमारी जनता ने निर्भीक होकर उन मूलभूत सिद्धान्तों, जीवन-मूल्यों तथा आकांक्षाओं की पुष्टि की जिन पर लगभग 30 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधारशिला रखी गई थी। भारत के लोगो ने अपनी कोई हुई स्वतन्त्रता और मूलभूत मानव-अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए। मैं भारतीय जनता की ओर से संयुक्त राष्ट्रसंघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूँ। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारा विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व में शान्ति और सुरक्षा कायम रखने और राष्ट्रों के बीच सहयोग के माध्यम से समानता, न्याय और समता पर आधारित शान्तिपूर्ण प्रगति को प्रोत्साहित करने का उपकरण बनेगा।

“जनता सरकार शान्ति, गुट-निरपेक्षता और सब देशों के साथ मैत्री की नीति का दृढ़ता से अनुसरण कर रही है। ये नीतियाँ सदा से भारत के राष्ट्रीय मंतव्य और परम्परा पर आधारित रही हैं। गुट-निरपेक्षता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राष्ट्रीय सम्प्रभुता का विस्तार है। इसका मूल तत्त्व तटस्थता न होकर स्वाधीनता है जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारे राष्ट्रीय सपनों और दामता नया दमन से मानव-चेतना की मुक्ति का सहज परिणाम है। हम राष्ट्रों की सच्ची स्वतन्त्रता में विश्वास रखते हैं। हमारी मान्यता है कि हर देश को अपने सर्वोत्तम राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नीति अनुसरण करने तथा प्रत्येक समस्या पर गुणों के आधार पर विचार करने तथा निर्णय लेने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

“नई सरकार के शासन सम्भालते ही न केवल गुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलते रहने की प्रतिज्ञा उसके मौलिक तथा सकारात्मक रूप को पुनः प्रतिष्ठित करने की घोषणा की। यह सन्तोष का विषय है कि वास्तविक गुट-निरपेक्षता पर हमारे द्वारा दिए गए जोर और इस नीति की उत्साह और गतिशीलता से प्राप्ति बढ़ाने के हमारे निर्णय को सही प्रर्थों में देखा और समझा गया है।

“‘समुर्ध्व कुटुम्बकम्’ की परिक्ल्पना पुरानी है। भारतवर्ष में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि ससार एक परिवार है। अनेकानेक प्रपत्तियों और प्रयोगों के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में इस स्वप्न के अथवा साकार होने की सम्भावना है क्योंकि संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता लगभग विश्वव्यापी हो गई है और वह 400 करोड़ लोगों का जो विभिन्न जातियों, रंगों और समुदायों के हैं, प्रतिनिधित्व करता है, तथापि यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ केवल सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों का मिलन मात्र मात्र न रहे। हमें इस लक्ष्य की ध्यान में रखना चाहिए कि किसी प्रकार राष्ट्रों की महासभा मानवता के सामूहिक विवेक और इच्छा-शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली मानव की समष्टि का रूप ले सके।

“संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणापत्र केवल राष्ट्रों की ओर से या राष्ट्रों के लिए किया गया आह्वान मात्र नहीं है। यह ससार के समस्त लोगों द्वारा किया गया उद्घोष है कि अपनी भावी पीढ़ियों की युद्ध की विभीषिका में रक्षा की जाए और वास्तविक स्वतन्त्रता के दातावरण में एक नई विश्व-व्यवस्था की रचना की जाए।

“हमारी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निरन्तर सर्वोच्च स्थान मनुष्य, उसके सुख और कल्याण तथा मानव की आधारभूत एकता को मिलना चाहिए। मेरा अभिप्राय किसी साकृतिहीन मानव से नहीं है जो अतीतकाल से निरकुण्ठता को थोपने का बहाना रहा है, मेरा मतलब जीते जागते मानव से है। उसकी सवेदनाएँ और अपेक्षाएँ, उसका सुख और दुःख हमारे प्रयत्नों का केन्द्र-बिन्दु होना चाहिए।

“हम विश्व-शान्ति के, ऐसी शान्ति के जो जीवन्त है, प्रबल समर्थक हैं। विश्व-शान्ति हमारे सब प्रयत्नों की आधारशिला है। शान्ति की परिभाषा केवल युद्ध न होना मात्र ही नहीं है। विश्व-शान्ति का ताता-बाना किसी समय भी छिन्न-भिन्न हो सकता है। उसका संरक्षण तो केवल उन सामूहिक प्रयत्नों से हो सकता है जो राष्ट्रों के बीच विद्यमान असमानता और असन्तुलन को मिटा सकें, एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के प्रभुत्व और शोषण का अन्त कर सकें और ससार के समस्त लोगों को समानता के आधार पर अवसर और अधिकार प्रदान कर सकें।

“निःसंदेह हर देश अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहता है। पर कोई देश सबसे अलग-थलग होकर अपनी चहारदीवारी के भीतर नहीं रह सकता। हमें यह समझना होगा कि विश्व के देशों में पारस्परिक निर्भरता के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है। इसी में विश्व के मानव का कल्याण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम सब अपने-अपने राष्ट्रीय क्षितियों के पार दृष्टि दोड़ाएँ। पारस्परिक सहकारिता और त्वाग की प्रवृत्ति को बल देकर ही मानव-समान प्रगति और समृद्धि का पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है।

“अध्यक्ष महोदय, महासभा के ममक्ष जो कार्यसूची है उसमें ससार की कई महत्त्वपूर्ण समस्याएँ सम्मिलित हैं। मैं इनमें से कुछ ऐसे विनिष्ट प्रश्नों का उल्लेख करना चाहूँगा जितना तात्कालिक महत्त्व है और जिनको हमारे इस सामूहिक विचार-विनिमय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

“हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या दक्षिणी अफ्रीका में मानव-अधिकारों और स्वतन्त्रता के लिए हो रहे महान् संघर्ष की है। भारत ने सदैव ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अनावश्यक रक्तपात और हिंसा का विरोध किया है। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों का समाधान शान्ति और स्पर्धा के द्वारा हो। एंटी-अहिंसा के अन्वेषण के अन्तर्गत ही भारत-अहिंसा आधारभूत सिद्धान्तों पर दृढ़ था। ये सिद्धान्त ये औपनिवेशिक दमन का तीव्र विरोध और रंगभेद के प्रत्येक रूप तथा मानव-अधिकारों के प्रत्येक हनन की पूर्ण अस्वीकृति। इन सिद्धान्तों के प्रति स्वतन्त्र भारत की अट्ठा घाज भी अधिक बढ़ी है।

“अफ्रीका में चुनौती स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि किसी जनता की स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठा से रहने का अपरिहार्य अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा अन्याय और दमन करता रहेगा। निःसंदेह रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। रंगभेद निश्चित रूप से

समाप्त होना चाहिए। इसका अस्तित्व मानवता पर कर्तक और समुक्त राष्ट्रसंघ पर गम्भीर आक्षेप है।

“भारत चाहता है कि जिम्बाबवे की समस्या का शान्तिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रीम समाधान हो। भारत ने इसी संदर्भ में अगस्त अमेरिकी प्रस्तावों के उन अंशों का स्वागत किया है जो एक विनिश्चित समाधान में वास्तविक बहुमत शासन की स्थापना की ओर इंगित करते हैं। आशा है कि इस विषय पर हाल ही में सुरक्षा परिषद् में स्वीकृत प्रस्ताव से सुदृढ़-विराम होगा और अन्तर्गत समस्या का समाधान निकलेगा। यह अधिकांश इस बात पर निर्भर है कि इयान स्मिथ का अवैधानिक शासन दुराग्रह और अक्ल स्थापित तथा विवेकहीन दृष्टिकोण अपनाते की तैयार है या नहीं।

‘जब तक स्मिथ सरकार हटा नहीं दी जाती और जब तक सम्बन्धित समस्या को स्वाधीनता पुनः प्राप्ति नहीं हो जाती, हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता के सेनानी अपने हथियार रख देंगे। भारत जिम्बाबवे में अपनी स्वतन्त्रता के विपक्षी सत्ता-देशभक्त-शक्तियों के प्रति अपने ठोस समर्थन की पुनः पुष्टि करता है जो अत्यन्त विषम परिस्थितियों में अपनी भूमिका के लिए बहादुरी से सघर्ष कर रहे हैं। अगर सत्ता-हत्या करने के निष्फल प्रयास में इयान स्मिथ विषम-जनमत की आतंक्य कर प्रवृत्ति करना तो समुक्त राष्ट्रसंघ की अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सार्वजनिक और अत्यन्त वाली सत्ता और उसके समर्थक दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अनिवार्य प्रतिवाधों को अधिक व्यापक बनाना होगा। इसी से अवैधानिक शासन का अन्त निकट आया और जिम्बाबवे की जनता को अपने आत्म के स्वयं निर्णय का अधिकार प्राप्त होगा।

“नामीबिया में भी, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र का स्वर प्राप्त है, समुक्त राष्ट्रसंघ की सत्ता विषयसमीक्षता और प्रतिष्ठा को समान चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी यह देखना शेष है कि वास्तविक देशों के प्रत्यक्ष दक्षिण अफ्रीकी सरकार को नामीबिया छोड़ने के लिए कहीं तक तैयार करते हैं ताकि समुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव क्रियान्वित हो सकें। वास्तविक के, जो नामीबिया का एक भाग है, में स्मिथ के शासन में शामिल करने के दक्षिण अफ्रीका के निर्णय की हम निन्दा करते हैं। अभी तरह नामीबिया के एक क्षेत्र का अलग परीक्षण के लिए कथित उपयोग करने की योजना की भी हम भर्त्सना करते हैं।

“हम पूर्ण रूप से स्वाधीन (दक्षिणी, पश्चिमी अफ्रीकी जन सत्ता) के साथ हैं और सभी देशों की उनके प्रतिनिध्यात्मक स्वयं को स्वीकार करने की शक्ति करते हैं। यदि स्वतन्त्रता प्राप्ति का यही एक मात्र उपाय रह जाता है तो हम नामीबिया की जनता से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि यह अपना सशस्त्र सघर्ष छोड़ दे। किन्तु हम समस्या का समाधान केवल हथियों के प्रयोग और सघर्ष पर ही नहीं छोड़ सकते। इस कार्य में समुक्त राष्ट्रसंघ का मासुहिक और प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व है समुक्त राष्ट्रसंघ ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार को नामीबिया से पूर्ण रूप से हट जाने में लिए बाध्य करने की अपनी सामर्थ्य का निश्चय ही अभी तक पूरा उपयोग नहीं किया है।

“जब दक्षिण अफ्रीका में हम उपनिवेशवाद और रंगभेद के निकृष्टतम रूप का सामना कर रहे हैं। पश्चिमी एशिया में विश्वशान्ति को और भी अधिक बिस्फोटक खतरा है। यहाँ भी कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का प्रश्न है। प्रथम, किसी को भी आक्रमण के लागे का उपयोग करने की छूट नहीं दी जा सकती। दूसरे, किसी भी जनसमूह को अपने ही देश में रहने के अपरिहार्य अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरे, सीमा सम्बन्धी सभी विवाद शक्ति-प्रयोग द्वारा नहीं बल्कि बातचीत द्वारा सुलझाए जाने चाहिए।

“इस दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट है कि इजरायल ने बल-प्रयोग द्वारा जिन क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा किया है उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। आक्रमण समाप्त होना ही चाहिए। यह भी आवश्यक है कि फिलिस्तीन के अरब लोगों को, जिन्हें बलपूर्वक अपने घरों से निष्कासित कर दिया गया है, पुनः अपने देश में लौटने के अपरिहार्य अधिकार का उपयोग करने दिया जाए। इस क्षेत्र के सभी लोगों और राज्यों को अपने पड़ोसियों के साथ शान्ति और मेल-मिलाप से रहने का अधिकार है। इस भूखण्ड की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए यह एक आवश्यक शर्त है। अभी हाल में इजरायल ने बेस्ट बक और गाजा में नई बस्तियाँ बसाकर अधिकृत क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन का जो प्रयत्न किया है सयुक्त राष्ट्रसंघ को उसे पूरी तरह अस्वीकार और रद्द कर देना चाहिए।

“यदि इन समस्याओं का सन्तोषजनक और स्वरित समाधान नहीं होता तो इसके दुष्परिणाम इस क्षेत्र के बाहर भी फेल सकते हैं। यह अति आवश्यक है कि जिनेवा सम्मेलन का शीघ्र ही पुनः आयोजन किया जाए और उसमें पी. एन. ओ. को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

“साइप्रस की स्थिति का भी समाधान शेष है। हमें अब भी आशा है कि द्विपक्षीय सामुदायिक बातचीत पुनः आरम्भ होगी और समस्या का ऐसा हल निकलेगा जो साइप्रस गणराज्य की क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकता और गुट-निरपेक्षता के अनुरूप होगा।

“अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आर्थिक समस्याओं का महत्व अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। समानता और न्याय पर आधारित एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को विश्व-समाज में मान्यता प्राप्त हो गई है। अब इसे मूर्त रूप देने की दिशा में शीघ्र अग्रसर होना है जिससे विश्व के सभी नर-नारियों को अधिक न्यायसंगत और समुचित अवसर तथा अपने धर्म के लाभ प्राप्त हों।

“इसमें सन्देह नहीं कि विकसित देशों की अपनी आन्तरिक सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ हैं। लेकिन उनके लिए अपने दृष्टिकोणों और नीतियों को तात्कालिक तथा सकीर्ण राष्ट्रीय हितों के ऊपर उठाना आवश्यक है। यह पुष्टा जा सकता है कि क्या विकसित देशों की आर्थिक ढाँचे की समस्याओं के समाधान का युक्तिसंगत और प्रयुक्त उपाय यह नहीं है कि इन देशों से विकासशील देशों में विशिष्ट मात्रा में वित्तीय और प्रौद्योगिक क्षमता का स्थानान्तरण किया जाए। समृद्ध देशों की

बेरोजगारी और आर्थिक उथल-पुथल का समुचित समाधान संसार के तीन अरब लोगो की श्रम-शक्ति में वृद्धि होने पर ही हो सकता है।

“भारत ने इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में उत्साह और ईमानदारी से भाग लिया है। हमारी मान्यता रही है कि संसार के आर्थिक रोगों का निवारण सफल की भावना को धल देने से नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक निर्भरता और सहयोग की नई भावना प्राप्त करने से होगा।

“भारत सब देशों से मैत्री चाहता है और किसी पर प्रभुत्व नहीं चाहता। जनता सरकार सभी देशों के साथ स्नेह, सहयोग और समझदारी के सेतु निर्माण करने के लिए सज्जित है। सर्वप्रथम हमारा ध्यान निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ करने की ओर गया है। मैं यह मैत्री-सन्देश लेकर हाल ही में नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान गया था। पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं जिससे न केवल स्थायी शान्ति कायम हो बल्कि लाभदायक सहयोग में भी वृद्धि हो।

“चार दिन पूर्व 30 सितम्बर, 1977 को भारत और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने गंगाजल की समस्या पर हुए एक सम्झौते पर प्रथम हस्ताक्षर किए हैं। यह एक व्यापक सम्झौता है जिसमें अल्पकालीन समस्या का समाधान किया गया है और दीर्घकालीन समस्या के समाधान की नींव डाली गई है। इससे दोनों देशों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।

‘पिछले एक वर्ष में दक्षिण एशिया के देशों में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। फिर भी इन देशों के लोगों को इस बात का ध्येय मिलना चाहिए कि दक्षिण एशिया पिछले कई दशकों की अपेक्षा आज तनाव से अधिक मुक्त है। यदि सचमुच दक्षिण एशिया में शान्ति और सहयोग का मार्ग प्रशस्त हो जाए तो हम सब, जिन पर विकास का समान बोझ है, अपने विकास की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे और अपने ससाधनों को विनाश से हटाकर विकास में लगा सकेंगे।

‘वस्तुतः हम यह विशेष प्रतीत करते हैं कि हमारे चारों तरफ के हिन्द महासागर के विशाल क्षेत्र की बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता और सैनिक झड़पों से मुक्त रखा जाए जिनका उपयोग आक्रमण के लिए हो सकता है। विस्तृत परिप्रेक्ष्य में भारत तनाव-शैथिल्य के प्रयत्नों का स्वागत करता है। भारत चाहता है कि तनाव-शैथिल्य केवल यूरोप तक ही सीमित न रहकर विश्वव्यापी हो और उसके लाभ विश्व के सब देशों और लोगों को प्राप्त हो।

‘वर्षानुवर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ में अनगिनत प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिनमें पूर्ण निस्त्रीकरण, विशेषकर आणविक निस्त्रीकरण की मांग की गई है। आणु शस्त्रों की दौड़ बहुत भयावह स्थिति में पहुँच गई है। विनाशकारी हथियारों के अस्स्वार ने सगर को भारी दुविधा में डाल दिया है। हमसे कहा जाता है कि युद्ध रोकने के लिए आणविक शस्त्र आवश्यक हैं और यह कि इन शस्त्रों के प्रयोग का हर ही युद्ध की रोकथाम करने में समर्थ हो सकता है। हम इस दावे को स्वीकार नहीं करते।

“हमारी धारणा यह है कि आणविक शस्त्र खतरनाक हैं, भले ही वे एक देश के पास हों, कुछ देशों के पास हो या कई देशों के पास हों। हम केवल आणविक शस्त्रों के विस्तार के विरुद्ध नहीं हैं, वस्तुतः हम तो आणविक शस्त्रों के ही विरुद्ध हैं। भारत सदा से ही आणविक शस्त्रों को प्राप्त करने और उन्हें विकसित करने का विरोधी रहा है।

“तथ्य तो यह है कि भारत पहला देश था जिसने संयुक्त राष्ट्रसंघ में 20 वर्ष पूर्व समस्त आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने का मामला उठाया था। उस समय बड़ी शक्तियाँ हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जब वे तैयार हुईं तो उन्होंने केवल आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी) पर हस्ताक्षर किए। यह 15 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय विश्व में हर्ष की लहर दौड़ गई और यह आशा बलवती हुई कि व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी) पर भी जल्दी ही समझौता हो जाएगा। किन्तु हम अभी भी उसकी राह देख रहे हैं। आंशिक प्रतिबन्ध लागू करने के बाद, पहले की बजाय अधिक अणुशस्त्र परीक्षण हुए हैं। भूमिगत शस्त्र परीक्षण तो अभी भी जारी हैं। आणविक निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

“भारत न तो आणविक शस्त्र-शक्ति है और न बनना चाहता है। नई सरकार ने अमर्दिघ शब्दों में इस बात की पुनर्घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि यदि विश्व के अन्य सभी देश आणविक शस्त्रों का निर्माण करने लगे तब भी भारत आणविक शस्त्रों के निर्माण को प्रारंभ नहीं होगा। हमने अणु-शस्त्रों के प्रसार को रोकने वाली सन्धि (एन पी टी) पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि हम उसे एक असमान और भेदभूलक सन्धि समझते हैं। यह सन्धि दस वर्ष पूर्व तैयार हुई थी। जब से अब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसके कारण हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई हो।”

पाकिस्तान के साथ भारत के सम्बन्ध

भारत के विभाजन की कीमत पर अगस्त, 1947 में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। यह आशा की गई थी कि देश के विभाजन से शान्ति और मैत्री को प्रोत्साहन मिलेगा लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान का रवैया उसके जन्मकाल से अब तक भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। सीमा-उल्लंघन, तोड़-फोड़, जासूसी आदि की घटनाओं को तो गिनती ही नहीं, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान चार बार आक्रामक कदम भी उठा चुका है—पहली बार सन् 1947 में, दूसरी बार अप्रैल, 1965 में कच्छ पर आक्रमण द्वारा, तीसरी बार सितम्बर, 1965 में और चौथी बार दिसम्बर, 1971 में। भारत ने इन आक्रमणों के बावजूद भी पाकिस्तान के प्रति मैत्री, सहयोग और उदारता का परिचय दिया है। ताशकन्द और शिमला समझौते इस बात के जीते-जागते प्रमाण हैं; तथापि इसे पुनः दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया फिर भी शत्रुतापूर्ण है और युद्ध तथा घमटी की भाषा में बात करता है। हाल ही में फरवरी, 1975 में श्री भुट्टो ने भारत को युद्ध की

धमकी देते हुए 'विश्व युद्ध होने से भी संकोच न करने' तक की चेतावनी दे डाली थी। इसका उत्तर रक्षा मन्त्री सरदार स्वर्णसिंह ने इन शब्दों में दिया था—“हम शान्ति चाहते हैं, किन्तु यदि कोई खुदबखी पर आमादा हो तो सिवाय लड़ाई के हमारे पास क्या चारा है? पाकिस्तान हमला करेगा तो उसको ऐसी सजा मिलेगी जो अब तक नहीं मिली।”¹

भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों का हम तीन युगों में विभाजन करके अध्ययन कर सकते हैं—नेहरू युग, शास्त्री युग और इन्दिरा युग।

नेहरू युग (अगस्त, 1947—मई, 1964)

प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने अपने शासन-काल में पाकिस्तान के प्रति मैत्री, सहानुभूति और भाईचारे की नीति अपनायी, लेकिन उन्हें मृत्युपर्यन्त पाकिस्तानी रवैये से निराशा ही हाथ लगी। नेहरू का प्रधानमन्त्रित्व-काल भारत की विदेश नीति का 'आदर्शवादी युग' था। यद्यपि चीनी आक्रमण के बाद नवम्बर, 1962 से इसने यथार्थवादी मोड़ लिया।

जूनगढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय—भारतीय क्षेत्र की रियासत जूनगढ़ के नवाब ने जब अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहा तो जनता ने विद्रोह कर दिया। जूनगढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया और रियासत के दीवान तथा चर्हों की पुलिस (जिनके हाथों में प्रशासन था) की प्रार्थना पर 9 नवम्बर, 1947 को भारत सरकार ने रियासत का शासन अपने हाथों में ले लिया। फरवरी, 1948 को जनमत-संग्रह में भारत के पक्ष में 1 लाख 90 हजार से भी अधिक मत आए जबकि पाकिस्तान के पक्ष में कुल 91 मत पड़े। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् में प्रश्न उठाया, किन्तु उसकी चाल सफल नहीं हुई।

हैदराबाद की रियासत भी पूरी तरह भारतीय क्षेत्र में थी। नवम्बर, 1947 में निजाम ने भारत के साथ एक 'यथा-पूर्व-स्थिति' का समझौता किया। यह निश्चय हुआ कि नया समझौता होने तक दोनों के बीच वही सम्बन्ध कायम रहेंगे जो पहले ब्रिटिश सरकार और हैदराबाद रियासत के बीच थे। लेकिन हैदराबाद की सरकार में प्रभावशाली मुस्लिम साम्प्रदायिक संगठन 'मजलिस-ए-इस्लाम' के रजाकारों ने रियासत में भीषण अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी और तब सितम्बर, 1948 में जनता तथा निजाम की सुरक्षा हेतु भारत ने पुलिस कार्यवाही की। रजाकारों ने आत्म-समर्पण कर दिया। हैदराबाद-सरकार ने समस्या को सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत कर दिया था, अतः समस्या का अन्तिम समाधान तब हुआ जब दिसम्बर, 1948 में भारत ने परिषद् में स्पष्ट कह दिया कि वह अब इस प्रश्न पर वाद-विवाद में कोई भाग नहीं लेगा।

श्वेत भुगतान का प्रश्न—स्वयम् भारत ने पुरानी सरकार के पूरे श्वेत का भार सम्भाला जिसके अनुसार उसे 5 वर्ष में पाकिस्तान से 300 करोड़ रुपा लेना

था, लेकिन पाकिस्तान ने ऋण चुकाने का नाम तक नहीं लिया जबकि भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपये का चुकारा कर दिया।

विस्थापित सम्पत्ति तथा अल्पसङ्ख्यकों की रक्षा का प्रश्न—सन् 1947 से 1957 तक लगभग 90 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और इतने ही गैर-मुस्लिम पाकिस्तान में भारत आए। दोनों ही क्षेत्रों के लोग अपने पीछे विशाल मात्रा में अपनी चल और अचल सम्पत्ति छोड़ गए। अनुमानतः भारतीयों ने पाकिस्तान में 3 हजार करोड़ रुपये की और मुसलमानों ने भारत में 300 करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ी थी। पाकिस्तान समस्या के समाधान के सभी सुझावों को ठुकराता रहा क्योंकि उसकी नीयत तो 27 सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति को हड़प लेने की थी।

दोनों देशों के समक्ष अल्पसङ्ख्यकों की रक्षा की समस्या भी विद्यमान थी। विभाजन के बाद पाकिस्तानी अत्याचारों के फलस्वरूप भारत में शरणार्थियों का ताँता लगा रहा। अप्रैल, 1950 में साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने और अल्पसङ्ख्यकों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों के बीच 'नेहरू लिखाकत समझौता' हुआ, जिसका पाकिस्तान की ओर से कभी पालन नहीं किया गया और पीड़ित हिन्दू शरणार्थी भारत में आते रहे।

नहरी विवाद—भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अन्य समस्या नदियों के पानी के सम्बन्ध में थी। पंजाब के विभाजन के कारण सिंचाई वाली नहरों के पानी के प्रश्न पर कठिन परिस्थिति पैदा हो गई। सतलज, व्यास और रावी नदियों के हैड वर्क्स भारत में रह गए, लेकिन नहरों की दृष्टि से 25 में से केवल 20 नहरें भारत में आई और एक नहर दोनों देशों में पड़ी। भारत के हिस्से में पंजाब का जो भी भाग आया उसकी कृषि-भूमि पैदावार की दृष्टि से प्रच्छी नहीं थी, क्योंकि वहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी जबकि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले भाग में सिंचाई की भरपूर व्यवस्था थी।

दोनों राष्ट्रों की सहमति से यह विवाद मध्यस्थता के लिए विश्व-बैंक को सौंप दिया गया जिसके प्रयत्नों से 19 सितम्बर 1960 को भारत और पाक में पन्ध्र देसित के पानी के दोनों राष्ट्रों में समान बँटवारे के बारे में 'नहरी पानी समझौता' (Indo-Pak Canal Water Treaties) सम्पन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार जो नदियों के विभाजन पर आधारित है, यह निश्चय किया गया कि 10 वर्ष की अवधि के बाद, जो पाकिस्तान की प्रार्थना पर 3 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी, तीनों पूर्वी नदियों का पानी भारत के अधिकार में और तीनों पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के अधिकार में रहेगा, केवल इनका सीमित पानी उत्तर की ओर के जम्मू और कश्मीर प्रान्त में प्रयोग किया जाएगा। यह तय हुआ कि 10 वर्ष तक भारत पूर्वी नदियों (सतलज रावी और व्यास) से पाकिस्तान को प्रत्येक वर्ष घटती हुई मात्रा में पानी देगा और नई नहरों के निर्माण के लिए पाकिस्तान को आवश्यक मात्रा में धन भी प्रदान करेगा। यदि पाकिस्तान भारत से पानी देने वाली

अबधि में 3 वर्ष के लिए प्रार्थना करेगा तो प्रार्थना स्वीकृत होने पर उसी अनुपात में भारत द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली धनराशि में कटौती कर दी जाएगी। 12 जनवरी, 1961 को इस सन्धि की शर्तें लागू कर दी गईं।

यह सन्धि पाकिस्तान के लिए विशेष लाभदायक थी। निष्पक्ष पर्यवेक्षकों को भी भारत के इस उदार दृष्टिकोण से आश्चर्य हुआ क्योंकि स्वयं उसको अपना कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए सिन्धु के पानी की काफी आवश्यकता थी।

भारत के युद्ध न करने के प्रस्तावों का ठुकराया जाना—करमौर पर सन् 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद से ही श्री नेहरू ने निरन्तर यह असफल प्रयत्न किया कि दोनों राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का युद्ध न करने सम्बन्धी एक स्थायी समझौता हो जाए। इस दिशा में श्री नेहरू ने प्रथम प्रयास दिसम्बर, 1949 में और दूसरा सन् 1956 में किया। नवम्बर, 1962 में श्री नेहरू ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान को लिखा कि भारत का पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष या झगड़े का विचार नहीं है, लेकिन भारत के शांति-प्रयत्नों को पाकिस्तानी अधिनायक खुशामद और कमजोरी समझते रहे।

चीनी आक्रमण, करमौर पर पाक-चीन अर्धवैध समझौता तथा असफल वार्ताएँ—सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने एक स्वर से भारत को दोषी ठहराया और भारत को दी जाने वाली अमेरिकी तथा ब्रिटिश सैनिक सहायता का भी तीव्र विरोध किया। नवम्बर, 1962 में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रयत्नों से दोनों देशों के बीच वार्ताक्रम चालू हुआ। नेहरू-अयूब के संयुक्त-वक्तव्य में आपसी मतभेदों को वार्ता द्वारा सुलझाने की बात कही गई। पहले दिसम्बर, 1962 में और फिर जनवरी और फरवरी, 1963 में मन्त्रि-स्तरीय सम्मेलन हुए जिनका कोई परिणाम नहीं निकला। अगले सम्मेलन से पूर्व ही पाकिस्तान ने चीन के साथ एक घुसंतापूर्ण समझौता कर पाक अधिकृत कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग अर्धधार्मिक रूप से चीन को दे दिया। भारत के विरोध का कोई फल नहीं निकला।

पाकिस्तान का जामूसी-पद्धत—सितम्बर, 1963 में पाकिस्तान के एक बड़े जामूसी जाल का पता चला। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास इस जामूसी पद्धत का केन्द्र था जिसका उद्देश्य भारत की गुप्त सामरिक बातों की जानकारी करना था। भारत ने जामूसी से सम्बद्ध पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों को भारत से हटाने का निश्चय किया, किन्तु तक उच्च आयुक्त के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार ने अपने निश्चय की घोषणा 5 दिन के लिए स्थगित कर दी। इसी बीच पाकिस्तान ने कराँची स्थित भारतीय दूतावास के प्रमुख अधिकारियों पर जामूसी करने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें पाकिस्तान छोड़ देने की आज्ञा दे दी। भारत-सरकार ने भी पाकिस्तानी अधिकारियों को भारत से निष्कासित कर दिया। पाकिस्तान ने इसे बदले की कार्यवाही कहकर भारत के विरुद्ध खूब विप-वमन किया।

इन घटनाओं के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। 24 अक्टूबर, 1963 को पाकिस्तान सरकार के आदेश से ढाका तथा राजशाही में भारतीय पुस्तकालय बन्द कर दिए गए। 21 नवम्बर को राजशाही में भारतीय हाईकमान का कार्यालय भी बन्द कर दिया गया। पाकिस्तानी समाचारपत्र घोषणा करने लगे कि पाकिस्तान कश्मीर की युद्धविराम रेखा को मान्यता नहीं देता। 4 दिसम्बर को पाक अधिकृत कश्मीर के राष्ट्रपति खुर्शीद ने अपने उत्तेजनात्मक भाषण में कहा कि युद्धविराम रेखा के निकट रहने वाले नागरिकों में 10 हजार रायफलों बाँट दी गई हैं तथा और भी बाँटी जाएँगी। वास्तव में पाकिस्तान इस प्रकार का वातावरण बनाने लगा जिससे भारत भयभीत होकर दबाव में आ जाए और पाकिस्तान की बातों को मानने।

हजरत बाल-काण्ड और पाकिस्तान की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियाँ—पाकिस्तान ने एक और घटना के सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध अपनी जन्मजात शत्रुता का खुला परिचय दिया। 28 दिसम्बर, 1963 को थिनगर की हजरत बाल मस्जिद से पेंगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र बाल चोरी चला गया। यद्यपि वह बाल मिल गया, पर पाकिस्तान ने इस घटना को लेकर बड़ा साम्प्रदयिक विद्वेष फैलाया।

कश्मीर पर भारत-पाक संघर्ष—पाकिस्तान ने अपने जन्म के लगभग 2 माह बाद ही 22 मितम्बर, 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा ने अपनी रियासत को भारत में विलय करने का समझौता किया और भारतीय सेनाएँ कश्मीर की रक्षा के लिए दौड़ पड़ी। भारत ने पाकिस्तान के साथ पूरे युद्ध की स्थिति से बचने के लिए 1 जनवरी, 1948 को सुरक्षा परिषद् में यह शिरोधार्य की कि पाकिस्तान की सहायता से क्वाइलियो ने भारत-भूमि पर आक्रमण किया है, मत. उन्हें रोका जाए। सुरक्षा परिषद् ने 20 जनवरी, 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा जाँच कमीशन नियुक्त किया जिसने 13 अगस्त, 1948 को सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच युद्ध-विराम हो और कश्मीर के भविष्य का निर्णय जनता की राय से किया जाए। 1 जनवरी, 1949 से कश्मीर में युद्ध बन्द हो गया और तत्पश्चात् भारत व पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से तथा सीधे परस्पर वार्ता होती रही।

श्री नेहरू की गुट-निरपेक्ष नीति से खिन्न संयुक्तराज्य अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया, प्रश्न: समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। पाकिस्तान ने मुख्यतः निम्नलिखित तर्कों का सहारा लिया—(1) कश्मीर का भारत में विलय भारत द्वारा प्रयोग की गई शक्ति और भय-प्रदर्शन का परिणाम था, (2) कश्मीर का भारत में विलय जनमत-संग्रह की शर्त पर आधारित था जिसे पूरा किए बिना कश्मीर स्थायी रूप से भारतीय-संघ का अंग नहीं माना जा सकता, (3) कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल प्रदेश का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए, (4) जनमत-संग्रह के प्रश्न पर पाकिस्तान का समानता का अधिकार है तथा कश्मीर पर कोई भी निर्णय करने में भारत और पाकिस्तान

को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, एवं (5) कश्मीर महाराजा ने जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत में सम्मिलित होना स्वीकार किया था जो अवैध है।

पाकिस्तान के सभी तर्क वेबुनियाद और बेतुके थे। कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण वैधानिक था क्योंकि राज्य के प्रमुख के हस्ताक्षर के उपरान्त ही उसका विलय भारत में किया गया था। कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय का प्रस्ताव भारत की शक्ति के भय से नहीं बल्कि इस डर से किया था कि पाकिस्तानी दकैन उसकी रियासत को हड़पने वाले थे और केवल भारत ही रियासत की रक्षा कर सकता था। पाकिस्तान का आक्रमण कश्मीर के साथ किए गए 'यथास्थिति समझौते' (Status-quo Agreement) के प्रति विश्वासघात था और एक छोटी-सी रियासत पर सैनिक शक्ति के बल पर अधिकार जमाने की चेष्टा थी।

भारत ने प्रारम्भ से ही यह निश्चित मत व्यक्त किया कि कश्मीर का भारत में प्रवेश पूर्णतः सैद्धान्तिक है। इस सम्बन्ध में मुख्यतः ये तर्क प्रस्तुत किए गए—(1) भारत में कश्मीर का विलय सन् 1947 के भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम में उल्लिखित प्रवेश-पत्रिका के अनुरूप पूर्णतः वैधानिक था; (2) कश्मीर की जनता ने स्वतन्त्र रूप से निर्वाचित अपनी सविधान सभा के माध्यम से कश्मीर को भारत-संघ का अभिन्न अंग घोषित कर दिया था; अतः जनमत-संग्रह की बात स्वतः ही पूर्ण हो गई; (3) आत्म-निर्णय एक लोकतान्त्रिक प्रश्न है जिसका प्रयोग राज्यों को टुकड़ों में विभाजित करने के लिए नहीं किया जाता; (4) स्वयं पाकिस्तान ने जिन राज्यों का विलय किया, उन्हें कभी आत्म-निर्णय का अधिकार नहीं दिया; (5) जो राष्ट्र अपनी जनता को भी लोकतान्त्रिक अधिकार नहीं दे पाया है, उसके द्वारा कश्मीर की जनता के लिए आत्म-निर्णय की बात कहना बेहूदा है; (6) एक आक्रमणकारी राष्ट्र विलय की बात नहीं कर सकता; (7) यह भी सर्वथा अवैधानिक है कि पाकिस्तान ने बलपूर्वक कश्मीर के जिस भाग पर कब्जा किया उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे राष्ट्र चीन को अवैध रूप से सौंप दिया; (8) भारत ने कश्मीर में जनमत-संग्रह करवाने की केवल इच्छा ही व्यक्ति की थी, वह विलय की पूर्ण शक्ति नहीं थी तथा जनमत-संग्रह का आश्वासन कश्मीर के शासक को दिया गया था, एक तृतीय पक्ष पाकिस्तान को नहीं; (9) जनमत-संग्रह की बात पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेनाएँ हटाने के बाद पूरी करने की कही गई थी, लेकिन पाक-फौजों की उपस्थिति स्वयं जनमत-संग्रह के मार्ग में बाधा बनी रही है, और अब कश्मीर में सशस्त्र चुनाव हो जाने के बाद जनमत-संग्रह का प्रश्न ही सम्मान्य हो जाता है; (10) कश्मीर में मुस्लिम बहुमत के आधार पर जनमत संग्रह की बातें गलत हैं, भारत-जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धान्त को मान्यता नहीं देता; एवं (11) पाकिस्तानी दुराग्रह स्वीकार करने का अर्थ सम्पूर्ण देश और कश्मीर की शान्ति भंग करना तथा भारत में कश्मीर-विलय के कश्मीरी जनता के निर्णय का अपमान करना है। भारत ने स्पष्ट रूप से यह स्थिति स्पष्ट कर दी कि जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है।

पाकिस्तान के शासकों ने न तो श्री नेहरू के प्रधानमन्त्रित्व काल में अपनी भारत-विरोधी नीति छोड़ी और न बाद में ही। 27 मई, 1964 को श्री नेहरू की मृत्यु हो गई। श्री नेहरू ने भारत की विदेश-नीति की आधारशिला मजबूती से जमा दी थी और यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत का हित गुट-निरपेक्ष नीति का अनुसरण करने में ही है। भारत जैसे नवोदित लोकतान्त्रिक राष्ट्र के लिए असंतुलनता की नीति पर चलते हुए विश्व के साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों शक्तिशाली गुटों की मंजी अर्जित करने का प्रयत्न श्लाघनीय था। यदि श्री नेहरू तत्कालीन परिस्थितियों में सैनिक गुटबन्दी का आश्रय लेने की नीति पर भारत को ले जाते तो भारत उसी प्रकार एक पर-निर्भर राष्ट्र बन जाता जिस प्रकार पाकिस्तान आज भी बना हुआ है। नेहरू की कमजोरी यह रही कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रति आवश्यकता से अधिक तुष्टिकरण की नीति अपनायी।

शास्त्री युग (मई, 1964-जनवरी, 1966)

श्री नेहरू की मृत्यु (27 मई, 1964) के पश्चात् श्री लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमन्त्री बने और जनवरी, 1966 में अपनी मृत्युपर्यन्त उन्होंने भारत की विदेश-नीति का बड़ी कुशलता से संचालन किया। श्री नेहरू के आदर्शवाद को निभाते हुए श्री शास्त्री ने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से यथार्थवादी नीति अपनाकर अपनी कूटनीतिज्ञता का सुन्दर परिचय दिया।

पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने का प्रस्ताव—श्री शास्त्री ने भी 15 अगस्त, 1964 को स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के साथ 'युद्ध न करने का समझौता' करने के लिए एक बार फिर प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान के शासकों के कानों में जूँ तक नहीं रेंगी। कच्छ पर और बाद में कश्मीर तथा भारत पर होने वाले पाकिस्तानी आक्रमणों ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तानी नेता भारत के प्रति शत्रुता और युद्ध की नीति से तब तक डिगने वाले नहीं हैं जब तक उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा।

कच्छ के भारतीय प्रदेश पर पाकिस्तान का आक्रमण—सन् 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर दो प्रबल सैनिक आक्रमण किए। इनमें पहला आक्रमण मार्च-अप्रैल, 1965 में कच्छ पर हुआ, दूसरा अगस्त-सितम्बर, 1965 में कश्मीर पर। कच्छ की खाड़ी (The Rann of Kutch) का क्षेत्रफल 9 हजार वर्गमील है। यह एक दलदलीय क्षेत्र है। जब पाकिस्तान ने इस प्रदेश के उत्तरी हिस्से में पहले एक सड़क बना ली और बाद में भारतीय सीमा में कजरकोट, डीग एवं विगीकाट नामक स्थानों पर अपनी स्थायी चौकियाँ स्थापित करली तो उसने भारत के विरोध-पत्रों की न केवल उपेक्षा कर दी बल्कि गुजरात के एक बड़े क्षेत्र पर भी अपने अधिकार का दावा किया। पाकिस्तान का यह दावा ऐतिहासिक और वैधानिक रूप से प्रवीण था क्योंकि इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तराष्ट्रीय सीमा पहले से निर्धारित हो चुकी थी, किन्तु पाकिस्तान ने इस खाड़ी को समुद्र मान कर उसके मध्य भाग को अन्तराष्ट्रीय सीमा माने जाने का दावा किया।

दोनों देशों के बीच वार्ता चालू थी कि 9 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी ने सरदार नामक भारतीय चौकी पर हमला बोल दिया। 24 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान की पूरी एक ब्रिगेड (3500 सैनिक) ने अमेरिकी टैंकों के साथ कच्छ पर भीषण आक्रमण कर दिया जिसका मुकाबला केवल 225 भारतीय सैनिकों द्वारा ऐतिहासिक वीरता के साथ किया गया। दाद में भारत की ओर से तुरन्त ही प्रभावकारी सैनिक कुमुक भेजी गई। कच्छ सीमा पर भारी-भरकब सघर्ष को रोकने के लिए ब्रिटेन ने युद्ध विराम (Cease Fire) का प्रस्ताव रखा जिसे भारत ने मान लिया लेकिन पाकिस्तान ने प्रस्वीकार कर दिया।

अन्त में, सन्धन में होने वाले राष्ट्रमण्डलीय प्रधानमन्त्रियों के सम्मेलन के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विम्पन के प्रयत्नों से भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के प्रश्न पर 30 जून, 1965 को एक समझौता हो गया जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख था—

1 1 जुलाई, 1965 से युद्ध बन्द कर दिया जाए।

2 दोनों देशों की सेनाएँ 7 दिन के भीतर पीछे हटा ली जाएँ और अपनी 1 जनवरी, 1965 वाली स्थिति पर लौट जाएँ।

3 सीमा-विवाद के प्रश्न का समाधान पहले मन्त्रियों की वार्ता द्वारा किया जाए और इन प्रकार की वार्ता मण्डल न होने पर यह प्रश्न एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण (Tribunal) को सौंपा जाए। न्यायाधिकरण के तीन सदस्य हों जिसमें एक-एक सदस्य भारत तथा पाकिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाए और अध्यक्ष के नाम पर यदि दोनों देशों में सहमति न हो सके तो संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव उसका नाम प्रस्तावित करें।

समझौता होने के बाद कच्छ सीमा पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अपनी-अपनी सेनाएँ 1 जनवरी, 1965 वाली स्थिति पर हटा लीं। पाकिस्तान द्वारा उठाए गए सीमा निर्धारण के प्रश्न पर विचार हेतु एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति कर दी गई जिसमें भारत द्वारा यूगोस्लाविया के न्यायाधीश को प्रस्तावित किया गया और पाकिस्तान द्वारा ईरान के न्यायाधीश को। दोनों ही देशों के मतभेद के कारण अध्यक्ष की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव द्वारा की गई। न्यायाधिकरण द्वारा दोनों देशों को आदेश दिए गए कि वे कच्छ के सम्बन्ध में अपने-अपने दावे प्रस्तुत करें।

सितम्बर 1967 में न्यायाधिकरण ने अपना काम शुरू किया और 19 फरवरी, 1968 को अपने अपना निर्णय दे दिया। इस निर्णय के अनुसार विवाद-ग्रस्त क्षेत्र का 90 प्रतिशत भाग भारत को दिया गया और शेष 320 वर्ग मील का प्रदेश पाकिस्तान को प्राप्त हुआ। इस प्रदेश में कजरकोट का वह विनष्ट किन्ना भी सम्मिलित था जहाँ से सन् 1965 का युद्ध आरम्भ हुआ था। इसके अनिर्दिष्ट छारेबेट की ऊँची भूमि और नगरपरकार के क्षेत्र भी पाकिस्तान को दिए गए भाग में शामिल थे। स्पष्ट है कि पाकिस्तान को महत्त्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र प्राप्त

हो गया। यद्यपि न्यायाधिकरण का निर्णय कुल मिला कर भारत के पक्ष में था, तथापि पाकिस्तान के साथ विशेष रियायत की गई थी। रहीम के बाजार में दक्षिणी क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने का कोई कारण नहीं था। न्यायाधिकरण का फैसला न्याय पर उतना आधारित नहीं था जितना राजनीति पर। भारत सरकार ने इस निर्णय को 'राजनीतिक कारणों से प्रेरित' बताकर इसकी निन्दा की। भारत के अनेक राजनीतिक दलों ने इस निर्णय को ठुकरा देने का अनुरोध किया, पर चूंकि भारत-सरकार पहले ही यह शर्त मान चुकी थी कि न्यायाधिकरण जो भी निर्णय देगा, वह उसे मान्य होगा, अतः भारत के सामने बचन निभाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भारत सरकार ने कूटनीतिक चालबाजी की जगह नैतिकता को उच्च समझा।

कश्मीर-विवाद और भारत-पाक युद्ध, 1965—30 जून, 1965 को होने वाले कुछ समझौते की स्थाही सूखने भी न पायी थी कि अगस्त में पाकिस्तान ने कश्मीर में हजारों सादा यस्त्रधारी सशस्त्र घुसपैठिये भेज दिए जिनका उद्देश्य राज्य में व्यापक तोड़-फोड़ करना, अराजकता फैलाना और यातायात केन्द्रों, सैनिक-ठिकानों तथा उद्योग स्थलों को नष्ट करना था। इस पर भारतीय सेना ने तेजी से घुसपैठियों का सफाया कर युद्धविराम रेखा के उन महत्वपूर्ण पहाड़ी और जंगली प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया जहाँ से घुसपैठिये भारत में प्रवेश करते थे।

कश्मीर को हथियाने के अपने इस प्रयास में असफल होकर पाकिस्तान एक हारे जुझारी की तरह बौखला गया। 1 सितम्बर, 1965 को पाकिस्तान ने विपुल टैंक शक्ति के साथ कश्मीर के छद्म क्षेत्र पर अचानक ही भीषण आक्रमण कर दिया, यह क्षेत्र पाकिस्तान की प्रधान सैनिक छावनियों के निकट और आक्रमण की दृष्टि से पाकिस्तान के अनुकूल था। यदि अखनूर पर पाक फौजें अधिकार कर लेती तो पाकिस्तान जम्मू को जीतकर जम्मू-कश्मीर की भारतीय सेना को शेष भारत से विलग कर सकता था। किन्तु पाकिस्तान के मनसूबे खाक में मिल गए। भारत के भीषण प्रत्याक्रमण ने पाकिस्तान को छोटी का दूध याद करा दिया। भारत ने पाक के विरुद्ध सम्पूर्ण-सीमा पर नए मोर्चे खोल दिए। 15 सितम्बर तक पाकिस्तान की वायु शक्ति की कमर टूट गई। पाकिस्तान को प्राप्त अमेरिकी गैटन टैंकों का कब्रिस्तान बन गया और पाकिस्तान की पराजय सन्निकट दिखायी देने लगी।

'अपने छोटे भाई' और 'अजीज दोस्त' को पिटते हुए देखकर 'बड़े भाका' चीन ने 16 सितम्बर को भारत की तीन दिन का गल्टीमेटम भेजते हुए यह बेहूदा आरोप लगाया कि भारत ने सिक्किम-तिब्बत पर चीनी प्रदेश में अपने सैनिक अड्डे तायम कर लिए हैं और 59 याक तथा 800 भेड़ें चुरा ली हैं, अतः उसे तीन दिन में अड्डों को नष्ट कर पशुओं को वापस कर देना चाहिए अन्यथा उसे गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत ने इन सैनिक अड्डों के निरीक्षण के लिए कई प्रस्ताव रखे, लेकिन चीन ने उन्हें ठुकरा दिया। ठुकराता भी क्यों नहीं? या फिर कोई अड्डे होते अभी तो उनका निरीक्षण किया जाता। चीन के गल्टीमेटम का उद्देश्य

तो पाकिस्तान को अपने समर्थन की आशा दिलाकर भारत के साथ युद्धरत रहने की प्रेरणा देता था। चीनी अल्टीमेटम का वास्तविक उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन 19 सितम्बर को इसकी अवधि की समाप्ति पर चीन ने अल्टीमेटम की अवधि 3 दिन और बढ़ा दी। इस बढ़ी हुई अवधि की समाप्ति पर एक तरफ तो सुरक्षा परिषद् ने मुद्द-विराम का निर्णय हुआ और दूसरी तरफ चीन ने यह विविध घोषणा कर दी कि भारत ने चीनी सीमा में बने हुए सैनिक बड़े स्वरूप में तोड़ दिए हैं, अतः अल्टीमेटम के अनुसार अगली कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। चीन अल्टीमेटम पाकिस्तान को खुश करने का दिखावा मात्र था, अन्यथा चीन यह भनी भाँति समझ चुका था कि भारत अब सन् 1962 का भारत नहीं था। चीन कार्यवाही से यह पुनः सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान और चीन में 'चोर-चोर मोसें भाई' का सम्बन्ध है।

भारत-पाक युद्ध 23 सितम्बर, 1965 तक चला और अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से 23 सितम्बर को 3½ बजे प्रातःकाल मुद्द-विराम हो गया। युद्ध-अन्तान्ति पर लगभग 740 वर्गमील पाकिस्तानी क्षेत्र भारत के अधिकार में था जबकि आकस्मिक आक्रमण का लाभ उठा लेने के कारण 240 वर्गमील का भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया था। भारत ने निरन्तर विजयी होते हुए भी मुद्द-विराम स्वीकार कर यह सिद्ध कर दिया कि वह एक शान्तिप्रिय राष्ट्र है। युद्ध से यह पुनः स्पष्ट हो गया कि साम्यवाद के विरोध के नाम पर पाकिस्तान का दी गई विशाल अमेरिकी सैनिक सहायता का किस प्रकार एक शान्तिप्रिय लोकतांत्रिक राष्ट्र के विरुद्ध दुरुपयोग किया जा सकता है। घटनाओं ने भारत का यह आरोप भी सत्य प्रमाणित कर दिया कि इस उप-महाद्वीप में शक्ति-संतुलन को बिगाड़ने का मुख्य उत्तरदायित्व अमेरिका और उसके मित्रराष्ट्रों का है।

भारत-पाक युद्ध के गम्भीर परिणाम और प्रभाव सामने आए। प्रथम, यह स्पष्ट हो गया कि भारत की धर्म-निरपेक्षता का आधार बड़ा ठोस है और कश्मीर के मुस्लिम नागरिक भारत के प्रति पूर्ण देशभक्त हैं। दूसरे, भारतीय एकता पुनः सुदृढ़ और सम्पुष्ट हुई तथा उसमें एक नया रूप और नया नित्यत्व आया। तीसरे, भारत में अपूर्व स्वाभिमान जाया तथा आत्मनिर्भर बनने की बलवती भावना जाग्रत हुई। चौथे, भारत की सन् 1962 में खोई हुई प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत कुछ पुनर्जीवित हो गई। पाँचवें, भारत को अपने मित्र और शत्रु देशों का अच्युत तरह पता चल गया। अमेरिकी और ब्रिटिश रवैया तो पहले ही स्पष्ट था, इंडोनेशिया, टर्की, ईरान आदि राष्ट्रों का भी भारत-विरोधी रवैया प्रकट हो गया। मलाया के अतिरिक्त अन्य किसी भी राष्ट्र ने पाक-आक्रमण की स्पष्ट रूप से निन्दा नहीं की। छठे, संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपयोगिता पुनः सिद्ध हो गई। यद्यपि विश्व-संस्था का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा, तथापि यह पुनः प्रकट हो गया कि यदि महाशक्तियाँ सहयोग से काम करें तो संयुक्त राष्ट्रसंघ को पूरी सफलता प्राप्त हो सकती है। सातवें, इस संघर्ष ने सोवियत कूटनीति को एक नया मोड़ लेने का अवसर प्रदान किया। दो

राष्ट्रों के विवाद को सुलझाने में मध्यस्थ के रूप में रूस पहली बार आगे आया। सोवियत कूटनीति के जादू ने ताशकन्द समझौता करा ही दिया।

युद्ध-विराम उल्लंघन और ताशकन्द समझौता 1966—युद्ध-विराम के बाद भी पाकिस्तान भड़काने वाली कार्यवाहियों से बाज नहीं आया और आए दिन सीमा-उल्लंघन की घटनाएँ जारी रही। यह आशका बनी रही कि कहीं दोनों ही पक्षों में युद्ध फिर न भड़क उठे। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए यद्यपि अमेरिका सहित पश्चिमी राष्ट्र और महासन्निव ऊपाट सक्रिय थे, तथापि सोवियत कूटनीति विशेष रूप से सफल हुई। सोवियत प्रधान मन्त्री कोसीगिन ने दोनों देशों के शीर्षस्थ नेताओं की प्रत्यक्ष वार्ता द्वारा ताशकन्द समझौते की व्यवस्था की। ताशकन्द वार्ता 4 जनवरी से 10 जनवरी, 1966 तक चालू रही। पाकिस्तानी दुराग्रह के कारण ताशकन्द सम्मेलन की सफलता पूर्ण सदिग्ध थी, किन्तु रूसी प्रधान मन्त्री की अन्तिम दिन की अग्र्यक दोड़-धूप के कारण 10 जनवरी को 9 बजे रात्रि को श्री अग्र्यव खाँ और श्री शास्त्री ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जो 'ताशकन्द घोषणा' (Tashkent Declaration) के नाम से विख्यात हुआ। इस समझौते के मुख्य तत्त्व ये थे—

(1) दोनों देश परस्पर प्रच्छेद पड़ोसियों के सम्बन्ध कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के अनुसार पूरा प्रयास करेंगे और शक्ति प्रयोग न कर आपसी विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाएँगे।

(2) दोनों देशों के सब सशस्त्र सैनिक 25 फरवरी, 1966 तक उन स्थानों पर लौट जाएँगे जहाँ वे 5 अगस्त, 1965 के पहले थे। दोनों ही पक्ष युद्ध-विराम रेखा पर युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे।

(3) दोनों देश एक दूसरे के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार बन्द कर देंगे और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देंगे जिससे मैत्री में वृद्धि हो।

(4) दोनों देशों के उच्चायुक्त अपनी-अपनी जगह लौट जाएँगे तथा सामान्य राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित किए जाएँगे। राजनयिक व्यवहार में सन् 1961 के दियना समझौते का सम्मान किया जाएगा।

(5) दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार, संचार और सांस्कृतिक सम्पर्क पुनः कायम करने पर विचार किया जाएगा और दोनों ही देश वर्तमान समझौतों को कार्यान्वित करेंगे।

(6) दोनों शीर्षस्थ नेता अपने अधिकारियों को युद्धबन्धियों की वापसी का आदेश देंगे।

(7) दोनों पक्ष शरणार्थियों, निष्कासितों और गैर-कानूनी रूप से बसने वालों की समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्नों पर वार्ता जारी रखेंगे और ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि लोगों का देश से पलायन बन्द हो। सचर्पकाल में दोनों पक्षों ने जिस साल और सन्धति पर अधिकार किया है उसके लौटाने के बारे में बातचीत की जाएगी।

(8) जिन मामलो का दोनों देशों से सीधा सम्बन्ध है, उन पर विचार के लिए दोनों पक्षों की सर्वोच्च तथा अन्य स्तरों पर बैठकें होती रहेंगी। दोनों ही पक्षों ने 'भारत-पाकिस्तान समुक्त समितियाँ' नियुक्त करने पर भी सहमति प्रकट की जो अपनी-अपनी सरकारों को बताएँगी कि घाने और क्या कदम उठाए जाएँ।

ताशकन्द समझौते की विभिन्न क्षेत्रों में कटु-आलोचना की गई। पाकिस्तान में आलोचना का प्रमुख आधार यह था कि समझौते से पाकिस्तान को अपने मुख्य लक्ष्य कश्मीर प्राप्त करने में कोई सफलता नहीं मिली। राष्ट्रपति अयूब खान ने प्रत्युत्तर में यह तर्क दिया कि समझौते से कश्मीर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है क्योंकि शान्ति-स्थापना के बाद अब यह प्रश्न सुरक्षा परिषद् में उठाया जा सकेगा। भारत में आलोचना के मुख्य कारण ये थे—(1) कश्मीर के महत्वपूर्ण दरों से फौजें हटा लेना भारतीय सेना के साथ विश्वासघात और भावी प्राक्रमण के खतरे को मोल लेना है, (2) पाक-चीन गुटबन्दी के प्रकाश में शत्रु को रियायत देना गलत है, (3) समझौता रूढ़ी दबाव में आकर किया गया है, एवं (4) समझौते से शान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। सरकारी पक्ष ने समझौते को उचित ठहराते हुए कहा कि इसने पाक-चीन गुटबन्दी के फलस्वरूप भावी युद्ध का संकट दूर किया है तथा दोनों देशों का समुक्त मोर्चा बनने का खतरा कम हो गया है। यह भी कहा गया कि भारतीय विदेश-नीति के सम्बन्ध में यह उचित था कि भारत शान्ति की भावना से काम करता। कश्मीर के महत्वपूर्ण दरों से सेनाएँ हटाना इसलिए उचित समझा गया क्योंकि पाकिस्तान ने महाशक्ति रूस की सहायता में शक्ति का प्रयोग न करने का आश्वासन दिया था। समझौते का एक कारण सुरक्षा-परिषद् का प्रस्ताव और रूस का प्रबल अनुरोध भी था। सुरक्षा-परिषद् के 20 सितम्बर के प्रस्ताव के अनुसार दोनों देश यह स्वीकार कर चुके थे कि वे अपनी सेनाएँ 5 अगस्त से पूर्व की स्थिति में लौटा लेंगे।

ताशकन्द समझौता भारत की उदारता और सहिष्णुता का प्रतीक था, लेकिन भावी इतिहास ने सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान भारत के प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्यवाहियों से बाज आने वाला नहीं था। यद्यपि उस समय तो दोनों देशों के सैनिक 5 अगस्त, 1965 से पूर्व की स्थिति में लौट गए और दोनों देशों का प्रचार-युद्ध भी बन्द हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद भारतीय सीमान्त पर पाकिस्तानी सैनिकों की हलचल पुनः शुरू हो गई। श्री शास्त्री ने पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर नीति अपनाकर भी अन्त में तुष्टिकरण की नीति का इस्तेमाल किया कि भारत की विदेश-नीति गुट-निरपेक्षता, शान्तिवाद और समरथाओं की आपसी बातों द्वारा सुलभाने की है। श्री शास्त्री का प्रधानमन्त्रित्व बहुत ही अल्पकालीन रहा, अतः उन्हें विदेश-नीति को पूर्ण यथायंवादी घरायल पर ला सड़ा करने का ममुचित समय नहीं मिल सका और वे श्री नेहरू के प्रादेशवाद से अभिभूत रहे। जो भी हो, यह श्रेय श्री शास्त्री को जाता है कि उन्होंने भारतीय विदेश-नीति को दृढ़ता और यथायंवादिता की ओर मोड़ने में पहल की तथा पाकिस्तान को बता दिया कि भारत

सन् 1962 का भारत नहीं है। श्री शास्त्री ने देश को पूर्ण प्रतिष्ठा दिलाने में बहुत-कुछ सफलता प्राप्त की।

इन्दिरा युग (जनवरी, 1966-मार्च, 1977)

श्री शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद स्वर्गीय श्री नेहरू की पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनीं। श्रीमती गांधी ने प्रपना स्थान सुदृढ़ करने के बाद यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत यद्यपि किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी गुट-निरपेक्ष और शान्तिवादी नीतियों का परित्याग नहीं करेगा, तथापि वह राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि महत्त्व देते हुए मयार्थ की अपेक्षा भी नहीं करेगा। श्रीमती गांधी ने भारतीय विदेश-नीति की आग्नियों को दूर कर उसे एक नई दिशा प्रदान की और आज सभी क्षेत्रों में यह स्वीकार किया जाता है कि श्री नेहरू द्वारा विरासन में दी गई भारतीय विदेश-नीति को जितनी अच्छी तरह श्रीमती गांधी ने समझा है और जिस रूप में उसके विविध पक्षों को उजागर किया है, वह स्तुत्य है। इन्दिरा-युग में भारत-पाक सम्बन्धों का जो ताना-बाना रहा वह निम्नानुसार है—

पाकिस्तान का भारत-विरोधी दृष्टिकोण पूर्ववत्—अल्पकालीन शान्ति के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ पुनः छेड़छाड़ प्रारम्भ कर दी। जुलाई-अगस्त, 1966 में पाक-सैनिकों ने सीमान्त पर अपनी हलचल पुन आरम्भ कर दी। तनाव कम करने के भारतीय प्रयासों के फलस्वरूप सितम्बर, 1966 में दोनों देशों के सैनिक अधिकारियों द्वारा यह निश्चय किया गया कि यदि सीमान्तों पर कोई सैनिक गतिविधि हो तो इसकी पूर्व सूचना वे एक दूसरे को दे दें पर पाकिस्तान के मन में तो कुटिलता भरी थी, अतः वह न केवल सीमान्त पर छुटपुट छेड़छाड़ करता रहा बल्कि भारत की वायु सीमा का भी अतिक्रमण करता रहा। विवश होकर भारत ने पुनः कठोर रुख अपनाया। सन् 1967 के प्रारम्भ में भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी विमान मार गिराया गया। इससे दोनों देशों में तनाव फिर बढ़ गया। मई, 1967 में अजमेर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच एक मुठभेड़ भी हुई। पहले पाकिस्तान ने की, घत आकस्मिक आक्रमण के कारण 7 भारतीय सैनिक मारे गए।

कश्मीर पर पाकिस्तानी रवैया पूर्ववत् रहा। अप्रैल, 1966 में पाकिस्तान कश्मीर समस्या को पुनः सुरक्षा-परिपद में ले गया। कश्मीर में हुए दंगों को पाकिस्तान ने 'कश्मीरियों के विद्रोह' की संज्ञा देते हुए सयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप की माँग की। भारत ने शक-आरोपों को बेहूदा बताया। सुरक्षा-परिपद कुछ न कर सकी। अन्त में, यही प्रस्ताव पारित होकर रह गया कि दोनों पक्ष अल्पकालीन शांति के लिए प्रयास करें।

पाहिया खाँ द्वारा सत्ता ग्रहण और पाक शत्रुता में वृद्धि—ताशकन्द समझौते के बाद से ही पाकिस्तान के प्रति हमी रवैये में कुछ परिवर्तन आया और जुलाई, 1968 में रूस ने उसे सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की चिन्ता और प्रतिक्रिया का रूस ने कोई स्थान नहीं दिया। इसी समय

पाकिस्तान की घातकीय राजनीति में उद्यम-युधन शुरू हुई और अप्रैल, 1969 में अयूबखान से सत्ता निकल कर जनरल याहिया खान के हाथों में आ गई। यह आशा की गई कि नया प्रशासन भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण रख अपनाएगा, लेकिन कुछ समय शान्त रहने के बाद जनरल याहिया खान ने भारत के प्रति घोर शत्रुतापूर्ण नीति अपनानी शुरू की जिसकी परिणति दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध और पाकिस्तान के विभाजन में हुई।

रवात सम्मेलन और पाक रवेया—22 सितम्बर, 1969 में मोरक्को की राजधानी रवात में इस्लामी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पाकिस्तान के विरोध के कारण सम्मेलन के आयोजकों ने भारत को निमन्त्रण नहीं भेजा। इस पर भारत की ओर से कूटनीतिक प्रयत्न किए गए और अन्ततोगत्वा 23 सितम्बर को उसे सम्मेलन में भाग लेने का निमन्त्रण प्राप्त हो गया। केन्द्रीय मंत्री कलशूदीन घनो अहमद के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल रवात पहुँचा। सम्मेलन में भारत को आमन्त्रित करने के विरोध में 24 सितम्बर को याहिया खान द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया गया और तब भारत को न केवल सम्मेलन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया बल्कि उसके साथ सामान्य शिष्टाचार भी नहीं बरतना गया। यह सब पाकिस्तानी कूटनीति का परिणाम था। पाकिस्तान ने सम्मेलन में भारत के भाग लेने पर सम्मेलन के बहिष्कार करने और लौट जाने की वमझी दी और मोरक्को, जॉर्डन आदि उनके अरब मित्रों ने उसका पूरा साथ दिया। केवल समुक्त अरब-गाज़राज्य का ही समर्थन भारत के पक्ष में रहा। वास्तव में रवात में जो कुछ हुआ वह भारत का राष्ट्रीय अपमान था। भारत ने अपने विरोध प्रदर्शन के लिए कठोर कूटनीतिक कार्यवाही कर 14 अक्टूबर को मोरक्को और जॉर्डन में अपने राजदूत वापस बुला लिए।

विमान अपहरण-काण्ड—पाकिस्तान निरन्तर भारत-विरोधी कार्यवाहियाँ करता रहा। 30 जनवरी, 1971 को इण्डियन एयर लाइंस के एक यात्री-विमान का अपहरण कर जबरन लाहौर हवाई अड्डे पर उतारा गया। पाकिस्तान ने अपहरणकर्त्ताओं को राजनीतिक शरण दी, विमान के यात्रियों को लौटा दिया लेकिन अपहरणकर्त्ताओं द्वारा आग लगाकर विमान जलवा दिया। भारत में तीव्र रोष की लहर दौड़ गई और सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के भारतीय प्रदेश में होकर उड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। यह स्पष्ट कह दिया गया कि पाक विमानों का भारतीय वायु प्रदेश के ऊपर से उड़ानों पर तब तक प्रतिबन्ध लगा रहेगा जब तक पाकिस्तान ध्वस्त किए गए विमान का मुआवजा नहीं देता और अपहरणकर्त्ताओं को गिर नहीं देता।

विमान अपहरण-काण्ड और भारत द्वारा बढ़ते की कार्यवाही से सीमांत पर प्रतिरोध का वातावरण और अधिक गम्भीर हो गया तथा पाकिस्तान में नागरिक सुरक्षा के अभाव हुए और लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण लेने का आग्रह किया गया वैसे भी जनरल याहिया खान 22 दिसम्बर, 1970 को ही पाकिस्तान के 18 से 2

वर्ष के युवकों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की घोषणा कर चुके थे। पाकिस्तानी शासक यह समझे बैठे थे कि उनका एकमात्र संबल घर्मान्धता और भारत-विरोध है।

बंगलादेश में मुक्ति फ्रान्दोलन का विस्फोट और भारत-पाक सम्बन्धों में तेजी से बिगाड़—पाक जनता की जनतान्त्रिक आकांक्षाओं के उठते हुए तूफान को शान्त करने के लिए जनरल याहिया ख़ाँ ने सत्ता ग्रहण करते समय यह घोषणा की थी कि वे शीघ्र ही नए चुनाव सम्भ्र करवा कर जन-प्रतिनिधियों को शासन सौंप देंगे। विवशता की घेड़ियों से जकड़े हुए याहिया ख़ाँ ने दिसम्बर, 1970 में चुनाव कराए जिनमें शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में गठित पूर्वी बंगाल की आवाामी लीग को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में गठित पीपुल्स पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई। आवाामी लीग की विजय उसके छः सूत्री कार्यक्रम के आधार पर हुई थी जिसका प्रमुख आधार पूर्वी बंगाल के लिए पूर्ण स्वायत्तता की मांग थी, अतः आवाामी लीग द्वारा पूर्वी बंगाल के लिए पूर्ण स्वायत्तता की मांग की गई जिसे जनरल याहिया ख़ाँ और भुट्टो द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और 25 मार्च को समझौता वार्ता भंग कर शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जनता के झान्तिपूर्ण असहयोग आन्दोलन को कुचलने के लिए नृगस सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। वास्तव होकर आवाामी लीग ने पूर्वी बंगाल की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी और पाकिस्तानी सैनिक आक्रमण से तबजान 'बंगलादेश' की रक्षा के लिए जनता ने संशय प्रतिरोध शुरू कर दिया।

पाकिस्तानी शासकों ने जनता के मुक्ति-आन्दोलन को भारत के पड़पन्न का परिणाम बतलाया और एक तरफ तो इसे भारत-पाक समस्या के रूप में विश्व जनमत के सम्मुख रखने का प्रयास किया और दूसरी तरफ बंगालवातियों पर घोर अत्याचार एवं असूतपूर्व हत्याकाण्ड का क्रम चालू रखा, जिससे शरणार्थियों के जत्थे के जत्थे भारत घाने लगे। लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत आए। इस प्रकार पाकिस्तान ने एक तरह से भारत के विरुद्ध भीषण आर्थिक युद्ध छेड़ दिया। भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ने लगा और बंगलादेश की समस्या लम्बे लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन गई। भारत ने समस्या की भीषणता को सही रूप में विश्व-जनमत के सम्मुख रखा तथा पाकिस्तान की बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियों से दुनिया को परिचित कराया। भारत ने विश्व के देशों से अपील की कि जब तक बंगलादेश की समस्या का सकल समाधान न हो जाए तब तक वे पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की सैनिक और आर्थिक सहायता न दें। भारत की ओर से अनेक प्रतिनिधियों ने एवं स्वयं श्रीमती गांधी ने विदेश-यात्रा की तथा बंगलादेश की समस्या के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सोवियत संघ और विश्व के अनेक राष्ट्रों ने भारतीय दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति प्रकट की तथा पाकिस्तान को सहायता बन्द कर दी, किन्तु अमेरिका और चीन ने बंगलादेश के प्रश्न को पाकिस्तान का घरेलू मामला बताकर उसे सैनिक और आर्थिक सहायता देने का क्रम बराबर जारी रखा।

जब परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई और शरणार्थियों का प्रवाह प्रवाह भारत में आना रहा तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रति तछोर रवैया अपनाते हुए बंगलादेश के जन आन्दोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने का निश्चय कर लिया। पाकिस्तान में भारत से युद्ध छेड़ने का उन्माद प्रबल होता गया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही सीमान्तों पर पाक-सेनाएँ आगे दिन छुट्टुट हमने करने लगी। फिर भी भारत ने पूर्ण समय से काम लेते हुए पर्याप्त प्रयत्न किया कि युद्ध के बादल छँट जायें, लेकिन जो होनी थी वह होकर रही। जनरल याहिया खान ने भारत पर आक्रमण करके न केवल अपनी राजनीतिक हत्या कर ली बल्कि पूर्वी बंगाल के पृथक्करण को सुनिश्चित बना दिया और बंगलादेश-भारत राज्य का उदय होकर रहा।

भारत-पाक युद्ध, दिसम्बर, 1971—चीन और पाकिस्तान से भेंट में प्राप्त विपुल सैनिक सहायता के बल पर युद्ध के नशे में घूर पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर, 1971 की रातकाल भारत के विभिन्न हवाई-प्रहरी पर आक्रान्त हो भीषण हवाई आक्रमण कर दिया। भारत की स्थल और जल सेना पूर्ण सक्रिय हो गई। भारत ने पाकिस्तान को एक न भूलने वाला सबक सिखाने का निष्पत्त्य करके विद्युत गति से प्रत्याक्रमण किया और पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही मोर्चों पर जल, पल और नम में पाकिस्तान के संग्रह तन्त्र को भीषण क्षति पहुँचाई। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर लड़ा गया और पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तथा मुक्ति-बाहिनी की संयुक्त कमान ने भारतीय ले जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में कहर डाल दिया।

युद्धकाल में 5 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद की प्रापादकालीन बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि वह 'पूर्वी पाकिस्तान' में आतंकवाधियों को सहायता देकर पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखण्डता पर प्रहार कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधि समरसेन ने पाक आरोपों का तीव्र विरोध किया और मोक्षियत स्व के बार-बार वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में भारत विरोधी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसी बीच 6 दिसम्बर को श्रीमती गांधी ने भारतीय सतद में 'बंगलादेश गणराज्य' के उदय की सूचना दी। 'बंगलादेश' को मान्यता देकर श्रीमती गांधी ने समस्या को बिलकुल एक नया मोड़ दे दिया और संयुक्त राष्ट्रमण तथा सम्पूर्ण विश्व को बता दिया कि भारत किसी आतंककारी आन्दोलन की नहीं बरन् एक स्वतन्त्र राज्य की बंध सरकार को सहायता दे रहा है जिसके साथ 'नाटो' जैसा कोई सैनिक सम्झौता न होने पर भी भारत की पूर्ण सहानुभूति है।

भारत-पाक-युद्ध केवल 14 दिन चला और 16 दिसम्बर, 1971 को बंगल देश की राजधानी ढाका में पाक सेना के ले. जनरल ए. ए. के नियाजी ने आत्म-समर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। पूर्वी मोर्चे पर लगभग 1 लाख पाक फौजों ने आत्म-समर्पण किया और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की लगभग 14 मी वर्गमील भूमि पर बर्बाद कर लिया गया। पाक फौजों के आत्म-समर्पण के तुरन्त बाद ही श्रीमती गांधी ने 17 दिसम्बर को रात्रि के 8 बजे 'एकपक्षीय युद्ध-विराम' की घोषणा

करते हुए पाक-राष्ट्रपति जनरल याहिया ख़ाँ से युद्धबन्दी-प्रस्ताव को स्वीकार करने को प्रयत्न की। पाकिस्तान के लिए तो यह एक वरदान था जिसे याहिया ख़ाँ ने स्वीकार कर लिया। भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपना शक्तिशाली सातवाँ जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था जिसका उद्देश्य किसी न किसी रूप में पाकिस्तान की सहायता करना था, किन्तु भारतीय हितों के रक्षार्थ हिन्दमहासागर में इसी युद्ध पोतों की उपस्थिति ने अमेरिका को कोई ऐसा कदम न उठाने के लिए विवश कर दिया जिससे दोनों महाशक्तियों के टकराने का भय पैदा हो जाए। भारत के एकपक्षीय युद्ध विराम ने भी अमेरिकी मनसूबों पर पानी फेर दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति निक्सन को विदेश-नीति के क्षेत्र में महुरी कूटनीतिक पराजय दी। इतिहास का यह मजाक ही कहा जाएगा कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए वह हथौड़ा आगे आया जिसे अमेरिका और उसके पिछलग्गू राष्ट्र लोकतन्त्र का शत्रु कहते आ रहे थे। प्रगते प्रापको महान् लोकतान्त्रिक देश कहने वाले अमेरिका ने याहिया ख़ाँ की अमानुषिक तानाशाही को समर्थन दिया और जनता के एक महान् लोकतान्त्रिक आन्दोलन के दमन में परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया।

युद्ध के परिणाम—दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले—

1. भारत की विदेश-नीति में एक नया परिवर्तन आया। उसने पूर्वपिछा अधिक यथार्थवादी और आत्मविश्वासपूर्ण रूप ग्रहण किया। पाकिस्तान के प्रति तुष्टिकरण की नीति के स्थान पर दृढ़ता और आवश्यक कठोरता की नीति अपनायी जाने लगी। इस नीति का प्रारम्भ तो पहले ही हो चुका था, लेकिन अब यह एक कदम और आगे बढ़ गई। विदेश-नीति में इस परिवर्तन का सामान्यतया स्वागत किया गया।

2. भारत के प्रति अमेरिकी विदेश-नीति की कुटिलता का अच्छी तरह पर्दाफाश हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका भारतीय हितों की कोई परवाह नहीं करता, एक महान् लोकतन्त्र के प्रति शत्रुता और तानाशाही राज्य के प्रति मित्रता का व्यवहार कर सकता है। भारत में अमेरिका के विरुद्ध तीव्र असन्तोष व्याप्त हो गया और भारत सरकार का यह निश्चय और भी दृढ़ हो गया कि अमेरिकी सहायता पर आश्रित न रहा जाए। अब भारत में आत्म-निर्भरता का एक आन्दोलन-ता उठ खड़ा हुआ।

3. सोवियत संघ और भारत की मंत्री और अधिक घनिष्ठ हो गई। भारतीय नेतृत्व ने जनता को यह विश्वास दिला दिया कि जिन राष्ट्रों के साथ भारत के हित सम्बद्ध हैं, भारत उन्हीं राष्ट्रों के साथ अपने सम्बन्ध और मजबूत बनाएगा। इस प्रकार के लक्षण स्पष्ट हो गए कि सोवियत संघ भारत का एक विश्वसनीय मित्र है, अमेरिका पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता और भारत को चीन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

4. इस युद्ध के फलस्वरूप न केवल पाकिस्तान विलुङ्गित हुआ, बल्कि अमेरिका और चीन के राजनीतिक हितों को भी गहरी ठेस पहुँची। अमेरिका और पाकिस्तान पहले की तुलना में और अधिक निकट आए क्योंकि अमेरिका के लिए एशिया में अब टूटे हुए पाकिस्तान के प्रभाव और कोई सहारा नहीं रहा।

5. अमेरिका और चीन का यह इरादा स्पष्ट हो गया कि वे भारत को एक कमजोर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। दोनों को यह बात सहन नहीं थी कि अफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक के विस्तृत भू-भाग में भारत एक महाशक्ति के रूप में उदित हो।

6. एक प्रबल सैनिक शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के मन में यह आशंका घर कर गई कि वही भारत उनके प्रति दबाव की नीति न अपनाए, लेकिन भारत ने इस प्रकार की आशंकाओं को निर्मूल कर दिया। उदाहरणार्थ, कच्चातिबु खीलका को सौंप कर भारत ने महान् उदारता का परिचय दिया।

7. पाकिस्तान में सैनिक शासन के प्रति तीव्र असन्तोष उत्पन्न हो गया और अन्त में पाकिस्तान की बागडोर अर्सेनिक राजनीतिज्ञ श्री भुट्टो के हाथ में आई।

8. नवोदित बंगलादेश और भारत के बीच मैत्री का निरन्तर विकास होता चला गया।

9. राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में तो इस युद्ध के फलस्वरूप श्रीमती गांधी को एक शक्तिशाली राष्ट्रीय नेतृत्व प्राप्त हुआ। भारतीय यह महसूस करने लगे मानो सदियों के बाद भारत को एक ऐसा नेता मिला है जो उसे विश्व में एक महान् राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने को कटिबद्ध है।

शिमला-समझौता, जुलाई, 1972

भारत ने पराजित और विलुङ्गित पाकिस्तान की दुर्वशा का कोई अनुचित लाभ न उठा कर इस दान का प्रयत्न किया कि दोनों देश पारस्परिक वार्ता द्वारा अपने सभी विवादों का समाधान कर उपमहाद्वीप में मैत्री के एक नए युग का सूत्रपात करें। काफी विचार-विमर्श के बाद अखिर भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला (भारत) में जून, 1972 के अन्तिम सप्ताह में एक शिखर सम्मेलन के आयोजन का निश्चय हुआ। शिमला-वार्ता 28 जून से 3 जुलाई तक चली। 3 जुलाई को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक शिमला-समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते के कुछ महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित हैं—

1. भारत व पाकिस्तान की सरकारों का संकल्प है कि वे दोनों देशों के बीच अब तक चले आ रहे विद्वेष और विवादों को समाप्त कर पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों व उपमहाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए काम करेंगी ताकि दोनों देश अपने साधनों व शक्ति का उपयोग अपनी जनता के हित में कर सकें।

इस सद्प की प्राप्ति के लिए भारत व पाकिस्तान की सरकारें इन बातों पर सहमत हैं—

(क) दोनों देशों का संकल्प है कि वे अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण उपायों से या ऐसे शान्तिपूर्ण उपायों से जिनके बारे में दोनों देशों के बीच सहमति हो गई हो, हल करेंगे। जब तक दोनों देशों की समस्या का अन्तिम रूप से समाधान न हो जाए, कोई भी एक पक्ष स्थिति को नहीं बदलेगा और दोनों देश इस बात का प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई काम न हो जिससे शान्तिपूर्ण सम्बन्धों को आघात पहुँचे।

(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा के अनुसार दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे तथा वे न तो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे और न राजनीतिक स्वतन्त्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे।

2. दोनों ही सरकारें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे के प्रति घृणापूर्ण प्रचार नहीं करेंगी। दोनों राष्ट्र उन सभी समाचारों को प्रोत्साहन देंगे जिनके माध्यम से आपसी सम्बन्धों में सुधार की आशा हो।

3. आपसी सम्बन्धों में सामान्यता लाने की दृष्टि से—(क) दोनों राष्ट्रों के बीच डाक-तार-सेवा तथा जल एवं वायु मार्गों द्वारा पुनः संचार-व्यवस्था स्थापित की जाएगी। (ख) एक दूसरे के नागरिक और निकट आएँ, इसके लिए नागरिकों को आने-जाने की सुविधाएँ दी जाएँगी। (ग) जहाँ तक सम्भव हो सके व्यापारिक एवं अन्य आर्थिक मामलों में सहयोग का क्रम शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ होगा। (घ) विज्ञान एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रादान-प्रदान बढ़ाया जाएगा।

4. स्थायी शान्ति स्थापना की प्रक्रिया का क्रम प्रारम्भ करने के लिए दोनों सरकारें सहमत हैं कि (क) भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएँ अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा में लौट जाएँगी। (ख) दोनों देश बिना एक दूसरे की स्थिति को क्षति पहुँचाए जम्मू-कश्मीर में 17 दिसम्बर, 1971 को हुए युद्ध-विराम की नियन्त्रण रेखा को मान्यता देंगे। (ग) सेनाओं की वापसी इस समझौते के लागू होने के 30 दिन के अन्दर पूरी हो जाएगी।

5. दोनों देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्षों की सुविधाजनक अवसर पर भविष्य में पुनः भेंट होगी। इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि स्थायी शान्ति की स्थापना और सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। इनमें युद्ध-वन्दियों एवं नागरिकों की वापसी, जम्मू-कश्मीर के अन्तिम हल व कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न शामिल हैं।

शिमला-समझौते के बारे में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए। आलोचकों ने 'जवानो के बलिदान की उपेक्षा' और 'जीती हुई भूमि' लौटाने के निश्चय पर तीव्र विरोध प्रकट किया। जनसघी नेता श्री बाजपेयी ने इस समझौते में सरकारी बुद्धि का दिवालियापन देखा कि पाकिस्तान 69 वर्ग मील क्षेत्र खाली करेगा जबकि भारत 5,139 वर्ग मील पाकिस्तानी इलाका देगा। लोकसभा में 31 जुलाई, 1972 के अपने भाषण में श्री बाजपेयी ने शिमला-समझौते को 'देश के हित के साथ

विश्वासघात' बताया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ स्थायी शान्ति का बहुत अच्छा अवसर गंवा दिया है। समझौते द्वारा यही सिद्ध होता है कि देश पश्चिम युद्ध में जीता है, लेकिन कूटनीति में सरकार मुझे से हार गई है। श्री वाजपेयी ने देशभक्ति के ओज भरे स्वर में कहा कि हम यह मानते हैं कि हमें पाकिस्तान की भूमि नहीं चाहिए, लेकिन कश्मीर में पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है उसे खाली कराए बिना क्षेत्र को लौटाना हम कैसे सहन कर सकते हैं।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि विरोधी पक्ष की घालीचलाओं में देशभक्ति की नुँज थी, मातृभूमि के लिए तत्पक्ष थी और देश के सम्मान तथा जवानों के बलिदान के प्रति समझ थी। किन्तु शिमला-समझौते का मूल्यांकन करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समझौते में भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे राष्ट्रीय सम्मान को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँची हो। इस समझौते से वातावरण के सुधार में सहायता मिली। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 13 जुलाई 1972 के अपने भाषण में लोकसभा में यह विश्वास प्रकट किया कि शिमला-समझौते में दोनों ओर से यह प्रह्लास किया गया है कि दोनों देशों का भला मिलकर चलने में ही है। भारत को शान्ति के लिए लड़ना है और उसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जो शान्ति की ओर ले चलें। भारत किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार है, किन्तु इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि क्या शान्ति सम्भव नहीं है। श्रीमती गांधी ने कहा कि प्राज्ञ ऐसी स्थिति हो गई है कि पाकिस्तान चाहे भी तो भारत के विरुद्ध अधिक कुछ नहीं कर सकता। यह देखना भारत का काम है कि यह स्थिति कायम रहे और कटोर रख से यह स्थिति कायम नहीं रह सकती। यदि यूरोप के देशों ने पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ वैसा ही व्यवहार किया होता जैसा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किया है, तो सम्भवतः हिटलर का उदय न हुआ होता।

शिमला-समझौते के बाद से मई, 1976 तक

शिमला-समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच सम्बन्ध सुधारने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। वाषाओं के बावजूद धीरे-धीरे प्रगति हुई। पाकिस्तान के दुरायही रवैये के कारण कई बार तनावों में वृद्धि हुई लेकिन फिर स्थिति में सुधार हुआ और यही कम प्रगति तक चल रहा है।

शिमला-समझौते की पुष्टि और ठाकुर चौक के बारे में समझौता—शिमला से लौटते ही श्री मुझे ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय एम्बेस्ली की एक बैठक बुलाई और कहा कि समझौते में पाकिस्तान ने किसी भी सिद्धान्त का परित्याग नहीं किया। अग्न में, एम्बेस्ली ने समझौते की पुष्टि कर दी और 7 अगस्त, 1972 को पाकिस्तान ने 6770 भारतीय नागरिकों को मुक्त करने की घोषणा भी कर दी। शिमला-समझौते के कार्यान्वयन के बारे में अगस्त, 1972 के अन्तिम सप्ताह में दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक हुई। वार्ताओं और कठिनाइयों का दौर चला। ठाकुर

चीक नामक गाँव के प्रश्न पर काफी विवाद हुआ। अन्त में, 7 दिसम्बर, 1972 को ठाकुर-चीक के बारे में समझौता हो गया और 11 दिसम्बर को जम्मू-कश्मीर में पुनः रेखांकन सम्बन्धी मानचित्रों पर भी दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात् पाकिस्तान ने ठाकुर-चीक भारत को सौंप दिया और भारतीय सेनाएँ पश्चिमी क्षेत्र में सिन्ध तथा पंजाब में सियालकोट क्षेत्रों से पीछे हट गईं। जम्मू-कश्मीर में वास्तविक नियन्त्रण-रेखा को अन्तिम रूप में अंकित करने के उपरान्त दोनों पक्षों की सेनाएँ अपने-अपने स्थानों पर लौट गईं।

पाकिस्तान द्वारा विश्व अदालत में फरियाद, मई, 1973—प्रत्येक समस्या पर पाकिस्तान का आचरण अड़ियल रहा। उसने शिमला-समझौते की भावना का अनादर किया। युद्धबन्दियों का प्रश्न विवाद का एन्ग बड़ा मुद्दा बन गया। पाकिस्तान चाहता था कि उसके सभी युद्धबन्दी तत्काल छोड़ दिए जाएँ, किन्तु बंगलादेश की यह न्यायोचित माँग थी कि पाकिस्तान से बंगालियों और बंगलादेश से बिहारी मुसलमानों की वापसी के प्रश्न पर भी बातचीत हो। 18 अप्रैल, 1973 को भारत तथा बंगलादेश के विदेश मन्त्रियों ने उपर्युक्त तीनों समस्याओं के समाधान के लिए एक त्रि-सूत्री प्रस्ताव रखा; किन्तु पाकिस्तान ने परस्पर बातचीत द्वारा कोई समझौता करने की जगह मई, 1973 में इस त्रिसूत्री प्रस्ताव के विरुद्ध विश्व-अदालत में फरियाद की। पाकिस्तान ने कहा कि सन् 1948 के जिनेवा समझौते के अनुसार नरसंहार के अपराधियों को सजा देने का अधिकार पाकिस्तान को है, भारत को इस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

मानवीय समस्याओं पर दिल्ली समझौता, अगस्त, 1973—विरोधों और कठिनाइयों के बावजूद पाकिस्तानी युद्धबन्दियों तथा अन्य मानवीय समस्याओं पर अनेक स्तरों पर बातचीत के दौर चले और अन्त में 28 अगस्त, 1973 को भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार पाकिस्तान से सभी बंगालियों, बंगलादेश से काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों और भारत से उन 195 युद्धबन्दियों को छोड़कर जिन पर बंगलादेश में मरुदमा चलाया जाना था, शेष सभी युद्धबन्दियों की जल्दी ही एक साथ अदला-बदली करने का निर्णय लिया गया। यह समझौता करने में भारत सरकार बंगलादेश की सरकार से निरन्तर परामर्श करती रही। 195 युद्धबन्दियों के विषय में समझौते में यह प्रावधान रखा गया कि प्रत्यावर्तन (अदला-बदली) की प्रक्रिया के बीच किसी पर कोई मरुदमा नहीं चलाया जाएगा और ये युद्धबन्दी भारत में ही रहेंगे। यह तय हुआ कि बाद में इस समस्या के समाधान के लिए त्रिपक्षीय विचार-विमर्श होगा।

दिसम्बर, 1973 में पाकिस्तान ने 195 युद्धबन्दियों सम्बन्धी अपना प्रावेदन-पत्र विश्व-अदालत से वापस ले लेने का निर्णय किया। पाकिस्तान की इस कार्यवाही का स्वागत करते हुए भारत ने प्राज्ञा प्रकट की कि अब इन युद्धबन्दियों के मामले को निपटाने की दिशा में पारस्परिक वार्ता से कोई उपयुक्त कदम उठाया जा सकेगा, दिल्ली-समझौते के अर्धन प्रयासों का कार्य, कुछ बाधाओं के बावजूद पूरा हो गया।

कश्मीर के प्रश्न पर महासभा में श्री भुट्टो की रट, सितम्बर, 1973—
 शिमला-समझौते में यह तय हुआ था कि कश्मीर के प्रश्न का स्थायी समाधान
 पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण और पूर्ण शांति स्थापना के बाद ही
 निवाला है, किन्तु सितम्बर, 1973 में श्री भुट्टो ने सयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष
 अपने भाषण में फिर कश्मीर की रट लगाई। भारतीय विदेश मन्त्री ने स्पष्ट रूप
 से कहा कि इस प्रश्न को सयुक्त राष्ट्रसंघ में उठाने की कोई तुक नहीं है क्योंकि
 शिमला में दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति हो गई थी कि प्रश्न का द्विपक्षीय
 वार्ता से समाधान किया जाएगा। नवम्बर, 1973 में पाक प्रधानमन्त्री ने पाकिस्तान
 अधिकृत कश्मीर के दौर के समय कुछ ऐसे घान जारी किए जो शिमला-समझौते
 के प्रावधानों के विपरीत थे, विशेष रूप से उन प्रावधानों के जिनमें एक दूसरे के
 आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात नहीं गई है। पाकिस्तान सरकार का
 घान इस ओर आक्षेपित किया गया और यह बात स्पष्ट कर दी गई कि पाकिस्तान
 का उक्तवचन प्राधिकारी अगर ऐसे वक्तव्य देता है तो शिमला-समझौते पर अमल
 के बारे में पाकिस्तान के इरादों के प्रति भारत में आशंका उत्पन्न हो सकती है।

बंगलादेश को पाकिस्तानी मान्यता, फरवरी, 1974—भारत और पाकिस्तान
 और पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच तनाव का एक मुख्य कारण यह भी रहा
 कि पाकिस्तान ने बंगलादेश को कूटनीतिक मान्यता प्रदान नहीं की। अगस्त, 1973
 के दिल्ली-समझौते के बाद यह दिखाई देने लगा कि पाकिस्तान बंगलादेश की शीघ्र
 ही मान्यता दे देगा। जब फरवरी, 1974 में लाहौर में अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी सम्मेलन
 आयोजित हुआ तो बंगलादेश को भी, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 7 करोड़
 है, सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया। किन्तु शेख मुजीब ने स्पष्ट कह दिया कि जब
 तक पाकिस्तान बिना शर्त बंगलादेश को मान्यता नहीं देता, तब तक पाकिस्तान की
 भूमि पर ही रहे किसी सम्मेलन में बंगलादेश भाग नहीं ले सकता। शेख मुजीब के
 इस उत्तर पर इस्लामी राज्यों में कूटनीतिक घर्षाओं का दौर चला। कुवैत के
 विदेश मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने ढाका जाकर शेख मुजीब और
 अन्य नेताओं से बातचीत की। अग्त में 22 फरवरी को पाकिस्तान ने बंगलादेश को
 मान्यता दे दी और शेख मुजीब भी बल-बल महिन इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने
 के लिए 23 फरवरी को लाहौर पहुँच गए। पाकिस्तान की मान्यता के तुरन्त बाद
 ईरान और टर्की ने भी बंगलादेश को मान्यता देने की घोषणा कर दी। बंगलादेश
 को मान्यता देकर पाकिस्तान ने भारतीय उपमहाद्वीप की एक वास्तविकता को
 बीकार किया जिससे इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया की ओर
 अमला। पाकिस्तान द्वारा मान्यता के बाद यह प्रायः निश्चित हो गया कि सयुक्त
 राष्ट्रसंघ में बंगलादेश के प्रवेश का चीन और पाकिस्तान विरोध नहीं करेंगे और
 195 घुट-पारराधियों की भी रिहाई हो जाएगी।

दिल्ली के दो समझौते, अप्रैल, 1974—भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान
 के विदेश मन्त्रियों ने 9 अप्रैल, 1974 को दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौते पर

हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार बंगलादेश ने विवादग्रस्त 195 पाकिस्तानी युद्ध-अपरराधियों को मुक्त करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि बंगलादेश में पाक-सैनिक अपराधियों ने अपराध किए होंगे। पाकिस्तान ने बंगलादेश से तीन प्रकार के पाकिस्तानी नागरिकों को वापस लेने की बात मान ली—(i) जो पश्चिमी पाकिस्तान के निवासी थे, (ii) जो पाकिस्तान-सरकार के कर्मचारी थे, तथा (iii) जो विभाजित परिवार के सदस्य थे। संख्या की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई। त्रिपक्षीय समझौते के अवसर पर ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्वि-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत उन भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकों के आदान-प्रदान का निश्चय किया गया जो वपों से उन दोनों देशों की जेलों में बन्दी थे। ये दोनों समझौते महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनके द्वारा न केवल कुछ गम्भीर मानवीय समस्याओं का समाधान हुआ बल्कि उन-महाद्वीप में शान्ति की शक्तियों को भी प्रोत्साहन मिला। राजनीतिक क्षेत्र में यह आशा व्यक्त की गई कि इन समझौतों से एक और भारत तथा पाकिस्तान में और दूसरी ओर पाकिस्तान तथा बंगलादेश में मैत्री और सद्भाव का एक नया अध्याय शुरू होगा।

भारत के परमाणु-विस्फोट पर पाकिस्तान की बौखलाहट, मई 1974— विदेश नीति के क्षेत्र में पाकिस्तान की रण-नीति कुछ विचित्र रही है। पूरी तरह युद्ध में अवमानित होकर पाकिस्तान समझौते के द्वार पर पहुँचना है। द्वार पर पहुँचने के बाद फिर अडगेबाजी करता है और तब फिर समझौता कर लेता है। इसके बाद अपनी शान्तिप्रियता का डिंडोरा पीटता है और फिर लड़ने, गाली गलौज करने, निराधार आरोप लगाने के मार्ग पर चल पड़ता है। सुघरते हुए सम्बन्धों को बिगाड़ लेने में पाकिस्तान का नेतृत्व अपनी सुरक्षा का अनुभव करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानी नेतृत्व को अपने ही देश में अपनी जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है और जन-भावनाओं को भारत के विरोध में उकसा कर अपनी गद्दी बचाने की कृति में लगा रहता है। अग्रेल, 1974 में दोनों दिल्ली-समझौतों के बाद पाकिस्तान ने फिर तनाव का वातावरण बनाना शुरू कर दिया। 18 मई, 1974 को भारत ने अपना प्रथम परमाणु-परीक्षण किया और मियाँ मुद्दो चीख उठे कि यदि भारत अणु-बम बनाता है तो पाकिस्तान भी अणु-बम बनाएगा, चाहे उसे घास-पात खाकर या भूखा रहकर ही जीवित रहना पड़े। पाकिस्तान की बौखलाहट ऐसी लगती थी कि मानो एक पागल का प्रलाप हो। श्रीमती गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अणु-शक्ति का विकास रचनात्मक उद्देश्यों के लिए कर रहा है, किन्तु पाकिस्तान और उसके हिमायती राष्ट्रों के गले यह बात नहीं उतरी। श्रीमती गांधी ने श्री मुद्दो को एक पत्र लिखकर दोनों देशों के बीच अनाक्रमण सन्धि का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सुरन्त ठुकरा दिया। 'कमजोर, गुस्ता ज्यादा' वाली कहावत ही चरितार्थ हुई। पाकिस्तानी रविवे में दोनों देशों के सम्बन्धों में पुनः कटुता आ गई।

संचार और यात्रा-सुविधाएँ जारी करने के बारे में समझौता, सितम्बर,

1974—युद्ध के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच डाक, दूर-संचार और याता-युवियाएँ समाप्त हो गई थी। सितम्बर, 1974 में इस्लामाबाद में दोनों पक्षों ने तीन समझौतों पर हस्ताक्षर करके इन मुविधाओं को तत्काल जारी करने का निर्णय लिया। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच फिर सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, किन्तु कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनः स्थापना अभी बहुत दूर की जोड़ी थी।

वर्ष 1975 में भारत-पाक सम्बन्ध—1975 के वर्ष में भारत पाकिस्तान के साथ मतभेदों को शान्तिपूर्वक दूर करने और उसके साथ सामान्य सम्बन्ध विकसित करने के लिए अपनी ओर से निरन्तर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता रहा ताकि इस उपमहादीप में स्थायी शान्ति स्थापित रह सके लेकिन पाकिस्तान की ओर से अनुकूल दृष्टिकोण नहीं प्रपनाया गया। जब फरवरी, 1975 में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड ने पाकिस्तान को पुनः अमेरिकी हथियार प्रदान करने की घोषणा की तो श्री मुट्ठो भारत के साथ दो-दो हाथ करने की बात करने लगे। लन्दन स्थित पश्चिमी सैनिक विशेषज्ञों तक ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान जिस प्रकार शस्त्रास्त्रों का सग्रह कर रहा है और अपने रक्षा व्यय में वृद्धि कर रहा है वह उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से बिल्कुल असम्बलित है। श्री मुट्ठो की घमकियाँ तब शान्त हुईं जब भारत के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि "यदि पाकिस्तान मांगे हुए हथियारों के बल पर भारत पर आक्रमण करेगा तो तड़ाई भारतीय क्षेत्र में नहीं होगी अतः हम पाकिस्तान की भूमि पर लड़ेंगे। हम पर यदि पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो यह निर्णय हम करेंगे कि लड़ाई कहाँ करनी है।"

2. मई, 1975 से पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध निराधार और निन्दात्मक प्रचार प्रान्दोलन शुरू कर दिया जिससे वातावरण और बिजुब्ध हो गया। अप्रैल में भारत ने समुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव लड़ने के लिए जब अपनी उम्मीद-वारी की घोषणा कर दी तो पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ चुनाव लड़ने का निश्चय किया। पाकिस्तान के सरकार-प्रचारी माध्यमों ने तथा विदेशों में स्थित उसके मिशनो ने यह मिथ्या प्रचार शुरू कर दिया कि भारत अपनी आन्तरिक स्थिति से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर सकता है। 15 अगस्त को बंगलादेश में शेख मुजीबुर्रहमान की सरकार को हिसापूर्वक हटा दिए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों ने अपने भारत-विरोधी प्रान्दोलन को एक नया रूप देने हुए यह कहा कि हो सकता है भारत बंगलादेश में हस्तक्षेप करे। भारत सरकार ने इस बमनस्यपूर्ण एवं निन्दात्मक प्रचार-प्रान्दोलन की ओर पाकिस्तान का ध्यान आकृष्ट किया क्योंकि यह शिमला समझौते के विपरीत था और सम्बन्धों को सामान्य बनाने के मार्ग में अडचन सिद्ध हो रहा था। जो भी हो, पाकिस्तान में सरकारी प्रचारतन्त्र और वहाँ के अखबारों ने यह प्रान्दोलन जारी रखा।

3. भारत और पाकिस्तान के बीच मई, 1975 में वायुमार्ग सम्बन्धी समझौते के लिए जो उच्चस्तरीय वार्ता हुई वह भी सफल नहीं हुई क्योंकि

पाकिस्तान इस आग्रह पर डटा रहा कि हवाई मार्गों की सुविधा के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौता होने के बाद ही पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था से भारत के विरुद्ध दायर किए गए अभियोग को वापस लेगा। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की यह समझाने की कोशिश व्यर्थ हुई कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था में अभियोग के चलते हुए दोनों देशों के बीच स्वस्थ और मित्रतापूर्ण वातावरण पैदा नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान अभियोग वापस ले।

4. भारत की पहल पर विदेश-सचिवों की बैठक में एक अन्य विषय पर भी चर्चा हुई जिसका सम्बन्ध सन् 1960 की तिन्धु जल सन्धि के अनुसार सलाल में चिनाब नदी पर पन बिजली-विद्युत परियोजना के निर्माण से था। भारत ने यह सुझाव दिया था कि पाकिस्तान में इस परियोजना के डिजाइन के सम्बन्ध में जो शर्तें उठायी गयी हैं उन्हें दूर करने के लिए द्विपक्षीय चर्चा हो। मई, 1975 में विदेश-सचिवों की बैठक में कुछ बातों पर सहमति हो गई, तथापि अन्त में पाकिस्तान सरकार ने निश्चय किया कि यह मामला किसी तटस्थ विशेषज्ञ के सामने रखा जाए।

5. जहाँ तक व्यापार का मामला है दोनों देशों के बीच व्यापार पुनः शुरू करने के बारे में जनवरी, 1975 में समझौता हो जाने के बाद भारत ने विदेशी मुद्रा में लगभग 25 करोड़ रु. मूल्य की 2 लाख सूत की गाँठें बिक्री करने का अपना वचन पूरा किया। पाकिस्तान 1975 के वर्ष में भारत से सामान खरीदने के लिए कोई समझौता करने में असफल रहा।

6. वर्ष 1975 के पाकिस्तान जम्मू तथा कश्मीर के उम प्रदेश की स्थिति एकतरफा तरीके से बदलने के प्रयत्न करता रहा जिस पर उसका अवैध कब्जा है। भारत सरकार के विरोधी के बावजूद पाकिस्तान इस दिशा में आगे बढ़ता रहा और अगस्त, 1975 में उसने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए एक परिपद् की स्थापना की जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर पर अपने नियन्त्रण को पहली बार सस्थागत व्यवस्थित रूप दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि इस परिपद् की स्थापना करने की उसकी कार्यवाही शिमला समझौते का उल्लंघन है क्योंकि यह जम्मू तथा कश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत प्रदेशों की स्थिति में एकपक्षीय परिवर्तन है। दोनों ओर से पत्रों के आदान प्रदान में भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इन अधिकृत प्रदेशों में लागू 'अन्तरिम सचिवान' में निहित तत्त्वों की दृष्टि से इस परिपद् की स्थापना एक बहुत बड़ा सांविधानिक परिवर्तन है जिसे मात्र प्रशासनिक प्रयत्न नहीं माना जा सकता।

7. कश्मीर की समस्या को शान्तिपूर्वक द्विपक्षीय तरीके से सुलझाने के लिए शिमला-समझौते की शर्तों के अनुसार वचनबद्ध होने के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के निर्जीव प्रस्तावों में पुनः अन्तर्राष्ट्रीय रुचि जगाने

की कोशिश की। टर्की और कम्बोडिया के राज्याध्यक्षों की पाकिस्तान-यात्राओं की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्तियों में भी इस प्राथम्य का उल्लेख किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिमला-समझौते में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि कश्मीर की परिस्थितियों में और उसकी स्थिति में आधारभूत परिवर्तन हो जाने के कारण यह प्रस्ताव पहले ही निर्जीव और निष्क्रिय हो चुका है। इस प्रकार पाकिस्तान शिमला-समझौते के शब्दों की एक पक्षीय और गलत व्याख्या करके अन्य देशों को भ्रमित करने की चेष्टा करता रहा।

वर्ष 1976-77 (मार्च, 77) तक सामान्य सम्बन्धों की स्थापना—जुलाई, 1972 में शिमला-समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से भारत ने इस उप-महाद्वीप में स्थायी शान्ति की स्थापना के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य करने के लिए स्वयं अपनी ओर से विभिन्न कदम उठाए। इसके परिणामस्वरूप बहुत सी समस्याओं का समाधान हो गया।

27 मार्च, 1976 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को सूचित किया कि 'सम्बन्धों को सामान्य बनाने हेतु आवश्यक प्रोत्साहन देने' के इरादे से पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमान सगठन से अपना मुकदमा वापस लेने को तैयार है। सम्बन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया की प्रगति के उद्देश्य से भारत ने पहले ही ऐसी कार्यवाही करने के लिए कहा था। भारत को इन दृढ़ आस्था के अनुरूप कि शिमला-समझौते में स्थायी शान्ति की स्थापना और समस्त द्विपक्षीय सम्बन्धों की सुदृढ़ रूपरेखा सन्निहित है, प्रधानमंत्री ने 11 अप्रैल, 1976 को इसको उत्तर देते हुए सुभाव दिया कि दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक हो और इस बैठक में वे न सिर्फ सिविल विमानन के मामलों पर विचार-विमर्श करें बल्कि रेल और सहक-संचार भी पुनः चालू करने के बारे में तथा दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित करने के बारे में भी विचार-विमर्श करें। पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री ने इन सुभावों को स्वीकार कर लिया और इसके परिणामस्वरूप 12 से 14 मई, 1976 तक इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के विदेश-सचिवों की नार्ता हुई और इस अवसर पर संयुक्त वक्तव्य प्रसारित किया गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच यह समझौता निहित था कि दोनों देशों के टूटे हुए सभी सम्पर्क पुनः मारम्भ किए जाएँगे। दोनों पक्षों ने निजी क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार चालू करना भी स्वीकार किया।

इस संयुक्त वक्तव्य में निहित समूचा समझौता 17 से 24 जुलाई, 1976 के बीच कार्यान्वित होना शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच हवाई सम्पर्क 21 जुलाई, से पुनः चालू हुआ, 22 जुलाई को अमृतसर से पहली रेलगाड़ी लाहौर के लिए रवाना हुई और दोनों देशों के राजदूतों ने अपने-अपने प्रत्यक्ष प्रस्तुत किए।

समीक्षाधीन वर्ष के उत्तरार्द्ध में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल नई दिल्ली और इस्लामाबाद में मिले और इस अवसर पर उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य में चिनाव नदी पर सलाह पन-विजली से विद्युत पैदा करने के

लिए इसके उपयोग के बारे में वार्ता की, बतलें कि इन संयन्त्रों का डिजाइन, निर्माण और संचालन सधि में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हो। यह मामला पिछले छ' वर्षों से स्पाई सिन्धु आयोग के विचाराधीन है जिसमें भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। चूंकि आयोग के माध्यम से कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए जुलाई, 1976 में पाकिस्तान ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सन्धि की शर्तों के अनुसार इस मामले को किसी तटस्थ विशेषज्ञ को परामर्श के लिए सौंप दिया जाए, किन्तु भारत ने यह सुझाव दिया कि ऐसा करने से पूर्व इस मामले पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श कर लिया जाए। पाकिस्तान ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। अक्टूबर, 1976 में नई दिल्ली और इस्लामाबाद में वार्ता के दो दौर चले। यह बातचीत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई तथा रचनात्मक और लाभदायक रही। इस्लामाबाद में हुई वार्ता के पश्चात् प्रसारित संयुक्त वक्तव्य में यह आशा प्रकट की गई है कि नई दिल्ली में इस वार्ता का जो तीसरा दौर होगा उसमें कोई अन्तिम समझौता हो जाएगा।

सामान्यीकरण की प्रक्रिया मोटे तौर पर सुचारु ढंग से चलती रही और कई दिशाओं में सम्पर्क पुनः स्थापित हुए जो बीच के कई वर्षों में रुके रहे थे। इन घटनाओं का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बहुत स्वागत हुआ।

मार्च, 1977-दिसम्बर, 1977 तक सम्बन्ध—भारत में गई सरकार के गठन के बाद मैत्रीपूर्ण संदेशों का आदान-प्रदान हुआ। अप्रैल, 1977 में श्री भट्टो ने हमारे प्रधानमन्त्री के लिए एक व्यक्तिगत संदेश के साथ अपने एक विशेष दूत को नई दिल्ली भेजा। नई सरकार को आशा है कि वह पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रखेगी तथा उनको बढ़ाएगी। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा के बाद उसी महीने में दोनों देशों ने यह निश्चय किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार की समीक्षा करने और उसमें वृद्धि के उद्देश्य से एक संयुक्त आयोग की स्थापना की जाएगी।

अप्रैल 1977 में ही विदेशमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के सामने युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव रखा। उनका विश्वास है कि इस प्रकार का समझौता उप-महाद्वीप में स्थायी शांति स्थापित करने का आधार बन सकता है। भारत द्वारा युद्ध न करने का प्रस्ताव पहली बार ही नहीं रखा गया है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। अखण्ड से इस प्रकार का पहला प्रस्ताव अक्टूबर 1959 में पंडित नेहरू द्वारा प्रेसीडेंट अयूब खान के सामने रखा गया था। इस समय स प्रस्ताव का फिर से रखा जाना चार कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, सरकार 15 दिनों के भीतर ही यह प्रस्ताव रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नई सरकार पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प है। दूसरा, इस प्रकार के समझौते से भारत-पाक सम्बन्धों में द्विपक्षीय नीति को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। तीसरा, जनता पार्टी का चुनाव घोषणा-पत्र भी यह स्पष्ट करता है कि वह पड़ोसी राष्ट्रों से अभी तक हल नहीं किए गए विवादों को निपटाने के लिए

प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान में भी विश्वास प्रकट किया गया था। परन्तु जब राजनैतिक दल सत्ता में आ जाते हैं और उनकी अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू राजनीति को वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है तो चुनाव घोषणा पत्र के वायदे धूमिल पड़ने लगते हैं। युद्ध न करने का प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनाव घोषणा-पत्र के कुछ मुद्दों को व्यावहारिक रूप देता है।

यदि पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वागत नहीं करता तो इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। प्रथम, शिमला-समझौते के प्रन्तर्गत सम्बन्ध सुधारने के प्रयासों में अधिक प्रगति नहीं हुई है। निःसन्देह दोनों राष्ट्रों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित हो गई है, परस्पर व्यापार में भी प्रगति हो रही है परन्तु यह उपाय धीमे व मुट्टि पूर्ण हैं तथा अधिक सारगर्भित नहीं हैं। पाकिस्तान को प्रारम्भ से ही यह भय रहा है कि भारत के साथ अच्छे सम्बन्ध उसके राष्ट्रीय अस्तित्व को ही समाप्त कर सकते हैं। पाक से हाल में युद्ध न करने के समझौते का प्रस्ताव वर्तमान भारत-पाक सम्बन्धों की दृष्टि से एक अधिक सुधारवादी कदम हो सकता है। प्रश्न यह भी है कि क्या पाकिस्तान, इस समय, अपनी विदेश नीति में इतनी बड़ी पहल कर सकेगा? इस प्रश्न को कुछ भिन्न दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह विवादास्पद विषय है कि क्या युद्ध न करने का समझौता भारत पाक के मध्य सम्बन्धों के पूर्णतः सामान्य हो जाने पर ही किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि युद्ध न करने का समझौता सभी स्वीकार्य हो जब भारत-पाक के मध्य सभी महत्वपूर्ण मामलों का समाधान कर लिया जाए। परन्तु युद्ध न करने का समझौता दोनों के मध्य विश्वास उत्पन्न करने के साधन के रूप में भी हो सकता है। यह उनके मध्य परस्पर विश्वास की स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिससे आगे चल कर उनमें सम्बन्धों में सुधार हो सकता है।

5 जुलाई, 1977 को एक रक्तहीन क्रांति के फलस्वरूप पाकिस्तान में फिर सैनिकशाही की स्थापना हो गई और भारत का उपर्युक्त प्रस्ताव पुनः खटाई में पड़ गया। पाकिस्तान में श्री भुट्टो सहित सभी राजनीतिक नेता बंदी कर लिए गए हैं और फौजी कानून लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्रमुख फौजी कानून प्रशासक जनरल जिया-उल-हक ने 6 जुलाई को आश्वासन दिया कि तीन महीने के भीतर लोकतन्त्र पुनः स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन दिसम्बर, 1977 के अन्त तक पाकिस्तान में सैनिकशाही की समाप्ति के सभी कोई लक्षण दिखाई नहीं देने। वैसे पाकिस्तान की सैनिक सरकार के साथ भारत के सम्बन्ध सामान्य हैं।

भारत और थैलैंका

भारत के दक्षिण और हिन्द-महासागर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मई, 1972 में नए संविधान के अनुसार थैलैंका गणराज्य बन गया है। इसका अंग्रेजी नाम 'सिलोन' हटा दिया गया है। थैलैंका ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य है और विदेश नीति में भारत के समान ही गूट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करता रहा है।

भारत और श्रीलंका के सम्बन्ध उतार-चढ़ाव के रहे हैं, तथापि कुल मिलाकर दोनों देशों की मैत्री में वृद्धि हुई है और पारस्परिक विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत ने श्रीलंका के आर्थिक विकास में सहायता दी थी। सन् 1955 के बाण्डुंग-सम्मेलन में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया। सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के सन्दर्भ में श्रीलंका ने निष्पक्ष नीति का अवलम्बन न कर भारतीय भावनाओं को ठेस पहुँचायी, तथापि प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायके ने तत्कालीन देशों का कोलम्बो सम्मेलन आयोजित किया और सम्मेलन द्वारा पारित कोलम्बो-प्रस्तावों के सम्बन्ध में पेरिस तथा दिल्ली की यात्राएँ की। इस प्रकार श्रीलंका का प्रयत्न यह रहा कि भारत-चीन विवाद का शान्तिपूर्ण समाधान निकल आए। सन् 1965 में दोनों देश तब अधिक निकट आ गए जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधान मंत्री सेनानायके ने भारत के न्यायोचित पक्ष का समर्थन किया और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने तथा कोलम्बो प्रस्तावों को न मानने के लिए उसकी निन्दा की। सन् 1970 में नेतृत्व पुनः श्रीमती भण्डारनायके के हाथ में आया। मई, 1971 में उनकी सरकार को उपद्रवाधी दामपयियों के व्यापक विद्रोह का सामना करना पड़ा जिसे दबाने के लिए उन्हें भारत जैसे मित्रदेशों की सहायता भी लेनी पड़ी। भारत के हेली-कोप्टरों ने श्रीलंका के अनेक भागों में गश्त लगायी और भारतीय जहाज श्रीलंका के बन्दर-गाह पर लगर डाले खड़े रहे ताकि श्रीलंका सरकार को शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। भारत ने श्रीलंका को शस्त्रों की सहायता भी दी।

दोनों देशों के सम्बन्ध उत्तरोत्तर सुधरते गए। श्रीमती गांधी ने अप्रैल, 1972 में श्रीलंका की यात्रा की और संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों प्रधान मन्त्रियों ने स्वीकार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों देशों के विचार एक-दूसरे के बहुत निकट हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग सहित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने अक्टूबर, 1973 में श्रीलंका की यात्रा की। जनवरी, 1973 में श्रीमती भण्डारनायके भारत आई।

दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे विवाद भी थे जिनका अब यद्यपि समाधान किया जा चुका है, तथापि अतीत में वे तनाव का मुख्य कारण रहे। अतः उपर्युक्त होगा कि इन विवादों का सुस्थिर निवेदन कर दिया जाए—

राज्य-विहीन नागरिक—यह विवाद सन् 1939 में उठा था, किन्तु अब लगभग हल मुलभूत हुआ है। राज्य-विहीन नागरिकों की संख्या में लगभग 11 लाख 40 हजार व्यक्ति आते हैं जिनमें से 1 लाख 34 हजार श्रीलंका के और 2 लाख 40 हजार भारत के नागरिक हैं। किन्तु विवाद उन 7 लाख 66 हजार व्यक्तियों के बारे में रहा है जो किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं। ये भारतीय ही हैं जिन्हें अंग्रेज अपने शासनकाल में श्रीलंका के चाय और रबर बागानों में मजदूरों के रूप में ले गए थे। तब से इन लोगों के परिवार वही पनपे और फले-फूले। भारतीय

मूल के नागरिकों के भारत वापस लौटने की मांग श्रीलंका में सन् 1939 में प्रारम्भ हुई। सन् 1949 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों में कुछ प्रस्थापी सम्मेलित हुए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। सन् 1954 में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर जान कोटलावाला और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू में जो सम्मेलित हुए वे भी प्रत्यक्षालिन सिद्ध हुए। 26 अक्टूबर, 1964 को श्री शास्त्री और श्रीमती भण्डारनायक में वास्तविक सम्मेलित हुआ जिसके अन्तर्गत सभी राज्य-विहीन नागरिकों को भारत या श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करने के आवेदन देने के लिए कहा गया। श्रीलंका सरकार 8 लाख 25 हजार लोगों में से 3 लाख लोगों को अपने वहाँ रखने के लिए सहमत हुई और 5 लाख 25 हजार नागरिकों का दायित्व भारत पर डाला गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ भारत में 7 व्यक्ति आए वहाँ श्रीलंका के 4 व्यक्ति रहे। इस प्रक्रिया को 15 वर्षों के भीतर अर्थात् 1979 तक पूरा किया जाना निश्चित हुआ। चूँकि श्रीलंका के अधिकारी प्रत्यावर्तन (प्रदलान-वदली) की गति से सन्तुष्ट नहीं थे, अतः अप्रैल, 1974 में जब श्रीमती गांधी श्रीलंका के दौरे पर गईं तो उन्होंने प्रत्यावर्तन की गति (वार्षिक 35 हजार) में 10 प्रतिशत की वृद्धि करना स्वीकार कर लिया सन् 1974 के प्रारम्भ में केवल डेढ़ लाख राज्य-विहीन नागरिक ही ऐसे शेष रहे जिन्हें भारत लौटना था। सन् 1975 में इस करार के अन्तर्गत 18448 व्यक्ति भारत प्रत्यावर्तित हुए। इस प्रकार 1964 के सम्मेलित के अनुसार कुल मिलाकर 525,000 तथा 300,000 व्यक्तियों में से 1975 के अन्त तक 157,470 व्यक्ति प्रत्यावर्तित किए जा चुके थे और 891993 को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जा चुकी थी।

कच्चातिरू- यह विवाद 28 जून, 1974 के सम्मेलित द्वारा निपटाया जा चुका है। कच्चातिरू (या कच्छदीप) भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच 200 एक्ड़ का एक छोटा-सा द्वीप है जिसमें नागरिकों के अनिश्चित और कुछ नहीं उगता। आस-पास मछुवारे मछली प्रवश्य पकड़ते हैं। इस भू-खण्ड की जनसंख्या नगण्य है। दोनों देश इस भूखण्ड पर अपना अधिकार जताते हैं। विवाद इसलिए और भी उग्र हो गया क्योंकि इस द्वीप के आसपास तेल के काफी बड़े भण्डार होने की आशा की जाती थी। भारत ने एक महान् पड़ोसी देश की परम्परा का निर्वाह करते हुए इस छोटे से द्वीप के कारण दोनों देशों के बीच विवाद को लम्बा खींचना उपयुक्त नहीं समझा। 28 जून, 1974 को दोनों में एक सम्मेलित सप्त हुआ जिसके अनुसार कच्चातिरू को श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में मान लिया गया। पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों में सुधार की दिशा में श्रीमती गांधी का यह एक महत्वपूर्ण कदम था। सन् 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की विजय से कई पड़ोसी देश आश्चरित हो उठे थे कि भारत एक महाशक्ति बनकर छोटे देशों को आतंकित करेगा। लेकिन कच्चातिरू श्रीलंका को सौंपकर भारत ने इस प्रकार की आशाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया।

कच्चातिबू-समझौते को भारत और श्रीलंका के बीच एक नए सहयोग के युग का प्रादुर्भाव माना जा सकता है। इस समझौते से भारत को कोई क्षति नहीं हुई है, अनि हुई है भारत के विरोधियों की। समझौते के बाद मार्च, 1976 तक दोनों देशों के बीच पारस्परिक यात्राओं से अधिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग और सुहृद हुआ है।

अप्रैल, 1976 से दिसम्बर, 1977 तक—23 अप्रैल, 1976 को भारत और श्रीलंका के बीच एक सीमा सम्बन्धी समझौता हुआ जो शीघ्र ही दोनों देशों द्वारा पुष्टि-पत्रों के आदान-प्रदान के साथ लागू हो गया। भारत और श्रीलंका के बीच कोई स्थल सीमा नहीं है, केवल समुद्र है। अतः यह सीमा समझौता वस्तुतः समुद्री सीमा विषयक समझौता ही है। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक देश के तट के 200 मील तक का समुद्री क्षेत्र उसका आधिक क्षेत्र होगा और जहाँ दोनों के बीच की दूरी 200 मील से कम होगी वहाँ दूसरे देश की मध्यस्थ रेखा सीमा रेखा होगी। इस समझौते का एक विशेष महत्व इस बात में है कि समुद्री कानून विषयक विश्व सम्मेलन अब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा है, जबकि भारत और श्रीलंका ने अपनी समस्या हल भी कर ली है।

अगस्त, 1976 में गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री ने कोलम्बो की यात्रा की जहाँ श्रीलंका सरकार और जनता ने उनका हार्दिक और मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। शिखर-सम्मेलन से पूर्व और उसके दौरान दोनों पक्षों के बीच निरुद्ध और निरुद्ध सहयोग से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध और दृढ़ हुए।

भारतीय मूल के व्यक्तियों से सम्बद्ध सन् 1964 के समझौते के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1976 तक 2,37,390 व्यक्ति भारत प्रत्यावर्तित किए गए और 1,35,680 व्यक्ति श्रीलंका में नागरिकों के रूप में पंजीकृत किए गए।

मार्च, 1977 में जैसी जनमत क्रांति भारत में हुई थी वैसे ही 21 जुलाई, 1977 को श्रीलंका में हुई और श्रीमती भंडारनायके की गत्ताल्ल श्रीलंका फ्रीडम पार्टी को 166 में से मात्र 8 स्थान प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि श्रीमती भंडारनायके ने 16 मार्च, 1971 को देश में आपात्कालीन स्थिति लागू कर दी थी और छ वर्ष के आपात्काल में उनकी सरकार की साक्ष बिलकुल गिर गई थी। श्रीमती भंडारनायके के पतन के बाद 72 वर्षीय श्री जयवर्धन श्रीलंका के प्रधानमंत्री हुए और उनकी सरकार के साथ भारत की नई सरकार के सम्बन्ध उत्तरोत्तर मैत्रीपूर्ण होते जा रहे हैं।

भारत और नेपाल

भारत और चीन के बीच हिमालय की गोद में स्थित इस देश के साथ कुछ अपवादों को छोड़कर भारत के सम्बन्ध न्यूनाधिक मैत्रीपूर्ण रहे हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से तो दोनों देश अनि निकट हैं ही, साथ ही आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के कारण भी दोनों में मैत्री स्वाभाविक है।

31 जुलाई, 1950 की सन्धि द्वारा दोनों देश निश्चय कर चुके थे कि वे शान्ति और मैत्री की नीति का अनुसरण करेंगे। दोनों में एक व्यापारिक सन्धि भी सम्पन्न हुई जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ कि नेपाल अपना विदेशी व्यापार भारतीय क्षेत्र से होकर सुचारु रूप में कर सकेगा।

नेपाल में कुछ भारत-विरोधी तरव पहले ही से विद्यमान थे। साम्यवादी चीन भी अपने प्रभाव-वित्तार के लिए भीतर ही भीतर नेपाल में भारत-विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन दे रहा था। अतः नेपाल में यह विचार बल पकड़ने लगा कि नेपाल की भारत और चीन के मध्य एक संघर्षक (बफर) राज्य की भूमिका निभानी चाहिए। सन् 1955 में राजा त्रिभुवन की मृत्यु के बाद राजा महेन्द्र विजयशहा नेपाल की राजगद्दी पर बैठे। राजा महेन्द्र ने असौकरतात्मिक कार्यवाही कर सन् 1960 में संसद को भंग कर दिया और देश का शासन स्वयं सम्भाल लिया। राजा महेन्द्र का यह कार्य यद्यपि भारत को अपात पहुँचाने वाला था, तथापि भारत ने नेपाली राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत नेपाल को आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के लिए सभी प्रकार मर्यादित प्रदान करता रहा। सन् 1956 में टवाग्रेसड घाचायें नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उनका भूतान चीन की ओर था, अतः नेपाल में भारत-विरोधी धारणाएँ पैदा करने में उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग रहा। सन् 1956-57 में प्रसिद्ध नापा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को नेपाल के राष्ट्रीय विकास में सहयोग देना चाहिए। इस कथन का अभिप्राय अत्यन्त रूप से भारत पर यह आरोप लगाना था कि भारत नेपाल को अपना पिछड़े देश बनाना चाहता है। सन् 1957 में डॉ. के. आर्द-विह प्रधानमंत्री बने और सन् 1959 में बी. पी. कोइराला। इन दोनों ही के प्रधानमन्त्रित्वकाल में भारत-नेपाल सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हो सका। डॉ. के. आर्द-विह के सुधार-प्रयत्नों की आचार्य-न्यायक समाचार-पत्रों ने गफल नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री कोइराला ने चीन के साथ एक्स्टेन्सिव ताल्लर के बारे में ऐसा समझौता किया जो नेपाल सरकार का भारत के साथ मित्रतासंधि था। कोइराला-मन्त्रिमण्डल के पतन के बाद भी सन् 1961 तक दोनों देशों के सम्बन्ध अनावस्यपूर्ण रहे। भारत के विरोध के बावजूद राजा महेन्द्र ने काठमाण्डू ल्हासा-सड़क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में चीन से समझौता किया। उन्होंने चीन के साम्यवादी नेताओं का समय-समय पर मिलने और भारत की उपेक्षा करने की नीति अपनायी। सन् 1961 में 6 पुष्टों की प्रचलित एक पुस्तिका में कहा गया कि नेपाल को विदेशों से प्राप्त सहायता में चीन ने सर्वाधिक उदार और विस्वायें योग दिया है। सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के प्रति नेपाल ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार साम्यवादी चीन के प्रति अत्यन्त रूप में सहानुभूति प्रकट की।

सन् 1964 में श्री नेहरू की मृत्यु के बाद श्री आम्बी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने नेपाल की भाषा की ओर दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ। राजा महेन्द्र भारत आए और राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन नेपाल गए। भारतीय

नेताओं ने नेपाली नेतृत्व को साम्यवादी चीन के वास्तविक खतरे से सचेत किया। सितम्बर, 1964 में भारतीय विदेशमन्त्री सरदार स्वर्णसिंह नेपाल गए और एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत ने 9 करोड़ रुपये की लागत से नेपाल के लिए एक 128 मील लम्बी सड़क बनाने का निर्णय किया। काठमाण्डू से भारतीय सीमा रक्सौल को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क योजना भी भारत ने अपने हाथ में ली। इसके प्रतिरिक्त भारत ने अपने व्यय से कोसी-योजना पूर्ण करने का भी निश्चय किया। अप्रैल, 1965 में श्री शास्त्री ने कोसी-योजना के पश्चिमी-नहर-कार्य का उद्घाटन किया। योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ की क्षति से बचाना और विजली तथा सिंचाई से लाभ पहुँचाना था। दिसम्बर, 1965 में नेपाल-नरेश ने भारत-यात्रा की और एक संयुक्त विज्ञप्ति द्वारा स्वीकार किया कि भारत की सहायता से नेपाल में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति सन्तोषजनक है। श्री शास्त्री के बाद श्रीमती गांधी ने भी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की नीति को आगे बढ़ाया। अक्टूबर, 1971 में दोनों देशों के बीच कोसी तथा गण्डक परियोजनाओं के निर्माण के लिए समझौता हुआ। श्रीमती गांधी ने नेपाली नेतृत्व के मस्तिष्क में यह बात बँटाने की कोशिश की कि भारत नेपाल की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करता है तथा उसका सन्ना मित्र है। जनवरी, 1972 में राजा महेन्द्र की मृत्यु हो गई और उनके बाद राजा बीरेन्द्रशाह गद्दी पर बैठे।

भारत नेपाल के विकास कार्यक्रमों में रुचि लेता रहा। सन् 1973-74 के बजट में नेपाल की विकास सहायता के लिए 9 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई। इसके प्रतिरिक्त 10 करोड़ रु. के स्टैंड बाई क्रेडिट की भी व्यवस्था की गई। राजा बीरेन्द्र का रवैया भारतीय उदारता के वाक्यवाद की दृष्टियों से प्रसरने वाला था। सन् 1973 में उन्होंने नई भौगोलिक स्थिति की घोषणा करते हुए कहा कि नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है। सितम्बर, 1974 में राजा बीरेन्द्र ने सिक्किम को भारत में सह-राज्य का दर्जा दिए जाने का खुल्लमखुल्ला विरोध किया। काठमाण्डू स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत के विरुद्ध बुनेटिन निकाले गए। नेपाल सरकार की चुप्पी ने चीनी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार को बहावा दिया। नेपाल के भारतीय स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे। इन घटनाओं को भारत सरकार ने अत्यन्त गम्भीरता से लिया और विदेश मन्त्रालय ने नेपाल के साथ सम्बन्धों पर पुनर्निर्धार किए जाने की आवश्यकता अनुभव की। कहा जाता है कि नेपाल से राजद्रोह वापस बुलाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया। अब नेपाल सरकार की बुद्धि पर से भ्रम का पर्दा हटने लगा। नेपाल सरकार ने समझ लिया कि भारत के सहयोग और समर्थन के बिना गाड़ी चलना बठिन है। सब तरफ से घिरा हुआ (लैंड लाकड) देश होने के कारण अन्य देशों से सम्बन्धों के लिए नेपाल को भारत पर निर्भरता आवश्यक है। हिमालय की रणवाट के कारण नेपाल चाहते हुए भी भारत से सम्बन्ध नहीं तोड़ सकता। नवम्बर, 1974 के लगभग नेपाली 'मदरलैंड' ने कहा कि विश्व के 'लैंड लाकड' देशों को जो सुविधाएँ प्राप्त हैं वही नेपाल को

ति मिलनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मन्त्री चट्टाण ने पाली प्रधानमन्त्री श्री रिजाल को स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत नेपाल को हर प्रकार सहायता देने को तैयार है, किन्तु सच्चा एवं बन्दरगाह सुविधाओं को प्रधिकारित रूप में नहीं भाँगा जाना चाहिए। नेपाल को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह एक उपमहाद्वीप की रक्षा-व्यवस्था का एक अंग है।

भारत के बड़े रक्त को देखकर नेपाल के महाराजा ने प्रत्यक्ष और हृत्नीतिक क्षेत्रों के माध्यम से भारत से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत सरकार ने सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा, लेकिन नेपाल सरकार के प्रति कोई सुराही रक्त नहीं अपनाया और सन् 1975 में दोनों देशों के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण बने रहे। प्रगत, 1975 में नेपाल के विदेश मन्त्री ने नई दिल्ली की यात्रा की और राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि भारत नेपाल की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में अपना योग देगा और हमेशा की तरह नेपाल को व्यापार तथा पारगमन सम्बन्धी समस्याओं पर मित्रतापूर्ण ढंग से विचार करेगा। उन तर्कों के जल का सुदुपयोग करने में भारत-नेपाल सहयोग पर विशेष रूप से जल दिया गया जो दोनों देशों से होकर बहती है। 30 सितम्बर और 1 अक्टूबर 1975 को नेपाल-नरेश भारत आए। यह यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे दोनों देशों के नेताओं के बीच उच्चतम स्तर पर विचार-विमर्श का सुप्रसन्नता प्राप्त हुआ। जनवरी, 1976 में अपनी नेपाल-यात्रा के दौरान भारतीय विदेश मन्त्री श्री चट्टाण ने सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों के विषय में तथा विकास एवं तत्सम्बन्धी जल-संसाधनों पर विचार-विनिमय किया।

साथ, 1976 से नवम्बर, 1977 तक—सन् 1976 में दोनों देशों के सम्बन्धों को दिशा में काफी ठोस कार्य हुआ। राजनीतिक और सरकारी स्तर पर कई यात्राएँ हुईं जिससे दोनों सरकारों के बीच लगातार बातों का अन्तर्गत प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि नेपाल के जो राष्ट्रीय भारत के सुरक्षित/प्रतिद्वन्द्वित क्षेत्रों का दौरा करना चाहेंगे उन्हें दूसरे विदेशी राष्ट्रों के समझ ही माना जाएगा और इस प्रकार उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए पारपत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा। इस बात का निश्चय करने के लिए कि इन क्षेत्रों की यात्रा करने वाले वास्तविक नेपाली नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, परमिट जारी करने के सीवे और सुविधाजनक विधियाँ तय की गई हैं।

वर्ष 1976 में कोसम्बो योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौक़े के अन्तर्गत भारत नेपाल को द्विपक्षीय आधार पर पूँजीगत तथा तकनीकी सहयोग देता रहा है। सन् 1976-77 में नेपाल की विकास-योजनाओं के महापता अनुदान के रूप में बजट में 10 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है।

अप्रैल, 1977 में नेपाल नरेश भारत की गैर-सरकारी यात्रा पर आए। तथा इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमन्त्री तथा नई सरकार में उनके सहयोगियों से

विस्तृत विचार-विमर्श किया। मई, 1977 में श्री विद्यानन्द झा भारत में नेपाल के अगले राजदूत मनोनीत किए गए।

भारत और भूटान

भारत की उत्तरी सीमा पर भूटान सन् 1971 से पूर्व तक भारत का संरक्षित राज्य (Protectorate) था, किन्तु सन् 1971 में भारत ने इस मित्र-देश की सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय दिया। भारत के ही सहयोग से भूटान ने सन् 1971 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश किया। भूटान की विदेश-नीति, भूटान की सहमति से अभी तक भारत द्वारा ही संचालित होती है, यद्यपि दोनों देशों के बीच समानता के आधार पर सम्बन्ध हैं और उनमें कभी किसी भी अवसर पर कटुता नहीं आई है। अप्रैल, 1975 में जब सिक्किम भारत में विलय हुआ तब भी भूटान ने भारत के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जबकि सिक्किम के राज-परिवार से भूटान के राज-परिवार के निकट सम्बन्ध है। सिक्किम के चोग्याल भूटान की राजमाता के रिश्ते में भाई होते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ में हर प्रश्न पर भूटान भारत का समर्थन करता रहा है। मतदान के हर अवसर पर भारत और भूटान के मत एक ही पक्ष में पड़े हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत भूटान का बड़ा भाई है, किन्तु उसने कभी भूटान पर अपनी इच्छा लादने का प्रयास नहीं किया है। सन् 1949 में दोनों देशों के बीच एक मैत्री और शान्ति-सन्धि द्वारा यह निश्चय हुआ था कि भारत भूटान के आन्तरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और भूटान के विदेश सम्बन्धों तथा प्रसिद्धि का दायित्व भारत पर रहेगा।

भारत भूटान के योजनाबद्ध विकास में निरन्तर सहायता देता रहा है। भूटानी योजनाओं का लगभग 95 प्रतिशत धन भारत ही वहन करता रहा है। वर्ष 1976 में यह निश्चय किया गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना (1976-81) के लिए भारत सरकार भूटान को 70-29 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान देगी।

कोलम्बो में पांचवें गुट-निरपेक्ष शिखर-सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हुए भूटान के महामहिम नरेश ने 13 और 14 अगस्त, 1976 के दो दिन दिल्ली में व्यतीत किए। अपने प्रवास काल में उन्होंने भारतीय नेताओं में भेंट वार्ता की। कोलम्बो शिखर-सम्मेलन में भूटान-नरेश ने कहा कि भारत का पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सामान्य करने के भारत के प्रयास से एशिया में शान्ति और स्थिरता की दिशा में सहयोग मिलेगा। भूटान नरेश ने 'अपने खेप्ट मित्र और पड़ोसी भारत' द्वारा उनके देश को दी गई उदारतापूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की।

विगत की भांति ही दोनों देशों के बीच विभिन्न विकास-क्षेत्रों में सहयोग चालू रहा। यह कार्य भारतीय विशेषज्ञों और जानकारों की भूटान यात्रा और वहाँ किए गए सर्वेक्षणों के माध्यम से हुआ। भूटान-नरेश ने अप्रैल, 1977 में भारत की यात्रा की और नई सरकार के साथ बान्धन की। इस यात्रा से दोनों पक्षों की मित्रता और भाईचारे के अपने विशिष्ट सम्पर्क को पुनः पुष्ट करने का अवसर मिला।

भारत और बंगलादेश

बंगलादेश का उदय तो 6 दिसम्बर, 1971 को ही हो गया था, जब भारत ने उसे मान्यता प्रदान कर दी थी। व्यवहार में बंगलादेश विश्व के नक्शे पर तब उजागर हुआ जब 16 दिसम्बर, 1971 को ढाका में पाक सेना के ले. जनरल नियाजी ने आत्म-समर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। बंगलादेश के मुक्ति संग्राम और उदय में भारत ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभायी और बलिदान किया, उसमें स्वभावतः दोनों देशों के बीच मंत्री निरन्तर बढ़ती गई।

सन् 1971-1973 की अवधि—नवोदित बंगलादेश ने भी भारत के ही समान, शान्तिपूर्ण सहस्रित्व, गुट-निरपेक्षता और विश्व-मैत्री को अपनी विदेश-नीति की आधारशिला बनाया। भारत ने नवोदित राष्ट्र को प्रत्येक सम्भव राहयोग और समर्थन देने की नीति अपनायी। 17 जनवरी, 1972 को दोनों देशों के बीच पहला अनुदान समझौता हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि—(1) भारत बंगलादेश को 25 करोड़ रुपये का सामान और सेवाएँ प्रदान करेगा, तथा (2) बंगलादेश की विदेशी मुद्रा की माँग की पूर्ति के लिए भारत 50 लाख शेण्ड का ऋण भी जुटाएगा।

मार्च, 1972 में श्रीमती गाँधी की बंगलादेश-यात्रा के दौरान 19 तारीख को दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक मंत्री-सन्धि हुई। इस समय तक भारतीय सेनाएँ बंगलादेश की भूमि से वापस सौट चुकी थी। सन्धि के अनुसार यह निश्चय हुआ कि—(1) दोनों देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए एक दूसरे के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे; (2) उपनिवेशवाद और जातिवाद की निन्दा की गई तथा मुक्ति-आन्दोलनों का समर्थन किया गया; (3) आर्थिक, प्राविधिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के विकास का निश्चय किया गया, (4) सांस्कृतिक प्रादान-प्रदान का निर्णय किया गया धारा 8 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि पारस्परिक मित्रता का सम्मान करते हुए दोनों में से कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ ऐसा सैनिक समझौता नहीं करेगा जो दूसरे के विरुद्ध हो; (5) धारा 9 में कहा गया कि न तो एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण किया जाएगा और न किसी तीसरे देश को आक्रमण के लिए अपनी सीमा का उपयोग करने दिया जाएगा; (6) धारा 10 में व्यवस्था दी गई कि दोनों देश किसी तीसरे देश को ऐसी सहायता नहीं देंगे जो दोनों में से किसी देश के हितों के विरुद्ध हो और यदि दोनों में से किसी पर आक्रमण होगा या आक्रमण का खतरा उत्पन्न होगा तो दोनों देश खतरे के निराकरण के लिए विचार-विमर्श करेंगे।

उपयुक्त ऐतिहासिक सन्धि 25 वर्ष के लिए की गई और दोनों देशों की सहमति पर इसके नवीनीकरण का प्रावधान भी रखा गया। 25 मार्च, 1972 को दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक सौ करोड़ रु. के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसकी अवधि एक वर्ष रही गई। 9 अगस्त, 1972 को बंगलादेश ने संयुक्त राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। संधि में भारतीय और

सोवियत प्रतिनिधियों ने बंगलादेश का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन चीन ने सुरक्षा परिषद में वोटो का प्रयोग कर भारतीय प्रयास को असफल कर दिया। 30 दिसम्बर, 1972 को भारत और बंगलादेश के बीच एक सांस्कृतिक समझौता हुआ। इसके द्वारा दोनों के मध्य सस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्राविधिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था की गई। बंगलादेश में भारत-विरोधी तत्वों ने भारत-विरोधी वातावरण उत्पन्न करने के जो प्रयास किए उन्हें मुज्जिब सरकार ने सफल नहीं होने दिया।

भारत के सहयोग से एक वर्ष से भी कम समय में बंगलादेश का स्थायी संविधान तैयार कर लिया गया जिसके अन्तर्गत मार्च, 1973 के प्रथम आम चुनाव हुए और सत्तारूढ़ आवामी पार्टी ने भारी बहुमत प्राप्त किया। मुज्जिब ने प्रधानमन्त्री का पद सम्भाला। पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध-निर्धारित करने में भारत ने कभी बंगलादेश की उपेक्षा नहीं की। 18 अप्रैल, 1973 को दोनों देशों ने मिलकर एक त्रिभुवी कार्यक्रम तैयार किया जिसके आधार पर भारत ने पाकिस्तान के साथ समझौते वार्ता चलाई। जुलाई और अगस्त, 1973 में क्रमशः रावलपिण्डी और दिल्ली में उपमहाद्वीप की समस्याओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार्ताएँ हुईं उनमें उपर्युक्त त्रिभुवी कार्यक्रम का पूरा पालन किया गया। वार्ता के प्रत्येक स्तर पर भारतीय अधिकारियों ने बंगलादेश की सरकार से विचार-विमर्श किया। बंगलादेश में मानवीय समस्या के हल के लिए दिल्ली समझौते का पूरा स्वागत किया गया। यद्यपि दिल्ली-समझौते से बंगलादेश को पाकिस्तान की कूटनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं हो सकी, तथापि कटुता का वातावरण बहुत कम हो गया। भारत और बंगलादेश की दृढ़ता तथा कतिपय मुस्लिम-राज्यों के प्रयासों से अन्ततः पाकिस्तान ने 22 फरवरी, 1974 को बंगलादेश को मान्यता प्रदान कर दी।

वर्ष 1974—अप्रैल, 1974 में पाकिस्तान, भारत और बंगलादेश के नेताओं की त्रिपक्षीय वार्ता हुई और 9 अप्रैल को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार—(1) बंगलादेश 195 पाकिस्तानी युद्ध-अपरराधियों को लौटाने के लिए सहमत हो गया; (2) पाकिस्तान ने उनके अपराधों की निन्दा करते हुए खेद प्रकट किया; एवं (3) पाकिस्तान ने बंगलादेश के पाकिस्तानी नागरिकों को वापस ले लेने की बात भी स्वीकार कर ली। यह समझौता भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य स्थिति कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत और बंगलादेश के बीच आर्थिक और ऋण सम्बन्धी समझौते भी सम्पन्न हुए। यह निश्चय किया गया कि भारत बंगलादेश को 41 करोड़ रुपये का ऋण देगा और वहाँ चार उद्योग स्थापित करने में सहायता देगा। समझौते द्वारा एक संयुक्त जूट प्रायोग की भी स्थापना की गई तथा तस्करी रोकने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित की गई।

मई, 1974 में शेख मुज्जिब ने भारत की यात्रा की। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार के साथ ही फरवका बाँध और दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श हुआ। दिसम्बर, 1974 में भारतीय

विदेश मन्त्री चङ्गाण ने वगलादेश की यात्रा के समय सहयोग-परियोजनाओं की प्रगति के बारे में बात की।

वर्ष 1975—25 जनवरी, 1975 को शेख मुजीब ने वगलादेश का प्रधान मन्त्री पद छोड़कर राष्ट्रपति-पद सम्भाल लिया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, “देश में इस दूसरी ज्वानि के माध्यम से गणतन्त्र के सारे प्रजासैनिक अधिकार उन्हींने अपने हाथ में ले लिए हैं।” 19 अप्रैल, 1975 को फरक्का बांध के सम्बन्ध में भारत-वगलादेश समझौता सम्पन्न हुआ। गंगाजल के बँटवारे और फरक्का बांध की बात रखने के लिए 12 वर्ष में चले आ रहे विवाद को हल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। समझौते में फरक्का बांध से गंगा का पानी छोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन इसमें वगलादेश के हिੱसों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि फरक्का बांध की सहायक नहर को चालू करना अनिवार्य।

नई दिल्ली में 29 मार्च से 2 अप्रैल तक विदेश मन्त्री स्तर पर हुई बातों में समुद्री-सीमा परिसीमन के प्रश्न पर मतभेदों को दूर कर एक ऐसी स्थिति तक लाया गया जहाँ दोनों पक्ष मानवस्तु हुए कि अब जल्दी ही एक परस्पर स्वीकार्य समझौता हो जाएगा। दुर्भाग्यवश वगलादेश में 15 अप्रैल के बाद हुई घटनाओं के कारण इस दिशा में आगे चाला नहीं हो सकी। वगलादेश मुजीबुर्रहमान, उनके परिवार के सदस्यों तथा वहाँ के कई अन्य प्रमुख नेताओं की नृशंस हत्या से भारत को गहरा आघात पहुँचा। शेख मुजीबुर्रहमान एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिन्होंने वगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दोलन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। वगलादेश में जिस तरह घटनाएँ घटीं उनसे वहाँ रहने वाले मारनीय राष्ट्रवादियों की सुरक्षा के विषय में भारत में चिन्ता होना स्वाभाविक था। वहाँ के अनियन्त्रित भारत-विरोधी प्रचार से भी, जो कभी-कभी वगलादेश के सरकारी प्रचार-माध्यमों में भी दृष्टिगोचर हुआ भारत चिन्तित हुआ, फिर भी वह वगलादेश की घटनाओं को उस देश का आन्तरिक मामला ही मानता रहा। हमारे हाई कमिश्नर के घर में हूबहोला राज देने और 26 नवम्बर, 1975 को तम्रय गार्ड कमिश्नर पर सशस्त्र आक्रमण करने जैसी गम्भीर उत्तेजनात्मक कारवाहियों के बावजूद, जिसमें रि के गम्भीर रूप से घायल होने से बाल बाल बच गए भारत ज्वानि और मध्यम का रूप धारण रहा। दिसम्बर में वगलादेश के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डल की नई दिल्ली यात्रा तथा दोनों देशों के सीमा सुरक्षा दलों के सम्पर्क की बैठक के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ और सीमा पर ज्वानि स्थिति रखने के उपायों पर एक समझौता भी हुआ।

वर्ष 1976—77—सन् 1976 में मई माह तक की अवधि भी भारत और वगलादेश के बीच चिन्ता और देखरेख का समय रही। भारत-वगलादेश सीमा पर कुछ छुटपुट सशस्त्र घटनाएँ घटीं। भारत इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा कि सीमा पर शांति रहे, लेकिन वगलादेश के समाचारपत्रों में अकारण भारत पर आरोप लगाया जाता रहा। मार्च, 1976 में वगलादेश ने फरक्का समझौते के सम्बन्ध में असम्बन्धित मामलों को उठाने की कोशिश की और भारत से माँग की

कि गंगा के पानी का बँटवारा केवल ग्रीष्म ऋतु में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर होना चाहिए। मुजीब की हत्या के बाद बंगला सरकार का रवैया 'वस्तुतः' सैद्धांतिक रहा और भारत सरकार यह सोचकर अपनी मित्रता का निर्वाह करती रही कि बंगलादेश की खोडकर-सरकार द्वारा फरक्का को विवाद का विषय बनाए रखने की कोशिश बंगलादेश की आन्तरिक स्थिति का नतीजा हो सकता है। फिर भी, बड़े पैमाने पर पूंजी-निवेश और कलकत्ता-बन्दरगाह की दृष्टि से भारत को फरक्का के विषय में कठोर रवैया अपनाना पड़ा और तब अप्रैल में बंगलादेश सरकार ने अपना नकारात्मक रवैया त्याग कर फरक्का के द्वारे में तकनीकी स्तर पर बातचीत करना स्वीकार कर लिया। एक ओर तो दोनों सरकारें समरथा पर बिचार करती रही और दूसरी ओर बंगलादेश के 96 वर्षीय वृद्ध नेता मौनाना भाशानी ने एक जुनून के साथ भारत की सीमा पार करने का नाटक रचा। भारत सरकार ने कठोर हथ्थ अपनाते हुए सीमा की सुरक्षा का पूरा प्रयत्न कर लिया तथा बंगलादेश सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि मौलाना भाशानी को अपनी अनुचित कार्यवाही से रोकना उसका कर्तव्य है; और तब भाशानी का वह जुनूस जो 16 मई को भारत की सीमा की ओर रवाना हुआ था, सीमा से कुछ ही किलोमीटर पर शिवगंज नामक स्थान पर समाप्त हो गया। मौलाना भाशानी और उनके समर्थकों ने फरक्का बाँध को तोड़ने तक की धमकी दी थी और उधर भारतीय सीमा सुरक्षा जवान इन बातों के लिए तैयार थे कि हर हालत में अपने देश की सीमाओं की रक्षा की जाएगी।

कृषि और सिंचाई मन्त्री श्री जगजीवनराम के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल ने फरक्का के मामले पर द्विपक्षीय बातों के लिए 6 से 8 दिसम्बर, 1976 तक बंगलादेश की यात्रा की। वार्ता में एक दूसरे की स्थिति को समझने की दिशा में कुछ प्रगति हुई थी और बातचीत को शीघ्र ही घांसे बढ़ाने का निश्चय किया गया था। जनवरी, 1977 में ढाका में वार्ता हुई और फिर नई दिल्ली में लेनिन दुर्गाय से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका।

नई सरकार के पठन के तुरन्त बाद गंगा के पानी के द्वारे में सीधी बातचीत फिर शुरू हुई। नई सरकार में रक्षा मन्त्री श्री जगजीवनराम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डल ने अप्रैल, 1977 में ढाका में विस्तार के साथ बातचीत के परिणाम-स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में पानी के बँटवारे के विषय में सिद्धान्त रूप में एक सामान्य समझौता हो गया। इसके बाद 7 से 11 मई तक अधिकारी-स्तर पर वार्ता हुई और एक सम्भव समाधान की दिशा में विवरण तैयार करने में काफी प्रगति हुई। बंगलादेश और भारत के बीच ऐसे कोई विवाद नहीं है जिनसे परस्पर तनाव की स्थिति पैदा हो, तथापि भारत के लिए यह अवश्य चिन्ताजनक बात है कि बंगलादेश में बहुत बड़ी सख्या में शरणार्थी भारत में आने लगे हैं। दिसम्बर, 1977 में समाचारपत्रों में दत्त माधव के जो समाचार प्रकाशित हुए, सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती।

भारत और चीन के सम्बन्ध

भारत और चीन दो घनिष्ठ मित्रों के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन सन् 1962 में चीन ने भारतीय सीमाओं पर आक्रामक आक्रमण कर इस मित्रता को पूल में मिला दिया। आज चीन भारत की कुछ भूमि पर अधिकार जमाये हुए है और भारत की ओर से सम्बन्ध-सुधार के प्रयत्नों के बावजूद भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रूप अपनाए हुए है।

नेहरू-युग में भारत-चीन सम्बन्ध (1947-मई, 1965)

चीन के प्रति मंत्री और तुष्टिकरण की नीति — भारत ने साम्यवादी चीन के प्रति प्रारम्भ से ही मंत्री और तुष्टिकरण की नीति अपनायी। उसने चीन को मान्यता प्रदान की और संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसके प्रवेश का जोरदार समर्थन किया। अक्टूबर, 1950 में ही तिब्बत में प्रवेश कर चीन ने अपने वास्तविक इरादों का सबूत दे दिया था लेकिन भारत ने चीनी इरादों को समझने में भूल की। जब भारत सरकार ने तिब्बत में उसके प्रवेश की ओर चीनी सरकार का ध्यान आकषिप्त किया तो 30 अक्टूबर, 1950 को चीन की ओर से भारत को कठोर शब्दों में उत्तर दिया गया— 'पश्चिम की साम्राज्यवादी नीति से प्रभावित भारत चीन के पक्षदेशीय मामलों में हस्तक्षेप करने का साहम न करे।' चीन द्वारा ऐसी कटु शब्दावली का प्रयोग करने के उपरान्त भी भारत सरकार चीन के प्रति सहानुभूति और तुष्टिकरण का दृष्टिकोण अपनाती रही। 1 फरवरी, 1951 को भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें चीन को कोरिया में आक्रमणकारी घोषित किया गया था। सितम्बर, 1950 में जापानी शान्ति-सन्धि के समय सेन-फ्रांसिसको सम्मेलन में भारत मुन्यत इसीलिए शामिल नहीं हुआ कि उसने चीन को आमन्त्रित नहीं किया गया था।

भारत ने हर अवसर पर चीन के प्रति अपनी सदाशयता प्रदर्शित की, लेकिन चीन दोहरी चाल खेलता रहा। एक ओर तो पीछी बातों में मंत्री का स्वाग भरता रहा और दूसरी ओर भारतीय सीमाओं पर गडबडी फैलाता रहा तथा तिब्बत को अपने शिकरे में जकड़ता रहा। भारत की तुष्टिकरण की नीति की हद तक हो गई जब 29 अप्रैल, 1954 को चीन के साथ एक व्यापारिक समझौता कर भारत ने तिब्बत में प्राप्त अपने बहिर्देशीय अधिकार (Extra territorial Rights) चीन को तौं दिए और बदले में स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तिब्बत में चीन की प्रभुता को स्वीकार करना भारत-सरकार की भारी भूल थी। समझौते की प्रस्तावना में दोनों देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट किया। इन्हीं सिद्धान्तों का सन् 1953 में बौडुग सम्मेलन में विस्तार किया गया। मई 1954 में चीनी प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई भारत आए और अक्टूबर, 1954 में प नेहरू ने चीन की यात्रा की। चीन विभिन्न रूप से भारत के साथ सीमा-विवाद उठाता रहा और तब 20 अक्टूबर, 1962 को उसने भारत पर विजाल पैमाने पर आक्रामक आक्रमण कर भारत की मित्रता का बदला चुकाया। प नेहरू की आशाओं और नीतियों पर यह एक घातक चोट थी।

भारत-चीन सीमा-विवाद—भारत और चीन के बीच व्यावहारिक रूप से मान्य सीमा को मेकमहोन रेखा (McMahon Line) के नाम से जाना जाता है। अप्रैल, 1914 में भारत और तिब्बत तथा तिब्बत और चीन के बीच सीमा-निर्धारण के लिए शिमला में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत-सचिव आर्थर हेनरी मेकमहोन ने भाग लिया। शिमला-सन्धि में यह तय हुआ कि— (1) तिब्बत पर चीन की Suzerainty रहेगी, लेकिन बाह्य तिब्बत (Outer Tibet) को अपने कार्य में पूरी स्वतन्त्रता होगी; (2) चीन तिब्बत के प्रान्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा; एवं (3) चीन तिब्बत को अपने राज्य का कभी प्रान्त घोषित नहीं करेगा। बाह्य तिब्बत और भारत के बीच की ऊँची पर्वत-श्रेणियों को सीमा मानकर एक नक्शे को साल गेंसिल से चिह्नित कर दिया गया, जिनमें तीनों प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। इसी सीमा को मेकमहोन रेखा (McMahon Line) की संज्ञा दी गई। जब कभी सीमा-विवाद उठा तो चीन ने इसी रेखा का समर्थन किया। सन् 1959 से पूर्व उसने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं उठाई। जहाँ तक लद्दाख की सीमा का प्रश्न है, जिस सीमा तक भारत और तिब्बत का शताब्दियों से अधिकार रहा है और जिसे भारत ने सदैव अपने नक्शे में दिखाया है, वही परम्परागत सीमा-रेखा मानी जाती रही है। कश्मीर की उत्तरी सीमा को स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने सन् 1899 में चीन को स्पष्ट लिखा था कि इसकी पूर्वी सीमा 80 अंशों पूर्व देशान्तर है। इस लेख-पत्र से सुनिश्चित हो जाता है कि अबतक चीन भारतीय सीमा के अन्तर्गत है और यह सीमा ऐतिहासिक तथा परम्परागत है।

भारत-चीन सीमा-विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत को स्वाधीनता प्राप्त करने के साथ-साथ उत्तराधिकार के रूप में तिब्बत में निम्नलिखित बहिर्देशीय (Extra-territorial) अधिकार प्राप्त हुए थे—(1) तिब्बत और ब्रिटिश-भारतीय व्यापारियों के विवादों में बचाव-पक्ष के देश की विधि लागू होती थी और उसी देश का न्यायाधीश मामले पर सुनवाई में अध्यक्षता करता था; (2) यदि तिब्बत में ब्रिटिश-राज्य के लोगों के बीच विवाद होने से तो उन विवादों का ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा निर्युक्त होना था; (3) ब्रिटिश एजेंटों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ सेना रखने का अधिकार था; (4) गेट टुंग के घान टुंग में व्याण्टसी तरु टेलीग्राफ और टेलीग्राफ सस्थाओं पर भी ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकार था; एवं (5) तिब्बत में भारत-सरकार के 11 विश्राम गृह थे। साम्प्रदायी चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता और भारत के बहिर्देशीय अधिकारों का कोई सम्मान न कर 7 अक्टूबर, 1950 को तिब्बत में अपने सैनिक भेज दिए। भारत द्वारा इस ओर ध्यान आकषिप्त किए जाने पर 30 फ़रवरी को चीन ने इसकी कठोर शब्दों में उपेक्षा की। चीन ने जो नए नक्शे प्रकाशित किए उसमें भारत की लगभग 50 हजार वर्गमील भूमा चीनी प्रदेश के अन्तर्गत दिखायी और थी नेहरू द्वारा यह प्रश्न उठाने पर चीनी प्रधानमंत्री ने कहा

कि ये नवसे राष्टवादी सरकार के पुराने नक्शों की नकल हैं तथा समय मिलते ही इन्हें टीक कर दिया जाएगा ।

चीन भारत के साथ सुनियोजित ढंग से अपने विवादों को उग्र बनाता रहा और भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करता रहा। चीनियों ने आक्साईचिन के पठार में सड़क बना ली और भारत के विरोध के बावजूद लद्दाख में अपनी कई सैनिक चौकियाँ स्थापित कर ली। जुलाई, 1958 में उन्होंने लद्दाख के ररगाम किले पर भी अपना अधिकार कर लिया। तिब्बत में चीनियों के दमन से आतंकित होकर 31 मार्च, 1957 को दलाईलामा ने भारत में राजनीतिक शरण ली जिसका चीन ने अनावश्यक रूप से विरोध किया। अपने एक पत्र में चाऊ-एन-लाई ने भारत को लिखा—“मेकमहोन रेखा चीन के तिब्बत प्रदेश के हिस्से अंग्रेजों की आक्रमणकारी नीति का परिणाम थी। कानूनी तौर से इसे बंध नहीं माना जा सकता।” नवम्बर, 1959 के पत्र में चीन ने आरोप लगाया कि भारत तिब्बत में सशस्त्र विद्रोहियों को सरक्षण दे रहा है। इसी पत्र द्वारा चीनी प्रधानमंत्री ने लद्दाख में भारत के दावों को दुहरा दिया। वहीं नहीं भारत के लगभग 90 000 किलोमीटर प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए चीन सरकार ने यह आरोप लगाया कि भारतीय सेनाएं इस प्रदेश में घुसकर चीन की प्रादेशिक अखण्डता को चुनौती दे रही हैं।

दोनों देशों का सीमा-विवाद उत्पन्न होता गया। अप्रैल, 1960 में दिल्ली में भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों ने संयुक्त विज्ञप्ति में स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद विद्यमान हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब जुलाई, 1962 में गलवान घाटी की भारतीय पुलिस चौकी को चीनियों ने घेरे में ले लिया। सीमान्त पर चीनी सैनिक कार्यवाही बढ़ाने लगे और भारतीय सैनिक चौकियों को घेरा जाने लगा।

चीनी आक्रमण, 1962—20 अक्टूबर, 1962 को प्रातःकाल भारत की उत्तरी सीमा के दोनों भागों पर चीन ने भीषण आक्रमण कर दिया। भारतीय सेनाएँ इस आक्रामक आक्रमण से सम्मिलित तब तक चीन ने वाकी भारतीय भूमि और सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने यह प्रचार किया कि चीन ने भारत पर कोई सैनिक आक्रमण नहीं किया है, बल्कि एक सामान्य सीमा-महर्ष को भारत ने निल का ताड़ बना दिया है। भारत के अनुरोध पर ब्रिटेन और अमेरिका ने इस सफटकाल में तेजी से सैन्य सामग्री भेजी, किन्तु भारत द्वारा सम्भल कर प्रत्यागमण करने से पूर्ण ही चीन ने अकस्मात् ही 21 नवम्बर, 1962 को एक-पक्षीय 'फुल स्केल' ऑपरेशन शुरू किया, 'इसके साथ ही चीन ने एक द्वि-पक्षीय योजना भी घोषित की—(1) चीनी सेनाएँ 7 नवम्बर, 1959 की 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Actual Line of Control) से 20 किलोमीटर अपनी ओर हट जाएंगी। सेना का हटना एक दिग्म्बर से प्रारम्भ होगा। (2) चीनी सेनाओं के हटने से जो क्षेत्र खाली होगा उसमें चीन सरकार अपनी असैनिक चौकियाँ कायम करेगी। इन चौकियों की स्थिति का पता भारत-सरकार को उसके दूतावास द्वारा

दे दिया जाएगा। चीन की ओर से भारत सरकार को इन शर्तों को मान लेने के लिए कहा गया कि वह अपनी सेनाओं को भी 7 नवम्बर, 1959 की रेखा से 20 किलोमीटर अपने ही क्षेत्र में ओर हटा ले।

विपरीत परिस्थितियों में भारत ने बिना स्वीकारोक्ति के चीन की एक-पक्षीय युद्ध-विराम घोषणा को मान लिया, किन्तु द्वि-मूत्रीय योजना को अस्वीकृत करते हुए घोषित किया कि जब तक चीनी सेनाएँ 8 सितम्बर, 1962 की स्थिति तक नहीं लौट जाती तब तक दोनों देशों के बीच कोई वार्ता सम्भव नहीं है। 8 सितम्बर, 1962 की यह रेखा वह थी जिसके उत्तर में चीनी सेनाएँ आक्रमण से पहले स्थित थी जबकि चीन द्वारा बताया गई 7 नवम्बर, 1959 की वास्तविक नियन्त्रण-रेखा वह थी जहाँ तक आक्रमण के बाद भी चीनी फौजे नहीं पहुँच पाई थी। जिस स्थान से 20 किलोमीटर वापसी की बात थी उसका तात्पर्य यह था कि चीनी सेनाएँ पश्चिमी क्षेत्र में जहाँ की तहाँ बनी रहे, पूर्वी क्षेत्र में कुछ हटें।

चीन के आक्रमण ने भारत की गुट-निरपेक्ष नीति के विरुद्ध आलोचनाओं को प्रोत्साहित किया, किन्तु श्री नेहरू ने पुनः इस नीति में गहरी आस्था प्रकट की। अवश्य ही अब भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद की ओर झुकाव शुरू हुआ। प. नेहरू ने घोषणा की कि—'अतीत में हम निर्धनता और निरक्षरता की मानवीय समस्याओं में इतने उलझे रहे कि हमने प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के प्रति तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम ध्यान दिया। यह स्पष्ट है कि अब हम इस ओर अधिक ध्यान देंगे, हम अपनी सेनाओं को सुदृढ़ बनाएँगे तथा जहाँ तक सम्भव होगा सेना के लिए आवश्यक अस्त्र शस्त्र तथा सामग्री अपने देश में ही तैयार करेंगे।'

कोलम्बो प्रस्ताव और चीन का दुराग्रह—दिसम्बर, 1962 में श्रीलंका, बर्मा, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, मल्ला और घाना ने भारत-चीन वार्ता के लिए कोलम्बो-सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें यह निश्चय किया गया कि सम्मेलन के प्रतिनिधि भारत और चीन जाकर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा दोनों देशों के संपर्क को समाप्त करने का प्रयत्न करें। प्रस्तावों को तब तक गुप्त रखने का निर्णय किया गया जब तक दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया ज्ञात न हो जाए। श्रीमती भगवन्तराय के स्वयं कोलम्बो प्रस्ताव लेकर पेरिस और नई दिल्ली गई और तब 19 जनवरी, 1963 को ये प्रस्ताव प्रकाशित कर दिए गए जिसके मूल तत्त्व ये थे—

(1) युद्ध-विराम का समय भारत-चीन विवाद के शान्तिपूर्ण हल के लिए उपयुक्त है, (2) चीन पश्चिमी क्षेत्र में अपनी सैनिक चौकियाँ 20 किलोमीटर पीछे हटा ले; (3) भारत अपनी वर्तमान सैनिक स्थिति कायम रखे, (4) विवाद का अन्तिम हल होने तक चीन द्वारा खाती क्रिया गया क्षेत्र अग्नि-क्षेत्र रहे जिसकी निगरानी दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त गैर-सैनिक चौकियाँ करें, (5) पूर्वी नेफा क्षेत्र में दोनों सरकारों द्वारा मान्य वास्तविक नियन्त्रण रेखा युद्ध-विराम रेखा का रूप ले, क्षेत्र क्षेत्रों के बारे में दोनों देश भावी वार्ताओं में निर्णय करें, (6) मध्यवर्ती क्षेत्र का समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाए।

कोलम्बो प्रस्तावों का वास्तविक उद्देश्य भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति समाप्त कर वार्तालाप का द्वार खोलना था। चीन ने यह आश्वासन दिया कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगा। भारत को भी कोई विशेष आपत्ति नहीं थी, केवल कुछ स्पष्टीकरण माँगा गया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वी छेदन में भारतीय सेना भेकमहोन रेखा तक (केवल उन स्थानों को छोड़कर जिनके बारे में मनभेद है) जा सकेगी और चीनी सेना भी अपने पूर्व-स्थानों तक जा सकेगी, लेकिन विवादग्रस्त स्थलों से उभे भी दूर रहना होगा। स्पष्टीकरण के बाद भारत ने प्रस्तावों पर विधिवत् अपनी सहमति दे दी। तब चीन ने कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी जिनसे प्रस्ताव व्यवहारतः महत्वहीन हो गया और चीन की अपरोक्ष स्वीकृति भी स्पष्ट हो गई। चीन ने तटस्थ देशों के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाएँ। इससे पुनः इस बात की पुष्टि होगई कि चीन भारत के साथ अपने विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना नहीं चाहता।

नामिर प्रस्ताव, 1963—भारत-चीन विवाद के गतिरोध को दूर करने के लिए 3 अक्टूबर, 1963 को मिश्र के राष्ट्रपति नामिर ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें कोलम्बो प्रस्तावों की शर्तों को दोहराते हुए यह सुझाव दिया गया कि विवाद के प्रश्न के लिए एक दूसरा कोलम्बो सम्मेलन आयोजित हो, किन्तु इस प्रस्ताव का भी कोई परिणाम नहीं निकला।

बर्मा, श्रीलंका आदि राष्ट्र दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए प्रयत्न करते रहे। मई, 1964 में श्री नेहरू की मृत्यु पर श्री चाऊ-एन-लाई ने अपना शोक सन्देश भेजा जिसमें यह भी कहा गया कि भारत और चीन के विवाद प्रस्थायी हैं जिनका समाधान शान्तिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। पर वास्तव में उनके इन शब्दों में कोई ईमानदारी न थी।

शास्त्री-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (मई, 1964—जनवरी, 1966)

श्री नेहरू के बाद 10 जनवरी, 1966 तक श्री लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस काल में भी भारत और चीन के सम्बन्धों में कोई सुधार न आ सका। सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में चीन ने पुनः अपना शत्रुतापूर्ण रवैया प्रदर्शित किया। भारत और चीन के सीमा-विवाद ने पाकिस्तान और चीन की मित्रता में वृद्धि की। भारत-पाक संघर्ष के समय चीन ने पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया और भारत को आक्रामक घोषित किया। घमकी द्वारा भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में विमुख करने का खेल भी खेला गया। 16 सितम्बर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि—“तीन दिन के भीतर भारत मित्रिम-चीन सीमा पर गैर-कानूनी ढंग में स्थापित 56 सैनिक प्रतिष्ठानों को हटा ले अन्यथा इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।” पत्र में यह माँग की गई कि भारत सीमा पर अपने “सभी प्रतिवर्ण तुरन्त बन्द कर दे, अग्रदूत सीमा-निवासियों तथा पकड़े गए नवेलियों को लौटा दे अन्यथा गम्भीर परिणामों के लिए भारत सरकार पूरी तरह उत्तरदायी रहेगी।”

चीन के अल्टीमेटम से ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध व्यापक रूप ले लेगा और चीन ने यदि भारत पर आक्रमण कर दिया तो सम्भवतः भारत-पाक युद्ध विश्व-युद्ध का रूप धारण कर लेगा, अतः महाशक्तियों ने अविलम्ब चीन को चेतावनी दी कि वह आग के साथ बिलबाड न करे। उधर चीनी अल्टीमेटम के जवाब में 17 दिसम्बर को श्री शास्त्री ने लोकसभा में कहा कि सिविक-तिब्बत सीमा पर भारत के अतिक्रमण की बात गलत है और भारतीय प्रदेश पर चीन का दावा हमें स्वीकार नहीं है। चीन की सैनिक शक्ति भारत को अपनी प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा से विचलित नहीं कर सकती। श्री शास्त्री ने चीन के आरोप के प्रत्युत्तर में कहा कि यदि चीन-सरकार समझती है कि भारत ने उसके प्रदेश में सैनिक प्रतिष्ठान बना लिए हैं तो वह उन्हें तोड़ सकती है, भारत कोई विरोध नहीं करेगा। वास्तव में चीन का आरोप निराधार था, भारत के चीनी प्रदेश में कोई सैनिक प्रतिष्ठान नहीं थे।

चीन ने सीमा पर सैनिक गतिविधियाँ आरम्भ कर दी। 19 सितम्बर को अल्टीमेटम की अवधि फिर तीन दिन के लिए बढ़ा दी, किन्तु बड़े पैमाने पर कोई सैनिक कार्यवाही करने का साहस नहीं किया। 23 सितम्बर को भारत-पाक युद्ध विराम हो जाने पर पैकिंग रेडियो ने यह नाटकीय घोषणा की कि “भारतीय सैनिक प्रतिष्ठानों को तोड़कर अपनी सीमा में वापस लौट गए हैं।” -

इन्दिरा-काल में भारत-चीन सम्बन्ध (जनवरी, 1966-मई, 1976)

श्री शास्त्री के बाद जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद सम्भाला। उन्होंने भी चीन के साथ सीमा-विवाद मुलभाने के कूटनीतिक प्रयास किए। श्रीमती गाँधी का यह कहना ठीक ही था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। यदि चीन भारत के शान्ति प्रयासों का अनुकूल उत्तर नहीं देता तो यह उसका दुराग्रह है जिस पर एक दिन उसे अवश्य पुनर्विचार करना पड़ेगा। सन् 1962 और 1975 के भारत में आकाश पाताल का अन्तर है और चीन भारत को सैनिक शक्ति द्वारा दवाने की बात अब सोच भी नहीं सकता।

चीन द्वारा पुनः छेड़-छाड़—भारत-पाक युद्ध में विजय से भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और चीन कुछ समय तक सीमा पर विशेष गड़बड़ी करने से रुका रहा। सितम्बर व अक्टूबर, 1967 में चीन ने नाथू-ला के भारतीय प्रदेश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भारी हानि उठाकर उसे पीछे हटना पड़ा। 2 अक्टूबर, 1967 को चीनियों ने चोला की भारतीय चौकी पर अचानक हमला किया, किन्तु फिर गहरी क्षति उठाकर अपने नापाक इरादों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। अप्रैल, 1968 में नाथू-ला में चीन की सैनिक गतिविधियों से स्थिति पुनः तनावपूर्ण हो गई, लेकिन कोई विशेष घटना नहीं घटी।

चीन का विंग-पोंग राजनय और भारत—एशिया और अफ्रीका के देशों ने बढ़ती हुई बदनामी, रूस और भारत के बढ़ते हुए सहयोग, एक सैनिक शक्ति के रूप

मे भारत के उदय आदि विभिन्न कारणों से सन् 1970 से ही चीन ने सीमान्त की भारतीय चौकियों पर आक्रमणवात्मक कार्यवाहियाँ लगभग बंद कर दी। भारत-विरोधी प्रचार की भाषा में भी बहुत धीरे आरों की गम्भीरता क्रमशः कम होने लगी। सन् 1971 के प्रारम्भ में ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार सम्भव है। अप्रैल 1971 में कैंटन के व्यापारिक मेले में भाग लेने के लिए चीन सरकार ने हांगकांग स्थित भारतीय पाणिप्य आयुक्त को निमन्त्रित किया। इसी माह अमेरिका की एक विप-वीग टीम को चीन में भेज खेनने के लिए आमन्त्रित किया गया। चीन-अमेरिका सम्बन्ध मधुर होने लगे और राजनीतिक क्षेत्रों में यह आशा जगी कि चीन की इन नई प्रवृत्तियों का एक परिणाम यह भी निकलेगा कि भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार होगा, अतः भारत को भी इस दिशा में अधिक सक्रिय हो जाना चाहिए। भारत के प्रति चीन का रुख कुछ नरम भी दिखाई दिया क्योंकि भारत के आमन्त्रण पर चीनी राजदूत राष्ट्रीय उत्सवों तथा राजनयिक अवसरों में उपस्थित होने लगे। विदेशों की राजधानियों में दोनों देशों के राजदूतों का सम्पर्क बढ़ने लगा। फिर भी चीन की ओर से सम्बन्ध-सुधार के कोई ठोस प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं हुए। 4 अगस्त, 1971 को राज्यसभा में भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह ने कहा कि—“भारत चीन के साथ सम्बन्धों में सुधार का स्वागत करता है लेकिन जब तक चीन की ओर से उचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते।” 13 नवम्बर, 1971 को पैंकिंग में अफ़ेशियाई टेबिल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें भाग लेने के लिए भारत को भी निमन्त्रण दिया गया। जब भारतीय टीम पैंकिंग जाने के लिए पालम हवाई अड्डे पर पहुँची तो विदाई देने के लिए चीनी दूनवाम के कुछ प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। नवम्बर, 1971 में संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन के प्रवेश की बात उठी और भारत ने चीन की सदस्यता का पूर्ण समर्थन किया। दोनों देशों के बीच राजदूतों को नियुक्त करने की बात भी उठी और चीनी प्रधानमन्त्री ने सुभाव दिया कि चूँकि भारत ने अपने राजदूत को पहले वापस बुलाया था, अतः उनकी पुनः नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत को ही पहल करनी चाहिए। इसी बीच दिसम्बर, 1971 का भारत-पाक युद्ध छिड़ गया जिससे दोनों देशों के सम्बन्धों में पुनः तनाव उत्पन्न हो गया।

बंगलादेश की समस्या और भारत-पाक युद्ध के प्रति चीनी दृष्टिकोण—सन् 1971 का वर्ष भारत के लिए समस्याओं का वर्ष रहा। बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन में भारत का सहयोग चीन को प्रसन्न नहीं लगा। चीन ने पाकिस्तान की तानाशाही का पूर्ण समर्थन किया और बंगलादेश के मुक्ति आन्दोलन में भारत के सहयोग को पाकिस्तान के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप बताया। जुलाई, 1971 में श्रीमती गाँधी ने चीनी प्रधानमन्त्री को एक पत्र लिख कर बंगलादेश की घटनाओं से अवगत कराया, लेकिन चीन ने इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश के बाद चीनी प्रतिनिधि ने अपने पहले ही भाषण में आरोप लगाया कि

भारत पाकिस्तान के मामले में ठीक उसी तरह हस्तक्षेप कर रहा है जिस तरह उसने तिब्बत में किया था। अगस्त, 1971 की भारत-सोवियत संधि ने चीन को और भड़का दिया। दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद की बहसों में चीनी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान का साथ देने में कोई बसर नहीं रखी और भारत को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। यह भी कहा गया कि भारत ने यह आक्रमण सोवियत संधि के सकेत पर किया है। चीन ने भारत को पुनः चेतावनियाँ दी, किन्तु ये चेतावनियाँ खोज़ली थी जिनका मुख्य उद्देश्य यह था कि पाकिस्तान के साथ एकता प्रदर्शित कर उसके मनोबल को ऊँचा रखा जाए और भारत को परेशानी में डाला जाए।

2 जनवरी, 1972 को श्रीमती गाँधी ने चीन के रवैये के बारे में भारतीय प्रतिक्रिया स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन किए जाने के बावजूद भारत-चीन सम्बन्ध सुधर सकते हैं। चीन ने भारत-पाक युद्ध पर एक नयी-तुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है—उसने पाकिस्तान का समर्थन न तो हमारी आशा से अधिक किया है और न उससे कम।

दोनों देशों की दूरियाँ यथावत कायम (1973-1975)—भारत-पाक युद्ध की घटनाओं के बाद भी समय-समय पर भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार के आसार प्रकट हुए, किन्तु कोई सुपरिणाम नहीं निकला और दोनों देशों की दूरियाँ आज भी कायम हैं। मार्च, 1973 में भारत ने नाथु-ला, जीतप-ला और चौदह क्षेत्रों में चीन-विरोधी प्रचार बन्द कर दिया। सन् 1973 में ही डॉ. द्वारकानाथ कोटनिस की स्मृति में (जिनकी 1938-43 में चीन में डॉक्टरों के सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी) कोटनिस कमीशन की स्थापना हुई। जून, 1974 में यह प्रतिनिधि-मण्डल डेनियल लतीफी के नेतृत्व में पैकिंग गया जहाँ इसका भव्य स्वागत किया गया। इस प्रतिनिधि-मण्डल ने लौटकर चीन की आर्थिक उन्नति का आश्चर्यजनक निवरण दिया। वयं का अन्त होते-होते अफगानिस्तान की मध्यस्थता में चीन और भारत के सम्बन्धों में सुधार लाने के कुछ सकेत प्राप्त हुए। अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष सरदार दाऊद खाँ के विशेष प्रतिनिधि श्री बडैय ने इस बारे में भारत तथा चीन की यात्रा की और चीनी नेताओं की प्रतिक्रिया से भारतीय नेताओं को अवगत कराने के लिए वे दिसम्बर, 1974 में भारत आए।

वयं 1975 में चीन के प्रसार-साधन भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार करते रहे। चीन सरकार ने 29 अप्रैल, 1975 को एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें कहा गया कि भारतीय सच में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त होना 'अवैध घबिग्रहण' है। चूँकि इस मामले का सम्बन्ध किसी अन्य सरकार से नहीं था, इसलिए भारत सरकार ने 1 मई, 1975 को एक सक्षिप्त वक्तव्य जारी कर इसे अपने आन्तरिक मामले में चीन का हस्तक्षेप बताया। चीन बराबर यह दावा करता रहा कि भारत अपने पड़ोसियों के प्रति 'आधिपत्य और विस्तारवादी आकांक्षाएँ' रखता है और चाहता है कि वह सोवियत सच के समर्थन से एक

‘उप-महान-देश’ बन जाए। चीन के इस मिथ्या प्रचार के बावजूद भारत ने किसी प्रकार का कोई प्रचार आन्दोलन नहीं छेड़ा।

भारत-सरकार ने चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सुसंगत नीति का अनुसरण किया। इडियन टेबिल टेनिस फेडरेशन के निमन्त्रण पर विश्व टेबिल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चीन की एक टेबिल टेनिस टीम फरवरी 1975 में भारत आयी। इसी प्रकार भारत और चीन के अनुरोध पर नई दिल्ली स्थित उनके राजदूतावास में पारस्परिकता के आधार पर सामान्य टेलेक्स व्यवस्था चालू करने की सहमति हो गई। भारत के एशियाई विकास बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन की उम्मीदवारी का समर्थन दिया।

20 अक्टूबर को लगभग 40 चीनी सैनिकों ने पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सीमा को पार किया, घात लगाई और भारतीय प्रदेश में हमारे 4 सैनिकों को मार डाला। भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास से इस घटना के बारे में तीव्र विरोध प्रकट किया।

चीन के उप प्रधान मन्त्री के नाम प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ने जनवरी 1976 में श्री चाऊ-एन-लाई की मृत्यु पर, अपनी ओर से और भारत सरकार की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एक सदेश भेजा।

वर्ष 1976 में भारत-चीन सम्बन्ध—वर्ष 1976 भारत और चीन सम्बन्ध-सुधार का सदेश लेकर आया। राजदूत स्तर के राजनयिक प्रतिनिधित्व की वापसी के बारे में दोनों देशों के बीच सरकारी स्तर पर 1976 के आरम्भ में प्रतीपचारिक बातचीत हुई। यह वार्ता लाभदायक सिद्ध हुई और बातचीत के बाद अप्रैल में चीन लोक गणराज्य में श्री के. आर. नारायणन की भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। भारत की पहल का सकारात्मक उत्तर देते हुए चीन ने जुलाई, 1976 में अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत किए। सितम्बर में अपने प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करते हुए चीनी राजदूत ने कहा कि सयुक्त प्रयत्नों द्वारा सम्बन्धों का सामान्यीकरण दोनों देशों की जनता के हितों के पूर्णतः अनुरूप था। 15 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद भारत ने चीन के साथ विकासशील निर्माणात्मक और पर्यापूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धों की स्थापना तथा सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में राजदूत के स्तर पर संचार के माध्यमों की वापसी को सर्वप्रथम आवश्यक समझा।

प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री ने अगस्त, 1976 में उत्तर-पूर्वी चीन में आए भूकम्प के लिए चीन के नेताओं को सहानुभूति के सन्देश भेजे। भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए चीन सरकार ने भारत की बहुत सहायता की। प्रधान मन्त्री ने अध्यक्ष, हुआ-कुओ-फेंग को उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए बधाई भी भेजी और यह आशा व्यक्त की कि भारत और चीन के बीच सम्बन्ध प्राणामी वर्षों में और अधिक विवर्धित होंगे।

अक्टूबर-नवम्बर, 1976 में चीन की बैडमिंटन टीम की भारत-यात्रा और डॉ. कोटनिस मेमोरियल हाल के उद्घाटन के अवसर पर दिसम्बर, 1976 में

एक गैर-सरकारी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की चीन यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सम्बन्धों की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई ।

वर्ष 1977 में भारत-चीन सम्बन्ध—भारत के एक गैर-सरकारी व्यापार प्रतिनिधि मण्डल जिसमें राज्य व्यापार सङ्गठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, अप्रैल, 1977 में 'केप्टन स्प्रिंग फेयर' में सम्मिलित हुआ । प्रारम्भिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और यह आशा व्यक्त की गई कि इनसे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने में कुछ वास्तविक प्रगति होगी ।

फरवरी, 1977 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भारत तथा चीन के बीच सीधा राजनयिक सम्पर्क होने के बावजूद चीन तीसरी पार्टियों के माध्यम से भारत के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न कर रहा है । ऐसी खबर है कि चीनी नेताओं ने यूगोस्लाविया के विदेशमंत्री श्री मिलोस मिनिक तथा बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री श्री साइरस वास के साथ भारत-चीन सम्बन्धों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया । चीन द्वारा यूगोस्लाविया तथा अमेरिका के माध्यम से सामान्य सम्बन्धों की स्थापना की चेष्टा स्वाभाविक ही है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आज वह इन दोनों देशों पर अधिक विश्वास कर सकता है । कम्युनिस्ट राष्ट्र होने के बावजूद स्टालिन के शासनकाल में ही यूगोस्लाविया रूस के प्रभाव क्षेत्र से वृत्त हो गया था । रूस-चीन सैद्धान्तिक विवाद खुलकर सामने आने के बाद चीन का यूगोस्लाविया की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था ।

जहाँ तक अमेरिका का प्रश्न है वह किसी भी पूँजीवादी राष्ट्र की तुलना में चीन के ज्यादा निकट है । भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री निक्सन की पीकिंग यात्रा के बाद इन दोनों राष्ट्रों के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित हुए । इनकी मंजी का मुख्य आधार शायद यही है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों ही रूसी गुट के विरुद्ध हैं ।

चीन यदि भारत के साथ सामान्य सम्बन्ध चाहता है तो वह स्वयं इस दिशा में पहल कर सकता है । दोनों देशों के बीच राजनीतिक सम्बन्ध सन् 1962 के संघर्ष के दौरान भी भग नहीं हुए थे । पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास के घेराव तथा आक्रमण की स्थिति में भारत ने अपने प्रतिनिधि को अवश्य वापस बुला लिया था । अब तो दोनों देशों के बीच पुनः राजदूतों का आदान-प्रदान हो गया है । इसलिए यदि चीन सामान्य सम्बन्धों की पुनः स्थापना के उद्देश्य से सीमा-विवाद सुलझाना चाहता है तो वह राजनयिक स्तर पर पहल कर सकता है । प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा भी है कि यदि चीन सीमा-विवाद पर वार्ता के लिए पहल करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं ।

भारत में जनता पार्टी की स्थापना के बाद ऐसी वार्ता के लिए निःसंदेह अनुकूल वातावरण उत्पन्न हुआ है । यद्यपि नई सरकार ने देश की विदेश नीति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है, तथापि सत्ता-परिवर्तन के बाद वातावरण में भन्नर तो आता ही है । कांग्रेस सरकार पर चीन का आग्रह तोर पर यह आरोप था कि वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत सघ का साथ देती है । वैसे

इस आरोप का कोई आधार नहीं है, क्योंकि भारत की सदा यह घोषित नीति रही है कि वह सभी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना चाहता है। अब जनता सरकार ने जब घोषणा कर दी है कि भारत वास्तविक निर्गुणता की नीति का पालन करेगा तो चीनी नेता भी सामान्य सम्बन्धों की स्थापना के बारे में सोचने लगे हैं। आशा की जाती चाहिए कि रूस तथा अन्य देशों के साथ भारत के जो सम्बन्ध हैं वे इस दिशा में प्रगति में बाधक नहीं बनेंगे।

भारत, फ्रांस और पुर्तगाल

आजादी के बाद भी भारत में कुछ फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियाँ रह गई थीं। चन्नगर, पाण्डिचेरी, कालीकट, माही और यनाम की बस्तियाँ फ्रांस के अधीन थी तथा गोवा, दमन और द्यू पर पुर्तगाल का आधिपत्य था। यह स्वाभाविक था कि भारत अपनी भूमि पर स्थित इन उपनिवेशों को मुक्त कराने की चेष्टा करता। भारत सरकार ने फ्रांस से अनुरोध किया कि वह भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों को मुक्त कर दे। फ्रांस ने समझदारी से काम लीते हुए नवम्बर, 1954 में पाण्डिचेरी, कालीकट, माही और यनाम को तथा मई, 1959 में चन्नगर को भारत के सुपुर्द कर दिया। फ्रांस ने भारत से हटने में जितनी अधिक समझदारी दिखायी उतनी ही बेतमन्नी और दुराग्रही प्रवृत्ति का परिचय पुर्तगाल ने भारत से न हटने में दिखाया। गरी नहीं, सन् 1961 तक पुर्तगाल ने ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जो भारत की सुरक्षा के लिए घातक थी। गोवा में विशाल तैयारियों की गई तथा पुर्तगाली सैनिक आए दिन भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने लगे। अन्त में, दिसम्बर, 1961 में भारतीय सेना ने पुर्तगाल को गोवा छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गोवा भारतीय संघ का अंग बन गया।

भारत और पुर्तगाल के बीच 31 दिसम्बर, 1974 को राजनयिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के परिणामस्वरूप, सन् 1975 में भारत-पुर्तगाल सम्बन्धों में सतीतपूर्ण विकास हुआ, 19 मई, 1975 को भारत और पुर्तगाल के विदेश मन्त्रियों के बीच पत्रों का जो आदान-प्रदान हुआ, उससे सन् 1886 के पुर्तगाल-वातिकान घर्मसन्धि (ककोर्डेट) सम्बन्धी अंग तथा पुर्तगाल और वातिकान के बीच हुए अन्य सम्बद्ध समझौते भारत के लिए अनुपयुक्त हो गए। इस प्रकार, भारत के केंपोलिटिक गिरजाघरों में ऊँचे धार्मिक पदों पर नियुक्ति द्वारा पुर्तगाली सरकार के अन्तिम चिह्न भी मिटा दिए गए। दोनों देशों ने एक-दूसरे देश की राजधानी में मिशन खोले। लिस्बन में भारत का राजदूत पहले ही अपना पद सम्भाल चुका है।

फ्रांस के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित होते रहे। जनवरी, 1976 में फ्रांस के प्रधानमन्त्री की भारत-यात्रा के समय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए मन्त्री-स्तर की एक भारत-फ्रांस समिति गठित की गई। दोनों देशों के बीच सहयोग से सम्बन्धित मुद्दों पर प्राथमिक विचार-विमर्श करने के लिए वारिंज्य मन्त्री श्री चट्टोपाध्याय ने जुलाई, 1976 में पेरिस की यात्रा की। उद्योग मन्त्री श्री टी. ए. पें और पेट्रोलियम मन्त्री श्री के. डी. मालवीय ने फ्रांस की यात्रा की

और इस बात का संकेत दिया कि भारत फ्रांस के साथ और अधिक सहयोग की सम्भावनाएँ खोजने के लिए प्रयत्नशील है। फ्रांस, भारत सहायता संधि (एड इण्डिया कंसोर्टियम) का पहला सदस्य है जिसमें सन् 1976-77 में भारत के साथ विकास सहायता समझौता किया है। इस वर्ष फ्रांस से सामान सरीसरे एवं सेवाएँ प्राप्त करने के लिए 3400 लाख फ्रैंक (लगभग 60 करोड़ रुपये का) वित्तीय ऋण मिला। दोनों देशों में यात्रा-विनिमय करने वाले अनेक प्रतिनिधि-मण्डलों में एक भारतीय सार्वभौमिक प्रतिनिधि-मण्डल है जिसने अक्टूबर, 1976 में राज्य-सभा के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में फ्रांस की यात्रा की।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के सम्बन्ध

भारत और अमेरिका विश्व के दो महान् प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हैं। दोनों के सम्बन्ध काफी उत्तार-चढ़ाव के रहे हैं और दुर्भाग्यवश विगत कुछ वर्षों से ये अधिक कटु बन गए हैं। तथापि दोनों ही देश सम्बन्ध-सुधार के लिए प्रयत्नशील हैं और सन् 1975 के मध्य से ऐसे जखण दिखाई दिए हैं कि निकट भविष्य में दोनों देश पुनः मित्रता की दिशा में अग्रसर होंगे।

नेहरू-युग में भारत और अमेरिकी सम्बन्ध (1947-1964)

एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय होने के बाद से ही अमेरिका की विदेश-नीति का यह मुख्य उद्देश्य रहा कि भारत को अमेरिकी शिविर में लाया जाए और इसके लिए 'दबाव तथा सहायता की नीति' अपनायी गई। जब दिसम्बर, 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाया गया तो अमेरिका ने न्याय का गला घोटते हुए पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन दिया और आज भी इस प्रश्न पर अमेरिका का भारत-विरोधी रवैया पूर्ववत् विद्यमान है। जब साम्यवादी चीन का उदय हुआ तो अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि वह चीन को मान्यता न दे, किन्तु भारत ने अपनी स्वतन्त्र निर्णय-शक्ति का उपयोग कर दिसम्बर, 1949 में चीन को मान्यता दे दी। कोरिया-युद्ध के समय भारत ने प्रारम्भ में अमेरिका के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया और सुरक्षा परिषद् में अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन भी किया। लेकिन बाद में जब अमेरिकी कमान के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रीय सेना ने 38वीं अक्षांश रेखा पार कर उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध किया। कोरिया युद्ध में भारत की गुट-निरपेक्ष नीति और शान्ति प्रयासों की अमेरिका ने कटु आलोचना की। पश्चिमी प्रेस ने प. नेहरू को डॉन क्विक्जोट' तक कह दिया। जब सितम्बर, 1951 में जापान के साथ शान्ति-सन्धि के लिए आयोजित सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत ने शामिल न होने का निर्णय किया और अमेरिका की इस एक-तरफा शान्ति-सन्धि का (जिसमें युद्धकालीन मित्रराष्ट्रों—चीन तथा रूस को शामिल नहीं किया गया था) विरोध किया तो अमेरिका के समाचार-पत्र भारत पर उबल पड़े। हिन्द-चीन की समस्या पर भी दोनों देशों के दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर रहा। भारत शान्तिपूर्ण समाधान के पक्ष में था जबकि अमेरिकी प्रशासन बल प्रयोग में विश्वास करता था।

भारत में अमेरिका के प्रति सब बहुत अधिक लोभ फैला जब मई, 1954 में उसने पाकिस्तान के साथ एक सैनिक सन्धि कर उसे इस बहाने भारी सैनिक सहायता देना शुरू किया कि अमेरिकी हथियारों का प्रयोग साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किया जाएगा। लेकिन सन् 1965 और 1971 के युद्धों ने भारत की इस आशका को भली प्रकार सत्य सिद्ध कर दिया कि अमेरिका के हथियारों का प्रयोग लोकतान्त्रिक देश भारत के विरुद्ध होना था। अमेरिका की सैनिक सहायता नीति का पर्याकाय करते हुए भूतपूर्व राजदूत चेस्टर वाउल्स ने कहा—“बिगत 15 वर्षों में यूरोप के बाहर हमारी अधिकांश सैनिक सहायता नई सरकार को इस उद्देश्य से दी गई है कि वह अमेरिकी विदेश-नीति का समर्थन करे।” सन् 1954 में अमेरिका ने पाकिस्तान को सीएटो और सेण्टो का भी सदस्य बना लिया। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सगठनों पर भी व्यापक मतभेद रहे। श्री नेहरू ने हर प्रकार के सैनिक सगठनों का तीव्र विरोध किया और इनकी स्थापना को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के मार्ग में बाधक तथा समुक्त राष्ट्रसंघ के मूल उद्देश्यों के विपरीत माना। उन्होंने ट्रूमैन-मिडान्त और माइजनहॉवर-मिडान्त की बटु आलोचना कर अमेरिकी प्रशासन को झूठ कर दिया। दोनों देशों के सम्बन्धों में तब और भी त्रिगाड प्राया जब भारत ने लेवतान और जॉर्डन में अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध किया।

गोम्रा की समस्या भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न था, किन्तु नवम्बर, 1955 में अमेरिकी विदेश मन्त्री टलेम ने कहा—“जहाँ तक मैं जानता हूँ, सम्पूर्ण ससार गोम्रा को पुर्नगाल के एक प्रान्त के रूप में स्वीकार करता है।” जब दिसम्बर, 1961 में भारत ने गोम्रा का पुर्नगाल की दासता से मुक्त किया तो मुरझा परिपक्व में अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीवेंसन फूट पड़े—“माज राशि को हम उस नाटक के प्रथम अंक को देख रहे हैं जिसका अन्त समुक्त राष्ट्रसंघ की मृत्यु के साथ हो सकता है।” नीपो, नि.सस्त्रीकरण, विषतनाम आदि समस्याओं पर भी भारत और अमेरिका में गम्भीर मतभेद रहे हैं। भारत का दृष्टिकोण यह रहा है कि अमेरिका को विषतनाम में बमवर्षा बन्द कर शान्ति स्थापना की दिशा में रचनात्मक कदम उठाना चाहिए।

असहयोग और तनाव के उपयुक्त प्रमुख विन्दुओं के बावजूद भारत और अमेरिका में सहयोग का क्षेत्र भी काफी रहा है। अमेरिका ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए दवाव-नीति के साथ-साथ प्राथिक और प्रनाज-नूटनीति का सहारा भी लिया। न केवल अमेरिका से भारत को विशाल आर्थिक सहायता प्राप्त हुई बल्कि मुख्यतः अमेरिकी प्रेरणा से ही विश्व विकास-ऋण-कोष तकनीकी सहयोग आदि समस्याओं ने भी ऋण तथा उपहार के रूप में भारत को काफी प्राथिक एवं प्राविधिक सहायता प्रदान की। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सहयोग का विस्तार हुआ। पुलब्राइट योजना के अन्तर्गत दोनों देशों ने एक बड़ी राक्या में विद्वानों का आदान-प्रदान किया। अमेरिका ने भारत को प्राथिक सहायता और साथ संकट में प्रनाज देकर उदारता दिखायी, लेकिन साथ ही अपनी गन्दी नूटनीतिक

चानों से किए कराये पर पानी केरने का काम भी किया। उदाहरणार्थ, कभी तो घनाज के उपहार को ऋण में बदला गया, कभी ऋण के बदले में मैंगनीज की माँग की गई तो कभी सहायता इसलिए स्थगित कर दी गई कि अमुक प्रश्न पर भारत ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया। प. नेहरू ने अमेरिका की दबाव-नीति का साहसपूर्वक सामना किया। दिसम्बर, 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहॉवर की भारत-यात्रा में आशा की गई कि दोनों देशों के बीच सहयोग के नए युग का प्रादुर्भाव होगा। अमेरिका के राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जाने लगा कि भारत का आर्थिक विकास अमेरिकी विदेश-नीति का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रपति आइजनहॉवर ने भारत को विशेष सम्मान देते हुए 4 मई, 1960 को वाशिंगटन में भारत के खाद्य-मन्त्री श्री एस. के. पाटिल के साथ स्वयं एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन समझौते के अन्तर्गत फल की कमी का सामना करने तथा गन्ने को मुरझाने रमने के लिए अमेरिका ने भारत को आगामी 4 वर्षों में चावल तथा गेहूँ में भरे हुए 1,500 जलयान भेजने का निश्चय किया। मई, 1960 का यह समझौता ही 'सार्वजनिक कानून 480' (पी एल. 480) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 4 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर इस समझौते की अवधि में वृद्धि कर भारत को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न सहायता दी जाती रही।

राष्ट्रपति कर्नेडी के समय यद्यपि गोपा के प्रश्न पर भारत-अमेरिका सम्बन्धों में काफी कटुता या गई, तथापि अक्टूबर, 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के उपरान्त इन सम्बन्धों में एकाएक सुधार प्रारम्भ हुआ। भारत के अनुरोध पर अमेरिका ने बड़ी तेजी और तत्परता के साथ भारत को युद्ध-सामग्री पहुँचायी। अमेरिका की इस सकटकालीन सहायता ने भारतीयों के पिछले सभी पावों को भर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि मनभेदों के बावजूद दोनों राष्ट्र मित्रता के स्थायी आधार-स्तम्भ पर खड़े हैं। अमेरिका ने भारत को यह सहायता बिना किसी शर्त के प्रदान की। चीनी आक्रमण के समय भी भारत जिन प्रकार अपनी गुट-निरपेक्ष नीति पर डटा रहा, उगही अमेरिकी विदेश सचिव डीन रस्क ने प्रशंसा की। भारत अपनी स्वतन्त्र नीति में डिगा नहीं, इसका एक बड़ा प्रमाण यही है कि एक ओर तो भारत ने अमेरिका से सैनिक सहायता की माँग की, दूसरी ओर उसके एक दिन बाद ही जब संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन को अपना स्थान देने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो भारत ने चीन के पक्ष में मत दिया। मार्च, 1963 में भारत ने लगभग 100 करोड़ डॉलर की अमेरिकी सैनिक सहायता की माँग की, लेकिन अमेरिका ने केवल 6 करोड़ डॉलर दिए। इस तरह मूल रूप में अमेरिका की भारत-के प्रति असहयता बनी रही।

शास्त्री-काल में भारत-अमेरिका सम्बन्ध (1964-1965)

राष्ट्रपति कर्नेडी के उत्तराधिकारी लिण्डन बी. जॉनसन और प्रधानमन्त्री नेहरू के उत्तराधिकारी लालबहादुर शास्त्री बने। अमेरिकी नेतृत्व का विचार या कि श्री शास्त्री प. नेहरू के मुकाबले एक कमजोर नेता सिद्ध होंगे, अतः उनको दबाव

द्वारा अमेरिका के पक्ष में सरलता से भुकाया जा सरेगा। लिटिन श्री शास्त्री ने गुट-निरपेक्ष नीति का प. नेहरू से भी अधिक दृढ़ता के साथ अनुमरण किया और उसे पहले की तुलना में अधिक गंभीरता दी।

प्रारम्भ में तो दोनों देशों के सम्बन्धों में कोई बिगाड़ नहीं आया, लेकिन उत्तर-विघटनानुसार पर अमेरिकी व्यवस्था की जब भारत में गंभीर और सार्वजनिक दोनों में आलोचना हुई तो अमेरिका जैसे महान् लोकतान्त्रिक राष्ट्र ने अपमान का बड़ा निर्लज्ज प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति जॉनसन के निमन्त्रण पर श्री शास्त्री ने जून में, 1965 में अमेरिका जाने का कार्यक्रम निश्चय कर लिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी कार्यक्षमता के वर्णन निमन्त्रण को वापस ले लिया। अमेरिका का यह स्वयं भारत के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतीय जनता का सार्वजनिक अपमान था और विदेश मंत्री सरदार स्वर्णसिंह को बहना पड़ा कि भविष्य में श्री शास्त्री अपनी मुविधा देकर ही निमन्त्रण स्वीकार करेंगे।

पहले कश्मिर के रक्त में और फिर सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी अस्त्रास्त्रों के प्रयोग से भारत-अमेरिका के सम्बन्धों में अधिक घटना उत्पन्न हो गई। युद्धकाल में भी अमेरिका का रुम बहुत कुछ भारत-विरोधी रहा। अतः पूर्व रक्षा-उद्घाटन उपसभ्य श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा अक्टूबर, 1970 में किए गए एक रहस्योद्घाटन के अनुसार सन् 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने 6 जहाजों को, जिनमें भारत के लिए रक्षा सामग्री थी, भारतीय सट में मात्र 15 मील की दूरी में वापस लौटा दिया। यही नहीं, अमेरिका ने न तो पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सामग्री का प्रयोग करने से रोकना और न अपनी इन कार्यवाही की निन्दा की। इसके बाद अमेरिका की बात यह हुई कि जब सन् 1966 में पाकिस्तान ने चीन से पश्चिम में सीमा पर चीन की पौरचीन से विशाल मात्रा में सैनिक सहायता भी प्राप्त की, तो भी अमेरिकी प्रशासन ने पाक-समर्थक रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया।

फिर भी, दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार के प्रयत्न जारी रहे और इससे कुछ सुपरिणाम भी दृष्टिगोचर हुए। एक तो अमेरिका ने यह निर्णय किया कि भारत की खाद्यान्न की सहायता पुनः चालू हो जाएगी। दूसरे अमेरिका ने ताशक सम्मेलन की आवाज पहुँचाने की कोई कार्यवाही नहीं की।

10 जनवरी, 1966 को श्री शास्त्री के देशान्तर के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। राष्ट्रपति जॉनसन ने नए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वह शीघ्र ही अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम बनाएँ। यह यात्रा की जाने लगी। दोनों देशों के बीच मैत्री के नए युग का सूत्रपात होगा, लेकिन अमेरिका की वर्तमान नीति ने इस यात्रा को घुमिल कर दिया। जॉनसन-प्रशासन काल में दोनों देशों के बीच मतभेद जारी रहे और निरन्तर-युग में तो चरम चोमः तक पहुँच गए।

मार्च, 1966 में श्रीमती गाँधी ने अमेरिका की यात्रा की, किन्तु कोई अनुद्घाटन परिणाम नहीं निकले। अमेरिकी प्रशासन का प्रयत्न रहा कि भारत की प्रति

कठिनाइयों से लाभ उठाकर नए प्रधानमंत्री को अमेरिका की ओर झुकने पर विवश किया जाए। जॉनसन-प्रशासन ने अपनी दबाव नीति में उत्तरोत्तर वृद्धि की। खाद्यान्न के मामले में कॅनेडी के चार-वर्षीय सहायता-कार्यक्रमों को पुनः लागू नहीं किया गया। उनके स्थान पर अलगाववादी कदम उठाने की नीति अपनाई गई। भारतीय रुपये के अवमूल्यन के लिए भी प्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला गया। भारत-पाक युद्ध काल में बन्द की गई आर्थिक सहायता यद्यपि पुनः चालू कर दी गई, तथापि यह निराशाजनक थी। कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान की पीठ चपथपाई जाती रही और अग्रेल, 1967 में नागा विद्रोही फिरो को अमेरिका में शरण दी गई। अमेरिकी रक्षा-सचिव मैकनमारा ने भारत-पाक संघर्ष को हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की सजा दी और भारत को अपना विरोध प्रकट करना पड़ा। सन् 1967 में यह भी रहस्योद्घाटन हुआ कि भारत में अनेक सगठनों के माध्यम से सी. आई. ए. (अमेरिकी जासूसी विभाग) अपनी भारत-विरोधी कार्यवाही कर रहा था। सन् 1968 में भारत को अमेरिका की ओर से जो सहायता-राशि स्वीकृत की गई वह पिछले 20 वर्षों में सबसे कम थी। अमेरिकी सहायता में कटौती ने भारत की आर्थिक योजनाओं पर गुरा प्रभाव पड़ने लगा, लेकिन श्रीमती गांधी ने घुटने टेकने से इकार कर दिया। सन् 1969-70 का वर्ष भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में एक प्रकार से शीत-युद्ध का वर्ष था। विपतनाम के प्रश्न पर दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। भारत सरकार ने अमेरिका की अप्रमत्तता की परवाह न कर जनवरी, 1970 में उत्तर विपतनाम के साथ पूर्ण दौलत सम्बन्धों की घोषणा कर दी। फरवरी, 1970 में भारत सरकार के एक आदेश के फलस्वरूप अमेरिका को बगान और हैदराबाद, लखनऊ, पटना तथा तिरुवनन्तपुरम के अपने सांस्कृतिक केन्द्र बन्द कर देने पड़े। भारत का यह कदम जिनेवा समझौते के नियमों के अनुकूल था जिसमें सभी दूतावासों को उन नगरों में अपने सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने का आदेश दिया गया था जहाँ उनके उप-दूतावास नहीं थे। लगभग इसी समय कम्बोडिया में अमेरिकी सेनाओं के प्रवेश का भी भारत द्वारा विरोध किया गया। अगस्त, 1970 में भारत ने 'यूनाइटेड नेशन्स एटलस 20' नामक प्रकाशन की ओर अमेरिकी दूतावास का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बात पर विगोर प्रकट किया कि भारतीय क्षेत्र से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि जब श्रीमती गांधी न्यूयार्क यात्रा पर रवाना हुईं तो अमेरिकी राजदूत हवाई अड्डे पर उन्हें बिदा करने नहीं पहुँचा। न्यूयार्क हवाई अड्डे पर भी भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कोई अमेरिकी बरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नहीं था। इस स्थिति में स्वभावतः श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति निकसन का निशेधन आने का निमन्त्रण ठुकरा दिया और सीधे भारत लौट आईं।

सन् 1971 का वर्ष दोनों देशों के सम्बन्धों में विस्फोटक रहा। पाकिस्तानी अत्याचारों से पीड़ित लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के भरण-पोषण का भार भारत पर आ पड़ा। पाकिस्तान का भारत पर यह अप्रत्यक्ष आक्रमण या जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था पर भारी भार ला पटका। भारत और विश्व के अनेक देशों के

मनुरोध के बावजूद अमेरिका ने इस मातृवीय सम-या की ओर से भाँते बन्द कर ली। पाकिस्तान को सैनिक तथा अन्य सहायता प्राप्त होती रही। जब प्रमस्त, 1971 में भारत और रूस के बीच मैत्री-सन्धि हुई गई तो अमेरिकी विदेश नीति को काफी पक्का लगा। दिसम्बर 1971 में भारत-पाक युद्ध काल में सुरक्षा परिषद् में अमेरिका ने भारत-विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो सोवियत वीटो के कारण विरस्त हो गए। अमेरिका ने 'युद्ध गैर राजनय' की धार चलाकर अपने सानवे बैठे की बगल की खाड़ी में भेजा ताकि बंगलादेश में विरोधी पाक फौजों को सहायता प्रदान की जा सके तथा भारत को सैनिक दबाव द्वारा मानसिक किया जा सके। किन्तु अमेरिकी कूटनीति चुरी तरह असफल हुई। हिन्द महासागर में रूसी नौ-मैलिक बेटे ने अमेरिका को सचेत कर दिया कि यदि उसने भारत के विरुद्ध नौ-मैलिक कार्यवाही की तो रूस बबल दसक माथ नहीं रहेगा। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता रोक दी, किन्तु भारत ने अपने विदेश कार्यक्रमों में डील नहीं आने दी। सन् 1972 के प्रारम्भ में अपनी फ्राम-यात्रा के समय श्रीमती गाँधी ने वहाँ के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री रिचर्ड मेडीज से कहा—

“आम समुत्तराज्य अमेरिका कहता है कि यह हमें आर्थिक सहायता नहीं देगा, कोई चीज नहीं। हम आर्थिक सहायता की जरूरत भी नहीं और अगर जरूरत होगी तो भी हम यह सहायता अपनी आजादी को खतरे में डालकर नहीं लेंगे। हम अपनी आजादी को हर कीमत पर कायम रखेंगे। लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं करते जो हमिषार उम्होने हमें दिए। उनकी हमने पूरी कीमत चुका दी है।”

फरवरी, 1972 में राष्ट्रपति निकसन ने काँग्रेस को दिए गए वार्षिक विदेश-नीति सम्बन्ध में कहा—“अमेरिका भारत से आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर बातचीत के लिए तैयार है। किन्तु उसकी रुचि इस बात में है कि दक्षिण एशिया का यह शक्तिशाली देश अपने पड़ोसियों के प्रति कैसा रवैया अपनाता है।” निकसन के इस वक्तव्य की भारत में प्रतिबल प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि निक्सन झूठे आरोप दुहराकर दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश बनकर पड़ोसियों को दबाना चाहता है। भारत-सोवियत सन्धि के सम्बन्ध में निक्सन की यह भारत को एक प्रकार से धमकी थी जिसमें सहित दिया गया था कि अमेरिका और भारत के सम्बन्धों में सुधार तभी हो सकता है जब भारत सभी महाशक्तियों के साथ समान सम्बन्ध स्थापित करने को सहमत हो। अर्थात् सोवियत संघ के साथ भारत के कोई विशेष सम्बन्ध न हो। 21 फरवरी को अमेरिक ने पाकिस्तान को आर्थिक और सैनिक सहायता फिर से शुरू किए जान की चेत्नी की। आर्थिक सहायता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन सैनिक सहायता का अर्थ भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः अशांति को बढ़ावा देना था। उसके तुरन् बाद ही निक्सन बेचि गए और निक्सन-चाऊ बार्ता के तत्पर्य में श्रीमती गाँधी ने नेतावनी दी कि यदि अमेरिका और चीन ने एशिया के भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया तो उसे अन्य एशियाई देश स्वीकार नहीं करेंगे। श्रीमती गाँधी ने कहा कि

यदि अमेरिका-चीन वार्ता शान्ति के लिए हो रही है तो स्वागत योग्य है, लेकिन हमें सावधान होना है कि इस वार्ता का उद्देश्य एक नए शक्ति गुट का निर्माण करना है। विपत्तनामी जनता ने सिद्ध कर दिया कि बड़ी शक्तियों द्वारा छोटे राष्ट्रों के भाग्य-निर्णय का सिद्धान्त अब पुराना पड़ चुका है। मिक्सन-यात्रा की समाप्ति पर प्रसारित समुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तान क्षेत्र से भारतीय सेना की वापसी और जम्मू-कश्मीर की जनता के 'आत्मनिर्णय के अधिकार' की मांग की गई। यह भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप जैसी बात थी, अतः समुक्त विज्ञप्ति पर भारत ने अपना विरोध व्यक्त कर दिया।

मार्च, 1973 में जब यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निश्चय कर लिया है तो भारत में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार की सम्भावना बहुत कम हो गई। सन् 1973-74 में ईरान की विशाल मात्रा में शस्त्रास्त्र देने की योजना मई, 1973 में प्रकट हुई। भारत ने इस पर चिन्ता प्रकट की क्योंकि सन् 1971 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी थी और ईरान ने हर प्रकार से इसकी सहायता का समर्थन भी किया था। दिसम्बर, 1973 में सोवियत नेता ब्रेझ्नेव की भारत यात्रा से अमेरिका में यह चिन्ता बलवती हो गई कि यदि भारत-अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार न लाया गया तो अमेरिका को महान् लोकतान्त्रिक देश की सहायता से हाथ धोना पड़ सकता है। अतः भारत के प्रति कुछ अनुकूल रुझाव अपनाया जाने लगा। 13 दिसम्बर, 1973 को पी. एल. 480 के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। पी. एल. 480 तथा कुछ अन्य ऋणों की मद में भारत द्वारा अमेरिका को 24 अरब रुपये देने थे। समझौते के अनुसार अमेरिका ने 16 अरब 68 करोड़ रुपये पाँचवी योजना के लिए भारत को अनुदान के रूप में प्रदान कर दिए और शेष रुपये अमेरिकी ढूँढावा के खाते में तथा नेपाल की सहायता के लिए छोड़ दिया गया। पी. एल. 480 की वास्तविकता को देखते हुए अमेरिका का यह कोई पहलान नहीं था, तथापि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध-सुधार की दिशा में यह एक शुभारम्भ माना जा सकता है।

अमेरिका द्वारा हिन्दमहासागर में स्थित ब्रिटिश अधिकृत टापू डियागो गार्सिया में प्रस्तावित नौ-सैनिक गढ़वा स्थापित करने के निर्णय से सन् 1974 में भारत और अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार के प्रयत्नों को पुनः प्राधान्य पहुँचा। श्रीमती गाँधी ने इस निर्णय की अस्वीकार्यता की और इसे शान्ति के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि हिन्दमहासागर में नौ-सैनिक तथा परमाणु-गढ़वा स्थापित करने का निर्णय समुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव के विपरीत है जिससे केवल तनाव में वृद्धि होगी और एशिया में अशांति बढेगी। 18 मई, 1974 को एक सफल भूगर्भीय आणविक परीक्षण द्वारा जब भारत परमाणु विरादरी का छठा देश बन गया तो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। इससे भी दोनों देशों के बीच तनाव में वृद्धि हुई।

अप्रैल, 1974 में निम्न के स्थान पर जेराल्ड फोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बने और यह घोषणा की गई कि नया नेतृत्व भारत के प्रति सहयोग और मैत्री की नीति अपनाएगा। लेकिन कुछ ही समय में स्पष्ट हो गया कि फोर्ड ने भी निम्न की रवैया ही अपनाया था। फरवरी, 1975 में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने की निम्न घोषणा कर दी और भारत को वही पुराना विसाधित आस्वाप्त दिया कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने इसे अमान्यपूर्ण कार्यवाही मानते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की प्रतिरक्षा नीति इन घोषणाओं से प्रभावित नहीं हो सकती क्योंकि भूतकाल में पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों का हर बार भारत के विरुद्ध उपयोग किया है। अप्रैल 1975 में अमेरिका और ब्रिक्सनाम से अमेरिका के पलायन ने सिद्ध कर दिया कि हिन्द-चीन के प्रति भारत की नीति ठोस थी और अमेरिका का इस प्रश्न पर भारत-विरोध निरर्थक था। यदि अमेरिका ब्रिक्सनाम में सैनिक हस्तक्षेप न करता प्रथम वहाँ से पहले ही हट जाता तो न तो ब्रिक्सनाम युद्ध इतना लम्बा निम्न और न अमेरिकी विदेश-नीति को ऐसा घक्का लगता।

सनमेरो के वायव्य परिपक्व एवं रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह समझने के लिए भारत-अमेरिका के बीच वार्ता और आदान-प्रदान का नम सन् 1975 में चालू रहा। घामाओ पर यह अनुभव किया गया कि इण्डोनेशिया, प्रायमिकता और समस्याएँ अन्तर के वायव्य दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय हित के स्तर पर कोई विवाद नहीं है और शान्ति, स्थिरता तथा सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए वे नि सन्देह बहुत कुछ कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान के लिए एक सम्मेलनक ढाँचा बनाने की प्रक्रिया भी जारी रही और इस दिना में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अक्टूबर, 1975 में भारत अमेरिका ने अमेरिका की यात्रा की। और भी नई सरकारी प्रतिनिधि मण्डल प्रेमिका गए। अमेरिका से भारत की यात्रा पर आने वालों में प्रमुख थे वित्त मंत्री, वेलियम साइमन और मिनेटर जॉन मेकगवर्न। सन् 1975 की विशेष उल्लेखनीय बात थी भारत-अमेरिकी संयुक्त आयोग की वारिक बैठक में शामिल होने के लिए तथा अमेरिकी विदेश मंत्री से यात्राओं करने के लिए हमारे विदेश मंत्री का वाशिगटन जाना। इन वार्ताओं में तथा बाद में राष्ट्रपति फोर्ड और दूसरे अमेरिकी नेताओं के साथ वातचीत में विदेश मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार-विमर्श किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीति भारतीय उन्नतवादीय में शान्ति और स्थिरता के सर्वजन की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत कि प्रकार प्रमुखतात्मक सम्मान और पारस्परिक सम्मान के आधार पर अपने पटोमिओ के साथ पारस्परिक सहयोग एवं सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है तथा भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति, एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सृजन के प्रति उसका समर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोगों के आर्थिक, वित्तीय, ऊर्जा, साध एवं सम्बन्ध समस्याओं के प्रति एक रचनात्मक इण्डोनेश तैयार करने में उसकी

क्या भूमिका है। इस उपमहाद्वीप में हथियारों की होड़ के खतरे के प्रति और हिन्दमहासागर को एक शान्ति-क्षेत्र बनाए रखने की आवश्यकता पर भी समुक्तराज्य अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया गया। जहाँ तक द्विपक्षीय सम्बन्धों का प्रश्न है हमारे विदेश-मन्त्री ने भारत को इस इच्छा की पुनः पुष्टि की कि भारत अमेरिका के साथ पारस्परिक समानता, सम्मान और समझौते के आधार पर अच्छे सम्बन्ध चाहता है। राष्ट्रपति फोर्ड और विदेश मन्त्री कीसिंगर दोनों ने शान्ति और गुट-निरपेक्षता के क्षेत्र में भारत की भूमिका को स्वीकार किया।

दोनों देशों के सम्बन्धों में रचनात्मक सुधार की प्रक्रिया सन् 1976 में भी धीरे-धीरे बढ़ी। भारत ने अमेरिका के साथ समझौता और सहयोग वृद्धि के प्रयत्न चालू रखे। ऐसा महसूस हुआ कि भारत तथा अमेरिका के बीच बहुत कुछ ऐसा था कि दोनों देश शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न कर सकते थे। भारत-अमेरिका सम्बन्धों में कुछ निश्चयात्मक तत्व था दोनों देशों की अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने, व्यावसायिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने की इच्छा। समस्त विश्व में तनाव दूर कर, सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति की दृष्टि से इस बात की आशा की गई कि भारत-अमेरिकी सम्बन्ध भी समानता तथा पारस्परिक मैत्री के आधार पर विकसित और सौहार्दपूर्ण होंगे। इस वर्ष दोनों देशों के मन्त्री तथा पदाधिकारियों ने एक दूसरे देश की यात्राएँ की।

व्यापार-परिपद ने, जिसको बंटक फरवरी, 1977 में वाशिंगटन में हुई थी, इस बात का निर्देश दिया कि भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्यिक सम्बन्ध दोनों देशों में समुक्त रूप से व्यापारिक और औद्योगिक सहयोग की वृद्धि द्वारा सुदृढ़ किए जा सकते हैं। परिपद ने अमेरिका को भारत के साथ व्यापार-सम्बन्धों की सम्भावना से अवगत कराने के लिए कार्यवाही करने का निर्णय लिया। समुक्तराज्य अमेरिका की स्वतन्त्रता की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने कई कदम उठाए जैसे—उस दिन भारत सरकार ने एक विशेष टिकट जारी किया, गत 200 वर्षों में भारत-अमेरिकी सम्बन्धों पर एक सचित्र पुस्तक प्रकाशित की और भारत की मैत्रीपूर्ण भावनाओं को अमेरिका की जनता तक पहुँचाने के लिए एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका भेजा। दिवंगत राष्ट्रपति फॉर्स्वोर्थ की अर्द्धशताब्दी की स्मृति में राष्ट्रपति कार्टर ने अपनी माता ओपेली विलियम कार्टर के नेतृत्व में एक विशेष प्रतिनिधिमण्डल भेजकर सम्भावना व्यक्त की।

वर्ष 1977 में भारत-अमेरिकी सम्बन्ध—अमेरिका ने भारत में शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रात्मक तरीके से निष्पक्ष और मुक्त चुनाव द्वारा सरकार बदलने की प्रशंसा की। राष्ट्रपति और नए प्रधानमन्त्री में मैत्रीपूर्ण सन्देशों का आदान-प्रदान हुआ। यह आशा की गई कि दोनों देशों में सुदृढ़ प्रवाह पर द्विपक्षीय सम्बन्धों को पुनः स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री कार्टर ने भारतीय चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करने हुए कहा कि पश्चिमी देशों को भारतीय लोकतन्त्र से प्रेरणा लेनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्रमन्त्रि में प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई के मानवीय प्रचिन्तन सम्बन्धी विचार अमेरिकी राजदूत श्री यग द्वारा उद्धृत किए। मई, 1977 में भारत के वित्तमन्त्री श्री एच. एम. पटेल ने अमेरिकी यात्रा की जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से भारत को अमेरिकी सहायता प्राप्त होने के संकेत मिले। अमेरिका ने एक तरफ पाकिस्तान को ए-7 बमवर्षक देने की घोषणा की तथा दूसरी ओर भारत को जाने वाली यूरेनियम सप्लाई पर प्रतिबन्ध हटा लिया। हिन्दमहासागर के वित्तगोचरण के बारे में श्री कार्टर ने सोवियत संघ के सम्मुख प्रस्ताव रखा है कि रुम के इस क्षेत्र से हटने पर अमेरिका भी हट जाएगा। कश्मीर-विवाद अभी भारत-पाक के बीच ठण्डा है क्योंकि पाकिस्तान आन्तरिक राजनीतिक उथल-पुथल में जलज्झा हुआ है।

भारत तथा अमेरिका दोनों में नई सरकारों ने विदेश-नीति तथा राजनयिक पद्धति को एक नया मोड़ दिया है। निक्सन कीसिजर की तरह अमेरिकी राष्ट्रपति श्री कार्टर हठधर्मों के शिखार दिखाई नहीं देते। इस विस्तारण से स्पष्ट है कि बदलती राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यदि दोनों देशों के राजनेता सच्चे दिल से सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं तो यह एक शुभ घड़ी है। जनवरी, 1978 के प्रथम सप्ताह में श्री कार्टर की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास को पूरा बल मिलेगा यह आशा की जाती है।

दक्षिण और मध्य अमेरिका

वर्ष 1976 में भारत, लेटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों ने विकासशील देशों के रूप में पारस्परिक सम्बन्ध विकसित करने तथा एक दूसरे के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न किया। लेटिन अमेरिका को इस बात का ज्ञान हो गया है कि इसका भाग्य सैय विकासशील विश्व के भाग्य निम्न राजनीतिक तथा धार्मिक सहयोग में ही निहित है। स्पानीय तथा क्षेत्रीय विघटनताओं के बावजूद विदेशी मामलों में अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की इच्छा काफी व्यापक रही। इस क्षेत्र के कई देशों ने गुट-निरपेक्षता के बारे में भारत के इस मन को रबीकार किया कि यह आन्दोलन मैनिफेस्ट सम्बन्धों तथा सैद्धान्तिक अनुसूचितता का प्रतीक था। इनमें से सात देश गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के पूर्णरूप से सदस्य हैं और चार नए चुनाव कोलम्बो में नमन्वय-व्यूरो के लिए किया गया। अन्य कई देशों ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में होने वाली गोष्ठियों तथा आन्दोलनों का अनुसरण किया।

द्विपक्षीय स्तर पर लेटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्रों में भारत की रुचि में वृद्धि हुई। वहाँ पर शीघ्र ही एक प्रवासो मिशन तथा भवतन्त्रिका महाकोसल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। इस समय भारत के 23 देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध हैं तथा इस क्षेत्र की 12 राजधानियों में भारत के आवासीय मिशन हैं। भारत और क्यूबा सांस्कृतिक मामलों तथा विज्ञान व तकनीक के विशेष क्षेत्रों में प्रथम बार एक दूसरे को सहयोग देंगे। तीन समझौतों का अनुसमर्थन किया गया, इनमें से एक तो सांस्कृतिक क्षेत्र में अजेंडाइना के साथ है और दो संस्कृति तथा व्यापार के क्षेत्र में कोलम्बिया के साथ हैं। सन् 1975 में मेक्सिको के साथ हुए

सांस्कृतिक विज्ञान-तकनीक समझौते के अन्तर्गत पारस्परिक सहयोग के कार्यक्रम की एक श्रृंखला तैयार की गई। सांस्कृतिक करार पर विचार-विमर्श करने के लिए वेनेजुएला के पदाधिकारियों के एक दल ने नई दिल्ली का दौरा किया।

वर्ष 1976 में लेटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्रों की यात्रा करने वाले महत्वपूर्ण नेता प्रतिनिधिमण्डल थे—जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्री, राज्य गृह मन्त्री जो मेक्सिको सिटी में अन्तर-संसदीय यूनियन में भी उपस्थित हुए। इनके अतिरिक्त प्रधानमन्त्री के विशेष राजदूत जो मेक्सिको सिटी में तृतीय विश्व केन्द्र के उद्घाटन में सम्मिलित हुए, सूचना एवं प्रसारण मन्त्री और जैम ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल, सेल, भारत निवेश केन्द्र, भारत प्रभूमनियम केवल लिमिटेड और मोकन के प्रतिनिधि थे। उस क्षेत्र से भारत में आने वाले उल्लेखनीय अतिथि थे—वेनेजुएला अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विभाग के मन्त्री डॉ. मेनयूल पीराज गुयरीरो, बयूबा की विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉ. जोइलो मोरीनेलो तथा विज्ञान और तकनीकी राज्य कमेटी के प्रथम उपाध्यक्ष, वाहुमस के उप-प्रधानमन्त्री तथा वित्तमन्त्री माननीय आर्थर हान्ना ब्राजील का एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल। ब्राजील के संसद-सदस्यो तथा जमैका के औद्योगिक निवेश-निगम के प्रतिनिधियो ने भी भारत का दौरा किया।

इस क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार तथा आर्थिक क्षेत्रों में भारत का सहयोग अभी कम ही है। फिर भी जैसा कि गुयाना में हुए संयुक्त सहयोग के कार्यक्रम से स्पष्ट है इन देशों के साथ भारत के सहयोग की पर्याप्त सम्भावना है। इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए जिनमें ब्राजील में एक औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना भी शामिल था। भारत तथा ब्राजील के व्यापार पदाधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हुआ। इस बातचीत के फलस्वरूप हुए एक समझौते के अनुसार ब्राजील ने भारत से विभिन्न प्रकार की इस्पात से बनी वस्तुएँ और इन्जीनियरी का सामान खरीदने की इच्छा प्रकट की। भारत ने ब्राजील से जहाज जलपोत तथा कुछ रासायनिक सामान खरीदने में अपनी रुचि दिखायी। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत की एस. टी. सी. जो घरण्डी के तेल की प्रमुख एजेंसी है, तथा समवर्ती ब्राजील सस्था के बीच इस मद के निर्यात मूल्यों के सम्बन्ध में समझौता होगा। अर्जेंटीना की एक जहाजरानी लाइन के साथ भारत तथा अर्जेंटीना के बीच एक द्विमासी सेवा आरम्भ करने की सम्भावनाओं पर भी बातचीत हुई। उसने अपनी सेवा का बम्बई तक विस्तार करने में रुचि प्रदर्शित की। भारत के जहाजरानी निगम में कैरेबियाई देशों की द्विमासीय सेवा चालू है और सिन्धिया का एक जहाज समय-समय पर कोलोन (पनामा) जाता रहता है।

सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध (Relations with Soviet Union)

स्टालिन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में भारत और रूस के सम्बन्ध कुछ तनावपूर्ण रहे, किन्तु उपरोक्त भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य और भारत की मुटु-निरपेक्षता

के सही इरादे स्पष्ट होते गए, सोवियत रूस के साथ भारत के सम्बन्धों में सुधार होता गया और आज तो दोनों देश प्रगाढ़ मित्र के बन्धन में आबद्ध हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व ही उपनिवेशवाद, निःशस्त्रीकरण, अणुवम, विशेषाधिकार आदि प्रश्नों पर भारत और रूस के बीच इतना मतभेद था कि अमेरिका के विदेश-मन्त्रि जॉन फोर्स्टर डनेल ने 18 जनवरी, 1947 को यहाँ तक कह दिया था कि—“भारत में सोवियत साम्यवाद अन्तरिम हिन्दू सरकार के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है।” लेकिन आने वाले समय ने सिद्ध कर दिया कि भारत न तो पूर्वोदासी बगल के शिकंजे में है और न साम्यवाद के प्रभाव में। सन् 1947 के बाद भारत में साम्यवादी दल ने अपनी विध्वंसकारी गतिविधियाँ प्रारम्भ कर भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी सतरे के विरुद्ध सचेत कर दिया। यूनान और कोरिया के प्रश्नों पर भारत और रूस में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए और इसी समय भारत द्वारा ब्रूमेल्स-सन्धि को स्वीकृति प्रदान कर देने से दोनों के सम्बन्ध और भी बिगड़ गए। अप्रैल, 1949 में सोवियत प्रेस ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ साठगाँठ कर रही है।

भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को ‘निर्बल अवसरवादी नीति’ का ही प्रतिरूप समझा गया। फिर नवोदित भारत अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से पश्चिमी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन और अमेरिका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना आवश्यक समझता था। भारत के पश्चिमी देशों के साथ सहयोग स्थापित करने के प्रयत्न सोवियत रूस की आलोचना के विषय देने, किन्तु सन् 1949 के अन्त तक भारत और रूस के सम्बन्धों में सुधार होने लगा। श्री नेहरू पश्चिम के साथ मैत्री-सम्बन्धों का निर्वाह करते हुए भी रूस की प्रतिधियों को दूर करने का प्रयत्न करते रहे। पश्चिम की अग्रसरता की परवाह न करते हुए साम्यवादी चीन की मांग्यता देख कर श्री नेहरू ने भारत की स्वतन्त्र विदेश नीति का परिचय दिया। मास्को में भारतीय राजदूत डॉ. राधाकृष्णन के सद्ग्रयासों से दिल्ली-मास्को के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के विकास में बहुत सहायता मिली। सन् 1949 में ही दोनों देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता सम्पन्न हुआ।

इस बढती हुई मैत्री को जून, 1950 में कोरिया-युद्ध छिड़ने पर भटका गया। भारत न्याय और निष्पक्षता के पक्ष में था, मत. उसने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने में कोई सकोच नहीं किया। इससे सोवियत संध में भारत के प्रति रोष पैदा हो गया, किन्तु जब कोरिया-युद्ध के अग्रिम चरण में भारत ने संयुक्तराष्ट्र सभाय तीनारों की 38वीं प्रस्ताव रखा पार करने तथा चीन को आक्रमणकारी घोषित करने के विरुद्ध चेतावनी दी तो स्टालिन को विश्वास हो गया कि भारत की निर्णय शक्ति स्वतन्त्र है, पश्चिम के दबाव से प्रेरित नहीं। इस घटना से दोनों देशों के बीच मतभेद पुनः कम हुए। दोनों देश एक-दूसरे के निरपेक्ष

और अधिक आए जब सितम्बर, 1951 में भारत ने जापानी शान्ति-मन्त्रि पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया क्योंकि यह सन्धि जापान को साम्राज्यवादी शिकजे में जड़ने की एक चाल थी। अप्रैल, 1952 में रूस के लौह-शासक स्टालिन ने भारतीय राजदूत डॉ. राधाकृष्णन से भेंट की। यह भेंट इस दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण थी कि पिछले दो वर्षों में स्टालिन किसी भी राजदूत से नहीं मिला था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस भेंट को भारत-रूस सम्बन्धों में सुधार का प्रतीक माना गया। दिसम्बर, 1952 में कोरिया के युद्धबन्धियों के प्रश्न पर दोनों देशों के बीच पुनः अल्पकालीन मतभेद पैदा हो गए।

छद्म-श्वेव-काल में भारत-रूस सम्बन्ध

मार्च, 1953 में स्टालिन का देहान्त हो गया। इसके बाद सोवियत शासन की वागडोर पहले मोर्लेंकोव और फिर बुल्गानिन-खश्चेव के हाथों में आई। इस काल में अमेरिका ने भारत द्वारा कोरिया के राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने का विरोध किया जिससे रूस और भारत के सम्बन्धों में अधिक प्रगाढ़ता आई। रूस ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैनिक सहायता का विरोध करके भी भारत की सद्भावना अर्जित की। सन् 1954 में रूस ने 'पंचशील' के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। दूसरी ओर अमेरिका ने साम्यवाद का प्रसार रोकने के नाम पर सैनिक सगठनों का जो जाल बिछाया, उसकी भारत द्वारा कटु आलोचना की गई। इन घटनाओं से भारत और सोवियत संघ के सम्बन्ध और भी मधुर हो गए। जून, 1955 में श्री नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की तथा रूसियों को अपने सह-अस्तित्व की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित किया। संयुक्त विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों देशों के सम्बन्ध पहले से ही मंत्री और सहिष्णुता पर आधारित हैं तथा भविष्य में भी पंचशील द्वारा निर्देशित होते रहेंगे। सन् 1955-56 में श्री बुल्गानिन और खश्चेव ने भारत की यात्रा की। सन् 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के बाद शायद पहली बार कोई रूसी प्रधान मंत्री सद्भावना-यात्रा पर इस प्रकार अपने देश से बाहर निकला था। रूसी नेताओं की यह यात्रा भारत की असलमता की नीति के लिए बहुत सम्मानजनक बात थी। अपनी इस भारत-यात्रा के समय सोवियत नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बात का समर्थन किया कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है।

उपनिवेशवाद और जातीय भेदभाव से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण समान रहे। सन् 1955 में हंगरी की घटना पर दोनों देशों के सम्बन्धों में कुछ तनाव पैदा हुआ, क्योंकि हंगरी में की गई सोवियत सैनिक कार्यवाही का भारत में विरोध हुआ, लेकिन यह तनाव अल्पकालिक ही रहा। इससे दोनों देशों के मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों में कोई विशेष बाधा उत्पन्न नहीं हुई। सन् 1955 के बाद से ही दोनों देशों के बीच अधिक सम्बन्ध भी विकसित होने लगे। कश्मीर-विवाद पर सोवियत संघ भारत को खुला समर्थन देता रहा और सुरक्षा-परिपक्व ने पश्चिमी राष्ट्रों के भारत-विरोधी प्रस्तावों पर 'वीटो' का प्रयोग करता रहा। निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में भी दोनों देशों के दृष्टिकोणों में काफी समानता रही। सन् 1959 और

1960 में महासभा के अधिवेशनों में भारत ने निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी हसी प्रस्तावों का समर्थन किया। सन् 1962 में गोमा-विलय के प्रश्न पर सुरक्षा-परिपक्व द्वारा भारतीय कार्यवाही पर निन्दा का प्रयत्न 'हमी वीटो' के प्रयोग द्वारा ही विफल हुआ।

अक्तूबर, 1962 में चीनी आक्रमण के प्रारम्भ में हसी दृष्टिकोण भारत के लिए निराशाजनक था। 25 अक्तूबर, 1962 के 'प्रावदा' के सम्पादकीय लेख में खुले रूप से चीन की 24 अक्तूबर वाली शर्तों का समर्थन किया गया था। यह एक प्रकार से बिना भारत की निन्दा किए चीन के पक्ष का समर्थन था। इतना ही नहीं, रूस ने भारत को मिय विमानों की सप्लाई रोक दी। इन सब बातों से भारत में रूस के प्रति प्रतिभूत प्रतिक्रियाओं का ज्वार-भा आ गया, किन्तु भारत सरकार का यह विश्वास कायम रहा कि वस्तु-स्थिति का ज्ञान होने पर हम चीन का पक्षग्रहण नहीं करेंगे, और हुआ भी यही। धीरे-धीरे भारत पर चीनी-आक्रमण के सम्बन्ध में सोवियत दृष्टिकोण बदलने लगा और दिसम्बर, 1962 में तो शुभीम सोवियत में ख्रुश्चेव ने भारत पर चीनी हमले की तुली निन्दा की। सन् 1963 में चीन द्वारा कोलम्बो प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर भी रूस ने चीन की कटु आलोचना की। भारत को मिय विमानों की सप्लाई की गई और मिय विमानों का एक कारखाना भी भारत में स्थापित किया गया। जुलाई, 1963 में सोवियत सभ गया सोवियत रूस से प्राप्त होने वाली सैनिक सहायता की सम्भावनाओं पर विचार करने के लिए भारत की ओर में एक मिशन सोवियत सभ गया। 4 नवम्बर, 1963 के एक समझौते के अनुसार भारत में टेल एण्ड रैस की खोज तथा उन्हें विकसित करने के लिए रूस द्वारा तकनीशियनों को भेजने का निश्चय हुआ। रूस ने बोंकारो कारखाना तथा एक शक्तिशाली रेडियो स्टेशन स्थापित करने में सहायता देने का भी वचन दिया।

ब्रेझ्नेव-कोसीगिन काल में भारत-रूस सम्बन्ध (1974-1975)

26 अक्तूबर 1964 को ख्रुश्चेव के पतन के बाद रूस में ब्रेझ्नेव और कोसीगिन के नए नेतृत्व का उदय हुआ जो आज भी सत्ताशुद्ध हैं। नए नेताओं ने सोवियत राष्ट्र के माध्यम से भारत को आश्वासन दिया कि उनके प्रति सोवियत नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आगामी कुछ वर्षों में भारत को रूस का वह समर्थन नहीं मिल सगा जो ख्रुश्चेव ने दिया था। सितम्बर, 1965 में भारत-पाक संधि के समय सोवियत नेतृत्व की नीति किसी न किसी प्रकार संधि को शान्त करने की रही और रूस ने पाकिस्तान के कार्यों का पहले के समान विरोध नहीं किया। संयुक्त राष्ट्रसभ में भी उसकी नीति कुछ इसी प्रकार की रही। किन्तु पर्व के पीछे जो नूटनीतिज्ञ खेल खेले गए उनके प्रति रूस ने खुले रूप में भारत को समर्थन दिया। उदाहरणार्थ, एंग्लो-अमेरिकी गुट का यह प्रयास था कि भारत को आतंककारी घोषित किया जाए और यदि ऐसा न हो तो कम से कम कश्मीर में संयुक्त राष्ट्रसभ की वेना भेज दी जाए, लेकिन सोवियत सभ द्वारा वीटो प्रयोग की घमकी के कारण एंग्लो-अमेरिकी सं-गुट को इन भारत विरोधी पद्धतय का परित्याग करना पड़ा। जब 16 सितम्बर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया, तब भी

सोवियत सरकार ने यह चेतावनी दी थी कि विदेशी शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को और बिगाड़ने का प्रयास न करें। सोवियत रूस ने भारत-पाक संघर्ष के बाद से ही इस प्रकार की नीति का अनुसरण किया कि दोनों देशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध कायम रहें और पाकिस्तान को चीनी प्रभाव से मुक्त कर अपने प्रभाव में लाया जाए तथा शनैः-शनैः इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वह भारत-विरोधी रुख छोड़ दे। इसी प्रकार की नीति पर चलते हुए रूस ने जनवरी, 1966 में ताशकन्द सम्मेलन का आयोजन किया और अपने कूटनीतिक जादू से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकन्द समझौता सम्पन्न करा दिया।

ताशकन्द-समझौते के बाद दोनों देशों के सम्बन्धों में थोड़ा-सा तनाव तब आया जब रूस ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का निश्चय किया। सोवियत कूटनीति की यह 'नई दिशा' भारत के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाली थी। जुलाई, 1968 में पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने का निर्णय करते समय रूस ने भारत को यह आश्वासन दिया कि पाकिस्तान को दिए गए रूसी शस्त्रों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं हो सकेगा, पर पाकिस्तानी आचरण को देखते हुए रूस के ऐसे किसी भी आश्वासन पर भारत को भरोसा नहीं हो सकता था।

सोभाभ्यवश रूस शीघ्र ही समझ गया कि पाकिस्तान जैसे अस्थिरचित राष्ट्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अतः कुछ ही समय बाद पाकिस्तान को रूसी शस्त्रों की सप्लाई रुक गई। इसके पश्चात् भारत-रूस के सम्बन्धों में उत्तरोत्तर विकास होता गया। बंगलादेश की समस्या पर रूस का दृष्टिकोण भारत से मिलता-जुलता रहा। रूस ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि वह बंगलादेश में हत्याकाण्ड समाप्त कर समस्या का राजनीतिक हल खोजे।

भारत-सोवियत मैत्री सन्धि, 1971—9 अगस्त, 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच शान्ति, मैत्री और सहयोग की 20 वर्षीय ऐतिहासिक सन्धि सम्पन्न हो गई। इस सन्धि द्वारा भारत को एक महाशक्ति की ओर मैत्री तो प्राप्त हुई ही, यद्यपि सोवियत संघ भी एशिया में एक प्रभावी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया।

यह सन्धि, जिसके दस्तावेजों का आदान-प्रदान मास्को में किया गया, आरम्भ में 20 वर्ष के लिए है, लेकिन कोई भी पक्ष सन्धि की अवधि समाप्त होने से 12 महीने पूर्व उसे समाप्त करने का नोटिस दे सकता है। ऐसा नोटिस न दिए जाने पर सन्धि की अवधि स्वतः हर बार 5 साल के लिए बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यह सन्धि स्थायी रूप से चालू रह सकती है।

सन्धि पर हस्ताक्षर के तुरन्त बाद कुछ क्षेत्रों में आरोप लगाया गया कि भारत गुट-निरपेक्षता की नीति त्याग कर सोवियत संघ के हाथों का क्लिबाना बन सकता है, लेकिन ये सभी आशंकाएँ निर्मूल सिद्ध हुईं। दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध और वयला देश के उदय के समय यह भली प्रफार साबित हो गया कि भारत की स्वतन्त्र निर्णय शक्ति पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता।

रूस और भारत की मंत्री-सन्धि कोई सैनिक गुटबन्दी नहीं है। सन्धि में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि भारत पर आक्रमण सोवियत सघ पर आक्रमण माना जाएगा। सन्धि में केवल यह व्यवस्था है कि "दोनों में से किसी पर आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर दोनों पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाए और शान्ति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं।" इन शब्दों में सैनिक गुटबन्दी जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। इससे यहो प्रतीत होता है कि आक्रमण का खतरा होने पर आक्रमण के प्रतिहार का उपाय सोचा जाएगा। इसका अर्थ सैनिक सहायता भी हो सकता है पर मूल बात आक्रमण या आक्रमण की आशका समाप्त करने की है। यदि आक्रमण समाप्त हो जाता है तो शान्ति के लिए और चाहिए भी क्या। राजनीतिक क्षेत्रों में आशा प्रकट की गई कि इस ऐतिहासिक सन्धि से भारत और सोवियत सघ न केवल एशिया और विश्व में शान्ति की स्थापना तथा जातिवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति की दिशा में पहले से अधिक सहयोग कर सकेंगे बल्कि शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों के सम्बन्धों का विस्तार होगा। इस मंत्री-सन्धि को हुए छ वर्ष पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक ऐसा एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जो यह सिद्ध करे कि भारत सोवियत दबाव में काम कर रहा है या सन्धि से भारत की स्वतन्त्र-निराश्रित शक्ति को आघात पहुँचा है। यह सन्धि भारत पर इस सन्धि के कारण ही अमेरिका और चीन दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध में उत्तमने से दूर रहे और भविष्य में भी यह सन्धि भारत और सोवियत सघ दोनों देशों के लिए शत्रुओं से एक रक्षा-कवच का काम देगी। यह समानता पर आधारित मंत्री-सन्धि है जिसकी चौथी धारा में सोवियत सघ ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति का सम्मान करता है।

भारत-पाक युद्ध 1971 पर सोवियत प्रतिक्रिया—दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक-युद्ध में सोवियत सघ ने भारत को पूर्ण समर्थन दिया। सोवियत समाचार पत्रों में श्रीमती गाँधी के उस भाषण को प्रमुखता प्रदान की गई जिसमें उन्होंने पूर्वी बंगाल का सफट हल करने लिए वहाँ से पाकिस्तानी सेना की वापसी को आवश्यक बताया था। सुरक्षा परिषद् में सोवियत सघ ने अमेरिका के उस प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया जिसमें युद्धविराम और सेनाओं की वापस की माँग की गई थी। बदले में सोवियत सघ ने यह प्रस्ताव रखा कि पूर्वी बंगाल की समस्या का राजनीतिक समाधान निकाला जाए। वीटो के उपरान्त सोवियत सरकार ने सभी देशों से अनुरोध किया कि वे भारत-पाक सघर्ष से दूर रहे और ऐसे कदम न उठाएँ जिनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति और भी जटिल बन जाए। सघर्ष को सीमित रखने का यह सोवियत प्रयत्न भारत के हित में था। 6 दिसम्बर को सुरक्षा परिषद् की दूसरी बैठक में अमेरिका ने पुनः भारत-विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको चीन ने पूर्ण समर्थन दिया। सोवियत सघ ने पुनः वीटो का प्रयोग कर इसे

निरस्त कर दिया। भारत के पक्ष में सुरक्षा परिषद् में रूस को पुनः तीसरी बार भी वीटो का प्रयोग करना पड़ा। इस प्रकार रूसी समर्थन के कारण सुरक्षा परिषद् में पिण्डी-शेफिन-वार्शिंगटन चाल भारत का अहित नहीं कर सकी। युद्धकाल में भारत के धी धर ने मास्को जाकर और सोवियत उपविदेश मन्त्री श्री कुजनेटसोव ने भारत आकर विचार-विमर्श किया। सोवियत विदेश मन्त्री दिल्ली में तब तक ठहरे रहे जब तक युद्ध का अन्त नहीं हो गया। रूस ने श्री धर और कुजनेटसोव के माध्यम से भारत-सरकार को पूर्ण आश्वासन दिया कि हर दशा में भारत की पूर्ण सहायता की जाएगी और मंत्री-सन्धि के वचनों को निभाया जाएगा। जब अमेरिका का सातवाँ वेड़ा बगाल की साड़ी की ओर रवाना हुआ तो सोवियत युद्धपोत भी हिन्द-महासागर की ओर चल पड़े ताकि अमेरिका के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। सोवियत चुनौती के कारण अमेरिका भारत के विरुद्ध 'युद्धपोत राजनय' व्यवस्था हो गया। भारत की एक पक्षीय युद्ध-विराम घोषणा का भी सोवियत सरकार ने खुले दिल से स्वागत किया। इसे शान्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। सोवियत सघ ने एक लम्बे वक्तव्य में राष्ट्रो से अपील की कि वे स्थिति के सामान्यीकरण में योग दें। 18 दिसम्बर को अपने पत्रों में श्रीमती गांधी ने सकलकाल में दी गई सहायता के लिए रूस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

सहयोग का बढ़ता हुआ दायरा (1972-1974) — भारत-सोवियत मंत्री उत्तरोत्तर विकसित होती रही। बंगला देश की समस्याओं के समाधान में दोनों देशों ने मिल-जुलकर काम करने की नीति अपनायी। शिमला-समझौते को रूस ने अपना पूरा समर्थन दिया। अगस्त, 1972 में सुरक्षा परिषद् में संयुक्त-राष्ट्रसघ की सदस्यता के लिए जब बंगलादेश के प्रार्थनापत्र पर विचार हुआ तो भारत और रूस ने बंगलादेश को अपना पूर्ण समर्थन दिया। चीन के वीटो के कारण उस समय बंगलादेश को सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी। लगभग इसी समय एक भारत-सोवियत-संयुक्त आयोग स्थापित करने का निश्चय हुआ जो प्राथमिक क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और अधिक व्यवस्थित कर सके। 2 अक्तूबर, 1972 को दोनों देशों के बीच विज्ञान और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौता हुआ। यह समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अभी तक विशेष रूस से पश्चिमी देशों में ही वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा था।

दोनों देशों में सहयोग निरन्तर विकसित होता गया। 26 से 30 नवम्बर 1973 तक नई दिल्ली में ब्रेझ्नेव-इन्दिरा की ऐतिहासिक भेंट के बाद दो अल्पकाल में ही सम्बन्धों में काफी घनिष्ठता घा गई। लाल किले में आयोजित अभिनन्दन समारोह में श्री ब्रेझ्नेव ने कहा — "हमारी पारस्परिक मंत्री एक पर्वतारोहण की भांति है। हम जितने भी ऊपर चढ़ते जाते हैं, मंत्री की नई सम्भावनाएँ खुलती जाती हैं।" ब्रेझ्नेव के दिल्ली-प्रवास के समय ही 29 नवम्बर, 1973 को दोनों देशों के बीच तीन ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिनके द्वारा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने, दोनों देशों के योजना आयोगों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने तथा एक

दूसरे के सरकारी प्रतिनिधियों को विशेष सुविधाएँ सुलभ कराने की व्यवस्था की गई। सोवियत नेता की यात्रा के फलस्वरूप भारत में भिलाई और बोकारो इस्पात कारखानों के विस्तार, मयुरा में तेल-शोधक कारखाने की स्थापना तथा मध्यप्रदेश में ताँबा परियोजना के निर्माण में सोवियत सहयोग प्राप्त हुआ। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सोवियत सहायता से भारत में 80 औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाएँ चालू हो चुकी हैं या चालू की जा रही हैं। भारत के कुल इस्पात-उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत, खनिज तेल का 60 प्रतिशत, बिजली का 20 प्रतिशत और मशीनरी का 60 प्रतिशत उत्पादन सोवियत सहयोग से स्थापित उद्योगों से हो रहा है। सन् 1953 में भारत-सोवियत व्यापार केवल 13 करोड़ रु का था जो सन् 1973 में 430 करोड़ रु का हो गया। सन् 1974 में इसमें 35 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह आशा की गई है कि दोनों देशों का व्यापार सन् 1980 तक बढाकर दुगुना हो जाएगा। दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों में भी विकास हुआ है। स्वास्थ्य-सेवा और साहित्य के क्षेत्र में परस्पर सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। सोवियत संघ में भारतीय लेखकों की 700 से भी अधिक पुस्तकें 34 भाषाओं में करोड़ों की संख्या में प्रकाशित हुई हैं। अक्टूबर, 1974 में भारत-सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमण्डल वार्ता मास्को में हुई जिसमें सन् 1975 के लिए व्यापार समझौते पर विचार किया गया। सोवियत संघ से भारत मशीनरी उपकरण, ट्रैक्टर बिजली के साज-सामान का आयात करता है। भारत से ऊन, मसाले, जूते, काफ़ी तथा अन्य परम्परागत वस्तुएँ निर्यात की जाती हैं। तेल क्षेत्रों के विस्तार में सोवियत सहायता से भारत विश्व के तेल उत्पादक देशों में गिना जाने लगा है।

वर्ष 1975-76 में भारत-रूस सम्बन्ध

वर्ष 1975 के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता, विचार सम्बन्धी तथा परस्पर लाभकारी सहयोग के सम्बन्ध अधिक विरसित, विस्तृत तथा सुदृढ़ हुए। सोवियत संघ की मित्रता के दृढ़ विकास और सर्वोत्तम सहयोग के विषय में निरन्तर यह मान्यता रही कि उनसे दोनों देशों के मूल हित में समानता आती है और उनसे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की प्रक्रिया और गहरी होने में सुविधा मिलती है तथा एशिया और विश्व में शान्ति सुदृढ़ होती है। कई घोषणाओं में सोवियत नेताओं ने गुट-निरपेक्षता आन्दोलन के महत्त्वपूर्ण कार्यों की पुनः पुष्टि की और विश्व शान्ति तथा सहयोग में गुट-निरपेक्षता आन्दोलन के अग्रदान के महत्त्व को मान्यता दी। भारत ने हेल्सिंकी में यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग के शिखर-सम्मेलन के सकल समापन के लिए सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के महत्त्वपूर्ण योगदान का स्वागत किया और यह भाषा व्यक्त की कि तनाव की कमी की भावना को स्थायी रखना तथा प्रभावी बनाने के लिए उसे विश्व के सभी भागों में फैलाना होगा। मास्को में दोनों देशों के बीच नवम्बर, 1975 में विदेशी कार्यालयों के बीच नियमित वार्षिक द्विपक्षीय परामर्शों से पारस्परिक हित की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उच्च-

स्तरीय लाभकारी विचार-विमर्श का स्वागत-योग्य अवसर प्राप्त हुआ। अप्रैल, 1975 में सर्वोच्च सोवियत के प्रधान मण्डल के उपाध्यक्ष श्री नियाजवेकोव के नेतृत्व में एक सोवियत संसदीय मण्डल ने भारत की यात्रा की।

भारत-सोवियत रुपया मुग़तान-व्यापार के ढाँचे के अधीन वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से सन् 1973 के 20 लाख टन गेहूँ ऋण का मुग़तान स्वीकार करने की सोवियत सहमति एक महत्वपूर्ण घटना थी जो इस बात की सूचक है कि सोवियत संघ भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रुचि रखता है। पिछले वर्ष की तरह सोवियत संघ व्यापार योजना के अन्तर्गत भारत को प्रचुर मात्रा में गिट्टी का तेल, डीजल तेल, त्वाद और अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ बराबर देता रहा। सन् 1976-80 की अगली पाँच वर्ष की अवधि के लिए एक दीर्घकालीन व्यापार समझौता सम्बन्धी बातचीत के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्री श्री डी. पी. चट्टोपाध्याय नवम्बर, 1975 में मास्को गए।

भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, प्रार्यभट्ट सोवियत राकेट वाहक की सहायता से 19 अप्रैल, 1975 को सोवियत संघ से छोड़ा गया। सन् 1977-78 में सोवियत राकेट वाहक की सहायता से दूसरा भारतीय वैज्ञानिक उपग्रह छोड़ने संबंधी समझौते पर 22 अप्रैल, 1975 को हस्ताक्षर किए गए। कृत्रिम उपग्रह तथा अन्तरिक्ष खोज के पर्यवेक्षण के द्वारा एक अन्तरिक्ष अनुसन्धान सहयोगात्मक कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते पर नवम्बर, 1975 में कार्य शुरू किया गया। वर्ष 1975 में विज्ञान तथा औद्योगिकी क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग में भारी वृद्धि हुई। जनवरी, 1976 में दोनों देशों ने सन् 1976-77 वर्षों के लिए कृषि एवं जन्तु-विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने दिसम्बर, 1975 में बसनाला कौयला खान दुर्घटना में अत्यन्त मूल्यवान और तात्कालिक सहायता प्रदान की।

वर्ष 1976 में भी दोनों देशों के सम्बन्धों में उत्तरोत्तर सुधार होता गया। 15 अप्रैल, 1976 को दोनों देशों के बीच सन् 1976-80 की अवधि के लिए एक नए व्यापार-समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते की कई विशेषताएँ हैं—यथा (1) इसमें भारत से परम्परागत निर्यात वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्यात का मार्ग प्रशस्त हो गया है जिनका सम्बन्ध आधुनिक मशीन और उपकरण निर्माण से है। (2) जो व्यापार-योजना बनाई गई है उसमें इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि व्यापार के मूल्यों की गणना सन् 1975 के मूल्यों के आधार पर की जाए। इससे पूर्व मूल्य तत्कालीन मूल्य-स्तर पर प्रांकि जाते थे। यह अनुमान लगाया गया कि सन् 1980 के लिए व्यापार का मूल्य 4346 करोड़ रुपये होगा। (3) यह महत्वपूर्ण है कि इस व्यवस्था में कई ऐसी परियोजनाओं के व्यापारिक पक्ष का समावेश नहीं है जो औद्योगिक सहयोग और तीसरे देशों को उपलब्ध कराने के क्रम में विचाराधीन हैं। यह समझा जाता है कि जब ये परियोजनाएँ प्रारूप का रूप ग्रहण कर लेंगी तो इनको सन् 1980 के व्यापार आँकड़ों में शामिल किया जाएगा और

यह आशा है कि उस वर्ष कुल व्यापार एक हजार करोड़ रुपये का हो जाएगा। इसने भारत का निर्यात 600 करोड़ रुपये का होने की आशा है।¹

वर्ष 1977 में भारत-रूस सम्बन्ध—मार्च, 1977 में ऐतिहासिक चुनाव-क्रान्ति द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आयी। कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में यह आशका व्यक्त की गई कि नई सरकार समाजवादों देशों के साथ पहले की तरह सम्बन्धों का निर्वाह नहीं करेगी, किन्तु अग्रे, 1977 में मोवियन विदेश मन्त्री श्री ग्रामिन्को की भारत-यात्रा और नई सरकार के साथ उनकी वार्ता के फलस्वरूप इस प्रकार की आशकाएँ निमूल हो गईं। यात्रा की समाप्ति पर प्रसारित समुक्त विज्ञप्ति और दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित तीन मध्यम समझौतों ने स्पष्ट कर दिया कि जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से भारत-मोवियन मैत्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, इसके विपरीत यह अधिक समृद्ध हुई है। जो तीन समझौते दोनों देशों में हुए उनमें एक समझौता दोनों देशों के बीच सीधी संचार-व्यवस्था स्थापित करने के बारे में है। अब तक दोनों देशों का दूर संचार सम्बन्ध नन्दन द्वारा होता था, परन्तु अब श्रीनगर तथा ताम्बु के बीच टेलीफोन-रेखा से सीधा दूर संचार सम्बन्ध कायम किया जाएगा जिसमें 1.5 करोड़ रु. की वार्षिक खर्च भी होगी। एक समझौते के अन्तर्गत मोवियन में भारत को रहती वार 25 करोड़ रुबल (लगभग 225 करोड़ रु.) का उन्मुक्त नष्ट देगा जिसका औद्योगिक विकास के किसी भी क्षेत्र में उपयोग किया जा सकेगा। इस प्राधिक तत्त्वों की मुख्य समझौते में अब तक की जर्नी से अधिक उदार जर्नी रखी गई है। तीसरे समझौते में हम वर्ष (1977-78) में 160 करोड़ रु. के अनिश्चित व्यापार की व्यवस्था है जिसमें दोनों देशों का वार्षिक व्यापार 780 करोड़ रु. से बढ़ कर 960 करोड़ रु. हो जाएगा। श्री ग्रामिन्को भारत-यात्रा से पूर्ण मन्तुष्ट होकर स्वदेश लौट। जैसा कि श्री वाशिंग्टन ने कहा है, 'निकट महयोग और सम्बन्धों की मजदूरी के लिए यह जरूरी है कि पारस्परिक भ्रान्तियाँ स्पष्ट वार्ता द्वारा दूर कर ली जाएँ।' इस वार्ता में भी निश्चय ही इस विधि का प्रयोग किया गया।

21 अक्टूबर, 1977 को प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने अपनी रुम-यात्रा के समय मास्को में राजि-भण्ड के अवसर पर बोलत हुए जो कुछ कहा वह भारत-रूस मैत्री के प्रति नई सरकार के दृष्टिकोण का परिचायक था। श्री देसाई ने वक्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण अंश ये थे—

"वर्ष 1977 हम दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। मोवियन सब शीघ्र ही अक्टूबर क्रांति की 60वीं वर्षगांठ मनाएगा जो कि आपके देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा यह विश्व के लिए भी एक प्रेरणादायक घटना रही है। भारत के लिए भी वर्ष 1977 एक ऐतिहासिक वर्ष है। इन वर्ष

1. रिमाल, 25 अप्रैल, 1976, पृष्ठ 19-20.

2. भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति, 21 अक्टूबर, 1977.

भारत में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। तीस वर्षों से जो दल सत्ताह्द था उसे सांविधानिक ढंग से अस्थायी कर दिया गया और अब एक नए दल पर यह भार सौंपा गया है। यह भी एक प्रकार की क्रान्ति है, किन्तु यह क्रान्ति गुप्त मतदान द्वारा लायी गई। इस परिवर्तन का विश्व भर में स्वागत किया गया है। इसने यह खान सिद्ध कर दी कि हमारे देश की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना महत्व देती है।

“दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को दृढ़ बनाने की हमारी परस्पर इच्छा समानता पर आधारित है न कि विचारधाराओं पर। दोनों देशों के बीच सम्बन्ध राष्ट्रीय हितों और समान उद्देश्यों पर भी आधारित हैं। हम दोनों ही राष्ट्र इस बात को मानते हैं कि हम विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिरता एवं सहयोग के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू की सन् 1955 में सोवियत संघ की अपनी प्रथम यात्रा के समय दोनों देशों ने सह-प्रसिद्धि और सहयोग के सिद्धान्तों पर अपनी सहमति की पुष्टि की थी। उस समय कई देशों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्या ऐसे दो राष्ट्र-जिनमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणाली की भिन्नता है प्रतिष्ठा, समानता और परस्पर विश्वास के आधार पर सम्बन्धों का विकास कर सकते हैं। आज के समय में इन सम्बन्धों को कायम रखना दो स्वानिमानी राष्ट्रों की परिपक्वता का उदाहरण है।

“17 वर्ष पूर्व मेरी यात्रा के समय से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। शीतयुद्ध लगभग समाप्त हो गया है और विश्व में शान्ति के लिए आशा के नए आसार बन गए हैं। यूरोप में, जो शताब्दियों से भयंकर विवादों का क्षेत्र रहा है, 32 वर्ष निरन्तर शान्ति के व्यतीत किए हैं।

“यूरोप में उपशमन और तनाव शैथिल्य वास्तविक रूप से सुरक्षित नहीं रह सकते जब तक यह भावना विश्व के अन्य भागों में भी नहीं फैलती। एशिया में हम लोगों ने शताब्दियों तक औपनिवेशिक शोषण सहा है और हमें आधुनिकीकरण तथा तकनीकी प्रगतियों के फलों से वंचित किया गया। हमारे लिए शान्ति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शान्ति और सहयोग के बिना हम कोई प्रगति या विकास नहीं कर सकते। आपको ज्ञात है कि शान्ति, विकास और सहयोग के प्रति बचनबद्धता के कारण ही हम अपनी स्वतन्त्रता के आरम्भ से ही गुट-निरपेक्षता को अपनी विदेश-नीति के आधार के रूप में अपनाए हुए हैं। हाल के अपने चुनावों के समय अनेकों विवादास्पद विषय थे परन्तु विदेश-नीति और गुट-निरपेक्षता का सिद्धान्त जो इस नीति का अनिवार्य अंग रहा है, कभी भी विवाद का विषय नहीं बना। यह एक ऐसी नीति है जो समानता और पारस्परिक हित के आधार पर हमें भिन्नता को पुष्पित करने की स्वतन्त्रता देती है।

“भारत-सोवियत सम्बन्ध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और यह किसी भी प्रकार गुट-निरपेक्षता की हमारी नीति से हमें विचलित नहीं करते। विश्व के

ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ पुराने तनाव और नए विवाद शान्ति और स्थायित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। पश्चिमी एशिया में एक दीर्घकालीन विवाद अभी भी उत्पन्न रहा है और किलिस्नीन के अरब लोगों को उनके देश के अधिकार से वंचित किए हुए हैं, किसी भी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के किसी भाग पर वकूफ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रक्रिया में नाबिबिया, जिम्बाबवे और दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा एक राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष चलाया जा रहा है। हम आज एक विश्व में रहने हैं और उस विश्व में कहीं भी स्वतन्त्रता का दमन सभी के लिए खतरा है। इसलिए यदि दक्षिण अफ्रीका में लोगों की राष्ट्रीय मुक्ति प्रपूर्णा रही है तो विश्व में अन्य सभी स्थानों पर लोगों की स्वतन्त्रता को सुनिश्चिन् नही कहा जा सकता।

“हम सभी प्रकार के जातीय भेदभाव की, चाहे वह कहीं भी किए जा रहे हों, निन्दा करते हैं और इसके विरुद्ध सघर्ष का समर्थन करते हैं। हम सोवियत सघ और अन्य प्रबुद्ध राष्ट्रों द्वारा परमाणु युद्ध के खतरे पर व्यक्त चिन्ता में शामिल हैं। यह अपने आप में हमारे ग्रह के लिए खतरा है। अनेकों वैज्ञानिक आविष्कारों के समान प्राणविक ऊर्जा के भी रचनात्मक और विनाशकारी पहलू हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इससे शान्ति की विजय को सुनिश्चिन् करें, न कि युद्ध की विनाशकारी जय। आज युद्ध हमारे ग्रह पर सम्पूर्ण जीवन को समाप्त कर सकता है। शान्तिपूर्ण उद्देश्यों में प्रयुक्त प्राणविक ऊर्जा मानव जाति के लिए प्रगति और लाभ के अनेकों द्वार खोल सकती है। इस खतरे को सामने रखते हुए भारत की स्थिति स्वदेश में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नीति की घोषणाओं में स्पष्ट की गई है। य. मंग और भारत के लोगों का दृढ़ विश्वास है कि विश्व को चाहिए कि सैनिक उद्देश्यों के लिए अणु का प्रयोग पूर्णतः समाप्त कर दे। यह सब सभी सम्भव हो सकता है जब हम वर्तमान परमाणु शस्त्रों का पूर्ण निरस्त्रीकरण करें। इसी विश्वास के साथ मैंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि भारत शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करेगा। मुझे आशा है कि जिन देशों ने परमाणु शस्त्र कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, सम्भावित अनर्थ को टालने में सहयोग देंगे।

“भारत-सोवियत सम्बन्धों की सन्धि दोनों देशों के बीच पारस्परिक सम्मान पर आधारित है।”

भारत-सोवियत समुक्त घोषणा-पत्र में जिस पर 26 अक्टूबर, 1977 को मास्को में हस्ताक्षर किए गए, पारस्परिक संधी और सहयोग को मजबूत बनाने का दृढ़ संकल्प किया गया। विश्व में दोनों के नागरिकों के हितों को प्रतिबिम्बित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द और सद्भाव की स्थापना की बात भी कही गई। समुक्त घोषणा-पत्र में हिन्द महासागर के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र की जनता की हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखने की इच्छा के प्रति समर्थन व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने हिन्द महासागर से सभी वर्तमान सैनिक अड्डों को समाप्त करने तथा नए अड्डों की स्थापना पर प्रतिक्रिया लपाने का प्रावधान किया। समुक्त

घोषणा-पत्र में दोनों देशों के बीच सन् 1971 की शान्ति, मैत्री और सहयोग सन्धि का उल्लेख करते हुए उसे सम्बन्धों के सन्तोषजनक विकास की प्रेरक शक्ति बताया गया। विज्ञप्ति में कहा गया कि दोनों पक्ष मुम्भावजे के आधार पर भारत में एक एश्युमीना परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में शीघ्र ही सहयोग की सम्भावनाओं पर विचार करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं के अध्ययन और उन्हें परिभाषित करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञों के दलों का गठन किया जाएगा। ये क्षेत्र हैं—लोह और प्रलोह धातु-विज्ञान, पेट्रोलियम, कोयला, कृषि तथा सिंचाई। साथ ही यह दस तृतीय विश्व के देशों के आर्थिक विकास के लिए आपसी सहयोग के सम्बन्ध में भी सुझाव देंगे। यह पहली बार है कि इस प्रकार के किसी समुक्त घोषणा-पत्र में एक विकास परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इससे प्रतिबद्धता का स्तर ऊँचा हुआ और इस भावना का पता चला है कि दोनों पक्ष पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए कितने व्यग्र हैं। विज्ञप्ति में व्यक्तिगत सम्पर्कों को सर्वोच्च स्तर तक पहुँचाने की सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। यह वह बात है जिस पर विचार-विमर्श में जोर दिया गया और प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख किया। ग्यारह पृष्ठों के अग्रेजी के इस दस्तावेज में कहा गया है कि भारत-सोवियत सम्बन्ध तत्कालिक हितों की दृष्टि से नहीं, बरन् एशिया और विश्व में शान्ति और स्थायित्व कायम रखने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। शिखर-वार्ता के दौरान जिन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं तथा पारस्परिक मामलों पर विचार-विमर्श हुआ उनकी दस्तावेज में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। दोनों पक्षों ने दक्षिण एशियाई देशों द्वारा पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने तथा मतभेदों को दूर करने में प्राप्ति सफलताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे उप महाद्वीप में अच्छे पड़ोसियों के अनुकूल वातावरण में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। समुक्त घोषणा-पत्र में एशिया में तनाव कम करने के बारे में सोवियत विचार से उत्पन्न एशियाई स्थायित्व की कल्पना की जगह का त्यों स्थान दिया गया। कहा गया कि दोनों ही पक्ष यह मानते हैं कि एशिया में शान्ति और स्थायित्व के लिए विभिन्न एशियाई देशों के बीच परस्पर हितकारी सहयोग का विकास किया जाना चाहिए।

भारत-सोवियत मैत्री गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण मह-अस्तित्व की नीति की विजय है। सोवियत रूस एक साम्यवादी राष्ट्र है किन्तु उसके साथ जिस तरह भारत ने अगने सम्बन्धों का विकास किया है वह भारतीय विदेश-नीति की एक महत्त्वपूर्ण सफलता है।

भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध

राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत और ब्रिटेन के सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। जनवरी, 1950 में स्वयं को गणराज्य घोषित करने के बाद भी भारत ने राष्ट्र-मण्डल से सम्बन्ध कायम रखने का निष्पक्ष किया और आज भी वह राष्ट्रमण्डल का एक महत्त्वपूर्ण सदस्य है। राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत की सम्प्रभुता पर किसी

तरह की धाँच नहीं आती। ब्रिटेन ने भारत की विकास-योजनाओं में समय-समय पर आर्थिक सहायता भी दी है। सन् 1962 में चीनी आक्रमण के समय ब्रिटेन द्वारा भारत को सैनिक सहायता भी प्रदान की गई थी और भारत-चीन विवाद में ब्रिटेन का रुख भारत के पक्ष में ही रहा था।

इस सहयोग के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ब्रिटेन की नीति भारत के प्रति अन्ध्यासपूर्ण और अमर्त्यपूर्ण रही है। कश्मीर के प्रश्न पर ब्रिटेन और उसके साथी राष्ट्रों का रुँपा भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। इस बात की चर्चा कश्मीर-प्रश्न के सन्दर्भ में विस्तार से की गई है। ब्रिटेन ने भारत के विरुद्ध सदा पाकिस्तान का समर्थन किया है। सन् 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के प्रश्न पर युद्ध छिड़ा, तब भी ब्रिटिश प्रेस, रेडियो और सरकार ने भारत के विरुद्ध प्रचार किया और खुले आम भारत-विरोधी नीति अपनायी। जब 1 सितम्बर, 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तब तो ब्रिटेन का रुँपा भारत के प्रति सहायुभूतिपूर्ण रहा, किन्तु जब भारत ने प्रत्याक्रमण किया तो ब्रिटिश प्रधानमन्त्री विल्सन ने उसे 'आक्रमण' की सजा दी। ब्रिटिश सरकार का रुँपा एकदम पक्षपातपूर्ण था और तभी से ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों में खिचाव आ गया है।

भारत-ब्रिटेन सम्बन्धों के इतिहास में सन् 1965 का वर्ष सनभौता भी महत्वपूर्ण है। जब कच्छ के रण के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद छिड़ गया और दोनों देशों में सैनिक मुठभेड़ भी हो गई तब ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री विन्सन के प्रयासों के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच जुलाई, 1965 में सनभौता हुआ।

पाकिस्तानी आक्रमण के समय ब्रिटेन के पाकिस्तान-समर्थक रुख के कारण दोनों देशों में जो कटुता पैदा हुई, उसमें एक रूप्या केन्सा के प्रवासी भारतीयों के प्रश्न का और जुड़ गया। पूर्वी अफ्रीका से भारत का सम्बन्ध बहुत पुराना है और सन् 1867 से ही भारतीय केन्सा जाते रहे थे। सन् 1963 में जब केन्सा स्वतन्त्र हुआ तब वहाँ भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 25 हजार थी। केन्सा की स्वतन्त्रता के समय भारतीयों के समक्ष उनकी नागरिकता से सम्बन्धित विकट समस्या खड़ी हो गई। उस समय भारत सरकार ने लगभग 4 हजार भारतीयों को अपना पारपत्र दिया, शेष भारतीय ब्रिटिश पारपत्र पर केन्सा में रहने लगे। किन्तु इस स्थिति में फरवरी, 1968 में खतरनाक विगाह आया जब कि केन्सा सरकार ने यह निश्चय किया कि उन एशियायी लोगों के साथ, जो वहाँ के नागरिक नहीं हैं, केन्सा में गैर-नागरिक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इस निश्चय का स्पष्ट अर्थ यह था कि केन्सा निवासी भारतीय जीवनयापन के साधनों से वंचित हो जाएँ।

केन्सा-सरकार के निर्णय से प्रवासी भारतीयों में बड़ी चिन्ता व्याप्त हो गई। सन् 1963 में केन्सा की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय अविज्ञान प्रवासी भारतीय ब्रिटिश पारपत्र प्राप्त कर ब्रिटिश नागरिक बन गए थे, अतः यह आशा थी कि ब्रिटेन उनके

प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा। किन्तु जब वे अमरुक्षा की अवस्था में ब्रिटेन जाने लगे तो ब्रिटिश सरकार ने ससद् में एक विधेयक पेश कर दिया जिसका उद्देश्य 1 मार्च, 1968 के बाद केन्याई भारतीयों के ब्रिटेन में प्रवेश को रोकना था। ब्रिटिश ससद् द्वारा इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया और इस तरह नए कानून के अनुसार उस पारपत्र का कोई मूल्य नहीं रहा जो ब्रिटेन ने केन्या के प्रवासी-भारतीयों को दिया था। ब्रिटिश सरकार का यह कदम अन्धधृष्टपूर्ण और अमानवीय था जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। भारत में यह मांग की गई कि भारत राष्ट्रमण्डल का परिस्थान कर दे और भारत में जो ब्रिटिश-सम्पत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यद्यपि भारत-सरकार ने इस मांग को अव्यावहारिक बताया, किन्तु ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट शब्दों में जता दिया कि एशियावासियों को ब्रिटेन में प्रवेश से रोकने वाले अधिनियम का ब्रिटिश-भारत सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सौभाग्य की बात थी कि इस समस्या से कोई व्यापक प्रतिकूल प्रतिनिध्या नहीं हुई।

सन् 1970 में बी. बी. सी. टेलीविजन फिल्मों में भारतीय जन-जीवन को विकृत रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रश्न पर भी भारत-ब्रिटेन सम्बन्धों में तनाव आया। भारत-सरकार ने एक आदेश द्वारा सितम्बर, 1970 में भारत में बी. बी. सी. को उपलब्ध सभी सुविधाएँ समाप्त कर दी और दिल्ली स्थित बी. बी. सी. के सञ्चालन को विष्कासित कर दिया। सन् 1971 में बंगलादेश के प्रश्न पर दोनों देशों में गलत-फहमी फैली। इसका निवारण तब हुआ जब भारत-पाक युद्ध छिड़ने पर सुरक्षा परिषद् ने ब्रिटेन ने भारत-विरोधी प्रस्तावों पर मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने इसे मंथीपूर्ण व्यवहार मानते हुए बी. बी. सी. को पुनः भारत में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सहयोग के नए युग का सूत्रपात हुआ। जनवरी, 1971 में ब्रिटिश विदेश मन्त्री डगलस ह्यूम ने भारत-यात्रा के अवसर पर कहा—“भारत अब एशिया में एक महान् शक्ति के रूप में उभरा है, यदि चीन से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर तो निश्चय ही है।” ब्रिटिश विदेश मन्त्री का यह कथन भारत के प्रति ब्रिटेन के बदलते हुए दृष्टिकोण का पूर्वाभास था। सन् 1974 के मध्यान्तर चुनावों में लेबर पार्टी विजय प्राप्त कर सत्तास्थ हुई। अम-दलीय सरकार का रवैया अनुदार दलीय सरकार की तुलना में भारत के प्रति अधिक मंथीपूर्ण है। अप्रैल मई, 1975 में बिस्मटन (जर्मका) में राष्ट्र-गणदलीय सम्मेलन में रोडेशिया के अन्धधृष्ट प्रशासन को जो अस्टीमेटम दिया गया वह अप्रत्यक्ष रूप में ब्रिटेन पर भी इस बात के लिए दबाव था कि वह रोडेशिया के विरुद्ध कठोर कदम उठाए। दोनों देशों के बीच वार्षिक द्वि-पक्षीय वार्ता हुई जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सामान्य समीक्षा करने के अलावा व्यावहारिक सहायता तथा वार्षिक, वार्षिक एवं तकनीकी सहयोग जैसे द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत हुई। सन् 1975 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत जैसे देशों को दी जाने वाली सभी ब्रिटिश सहायता, जिनकी प्रति व्यक्ति माय 200 अमेरिकी डॉलर वार्षिक से

कम है, भविष्य में ऋणों के बजाय सीधे अनुदानों के रूप में होगी। सन् 1975-76 के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग 10 करोड़ पौंड की सहायता का वचन दिया जिससे ब्रिटेन भारत को द्विपक्षीय ऋण देने वाले देशों की सूची में सर्वोपरि हों गया। सन् 1975-76 में ब्रिटिश संसद के कई सदस्य सरकारी निमन्त्रण पर भारत आए। भारत-ब्रिटेन वार्षिक सहयोग एवं व्यापार समुक्त समिति के गठन के लिए दोनों देशों के बीच जनवरी, 1976 में विनिमय पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्रिटिश उद्योग सब के उपाध्यक्ष सर रात्क वेटमैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय ब्रिटिश औद्योगिक मिश्रण ने अक्टूबर, 1976 में भारत की यात्रा की। इसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच अधिकारिक व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग तथा तीसरे देशों में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना था। व्यापार और वार्षिक सहयोग के लिए भारत-ब्रिटिश समुक्त समिति की मन्त्रि-स्तरीय बैठक लंदन में हुई। सन् 1976-77 में भारत को मिलने वाली ब्रिटिश विकास सहायता 1120 लाख पौंड (लगभग 170 करोड़ रुपये) थी। यह राशि किसी भी अन्य देश से प्राप्त सबसे बड़ी रकम थी। यह सहायता पूर्णतया अनुदान रूप में दी गई थी।

भारत और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका

पश्चिमी एशिया के संदर्भ में भारत की विदेश-नीति का अध्ययन महत्वपूर्ण है। अरब-इजरायल युद्धों में भारत ने गर्व अरब राज्यों का पक्ष लिया है। भारत की सहायुक्ति और मैत्री अरब देशों के प्रति बहुत अधिक रहने में इजरायल को भारत ने सभी तक कूटनीतिक मान्यता नहीं दी है। अरब-देशों के प्रति भारत की नीति को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उपयोगी माना गया है। अरब-राष्ट्रों से प्राप्त होने वाले तेल में कोई भी बड़ी बाधा भारत के सम्पूर्ण वार्षिक ढांचे की हिला सक्ती है। स्वेज नहर भारत के विदेशी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके प्रतिरिक्त इजरायल के विरुद्ध अरबों के दावे अधिक न्यायोचित हैं। फिर भी भारत का दृष्टिकोण संतुलित रहा है क्योंकि जहाँ भारत ने अरबों के दावों का समर्थन किया है, वहाँ इजरायल के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। भारत का मन रहा है कि अरब राष्ट्रों को इजरायल का अस्तित्व स्वीकार कर उसे एक सम्पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देनी ही चाहिए।

भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट सन् 1976-77 के अनुसार

“भारत पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्धों और सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने को अधिक महत्व देता रहा। उनकी अर्थव्यवस्थाओं के अनुपूरकों और विकास की आवश्यकताओं के आधार पर स्थापित भारत के इन देशों के साथ वाणिज्यिक, वार्षिक और तकनीकी सहयोग में बहुत विस्तार हुआ। उच्च स्तर की योजनाओं के अधिक प्रादान-प्रदान और अन्य स्तरों पर बातचीत से भारत और पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका देशों के बीच परम्परागत सम्बन्धों और महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विवादों पर विचारों की मनिष्ठ समानता को फिर दोहराया गया।”

“सन् 1967 में अधिकृत सभी अरब क्षेत्रों से इजरायलियों की वापसी और फिलिस्तीनियों के वैध अधिकारों तथा आर्काइवाओं की उपलब्धि पर आधारित अरब-इजरायली समस्या का न्यायोचित समाधान ढूँढ़ने के अरब राज्यों के प्रयत्नों का भारत सरकार पूर्ण समर्थन करती रही। लेबनान में दुःखद मंत्रीघातक लड़ाई की पूर्णतः समाप्ति की सम्भावना पर भारत को मुक्ति मिली जिसका प्रभाव उस क्षेत्र पर इस वर्ष की अधिकांश अवधि के लिए रहा। कच्चा तेल और उर्वरकों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि के कारण समस्याओं का सामना करने वाले भारत जैसे मित्र देश के प्रति तेल निर्यात करने वाले देशों द्वारा प्रदर्शित सहानुभूति से भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवृद्धि के प्रभावों को कम करने में कुछ हद तक सहायता मिली। भारत की आशा है कि यह सहानुभूति निरन्तर कायम रहेगी। पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका में भारतीय मिशनों के 21 प्रमुखों का एक सम्मेलन जनवरी, 1977 में नई दिल्ली में हुआ। इस सम्मेलन में भारत के लिए इस क्षेत्र के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया। इस बात पर भी बल दिया गया कि भारत और इन देशों के बीच गहले से विद्यमान सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्धों को और अधिक बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए।”

“लेबनान में हिंसा और रक्तपात और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए किए गए निरन्तर प्रयत्नों की असफलता भारत सरकार के लिए अधिक चिन्ता का विषय था। बेहतर में भारतीय मिशन के कार्मिकों को अनेच्छा से वापस बुला लिया गया। जब वहाँ उनकी सुरक्षा व्यवस्था कठिन हो गई तो बेहतर में रहने वाले बहुत से अन्य भारतीयों ने भी बेहतर छोड़ दिया। जब रियाद और काहिरा शिखर-सम्मेलनों में अरब राजनेता अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता से युद्ध और रक्तपात को कम करने के एक समझौते पर पहुँच सके, तो भारत सरकार को सन्तोष हुआ। भारत सरकार की यह आशा थी कि लेबनान में सामान्य राजनीति और आर्थिक जीवन तेजी से पुनः चालू हो जाएगा और इसकी प्रमुखता, अखण्डता एवं गुट-निरपेक्षता सुरक्षित हो जाएगी। भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण और जन-सेवाओं और उपयोगिताओं को फिर से चालू करने में सभी सम्भव सहयोग और सहायता प्रदान करने की अपनी उत्तरदायित्व प्रदर्शित की।”

“भारत सरकार ने सीरिया और मिस्र के बीच समन्वय का स्वागत किया जिसे इसने अरब राज्यों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु सयुक्त प्रयत्नों के लिए आवश्यक समझा। मध्यपूर्व के बारे में जिनेवा सम्मेलन को पुनः आयोजित करने सम्बन्धी विवरणों में सतर्क आशावाद के लिए एक उद्देश्य की व्यवस्था थी। भारत सरकार का यह मत था कि सम्मेलन को सार्थक बनाने के लिए सभी सम्बद्ध दलों के, जिसमें फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन शामिल है, कारगर तरीके से भाग लेने की आवश्यकता होगी।”

“इजरायल द्वारा अपने अधिकार में किए गए क्षेत्रों में अरब जनता के साथ व्यवहार चिन्ता का विषय था। भारत को यह विश्वास था कि फिलिस्तीनियों को

उनके बीच राष्ट्रीय अधिकारों की वापसी अरब-इजरायली समझौते के लिए महत्वपूर्ण थी। दक्षिण लेबनान में इजरायल के आक्रमणों और क्षेत्रों पर कब्जे से इजरायली नेताओं के वक्तव्यों की विश्वसनीयता कम हो गई जिसमें उन्होंने शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भारत के इस क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध यात्राओं के आदान प्रदान, यातचीत तथा द्विपक्षीय समझौतों द्वारा हल हुए।”

“भारत और ईरान के बीच बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों की सन् 1976-77 में प्रशस्तनीय प्रगति होती रही। तबभग सभी परियोजनाएँ, जिनमें दोनों देश कार्य कर रहे हैं, अपने आप में केवल यात्रा की दृष्टि से ही प्रभावकारी नहीं हैं, बल्कि उनका दोनों देशों की विकासशील प्रबंधनस्थापनों की दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व है। उनमें से एक को चुन लेना आपत्तिजनक होगा, परन्तु कुद्रेमुख परियोजना, जो प्रति उत्तम ढंग से प्रारम्भ हो चुकी है, विशेष उल्लेखनीय है।”

भारत और अफ्रीका (सहारा के दक्षिणी देश)

भारत के अफ्रीका (सहारा के दक्षिणी देश) के देशों के साथ सम्बन्ध महत्वपूर्ण होते आ रहे हैं। इन सम्बन्धों के हाल ही के विकास पर भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय की सन् 1976-77 की वार्षिक रिपोर्ट में जो प्रकाश डाला गया है वह पठनीय है—

“भारत के अफ्रीका (सहारा के दक्षिणी देश) के देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने तथा उनके साथ सहयोग बढ़ाने के लिए सम्पर्क स्थापित किए गए। इन दोनों देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करने तथा प्रमुख नेताओं के एक दूसरे के देश में आवागमन से सम्पर्क में वृद्धि हुई। इनसे दक्षिण अफ्रीका के विकास कार्यक्रम में भारत ने रुचि दिखाई तथा उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद के विषय में भारत ने विरोध प्रकट किया और गोरों के साम्राज्य को समाप्त करने में अफ्रीका के स्वतन्त्रता आन्दोलन को समर्थन दिया।”

“पूर्वी अफ्रीका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विभिन्न स्तरों पर यात्राओं के विनिमय में प्रतिबिम्बित हुए। केनिया के विदेशमन्त्री श्री एफ. एम. वईयाकी ने अगस्त, 1976 में भारत की यात्रा की और विदेशमन्त्री के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर तथा भारत और केनिया के बीच सम्बन्धों को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। भारतीय नौसेना के दो जहाज सद्भावना यात्रा पर केनिया गए। उगांडा सरकार द्वारा भारत को 1,44,88,792-60 रु की राशि दे देने से सन् 1972 में उगांडा से निष्कासित भारतीय राष्ट्रिकों को मुआवजा देने की समस्या का सफलतापूर्वक समाधान हो गया। उगांडा सरकार से प्राप्त इस राशि का एक बड़ा भाग उचित जीव पड़ताल करने के बाद सम्बद्ध दावेदारों में बाँट दिया गया। यह जीव पड़ताल उगांडा मुआवजा भुगतान कार्यालय द्वारा की गई जिससे इस उद्देश्य के लिए धम्बई में स्थापित किया गया था। उगांडा के उद्योग तथा ऊर्जा और परिवहन तथा संचार-मन्त्रियों की भारत-यात्रा से भारत तथा उगांडा के बीच वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग की वृद्धि में सहायता मिली।”

“अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सम्बन्धों के विकास के सम्दर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत की प्रधानमंत्री द्वारा मारीशस (8-11 अक्तूबर), तंजानिया (11-14 अक्तूबर), जाम्बिया (15-17 अक्तूबर) और शेसेल्स (17 अक्तूबर) की यात्राएँ थीं। मारीशस के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध तभी प्रकट हो गए थे जब भारत ने स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डॉ. कर्णसिंह के नेतृत्व में 30 व्यक्तियों का एक राजकीय प्रतिनिधिमण्डल मारीशस में सम्पन्न द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मारीशस भेजा था। दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध और भी स्पष्ट हो गए जब भारत की प्रधानमंत्री ने अपनी मारीशस यात्रा के समय गाँधी इन्स्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इससे पूर्व मारीशस के स्वतन्त्रता समारोह के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इस्पात एवं खान मंत्री की यात्राओं में भारत और मारीशस के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध प्रतिबिम्बित हुए।”

“अक्तूबर में प्रधानमंत्री की तंजानिया यात्रा से पहले दोनों देशों के उच्च पदाधिकारी अनेकों बार एक दूसरे के देश में आए गए। अप्रैल, 1976 में भारत और तंजानिया ने तंजानिया में कई लघु-उद्योग परियोजनाएँ स्थापित करने सहयोग देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री की जाम्बिया यात्रा ने एक ऐसे मित्र देश के साथ हो रही वार्तालाप में, जिसके साथ भारत ने रचनात्मक सहयोग की परम्परा स्थापित की थी, एक और कड़ी जोड़ दी। उनकी यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि वे एक-दूसरे की सहायता करेंगे जिनमें वे अपने सम्बन्धों का विस्तार कर सकते हैं।”

“प्रधानमंत्री की यात्रा के समय उल्लेखनीय बात यह देखने में आयी कि प्रधानमंत्री तथा मारीशस, तंजानिया तथा जाम्बिया के नेताओं ने दक्षिणी अफ्रीका के विकास कार्यक्रमों में समान रूप से रुचि प्रदर्शित की। इस यात्रा से दक्षिण अफ्रीका के दलित लोगों के न्यायपूर्ण सघर्ष के प्रति उन देशों के समुक्त समर्थन के लिए भारत ने सहानुभूति दिखायी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अफ्रीका के मुक्ति आन्दोलन के नेताओं से मिली और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि उनके सघर्ष में भारत उनका पूरा साथ देगा। भारत तथा इन देशों ने इस बात का पुनः समर्थन किया कि नामिबिया के लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है तथा उन्होंने उन्हें सवापो के नेतृत्व में उनके वीरतापूर्ण सघर्ष में नैतिक तथा आर्थिक सहयोग देने का वचन दिया। जहाँ तक जिम्बावे का प्रश्न है, भारत और इन देशों की प्रतीति हुआ कि सितम्बर, 1976 में रोडेशिया के जातिवादी शासन की इस घोषणा से कि दो वर्ष की अवधि में देश में बहुमत शासन की स्थापना कर दी जाएगी, स्थिति अनुकूल हो गई है। भारत ने जेनेवा में सांविधानिक सम्मेलन के आयोजन का स्वागत किया और घोषणा व्यक्त की कि इससे जिम्बावे में तुरन्त बहुमत का शासन स्थापित हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने घागे इस बात को भी स्पष्ट किया कि यदि सांविधानिक सम्मेलन असफल रहा तो भारत सरकार जाम्बिया की स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष में अपना पूर्ण सहयोग देगी।”

“प्रधानमन्त्री की शेरसेस की तृतीय यात्रा से भारत की इस द्वीप के साथ मैत्री को दृढ़ करने की इच्छा प्रदर्शित हुई। भारत के शेरसेस के साथ पहले ही मैत्रीपूर्ण सम्पर्क स्थापित हो चुके थे जब 29 जून को उस द्वीप की स्वतन्त्रता के अवसर पर राज्य पर्यटन एवं सिविल विमान मन्त्री श्री सुरेंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल बर्मा गया था। शेरसेस की स्वतन्त्रता के अवसर पर हुए समारोह में दस सदस्यों के एक सांस्कृतिक दल और 3 भारतीय जहाजों के एक बड़े ने भी भाग लिया था। शेरसेस के प्रधानमन्त्री थी एफ. ए. रीनीज सितम्बर में भारत की यात्रा पर आए और भारत तथा शेरसेस के बीच सम्बन्धों के और विकास करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन का पूर्णरूप से बहिष्कार करती रही और अपने जातिवाद की घातक नीति की भर्त्सना की। भारत सरकार ने, दक्षिण अफ्रीकी सरकार की सोवेटो नगर क्षेत्र के उन स्कूली बच्चों के विरुद्ध क्रूर कार्रवाई करने की निन्दा की जिन्होंने स्कूलों में अफ्रीकी भाषा जबरदस्ती पढ़ाई जाने का विरोध किया था।”

“दक्षिण अफ्रीका में भारत की रुचि, भोजाम्बिक के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने तथा लीसाको और बोतस्वाना के साथ निरपेक्ष सम्पर्क स्थापित करने में प्रदर्शित हुई। श्री श्री विपिनपाल दास ने अक्टूबर में अपनी भोजाम्बिक यात्रा के समय भोजों के भी अपनी नव-प्रतिष्ठित स्वतन्त्रता को सुदृढ़ करने में सहायता देने की भारत साथ सहयोग इच्छा व्यक्त की। उनकी यात्रा के दौरान तकनीकी, आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए। भारत से कुछ आवश्यक सामान खरीदने के लिए भारत सरकार ने इसे राष्ट्रमण्डल की संयुक्त सहायता प्रणाली के रूप में 9,00,000 रु. का अनुदान देने का वचन दिया। इससे भोजाम्बिक को उम अतिरिक्त में सहायता मिलेगी जो इसे संयुक्तराष्ट्र के निश्चय के जवाब में रोडेजिया के साथ सीमावन्दी से होगी। लीसाको के विदेशमन्त्री श्री सी डी. मोसापो ने अगस्त में भारत की यात्रा की और उनकी यात्रा के समय भारत और लीसाको के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर भारत के उपविदेशमन्त्री की उम देश की यात्रा के समय हस्ताक्षर किए गए। वह उसकी स्वतन्त्रता के 10वें वार्षिक समारोह के अवसर पर बर्मा गए थे। अप्रैल, 1976 में बोतस्वाना के राष्ट्रपति तथा विदेशमन्त्री की भारत यात्रा से बोतस्वाना के साथ भारत के बढ़ते हुए सम्पर्क उजागर हुए। भारत और बोतस्वाना आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में अपने सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सहमत हुए। दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हो गए जब 30 सितम्बर, 1976 को इसकी स्वतन्त्रता के 10वें वार्षिक समारोह के अवसर पर भारत के उपविदेशमन्त्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।”

“वहाँ तक पश्चिमी अफ्रीका का सम्बन्ध है, भारत ने अंगोला के साथ अपने सम्बन्ध सुदृढ़ किए और घाना तथा नाइजीरिया के साथ सम्पर्क बढ़ाया। प्रधानमन्त्री के विशेष दूत अपनी अंगोला यात्रा के समय दवाइयो के साथ-साथ राष्ट्रपति

ग्रंगोस्टोनिग्रो नेटो के लिए प्रधानमंत्री का एक विशेष सन्देश भी ले गए। ग्रंगोला के राष्ट्रपति ने इस बात की सराहना की। भारत ने ग्रंगोला की जनता को अपनी नवभ्रजित स्वतन्त्रता की रक्षा करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने में पूर्ण सहयोग देने के वचन की पुनः पुष्टि की।”

“भारत के घाना तथा नाइजीरिया के साथ सम्बन्धों के विकास के सन्दर्भ में उल्लेखनीय बात इन देशों के साथ हवाई सेवा के समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना था। इन समझौतों के अनुसार एयर इण्डिया लागोस तथा अकारा के लिए सप्ताह में दो सेवाएँ आरम्भ करने में समर्थ होगी और इससे भारत तथा इन देशों के बीच सम्पर्क बढ़ने में सहायता मिलेगी। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री ए.एन. रे की घाना के सुप्रीम कोर्ट के शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने से, तथा भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् के निमन्त्रण पर घाना के पर्यटक राजदूत श्री ओ अप्पीआह की भारत यात्रा से भारत के घाना के साथ सम्बन्धों में वृद्धि हुई। घाना के निर्माण एवं आवास मन्त्री कर्नल के. ए. जैकसन अपनी भारत यात्रा के समय विन्म तथा मध्य वर्ग के लोगों के लिए गृह-निर्माण के लिए प्रयुक्त डिजाइन तथा तरीकों से प्रभावित हुए। भारत ने भवन-निर्माण के क्षेत्र में घाना को सहयोग देने की पेशकश की।”

“जहाँ तक पश्चिमी अफ्रीका के अन्य देशों का सम्बन्ध है, मार्च, 1976 में अपर वोल्टा के वाणिज्य और औद्योगिक विकास मन्त्री की भारत-यात्रा का परिणाम यह हुआ कि भारत तथा अपर वोल्टा के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के एक समझौता आपन पर मार्च, 1976 में हस्ताक्षर द्वारा सयुक्तराष्ट्र के हाई कमिश्नर की शरणाधिकियों के लिए अवील के बचाव में भारत ने सद्भावना स्वरूप बाढग्रस्त लोगो की सहायता के लिए गिनिया (बोसाउ) को 30 000 रु. की औपधियाँ भेजी। भारत ने केप वर्दी द्वीप के बाढग्रस्त लोगो की सहायता में भी अपना योगदान दिया।”

“माली के विदेशमन्त्री कर्नल चार्ल्स सोसोकोसावा की भारत-यात्रा माली के साथ भारत के मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की शुरुआत थी।”

“दिसम्बर, 1976 में नई दिल्ली में हुए सहारा के दक्षिण अफ्रीकी देशों के भारतीय मिशनो के प्रधान अधिकारियों के सम्मेलन से पारस्परिक सहयोग द्वारा सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के तरीके तथा साधन खोजने के लिए विभिन्न देशों में होने वाले विकासों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने की भारत ने इच्छा व्यक्त की तथा यह बात भी स्पष्ट की कि भारत के विचार में अफ्रीका का क्या महत्त्व है। इस सम्मेलन में इथोपिया, गुयनिया, मोजाम्बिक, जाईरा, सेनीगल, घाना, माली, तजानिया, मालवी, उगांडा, जाम्बिया के लिए भारतीय दूतों तथा केनिया व मदगास्कर के लिए नामोबद्रिष्ट भारतीय दूतों और नाइजीरिया में भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर भी उपस्थित हुए। इस सम्मेलन में भारत की नीति, इसके राजनयिक उद्देश्यों तथा आर्थिक और तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध समस्याओं और परिप्रेक्ष्यों पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया। ऐसा महसूस किया गया कि विकास के

क्षेत्र में भारत का अनुभव महत्वपूर्ण है और वह अपने अनुभवों को प्रकीर्ण देशों के साथ बांट सकता है। भारत ने उद्योग, विज्ञान, तकनीकी और कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति की है और इन क्षेत्रों में भारत द्वारा प्राविष्ट तथा प्रयुक्त तरीके प्रगीर देशों की अपेक्षा प्रकीर्ण देशों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत तथा प्रकीर्ण देशों के बीच इस आधारभूत तथ्य की तकनीकी सहयोग से यथाव्यय में बढ़ता जा सकता है। इस सम्मेलन ने अफ्रीका में भारत की उपस्थिति को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में प्रकीर्ण देशों के वर्तमान तथा सम्भावित नेताओं को भारत की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।”

भारत और राष्ट्रमण्डल

राष्ट्रमण्डल प्रभुसत्ता-सम्पन्न देशों का संगठन है जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 36 है। इनमें 32 विकासशील राष्ट्र हैं। इस संगठन में जो सदस्य देश हैं वे किसी एक जाति विशेष के न होकर विभिन्न जातियों के हैं।

राष्ट्रमण्डल का सचिवालय यद्यपि लन्दन में स्थित है किन्तु शासनाध्यक्षों के पिछले तीन सम्मेलन सिंगापुर (1971) ओटावा (1973) और किंगस्टन (1975) में हो चुके हैं। पिछले किंगस्टन सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि महारानी ऐलिजाबेथ के राजत-जयन्ती समारोह को ध्यान में रखकर अगला सम्मेलन लन्दन में किया जाए। इससे पहले लन्दन में शासनाध्यक्षों का सम्मेलन सन् 1969 में हुआ था जिसमें यह तय किया गया था कि अब एक वर्ष के अन्तर में यह सम्मेलन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के लाभ

राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से भारत को विभिन्न प्रकार के और ओस लाभ प्राप्त होते रहे हैं। इनमें सदस्य-देशों के विशेषज्ञों के बीच व्यावसायिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी और तकनीकी विषयों पर विचारों और जानकारी का निरन्तर आदान-प्रदान शामिल है।

इस प्रकार के लाभदायक सहयोग का सबसे प्रच्छन्न उदाहरण तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमण्डल निधि की व्यवस्था है। इस निधि में आजकल 40 लाख पौंड स्टर्लिंग का जमा है। सन् 1971 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी गतिविधि 15 गुना बढ़ गई है। भारत को इस राष्ट्रमण्डलीय-निधि से तकनीकी सहायता तथा शिक्षा, प्रशिक्षण और निर्यात-बाजार विकास के कार्यक्रमों के रूप में उससे कहीं अधिक लाभ मिला है जो इसमें भारत ने लगाया है। राष्ट्रमण्डल तकनीकी सहयोग निधि में सन् 1975-76 में यह राशि 80,000 पौंड स्टर्लिंग थी। जबकि सन् 1974-75 सन् 1976-77 में यह राशि 3,80,000 पौंड स्टर्लिंग थी। जबकि सन् 1974-75 के दो वर्षों में भारत को इस निधि से जो लाभ मिला है वह 3,80,000 पौंड स्टर्लिंग के लगभग है। राष्ट्रमण्डलीय युवक कार्यक्रम के अधीन एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के लिए चण्डीगढ़ में युवक कार्यक्रम सम्बन्धी उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रमण्डलीय संस्थान

की स्थापना की गई है। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण यह केन्द्र अभी पूरी तरह कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाया है, लेकिन जब ऐसा होने लगेगा तब एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के अन्य भागों के युवक नेताओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने में इसका काफी लाभदायक उपयोग हो सकेगा।

राष्ट्रमण्डलीय प्रतिष्ठान भी, जो वैज्ञानिकों और अन्य अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए व्यावसायिक आदान-प्रदान और विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है, भारत के लिए उपयोगी है। भारत प्रतिष्ठान के बजट में जो अंशदान देता है, उससे कहीं अधिक लाभ प्राप्त करता है।

राष्ट्रमण्डलीय सम्पर्क की उपयोगिता के अन्य उदाहरण राष्ट्रमण्डल दूर-संचार समझौता, राष्ट्रमण्डल वायु परिवहन परिषद् और राष्ट्रमण्डल कृषि म्यूरों से मिलते हैं। वरिष्ठ राष्ट्रमण्डल अधिकारियों के लिए शासन में व्यावहारिक अध्ययन का कोर्स अपनाया सम्भव है और सरकारी प्रशासन के सामान्य क्षेत्र में वे अनुभव का आदान-प्रदान भी कर सकते हैं। वैधानिक व कानून सम्बन्धी प्रारूप तैयार करने वालों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी मंच

राष्ट्रमण्डल सदस्य-देशों के नेताओं को विचारों के आदान-प्रदान का उपयोगी मंच प्रदान करता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रमण्डलीय मामलों में उनके बीच अधिक सद्भाव और सहयोग उत्पन्न होता है। एक बार इस छोटे, पर अपेक्षाकृत अधिक सगठित मंच पर आम सहमति प्राप्त हो जाने के बाद अपेक्षाकृत बड़े अन्तर्राष्ट्रीय सगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र में अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रमण्डल के विकसित देशों की उपस्थिति इस सम्बन्ध में उपयोगी है क्योंकि सन् 1973 में ओटावा में हुए राष्ट्रमण्डल के सामनाध्यक्ष सम्मेलन से यह औपचारिक विचार-विमर्श की वजह राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर उपयोगी व अधिक व्यावहारिक विचार विनिमय की दिशा में प्रयत्नशील है। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच अन्धधायपूर्ण आर्थिक विषमताओं को दूर करना है। लिगस्टन में सन् 1975 में विशेषज्ञों के दल का निर्माण किया गया था जिसका काम विकसित और विकासशील देशों के बीच खाई पाटने के लिए विभिन्न उपाय और साधन सुझाना था।

राजनीतिक क्षेत्र — राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रमण्डल ने दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की जातिभेद की नीतियों का चुनकर और स्पष्ट रूप से विरोध किया है। जब मोजाब्बिक ने रोडेशिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए थे तो राष्ट्रमण्डल ने मोजाब्बिक की सहायता के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के कारण मोजाब्बिक की जो हानि हो रही थी, उसकी पूर्ति करना था। इस विषय में बहुत तेजी से कार्यवाही की गई है।

राष्ट्रमण्डल में भारत की भूमिका

राष्ट्रमण्डल के अधिवेशनों में भारत की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।

अप्रैल-मई, 1975 में किंगस्टन (जमैका) में हुए राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की भूमिका बहुत ही उल्लेखनीय थी। श्रीमती गांधी ने 29 अप्रैल के अपने भाषण में कहा कि "राष्ट्रमण्डल ऐसी स्थिति में है कि वह सदस्य-देशों की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझने और उन्हें दूर करने की दिशा में कदम उठाने की पहल कर सकता है। पहले राष्ट्रमण्डल की बैठकी में हम जाति व रंगभेद की समस्या पर विचार करते थे। आज हम सर्व-सम्मति से इसे एक घातक रोग मानते हैं और महसूस करते हैं कि इससे राष्ट्रमण्डल नष्ट हो सकता है। उसी तरह हम धार्मिक विषमता पर विचार कर सकते हैं और मिल-जुलकर कदम उठाने का वातावरण तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रमण्डल के वर्तमान अधिवेशन में तथा भविष्य के अधिवेशनों में इस पर विचार होना चाहिए। आज की राई मृशनात्मक दृष्टिकोण अपनाते, सार्थक कदम उठाने तथा ठोस परिणाम प्राप्त करने की है। प्राचीन चारणाएँ समय की नई चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती। राष्ट्रमण्डल को सभी सबीलों धारणाओं से ऊपर उठकर इन मामलों में साहसपूर्ण ढंग से नेतृत्व करना चाहिए।"¹

राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए उनमें भारतीय प्रधानमंत्री के विचारों की गहरी छाप रही। उन्होंने इस अवसर का उपयोग विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमन्त्रियों से व्यक्तिगत भेंटवार्ता के लिए भी किया। इस प्रकार अनेक मतलों पर भारत के दृष्टिकोण को राष्ट्रमण्डलीय सदस्यों के सामने भली प्रकार व्यक्त किया जा सका। अगस्त, 1975 तीमा में गुट-निरपेक्ष विदेशमन्त्रियों के सम्मेलन में भारत ने राष्ट्र-मण्डल के देशों के बीच परस्पर सहयोग की आवश्यकता तथा गुट-निरपेक्ष देशों के बीच एकता पर बल दिया जिसने कि धार्मिक तथा राजनीतिक सहयोग के तद्वय की ओर बढ़ा जा सके और समानता तथा न्याय पर आधारित एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विकसित हो सके।

जून, 1977 में जो राष्ट्रमण्डल अथवा राष्ट्रकुल सम्मेलन हुआ, उसमें भी भारत के विचारों को बड़ ध्यान के साथ सुना गया। 15 जून, 1977 को सम्मेलन की सयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस सयुक्त विज्ञप्ति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। यह उपायुक्त होगा कि हम इस सयुक्त विज्ञप्ति की प्रमुख बातों से प्रवर्गत हो जाएँ जो जून-जुलाई, 1977 के दिनमान के अनुसार निम्न प्रकार हैं।

राष्ट्रकुल सम्मेलन (15 जून, 1977) की सयुक्त विज्ञप्ति

15 जून, 1977 को समाप्त हुए हफ्ते भर के राष्ट्रकुल सम्मेलन की सयुक्त विज्ञप्ति में उगांडा द्वारा मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन किए जाने की भर्त्सना की गई। किसी सदस्य-देश को इस तरह की भर्त्सना किए जाने की यह दूसरी घटना थी। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद व जातिभेद की नीतियों की

निन्दा की गई थी जिसके कारण उसने राष्ट्रकुल से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया था। अब दूसरी बार उगांडा की अनुपस्थिति में उसकी नीतियों की निन्दा की गई। लेकिन यह संयुक्त विज्ञप्ति सर्वसम्मत् नहीं थी। हालाँकि ईदी अमीन का नाम नहीं लिया गया था, तथापि यह अवश्य कहा गया था कि उगांडा में मानवाधिकारों का जिस तरह हनन हो रहा है उसकी विश्व भर में मर्त्सना होनी चाहिए। इस विज्ञप्ति के साथ नाइजीरिया ने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की।

प्रमुख मुद्दे—इसके अलावा संयुक्त विज्ञप्ति में रोडेशिया और दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद और नस्लवाद की नीतियों पर भी प्रहार किया गया। रोडेशिया में बहुसंख्यक शासन स्थापित करने की माँग की गई और दक्षिण अफ्रीका से कहा गया कि वह नामीबिया में अपना अधिकार और नियन्त्रण तुरन्त समाप्त कर दे। यह भी माँग की गई कि रोडेशिया को तेल का निर्यात तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिए (ब्रिटेन इस तरह के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था)। रोडेशिया द्वारा अपने पड़ोसी देशों की क्षेत्रीय अखण्डता का उल्लंघन करने के कार्यों की भी आलोचना की गई। रोडेशियाई सैनिकों द्वारा मोजाम्बिक में प्रवेश कर आक्रमण करने की निन्दा की गई। इस बात पर भी रोप व्यक्त किया गया कि रोडेशिया लगातार संयुक्तराष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, अतः यह आवश्यक है कि इयान स्मिथ की अवैध सरकार पर हर सम्भव प्रतिबन्ध लगाए जाने चाहिए। इन प्रतिबन्धों में उसे तेल देने पर प्रतिबन्ध लगाना एक प्रमुख मुद्दा है। इसके अतिरिक्त हिन्द महासागर में बड़े देशों की गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया। इन समय जिस तरह नौसैनिक गतिविधियाँ तेज हो रही हैं और सैनिक अड्डों की स्थापना एवं सैनिक साज-सामान की दिशा में जो कार्यवाही हो रही है उससे हिन्द महासागर में तनाव की स्थिति पैदा होगी। संयुक्तराष्ट्र के प्रस्ताव में हिन्द महासागर को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की माँग की गई है, अतः हिन्द महासागर की शान्ति भंग न करते हुए इसे बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनने से रोका जाना चाहिए।

गोपनीय वार्ता—11 और 12 जून को राष्ट्रकुल देशों के सदस्यों ने स्कॉटलैंड में अवकाश मनाया। इस अवकाश के साथ ही ग्लेनईगन होटल में सदस्य-देशों ने अनौपचारिक बातचीत की। कुछ गोपनीय विचार-विमर्श भी हुआ। इस तरह के विचार-विमर्श में सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इस तरह की गोपनीय बातों का ब्योरा प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन इन बात के प्रमाण हैं कि विश्व की बहुत-सी ऐसी समस्याओं पर खुलकर बातचीत हुई जिनका लगभग हर देश से सम्बन्ध है। मोटे तौर पर दो प्रमुख मुद्दे सामने आए। अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकर सहयोग कायम रखते हुए विश्व-सम्पत्ति के वितरण में व्याप्त भेदभाव को किस प्रकार कम किया जाए और अगले वर्ष एडमांटन (कैनाडा) में होने वाले राष्ट्रकुल खेलों में कुछ देशों द्वारा बहिष्कार करने के फैसले से बचाया जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलकूद सम्बन्ध बने हुए हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिण-अफ्रीका के साथ इन सम्बन्धों के प्रश्न पर तीखी प्रतिक्रिया हुई।

खेल सम्बन्ध—राष्ट्रकुल देशों के नेताओं ने अपना 'पुनीत करार' सम्पन्न किया। अन्य क्षेत्रों की तरह खेलकूद के क्षेत्र में व्याप्त रंगभेद की नीति को भी समाप्त किया जाये। दक्षिण अफ्रीका के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद के सम्बन्धों की स्थापना का प्रथम जाति, रंग और साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना है। न्यूजीलैण्ड के दक्षिण अफ्रीका के साथ सम्बन्धों की भी कटु शब्दों में आलोचना की गई। लगभग सभी देशों ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक दक्षिण अफ्रीका जातिभेद और नस्ल पर आधारित अपनी नीतियों को अपनाता रहेगा कोई भी देश उससे किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रखेगा। केवल यही नहीं, यदि कोई देश दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलकूद सम्बन्ध रखेगा तो उस देश का भी बहिष्कार किया जाएगा। यही कारण था कि न्यूजीलैण्ड और दक्षिण अफ्रीका के खेलकूद सम्बन्धों के प्रश्न पर राष्ट्रकुल खेलों के बहिष्कार का खतरा पैदा हो गया। भारत ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि जब तक न्यूजीलैण्ड स्पष्ट रूप से यह प्राश्नात्मक नहीं दे देता कि वह दक्षिण अफ्रीका से खेलकूद-स्तर पर भी अपना सम्बन्ध नहीं रखेगा तब तक भारत अपने अपने होने वाले राष्ट्रकुल खेलों में भाग नहीं लेगा। यही नहीं अश्वेत देशों ने राष्ट्रकुल खेलों का बहिष्कार करने का वक्तव्य भी जारी कर दिया। इससे गोरे देशों में बातचीत शुरू हो गई और न्यूजीलैण्ड ने यह स्पष्ट प्राश्नात्मक दिया कि वह दक्षिण अफ्रीका से अपने खेलकूद सम्बन्ध समाप्त कर देगा। राष्ट्रकुल शिखर सम्मेलन की एकता की यह पहली और एक महान् सफलता थी।

डॉ. ओवेन का विश्लेषण—ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉ. डेविड ओवेन ने अफ्रीका की अपनी यात्रा और वहाँ पर व्याप्त समस्याओं के सम्बन्ध में कहा कि इस समय वहाँ पर जिस तरह की स्थिति है उससे यही प्रतीत होता है कि यह समस्या लाइलाज है। लेकिन विभिन्न समुदायों के लोगों और गुटों से बातचीत के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि यह विवाद बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है और मेरा यह निश्चित मन है कि सन् 1978 में स्वाधीन जिम्बाब्वे (रोडेज़िया) अस्तित्व में आ जाएगा। निस्संदेह इस समय अफ्रीकी नेता सशस्त्र संघर्ष के अलावा इस समस्या के समाधान का कोई अन्य विकल्प नहीं समझते, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास है कि वे लोग भी युद्ध से अच्छे समझौते के रास्ते को प्राथमिकता देंगे। प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या हम उन्हें समझौता करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं? क्या हम व्यवस्थित ढंग से उन्हें प्रत्यायी या सक्रमणकालीन सरकार की स्थापना करने की सम्भावनाओं के बारे में दृष्टि सज्ज हैं। निस्संदेह जिम्बाब्वे में शांति स्थापित करने का मार्ग ढूँढ़ना उनका नैतिक दायित्व है और वह अपने इस दायित्व से पीछे हटना नहीं चाहते। उन्होंने बहुसंख्यक और गैरनस्ली सरकार का एक सपना देखा है जिसे साकार करने के लिए वह कुनसत्तन है। डॉ. ओवेन ने रोडेज़िया के मामले, डॉ. हेनरी कीसिंगर की अफ्रीका यात्रा और जेनेवा सम्मेलन, कासों और मोरो में बातचीत, उनमें प्रनवन, अस्थायी सरकार के मार्ग में आने वाली सड़क, विदेश मंत्री का पद

सम्भालने के बाद उनकी अफ्रीकी देशों की यात्रा और विभिन्न नेताओं से विचार-विमर्श तथा ब्रिटेन अमेरिकी प्रस्ताव आदि प्रयत्नों का सविस्तार उल्लेख किया।

अन्य समस्याएँ—निस्संदेह इस सम्मेलन पर अफ्रीकी समस्याएँ हावी रही—ईदी अमीन की भूमिका से लेकर रोडेसिया और दक्षिण अफ्रीका के मामले तक—लेकिन अन्य मामलों पर भी काफी विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रकुल सम्मेलन में क्षेत्रीय सम्बन्धों के विकास का प्रश्न भी उठाया गया। भारत के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह अफ्रीकी देशों और लातीनी अमेरिकी देशों में क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्ध हैं, उसी तरह के सम्बन्ध दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के देशों में भी स्थापित होने चाहिए। यह प्रस्ताव आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री मार्कम फ्रेजर ने रखा था। इस तरह के क्षेत्रीय सम्बन्ध स्थापित हो जाने से इन देशों में परस्पर व्यापारिक, आर्थिक सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सम्बन्ध मजबूत होंगे और पारस्परिक अविश्वास की भावना पैदा नहीं होने पाएगी। पेरिस में उत्तर-दक्षिण के देशों के सवाद को भी महत्वपूर्ण बताया गया। यद्यपि अभी किसी नियंत्रण पर नहीं पहुँचा जा सकता, तथापि विकसित तथा अविकसित देशों में जिस तरह के सम्पर्क स्थापित हुए हैं उससे निश्चित रूप से एक नयी दिशा मिलनी है। सभी देशों ने इस तरह के सम्पर्क बढ़ाए जाने पर बल दिया।

अनुपस्थित देश—सेशेल्स और उर्गांडा इस सम्मेलन में अनुपस्थित रहे। सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स माशेम को एक नान्ति द्वारा सत्ताप्युक्त कर दिया गया और उनके स्थान पर एस्वर्ट रेने ने सत्ता सम्भाली, लेकिन न तो रेने और न ही उनके किसी प्रतिनिधि ने ही लन्दन सम्मेलन में भाग लिया। जेम्स माशेम लन्दन में मौजूद थे। इस तरह के सत्ता पलटने की एक घटना पहले भी हा चुकी है। प्रायः छः वर्ष पहले जब सिंगापुर में राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉ मिस्टन ग्रीवोटे गए थे तो ईदी अमीन ने उर्गांडा में उनका तख्ता पलट दिया था।

चर्चा अमीन की—उसी ईदी अमीन को इस बार के राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई या यो कहिए कि उनका विरोध हुआ। लन्दन में वातावरण इसना आशामक था कि अगर अमीन वहाँ पहुँच भी जाते तो न तो उनका स्वागत होता और न ही उन्हें सम्मेलन में सम्मिलित होने दिया जाता। यद्यपि इस प्रकार का समाचार प्रकाशित हुआ था कि ईदी अमीन प्रतिवन्दों और विरोध के बावजूद सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और तो और, पापुवा के मिशेल समोरा ने सम्मेलन में अमीन की नीतियों की निन्दा करते हुए कहा कि सभी अफ्रीकी देशों को अमीन की नीतियों का विरोध कर उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाने चाहिए। अमीन के बारे में तरह-तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। अमीन ने कहा था कि प्रतिवन्दों के बावजूद वह लन्दन सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन शुरू होने से पहले यह भी कहा गया कि वह उर्गांडा से लन्दन के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके बाद कहा गया कि वह एक अन्य अफ्रीकी देश (लीबिया) पहुँच गए हैं लेकिन इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी। फिर खबर उठी कि वह समुद्री मार्ग से लन्दन पहुँच रहे हैं, लेकिन यह भी रहस्य ही

रहा। इसके बाद यह समाचार प्रचारित किया गया कि यह आयरलैण्ड जा रहे हैं, लेकिन आयरलैण्ड की सरकार ने उतरने की इजाजत नहीं दी। आयरलैण्ड ने कहा कि यह उनके विमान को ईंधन सने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन अमीन को वहाँ पर उतरने की नहीं।

भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ

भारत उन देशों में से है जिन्होंने सन् 1945 में सान-फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्रसंघ के जन्म से ही भारत उसके आदर्शों के लिए निरन्तर कार्य करता रहा है। भारत सदा इस बात का दृष्टिकोण रहा है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ सही अर्थों में सारे सभार की प्रतिनिधि संस्था का रूप ले ले। इसी कारण उसने चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान देने का समर्थन किया, भले ही चीन के साथ उसके क्षेत्रीय विवाद थे। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत ने हमेशा शान्ति स्थापना के सभी कार्यों का हार्दिक समर्थन किया है। कोरिया और स्वेज के संकट के समय भारत के कार्य की सर्वत्र सराहना हुई। कोरिया में भारत का मुख्य रूप से बीच-बचाव का काम था। कांगो में भारत ने जो काम किया वह ठोस था। वहाँ जगने संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपील पर अपने सैनिक भेजे। कुल मिला कर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत की विदेश-नीति का सार रहा है—हर प्रकार के उपनिवेशवाद, जातिवाद और रंगभेद का विरोध, विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान में सहयोग, भारतीय हिंदुओं को आघात पहुँचाने वाले प्रस्तावों के विरुद्ध कूटनीतिक मोर्चा, संयुक्त राष्ट्रसंघ की उन अपीलों का सम्मान जो देश के हिंदुओं के विपरीत न हों, सभ के निश्चयीकरण के प्रयासों में योगदान, आदि। भारत सभ से सम्बद्ध संस्थाओं के कार्यों में भी प्रमुख भाग लेता आया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सभ यूनेस्को और विश्व-स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में उसकी विशेष रुचि रही है। भारत के प्रतिनिधियों ने सभ की विभिन्न शाखाओं तथा उनके विभिन्न आयोगों और विशिष्ट मितियों में सक्रिय भाग लेकर देश का गौरव बढ़ाया है।

भारत की विदेश-नीति का मूलपांक्तन

भारत की विदेश-नीति पर अत्यधिक आदर्शवादी और भावना-प्रधान होने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह भी कहा जाता है कि हमारी विदेश-नीति सोवियत सभ से प्रभावित है और इजरायल, अरब राज्यों आदि के सम्बन्ध में इसका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि हमारी नीति राष्ट्रीय हिंदुओं के प्रतिरूप मिथ्य हुई है।

भारतीय विदेश नीति की आलोचनाएँ नेहरू-काल और कुछ-कुछ आस्था-राज में अधिक तीव्र थी। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत की सुट-निरपेक्ष नीति के मौखिक सिद्धान्तों की पूर्ण रक्षा करते हुए उसे नई दिशा दी, मध्यमवादी चरम से दूरा और राष्ट्रीय हिंदुओं के सर्वथा अनुकूल सिद्ध कर दिखाया। किसी भी नीति की सफलता उसके कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर है। नेहरू-काल में आवश्यक था कि तबोदित भारत-राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता रखी जाए, विभाजन-जन्य विषम

परिस्थितियों को निपटाया जाए और पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों के प्रति भी दुष्टिकरण की नीति अपनाते हुए युद्ध की सम्भावनाओं को यथासाध्य टाला जाए। इसलिए चीन के साम्राज्यवादी इरादों को कुछ-कुछ भाँवते हुए भी और पाकिस्तान की शत्रुता को भली-भाँति समझते हुए भी श्री नेहरू ने भारत को ऐसे नैतिक घरातल पर खड़ा करने की चेष्टा की जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भारत को प्रतिष्ठा भी मिले, पूँजीवादी और साम्यवादी दोनों ही जिविर उसकी आवाज सुनें और उसकी सहायता के लिए तत्पर रहे तथा साथ ही युद्ध की सम्भावना भी टलती रहे ताकि भारत भविष्य में शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण कर सके। श्री नेहरू को अपने उद्देश्य में सन् 1962 में पूर्व तक पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। सन् 1962 के चीनी आक्रमण ने उनकी शान्तिवादी नीति को गहरा आघात पहुँचाया, लेकिन गुट-निरपेक्षता की उपयोगिता में उनकी आस्था समाप्त नहीं हुई क्योंकि संकट-काल में सोवियत गुट और पश्चिमी गुट दोनों ने भारत को अपना समर्थन दिया। फिर भी इस आक्रमण ने श्री नेहरू को यह अनुभूति करा दी कि अब विदेश-नीति को यथार्थवाद की ओर मोड़ा जाए तथा गुट-निरपेक्षता पर धमल करते हुए सैनिक दृष्टि से भी भारत को शक्तिशाली बनाया जाए। श्री नेहरू यथार्थवादी नीति का अनुसरण कर भारत को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से आवश्यक आर्थिक और सैनिक उद्योगों तथा कल-कारखानों की आधारभूमि का पहले ही निर्माण कर चुके थे। अब चीन का वृक्ष रूप में परिणत होना था।

दुर्भाग्यवश श्री नेहरू का सन् 1964 में आकस्मिक निधन हो गया। उनके उत्तराधिकारी श्री शास्त्री ने नेहरू की नीति को आगे बढ़ाया और भारतीय विदेश-नीति में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का सुन्दर समन्वय किया। पाकिस्तान को उसके आक्रमण का मुँह तोड़ उत्तर देकर तथा अमेरिका जैसी महाशक्ति के दबाव के प्रागे न झुककर जहाँ श्री शास्त्री ने यथार्थवादी नीति का परिचय दिया वहाँ ताशकन्द-समझौता करके आदर्शवाद को भी कायम रखा। यद्यपि ताशकन्द-समझौता व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक युद्ध के बाद इस प्रकार के समझौते न्यूनाधिक हेर-फेर के साथ करने ही पड़ते हैं। यदि पराजित राष्ट्र पर वर्णाय की सन्धि जैसा कोई समझौता थोपा जाए तो उसके ब्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं, इसका इतिहास साक्षी है।

श्री शास्त्री का प्रधानमन्त्रित्व काल इतना अल्प रहा कि उनकी नीति का पूरे मूल्योंकन नहीं किया जा सकता। उनके निधन के बाद भारत की बागडोर श्रीमती इन्दिरा गाँधी के हाथों में आई और हम इस बात से भली प्रकार परिचित हैं कि बंगलादेश के मुक्ति-ग्रान्दीजन, बंगलादेश की मान्यता, अमेरिका के प्रति दृढता, रूस के साथ सम्मानजनक तथा गुट-निरपेक्षता पर आधारित मैत्री सन्धि, पाक शत्रुता का मुँह तोड़ उत्तर आदि कार्यों द्वारा उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हितों की किस कुशलता से रक्षा की। साथ ही शिमला-समझौते द्वारा उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारत साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बिल्कुल समर्थक नहीं है तथा पड़ोसी देशों के साथ और विश्व के हर राष्ट्र के साथ मैत्री का दृष्टिकोण है।

कम्बोडिया और वियतनाम में जो कुछ हुआ उसे भी भारतीय विदेश-नीति की सफलता माना जाएगा। भारत उन गिने-बुने देशों में से है जिन्होंने शुरू से ही कम्बोडिया और वियतनाम के मुक्ति-प्राप्तियों का समर्थन किया था। ऐसे करते हुए भारत ने अमेरिका तथा कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्रों की अप्रसन्नता भी मोल ली, लेकिन बदले में उसे दक्षिणी-एशिया की जनता से जो सद्भावना प्राप्त हुई वह कुछ कम नहीं थी। अब कम्बोडिया का गृह-युद्ध समाप्त हो चुका है, वियतनाम से अमेरिका पलायन कर चुका है और उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम का एकीकरण हो चुका है। आरम्भ में जिन देशों ने दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारतीय विदेश-नीति को आत्मघाती बताया था, आज वे अवश्य अनुमन्य कर रहे होंगे कि भारतीय विदेश-नीति नहीं, बल्कि उनकी अपनी विदेश-नीति गलत बुनियाद पर खड़ी थी। सोवियत संघ के साथ सम्बन्धों का अधिकाधिक दृढ़ होते जाना भारत की विदेश-नीति की प्राश्नचर्यजनक सफलता है। वास्तव में भारत का विकास सोवियत विदेश-नीति का भी एक आवश्यक घटक बन गया है। सोवियत रुस चाहता है कि एशिया में चीन एकमात्र महाशक्ति न रहे। उसका मुकाबला करने के लिए कम से कम एक देश का होना जरूरी है। सोवियत नेता इस तथ्य से प्रचण्डी तरह परिचित हैं कि यह देश केवल भारत ही हो सकता है और इसीलिए न केवल पान्चिकी के क्षेत्र में बल्कि बाणिज्य, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में भी सोवियत रुस भारत की सहायता कर रहा है। यह कहना गलत होगा कि भारत ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकायी है। सोवियत रुस से सहायता लेते हुए भी भारत ने अपनी प्रभुमत्ता को दाव पर नहीं रखा है।

गुट-निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की व्यापक पृष्ठभूमि में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ तथा विश्व के अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। चीन और पाकिस्तान के प्रति भी भारत का रवैया बहुत ही रचनात्मक रहा है। उसके फलस्वरूप सन् 1976 में दोनों देशों के साथ पुनः दूतनीतिक सम्बन्ध कायम हो सके हैं। पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति का सत्य सदैव यही रहा है कि परस्पर विश्वास, समझ-बूझ और सहयोग के आधार पर उनके साथ घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध विकसित किए जाएँ। भारत ने विश्व के सभी भागों में राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय का सदैव स्वागत किया है। इसी प्रकार कोरिया और वियतनाम के एकीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए स्वागत योग्य रही है। भारत निःसन्देह गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशों की आशा बन चुका है। भारत का निश्चित मत है कि विकासशील राष्ट्रों के सहयोग न केवल गृहस्थ आत्मविश्वास के लिए अनिवार्य है बल्कि बड़े राष्ट्रों के उस दबाव का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है जो विकासशील देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए डाला जा रहा है ताकि विश्व के विभिन्न भागों में उनके अपने हित अधिकाधिक विलुप्त हो सकें। विकासशील देश आत्मविश्वास, सहयोग और विकास के माध्यम से ही शांति और स्थिरता की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं और

तभी वे एक ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में सहायक हो सकते हैं जो विश्व के सभी राष्ट्रों के बीच सहयोग और मित्रता के आधार पर स्थित हो ।

मार्च, 1977 में कांग्रेस-शासन के पतन के बाद प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता सम्भाली । नई सरकार ने भारत के बुनियादी हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश-नीति में मौलिक परिवर्तन न करने का निर्णय कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है । प्रारम्भ में यथार्थ निर्गुणता की नीति की घोषणा के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में आशंका प्रकट की गई थी, किन्तु जनता सरकार जिस ढंग से विदेश-नीति के क्षेत्र में अग्रसर हो रही है उससे स्पष्ट है कि इसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा । भारत की नई सरकार ने भारत-रूस मैत्री के समर्थन द्वारा भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति को यथावत कायम रखने की घोषणा कर रूसी शासकों को आश्वासित कर दिया कि जनता सरकार अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नीति का अनुसरण करेगी । रूस के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों के बावजूद अन्य देशों के साथ सम्बन्धों में सुधार करेगी और किसी एक देश की मित्रता अन्य देश के साथ सम्बन्धों में बाधक नहीं बनेगी । अमेरिका के साथ विगत वर्षों के सम्बन्ध-शैथिल्य टूट रहे हैं और चीन के साथ भावी सम्बन्ध स्थापना के बारे में सावधानीपूर्वक कदम उठाने की तैयारी भी की जा रही है । किसी भी देश की विदेश-नीति वस्तुतः उसके मूल राष्ट्रीय हितों और आकांक्षाओं के अनुकूल होती है और भारत भी अपने व्यवहार में यही कर रहा है । बंगलादेश के साथ गंगाजल पानी के विवाद के हल में भारत ने जो उदारता दिखायी है वह पड़ोसी देशों के प्रति हमकी सहयोगी नीति का परिणाम है ।

चीन की विदेश नीति

(FOREIGN POLICY OF CHINA)

"विश्व की शांति चीन पर निर्भर है और जो कोई चीन को समझ सकेगा, उसी के हाथ में आगामी पाँच शताब्दियों तक विश्व-राजनीति की कुंजी होगी।"

—जान हे

वर्तमान साम्यवादी चीन यह था चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर, 1949 को हुई। च्यांग-काई-शेक और उसका राष्ट्रवादी दल चीन के शृङ्खुद में साम्यवादियों के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। संयुक्तराज्य अमेरिका ने च्यांग-काई-शेक को वहाँ तक भरपूर सैनिक सहायता दी, लेकिन माघ्रो-स्ते-जुंग के नेतृत्व में साम्यवादी सेना ने अमेरिका की मनोकामना पूरी नहीं होने दी। च्यांग-काई-शेक ने भाग कर चीन की मुख्य धरती से कुछ ही मील दूर फारमोसा द्वीप में शरण लेकर वही चीन की 'निर्वासित सरकार' स्थापित कर ली। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रसंघ इसी सरकार को अर्थात् राष्ट्रवादी चीन को मान्यता देते रहे। चीन की मान्यता का प्रश्न सन् 1949 से 25 अक्टूबर, 1971 तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय बना रहा। वास्तव में दो चीन की स्थिति कायम रही। दुनिया के लगभग 35 राज्यों की मान्यता साम्यवादी चीन को प्राप्त थी और 42 देश च्यांग-काई-शेक की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता देते थे। भारत ने प्रारम्भ से ही एक चीन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी थी। अखिर 26 अक्टूबर, 1971 को दो चीन वाली यह स्थिति समाप्त हो गई। संयुक्तराष्ट्र महासभा ने राष्ट्रवादी चीन (ताइवान या फारमोसा) को संयुक्तराष्ट्र से निष्काशित कर उसके स्थान पर जनवादी (साम्यवादी) चीन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव 35 के विरुद्ध 76 मतों से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 22 वर्ष का वह संघर्ष समाप्त हो गया जो साम्यवादी चीन को विश्व सत्ता का सदस्य बनाने के लिए चल रहा था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के इतिहास में यह पहला प्रयत्न था जब संघ के किसी सदस्य और सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य को सभ

की सदस्यता से निष्कासित कर उसके स्थान पर किसी अन्य देश को सदस्य बनाया गया हो। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का हक सदा आक्रामक रहा है, पर माओ की मृत्यु के बाद नया नेतृत्व कुछ उदार है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी चीन के उदय के परिणाम

चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटना थी जिसने सम्पूर्ण विश्व-राजनीति को गभीर रूप से प्रभावित किया और उन परिवर्तनों को जन्म दिया जो विश्व-राजनीति को लम्बे समय तक प्रभावित करते रहेगे—

प्रथम, स्वयं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ा है। साम्यवादी क्रान्ति से पूर्व भी यद्यपि चीन को पांच बड़ी शक्तियों में स्थान प्राप्त था, तथापि सही प्रर्थों में वह एक बड़ी शक्ति नहीं था। साम्यवादियों के नेतृत्व में एक सुसंगठित और शक्तिशाली चीन का उदय हुआ जो आज न केवल एक बड़ी शक्ति है, बल्कि अमेरिका और रूस के बाद तीसरी महाशक्ति भी गिना जाने लगा है।

दूसरे, साम्यवादी चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक नया शक्ति-सन्तुलन स्थापित कर लिया है। जिधर वह झुक जाए, सन्तुलन का पलड़ा उधर ही झुक जाएगा। चीन के समक्ष भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो चीन-विरोधी पक्ष के साथ मिलकर शक्ति-सन्तुलन के दोनों पलड़ों को बहुत-कुछ बराबर ला सकता है। आज जबकि चीन सोवियत संघ का प्रतिद्वन्द्वी बन कर अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत का एक सन्तुलनकारी शक्ति के रूप में विशेष महत्व हो गया है।

तीसरे साम्यवादी चीन के उदय के फलस्वरूप पश्चिमी देशों की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और चीन की शक्ति तथा प्रभाव आज भी उनकी नीति में नित नए मोड़ लाने में सहायक है। लाल चीन के उदय के उपरान्त साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ही अमेरिका ने ताइवान, अथवा फारमोसा में च्यांग की भगोड़ी राष्ट्रवादी सरकार की रक्षा का उत्तरदायित्व सभाला, एशिया में साम्यवादी-प्रबलपक्ष की नीति पर आचरण शुरू किया और मर-साम्यवादी तत्वों को अधिकाधिक आर्थिक तथा सैनिक सहायता दी। साम्यवादी चीन के उदय से सोवियत गुट का शक्ति-सन्तुलन का जो पलड़ा झुक गया उसी से चिन्तित होकर साम्यवाद विरोधी प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की स्थापना के मार्ग का अनुसरण किया गया। आज जब चीन और रूस में तीव्र मतभेद उठ खड़े हुए हैं, अमेरिकी गुट का सर्वोपरि लक्ष्य यही है कि चीन को तोड़ कर पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया जाए। पेकिंग-पिण्डो-वाशिंगटन घुंरी के मुहड़ और सबल होने की आकांक्षा से रूस का चिन्तित हो उठना और फलस्वरूप भारत की मंत्री के महत्व को अधिकाधिक अनुभव करना स्वाभाविक है।

चौथे, लाल चीन के उदय ने अमेरिका और उसके साथी-राष्ट्रों के बीच कुछ मतभेद भी पैदा कर दिए, जो अब कम हो गए हैं। अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने से इंकार कर दिया जबकि ब्रिटेन, फ्रांस आदि ने अपने

व्यापारिक लाभों के कारण उसे मान्यता प्रदान की और इसके साथ सम्पर्क बढ़ाए। अतः उनके धीरे-धीरे अमेरिका के बीच कुछ मन-मुटाव हो जाना स्वाभाविक था। प्रबल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर, अमेरिका स्वयं चीन की मंजी के लिए लाजापित है, अतः चीन के सम्बन्ध में जो मतभेद पैदा हुए थे वे शिथिल पड़ गए हैं।

पाँचवें, चीन में साम्यवादियों की विजय सोवियत संघ के लिए बरदान और अभिशाप दोनों ही सिद्ध हुई है। बरदान इसलिए कि इससे जनसत्ता, साधन-स्रोत और सैन्य शक्ति की दृष्टि से साम्यवादी जगद् भ्रष्टाचार शक्ति-सम्पन्न हो गया और विश्व में शक्ति-सन्तुलन स्थापित हुआ। अभिशाप इसलिए कि माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन सोवियत संघ का घोर प्रतिद्वन्द्वी बन गया और आज सैद्धान्तिक संघर्ष की धार में दोनों देश शक्ति-संघर्ष के भय से आशंकित हैं। सन् 1949 तक सोवियत संघ साम्यवादी जगद् का एकछत्र प्रमदिग्ध नेता था और विश्व के सभी साम्यवादी देश उसके अनुयायी थे, लेकिन साम्यवादी चीन के उदय ने इसी नेतृत्व को चुनौती दी है।

छठे, चीन की साम्यवादी क्रांति ने एक ओर तो एशिया तथा अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर एशियायी एकता के विकास में बाधा पहुँचाई। चीन का नेतृत्व 'फूट डालो और अपना उल्लू सीधा करो' की नीति में विश्वास रखता है। चीन भारत को अपना मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मानकर इस नीति पर चल रहा है कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में भारत-विरोधी वातावरण पैदा करे। भारत उपमहाद्वीप में शान्ति की स्थापना में चीन की कोई रुचि नहीं है, इसलिए वह पाकिस्तान को भारी सैनिक सहायता देकर भारत के विरुद्ध सक्रियता रहता है।

सातवें, चीन न केवल साम्यवादियों के लिए बल्कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों के लिए साम्यवादी मिढान्त और कुटिल दावेषों के विकास का परीक्षण स्थल बन गया है।

आठवें, साम्यवादी चीन के उदय का पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। चीन स्वयं को पूर्ण रूप से एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित-देखना चाहता है और इसके लिए-उसने संघर्ष तथा दबाव-नीति का मार्ग चुना है। सुदूरपूर्व में जो संघर्ष है वह बहुत कुछ चीन की महत्वाकांक्षा का भी परिणाम है। चीन में साम्यवाद के उदय ने एशिया में चीन और अमेरिका को तथा प्रबल चीन, अमेरिका और रूस को एक-दूसरे का प्रबल प्रतिद्वन्द्वी बना दिया है जिससे यह प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विस्फोटक-केन्द्र बना हुआ है।

सन् 1921 में जनरल स्मटन ने कहा था—“रगमग अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुँच गया है।” ये शब्द सम्भवतः उस समय सत्य नहीं थे, लेकिन साम्यवादी चीन के उदय के फलस्वरूप विश्व-राजनीति में उत्पन्न परिवर्तनों से आज सत्य सिद्ध हो रहे हैं।

साम्यवादी चीन की विदेश-नीति के आधारभूत तत्त्व, साधन और लक्ष्य

साम्यवादी चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में जो नीति अपनाई है उसे भली प्रकार समझा जा सकेगा जब हम चीनी विदेश-नीति के सैद्धान्तिक आधार को समझ लें और इस बात से परिचित हो जाएँ कि वह किन तत्त्वों, साधनों और लक्ष्यों पर आधारित है।

आधारभूत तत्त्व

साम्यवादी विचारधारा—इस की भाँति चीन की विदेश-नीति भी मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों से पूर्णतः प्रभावित है। ल्यूशाओची के शब्दों में, "हमारी सफलताएँ मार्क्सवाद-लेनिनवाद की नवीन पुष्टियाँ और नवीन सफलताएँ हैं।" साम्यवाद के मुख्य सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, पूँजीवाद का साम्राज्यवादी रूप आदि से चीन की विदेश-नीति पर्याप्त प्रभावित है, इसलिए एशिया एव अफ्रीका में साम्यवाद के प्रसार को चीन अपना उत्तरदायित्व मानकर व्यवहार कर रहा है। चीनी नेताओं का विश्वास है कि विजय की प्राप्ति के लिए किसी एक धोर भुक्तना होगा—साम्राज्यवाद की और अथवा समाजवाद की ओर। तटस्थता तो बेवस घोटा है, तीसरा मार्ग पाया ही नहीं जाता। माओ-त्से-तुंग ने मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों की चीनी संस्करण का रूप दिया है, उनका चीन के इतिहास और उसकी समस्याओं के समाधान में उपयोग किया है। माओ की मान्यता है कि मार्क्सवाद निराधार नहीं है बल्कि ठोस रूप में है जिसे राष्ट्रीय रूप में ग्रहण किया जाना तथा देशकालीन परिस्थितियों की अनुकूलता के सम्बन्ध में अपनाया जाना चाहिए। राज्य शासक-वर्ग के हाथ में दमन का एक साधन है।

राष्ट्रीय हित—चीन की विदेश-नीति में सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय हित साथ-साथ चलते हैं। सिद्धान्त राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हैं और राष्ट्रीय हित के अनुसार ही सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है। चीनी नेतृत्व के प्रत्येक कार्य का मूल लक्ष्य देश के शक्ति-स्तर (Power-status) में वृद्धि होता है। माओ की स्पष्ट धारणा है कि जो देश चीन को महान् शक्ति न माने उसे मानने के लिए बाध्य किया जाए अथवा कोई बड़ी शक्ति उसे अपने समान न समझे तो उसको इसका पाठ पढ़ाया जाए। शक्ति की प्राप्ति और अभिवृद्धि के लिए साम्यवादी चीन किसी भी बलिदान को बड़ा नहीं मानता।

पूँजीवाद का विरोध—चीन की विदेश-नीति पूँजीवादी देशों के साथ घोर प्रतिद्वन्द्विता की है। माओ पूँजीवाद के विनाश पर साम्यवाद का महल खड़ा करना चाहता है। विश्व के देशों में राष्ट्रवादी तत्त्वों को उभार कर वहाँ साम्यवादी क्रान्ति के उपयुक्त वातावरण बनाना चीन की विदेश-नीति का मूल सिद्धान्त है।

माओ का अनुगमन—अपने जीवनकाल में माओ चीन की सम्पूर्ण नीतियों का निर्माता और संचालक रहा और उसकी सीख को चीन शायद ही कभी भूल सकेगा। माओ ने मार्क्सवाद और लेनिनवाद की नीतियों की व्याख्या की, चीन के

साहित्य और कला के आदर्श एवं स्तर निर्धारित किए तथा सभी राजनीतिक-नैतिक-आर्थिक कार्यवाहियाँ उसी के नाम से प्रचारित होनी रही। माओ के नेतृत्व में चीन द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, वे शायद ही किसी अन्य नेता के नेतृत्व में अपनाई जा सकती थी। माओ का यह अभिमत चीनी विदेश-नीति का केन्द्र-बिन्दु है कि राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली से प्राप्ति होती है। आणविक आयुधों से भी माओ के अनुयायियों को भयभीत न होने की शिक्षा दी गई है। माओ का कहना है कि इन आयुधों के प्रयोग के बाद भी इतनी बड़ी सत्या में चीनी बच जाएँगे कि वे अपने स्वप्न की पूर्ति द्वारा एक उत्कृष्ट सम्पत्ता का सृजन कर सकेंगे। माओ ने विदेश-नीति को लचीला बनाया ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसे ढाला जा सक। इसीलिए चीन की विदेश-नीति में कभी एकरूपता या स्थायित्व नहीं रहा है।

राष्ट्रवादिता—चीन की विदेश-नीति राष्ट्रवादिता से प्रेरित है। चीनी लोग अपने पूर्वजों चनेजखाँ व कुबलाखाँ की विस्तारवादी परम्पराओं के अनुयायी हैं। साम्यवादी चीन को अपने देश की प्राचीन सम्पत्ता और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर गर्व है जिसकी पुन प्राप्ति के लिए वह हर बलिदान के लिए तैयार है। माओ ने सन् 1949 में कहा था—“हमारा राष्ट्र अब कभी भी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा, हम उठ खड़े हुए हैं।” उस राष्ट्रवादिता में प्रेरित होने के कारण ही अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की नीति किसी दूसरे देश की नीति से मेल नहीं खाती।

साम्यवादी चीन विस्तारवाद और साम्राज्यवाद का प्राईसी है। जिस किसी भी नू-भाग पर चीन का कभी अस्थायी या नाममात्र को भी अधिकार रहा था, उसे वर्तमान चीन अपना ‘खोया हुआ भाग’ मानता है। चीन की विदेश-नीति के साधन पवित्रता-अपवित्रता जैसी सीमाओं से प्रतिबद्ध नहीं हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए चीन निरूप्रष्ट से निरूप्रष्ट साधन भी अपनाते में सकाच नहीं करता। चीनी विदेश-नीति के मुख्य साधन ये हैं—

युद्ध एवं हिंसा—माओ ने लिखा है—“हम साम्यवादी युद्ध को सर्वव्यापक मानते हैं। युद्ध अनुचित न होकर सर्वथा उचित और मानसवादी हो।” माओ भी सोच है कि सारा ससार केवल बन्दूक की सहायता से ही बदला जा सकता है। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति साम्यवाद के विरुद्ध है तथा सशोधनवाद की प्रतीक है।

सम्ये संघर्ष की योजना—चीन के साम्यवादी नेताओं के अनुसार विश्व साम्यवाद के प्रसार के लिए संघर्ष की योजना का अनुसरण करना होगा। यह योजना साम्यवादी सिद्धान्तों पर आधारित है, लेकिन इसकी व्याख्या माओ की अपनी है। माओ का विचार है कि पूँजीवादी देशों में हठ निश्चय और साहस नहीं होता, अतः जब उनके विरुद्ध सावधानी के साथ प्रचुर देवकर लम्बा संघर्ष देखा जाएगा तो वे टिक नहीं सकेंगे। साम्यवादी राष्ट्रों के पीछे सिद्धान्त का बल होता है और राजनीति का अवलम्ब, इसीलिए वे पूँजीवादी देशों में तोड़-फोड़ कर सकते हैं।

सन्धे संघर्ष की योजना के अधीन पश्चिमी देशों का तीव्र विरोध किया जाता है और दूसरे देशों में साम्यवादी दलों की सहायता की जाती है।

साम्यवादी प्रचार—माओ चीन की विदेश-नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्व के सभी गैर-साम्यवादी देशों में—विशेषकर एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में साम्यवादी प्रचार का पक्ष-पोषक रहा और नए नेतृत्व का दृष्टिकोण भी कुछ विपरीत प्रतीत नहीं होता। माओ का कहना था कि विश्व के साम्यवादी 3 आन्दोलन चीन को आदर्श मानकर सशस्त्र रूप धारण कर लेंगे।

सैनिक सहायता कार्यक्रम—साम्यवाद की स्थापना के लिए चीन दूसरे देशों को सैनिक सहायता देने का पक्षधर है, लेकिन उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उस देश के लक्ष्य लगभग वही हैं जो स्वयं चीन के हैं तथा चीनी सहायता की प्रतिक्रिया स्वरूप यथासम्भव किसी बड़े देश का मुकाबला न करना पड़े और सहायता से चीन की सुरक्षा को कोई खतरा पहुँचने की सम्भावना न हो।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व—इस साधन का उपयोग प्रायः लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चीनी नेताओं ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति की व्याख्या इस प्रकार की है कि वे समय के अनुकूल युद्ध और शान्ति दोनों ही मार्ग अपनाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

दोहरी नीति—चीन की विदेश-नीति पर विचारधारा और राष्ट्रीय हित—दो तत्वों का विशेष प्रभाव है जिनमें असन्तुलन पैदा हो जाने अथवा सामञ्जस्य रहने पर जो नीति बन जाती है उसका अनुमान चीन और रूस के सम्बन्धों के देखकर लगाया जा सकता है। इन दोनों देशों की नीति एक ही साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा की है। दोनों ही देश साम्यवाद का प्रसार करना चाहते हैं और दोनों ही पूँजीवाद के शत्रु हैं। लेकिन दोनों ही के हित परस्पर विरोधी हैं। चीन रूसी नेतृत्व का अनुचर नहीं रहना चाहता। नेतृत्व की होड़ व्यापक राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अत्यधिक संघर्षपूर्ण हो गई है और दोनों साम्यवादी राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध तोड़-फोड़ के कूटनीतिक दाव-पेच खेल रहे हैं। सैद्धान्तिक घरातल पर भी सहयोग-असहयोग का विचित्र संघर्ष है। रूस की वर्तमान विदेश-नीति चीनियों की दृष्टि में सशोधन-वादी, बुजुर्गवादी तथा प्रतिस्पर्धावादी है, पर यह समझ में नहीं आता कि चीन फिर स्वयं अमेरिका की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने लगा है।

लक्ष्य

सितम्बर, 1949 में जन-परामर्श सम्मेलन में साम्यवादी चीन की विदेश-नीति का निरूपण इन शब्दों में किया गया—

“चीनी गणराज्य की विदेश-नीति का उद्देश्य देश की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता व प्रादेशिक सम्मान की रक्षा करना, स्थायी विश्व-शान्ति को सुरक्षित रखना, विभिन्न राज्यों में मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा आक्रमण व युद्ध की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करना है। चीनी गणराज्य विदेशों में बसने वाले चीनियों के उचित अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करेगा।

वह उन सभी लोगों को राजनीतिक शरण प्रदान करेगा जो जन-हित, शान्ति तथा जनतन्त्र के लिए संचालित संघर्ष में भाग लेने के कारण अपनी सरकारों द्वारा पीड़ित हो।”

जब 1 दिसम्बर, 1949 को चीन की साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो विदेश-नीति के ये लक्ष्य घोषित किए गए—(1) चीन की स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा करना, (2) स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सब देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग के लिए प्रयत्न करना, (3) उन विदेशी सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना जो राष्ट्रवादी चीन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर चुकी हो; (4) साम्राज्यवादियों और विशेषतः समुक्तराज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष में साम्यवादी देशों का साथ देना, एवं (5) प्रवासी चीनियों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना, आदि।

चीनी विदेश-नीति के उपर्युक्त सभी लक्ष्य बड़े आकर्षक हैं, लेकिन इनकी व्याख्या चीन की अपनी स्वेच्छाचारी विस्तारवादी है जिसका कोई भी शान्तिप्रिय राष्ट्र स्वागत नहीं करेगा। स्वतन्त्रता और अखण्डता की रक्षा से अभिप्राय है कि साम्यवादी चीन उन भागों पर भी अपना ही अधिकार मानता है जिन पर अधिराष्ट्रीय सरकार का अधिकार है। वे भाग जिन पर चीन का अधिकार था और जो कालान्तर में चीन से छूट चुके थे तथा जिन्हें राष्ट्रीय सरकार वापस नहीं ले सकी, उन्हें भी चीन अपना मानता है। सुदूरपूर्वी मध्य-एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियायी क्षेत्रों में साम्राज्यवादी घाबोलनों को प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन देकर चीन-विस्तारवाद की अपनी कुत्सित प्रवृत्तियों को पूरा करना चाहता है। भारतीय जनतन्त्र को वह अपने मार्ग में बाधा समझता है और उसके शत्रुओं को अपना मित्र। वह भारत और बर्मा द्वारा नियन्त्रित सीमावर्ती क्षेत्र तथा मंगोलिया और कोरिया पर अपना अधिकार चाहता है। उसने मजबूत होने देखा जो मांगता न देकर भारत के साथ सीमा-संघर्ष छेड़ रखा है। अपनी विदेश-नीति में साम्यवादी चीन ने स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की बात कही है। इस सम्बन्ध में चीन का विशेष मत यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति में स्थायित्व तभी आ सकता है जबकि विश्व में साम्राज्यवाद की समाप्ति और साम्यवाद की स्थापना हो जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति का एकमात्र उपाय युद्ध है। मैत्रीपूर्ण भावना वाले देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना की नीति से साम्यवादी चीन का आशय यह है कि गैर-साम्यवादी देशों में अस्थायी निरन्तरता स्थापित कर साम्राज्यवादी देशों की शक्ति को कमजोर किया जाए। चीनी विदेश-नीति में साम्राज्यवादियों और विशेषतया समुक्तराज्य अमेरिका के विरुद्ध संघर्ष की चर्चा की गई है। वस्तुतः पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति चीनवासियों की परम्परागत घृणा और विरोध का बदला साम्यवादी चीन अमेरिका से चुकाने पर उतारू है। चीनी युवकों और युवतियों के दिमाग में यह बात ठूँस-ठूँस कर भर दी गई है कि अमेरिका उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सोवियत संघ से पूर्ण मित्रता के सम्बन्ध बनाए रखने की विदेश-नीति भी आत्मक है, क्योंकि अन्तिम रूप से चीनी

विदेश-नीति का लक्ष्य विश्व में साम्यवादी चीन के एकछत्र प्रभुत्व की स्थापना है। इस दिशा में चीन रूस का कठोर प्रतिद्वन्द्वी है। चीन की विदेश-नीति में प्रवासी चीनियों के हितों की रक्षा का भी उल्लेख है। चीन, मलाया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, कम्बोडिया, दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम, इण्डोनेशिया, बर्मा, लाओस आदि देशों को, प्रवासी चीनियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में आतंकित करता रहा है। किन्तु इसके विपरीत ये प्रवासी उन देशों को खतरा पैदा किए हुए हैं जहाँ वे रह रहे हैं।

चीन की छद्मवेशी विदेश-नीति की इस व्याख्या के उपरान्त हमें उन लक्ष्यों पर दृष्टिपात करना उपयुक्त होगा जिनकी पूर्ति के लिए आज चीन प्रयत्नशील है। ये लक्ष्य इस प्रकार हैं—

1. सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद का प्रसार आज के रूसी ढंग का न होकर विशुद्ध मार्क्सवादी, लेनिनवादी ढंग का शुद्ध साम्यवाद हो।

2. हिंसा, छल, बल और कौशल द्वारा साम्यवादी चीन की सीमाओं का अधिकाधिक विस्तार किया जाए ताकि एशिया में पूर्वी यूरोपीय ढंग के कठपुतली देशों की स्थापना की जा सके।

3. एशिया के समस्त देशों पर प्रभावशाली राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक नियन्त्रण स्थापित किया जाए।

4. सम्पूर्ण एशिया और सुदूरपूर्व में पश्चिम के, विशेषकर अमेरिका के, प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी (चीन की) सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े।

5. एशिया ही नहीं अपितु समस्त विश्व का एकछत्र साम्यवादी नेता बनने की दिशा में हर उपाय से आगे बढ़ा जाए, चाहे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आति-गाइयों से ही यद्यपि क्यों न मोल लेना पड़े। रूस-चीन अन्तर्विरोध का यही एक मुख्य कारण है।

6. सेना को आधुनिकतम और आणविक शस्त्रास्त्रों एवं सैनिक उपकरणों से सुसज्जित करके तथा चीन की राष्ट्रीय शक्ति का सैनिक आधार पर पूर्णतः गठन करके उभरुक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए।

7. एशिया में प्रभुत्व की स्थापना के लिए भारत को घेरने की नीति अपनाई जाए और इस दृष्टि से पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों को पूरी तरह अपने पक्ष में किया जाए। पाकिस्तान के साथ पूरा सैनिक गठबन्धन करने में तो चीन सफल हो चुका है।

चीनी विदेश-नीति की प्रधान अवस्थाएँ (Main Stages of China's Foreign Policy)

साम्यवादी चीन की विदेश-नीति पर टिप्पणी करते हुए डाक बार्नेट ने ठीक ही लिखा है कि—“पेकिंग की नीति कभी भी केवल चिकनी-चुपड़ी बातों अथवा दवावों की नहीं रही। इसमें प्रलोभन, धमकी और तोड़-फोड़ का विभिन्न अनुपात में

सम्मिश्रण रहा है।" चीन अपनी विदेश-नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार कभी एक तत्त्व पर तो कभी दूसरे तत्त्व पर विशेष बल देता रहा है। उसका मूलभूत उद्देश्य यही रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों को अधिकधिक घटाने अनुकूल बनाकर उनका भरपूर लाभ उठाया जाए और अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया जाए। इस दृष्टि से चीनी विदेश-नीति अभी तक चार प्रधान प्रवस्थाओं में से होकर गुजरी है, चौथी प्रवस्था जारी है—

(1) आन्तरिक पुनर्गठन एवं उग्र नीति का युग (1949-1953)

(2) उदारतावादी युग (1954-1959)

(3) नया उग्रतावादी एवं क्रान्तिकारी युग (1959-1969)

(4) सहयोग और मैत्री की नई दृष्टि नीति का काल (1970 से अब तक)

प्रथम युग : आन्तरिक पुनर्गठन का युग (1949-1953)

इस युग में चीन ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति देश की आन्तरिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा दी। इस अवधि में उसकी विदेश-नीति कठोर और उग्र रही—विशेषकर पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति। चीन ने सर्वप्रथम दिसम्बर, 1949 में सोवियत संघ से दोस्त सम्बन्ध स्थापित किए और तत्पश्चात् उसके साथ विभिन्न मैत्रीपूर्ण सुरक्षा एवं पारस्परिक सहायता सम्बन्धी तथा आर्थिक संधियाँ सम्पन्न की। चीनी नेताओं ने सोवियत सहायता से विश्व के अन्य देशों में, विशेषकर अफ्रीका, एशिया के देशों में साम्यवाद के प्रसार का बीड़ा उठाया। इसी उद्देश्य से नवम्बर, 1949 में ट्रेड-यूनिफ़ॉर्म क विश्व मंच के सम्मेलन बुलाया गया। इसमें उपर्युक्त महाद्वीपों के वामपंथी श्रमिक नेता सम्मिलित हुए। सम्मेलन में श्री ल्यू-शाओ-ची द्वारा यह घोषणा की गई कि इस सम्मेलन को सम्पूर्ण एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का समर्थन करना चाहिए। श्री ल्यू-शाओ-ची ने विप्लवनाम, वर्मा, इण्डोनेशिया मलाया, फिलीपाइन आदि के मुक्ति-संग्रामों की ओर सन्नेत करते हुए सम्मेलन के प्रतिनिधियों को उपदेश दिया कि—“चीनी जनता के पक्ष में अनुसरण करते हुए संश्लेषण संपर्क द्वारा एशिया के अधिकांश भाग में क्रान्ति का प्रसार किया जाना चाहिए।” चीनी नेता ने चीनी जनता के पक्ष का स्वरूप भी स्पष्ट किया। उसने इस सम्बन्ध में चार बातों पर विशेष बल दिया—

(i) श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद-विरोधी सभी दलों और संगठनों के साथ मिल जाना चाहिए, (ii) श्रमिक वर्ग को केन्द्र बनाकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी संयुक्त मोर्चा स्थापित किया जाना चाहिए और इसका केन्द्र साम्यवादी दल होना चाहिए, (iii) साम्राज्यवाद के विरुद्ध संपर्क में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित और जनता से घनिष्ठतम सम्बन्ध रखने वाला साम्यवादी दल होना आवश्यक है; एवं (iv) साम्यवादी दल के नेतृत्व में शत्रुओं से लड़ने के लिए राष्ट्रीय सेना का संगठन भी किया जाना चाहिए।

आन्तरिक पुनर्गठन की दिशा में चीनी साम्यवादियों ने दो उद्देश्यों पर विशेष

बल दिया—चीन से विदेशी प्रभाव को पूर्णतः समाप्त कर देना और चीन का एकीकरण कर सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन के अन्तर्गत लाना। इस समय से ही चीनियों ने रूसियों को छोड़कर अन्य सभी पारचात्य देशों के लोगों को चीन से निकालना आरम्भ कर दिया। चीन के एकीकरण के लिए 'चीनी प्रदेशों' को साम्यवादी शासन के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से सन् 1950 में पेरिंग द्वारा तिब्बत पर आक्रमण और कोरिया युद्ध में हस्तक्षेप किया गया, तथापि कतिपय कारणों से चीन ने अपनी युद्ध-नीति में परिवर्तन बाँझनीय समझा। पहला कारण व्यापारिक प्रतिबन्धों से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ थी। इन्हें हल करने के लिए अप्रैल, 1952 में मास्को में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिससे साम्यवादी देशों का गैर-साम्यवादी देशों के साथ व्यापार का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा कारण सन् 1952 की स्टालिन की यह घोषणा थी कि—“पूँजीवाद और साम्यवाद का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव है।” अपने एक लेख में स्टालिन ने यह मिथ्य करने का प्रयास किया कि समाजवाद के प्रसार के साथ-साथ पूँजीवादी देशों की मण्डियाँ कम हो रही हैं। परिणामतः पूँजीवादी विश्व नाना सक्तों और संघर्षों का शिकार बनेगा और अन्ततः समाजवाद से पराजित होगा। अतः साम्यवादियों को पश्चिम के साथ आर्थिक प्रतियोगिता करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से बिना युद्ध किए ही पूँजीवाद की इतिथी हो जाएगी। तीसरा कारण चीन द्वारा यह अनुभव किया जाना था कि एशिया में समुक्तराज्य अमेरिका की शक्ति का विस्तार हो रहा है। चौथा कारण कोरिया-युद्ध द्वारा चीन की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना था। अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के सफल संचालन के लिए दूसरे देशों का सहयोग अपेक्षित था और इसके लिए उदार नीति अपनाना अधिक उचित था। इन्हीं सब कारणों से प्रभावित होकर साम्यवादी चीन के प्रतिनिधि सुझा परिपक्व के सम्मुख भी उपस्थित हुए और उन्होंने सन् 1951 से 1953 तक कोरिया में युद्ध विराम सम्बन्धी वार्ताएँ कीं।

सन् 1949 से 1953 तक की अवधि में साम्यवादी चीन ने विदेश-नीति के क्षेत्र में प्रधानतः रूस का अनुसरण किया। उसका अपना कोई स्वतन्त्र और महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं था। रूस से मित्रता और अमेरिका से शत्रुता—ये दो बातें उनके संपूर्ण कार्यों का आधार रही।

द्वितीय युग : उदारतावादी युग (1954-1959)

यह युग सन् 1954 से 1959 तक रहा, यद्यपि इसका शीर्षक सन् 1952-53 में ही हो चुका था। चीन की उपर और युद्धवादी क्रान्तिकारी नीति में परिवर्तन की पहली सूचना पेरिंग में प्रवृत्त, 1952 में होने वाले एशियायी और प्रशान्त क्षेत्रीय शान्ति-सम्मेलन में मिली। इसमें सन् 1954 के ट्रेड-यूनियन-सम्मेलन के संबंध विपरीत दृष्टि और हिंसा के स्थान पर शान्ति एवं सह-अस्तित्व की चर्चा की गई। इस सम्मेलन ने समुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया कि वह वियतनाम, मलाया एवं अन्य देशों में युद्ध समाप्त कर सन्धि-वार्ता द्वारा न्यायपूर्ण समझौता कराने

की दिशा में प्रयत्नशील हो। सम्मेलन में चीनी प्रतिनिधि द्वारा घोषणा की गई विभिन्न सामाजिक पद्धतियों का शान्तिपूर्ण सह-प्रतिस्तरव सम्भव है। जून, 1953 कोरिया की युद्ध विराम-सन्धि से चीन की इस परिवर्तित छद्मवेशी उदार पद्धति की पुष्टि हुई। सन् 1954 में चीन ने विश्व राजनीति में सन्धि भाग लेना शुरू कर दिया। इस वर्ष उसने जेनेवा सम्मेलन में सट्टवपूर्ण भाग लिया और शान्तिवादी नीति का अनुसरण करने हुए 17वीं प्रस्तावित रेखा पर विपक्षता का विभाजन तथा लाओस और कम्बोडिया की पृथक् व्यवस्था स्वीकार कर ली। प्रचुरी-इन-स्वीकारोक्ति द्वारा चीन ने अपनी शान्तिवादिता का डिंडोरा पीटा जबकि वास्तविकता यह थी कि उसने समझौता इसलिए स्वीकार किया था कि इससे आधे विपक्षता के साम्यवादी राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो रही थी और इसे ग्रहण बनाकर चीनी साम्यवाद आगे बढ़ सकता था। इस सम्मेलन में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाऊ ने यह अनुभव किया कि विभिन्न सरकारों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध और सन्धियों द्वारा चीन की शक्ति वृद्धि के प्रयास करने चाहिए ताकि प्रयत्न आने पर चीन उप शक्ति का अपने पक्ष में उपयोग कर सके। इन नीति का अनुसरण कर चीन ने नवप्रथम प्रमेल, 1954 में निम्नलिखित के द्वारे में सन्धि की धार पक्षशील के मिहान्तों में 'हाईक' आस्था प्रकट की।

पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन की नेकनीयती पर भरोसा नहीं किया और पक्षशील की घोषणा को कोरा प्रचार बताया। फिर भी एशिया के विभिन्न देशों को अपने शब्दनाम और अपनी कुशल कूटनीति द्वारा प्रभावित करने में चीन की उत्प्रेषणीय सफलता प्राप्त हुई। कोरिया-युद्ध में अमेरिका को टक्कर देकर एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में अपनी सैनिक शक्ति का आनक यह पहले ही पंदा कर चुका था, अब, उन्हें शक्तिशाली चीन को अपना निम्न बना लेने में क्या सकोच हो सकता था। चीन को अपनी छद्मवेशी उदार-नीति में सफलता इसलिए भी प्राप्त हुई कि चीन ने पश्चिमी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो जिहाद छोड़ा था अपने सभी एशियाई देशों को सहानुभूति थी क्योंकि वे सब उसमें पीड़ित रह चुके थे। चीनी सफलता का एक और भी कारण था। कोरिया-युद्ध के बाद से ही मधुकराज्य अमेरिका साम्यवाद से सुरक्षा के लिए सैनिक-सन्धियों का जाल बुन रहा था और भारत जैसे देशों की मान्यता थी कि इन सैनिक-सन्धियों द्वारा चीन-युद्ध को एशिया के इस भाग में लाया जा रहा है। चीन ने एशियाई राष्ट्रों की इस मनोदशा का पूरा लाभ उठाया। उसने पश्चिम द्वारा समर्थित सैनिक-सन्धियों और ग्रहणों के विरुद्ध आग उगानी, पश्चिम की इस नीति को नवीन साम्राज्यवादी चाल की मजा दी और शान्ति का ध्वज विस्तृत करने पर बल देते हुए विदेशों के साथ दो-दो सम्बन्ध विकसित करने आरम्भ किए। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में चीनी राजदूत प्रतिष्ठित हो गए। अप्रैल, 1955 में चीन ने वाइंग-सम्मेलन में भाग लिया और एशिया तथा अफ्रीका के 29 राष्ट्रों के सम्मुख प्रयत्न कूटनीतिज्ञता का प्रदर्शन करने हुए अपनी शान्तिवादी उदार नीति का समर्थन किया। वाइंग-सम्मेलन में चाऊ-एन-लाई ने दो

कार्यों से अपने राष्ट्र को शान्ति-प्रेमी सिद्ध करने में सफलता पायी—(1) प्रवासी चीनियों के बारे में इण्डोनेशिया के साथ सन्धि करके उसने एशियायी देशों को आश्वस्त किया कि उन्हें अपने यहाँ के चीनी प्रवासियों से आशंकित नहीं होना चाहिए, एवं (ii) ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए चाऊ ने सन्धि-वार्ता का प्रस्ताव रखा। बांडुंग सम्मेलन के अवसर पर चीन की बहुत प्रशंसा हुई और बाद में सन् 1958 तक चीन की शान्तिप्रियता का यह ढोंग बढस्तूर चलता रहा।

नृतीय युग : नया उग्रवादी युग (1959 से 1969 तक)

यह युग सन् 1959 से आरम्भ हुआ, दृष्टि इसके लक्षण सन् 1957 के उत्तगर्द से ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। सन् 1957 से ही पश्चिमी देशों के साथ साथ एशियायी देशों के प्रति भी चीनी व्यवहार में बदोर्ता आने लगी। नवम्बर में मास्को में बोलशेविक क्रान्ति की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर सत्कार के सभी साम्यवादी दलों के सम्मेलन में चीन की नवीन उग्र नीति का स्पष्ट संकेत मिला। माओ-त्से-तुंग ने 18 नवम्बर के अपने भाषण में पूर्व और पश्चिम के संघर्ष पर बल देते हुए चीन की नवीन नीति का सिह्नाद इन शब्दों में किया—“इस समय विश्व में दो हवाएँ हैं—पूर्वी हवा और पश्चिमी हवा। चीन में एक कहावत है ‘यदि पूर्वी हवा पश्चिमी हवा पर हावी नहीं होगी तो पश्चिमी हवा पूर्वी हवा पर हावी हो जाएगी।’ मेरे विचार में वर्तमान स्थिति की यह विशेषता है कि पूर्वी हवा पश्चिमी हवा पर हावी है अर्थात् समाजवाद की शक्ति पूँजीवाद की शक्ति से अधिक है।”

अपनी नई उग्रवादी नीति का श्रीगणेश करने हुए चीन ने सर्वप्रथम उन लोगों का प्रबल विरोध किया जिनके अनुसार साम्यवादी नीति में कुछ सफोवन होना चाहिए था। तत्पश्चात् सन् 1958 के लेबनान-संकट में चीन के तटवर्ती टापुओं के संकट में तथा सन् 1959 के लासोस संकट में पेकिंग ने कठोर रुख अपनाया। सन् 1959 से तो चीन की विदेश-नीति में अतिस्पष्ट रूप में एक नया मोड़ आया और वह अधिकाधिक उग्र, आक्रामक तथा साम्राज्यवादी बनती गई। सन् 1959 में अपने वचनों का उल्लंघन कर चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता को नष्ट कर दिया और दलाईलामा को अपना देश छोड़ कर भागना पड़ा। इसी समय से चीन भारत के साथ सीमा-विवाद में कठोर नीति का अनुसरण करने लगा और शनैः-शनैः भारतीय सीमा पर उसके अतिक्रमण बढ़ते गए। सन् 1959 में ही श्री खश्चेव ने संयुक्तराज्य अमेरिका की यात्रा की जिसमें चीनी नेताओं ने पसन्द नहीं किया और उनका दृष्टिकोण रूस के प्रति आलोचनात्मक हो गया। इसके बाद धीरे-धीरे रूस अधिकाधिक शान्ति-पूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थक बनता गया और चीनी दृष्टिकोण इस नीति तथा रूस का अधिकाधिक विरोधी होता गया। सन् 1962 में अपने मित्र देश भारत पर चीन के आक्रमण ने उनके साम्राज्यवादी स्वरूप की सूर्य के प्रकाश की भाँति उजागर कर दिया।

अपनी नवीन उग्र नीति के कारण चीन ने दिसम्बर, 1963 से एक नवीन कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया। अफ्रीका महाद्वीप को वा लिए ए. दम. मनु

समकाल वहाँ अपने प्रभाव का तीव्र गति से विस्तार करने के उद्देश्य से दिसम्बर, 1963 में चाऊ एन-लाई ने विभिन्न अफ्रीकी देशों की 8 सप्ताह की यात्रा की। चीनी प्रधानमन्त्री सयुक्तप्रदेश गणराज्य, अल्जीरिया, मालवी, झम्बुवीनिया, घाना, माली, गिनी, मूडान, इथोपिया, सोमालिया आदि देशों में गए और फरवरी 1964 में वहाँ, पाकिस्तान और थाईलैंड की यात्रा भी की। अपनी यात्रा के दौरान श्री चाऊ ने इन देशों का भरमक प्रशंसा किया कि प्रथम तो इन देशों पर गोविन्द व पश्चिमी प्रभाव शीघ्र होकर चीनी प्रभाव में वृद्धि हो जाए और दूसरे भारत और रूस के साथ सीमा विवाद में उसे इन देशों का समर्थन प्राप्त हो जाए, परन्तु सन् 1965 के अन्त तक होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने चीन की विदेश-नीति और नवीन कूटनीतिक अभियान की अमरफलताओं को उजागर कर दिया। वह अल्जीरिया में अफ्रेशियायी राष्ट्रों के वाँदुग जैसा सम्मेलन बुलाने में सफल रहा। अल्जीरिया में अपने विषय वेनवेल्ता द्वारा आसित अल्जीरिया में सम्मेलन का आयोजन कर माओ-त्से-तुंग अफ्रेशियायी देशों पर चीन की धारक बैठाना चाहता था, परन्तु सम्मेलन आरम्भ होने से पहले ही वेनवेल्ता का पतन हो गया। सम्मेलन के आयोजन में सफलता पाने के उद्देश्य से चीन ने अल्जीरिया की नई सरकार का समर्थन किया, परन्तु भारत आदि राष्ट्रों ने सम्मेलन को स्थगित करवा दिया। वेनवेल्ता के विरोधियों का समर्थन कर चीन ने यह सिद्ध कर दिया कि अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए चीन साम्यवाद के सिद्धान्तों को भी उपेक्षा कर सकता है। चीन की स्वार्थपरता ने अफ्रेशियायी देशों में उसे बदनाम कर दिया। पाकिस्तान के प्रति चीन की सहानुभूति की धार भी उस समय खुर गई, जब भारत-पाक संघर्ष के समय चीन भारत को केवल धमकी देना रहा और इस तरह उसने पाकिस्तान की आशा को आघात पहुँचाया कि चीन भारत की गहरी हानि पहुँचाकर पाकिस्तान के प्रति अपनी दोस्ती का सच्युत देगा। चीन के इस रुख से पाकिस्तान को मत हँ। मत बहून अप्रसन्नता व निराशा हुई। इसके अनिश्चित साम्यवादी देशों को भी इस बात से बड़ी ठेग पहुँची कि चीन अपने पोर शत्रु संयुक्त-राज्य अमेरिका के मिट्टू और उसने सैनिक सहायता पाने वाले पाकिस्तान का खूनम-बुल्ला समर्थन कर रहा था। सन् 1965 में ही इण्डोनेशिया में चीन के इरादों की मिट्टी में मिला दिया गया। चीन प्रेरित साम्यवादी क्रांति अमरक्य हुई और इण्डोनेशियायी सेना ने साम्यवादियों का बुरी तरह दमन किया। विश्व के साम्यवादी दलों में इण्डोनेशियायी साम्यवादी दल का एक विनिष्ट स्थान था। उसके प्रघातन से विश्व के साम्यवादी आन्दोलन को गहरा आघात पहुँचा और साथ ही पैकिंग पिडी-जकार्ता घुसी दिन-मिश्र हो गई। अफ्रेशियायी देशों में भी चीन का प्रभाव सीख हो गया और व चीनी साम्यवाद के तबरे को समझने लग गए। दिसम्बर, 1965 में मलावी के प्रधानमन्त्री डॉ. हेस्टिंग्स बाग्डा ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की—

“अफ्रीका की रिलतता के बारे में चीनी यह समझते हैं कि इनकी पूर्ति उन्हीं के द्वारा होनी है। पैकिंग के लोग चनेदस्ता की कल्पना से भी बड़ा ऐसा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सम्पूर्ण एशिया तथा अफ्रीका सम्मिलित हो तथा यदि

जनता आपत्ति न करे तो इसमें यूरोप और अमेरिका भी सम्मिलित हो। जब मैक्मिकान पर विचार करता हूँ तो मुझे इसीसे से जना नय नही है जितना चीनियों से है। समय की गति के साथ रूमी नरम पड़ गए हैं, किन्तु चीनी नरम नहीं पड़े हैं।

अफ्रीका महाद्वीप में चीन तेजी से अपनी प्रतिष्ठा खोता गया और पेरिंग से कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद का क्रम आरम्भ हो गया। इसी बीच चीन तथा रूस के सम्बन्धों में भी काफी बिगाड़ आ गया। दोनों के सैद्धान्तिक मतभेद उग्र हो गए। चीन सोवियत संघ को सशोषणवादी और सोवियत संघ चीन को कट्टरपंथी कहकर दोनों एक दूसरे को बदनाम करने लगे। वास्तव में साम्यवादी जगत् के लिए नेतृत्व की होड़ शुरू हो गई क्योंकि चीन ने रूसी नेतृत्व अस्वीकार कर दिया। दोनों देशों में कटु सीमा-विवाद भी उत्पन्न हो गए और मार्च, 1969 में सीमा पर सैनिक भड़पें भी हुई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि दोनों देशों के सम्बन्ध विच्छेद के कगार पर पहुँच गए।

चतुर्थ युग : सहयोग और मैत्री की कूटनीति का युग (1970 से अब तक)

उग्रतावादी एवं आन्तिकारी युग में साम्यवादी चीन ने आतंक और तोड़ फोड़ की जिस विदेश-नीति का अनुसरण किया उससे वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में काफी बदनाम हो गया और उसके दो धनिष्ठ मित्र भारत और रूस उसके विरुद्ध हो गए। चारों ओर से उमका विरोध होने लगा और वह लगभग अलग-थलग पड़ गया। चीन ने अपनी इस पृथक्ता की स्थिति को तोड़ने के लिए एशिया और अफ्रीका के छोटे देशों में अपने प्रभाव-विस्तार की चेष्टाएँ की, किन्तु तब भी वह लगभग असफल रहा। अरब जगत् ने नासिर के नेतृत्व में चीनी कूटनीति का शिकार होने से स्वयं को बचाए रखा। अतः यह प्रावश्यक हो गया कि चीन अपनी विदेश नीति का पुनर्पूर्णांकन कर आतंक एवं तोड़-फोड़ के स्थान पर सहयोग, मैत्री एवं सह-प्रस्तित्व की नीति अपनाए—चाहे मौलिक रूप में उमका इनमें विश्वास नहीं था। सन् 1970 के प्रारम्भ से ही चीन ने अपनी विदेश नीति का संचालन पुनः इस रूप में आरम्भ किया ताकि अधिकाधिक मित्र और समर्थन प्राप्त किया जा सके तथा पुरानी नीति के कारण विदेश नीति के स्वरूप में जो बिगाड़ पैदा हुए थे, उन्हें सुधार कर विश्व के देशों को अपनी 'सदाशयता' में विश्वास दिलाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ ऐसी करवट ली कि चीन का मार्ग सुगम हो गया। राष्ट्रपति निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका ने अपना चीन-विरोधी रवैया शिथिल कर दिया, चीन की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया तथा अमेरिकी सहयोग से रूमी नेतृत्व का मुकाबला करने के लिए चीन को प्रार्थित किया। चीन को सयुक्तराष्ट्र तब में भी प्रवेश मिल गया जिससे उसे सुप्रचमर प्राप्त हुआ। सांस्कृतिक क्रान्ति की सफलता आर्थिक और सैनिक शक्ति में तीव्र विकास तथा महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होने की आकांक्षा ने चीन को प्रेरित किया कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 'बचकाना' हरकतों का रास्ता त्याग दे।

मैत्री, सहयोग और सयम की नयी कूटनीति अपनाते हुए चीन ने एक ओर अमेरिका के साथ सम्बन्ध स्थापित करने शुरू किए तथा दूसरी ओर रूस के विरुद्ध

अपना प्रचार अभियान कम किया। सन् 1970 में ही रुस और चीन के बीच पुनः एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसके बाद से एक दूसरे पर कठोर शब्दों का प्रयोग कम होता गया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने चीन की यात्रा की तथा दूसरे देशों के साथ भी चीन 'रिंग-पांग कूटनीति' के मार्ग पर चलने लगा। भारत के प्रति चीनी रवैया यद्यपि पूर्ववत् रहा तथापि दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक संधि में न तो पहले की तरह चीन द्वारा भारत को कोई 'गस्टीमेटम' दिया गया और न ही सीमा पर सैनिक हलचल करके तनाव पैदा किया गया। सन् 1970 से भारत के सीमान्त पर चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ों की वारदातें भी नहीं हुई हैं। कूटनीतिक क्षेत्र में चीन का भारत विरोधी रवैया किसी भी अनुपात में रहा हो, लेकिन व्यवहार में उसने भारत को सैनिक दृष्टि में भडकाने वाली कोई कार्यवाही करने में सफल नहीं किया है। पाकिस्तान को सैनिक सहायता और कूटनीतिक समर्थन देकर अपने पक्ष में करने की चीनी नीति पूर्ववत् सक्रिय है, लेकिन चीनी नेताओं ने अपने व्यवहार से यह संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान को ऐसी कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि उसके कारण वह भारत से सैनिक संधि में उलझने की भूल करेगा। सन् 1976 में पेरिस में भारतीय राजदूत की नियुक्ति के बाद दोनों देशों में कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए हैं जो सन् 1962 के चीनी हमले के बाद टूट गए थे। यह आशा की जाती चाहिए कि चीन भारत की मंत्री के महत्त्व को स्वीकार कर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। नवम्बर, 1977 में भारत के विदेश मंत्री श्री वाजपेयी का यह संकेत उत्साहजनक है कि दोनों ही देश परस्पर सम्बन्ध सुधारने को प्रयत्नशील हैं।

अब हमें देखना है कि प्राग्भ से चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कैसे रहे, विभिन्न देशों के साथ उनकी विदेश नीति किस रूप में संचालित हुई तथा वर्तमान चीनी नीति का व्यावहारिक रूप क्या है।

चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (International Relations of China)

विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के साथ चीन के जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध रहे हैं उनका विवेचन सयुक्तराज्य अमेरिका, सोवियत संघ और भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में विस्तार से किया जा चुका है। अब यहाँ चीन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का तथैतिक विवेचन ही अपेक्षित है।

चीन और अमेरिका

राष्ट्रपति निक्सन द्वारा चीन के प्रति मंत्री का हाथ बढ़ाने से पूर्व दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त शत्रुतापूर्ण थे। अमेरिका ने नवोदित साम्यवादी चीन को न केवल मायगता देने से इकार कर दिया बल्कि सयुक्तराष्ट्र में उसके प्रवेश के विरुद्ध भी मोर्चाबन्दी की। अमेरिका की नीति मुख्यतः यह रही कि साम्यवादी चीन के साथ मत्री और सहानुभूति रखने वाले देश अमेरिका के मित्र नहीं माने जा सकते। सन् 1950 में कोरिया युद्ध में सयुक्तराष्ट्र सघीय सेनाओं ने अमेरिकी कमान में युद्ध

लड़ा । जब मयुक्तराष्ट्र संधीय सेनाएँ 38 अक्षांश रेखा को पार कर मालू नामक स्थान पर पहुँची तो उत्तर कोरिया की ओर से चीनी सैनिक टिड्डो-दल की भाँति उन पर टूट पड़े । कोरिया का युद्ध अब प्रचलित, अमेरिका व चीन का युद्ध बन गया । अक्तूबर, 1951 में माग्रोसे-नुंग ने कहा—“हम अपने देश की रक्षा के लिए ही ‘साम्राज्यवादी आक्रमणों’ के विरुद्ध लड़ रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यदि अमेरिकी सेनाओं ने हमारे ताइवान (फारमोसा) पर कब्जा न किया होता और हमारे साम्यवादी मित्र-राज्य पर दक्षिणी कोरिया ने आक्रमण न किया होता तथा स्वयं अपनी कार्यवाहियों का विस्तार हमारी उत्तर-पूर्वी सीमा तक न किया होता तो हम आज अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध लड़ रहे होते ।”

कोरिया-युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका ने फारमोसा को साम्यवादी चीन के सम्भावित आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए खुल कर सैनिक सहायता देने का निश्चय कर लिया । अमेरिका के इस निश्चय ने दोनों देशों के सम्बन्धों को और भी अधिक कटु बना दिया । चीन में वाशिंगटन-विरोधी प्रचार-प्रभियान तीव्र कर दिया गया । क्लॉड बस (Claud Buss) के शब्दों में—“चीनवासियों ने अमेरिका पर जापान में फासिस्टवाद तथा सैनिकवाद की पुनर्स्थापना करने तथा एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जापान का एक साधन के रूप में प्रयोग करने के आरोप लगाए । इसी तरह उन्होंने अमेरिका को दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति शिमन री की सहायता करने एवं कोरिया में युद्ध-युद्ध छेड़ने के लिए भी दोषी ठहराया ।” चीन के साम्यवादी नेताओं ने कोरिया-युद्ध की व्याख्या करते हुए कहा कि—“यह युद्ध कोरिया, फारमोसा, हिन्दी चीन एवं फिनीषाईन्स पर कब्जा करने तथा उसके पश्चात् एशियायी मामलों में हस्तक्षेप करने के अमेरिकी षडयन्त्र का ही अग्रिम भाग है ।”

साम्यवाद के प्रसार को अवरोध करने के लिए मयुक्तराज्य अमेरिका ने विभिन्न सैनिक और प्रतिरक्षात्मक मण्डलों का निर्माण किया । अमेरिका द्वारा निर्मित और प्रेरित नाटो, सीटो, अज़ुपस (ANZUS), बगदाद पैक्ट (पब सैंटो) तथा मध्य पूर्वी कमान सन्धियों की साम्यवादी चीन ने यह कहकर तीव्र भर्त्सना की कि इन सबका उद्देश्य विश्व में अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना करना है । अमेरिकियों के लिए चीन की मुख्य भूमि के द्वार बन्द कर दिए गए । अनेक बार तो अमेरिकी पत्रकारों तक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई । चीन-स्थित अमेरिकी सम्पत्ति भी ज्वन कर ली गई । अमेरिका के साथ व्यापारिक सम्बन्ध पूर्णतः भंग कर दिए गए । उसके साथ सभी प्रकार के सम्पर्कों पर—चाहे वे सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों या कूटनीतिक हों—रोक लगा दी गई । कोरियाई युद्ध में जिन अमेरिकी चालकों को बन्दी बना लिया गया था, उन्हें भी सोवियत रूस के आग्रह पर बड़े वाद-विवाद के बाद मुक्त किया गया ।

सन् 1954 में हिन्द चीन के प्रश्न पर भी दोनों देशों में काफी तनाव पैदा हो गया। डीन-विन-गू में फ्रेंच सेनाओं की निष्पत्ति पराजय के उपरान्त जब वाशिंगटन ने फ्रांस की सहायतायें भारी सख्या में अपनी सेनाएँ भेजने का निश्चय किया तो अमेरिका और साम्यवादी चीन में प्रत्यक्ष युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। सन् 1959 में चीन और अमेरिका के बीच संपर्क के नए कारण उत्पन्न हो गई। लाओस में संपर्क के लिए चीन ने अमेरिका को उत्तरदायी ठहराया और कहा कि वह वियतनाम के प्रजातन्त्रवादी गणराज्य एवं चीन की सुरक्षा को सीधी चुनौती देने के लिए ही सुदूर पूर्व में संपर्क चाहता है। विवाद को शान्ति के बारे में समुत्तराज्य अमेरिका के रवैये से भी चीन को भारी क्षोभ हुआ। इसके प्रतिरिक्त जनवरी, 1960 में जापान तथा अमेरिका के बीच जो पारस्परिक सहयोग एवं सुरक्षा की सन्धि सम्पन्न हुई, उससे भी चीन के सम्बन्ध कटु बने। चीन ने हर सम्भव प्रयत्न द्वारा जापान व अमेरिका के गठबन्धन को निरस्त करने का प्रयास किया। पॅकिंग रेडियो ने अमेरिका पर एशिया में साम्राज्यवादी पद्धन्त रचने का आरोप लगाया। 9 मितम्बर, 1962 को साम्यवादी चीन की वायुसेना ने कुयोमिताग सेना के एक यू-2 सैनिक जॉब वायुयान को चीन की मृत्त भूमि पर मार गिराया। चीन सरकार ने इस घटना पर एक विस्तृत पत्रकार प्रसारित किया और अमेरिका को इस विमान की उड़ान के लिए उत्तरदायी ठहराया। अक्टूबर, 1962 में 'क्यूबा संकट' के समय साम्यवादी चीन द्वारा समुत्तराज्य अमेरिका के विरुद्ध भारी बिष-बमन किया गया। सम्पूर्ण चीन में क्यूबा समर्थक विमान प्रदर्शन सगठित किए गए, क्यूबा समर्थक नारे लगाए गए और क्यूबा के नेताओं के चित्रों का प्रदर्शन किया गया। सन् 1962 में समुत्तराज्य अमेरिका ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध भारत को जो प्रभावशाली सैनिक सहायता भेजी, उससे भी साम्यवादी चीन के आक्रोश में वृद्धि हुई।

सन् 1965-66 में वियतनाम-ममन्ग के प्रश्न पर दोनों देशों के सम्बन्धों में कटुता में और भी वृद्धि हुई। वियतनाम में शान्ति-स्थापना के हर प्रयास को चीन ने असफल बनाने की कोशिश की। चीन की प्रेरणा से ही उत्तर-वियतनाम ने ममी शान्ति-प्रस्तावों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाते हुए केवल अपने ही प्रस्ताव को मानने पर बल दिया। जब हवाई सरकार शनैः-शनैः पॅकिंग की अपेक्षा मास्को के अधिक निकट घाने लगी तो यह भी चीन को बुरा लगा और उसका प्रयत्न यही रहा कि हवाई चीन के सैनिक निर्वेशन में दक्षिण वियतनाम में घुसकर रहे।

राष्ट्रपति जॉनसन के समय तक चीन और अमेरिका के सम्बन्ध निरन्तर कटु होते गए। वियतनाम युद्ध का कुप्रभाव सम्पूर्ण अमेरिकी प्रबंधन-संस्था पर पड़ने लगा और डॉनर की स्थिति कमजोर होती गई। इसके साथ ही कूटनीतिक क्षेत्र में सोवियत रूस की मफला ने विशेषकर मध्यपूर्व क्षेत्र और भारतीय उपमहाद्वीप में रूसी प्रभाव ने, अमेरिका को चिन्तित कर दिया। अतः जॉनसन के उत्तराधिकारी

राष्ट्रपति निक्सन ने ऐसे प्रयत्न आरम्भ किए जिनका उद्देश्य चीन से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना था ताकि एक ओर तो वियतनाम-युद्ध से अमेरिका ससम्मान पीछा छुड़ा सके और दूसरे सोवियत प्रभुत्व को सफल चुनौती देते हुए राजनीतिक क्षेत्र में पैकिंग-पिण्डी-वाशिंगटन धुरी का निर्माण कर, शक्ति-सन्तुलन अपने पक्ष में करले। अमेरिका को यह लालसा भी रही कि लगभग 70 करोड़ की विशाल जनसंख्या वाले देश से मंत्री-सम्बन्ध स्थापित करके अमेरिका व्यापक व्यापारिक और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। चीन की भी यह आकांक्षा थी कि सोवियत हस्त के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए वह अमेरिका जैसे सख्त राष्ट्र को अपने पक्ष में करले।

सम्बन्ध-मुधार की इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप चीन-अमेरिका के बीच 'पिंगपोंग कूटनीति' का उदय हुआ। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार, यात्रा और जहाजरानी सम्बन्धी कानूनी रुकावटों में ढील दे दी तथा अपनी टेबलटेनिस टीम को पिंगपोंग खेलने के लिए चीन भेजा। सन् 1970 में माओ-त्से-तुंग ने अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो के साथ बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति का चीन में स्वागत करने की इच्छा प्रकट की। दोनों देशों में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु वारसा, पेरिस आदि स्थानों पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच वार्ताओं का दौर आरम्भ हुआ जिनकी प्रगति के आधार पर 15 जुलाई, 1971 को बहुत ही नाटकीय ढंग से राष्ट्रपति निक्सन ने मई, 1972 के पूर्व अपनी चीन-यात्रा की घोषणा की। भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इस घोषणा का स्वागत किया और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामन्त्रि ने इन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक नया अध्याय प्रारम्भ करने वाली घटना बतलाया। 21 फरवरी, 1972 को राष्ट्रपति निक्सन दलबल सहित पैकिंग पहुँचे। संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार दोनों देशों में अनेक विषयों पर मतभेदों के बावजूद सोहार्दपूर्ण वार्ता हुई। दोनों देशों ने ज्ञान और कला के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक विनिमय और सम्पर्क का निश्चय किया। आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्धों में वृद्धि पर भी विचार-विमर्श किया गया। यह भी निश्चय किया गया कि सामान्य हित के विषयों पर विचार-विनिमय और सम्बन्धों के सामान्यीकरण के लिए विभिन्न माध्यमों से अधिकाधिक सम्पर्क स्थापित किया जाए। निक्सन की पैकिंग-यात्रा के बाद दोनों देशों के सम्बन्ध तेजी से सामान्य बनते गए। बंगलादेश के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में दोनों ने आपस में सहयोग किया। फरवरी, 1973 में निक्सन क निजी सलाहकार हेनरी किस्सिजर ने पैकिंग में चाऊ-एन-लाई तथा अन्य नेताओं से वार्ता की। अमेरिका और चीन द्वारा एक दूसरे के यही सम्पर्क कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया। यद्यपि इन कार्यालयों को दूतावास की सजा नहीं दी गई कथापि व्यवहार में इनका कार्य दूतावास जैसा ही रखा गया। दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि हुई। पारस्परिक व्यापार-विस्तार का एक निश्चित कार्यक्रम बनाया गया। चीन ने अमेरिका के दो बग्दी वायुयान-चालकों को मुक्त कर और अमेरिका ने ताइवान में अपनी सेना में पर्याप्त कटौती का संकेत देकर यह प्रदर्शित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों देश अधिकाधिक निकट आने को उत्सुक हैं।

दोनों देशों के सम्बन्धों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया तब कुछ मन्द हो गई जब चीन ने देखा कि अमेरिका रूस के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने के प्रयत्नों में महत्वपूर्ण विषयों पर बातों में चीन की उपेक्षा कर रहा है। नवम्बर, 1974 में जब अमेरिकी विदेश मंत्री डॉ. किस्सिंगर चीन गए तो उनके स्वागत में उदासीनता प्रकट कर चीनी नेताओं ने अपनी अप्रमत्तता प्रकट की। इस अप्रमत्तता के दो प्रमुख कारण थे—अमेरिका द्वारा ताइवान सम्बन्धी लग बर्पाई-समझौते को कार्यान्वित न किया जाना जो साल भर पहले दोनों के बीच हुआ था, एवं अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेज्नेव द्वारा वार्ता के लिए व्लाडीवोस्तोक को चुनना। व्लाडीवोस्तोक कभी चीन का हिस्सा था; अतः चीन ने सोचा कि इसे चिढ़ाने के लिए इसे वार्तास्थल चुना गया है। सन् 1972 की बर्पाई विज्ञप्ति में किए गए वायपरी में एक महत्वपूर्ण वायदा यह था कि अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मान लेगा। अप्रैल, 1975 में च्वांग-काई-शेक की मृत्यु के बाद ताइवान अब फिर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रावर्ण्य केन्द्र बन गया। मार्शल च्वांग के निधन का न केवल ताइवान की अन्तरिक राजनीति पर बल्कि अन्य देशों से सम्बन्धों पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। वैसे च्वांग के उत्तराधिकारी उनके पुत्र प्रधानमन्त्री च्वांग-जुंग-कुओ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने देश पर कभी भी साम्यवाद की छाया नहीं पड़ने देंगे और चीन की मुख्य भूमि को साम्यवाद से मुक्त करने के लिए निरन्तर सपर्प करते रहेंगे।

निकसन के हटने के बाद से ही अमेरिका और चीन के सम्बन्धों में कुछ शिथिलता उत्पन्न हो गई है। जैसा कि अमेरिकी विदेश-नीति के सन्दर्भ में बताया। चुका है, जब डॉ. किस्सिंगर ने अक्टूबर, 1975 में और राष्ट्रपति फोर्ड ने 1 दिसम्बर, 1975 में चीन की यात्रा की तो उनका बहुत ही फीका स्वागत हुआ।

20 जनवरी, 1977 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर श्री जिम्मी कार्टर आरुढ़ हुए और विदेश मंत्री पद पर उन्होंने श्री साइरस वेंस को नियुक्त किया। कार्टर प्रशासन अमेरिकी विदेश नीति को एक नई दिशा देने की प्रयत्नशील है। कार्टर की यह इच्छा है कि चीन के साथ अमेरिका के सम्बन्धों में सुधार हो, किन्तु इस दिशा में वे अपने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते और न ही भुक्त कर कोई काम करना चाहते हैं। नवम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह में अमेरिका विदेश मंत्री श्री वेंस ने चीन की यात्रा की लेकिन वार्ता में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी। ताईवान में अमेरिका के सम्बन्ध विच्छेद के प्रश्न पर गतिरोध बना रहा। अमेरिका को इन बातों में काफी गिराशा हुई कि पेकिंग में अमेरिकी विदेश मंत्री की उपस्थिति को कोई लाभ महत्व नहीं दिया गया। अमेरिका के एक भूतपूर्व उपविदेश मंत्री जॉर्ज बाल ने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी कि ताइवान के साथ सम्बन्ध-विच्छेद करके पेकिंग के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करना राष्ट्रपति कार्टर की विदेश-नीति की भारी पराजय है। ऊपर कुछ अमेरिकी क्षेत्रों में यह भी कहा गया कि यदि अमेरिका चीन के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं करता है

और ताइवान के साथ मैत्री की अपनी नीति पर अड़ा रहता है तो निश्चय ही पैकिंग और मास्को के मतभेद कम होंगे और चीन का रुझान सोवियत संघ की तरफ अधिक हो जाएगा। अमेरिका के रक्षा-विभाग की खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत अपने एक प्रतिवेदन में बताया कि चीन की परमाणु प्रक्षेपास्त्र छोड़ने की शक्ति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वह इस दिशा में प्रगति कर रहा है। चीन के पास इस समय जो परमाणु प्रक्षेपास्त्र हैं वे सोवियत संघ और ऑस्ट्रेलिया तक तो मार कर सकते हैं पर अमेरिका के किसी भाग तक नहीं पहुंच सकते।

राष्ट्रपति कार्टर के लिए चीन की इन शर्तों को एनाएक स्वीकार कर लेना बहुत कठिन है कि अमेरिका ताइवान से राजनयिक सम्बन्ध पूर्णतः विच्छेद कर ले, अपनी सेनाएँ वहाँ से बिल्कुल हटा ले और राष्ट्रवादी चीन के साथ अपनी सुरक्षा-सन्धि पूर्णतः समाप्त कर दे। कार्टर प्रशासन यह स्पष्ट कर चुका है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसका यह अर्थ लगाया जाए कि उसने ताइवान का परित्याग कर दिया है। कार्टर प्रशासन के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री श्री वेंस की वर्तमान पीकिंग घाटी सम्बन्ध सुधार की दिशा में केवल एक 'प्रारम्भिक यात्रा' है। चीन के प्रति अपनी नीति को एक नया मोड़ देते हुए ही कार्टर प्रशासन ने चीन को विभिन्न प्रकार के हथियारों तथा विद्युत आणविक उपकरणों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में ढील देने का निश्चय किया है। अब तक ये हथियार सामान्यतया निर्यात नहीं किए जाते थे। अबपय ही इन हथियारों और उपकरणों के डिजाइन तथा निर्माण-तकनीक के निर्यात पर नियन्त्रण यथावत लागू रहेगा। सितम्बर, 1977 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रक्षा मन्त्रालय को इस आशय के निर्देश भेज दिए हैं। अमेरिका के इस नई नीति की घोषणा ऐसे समय की गई जब चीन का एक व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल अमेरिकी प्रौद्योगिकी का सर्वेक्षण करने के लिए अमेरिका आया हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स की टिप्पणी थी कि नई अमेरिकी नीति का सर्वाधिक लाभ चीन को ही उपलब्ध होगा।

चीन और सोवियत संघ

चीन और सोवियत संघ दो महान् साम्यवादी राष्ट्र हैं। इनके पारस्परिक सम्बन्ध मैत्री और शत्रुता, सहयोग और स्पर्धा, भ्रातृत्व और वैमनस्य की कहानी है। 1 अक्टूबर, 1949 को साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद रूसी-चीनी मैत्री तेजी से विकसित होती गई, लेकिन कुछ ही वर्ष बाद न केवल सैद्धान्तिक मतभेद उभरे बल्कि सीमा-विवाद भी उठ खड़े हुए और सशस्त्र सीमा-संघर्ष भी चालू हो गए। आज स्थिति यह है कि एक ओर तो चीन और अमेरिका, जो कभी परस्पर शत्रु थे, सोवियत संघ के विरुद्ध हाथ मिला रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका और सोवियत संघ परस्पर सहयोग द्वारा चीन की विस्तारवादी आकांक्षाओं पर अक्रुश लगाने को सचेष्ट हैं। रूस-चीन-अमेरिका का यह त्रिकोणात्मक संघर्ष विश्व-राजनीति में अान्तिकारी परिवर्तन ला रहा है।

रूस-चीन में सहयोग का काल

चीन में जनवादी गणतन्त्र की स्थापना होते ही सोवियत रूस ने उसे अपनी मान्यता प्रदान कर दी और माओ-त्से-तुंग ने फरवरी, 1950 में रूस की यात्रा के दौरान 24 फरवरी को दोनों के बीच तीन सन्धियाँ सम्पन्न की—(1) 30 वर्ष के लिए भूमी सन्धि, (2) व्यापक चुन-रेल्वे पोर्ट आर्थर तथा दाइरल से सम्बद्ध सन्धि, एवं (3) ऋण सम्बन्धी सन्धि। प्रथम सन्धि के अन्तर्गत जापानी अथवा उसके सट्टेज से किसी भी विदेशी आक्रमण की स्थिति में दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे की सहायता करने तथा पारस्परिक हितों को ठेस पहुँचाने वाली किसी भी सन्धि में सम्मिलित न होने का निश्चय किया गया। जापान के साथ शान्ति सन्धि के लिए प्रयास करने, समान हितों के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर आपसी विचार विमर्श करते रहने तथा पारस्परिक घनिष्ठ आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर भी सहमति प्रवृत्त की गई। द्वितीय सन्धि द्वारा सोवियत संघ ने व्यापक चुन-रेल्वे को जापानी शान्ति सन्धि के बाद अथवा अधिक से अधिक सन् 1952 के अन्त तक चीन की हस्तान्तरित करने का वचन दिया। यह भी निश्चित हुआ कि सन् 1952 तक सोवियत संघ की सेनाएँ पोर्ट आर्थर से वापस बुला ली जाएंगी। तृतीय सन्धि के माध्यम से सोवियत संघ ने चीन को 5 वर्ष की अवधि के लिए 3 करोड़ डॉलर का ऋण देना स्वीकार किया। इस ऋण को 5 किश्तों में दिया जाना तथा 31 दिसम्बर 1954 के पश्चात् 10 किश्तों में लौटाया जाना तय हुआ।

सन्धियाँ सम्पन्न होने के उपरान्त कुछ वर्षों तक रूस-चीन मंत्री विकसित होती रही। सितम्बर, 1952 में व्यापक चुन-रेल्वे चीन को लौटा दी गई, परन्तु पोर्ट आर्थर के बारे में यह निश्चय हुआ कि वह तब तक नहीं लौटाया जायगा जब तक कि जापान की रूस और चीन के साथ शान्ति-सन्धि नहीं हो जाती। बाद में सन् 1954 में यह तय किया गया कि पोर्ट आर्थर सन् 1955 में चीन को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। मई, 1955 में इसे चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस अवधि में सोवियत संघ द्वारा चीन को दी जाने वाली वित्तीय, वाणिज्य और प्राविधिक सहायता में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। चीन का लगभग 70 प्रतिशत व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसमें सन् 1950 के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली गई। सन् 1954 में रूस ने चीन की अणुशक्ति उत्पादन में भी सहयोग देना स्वीकार किया, परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन द्वारा अणु परीक्षण रूस की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त चीनी-रूसी मंत्री समूह स्थापित किए गए।

सोवियत संघ ने चीन को संयुक्त राष्ट्रमण्डल में स्थान दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास किया। सन् 1954-55 में दोनों ही देशों ने पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका निमित्त प्रादेशिक सैनिक समूहों की बटु आलोचना की। सन् 1956-57 में दोनों ने मिस्र पर विटेन व फ्रांस के आक्रमण की निन्दा की। हंगरी में जब दक्षिणपंथी विद्रोह हुए तब भी दोनों देशों में नियमित रूप से विचार-विमर्श होने रहे। सन् 1958 में टीटो के सशोषनवाद की बटु आलोचना भी दोनों देशों द्वारा की

गई। सोवियत संघ की भांति ही अन्य समाजवादी देशों के साथ चीन ने, मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहे।

रूस-चीन में मतभेद और तीव्र वैमनस्य का काल

रूस और चीन के मंत्रीपूर्ण सम्बन्धों में तनाव का बीजारोपण सन् 1954 में ही प्रकट हो गया। सोवियत-साम्यवादी दल की 23वीं कांग्रेस में श्री ख्रुश्चेव ने युद्ध और हिंसात्मक क्रान्ति की अनिवार्यता से इन्कार करते हुए विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया और ससदीय तरीके से समाजवाद की स्थापना को समर्थन दिया। श्री ख्रुश्चेव की ये मान्यताएँ चीनी नेताओं के गले नहीं उतरी। चीनी साम्यवादी दल ने ख्रुश्चेव पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया और आलोचना-प्रत्यालोचना की खुली शुरुआत हुई। सन् 1956 में और तत्पश्चात् 1961 में रूसी साम्यवादी दल की कांग्रेस में ख्रुश्चेव द्वारा स्टालिन की निन्दा ने दोनों देशों में मतभेद और सैद्धान्तिक सवर्ण उग्र कर दिए। ख्रुश्चेव के स्टालिन विरोधी अभियान को विस्तारित करने की संज्ञा दी गई। जब मास्को यूगोस्लाविया को साम्यवादी आतृत्व में वापस लाने को तत्पर हुआ तो भी चीन को बहुत बुरा लगा। सितम्बर, 1959 में ख्रुश्चेव की अमेरिका-यात्रा चीन ने पसंद नहीं की और इसलिए चीन की यात्रा के समय सोवियत नेता का कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। सन् 1959 में अपनी चीन यात्रा के समय ख्रुश्चेव ने पुनः यह बात दोहराई कि साम्यवादी चाहें कितने ही सशक्त हो जाएँ, उन्हें पूँजीवादी जगत के विरुद्ध शक्ति के प्रयोग से बचे रहना चाहिए। चीनी मार्क्सवादियों को ख्रुश्चेव का उपदेश 'प्रतिक्रियावादी शक्तियों की प्रगतिवादी शक्तियों पर विजय' जैसा लगा। सन् 1959-60 में भारत-चीन सीमा-विवाद पर ख्रुश्चेव की यह टिप्पणी भी चीनी नेताओं को अखरी कि दोनों देश अपना सीमा-विवाद शीघ्र ही शान्तिपूर्ण ढंग से निपटा लें।

दोनों देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद उग्र होते गए। जून, 1960 में बुखारेस्ट में रूमानिया कर्मचारी दल के तृतीय सम्मेलन में ख्रुश्चेव ने पुनः कहा कि लेनिन का 'पूँजीवाद के विरुद्ध युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धान्त' अब लागू नहीं होता। दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है, युद्ध का खतरा बना रहेगा। जुलाई, 1960 में रूस द्वारा चीन की विकास-योजनाओं में कार्यरत सोवियत वैज्ञानिकों को वापस बुला लिया गया। चीन को सामग्री, मशीनें आदि भेजना भी बन्द प्रत्यक्ष सीमित कर दिया गया। सन् 1961 में प्रकाशित सोवियत साम्यवादी दल के कार्यक्रम में 20 वर्ष की अवधि में रूस में साम्यवाद की स्थापना का नारा बुलन्द किया गया। इस कार्यक्रम में साम्यवाद का अर्थ वस्तुओं की प्रचुरता बनवाया गया। चीनी साम्यवादी दल के लिए साम्यवाद की यह व्याख्या अत्यन्त आपत्तिपूर्ण थी। सन् 1962 में रूस द्वारा भारत को मिग विमान देने और उन्हें बनाने के कारखानों में सहायता देने की भी चीनी नेताओं को खतरनाक लगा। सन् 1962 में ही दूना-काण्ड ने कहा कि रूस का पहला दोष था 'दुस्ताहस' और दूसरा दो

अमेरिका के घाते 'धृष्टित आत्म-समर्पण' करना। सन् 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में अपनायी गई रूसी नीति ने भी चीन को अप्रसन्न करने में भाग में ची का काम किया।

जुलाई, 1963 में मास्को में रूसी और चीनी साम्यवादी दलों की वार्ता न केवल असफल हुई बल्कि दोनों देशों ने एक दूसरे को कटु आलोचना की। रूस ने पश्चिम के साथ सहप्रस्थित्व के विचार का समर्थन किया जबकि चीन ने कहा कि साम्राज्यवाद के पूर्ण विनाश के लिए युद्ध अत्याज्य है और तृतीय महायुद्ध अमेरिका तथा रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नहीं। 25 जुलाई, चीन ने 1963 की प्रगु-परीक्षण निरोध सन्धि का बहिष्कार किया तथा रूस पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका के साथ मिलकर आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार कायम करना चाहता है।

अक्तूबर, 1964 में श्री ख्रूश्चेव के हटने पर पेरिंग में खुशियाँ मनाई गई, लेकिन जब रूस के नए नेतृत्व ने भी पश्चिमी जगत के साथ सह-प्रस्थित्व की नीति में विश्वास प्रकट किया तो चीनियों को घोर निराशा हुई। रूसी बोल्शेविक क्रान्ति के 47वें वार्षिक उत्सव में चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-साई की कूटनीतिक वार्ता भी असफल रही क्योंकि रूस ने अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकता के शान्तिकारी प्रयासों में चीन का साथ देने से इन्कार कर शान्तिपूर्ण सहप्रस्थित्व के सिद्धान्त में आस्था प्रकट की।

सैद्धान्तिक संधि के प्रतिरिक्त दोनों देशों के बीच सीमा-विवाद भी उभरे जिन्होंने सशस्त्र सीमा संधियों का रूप ले लिया। रूस-चीन विवाद के मुख्य कारण

1. दोनों देशों के बीच सैद्धान्तिक मतभेद हैं। स्तालिनोत्तर युग की सोवियत नीति विश्व-क्रान्ति और युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास नहीं करती, जबकि लाव चीन क्रान्ति, हिंसा और युद्ध द्वारा पूंजीवादी जगत के विनाश में विश्वास करता है। रूसी सरकार के सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय पत्र 'इन्टरनेशनल अफेयर्स' के दिसम्बर 1971 के प्रक में प्रकाशित एक लेख में रूसी लेखक जी एपलिन ने लिखा था कि— 'माओ की विदेश नीति लडाकू, खतरनाक तथा रक्तस्त्रिप्त है जिससे चीनी लोकतन्त्र को भारी हानि हुई है। यह न तो मानसंधावी है और न ही सेनिनवादी।'

2. नेतृत्व का नया दोनों ही देशों पर छाया हुआ है। रूस द्वारा साम्यवादी जगत का एक छत्र नेतृत्व सहन करने को चीन तैयार नहीं है। एशिया में रूस के प्रभाव-विस्तार को चीन सन्देह की दृष्टि से देखता है।

3. भूमध्यसागर रूस और चीन के तनाव का एक केन्द्र है। रूस और अमेरिका के जहाज तो भूमध्यसागर में घूमते ही हैं, चीन की पनडुब्बियों ने भी इस सागर में घूमना प्रारम्भ कर दिया है। भूमध्यसागर में चीन की कुछ सैनिक और राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं। चीन चाहता है कि—(1) भूमध्यसागरीय देशों पर उसकी बात का वजन रहे, (2) रूसी मसुवों को हर क्षेत्र में चुनौती दी जाए या उसके मार्ग

मे कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न की जाए, (iii) भूत्वानिया जैसे जिन साम्यवादी देशों को चीन ने अपने प्रभाव में ले लिया है उन पर और रीढ़ आतंकित रखा जाए, (iv) प्रक्षेपास्त्रों से सज्जित जिन पनडुब्बियों का विकास चीन कर रहा है उनकी सैनिक गतिविधियों का क्षेत्र पहले से ही तयार कर लिया जाए ताकि रूस और अमेरिका के मुख्य क्षेत्र चीन की मार में आ सकें।

4. चीन का सन् 1969 से पहले तक नारा था कि विश्व के दो भाग हैं—समाजवादी और असमाजवादी। लेकिन सन् 1969 में चीनी साम्यवादी दल ने जो साम्यवादी व्याख्या की उसने सोवियत रूस को भी असमाजवादी अथवा साम्राज्यवादी राष्ट्रों की श्रेणी में ला दिया।

5. एक परमाणु शक्ति के रूप में चीन के विकास को न केवल रूस बल्कि अन्य देश भी एक बड़े सतरे के रूप में देखते हैं। प्रारम्भ में सोवियत संघ ने चीन को परमाणुविक जानकारी दी, लेकिन ज्यों-ज्यों चीन के इरादे स्पष्ट होते गए रूस ने इस सम्बन्ध में प्राधुनिकतम प्रविधि के बारे में गोपनीयता बरती। सन् 1959 में 1957 के उस समझौते को भंग कर दिया गया जिसमें रूस द्वारा चीन को परमाणु बम की प्रक्रिया का ज्ञान कराने का प्रावधान था। परमाणु असुरों के प्रश्न पर चीन और रूस के मतभेद बढ़ते ही गए।

6. विवाद की एक बड़ी जड़ मंगोलिया है। चीन अपनी बढ़ती हुई आवादी को बसाने के लिए प्रादेशिक विस्तारवाद के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। रूसी मंगोलिया पर, जिसे 'स्वतन्त्र मंगोलिया प्रजातन्त्र' कहते हैं, चीन की ग्रांथ है। मंगोलिया का पूर्वी भाग चीन के अधिकार में है। चीन चाहता है कि दोनों मंगोलिया एक होकर चीन का प्रदेश बन जाएँ। चीन का आरोप है कि रूस ने 'स्वतन्त्र मंगोलिया' को हड़प लिया है। मंगोलिया के कारण दोनों देशों की सीमाओं पर भारी सैनिक जमाव रहता है और कितनी ही बार सैनिक झड़पें भी हो चुकी हैं जिनमें परसजित होकर चीनियों को पीछे हटना पड़ा।

7. अमेरिका भी रूस और चीन के मतभेदों को उबसाने के लिए उत्तरदायी है। जब सन् 1969 के बाद रूस-चीन सीमा पर झड़पें हुईं तो अमेरिकी समाचार-पत्रों में प्रचार किया गया कि सन् 1969 में रूसी सैनिक अधिकारी इस बात पर विचार कर रहे थे कि चीन पर आकस्मिक हमला किया जाए ताकि उसकी परमाणु शक्ति समाप्त हो जाए। वास्तव में अमेरिका यह तो नहीं चाहता कि रूस और चीन के बीच बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध हो क्योंकि इसका प्रभाव रूस और चीन के बाहर दूर-दूर तक पड़ेगा। इसके अतिरिक्त चीन की समाप्ति से रूसी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि विश्व में शक्ति सन्तुलन बिगड़ जाएगा। मगर अमेरिका यह अवश्य चाहता है कि दोनों देशों के बीच इस प्रकार का तनाव बना रहे जिससे अमेरिका लाभान्वित हो।

8. चीन दुनिया के हर देश में रूस विरोधी प्रचार कर रहा है। यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों में उसने रूस के प्रति भाग भड़काने की हर सम्भव चेष्टा की है।

प्रत्वानिया को रूस से विमुख करने में चीन की सफलता भी प्राप्त हुई है। रूसी नेतृत्व चीन की इन कार्यवाहियों से परेशान है और अपने प्रभुत्व की रक्षा के लिए ध्यग्र है।

9. चीन की विश्वास होने लगा है कि पूर्वी एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति अस्थायी है जबकि जापान निरन्तर शक्तिशाली होकर पूर्वी एशिया में स्थायी रूप से छा जाने की प्रयत्नशील है, अतः अमेरिका ही सन्तुलन कायम रखकर पूर्वी एशिया सोवियत सघ की उपस्थिति को असम्भव बनाकर चीन की सैनिक उपस्थिति की सम्भावनाओं को सुदृढ़ कर सकता है। चीन और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत हैं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया से अमेरिका के हटने के बाद रित्त स्थान की पूर्ति सोवियत सघ द्वारा नहीं होनी चाहिए।

10. पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के सम्बन्धों में सुधार रूस को प्रमीष्ट है, लेकिन वह चीन और अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार को पथद नहीं करता।

11. रूस का विचार है कि युद्ध अवश्यम्भावी नहीं है और विध्वंसक प्राणविक अस्त्रों के निर्माण के कारण यह वाछनीय भी नहीं है, जबकि चीन का मत है कि समाजवाद की तथान्वित सैनिक सर्वोच्चता के कारण सशस्त्र-नीति व्यावहारिक है। चीनी नेतृत्व का यह विश्वास था कि साम्राज्यवादियों को भुक्तने के लिए विवश किया जा सकता है और यदि ऐसा न हो तो युद्ध द्वारा उनके भाग्य का निर्णय किया जाना चाहिए चाहे उसमें एक तिहाई या आधी मानव-सम्पत्ति ही नष्ट क्यों न हो जाय। सितम्बर 1976 में माओ की मृत्यु के बाद भी चीन के दृष्टिकोण में कोई विशेष अन्तर तक नहीं आया है तथापि ऐसा आभास प्रवश्य होने लगा है कि नया नेतृत्व सघर्ष के बजाय सहयोग की राजनीति पर चलने का प्रयत्न करेगा।

12. रूसियों का अपने समाज के सम्बन्ध में तर्क है कि वर्ग-सघर्ष की विजय पूर्ण हो चुकी है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को सम्पूर्ण जनता के राज्य का रूप दे दिया गया है। चीनी इससे मात्र कुतर्क कहकर अस्वीकार करते हैं। उनके विचार से यह सोवियत सघ के अन्तर्गत प्रचुरता से बड़े नोकरशाही तत्वों पर आनरण डालने की एक योजना है जो सर्वहारा तानाशाही एवं वर्ग-सघर्ष सम्बन्धों के निनवादी विचारधारा के लिए खतरा है।

13. चीनी सोवियत सघ से प्राप्त आर्थिक सहायता से कभी भी सन्तुष्ट नहीं रहे। कोरिया युद्ध के लिए प्राप्त ऋण के दायित्व ने उन्हें और भी अप्रसन्न कर दिया। जब रूस ने चीन की सहायता धन्य कर दी तो चीन ने इसका प्रर्थ यह लगाया कि रूस उस पर साम्यवादी दल से वार्ता के लिए आर्थिक दबाव डलाना चाहता है। रूसी नेतृत्व को यह विश्वास हो गया कि चीन को आर्थिक सहायता देने का वही अवाछनीय परिणाम होगा जो सैनिक सहायता का हुआ है।

14. प्रत्वानिया का प्रश्न विदेश-नीति का विषय होते हुए भी दल का प्रश्न बन गया। प्रश्न था कि क्या सोवियत साम्यवादी दल को यह निश्चय करने

का अधिकार है कि कौनसा शासक दल साम्यवादी गुट में है और वास्तविक समाजवादी देश कौनसा है ? सोवियत साम्यवादी दल ने अल्बानिया को एक्झीक्यूटिव कार्यवाही द्वारा गुट से निकाल दिया क्योंकि उसने मास्को की अवज्ञा की थी। चीनियों ने रूस की इस कार्यवाही की भर्त्सना की और अल्बानिया चीनी गुट में शामिल हो गया।

15. सोवियत संघ के विरुद्ध चीन के अविश्वास का एक बड़ा ऐतिहासिक आधार भी है। राजनीतिक विचारकों और इतिहासकारों का तर्क है कि प्रभी तक इतिहास में चीन की ओर से सोवियत संघ पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ जबकि इसके विपरीत आन्तिपूर्व रूसी शासकों ने चीन पर कई बार आक्रमण कर उसके भूभाग को हड़प लिया था। वास्तव में सोवियत संघ मूलतः यूरोपीय देश है और एशिया में उसका इतना विस्तार आन्ति पूर्व रूसी शासकों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का ही फल है।

इस प्रकार सोवियत चीन वैमनस्य साधारण और तथ्यपूर्ण है। सीमा पर दोनों ओर सैनिक जमाव है और जब तक झड़पें हो जाती हैं। विगत कुछ वर्षों से चीनी नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि सोवियत संघ ने उनकी सीमा पर भारी सैनिक जमाव कर रखा है जिससे उसकी प्रभुसत्ता एवं अखण्डता को काफी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए चीन तेजी से सामरिक तैयारियाँ कर रहा है। पर यह कहना कठिन है कि सोवियत रूस की ओर से यह तथ्यांकित खतरा वास्तविक है या काल्पनिक। हाल ही के वर्षों का इतिहास चीनी विस्तारवादी मनोवृत्ति की पुष्टि करता है। चीन ने जिस प्रकार मित्र देश भारत की भूमि हड़पी है, पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से दी गई कश्मीर भूमि को हड़पा है, मित्र देशों के साथ घोर विश्वासघात किया है, उसे देखते हुए चीन के पक्ष में कुछ कहना वस्तुतः कठिन है। जो भी हों, सोवियत चीन सवर्ष आज राजनीतिक और राजनयिक पर्यवेक्षकों के लिए विचारणीय विषय बना हुआ है। जहाँ तक सीमा पर सैनिक जमाव का प्रश्न है, यह एक स्थापित तथ्य है। राजनीतिक समीक्षाकार वृजेन्द्र रावेल के कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान में प्रकाशित एक लेख में कहा गया था कि—

“प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चीन-रूपी गोमागो पर लगभग 53 सोवियत डिवीजन तैनात हैं। इनमें से 21 डिवीजन सुदूर-पूर्व में, 5 मंगोलिया में और 27 तिब्बत, सिक्किम तथा तिब्बत क्षेत्र में नियत हैं। इस प्रकार सोवियत संघ की लगभग एक-तिहाई फल सेना चीनी सीमा पर जमी हुई है। इसके अलावा, ब्लाडी-वोस्टोक पर सोवियत नौसेना का भारी जमाव है और इसके पास ही सोवियत आणविक शक्ति केन्द्र स्थित है। कहा जाता है कि सोवियत प्रक्षेपास्त्रों का रूप चीन के प्रमुख केन्द्रों की ओर है। इसके जवाब में चीन ने भी लगभग 50-60 डिवीजन सेवा सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कर रखी है। 28 डिवीजन शेन्यांग व पेंगिंग सैनिक सम्भागों में मचूरिया के निकट, 7 डिवीजन सिक्किम में और शायद 11 डिवीजन

संघाट सैनिक सम्भाग में तैनात है। इसके अलावा चीन ने अनेक प्रक्षेपास्त्र केन्द्र भी स्थापित किए हैं जहाँ से प्रमुख सोवियत नगरों व सैनिक छाड़ों पर प्रहार किया जा सकते हैं।"

इन सैनिक कार्यवाहियों के अलावा दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी सुरक्षा के हित में विभिन्न राजनीतिक और राजनयिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उदाहरणार्थ, रूस ने ईराक, अफगानिस्तान और भारत से मंत्री सन्धि कर उन्हें अपनी चीन-विरोधी व्यूह रचना में शामिल कर लिया है, तो चीन ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध तैयार कर रखा है। रूस ने एशियाई देशों के लिए एक सामूहिक सुरक्षा-योजना भी तैयार की है, पर इस दिशा में उसे अभी तक उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। दूटनीतिक मोर्चे पर रूस और चीन दोनों ही अमेरिका को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं तथा तनाव के क्षेत्र कम कर रहे हैं।

वस्तुतः रूस और चीन के बीच सघर्ष के मूल कारण वैधानिक उतने नहीं हैं जिनके कि राजनीतिक और सामरिक। साम्यवादी जगत का नेतृत्व बौन करे—यह भगते की जड़ है।

रूस-चीन के समझौते-प्रयास

अपने तीव्र मतभेदों के बावजूद रूस और चीन दोनों ही समझते हैं कि वे एक दूसरे के शत्रु नहीं बने रह सकते, अन्यथा अमेरिका की 'बन्दर वांट' नीति सफल हो जाएगी। पश्चिमी जगत, विशेष कर अमेरिका के निहित स्वार्थों और वास्तविक इरादों से दोनों ही देश अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय रजनीति में अपने-अपने बर्चस्व हेतु तथा शक्ति-सन्तुलन को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही अमेरिका की मंत्री के मार्काशी हैं। वस्तुस्थिति को समझ कर ही रूस और चीन समय-समय पर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बातचीत करते रहे हैं तथा सन् 1970 से दोनों के बीच सैनिक सघर्ष की सम्भावना बहुत-कुछ कम हुई है। सन् 1970 की 13 जनवरी को दोनों देशों ने सीमा-समस्या के समर्थन के लिए आपस में जो वाता की उससे उनके बीच मतभेद कुछ कम हुए हैं। मस्कूबर, 1970 में हुई सोवियत-चीनी व्यापार-सन्धि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधार की दिशा में एक कदम था जिसके अनुसार सोवियत रूस ने चीन से अपने व्यापार में सन् 1971-72 में 200 प्रतिशत वृद्धि कर देने का आश्वासन दिया। सितम्बर, 1973 में यद्यपि चाङ-एन-ताई ने यह आरोप लगाया कि 'रूस चीन के साथ स्थिति सामान्य बनाना नहीं चाहता, चीन की सीमा पर हमनी दृष्टि है। रूस और अमेरिका की सत्तार की सम्पत्ति परस्पर वांट लेने का कोई अधिकार नहीं है। बारसा-सन्धि सगठन व स्वरूप प्राप्ताम है," तथापि यह वाक्-युद्ध पहले के समान कठोर रूप लिए हुए नहीं था। वाक्-युद्ध दोनों देशों के बीच अब भी चल रहा है, किन्तु पारस्परिक मतभेद दूर करने के लिए भी दोनों ही उत्तुङ हैं। राजनीति की दुनिया में न कोई स्थायी मित्र हो सकते हैं और न कोई स्थायी शत्रु। भारत रूसी-मैत्री चीन को खटकती है जबकि वास्तविकता यह है कि भारत-रूस-मैत्री न तो चीन और भारत के और न रूस और

चीन के सम्बन्धों के सामान्यीकरण में बाधक है। चीन को यह बात बहुत बुरी तरह सटकती है कि रूस भारतीय क्षेत्र पर चीनी अधिकार का पक्ष नहीं लेना। 30 अक्टूबर, 1975 को सोवियत संघ के चीनी मामलों के विशेषज्ञ श्री एन. निमेटोव ने कहा था कि पेंकिंग घोषणापत्र का सहारा लेकर भारत पर अपने सीमा सम्बन्धी विचार थोपने का प्रयत्न कर रहा है। चीनी विस्तारवाद पर लिखे गए अपने लेख में उन्होंने कहा है कि चीन ने भारत के 14 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आक्रमण का उस पर कब्जा कर रखा है। तथा अभी तक वहाँ जमा हुआ है। प्रेक्षकों के मतानुसार संघ ने उक्त लेख द्वारा पहली बार भारत के इस बंध दावे को स्वीकार किया है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। अब जबकि अप्रैल, 1976 से भारत और चीन के बीच राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए हैं, यह आशा की जानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच के विवाद सम्मानजनक ढंग से शीघ्र ही निपटा लिए जाएँगे। भारत का दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक रहा है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि चीन भी वही दृष्टिकोण अपनाए।

माओ की मृत्यु के बाद रूस-चीन तनाव में कमी आने की सम्भावना

9 मितम्बर, 1976 को माओ-त्से-तुंग की मृत्यु के उपरान्त राजनीतिक क्षेत्रों में यह धोपणा व्याप्त होने लगी है कि चीनी नेतृत्व अपने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उदार बनेगा और सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध सुधार के लिए सचेष्ट होगा। माओ के उत्तराधिकारी के रूप में श्री हुआ केमो फेंग को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सैनिक परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

राजनीतिक क्षेत्रों में कहा जाता है कि श्री हुआ यद्यपि वर्ग-सर्प के माओवादी टाँचे के अन्तर्गत ही चीन के समाजवादी पुनर्निर्माण का कार्य करेंगे, तो भी उनकी नीतियाँ नरम और उदारवादी होगी। सोवियत संघ और चीन में मूलतः साम्यवादी जगत् के नेतृत्व के सम्बन्ध में जो दरार पैदा हो गई है वह भी मिट जाएँगी। 27 अक्टूबर, 1976 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार सोवियत संघ के साम्यवादी दल के महासचिव ने दल की केन्द्रीय समिति की बैठक में कहा था कि सोवियत संघ चीन के साथ सह-अस्तित्व के आधार पर सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने को नैयार है। चीनी नेतृत्व ने भी सोवियत संघ की बोलशेविक क्रान्ति की 59वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रेषित सन्देशों में सोवियत संघ के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए उत्सुक होने का संकेत दिया है। चीन की ओर से यह भी कहा गया है कि सिद्धान्त के प्रश्नों पर दोनों देशों के विवाद से राष्ट्रीय और प्रशासनिक स्तर पर उनके सम्बन्धों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सन्देशों में दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया जबकि सन् 1975 में इसी तरह के सन्देश में सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर सक्रिय कदम उठाने पर जोर दिया गया था।

यदि चीन नरम और उदार बनता है तो आन्तरिक क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी निश्चित रूप से मधुर बनाने का प्रयास करेगा।

चीन और भारत

भारत और चीन के सम्बन्धों पर विस्तार से प्रकाश भारतीय विदेश-नीति के पिछले अध्याय में डाला जा चुका है। लगभग सन् 1960 तक दोनों देशों के सम्बन्ध सामान्य थे, यद्यपि सीमा विवाद अधिक उग्र हुआ और अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के विशाल सुनिर्मित आक्रमण के उपरान्त अब तक दोनों देशों के सम्बन्ध कटुतापूर्ण ही हैं। चीन की परराष्ट्र नीति का एक मुख्य तत्त्व यही है कि वह उन सभी राष्ट्रों के माध्यम से भारत की ताकाबन्दी करे जो या तो उनकी नीतियों के समर्थक हैं या प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से उससे सहायता चाहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान चीन का बहुत अच्छा साथी बन गया है और चीनी नेता भारत के विरोध में पाकिस्तान को मोहरा बनाने का कोई अवसर नहीं चूकते हैं। चीन के जहाज हिन्दमहासागर की जल-सीमा का प्रतिक्रमण करते देखे गए हैं। यह स्थिति भारत के लिए चिन्ताजनक है। मोर्वियत-भारत-मैत्री संधि के बाद तो माप्रो-सैन्य का यह पूर्ण प्रयास रहा कि पेरिंग-विण्डी-वांशगडन घुंरी का मुहक निर्माण हो जाए।

सन् 1974 की भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन-भारत सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ। भारतीय प्रवक्ता का चीन की ओर से अनुमूल उत्तर न मिलना ही निराशा का कारण है। चीन भारत के आन्तरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने से नहीं चूकता। इसे बहुत खेदजनक बात माना जाएगा कि सिक्किम के भारत में विलय पर चीन और पाकिस्तान ने तूटान मचा दिया। 27 जून 1975 को समुक्त राष्ट्रमण्डल में एशियायी गुट की मनीषाचारिक बैठक में भी इस बात पर भारत और चीन के प्रतिनिधियों में झड़प हो गई। चीनी प्रतिनिधि पाऊ ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तान का समर्थन करेगी और भारत का विरोध करेगी। उसने आरोप लगाया कि भारत एक विस्तारवादी देश है क्योंकि उसने सिक्किम को अपने सप में मिला लिया है। भारत के द्वायी प्रतिनिधि श्री हाशमी का उत्तर था कि यह आरोप सर्वथा असंगत है।¹

चीन द्वारा भारत विरोध के मून उद्देश्यों की ओर 11 मई, 1975 के दिनमान में प्रकाशित लेख के अशोकित उद्धरणों से अच्छा प्रकाश पड़ता है—

‘चीनी राजनता यह मानते हैं कि भारत तभी से हथियारों का उत्पादन कर अपनी सैनिक सैधारी में वृद्धि कर रहा है। सन् 1971 में भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय से चीन सशक्ति हुआ था। यह नहीं कि चीन यह सोचता था कि भारत चीन पर आक्रमण कर देगा। चीनी नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का न तो कोई ऐसा इरादा है और न ही मौजूदा अर्थ-व्यवस्था में भारत इस तरह की किसी लड़ाई का जोखिम उठा सकता है। चीन का वास्तविक उद्देश्य भारत के शत्रुओं को मदद देना और उनका मनोबल ऊँचा रखना है। जब भी चीन भारत के शिरक कुछ कहता है तब उसके ताउहस्थीकर का मुस पाकिस्तान की ओर होता है। वह

पाकिस्तानी जनता और सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि भारत का इरादा पाकिस्तान को समाप्त करने का है।”

“इसके अलावा चीन की नाराजगी भारत-रूस मैत्री से भी है, यत्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि चीन भारत-रूस मैत्री को अपने लिए मुख्य चुनौती मानता है। अब इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि दक्षिणी एशिया में अमेरिका का किला ढहने के बाद सोवियत रूस के प्रभाव-क्षेत्र में विस्तार होगा। सोवियत रूस पहले से ही एशियाई देशों के लिए एक सामूहिक सुरक्षा पद्धति की बकालत करता रहा है। चीन इस बात को समझता है कि सोवियत रूस भारत की सहायता या सहयोग से दक्षिणी एशिया में चीनी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर सकता है।”

“चीन को यह सत्य नहीं है कि दक्षिणी-एशियायी देशों में सोवियत रूस को वह मान्यता प्राप्त हो जो चीन को अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। चीनी विदेश-नीति के निर्माता इस स्थिति के लिए बहुत हद तक भारत को जिम्मेदार मानते हैं। उनका यह ह्जाज है कि भारत की मदद के बिना सोवियत रूस दक्षिणी-एशिया में अपना प्रभाव नहीं बढ़ा सकता। सोवियत रूस एक यूरोपीय देश है जबकि भारत एक एशियाई राष्ट्र है। इसके अलावा भारत को एक गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में एशियाई देशों में विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त है। चीनी राजनेताओं की मुख्य आशंका यह है कि सोवियत रूस एशिया में जो कुछ स्वयं कर सकने में समर्थ नहीं है वह भारत की मदद से कर सकता है।”¹

सितम्बर, 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन का नया नेतृत्व विश्व राजनीति में अपने दृष्टिकोण को बदलता दिखाई दे रहा है और भारत के साथ भी चीन के राजनयिक सम्बन्ध पुनः स्थापित हो गए हैं। मार्च, 1977 में भारत में ऐतिहासिक सत्ता-परिवर्तन के साथ नई सरकार के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन् 1977 के अन्तिम चरण में अपने भाषणों में जो कुछ कहा है उससे संकेत मिलता है कि दोनों ही देश एक-दूसरे से सम्बन्ध सुधार के लिए पहल करने को तैयार हैं—चीन सम्भवतः तीसरे पक्ष के माध्यम से पहल करने को उत्तुंग है। जो भी हो, पिछले इतिहास को देखते हुए भारत को फूँक-फूँक कर कदम उठाने होंगे क्योंकि चीनी रीति नीति अतीत में विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुई है।

पाकिस्तान और चीन

भारत की स्वाधीनता के प्रथम दशक में और कुछ समय बाद तक भी चीन ने भारत के प्रति मैत्री का स्वाँग अच्छी तरह निभाया। इस अवधि में पाक-चीन सम्बन्धों में कोई विशेष प्रेमालाप नहीं हुआ, यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न सन् 1956 से शुरू हो गए थे। सन् 1956 में तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद अली जinnah ने चीन की और प्रधानमंत्री श्री चाऊ ने पाकिस्तान की यात्रा की। इस पारस्परिक दौरे के बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान शुरू हुए। चीन ने पूर्वी

पाकिस्तान को अपना कार्यक्षेत्र चुनकर ढाका में एक पाक-चीन सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की पर यह कम प्रचिन्न नहीं चल सका और प्रवृत्त, 1958 में पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही की स्थापना के साथ ही समाप्त हो गया।

पाकिस्तान की भारत-विरोधी नीति सैनिक तानाशाही के युग में निरन्तर उभरती गई। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध दुनिया के हर देश से सैन्य सामग्री प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। भला चीन ऐसे मौके को कब भूलने वाला था। उसने पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने के लिए कूटनीतिक पक्षे कैंडे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति कनेडी ने भारत में सम्मेलन बढाने के प्रयास शुरू किए तो पाक राजनेताओं ने इसे पसन्द नहीं किया और चीनी शासकों ने परिस्थितियों का लाभ उठाया। सोमा-विवाद के फलस्वरूप भारत-चीन सम्बंधों की भागवा बढने पर अमेरिका ने भारत को अधिक आर्थिक और शस्त्र सहायता देना आरम्भ किया तथा पाकिस्तानी प्रसन्नता की उपेक्षा कर दी तो पाकिस्तान ने चीन की ओर झुकते हुए पहली बार समुक्त राष्ट्रसंघ में चीन की सदस्यता के प्रश्न पर अमेरिका के विरोध में मतदान दिया।

चीन पाकिस्तान को अपने पक्ष में समेटने को तैयार ही बँठा था। तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने पाक-चीन संबंधों की पृष्ठभूमि तैयार करनी शुरू कर दी। सन् 1964 में सैंटो सगठन की बैठक होने में पहले ही अयूब खान ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान चीन के साथ सीमा सम्मेलन करेगा। सन् 1960 में पाकिस्तान की ओर से इस दिशा में पहल की गई और चीन से उसे हर तरह मददकर सन् 1962 में उसके साथ एक सीमा-सम्मेलन सम्पन्न किया। पाकिस्तान इस सम्मेलन के माध्यम से अमेरिका को और चीन को विपक्ष सप को चिढ़ाना चाहता था। यह सीमा-सम्मेलन भारतीय हितों पर बड़ी प्रहार ली, इनके सम्बंधन सिक्किम और पाक-प्रचिन्न कश्मीर के बीच सीमा-निर्धारण की समस्या थी। सन्धि द्वारा पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर का 2050 वर्ग मील क्षेत्र अर्पण रूप में चीन को सौंप दिया। सम्मेलन के बहुत सम्भार परिणाम निकले क्योंकि एक तो चीन की नीमा-प्रतिरक्षा सुदृढ़ हो गई और दूसरे इस उपमहाद्वीप में प्रवेश करने की सुविधा होकर जाती है और सर्दियों में भी खुली रहती है। इस सड़क से दोनों देश जुड़ गए, विशेष लाभ चीन को मिला। चीन इस भावी अग्रतयागित लाभ के बदले पाकिस्तान को पूर्ण राजनीतिक और सैनिक सम्बंधन देने लगा।

विण्डी-येरिंग घुमि की स्थापना को विश्व के देशों ने आरम्भ में प्रत्येक विवाद की दृष्टि से देखा और उत पर सन्देह किया, लेकिन दोनों देशों ने बढते हुए प्रेमालाप ने उनकी आँखें खोल दी। चीन से विपुल सैनिक सहायता प्राप्त कर पाकिस्तान ने सैंटो और सीएटो सगठनों की उपेक्षा शुरू कर दी तथा मनीला में आयोजित सीएटो की बैठक में भाग लेने से इकार कर दिया। प्रवृत्त, 1962 में भारत-चीन युद्ध के समय पाकिस्तान ने खुले आम अपने 'बड़े भ्राता' चीन का सम्बंधन

किया और भारत को आक्रमक ठहराया। भारत की पराजय पर पाकिस्तान में खुशियाँ मनायी गईं।

'चोर-चोर मौसेरे भाई' की तरह पाक-चीन की दोस्ती दबती गई और दिसम्बर, 1963 में चीन के विदेश-व्यापार उपमन्त्री थो नानहान चैन ने अपनी पाक-यात्रा के समय यह आश्वासन दिया कि किसी भी भारत-पाक युद्ध में चीन पाकिस्तान को पूर्ण समर्थन देगा। सन् 1964 में चीनी प्रधानमन्त्री ने पाक-यात्रा के समय उपर्युक्त आश्वासन की पुष्टि की। पाकिस्तान ने चीन की खुले दिल से जो सेवाएँ की उसके पुरस्कार स्वरूप जुलाई, 1964 में चीन ने पाकिस्तान को 6 करोड़ डॉलर का व्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया। चीन से भारी मात्रा में सैनिक सामग्री भी पाकिस्तान को अनुदान स्वरूप मिलती रही। उधर अमेरिका भी पाकिस्तान को चीन की ओर से विमुख करने हेतु आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करता रहा यह समझने हुए भी कि अमेरिकी हथियारों का प्रयोग पाकिस्तान चीन के विरुद्ध नहीं बल्कि भारतीय लोकतन्त्र के विरुद्ध करेगा।

चीन से प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाकर पाकिस्तान ने अप्रैल, 1965 में कच्छ पर आक्रमण कर दिया। इस समय और बाद में भी कुछ माह तक प्रमुख चीनी राजनेता पाकिस्तान में उपस्थित रहे। दोनों देशों में एक हवाई समझौता भी हुआ जिसके अन्तर्गत चीन को पूर्वी पाकिस्तान से होकर रक्षा तथा दक्षिणी एशिया तक विमान उड़ाने की सुविधा प्राप्त हो गई। यह एक ऐसी सुविधा थी जिसका प्रयोग चीन भारत के विरुद्ध आसानी से कर सकती था। तत्पश्चात् नौका-नयन और संचार सम्बन्धों के विषय में भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते हुए। चीन को पूरी अपनी पीठ पर पाकर पाकिस्तान ने सितम्बर, 1965 में भारत पर आक्रामक रूप से भीषण आक्रमण कर दिया। रूसी भय एवं अन्य कतिपय कारणों से तथा भारत की विकसित सैन्य शक्ति का अनुमान लगाकर चीन ने यद्यपि भारत के उत्तरी सीमान्त पर पाकिस्तान के समर्थन में कोई आक्रमण नहीं किया, तथापि वहाँ सैनिक गतिविधि तेज करके तथा भारत को तीन दिवसीय अस्टोमेटम देकर पाकिस्तान को 'आश्वस्त' करने की चेष्टा की। कूटनीतिक क्षेत्र में पाकिस्तान को चीन से पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। चीनी अस्टोमेटम भी तब दिया गया जब पाक विदेश मन्त्री न्यूयॉर्क में थे। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली से 23 दिसम्बर को युद्धविराम न होता तो सम्भवतः चीन पाकिस्तान को बचाने के लिए सैनिक कार्यवाही कर बैठता।

सन् 1965 से पाक-चीन सम्बन्धों में एक नया चरण शुरू हुआ जिसके अनुसार चीन ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक और सामरिक सहायता देने की नीति अपनायी। लगभग इसी वर्ष से पाकिस्तान ने अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ दिया और मार्च, 1966 में स्पष्ट रूप से घोषित किया कि उसे चीन से भारी मात्रा में सहायता, विमान और टैंक मिल रहे हैं। चीन से पाकिस्तान को जो सामरिक सहायता मिली, वह अमेरिकी सैन्य सहायता से कहीं अधिक थी। विण्डी-पेकिंग धुरी ने संयुक्त रूप से भारत में विध्वनकारी तत्त्वों को प्रोत्साहन देना शुरू

कर दिया। नागालैण्ड और मिजो क्षेत्र में विद्रोहियों को भड़काया गया तथा भारत के विरुद्ध उन्हें शस्त्रास्त्र-सहायता तथा सैनिक प्रशिक्षण देने की भरपूर चेष्टा की गई। दोनों देशों के इन कूटिल प्रयासों से भारत को घनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

दिसम्बर, 1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् पिण्डी-पेरिंग सम्बन्धों में एक नए चरण का सूचना हुआ। युद्ध काल में चीन ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र-सहायता और राजनीतिक समर्थन देने तक ही अपने को सीमित रखा। चीन पाकिस्तान की इस आशा को गिठाना चाहता था कि अमेरिका भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की हर प्रकार की सहायता करेगा। पाक-अमेरिकी प्रतिरक्षा-सन्धि के अन्तर्गत अमेरिका ने वचन दिया था कि वह पाकिस्तान की अखण्डता और प्रभुसत्ता को रक्षा करेगा लेकिन पाकिस्तान का विभाजन हो गया और अमेरिका का वचन बुरा कामजी सिद्ध हुआ। इस प्रकार चीन की पाकिस्तान से यह कहने का अवसर मिल गया कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

पिण्डी-पेरिंग घुरी अब एक ठोस तथ्य है, अतः भारत को किसी भी सम्भावित संयुक्त खतरे के मुकाबले के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार रहना चाहिए। जिमला समझौते ने पाकिस्तान के साथ शान्ति के आकार बढ गए हैं लेकिन पाकिस्तानी नेतृत्व जिस तरह शान्ति और धमकी की दुरणी नीति पर चल रहा है और दुनिया के हर देश से संयुक्त-सामग्री बटोरने में लगा हुआ है वह भारत की चौकाने के लिए काफी है। पाकिस्तान के रक्षा बजटों में चीन तथा अन्य मित्र देशों से बिना भूतय प्राप्त हथियारों और उपकरणों की चर्चा नहीं की जाती। गैर-कम्प्युनिस्ट देशों में चीन ने पाकिस्तान की जिनकी सैनिक सहायता दी है उनमें किसी दूसरे देश को नहीं दी गई है। भारत-सरकार इन सभी गतिविधियों के प्रति सतर्क है।

चीन-अल्बानिया : बदलते रिश्ते

पूर्वी यूरोप के एक छोटे से देश अल्बानिया (कुल जनसंख्या लगभग 25 लाख) ने एक घमाका मन् 1961 में किया था। उसने तब साम्यवादी मान्दोलन के एक मात्र मुखिया सोवियत संघ से सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था और उस चीन से नाता जोड़ा था जो सोवियत संघ के नेतृत्व से मुक्ति पाने के लिए बसमसा रहा था और दोनों देशों के बीच छुट-पुट मतभेद उभरने लगे थे। चीन ने सोवियत संघ की प्रलोचना करते हुए तब एक मज्बे और विश्वस्त मित्र के रूप में अल्बानिया का स्वागत किया था और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी मान्दोलन की एक और घुरी के निर्माण की सम्भावना उत्पन्न हुई जिसने प्रागे चलकर अक्टूबर 1962 में चीन और सोवियत संघ के बीच सम्बन्ध विच्छेद के बाद साकार रूप ग्रहण कर लिया।

अल्बानिया ने दूसरा घमाका जुलाई, 1977 में किया। अल्बानियाई कम्युनिस्ट पार्टी के समाचार पत्र जेरी पापुलित ने अपने सम्पादकीय में चीन का नाम लिए बिना उसकी विदेश-नीति के कई तत्वों की सैद्धान्तिक आधार पर कटु आलोचना

की। सम्पादनीय में 'तीसरी दुनिया' के सिद्धान्त की भी भर्त्सना की गई। स्वर्गीय माओ-त्से तुंग ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था और अप्रैल, 1974 में संयुक्तराष्ट्र में चीन के भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री हेङ् सिआओ पिंग् ने उसे प्रथम बार अधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। तब से विकासशील देशों को 'तीसरी दुनिया' के देश कह कर सम्बोधित किया जा रहा है।

सम्पादकीय में 'तीसरी दुनिया' के सिद्धान्त को लेनिनवाद विरोधी कहकर उसके समर्थकों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्हें अनेक विकासशील देशों में वास्तविक साम्राज्यवाद विरोधी, क्रान्तिकारी शक्तियों और साम्राज्यवाद समर्थक, प्रतिक्रियावादी फासी शक्तियों के बीच पहचान की तमोज नहीं है। इस प्रकार समाचार पत्र ने तीसरी दुनिया के उस मूखिया पर खुला प्रहार किया जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में एक प्रमुख शक्ति माना जाता है।

अल्बानिया रातोंरात चीन विरोधी नहीं बन गया है। जब सन् 1974 में चीन ने शत्रु का शत्रु अपना मित्र का सिद्धान्त अपनाकर अमेरिका से सम्पर्क स्थापित किया तभी से इस विरोध का आभास मिलने लगा था जिसका संकेत अल्बानियाई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अनवर होक्सा ने अपने वहाँ के कुछ हठवादी साम्यवादियों को दण्डित कर दे दिया था। इनमें एक प्रतिरक्षामन्त्री बेकिर दाल्यू भी थे। उससे पूर्व सन् 1971 की पार्टी कांग्रेस में भी श्री होक्सा चीनी नेता माओ द्वारा सोवियत संघ और अमेरिका को मिडाने के प्रयासों की यह कहकर आलोचना कर चुके थे कि एक साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए दूसरे साम्राज्यवाद का प्रयोग करना सम्भव नहीं है।

फिर भी मई, 1976 तक अल्बानिया और चीन मित्र बने रहे। किन्तु अक्टूबर, 1976 में चीन में सत्ता परिवर्तन के साथ ही दोनों देशों की 'एकही मित्रता' में दरार पड़ गई जो उत्तरोत्तर चौड़ी होती गई। श्री होक्सा ने तब अपनी पार्टी के 7वें अधिवेशन में अध्यक्ष हुआ कुओ फेङ् के प्रशासन की प्रशंसा सम्भवतः जानबूझ कर नहीं की। उससे पूर्व उन्होंने माओ के उत्तराधिकारी को एक असाधारण रूप से सक्षिप्त तार भेजकर वार्दाई प्रवश्य दी थी। श्रीमती माओ समेत चार नेताओं की गिरफ्तारी को होक्सा ने पसन्द नहीं किया। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि चीन का नया नेतृत्व अन्ततः सोवियत समर्थक सिद्ध होगा। हाल में चीन ने अफीकी नीति के सन्दर्भ में और अपनी सीमाओं के प्रश्न पर सोवियत संघ की नीतियों पर प्रहार अवश्य किया है फिर भी ऐसा नहीं लगता कि तीसरी महाशक्ति बनने का आकांक्षी चीन प्रकरण ही सोवियत संघ से बैर मोल लेगा। श्री होक्सा की चीन विषयक आशका सर्वथा निराश्वर नहीं है।

चीन की बैसाखियों के सहारे चलने वाले अल्बानिया के इस विरोध को एक मित्र के प्रति दूसरे मित्र के आक्रोश के रूप में नहीं देखा जा सकता। अल्बानिया को चीन से न केवल अपार आर्थिक सहायता मिली है बल्कि अब तक उसका दो तिहाई व्यापार भी चीन के साथ ही होता रहा है। ऐसी स्थिति में चीन के प्रति अल्बानिया

के ताज़े रवंगे को एक साधारण घटना नहीं माना जा सकता। यह अस्त्वानिया की साम्यवादी आन्दोलन सम्बन्धी सैद्धान्तिक सफर की ही एक कड़ी है। अस्त्वानिया नहीं मानता कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के केवल कोई एक या दो केन्द्र बिन्दु ही हो सकते हैं।

चीन और सोवियत सघ के बीच विगाट पैदा होने से पहले तक सोवियत नेतृत्व स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन का भाग्य विधाता मानता था। किन्तु चीन ने उनकी इस प्रतिभा को सख्खित कर दिया। कुछ वर्ष पहले तक साम्यवादी आन्दोलन के दो केन्द्र रहे जिनमें सल्वा और प्रभाव की दृष्टि से चीन का स्थान निश्चय ही सोवियत सघ के बाद था। पिछले कुछ वर्षों में साम्यवादी आन्दोलन का एक और केन्द्र उभरा जिसे यूरोपीय की संज्ञा दी गई और जिसके प्रवक्ता पश्चिम यूरोप के साम्यवादी दल हैं।

पिछले दिनों रोमानिया ने यूरोपीय साम्यवाद की प्रशंसा की थी। प्रथम अस्त्वानिया ने चीन के विरोध का मार्ग प्रपन्नाकर सभवतः यह संकेत दिया है कि वह भी स्वतन्त्र निर्णय के मार्ग को पसन्द करता है। यदि सचमुच अस्त्वानिया यूरोपीय साम्यवाद की धारणा पसन्द करता है तो उसके इन निर्णय के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। देर सवेर पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देश भी उसका अनुकरण कर सकते हैं जो सोवियत सघ के नेतृत्व से मुक्ति पाने के लिए एक झरते में छटपटा रहे हैं। सोवियत सघ यह नहीं चाहता और इसीलिए वह यूरोपीय साम्यवाद के विचार का भी कट्टर विरोधी है।

चीन-यूगोस्लाविया : रिरस्ते में नया मोड़

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो पितम्बर, 1977 में चीन की नौ दिन की राजनीय यात्रा के बाद स्वदेश लौट गए। अपने पहले चीन प्रवास के दौरान मार्शल टीटो को चीनी नेताओं और चीनी नागरिकों से जो सम्मान मिला वह सामान्य प्रतिधि को मिलने वाले सम्मान से कहीं अधिक था, इसलिए और भी कि अभी हाल तक मार्शल टीटो चीन की दृष्टि में 'सशोधनवादी' थे और चीनी नेताओं को वह फूटी ब्राँस नहीं मुड़ाते थे। किन्तु वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सन्दर्भ में, जो फूटी ब्राँस के अनुसार 'सभी देशों की जनता के अनुकूल और महाशक्तियों के अनिकूल' है, स्वयं टीटो ने टीटो को द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान फानी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने वाले एक प्रमुख नेता, यूगोस्लाविया समाजवादी गणराज्य के संस्थापक, मुनिहयान राजनीतिज्ञ और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के एक प्रणेता के रूप में देखा और उनकी यात्रा को चीन यूगोस्लाविया सम्बन्धों की एक महान् घटना बताया।

निस्सन्देह मार्शल टीटो की चीन यात्रा चीन-यूगोस्लाविया सम्बन्धों की एक महान् घटना है, बल्कि कहना चाहिए कि कम्युनिस्ट जगत् की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे यदि साम्यवाद के बारे में विरोधी विचार वाले साम्यवादी देशों के बीच सफर के प्रादुर्भाव के रूप में देखा जाए तो इसका महत्त्व और भी बड़ जाता है। टीटो की पीपुल्स याना से प्रथम अगले कुछ महीनों में अध्यक्ष हुमा की सभाविता बेलग्रेड

यात्रा से दोनों देशों के सैद्धान्तिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे यह मानना राजनीतिक अदूरदर्शिता होगी, किन्तु इससे इतना तो हुआ ही कि वे आपसी संपर्क स्थापित होने से उनके बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पैदा हुई है। एक समाचार के अनुसार सन् 1978 तक चीन और यूगोस्लाविया का व्यापार आज ने चौगुना हो जाएगा। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि सन् 1971-75 के बीच सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के व्यापार में तीन अरब डॉलर की वृद्धि हुई और अगले तीन वर्ष में उसके तीन गुने होने की संभावना है।

यात्रा की समाप्ति पर किसी संयुक्त विज्ञप्ति का प्रसारित न किया जाना इस बात का संकेत माना जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच अनेक विषयों पर मतभेद नहीं था। यात्रा का यह कोई अप्रत्याशित परिणाम नहीं था। उनके मतभेद इतने व्यापक रहे हैं कि एक ही वार्ता में मतभेद की आशा नहीं की जा सकती थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मतभेदों के बावजूद उन्होंने परस्पर सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया। अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रीतिमोज में मार्शल टीटो ने कहा कि मतभेदों को इस सहयोग में बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वे (मतभेद) उन भिन्न परिस्थितियों के परिणाम हैं जिनमें हम रहते आए हैं और आज भी रह रहे हैं। सहयोग का आधार समानता का सिद्धान्त होने पर मतभेद बाधक नहीं बन सकते, तब और भी नहीं जबकि हम अपने विचार एक-दूसरे पर लादना न चाहें। इस बारे में चीन के नेताओं की कोई भिन्न राय है ऐसा कोई संकेत उन्होंने मार्शल टीटो से बातचीत के दौरान नहीं दिया।

वास्तविकता तो यह है कि अध्यक्ष हुआ की राय भी मतभेदों के बीच सहयोग की नीति के बारे में श्री टीटो से भिन्न नहीं रही होगी क्योंकि चीन की वर्तमान विदेश-नीति के सन्दर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि उसका सम्बन्ध अधिकाधिक साम्यवादी देशों से स्थापित हो ताकि वह साम्यवादी, साम्राज्यवादी और गुट-निरपेक्ष शिबिर के उन देशों से निपट सके जिन्हें वह अपनी उस राह का काँटा मानता है जिस पर चलकर वह महाशक्ति बनने का स्वप्न देख रहा है। इसके लिए वह अपनी आवश्यकता के लिए काँटे से काँटा निकालने की नीति का प्रयोग भी कर लेता है। उदाहरणार्थ जब सोवियत संघ से उसका विवाद जोरो से चल रहा था तो उसने अमेरिका से संपर्क स्थापित किया। रिपर्स निवृत्तन के समय में सन् 1971 में स्थापित वह संपर्क फोर्ड के कार्यकाल में सन् 1975 के अन्त में घनिष्ठ मित्रता में बदल चुका था और दोनों मिलकर सोवियत संघ की निन्दा करते नहीं अघाते थे। उस दौरान चीन ने भारत के विरुद्ध विषममन भी बन्द-सा कर रखा था और भारतीय राजनेताओं के मन में वह यह भ्रम पैदा करने में भी सफल हो चुका था कि वह भारत से मित्रता करना चाहता है किन्तु जनवरी, 1977 में जिम्मी कार्टर के राष्ट्रपति बनने और मार्च, 1977 में भारत में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही चीन ने रण बदलना शुरू कर दिया और साम्यवादी गुट के देशों से संपर्क बढ़ाने की आशा के साथ ही वह अमेरिका और भारत की खबर लेने पर उतार हो गया जान पड़ता है।

(दिनमान सितम्बर-अक्टूबर, 1977)

चीन और अन्य राष्ट्र

साम्यवादी चीन के यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अन्य राष्ट्रों के साथ भी सम्बन्ध उतार-चढ़ाव और अधिकांशतः मनमुटाव के रहे हैं। बाह्य मंगोलिया पूर्वी एशिया का छोटा-सा देश जो यद्यपि समुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है, तथापि व्यवहारतः सोवियत रूस के प्रभाव और नियन्त्रण में है। मंगोलिया पर प्रभुत्व के मामले में चीन रूस का प्रतिद्वन्द्वी है। सत्तार की छत कहे जाने वाले तिब्बत को चीन ने निगल लिया है। अरब-जगत् में भी चीन अपने पैर फैलाने को प्रयत्नशील है। इस दिशा में अभी उसे कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल सकी है। चीन की दृष्टि हिन्द महासागर पर भी है। मॉरिशस, तंजानिया, जाम्बिया आदि को सहायता देने के नाम पर चीन हिन्द महासागर के जल-मार्गों का प्रयोग अपने हित में कर रहा है। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित करने और उन्हें घनिष्ठ बनाने की दिशा में चीन काफी समय से प्रयत्नशील है। रूमानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड आदि देशों से चीन के सम्बन्ध पूर्वापेक्षा कुछ विवर्धित हुए हैं, लेकिन वे सभी राष्ट्र सोवियत रूस के प्रभाव में हैं नया रूस-विरोधी किसी भी चीनी कार्यवाही के प्रति सचेष्ट है। चीन ने हाल ही में जापान की ओर भी दृष्टिपात किया है। सन् 1972 में चीनी प्रधानमंत्री द्वारा जापान के नये प्रधानमंत्री को पेरिंग आने का निमन्त्रण इस बात का सूचक था कि चीन जापान के साथ अच्छे सम्बन्ध कायम कर जापानी सैन्यवाद से अपनी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है।

चीन एशियायी देशों में राजनीतिक पंठ बढ़ाने को उत्सुक है। जून, 1975 में चीन द्वारा फिलिपाइन और थाइलैंड के दो उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डलों का स्वागत करने के लिए उड़ाए गए कदन इसी बात के स्रोतक हैं। चीन इस क्षेत्र में बढ़ रहे सोवियत प्रभाव को कम करना चाहता है। एशियायी देशों में केवल मलेशिया ही ऐसा देश है जिसके चीन के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध हैं।¹ दण्डोनेशिया के साथ चीन के सम्बन्धों में जी बिगाड़ हुआ वह अभी तक नहीं सुधर सका है।

चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन (Evaluation of China's Foreign Policy)

चीन की विदेश-नीति ने चाहे कितने ही रूप बदले हों पर सिद्धान्तों की आड में उसके सकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थों का घूर्णित रूप बराबर उजागर होता रहा है। रूस और भारत ने चीन को हर तरह अपना सहयोग और समर्थन दिया, लेकिन चीन ने दोनों को ही शत्रु राष्ट्रों की श्रेणी में सा पटका है। दोनों देशों के साथ चीन ने मतमाने लग से सीमा-विवाद उत्पन्न किए हैं और आज चीनी विदेश नीति का केन्द्र-बिन्दु यही है कि रूस और भारत के प्रभाव को किसी भी उचित-अनुचित उपाय से खींच लिया जाए। अमेरिका जो चीन का शत्रु नम्बर एक था, आज चीन के निकट है और चीनी नेतृत्व अमेरिकी मित्रता प्रजित कर साम्यवादी शिविर का नेतृत्व अपने

1. वही, दिनांक 7 जून, 1975.

हाथ में लेने को प्रयत्नशील है। चीन पूर्वी एशिया में अमेरिका की सैनिक उपस्थिति को अस्थायी मानता है और उसको अपना साथी बनाकर जापान तथा रूस की उपस्थिति को पूर्वी एशिया में असम्भव बनाने की चेष्टा में है। अमेरिका यह सकेत दे चुका है कि वह दक्षिण-पूर्वी एशिया से हटकर वहाँ चीन की उपस्थिति के अधिक पक्ष में है। एशिया में चीन ऐसी भूमिका निभा रहा है, जिससे उनका दबदबा एशिया के साथ-साथ वे सभी देश अनुभव करें जिनकी सीमाएँ चीन से मिलती हैं अथवा जहाँ व्यापारिक क्षेत्र में उसकी धाक है। एशियायी देशों के प्रतिरिक्त चीन की दृष्टि अफ्रीका के विभिन्न देशों और अरब राष्ट्रों पर भी है। वह इनको अपनी दोस्ती के दायरे में लाकर भारत को 'घड़ू' का स्तर देने के लिए प्रयत्नशील है, किन्तु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश चीन की चालें समझ चुके हैं। वे जानते हैं कि चीनी नीति भारत सहित अन्य एशियायी-अफ्रीकी देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की रही है जिससे न केवल एशिया और अफ्रीका में एकता को आघात पहुँचा है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत् में इन महाद्वीपों के देशों के प्रति महाशक्तियों को मनमाना खेल खेलने का प्रोत्साहन भी मिल है। माओपोंग नेतृत्व यह सोचता रहा है कि 'उसकी' कथनी और करनी का अन्तर रहस्य ही बना रहेगा और वह एशिया की आँखों में धूल भोंकता रहेगा। मगर 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रपञ्चपूर्ण राजनीति के इस खेल को जाग्रत एशिया के देश अब अन्धवीं तरह समझ गए हैं और माओपोंग चीन का सही चेहरा यानी उसका प्रसारवादी स्वरूप उजागर हो गया है।

चीन की विदेश नीति मूलतः शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती। उसने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच राजनीतिक-विग्रह खड़ा करने का जो आन्दोलन काफी समय से शुरू कर रखा है उसमें अभी कोई अन्तर नहीं आया है। वह इन दो महाशक्तियों के बीच किसी भी तरह का सद्भाव स्थापित न होने देने के लिए कृतसंकल्प है। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद में फूट डालने की नीति का भी चीन ने परित्याग नहीं किया है। इस समय वह पूरे साम्यवादी जगत् में विघटन की प्रक्रिया का अग्रदूत बना हुआ है।

इन सब विरोधी और विध्वंसक प्रवृत्तियों के बीच आशा की किरणें यही हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, महाशक्तियाँ सह-अस्तित्व के मिद्धान्त को मानने लगी हैं चीनी नेतृत्व अपनी कालिमा को धोने के लिए सोच विचार करने लगा है और यह भी समझ गया है कि भारत राजनीतिक, प्राथमिक और सैनिक दृष्टि से निरन्तर शक्तिशाली बनता जा रहा है, अतः उसके प्रति रचनात्मक रवैया अपनाना ही उचित होगा। फिर भी चीन के अभी तक के व्यवहार को देखकर कोई निश्चित भविष्यवाणी करना कठिन है।

ब्रिटेन और फ्रांस की विदेश नीति (THE BRITISH AND FRENCH FOREIGN POLICY)

“मेरी धारणा है कि किसी भी देश को शाश्वत रूप से शत्रु अथवा मित्र मान लेना एक संकीर्ण नीति है। केवल हमारे हित ही शाश्वत तथा विरग्न हैं तथा हमारा कर्तव्य है कि हम इन हितों का अनुसरण करें।”

—साईं पामस्टन

ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को ही द्वितीय महायुद्ध में प्रबल आघात सहने पड़े और उनके हितों की कल्पनाहीन क्षति पहुँची। उनकी स्थिति तीसरी श्रेणी के राष्ट्रों जैसी हो गई। घुरी राष्ट्र को अपना साम्राज्य छोड़ देना, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस आदि विजेता राष्ट्र भी अपने साम्राज्यों की रक्षा नहीं कर सके और एक-एक करके उनके अधीनस्थ लगभग सभी प्रदेश स्वतन्त्र हो गए।

ब्रिटेन की विदेश नीति (British Foreign Policy)

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटेन की विदेश नीति दो सिद्धान्तों पर आधारित थी—प्रथम, यूरोप में सन्तुलन की शक्ति (Balance of Power) को कायम रखना तथा द्वितीय, अपनी वस्तुियों (Colonies) में अपना प्रभुत्व स्थापित रखना। परन्तु इस दूसरे महामय ने तो उसका चित्र ही परिवर्तित कर दिया। किसी ने लिखा है “इंग्लैण्ड जो दूसरों को जीतने के लिए था, उसने स्वयं को विजित कर लिया।” चूँकि ब्रिटेन में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि वह यूरोप में सन्तुलनकारी सत्ता के रूप में रह सके, अतः उसने शान्तितात् में ही सुरक्षा-अग्नियों की समस्या करना आरम्भ कर दिया था। परन्तु इस मन्त्रि व्यवस्था में भी उसके मन्त्रिभक्त में शक्ति-अन्तुलन का भूत समाया रहा ताकि ये तो आपस में लड़ें और ब्रिटेन प्रसूत रह सके।

युद्धोपरान्त अपने साम्राज्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने एक नयी नीति का अनुसरण किया जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ देश स्वतन्त्र हो गए पर ब्रिटेन के

साथ उनका सशक्त कार्यम रहा। पुराने ब्रिटिश-साम्राज्य ने अब ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल (British Commonwealth) का स्वरूप ग्रहण किया और अन्तराष्ट्रीय राजनीति में ब्रिटेन अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम रख सका। आज ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का जो रूप है उसमें सब सदस्य-राज्यों की स्थिति बराबर है। सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्नता को अक्षुण्ण रखते हुए वे राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं। यदि वे चाहें तो इससे पृथक् भी हो सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की सदस्यता आज भी ग्रहण किए हुए हैं। राष्ट्रमण्डल में कतिपय ऐसे प्रदेश भी हैं जिन्हें अभी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई है। हिन्द महासागर और भूमध्यसागर में अनेक ऐसे द्वीप हैं जिन पर ब्रिटिश प्रभुत्व विद्यमान है।

ब्रिटेन और कोलम्बो-योजना

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्यों की आर्थिक उन्नति के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों में कोलम्बो-योजना का विशेष महत्त्व है। जनवरी, 1950 में ब्रिटेन के प्रयत्नों से श्री लंका की राजधानी कोलम्बो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के विभिन्न देशों की आर्थिक उन्नति में सहायता के लिए एक योजना तैयार की गई। इस योजना में प्रारम्भ में केवल ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्य-राज्य ही सम्मिलित थे, पर अब पश्चिमी एशिया के भी अनेक राज्य इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

ब्रिटेन और अमेरिका

गुटोत्तर काल में ब्रिटेन ने अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी नीति अपनायी। ब्रिटेन आर्थिक विपन्नता की अवस्था में था और उसे अपने पुनर्निर्माण तथा आर्थिक स्थिरता के लिए भारी आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, अतः यह स्वाभाविक था कि ब्रिटेन ने अमेरिका का सहयोग प्राप्त किया और अपनी विदेश-नीति का मुख्य आधार अमेरिका का समर्थन करना बना लिया। यद्यपि पेरिस शान्ति-सम्मेलन में ब्रिटेन ने घोषणा की थी हम किसी भी गुट में मिलना नहीं चाहते, लेकिन कथनी और करनी में अंतर रहा। अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से मार्शल-योजना के अन्तर्गत पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त की। अमरतीय विदेश-मन्त्री थी बेविन ने ट्रूमैन सिद्धान्त को भी स्वीकार कर लिया। यद्यपि ब्रिटेन अमेरिकी गुट में एक सहायक के रूप में ही रहा, तथापि यह स्पष्ट हो गया कि पारचाय जगत् का नेतृत्व ब्रिटेन के नहीं, अमेरिका के हाथ में है। अनेक क्षेत्रों में ब्रिटेन का स्थान अमेरिका लेना गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे पुराने डोमिनियनों ने राष्ट्रमण्डल में बाहर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 'अजुयस पॅक्ट' (Anzus Pact) करना उचित समझा। मध्य पूर्व में भी, किलिरीन, टर्की और अन्य क्षेत्रों में ब्रिटेन के चले जाने से जो शक्ति-शून्यता पैदा हो गई उसे अमेरिका ने भरा। नाटो (NATO) में सम्मिलित होकर ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ सुला सैनिक गठबन्धन कर लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि साम्यवाद के विरुद्ध जेहाद में वह पूरी तरह अमेरिका के साथ है।

निःशस्त्रीकरण संबंधी सभी बातोंमें में ब्रिटेन और अमेरिका की नीति में सामान्यतः सामञ्जस्य रहा और लन्दन में वाशिंगटन को पूर्ण समर्थन दिया। सितम्बर, 1954 में ब्रिटेन ने समुत्तराञ्च अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, थाईलैंड आदि के साथ पारस्परिक सहायता और सामूहिक सुरक्षा-सन्धि पर हस्ताक्षर कर दक्षिण पूर्वी एशिया सन्धि सङ्घन (SEATO) को जन्म दिया (जो 30 जून, 1977 को विघटित कर दिया गया)। ब्रिटेन ने सन् 1957 में प्रतिपादित आइज़नहावर सिद्धान्त के प्रयोग में पूर्ण विच्छा प्रदर्शित की और बोर्डन में जो द्वय विद्वान्त के प्रयोग की दिशा में उसका व्यावहारिक व सश्रिय सहयोग रहा। जर्मनी के प्रश्न पर भी ब्रिटेन का धन्य सम्बन्धित पश्चिमी शक्तियों के साथ पूर्ण सहयोगी रूप है। सन् 1963 में अमेरिका रूस और ब्रिटेन द्वारा मास्को में धनु-परीक्षण प्रतिवन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर किए गए और फिर 1968 की परमाणुविक सन्धि पर भी ब्रिटेन प्रमुख हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्र था।

अमेरिका के साथ अपना घनिष्ठ सहयोग करते हुए भी अनेक विषयों पर ब्रिटेन का अपना स्वतन्त्र दृष्टिकोण रहा है। विरोध करते समय खोनी देत यह मान कर चले हैं कि एक शक्ति को अपने मित्र की प्रालोचना करने का अधिकार है। अतः, 1945 में ब्रिटेन की तब सप्रसन्नता हुई जब अमेरिका द्वारा एकदम लैंड-लीज (Land-Lease) को बन्द कर दिए जाने से ब्रिटिश अर्थ-नीति पर विनोत प्रभाव पड़ा। युद्धोत्तरकाल में ब्रिटेन में जो समाजवादी आन्दोलन छिड़ा और शक्ति सरकार द्वारा नीतिषी अपनायी गई उनके प्रति अमेरिका में सदैहपूर्ण आतावरण पैदा हुआ। साम्प्रदायी रूप के प्रति अमेरिका की कठोर नीति की ब्रिटेन ने विशेष सराहना नहीं की। ब्रिटेन की वही धारणा रही कि रूस एवं अन्य साम्यवादी देशों के साथ अधिकाधिक व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहिए और रूस तथा चीन को समझौते-पूर्ण रवैये द्वारा अपने निकट आने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्रिटेन ने अमेरिका की सप्रसन्नता की परवाह न कर जनवरी, 1950 में ही चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देने के विचार की घोषणा कर दी। उपनिवेशवाद के मन्त्र में भी अमेरिकी रूस के प्रति ब्रिटेन में प्रसन्नता रहा। उसका यही मत है कि हिन्द चीन, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया आदि प्रदेशों में ब्रिटिश सहयोग और हितों के प्रति अमेरिका का दृष्टिकोण विशेष सहाय्यपूर्ण नहीं रहा है। स्वेड का सन् 1956 में नासिर द्वारा राष्ट्रीकरण किए जाने पर ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा जो आक्रामक नीति अपनायी

1. साम्यवाद के विरुद्ध लौटपुट के लिए गठित दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि सङ्घन (सोर्टो) ने नासिर-पूर्वक हुत्ता पीक मजले हुए 30 जून, 1977 को समाप्त कर दिया। 23 वर्ष पुराने इस सङ्घन को उत्तर के छ सन्धय देशों के द्वय दृष्टिकोण के कारण बन्द किया गया कि दक्षिण में कम्युनिस्टों की विजय के कारण परिस्थितियाँ बदलती हैं तथा सन् 1950 के जब एक साम्यवाद के प्रति आतंकवादी देशों के दृष्टिकोण में काफी सुधार हुआ है। सोर्टो का जग कम्प्लिक्ट विरोधी सङ्घन सुरक्षा सन्धि के रूप में सन् 1954 में मनीषा समझौते के मनीषा हुआ था। सैनिक कटगोड़ को समाप्त करने के बाद यह मनीषा समझौता अभी भी बाधक रहेगा।

गई उसका अमेरिका ने समर्थन नहीं किया। अमेरिका का यह दृष्टिकोण ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के लिए बड़ा अनपेक्षित था। अरब-इजराइल के सन् 1967 के संघर्ष में भी ब्रिटिश और अमेरिकी नीतियों में विशेष निकटता नहीं थी।

परन्तु विभिन्न मतभेदों के बावजूद भी दोनों देशों के मौलिक हित परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं और श्री चर्चिल के ये शब्द आज पूर्ण महत्त्व रखते हैं कि— “हमारे अस्तित्व की सम्पूर्ण नींव संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ संधि, मित्रता तथा बढ़ते हुए भाई-चारे की भावना पर आधारित है।” निक्सन और फोर्ड प्रशासन के उपरान्त वर्तमान कार्टर प्रशासन से ब्रिटेन के सम्बन्ध अधिक सहयोगपूर्ण हैं।

ब्रिटेन के फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी देशों से सम्बन्ध

ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को दृढ़ करने के अतिरिक्त अन्य पश्चिमी देशों को भी साथ लेने की कोशिश की और अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रीय योजनाओं का विकास किया। 4 मार्च, 1947 को उसने फ्रांस के साथ डकर्क-सन्धि (Dunkirk Treaty) सम्पन्न की जो भावी जर्मन आक्रमणों के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता करने के उद्देश्य से हुई। इसके बाद 17 मार्च, 1948 को ब्रिटेन ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग और फ्रांस के साथ मिल कर ब्रूसेल्स सन्धि की जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोपीयन संघ (Western European Union) का निर्माण हुआ। इस सन्धि-संगठन के सदस्यों में यह निश्चय हुआ कि हस्ताक्षरकर्ता देशों में से किसी देश पर यदि यूरोप में सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की पारा 51 के अनुसार अपनी सम्पूर्ण सैनिक तथा अन्य सहायता आक्रमण के शिकार देश को प्रदान करेंगे।

डकर्क, ब्रूसेल्स और नाटो संधियों का सदस्य बन जाने के बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय परिषद् (Council of Europe) के निर्माण में रुचि ली। 5 मई, 1949 को इस परिषद् की स्थापना हुई।

जनवरी, 1958 में यूरोपीयन सामान्य मण्डी या साझा बाजार की स्थापना हुई जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग सम्मिलित हुए। ब्रिटेन इस मण्डी में सम्मिलित नहीं हुआ। परन्तु जब यूरोपीयन सामान्य मण्डी से ब्रिटेन और अन्य देशों को काफी हानि पहुँचने लगी तो इसके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने यूरोपीयन मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association) का निर्माण किया। यह संघ यूरोपीयन सामान्य मण्डी का मुकाबला न कर सका। सन् 1961 तक ब्रिटेन का यूरोप के साथ निर्यात व्यापार घट गया, उसकी कृषि-वस्तुओं की मण्डी समाप्त प्रायः हो गई, अतः विचारा होकर उसने यूरोपीयन सामान्य मण्डी का सदस्य बनने का प्रयत्न किया, किन्तु फ्रांस की हठधर्मी के कारण उसके सदस्य बनने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटेन यूरोपीयन सामान्य मण्डी का सदस्य बनने का निरन्तर प्रयास करता रहा और उसका सदस्य बन जाना लगभग निश्चित-सा हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री विल्सन ने मई, 1967 में ब्रिटिश संसद् में इस बात की घोषणा भी की, किन्तु

थी डिगॉल का दृढ़ इस 'निश्चय' को त्रियान्वित करने में सहायक नहीं हुआ। अप्रैल, 1969 में डिगॉल ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और अन्ततः दस वर्ष से भी अधिक समय के प्रवास के बाद ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन ही गया।

28 दिसम्बर, 1971 को ब्रिटेन और साभा बाजार के सदस्यों के बीच समझौता हो गया। साभा बाजार के विस्तार से सम्बन्धित रोम की सन्धि पर 22 जनवरी, 1972 को ब्रिटेन, नार्वे, डेनमार्क और एयर (उत्तर आयरलैण्ड) तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के वर्तमान छः सदस्य देशों (पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली और बेल्जियम) ने ब्रुसेल्स में हस्ताक्षर किए। साभा बाजार का त्रिविध विस्तार जनवरी, 1973 में हुआ और नए चार सदस्यों ने अपने-अपने देश में सन्धि की पुष्टि करायी। ब्रिटेन में ससद् तथा नार्वे, डेनमार्क और एयर में वहाँ के मतदाताओं ने उसकी पुष्टि की। पुष्टि से सम्बन्धित प्रश्न 31 दिसम्बर, 1972 तक साभा बाजार के मुख्यालय में जमा कराए गए। सन्धि के अनुसार नए सदस्य-देशों को साभा बाजार की भविष्य में होने वाली बैठकों में भाग लेने का अधिकार मिल गया।

ब्रिटेन एवं अन्य देश

अमेरिकी मुठ ने रहते हुए और विभिन्न अवसरों पर साम्यवादी देशों की कटु आलोचना करने पर भी युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन ने साम्यवादी मुठ के देशों के साथ राजनीतिक सम्बन्धों के प्रतिरिक्त व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित किए हैं। वास्तव में साम्यवादी देशों प्रमुखतः रूस और चीन के प्रति ब्रिटेन ने द्विमुखी नीति का अनुसरण किया है। एक ओर तो यूरोप में बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को तथा विश्व के अन्य भागों में साम्यवादी प्रसार को प्रवण्ड करने के लिए वह 'शीत-युद्ध' में सुम्मित हो गया और पार्श्विक संगठनों द्वारा साम्यवादी प्रभाव का विस्तार रोकने में तत्पर होने लगा और दूसरी ओर अपने साम्यवादी देशों के साथ अपने व्यावसायिक सम्बन्ध विकसित करने की चेष्टा की। संयुक्तराज्य अमेरिका का अनुगमन करते हुए भी ब्रिटेन ने चीन का विरोध नहीं किया है क्योंकि चीन में उसकी अपार सम्पत्ति तथा वृहद् व्यवसाय है। उसने चीन को, अमेरिकी विरोध के बावजूद कूटनीतिक साम्यता भी प्रदान कर दी है। चीन के व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डलों ने छोट ब्रिटेन का भ्रमण किया और ब्रिटेन द्वारा चीन से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए गए। दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने एक दूसरे के देशों की यात्राएँ की। दोनों के मध्य समय-समय पर प्रतिनिधि मण्डलों के जाने-जाने का क्रम भी जारी है। 3 मई, 1976 को ब्रिटिश विदेश मंत्री जॉनलैण्ड ने चीन की यात्रा की और चीन की विमानों की विदेशी, वैज्ञानिक सार-सामान देने के बारे में बातचीत की। जॉनलैण्ड ने चीनी नेताओं से घण्टा हिमा कि दिसम्बर में ब्रिटेन में होने वाले फार्मो विमान प्रदर्शनों में चीन अवश्य शामिल हो। विश्व की विभिन्न पक्षविधियों पर भी विचार-विमर्श हुआ, चीनी नेताओं ने तीसरे विश्व-युद्ध का भय

प्रकट करते हुए कहा कि दो बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है और युद्ध स्थान एक बार फिर यूरोप की घरती ही बनेगी, फ्रांसलैण्ड ने चीन के इस भय को निराधार बताते हुए अपने भाईचारों के विचारों से चीनी अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार हर हालत में पश्चिमी यूरोप में एकता और सुरक्षा कायम रखना चाहती है। हमारा मविष्य यूरोपीय समुदाय के साथ ही है। समुदाय विकास की स्थिति में है और भावी विकास के लिए सभी सदस्य-देश पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाते हैं, तथापि समुदाय के भीतर रह कर हम सब सहयोग के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम सबका प्रयास रहता है कि यूरोप की एकता किसी भी तरह से खण्डित न होने पाए। पिछले तीन वर्षों से ब्रिटेन की हर सरकार—कजरवेटिव या लेबर ने यह अनुभव किया है कि हमारी सुरक्षा नाटो पर आधारित है और यही कारण है कि हम उसकी उपयोगिता को महत्व देते हैं। फ्रांसलैण्ड की यात्रा की समाप्ति पर प्रसारित ममुक्त विज्ञप्ति में यह बात स्पष्ट कर दी गई कि नेतृत्व में परिवर्तन के बावजूद ब्रिटेन और चीन में सहयोग और मैत्री पर किसी तरह का अन्नर नहीं आया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में ब्रिटेन पश्चिमी गुट का उपनेता है और अधिकांशतः उसने संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मिलकर कार्य किया है। संघ में ब्रिटेन को अधिकांशतः एशिया और अफ्रीका के राज्यों का विरोध सहना पड़ा है। इस विरोध का प्रमुख कारण एशियाई और अफ्रीकी राज्यों के प्रति अपनायी जाने वाली उसकी विरोधी नीति रही है। भारत के साथ कश्मीर के मामले में और मिस्र अथवा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ स्वेज एंव इजरायल विवाद पर ब्रिटेन से ग्याय का गला घोटने की कोशिश की है। सन् 1956 में स्वेज-विवाद पर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र के विरुद्ध जो आक्रामक कार्यवाही की उससे मिस्र और ब्रिटेन के सम्बन्ध तनावपूर्ण बन गए और सन् 1967 में अरब-इजरायल संघर्ष में उसके द्वारा अरब विरोधी दृष्टिकोण अपनाने के कारण ये सम्बन्ध और भी कटु बन गए हैं। सतभेदों के बावजूद कतिपय अवसरों पर ब्रिटेन का रुख भारत के प्रति उदार रहा है। चीनी आक्रमण के समय ब्रिटेन ने भारत को मविलम्ब सैनिक सहायता प्रदान की थी और वैसे भी ब्रिटेन से विकासशील देशों को जो आर्थिक सहायता दी जाती रही है उसमें सबसे अधिक राशि भारत को प्राप्त हुई है। सन् 1970 में ब्रिटेन ने विकासशील देशों की सहायता पर लगभग 334.8 करोड़ रुपये व्यय किए थे जिसमें भारत के हिस्से में 81 करोड़ रुपये आए। यगलादेश के मुक्ति आन्दोलन और भारत में शरणार्थियों की बाढ़ के समय ब्रिटिश सरकार का रुख भारत के लिए यद्यपि उदासीन सा रहा तथापि अमेरिका की भांति असंगत विरोध करने की दृष्टि से सयम ही रखा गया। दिसम्बर, 1971 में भारत-पाक युद्ध के समय सुरक्षा परिषद् में ब्रिटेन का रुवैया चाहे पूर्ववत् रहा हो फिर भी अन्य दृष्टियों से वह अमेरिका के समान बहुका नहीं था। फिर भी कुल मिलाकर ब्रिटेन का आधिक समर्थन तो पाकिस्तान की ओर ही है। हिन्दमहासागर में भी यह भारत के वचस्व का पक्षधर नहीं है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के प्रति ब्रिटेन ने कोरा प्रदर्शनात्मक विरोध ही किया है। वह अफ्रीका में रोडेशिया की गोरी सरकार की नीतियों को भी नहीं रोक पाया है। पर, वह संदेह व्याप्त है कि रोडेशिया की अल्पसंख्यक स्मिथ सरकार को ब्रिटेन का गुप्त एवं अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्राप्त है। एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों के समर्थन में ब्रिटिश विदेश-नीति अधिर्ज्ञातः प्रस्यर और अस्पष्ट रही है।

फ्रांस की विदेश-नीति (French Foreign Policy)

फ्रांस की सन् 1958 तक कमजोर स्थिति

यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में स्थित यह देश उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रमशः उत्तरी सागर व इंगलिश चैनल, अटलांटिक महासागर तथा भूमध्यसागर से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में जर्मनी है, पूर्वोत्तर में हॉलैण्ड-बेल्जियम, दक्षिण-पूर्व में इटली और दक्षिण-पश्चिम में स्पेन। यद्यपि फ्रांस की विदेश-नीति अपने पड़ोसियों के प्रति परिवर्तनशील रही है, तथापि घनिष्ठ मित्रता के बावजूद भी फ्रांस ब्रिटेन की ओर सदा सशक्त रहा है। ब्रिटेन ने कभी भी फ्रांस को यूरोप का सर्वाधिक शक्ति-शाली राज्य नहीं बनने दिया। प्रथम महायुद्ध के बाद फ्रांस ने जो कुछ भी शक्ति और स्याति अर्जित की, वह द्वितीय महायुद्ध में घूल में मिल गई। युद्ध की समाप्ति के बाद फ्रांस की नई सरकार की अध्यक्षता जनरल डिगॉन के हाथों में आ गई, परन्तु फ्रांस के सविधान से ऊँचकर तथा मन्त्रिमण्डलों की अस्थिरता से परेशान होकर डिगॉन ने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति से सम्प्राप्त ले लिया। अब फ्रांस की अस्थिरता का वही पुराना चक्र पुनः आरम्भ हो गया। सन् 1946 से 1958 तक 22 मन्त्रिमण्डल बने। युद्ध और अस्थिर शासन ने फ्रांस को इतना निःशक्त बना दिया कि यह किसी प्रकार की प्रभावशाली विदेश-नीति नहीं अपना सका। मार्च, 1947 में उसने ब्रिटेन के साथ ढकक की सन्धि की, तत्पश्चात् संयुक्तराज्य अमेरिका के साथ मार्शल योजना में भागीदार बनकर उसने अमेरिका से पर्याप्त सहायता प्राप्त की। पश्चिम यूरोप के राजनीतिक एकीकरण को विभिन्न योजनाओं में उसने सहयोग किया। वह ब्रुसेल्स पंचट और नाटो का भी सदस्य बना। अन्य पाँच राष्ट्रों के साथ मिलकर फ्रांस ने यूरोपियन साम्राज्य बाजार का निर्माण किया और इसमें ब्रिटेन के प्रवेश को रोकने का सफल प्रयास किया। साम्राज्य बाजार में ब्रिटिश प्रवेश मुख्यतः श्री डिगॉन के विरोधी रुख के कारण ही रुका रहा।

फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश-मन्त्रियों ने सितम्बर, 1950 में जर्मनी के प्रश्न पर विचार कर जर्मन लोगों की एकीकरण की भावना का समर्थन किया। रुख के प्रसङ्गों के कारण जर्मनी का एकीकरण सम्भव न हो। सका अन्त में तीनों राष्ट्रों ने जर्मन-संघीय गणराज्य (पश्चिमी जर्मनी) को ही जर्मन जनता का वास्तविक प्रतिनिधि मानने का निश्चय किया। एशियायी विवादों में फ्रांस ने अधिक भाग नहीं लिया क्योंकि हिन्द चीन की समस्या में फ्रांस को निरन्तर पीछे हटना पड़ा तथा

जुलाई, 1954 के जिनेवा शिखर-सम्मेलन में वियतनाम के विभाजन को मान्यता मिल गई। फ्रांस कोरिया-युद्ध में भी कोई भाग इसलिए नहीं ले सका था क्योंकि वह उस समय हिन्द चीन में साम्यवादियों से युद्ध में उलझा हुआ था। सन् 1956 में फ्रांस और ब्रिटेन ने इजरायल के साथ मिलकर मिस्र पर आक्रमण किया; किन्तु उनके साम्राज्यवादी इरादे परस्त हो गए, यहाँ तक कि उन्हें समुक्तराज्य अमेरिका तक के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा।

डिगॉलकालीन विदेश-नीति

सन् 1958 के मध्य तक फ्रांस अपनी राजनीतिक अस्थिरता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा सका, किन्तु इसके बाद स्थिति में परिवर्तन आया। मई, 1958 में पिछरे फिलगिन सरकार का पतन हो जाने के बाद डिगॉल के प्रधानमन्त्रित्व में फ्रांस के पाँचवें गणतन्त्र का उदय हुआ। असेम्बली ने डिगॉल को 6 मास के लिए ससदीय हस्तक्षेप से मुक्त समस्त अधिकार सौंप दिए। उन्होंने 3 जून, 1959 को एक सांविधानिक कानून का निर्माण किया जिसके ससदीय सुधारों को राष्ट्रीय असेम्बली में प्रस्तुत न कर सीधे इलेक्टोरेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता था। 4 सितम्बर, 1959 को पाँचवें गणतन्त्र का नवीन संविधान प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार ससद् की अनेक शक्तियाँ राष्ट्रपति को हस्तान्तरित कर दी गयीं। दिसम्बर, 1959 को राष्ट्रपति के चुनाव में डिगॉल पहले ही बहुमत से राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। डिगॉल ने फ्रांस की समस्याओं का हृदय से सामना किया और उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान दिलाया।

अल्जीरिया-फ्रांस संघर्ष का अन्त—फ्रांस ने नवीन संविधान के अनुसार 2 अक्टूबर, 1958 को गिनी राज्य की स्वतन्त्र मान लिया और 23 नवम्बर को वह समुक्त राष्ट्रमण्डल का सदस्य बन गया। राष्ट्रपति डिगॉल ने शासन की बागडोर हाथ में लेते ही अपना ध्यान अल्जीरिया की तरफ केन्द्रित किया। डिगॉल के पूर्ववर्ती सभी फ्रेंच नेता कह चुके थे कि फ्रांस अल्जीरिया में अपने अधिकारों को कभी समाप्त नहीं करेगा। अपने साम्राज्यवादी अधिकारों की रक्षा के लिए फ्रांस अल्जीरिया के स्वाधीनता आन्दोलन को जुरी तरह कुचलता रहा, किन्तु इससे अल्जीरियावासियों के स्वातन्त्र्य-संघर्ष में कोई कमी नहीं आई। राष्ट्रपति डिगॉल ने विद्रोहियों को शान्त करने और अल्जीरिया युद्ध को रोकने के लिए समझौता कराने का निश्चय किया। विद्रोहियों को शान्त करने में तो वह सफल हो गए, किन्तु दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। डिगॉल ने अल्जीरियावासियों को फ्रेंच नागरिकता का प्रलोभन दिया, किन्तु वे तो अल्जीरिया की नागरिकता चाहते थे, फ्रांस की नहीं। तब सितम्बर, 1959 में डिगॉल ने घोषणा की कि अल्जीरिया निवासी शान्ति का मार्ग स्वीकार कर लेंगे तो 4 वर्ष के अन्दर ही वहाँ इन सुझावों पर जनमत लिया जाएगा—

1. फ्रांस अल्जीरिया पर अपने समस्त अधिकारों को त्याग देगा।
2. फ्रांस के साथ अल्जीरिया का एकीकरण कर लिया जाएगा और

अल्जीरिया-निवासियों को मेट्रोपोलिटन फ्रांस के नागरिकों को प्राप्त सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।

3. अल्जीरिया निवासी ही वहाँ का शासन करेंगे, किन्तु इसके पीछे फ्रांस का भी आर्थिक-शैक्षिक तथा वैदेशिक सहयोग रहेगा।

परन्तु ये सुभाव उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। प्रथम तो ये सुभाव शान्ति-स्थापना के बाव ही क्रियान्वित किए जा सकते थे और शान्ति की स्थापना तभी हो सकती थी जब अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाए। दूसरे चुनाव-परिणामों को फ्रेंच सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी थी जो वहाँ की जनता की राष्ट्रीय भावना के लिए अपमानजनक बात थी। अल्जीरियन गणतन्त्र की अन्तर्कालीन सरकार ने इस विषय पर फ्रेंच सरकार से बातलाप करना स्वीकार किया, परन्तु डिगॉल ने उसे अल्जीरिया के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। जनवरी, 1960 में अल्जीरिया में डिगॉल-विरोधियों ने भीषण विद्रोह कर दिया जिससे समस्या का समाधान और भी दुष्कर हो गया। फरवरी, 1960 में फ्रेंच-संसद द्वारा राष्ट्रपति डिगॉल को अल्जीरिया-विवाद के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिए गए। उन्होंने अल्जीरिया तथा फ्रांस में जनमत-संग्रह कराने का प्रस्ताव किया। यद्यपि यह जनमत-संग्रह 'अल्जीरिया-अल्जीरिया वालों के लिए' विषय पर होना था। किन्तु अल्जीरिया की अन्तर्कालीन सरकार (स्वातन्त्र्य शान्दोलन की संचालक) के अध्यक्ष अब्बास ने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया और अपने अनुयायियों को मतदान में भाग न लेने का आदेश दिया। 1961 में जनमत-संग्रह हुआ जिसमें लगभग षेड करोड़ लोगों ने अल्जीरिया में स्वयत्त शासन स्थापित होने के पक्ष में तथा 50 लाख लोगों ने इसके विपक्ष में मत दिया। परन्तु समस्या यह थी कि स्वायत्त शासन प्राप्त करने पर भी अल्जीरिया पूर्ण स्वतन्त्र न होता क्योंकि किसी न किसी रूप में उस पर फ्रांस का प्रभिकार बना ही रहता, तथापि पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कोई समाधान निकल जाने की सम्भावना अवश्य बढ गई। किन्तु अप्रैल, 1961 में, डिगॉल-विरोधी कुछ अवकाश प्राप्त फ्रेंच सैनिक अधिकारियों ने सहसा आक्रमण कर अल्जीरिया पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। डिगॉल ने इस सैनिक विद्रोह को दबा दिया और अल्जीरिया की राष्ट्रवादियों के साथ वार्ता शुरू कर दी। अतः, 1 जुलाई, 1962 को अल्जीरिया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई और इस प्रकार राष्ट्रपति डिगॉल ने अल्जीरिया-फ्रांस संघर्ष का अन्त कर दिया।

अन्तर्राष्ट्रीय गौरव की पुनः प्राप्ति की चेष्टा—राष्ट्रपति डिगॉल की प्रमुख चिन्ता सदैव यह रही कि फ्रांस किसी न किसी प्रकार अपने विलुप्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान की पुनः प्राप्ति कर ले। इसीलिए शनैः-शनैः वह अपने राष्ट्र को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त करने लगे और दूसरी ओर ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकने की चेष्टा में लगे रहे तथा इसीलिए साम्यवादी देशों के साथ उन्होंने मधुर सम्बन्ध स्थापित किए। साम्यवादी चीन के साथ फ्रांस के निरन्तरपूर्ण सम्बन्धों में विकास हुआ। मास्को की मधु-परीक्षण विरोध-सन्धि पर हस्ताक्षर न करने वाले केवल दो

ही बड़े देश थे—चीन और फ्रांस। दोनों ही ने यह तर्क दिया कि सन्धि का उद्देश्य सोवियत संघ, संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा अणु-शस्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना है एवं उनका यह प्रयोजन है कि अन्य देश इस शक्ति का विकास न करने पाएँ।

फ्रांस ने विद्यतनाम में संयुक्तराज्य अमेरिका की कार्यवाही की निन्दा जिन शब्दों में की, उनमें चीनी आलोचना की गन्ध थी। यूरोपियन साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश को रोकने की डिगॉल की नीति ने पश्चिमी गुट में फूट का संकेत दिया। संयुक्तराज्य अमेरिका ने बहुत चाहा कि ब्रिटेन को यूरोपियन साझा बाजार की सदस्यता प्राप्त हो जाए। इसके लिए उसने फ्रांस पर दबाव भी डाला, किन्तु डिगॉल अपनी हठ पर दृढ़ रहे। इतना ही नहीं, कुछ और बातों पर भी फ्रांस तथा ब्रिटेन-अमेरिका के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्योदनाया गया तो उसने इसमें भाग लेने से इकार कर दिया। इससे भी बढ़कर घटना नाटो को पोलरिस यन्त्रों से युक्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में घटी। सन् 1962 में अमेरिका और ब्रिटेन में एक समझौते द्वारा यह तय हुआ कि नाटो राज्यों की सेनाओं को पोलरिस प्रक्षेपणास्त्रों से लैस किया जाए, परन्तु फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इकार कर दिया और निर्णय लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा। सन् 1963 में मरसीसी सरकार द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर देने और दोनों राष्ट्रों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हो जाने की घटना से यह और भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति डिगॉल का अपना पृथक् मार्ग है जो नाटो राज्यों से भिन्न है।

चीन को कूटनीतिक मान्यता प्रदान करने के अतिरिक्त राष्ट्रपति डिगॉल ने विश्व के समक्ष एक और मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि दक्षिणपूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त डंवाडोल है, अतः इस क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता कर तटस्थीकरण (Neutralisation of S. E Asian Region) कर दिया जाए। संयुक्तराज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों ने डिगॉल के मुद्दा का तीव्र विरोध किया। वास्तव में फ्रांस की ये सभी कार्यवाहियाँ अटलांटिक समुदाय की एकता भंग करने वाली थी। इस एकता को भीषण आघात तो 12 मार्च, 1966 की डिगॉल की इस घोषणा से पहुँचा कि फ्रांस नाटो सगठन से पृथक् होना चाहता है। फ्रांस द्वारा यह निश्चय व्यक्त किया गया कि तीन वर्ष के अन्दर वह अपने सभी अफसरों को नाटो-सेवा से वापस बुला लेगा और उसके साथ ही नाटो के साथ अपने सारे सम्बन्धों को समाप्त कर देगा। फ्रांस की माँग पर ही संयुक्तराज्य अमेरिका को फ्रांसीसी भूमि पर स्थित नाटो ब्रिगो को खाली कर देना पड़ा। वास्तव में फ्रांस के नाटो के परित्याग के निर्णय से पश्चिमी गुट पर एक महान् संकट आ गया। नाटो में पश्चिम जर्मनी को इस शर्त पर 1955 में शामिल किया गया था कि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा। इस शर्त के लिए स्वयं फ्रांस का विशेष आग्रह था। परन्तु अब फ्रांस ही नाटो से निकल जाता तो पश्चिम जर्मनी

भी इस शर्त से मुक्त हो जाता और तब वहाँ सैन्यशक्ति में वृद्धि का कार्यक्रम तीव्र गति से चलने की सम्भावना हो जाती। पश्चिम जर्मनी द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास की प्रतिक्रिया सोवियत गुट के देशों से होती और इस तरह हथियारबन्दी की होड़ का कुक्कुर फिर जोरों से चलना शुरू हो जाता। राष्ट्रपति डिगॉल का यह निर्णय कई मजबूर परिणामों से मुक्त था। इसके कारण यूरोप की कूटनीतिक स्थिति खराब हो सकती थी और पश्चिम जर्मनी के प्रश्न पर युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती थी।

वस्तुतः जनरल डिगॉल कई वर्षों से अपने विभिन्न व्यवहार से राजनीतिक जगत् को चौंकाते रहे। कुछ लोगों ने इसे 'वृद्धावस्था' की सनक का नाम दिया। मगर जो लोग इन कार्यवाहियों के पीछे उद्देश्य खोजने के पक्ष में थे, उनके अनुसार यूरोप और सम्पूर्ण विश्व के प्रति जनरल डिगॉल का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा था—“अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और स्वभावतः वह अपनी शक्ति को बढ़ाने पर तुला हुआ है।” इस शक्ति-विस्तार से बचने के लिए उनके अनुसार दो ही उपाय थे, पहला यह कि उसी गुट का एक सदस्य बन जाए, जहाँ अमेरिकन शक्ति सर्वोपरि है और यह मार्ग सुगम था। दूसरा उपाय था अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा। इसके लिए यह आवश्यक था कि फ्रांस और जर्मनी एक-दूसरे के निकट आएँ, अन्यथा अमेरिकी प्रभाव से नहीं बचा जा सकता था। इसीलिए फ्रांस और जर्मनी में राजनीतिक घनिष्ठता के प्रति सक्रिय कदम उठाए जाते रहे। जनरल डिगॉल का विश्वास था कि फ्रांस ने जिस आर्थिक ढाँचे को पिछले 6 वर्षों में खड़ा किया है, उसे नष्ट न होने दें, ताकि उसे अमेरिकी पद्धति द्वारा आत्मसात् न किया जा सके। अपने व्यक्तित्व की कायम रखने के लिए ही उनकी तीसरी शर्त यह थी कि विश्व में इस बात को समाप्त कर दिया जाए कि शक्ति के कुल दो ही गुट हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। तीसरे गुट की रचना के लिए उन्होंने फ्रांस को पूर्वी यूरोपीय देशों के निकट लाना चाहा ताकि ‘विश्व राजनीति’ में दो गुटों की पद्धति के प्रतिरिक्त भी कुछ हो। इसी नीति को प्रभावकर ब्रिटेन के यूरोपीय सान्ना बाजार में सम्मिलित होने का उन्होंने विरोध किया था।

यद्यपि अनेक राजनीतिज्ञों ने यह मत व्यक्त किया कि विश्व की राजनीति को अपने विचारों के अनुकूल परिवर्तित करना और अपनी इच्छानुसार गुटों का निर्माण और विनाश करना फ्रांस के बूते की बात नहीं है तथा डिगॉल ने विश्व की राजनीतिक घटनाओं को नियन्त्रित करने की शक्ति नहीं है, तथापि जनरल डिगॉल ने अत्यन्त सदिग्य और विवादास्पद परिस्थितियों में भी फ्रांस की प्रतिष्ठा का निरन्तर विकास किया। उन्होंने सन् 1962 में अल्जीरियाई स्वतन्त्रता के समय अपने मन्त्रिमण्डल से कहा था—“मित्रो, फ्रांस का जहाज बहुत ही तूफानी पानी पर भ्रमणर है, जिन्हें भाषा की ध्वनि महसूस होती है वे जहाज से उतर जाएँ और दूसरों को लहरों के गपड़े खाने दें।” डिगॉल ने अपने राष्ट्रपति काल में फ्रांस की वास्तव में तूफानी यात्रा पर चलाया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की जहाज की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बहुत कुछ सफल चेष्टा की।

डिगॉल के बाद फ्रेंच नीति

यद्यपि राष्ट्रपति डिगॉल ने फ्रांसीसी शासन को स्थायित्व प्रदान किया, तथापि उसकी कुछ नीतियों के प्रति देश में असन्तोष तीव्र होता गया। 29 अप्रैल, 1969 को फ्रांस में एक जनमत-संग्रह के परिणामों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति डिगॉल ने याग-पत्र दे दिया। इस तरह न केवल फ्रांस के इतिहास में ही बल्कि वास्तव में यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ। 1 जून को फ्रांस में राष्ट्रपति भेद के लिए चुनाव हुआ और जॉर्ज पोम्पिडू ने निर्वाचन में विजय प्राप्त की।

नई सरकार ने परिस्थितियों का, डिगॉल-शासन की अपेक्षा, ब्रिटेन के प्रति रुख रख अपनाया है, फलस्वरूप वह तात्का बाजार में शामिल हो सका। चकोस्लोवाकिया में रूसी हस्तक्षेप की घटना के बाद फ्रांस ने नाटो संगठन में बने रहना सम्भवतः अधिक उपयोगी और आवश्यक अनुभव किया। राष्ट्रपति पोम्पिडू ने अपेक्षाकृत अधिक सहयोगपूर्ण और नरम रुख अपनाते हुए भी डिगॉल की इस मुख्य नीति का निर्वहन किया कि राष्ट्रीय सम्प्रभुता किसी भी कीमत पर दूसरे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। राष्ट्रपति पोम्पिडू ने अमेरिका से सम्बन्ध-विच्छेद करने में विश्वास नहीं किया तथापि यह अनुभव किया कि यूरोप अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं परम्पराओं और विशेषताओं के कारण अमेरिका से भिन्न है। फ्रांस का यह दृष्टिकोण भी रहा कि उसने अब इंग्लैंड के अमेरिका के साथ स्वाभाविक सम्बन्धों को 'यूरोपीय दृष्टिकोण' के विरुद्ध नहीं माना। दिसम्बर, 1970 में स्वयं पोम्पिडू ने अपने इस अभिमत का संकेत दिया। डिगॉल की तरह ही पोम्पिडू ने भी फ्रांस को एक परमाणु-शक्ति के रूप में देखना चाहा और इसीलिए सभी तरह के अन्तर्राष्ट्रीय विरोधों के बावजूद जून, 1972 में फ्रांस ने दक्षिण प्रशान्त महासागर में अपने परमाणु परीक्षण कर डाले।

सन् 1974 में फ्रांस के राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। अक्टूबर, 1973 में अरब-इजरायल युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा तेल का मूल्य बढ़ाकर तेल की सप्लाई नियन्त्रित करने से विश्व में जब तेल संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने तेल का उपयोग करने वाले देशों की समुक्त कार्यवाही द्वारा उसका सामना करने की जो योजना बनाई, फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्ज पोम्पिडू ने उससे फ्रांस को पृथक् रखा। 2 अप्रैल, 1974 को पोम्पिडू की मृत्यु के बाद जिस्कार द एस्ते राष्ट्रपति निर्वाचन हुए। उन्होंने भी अरब देशों पर समुक्त रूप से दबाव डालने के बजाय द्वितीय आघात पर महयोग बढ़ाने की नीति चालू रखी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड के साथ जिस्कार की भेंट के बाद फ्रांस ने भी तेल उपभोक्ता देशों के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त कर दी। फ्रांस ने अरब-इजरायल युद्ध के समय से पश्चिम एशिया के देशों के लिए शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जो अगस्त 1974 में उठा लिया गया। राष्ट्रपति जिस्कार ने फ्रांस की विदेश-नीति को अभी नया मोड़ नहीं दिया है और उनके अभी तक के कार्य-काल में फ्रांस की आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आई है। भारत के साथ जिस्कार के कार्यकाल से ही

फ्रांस के सम्बन्ध पूर्ववत् सधुर बने रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि-मण्डल एक दूसरे देश की यहाँ यात्रा करते रहे हैं। जनवरी, 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में सहायता मिली। दोनों देशों ने भारत-फ्रांस तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए और आपसी लाभ के लिए आर्थिक आदान-प्रदान उद्योग एवं औद्योगिकी में सहयोग का विस्तार करने के लिए इस ढाँचे का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। अक्टूबर, 1976 में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल ने फ्रांस की यात्रा की। मार्च, 1977 में भारत में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ और जनता पार्टी की सरकार कायम हुई। नयी सरकार भारत की परम्परागत मैत्री-नीति के अनुकूल फ्रांस के साथ भारत के मैत्री सम्बन्धों का विकास कर रही है। वास्तव में नयी सरकार के कार्यकाल में विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने 13 अक्टूबर, 1977 को स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'विना अनिश्चयिता के यह कहा जा सकता है कि भारत की प्रतिष्ठा ऊँची है। हमारे शान्तिपूर्ण और अहिंसक क्रान्ति से भारत में स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र की जो पुनर्स्थापना हुई है उसने विशिष्ट रूप से इस देश की विश्वसनीयता बढ़ी है।'

शान्ति, मित्रता और सहयोग सन्धि (अगस्त 1971)

"दोनों के बीच वर्तमान सच्ची मित्रता के सम्बन्धों को सुदृढ़ और सुविस्तृत करने की इच्छा रखते हुए,

इस विश्वास से कि मित्रता और सहयोग के अधिक विकास से दोनों राज्यों के मौलिक राष्ट्रीय हित तथा एशिया और सारे संसार में सुदीर्घ शांति को पोषण मिलता है।

विश्व शांति और सुरक्षा की दृढ़ता को संबंधित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के मत्त प्रयास एवं उपनिवेशवाद के अवशेषों को पूर्णतया एवं अन्तिम रूप से समाप्त करने के निश्चय से,

विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणालियों वाले राज्यों के बीच शांति-पूर्ण सह-प्रतिस्त्व और सहयोग के सिद्धान्तों में अटूट विश्वास रखते हुए,

इस पूर्व विश्वास के साथ कि संसार की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ सचपें द्वारा न सुलझाई जाकर मात्र सहयोग द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं,

संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के अनुसरण के सकल्प की पुन पुष्टि करते हुए,

एक ओर भारत गणतन्त्र और दूसरी ओर सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ ने वर्तमान सन्धि करने का निश्चय किया है, जिसके लिए निम्नावित पूर्णाधिकारी नियुक्त किए गए हैं :

भारत गणतन्त्र की ओर से श्री सरदार स्वर्णसिंह विदेश मंत्री

सोवियत समाजवादी गणतन्त्र की ओर से श्री प्र. प्र. ग्रोमिको विदेश मंत्री

जिनोंने अपने प्रत्यय पत्र प्रस्तुत किए हैं और जिनको शुद्ध और सही माना गया है, वे निम्न प्रकार से सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद एक—महान् सविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि दोनों देश और उनकी जनता के बीच स्थायी शांति और मित्रता स्थापित रहेगी। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करेगा तथा दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। महान् सविदाकारी पक्ष सच्ची मित्रता, अन्धे प्रतिवेशिता और ध्वांगक सहयोग के वर्तमान सम्बन्धों को उपर्युक्त सिद्धान्तों तथा समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर विकसित और सुदृढ़ करते रहेंगे।

अनुच्छेद दो—प्रत्येक सम्भव प्रकार से दोनों देशों की जनता ने लिए स्थायी शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में योगदान की इच्छा से प्रेरित होकर महान्

सविदाकारी पक्ष अपने इस सबर की घोषणा करते हैं कि वे एशिया और मधुचे सतार में शान्ति स्थापित रखने, शस्त्र-दोड़ को रोकने तथा प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रीय विमन्त्रण के अधीन सामान्य एवं सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए, जिनमें आणविक एवं परम्परागत अस्त्र-शस्त्र दोनों शामिल हैं, सतत् प्रयास करते रहेंगे।

अनुच्छेद तीन—समस्त राष्ट्र और सभी देशों की जनता की समानता के, चाहे उनका व ई भी धर्म या जाति हो, उच्च आदर्श के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित, होकर महान् सविदाकारी पक्ष उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी स्वरों की निंदा करते हैं और उन्हें पूर्णतया लुप्त कर देने के प्रयास के सफलता में पुन आस्था प्रकट करते हैं।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध सघर्ष करने वाले सभी देशों की जनता की उचित आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए महान् सविदाकारी पक्ष अन्य राज्यों के साथ सहयोग करेंगे।

अनुच्छेद चार—भारत गणतन्त्र सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ की शान्तिप्रिय नीति का सम्मान करता है जिसका उद्देश्य सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता और सहयोग को सुदृढ़ करना है।

सोवियत समाजवादी जनतन्त्र सघ भारत की मुक्त नीति का सम्मान करता है और इसमें पुन आस्था प्रकट करता है कि विश्व-शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने तथा सतार में तनाव को कम करने में इस नीति का महत्वपूर्ण स्थान है।

अनुच्छेद पाँच—विश्वशान्ति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने में यहन अभिरुचि रखते हुए तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग का भारी महत्व देते हुए महान् सविदाकारी पक्ष दोनों राज्यों के हितों को प्रमाणित करने वाली मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में प्रमुख राजनेताओं के बीच गोष्ठी और विचारों के आदान-प्रदान, दोनों सरकारों के विशेष दूतों तथा सरकारी प्रतिनिधि-मंडलों की यात्रा एवं राजनयिक माध्यमों के द्वारा बराबर सम्पर्क बनाए रखेंगे।

अनुच्छेद छः—दोनों के बीच मार्शिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को पूरा महत्व देने हुए महान् सविदाकारी पक्ष परस्पर लाभकारी एवं व्यापक सहयोग को इन क्षेत्रों में बराबर सुदृढ़ एवं विस्तृत करते रहेंगे तथा 26 दिसम्बर, 1970 के भारत-सोवियत व्यापार समझौते के अन्तर्गत निरंकुश देशों के साथ उत्थित विशेष व्यवस्था एवं वर्तमान समझौते के अधीन समानता, पारस्परिक लाभ तथा आतु अनुपुष्टी राष्ट्र के प्रति व्यवहार के आधार पर व्यापार, परिवहन और संचार का विस्तार करेंगे।

अनुच्छेद सात—महान् सविदाकारी पक्ष विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, पर्यटन और खेल के क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध एवं सम्पर्क और अधिक विकसित करेंगे।

अनुच्छेद आठ—दोनों देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अनुसार महान् सविदाकारी पक्षों का प्रत्येक पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी ऐसे सैनिक संगठन में, जो दूसरे पक्ष के विरुद्ध हो, न सम्मिलित होगा और न भाग लेगा।

प्रत्येक महान् सविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह एक दूसरे पक्ष पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा तथा अपने क्षेत्र में किसी प्रकार के ऐसे कार्य को नहीं होने देगा जिससे दूसरे पक्ष की सैनिक क्षति होने की आशंका हो।

अनुच्छेद नौ—प्रत्येक महान् सविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह किसी तीसरे पक्ष को, जो महान् सविदाकारी पक्ष के विरुद्ध शस्त्र संपर्क में रत हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। दोनों में से किसी पक्ष पर आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान् सविदाकारी पक्ष जो भी ही परस्पर विचार-विमर्श करेंगे तानि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाए तथा दोनों देशों की शान्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाए जाएँ।

अनुच्छेद दस—प्रत्येक महान् सविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा जो इस सन्धि के प्रतिकूल हो। महान् सविदाकारी पक्ष का प्रत्येक पक्ष यह भी घोषित करता है कि उसका किसी राज्य या राज्यों के साथ न कोई ऐसा वर्तमान दायित्व है और न भविष्य में वह कोई ऐसा दायित्व लेगा जिससे दूसरे पक्ष को किसी प्रकार की हानि हो सकती हो।

अनुच्छेद ग्यारह—यह सन्धि बीस वर्षों की अवधि के लिए की गई है और महान् सविदाकारी पक्षों में से एक पक्ष सन्धि के समाप्त होने के बारह महीने पूर्व दूसरे पक्ष को नोटिस देकर सन्धि को समाप्त करने की इच्छा घोषित न करे तो प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि के बाद स्वतः इसकी अवधि बढ़ जाएगी। यह सन्धि अनुसमर्थन के अधीन होगी और अनुसमर्थन के दस्तावेज के आदान-प्रदान के दिन से लागू होगी। दस्तावेजों का यह आदान-प्रदान हस्ताक्षर हो जाने के एक महीने के भीतर मास्को में होगा।

अनुच्छेद बारह—महान् सविदाकारी पक्षों के बीच इस सन्धि के किसी एक या एकाधिक अनुच्छेद की व्याख्या में किसी प्रकार का अन्तर उत्पन्न होने पर शान्तिपूर्ण उपायों, पारस्परिक सम्मान और सूझबूझ द्वारा द्विपक्षीय ढंग से उसे निपटाया जाएगा।

उपयुक्त पूर्णाधिकारियों ने वर्तमान सन्धि पर हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए हैं इन पर उन्होंने अपनी मुहर लगा दी है और इस सन्धि के सभी के सभी पाठ समान रूप से प्राधिकृत हैं।

प्राज्ञ, नई दिल्ली में ईसवी सन् 1971 के अगस्त मास के नवें दिन तदनुसार शक सवन् 1893 के आषाढ मास के अठारहवें दिन यह सन्धि सम्पन्न हुई।

Appendix—B

यूरोपीय साम्यवाद और सोवियत संघ

पश्चिमी यूरोप के देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों का सोवियत प्रभाव से मुक्त रहने का आग्रह कोई नया नहीं है, किन्तु इस आग्रह को लेकर इतनी कटु बहस पहले सम्भवतः कभी नहीं हुई जितनी कि स्पानी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सांतियागो कारिल्लो की पुस्तक 'यूरोपीय साम्यवाद और राज्य' को लेकर हुई है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के इतिहास में यह कोई नया मोड़ है, फिर भी यह सम्भावना तो है ही कि विवाद बढ़ने पर पश्चिमी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियाँ अन्ततः मास्को से सम्बन्ध तोड़ सकती हैं।

श्री कारिल्लो ने अपनी पुस्तक में यह तर्क दिया है कि लेनिन ने जिस प्रकार के सर्वहारा वर्ग के राज्य का सुझाव दिया था वंसा कहीं अस्तित्व में नहीं है और उस देश में तो और भी नहीं है जिसे हमारा आदर्श बनाया जाता है। उनका कहना है कि आग सोवियत संघ में गौतमशाही के पास विभिन्न स्तरों पर अनुदार तथा अनियमित सत्ता है, वह मजदूरों और पार्टी की भी अपेक्षा करके नियंत्रण करती है। सोवियत संघ में वास्तविकता सिद्धान्त से कहीं दूर जा पड़ी है और वहाँ भी बुर्जुआ समाज की तरह कपती और करनी में भारी अन्तर आ गया है जिसके कारण सारी व्यवस्था 'अलग-थलग और दुर्गोच' बन गई है।

श्री कारिल्लो ने सोवियत संघ की आर्थिक उपलब्धियों को स्वीकार किया है। वह उन कारणों को भी स्वीकार करते हैं जिससे बाध्य होकर सोवियत संघ को अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार करना पड़ा। उनका आरोप तो यह है कि आर्थिक तथा सैनिक शक्ति संधय की प्रक्रिया में सोवियत संघ लोकतन्त्रीकरण में दूर जा पड़ा और शक्ति की ही चरम साध्य मानकर उसने सिद्धान्त को सत्ता प्राप्ति का एक साधन बना दिया जिसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि वह प्रत्येक राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को और समाजवाद के लिए लड़ी जाने वाली हर लड़ाई को विश्व में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का साधन मानने लगा।

सोवियत संघ में इस पर तीव्री प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। सोवियत पत्रिका 'न्यू टाइम्स' ने पुस्तक की समीक्षा प्रकाशित की जिसमें सांतियागो कारिल्लो पर 'निष्ठुर सोवियतवाद विरोधी' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने 'हमारे देश और हमारी पार्टी' की जिन शक्तियों में आलोचना की उनका प्रयोग तो

अतिप्रतिक्रियावादी लेखक भी प्रायः नहीं करते। श्री कारिल्लो ने इस आरोप का तत्काल खण्डन करते हुए 'कटकार और हुक्का पानी बन्द' करने की सोवियत तकनीक की भर्त्सना की। उन्होंने सोवियत छाप साम्यवाद को अस्वीकार करते हुए कहा कि "स्पानी पार्टी किसी सत्तारूढ़ दल या इकाई के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है।"

इस विवाद पर रोमानिया में भी प्रतिक्रिया हुई। वहाँ की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक वक्तव्य में सोवियत विचारों में तीव्र मतभेद व्यक्त करते हुए श्री कारिल्लो के यूरोपीय साम्यवाद का समर्थन किया। पार्टी के समाचार पत्र 'सितेप्रा' ने लिखा कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियों का यह मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य है कि वे वास्तविक आलोचना से मुक्त रह कर अपनी नीतियाँ स्वयं निर्धारित करें। समाचार-पत्र ने विवाद पैदा करने, आरोप लगाने और साम्यवादी आन्दोलन में तीव्र मतभेद उत्पन्न करने के प्रयास की भी निन्दा की।

इटली के उस प्रतिनिधि-मण्डल के जो हाल ही में सोवियत संघ से लौटा है, एक सदस्य एमानुएले मकालुसो ने भी रोम लौटने पर यह कहा कि पश्चिमी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियाँ और सोवियत संघ के सम्बन्ध कठिन किन्तु सम्भव तथा अनिवार्य हैं। इटली की कम्युनिस्ट पार्टी चेकोस्लोवाकिया की स्थिति को एक हल न हुआ सकत मानती है और उसका आग्रह है कि पूर्वी यूरोप में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कार्यवाही की जाए। श्री मकालुसो ने बताया कि मस्क्वा में बातचीत के दौरान इटली के प्रतिनिधि-मण्डल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यूरोपीय साम्यवाद के विचार पर वहम का तो इटली समर्थन करता है, किन्तु वह श्री कारिल्लो को समाजवाद का शत्रु बनाने वाली 'न्यू टाइम्स' की घोषणा का समर्थन नहीं कर सकता।

यूरोपीय साम्यवाद की इस धारणा ने ग्रीटन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी उईलित कर रखा है, और पार्टी विभाजन के कगार पर खड़ी है। पार्टी ने इस सम्भावित विभाजन को टालने के लिए अपने नए घोषणा-पत्र 'समाजवाद का ब्रितानी मार्ग' में यह सकल्प दोहराया है कि वह मतपेटी द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहती है, यद्यपि इसके लिए 'जन संघर्ष' का सहारा लिया जा सकता है।

यूरोपीय साम्यवाद को हर कीमन पर सोवियत संघ में स्वतन्त्र रखने के श्री कारिल्लो के विचार की समर्थक फ्रांस और इटली की कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी हैं। फ्रांस, इटली और स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टियाँ यह जानती हैं कि सोवियत संघ से जुड़े रहकर वह अपने देश के मनवानाओं से नहीं जुड़ पाएँगी। मगस्य आम्ति द्वारा सत्ता हासिलाना पश्चिमी यूरोप में किन्वाहल सम्भव नहीं है। तब उनके सामने यही एक मार्ग रह जाता है कि वे लोकतन्त्री उपायों से सत्ता प्राप्त करें। पश्चिम का उदार मनदाता, चाहे वह साम्यवादी ही क्यों न हो, बाहर से निर्देश प्राप्त करने के पक्ष में नहीं है और न ही उसे साम्यवाद के प्रचार-प्रसार का सोवियत तरीका पसन्द है। प्रायः यूरोप को साम्यवाद के सरक्षक की ओट में सोवियत संघ किस प्रकार दबोचे हुए है, इसकी कसक भी उनके मन में है। इसीलिए जब पश्चिमी यूरोप की

कोई कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी यूरोप में मानवाधिकारों की रक्षा और सोवियत संघ से स्वतन्त्र होने की बात कहती है तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

और यही सोवियत संघ की सबसे बड़ी परेशानी है। वह पूर्वी यूरोप में पश्चिमी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियों का हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता। यूरोपीय साम्यवाद से उसके विरोध के मूल में भी मुक्ततः यही कारण है। हंगरी की कम्युनिस्ट पार्टी के रवेंगे ने, जिसका इटली की कम्युनिस्ट पार्टी से घनिष्ठ सम्पर्क है, सोवियत संघ की चिन्ता को और भी बढ़ा दिया है। हंगरी की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने-अपने देशों में लोकतान्त्रिक परिवर्तन और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए अपनी नीतियाँ निर्धारित करने के यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के अधिकार और कर्तव्य के सिद्धान्त को मुखर समर्थन दिया है।

स्वारोपित इस बहस में सोवियत संघ को बिपक्ष स्थिति में डाल दिया है। यदि वह यूरोपीय साम्यवाद के विरोध के स्वर को और तीव्र करता है तो पश्चिमी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियों से उसका सम्बन्ध विच्छेद प्रायः निश्चित हो जाएगा और तब वे पार्टियाँ पूर्वी यूरोप में मानवाधिकारों के सर्प को तीव्र करने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र होंगी। इससे वारसा-सन्धि-मण्डल की स्थिति कमजोर होगी, किन्तु यदि वह यूरोपीय साम्यवाद के विचार को मान्यता देता है तो अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन का मुखिया होने का उसका दावा निरस्त हो जाएगा। यूगोस्लाविया, चीन और अल्बानिया उससे सम्बन्ध-विच्छेद करके नेतृत्व को पहले ही सशक्त चुनौती दे चुके हैं।

ऐसी स्थिति में सोवियत संघ के सामने बीच का जो मार्ग बचा रहता है वह है बीती बिसार कर मेन केन-प्रकारेण पश्चिमी यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े रहना। यह उसने लिए एक कड़वा घूँट होगा, किन्तु और कोई चारा भी नहीं है। यदि वह चाहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन में उसकी साक्ष को और ठेस न पहुँचे तो यह कड़वा घूँट उसे पीना ही होगा। इससे न केवल फ्रांस, इटली और स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टियों के सोवियत-विरोध की प्रखरता कम होगी बल्कि दक्षिणी, एशियाई और लातीनी अमेरिकी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों को भी सोवियत विरोध की हवा से एक हृद तक बचाए रखा जा सकेगा।

सोवियत संघ की इस नीति का एक दूरगामी परिणाम यह भी हो सकता है कि जब कभी फ्रांस, इटली और स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टियाँ मतपेटी द्वारा सत्तारूढ़ होंगी तो वे नाटो को कमजोर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। लेकिन यह बहुत दूर की कौड़ी है। वर्तमान में तो सोवियत संघ की मुख्य समस्या अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन में अपने नेतृत्व और पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की है।

(दिनमान, 17-23 जुलाई, 1977)

Appendix—C

दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान का बढ़ता प्रभाव

दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान को अब एक नया प्रभुत्व प्राप्त हो गया है। मार्च, 1971 में जापानी प्रधानमन्त्री ताकियो फुकुदा, जब वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर से भेंट-वार्ता के लिए गए थे, तब राष्ट्रपति कार्टर ने फुकुदा से कहा था कि एशिया की राजनीति को स्थिर रखने में जापान को अमेरिका का हाथ बंटाना चाहिए। फुकुदा से यद्द भी कहा गया था कि जापान दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की नीति में है और यह उत्तरदायित्व उसको ग्रहण करना चाहिए।

इस अमेरिकी-जापान विचार-विनिमय के फलस्वरूप जापानी प्रधानमन्त्री ने अगस्त में पूर्वी एशिया की छः राजधानियों की यात्रा की तथा मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में 'एशियान' (पाँच दक्षिण-पूर्वी देशों का संगठन, जिसके सदस्य हैं इण्डोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड) के राष्ट्रपतियों तथा प्रधानमन्त्रियों के शिखर-सम्मेलन में भाग लिया तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमन्त्रियों से, जो तब वहाँ 'एशियान' के नेताओं से वार्ता के लिए आए हुए थे, विचार-विमर्श किया। विचार-विमर्श का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी एशिया की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से सम्बद्ध 'एशियान' देशों की सहायता करना तथा समर्थ बनाना था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया सन् 1975 से दो स्पष्ट भागों में बँट गया है—हिन्दचीन के तीन देशों का समाजवादी भाग तथा स्वतन्त्र अर्थनीति वाले पूँजीवाद से सम्बन्धित 'एशियान' के पाँच देशों का भाग। हिन्दचीन के सफल जन-संघर्ष के बाद सभी पारचात्य पूँजीवादी देशों को आशंका है कि अब यदि 'एशियान' को आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक क्षेत्रों में सुदृढ़ नहीं किया गया तो इनमें समाजवादी क्रान्ति फूट पड़ेगी और यह क्रान्ति अन्य-समाजवादी देशों की सहायता से इन देशों की सत्ता तथा शासकों का अन्त कर देगी। यह स्थिति कुछ कुछ थाईलैंड में शुरू हो गई है।

एशियान देशों के खड्ड तथा अन्य बागों और कल-कारखानों में जापान तथा पारचात्य देशों की बहुत-सी पूँजी लगी हुई है तथा पूँजीवादी देशों से इनकी अर्थव्यवस्था जुड़ी होने के कारण यहाँ बैक, बीमा कम्पनियाँ, व्यापार तथा समुद्री यातायात अधिकतर पूँजीवादी देशों के हाथों में हैं। इन देशों की राजसत्ता यदि बदली तो यहाँ की अर्थव्यवस्था को, जो अधिकतर जापान, तथा पारचात्य देशों के हाथों में हैं, हानि होने की पाशंका है। इसलिए जापान जो एशिया में पूँजीवादी देशों का अनुयायी है, तथा अमेरिका, जो पूँजीवादी व्यवस्था का विश्व-नेता है,

मिन्-जुलकर इस कोशिश में है कि इस्लाम-पूर्वी एशिया की शेष राजमस्तकें न केवल ज्यों की त्यों रहे बल्कि और सुदृढ़ हो ताजि बगल के समाजवादी देशों में होने वाले संघर्ष में वे अपनी स्थिति कायम रख सकें।

'एशियान' देश अन्य कारणों से भी जापान तथा पाश्चात्य देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। बहुत से पदार्थ जो प्रमुख उद्योगों या मैनिक उद्योगों के लिए प्रति आवश्यक हैं, जैसे रबर, टीन, गहनीर तथा इमारती लकड़ी नाइ तथा नारियल का तेल, पेट्रोल और अन्य खनिज, इन देशों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। रबर, टीन तथा ताइपेल के ये देश विश्व के सबसे बड़े उत्पादक हैं। अगर इन देशों की सरकारों में परिवर्तन हुआ तो इन पदार्थों के उत्पादन पर जो नियन्त्रण आज जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि के हाथों में है, वह निकल जाएगा और इन पदार्थों के बिना जापानी उद्योग बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे। वियतनाम में द्वार के बाद अमेरिका इन राजमस्तकों को कायम रखने तथा मजबूत बनाने का भार सीधे अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिकी जनता अब हजारों मील दूरस्थ देशों की सत्ताओं की प्रतिरक्षा का भार नहीं उठाना चाहती।

अमेरिकी नेता अब जानते हैं कि यदि उन्होंने अपने देश को दूसरी सत्ताओं की रक्षा में भोका तो उस चेष्टा में देश की सही-सही मान्यताएँ भग हो जाएंगी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस उत्तरदायित्व को अब वह बाँटना चाहता है। इस बंटवारे के लिए अमेरिका ने तीन सम्झौदार छीटे हैं—जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। 'एशियान' देशों की प्राथिक सहायता का कुछ भार अमेरिका जापान पर लादना चाहता है तथा सैनिक सहायता का भार आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड पर।

जापान 'एशियान' देशों में लगाए हुए कल कारखानों तथा इनके साथ व्यापार द्वारा हर साल बहुत धन कमाता है। इण्डोनेशिया के प्रतिरिक्त, जिसका करीब 80 फीसदी तेल जापान खरीदता है, शेष सभी चार 'एशियान' देश हर वर्ष जापान के ऋणी रहते हैं क्योंकि उनका जापान के साथ निर्यात उनके आयात का औसतन एक चौथाई होता है। खनिजों तथा अपने उद्योगों के प्रति आवश्यक पदार्थों के प्रतिरिक्त अन्य वस्तुएँ जापान 'एशियान' देशों से नहीं खरीदना चाहता और अपने उद्योग की सभी वस्तुएँ इन देशों में बेचने की जापान की खुली छूट है। इसमें जहाँ भी जाइए, सब जगह जापानी ट्रांजिस्टर्स, कैमरों, घड़ियों, टेप रिकार्डर्स, कपड़ों तथा तरह-तरह की छोटी बड़ी मशीनों के विज्ञापन तथा दुकानें दिखाई देगी। इन देशों में जापानी कम्पनियों के हाथों में शोक व्यापार ही नहीं बल्कि फुटकर व्यापार भी है। यहाँ जापानी बड़ी दुकानें सिर्फ बड़े, पड़ी, कलपुर्जे ही नहीं घात-पील की सभी चीजें फुटकर में बेचती हैं। यहाँ पर्यटन से लेकर मशीनरी तथा स्कूल के बच्चों की पेंसिल रबर का व्यापार तक जापानियों के हाथों में है। जापान इन देशों से इतना धन कमाता है कि उसका सही अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि जापान यथास्थिति बनाए रखने के लिए इन देशों को प्राथिक सहायता प्रदान करे।

आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड अमेरिका से सैनिक सन्धि, 'एनजुस' द्वारा बंधे हैं और ये दोनों देश, सिंगापुर तथा मलेशिया के साथ 'पाँच देशों के रक्षा-प्रबन्ध' से प्रतिबद्ध हैं। इस रक्षा-प्रबन्ध के सदस्य ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर हैं। इस प्रबन्ध के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया अपनी हवाई सैनिक टुकड़ियों तथा लड़ाकू विमान (एफ-111 तथा एफ-5 ई) मलेशिया में ब्रटरबर्थ के हवाई अड्डे पर रखता है तथा न्यूजीलैंड के 1100 से 1500 तक सैनिक तथा उनके हथियार सिंगापुर में रहते हैं।

दो अन्य देश, थाईलैंड तथा फिलीपिन्स, अमेरिका के साथ रक्षा-सन्धियों से सम्बद्ध हैं। सन् 1965 में सत्ता-परिवर्तन के बाद इण्डोनेशिया का समस्त सैनिक सामान अमेरिका से आता है। इसमें से कुछ सहायता के रूप में आता है तो कुछ इण्डोनेशिया पैसा देकर खरीदता है। इसके फलस्वरूप कि अब 'एशियान' के पाँचों सदस्य-देश अपनी सेनाओं का साज-सामान मुख्य तौर से अमेरिका से खरीदते हैं।

अमेरिकी-जनता अब प्रश्न करने लगी है कि उनकी सरकार दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को सैनिक साज-सामान में सहायता क्यों देती है? प्रश्न का उत्तर देना सरकार के लिए कठिन होता जा रहा है। इसलिए उसने यह उपाय निकाला है कि यह रक्षा-साज-सामान पहले अपने से सैनिक सन्धि से बंधे देशों, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को दे और तब फिर ये देश उस साज सामान को 'एशियान' के सदस्यों को दें। संक्षेप में अमेरिका की ओर से जापान 'एशियान' देशों की आर्थिक सहायता करे तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सैनिक तथा सामरिक सहायता दें। इस दशा में कार्य चालू करने के लिए अगस्त, 1977 के दूसरे सप्ताह में जापान, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के प्रधानमन्त्री क्वालालम्पुर में 'एशियान' के राष्ट्रपतियों तथा प्रधानमन्त्रियों से वार्ता करने आए थे।

यद्यपि जापान ने, शब्दों में, अमेरिका के अनुरोध पर क्वालालम्पुर में 'एशियान' की आर्थिक सहायता करने का भार ले लिया, तथापि वास्तव में उसकी इन देशों का शोषण करने की नीयत में कोई अन्तर नहीं आया है। जापान अब यह सोचना है कि इस नए रिश्ते से वह क्या लाभ उठा सकता है।

क्वालालम्पुर में 'एशियान' नेताओं ने जापान से प्रार्थना की थी कि वह इन देशों के अन्य उत्पादक तथा उनके द्वारा निम्नित वस्तुएँ खरीदे ताकि उनका जापान के साथ व्यापार सन्तुलित हो सके। जापान ने इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। क्वालालम्पुर में उसके प्रधानमन्त्री ने एक ही वचन किया कि जापान 'एशियान' के पाँच नए उद्योगों के लिए एक अरब अमेरिकी डालर अर्थात् करीब नौ अरब रुपये का ऋण देगा, किन्तु ऋण देने से पहले वह जानना चाहेगा कि ये उद्योग मुनाफा कमा सकते हैं कि नहीं।

(विनमान, सितम्बर-अक्तूबर, 1977)

Appendix—D

जनवरी 1977 से दिसम्बर 1977 तक की महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की कलक

जनवरी, 1977

- 1 कनाडा द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सम्बन्धी जानकारी देना बन्द ।
- 2 रोडेशिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ द्वारा ब्रिटेन की अन्तरिम सरकार का प्रस्ताव रद्द । इक्वाडोर द्वारा अमेरिकी तेल कम्पनी का राष्ट्रीकरण ।
- 4 बंगलादेश के मार्शल ला प्रशासक जनरल जियाउर्रहमान द्वारा पीकिंग में दो समझौते पर हस्ताक्षर । जिम्बी कार्टर द्वारा पश्चिमी एशिया सम्मेलन पुनः शुरू कराने के लिए इजरायल पर दबाव ।
- 7 पांच अफ्रीकी राष्ट्रपतियों की लुसाका में शिखर-वार्ता ।
- 8 जनरल बिक्टर कुलीकोव वारसा-सन्धि समझौते के सेनाध्यक्ष नियुक्त ।
- 9 जिम्बाब्वे मुक्ति मोर्चे को पूर्ण समर्थन देने का प्रस्ताव पारित कर लुसाका शिखर-सम्मेलन समाप्त ।
- 12 फ्रांस द्वारा अरब-देशों को 200 मिराज देने का निष्ण ।
- 18 श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा भारत में मार्च में ग्राम चुनाव की घोषणा ।
- 20 जिम्बी कार्टर द्वारा अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ-ग्रहण ।
- 24 इयान स्मिथ द्वारा रोडेशिया पर ब्रिटेन के ताज्जा प्रस्ताव रद्द ।
- 29 हिन्दमहासागर में अमेरिकी नौसैनिक टुकड़ियों की गश्त की चीन द्वारा निन्दा ।
- 30 सूडान के राष्ट्रपति नुमेरी द्वारा लालसागर की शान्ति का क्षेत्र घोषित करने का आग्रह ।
- 31 एड्मंड्स द्वारा संयुक्तराज्य अमेरिका के स्वामी प्रतिनिधि के रूप में शपथ-ग्रहण ।

फरवरी, 1977

- 1 अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया से धीरे-धीरे सेना हटाने का निश्चय ।
- 2 साइप्रस बैत की 28 मार्च को तोषित सप की यात्रा ।
- 3 दक्षिणोषिया की विफल शान्ति में राज्याध्यक्ष तेकरी बटि और उनके सात समर्थकों की हत्या ।

- 5 मिस्र और सीरिया द्वारा संयुक्त कमान गठित करने का निर्णय ।
- 7 सऊदी अरब के शाह खालिद को सयुक्तराष्ट्र शान्ति पुरस्कार ।
- 12 ढाका में भारत और बंगलादेश में व्यापार समझौता ।
- 16 मुहम्मद दाऊद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित ।
- 18 संयुक्तराष्ट्र में अमेरिकी राजदूत एंड्रू यंग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कालो के शासन का समर्थन ।
- 19 ईराक और मलेशिया द्वारा हिन्दमहासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखने की माँग ।
- 23 काठमाण्डू में संयुक्तराष्ट्र द्वारा आयोजित समारोह (एशियाई स्त्रियों द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय होना) समाप्त ।

मार्च, 1977

- 2 रूस और चीन की सीमा-वार्ता में पुनः गतिरोध ।
- 4 दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र के सभी प्रस्तावों का अमेरिका द्वारा पूर्ण समर्थन का आश्वासन ।
- 5 रोडेशिया की समस्या का समाधान करने के लिए अमेरिका तथा ब्रिटेन का नया प्रस्ताव । ब्राजील द्वारा अमेरिका से सैनिक समझौता रद्द ।
- 7 काहिरा में अरब-अफ्रीकी देशों के शिखर-सम्मेलन में 60 देश सम्मिलित ।
- 10 अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा हिन्दमहासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखने का सुझाव ।
- 11 कुवैत द्वारा अफ्रीकी देशों को बीस करोड़ डॉलर का ऋण । पश्चिमी एशिया के बारे में कार्टर के नए प्रस्ताव की व्याख्या ।
- 12 ब्राजील द्वारा अमेरिका से प्रतिरक्षा समझौता रद्द ।
- 13 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स कैलेहन द्वारा हिन्दमहासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाने का समर्थन ।
- 18 अफगानिस्तान में प्रसन्निक सरकार का गठन ।
- 19 ढाका में श्रीलंका के राष्ट्रपति विलियम गोपालवा और बंगलादेश के राष्ट्रपति ए. एम. सैयम में हिन्दमहासागर के देशों में शान्ति स्थापित रखने पर बल ।
- 20 तुर्की और सोवियत संघ में मैत्री-समझौता । चीन द्वारा शक्तिशाली नौसेना निर्माण करने का निश्चय ।
- 21 ब्रेक्नेन द्वारा रूस के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अमेरिका पर आरोप ।
- 24 भारत में मोरारजी देसाई जनता पार्टी के नेता निर्वाचित और प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण ।
- 26 यूरोपीय आर्थिक समुदाय की 20वीं जयन्ती का दो दिवसीय सम्मेलन रोम में समाप्त । सामरिक प्रत्याग के प्रसार पर रोक लगाने (साल्ट) सम्बन्धी

वार्ता में भाग लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री साइरस वैंस सोवियत सघ रवाना ।

- 27 सोवियत सघ द्वारा कार्टर-प्रशासन की आलोचना जारी । रूसी राष्ट्रपति पोदगोर्नी द्वारा अफ्रीकी देशों को पूर्ण सहायता का प्रावधान ।
- 29 सोवियत सघ के राष्ट्रपति निकोलाई पोदगोर्नी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गोरों का शासन समाप्त करने का आग्रह ।
- 30 सोवियत सघ द्वारा अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने सम्बन्धी अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार । रॉबर्ट गोहोर्न अमेरिका के भारत में नए राजदूत ।
- 31 भारत की द्विपक्षीय सहायता देने के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव । मोजाम्बिक और सोवियत सघ में मैत्री-समझौते पर हस्ताक्षर ।

अप्रैल, 1977

- 3 हमले का खतरा होने पर सोवियत सघ द्वारा मोजाम्बिक को पूर्ण सहायता का प्रावधान ।
- 4 जर्नल जोयसिम योबी प्रायोंको कांगो के नए राष्ट्रपति । यूगोस्लाविया और इटली का सीमा-विवाद समाप्त ।
- 7 अमेरिकन द्वारा विधानों गामिया में सैनिक अड्डे का लेजी से निर्माण ।
- 8 विदेशी बैंक में खाते रखने के विषय पर इजरायल के प्रधानमन्त्री रॉबिन का रणमण्य ।
- 9 रूस और क्यूबा द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सघर्ष का समर्थन ।
- 14 जोर्हन द्वारा चीन से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय ।
- 15 अमेरिका द्वारा 13 देशों को दोषपूर्ण हथियार । अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर द्वारा मानवाधिकार का समर्थन करने वाले देशों को सहायता का प्रावधान ।
- 18 सात अफ्रीकी देशों की यात्रा के बाद ब्रिटिश विदेश मन्त्री डॉ. डेविड ओवेन लंदन वापस ।
- 21 जनरल जियाउर्रहमान बंगलादेश के नए राष्ट्रपति ।
- 25 सोवियत सघ के विदेश मन्त्री ग्रोमिको का दिल्ली में भ्रम्य स्वागत ।
- 26 माल्कान टून अमेरिका के रूस में नए राजदूत । पश्चिम जर्मनी द्वारा सोवियत सघ को एक अरब डॉलर का ऋण ।
- 27 भारत और सोवियत सघ में तीन समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर । जनरल टिक्रा खाँ पाकिस्तान के नए प्रतिरक्षा मन्त्री ।

मई, 1977

- 6 आधिक शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का लन्दन प्रावसन ।
- 7 पाकिस्तान को अमेरिका से दो विध्वंसक प्राप्त ।

- 8 सीरिया को और सोवियत हथियार प्राप्त । कुवैत को आठ और अमेरिकी जेट बमबर्क प्राप्त ।
- 14 चीन द्वारा प्राधुनिक यस्त्रों के निर्माण का निश्चय ।
- 18 इजरायल के ग्राम चुनाव में सेडर पार्टी पराजित और दक्षिण पवियों की विजय ।
- 19 अमेरिका तथा सोवियत संघ सहित 31 देशों द्वारा कृत्रिम मौसम का शस्त्र के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध ।
- 20 हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर की छ सूत्री योजना । इजरायली लिकुड पार्टी के नेता ब्रेटिन जेनेवा-सम्मेलन में शामिल होने पर सहमत ।
- 23 बेगिन द्वारा अरब अधिभूत क्षेत्रों को 'मुक्त क्षेत्र' बताना ।
- 24 सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकोलाइ पोदगोर्नो का कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो से हटाया जाना ।

जून, 1977

- 1 चीन द्वारा रूस और अमेरिका पर भारत महाद्वीप के आर्थिक शोषण का आरोप ।
- 2 अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को ए-7 लड़ाकू विमान बेचने पर रोक ।
- 3 पेरिस में उत्तर-दक्षिण आर्थिक सम्मेलन की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी ।
- 4 अमेरिका और बयूबा राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने पर सहमत ।
- 7 प्रधानमंत्री देसाई और विदेशमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन रवाना । लन्दन में मोरारजी देसाई का भव्य स्वागत ।
- 8 लन्दन में राष्ट्रकुल शिलर-सम्मेलन शुरू ।
- 10 रोडेशिया के विरुद्ध केनेय काउंडा की योजना का राष्ट्रकुल सम्मेलन में भारत द्वारा समर्थन ।
- 12 मिस्र की साऊदी अरब से चार करोड़ चालीस लाख डालर का ऋण प्राप्त ।
- 14 चीन द्वारा जापान और दक्षिण कोरिया के समझौते को अवैध ठहराना ।
- 15 लन्दन में राष्ट्रकुल सम्मेलन की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति जारी ।
- 16 लियोनिद ब्रेझ्नेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित । प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की फ्रांस के राष्ट्रपति जिस्कार द ऐलें से पेरिस में वार्ता ।
- 17 बेलग्रेड में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका द्वारा मानवाधिकार पर बहस का प्रयास । राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दिल्ली वापस ।
- 19 वाटरगेट कांड समाप्त ।
- 21 लिकुड के नेता ब्रेटिन द्वारा इजरायल के प्रधानमंत्री-पद की शपथ ग्रहण ।

- 22 पेरिस में लियोनिद ब्रेझ्नेव की राजकीय यात्रा की समाप्ति पर प्रसारित संयुक्त विज्ञप्ति में विश्व में निरस्त्रीकरण पर बल ।
- 24 ब्रेझ्नेव का रूस का राष्ट्रपति चुने जाने पर चीन की बधाई ।
- 25 उत्तर और दक्षिण कोरिया के विलय के प्रश्न पर विचार करने के लिए अल्जीरिस में तेरह देशों की वामपन्थी पार्टियों का सम्मेलन ।
- 27 अफ्रीका स्थित जिवूती को स्वाधीनता प्राप्त ।
- 28 अमेरिका द्वारा इजरायल को भरखों की भूमि से अपनी सेनाएँ हटाने का अनुरोध ।
- 30 यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए पृथक् राज्य का समर्थन ।

जुलाई, 1977

- 3 साइबरबिस्ते (गबोन) में अफ्रीकी एकता संगठन के शिखर-सम्मेलन में उगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन का नाटकीय प्रवेश ।
- 5 पाकिस्तान में रक्तहीन शान्ति । मुद्रो सहित सभी राजनीतिक नेता गिरफ्तार और फौजी कानून लागू ।
- 6 पाकिस्तान के प्रमुख फौजी कानून प्रशासक जनरल जिया-उल-हक द्वारा 90 दिन में लोकतन्त्र बहाल करने का आश्वासन ।
- 12 चीन द्वारा दक्षिण कोरिया से अमेरिकी सेना हटाए जाने की माँग ।
- 16 अमेरिकी नेताओं से बातचीत के लिए इजरायल के प्रधानमन्त्री बेगिन का न्यूयार्क आगमन ।
- 20 सुरक्षा परिषद् द्वारा बियतनाम को संयुक्तराष्ट्र का सदस्य बनाने का अनुमोदन ।
- 23 श्रीलंका में जयवर्देन मन्त्रिमण्डल द्वारा शपथ ग्रहण ।
- 25 इजरायल के प्रधानमन्त्री बेगिन का पश्चिमी एशिया पर शान्ति प्रस्ताव ।
- 26 अल्बानिया द्वारा चीनी विशेषज्ञों का बहिष्कार ।
- 28 चीन द्वारा उद्गम बम का विस्फोट ।
- 29 ढाका में भारत और बंगलादेश के प्रतिनिधियों में फरवरी-वार्ता आरम्भ ।
- 30 न्यूट्रान बम के विकसित करने पर सोवियत संघ की अमेरिका को कड़ी चेतावनी ।
- 31 सोवियत संघ द्वारा न्यूट्रान बम की काट का दावा ।

अगस्त, 1977

- 1 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात द्वारा लीबिया के साथ सन्धियों में सोवियत संघ का हाथ बँटाना ।
- 5 पश्चिमी एशिया पर अमेरिका-मिस्र प्रस्ताव सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज असद को अस्वीकार ।

- 7 श्रीलंका की जयवर्द्धन सरकार द्वारा बांडुंग के सिद्धान्तों पर विदेश नीति आधारित ।
- 10 पेंकिंग में चीन की पार्टी का ग्यारहवाँ अधिवेशन । रोडेशिया पर अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत ।
- 11 सोवियत संघ और चीन में सीमा वार्ता । अमेरिका की दक्षिण कोरिया को 190 करोड़ डालर की सहायता ।
- 14 विश्व के कम्युनिस्टों में भाईचारे की भावना स्थापित करने के लिए मार्शल टीटो की सोवियत संघ और चीन की यात्रा ।
- 15 प्ररव-इजरायल संघर्ष की समाप्ति के लिए अमेरिका द्वारा आठ मूत्री योजना प्रस्तुत ।
- 16 विदेशमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी का रंगून में भव्य स्वागत ।
- 18 मार्शल टीटो और लियोनिद ब्रेझ्नेव की वार्ता मास्को में समाप्त ।
- 19 अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भारत और बर्मा में कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति ।
- 24 पेंकिंग में हुआ और वैंस में संघर्षों को सामान्य करने पर वार्ता ।
- 26 रोडेशिया के प्रधानमन्त्री इयान स्मिथ को ब्रिटेन-अमेरिका का प्रस्ताव अस्वीकार । ताइवान के बारे में अमेरिका और चीन में मतभेद यथापूर्व ।

सितम्बर, 1977

- 1 रोडेशिया के चुनाव में इयान स्मिथ के रोडेशियाई मोर्चे को भारी बहुमत प्राप्त ।
- 6 मास्को में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डॉ. वात्सहीम और सोवियत विदेशमन्त्री ग्रेमिन्को द्वारा विश्व में निःशस्त्रीकरण पर जोर ।
- 9 फाम द्वारा पाकिस्तान को परमाणु सन्नद्ध देने की वायदे की पुष्टि । भारत और वियतनाम के बीच दो नए समझौते पर हस्ताक्षर ।
- 10 अमेरिकी सेंनेट द्वारा 11 हजार करोड़ डॉलर का प्रतिरक्षा बजट स्वीकार ।
- 13 अमेरिकी विदेश मन्त्रालय द्वारा पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना करने के सबंध में फिलिस्तीनी छापामार गुटों को शामिल करने की मांग ।
- 16 सोवियत संघ द्वारा स्वायत्त दल बना कर पश्चिमी देशों पर कम्युनिस्ट घान्दोलन को विघटित करने का आरोप ।
- 18 वाशिंगटन में विश्व बैंक द्वारा भारत की आर्थिक स्थिति पर सतोष और अगले वर्ष के लिए अधिक प्रगति की आशा व्यक्त ।
- 19 इजरायल के विदेशमन्त्री जनरल दयान पश्चिम एशिया की समस्या पर बातचीत करने के लिए वाशिंगटन खाना ।
- 21 संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर वियतनामी समाजवादी गणतन्त्र का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश ।
- 24 चीन द्वारा तीन अफ्रीकी देश जिनी, नाइजर और मोजाम्बिक के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौते ।

- 25 चीन के उप-सेनापति जनरल याङ्ग वू द्वारा फ्रांस से चीनी सेनाओं के हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता की माँग।
- 26 अमेरिका के पश्चिमी एशिया-शान्ति-वार्ता के प्रस्ताव का फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधियों द्वारा विरोध।
- 28 राष्ट्रमण्डल समिति द्वारा दक्षिण अफ्रीका से यह शर्त मनवाने का फैसला कि वह रोडेशिया को तेल देना बंद करे।
- 30 ब्रिटेन द्वारा भारत को समुद्र में तेल की खोज के सत्रों में हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन।

अक्टूबर, 1977

- 1 वाशिंगटन में भारत के विदेशमन्त्री द्वारा तब तक परमाणु बिस्तर निरोधक सन्धि पर हस्ताक्षर न करने की घोषणा जब तक सभी देश इस प्रकार के अस्त्रों को समाप्त करने की कार्यवाही न करें।
- 2 संयुक्तराष्ट्र में भारत के विदेशमन्त्री श्री बाजपेयी द्वारा पहली बार हिन्दी में भाषण।
- 5 संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा भारत के जनरल प्रेमचन्द रोडेशिया के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त। अमेरिकी राष्ट्रपति श्री कार्टर के अनुसार हिन्द-महासागर में रूस या अमेरिका की सेनाएँ अधिक संख्या में नहीं।
- 6 चीन द्वारा यूगोस्लाविया और अमेरिका के राजनयिकों से भारत के साथ संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त।
- 7 चीन और सोवियत संघ के बीच पिछले आठ वर्षों में पहली बार नौ-सैनिक समझौता सम्पन्न।
भारतीय राजदूत श्री नानी पाखकीवाला को राष्ट्रपति कार्टर द्वारा भारत के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते का आश्वासन। अमेरिका, सोवियत संघ, इजराइल और अरब राज्यों द्वारा दिसम्बर में जेनेवा में बातचीत करने का अनौपचारिक निर्णय।
- 13 स्वीडन द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत समेत 7 विकसनीय देशों को दिए गए ऋण को समाप्त करने की घोषणा।
न्यूयार्क से लौटते पर विदेशमन्त्री श्री यश्वन्त सिंह बान्जपेयी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की घोषणा की।
- 20 थाईलैंड में शान्ति और प्रतिरक्षा मन्त्री एडमिरल सयद द्वारा मत्ता पर नियंत्रण।
- 21 प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई का मास्को पहुँचने पर भव्य स्वागत।
- 23 रोडेशिया के प्रधानमन्त्री इयान स्मिथ द्वारा ब्रिटेन-अमेरिका के शान्ति प्रस्ताव को अत्यावहारिक ठहराना।
- 26 नेवादा मरुस्थल में अमेरिका द्वारा परमाणु बम विस्फोट।

नवम्बर, 1977

- 1 सुरक्षा परिषद् में दक्षिण अफ्रीका विरोधी प्रस्तावों पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा निषेधाज्ञा के अविकार का प्रयोग ।
मारिशस के प्रधानमंत्री सर भिन्नसागर रामगुलाम का दिल्ली आगमन ।
- 2 अमेरिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन से हटना । सोवियत संघ द्वारा परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबन्ध का आग्रह ।
- 3 अमेरिका द्वारा दक्षिण अफ्रीका को सैनिक साज-सामान बन्द करने का निश्चय ।
- 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा दक्षिण अफ्रीका को अस्त्र देने पर प्रतिबन्ध ।
- 10 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात द्वारा पश्चिमी एशिया में शान्ति स्थापना के लिए इजरायल जाने की घोषणा ।
- 13 सोवियत संघ द्वारा नेपाल के लिए आर्थिक सहायता का प्रस्ताव ।
- 15 इजरायल के प्रधानमंत्री द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात को यरूशलम आने का विधिवत निमन्त्रण ।
- 19 यरूशलम पहुँचने पर अनवर सादात का भव्य स्वागत । घटल बिहारी बाजपेयी शिष्ट (भूटान) में । लीबिया द्वारा मिस्र से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद ।
- 20 सादात का इजराइल ससद् को सम्बोधन ।
- 21 सादात और बेगिन द्वारा युद्ध न करने का एलान ।
- 23 स्पेन और पुर्तगाल में सहयोग की दस-साला मंत्री सन्धि पर हस्ताक्षर ।
- 24 लीबिया द्वारा मिस्र से सम्बन्ध विच्छेद ।
- 26 मिस्र के राष्ट्रपति सादात द्वारा जिनेवा सम्मेलन से पूर्व काहिरा में एक सम्मेलन के लिए निमन्त्रण ।
- 30 काहिरा सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डल की घोषणा ।

दिसम्बर, 1977

- 1 सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण । दक्षिण अफ्रीका के चुनाव में सत्ताह्वद नेशनल पार्टी की भारी विजय ।
- 2 त्रिपोली में सादात विरोधी सम्मेलन । दक्षिण अफ्रीकी प्रधानमंत्री जान वॉर्टर की पार्टी को 134 में से 104 स्थान प्राप्त ।
- 4 यामिर अराफत के नेतृत्व में सभी फिलिस्तीनी गुटों में एका ।
- 5 मिस्र द्वारा लीबिया और सीरिया से राजनयिक सम्बन्ध विच्छेद का निर्णय । बोकासा प्रथम मध्य अफ्रीकी साम्राज्य के सम्राट् ।
- 7 मिस्र द्वारा सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, हंगरी आदि के सांस्कृतिक केन्द्रों को बन्द करने के आदेश ।
- 9 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का काठमाण्डु में भव्य स्वागत ।

- 11 रोडेसिया के प्रधानमन्त्री इवान स्मिथ द्वारा गोरो की सुरक्षा की गारंटी देने की माँग ।
- 14 काहिरा में मिस्र और दूजरायल के प्रतिनिधियों में बातों शुरू ।
- 25 इजरायली प्रधानमन्त्री श्री बेगिन और मिस्री राष्ट्रपति सादात के बीच हस्ताक्षरों में शिखर बातें ।
- 26 सादात-बेगिन की सम्मिलित बातें निकल, मुख्य बाधा फिलिस्तीन समस्या का हल न ढूँढ पाना ।

जनवरी, 1978

- 1 अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जिम्मी कार्टर का भारत आगमन ।
- 3 भारत-अमेरिका समुक्त घोषणा : तीन कारागारों और घोषणाओं पर हस्ताक्षर ।
- 5 ब्रिटिश प्रधानमन्त्री श्री जेम्स कैलहन का छः दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली आगमन ।



संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मन्त्री की संयुक्त घोषणा

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1978

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जिम्मी कार्टर और भारत के प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने आज यहाँ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसमें परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने तथा वर्तमान भण्डारों को अन्ततः समाप्त करने तथा परम्परागत हथियारों को कम करने का आग्रह किया गया है और कहा गया है कि युद्ध राजनीतिक विवादों को हल करने का स्वीकार्य साधन नहीं है।

संयुक्त घोषणा में यह भी कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के बीच वर्तमान आर्थिक विषमताएँ मिटाई जाएँ और अधिक न्यायसंगत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम की जाए।

संयुक्त घोषणा

भारत और संयुक्तराज्य अमेरिका इतिहास और संस्कृति में विभिन्नता के बावजूद, इस बात को स्वीकार करने में एक हैं कि सत्ता और सार्वजनिक नीति की अन्तिम स्वीकृति व्यक्ति की गरिमा और कल्याण के प्रति आदर भाव में निहित है। जाति, लिंग, धर्म और सामाजिक स्तर के भेदभाव के बिना प्रत्येक मनुष्य को जीवन और स्वतन्त्रता, अभाव से मुक्ति और धमकी या जोर जबरदस्ती के बिना अभिव्यक्ति व पूजा आराधना की आजादी का अधिकार है।

दोनों की ऐसी लोकतान्त्रिक शासन-पद्धति में हम दोनों की गहरी आस्था है जिसमें सभी नागरिकों को कानून के अन्तर्गत मूलभूत स्वतन्त्रताओं की गारंटी प्राप्त होती है तथा उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने और अपना भविष्य निर्धारित करने का अधिकार होता है।

साथ ही हमारा यह भी विश्वास है कि सहकारी और स्थिर विश्व व्यवस्था, जनता द्वारा अपनी सरकार स्वयं गठित करने और हर राष्ट्र द्वारा अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ तय करने के अधिकार पर निर्भर है।

हम यह देख कर सन्तुष्ट हैं कि उपनिवेशों को समाप्त करने की प्रक्रिया में अन्तर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को लोकतान्त्रिक रूप दे दिया है जिससे अधिकांश राष्ट्रों

को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग से सम्बन्धित निर्णय करने की प्रक्रिया में भाग लेने का पहली बार अवसर मिला है ।

यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करनी है तो राष्ट्रों के बीच विद्यमान आर्थिक शक्ति की विषमताओं को मिटाया जाना चाहिए और अधिक व्यापकगत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ।

हम यह स्वीकार करते हैं कि एक आधुनिक राज्य के लिए विस्तृत आर्थिक विकास आवश्यक है, पर यह भी मानते हैं कि अगर इसके लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुँचते तो इस प्रकार की प्रगति खोखली है ।

आज की दुनिया के पास जीवन को अधिक सुखी सम्पन्न बनाने और राष्ट्रों के भीतर और राष्ट्रों के बीच अधिक सामाजिक न्याय सुलभ करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक दक्षता प्राप्त है । हमारा परस्पर निर्भर राष्ट्र समुदाय से अप्रह है कि वह हमारी पृथ्वी के साधनों और पर्यावरण को साम्राज्य विरासत के संरक्षण और परियोजना के लिए मिलकर कार्य करें । हम घोषणा करते हैं कि युद्ध राजनीतिक विवादों को हल करने का स्वीकार्य साधन नहीं है । दोनों देश अन्य देशों के साथ विवादों को सद्भावनापूर्वक और समुक्त राष्ट्र पोषणा वन के अनुसार हल करने के लिए भरमक प्रयत्न करेंगे और अन्य देशों के विवादों को हल करने में सहायता करेंगे ।

दुनिया में युद्ध की काली छाया काफ़ी लम्बे समय से भण्डाती रही है । परमाणु हथियारों के वर्तमान भण्डारों को घटाय ही कम किया जाना चाहिए और अन्ततः खत्म कर दिया जाना चाहिए और परमाणु हथियारों के विस्तार के खतरे को समाप्त किया जाना चाहिए । इसके अलावा परम्परागत हथियारों को धीरे-धीरे कम करने तथा इस प्रकार मुक्त होने वाली उत्पादक शक्तियों को मानव समाज की भलाई के कार्यों में लगाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम अपने भागों को प्रतिबद्ध करते हैं ।

राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से आगे आज की दुनिया में अधिक मुक्त और पूर्णतर बौद्धिक और वैज्ञानिक आदान-प्रदान के अवसर सुलभ हैं । ऐसी दुनिया में, जहाँ मन निर्भय हो, जहाँ विचार-स्वातन्त्र्य हो और सांस्कृतिक तथा कलात्मक गतिविधियों के पारस्परिक प्रभाव को बल मिलता हो, एक ऐसा वातावरण बन सकता है जहाँ सहिष्णुता और सद्भाव पल्लवित हो सकते हैं ।

शासन कला के परम्परागत विचारों से आगे बढ़ कर भारतीय और अमेरिकी यह स्वीकार करते हैं कि उनका अपने प्रति और अन्यो के प्रति यह दायित्व है कि राष्ट्रों के लिए कदापि कुटिल साधनों को उचित नहीं ठहराया जा सकता । व्यक्तिगत की तरह राष्ट्र भी अपने कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं ।

(मोराजी देसाई)
भारत के प्रधान मंत्री

(जिम्मी कार्टर)
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति

प्रश्न-कोश (QUESTION BANK)

अध्याय 1

- 1 द्वितीय महायुद्ध के समय हुए मित्र राष्ट्रों के बीच सम्मेलनों का संक्षिप्त सर्वेक्षण कीजिए ।
Describe in short the Wartime Conferences of the Allies Nations during the World War II.

- 2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (अ) चार स्वतन्त्रताएँ, | (आ) अटलान्टिक चार्टर, | (इ) मास्को-सम्मेलन, |
| (ई) तेहरान-सम्मेलन, | (उ) याल्टा-सम्मेलन, | (ऊ) पोद्साडम-सम्मेलन, |
| (ए) सान-फ्रांसिस्को-सम्मेलन । | | |

Write short notes on the following—

(a) Four Freedoms, (b) Atlantic Charter, (c) Moscow Conference, (d) The Tehran Conference, (e) The Crimea (Yalta) Conference, (f) The Berlin (Potsdam) Conference, (g) San-Francisco Conference. (1976, 77)

- 3 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और बर्लिन का विभाजन क्यों हुआ ? अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में आज जर्मनी का एकीकरण महत्वपूर्ण समस्या क्यों नहीं है ?

Why did the division of Germany and of Berlin take place after the Second World War ? Why is German unification no longer an important issue in the international affairs today ? (1976)

- 4 द्वितीय महायुद्ध के बाद शान्ति निर्माण में क्या कठिनाईयाँ थी ? शान्ति स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए ?

What were the hindrances in the establishment of peace after Second World War ? What efforts were made for peace ?

- 5 1945 के बाद पश्चिमी एशिया में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की समीक्षा कीजिए ।

Examine the factors which influenced international politics in West Asia after 194

अध्याय 2

- 6 संयुक्त राष्ट्रसंघ के संगठन और उसके चार्टर के संशोधन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए ।

Give an account of the organisation and functions of the United Nations Organisation.

7 1945 के उपरान्त संयुक्त राष्ट्रसंघ के संरचना तथा कार्यप्रणाली में होने वाले मुख्य परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए।
Examine the main changes that have taken place in the organisation and working of the United Nations since 1945.

8 सुरक्षा परिषद् के संरचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसमें मतदान प्रणाली की विवेचना कीजिए। पीटो संयुक्त राष्ट्र के कार्य की विरुद्ध रूप से कहाँ तक प्रभावित कर पाया है ?
Describe the composition and powers of the Security Council. Discuss its voting procedure. To what extent has the Veto adversely affected the working of the U.N.?

9 अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संरचना का परीक्षण कीजिए और इसका विश्व शान्ति को स्थिर रखने वाले कार्य के रूप में मूल्यांकन कीजिए। इसका निर्णय किस प्रकार लागू किया जाता है ?
Examine the composition of the International Court of Justice. Evaluate it as an instrument of maintaining world peace. How are its decisions executed? (1977)

10 विश्व समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the United Nations as a means of solving world problems.

11 संयुक्त राष्ट्रसंघ में निम्न विवादों में क्या भूमिका बरती की है, इसका मूल्यांकन कीजिए—
(क) कश्मीर का प्रश्न, (ख) कोरिया-युद्ध, (ग) भारत-पाक युद्ध, 1971.
Estimate the role which the U.N. has played in the following—
(a) Kashmir Question, (b) Korean War, (c) Indo-Pak War, 1971

12 संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक गतिविधियों में उसके महासचिव की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए।
Assess the role of the Secretary-General in the political activities of the United Nations

13 क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघ का सुधोला उन्नत रूप है ? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए वृत्तियाँ दीजिए।
Do you consider the United Nations Organisation to be an improvement over the League of Nations? Give reasons for your answer (1975)

14 संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्रसंघ की रचने अधिक सफलता के माध्यम से शान्त-शान्ति काया है ?
Estimate the achievements of the United Nations Organisation in the political field. What are the obstacles in the way of the greater success of the United Nations Organisation?

15 संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्य-प्रणाली को अधिक प्रबल बनाने के लिए आप किन-किन सुधारों को आवश्यक मानते हैं ?
What reforms do you consider necessary to improve the working of the United Nations Organisation?

16 विश्व शान्ति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्रसंघ की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए।
Estimate the achievements of the U.N.O. towards the establishing of world peace (1976)

17 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के साधन के रूप में संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से क्या हासिल है ?
What are the hindrances in the way of the United Nations to serve as an instrument of maintaining international peace? (1976)

18 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) भ्रष्ट प्रशासन, (ख) मनुष्य सृष्टि महानगर का भ्रष्ट के लिए मनुष्य प्रभाव ।

Write short notes on—

(a) Trusteeship system, (b) Uniting for peace resolution of the General Assembly of the United Nations. (1976)

अध्याय 3

19 एक महाशक्ति के रूप में मनुष्यप्रभाव अमेरिका के उदय की विवेचना कीजिए ।

Discuss the rise of U.S.A. as super-power.

20 एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ के उदय की विवेचना कीजिए ।

Discuss the rise of Soviet Union as super-power.

21 द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव के विस्तारक घटनाक्रम का वर्णन कीजिए ।

Narrate the course of events leading to the expansion of influence of the U.S.S.R. in Europe after the Second World War.

अध्याय 4

22 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

(क) परमाणु प्रसारण परिसीमित कर, (ख) निगन्धीकरण के कार्य में बाधाएँ,

(ग) निगन्धीकरण ।

Write short notes on—

(a) Nuclear Nonproliferation Treaty,

(b) Hindrances in the way of disarmament,

(c) Disarmament.

23 निगन्धीकरण के क्या तात्पर्य हैं ? यह किन्तु प्रकार का होता है ?

What do you mean by Disarmament ? What are its types ?

24 निगन्धीकरण की आवश्यकता किन कारणों से हुई ? उसकी सफलता में क्या बाधाएँ हैं ?

How did the necessity for disarmament arise ? What are the difficulties in its success ?

25 द्वितीय महायुद्ध के बाद निगन्धीकरण की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं ? वे सफल क्यों नहीं हुए ?

What efforts have been made for disarmament after the Second World War ? Why did they not succeed ?

अध्याय 5

26 शीत-युद्ध की प्रकृति, प्रारम्भ और मुख्य अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए ।

Discuss the nature, origin and main phases of the cold-war.

27 ठण्डाई 'शीत-युद्ध' के कारणों की व्याख्या कीजिए । किन मुख्य राज्यों की लेकर यह युद्ध या युद्ध है और 1946 से किन मुख्य घटनाओं के वर्णन करने के लिए हैं, उनका वर्णन कीजिए ।

Explain the causes of the so-called 'Cold-war'. Indicate main fronts on which it is being fought and the main episodes it has witnessed since 1946.

- 28 शीत-युद्ध से आप क्या समझते हैं ? इसकी प्रकृति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव की परीक्षा कीजिए ।
What do you understand by 'Cold War' ? Examine its nature and impact on international politics
- 29 वियतनाम संकट के क्या कारण थे ? इस समस्या को किस प्रकार सुलझा लिया गया है ?
What were the causes of Vietnam crisis ? How has the problem been solved ? (1977)
- 30 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
(क) क्यूबा संकट, (ख) बर्लिन की नाबादगद्दी, (ग) शीत-युद्ध ।
Write short notes on—
(a) Cuba Crisis, (b) Berlin Blockade, (c) Cold War (1976)
- 31 1949 के बाद महाशक्ति के रूप में चीन के उदयान का सुदूरपूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के घटनाक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा ?
What effect did the rise of China as a great power after 1949 leave on the course of events in the Far East and South-East Asia. (1977)
- 32 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में शीत-युद्ध की उत्पत्ति के कारण बताइए । किन तत्वों ने भब इस स्थिति को बदल दिया है ?
Account for origin of Cold War in the post Second World War Period
What factors have changed the situation now ?
- 33 1947 से अरब-इसरायल युद्ध में महाशक्तियों की क्या भूमिका रही है ?
What has been the role of Great-Powers in Arab-Israeli conflict since 1947.
- 34 'डेटेन्ट' से आप क्या समझते हैं ? इसके लिए उत्तरदायी कारणों की चीन-रूस मतभेद और चीन-अमेरिका के सम्बन्धों के सन्दर्भ में समीक्षा कीजिए ।
What do you understand by the 'Detente' ? Discuss the factors responsible for it in the context of Sino Soviet differences and Sino-U S relations

अध्याय 6

- 35 'असंलग्नता, उसके तत्व और बदलते हुए स्वरूप' पर आलोचनात्मक विवेक लिखिए ।
Write a critical essay on 'Non-alignment-Its Elements and Changing Patterns'.
- 36 असंलग्नता की नीति के प्रमुख सिद्धान्तों की परीक्षा कीजिए । वर्तमान में वे कहां तक उपयुक्त हैं ? भारत के अन्तर्गत के प्रयास में विस्तार से विवेचना कीजिए ।
Critically examine the main postulates of the policy of Non-alignment To what extent are they relevant now ? Discuss in detail by drawing up India's experience. (1974)
- 37 भारत की असंलग्नता की नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए ।
Critically examine India's policy of Non-alignment (1977)
- 38 असंलग्नता की नीति से आप क्या समझते हैं ? क्या आपके विचार में यह एक ठोस नीति है ? सोझाहरण समझाइए । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की इनके किस प्रकार प्रभावित किया ?
What do you understand by the policy of non-alignment ? Do you think that it is a sound policy ? In what ways has it affected international policies ? (1977)
- 39 विश्व राजनीति में असंलग्न राज्यों के गुट के महत्व पर एक विवेक लिखिए ।
Write an essay on the significance of the bloc of non-aligned states in world politics. (1976)

- 40 मार्च, 1977 के बाद भारत की जनता पार्टी की सरकार की असतलगतता की नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए ।
Critically examine the policy of non-alignment followed by the Janta Govt. of India after March, 1977.

अध्याय 7

- 41 एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के अन्त का वर्णन कीजिए ।
Describe 'de-colonization' in Asia and Africa
- 42 "एशिया का विद्रोह बीसवीं शताब्दी की बहुत महत्वपूर्ण घटना हो सकती है ।" इस कथन की विवेचना कीजिए ।
"The revolt of Asia may prove to be the most significant development of the twentieth century" (Palmer and Perkins) Comment on this statement (1975)
- 43 "एशिया इस समय मुकाबलों का सचचा कड़ाहा है और भविष्य में भी रहेगा ।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए और इस पर टिप्पणी कीजिए ।
"Asia is now, and will continue to be, a veritable cauldron of confrontations" Elucidate and comment
- 44 1945 और 1947 के बीच एशियायी स्वतन्त्रता एवं एकता के लिए राष्ट्रवादी भारत के नेतृत्व ने क्या किया ?
What did the Indian Nationalist leadership do to further Asian freedom and unity between 1945 and 1947.
- 45 अफ्रीका में स्वायत्त राज्यों के उदय के महत्व पर सक्षिप्त परीक्षण कीजिए, और इसके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभावों का विवेचन कीजिए ।
Examine briefly the importance of the emergence of independent states in Africa and its effects on international politics.
- 46 मध्यपूर्व की द्वितीय महायुद्धोत्तर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक सक्षिप्त लेख लिखिए ।
Write a short essay on international politics of the Middle East after World War II.
- 47 अफ्रीका के आगमन की विवेचना कीजिए ।
Discuss the resurgence of Africa.
- 48 'अफ्रो-एशियाई एकता' पर आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए । इस एकता के भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं ?
Write a critical essay on 'Afro-Asian Unity'. What do you think about the prospect of such unity ?
- 49 गणप्रजातन्त्री बंगलादेश के उदय का मूल्यांकन करें । साथ ही बंगलादेश की विदेश-नीति के मुख्य लक्षणों का भी संकेत दीजिए ।
Evaluate the emergence of Ganprajatantri Bangladesh. Also indicate the main features of its foreign policy.
- 50 एशिया के पुनर्जागरण के कारण समझाइए तथा उसके राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए ।
Account for the resurgence of Asia and bring out its political effects. (1977)
- 51 महाशक्तियों द्वारा उन पर प्रभाव स्थापित करने के शुक्त्रों के समग्र नवस्वतन्त्र अफ्रीकी राज्यों के मध्य एकता की स्थापना के मार्ग में बाधक तत्व कौन-कौन से हैं ?

What are the factors that prevent the unity of the newly independent African states in the face of the designs of the Great-powers for influence over them. (1976)

- 52 अरब राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए।
Discuss the main causes for the rise of Arab Nationalism (1976)

- 53 अफ्रीकी एकाता संगठन पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए।
Write a short essay on the Organisation of African Unity. (1977)

- 54 भारत और बांग्लादेश के मध्य सम्बन्धों का विवेचन कीजिए।
Discuss the relations between India and Bangladesh (1977)

अध्याय 8

- 55 "समकालीन विश्व राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है दो भीषणतम देशों (रूस और अमेरिका) के बीच का संघर्ष।" व्याख्या कीजिए और समझाइए कि क्या यह बयान अभी भी सही है?

"The conflict between two monolithic giants-the U.S.A. and the U.S.S.R. is the dominant reality of the contemporary world politics." Explain Does it still hold good? (1977)

- 56 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं?
What have been the contemporary trends in International Politics.

- 57 संयुक्त राष्ट्रसंघ के 31वें अधिवेशन में निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भारत की क्या भूमिका रही?

What was the role played by India in 31st United Nations meet?

- 58 अफ्रीकी शासनतन्त्र में क्या परिवर्तन आ रहा है? इसके क्या कारण हैं?
What changes are taking place in the administrative system of Africa?

- 59 जून, 1977 के राष्ट्रकुल सम्मेलन की क्या विशेषता थी? उसके विचार के मुख्य विषय क्या थे?

What was the special feature of June 1977 Common Wealth of Nations Conference? What were principal subjects discussed in it?

- 60 अमेरिकी हतहानीति में क्या परिवर्तन आया है? इसका भारत उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ा है?

What change has come in American Arms Supply Policy? How has it affected the Indian subcontinent?

- 61 अफ्रीका की स्थिति विस्फोट हो जाने के पीछे क्या कारण हैं? इसके क्या खतरे हैं?
What are the causes of explosive situation of Africa? What are the dangers inherent in it?

- 62 लैटिन अमेरिका की राजनीतिक स्थितियों में स्थिरता क्यों नहीं है? इसमें समुत्तराज्य अमेरिका का क्या हाथ है?

Why is there no stability in Latin America? How far is U.S.A. responsible for it?

- 63 पश्चिमी एशिया की राजनीति में क्या अन्तर आया है? इसके क्या कारण हैं?
What change has come in West Asian Politics? What are its reasons?

- 64 पश्चिमी एशिया में शान्ति-स्थापना के लिए क्या नए प्रयास शुरू हुए हैं? इनकी सफलता की क्या आशा है?

What new efforts are being made for peace in West-Asia What are the chances of success ?

65 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- (अ) नि रक्षणीकरण पर ब्रिमेनेव प्रस्ताव,
- (ब) शेसेलस की ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति,
- (स) शिपर सम्मेलन, मार्च 1977,
- (द) सात बड़ों का सम्मेलन, मई 1977.

Write short notes on—

- (a) Brezhnev's disarmament proposals,
- (b) Independence of Shesells from British Empire.
- (c) Conference of the Heads of States, March 1977,
- (d) Meeting of the Seven Bigs, May 1977.

अध्याय 9

66 'पहले एशिया' अथवा 'पहले यूरोप' के सन्दर्भ में युद्धोत्तर अमेरिकी विदेश-नीति में क्या-क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं—विश्लेषण कीजिए।

Identify the main shifts in postwar U. S. Foreign Policy in the context of 'Asia First' or 'Europe First'. (1971)

67 शीत-युद्ध के सैन्यिक के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि क्या इनमें यह परिवर्तित होता है कि अमेरिका और रूस के हित मूलतः एक ही दिशा में उन्मुख हैं।

What are the primary reasons for the thaw in the cold war and do you think it represents any basic convergence in U S -Soviet interests. (1971)

68 राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका ने सोवियत संघ के साथ जो कुछ समझौते किए थे उनके स्वरूप व सारभूत तत्वों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

Describe, in brief, the nature and content of some of the important agreements that the American Policy-makers under Richard Nixon arrived at with their counterparts in the Soviet Union. (1975)

69 आपकी राय में एशिया के प्रति अमेरिकी नीतियों पर वियतनाम युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है ? How has the war in Vietnam affected, in your view, U S policies towards Asia ? (1972)

70 निम्न प्रशासन काल की अमेरिकी विदेश नीति पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।

Write a critical note on the American Foreign Policy under the Nixon Administration (1973)

71 ट्रूमैन प्रशासन काल की अमेरिकी विदेश नीति पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।

Write a critical note on the American Foreign Policy during the Truman Administration. (1974)

72 अमेरिका की साम्यवादी चीन सम्बन्धी नीतियों में वर्तमान में आए जाने वाले परिवर्तनों के क्या कारण हैं ? संतुष्ट कर लिखिए।

What are the reasons for the change in the U S. A. towards Communist China in recent years ? (1976)

73 1945 से दक्षिण पूर्व में संयुक्तराज्य अमेरिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Examine the role of the U.S.A. in South-East Asia since 1945. (1977)

74 1945 से 1964 तक सोवियत संघ के प्रति संयुक्तराज्य अमेरिका की विदेश-नीति की विवेचना कीजिए।

Discuss the foreign policy of the U.S.A. towards the U.S.S.R. from 1945 to 1964 (1977)

- 75 सन् 10 वर्षों से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सम्बन्धों का विश्लेषण कीजिए।

Discuss the relations between China and the U.S.A. during the last ten years (1977)

- 76 द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया-प्रशांत क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्धों का मूल्य वर्धन कीजिए।

Briefly describe the involvement of U.S.A. in the region of Indo-China after the Second World War. (1976)

- 77 द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् अमेरिका की यूरोप के प्रति नीति को समझाइए।

Discuss the policy of U.S.A. towards Europe after the Second World War. (1976)

- 78 'जिम्सन सिद्धान्त' से क्या क्या समझते हैं? अमेरिका की एशिया-प्रशांत नीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा?

What do you understand 'Janson Doctrine'? How has it affected American policy towards Asia?

- 79 फोर्ड प्रशासन के अधीन अमेरिका की विदेश-नीति को आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए।

Critically examine the American Foreign Policy under Ford-administration

- 80 'समृद्धि कार्डर' ने अमेरिका की विदेश-नीति को क्या क्या मोड़ दिया है? उनके शांति प्रयत्नों की परीक्षा कीजिए।

What new turn has Carter given to American Foreign Policy? Examine his peace efforts

प्रश्नावली 10

- 81 रशियन की मृत्यु के बाद से एशिया के प्रति सोवियत नीति के विकास की विवेचना कीजिए।

Discuss the development of Soviet policy towards Asia since the death of Stalin (1971)

- 82 सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश-नीतियों में चौकसी क्यों तथा और क्यों-क्यों कारण निरोधी हैं?

Examine the points of conflict and convergence in the foreign policies of the Soviet Union and the United States (1973)

- 83 सोवियत विदेश-नीति के भारतीय उप-महाद्वीप में जो उद्देश्य हैं उनको समीक्षा कीजिए।

Examine critically the foreign policy objects of the Soviet Union in the Indian Sub-continent (1974)

- 84 चीन-रूस संघर्ष के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि सन्धि के मुद्दे किसे क्या हैं?

Analyse the nature of the Sino-Soviet conflict and discuss the principal areas of disagreement (1971)

- 85 चीन और सोवियत संघ की आपसी अन्धविश्वास के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसके विचार में क्या यह अनवरत अनिवार्य थी? वर्तमान राजनीति पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए।

Discuss the causes of the Sino-Soviet rift. Do you think the rift was inevitable? Discuss its effect on contemporary international politics. (1972, 73)

- 86 1958-1963 के बीच दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रति चीन की नीति का विश्लेषण कीजिए।

Discuss China's policy towards South-East Asia during 1958-63 (1972)

- 87 अरब-इजराइल संघर्ष में सोवियत सप की सन् 1948 से क्या भूमिका रही है ?
What has been the role of the U.S.S.R. in the Arab Israel conflict since 1948. (1977)
- 88 स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत विदेश-नीति का विवेचन कीजिए। इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं ?
Discuss the Soviet foreign policy after the death of Stalin in March, 1953. What changes have come into it? (1977)
- 89 द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यूरोप में सोवियत सप के प्रभाव के विस्तारक घटनाक्रम का वर्णन कीजिए।
Narrate the course of events leading to the expansion of the Soviet-area of influence in Europe after the Second World War. (1976)
- 90 आधुनिक वर्षों में सोवियत रूस की विदेश-नीति में क्या सुधार हुआ है ? उत्तर की पुष्टि में ठोस उदाहरण दीजिए।
In what respect has the foreign policy of U.S.S.R. modified in recent years Give concrete instances to illustrate answer.
- 91 सोवियत रूस और अमेरिका की नीतियों के विशेष संदर्भ में उन तत्त्वों की विवेचना कीजिए जो अब तक चल रहे पश्चिमी एशिया के संकट के लिए उत्तरदायी हैं।
Analyse the factors responsible for the continued West-Asian crisis with particular reference the policies of the Soviet Union and the U S A
- 92 1977 में भारत और अमेरिका के प्रति सोवियत विदेश-नीति की परीक्षा कीजिए।
Examine the Soviet Foreign Policy towards India and the United States of America during the year 1977.

अध्याय 11

- 93 भारत की विदेश-नीति के निर्धारक तत्व क्या हैं ? 1947 के बाद से उसके विकास के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए।
What are the determinants of India's foreign policy ? Discuss the salient points of its evolution since 1947. (1971)
- 94 भारत-चीन संघर्ष के कारणों का विश्लेषण कीजिए और 1959-62 के बीच भारत के प्रति चीन के रवैये में जो परिवर्तन आया उसका निरूपण कीजिए।
Analyse the factors in the India-China conflict and discuss the change in China's attitude towards India during 1959-62. (1971)
- 95 श्रीलंका के साथ भारत के सम्बन्धों के विकास-क्रम पर संक्षेप में चर्चा करें और दोनों के बीच की समस्याओं का स्वरूप क्या है ?
Trace the course of India's relations with Ceylon and analyse the nature of the problems between the two. (1971)
- 95 1971 की भारत-रूस सन्धि को शान्ति, मित्रता तथा सहयोग की सन्धि कहा गया है, सैनिक सन्धि नहीं। इसका मूल्यांकन कीजिए।
The Indo-Soviet Treaty of 1971 has been described as a treaty of peace, friendship and co-operation, and not a military treaty How do you evaluate it ? (1971)

- 97 नेपाल के साथ भारत के सम्बन्धों के विकास का वर्णन करते हुए दोनों के बीच की समस्याओं के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए।
Trace the course of India's relations with Nepal and analyse the nature of the problem between the two (1971)
- 98 भारत और नए उदयमान एशियायी तथा अफ्रीकी देशों के राष्ट्रमन्त्रालय में शामिल होने के कारणों पर प्रकाश डालिए।
Discuss the reasons which led India and some other newly emerging Asian and African countries to join the Commonwealth (1972)
- 99 भारत-चीन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए पुनर्मेल की सम्भावनाओं का विवेचन कीजिए।
Analyse the India China conflict and discuss the possibilities of rapprochement (1972)
- 100 बंगलादेश की स्थापना में भारत की जो भूमिका रही है उसका विश्लेषण कीजिए। क्या आपके विचार से इस भूमिका से भारत की विदेश-नीति में कुछ नई दिशाओं के प्रादुर्भाव का सबेह मिलता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए।
Analyse India's role in the emergence of Bangladesh. Do you think that this role represents any new directions in India's foreign policy? Give reasons in support of your answer (1973)
- 101 1969 के बाद से 'सुपरशक्तियों' के प्रति भारत की जो नीति रही है उसकी मुख्य विशेषताओं को विवेचन कीजिए।
Discuss the main features of India's policy towards the Super Powers since 1969 (1974)
- 102 1971 के बंगलादेश संकट के सम्बन्ध में ब्रिटेन और चीन ने जो दृष्टिकोण अपनाए उनका विवेचन कीजिए। इन दोनों देशों के अपने-अपने दृष्टिकोण अपनी-अपनी विदेश-नीति के आधारभूत सिद्धान्तों से कहीं तक मेल खाते थे?
Analyse the Chinese and British attitudes to the Bangladesh crisis of 1971. How far were these attitudes in accordance with the basic principles of the foreign policies of the two countries? (1974)
- 103 आपके विचार में वे कौनसे मूलभूत कारण थे, जो कि भारत की असमानता की नीति के लिए उत्तरदायी थे?
What in your view, were the basic factors which were responsible for India's policy of non-alignment? (1975)
- 104 "भारत ने त्रिपक्षीय व्यवस्था की नीति का पालन किया है, उसे भारत-सोवियत शैली सन्धि न खटाई में नहीं डाला, बल्कि इस सन्धि से वह नीति पुष्ट हो गई है।" इस कथन की सकारण विवेचना कीजिए।
"The Indo-Soviet Treaty nowhere contradicts but rather upholds the basic tenets of the policy of non-alignment that India has pursued so far." Do you agree? Give reasons in support of your answer (1975)
- 105 1947 से आज तक के भारत-रूस सम्बन्धों की एक संक्षिप्त समीक्षा कीजिए।
Discuss briefly the Indo-U S S R relations since 1947 (1976)
- 106 भारत और बंगलादेश सम्बन्धों का विवेचन कीजिए।
Discuss the relations between India and Bangladesh. (1977)
- 107 सन् 1950 से भारत-चीन सम्बन्धों की वास्तविकतात्मक समीक्षा कीजिए।
Critically examine the Sino-Indian relations since 1950 (1976, 77)

108 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—

- (अ) भारत-पाक शिमला समझौता,
(ब) रूस-भारत मैत्री सन्धि, 1971,
(स) भारत और यूरोपीय साम्राज्य बाजार।

Write short notes on—

- (a) Indo-Pak Simla Agreement.
(b) Russia-Indian Friendship Treaty,
(c) India and the European Common Market. (1977)

109 शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व से आप क्या समझते हैं ? सोवियत संघ और भारत की विदेश-नीतियों के सम्बन्ध में इसकी विवेचना कीजिए।

What do you mean by 'Peaceful Co-existence'? Discuss in the context of the U S S R and Indian foreign policies

110 गिप्त, इनराष्ट्र और अरब देशों के प्रति भारत की विदेश-नीति को समझाइए।

Explain India's foreign policy towards Egypt, Israel and the Arab countries. (1976)

111 1967 से भारत की विदेश-नीति का मूल्यांकन कीजिए।

Give an assessment of India's foreign policy since 1967 (1976)

112 क्या एशिया के दो महान् पड़ोसियों—चीन और भारत की परराष्ट्र नीतियों के लक्ष्यों की कोई समान भूमि नहीं बची है ?

Does there exist no common ground between the foreign policy objectives of the two big neighbours of Asia namely China and India ?

113 नेहरूजी की मृत्यु के पश्चात् भारत की अणु ब्यावहारिक विचारों का प्रभाव पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से आप वहाँ तक सहमत हैं ?

How do you agree with the view that India's foreign policy is being influenced more by pragmatic consideration than by Idealistic ones since after the death of Nehru ?

114 क्या आपके विचार में भारत के विदेशमन्त्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी असत्यता की नीति के सच्चे प्रवक्ता हैं ?

Do you think that Mr. Atalbihari Bajpai, the new Foreign Minister of India, is the true advocate of the policy of non-alignment ?

अध्याय 12

115 चीन की विदेश-नीति के भारतीय उप-महाद्वीप में जो लक्ष्य हैं उनकी समीक्षा कीजिए।

Examine critically the foreign policy objectives of China in the Indian Sub-continent (1973)

116 अमेरिका और पाकिस्तान के प्रति अरनाई गई चीन की नीति के मोझूझ और पर एक आलोचनात्मक निबन्ध लिखिए।

Write a critical note on the current phase of the Chinese policy towards the United States and Pakistan (1974)

117 1949 में साम्यवादी चीन के शुरुआत के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।

Discuss critically the impact of the emergence of the Communist China upon international politics since 1949. (1945)

- 118 1949 से महाशक्ति के रूप में चीन के उदय का मुद्दापूर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया में महान-क्रम पर क्या प्रभाव पड़ा ?
What effect did the rise of China as a great power after 1949 have on the course of events in the Far East and South-East Asia (1977)
- 119 जनवादी चीन की विदेश-नीति के निर्णायक तत्वों का विश्लेषण कीजिए ।
Analyse the factors which determine the foreign policy of Peoples Republic of China (1976)
- 120 अफ्रीकी नवस्वतन्त्र राज्यों के प्रति सन् 1950 से जनवादी चीन की नीति का विवरण दीजिए ।
Give an account of the policy of the People's Republic of China towards the newly independent States of Africa since 1950 (1976)
- 121 पाकिस्तान और चीन की विदेश-नीतियों के समीप आने के साथ कौन-से कारण देंगे ?
How do you account for the closer coming together of Pakistan and China in their foreign policies

अध्याय 13

- 122 स्वेज-पूर्व के प्रति ब्रिटिश नीति का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि क्या टोरी सरकार के सत्कार्य होने के बाद इस नीति में कोई स्पष्ट परिवर्तन आया है ?
Discuss the British policy towards East of the Suez and whether there has been any perceptible change in this policy with the assumption of power by a Tory government (1971)
- 123 यूरोपीय साक्षा-वाचार के प्रति ब्रिटेन के बदलते हुए दृष्टिकोणों के कारणों की व्याख्या कीजिए ।
Discuss the factors responsible for the changes in Britain's attitudes towards European Common Market (1973)
- 124 'साष्टमण्डल' से आप क्या समझते हैं ? ब्रिटेन की विदेश-नीति निर्धारित करने में साष्टमण्डल का जो महत्त्व है उस पर प्रकाश डालिए ।
What is the Commonwealth ? Explain the significance of the Commonwealth as a determining factor in the British Foreign policy (1974)
- 125 मुद्रोत्तर ब्रिटिश विदेश-नीति की परीक्षा कीजिए ।
Examine carefully the post-war British foreign policy
- 126 मुद्रोत्तर फ्रेंच विदेश-नीति की परीक्षा कीजिए ।
Examine carefully the post-war French Foreign Policy
- 127 ब्रिटेन तथा फ्रांस के द्वितीय मुद्रोत्तरकालीन सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए ।
Examine the post-war relations of Britain and France ?
- 128 रोडेशिया की समस्या क्या है ? ब्रिटेन इस समस्या को सुलझाने में सफल क्यों नहीं हो रहा है ?
What is the Rhodesia problem? Why is Britain not so successful in solving it?

- 6 अफ्रीकी नवस्वतंत्र राज्यों के प्रति सन् 1950 से जनवादी चीन की नीति का विवरण दीजिए । (1976)

Give an account of the policy of the People's Republic of China towards newly independent States of Africa since 1950.

- 7 हाव ही के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियों के समूहों की चीनी गणराज्य के उदय ने किस प्रकार प्रभावित किया है ? (1979)

How has the rise of People's Republic of China affected the alignment of international forces in recent years ?

अध्याय 13

- 38 स्वेज पूर्व के प्रति ब्रिटिश नीति का निरूपण कीजिए और बताइए कि क्या टोरी सरकार के सत्ताह्व होने के बाद इस नीति में कोई स्पष्ट परिवर्तन आया है । (1971)

Discuss the British policy towards East of the Suez and whether there has been any perceptible change in this policy with the assumption of power by a Tory government

- 39 यूरोपीय साम्राज्य-बाजार के प्रति ब्रिटेन के बदलते हुए दृष्टिकोणों के कारणों की व्याख्या कीजिए । (1973)

Discuss the factors responsible for the changes in Britain's attitudes towards European Common Market

- 40 'राष्ट्रमण्डल' से आप क्या समझते हैं ? ब्रिटेन की विदेश-नीति निर्धारित करने में राष्ट्रमण्डल का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालिए । (1974)

What is the Commonwealth ? Explain the significance of the Commonwealth as a determining factor in the British Foreign policy.

- 41 युद्धोत्तर ब्रिटिश विदेश नीति की परीक्षा कीजिए ।

Examine carefully the post war British foreign policy

- 42 युद्धोत्तर फ्रेंच विदेश-नीति की परीक्षा कीजिए ।

Examine carefully the post-war French Foreign Policy

- 43 ब्रिटेन तथा फ्रांस के द्वितीय युद्धोत्तरकालीन सम्बन्धों की समीक्षा कीजिए ।

Examine the post-war relations of Britain and France.

- 44 रोडेशिया की समस्या क्या है ? ब्रिटेन इस समस्या को सुलझाने में सफल क्यों नहीं हो रहा है ?

What is Rhodesia problem ? Why is Britain not so successful in solving it ?

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और टिप्पणियाँ

- 45 अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ऊर्जा संकट के प्रभाव की विवेचना कीजिए ।

(1978)

Discuss the impact of energy crisis of International Politics

- 46 संयुक्त राष्ट्र संधि के संविधान के संशोधन पर एक निबंध लिखिए । (1978)

Write an essay on the revision of the U. N Charter.

- 47 'द्वैतान्त' से आप क्या समझते हैं ? इसके कारणों व विश्व-राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की भी बर्चा कीजिए । (1978)

What do you understand by 'Détente' ? Also give its causes and impact on World Politics

- 148 'शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व' से क्या आशय है ? युद्धोत्तर सोवियत विदेश नीति में इस सिद्धान्त का किस प्रकार समावेश हुआ है ? (1978)

- 149 संयुक्त राष्ट्रसंघ के समूहन तथा कार्य-प्रणाली पर शीत-युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा ? विश्लेषण कीजिए । (1978)

- 150 क्या आपके विचार से तनाव शैथिल्य के युग में गुट-निरपेक्षतावाद का कोई महत्वपूर्ण स्थान है ? अपने उत्तर की पुष्टि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नवीन घटनाओं के आधार पर कीजिए । (1978)

Do you think non-alignment has any utility in the age of détente ? Illustrate your answer with new development in world politics

- 151 निम्नांकित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (अ) द्वितीय महायुद्ध के बाद जापान से सन्धि,
- (ब) चीन-सोवियत संघ विवाद,
- (स) 'तेल कूटनीति',
- (द) संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र का संशोधन ।

Write short notes on any two of the following :—

- (a) Treaty with Japan (after the Second World War)
- (b) Sino-Soviet Conflict,
- (c) 'Oil Diplomacy'
- (d) Revision of the U N Charter

- 152 गुट-निरपेक्षतावाद से आपका क्या अभिप्राय है ? भारत की विदेश नीति कहाँ तक इस पर आधारित रही है ? (1979)

What do you mean by Non-alignment ? How far is Indian foreign policy based on it ?

- 153 1947 से आज तक के भारत-अमेरिकी सम्बन्धों की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए । Discuss briefly the Indo-U S relations after 1947 (1979)

- 154 'तेल सराफ़' के संदर्भ में 1954 के बाद की पश्चिम एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों की समीक्षा कीजिए । (1979)

Discuss with special reference to oil diplomacy the factors which have influenced international politics in West Asia since 1954